CET-2026

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)

समान पात्रता परीक्षा

स्नातक स्तर – (हिन्दी माध्यम)

NODIA

भाग - 1

अर्थशास्त्र
ECONOMICS

अध्यायवार MCQs

Nodia

Scan QR for Demo PDF

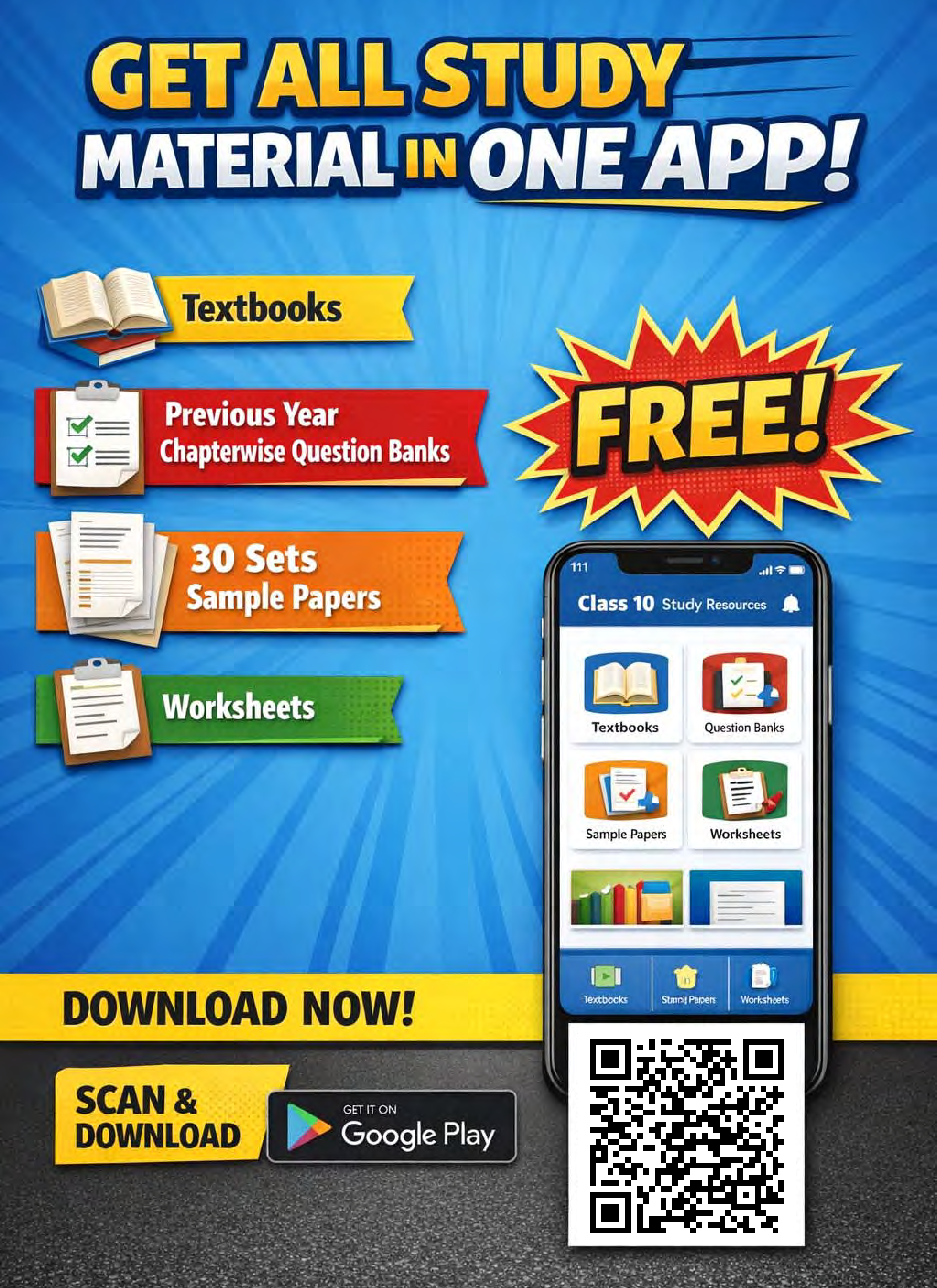
GET ALL STUDY MATERIAL IN ONE APP!
Textbooks
Previous Year Chapterwise Question Banks
30 Sets Sample Papers
Worksheets
FREE!
Class 10 Study Resources
Textbooks
Question Banks
Sample Papers
Worksheets
DOWNLOAD NOW!
SCAN & DOWNLOAD
GET IT ON Google Play

RSSB 2026
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

COMMON ELIGIBILITY TEST (CET)
GRADUATE LEVEL
समान पात्रता परीक्षा
स्नातक स्तर

PART 1
ECONOMICS
भाग 1
अर्थशास्त्र

अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक
नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार

Nodia

Downloaded from www.pdf.tube

RSSB CET स्नातक स्तर अर्थशास्त्र भाग 1
Edition July 2026
Published by :Nodia
An Imprint of NODIA EDITIONS LLP

इस पुस्तक में निहित जानकारी लेखक द्वारा ऐसे स्रोतों से प्राप्त की गई है जिन्हें विश्वसनीय माना गया है। तथापि, Nodia तथा इसके लेखक इस पुस्तक में दी गई किसी भी जानकारी की शुद्धता, पूर्णता अथवा अद्यतनता की कोई गारंटी नहीं देते हैं। इस पुस्तक में किसी प्रकार की त्रुटि, चूक अथवा इसमें निहित जानकारी के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानि के लिए Nodia तथा इसके लेखक उत्तरदायी नहीं होंगे। यह पुस्तक इस समझ के साथ प्रकाशित की गई है कि Nodia तथा इसके लेखक केवल सामान्य जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इसका उद्देश्य अभियांत्रिकी (Engineering) अथवा किसी अन्य व्यावसायिक या विशेषज्ञ सेवा अथवा परामर्श प्रदान करना नहीं है।

© NODIA EDITIONS LLP

MRP ₹500.00

NODIA

NODIA EDITIONS LLP
125, Sector 6, Vidyadhar Nagar, Jaipur 302039
Phone :+91 9001005245
email : mail@nodia.in

विषय-सूची

अध्याय 1.	बजट निर्माण प्रक्रिया	5
अध्याय 2.	बैंकिंग प्रणाली	21
अध्याय 3.	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	40
अध्याय 4.	राष्ट्रीय आय, वृद्धि एवं विकास	59
अध्याय 5.	राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति	78
अध्याय 6.	सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य	98
अध्याय 7.	कृषि उद्योग क्षेत्र : स्थिति, समस्याएँ एवं पहल	117
अध्याय 8.	सेवा व्यापार : क्षेत्र, वर्तमान स्थिति, समस्याएँ एवं पहल	135
अध्याय 9.	हरित, श्वेत एवं नीली क्रांति	154
अध्याय 10.	पंचवर्षीय योजनाएँ एवं नियोजन प्रणाली	171
अध्याय 11.	आर्थिक समस्याएँ, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण	189
अध्याय 12.	राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्यिक फसलें	209
अध्याय 13.	राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग	225
अध्याय 14.	राजस्थान के खनिज आधारित उद्योग	242
अध्याय 15.	राजस्थान की प्रमुख सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएँ	260

Click Here to Buy book on Amazon

अध्याय 16. बंजर भूमि एवं सूखा-प्रवण क्षेत्र विकास परियोजनाएँ 276

अध्याय 17. इंदिरा गांधी नहर परियोजना 294

अध्याय 18. राजस्थान में औद्योगिक विकास एवं उद्योगों का अवस्थिति 309

अध्याय 19. राजस्थान के लघु, कुटीर एवं ग्रामोद्योग 328

अध्याय 20. राजस्थान के निर्यात योग्य हस्तशिल्प 346

अध्याय 21. गरीबी : अवधारणा, प्रकार एवं कारण 365

अध्याय 22. बेरोज़गारी : अवधारणा, प्रकार एवं कारण 384

अध्याय 23. गरीबी एवं बेरोज़गारी के समाधान तथा वर्तमान प्रमुख सरकारी योजनाएँ 402

अध्याय 24. सामाजिक न्याय एवं कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण 420

अध्याय 25. कल्याणकारी योजनाएँ एवं विकास संस्थान 439

अध्याय 26. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 458

अध्याय 27. पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास 476

NODIA

****

अध्याय 01

बजट निर्माण प्रक्रिया

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, सरकारी बजट के लिए किस औपचारिक शब्द का प्रयोग किया जाता है?
(A) समेकित वित्तीय विवरण
(B) वार्षिक वित्तीय विवरण
(C) केंद्रीय वित्तीय बजट
(D) विनियोग एवं वित्त विवरण

2. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प संतुलित बजट का सर्वोत्तम वर्णन करता है?
(A) ऐसा बजट जहाँ कुल राजस्व प्राप्तियाँ कुल पूँजीगत व्यय से निश्चित रूप से अधिक होती हैं
(B) ऐसा बजट जहाँ राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटे के बराबर होता है
(C) ऐसा बजट जहाँ योजनेतर व्यय को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है
(D) ऐसा बजट जहाँ सरकार की अनुमानित कुल प्राप्तियाँ उसके अनुमानित कुल व्यय के बराबर होती हैं

3. लोक वित्त के संदर्भ में, अधिशेष बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है?
(A) यह समग्र माँग को कम करके अर्थव्यवस्था में संकुचनकारी भूमिका निभाता है
(B) यह आर्थिक मंदी के दौरान एक विस्तारवादी साधन के रूप में कार्य करता है
(C) इसमें माँग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अपने राजस्व से अधिक व्यय किया जाता है
(D) यह विकासशील देशों द्वारा अपनाया जाने वाला बजट का सबसे सामान्य रूप है

4. सरकारी बजट में निम्नलिखित में से कौन-सा पूँजीगत प्राप्तियों का उदाहरण है?
(A) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभांश
(B) स्पेक्ट्रम की नीलामी से प्राप्त आय
(C) सरकार द्वारा बाज़ार उधारों के माध्यम से जुटाई गई राशि
(D) आयकर और निगम कर से अर्जित आय

5. सरकारी बजट में प्राथमिक घाटे की गणना निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा की जाती है?
(A) राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
(B) राजस्व घाटा – पूँजीगत व्यय
(C) कुल व्यय – कुल प्राप्तियाँ
(D) राजकोषीय घाटा – राजस्व घाटा

6. बजट निर्माण प्रक्रिया के दौरान, मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने से पहले विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त बजट प्रस्तावों को कौन-सा निकाय समेकित करता है?
(A) भारतीय रिज़र्व बैंक
(B) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
(C) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(D) वित्त मंत्रालय

7. विकासशील अर्थव्यवस्था में घाटे की वित्त-व्यवस्था को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस आधार पर उचित ठहराया जाता है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन करने के लिए
(B) दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि के लिए उत्पादक निवेशों का वित्तपोषण करने के लिए
(C) कर राजस्व को पूरी तरह से संप्रभु उधारों द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए
(D) घरेलू मूल्य स्तरों को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीति को तेज़ी से रोकने के लिए

8. राजस्व प्राप्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. ये सरकार के लिए कोई तदनुरूपी देनदारी उत्पन्न नहीं करती हैं।
II. इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त आय शामिल होती है।
III. इनसे सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं आती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

9. संसदीय बजट प्रक्रिया में, विनियोग विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर नीतियों को पेश करना
(B) राजस्व साझाकरण के लिए क्षैतिज अंतरण सूत्र निर्धारित करना
(C) विगत प्रदर्शन से संबंधित आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना
(D) भारत की संचित निधि से धन की निकासी की अनुमति

Downloaded from www.pdf.tube

देना

10. बजट निर्माण की कौन-सी अवधारणा यह आवश्यकता प्रस्तुत करती है कि शून्य के आधार से शुरु करते हुए, प्रत्येक नई अवधि के लिए सभी खर्चों का औचित्य सिद्ध किया जाए?
(A) शून्य-आधारित बजट
(B) परिणाम-आधारित बजट
(C) निष्पादन बजट
(D) पूँजीगत बजट

11. निम्नलिखित में से कौन-सा आंतरिक सार्वजनिक ऋण की श्रेणी में नहीं आता है?
(A) भारतीय रिज़र्व बैंक को जारी किए गए ट्रेज़री बिल
(B) अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जारी किए गए संप्रभु बॉण्ड
(C) वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए बाज़ार ऋण
(D) लघु बचत योजनाओं के माध्यम से एकत्रित धन

12. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): विकासशील अर्थव्यवस्थाओं द्वारा आमतौर पर संतुलित बजट की तुलना में घाटे के बजट को प्राथमिकता दी जाती है।
कारण (R): विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अवसंरचना और कल्याणकारी कार्यों में अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होती है, जो अक्सर उनकी वर्तमान राजस्व सृजन क्षमता से अधिक होता है।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।

13. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करना था?
(A) सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य निर्धारित करना
(B) वार्षिक बजट से सभी पूँजीगत व्यय को समाप्त करना
(C) यह सुनिश्चित करना कि बाह्य ऋण नियमित रूप से आंतरिक ऋण से अधिक रहे
(D) लगातार पाँच वर्षों के लिए अधिशेष बजट लागू करना

14. भारत में किस वर्ष रेल बजट का प्रस्तुतीकरण केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था?
(A) 2015
(B) 2016
(C) 2017
(D) 2019

15. पूँजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसके फलस्वरुप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होता है।
II. इसमें वेतन और पेंशन के भुगतान पर होने वाला व्यय शामिल है।
III. इससे वित्तीय देनदारियों में कमी आती है, जैसे कि पुराने ऋणों का पुनर्भुगतान।
IV. यह आवर्ती प्रकृति का होता है और मुख्य रूप से दैनिक प्रशासन को बनाए रखता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और IV
(D) केवल III और IV

16. बजट की संसदीय स्वीकृति प्रक्रिया के संदर्भ में 'गिलोटिन' शब्द का क्या अर्थ है?
(A) लंबी विधायी बहस के बाद उच्च सदन द्वारा वार्षिक वित्त विधेयक को अस्वीकार कर देना
(B) वित्तीय वर्ष के अंत में अनुपयुक्त विभागीय आवंटन का स्वतः समाप्त हो जाना
(C) आवंटित समय समाप्त होने पर बिना किसी बहस के शेष अनुदान की मांगों पर एकमुश्त मतदान कराना
(D) राष्ट्रीय चुनाव चक्रों के दौरान नए कर प्रस्ताव लाने पर संवैधानिक प्रतिबंध

17. भारतीय बजट में योजनागत और गैर-योजनागत व्यय के बीच का अंतर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण था। केंद्रीय बजट में इस वर्गीकरण को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष समाप्त किया गया था?
(A) 2014-15
(B) 2017-18
(C) 2019-20
(D) 2021-22

18. संसद में बजट पारित होने के निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए:
I. विनियोग विधेयक का पारित होना
II. सामान्य चर्चा
III. बजट का प्रस्तुतीकरण
IV. अनुदान की मांगों पर मतदान
निम्नलिखित में से कौन-सा उपर्युक्त चरणों का सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाता है?
(A) III, II, IV, I
(B) III, IV, II, I
(C) II, III, I, IV
(D) III, II, I, IV

NODIA

19. निम्नलिखित में से कौन-सा संघ सरकार के लिए गैर-कर राजस्व का उदाहरण है?
(A) राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज
(B) सभी घरेलू क्षेत्रों से एकत्र किया गया व्यापक वस्तु एवं

सेवा कर
(C) राष्ट्रीय सीमा में आयातित वस्तुओं पर लगाया गया सीमा शुल्क
(D) व्यावसायिक संस्थाओं के शुद्ध लाभ पर लगाया गया निगम आय कर

20. वित्त विधेयक, जो भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए लाया जाता है, संसद में किस रूप में पेश किया जाता है?
(A) संविधान संशोधन विधेयक
(B) साधारण विधेयक
(C) धन विधेयक
(D) गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक

21. लगातार उच्च राजस्व घाटे का मुख्य आर्थिक प्रभाव क्या है?
(A) परिचालन संबंधी खर्चों के लिए उधार लेना, जिससे पूँजी निर्माण में कमी आती है
(B) आगामी पूँजीगत परियोजनाओं के लिए समर्पित अधिशेष राजकोषीय आरक्षित निधियों का संचयन होना
(C) एक ऐसी निरंतर आर्थिक अवधि में प्रवेश करना जो नकारात्मक उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति से चिह्नित हो
(D) बाह्य सार्वजनिक संप्रभु दायित्वों को घरेलू साख साधनों में परिवर्तित करना

22. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (घाटा सूचक)
P. राजस्व घाटा
Q. राजकोषीय घाटा
R. प्राथमिक घाटा
S. बजटीय घाटा
सूची II: (गणितीय परिभाषा)
1. कुल व्यय – कुल प्राप्तियाँ (उधारों को छोड़कर)
2. राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ
3. कुल व्यय – कुल प्राप्तियाँ
4. राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-3, R-4, S-1
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

23. भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं से प्राप्त ऋणों को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है?
(A) आंतरिक सार्वजनिक ऋण
(B) बाह्य सार्वजनिक ऋण
(C) राजस्व प्राप्तियाँ
(D) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

24. परिणाम-आधारित बजट का उद्देश्य बजटीय आवंटन को सख्ती से किसके साथ जोड़ना है?
(A) सभी सरकारी विभागों में ऐतिहासिक परिचालन व्यय पैटर्न से
(B) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाए गए आंतरिक बाज़ार ऋण की कुल मात्रा से
(C) स्पष्ट, मापने योग्य लक्ष्यों और परिभाषित निष्पादन परिणामों से
(D) कार्यपालक मंत्रालय के कुल प्रशासनिक तंत्र और कर्मचारियों के आकार से

25. भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह संघ और राज्यों के बीच करों के लंबवत अंतरण की सिफारिश करता है।
II. यह राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत हर पाँच साल में गठित एक वैधानिक निकाय है।
III. यह विभिन्न राज्यों के बीच संसाधनों को आवंटित करने के लिए क्षैतिज वितरण सूत्र निर्धारित करता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

26. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त आय को केंद्रीय बजट में किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है?
(A) गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ
(B) कर राजस्व प्राप्तियाँ
(C) गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ
(D) ऋण-सृजित पूँजीगत प्राप्तियाँ

27. सरकारी बजट में राजस्व वर्गीकरण के संदर्भ में विषम विकल्प की पहचान कीजिए:
(A) व्यक्तिगत वार्षिक आय पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष व्यक्तिगत आयकर
(B) सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त वार्षिक लाभांश भुगतान
(C) कंपनियों के शुद्ध परिचालन लाभ पर लगाया जाने वाला निगम कर
(D) लाभप्रद वित्तीय परिसंपत्तियों पर लगाया जाने वाला पूँजीगत लाभ कर

28. राजकोषीय घाटे को परिभाषित करने के उद्देश्य से कुल प्राप्तियों की गणना करते समय किस घटक को सख्ती से बाहर रखा जाता है?
(A) कर राजस्व
(B) बाज़ार उधार
(C) विनिवेश से प्राप्तियाँ
(D) ऋणों की वसूली

29. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): नई मुद्रा छापकर घाटे का मुद्रीकरण करने से

Click Here to Buy book on Flipkart

सरकारें आमतौर पर बचती हैं।
कारण (R): इससे मुद्रा आपूर्ति में अत्यधिक संकुचन होता है और गंभीर अवस्फीति पैदा होती है।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।

30. निम्नलिखित में से किस मद को ऐतिहासिक रूप से (वर्गीकरण के विलय से पूर्व) योजनेतर व्यय का एक प्रमुख घटक माना जाता था?
(A) राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के निर्माण के लिए पूँजीगत परिव्यय
(B) नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए अवसंरचना ढाँचा
(C) ऋण ब्याज भुगतान के साथ-साथ रक्षा राजस्व व्यय
(D) राज्य की योजनाओं के लिए वितरित केंद्र सरकार के वित्तीय अनुदान

31. सरकार द्वारा आंतरिक और बाह्य ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज के भुगतान को बजट में किसके अंतर्गत दर्ज किया जाता है?
(A) पूँजीगत व्यय
(B) पूँजीगत प्राप्तियाँ
(C) राजस्व प्राप्तियाँ
(D) राजस्व व्यय

32. सरकारी उधार के संदर्भ में, कौन-सी विधि घाटे की वित्त-व्यवस्था के सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारी रूप का प्रतिनिधित्व करती है?
(A) संस्थागत और खुदरा निवेशकों को दीर्घकालिक संप्रभु बॉण्ड जारी करना
(B) बहुपक्षीय बैंकिंग संस्थाओं से बाह्य ऋण सुविधाएँ प्राप्त करना
(C) केंद्रीय बैंक द्वारा प्रत्यक्ष मुद्रा सृजन के माध्यम से घाटे का मुद्रीकरण
(D) खुदरा लघु बचत प्रमाण पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक पूँजी का संचयन

33. सरकारी बजट के निर्माण और संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राजस्व बजट केवल सरकार के वर्तमान वित्तीय परिचालनों से संबंधित होता है।
II. पूँजीगत बजट में केवल वही लेन-देन शामिल होते हैं जो सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रभावित करते हैं।
III. राज्य सरकारों को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों को हमेशा पूँजीगत व्यय माना जाता है।
IV. केंद्र सरकार द्वारा ऋणों की वसूली एक पूँजीगत प्राप्ति है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल III
(C) केवल II और IV
(D) केवल III और IV

34. धनराशि जुटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संप्रभु बॉण्ड सीधे तौर पर देश के किस घटक में वृद्धि करेंगे?
(A) घरेलू बाज़ार उधार
(B) कुल कर राजस्व
(C) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
(D) बाह्य सार्वजनिक ऋण

35. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार को हस्तांतरित अधिशेष किसका हिस्सा होता है?
(A) गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ
(B) पूँजीगत राजस्व प्राप्तियाँ
(C) कर-आधारित राजस्व प्राप्तियाँ
(D) आंतरिक बाज़ार उधार

36. केंद्रीय बजट के प्रस्तुतीकरण को फरवरी के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 1 फरवरी करने के पीछे मुख्य तर्क क्या था?
(A) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग चक्रों को कैलेंडर वर्ष की अवधि के साथ जोड़ना
(B) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन ढाँचे के तहत अनिवार्य वैधानिक अनुपालन नियमों को पूरा करना
(C) 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले विधायी स्वीकृति प्रक्रिया को पूरा करना
(D) लोकसभा में अनिवार्य सामान्य चर्चा चरण को छोड़ना

37. अतीत के उधार निर्णयों के प्रभाव को पूरी तरह से अलग करते हुए, सरकार के वर्तमान राजकोषीय रुख का सबसे सटीक सूचक निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) प्राथमिक घाटा
(B) बजटीय घाटा
(C) राजकोषीय घाटा
(D) राजस्व घाटा

38. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (बजट से संबंधित शब्द)
P. विनिवेश
Q. घाटे की वित्त-व्यवस्था
R. वित्त विधेयक
S. विनियोग विधेयक
सूची II: (विवरण)
1. संचित निधि से धन निकालने का कानूनी प्राधिकरण
2. नए करों या कर परिवर्तनों के लिए विधायी प्रस्ताव
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी बेचना

Downloaded from www.pdf.tube

4. उधार या नई मुद्रा के माध्यम से राजकोषीय अंतर का वित्तपोषण करना

(A) P-3, Q-4, R-2, S-1
(B) P-4, Q-3, R-1, S-2
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

39. खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है?

(A) पूँजीगत प्राप्तियाँ
(B) राजस्व व्यय
(C) पूँजीगत व्यय
(D) राजस्व प्राप्तियाँ

40. संसद में प्रस्तुतीकरण से पहले बजट तैयारी चरण का सही क्रमिक क्रम चुनिए:

(A) वित्त मंत्रालय द्वारा परिपत्र जारी करना → मंत्रालयों द्वारा अनुमान प्रस्तुत करना → बजट-पूर्व बैठकें → वित्त मंत्रालय द्वारा समेकन → मंत्रिमंडल की मंजूरी
(B) मंत्रालयों द्वारा अनुमान प्रस्तुत करना → बजट-पूर्व बैठकें → वित्त मंत्रालय द्वारा परिपत्र जारी करना → मंत्रिमंडल की मंजूरी → वित्त मंत्रालय द्वारा समेकन
(C) वित्त मंत्रालय द्वारा परिपत्र जारी करना → बजट-पूर्व बैठकें → वित्त मंत्रालय द्वारा समेकन → मंत्रालयों द्वारा अनुमान प्रस्तुत करना → मंत्रिमंडल की मंजूरी
(D) मंत्रिमंडल की मंजूरी → वित्त मंत्रालय द्वारा परिपत्र जारी करना → मंत्रालयों द्वारा अनुमान प्रस्तुत करना → बजट-पूर्व बैठकें → वित्त मंत्रालय द्वारा समेकन

41. आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में संतुलित बजट को अक्सर एक दुर्लभ व्यावहारिक घटना क्यों माना जाता है?

(A) वैधानिक संवैधानिक जनादेश सरकारों को राजकोषीय घाटा प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करते हैं
(B) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन घाटे के बिना काम करने वाले देशों को दंडित करते हैं
(C) कुल राजस्व और व्यय को संतुलित करने से संरचनात्मक अति-मुद्रास्फीति चक्र शुरू हो जाते हैं
(D) अनुमानित राजस्व का वास्तविक व्यय से सटीक मिलान होना लगभग असंभव है

42. कर लगाने, समाप्त करने या उसमें संशोधन से संबंधित कोई भी प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लाया जाना चाहिए?

(A) वित्त विधेयक
(B) विनियोग विधेयक
(C) लेखानुदान
(D) अनुदान की माँग

43. निम्नलिखित में से किसे छोड़कर, अन्य सभी केंद्र सरकार की पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं?

(A) ट्रेज़री बिल जारी करके अल्पकालिक धन जुटाना
(B) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त लाभांश वितरण
(C) राज्य सरकारों द्वारा ऋण पुनर्भुगतान से मूल राशि की वसूली
(D) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय साख सुविधाएँ प्राप्त करना

NODIA

44. यदि सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा शून्य है, तो इसका तात्पर्य है कि:

(A) केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी नया उधार लेने से बचती है
(B) राजकोषीय घाटा पिछले उधारों पर ब्याज भुगतान के बराबर है
(C) संचित राजस्व घाटे को राज्य के खातों से पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है
(D) देश ने अपने बकाया बाह्य सार्वजनिक ऋण दायित्वों का पूरी तरह से निपटान कर दिया है

45. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।

अभिकथन (A): राजस्व व्यय की तुलना में पूँजीगत व्यय को अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक माना जाता है।

कारण (R): पूँजीगत व्यय से उत्पादक अवसंरचना और परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, जो भविष्य की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है।

(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।

46. किस अधिनियम के पारित हुए बिना किसी भी सरकारी व्यय के लिए भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता है?

(A) एक संविधान संशोधन अधिनियम
(B) एक वित्त अधिनियम
(C) एक विनियोग अधिनियम
(D) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम

47. "शून्य-आधारित बजट" की अवधारणा, जिसके तहत प्रबंधकों को अपने सभी बजटीय खर्चों का नए सिरे से औचित्य सिद्ध करना होता है, पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में किसके द्वारा विकसित की गई थी?

(A) जॉन मेनार्ड कीन्स
(B) मिल्टन फ्रीडमैन
(C) एडम स्मिथ
(D) पीटर पायर

48. राजस्व बजट को पूँजीगत बजट से अलग करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. राजस्व बजट गैर-देनदारी सृजित करने वाली प्राप्तियों से संबंधित है, जबकि पूँजीगत बजट देनदारी सृजित करने वाली प्राप्तियों या परिसंपत्ति-घटाने वाली प्राप्तियों से संबंधित है।
II. राजस्व व्यय के परिणामस्वरुप भौतिक परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है, जबकि पूँजीगत व्यय से होता है।
III. राष्ट्रीय सुरक्षा महत्व के कारण रक्षा पूँजीगत परिव्यय राजस्व बजट के अंतर्गत आता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

49. वित्त आयोग की भूमिका के संदर्भ में, 'क्षैतिज अंतरण' शब्द का तात्पर्य है:
(A) केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों का वितरण
(B) विभिन्न राज्यों के बीच करों के राज्यीय हिस्से का वितरण
(C) केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच निधियों का आवंटन
(D) भारतीय रिज़र्व बैंक से भारत सरकार को अधिशेष निधि का हस्तांतरण

50. भारतीय वायु सेना के लिए लड़ाकू विमानों की खरीद पर सरकार द्वारा किए गए व्यय को किस बजटीय शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है?
(A) रक्षा राजस्व व्यय
(B) योजनेतर राजस्व व्यय
(C) सामान्य सेवा व्यय
(D) रक्षा पूँजीगत व्यय

51. ट्रेज़री बिल अल्पकालिक उधार साधन हैं जिनका उपयोग मुख्य रुप से सरकार द्वारा अस्थायी तरलता असमानताओं को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। ये किसका हिस्सा हैं?
(A) आंतरिक सार्वजनिक ऋण
(B) बाह्य संप्रभु ऋण
(C) गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ
(D) पूँजीगत बजट व्यय

52. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (मद)
P. सरकारी कर्मचारियों का वेतन
Q. स्पेक्ट्रम नीलामी से प्राप्त आय
R. सरकार द्वारा पुराने ऋणों का पुनर्भुगतान
S. बाज़ार उधार

सूची II: (बजटीय वर्गीकरण)
1. पूँजीगत व्यय
2. पूँजीगत प्राप्ति
3. राजस्व व्यय
4. गैर-कर राजस्व प्राप्ति

(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-3, Q-2, R-1, S-4
(C) P-1, Q-4, R-3, S-2
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

53. निम्नलिखित में से कौन-सी 'राजकोषीय घाटे' की सबसे सटीक परिभाषा है?
(A) कुल व्यय − (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ)
(B) सकल वार्षिक बजटीय प्राप्तियाँ − कुल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय
(C) आवर्ती राजस्व व्यय − सकल वार्षिक कर एवं गैर-कर प्राप्तियाँ
(D) शुद्ध वार्षिक पूँजीगत व्यय − कुल गैर-उधार प्राप्तियाँ

54. लोकसभा में 'अनुदान की माँगें' मंत्रालयवार प्रस्तुत की जाती हैं। कौन-सा संवैधानिक अनुच्छेद स्पष्ट रूप से इन मांगों के प्रस्तुतीकरण को नियंत्रित करता है?
(A) अनुच्छेद 110
(B) अनुच्छेद 112
(C) अनुच्छेद 113
(D) अनुच्छेद 114

55. अधिशेष बजट संकुचनकारी राजकोषीय नीति का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से किस समष्टि आर्थिक परिदृश्य में सरकार द्वारा जानबूझकर अधिशेष बजट का अनुसरण करने की सबसे अधिक संभावना है?
(A) लंबे समय से चली आ रही औद्योगिक विकास स्थिरता के साथ उच्च प्रणालीगत बेरोजगारी
(B) अत्यधिक समग्र आर्थिक माँग से उत्पन्न अति-मुद्रास्फीति
(C) गंभीर आर्थिक मंदी जिसमें बड़े पैमाने पर सरकारी खर्च प्रोत्साहन की आवश्यकता हो
(D) निजी उद्यम पूँजी निर्माण और निवेश में तीव्र गिरावट

56. लोक वित्त के निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए:
I. एशियाई विकास बैंक से बहुपक्षीय ऋण
II. राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के माध्यम से जुटाई गई राशि
III. संप्रभु स्वर्ण बॉण्ड जारी करना
IV. दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से जुटाए गए बाज़ार ऋण

उपर्युक्त में से किसे/किन्हें सख्ती से 'आंतरिक सार्वजनिक ऋण' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है?
(A) केवल I, II और IV
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, III और IV
(D) I, II, III और IV

57. स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, खानों से प्राप्त रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क से सरकार के संग्रह को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है?
(A) अप्रत्यक्ष कर

Click Here to Buy book on Amazon

(B) कर राजस्व
(C) पूँजीगत प्राप्तियाँ
(D) गैर-कर राजस्व

58. राजकोषीय घाटे की गणना के निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए:
I. कुल राजस्व और गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ निर्धारित करना
II. ब्याज भुगतान घटाना
III. कुल व्यय की गणना करना
IV. राजकोषीय घाटे की गणना करना
प्राथमिक घाटे तक पहुँचने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा चरणों के सही तार्किक क्रम का प्रतिनिधित्व करता है?
(A) III, I, IV, II
(B) I, III, II, IV
(C) III, IV, I, II
(D) I, II, III, IV

59. अवसंरचना विकास के लिए जापानी सरकार के साथ द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्राप्त ऋणों को किस रूप में दर्ज किया जाता है?
(A) आंतरिक बाज़ार उधार
(B) बाह्य सार्वजनिक ऋण
(C) पूँजीगत व्यय
(D) विदेशी सहायता अनुदान

60. उच्च राजकोषीय घाटा अनिवार्य रूप से सरकार के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति को दर्शाता है?
(A) भविष्य के ऋण भुगतान और ब्याज दायित्वों में संरचनात्मक कमी
(B) बाज़ार उधार या घाटे की वित्त-व्यवस्था पर अधिक निर्भरता
(C) वार्षिक राजस्व खाते में तत्काल संरचनात्मक अधिशेष
(D) घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में स्वचालित वृद्धि (अधिमूल्यन)

61. भारतीय संविधान के तहत, कराधान प्रस्तावों वाले वित्त विधेयक को धन विधेयक माना जाता है। इस संदर्भ में, राज्यसभा इसके पारित होने में अधिकतम कितनी अवधि तक विलंब कर सकती है?
(A) 7 दिन
(B) 14 दिन
(C) 30 दिन
(D) 6 महीने

62. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का एक प्रमुख उद्देश्य शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करना है।
कारण (R): शून्य राजस्व घाटा यह सुनिश्चित करता है कि सरकार अपने दैनिक प्रशासनिक उपभोग को पूरा करने के लिए उधार का सहारा न ले।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।

NODIA

63. केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को पहले दिए गए ऋणों की वसूली को केंद्रीय बजट में किस रूप में शामिल किया जाता है?
(A) राजस्व प्राप्ति
(B) ऋण-सृजित पूँजीगत प्राप्ति
(C) पूँजीगत व्यय
(D) गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्ति

64. यदि कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम शुद्ध लाभ कमाता है और उसका एक हिस्सा भारत सरकार को वितरित करता है, तो यह लेन-देन बजट में कहाँ परिलक्षित होता है?
(A) विनिवेश के रूप में पूँजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत
(B) निगम कर के रूप में कर राजस्व के अंतर्गत
(C) लाभांश के रूप में गैर-कर राजस्व के अंतर्गत
(D) निवेश प्रतिफल के रूप में पूँजीगत व्यय के अंतर्गत

65. राजकोषीय अंतर को पूरा करने के लिए तदर्थ ट्रेज़री बिल जारी करके केंद्रीय बैंक से सीधे सरकार द्वारा उधार लेने की क्रिया को ऐतिहासिक रूप से क्या कहा जाता है?
(A) संप्रभु ऋण पुनर्गठन
(B) घाटे का मुद्रीकरण
(C) राजकोषीय अंतरण नीति
(D) संप्रभु ऋण व्यतिक्रम

66. जबकि शून्य-आधारित बजट प्रस्तावित व्यय के प्रत्येक रुपये का औचित्य सिद्ध करने पर केंद्रित है, परिणाम-आधारित बजट मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है?
(A) विनियोग विधेयक की सटीक कानूनी शब्दावली और धाराओं का विश्लेषण करने पर
(B) रेल बजट को सामान्य बजट ढाँचे में औपचारिक रूप से मिलाने पर
(C) वार्षिक घाटे के लक्ष्यों को संतुलित करने के लिए अनावश्यक पूँजीगत खर्च को कम करने पर
(D) व्यय के अंतिम परिणामों और भौतिक लक्ष्यों के अनुश्रवण पर

67. संसदीय बजट प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. बजट राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि पर वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है।
II. अनुदान की मांगों पर केवल लोकसभा में मतदान होता है, राज्यसभा में नहीं।
III. राज्यसभा के पास विनियोग विधेयक को अस्वीकार या

संशोधित करने की शक्ति है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

68. राजस्व घाटा सरकार के वित्तीय व्यवहार के बारे में गणितीय रूप से क्या दर्शाता है?

(A) सरकार के राजकोषीय आरक्षित कोष और शुद्ध बचत कुल मिलाकर अत्यधिक धनात्मक हैं
(B) पिछले रुझानों की तुलना में वार्षिक कर संग्रह असाधारण रूप से तेज़ी से बढ़ता है
(C) वर्तमान व्यय वर्तमान आवर्ती राजस्व से अधिक है
(D) पूँजीगत व्यय की वृद्धि पूँजीगत खाते की प्राप्तियों से काफी आगे निकल जाती है

69. राजस्व घाटे की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा सही सूत्र है?

(A) कुल राजस्व व्यय – कुल राजस्व प्राप्तियाँ
(B) कुल पूँजीगत व्यय – कुल पूँजीगत प्राप्तियाँ
(C) राजकोषीय घाटा – राजस्व व्यय
(D) प्राथमिक घाटा + ब्याज भुगतान

70. केंद्रीय बजट प्रस्तुतीकरण में लागू किए गए प्रमुख ऐतिहासिक परिवर्तनों का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन-सा है?

(A) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का अधिनियमन → रेल और सामान्य बजट का विलय → बजट प्रस्तुतीकरण को 1 फरवरी करना
(B) बजट प्रस्तुतीकरण को 1 फरवरी करना → रेल और सामान्य बजट का विलय → राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का अधिनियमन
(C) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का अधिनियमन → बजट प्रस्तुतीकरण को 1 फरवरी करना एवं रेल और सामान्य बजट का विलय
(D) रेल और सामान्य बजट का विलय → राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का अधिनियमन → बजट प्रस्तुतीकरण को 1 फरवरी करना

71. एक विकासशील अर्थव्यवस्था घाटे का बजट चलाने को मुख्य रूप से इसलिए उचित ठहराती है क्योंकि इससे:

(A) उपभोक्ता बाज़ारों में तेज़ी से मूल्य अवस्फीति होती है
(B) पूँजी निर्माण और अप्रयुक्त संसाधनों का संग्रहण होता है
(C) आयात शुल्कों का पूर्ण संरचनात्मक उन्मूलन होता है
(D) राष्ट्रीय मुद्रा आपूर्ति में तीव्र प्रणालीगत कमी आती है

72. सरकारी राजस्व के निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए:

I. सीमा शुल्क
II. ब्याज प्राप्तियाँ
III. निगम कर
IV. लाइसेंस शुल्क

केंद्रीय बजट में उपर्युक्त में से किसे/किन्हें सख्ती से 'कर राजस्व' के रूप में वर्गीकृत किया गया है?

(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल III और IV
(D) केवल I, III और IV

73. बाह्य सार्वजनिक ऋण को आंतरिक सार्वजनिक ऋण से क्या अलग करता है?

(A) बाह्य ऋण केवल राष्ट्रीय रक्षा खरीद आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुटाया जाता है
(B) बाह्य ऋण पर ऋण लेने वाले देश के लिए शून्य ब्याज दर की देनदारियाँ होती हैं
(C) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के तहत बाह्य ऋण कानूनी रूप से प्रतिबंधित है
(D) बाह्य ऋण में मुद्रा जोखिम और विदेशी मुद्रा पुनर्भुगतान देनदारियाँ शामिल होती हैं

74. यदि राज्यसभा वित्त विधेयक में किसी संशोधन की सिफारिश करती है, तो इसका प्रक्रियात्मक परिणाम क्या होगा?

(A) लोकसभा सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है
(B) कर प्रस्ताव विधेयक को तुरंत विधायी कार्यसूची से वापस लिया जाना चाहिए
(C) राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाना चाहिए
(D) प्रस्तावित संशोधन अंतिम रूप दिए गए कानून में स्वतः शामिल हो जाते हैं

75. पूँजीगत व्यय के रूप में इसके वर्गीकरण के संबंध में भिन्न विकल्प की पहचान कीजिए:

(A) एक नए राष्ट्रीय अस्पताल का निर्माण
(B) ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सब्सिडी का भुगतान
(C) एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान में इक्विटी शेयर खरीदना
(D) संप्रभु ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान

76. पिछली सरकारों के ऋण की विरासत की उपेक्षा करते हुए वर्तमान सरकार के राजकोषीय अनुशासन का आकलन करने के लिए, एक अर्थशास्त्री को सख्ती से किसका विश्लेषण करना चाहिए?

(A) राजस्व घाटा
(B) प्राथमिक घाटा
(C) प्रभावी राजस्व घाटा
(D) सकल राजकोषीय घाटा

77. लोक भविष्य निधि और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र से संग्रह भारत के लोक खाते के तहत शामिल किए जाते हैं। ये मूल रूप से सरकार के किस भाग का गठन करते हैं?

(A) आंतरिक सार्वजनिक ऋण

Downloaded from www.pdf.tube

(B) वार्षिक कर राजस्व
(C) प्रत्यक्ष पूँजीगत व्यय
(D) गैर-कर राजस्व प्राप्ति

78. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (बजटीय सूचक)
P. बढ़ता राजस्व घाटा
Q. शून्य प्राथमिक घाटा
R. उच्च पूँजीगत व्यय
S. बढ़ता बाज़ार उधार
सूची II: (आर्थिक प्रभाव)
1. बढ़ते अवसंरचना और परिसंपत्ति सृजन को दर्शाता है
2. बढ़ता राजकोषीय घाटा और निजी निवेश का निष्कासन
3. उधार ठीक ब्याज भुगतान दायित्वों के बराबर है
4. सरकार के नियमित दैनिक कामकाज का वित्तपोषण करने के लिए उधार का उपयोग
(A) P-4, Q-3, R-1, S-2
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-4, Q-1, R-3, S-2
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

79. संसद में बजट पारित होने के 'सामान्य चर्चा' चरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित है?
(A) सदस्यों का सामान्य आर्थिक सिद्धांतों पर भाषण देना
(B) चर्चा के अंत में वित्त मंत्री का उत्तर देना
(C) सरकार के राजकोषीय नीतिगत रुख पर चर्चा करना
(D) प्रस्तावित अनुदान राशियों को कम करने के लिए कटौती प्रस्ताव पेश करना

NODIA

80. नए रेल गलियारे के निर्माण के लिए धन के आवंटन को केंद्रीय बजट में किस रुप में दर्ज किया जाता है?
(A) पूँजीगत प्राप्ति
(B) राजस्व प्राप्ति
(C) पूँजीगत व्यय
(D) राजस्व व्यय

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) वार्षिक वित्तीय विवरण
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके स्थान पर आधिकारिक रुप से वार्षिक वित्तीय विवरण पद का प्रयोग हुआ है। यह विवरण आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्र सरकार की अनुमानित कुल प्राप्तियों तथा व्यय का व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत करता है। इसे राष्ट्रपति की सहमति से प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे।

2. (D) ऐसा बजट जहाँ सरकार की अनुमानित कुल प्राप्तियाँ उसके अनुमानित कुल व्यय के बराबर होती हैं
संतुलित बजट वह वित्तीय स्थिति है जिसमें किसी निश्चित वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार का अनुमानित कुल राजस्व उसकी कुल अनुमानित लागत या व्यय के पूर्णतः समतुल्य होता है। इस स्थिति में सरकार न तो कोई राजकोषीय घाटा दर्शाती है और न ही कोई वित्तीय अधिशेष उत्पन्न करती है। लोक वित्त में यह स्थिति यह संकेत देती है कि सरकार अपनी सीमाओं के भीतर कार्य कर रही है।

3. (A) यह समग्र माँग को कम करके अर्थव्यवस्था में संकुचनकारी भूमिका निभाता है
अधिशेष बजट तब होता है जब सरकार का कुल अनुमानित राजस्व उसके कुल अनुमानित व्यय से अधिक होता है। ऐसी स्थिति में सरकार अर्थव्यवस्था से कराधान के माध्यम से अधिक धन वापस लेती है और खर्च कम करती है, जिससे बाजार में कुल प्रभावी माँग घटती है। इसलिए इसे संकुचनकारी राजकोषीय नीति का साधन माना जाता है। इसका प्रयोग प्रायः अति-मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए होता है।

4. (C) सरकार द्वारा बाज़ार उधारों के माध्यम से जुटाई गई राशि
सरकारी बजट में पूँजीगत प्राप्तियाँ वे निधियाँ होती हैं जो या तो सरकार की देनदारियों में वृद्धि करती हैं अथवा उसकी परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं। बाजार उधार के अंतर्गत जुटाई गई राशि सरकार पर एक प्रत्यक्ष वित्तीय देनदारी उत्पन्न करती है, क्योंकि इसे भविष्य में ब्याज सहित पुनर्भुगतान करना आवश्यक होता है। अतः बाजार उधार को पूँजीगत प्राप्ति माना जाता है, जबकि कर राजस्व प्राप्ति है।

5. (A) राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की शुद्ध ऋण आवश्यकताओं को दर्शाता है। यह घाटा राजकोषीय घाटे में से विगत वर्षों के संचित ऋणों पर किए गए कुल ब्याज भुगतान को घटाकर प्राप्त किया जाता है। प्राथमिक घाटे की गणना से यह स्पष्ट होता है कि पिछले ऋणों की देनदारियों को हटाकर चालू वर्ष के सरकारी खर्चों को पूरा किया जा रहा है।

6. (D) वित्त मंत्रालय
भारत में केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग का बजट प्रभाग इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह प्रभाग विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त व्यय एवं राजस्व अनुमानों को समेकित करता है। तत्पश्चात, इसे मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी हेतु रखा जाता है।

7. (B) दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि के लिए उत्पादक निवेशों का वित्तपोषण करने के लिए
विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास में तेज़ी लाने के लिए बुनियादी ढाँचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं में भारी निवेश की आवश्यकता होती है। चूँकि ऐसे देशों में वर्तमान कर राजस्व सीमित होता है, इसलिए सरकारें घाटे की वित्त-व्यवस्था अपनाती हैं। इस प्रक्रिया में ली गई उधारी को उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण में लगाया जाता है। इससे दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है।

8. (C) केवल I और III
सरकारी बजट में राजस्व प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जो न तो सरकार की किसी देनदारी को बढ़ाती हैं और न ही उसकी किसी परिसंपत्ति को कम करती हैं। कर और गैर-कर राजस्व इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों के विनिवेश से प्राप्त धन पूँजीगत प्राप्ति की श्रेणी में आता है क्योंकि इससे सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है। अतः प्रथम और तृतीय कथन सत्य हैं।

9. (D) भारत की संचित निधि से धन की निकासी की अनुमति देना
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार, संसद की पूर्व कानूनी स्वीकृति के बिना भारत की संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता। विनियोग विधेयक का मुख्य उद्देश्य सरकार को अनुदान की मांगों और संचित निधि पर भारित व्यय को पूरा करने के लिए धन निकाले जाने का विधिक अधिकार प्रदान करना है। पारित होने पर ही निकासी संभव होती है।

10. (A) शून्य-आधारित बजट
शून्य-आधारित बजट निर्माण की एक आधुनिक तकनीक है, जिसमें प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष के बजट का निर्माण करते समय पिछले वर्षों के बजटीय आवंटन या आधार को पूरी तरह उपेक्षित कर दिया जाता है। प्रत्येक कार्यक्रम और व्यय मद का शून्य से प्रारंभ करके नए सिरे से औचित्य सिद्ध करना अनिवार्य होता है। इससे अनावश्यक खर्चों पर रोक लगती है और दक्षता बढ़ती है।

Click Here to Buy book on Flipkart

11. (B) अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जारी किए गए संप्रभु बॉण्ड
आंतरिक सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत वे सभी सरकारी ऋण आते हैं जो देश की भौगोलिक सीमा के भीतर नागरिकों, वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा केंद्रीय बैंक से जुटाए जाते हैं। ट्रेजरी बिल, बाज़ार उधार और लघु बचत इसके उदाहरण हैं। इसके विपरीत, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जारी किए गए संप्रभु बॉण्ड विदेशी क्षेत्राधिकार से संबंधित होने के कारण बाह्य ऋण की श्रेणी में आते हैं।

12. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक संवृद्धि, बुनियादी ढाँचे के विस्तार और सार्वजनिक कल्याण के लिए भारी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। चूँकि इन देशों में राजस्व आय कम होती है, इसलिए सरकारें संतुलित बजट के स्थान पर घाटे का बजट बनाना पसंद करती हैं। घाटे का वित्तपोषण करके सरकार उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करती है, जिससे दीर्घकालिक विकास को गति मिलती है। अतः कथन तथा कारण सत्य हैं।

13. (A) सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य निर्धारित करना
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2003 में लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में राजकोषीय अनुशासन स्थापित करना, अंतर-पीढ़ीगत समानता सुनिश्चित करना और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना है। यह कानून सरकार के लिए राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे को सीमित करने तथा सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन हेतु वैधानिक लक्ष्य निर्धारित करता है। यह पारदर्शिता बढ़ावा देता है।

14. (C) 2017
वर्ष 1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। लगभग 93 वर्षों तक अलग प्रस्तुत किए जाने के बाद, भारत सरकार ने वर्ष 2017 में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए रेल बजट का विलय केंद्रीय बजट में कर दिया। वित्तीय वर्ष 2017-18 से रेल बजट को केंद्रीय बजट का अंग बना दिया गया।

15. (B) केवल I और III
पूँजीगत व्यय ऐसा सरकारी व्यय है जो या तो भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण करता है (जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़क निर्माण) अथवा वित्तीय देनदारियों में कमी लाता है (जैसे पुराने ऋणों का पुनर्भुगतान)। इसके विपरीत, वेतन, पेंशन तथा दैनिक प्रशासनिक खर्च गैर-परिसंपत्ति निर्माणकारी व्यय होते हैं, जिन्हें राजस्व व्यय माना जाता है। अतः प्रथम और तृतीय कथन ही पूर्णतः सही हैं।

16. (C) आवंटित समय समाप्त होने पर बिना किसी बहस के शेष अनुदान की मांगों पर एकमुश्त मतदान कराना
संसदीय बजट प्रक्रिया में 'गिलोटिन' एक विशेष प्रक्रियात्मक साधन है। लोकसभा में अनुदान की मांगों पर चर्चा के लिए एक निश्चित समय सीमा आवंटित की जाती है। जब निर्धारित समय समाप्त हो जाता है और कई मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा होना शेष रह जाता है, तब अध्यक्ष महोदय बिना किसी बहस के उन सभी बची हुई मांगों पर एकमुश्त मतदान करा देते हैं।

17. (B) 2017-18
ऐतिहासिक रूप से, भारत के सरकारी व्यय को योजनागत व्यय और गैर-योजनागत व्यय में विभाजित किया जाता था। नीति आयोग के गठन और पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति के बाद, राजकोषीय प्रबंधन को सरल बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 से केंद्रीय बजट में इस वर्गीकरण को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अब केवल राजस्व और पूँजीगत व्यय का वर्गीकरण लागू रहता है।

18. (A) III, II, IV, I
भारतीय संसद में बजट पारित होने का एक निश्चित कालानुक्रमिक क्रम होता है। सर्वप्रथम वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में बजट का प्रस्तुतीकरण किया जाता है। इसके पश्चात् बजट के सामान्य सिद्धांतों पर सामान्य चर्चा आयोजित की जाती है। तत्पश्चात् विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान की मांगों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न होती है। अंत में संचित निधि हेतु विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।

NODIA

19. (A) राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज
केंद्र सरकार के राजस्व को कर राजस्व और गैर-कर राजस्व में वर्गीकृत किया जाता है। कर राजस्व में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर (जैसे निगम कर, जीएसटी और सीमा शुल्क) शामिल होते हैं। दूसरी ओर, गैर-कर राजस्व में सरकार द्वारा दी गई सेवाओं का शुल्क, लाभांश तथा दिए गए ऋणों पर प्राप्त होने वाला ब्याज शामिल होता है। अतः ब्याज गैर-कर प्राप्ति का उदाहरण है।

20. (C) धन विधेयक
वार्षिक बजट प्रक्रिया के भाग के रूप में प्रस्तुत वित्त विधेयक भारत सरकार के कराधान संबंधी प्रस्तावों को लागू करने के लिए लाया जाता है। चूँकि इसमें कर लगाने, हटाने या संशोधन करने से संबंधित प्रावधान होते हैं, इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार इसे धन विधेयक माना जाता है। इस पर लोकसभा का विशेष अधिकार होता है और प्रधानता रहती है।

21. (A) परिचालन संबंधी खर्चों के लिए उधार लेना, जिससे पूँजी निर्माण में कमी आती है
राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार का दैनिक आवर्ती व्यय उसकी प्राप्तियों से अधिक हो जाता है। जब सरकार लगातार उच्च राजस्व घाटा दर्ज करती है, तो उसे परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ता है। इस तरह ली गई उधारी से किसी भी नई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता। परिणामस्वरूप, पूँजी निर्माण और विकास कार्यों में कमी आती है।

22. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
लोक वित्त में विभिन्न घाटा सूचकांकों की गणितीय परिभाषाएं अलग हैं। राजस्व घाटा कुल राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर होता है। राजकोषीय घाटा उधारियों को छोड़कर कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर है, जो ऋण आवश्यकता दर्शाता है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से ब्याज घटाकर प्राप्त होता है। बजटीय घाटा कुल व्यय और प्राप्तियों का अंतर प्रस्तुत करता है।

23. (B) बाह्य सार्वजनिक ऋण
जब भारत सरकार विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं या विदेशी सरकारों से विकास परियोजनाओं के लिए ऋण प्राप्त करती है, तो ऐसे दायित्वों को बाह्य सार्वजनिक ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये ऋण देश की सीमाओं के बाहर की संस्थाओं से प्राप्त होते हैं और इनका पुनर्भुगतान विदेशी मुद्रा जोखिम से युक्त होता है।

24. (C) स्पष्ट, मापने योग्य लक्ष्यों और परिभाषित निष्पादन परिणामों से
परिणाम-आधारित बजट प्रबंधन का एक ऐसा बजटीय दृष्टिकोण है जो केवल निधियों के आवंटन और व्यय पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बजटीय आवंटन को स्पष्ट, मापने योग्य भौतिक लक्ष्यों और अंतिम परिणामों के साथ सीधे जोड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह मूल्यांकन करना है कि सरकारी खर्च से वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं। यह जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

25. (C) केवल I और III
वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है, न कि वैधानिक निकाय। यह राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में गठित किया जाता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के लंबवत अंतरण की सिफारिश करना है। साथ ही, यह विभिन्न राज्यों के बीच क्षैतिज वितरण का सूत्र भी निर्धारित करता है। अतः विकल्प सत्य है।

26. (A) गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी शेयरधारिता बेचने या विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि को गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्ति माना जाता है। यह पूँजीगत प्राप्ति इसलिए है क्योंकि इससे सरकारी परिसंपत्तियों में कमी आती है। लेकिन यह गैर-ऋण प्रकृति की है, क्योंकि इससे सरकार पर कोई नया ऋण या पुनर्भुगतान का वित्तीय दायित्व नहीं बनता है। अतः यह गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्ति है।

27. (B) सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त वार्षिक लाभांश भुगतान
सरकारी बजट में राजस्व प्राप्तियों को कर राजस्व और गैर-कर राजस्व में विभाजित किया जाता है। व्यक्तिगत आयकर, निगम कर और पूँजीगत लाभ कर तीनों ही कर राजस्व के उदाहरण हैं। इसके विपरीत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त वार्षिक लाभांश गैर-कर राजस्व की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह निवेश पर प्रतिफल होता है। इसलिए यह अन्य विकल्पों से भिन्न है।

28. (B) बाज़ार उधार
राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और गैर-ऋण प्राप्तियों का अंतर होता है। इसकी गणना करते समय कुल प्राप्तियों में कर, गैर-कर, ऋण वसूली तथा विनिवेश आय शामिल की जाती है, परंतु बाज़ार उधार को बाहर रखा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राजकोषीय घाटा स्वयं सरकार की उधार लेने की कुल ज़रूरत का माप होता है। अतः उधार को घटाया जाता है।

29. (C) अभिकथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
घाटे का मुद्रीकरण करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा नई मुद्रा छापना जोखिम भरा कदम है, इसलिए सरकारें इससे बचती हैं। इसका कारण यह है कि नई मुद्रा के प्रवाह से मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, न कि घटती है। इससे बाज़ार में तीव्र मुद्रास्फीति पैदा होती है। इस प्रकार अभिकथन सही है परंतु दिया गया कारण तथ्यात्मक दृष्टि से पूर्णतः गलत और अस्वीकार्य है।

30. (C) ऋण ब्याज भुगतान के साथ-साथ रक्षा राजस्व व्यय
वर्ष 2017-18 से पूर्व बजटीय व्यय को योजनागत और योजनेतर भागों में विभाजित किया जाता था। योजनेतर व्यय के अंतर्गत वे अनिवार्य खर्चे आते थे जो योजनाओं से संबंधित नहीं थे। इसमें ब्याज भुगतान, रक्षा राजस्व व्यय, पेंशन तथा सब्सिडी शामिल थे। अवसंरचना निर्माण जैसे कार्य योजनागत व्यय के अधीन आते थे। अतः ब्याज तथा रक्षा व्यय योजनेतर मद के उदाहरण हैं।

31. (D) राजस्व व्यय
सरकार द्वारा अपनी आंतरिक और बाह्य उधारी पर दिया जाने वाला ब्याज भुगतान एक नियमित और आवर्ती वित्तीय दायित्व है। ब्याज का यह भुगतान न तो सरकार की किसी परिसंपत्ति का निर्माण करता है और न ही इससे मूल ऋण कम होता है। इसलिए लोक वित्त के नियमानुसार, सरकार द्वारा दिए जाने वाले ब्याज भुगतान को राजस्व व्यय के अंतर्गत रखा जाता है।

32. (C) केंद्रीय बैंक द्वारा प्रत्यक्ष मुद्रा सृजन के माध्यम से घाटे का मुद्रीकरण
घाटे की वित्त-व्यवस्था के विभिन्न तरीकों में केंद्रीय बैंक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नई मुद्रा छापकर घाटे का मुद्रीकरण करना सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारी माना जाता है। जब केंद्रीय बैंक नई मुद्रा बनाकर सरकारी खर्चों को पूरा करता है, तो उत्पादन बढ़े बिना ही मुद्रा आपूर्ति तेज़ी से बढ़ जाती है। इससे बाजार में मूल्य स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है। अतः यह जोखिमपूर्ण है।

NODIA

33. (B) केवल III
राजस्व बजट सरकार के वर्तमान वित्तीय परिचालनों से संबंधित होता है, जबकि पूँजीगत बजट परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रभावित करता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान राजस्व व्यय माने जाते हैं, न कि पूँजीगत व्यय। ऋण की वसूली पूँजीगत प्राप्ति है। इस प्रकार तृतीय कथन गलत है तथा अन्य सभी कथन पूर्णतः सत्य तथा उचित हैं।

34. (D) बाह्य सार्वजनिक ऋण
जब भारत सरकार अपनी बजटीय आवश्यकताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाज़ारों में संप्रभु बॉण्ड जारी करके विदेशी मुद्रा में धन जुटाती है, तो यह देश के बाह्य सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करता है। यह ऋण विदेशी निवेशकों तथा संस्थाओं का दायित्व होता है और इसे विदेशी मुद्रा में पुनर्भुगतान करना पड़ता है। अतः यह बाह्य सार्वजनिक ऋण का भाग बनता है।

35. (A) गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ
भारतीय रिज़र्व बैंक एक स्वायत्त केंद्रीय बैंक है जो अपने निवेशों और वित्तीय परिचालनों से लाभ अर्जित करता है। रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार, यह अपने वार्षिक अधिशेष लाभ का एक हिस्सा भारत सरकार को हस्तांतरित करता है। चूँकि यह राशि किसी कर द्वारा नहीं आती, इसलिए इसे केंद्रीय बजट में गैर-कर राजस्व प्राप्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

36. (C) 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले विधायी स्वीकृति प्रक्रिया को पूरा करना
पूर्व में केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम दिन प्रस्तुत होता था, जिससे बजट मई तक पारित हो पाता था। इस विलंब को दूर करने तथा 1 अप्रैल से शुरु होने वाले वित्तीय वर्ष से पहले ही समस्त संसदीय स्वीकृति प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु बजट प्रस्तुतीकरण 1 फरवरी किया गया। इससे वित्तीय वर्ष के आरंभ से ही धन उपलब्ध हो जाता है।

37. (A) प्राथमिक घाटा
प्राथमिक घाटा किसी देश की सरकार के वर्तमान राजकोषीय नीतिगत रुख का सबसे सटीक मापक माना जाता है। इसकी गणना राजकोषीय घाटे में से अतीत के ऋणों पर किए गए ब्याज भुगतान को घटाकर की जाती है। चूंकि ब्याज भुगतान पुराने ऋणों का नतीजा है, इसलिए इसे हटाने से वर्तमान सरकार का वास्तविक राजकोषीय अनुशासन स्पष्ट दिखाई देता है तथा सटीक जानकारी मिलती है।

38. (A) P-3, Q-4, R-2, S-1
बजट से संबंधित शब्दावली में प्रत्येक पद का विशिष्ट अर्थ है। विनिवेश का तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने से है। घाटे की वित्त-व्यवस्था का अर्थ उधारी या नई मुद्रा से राजकोषीय अंतर को पूरा करना है। वित्त विधेयक कर प्रस्तावों से संबंधित होता है, जबकि विनियोग विधेयक संचित निधि से धन निकासी का कानूनी अधिकार प्रदान करता है।

39. (B) राजस्व व्यय
खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों में सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी सहायता प्रदान करना तथा आम जनता को किफायती दरों पर वस्तुएं उपलब्ध कराना है। सब्सिडी पर होने वाला यह खर्च आवर्ती प्रकृति का होता है और इससे सरकार की किसी भी प्रकार की स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। अतः इसे राजस्व व्यय माना जाता है।

40. (A) वित्त मंत्रालय द्वारा परिपत्र जारी करना → मंत्रालयों द्वारा अनुमान प्रस्तुत करना → बजट-पूर्व बैठकें → वित्त मंत्रालय द्वारा समेकन → मंत्रिमंडल की मंजूरी
भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया एक चरणबद्ध प्रणाली का पालन करती है। सबसे पहले वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों को बजटीय अनुमान हेतु परिपत्र जारी करता है। इसके बाद विभिन्न मंत्रालय अपने अनुमान प्रस्तुत करते हैं। तत्पश्चात् वित्त मंत्रालय बजट-पूर्व बैठकें करके समग्र समेकन करता है। अंत में, संसद में प्रस्तुतीकरण से पूर्व मंत्रिमंडल की औपचारिक स्वीकृति ली जाती है।

41. (D) अनुमानित राजस्व का वास्तविक व्यय से सटीक मिलान होना लगभग असंभव है
व्यवहार में किसी आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए पूर्णतः संतुलित बजट प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि बजट भविष्य के अनुमानों पर आधारित होता है। बाज़ार की अनिश्चितताओं, व्यापक आर्थिक उतार-चढ़ाव, कर संग्रह में अंतर तथा अचानक आने वाली आपात स्थितियों के कारण वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का सटीक मिलान होना व्यावहारिक रूप से असंभव होता है।

42. (A) वित्त विधेयक
भारतीय संविधान के तहत सरकार द्वारा किसी भी नए कर को लगाने, मौजूदा कर की दरों में बदलाव करने, उसे समाप्त करने या कर संरचना में किसी संशोधन से संबंधित प्रस्तावों को संसद के समक्ष वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया जाता है। वित्त विधेयक को वार्षिक बजट प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग माना जाता है। इसके बिना कराधान अवैध है।

43. (B) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त लाभांश वितरण
केंद्र सरकार की पूँजीगत प्राप्तियाँ वे निधियाँ हैं जो या तो देनदारी बढ़ाती हैं या परिसंपत्तियों को कम करती हैं। ट्रेजरी बिलों से उधारी, ऋणों की मूल वसूली और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ली गई साख सुविधाएँ पूँजीगत प्राप्तियाँ हैं। इसके विपरीत, सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभांश निवेश पर अर्जित आय होती है। अतः यह गैर-कर राजस्व प्राप्ति की श्रेणी में आता है।

44. (B) राजकोषीय घाटा पिछले उधारों पर ब्याज भुगतान के बराबर है
प्राथमिक घाटे का सूत्र राजकोषीय घाटा घटाव ब्याज भुगतान होता है। यदि सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा शून्य के बराबर है, तो इसका स्पष्ट निष्कर्ष यह होता है कि उस वर्ष का संपूर्ण राजकोषीय घाटा केवल अतीत में लिए गए ऋणों के ब्याज भुगतान की देनदारियों के बराबर है। वर्तमान चालू वर्ष का प्राथमिक खर्च राजस्व से संतुलित हो चुका है।

45. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
राजस्व व्यय उपभोग प्रकृति का होता है जो दैनिक प्रशासन, वेतन और सब्सिडी में खर्च होता है तथा इससे कोई स्थायी संपत्ति नहीं बनती। इसके विपरीत, पूँजीगत व्यय सड़कों, पुलों,

Downloaded from www.pdf.tube

अस्पतालों और उद्योगों जैसे उत्पादक ढाँचे और परिसंपत्तियों का निर्माण करता है। यह निर्माण दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देता है। अतः अभिकथन तथा कारण दोनों ही सत्य हैं और सही व्याख्या प्रस्तुत करते हैं।

46. (C) एक विनियोग अधिनियम
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि संसद द्वारा विधिवत रूप से विनियोग अधिनियम पारित किए बिना भारत की संचित निधि से कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती। अनुदान की मांगें स्वीकृत होने के बाद उन्हें विनियोग विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति से यह अधिनियम बन जाता है।

47. (D) पीटर पायर
बजट निर्माण में शून्य-आधारित बजट की अवधारणा का विकास सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में पीटर पायर द्वारा किया गया था। उन्होंने एक निजी कंपनी में इस बजटीय दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक लागू किया था। बाद में जिमी कार्टर ने इसे अमरीका के संघीय शासन में व्यापक रूप से लागू किया। इस तकनीक में प्रत्येक खर्च का शून्य से औचित्य सिद्ध किया जाता है।

48. (A) केवल I और II
राजस्व बजट गैर-देनदारी प्राप्तियों और गैर-परिसंपत्ति व्यय से संबंधित होता है, जबकि पूँजीगत बजट देनदारी बढ़ाने या परिसंपत्ति घटाने वाली प्राप्तियों और भौतिक परिसंपत्तियों का निर्माण करने वाले व्यय से संबंधित है। रक्षा पूँजीगत परिव्यय को पूँजीगत बजट के अंतर्गत ही रखा जाता है, न कि राजस्व बजट में। इसलिए प्रथम तथा द्वितीय कथन सत्य हैं जबकि तृतीय कथन गलत है।

49. (B) विभिन्न राज्यों के बीच करों के राज्यीय हिस्से का वितरण
वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में अंतरण के दो आयाम होते हैं। लंबवत अंतरण का अर्थ केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा होता है। वहीं क्षैतिज अंतरण का तात्पर्य विभिन्न राज्यों के बीच करों के राज्यों के हिस्से के वितरण से है। इसके लिए जनसंख्या, क्षेत्रफल तथा आय असमता जैसे मापदंडों का उपयोग किया जाता है। यह संतुलित विकास लाता है।

50. (D) रक्षा पूँजीगत व्यय
भारतीय वायु सेना के लिए लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों तथा सैन्य उपकरणों की खरीद एक दीर्घकालिक परिसंपत्ति का निर्माण करती है। यह व्यय देश की सुरक्षा क्षमता को मजबूत बनाता है। चूंकि सैन्य सामग्री और विमानों का क्रय परिसंपत्ति सृजन है, इसलिए इसे केंद्रीय बजट के अंतर्गत रक्षा पूँजीगत व्यय की श्रेणी में रखा जाता है। वेतन आदि राजस्व व्यय में आते हैं।

51. (A) आंतरिक सार्वजनिक ऋण
ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा अपनी अल्पकालिक तरलता असमानताओं को पूरा करने के लिए जारी किए जाने वाले ऋण साधन हैं। इनकी परिपक्वता अवधि 364 दिनों से कम होती है। चूँकि ये प्रतिभूतियाँ देश की घरेलू सीमाओं के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से बैंकों तथा निवेशकों को जारी की जाती हैं, इसलिए ये आंतरिक सार्वजनिक ऋण का भाग बनते हैं।

52. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
बजटीय मदों का सही वर्गीकरण इस प्रकार है: कर्मचारियों का वेतन राजस्व व्यय होता है। स्पेक्ट्रम नीलामी आय गैर-कर राजस्व प्राप्ति है। पुराने ऋणों का पुनर्भुगतान देनदारी कम करता है, अतः यह पूँजीगत व्यय है। बाज़ार उधार देनदारी बढ़ाता है, जिससे यह पूँजीगत प्राप्ति की श्रेणी में शामिल होता है। इस प्रकार सभी मदें सटीक रूप से सुमेलित की गई हैं।

53. (A) कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ)
राजकोषीय घाटे की सब्सिडीयुक्त परिभाषा यह है कि यह किसी वित्तीय वर्ष में सरकार के कुल व्यय तथा उसकी कुल गैर-ऋण प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियाँ तथा गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश) के बीच का अंतर होता है। यह घाटा सीधे तौर पर उस कुल धनराशि का प्रतिनिधित्व करता है जिसे सरकार को उधार लेना पड़ता है। अतः यह सटीक सूत्र दर्शाता है।

54. (C) अनुच्छेद 113
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 113 बजट प्रक्रिया में अनुदान की मांगों से संबंधित प्रावधानों को नियंत्रित करता है। इसके अनुसार, भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय के अनुमान लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांगों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। लोकसभा को इन मांगों पर स्वीकृति देने या राशि कम करने का अधिकार प्राप्त होता है। यह संवैधानिक नियम है।

55. (B) अत्यधिक समग्र आर्थिक माँग से उत्पन्न अति-मुद्रास्फीति
अधिशेष बजट एक संकुचनकारी राजकोषीय नीति का प्रतीक है, जहाँ सरकार का राजस्व उसके कुल व्यय से अधिक होता है। जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक माँग के कारण तीव्र मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, तब सरकार अधिशेष बजट अपनाती है। कर बढ़ाकर और सरकारी खर्च घटाकर बाज़ार में उपलब्ध तरलता को कम किया जाता है। इससे माँग घटती है और मुद्रास्फीति शांत होती है।

56. (B) केवल II, III और IV
आंतरिक सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत सरकार के वे सभी वित्तीय दायित्व आते हैं जो देश के भीतर से जुटाए जाते हैं। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, संप्रभु स्वर्ण बॉण्ड तथा दिनांकित प्रतिभूतियाँ आंतरिक सार्वजनिक ऋण के उदाहरण हैं। दूसरी ओर, एशियाई विकास बैंक जैसे संस्थानों से लिया गया ऋण बाह्य ऋण की श्रेणी में आता है। अतः द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ विकल्प सही हैं।

57. (D) गैर-कर राजस्व
सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कर और गैर-कर राजस्व शामिल होते हैं। स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, खानों से प्राप्त रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क तथा सेवा शुल्क जैसी राशियाँ कर नहीं हैं। ये राशियाँ

NODIA

सरकार द्वारा अपनी परिसंपत्तियों अथवा विशिष्ट सेवाओं के उपयोग की अनुमति देने के बदले ली जाती हैं। इसलिए, इन्हें बजट में गैर-कर राजस्व संग्रह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

58. (A) III, I, IV, II
प्राथमिक घाटे तक पहुँचने की तार्किक प्रक्रिया में सर्वप्रथम कुल व्यय का निर्धारण किया जाता है। इसके पश्चात कुल राजस्व तथा गैर-ऋण प्राप्तियों का आकलन होता है। कुल व्यय में से गैर-ऋण प्राप्तियाँ घटाकर राजकोषीय घाटा निकलता है। अंत में, राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। अतः क्रम पूर्णतः सटीक और तार्किक है।

59. (B) बाह्य सार्वजनिक ऋण
जब भारत सरकार द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत किसी विदेशी सरकार से अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए ऋण प्राप्त करती है, तो ऐसे दायित्वों को बाह्य सार्वजनिक ऋण के रूप में दर्ज किया जाता है। यह ऋण विदेशी संस्था से संप्रभु स्तर पर लिया जाता है और इसे तय शर्तों पर चुकाना होता है। अतः यह बाह्य सार्वजनिक ऋण का उदाहरण है।

60. (B) बाज़ार उधार या घाटे की वित्त-व्यवस्था पर अधिक निर्भरता
राजकोषीय घाटा सरकार की कुल व्यय आवश्यकताओं और उसकी गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच के अंतर को दर्शाता है। एक उच्च राजकोषीय घाटा यह स्पष्ट संकेत देता है कि सरकार का राजस्व उसके खर्चों की तुलना में कम है। ऐसी स्थिति में बजटीय घाटे को भरने के लिए सरकार को बाज़ार उधार या घाटे की वित्त-व्यवस्था पर अत्यधिक निर्भर होना पड़ता है।

61. (B) 14 दिन
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 और 110 के अनुसार कराधान प्रस्तावों वाले वित्त विधेयक को धन विधेयक माना जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है। लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद इसे राज्यसभा को भेजा जाता है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्यसभा इसे केवल अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, तत्पश्चात् यह पारित माना जाता है।

62. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार का दैनिक प्रशासनिक व्यय उसके राजस्व से अधिक होता है। शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करना विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य होता है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार दैनिक उपभोग व्यय हेतु उधार नहीं ले रही है। उधार का उपयोग केवल पूँजी निर्माण में होता है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं।

63. (D) गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्ति
जब केंद्र सरकार राज्य सरकारों को दिए गए पुराने ऋणों के मूलधन की वसूली करती है, तो यह प्राप्त राशि बजट के पूँजीगत खाते में दर्ज होती है। यह पूँजीगत प्राप्ति इसलिए है क्योंकि ऋण वसूली से सरकार की वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी आती है। चूँकि इससे सरकार पर कोई नया ऋण नहीं बनता, इसलिए इसे गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्ति माना जाता है।

64. (C) लाभांश के रूप में गैर-कर राजस्व के अंतर्गत
जब किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को वार्षिक परिचालन से लाभ प्राप्त होता है और वह उस लाभ का एक हिस्सा सरकार को वितरित करता है, तो इसे लाभांश कहा जाता है। सरकारी बजट में लाभांश प्राप्तियों को गैर-कर राजस्व के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह निवेश पर प्राप्त आय है, जो कराधान से अलग होती है।

65. (B) घाटे का मुद्रीकरण
ऐतिहासिक रूप से जब सरकार के कुल व्यय और प्राप्तियों का अंतर बढ़ जाता था, तो राजकोषीय अंतर को भरने के लिए सरकार तदर्थ ट्रेजरी बिल जारी करके केंद्रीय बैंक से सीधे उधार लेती थी। इस प्रक्रिया को घाटे का मुद्रीकरण कहा जाता था। इसके तहत केंद्रीय बैंक नई मुद्रा छापकर सरकारी ऋणों का वित्तपोषण करता था, जिससे तरलता बढ़ती थी।

66. (D) व्यय के अंतिम परिणामों और भौतिक लक्ष्यों के अनुश्रवण पर
बजटीय प्रबंधन की विभिन्न तकनीकों के अपने अलग-अलग प्राथमिक लक्ष्य होते हैं। जहाँ शून्य-आधारित बजट प्रत्येक खर्च का औचित्य सिद्ध करने पर केंद्रित होता है, वहीं परिणाम-आधारित बजट का मुख्य ध्यान आवंटित निधियों के उपयोग से प्राप्त होने वाले अंतिम परिणामों और भौतिक लक्ष्यों के अनुश्रवण पर होता है। यह प्रणाली जमीनी स्तर पर वास्तविक और मापने योग्य लाभ सुनिश्चित करती है।

67. (A) केवल I और II
संसदीय बजट प्रक्रिया में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि पर वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में बजट पेश होता है। अनुदान की मांगों पर केवल लोकसभा में मतदान होता है। राज्यसभा के पास अनुदान मांगों पर मतदान का अधिकार नहीं है। इसके अलावा, राज्यसभा विनियोग विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती, वह केवल सिफारिशें दे सकती है। अतः पहला तथा दूसरा कथन सत्य है।

68. (C) वर्तमान व्यय वर्तमान आवर्ती राजस्व से अधिक है
राजस्व घाटा सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण सूचक है। गणितीय रूप से यह तब उत्पन्न होता है जब सरकार का कुल आवर्ती राजस्व व्यय उसकी कुल आवर्ती राजस्व प्राप्तियों की तुलना में अधिक हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि सरकार की नियमित वार्षिक आय उसके सामान्य प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने में असमर्थ है, जिससे ऋण की ज़रूरत बढ़ती है।

69. (A) कुल राजस्व व्यय – कुल राजस्व प्राप्तियाँ
सरकारी बजट में राजस्व घाटे की गणना करने के लिए एक सीधा गणितीय सूत्र उपयोग किया जाता है। राजस्व घाटा सरकार के कुल राजस्व व्यय में से कुल राजस्व प्राप्तियों को घटाकर प्राप्त होता है। यह अंतर केवल चालू वित्तीय वर्ष के आवर्ती भुगतानों

Click Here to Buy book on Amazon

और आय को ही शामिल करता है। इसमें पूँजीगत खाते को नहीं जोड़ा जाता, जिससे सटीक स्थिति दिखती है।

70. (C) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का अधिनियमन → बजट प्रस्तुतीकरण को 1 फरवरी करना एवं रेल और सामान्य बजट का विलय
भारत की बजटीय प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सुधार हुए हैं। इनका सही कालानुक्रम इस प्रकार है: सर्वप्रथम वर्ष 2003 में राजकोषीय अनुशासन हेतु एफआरबीएम अधिनियम पारित किया गया था। इसके पश्चात्, वर्ष 2017 में दो प्रमुख सुधार एक साथ किए गए जिसके तहत बजट प्रस्तुतीकरण को 1 फरवरी किया गया और रेल बजट का सामान्य बजट में विलय हुआ। अतः विकल्प सत्य है।

71. (B) पूँजी निर्माण और अप्रयुक्त संसाधनों का संग्रहण होता है
एक विकासशील अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र प्रायः बड़े पैमाने पर अवसंरचना और बुनियादी उद्योगों में निवेश करने में असमर्थ होता है। ऐसी स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाकर अतिरिक्त उधारी के माध्यम से पूँजी निर्माण को बढ़ावा देती है। घाटे के बजट द्वारा जुटाए गए धन से देश के अप्रयुक्त संसाधनों का कुशल संग्रहण संभव होता है, जिससे आर्थिक वृद्धि होती है।

72. (B) केवल I और III
केंद्रीय बजट में सरकारी राजस्व प्राप्तियों को कर राजस्व और गैर-कर राजस्व में वर्गीकृत किया जाता है। सीमा शुल्क (अप्रत्यक्ष कर) और निगम कर (प्रत्यक्ष कर) दोनों ही कर राजस्व की श्रेणी में आते हैं। इसके विपरीत, ऋणों पर प्राप्त ब्याज तथा लाइसेंस शुल्क गैर-कर राजस्व के उदाहरण हैं। अतः प्रथम और तृतीय मदें कर राजस्व के अधीन आती हैं।

73. (D) बाह्य ऋण में मुद्रा जोखिम और विदेशी मुद्रा पुनर्भुगतान देनदारियाँ शामिल होती हैं
आंतरिक और बाह्य सार्वजनिक ऋण के बीच मुख्य अंतर उनकी भौगोलिक सीमा तथा पुनर्भुगतान मुद्रा में होता है। आंतरिक ऋण देश के भीतर घरेलू मुद्रा में लिया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा जोखिम नहीं होता। इसके विपरीत, बाह्य ऋण विदेशी संस्थाओं या बाज़ारों से प्राप्त किया जाता है। इसलिए बाह्य ऋण में विदेशी मुद्रा पुनर्भुगतान और विनिमय जोखिम शामिल होते हैं।

74. (A) लोकसभा सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है
संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को सीमित अधिकार प्राप्त हैं। जब लोकसभा वित्त विधेयक को पारित करके राज्यसभा को भेजती है, तो राज्यसभा 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें दे सकती है। हालाँकि, लोकसभा के पास यह पूर्ण अधिकार होता है कि वह उन सिफारिशों को स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे। लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है।

75. (B) ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सब्सिडी का भुगतान
पूँजीगत व्यय ऐसा व्यय है जो या तो किसी परिसंपत्ति का निर्माण करता है अथवा वित्तीय देनदारियों को कम करता है। अस्पताल निर्माण, शेयर खरीदना तथा ऋणों का पुनर्भुगतान पूँजीगत व्यय के उदाहरण हैं। इसके विपरीत, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सब्सिडी का भुगतान एक आवर्ती व्यय है जिससे कोई परिसंपत्ति नहीं बनती, अतः यह राजस्व व्यय का भाग है तथा भिन्न है।

76. (B) प्राथमिक घाटा
पिछली सरकारों द्वारा लिए गए ऋणों के कारण वर्तमान सरकार पर भारी ब्याज भुगतानों का दायित्व होता है। यदि किसी अर्थशास्त्री को अतीत के ऋणों की विरासत को हटाकर केवल वर्तमान सरकार के राजकोषीय अनुशासन का सटीक मूल्यांकन करना हो, तो उसे प्राथमिक घाटे का विश्लेषण करना चाहिए। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाकर प्राप्त होता है और स्थिति दर्शाता है।

77. (A) आंतरिक सार्वजनिक ऋण
लोक भविष्य निधि और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जैसी लघु बचत योजनाओं से प्राप्त संग्रह भारत के लोक खाते में जमा किया जाता है। हालाँकि ये निधियाँ राजस्व नहीं हैं, लेकिन सरकार इन जमा राशियों को नागरिकों को ब्याज सहित लौटाने के लिए कानूनी रूप से देनदार होती है। अतः ये राशियाँ सरकार के आंतरिक सार्वजनिक ऋण का ही अंग बनती हैं।

NODIA

78. (A) P-4, Q-3, R-1, S-2
विभिन्न बजटीय सूचकांकों के आर्थिक प्रभाव इस प्रकार हैं: बढ़ता राजस्व घाटा दैनिक खर्चों हेतु उधार का उपयोग दर्शाता है। शून्य प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान के बराबर उधारी को प्रदर्शित करता है। उच्च पूँजीगत व्यय परिसंपत्ति सृजन को दर्शाता है। बढ़ता बाज़ार उधार राजकोषीय घाटे और निजी निवेश निष्कासन को दर्शाता है। अतः सही सुमेल विकल्प अनुसार 4, 3, 1, 2 है।

79. (D) प्रस्तावित अनुदान राशियों को कम करने के लिए कटौती प्रस्ताव पेश करना
लोकसभा में बजट के बाद सामान्य चर्चा का चरण होता है। इस दौरान सांसद राजकोषीय नीति तथा आर्थिक सिद्धांतों पर व्यापक चर्चा कर सकते हैं। हालाँकि, इस चरण में किसी भी अनुदान राशि को कम करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। कटौती प्रस्ताव केवल मांगों पर मतदान के दौरान ही लाए जा सकते हैं। यह नियम है।

80. (C) पूँजीगत व्यय
सरकार द्वारा नए रेल गलियारों के निर्माण तथा परिवहन अवसंरचना के विकास पर किया जाने वाला वित्तीय आवंटन एक दीर्घकालिक भौतिक परिसंपत्ति का निर्माण करता है। चूंकि इस प्रकार के सरकारी व्यय से देश की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है और नई राष्ट्रीय परिसंपत्तियां निर्मित होती हैं, इसलिए इसे केंद्रीय बजट में पूँजीगत व्यय शीर्षक के तहत दर्ज किया जाता है।

अध्याय 02
बैंकिंग प्रणाली

1. भारतीय बैंकिंग प्रणाली में विभिन्न प्रकार के संस्थान शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में अनुसूचित और गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बीच मूलभूत अंतर का सबसे सही वर्णन करता है?
   (A) अनुसूचित बैंक सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं, जबकि गैर-अनुसूचित बैंक पूरी तरह से निजी स्वामित्व वाले होते हैं।
   (B) अनुसूचित बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं, जबकि गैर-अनुसूचित बैंक शामिल नहीं हैं।
   (C) अनुसूचित बैंक करेंसी नोट जारी कर सकते हैं, जबकि गैर-अनुसूचित बैंक नहीं कर सकते।
   (D) अनुसूचित बैंक केवल शहरी क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जबकि गैर-अनुसूचित बैंक विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते हैं।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) भारतीय अर्थव्यवस्था में कई मुख्य कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन-सा आरबीआई का पारंपरिक कार्य नहीं है?
   (A) वाणिज्यिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना।
   (B) भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करना।
   (C) मौद्रिक नीति का निर्माण और कार्यान्वयन करना।
   (D) आम जनता से मांग जमा स्वीकार करना।

3. बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वाणिज्यिक बैंकों पर व्यापक नियामक शक्तियां हैं। इस अधिनियम की कौन-सी विशिष्ट धारा आरबीआई को भारत में बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए संस्थाओं को लाइसेंस जारी करने की शक्ति प्रदान करती है?
   (A) धारा 11
   (B) धारा 22
   (C) धारा 35
   (D) धारा 42

4. रेपो दर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपकरण है। मौद्रिक नीति संचालन के संदर्भ में, रेपो दर विशेष रूप से क्या दर्शाती है?
   (A) वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक कॉर्पोरेट संस्थाओं को दीर्घकालिक पूंजी ऋण देते हैं।
   (B) वह दर जिस पर आरबीआई बिना किसी संपार्श्विक के वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है।
   (C) वह दर जिस पर आरबीआई स्वीकृत प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धनराशि उधार देता है।
   (D) जमा का वह अनिवार्य प्रतिशत जिसे बैंकों को आरबीआई के पास नकद रूप में रखना होता है।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक की तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के ढांचे के तहत, रिवर्स रेपो दर एक विशिष्ट समष्टि आर्थिक उद्देश्य पूरा करती है। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन इस उद्देश्य का सबसे सटीक वर्णन करता है?
   (A) इसका उपयोग आरबीआई द्वारा बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए किया जाता है।
   (B) इसका उपयोग अत्यधिक निकासी (बैंक रन) का सामना कर रहे बैंकों में आपातकालीन तरलता डालने के लिए किया जाता है।
   (C) यह उस न्यूनतम ब्याज दर को निर्धारित करता है जो वाणिज्यिक बैंक खुदरा जमाकर्ताओं को दे सकते हैं।
   (D) यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण (PSL) के लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहने वाले बैंकों के लिए जुर्माना दर निर्धारित करता है।

6. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था में बढ़ते मुद्रास्फीति के दबाव को देखता है और एक कठोर मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है, तो नकद आरक्षित अनुपात (CRR) के संबंध में निम्नलिखित में से किस कार्रवाई को लागू करने की सबसे अधिक संभावना है?
   (A) वाणिज्यिक बैंकों को अपने साख सृजन और ऋण देने का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु CRR में कमी करना।
   (B) वाणिज्यिक बैंकों में तरलता के दबाव को कम करने के लिए अस्थायी रूप से CRR आवश्यकता को समाप्त करना।
   (C) CRR को बनाए रखना लेकिन वाणिज्यिक बैंकिंग संस्थाओं द्वारा उच्च लाभांश भुगतान को सख्ती से अनिवार्य बनाना।
   (D) वाणिज्यिक बैंकों के पास उपलब्ध ऋण योग्य निधि को कम करने के लिए CRR में वृद्धि करना।

7. भारत में वाणिज्यिक बैंकों को वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) बनाए रखना आवश्यक है। बैंकों के लिए इस अनिवार्य आरक्षित निधि को बनाए रखने हेतु प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से कौन-सी परिसंपत्तियां पात्र हैं?
   (A) शीर्ष श्रेणी की निजी कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा जारी

Downloaded from www.pdf.tube

इक्विटी शेयर और ऋण साधन।
(B) नकद, सोना और प्रभार-मुक्त स्वीकृत सरकारी प्रतिभूतियां।
(C) बैंक की वाणिज्यिक अचल संपत्ति (रियल एस्टेट) धारिताएं और भौतिक बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियां।
(D) घरेलू बैंकों की विदेशी शाखाओं में रखी विदेशी मुद्रा मांग जमा।

8. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. भारत सरकार के पास इन बैंकों में न्यूनतम 51 प्रतिशत शेयरधारिता होती है।
II. परिसंपत्ति के आकार के हिसाब से भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है।
III. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सार्वजनिक इक्विटी बाजारों से कोई भी पूंजी जुटाने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

9. भारतीय बैंकिंग संरचना के संदर्भ में, स्वामित्व वर्गीकरण के आधार पर विषम (अलग) की पहचान कीजिए।
(A) एचडीएफसी बैंक
(B) आईसीआईसीआई बैंक
(C) एक्सिस बैंक
(D) केनरा बैंक

10. भारत में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण दो प्रमुख चरणों में हुआ। 1969 में पहले चरण के दौरान, कितने प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और उनके चयन के लिए न्यूनतम जमा मापदंड क्या था?
(A) 20 करोड़ रुपये से अधिक जमा वाले 10 बैंक
(B) 50 करोड़ रुपये से अधिक जमा वाले 14 बैंक
(C) 100 करोड़ रुपये से अधिक जमा वाले 14 बैंक
(D) 200 करोड़ रुपये से अधिक जमा वाले 20 बैंक

11. 1969 और 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 'सामाजिक बैंकिंग' के दर्शन से प्रेरित था। इसके तुरंत बाद के दशकों में इस नीतिगत बदलाव का सबसे प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन-सा था?
(A) बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) का पूर्ण उन्मूलन।
(B) ग्रामीण और बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का व्यापक विस्तार।
(C) बैंकों की परिचालन लागत और कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी।
(D) घाटे में चल रहे विनिर्माण उद्योगों का तत्काल निजीकरण।

12. निम्नलिखित कथन भारत में बैंकिंग प्रणाली से संबंधित हैं:
कथन (A): ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष साख (ऋण) सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की स्थापना की गई थी।
कारण (R): उस समय वाणिज्यिक बैंक मुख्य रूप से नगर-केंद्रित थे और उनमें ग्रामीण कृषि ऋण के लिए आवश्यक स्थानीय दृष्टिकोण की कमी थी।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

13. भारत में ग्रामीण सहकारी साख संरचना, जो अल्पकालिक और मध्यमकालिक ऋण प्रदान करती है, आम तौर पर त्रि-स्तरीय प्रणाली पर कार्य करती है। इस संरचना में जिला स्तर पर कौन-सा संस्थान कार्य करता है?
(A) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
(B) प्राथमिक कृषि साख समिति
(C) राज्य सहकारी बैंक
(D) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

NODIA

14. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 2014 में आरबीआई द्वारा भुगतान बैंकों (पेमेंट बैंकों) की शुरुआत की गई थी। भुगतान बैंकों को निम्नलिखित में से कौन-सी गतिविधि करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है?
(A) अपने ग्राहकों को एटीएम और डेबिट कार्ड जारी करना।
(B) मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना।
(C) क्रेडिट कार्ड जारी करना और सामान्य ऋण देना।
(D) एक निर्दिष्ट नियामक सीमा तक मांग जमा स्वीकार करना।

15. भारत में लघु वित्त बैंकों (SFBs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इनकी स्थापना छोटे किसानों और एमएसएमई सहित बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम सुविधा प्राप्त वर्गों को बुनियादी बैंकिंग गतिविधियां प्रदान करने के लिए की गई है।
II. भुगतान बैंकों के विपरीत, लघु वित्त बैंकों को ऋण देने की गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति है।
III. इन्हें अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का ठीक 40 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को देना अनिवार्य है।
IV. इनके ऋण पोर्टफोलियो का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा 25 लाख रुपये तक के ऋण और अग्रिम का होना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, II और IV

(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

16. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) भारत की वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं लेकिन कई मायनों में वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन उनके बीच के एक मुख्य अंतर को उजागर करने वाला सही कथन है?
(A) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को कानूनी रूप से खुदरा सार्वजनिक ग्राहकों से सीधे मांग जमा स्वीकार करने की अनुमति है।
(B) NBFCs भारतीय रिज़र्व बैंक के ढांचे से बाहर पूरी तरह से अनियंत्रित वित्तीय संस्थाओं के रूप में कार्य करती हैं।
(C) NBFCs भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं बनती हैं और स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकती हैं।
(D) NBFCs को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सावधि ऋण प्रदान करने से सख्ती से प्रतिबंधित और दंडित किया जाता है।

17. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) का संचय भारतीय बैंकों के लिए एक निरंतर समस्या बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प "स्वेच्छाचारी चूककर्ता" (विलफुल डिफ़ॉल्टर) की अवधारणा का सटीक वर्णन करता है?
(A) वह उधारकर्ता जो भुगतान करने की वास्तविक इच्छा के बावजूद अचानक वैश्विक समष्टि आर्थिक झटकों के कारण चूक करता है।
(B) वह उधारकर्ता जिसके पास चुकाने की क्षमता है लेकिन वह जानबूझकर भुगतान दायित्वों में चूक करता है।
(C) वह उधारकर्ता जिसके व्यवसाय को वास्तविक तकनीकी विफलता का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वह ऋण चुकाने में असमर्थ रहा।
(D) एक बैंक कर्मचारी जो अनजाने में ऐसे ऋण आवेदन को मंजूरी देता है जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज़ गायब हैं।

18. बैंक बैलेंस शीट पर पुरानी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के भारी बोझ से निपटने के लिए, भारत सरकार ने एक 'बैड बैंक' के निर्माण का समर्थन किया। इन बड़ी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को एकत्र और निस्तारित करने के लिए मुख्य रूप से शामिल की गई इकाई का औपचारिक नाम क्या है?
(A) नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)
(B) डिपाज़िट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC)
(C) इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS)
(D) नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL)

19. 1991 के बाद भारत में बैंकिंग क्षेत्र के महत्वपूर्ण सुधार एक उच्च स्तरीय समिति की व्यापक सिफारिशों के आधार पर शुरू किए गए थे। वित्तीय प्रणाली पर बनी इस महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता किसने की थी?
(A) एम. नरसिम्हम
(B) उर्जित पटेल
(C) रघुराम राजन
(D) सी. रंगराजन

20. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए:
सूची I: संस्थान/इकाइयां
P. भारतीय रिज़र्व बैंक
Q. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
R. लघु वित्त बैंक
S. परिसंपत्ति पुनर्रचना कंपनियां (ARCs)
सूची II: मुख्य ध्यान केंद्रित क्षेत्र/कार्य
1. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का एकत्रीकरण और समाधान
2. शीर्ष मौद्रिक और बैंकिंग नियामक प्राधिकरण
3. खुदरा डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचा और निपटान
4. विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों और छोटे किसानों को लक्षित करने वाली साख और जमा सुविधाएं
(A) P-2, Q-3, R-4, S-1
(B) P-2, Q-4, R-3, S-1
(C) P-3, Q-2, R-4, S-1
(D) P-1, Q-3, R-2, S-4

21. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) वित्तीय समावेशन के लिए एक प्रमुख योजना है। निम्नलिखित में से कौन-सा इस योजना के तहत खोले गए खातों की एक मुख्य विशेषता नहीं है?
(A) ये खाता सक्रिय करने के लिए तत्काल 10,000 रुपये की अग्रिम जमा राशि अनिवार्य करते हैं।
(B) इन्हें शून्य-शेष खातों के रूप में डिज़ाइन किया गया है जिनमें कोई न्यूनतम जमा शेष अनिवार्य नहीं है।
(C) ये प्रत्येक प्राथमिक खाताधारक को एक बुनियादी रूपे (RuPay) डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान करते हैं।
(D) ये धारकों के लिए एक अंतर्निहित व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करते हैं।

22. भारत में डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में, व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली वास्तविक समय भुगतान प्रणाली UPI का पूर्ण रूप क्या है?
(A) यूनिवर्सल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर
(B) यूनाइटेड प्रोसेसिंग इंटरफेस
(C) यूनिवर्सल प्रायोरिटी इंटरबैंक
(D) यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस

23. पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित करने के लिए 2016 में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) लागू की गई थी। IBC के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की मुख्य विशेषता क्या है?
(A) यह बैंकों को डिफ़ॉल्ट करने वाली कंपनियों से कोई भी ऋण वसूलने से स्थायी रूप से रोकती है।

Click Here to Buy book on Flipkart

(B) यह दिवाला समाधान के लिए एक सख्त, समयबद्ध तंत्र लागू करती है।
(C) यह अनिवार्य करती है कि 90 दिनों के बाद सभी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को स्वचालित रूप से बट्टे खाते में डाल दिया जाए।
(D) यह सभी डिफ़ॉल्ट करने वाली कंपनियों का स्वामित्व सीधे भारतीय रिज़र्व बैंक को स्थानांतरित करती है।

24. बासेल III मानदंड बैंक पूंजी आवश्यकताओं को मजबूत करने के लिए अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नियामक मानक हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा एक अपवाद है और बासेल III ढांचे के तीन मूलभूत स्तंभों में से एक नहीं है?
(A) न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं और आरक्षित अनुपात
(B) जोखिम प्रबंधन के लिए पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया
(C) सार्वभौमिक बुनियादी आय गारंटी
(D) बाजार अनुशासन और वित्तीय प्रकटीकरण मानक

25. निम्नलिखित में से कौन भारत में इन प्रमुख बैंकिंग मील के पत्थरों की स्थापना या घटित होने का सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाता है?
(A) 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, भुगतान बैंकों की शुरुआत, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का अधिनियमन
(B) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का अधिनियमन, भुगतान बैंकों की शुरुआत
(C) 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भुगतान बैंकों की शुरुआत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का अधिनियमन
(D) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, भुगतान बैंकों की शुरुआत, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का अधिनियमन

26. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण (PSL) यह अनिवार्य करता है कि बैंक अपने ऋण का एक विशिष्ट हिस्सा महत्वपूर्ण क्षेत्रकों को आवंटित करें। घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के लिए उनके समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) के प्रतिशत के रूप में मानक PSL लक्ष्य क्या है?
(A) 18 प्रतिशत
(B) 25 प्रतिशत
(C) 40 प्रतिशत
(D) 75 प्रतिशत

27. अप्रैल 2020 में लागू हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वृहद विलय में, बड़े और मजबूत संस्थान बनाने के लिए विभिन्न बैंकों का समेकन किया गया था। इस संदर्भ में, किस बैंक ने एंकर बैंक के रूप में कार्य किया, जिसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ था?
(A) भारतीय स्टेट बैंक
(B) पंजाब नेशनल बैंक
(C) बैंक ऑफ बड़ौदा
(D) केनरा बैंक

28. आरबीआई के मौद्रिक नीति उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. रेपो दर में वृद्धि से आम तौर पर वाणिज्यिक बैंकों की ऋण दरों में वृद्धि होती है।
II. बैंकों को आरबीआई के पास धन जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु रिवर्स रेपो दर को आमतौर पर रेपो दर से अधिक रखा जाता है।
III. नकद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन से वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता प्रभावित होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

29. भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना के तहत, गैर-अनुसूचित बैंक वे हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं हैं। कौन-सी स्थिति आमतौर पर किसी बैंक को इस अनुसूची में सूचीबद्ध होने के लिए अयोग्य बनाती है?
(A) 5 लाख रुपये से कम की प्रदत्त पूंजी और कुल आरक्षित निधि होना।
(B) केवल एक ही महानगरीय शहर की भौगोलिक सीमाओं के भीतर कार्य करना।
(C) कम आय वाले खुदरा ग्राहकों को सूक्ष्म-वित्त ऋण प्रदान करने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना।
(D) आधुनिक कोर बैंकिंग प्रौद्योगिकी समाधान को पूरी तरह से लागू करने और तैनात करने में विफल रहना।

30. भारतीय रिज़र्व बैंक देश में करेंसी नोट जारी करने वाला एकमात्र प्राधिकरण है। हालांकि, मुद्रा का एक विशिष्ट मूल्यवर्ग इसका एक अपवाद है, क्योंकि यह वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इस अपवाद की पहचान कीजिए।
(A) दस रुपये का नोट
(B) पाँच रुपये का सिक्का
(C) एक रुपये का नोट
(D) बीस रुपये का नोट

31. अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों के तहत, आरबीआई समय-समय पर वाणिज्यिक बैंकों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है। यह मजबूत पर्यवेक्षी शक्ति प्राथमिक रूप से किस कानून से प्राप्त होती है?
(A) कंपनी अधिनियम, 2013
(B) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999
(C) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992
(D) बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949

32. निम्नलिखित कथन आरबीआई द्वारा समष्टि आर्थिक विनियमन से संबंधित हैं:

Downloaded from www.pdf.tube

कथन (A): उच्च मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक आमतौर पर रेपो दर में वृद्धि करता है।
कारण (R): रेपो दर में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों के लिए उधार लेना सस्ता हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

33. नकद आरक्षित अनुपात (CRR) के तहत बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है। वर्तमान नियामक ढांचे के आधार पर, इन अनिवार्य CRR शेष पर आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को कितना ब्याज दिया जाता है?
(A) यह प्रचलित रेपो दर के बराबर होता है।
(B) आरबीआई CRR शेष पर कोई ब्याज नहीं देता है।
(C) यह 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की निश्चित दर पर निर्धारित है।
(D) यह मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर गतिशील रूप से बदलता रहता है।

34. यद्यपि CRR और SLR दोनों ही तरलता नियंत्रण के साधन हैं, लेकिन वे अलग तरह से कार्य करते हैं। नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के बीच निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे सटीक अंतर है?
(A) CRR को विशेष रूप से भौतिक स्वर्ण भंडार में रखा जाता है, जबकि SLR को पूरी तरह से तरल नकदी में बनाए रखा जाना चाहिए।
(B) SLR केवल निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है, जबकि CRR केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू होता है।
(C) CRR मुख्य रूप से दीर्घकालिक वाणिज्यिक ऋण विस्तार को प्रतिबंधित करता है, जबकि SLR अल्पकालिक अंतर-बैंक उधार को प्रतिबंधित करता है।
(D) CRR शेष राशि आरबीआई के पास जमा की जाती है, जबकि SLR परिसंपत्तियां स्वयं बैंकों द्वारा रखी जाती हैं।

35. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इनका गठन 1975 में नरसिम्हम कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।
II. एक RRB की स्वामित्व इक्विटी केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के बीच विभाजित होती है।
III. एक RRB में केंद्र सरकार के पास शेयर पूंजी का ठीक 50 प्रतिशत हिस्सा होता है।
IV. RRBs को नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) बनाए रखने से पूरी तरह से छूट प्राप्त है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, II और IV
(D) केवल I, III और IV

36. विदेशी बैंक भारत में या तो शाखा मॉडल के माध्यम से या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (WOS) के रूप में कार्य करते हैं। जब विदेशी बैंक केवल शाखाओं के बजाय पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में कार्य करते हैं, तो आरबीआई को प्राथमिक नियामक लाभ क्या प्राप्त होता है?
(A) विदेशी बैंक की सहायक कंपनियों को स्थानीय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण (PSL) लक्ष्यों को पूरा करने से पूरी तरह छूट मिलती है।
(B) विदेशी बैंक सहायक कंपनियों का संचालन पूरी तरह से उनके गृह देश के नियामकों के कानूनी क्षेत्राधिकार में आता है।
(C) आरबीआई अधिक पर्यवेक्षी नियंत्रण प्राप्त करता है और स्थानीय परिचालनों को मूल वैश्विक झटकों से सुरक्षित रखता है।
(D) विदेशी बैंक की सहायक कंपनियों को अनिवार्य रूप से केवल घरेलू बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को ऋण आवंटित करने के लिए मजबूर किया जाता है।

37. अप्रैल 1980 में बैंक राष्ट्रीयकरण के दूसरे प्रमुख चरण के दौरान, छह और वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी नियंत्रण में लाया गया था। इन छह बैंकों का चयन करने के लिए निर्णायक मापदंड क्या था?
(A) 100 करोड़ रुपये से अधिक की मांग और सावधि देयताएं (NDTL)
(B) 200 करोड़ रुपये से अधिक की मांग और सावधि देयताएं (NDTL)
(C) क्षेत्रक में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) की उच्चतम संख्या
(D) 15 से अधिक भारतीय राज्यों में परिचालनात्मक उपस्थिति

38. राष्ट्रीयकरण के बाद के दौर में अर्थव्यवस्था के पहले से उपेक्षित क्षेत्रों को लक्षित ऋण प्रदान किया गया। इस निर्देशित ऋण को संस्थागत बनाने के लिए आरबीआई द्वारा कौन-सा विशिष्ट संरचनात्मक तंत्र आक्रामक रूप से लागू किया गया था?
(A) रेपो दर का उन्मूलन
(B) क्रिप्टो-संपत्तियों की शुरुआत
(C) पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता का कार्यान्वयन
(D) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण (PSL) लक्ष्य

39. अल्पकालिक सहकारी साख की त्रि-स्तरीय संरचना में, कौन-सी इकाई प्राथमिक ग्राम स्तर पर कार्य करती है, जो सीधे किसानों से जुड़ती है?
(A) राज्य स्तर पर शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करने वाला

NODIA

राज्य सहकारी बैंक
(B) गाँव के स्तर पर कार्य करने वाली प्राथमिक कृषि साख समिति (PACS)
(C) मध्यवर्ती जिला स्तर पर कार्य करने वाला जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
(D) वाणिज्यिक बैंकों और सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

40. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए:
सूची I: बैंकिंग दरें और अनुपात
P. रेपो दर
Q. रिवर्स रेपो दर
R. नकद आरक्षित अनुपात (CRR)
S. वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)
सूची II: मुख्य परिभाषाएं
1. तरलता परिसंपत्तियां (जैसे जी-सेक) जो बैंकों को NDTL के प्रतिशत के रूप में आंतरिक रूप से बनाए रखनी होती हैं।
2. NDTL का वह प्रतिशत जो बैंकों को आरबीआई के पास नकद रूप में जमा करना होता है।
3. वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों से तरलता को अवशोषित करता है।
4. वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक धनराशि उधार देता है।
(A) P-4, Q-3, R-2, S-1
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-4, Q-2, R-3, S-1
(D) P-1, Q-2, R-4, S-3

41. भुगतान बैंक भारत में एक विभेदित बैंकिंग मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक परिचालन शुरू करने वाली ऐसी पहली संस्था थी। निम्नलिखित में से कौन-सा ग्राहक वर्ग भुगतान बैंकों का प्राथमिक लक्ष्य है?
(A) जटिल सिंडिकेटेड वाणिज्यिक ऋणों की आवश्यकता वाले बड़े कॉर्पोरेट समूह
(B) विशेष निजी संपत्ति प्रबंधन की आवश्यकता वाले उच्च-निवल मूल्य वाले व्यक्तिगत निवेशक
(C) घरेलू पूंजी बाजारों में सक्रिय रूप से व्यापार करने वाले विदेशी संस्थागत इक्विटी निवेशक
(D) प्रवासी मजदूर, कम आय वाले परिवार और असंगठित छोटी व्यावसायिक इकाइयां

42. लघु वित्त बैंकों (SFBs) से सूक्ष्म ऋण बाजार में गहराई से पैठ बनाने की उम्मीद की जाती है। परिणामस्वरूप, वे एक कठोर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण (PSL) लक्ष्य के अधीन हैं। SFBs को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का कितना प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आवंटित करना अनिवार्य है?
(A) 25 प्रतिशत
(B) 40 प्रतिशत
(C) 50 प्रतिशत
(D) 75 प्रतिशत

43. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) भारत के 'शैडो बैंकिंग' क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यद्यपि NBFCs बैंकों के समान ऋण प्रदान करती हैं, फिर भी नियामक प्राधिकरण शैडो बैंकिंग क्षेत्र को सतर्कता से क्यों देखते हैं?
(A) क्योंकि NBFCs सभी उधारकर्ताओं को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वाणिज्यिक ऋण देकर कार्य करती हैं।
(B) क्योंकि NBFCs को आरबीआई की अंतिम ऋणदाता तरलता सहायता तक सीधी पहुंच के बिना परिसंपत्ति-देयता असंतुलन का सामना करना पड़ता है।
(C) क्योंकि NBFCs कानूनी रूप से केवल विदेशी कॉर्पोरेट ग्राहकों को वित्तीय ऋण प्रदान करने के लिए प्रतिबंधित हैं।
(D) क्योंकि वैधानिक नियमों द्वारा NBFCs को अपनी सभी परिसंपत्तियों को सख्ती से अचल संपत्ति में रखने का स्पष्ट जनादेश प्राप्त है।

44. पिछले दशक में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) का एक प्रमुख कारण "दोहरी बैलेंस शीट" की समस्या थी। इस परिघटना के तहत किन दो अलग-अलग संस्थाओं की बैलेंस शीट तनावग्रस्त होने की विशेषता बताई गई थी?
(A) वाणिज्यिक बैंकिंग संस्थान और भारतीय रिज़र्व बैंक नियामक प्राधिकरण
(B) तनावग्रस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और अत्यधिक कर्जदार कॉर्पोरेट इकाइयां
(C) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और अत्यधिक कर्ज में डूबे खुदरा घरेलू उधारकर्ता
(D) केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारें

45. भारतीय बैंकिंग और नियामक परिदृश्य के विकास से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) का अधिनियमन
II. 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण
III. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की शुरुआत
IV. वित्तीय प्रणाली पर एम. नरसिम्हम समिति की स्थापना
(A) II, IV, III, I
(B) II, IV, I, III
(C) IV, II, III, I
(D) II, I, IV, III

46. परिसंपत्ति पुनर्रचना कंपनियां (ARCs) गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) समाधान में एक विशेष भूमिका निभाती हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प ARC के मूल कार्य का सबसे सटीक वर्णन करता है?
(A) मौलिक रूप से मजबूत लेकिन अस्थायी रूप से तरलता संकट से जूझ रही वाणिज्यिक संस्थाओं को नया दीर्घकालिक कार्यशील पूंजी वित्तपोषण प्रदान करना।

Click Here to Buy book on Amazon

(B) डिफ़ॉल्ट करने वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं को औपचारिक रूप से दिवालिया घोषित करने के लिए सशक्त सर्वोच्च निर्णायक न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करना।
(C) बैंकों से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को उनके समाधान, पुनर्गठन या परिसंपत्ति वसूली का प्रयास करने के लिए खरीदना।
(D) कम पूंजी वाले सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों में पुनर्पूंजीकरण करने के लिए विशेष रूप से नए संप्रभु ऋण साधनों को संरचित और जारी करना।

47. नरसिम्हम समिति II (1998) ने संरचनात्मक बैंकिंग सुधारों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया। बैंक समेकन के संबंध में इस विशिष्ट समिति की एक प्रमुख सिफारिश निम्नलिखित में से कौन-सी थी?
(A) देश भर के प्रत्येक कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का विलय एक एकल विशाल राष्ट्रीयकृत बैंकिंग संस्थान में करना।
(B) राष्ट्रीयकरण नीति को पूरी तरह से उलटना और सभी राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों का तुरंत निजीकरण करना।
(C) भारतीय क्षेत्र के भीतर कहीं भी शाखाएं संचालित करने वाले विदेशी वाणिज्यिक बैंकिंग संस्थानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना।
(D) वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करके मजबूत विशाल बैंक (मेगा बैंक) बनाना।

48. रुपे (RuPay) कार्ड नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा लॉन्च किया गया था।
II. यह अंतर्राष्ट्रीय कार्ड योजनाओं पर निर्भरता कम करने के लिए बनाया गया एक स्वदेशी भुगतान नेटवर्क है।
III. इसका उपयोग भारत के क्षेत्र के बाहर किसी भी स्वचालित टेलर मशीन (ATM) में नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

49. वास्तविक समय में खाते से खाते में स्थानांतरण तंत्र की शुरुआत के साथ भारत में डिजिटल बैंकिंग को भारी बढ़ावा मिला। NPCI द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लॉन्च किया गया था?
(A) 2010
(B) 2014
(C) 2016
(D) 2020

50. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) 2016 के ढाँचे के तहत, कौन-सा विशेष अधिकरण कॉर्पोरेट दिवाला समाधान मामलों के लिए प्राथमिक निर्णयकारी प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है?
(A) ऋण वसूली से संबंधित मुकदमों को संभालने वाला ऋण वसूली अधिकरण (DRT)
(B) बाजार अपीलों को संभालने वाला प्रतिभूति अपील अधिकरण (SAT)
(C) बाजार नियामक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)
(D) राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (NCLT)

51. बासेल III मानदंड बैंकिंग संस्थानों के लिए सख्त पूंजी मानकों को अनिवार्य करते हैं। इस संदर्भ में, पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) मुख्य रूप से क्या मापता है?
(A) बैंक की पूंजी का उसकी जोखिम-भारित परिसंपत्तियों से अनुपात।
(B) बैंक की ग्रामीण शाखाओं का उसकी शहरी शाखाओं से अनुपात।
(C) कुल जुटाई गई जमा राशि का कुल संवितरित ऋणों से अनुपात।
(D) गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का निष्पादित परिसंपत्तियों से अनुपात।

52. निम्नलिखित कथन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण (PSL) पर केंद्रित हैं:
कथन (A): भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों को कृषि और एमएसएमई जैसे क्षेत्रों को अपने फंड का एक विशिष्ट हिस्सा उधार देने के लिए अनिवार्य करता है।
कारण (R): ये क्षेत्र स्वाभाविक रूप से अत्यधिक लाभदायक हैं और बड़े कॉर्पोरेट ऋण की तुलना में सबसे कम साख जोखिम प्रस्तुत करते हैं।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

53. वैश्विक आकार के बैंक बनाने के लिए बैंक समेकन सरकार की एक प्रमुख रणनीति रही है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का अपने पांच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के साथ प्रभावी रूप से विलय किस वर्ष हुआ था?
(A) 2015
(B) 2017
(C) 2019
(D) 2021

54. सहकारी बैंकों ने ऐतिहासिक रूप से अपने विनियमन और प्रबंधन के संबंध में "दोहरे नियंत्रण" की समस्या का सामना किया है। हालिया विधायी संशोधनों द्वारा आरबीआई के नियंत्रण को सख्त किए जाने से पहले, शहरी सहकारी बैंकों

NODIA

पर मुख्य रुप से किन दो संस्थाओं ने इस अतिव्यापी नियामक प्राधिकरण का प्रयोग किया था?
(A) पूंजी परिचालन का प्रबंधन करने वाले भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक।
(B) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के साथ केंद्रीय वित्त मंत्रालय।
(C) संबंधित राज्य सरकार के कार्यकारी विभागों के साथ प्रायोजक के रूप में कार्य करने वाला भारतीय स्टेट बैंक।
(D) आरबीआई और संबंधित राज्य या केंद्र सरकार का सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार (RCS)।

55. "सरकार के बैंकर" के रूप में आरबीआई की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह केंद्र सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है।
II. यह विशिष्ट समझौतों की आवश्यकता के बिना, डिफ़ॉल्ट रूप से सभी राज्य सरकारों के बैंकिंग परिचालनों का प्रबंधन करने के लिए कानूनी रुप से बाध्य है।
III. यह नए संप्रभु ऋण जारी करने की सुविधा प्रदान करता है और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है।
IV. यह प्राप्तियों और भुगतानों में अस्थायी असंतुलन को दूर करने के लिए सरकारों को साधन और उपाय अग्रिम (WMA) प्रदान करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

56. जब किसी वाणिज्यिक बैंक का वित्तीय स्वास्थ्य महत्वपूर्ण सीमाओं (पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता या लाभप्रदता) से नीचे चला जाता है, तो आरबीआई इसे एक विशेष पर्यवेक्षी ढांचे के तहत रखता है जो कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। इस ढांचे का नाम क्या है?
(A) परिसंपत्ति पुनर्रचना तंत्र (ARM)
(B) कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन (CDR)
(C) त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA)
(D) न्यूनतम पूंजी आवश्यकता ढांचा (MCRF)

57. रेपो दर का निर्धारण एक समर्पित समिति द्वारा किया जाता है जिसका उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। भारत में इस मौद्रिक नीति समिति (MPC) का निर्धारित आकार कितना है?
(A) 3 सदस्य
(B) 5 सदस्य
(C) 6 सदस्य
(D) 9 सदस्य

58. स्थायी जमा सुविधा (SDF) की शुरुआत से पहले, कौन-सी विशिष्ट दर आरबीआई द्वारा प्रबंधित तरलता समायोजन सुविधा (LAF) गलियारे की निचली सीमा बनाती थी?
(A) रिवर्स रेपो दर
(B) बैंक दर
(C) सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर
(D) नकद आरक्षित अनुपात

59. नकद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात की गणना बैंक के NDTL के प्रतिशत के रूप में की जाती है। बैंकिंग शब्दावली में संक्षिप्त नाम NDTL का क्या अर्थ है?
(A) नेशनल डिपॉजिट एंड टर्म लोन
(B) नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज (निवल मांग और सावधि देयताएं)
(C) नॉमिनेटेड डेट एंड टर्म लायबिलिटीज
(D) नेट डिफ़ॉल्ट एंड ट्रेड लोन

60. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए:
सूची I: समितियां/अधिनियम
P. नरसिम्हम समिति (1991)
Q. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (2016)
R. बैंकिंग नियमन अधिनियम (1949)
S. बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति
सूची II: मुख्य विषय/परिणाम
1. अंतर्राष्ट्रीय पूंजी पर्याप्तता मानदंड
2. भारतीय बैंकों के लिए बुनियादी नियामक ढांचा
3. वित्तीय क्षेत्रक का विनियमन मुक्तीकरण और सुधार
4. तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए समयबद्ध तंत्र
(A) P-3, Q-4, R-2, S-1
(B) P-4, Q-3, R-1, S-2
(C) P-3, Q-2, R-4, S-1
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

61. वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) बनाए रखने के लिए, बैंक विशिष्ट प्रकार की सुरक्षित, तरल परिसंपत्तियां रखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर SLR की गणना के लिए पात्र परिसंपत्ति नहीं माना जाता है?
(A) असुरक्षित कॉर्पोरेट डिबेंचर
(B) बैंक तिजोरियों में रखा भौतिक सोना
(C) भारत सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियां
(D) राज्य विकास ऋण (SDLs)

62. वर्तमान में कुल परिसंपत्तियों, जमा और शाखा नेटवर्क के संदर्भ में भारत के बैंकिंग क्षेत्र में किस सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था का सबसे बड़ा बाजार हिस्सा है?
(A) पंजाब नेशनल बैंक
(B) बैंक ऑफ बड़ौदा
(C) भारतीय स्टेट बैंक
(D) केनरा बैंक

63. 1955 में भारतीय स्टेट बैंक में रुपांतरित होने से पहले, देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक की स्थापना तीन प्रेसीडेंसी बैंकों

Downloaded from www.pdf.tube

के विलय के माध्यम से की गई थी। इस पूर्ववर्ती संस्थान का नाम क्या था?
(A) रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया
(B) अवध कमर्शियल बैंक
(C) एलायंस बैंक ऑफ शिमला
(D) इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया

64. 1969 के राष्ट्रीयकरण के बाद, भारतीय बैंकिंग नीतियों ने बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में शाखा विस्तार पर भारी जोर दिया। ग्रामीण शाखा विस्तार को लागू करने के लिए आरबीआई ने 1970 और 1980 के दशक के दौरान कौन-सी विशिष्ट रणनीति या अनुपात लागू किया था?
(A) एक नियामक आवश्यकता जिसमें यह शर्त रखी गई थी कि विदेशी बैंकिंग संस्थानों को ग्रामीण शाखाएं स्थापित करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था।
(B) सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कॉर्पोरेट मुख्यालयों को तुरंत और पूरी तरह से ग्रामीण जिलों में स्थानांतरित करने का आदेश देने वाली एक केंद्रीय नीति।
(C) एक अनिवार्य शाखा-लाइसेंसिंग फॉर्मूला जिसके तहत बैंकों को प्रत्येक स्वीकृत शहरी शाखा के लिए ग्रामीण शाखाओं का एक निश्चित कोटा खोलना आवश्यक था।
(D) निजी वाणिज्यिक बैंकों को महानगरीय व्यावसायिक केंद्रों में कोई भी नई शाखा खोलने से रोकने वाला एक सख्त वैधानिक प्रतिबंध।

65. राजस्थान जैसे राज्यों में आमतौर पर कार्य करने वाली सहकारी साख संरचना का सही आरोही क्रम (प्राथमिक स्तर से राज्य स्तर तक) निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) राज्य सहकारी बैंक → प्राथमिक कृषि साख समिति → जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
(B) प्राथमिक कृषि साख समिति → जिला केंद्रीय सहकारी बैंक → राज्य सहकारी बैंक
(C) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक → प्राथमिक कृषि साख समिति → राज्य सहकारी बैंक
(D) प्राथमिक कृषि साख समिति → राज्य सहकारी बैंक → जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

66. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) अपने संयुक्त स्वामित्व मॉडल के कारण संरचनात्मक रूप से अद्वितीय हैं। इस व्यवस्था में, प्रायोजक बैंक द्वारा रखी गई शेयर पूंजी का सटीक प्रतिशत क्या है?
(A) 15 प्रतिशत
(B) 35 प्रतिशत
(C) 50 प्रतिशत
(D) 75 प्रतिशत

67. राजस्थान की सहकारी बैंकिंग संरचना के संदर्भ में, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड राज्य के शीर्ष स्तर पर कार्य करता है। कौन-से संस्थान प्राथमिक स्तर की समितियों को पुनर्वित्त देने के लिए इस शीर्ष बैंक से सीधे उधार लेते हैं?
(A) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs)
(B) शहरी सहकारी बैंक
(C) राजस्थान में कार्य करने वाले वाणिज्यिक बैंक
(D) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

NODIA

68. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) समाधान तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. एक बार NCLT द्वारा आवेदन स्वीकार कर लिए जाने के बाद, कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ ऋणों की वसूली को प्रतिबंधित करने वाला एक स्थगन आदेश (मोराटोरियम) घोषित कर दिया जाता है।
II. लेनदारों की एक समिति (CoC) का गठन किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से परिचालन लेनदार शामिल होते हैं जिनके पास अधिकतम मतदान अधिकार होता है।
III. यदि अनिवार्य समय-सीमा के भीतर कोई समाधान योजना स्वीकृत नहीं होती है, तो निर्णयकारी प्राधिकारी कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन का आदेश देता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

69. भारत में एक लघु वित्त बैंक (SFB) स्थापित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक प्रवर्तक के लिए एक निश्चित न्यूनतम प्रदत्त मताधिकार इक्विटी पूंजी को अनिवार्य करता है। अद्यतन दिशानिर्देशों के अनुसार, एक नया SFB स्थापित करने के लिए यह न्यूनतम पूंजी आवश्यकता क्या है?
(A) 50 करोड़ रुपये
(B) 100 करोड़ रुपये
(C) 200 करोड़ रुपये
(D) 500 करोड़ रुपये

70. भारतीय बैंकिंग प्रणाली में निम्नलिखित तकनीकी और समावेशन पहलों को उनके शुभारंभ (लॉन्च) के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)
II. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर (NEFT) की शुरुआत
III. NPCI द्वारा रुपे (RuPay) कार्ड योजना का शुभारंभ
IV. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की शुरुआत
(A) II, III, I, IV
(B) I, II, III, IV
(C) III, II, I, IV
(D) II, I, IV, III

71. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को उनके परिचालन की प्रकृति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। संक्षिप्त नाम NBFC-MFI क्या दर्शाता है?
(A) मॉर्गेज फाइनेंस इंटरमीडिएटरी
(B) माइक्रो-फाइनेंस इंस्टीट्यूशन
(C) म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर

(D) मैक्रो-फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट

72. निम्नलिखित कथन गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के मुद्दे से संबंधित हैं:

कथन (A): आर्थिक सुस्ती की लंबी अवधि के दौरान, वाणिज्यिक बैंक निश्चित रूप से अपने सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपातों में वृद्धि का अनुभव करते हैं।

कारण (R): आर्थिक सुस्ती कॉर्पोरेट लाभप्रदता को कम करती है और व्यक्तियों की आय को प्रभावित करती है, जिससे मौजूदा ऋणों को चुकाने की उनकी क्षमता कम हो जाती है।

(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

73. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के कार्यान्वयन से पहले, बैंक अदालत के हस्तक्षेप के बिना अपने सुरक्षा हितों को लागू करने और ऋण वसूलने के लिए एक विशिष्ट कानून पर अत्यधिक निर्भर थे। किस अधिनियम ने यह तंत्र प्रदान किया था?

(A) पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881
(B) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999
(C) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002
(D) सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम, 2002

74. 2010 के दशक के मध्य में NPAs में वृद्धि का एक प्रमुख कारण कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा अत्यधिक कर्ज लेना था। इस संदर्भ में अत्यधिक कर्जदार (ओवर-लीवरेज्ड) शब्द का क्या अर्थ है?

(A) कंपनियों द्वारा इक्विटी पूंजी की तुलना में अत्यधिक बैंक ऋण लेना, जिसके परिणामस्वरुप ऋण चुकाने का गंभीर बोझ पड़ता है।
(B) बिना कोई ऋण लिए घरेलू क्षेत्रों में अपने बाजार परिचालनों और भौगोलिक उपस्थिति का तेजी से विस्तार करने वाली कंपनियां।
(C) सार्वजनिक पूंजी बाजारों में सीधे विदेशी खुदरा निवेशकों से असमान रूप से उच्च मात्रा में इक्विटी पूंजी जुटाने वाली कंपनियां।
(D) विस्तार के लिए विशेष रूप से आंतरिक नकद भंडार का उपयोग करके वाणिज्यिक बैंक उधार के सभी रूपों से सख्ती से बचने वाली कंपनियां।

75. भारत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण (PSL) लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. कृषि क्षेत्रक को ऋण देने का लक्ष्य आमतौर पर ANBC का 18% होता है।
II. भारत में 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को सभी PSL दायित्वों से छूट दी गई है।
III. स्टार्टअप्स को दिए जाने वाले ऋण (50 करोड़ रुपये तक) को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण के तहत मान्यता प्राप्त है।
IV. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्रक को दिए जाने वाले अग्रिम PSL के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल I, II और IV
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

76. नरसिम्हम समिति (1991) ने बैंक लाभप्रदता और स्वायत्तता में सुधार के लिए कई क्रांतिकारी सिफारिशें कीं। वैधानिक आरक्षित आवश्यकताओं के संबंध में इसकी प्रमुख संरचनात्मक सिफारिशों में से एक निम्नलिखित में से कौन-सी थी?

(A) सार्वजनिक खुदरा बैंक जमा की सुरक्षा को अधिकतम करने के लिए वैधानिक तरलता अनुपात को धीरे-धीरे 50 प्रतिशत तक बढ़ाना।
(B) उत्पादक वाणिज्यिक साख ऋण के लिए बैंक संसाधनों को मुक्त (अनलॉक) करने हेतु SLR और CRR आवश्यकताओं को कम करना।
(C) नकद आरक्षित अनुपात को पूरी तरह से समाप्त करना, जबकि वैधानिक तरलता आवश्यकताओं को स्थायी रूप से 40 प्रतिशत पर बनाए रखना।
(D) वैधानिक तरलता और नकद आरक्षित अनुपातों को पूरी तरह से एक अनिवार्य 'राष्ट्रीय विकास कोष' नियामक कर से बदलना।

77. बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (BCBS) द्वारा बासेल III नियामक ढांचा मुख्य रूप से किस प्रमुख वैश्विक घटना के जवाब में विकसित किया गया था?

(A) 2007-08 का वैश्विक वित्तीय संकट
(B) 2001 का डॉट-कॉम बुलबुला फटना
(C) 1997 का एशियाई वित्तीय संकट
(D) 2020 का कोविड-19 महामारी आर्थिक झटका

78. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए:

सूची I: विलय किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

P. सिंडिकेट बैंक
Q. इलाहाबाद बैंक
R. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
S. आंध्रा बैंक

सूची II: एंकर बैंक

1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
2. केनरा बैंक
3. पंजाब नेशनल बैंक
4. इंडियन बैंक

(A) P-2, Q-4, R-3, S-1
(B) P-3, Q-1, R-2, S-4
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3

Click Here to Buy book on Flipkart

(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

79. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) 2016 की परिसमापन प्रक्रिया के तहत, एक सख्त 'वाटरफॉल तंत्र' होता है जो देनदार की परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को वितरित करने के लिए प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से किस लागत को भुगतान की उच्चतम प्राथमिकता प्राप्त होती है?
(A) असुरक्षित लेनदारों का वित्तीय ऋण
(B) सरकारी बकाया और बकाया कर
(C) परिसमापन की शुरुआत से पहले के 24 महीनों की अवधि के लिए श्रमिकों का बकाया
(D) दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत और परिसमापन लागत

80. 2019 और 2020 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वृहद विलय (मेगा-मर्जर) करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्राथमिक समष्टि आर्थिक और परिचालन तर्क क्या दिया गया था?
(A) राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को तत्काल पूर्ण पैमाने पर निजीकरण और निजी खरीदारों को बहुलांश इक्विटी नियंत्रण के हस्तांतरण के लिए तैयार करना।
(B) बैलेंस शीट में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को समेकित करके आरबीआई के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढांचे के तहत नियामक पर्यवेक्षण को दरकिनार करना।
(C) जोखिम लेने की क्षमता में वृद्धि और समेकित परिचालन संरचनाओं वाले बड़े, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विशाल बैंकों का निर्माण करना।
(D) सभी सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को सूक्ष्म-ऋण बुनियादी ढांचे पर केंद्रित विशेष गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में जबरन परिवर्तित करना।

NODIA

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) अनुसूचित बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं, जबकि गैर-अनुसूचित बैंक शामिल नहीं हैं।
भारतीय बैंकिंग प्रणाली में वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण वैधानिक मापदंडों पर आधारित है। अनुसूचित बैंक वे संस्थान हैं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। इन बैंकों को केंद्रीय बैंक से पुनःकटौती और तरलता सुविधाएं प्राप्त करने की पात्रता होती है। दूसरी ओर, गैर-अनुसूचित बैंक इस अनुसूची में शामिल नहीं होते तथा वे इस विशेष सुविधा से वंचित रहते हैं।

2. (D) आम जनता से मांग जमा स्वीकार करना।
भारतीय रिज़र्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, जो शीर्ष मौद्रिक और नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। इसके मुख्य कार्यों में मुद्रा निर्गमन, सरकार और बैंकों का प्रबंधन तथा मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन शामिल है। रिज़र्व बैंक आम जनता से सीधे लेन-देन नहीं करता और न ही व्यक्तिगत मांग जमा स्वीकार करता है। यह कार्य केवल वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संपादित किया जाता है।

3. (B) धारा 22
बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 भारत में बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को भारत में बैंकिंग व्यवसाय शुरु करने हेतु संस्थाओं को लाइसेंस प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी वित्तीय इकाई रिज़र्व बैंक द्वारा जारी वैध लाइसेंस के बिना बैंकिंग गतिविधियों का संचालन नहीं कर सकती है। यह प्रावधान प्रणालीगत अनुशासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

4. (C) वह दर जिस पर आरबीआई स्वीकृत प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धनराशि उधार देता है।
रेपो दर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने हेतु प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण अल्पकालिक नीतिगत दर है। इस व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। जब रिज़र्व बैंक रेपो दर में परिवर्तन करता है, तो व्यावसायिक बैंकों की लागत प्रभावित होती है, जिससे बाज़ार में ब्याज दरों और साख की उपलब्धता पर सीधा असर पड़ता है।

5. (A) इसका उपयोग आरबीआई द्वारा बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए किया जाता है।
रिवर्स रेपो दर भारतीय रिज़र्व बैंक की तरलता समायोजन सुविधा का एक प्रमुख मौद्रिक उपकरण है। यह वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अतिरिक्त धनराशि को केंद्रीय बैंक के पास जमा करते हैं। जब बैंकिंग प्रणाली में अत्यधिक नकदी उपलब्ध होती है, तब रिज़र्व बैंक इस दर के माध्यम से बाज़ार से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करता है, जिससे वित्तीय बाज़ार में स्थिरता बनी रहती है।

NODIA

6. (D) वाणिज्यिक बैंकों के पास उपलब्ध ऋण योग्य निधि को कम करने के लिए CRR में वृद्धि करना।
नकद आरक्षित अनुपात वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं का वह अनिवार्य प्रतिशत है जिसे उन्हें नकद रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखना होता है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ता है, तो रिज़र्व बैंक संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाता है। इसके तहत CRR में वृद्धि की जाती है, जिससे बैंकों के पास ऋण देने योग्य उपलब्ध धनराशि घट जाती है। इसके परिणामस्वरूप मुद्रा की आपूर्ति कम होती है।

7. (B) नकद, सोना और प्रभार-मुक्त स्वीकृत सरकारी प्रतिभूतियां।
वैधानिक तरलता अनुपात एक अनिवार्य आवश्यकता है जिसके तहत वाणिज्यिक बैंकों को अपनी निवल मांग और सावधि देयताओं का निश्चित प्रतिशत तरल परिसंपत्तियों के रूप में स्वयं के पास रखना अनिवार्य होता है। इस आरक्षित निधि हेतु केवल अति-तरल परिसंपत्तियां पात्र होती हैं, जिनमें नकद, सोना और प्रभार-मुक्त स्वीकृत सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं। यह व्यवस्था बैंकिंग प्रणाली में वित्तीय सुरक्षा और तरलता संतुलन बनाए रखने हेतु आवश्यक है।

8. (A) केवल I और II
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे हैं जिनमें भारत सरकार के पास कम से कम 51 प्रतिशत की बहुलांश शेयरधारिता होती है। परिसंपत्ति आकार और व्यापारिक मात्रा के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को शेयर बाज़ार से पूंजी जुटाने पर कोई वैधानिक रोक नहीं है; वे सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखते हुए इक्विटी जुटा सकते हैं।

9. (D) केनरा बैंक
भारतीय बैंकिंग प्रणाली में बैंकों को उनके स्वामित्व पैटर्न के आधार पर मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों में वर्गीकृत किया जाता है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक निजी क्षेत्र के प्रमुख वाणिज्यिक बैंक हैं, जिनका स्वामित्व निजी निवेशकों के पास होता है। इसके विपरीत, केनरा बैंक भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है।

10. (B) 50 करोड़ रुपये से अधिक जमा वाले 14 बैंक
भारत में बैंकिंग क्षेत्र का पहला प्रमुख राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को लागू किया गया था। इस चरण के अंतर्गत सरकार द्वारा 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

इन बैंकों के चयन हेतु 50 करोड़ रुपये से अधिक की कुल जमा राशि को न्यूनतम मापदंड निर्धारित किया गया था। इस ऐतिहासिक निर्णय का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना था।

11. (B) ग्रामीण और बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का व्यापक विस्तार।
1969 और 1980 के बैंक राष्ट्रीयकरण का प्राथमिक दर्शन 'सामाजिक बैंकिंग' को बढ़ावा देना था, ताकि वित्तीय संसाधनों का लाभ केवल बड़े उद्योगपतियों तक सीमित न रहे। इस नीतिगत बदलाव का सबसे प्रत्यक्ष और व्यापक सकारात्मक परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण, अर्ध-शहरी और बैंकिंग सुविधाओं से अछूते क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का भारी विस्तार हुआ। इसने कृषि और छोटे व्यवसायों को औपचारिक साख से जोड़ा।

12. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
वर्ष 1975 में नरसिम्हम कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। उस समय देश के वाणिज्यिक बैंक मुख्य रूप से शहरी और व्यावसायिक केंद्रों में केंद्रित थे, जिसके कारण उनमें स्थानीय ग्रामीण परिस्थितियों, कृषि आवश्यकताओं और छोटे किसानों की ऋण जरूरतों को समझने वाले दृष्टिकोण की कमी थी। इसलिए ग्रामीण साख की खाई को पाटने हेतु इन्हें स्थापित किया गया था।

13. (A) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
भारत में अल्पकालिक और मध्यमकालिक ऋण प्रदान करने वाली ग्रामीण सहकारी साख संरचना त्रि-स्तरीय प्रणाली के तहत गठित है। इस ढाँचे में सबसे निचले यानी ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियां कार्य करती हैं। मध्यवर्ती यानी जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कार्य करते हैं, जो प्राथमिक समितियों को वित्तपोषित करते हैं। राज्य स्तर पर शीर्ष संस्था के रूप में राज्य सहकारी बैंक कार्य करता है।

14. (C) क्रेडिट कार्ड जारी करना और सामान्य ऋण देना।
भुगतान बैंक भारत में वित्तीय समावेशन को गति देने के लिए स्थापित एक विशेष और विभेदित बैंकिंग श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन बैंकों को मांग जमा स्वीकार करने, एटीएम या डेबिट कार्ड जारी करने तथा इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होती है। हालांकि, वित्तीय जोखिमों को रोकने के उद्देश्य से भुगतान बैंकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऋण देने से प्रतिबंधित किया गया है।

15. (B) केवल I, II और IV
लघु वित्त बैंक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु स्थापित संस्थाएं हैं, जो असंगठित क्षेत्र, छोटे किसानों और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण एवं जमा सेवाएं प्रदान करते हैं। भुगतान बैंकों के विपरीत, लघु वित्त बैंकों को उधार देने और साख सृजन की पूर्ण अनुमति है। इन बैंकों के लिए अनिवार्य है कि उनके कुल ऋण का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा 25 लाख रुपये तक का हो।

16. (C) NBFCs भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं बनती हैं और स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकती हैं।
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं लेकिन वे कई महत्वपूर्ण पहलुओं में वाणिज्यिक बैंकों से अलग होती हैं। सबसे प्रमुख अंतर यह है कि NBFCs देश की औपचारिक भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं बनती हैं। नतीजतन, वे अपने स्वयं के खातों पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकती हैं और न ही उन्हें मांग जमा स्वीकार करने की अनुमति होती है।

17. (B) वह उधारकर्ता जिसके पास चुकाने की क्षमता है लेकिन वह जानबूझकर भुगतान दायित्वों में चूक करता है।
भारतीय बैंकिंग विनियमों के तहत "स्वेच्छाचारी चूककर्ता" उस उधारकर्ता या संस्था को घोषित किया जाता है जिसके पास अपने वित्तीय ऋण दायित्वों को चुकाने की पूर्ण क्षमता उपलब्ध होने के बावजूद, वह जानबूझकर भुगतान करने में चूक करता है। इसके अतिरिक्त, इस श्रेणी में वे उधारकर्ता भी शामिल हैं जिन्होंने ऋण का दुरुपयोग किया या बैंक की सहमति के बिना परिसंपत्तियां बेच दीं।

18. (D) नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL)
भारतीय बैंकिंग प्रणाली में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के भारी बोझ को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक 'बैड बैंक' संरचना का समर्थन किया। इसके तहत नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) की स्थापना की गई। NARCL बैंकों की बैलेंस शीट से बड़ी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को अधिग्रहित करती है और उनकी वसूली का प्रबंधन करती है। इससे बैंकों की साख क्षमता बढ़ती है।

19. (A) एम. नरसिम्हम
1991 के आर्थिक संकट के पश्चात भारत सरकार ने वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक संरचनात्मक सुधारों की रुपरेखा तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस वित्तीय प्रणाली समिति के अध्यक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर एम. नरसिम्हम थे। नरसिम्हम समिति की सिफारिशों ने भारत में आधुनिक बैंकिंग क्षेत्र के उदारीकरण और सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया।

20. (A) P-2, Q-3, R-4, S-1
भारतीय वित्तीय प्रणाली में विभिन्न संस्थाएं विशिष्ट कार्य संपादित करती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक देश का शीर्ष मौद्रिक और बैंकिंग नियामक प्राधिकरण है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खुदरा डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे और निपटान का प्रबंधन करता है। लघु वित्त बैंक सूक्ष्म उद्यमों और छोटे किसानों को साख सुविधाएं देते हैं। परिसंपत्ति पुनर्रचना कंपनियां गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का एकत्रीकरण और समाधान करती हैं।

21. (A) ये खाता सक्रिय करने के लिए तत्काल 10,000 रुपये की अग्रिम जमा राशि अनिवार्य करते हैं।
प्रधानमंत्री जन धन योजना अगस्त 2014 में शुरु की गई भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी वित्तीय समावेशन पहल है।

Downloaded from www.pdf.tube

इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक परिवार को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है। इस योजना के तहत खोले जाने वाले खाते शून्य-शेष खाते होते हैं, जिनमें कोई भी न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि अनिवार्य नहीं होती है। इन खातों के साथ ग्राहकों को रुपे डेबिट कार्ड और बीमा कवर मिलता है।

22. (D) यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस
डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले UPI का पूरा नाम 'यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' है। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किया गया है। UPI एक एकल मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से कई बैंक खातों को एकीकृत करता है और उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में त्वरित और सुरक्षित रूप से धन स्थानांतरित करने की सुविधा देता है।

23. (B) यह दिवाला समाधान के लिए एक सख्त, समयबद्ध तंत्र लागू करती है।
वर्ष 2016 में अधिनियमित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) भारत में कंपनियों के दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित करती है। इस कानूनी ढांचे की सबसे मुख्य विशेषता एक सख्त और समयबद्ध समाधान प्रक्रिया प्रदान करना है। इसके तहत संकटग्रस्त कंपनियों का परिसमापन करने के बजाय उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का त्वरित निपटान हो सके।

24. (C) सार्वभौमिक बुनियादी आय गारंटी
बासेल III मानदंड वैश्विक बैंकिंग प्रणाली में जोखिम प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए जारी अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं। यह ढांचा तीन मूलभूत स्तंभों पर आधारित है: पहला- न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं; दूसरा- पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया; और तीसरा- बाज़ार अनुशासन तथा वित्तीय प्रकटीकरण। सार्वभौमिक बुनियादी आय गारंटी एक सामाजिक कल्याण अवधारणा है, जो इन मानकों का हिस्सा नहीं है।

25. (A) 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, भुगतान बैंकों की शुरुआत, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का अधिनियमन
भारतीय बैंकिंग इतिहास में इन महत्वपूर्ण घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है: सर्वप्रथम, 1969 में 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद, 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। तत्पश्चात, 2014 में भुगतान बैंकों की शुरुआत हुई। अंततः, 2016 में ही तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के त्वरित समाधान हेतु दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अधिनियमित की गई।

26. (C) 40 प्रतिशत
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण (PSL) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लागू एक महत्वपूर्ण नियामक ढांचा है। इसके तहत सभी घरेलू वाणिज्यिक बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, शिक्षा तथा आवास जैसे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आवंटित करना अनिवार्य होता है।

27. (B) पंजाब नेशनल बैंक
अप्रैल 2020 में लागू सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समेकन के व्यापक पुनर्गठन दौरान, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। पंजाब नेशनल बैंक ने इस एकीकरण में एंकर बैंक के रूप में कार्य किया, जिससे वह भारतीय स्टेट बैंक के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया।

28. (B) केवल I और III
भारतीय रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति उपकरणों का अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब आरबीआई रेपो दर में वृद्धि करता है, तो वाणिज्यिक बैंकों की ऋण दरें बढ़ती हैं। नकद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। हालांकि, रिवर्स रेपो दर को हमेशा रेपो दर से कम रखा जाता है ताकि बैंक अर्थव्यवस्था में ऋण देने हेतु प्रोत्साहित रहें।

29. (A) 5 लाख रुपये से कम की प्रदत्त पूंजी और कुल आरक्षित निधि होना।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी बैंक को दूसरी अनुसूची में शामिल होने के लिए न्यूनतम 5 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधि का होना अनिवार्य है। यदि किसी वित्तीय बैंक की प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधि 5 लाख रुपये से कम है, तो वह अनुसूची में सूचीबद्ध होने हेतु अयोग्य हो जाता है तथा गैर-अनुसूचित बैंक कहलाता है।

30. (C) एक रुपये का नोट
भारत में करेंसी नोट और सिक्कों के निर्गमन की व्यवस्था एक विशेष संरचना पर आधारित है। रिज़र्व बैंक दो रुपये और उससे अधिक मूल्यवर्ग के नोट जारी करता है। इसके विपरीत, एक रुपये का नोट और सभी सिक्के सीधे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। इसी कारण एक रुपये के नोट पर रिज़र्व बैंक गवर्नर के बजाय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।

NODIA

31. (D) बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949
भारतीय रिज़र्व बैंक को देश की बैंकिंग प्रणाली का प्रभावी पर्यवेक्षण और निरीक्षण करने का व्यापक कानूनी अधिकार बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 से प्राप्त होता है। इस अधिनियम के तहत रिज़र्व बैंक को वाणिज्यिक बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य, लेखा-परीक्षा और प्रशासन की जांच करने हेतु प्रत्यक्ष निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, जिससे जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

32. (C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक रेपो दर में वृद्धि करता है। रेपो दर बढ़ने से वाणिज्यिक बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है, जिससे

वे अपनी ऋण दरों को बढ़ाते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में साख की मांग घटती है और मुद्रा की आपूर्ति कम होती है। इसलिए कारण में उधार सस्ता होने का दावा गलत है।

33. (B) आरबीआई CRR शेष पर कोई ब्याज नहीं देता है।
नकद आरक्षित अनुपात एक वैधानिक आवश्यकता है जिसके तहत वाणिज्यिक बैंकों को अपनी निवल मांग और सावधि देयताओं का एक निश्चित प्रतिशत नकद रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा रखना होता है। वर्तमान नियामक ढांचे के अनुसार, रिज़र्व बैंक के पास रखी जाने वाली इस अनिवार्य CRR जमा राशि पर बैंकों को कोई भी ब्याज प्रदान नहीं किया जाता है।

34. (D) CRR शेष राशि आरबीआई के पास जमा की जाती है, जबकि SLR परिसंपत्तियां स्वयं बैंकों द्वारा रखी जाती हैं।
यद्यपि CRR और SLR दोनों ही बैंकों की तरलता को नियंत्रित करने वाले मौद्रिक उपकरण हैं, लेकिन उनके रखरखाव में एक मुख्य अंतर है। नकद आरक्षित अनुपात के तहत निर्धारित राशि को बैंकों द्वारा नकद रूप में रिज़र्व बैंक के पास जमा करना होता है। इसके विपरीत, वैधानिक तरलता अनुपात के अंतर्गत स्वीकृत तरल परिसंपत्तियों को बैंक स्वयं अपने पास बनाए रखते हैं।

35. (A) केवल I, II और III
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में नरसिम्हम कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। इन बैंकों की शेयर पूंजी केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के बीच 50:15:35 के अनुपात में विभाजित होती है, जिसमें केंद्र सरकार के पास 50 प्रतिशत हिस्सेदारी होती है। RRBs को भी CRR और SLR बनाए रखना पूर्णतः अनिवार्य होता है।

36. (C) आरबीआई अधिक पर्यवेक्षी नियंत्रण प्राप्त करता है और स्थानीय परिचालनों को मूल वैश्विक झटकों से सुरक्षित रखता है।
जब विदेशी बैंक भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में कार्य करते हैं, तो उन्हें स्थानीय बैंक माना जाता है। इससे भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके शासन और जोखिम प्रबंधन पर बेहतर पर्यवेक्षी नियंत्रण प्राप्त होता है। यह व्यवस्था विदेशी बैंकों के स्थानीय परिचालनों को उनकी वैश्विक मूल संस्थाओं के वित्तीय झटकों से सुरक्षित रखने में मदद करती है।

37. (B) 200 करोड़ रुपये से अधिक की मांग और सावधि देयताएं (NDTL)
अप्रैल 1980 में भारत सरकार ने बैंक राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण की घोषणा की, जिसके तहत छह और निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इन बैंकों के चयन हेतु सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपये से अधिक की निवल मांग और सावधि देयताओं (NDTL) को निर्णायक मापदंड निर्धारित किया गया था। इस कदम का उद्देश्य साख नियंत्रण का विस्तार करना था।

38. (D) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण (PSL) लक्ष्य
राष्ट्रीयकरण के उपरांत, भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण (PSL) के दिशानिर्देशों को लागू किया ताकि बैंक अर्थव्यवस्था के उपेक्षित क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण प्रदान करें। इस नीति के तहत कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा कमजोर वर्गों के लिए बैंकों के कुल ऋण का एक विशिष्ट हिस्सा आवंटित करना अनिवार्य कर दिया गया, जिससे उनका समावेशी विकास हो सके।

39. (B) गाँव के स्तर पर कार्य करने वाली प्राथमिक कृषि साख समिति (PACS)
भारत की त्रि-स्तरीय अल्पकालिक सहकारी साख संरचना में प्राथमिक कृषि साख समिति (PACS) ग्राम स्तर पर कार्य करती है। यह इकाई सीधे किसानों और छोटे उधारकर्ताओं से जुड़ती है तथा उन्हें कृषि कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। PACS ग्राम स्तर पर किसानों से सीधे जमा स्वीकार करने और उन्हें सस्ती दरों पर साख प्रदान करने वाली प्राथमिक संस्था होती है।

40. (A) P-4, Q-3, R-2, S-1
विभिन्न बैंकिंग अनुपातों और दरों का सही मिलान इस प्रकार है: रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। रिवर्स रेपो दर पर आरबीआई अतिरिक्त तरलता अवशोषित करता है। नकद आरक्षित अनुपात NDTL का वह प्रतिशत है जिसे बैंकों को आरबीआई के पास नकद रखना होता है। वैधानिक तरलता अनुपात बैंकों द्वारा स्वयं रखी जाने वाली परिसंपत्तियां हैं।

41. (D) प्रवासी मजदूर, कम आय वाले परिवार और असंगठित छोटी व्यावसायिक इकाइयां
भुगतान बैंकों का मुख्य उद्देश्य प्रवासी मजदूरों, कम आय वाले परिवारों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यवसायियों को लघु बचत खाते एवं भुगतान सेवाएं उपलब्ध कराकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। इन वर्गों को पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली में अपर्याप्त सेवाएं मिलती थीं। भुगतान बैंक प्रद्योगिकी का उपयोग करके इन लक्षित समूहों को कम लागत पर सुलभ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं।

42. (D) 75 प्रतिशत
लघु वित्त बैंक विशेष रूप से उन क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं जहां पारंपरिक बैंकों की पहुंच कम है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु, रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों पर कठोर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण लक्ष्य लागू किया है। सामान्य वाणिज्यिक बैंकों के 40 प्रतिशत की तुलना में, इन बैंकों को अपने ANBC का 75 प्रतिशत हिस्सा PSL में देना होता है।

43. (B) क्योंकि NBFCs को आरबीआई की अंतिम ऋणदाता तरलता सहायता तक सीधी पहुंच के बिना परिसंपत्ति-देयता असंतुलन का सामना करना पड़ता है।
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 'शैडो बैंकिंग' क्षेत्र माना जाता है क्योंकि वे बैंकों की भांति ऋण देती हैं। नियामक इन पर

Click Here to Buy book on Amazon

सतर्कता बनाए रखते हैं क्योंकि NBFCs अक्सर अल्पकालिक बाज़ार निधियों से वित्तपोषण करके दीर्घकालिक ऋण देती हैं, जिससे परिसंपत्ति-देयता असंतुलन का जोखिम उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें केंद्रीय बैंक से अंतिम ऋणदाता की सीधी तरलता सहायता प्राप्त नहीं होती है।

44. (B) तनावग्रस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और अत्यधिक कर्जदार कॉर्पोरेट इकाइयां
भारतीय अर्थव्यवस्था में "दोहरी बैलेंस शीट" की समस्या तनावग्रस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अत्यधिक कर्जदार कॉर्पोरेट समूहों के वित्तीय संकट को दर्शाती है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की बड़ी कंपनियों ने अत्यधिक ऋण लिया, लेकिन राजस्व में गिरावट के कारण वे दबाव में आ गईं। इसके परिणामस्वरुप बैंकों की बैलेंस शीट में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां बढ़ गईं, जिससे दोनों क्षेत्र वित्तीय तनाव में आ गए।

45. (A) II, IV, III, I
भारतीय बैंकिंग और नियामक ढाँचे का सही कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है: सर्वप्रथम, 1969 में 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद, 1991 में नरसिम्हम समिति की स्थापना की गई। तत्पश्चात, 2016 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की शुरुआत की गई। अंततः, 2016 में ही तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान हेतु दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता लागू की गई।

46. (C) बैंकों से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को उनके समाधान, पुनर्गठन या परिसंपत्ति वसूली का प्रयास करने के लिए खरीदना।
परिसंपत्ति पुनर्रचना कंपनियां विशेष वित्तीय संस्थान हैं जो बैंकों की बैलेंस शीट को स्वच्छ बनाने में मदद करती हैं। ARC का मूल कार्य वाणिज्यिक बैंकों से उनकी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को खरीदना है। इसके बाद, ये कंपनियां उधारकर्ताओं के व्यवसाय का पुनर्गठन करके, परिसंपत्तियों का प्रबंधन करके या उनकी बिक्री करके ऋण वसूली का प्रयास करती हैं, जिससे वित्तीय स्थिरता बनी रहती है।

47. (D) वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करके मजबूत विशाल बैंक (मेगा बैंक) बनाना।
वित्तीय क्षेत्रक सुधारों पर गठित दूसरी नरसिम्हम समिति (1998) ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशाल बैंकों के निर्माण की सिफारिश की थी। समिति का मानना था कि छोटे बैंकों के स्थान पर बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समेकन करके मजबूत और पूंजीगत रुप से सक्षम मेगा बैंक बनाए जाने चाहिए जो वैश्विक स्तर पर मुकाबला कर सकें।

48. (A) केवल I और II
रुपे कार्ड नेटवर्क भारत का एक स्वदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क है, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा घरेलू स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणालियों पर निर्भरता कम करने हेतु विकसित किया गया था। यह कम लागत वाला भुगतान विकल्प प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के माध्यम से रुपे कार्ड का उपयोग विदेशों में भी एटीएम और दुकानों पर किया जा सकता है।

49. (C) 2016
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा वर्ष 2016 में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। इस अभूतपूर्व तकनीकी नवाचार ने भारत में डिजिटल भुगतान परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। UPI के माध्यम से उपयोगकर्ता बिना बैंक विवरण साझा किए, केवल एक वर्चुअल एड्रेस के ज़रिए वास्तविक समय में त्वरित धन हस्तांतरण कर सकते हैं।

50. (D) राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (NCLT)
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के वैधानिक ढांचे के तहत, राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (NCLT) कॉर्पोरेट संस्थाओं और पंजीकृत कंपनियों के दिवाला समाधान मामलों के लिए प्राथमिक निर्णयकारी प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। जब कोई कॉर्पोरेट कर्जदार अपने ऋण भुगतान में चूक करता है, तो लेनदार समाधान प्रक्रिया शुरु हेतु NCLT के समक्ष आवेदन दायर करते हैं।

51. (A) बैंक की पूंजी का उसकी जोखिम-भारित परिसंपत्तियों से अनुपात।
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR), जिसे जोखिम-भारित परिसंपत्ति पूंजी अनुपात भी कहा जाता है, बैंकिंग विनियमन का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। यह अनुपात बैंक की उपलब्ध कुल पूंजी की उसकी कुल जोखिम-भारित परिसंपत्तियों से तुलना करता है। यह मापदंड यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि बैंक संभावित वित्तीय नुकसान को सहन करने के लिए पर्याप्त पूंजी रखें।

NODIA

52. (C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण नीति के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को कृषि और सूक्ष्म उद्यमों को अपनी निधियों का निश्चित प्रतिशत उधार देने हेतु बाध्य करता है। हालांकि, इन क्षेत्रों को ऋण इसलिए नहीं दिया जाता कि वे अत्यधिक लाभदायक या कम जोखिम वाले हैं, बल्कि इसलिए दिया जाता है क्योंकि वे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं।

53. (B) 2017
भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने बैंक समेकन की पहल की। इस ऐतिहासिक निर्णय के तहत, 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में उसके पांच सहयोगी बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक का विलय प्रभावी हुआ। इस विलय के बाद भारतीय स्टेट बैंक विश्व के शीर्ष पचास बैंकों में शामिल हो गया।

54. (D) आरबीआई और संबंधित राज्य या केंद्र सरकार का सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार (RCS)।
भारत में शहरी सहकारी बैंक ऐतिहासिक रूप से एक 'दोहरे नियंत्रण' ढांचे के तहत कार्य करते रहे हैं। इस संरचना में, बैंकिंग संबंधी कार्यों, जैसे लाइसेंसिंग और पूंजी पर्याप्तता का नियमन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता था, जबकि उनका प्रशासनिक प्रबंधन और चुनाव संबंधित राज्य या केंद्र सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCS) के नियंत्रण में आता था।

55. (B) केवल I, III और IV
भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है तथा सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन और नए ऋण साधन जारी करता है। यह सरकारों को प्राप्तियों और भुगतानों में अस्थायी असंतुलन को दूर करने के लिए साधन और उपाय अग्रिम (WMA) प्रदान करता है। हालांकि, आरबीआई विशिष्ट समझौतों के आधार पर ही राज्य सरकारों के बैंकिंग परिचालनों का प्रबंधन करता है।

56. (C) त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA)
त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किया गया एक विशेष पर्यवेक्षी ढांचा है। इसका उद्देश्य वित्तीय रूप से कमज़ोर बैंकों में समय रहते हस्तक्षेप करना है। जब किसी बैंक के वित्तीय मापदंड, जैसे पूंजी पर्याप्तता और परिसंपत्ति गुणवत्ता, निर्धारित सीमा से नीचे गिर जाते हैं, तो आरबीआई उस पर PCA लागू करके उसकी विशिष्ट गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है।

57. (C) 6 सदस्य
भारत में मौद्रिक नीति समिति (MPC) एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन मूल्य स्थिरता बनाए रखने और रेपो दर निर्धारित करने हेतु किया गया है। मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य शामिल होते हैं। इन छह सदस्यों में से तीन सदस्य भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि होते हैं और शेष तीन सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ होते हैं।

58. (A) रिवर्स रेपो दर
अप्रैल 2022 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थायी जमा सुविधा (SDF) लागू किए जाने से पहले, तरलता समायोजन सुविधा (LAF) गलियारे की निचली सीमा रिवर्स रेपो दर द्वारा निर्धारित की जाती थी। LAF गलियारे की ऊपरी सीमा MSF दर और मध्य बिंदु रेपो दर होता था। SDF की शुरुआत के बाद, इसने तरलता सोखने हेतु रिवर्स रेपो दर का स्थान ले लिया।

59. (B) नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज (निवल मांग और सावधि देयताएं)
भारतीय बैंकिंग प्रणाली में NDTL का पूर्ण रूप 'नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज' है। यह बैंक की जनता और वित्तीय संस्थानों के प्रति कुल जमा देयताओं को दर्शाता है। इसमें बचत और चालू खाते जैसी मांग देयताएं तथा सावधि जमाएं शामिल होती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अनिवार्य आरक्षित अनुपातों, जैसे CRR और SLR, की गणना NDTL के प्रतिशत के रूप में करता है।

60. (A) P-3, Q-4, R-2, S-1
विभिन्न बैंकिंग समितियों और अधिनियमों का सही मिलान इस प्रकार है: नरसिम्हम समिति 1991 ने वित्तीय क्षेत्रक सुधारों की सिफारिश की। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान हेतु समयबद्ध तंत्र प्रदान करती है। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 भारतीय बैंकों के लिए बुनियादी नियामक ढांचा प्रदान करता है। बासेल समिति अंतर्राष्ट्रीय पूंजी पर्याप्तता मानदंड तैयार करती है।

61. (A) असुरक्षित कॉर्पोरेट डिबेंचर
वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के तहत बैंकों को अपनी देयताओं का निर्दिष्ट हिस्सा अत्यधिक तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना अनिवार्य होता है। SLR हेतु पात्र परिसंपत्तियों में नकद, सोना, सरकारी प्रतिभूतियां और राज्य विकास ऋण शामिल हैं। निजी कंपनियों द्वारा जारी असुरक्षित कॉर्पोरेट डिबेंचर में साख जोखिम होता है, इसलिए वे SLR के तहत पूरी तरह अयोग्य माने जाते हैं।

62. (C) भारतीय स्टेट बैंक
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) भारत की समग्र बैंकिंग प्रणाली में कुल परिसंपत्तियों, जमा राशि, ऋण संवितरण और शाखा नेटवर्क के संदर्भ में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। देश के बैंकिंग परिचालन में इसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है। 2017 में अपने सहयोगी बैंकों के विलय के उपरांत, भारतीय स्टेट बैंक विश्व के शीर्ष पचास बैंकों में शामिल होने वाला एकमात्र बैंक बना।

63. (D) इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया
वर्ष 1921 में तीन प्रेसीडेंसी बैंकों का विलय करके 'इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया' का गठन किया गया था। यह बैंक स्वतंत्रता-पूर्व भारत में व्यावसायिक और केंद्रीय बैंकिंग कार्य संपादित करता था। स्वतंत्रता के पश्चात, ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों पर, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम बदलकर 'भारतीय स्टेट बैंक' कर दिया गया था।

64. (C) एक अनिवार्य शाखा-लाइसेंसिंग फॉर्मूला जिसके तहत बैंकों को प्रत्येक स्वीकृत शहरी शाखा के लिए ग्रामीण शाखाओं का एक निश्चित कोटा खोलना आवश्यक था।
1969 के बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्रामीण बैंकिंग विस्तार को गति देने के लिए एक सख्त शाखा-लाइसेंसिंग नीति लागू की। इस नीति के तहत एक अनिवार्य फॉर्मूला निर्धारित किया गया था, जिसके अनुसार वाणिज्यिक बैंकों को शहरी केंद्रों में एक नई शाखा खोलने की अनुमति तभी दी जाती थी जब वे ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलते थे।

65. (B) प्राथमिक कृषि साख समिति → जिला केंद्रीय सहकारी बैंक → राज्य सहकारी बैंक
राजस्थान सहित भारत में अल्पकालिक सहकारी साख संरचना तीन स्तरों में संगठित है। इसका सही आरोही क्रम इस प्रकार है:

Downloaded from www.pdf.tube

सबसे निचले गांव के स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियां स्थित होती हैं; जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कार्य करते हैं; और राज्य स्तर पर शीर्ष संस्था के रूप में राज्य सहकारी बैंक सक्रिय भूमिका निभाता है।

66. (B) 35 प्रतिशत
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) एक विशिष्ट संयुक्त स्वामित्व संरचना के तहत कार्य करते हैं, जिसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक प्रायोजक वाणिज्यिक बैंक के बीच साझा किया जाता है। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल शेयर पूंजी में भारत सरकार का हिस्सा 50 प्रतिशत, राज्य सरकार का 15 प्रतिशत और प्रायोजक बैंक का हिस्सा 35 प्रतिशत होता है।

67. (A) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs)
राजस्थान की सहकारी साख संरचना में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड राज्य स्तर पर सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करता है। यह शीर्ष बैंक सीधे जिला स्तर पर कार्यरत जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) को वित्तीय संसाधन और पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है। इसके बाद, DCCBs प्राथमिक कृषि साख समितियों को ऋण संवितरित करते हैं जो अंततः किसानों तक पहुंचता है।

68. (B) केवल I और III
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत, जब NCLT आवेदन स्वीकार करता है, तो ऋण वसूली रोकने हेतु मोराटोरियम की घोषणा की जाती है। इसके बाद लेनदारों की समिति (CoC) बनाई जाती है, जिसमें मुख्यतः वित्तीय लेनदार शामिल होते हैं तथा उनके पास मतदान अधिकार होता है। यदि समय-सीमा में समाधान न हो, तो NCLT कंपनी के परिसमापन का आदेश देता है।

69. (C) 200 करोड़ रुपये
भारतीय रिज़र्व बैंक के अद्यतन दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत में एक नया लघु वित्त बैंक (SFB) स्थापित करने हेतु न्यूनतम प्रदत्त इक्विटी पूंजी 200 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, लघु वित्त बैंक में परिवर्तित होने वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़ रुपये है जिसे आगे बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करना अनिवार्य होता है।

70. (A) II, III, I, IV
भारतीय बैंकिंग प्रणाली में इन तकनीकी पहलों का सही कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है: सर्वप्रथम, 2005 में NEFT की शुरुआत (II) की गई। इसके बाद, 2012 में रुपे कार्ड योजना (III) लॉन्च की गई। तत्पश्चात, 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना (I) शुरू की गई। अंत में, 2016 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (IV) की शुरुआत सफलतापूर्वक की गई।

71. (B) माइक्रो-फाइनेंस इंस्टीट्यूशन
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण में NBFC-MFI का पूर्ण रूप 'माइक्रो-फाइनेंस इंसटीट्यूशन' (सूक्ष्म वित्त संस्थान) है। यह एक विशेष NBFC होती है जो मुख्य रूप से कम आय वाले परिवारों, महिला स्व-सहायता समूहों और छोटे ग्रामीण उद्यमियों को बिना किसी संपार्श्विक के छोटे आकार के ऋण प्रदान करती है, जिससे जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा प्राप्त होता है।

72. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
लंबी आर्थिक सुस्ती की अवधि के दौरान बैंकों के सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात में वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि आर्थिक मंदी कॉर्पोरेट क्षेत्र की लाभप्रदता को घटाती है तथा व्यक्तियों की आय को प्रभावित करती है। वित्तीय दबाव के कारण उधारकर्ताओं की अपने ऋणों को समय पर चुकाने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे NPA बढ़ता है।

73. (D) सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम, 2002
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता पारित होने से पहले, भारतीय बैंकों के पास खराब ऋणों की वसूली हेतु सरफेसी अधिनियम, 2002 एक शक्तिशाली कानूनी उपकरण था। यह अधिनियम बैंकों को अदालतों के हस्तक्षेप के बिना चूककर्ता उधारकर्ताओं की बंधक रखी गई परिसंपत्तियों को जब्त करने और उन्हें बेचकर ऋण वसूलने की सीधी शक्ति देता था।

74. (A) कंपनियों द्वारा इक्विटी पूंजी की तुलना में अत्यधिक बैंक ऋण लेना, जिसके परिणामस्वरूप ऋण चुकाने का गंभीर बोझ पड़ता है।
वित्तीय शब्दावली में "अत्यधिक कर्जदार" शब्द उस स्थिति का वर्णन करता है जहां किसी कंपनी ने अपनी इक्विटी पूंजी की तुलना में अत्यधिक मात्रा में बैंक ऋण ले लिया होता है। ऐसी स्थिति कंपनी के ढांचे को जोखिमपूर्ण बनाती है। जब आर्थिक मंदी या व्यावसायिक व्यवधान आते हैं, तो ये कंपनियां भारी ब्याज का बोझ उठाने में असमर्थ हो जाती हैं।

75. (B) केवल I, III और IV
भारत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण (PSL) दिशानिर्देशों के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों को कृषि क्षेत्रक के लिए अपने ANBC का न्यूनतम 18 प्रतिशत आवंटित करना होता है। इसके अतिरिक्त, MSME क्षेत्र और 50 करोड़ रुपये तक के स्टार्टअप्स को दिए गए ऋण भी PSL में शामिल हैं। 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों पर भी यह लक्ष्य लागू होता है।

76. (B) उत्पादक वाणिज्यिक साख ऋण के लिए बैंक संसाधनों को मुक्त (अनलॉक) करने हेतु SLR और CRR आवश्यकताओं को कम करना।
1991 की नरसिम्हम समिति ने वित्तीय क्षेत्रक सुधारों के तहत बैंकों की लाभप्रदता और दक्षता में सुधार हेतु वैधानिक आरक्षित अनुपातों को कम करने की सिफारिश की थी। उस समय उच्च SLR और CRR के कारण बैंकों के संसाधनों का बड़ा हिस्सा अवरुद्ध होता था। समिति ने सिफारिश की कि इन अनुपातों को घटाकर व्यावसायिक ऋण हेतु संसाधनों को मुक्त किया जाए।

77. (A) 2007-08 का वैश्विक वित्तीय संकट
बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट के प्रत्यक्ष जवाब में बासेल III अंतर्राष्ट्रीय नियामक ढांचे को विकसित किया था। इस वित्तीय संकट ने बैंकिंग प्रणाली में अत्यधिक जोखिम और अपर्याप्त पूंजी को उजागर किया था। बासेल III का उद्देश्य पूंजी मानदंडों को सख्त बनाकर और तरलता संतुलन लागू करके बैंकिंग स्थिरता को मजबूत करना था।

78. (A) P-2, Q-4, R-3, S-1
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वृहद विलय के तहत एंकर बैंकों और संबंधित बैंकों का सही मिलान इस प्रकार है: सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हुआ। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।

79. (D) दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत और परिसमापन लागत
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 की धारा 53 के तहत परिसमापन की स्थिति में परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि के वितरण हेतु एक जलप्रपात (वाटरफॉल) प्राथमिकता तंत्र है। इस क्रम में सबसे शीर्ष प्राथमिकता दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत और परिसमापन लागत के भुगतान को दी गई है। इन लागतों के भुगतान के बाद ही अन्य दावों का निपटान होता है।

80. (C) जोखिम लेने की क्षमता में वृद्धि और समेकित परिचालन संरचनाओं वाले बड़े, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विशाल बैंकों का निर्माण करना।
भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वृहद विलय का मुख्य उद्देश्य ऐसे बड़े और मजबूत विशाल बैंक बनाना था जिनकी जोखिम सहने की क्षमता अधिक हो तथा जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें। इस विलय से बैंकों का पूंजी आधार बढ़ा, परिचालन लागत घटी और तकनीकी संसाधनों का समेकन हुआ, जिससे साख संवितरण क्षमता में सुधार हुआ।

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Flipkart

अध्याय 03
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

1. प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच निम्नलिखित में से कौन-सा एक मौलिक अंतर है?
   (A) प्रत्यक्ष कर केवल वस्तुओं पर लगाए जाते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर केवल सेवाओं पर लगाए जाते हैं।
   (B) प्रत्यक्ष कर में, कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर में, ये अलग-अलग व्यक्तियों पर पड़ते हैं।
   (C) प्रत्यक्ष कर को उपभोक्ता पर स्थानांतरित किया जा सकता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।
   (D) अप्रत्यक्ष कर प्रकृति में प्रगतिशील होते हैं, जबकि प्रत्यक्ष कर सामान्यतः प्रतिगामी होते हैं।

2. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है?
   (A) सीमा शुल्क
   (B) वस्तु एवं सेवा कर
   (C) केंद्रीय उत्पाद शुल्क
   (D) निगम कर

3. भारत सरकार द्वारा शुरु की गई नई आयकर व्यवस्था के तहत, पुरानी व्यवस्था की तुलना में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन एक प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है?
   (A) नई व्यवस्था कम कर दरों की पेशकश करती है लेकिन करदाता को अधिकांश पारंपरिक कटौतियों और छूटों को त्यागने की आवश्यकता होती है।
   (B) नई व्यवस्था सभी आय श्रेणियों के लिए उच्च कर दरों को अनिवार्य करती है लेकिन असीमित छूट प्रदान करती है।
   (C) नई व्यवस्था केवल कॉर्पोरेट संस्थाओं पर लागू होती है, जबकि पुरानी व्यवस्था व्यक्तियों पर लागू होती है।
   (D) नई व्यवस्था व्यक्तियों को रिटर्न दाखिल किए बिना अनिश्चित काल के लिए घाटे को आगे ले जाने की अनुमति देती है।

4. आयकर पर अधिभार लगाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
   (A) सभी करदाताओं के लिए प्राथमिक आयकर को प्रतिस्थापित करना।
   (B) केंद्रीय पूल से सीधे स्थानीय नगर निकायों को निधि देना।
   (C) विशेष रूप से उच्च आय वर्ग के करदाताओं से अतिरिक्त राजस्व एकत्र करना।
   (D) वरिष्ठ नागरिकों को कर छूट प्रदान करना।

5. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
   कथन (A): अप्रत्यक्ष करों की अक्सर प्रकृति में प्रतिगामी होने के लिए आलोचना की जाती है।
   कारण (R): अप्रत्यक्ष कर उपभोक्ता के आय स्तर की परवाह किए बिना एक समान दर से लगाए जाते हैं, जो उच्च आय अर्जित करने वालों की तुलना में कम आय अर्जित करने वालों की आय का एक बड़ा प्रतिशत लेते हैं।
   (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।
   (B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
   (C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
   (D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

6. 2016 का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम मुख्य रूप से भारत में निम्नलिखित में से किस आर्थिक सुधार से संबंधित है?
   (A) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की शुरुआत
   (B) वैधानिक मौद्रिक नीति समिति की स्थापना
   (C) कॉर्पोरेट्स के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर का उन्मूलन
   (D) वस्तु एवं सेवा कर ढांचे की शुरुआत

7. जीएसटी के संदर्भ में "एक राष्ट्र, एक कर" के नारे के पीछे अंतर्निहित औचित्य क्या है?
   (A) बिना किसी अपवाद के पूरे भारत में सभी घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर 18% की एकल सार्वभौमिक कर दर लागू करना।
   (B) विभिन्न केंद्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष करों को एक एकल कर ढांचे में शामिल करके घरेलू बाजार को एकीकृत करना।
   (C) सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को एक एकीकृत कर संरचना में मिलाना जो विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाए।
   (D) किसी भी घरेलू राजस्व धाराओं को एकत्र करने के सभी व्यक्तिगत राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकार को समाप्त करना।

8. सूची-I में दिए गए कराधान शब्दों का सूची-II में दिए गए उनके उपयुक्त विवरणों के साथ मिलान कीजिए।
   सूची I: कराधान शब्द
   P. अधिभार
   Q. न्यूनतम वैकल्पिक कर

Downloaded from www.pdf.tube

R. कर अवकाश
S. उपकर

सूची II: विवरण
1. निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए करों के भुगतान से एक अस्थायी छूट
2. बही-खाता लाभ दर्शाने वाली शून्य-कर कंपनियों पर लगाया जाने वाला कर
3. उच्च आय अर्जित करने वालों द्वारा देय कर पर लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त शुल्क
4. किसी विशिष्ट उद्देश्य या क्षेत्र के विकास के लिए लगाया जाने वाला कर

(A) P-3, Q-2, R-1, S-4
(B) P-4, Q-1, R-2, S-3
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

9. जीएसटी-पूर्व निम्नलिखित अप्रत्यक्ष करों में से कौन-सा विशेष रूप से राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता था?
(A) केंद्रीय उत्पाद शुल्क
(B) सेवा कर
(C) अतिरिक्त सीमा शुल्क
(D) मूल्य वर्धित कर

10. निम्नलिखित में से कौन-सा केंद्रीय कर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत शामिल नहीं किया गया था?
(A) बुनियादी सीमा शुल्क
(B) केंद्रीय उत्पाद शुल्क
(C) सेवा कर
(D) उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त प्रभार

11. जीएसटी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, न कि एक संवैधानिक निकाय।
II. केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं।
III. परिषद में प्रत्येक राज्य सरकार का वोटिंग वेटेज केंद्र सरकार के बराबर होता है।
IV. जीएसटी परिषद में निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित वोटों के कम से कम तीन-चौथाई बहुमत से लिए जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों का कौन-सा संयोजन सही है?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और IV
(C) I, II और III
(D) II, III और IV

12. जीएसटी परिषद की मतदान संरचना में, केंद्र सरकार के वोट को कितना भार दिया गया है?
(A) डाले गए कुल वोटों का आधा
(B) डाले गए कुल वोटों का एक-तिहाई
(C) डाले गए कुल वोटों का दो-तिहाई
(D) डाले गए कुल वोटों का एक-चौथाई

13. निम्नलिखित में से कौन-सा जीएसटी परिषद का एक प्राथमिक कार्य है?
(A) जीएसटी के अधीन या जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं की सिफारिश करना
(B) संसद में वार्षिक केंद्रीय बजट तैयार करना और प्रस्तुत करना
(C) वाणिज्यिक बैंकों के लिए मौद्रिक नीतियों और बेंचमार्क दरों का निर्धारण करना
(D) राज्यों में व्यक्तिगत आयकर रिटर्न का प्रसंस्करण और लेखा परीक्षा करना

14. जीएसटी के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. CGST अंतरा-राज्यीय आपूर्ति पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है।
II. SGST अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है।
III. IGST केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है और केंद्र तथा राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों का कौन-सा संयोजन सही है?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

15. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प भारत में वर्तमान में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लागू मानक नियमित जीएसटी कर स्लैब के सही क्रम को न्यूनतम दर से उच्चतम दर तक दर्शाता है?
(A) 0%, 5%, 12%, 18%, 28%
(B) 5%, 10%, 15%, 20%, 25%
(C) 0%, 8%, 14%, 20%, 28%
(D) 5%, 12%, 18%, 24%, 32%

NODIA

16. आम नागरिकों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र/सेवा को सामान्यतः वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रभार से छूट दी गई है?
(A) दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं
(B) वित्तीय मध्यस्थता और बैंकिंग सेवाएं
(C) स्वास्थ्य सेवा और शैक्षणिक सेवाएं
(D) रेस्तरां, होटल और कैटरिंग सेवाएं

17. जीएसटी के कार्यान्वयन के बारे में कहा जाता है कि यह "अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण" को बढ़ावा देता है। इसका मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है?
(A) श्रमिकों को ग्रामीण कृषि गतिविधियों से औपचारिक शहरी औद्योगिक विनिर्माण इकाइयों में स्थानांतरित करना।
(B) असंगठित और अनौपचारिक व्यवसायों को नियामक

और कर अनुपालन ढांचे में एकीकृत करना।
(C) वाणिज्यिक आर्थिक लेनदेन को सख्ती से भौतिक नकद चैनलों के माध्यम से संचालित करने का आदेश देना।
(D) परिचालन लागत को कम करने के लिए छोटे विक्रेताओं के बीच डिजिटल भुगतान प्रणालियों को हतोत्साहित और सीमित करना।

18. वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) की क्या भूमिका है?
(A) यह प्रमुख कर वंचकों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जिम्मेदार एक विशेष केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसी है।
(B) यह सभी अंतर-राज्यीय आर्थिक सीमाओं पर स्वचालित टोल प्लाजा का एक भौतिक निगरानी नेटवर्क है।
(C) यह जीएसटी देनदारियों के लिए व्यवसायों को अल्पकालिक वाणिज्यिक ऋण प्रदान करने वाला एक विशेष बैंकिंग संस्थान है।
(D) यह वह प्रौद्योगिकी रीढ़ है जो जीएसटी कार्यान्वयन के लिए आईटी अवसंरचना और डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है।

19. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): जीएसटी की शुरुआत से करों के कैस्केडिंग प्रभाव (कर पर कर) में काफी कमी आई है।
कारण (R): जीएसटी व्यवस्था के तहत, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) तंत्र पूरी आपूर्ति श्रृंखला में उपलब्ध है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कर केवल प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर ही लगाया जाए।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

20. सूची-I में दिए गए जीएसटी-पूर्व करों का सूची-II में दी गई उनकी विशिष्ट प्रकृति/संग्रहण प्राधिकरण के साथ मिलान कीजिए।
सूची I: जीएसटी-पूर्व कर
P. चुंगी
Q. केंद्रीय उत्पाद शुल्क
R. सेवा कर
S. मूल्य वर्धित कर
सूची II: विशिष्ट प्रकृति / संग्रहण प्राधिकरण
1. वस्तुओं के विनिर्माण पर कर, जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है
2. वस्तुओं की अंतरा-राज्यीय बिक्री पर कर, जो राज्यों द्वारा लगाया जाता है
3. उपयोग या बिक्री के लिए किसी नगरपालिका में वस्तुओं के प्रवेश पर कर
4. सेवाओं के प्रावधान पर कर, जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

21. जीएसटी ढांचे के तहत, किसी माल की खेप का सामान्य सीमा मूल्य क्या है जिससे अधिक मूल्य पर वस्तुओं के अंतर-राज्यीय परिवहन के लिए ई-वे बिल तैयार करना अनिवार्य है?
(A) 10,000 रुपये
(B) 50,000 रुपये
(C) 1,00,000 रुपये
(D) 5,00,000 रुपये

22. जीएसटी व्यवस्था के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से एक बड़ी अनुपालन चुनौती के रूप में उद्धृत किया जाता है?
(A) सभी संघीय और राज्य कर क्षेत्राधिकारों में पंजीकरण के सभी रूपों से अनिवार्य वैधानिक छूट प्राप्त करना।
(B) अपने गृह राज्य से बाहर स्थित खुदरा उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक सामान बेचने के खिलाफ सख्त कानूनी प्रतिबंधों का सामना करना।
(C) सभी मासिक जीएसटी देनदारियों का भुगतान विशेष रूप से विदेशी मुद्रा में करने की अनिवार्य नियामक आवश्यकता को पूरा करना।
(D) पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए सटीक चालान मिलान सुनिश्चित करते हुए कई जटिल रिटर्न दाखिल करना।

23. आयातित वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क लगाने के पीछे की मूल अवधारणा क्या है?
(A) घरेलू बाजार में सभी विदेशी वाणिज्यिक वस्तुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाला एक पूर्ण राष्ट्रीय नाकाबंदी लागू करना।
(B) राज्य का राजस्व उत्पन्न करना और घरेलू विनिर्माण उद्योगों को सस्ते विदेशी मुकाबले से बचाना।
(C) भारत में रहने और काम करने वाले विदेशी नागरिकों पर लगाए गए व्यक्तिगत आयकर के पूर्ण विकल्प के रूप में कार्य करना।
(D) देश से महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल के बड़े पैमाने पर निर्यात को सीधे प्रोत्साहित करना।

24. कर प्लवमानता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. कर प्लवमानता सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तनों के प्रति कर राजस्व वृद्धि की संवेदनशीलता को मापती है।
II. 1 से अधिक कर प्लवमानता यह दर्शाती है कि कर राजस्व जीडीपी की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है।
III. उच्च कर प्लवमानता को सामान्यतः किसी अर्थव्यवस्था के लिए एक नकारात्मक संकेतक माना जाता है।
उपर्युक्त कथनों का कौन-सा संयोजन सही है?

Click Here to Buy book on Amazon

(A) केवल I और III
(B) केवल II और III
(C) केवल I और II
(D) I, II और III

25. दो देशों के बीच हस्ताक्षरित दोहरा कराधान निवारण समझौते का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) यह सुनिश्चित करना कि बहुराष्ट्रीय निगम दोनों अनुबंधित क्षेत्राधिकारों में मानक कर दर से दोगुना भुगतान करें।
(B) दो देशों के बीच व्यापार की जाने वाली कच्ची सामग्रियों और तैयार माल पर आयात सीमा शुल्क के सभी रूपों को समाप्त करना।
(C) अमीर व्यक्तिगत निवेशकों को कर देनदारियों के बिना ऑफशोर खातों में कानूनी रूप से आय छिपाने की अनुमति देना।
(D) एक ही आय पर स्रोत के देश और निवास के देश दोनों में कर लगाने से रोकना।

26. निम्नलिखित में से कौन "कर वंचना" को "कर परिहार" से सबसे बेहतर ढंग से अलग करता है?
(A) कर वंचना कर का अवैध गैर-भुगतान है, जबकि कर परिहार वैधानिक प्रावधानों का उपयोग करके कानूनी रूप से कर देनदारी को कम करता है।
(B) कर वंचना का अर्थ उपलब्ध कर छूटों का कानूनी रूप से उपयोग करना है, जबकि कर परिहार का अर्थ अर्जित आय को अवैध रूप से छिपाना है।
(C) कर वंचना केवल कॉर्पोरेट संस्थाओं पर लागू एक नियामक सिद्धांत है, जबकि कर परिहार केवल प्राकृतिक व्यक्तियों पर लागू होता है।
(D) कर वंचना विशेष रूप से अप्रत्यक्ष करों पर लागू एक ढांचा है, जबकि कर परिहार सख्ती से प्रत्यक्ष आय करों पर लागू होता है।

27. जीएसटी लागू होने पर, केंद्र सरकार ने एक विशिष्ट अवधि के लिए राजस्व के किसी भी नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजे की गारंटी दी थी। यह प्रारंभिक गारंटीकृत मुआवजा अवधि कितनी लंबी थी?
(A) 3 वर्ष
(B) 5 वर्ष
(C) 10 वर्ष
(D) 15 वर्ष

28. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): बुनियादी सीमा शुल्क को वस्तु एवं सेवा कर में शामिल नहीं किया गया था।
कारण (R): जीएसटी मूल रूप से घरेलू उपभोग और आपूर्ति पर एक कर है, जबकि बुनियादी सीमा शुल्क अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने और घरेलू बाजारों की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक संप्रभु उपकरण है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

NODIA

29. हाल के जीएसटी सुधारों के संदर्भ में, जीएसटी परिषद द्वारा गठित "दर युक्तीकरण" समितियों या मंत्रियों के समूह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) कर दरों की समीक्षा करना, शुल्क विसंगतियों को दूर करना और संरचनात्मक सरलीकरण के लिए स्लैब के विलय का मूल्यांकन करना।
(B) वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क को पूरी तरह से समाप्त करना और राष्ट्रीय कराधान को पूर्व राज्य-स्तरीय वैट प्रणाली पर वापस लाना।
(C) राष्ट्रव्यापी सभी वाणिज्यिक वस्तुओं और उपभोक्ता सेवाओं पर उच्चतम स्लैब दर को 28% से बढ़ाकर स्थायी रूप से 50% करना।
(D) प्रशासनिक कर संग्रह शक्तियों को केंद्रीय और राज्य अधिकारियों से स्थानीय ग्राम पंचायतों में पूरी तरह से स्थानांतरित करना।

30. जीएसटी के कार्यान्वयन ने भारत में एक एकीकृत साझा बाजार बनाने में कैसे योगदान दिया?
(A) वाणिज्यिक व्यावसायिक दस्तावेजों के लिए सभी संघीय राज्यों को कानूनी रूप से एक ही अनिवार्य आधिकारिक भाषा अपनाने के लिए बाध्य करके।
(B) यह अनिवार्य करके कि सभी राष्ट्रीय औद्योगिक और विनिर्माण गतिविधियां एक निर्दिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर हों।
(C) अंतर-राज्यीय जांच चौकियों को हटाकर और मुक्त व्यापार के लिए राज्य की सीमाओं पर दरों का मानकीकरण करके।
(D) सभी घरेलू अंतर-राज्यीय व्यापार के लिए एक नई एकीकृत एकल राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा स्थापित और विनियमित करके।

31. जीएसटी के बाद की व्यवस्था के तहत, कराधान तंत्र "उत्पत्ति-आधारित" कर प्रणाली से काफी हद तक किसमें स्थानांतरित हो गया है?
(A) एक केंद्रित निर्माता-आधारित अप्रत्यक्ष कर प्रणाली
(B) एक राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत निर्यात-उन्मुख कर प्रणाली
(C) सभी क्षेत्रों में एक समान फ्लैट संपत्ति कर प्रणाली
(D) एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर प्रणाली

32. भारत में आयकर संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. आयकर एक प्रगतिशील कर है जहाँ उच्च आय श्रेणियों पर उच्च कर दरें लागू होती हैं।
II. भारत में कृषि आय को सामान्यतः केंद्रीय आयकर से

छूट प्राप्त है।

III. नई कर व्यवस्था पुरानी व्यवस्था की तुलना में उच्च मूल छूट सीमाएं प्रदान करती है।

IV. नई कर व्यवस्था के तहत, व्यक्ति बिना किसी प्रतिबंध के मकान किराया भत्ता और छुट्टी यात्रा भत्ता जैसी मानक कटौतियों का दावा कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों का कौन-सा संयोजन गलत है?

(A) केवल I और II
(B) केवल III
(C) केवल IV
(D) केवल II और IV

33. भारत सरकार ने हाल के वर्षों में कॉर्पोरेट कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती की घोषणा की, जिससे नई विनिर्माण कंपनियों के लिए आधार दर घटकर 15% हो गई। इस नीति का प्राथमिक समष्टि अर्थशास्त्रीय औचित्य क्या था?

(A) घरेलू फर्मों से कम कुल कॉर्पोरेट कर प्राप्तियां एकत्र करके राष्ट्रीय राजकोषीय घाटे को तुरंत कम करना।
(B) विनिर्माण में घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना और व्यापक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
(C) अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने से वाणिज्यिक कंपनियों को सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना।
(D) निजी छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों पर वैधानिक कर अनुपालन और रिपोर्टिंग के बोझ को व्यवस्थित रूप से बढ़ाना।

34. भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच जीएसटी परिषद की सिफारिशों से उत्पन्न किसी विवाद के मामले में, विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का प्राथमिक जनादेश किसके पास है?

(A) भारत का सर्वोच्च न्यायालय
(B) वित्त आयोग
(C) भारत की संसद
(D) स्वयं जीएसटी परिषद

35. भारत में निम्नलिखित कराधान-संबंधित घटनाओं को उनके घटित होने के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:

I. वस्तु एवं सेवा कर का कार्यान्वयन
II. वर्तमान में लागू व्यापक आयकर अधिनियम का अधिनियमन
III. अधिकांश राज्यों में मूल्य वर्धित कर की शुरुआत
IV. "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट कर दरों में ऐतिहासिक कटौती

(A) II, III, I, IV
(B) III, II, I, IV
(C) II, I, III, IV
(D) I, II, IV, III

36. निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार कीजिए:

I. बिना पैक किए गए खाद्यान्न
II. मानव उपभोग के लिए शराब
III. कच्चा पेट्रोलियम

उपर्युक्त में से कौन-सी वस्तुएं वर्तमान में जीएसटी के दायरे से बाहर हैं?

(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

37. वस्तुओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति में, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है। गंतव्य राज्य के राजस्व का हिस्सा कैसे प्राप्त होता है?

(A) केंद्र अंतिम उपभोग के आधार पर गंतव्य राज्य के IGST हिस्से को आबंटित करता है।
(B) केंद्र सरकार किसी भी राज्य को धन हस्तांतरित किए बिना संपूर्ण एकत्र किए गए IGST राजस्व को स्थायी रूप से अपने पास रखती है।
(C) गंतव्य राज्य अंतर-राज्यीय बिक्री पर खरीदार से सीधे एक अतिरिक्त SGST घटक लगाता है और एकत्र करता है।
(D) मूल विनिर्माण राज्य पूरा राजस्व एकत्र करता है और उसके बाद गंतव्य राज्य को आवश्यक हिस्सा हस्तांतरित करता है।

38. जीएसटी व्यवस्था के तहत एकल फ्लैट दर के बजाय कई कर स्लैब (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) बनाए रखने का प्राथमिक आर्थिक औचित्य क्या है?

(A) प्रशासनिक जटिलता पैदा करना जो जानबूझकर निजी व्यवसायों को पेशेवर कर सलाहकारों पर अत्यधिक निर्भर रहने के लिए प्रोत्साहित करे।
(B) बुनियादी कृषि वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं पर उच्चतम दर स्लैब रखकर कुल राज्य कर राजस्व को अधिकतम करना।
(C) विनिर्माण इनपुट पर कर दरों को निरंतर और अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव की स्थिति में रखकर औद्योगिक विस्तार को हतोत्साहित करना।
(D) आवश्यक वस्तुओं पर कम कर और विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगाना, जिससे अप्रत्यक्ष कराधान के प्रतिगामी प्रभाव को कम किया जा सके।

39. सूची-I में दिए गए निम्नलिखित जीएसटी अनुपालन फॉर्मों का सूची-II में दिए गए उनके प्राथमिक उद्देश्य से मिलान कीजिए।

सूची I: जीएसटी अनुपालन फॉर्म

P. GSTR-1
Q. GSTR-3B
R. GSTR-9
S. CMP-08

सूची II: प्राथमिक उद्देश्य

1. देनदारी घोषित करने और कर का भुगतान करने के लिए संक्षिप्त रिटर्न

Downloaded from www.pdf.tube

2. बाह्य आपूर्ति का विवरण (बिक्री विवरण)
3. कंपोजिशन योजना करदाताओं के लिए विवरण-सह-चालान
4. वार्षिक जीएसटी रिटर्न

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

40. निम्नलिखित में से कौन-सा कारक वस्तुओं की आवाजाही के लिए तैयार किए गए ई-वे बिल की वैधता अवधि निर्धारित करता है?
(A) परिवहन की गई वस्तुओं का कुल घोषित मौद्रिक चालान मूल्य
(B) परिवहन वाहन की विशिष्ट तकनीकी श्रेणी और एक्सल भार
(C) वह दूरी जिस पर वस्तुओं का परिवहन किया जा रहा है
(D) आपूर्तिकर्ता उद्यम का वार्षिक कुल वाणिज्यिक कारोबार

41. जीएसटी के संदर्भ में, "इनपुट टैक्स क्रेडिट" शब्द का अर्थ है:
(A) कच्चे माल के इनपुट पर अर्जित जीएसटी देनदारियों का भुगतान करने के लिए स्पष्ट रूप से नामित एक विशेष कम ब्याज वाला वाणिज्यिक बैंक ऋण प्राप्त करना।
(B) अंतिम खुदरा उपभोक्ता को बिक्री के बिंदु पर अंतिम आउटपुट पर सीधे लगाया गया कुल संचयी अप्रत्यक्ष कर।
(C) विदेशों में वस्तुओं का निर्यात करने के लिए घरेलू विनिर्माण उद्यमों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष बजटीय नकद सब्सिडी।
(D) अंतिम आउटपुट आपूर्ति पर देय कर के विरुद्ध इनपुट वस्तुओं और सेवाओं पर भुगतान किए गए कर को समायोजित करना।

42. निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए:
I. स्थानीय निकायों द्वारा लगाया जाने वाला मनोरंजन कर
II. अचल संपत्ति लेनदेन पर स्टाम्प शुल्क
III. चुंगी और प्रवेश कर
IV. शराब पर राज्य उत्पाद शुल्क

उपर्युक्त में से कौन-से कर जीएसटी में शामिल नहीं किए गए थे?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और IV
(C) केवल III और IV
(D) I, II और IV

43. किसी देश का "कर-जीडीपी अनुपात" एक महत्वपूर्ण समष्टि आर्थिक संकेतक है। एक उच्च कर-जीडीपी अनुपात सामान्यतः क्या दर्शाता है?
(A) एक गंभीर संरचनात्मक आर्थिक संकुचन यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एक गहरी मंदी में प्रवेश कर चुकी है।
(B) एक व्यापक कर आधार और उच्च अनुपालन, जो तेजी से औपचारिक होती अर्थव्यवस्था का संकेत देता है।
(C) एक ऐसी स्थिति जहाँ केंद्र सरकार गैर-उत्पादक सामाजिक सब्सिडी कार्यक्रमों पर अत्यधिक खर्च कर रही है।
(D) एक प्रणालीगत वित्तीय स्थिति जहाँ राष्ट्रीय वाणिज्य का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में संचालित होता है।

44. दोहरा कराधान निवारण समझौते के तहत, देश आमतौर पर करदाताओं को राहत कैसे प्रदान करते हैं?
(A) सीमा पार व्यापार से पहले व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट करदाताओं को अपनी प्राथमिक नागरिकता का औपचारिक रूप से त्याग करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करके।
(B) छूट (केवल एक राष्ट्र में आय पर कर लगाना) या टैक्स क्रेडिट (गृह कर देनदारी के विरुद्ध विदेशों में भुगतान किए गए कर का क्रेडिट देना) के माध्यम से।
(C) सभी निवर्तमान सीमा पार वित्तीय लेनदेन पर व्यवस्थित रूप से एक अतिरिक्त संप्रभु अधिभार और नियामक उपकर लगाकर।
(D) पूर्ण वैधानिक उन्मुक्ति प्रदान करके और विदेशी बहुराष्ट्रीय फर्मों के लिए सभी स्थानीय और राष्ट्रीय कर दायित्वों को पूरी तरह से माफ करके।

NODIA

45. करदाता द्वारा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा सही निर्धारित क्रम है?
(A) सबसे पहले IGST देनदारी के विरुद्ध, फिर किसी भी क्रम या अनुपात में CGST और SGST देनदारियों के विरुद्ध।
(B) सबसे पहले विशेष रूप से SGST देनदारी के विरुद्ध, उसके बाद CGST देनदारी के विरुद्ध, और अंत में किसी भी शेष IGST देनदारी के विरुद्ध।
(C) सबसे पहले विशेष रूप से CGST देनदारी के विरुद्ध, जिसमें शेष क्रेडिट राशि को IGST और SGST देनदारियों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा।
(D) IGST क्रेडिट सख्ती से IGST देनदारी को निपटाने तक सीमित है और इसे CGST या SGST देनदारियों को ऑफसेट करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

46. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): कर परिहार को एक कानूनी प्रथा माना जाता है, जबकि कर वंचना एक आपराधिक अपराध है।
कारण (R): कर परिहार में कपटपूर्ण साधनों का उपयोग करके आय को जानबूझकर छिपाना शामिल है, जबकि कर वंचना में कर देनदारी को कम करने के लिए कर कानूनों की कमियों का उपयोग करना शामिल है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की

सही व्याख्या करता है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

47. राज्यों को 5 वर्षों की अवधि के लिए गारंटीकृत जीएसटी मुआवजे के वित्तपोषण के लिए, केंद्र सरकार ने एक जीएसटी मुआवजा कोष बनाया। इस कोष के लिए राजस्व कैसे उत्पन्न किया जाता है?
(A) विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय विकास संस्थानों से सीधे दीर्घकालिक संरचनात्मक समायोजन ऋण प्राप्त करके।
(B) संघीय राजकोषीय राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से आपातकालीन वित्तीय भंडार को पुनर्वितरित करके।
(C) राज्य के राजस्व घाटे को सीधे मुद्रीकृत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अतिरिक्त फिएट मुद्रा छापने के लिए अधिकृत करके।
(D) निर्दिष्ट विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर एक समर्पित जीएसटी मुआवजा उपकर लगाकर।

48. जीएसटी कार्यान्वयन के बाद अंतर-राज्यीय जांच चौकियों को हटाने के कारण आपूर्ति श्रृंखला क्षेत्र में देखा गया एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स लाभ क्या था?
(A) प्रमुख आर्थिक राज्य सीमाओं के पार यात्रा करने के लिए वाणिज्यिक माल ट्रकों के लिए आवश्यक कुल पारगमन समय में भारी वृद्धि।
(B) फ्रेट शिपर्स के लिए एक एकल अंतर-राज्यीय यात्रा के लिए कई अलग-अलग क्षेत्रीय परिवहन कंपनियों को किराए पर लेने की नियामक आवश्यकता।
(C) ट्रकों के टर्नअराउंड समय में कमी और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में परिचालन दक्षता में वृद्धि।
(D) राज्य सीमा बिंदुओं पर लोडिंग और अनलोडिंग के लिए विशेष मैन्युअल श्रम को किराए पर लेने की परिचालन लागत में तेज वित्तीय वृद्धि।

49. जीएसटी से पहले, पारंपरिक बिक्री कर प्रणाली को बदलने के लिए मूल्य वर्धित कर पेश किया गया था। पुरानी बिक्री कर प्रणाली के साथ प्राथमिक समस्या क्या थी जिसे वैट का उद्देश्य हल करना था?
(A) कर वैधानिक ढांचा अत्यधिक पारदर्शी था, जिससे प्रशासनिक बोझ कम हो गया था और छोटी फर्मों के लिए अनुपालन की गणना बहुत आसान हो गई थी।
(B) इसने इनपुट क्रेडिट की कमी के कारण बिक्री के चरणों में कर-पर-कर (कैस्केडिंग) प्रभाव पैदा किया।
(C) यह प्रभार कानूनी रूप से विदेशी आयातित वस्तुओं तक सीमित था, जिससे बिक्री कर से घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं को पूरी तरह से बाहर रखा गया था।
(D) कर केवल केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता था, जिससे राज्य के खजाने आवश्यक स्वतंत्र राजस्व धाराओं से वंचित हो जाते थे।

50. जीएसटी के तहत ई-वे बिल प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह वस्तुओं की आवाजाही पर नज़र रखने और कर चोरी की जाँच करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करता है।
II. यह केवल हवाई परिवहन के माध्यम से माल की आवाजाही के लिए अनिवार्य है।
III. ई-वे बिल जनरेट करने की जिम्मेदारी प्रेषक, प्रेषिती या परिवहनकर्ता पर आ सकती है।
उपर्युक्त कथनों का कौन-सा संयोजन सही है?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

51. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है?
(A) सेवा कर
(B) निगम कर
(C) पूंजीगत लाभ कर
(D) प्रतिभूति लेनदेन कर

52. सूची-I की मदों का सूची-II में दी गई उनकी वर्तमान जीएसटी स्थिति के साथ मिलान कीजिए।
सूची I: मदें
P. ताजा दूध और सब्जियां
Q. सोना और बहुमूल्य रत्न
R. मोटर वाहन
S. विमानन टर्बाइन ईंधन
सूची II: वर्तमान जीएसटी स्थिति
1. 3% की विशेष जीएसटी स्लैब दर को आकर्षित करता है
2. वर्तमान में जीएसटी के दायरे से बाहर है
3. जीएसटी (0%) से छूट प्राप्त है
4. 28% की उच्चतम जीएसटी स्लैब (उपकर के साथ) को आकर्षित करता है
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-1, Q-3, R-2, S-4
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

53. व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में हाल के परिवर्तनों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बाद से निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है?
(A) नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट विकल्प है, जबकि करदाताओं के पास पुरानी व्यवस्था को चुनने का विकल्प बना रहता है।
(B) नई कर व्यवस्था को बिना किसी वैधानिक अपवाद के सभी व्यक्तिगत करदाताओं के लिए सख्ती से अनिवार्य कर दिया गया है।
(C) पुरानी कर व्यवस्था को सभी करदाता श्रेणियों में पूरी तरह से निरस्त और स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया है।

Click Here to Buy book on Flipkart

(D) नई कर व्यवस्था के तहत मूल आय छूट सीमा में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की तुलना में काफी कमी की गई है।

54. भारत में कॉर्पोरेट कराधान के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सामान्यतः सटीक है?
(A) घरेलू उद्यम और विदेशी कॉर्पोरेट संस्थाएं सभी स्लैबों में समान वैधानिक कॉर्पोरेट कर दरों के अधीन हैं।
(B) कॉर्पोरेट आयकर की गणना सीधे सकल वार्षिक व्यावसायिक कारोबार पर की जाती है और लगाई जाती है, भले ही किसी फर्म को लाभ हो या हानि।
(C) पात्र वाणिज्यिक स्टार्टअप अपने परिचालन अस्तित्व के दौरान किसी भी कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने से वैधानिक, स्थायी छूट का आनंद लेते हैं।
(D) विदेशी कंपनियां सामान्यतः घरेलू फर्मों की तुलना में उच्च कॉर्पोरेट कर दर के अधीन होती हैं।

55. निम्नलिखित में से कौन जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है?
(A) भारत के प्रधानमंत्री
(B) केंद्रीय वित्त मंत्री
(C) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर
(D) भारत के वित्त सचिव

56. वस्तुओं की अंतरा-राज्यीय आपूर्ति में (उदाहरण के लिए जयपुर में एक विक्रेता द्वारा जोधपुर में एक खरीदार को बेचना), जीएसटी ढांचे के तहत कौन-से कर लगाए जाते हैं?
(A) केवल एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST)
(B) केवल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST)
(C) CGST और SGST दोनों
(D) केवल केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST)

57. 28% की उच्चतम मानक जीएसटी स्लैब सामान्यतः किस श्रेणी की वस्तुओं पर लागू होती है?
(A) आवश्यक कच्ची खाद्य वस्तुएं और जीवनरक्षक दवाएं
(B) भारी कृषि मशीनरी, औद्योगिक उपकरण और रासायनिक उर्वरक
(C) पारंपरिक हथकरघा उत्पाद, कुटीर उद्योग का सामान और काटा हुआ खादी
(D) विलासिता की वस्तुएं और अहितकर वस्तुएं जैसे तंबाकू और वातित पेय

58. स्कूलों और मान्यता प्राप्त कॉलेजों द्वारा प्रदान की जाने वाली मानक शैक्षणिक सेवाओं को जीएसटी व्यवस्था के तहत कैसा माना जाता है?
(A) उन्हें जीएसटी से छूट प्राप्त है।
(B) उन पर 18% की एक समान दर से कर लगाया जाता है।
(C) उन पर 28% की उच्चतम दर से कर लगाया जाता है।
(D) उन्हें विलासिता सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन पर उपकर लगता है।

59. जीएसटी के तहत सीमित कारोबार वाले छोटे व्यवसायों पर अनुपालन भार को कम करने के लिए, सरकार ने एक सरलीकृत योजना शुरु की, जहाँ वे इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा के बिना एक निश्चित, निचली दर पर कर का भुगतान करते हैं। इस योजना को क्या कहा जाता है?
(A) छूट योजना
(B) कंपोजिशन योजना
(C) औपचारीकरण योजना
(D) इनपुट क्रेडिट योजना

60. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम की धारा 17(5) के तहत, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को कुछ आपूर्तियों के लिए स्पष्ट रूप से अवरुद्ध कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस पर सामान्यतः ITC उपलब्ध नहीं है?
(A) उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण के लिए खरीदे गए कच्चे माल और औद्योगिक घटक
(B) कॉर्पोरेट कर्मचारियों के व्यक्तिगत परिवहन के लिए खरीदे गए मोटर वाहन
(C) कार्यालय वित्तीय लेखांकन के लिए खरीदे गए डेस्कटॉप कंप्यूटर और आईटी हार्डवेयर उपकरण
(D) तैयार उत्पादों के भंडारण और शिपिंग के लिए उपयोग की जाने वाली विशेष सुरक्षात्मक पैकेजिंग सामग्री

61. जीएसटी के व्यापक आर्थिक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसके कारण एक राष्ट्रीय एकीकृत बाजार का निर्माण हुआ है।
II. इसने भारतीय अर्थव्यवस्था से अनौपचारिक क्षेत्र को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।
III. इसने कई जटिल अप्रत्यक्ष कर कानूनों को बदलकर कर प्रशासन को सरल बनाया है।
IV. इसने आपूर्ति श्रृंखलाओं की डिजिटल रुप से ट्रैकिंग को सक्षम बनाया है, जिससे काले धन के निर्माण की गुंजाइश कम हुई है।
उपर्युक्त कथनों का कौन-सा संयोजन सही है?
(A) I, II और III
(B) I, III और IV
(C) II, III और IV
(D) I, II, III और IV

62. उपभोग के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश पर नगर पालिका अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से एकत्र किए जाने वाले किस स्थानीय कर को जीएसटी के तहत शामिल किया गया था?
(A) संपत्ति कर
(B) पेशेवर कर
(C) चुंगी
(D) जल कर

63. अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई भारी कर चोरी का मानक परिणाम क्या है?

NODIA

(A) चोरी की गई पूरी कर राशि को ब्याज मुक्त दीर्घकालिक सरकारी ऋण में परिवर्तित कर दिया जाता है।
(B) गैर-अनुपालन करने वाले करदाता को कानूनी रूप से संप्रभु अवसंरचना बॉन्ड में चोरी की गई राशि का निवेश करने का आदेश दिया जाता है।
(C) कर इकाई को कानूनी रूप से पूर्ण अर्जित कर देनदारी को सीधे अपने कार्यस्थल कर्मचारियों पर स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है।
(D) भारी जुर्माना, ब्याज शुल्क और संभावित आपराधिक मुकदमा चलाना।

64. एक नियमित व्यावसायिक लेनदेन के लिए जीएसटी जीवनचक्र में आमतौर पर शामिल क्रमिक चरणों को व्यवस्थित कीजिए:
I. खरीदार दाखिल किए गए रिटर्न के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करता है
II. आपूर्तिकर्ता बाह्य आपूर्तियों का विवरण देते हुए GSTR-1 दाखिल करता है
III. आपूर्तिकर्ता और खरीदार एक लेनदेन पर सहमत होते हैं और एक कर चालान बनाते हैं
IV. आपूर्तिकर्ता GSTR-3B दाखिल करता है और शुद्ध कर देनदारी का भुगतान करता है
(A) III, II, IV, I
(B) I, II, III, IV
(C) III, IV, II, I
(D) II, I, III, IV

65. जीएसटी परिषद कभी-कभी "दर युक्तीकरण" की जांच के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित करती है। इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य है:
(A) कर स्लैब की मौजूदा संख्या को पांच से बढ़ाकर दस अलग-अलग वैधानिक दर श्रेणियों में विस्तारित करना।
(B) कर संरचना की समीक्षा करना, उल्टे शुल्क के मुद्दों को ठीक करना और स्लैब के विलय का सुझाव देना।
(C) SGST घटक को पूरी तरह से समाप्त करना और सभी अप्रत्यक्ष कर संग्रह को केंद्र सरकार को स्थानांतरित करना।
(D) व्यक्तिगत प्रत्यक्ष आयकर और वाणिज्यिक कृषि उपज को शामिल करने के लिए जीएसटी के दायरे का विस्तार करना।

66. जीएसटी के संदर्भ में, "गंतव्य सिद्धांत" का तात्पर्य है कि:
(A) कर राजस्व उस राज्य को प्राप्त होता है जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन होता है।
(B) उपभोग की परवाह किए बिना कर राजस्व पूरी तरह से केंद्र सरकार को प्राप्त होता है।
(C) कर राजस्व भारत के सभी राज्यों के बीच समान रूप से विभाजित होता है।
(D) कर राजस्व उस राज्य को प्राप्त होता है जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग होता है।

67. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद बुनियादी सीमा शुल्क की स्थिति की सही पहचान करता है?
(A) बुनियादी सीमा शुल्क आयात पर जारी रहता है, जिसमें बुनियादी सीमा शुल्क के अतिरिक्त IGST लगाया जाता है।
(B) बुनियादी सीमा शुल्क को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया है और इसे पूरी तरह से IGST ढांचे से बदल दिया गया है।
(C) बुनियादी सीमा शुल्क को मौजूदा केंद्रीय उत्पाद शुल्क तंत्र में संरचनात्मक रूप से विलय कर दिया गया है।
(D) बुनियादी सीमा शुल्क संग्रह के अधिकार केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

68. दोहरा कराधान निवारण समझौते के तहत, भारत में कर संधि लाभों का दावा करने के लिए किसी अनिवासी द्वारा प्राथमिक रूप से किस दस्तावेज की आवश्यकता होती है?
(A) भारतीय अधिकारियों द्वारा जारी एक वैध बायोमेट्रिक आधार कार्ड
(B) उनके मूल गृह देश द्वारा जारी एक आधिकारिक मतदाता पहचान पत्र
(C) उनके गृह देश से एक कर रेसीडेंसी प्रमाण पत्र
(D) भारत में पंजीकृत एक आधिकारिक कॉर्पोरेट निगमन प्रमाण पत्र

NODIA

69. जून 2022 में 5 वर्षीय जीएसटी मुआवजा गारंटी अवधि के समाप्त होने के बाद, कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच क्या विवाद उत्पन्न हुआ?
(A) राज्यों ने महामारी से संबंधित राजस्व घाटे के कारण जीएसटी मुआवजा बढ़ाने की मांग की।
(B) राज्यों ने औपचारिक रूप से अनुरोध किया कि वितरण के लिए सभी राष्ट्रीय जीएसटी संग्रह केंद्र सरकार को सीधे सौंप दिए जाएं।
(C) राज्यों ने स्थानीय मूल्य वर्धित कर लगाने की संवैधानिक शक्ति को स्थायी रूप से वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से आधिकारिक रूप से याचिका दायर की।
(D) अपूरणीय नीतिगत मतभेदों के कारण राज्यों ने सर्वसम्मति से संवैधानिक जीएसटी परिषद को स्थायी रूप से भंग करने की मांग की।

70. जीएसटी के मूलभूत लाभों में से एक "क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह" है। इसका विशेष रूप से अर्थ है:
(A) वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी भौतिक संपार्श्विक संपत्ति के पंजीकृत व्यवसायों को पूंजी ऋण देने का वैधानिक आदेश है।
(B) व्यावसायिक ग्राहकों को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं से सीधे विस्तारित और असीमित वाणिज्यिक क्रेडिट भुगतान अवधि स्वचालित रूप से प्राप्त होती है।
(C) पंजीकृत करदाताओं को वित्तीय ब्याज दंड के बिना अपनी मासिक अप्रत्यक्ष कर देनदारियों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की अनुमति है।

(D) आपूर्ति श्रृंखला के पूर्ववर्ती चरणों में भुगतान किए गए कर राज्य सीमाओं के पार अंतिम कर देनदारियों को निर्बाध रूप से समायोजित करते हैं।

71. वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को किस रूप में संरचित किया गया है?
(A) केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत पूरी तरह से संचालित एक विशेष प्रशासनिक विभाग
(B) एक गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी, धारा 8 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
(C) संविधान के अनुच्छेद 280 के स्पष्ट प्रावधानों के तहत निर्मित एक स्थायी संवैधानिक निकाय
(D) भारतीय संसद के एक समर्पित सक्षम अधिनियम के माध्यम से स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय

72. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम के अनुसार, जीएसटी परिषद की वैध बैठक गठित करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) क्या है?
(A) सदस्यों की कुल संख्या का एक-चौथाई
(B) सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई
(C) सदस्यों की कुल संख्या का आधा
(D) सदस्यों की कुल संख्या का दो-तिहाई

73. भारत में एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) के प्रशासन और संग्रह के लिए कौन-सा प्राधिकरण जिम्मेदार है?
(A) वह राज्य सरकार जहाँ वस्तुओं का उपभोग होता है
(B) अंतर-राज्यीय परिषद
(C) भारतीय रिजर्व बैंक
(D) केंद्र सरकार

74. भारत में व्यक्तिगत आयकर पर लगाए जाने वाले अधिभार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है?
(A) यह देय आयकर पर एक प्रतिशत शुल्क है, जो उच्च आय अर्जित करने वालों को लक्षित करता है।
(B) यह सभी पंजीकृत व्यक्तिगत करदाताओं पर उनकी कुल कर योग्य आय श्रेणी की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होता है।
(C) यह प्रतिवर्ष पंजीकृत करदाता पर लगाया जाने वाला ठीक 10,000 रुपये का एक अनिवार्य फ्लैट प्रशासनिक मूल्यांकन शुल्क है।
(D) यह आकलन के दौरान सकल कुल कर योग्य आय में से एक स्वीकार्य व्यावसायिक व्यय के रूप में पूरी तरह से कटौती योग्य है।

75. "मेक इन इंडिया" पहल को बढ़ावा देने के लिए, कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए रियायती आधार दर पर कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने का एक विकल्प प्रदान किया, जो दर है:
(A) 25%
(B) 22%
(C) 15%
(D) 10%

76. भारत में जीएसटी की संरचना को अक्सर "दोहरी जीएसटी" मॉडल कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि:
(A) यह सभी उत्पाद श्रेणियों में ठीक दो मानक वैधानिक कर स्लैब का उपयोग करके विशेष रूप से काम करता है।
(B) केंद्र और राज्य सरकारें एक साझा आधार पर एक साथ कर लगाती हैं।
(C) यह अमूर्त उपभोक्ता सेवाओं को पूरी तरह से बाहर रखते हुए सख्ती से मूर्त वाणिज्यिक वस्तुओं पर लागू होता है।
(D) यह अनिवार्य करता है कि व्यवसाय बिना किसी समायोजन सुविधा के समान वाणिज्यिक लेनदेन पर दो बार कर का भुगतान करें।

77. जीएसटी शब्दावली में, "छूट प्राप्त आपूर्ति" और "शून्य-दर आपूर्ति" के बीच मुख्य अंतर क्या है?
(A) छूट प्राप्त आपूर्तियां ITC पुनर्प्राप्ति की अनुमति नहीं देती हैं, जबकि शून्य-दर आपूर्तियां ITC दावों/रिफंड की अनुमति देती हैं।
(B) वे जीएसटी नियमों के तहत कानूनी रूप से समान वैधानिक अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें कोई व्यावहारिक या परिचालन कर अंतर नहीं होता है।
(C) छूट प्राप्त आपूर्तियां सख्ती से उपभोक्ता सेवाओं पर लागू होती हैं, जबकि शून्य-दर आपूर्तियां विशेष रूप से मूर्त भौतिक वस्तुओं पर लागू होती हैं।
(D) शून्य-दर आपूर्तियों को अवैध वाणिज्यिक लेनदेन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि छूट प्राप्त आपूर्तियां कानून के तहत पूरी तरह से अनुमेय हैं।

78. यदि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) एक वर्ष में 8% बढ़ता है और उसका कुल कर संग्रह उसी वर्ष में 12% बढ़ता है, तो कर प्रणाली प्रदर्शित कर रही है:
(A) 1 से काफी कम कर प्लवमानता
(B) एक अत्यधिक प्रतिगामी राष्ट्रीय कर संरचना
(C) 1 से अधिक कर प्लवमानता
(D) एक गंभीर कैस्केडिंग कर प्रभाव

79. हालांकि कर वंचना अवैध है, "कर शमन" को कानूनी रूप से अनुमेय माना जाता है। कर शमन में आमतौर पर क्या शामिल होता है?
(A) कुल समग्र कारोबार को धोखाधड़ी से कम करने के लिए व्यावसायिक बिक्री चालान और वित्तीय बही-खातों में व्यवस्थित रूप से हेरफेर करना।
(B) कर कानून के शाब्दिक शब्दों को तोड़े बिना वैधानिक कमियों का फायदा उठाने के लिए कृत्रिम रूप से वाणिज्यिक लेनदेन की रचना करना।
(C) आधिकारिक कर लेखा परीक्षा कार्यवाही में जानबूझकर देरी करने या उसे दबाने के लिए सार्वजनिक कर मूल्यांकन अधिकारियों को सीधे रिश्वत देना।
(D) कानून द्वारा प्रदान किए गए कर प्रोत्साहनों और कटौतियों का वैध रूप से उपयोग करने के लिए मामलों

Downloaded from www.pdf.tube

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from
PRINTED BOOKS has up to
4× HIGHER RETENTION
than studying from screens.

PRINT BOOK = **BETTER MEMORY**

PDF = **LOWER RETENTION**

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

को व्यवस्थित करना।

80. समष्टि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से, अंतर-राज्यीय जांच चौकियों को हटाने और जीएसटी के तहत एकल राष्ट्रीय कर दर के कार्यान्वयन का मुख्य उद्देश्य था:

(A) राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए भारी वाणिज्यिक मालवाहकों के लिए आवश्यक पारगमन समय को जानबूझकर बढ़ाना।
(B) ग्रामीण पंचायतों और नगर निकायों की प्रत्यक्ष स्थानीय कर राजस्व संग्रह क्षमताओं को काफी बढ़ाना।
(C) लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, पारगमन में देरी को घटाना और व्यापार करने में सुगमता में सुधार करना।
(D) अंतरराष्ट्रीय विदेशी आयातों को प्रोत्साहित करने के पक्ष में संघीय राज्यों के बीच घरेलू व्यापार को व्यवस्थित रूप से हतोत्साहित करना।

www.nodia.in

NODIA

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) प्रत्यक्ष कर में, कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर में, ये अलग-अलग व्यक्तियों पर पड़ते हैं।
प्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में कर का प्रारंभिक आघात तथा अंतिम वित्तीय प्रहार एक ही इकाई पर पड़ता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत करदाता अपने कर भार को किसी अन्य व्यक्ति पर स्थानांतरित नहीं कर पाता है। दूसरी ओर, अप्रत्यक्ष कराधान में कर का मौद्रिक दायित्व मध्यवर्ती संस्थाओं से होता हुआ अंतिम उपभोक्ता पर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे कर का भुगतान करने वाला और उसका भार वहन करने वाला व्यक्ति अलग-अलग होते हैं।

2. (D) निगम कर
निगम कर कंपनियों और व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ या आय पर प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक कर है। चूंकि इस कर का भुगतान सीधे वही व्यावसायिक इकाई करती है जिस पर यह रोपित किया जाता है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष कराधान का प्रमुख अंग माना जाता है। इसके विपरीत सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आते हैं।

3. (A) नई व्यवस्था कम कर दरों की पेशकश करती है लेकिन करदाता को अधिकांश पारंपरिक cutouts और छूटों को त्यागने की आवश्यकता होती है।
नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था को कर संरचना को सरल बनाने और कर अनुपालन में सुगमता लाने के उद्देश्य से पेश किया गया था। इस प्रणाली के अंतर्गत करदाताओं को आयकर की विभिन्न श्रेणियों में अपेक्षाकृत कम कर दरों का लाभ मिलता है। हालांकि, इस व्यवस्था का चयन करने वाले नागरिकों को पारंपरिक रूप से उपलब्ध विभिन्न प्रकार की कर कटौतियों, जैसे मकान किराया भत्ता और विभिन्न निवेश छूटों का लाभ छोड़ना अनिवार्य होता है।

4. (C) विशेष रूप से उच्च आय वर्ग के करदाताओं से अतिरिक्त राजस्व एकत्र करना।
अधिभार वास्तव में देय आयकर की कुल राशि पर रोपित किया जाने वाला एक अतिरिक्त कर होता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में उच्च आय वाले व्यक्तियों तथा समृद्ध संस्थाओं से अतिरिक्त राजकोषीय राजस्व प्राप्त करना है। यह व्यवस्था धन के पुनर्वितरण और राजकोषीय समता को बढ़ावा देती है क्योंकि यह केवल एक निश्चित उच्च आय सीमा को पार करने वाले करदाताओं पर ही प्रगतिशील रूप से लागू की जाती है।

5. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।
अप्रत्यक्ष करों को उनकी संरचनात्मक प्रकृति के कारण प्रतिगामी माना जाता है। ये कर किसी वस्तु या सेवा का क्रय करने वाले सभी व्यक्तियों पर आय के स्तर पर ध्यान दिए बिना एक समान दर से लागू होते हैं। परिणामस्वरुप, कम आय वाले निर्धन वर्ग को अपनी कुल आय का एक बड़ा अंश इस कर के रूप में चुकाना पड़ता है, जबकि समृद्ध वर्ग पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत बहुत कम महसूस होता है।

6. (D) वस्तु एवं सेवा कर ढांचे की शुरुआत
वर्ष 2016 के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में दूरगामी बदलाव करके वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। इस ऐतिहासिक संशोधन ने केंद्र और राज्यों दोनों को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर अप्रत्यक्ष कर लगाने तथा एकत्र करने का समवर्ती संवैधानिक अधिकार प्रदान किया, जिससे देश में संपूर्ण अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का एकीकरण संभव हो सका।

7. (B) विभिन्न केंद्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष करों को एक एकल कर ढांचे में शामिल करके घरेलू बाजार को एकीकृत करना।
वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के संदर्भ में "एक राष्ट्र, एक कर" का मुख्य उद्देश्य भारत के समूचे भौगोलिक क्षेत्र को एक एकीकृत साझा राष्ट्रीय बाजार के रूप में विकसित करना है। इस सुधार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जटिल केंद्रीय तथा राज्य-स्तरीय अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था स्थापित की गई, जिससे अंतर-राज्यीय व्यापार में उत्पन्न होने वाली कर बाधाएं समाप्त हुईं।

8. (A) P-3, Q-2, R-1, S-4
कराधान प्रणाली में अधिभार उच्च आय अर्जित करने वालों द्वारा देय आयकर पर लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त शुल्क है। न्यूनतम वैकल्पिक कर उन शून्य-कर कंपनियों पर लागू होता है जो बही-खाते में लाभ दर्शाती हैं। इसके अतिरिक्त, कर अवकाश नए निवेशों और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान से अस्थायी छूट है, जबकि उपकर किसी विशिष्ट उद्देश्य या क्षेत्र के विकास हेतु एकत्र किया जाता है।

9. (D) मूल्य वर्धित कर
जीएसटी के लागू होने से पूर्व मूल्य वर्धित कर एक राज्य-स्तरीय अप्रत्यक्ष कर था, जो राज्यों के भीतर होने वाली वस्तुओं की बिक्री पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता था। इसके विपरीत, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा अतिरिक्त सीमा शुल्क केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले अप्रत्यक्ष कर थे, जिन्हें जीएसटी प्रणाली के आने पर पूरी तरह से एकीकृत कर दिया गया।

Click Here to Buy book on Amazon

10. (A) बुनियादी सीमा शुल्क
वस्तु एवं सेवा कर के प्रवर्तन के समय विभिन्न अप्रत्यक्ष करों का इसमें विलय किया गया था, परंतु बुनियादी सीमा शुल्क को इससे अलग रखा गया। यह कर विदेशों से भारत में आयातित माल पर संप्रभु राजस्व जुटाने और घरेलू उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अलग से लगाया जाता है। अन्य केंद्रीय कर जैसे उत्पाद शुल्क और सेवा कर जीएसटी में शामिल हो चुके हैं।

11. (B) केवल II और IV
जीएसटी परिषद संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। इस निकाय में निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित वोटों के कम से कम तीन-चौथाई बहुमत से लिए जाते हैं। वोटिंग वेटेज में केंद्र सरकार का भार कुल वोट का एक-तिहाई और सभी राज्यों का संयुक्त भार दो-तिहाई होता है, जिससे दोनों को समान शक्तियां नहीं मिलतीं।

12. (B) डाले गए कुल वोटों का एक-तिहाई
जीएसटी परिषद की निर्णय लेने की प्रक्रिया एक सहकारी संघवाद ढांचे पर आधारित है। परिषद में मतदान के समय केंद्र सरकार के वोट को डाले गए कुल वैध वोटों का एक-तिहाई (33.33%) भार प्रदान किया गया है। इसके साथ ही, भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को मिलाकर संयुक्त रूप से शेष दो-तिहाई (66.67%) भार सौंपा गया है, जिससे सभी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।

13. (A) जीएसटी के अधीन या जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं की सिफारिश करना
जीएसटी परिषद भारत में वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था से जुड़े नीतिगत मामलों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है। इसका प्राथमिक कार्य केंद्र और राज्यों को उन वस्तुओं तथा सेवाओं की सिफारिश करना है जिन पर कर लगाया जाएगा या जिन्हें कर से छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यह परिषद कर दरों, छूट सीमाओं तथा कर से जुड़े कानूनों एवं नियमों के प्रारूप की भी सिफारिश करती है।

14. (B) केवल I और III
अंतरा-राज्यीय आपूर्ति पर केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और राज्य सरकार द्वारा राज्य वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाता है। इसके विपरीत, अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लागू होता है। यह कर केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है और फिर इसे केंद्र और राज्यों के मध्य समान नियमों के अधीन विभाजित किया जाता है।

15. (A) 0%, 5%, 12%, 18%, 28%
भारत में लागू वर्तमान वस्तु एवं सेवा कर संरचना के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को पांच मुख्य मानक कर स्लैब में वर्गीकृत किया गया है। ये दरें न्यूनतम से उच्चतम के क्रम में 0 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत के रूप में व्यवस्थित की गई हैं, जो सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं और जनहित को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई हैं।

16. (C) स्वास्थ्य सेवा और शैक्षणिक सेवाएं
जनकल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के ध्येय से प्राथमिक एवं बुनियादी सेवाओं को कर दायरे से बाहर रखा गया है। भारत की कराधान प्रणाली में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा और लाइसेंस प्राप्त अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर से मुक्त रखा गया है।

17. (B) असंगठित और अनौपचारिक व्यवसायों को नियामक और कर अनुपालन ढांचे में एकीकृत करना।
अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण का तात्पर्य उन असंगठित एवं अनौपचारिक व्यावसायिक गतिविधियों को डिजिटल और कानूनी रूप से पंजीकृत तंत्र के अंतर्गत लाना है। जीएसटी व्यवस्था के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए व्यवसायों को डिजिटल पंजीकरण, पारदर्शी चालान और नियमित रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होता है। इस प्रक्रिया से असंगठित उद्यम मुख्यधारा की बैंकिंग और विनियामक व्यवस्था में समाहित हो जाते हैं।

18. (D) यह वह प्रौद्योगिकी रीढ़ है जो जीएसटी कार्यान्वयन के लिए आईटी अवसंरचना और डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है।
वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क एक विशिष्ट सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना मंच है जो संपूर्ण जीएसटी व्यवस्था के तकनीकी संचालन का आधार है। यह नेटवर्क करदाताओं को ऑनलाइन पंजीकरण, कर चालान अपलोड करने, मासिक रिटर्न दाखिल करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान करने तथा कर भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से पूर्ण करने हेतु एक केंद्रीय एकीकृत पोर्टल और सेवाएं प्रदान करता है।

19. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।
जीएसटी प्रणाली ने भारतीय अप्रत्यक्ष कर ढांचे से कर-पर-कर (कैस्केडिंग प्रभाव) की समस्या को दूर किया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट तंत्र का निर्बाध लाभ मिलता है। इसके माध्यम से व्यवसाय पिछले चरण में चुकाए गए कर की राशि को अपने आउटपुट कर दायित्व से घटा लेते हैं, जिससे कर केवल मूल्य संवर्धन पर लगता है।

20. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
जीएसटी लागू होने से पूर्व चुंगी स्थानीय निकाय द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश पर लगाया जाने वाला कर था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क का संग्रहण वस्तुओं के विनिर्माण पर केंद्र द्वारा किया जाता था। इसके अतिरिक्त, सेवा कर सेवाओं के प्रावधान पर केंद्र सरकार द्वारा रोपित किया जाता था, जबकि मूल्य वर्धित कर वस्तुओं की बिक्री पर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता था।

21. (B) 50,000 रुपये
वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के नियमों के अंतर्गत, यदि अंतर-राज्यीय माध्यम से परिवहन की जाने वाली वस्तुओं की किसी

NODIA

खेप का कुल चालान मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल (ई-वे बिल) जनरेट करना अनिवार्य होता है। इस डिजिटल व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य माल की आवाजाही को पारदर्शी बनाना तथा कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण लगाना है।

22. (D) पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए सटीक चालान मिलान सुनिश्चित करते हुए कई जटिल रिटर्न दाखिल करना।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को जीएसटी व्यवस्था के संचालन में अनेक तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें से सबसे बड़ी चुनौती मासिक तथा त्रैमासिक आधार पर कई जटिल जीएसटी रिटर्न दाखिल करना तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने हेतु आपूर्तिकर्ताओं के बिक्री चालानों का सटीक मिलान करना है। सीमित संसाधनों के कारण यह प्रक्रिया अत्यधिक बोझिल हो जाती है।

23. (B) राज्य का राजस्व उत्पन्न करना और घरेलू विनिर्माण उद्योगों को सस्ते विदेशी मुकाबले से बचाना।
बुनियादी सीमा शुल्क अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो अन्य देशों से आयातित माल पर लगाया जाता है। इसके पीछे दो मुख्य आर्थिक उद्देश्य होते हैं: पहला, सरकार के लिए महत्वपूर्ण राजकोषीय राजस्व का सृजन करना तथा दूसरा, विदेशों से आने वाले अत्यधिक सस्ते उत्पादों पर कर लगाकर घरेलू उद्योगों और स्थानीय निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा प्रदान करना।

24. (C) केवल I और II
कर प्लवमानता किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में होने वाले परिवर्तन के सापेक्ष सरकारी कर राजस्व में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत अनुपात दर्शाती है। यदि कर प्लवमानता का मान 1 से अधिक होता है, तो इसका अर्थ यह है कि कर राजस्व देश की जीडीपी की तुलना में अधिक तीव्र गति से बढ़ रहा है। यह एक सकारात्मक आर्थिक संकेत है।

25. (D) एक ही आय पर स्रोत के देश और निवास के देश दोनों में कर लगाने से रोकना।
दोहरा कराधान निवारण समझौता दो या अधिक संप्रभु राष्ट्रों के मध्य हस्ताक्षरित एक अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय संधि है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी सीमा पार करदाता या बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा अर्जित एक ही आय पर उसके स्रोत वाले देश और निवास वाले देश दोनों में दोहरा कर लगाने की स्थिति का निवारण करना है। यह व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय निवेश तथा व्यापार को प्रोत्साहित करती है।

26. (A) कर वंचना कर का अवैध गैर-भुगतान है, जबकि कर परिहार वैधानिक प्रावधानों का उपयोग करके कानूनी रूप से कर देनदारी को कम करता है।
कर वंचना एक गैर-कानूनी और दंडनीय कार्य है जिसमें करदाता अपनी वास्तविक आय छुपाकर, झूठे दस्तावेज जमा करके या धोखाधड़ी का सहारा लेकर कर का भुगतान करने से बचता है। दूसरी ओर, कर परिहार के अंतर्गत करदाता कर कानूनों में मौजूद अस्पष्टताओं और छूटों का लाभ उठाकर कानूनी सीमाओं के भीतर अपनी कुल कर देनदारी को कम करने का प्रयास करता है।

27. (B) 5 वर्ष
जुलाई 2017 में भारत में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत के समय, राज्य सरकारों को पुरानी बिक्री कर और वैट प्रणालियों को समाप्त करने से होने वाले संभावित कर राजस्व नुकसान की चिंता थी। राज्यों के वित्तीय हितों की सुरक्षा करने तथा उनका विश्वास हासिल करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू होने की तिथि से 5 वर्षों की गारंटी दी थी।

28. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।
वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत केवल घरेलू उपभोग तथा देश की सीमाओं के भीतर आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर लगाया जाता है। इसके विपरीत, बुनियादी सीमा शुल्क अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने वाले विदेशी माल के आयात पर रोपित होता है। यह कर विदेशी व्यापार नीतियों को नियंत्रित करने तथा घरेलू उद्योग को सुरक्षा देने का कार्य करता है।

29. (A) कर दरों की समीक्षा करना, शुल्क विसंगतियों को दूर करना और संरचनात्मक सरलीकरण के लिए स्लैब के विलय का मूल्यांकन करना।
जीएसटी परिषद द्वारा गठित दर युक्तीकरण समितियों का प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा कर संरचना की गहन समीक्षा करना है। ये समितियां विभिन्न उत्पाद श्रेणियों के अंतर्गत व्याप्त उल्टे शुल्क ढांचे की विसंगतियों को सुधारने का कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त, वे कर स्लैब के संभावित विलय का सुझाव देकर कर ढांचे को अधिक सरल, पारदर्शी और कुशल बनाने का प्रयास करती हैं।

30. (C) अंतर-राज्यीय जांच चौकियों को हटाकर और मुक्त व्यापार के लिए राज्य की सीमाओं पर दरों का मानकीकरण करके।
वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से पूर्व विभिन्न राज्यों की सीमाओं पर स्थापित अंतर-राज्यीय जांच चौकियां माल ढुलाई में अत्यधिक विलंब का कारण बनती थीं। जीएसटी लागू होने से देश भर में राज्यस्तरीय व्यापार बाधाओं और जांच चौकियों को समाप्त कर दिया गया। कर दरों के मानकीकरण से वस्तुओं की आवाजाही सुगम हुई जिससे भारत एक एकीकृत बाजार बन गया।

31. (D) एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर प्रणाली
पुरानी अप्रत्यक्ष कराधान व्यवस्था काफी हद तक उत्पत्ति-आधारित थी, जिसमें कर का राजस्व उस राज्य को प्राप्त होता था जहाँ वस्तु का उत्पादन होता था। इसके विपरीत, वस्तु एवं सेवा कर एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर प्रणाली है। इस मॉडल के तहत अप्रत्यक्ष कर का राजस्व अंतिम रूप से उस राज्य को हस्तांतरित होता है जहाँ वस्तु का उपभोग किया जाता है।

Downloaded from www.pdf.tube

32. (C) केवल IV
भारत की व्यक्तिगत आयकर प्रणाली में नई कर व्यवस्था का चयन करने वाले करदाताओं को पुरानी व्यवस्था की तरह विभिन्न प्रकार की मानक कटौतियों और भत्तों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी गई है। नई व्यवस्था के अंतर्गत मकान किराया भत्ता, छुट्टी यात्रा भत्ता तथा विभिन्न निवेश छूटों को समाप्त कर दिया गया है। अतः नई व्यवस्था में यह अनुमति नहीं है।

33. (B) विनिर्माण में घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना और व्यापक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
केंद्र सरकार द्वारा नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए आधार कॉर्पोरेट कर दर को घटाकर 15 प्रतिशत करने का मुख्य समष्टि अर्थशास्त्रीय उद्देश्य देश में विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाना था। इस कर कटौती से घरेलू तथा विदेशी पूंजी निवेश में तेजी आती है, नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है तथा व्यापक आर्थिक विकास प्रशस्त होता है।

34. (D) स्वयं जीएसटी परिषद
संविधान के अनुच्छेद 279A के स्पष्ट प्रावधानों के अंतर्गत, जीएसटी परिषद को स्वयं ही एक ऐसे उपयुक्त न्यायिक या प्रशासनिक तंत्र की स्थापना करने का वैधानिक जनादेश प्राप्त है जो भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के मध्य या विभिन्न राज्य सरकारों के आपस में जीएसटी परिषद की सिफारिशों अथवा उनके कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निष्पक्ष न्यायनिर्णयन कर सके।

35. (A) II, III, I, IV
भारत के कराधान इतिहास में आयकर अधिनियम 1961 में अधिनियमित किया गया था। इसके पश्चात अधिकांश राज्यों में वर्ष 2005 में मूल्य वर्धित कर की शुरुआत की गई। फिर 1 जुलाई 2017 को देश भर में वस्तु एवं सेवा कर को प्रभावी रूप से लागू किया गया। तत्पश्चात वर्ष 2019 में विनिर्माण क्षेत्र को गति देने हेतु कॉर्पोरेट कर दरों में कटौती की गई।

36. (B) केवल II और III
भारतीय जीएसटी ढांचे में मानव उपभोग के लिए शराब और कच्चा पेट्रोलियम पूरी तरह से जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए हैं, जिन पर पुरानी व्यवस्था के अनुसार राज्यों और केंद्र द्वारा अलग-अलग कर लगाए जाते हैं। इसके विपरीत, बिना पैक किए गए खाद्यान्न वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत आते हैं, लेकिन उन पर 0 प्रतिशत दर लागू होती है।

37. (A) केंद्र अंतिम उपभोग के आधार पर गंतव्य राज्य के IGST हिस्से को आबंटित करता है।
वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति होने पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का संपूर्ण संग्रहण शुरू में केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। चूंकि जीएसटी एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर है, इसलिए केंद्र सरकार इस प्रकार एकत्र किए गए राजस्व में से गंतव्य राज्य का निर्धारित हिस्सा अंतिम उपभोग के आधार पर उस राज्य को आबंटित और स्थानांतरित कर देती है।

38. (D) आवश्यक वस्तुओं पर कम कर और विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगाना, जिससे अप्रत्यक्ष कराधान के प्रतिगामी प्रभाव को कम किया जा सके।
जीएसटी के तहत कई कर स्लैब की मौजूदगी का मुख्य आर्थिक औचित्य समाज में प्रगतिशील कराधान और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। आम जनता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं पर 0% या 5% जैसी न्यूनतम कर दरें रखी गई हैं, जबकि विलासिता की वस्तुओं पर 28% की उच्चतम दर लगाई जाती है, जिससे प्रतिगामी प्रभाव कम होता है।

39. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
जीएसटी अनुपालन ढाँचे में GSTR-1 का प्रयोग पंजीकृत करदाताओं द्वारा अपनी बाह्य आपूर्तियों या बिक्री का ब्यौरा देने के लिए किया जाता है। GSTR-3B एक संक्षिप्त विवरण-पत्र है जिसका उपयोग कर दायित्व घोषित करने और कर का भुगतान करने हेतु होता है। इसके अलावा GSTR-9 वित्तीय वर्ष का संपूर्ण वार्षिक जीएसटी रिटर्न है, जबकि CMP-08 कंपोजिशन योजना चुनने वाले करदाताओं के लिए एक विवरण-सह-चालान फॉर्म है।

40. (C) वह दूरी जिस पर वस्तुओं का परिवहन किया जा रहा है
इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल (ई-वे बिल) की वैधता अवधि पूरी तरह से उस सड़क या यात्रा दूरी पर निर्भर करती है जिस पर वस्तुओं का परिवहन किया जा रहा है। जीएसटी नियमों के अनुसार सामान्य मालवाहकों के लिए प्रति 200 किलोमीटर की दूरी के लिए 1 दिन की वैधता प्रदान की जाती है, जबकि अत्यधिक बड़े वाहनों हेतु प्रति 20 किलोमीटर पर 1 दिन तय है।

41. (D) अंतिम आउटपुट आपूर्ति पर देय कर के विरुद्ध इनपुट वस्तुओं और सेवाओं पर भुगतान किए गए कर को समायोजित करना।
इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी प्रणाली का एक मूल स्तंभ है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी पंजीकृत व्यवसाय या व्यापारी अपनी अंतिम आउटपुट बिक्री या सेवाओं की आपूर्ति पर बनने वाले कर दायित्व का भुगतान करते समय अपने व्यापार हेतु कच्ची सामग्री, इनपुट वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर पहले ही चुकाए गए कर की राशि को उसमें से घटा सकता है।

NODIA

42. (B) केवल II और IV
जीएसटी लागू करते समय अनेक करों का विलय किया गया, परंतु कुछ करों को इससे पूरी तरह बाहर रखा गया। अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर लगाया जाने वाला स्टाम्प शुल्क और मानव उपभोग वाली शराब पर लगाया जाने वाला राज्य उत्पाद शुल्क जीएसटी में शामिल नहीं किए गए थे। इसके विपरीत चुंगी एवं प्रवेश कर को जीएसटी में समाहित कर लिया गया।

43. (B) एक व्यापक कर आधार और उच्च अनुपालन, जो तेजी से औपचारिक होती अर्थव्यवस्था का संकेत देता है।
कर-जीडीपी अनुपात किसी देश के कुल उत्पादित सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में उसके द्वारा एकत्र किए जाने वाले कुल कर राजस्व का प्रतिशत होता है। एक उच्च कर-जीडीपी अनुपात यह दर्शाता है कि उस अर्थव्यवस्था का कर आधार अत्यंत

व्यापक है, नागरिक कर कानूनों का उच्च अनुपालन कर रहे हैं तथा देश की आर्थिक गतिविधियां तेजी से औपचारिक हो रही हैं।

44. (B) छूट (केवल एक राष्ट्र में आय पर कर लगाना) या टैक्स क्रेडिट (गृह कर देनदारी के विरुद्ध विदेशों में भुगतान किए गए कर का क्रेडिट देना) के माध्यम से।
दो देशों के बीच हस्ताक्षरित दोहरा कराधान निवारण समझौते के तहत करदाताओं को दो प्रमुख तंत्रों के माध्यम से राहत प्रदान की जाती है। पहला 'छूट विधि' है, जिसमें संबंधित आय पर केवल एक ही देश में कर लगाया जाता है। दूसरा 'टैक्स क्रेडिट विधि' है, जिसमें करदाता को गृह देश में देय कर के विरुद्ध विदेश में भुगतान किए गए कर का क्रेडिट मिलता है।

45. (A) सबसे पहले IGST देनदारी के विरुद्ध, फिर किसी भी क्रम या अनुपात में CGST और SGST देनदारियों के विरुद्ध।
जीएसटी नियमों के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग का एक निश्चित वैधानिक क्रम निर्धारित किया गया है। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) के क्रेडिट का उपयोग सबसे पहले स्वयं IGST के आउटपुट कर दायित्व को चुकाने के लिए किया जाना अनिवार्य है। इसके पश्चात यदि क्रेडिट बचता है, तो उसका उपयोग CGST और SGST की देनदारियों को समायोजित करने हेतु होता है।

46. (C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
कर परिहार कानून के दायरे के भीतर रहकर उसकी तकनीकी कमियों और कानूनी प्रावधानों का उपयोग करके कर देनदारी को कम करने का एक वैध तरीका है, जबकि कर वंचना जानबूझकर आय छिपाने तथा धोखाधड़ी के माध्यम से किया जाने वाला गैर-कानूनी और आपराधिक अपराध है। चूंकि कारण में इन परिभाषाओं को बदल दिया गया है, इसलिए कारण गलत सिद्ध होता है।

47. (D) निर्दिष्ट विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर एक समर्पित जीएसटी मुआवजा उपकर लगाकर।
जीएसटी लागू होने के बाद शुरुआती 5 वर्षों के दौरान राज्यों को होने वाले कर राजस्व नुकसान की भरपाई हेतु जीएसटी मुआवजा कोष का निर्माण किया गया था। इस विशिष्ट कोष के लिए आवश्यक धन एकत्र करने हेतु केंद्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत कुछ विशिष्ट विलासिता की वस्तुओं तथा अहितकर वस्तुओं पर एक समर्पित जीएसटी मुआवजा उपकर रोपित किया था।

48. (C) ट्रकों के टर्नअराउंड समय में कमी और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में परिचालन दक्षता में वृद्धि।
जीएसटी व्यवस्था लागू होने के पश्चात राज्यों के सीमावर्ती बिंदुओं पर स्थित भौतिक जांच चौकियों को समाप्त कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप अंतर-राज्यीय माल परिवहन में लगने वाला पारगमन समय काफी घट गया। वाणिज्यिक ट्रकों का टर्नअराउंड समय कम होने से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की परिचालन दक्षता में भारी वृद्धि हुई, ईंधन बचा और संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला की समय-लागत में कमी आई।

49. (B) इसने इनपुट क्रेडिट की कमी के कारण बिक्री के चरणों में कर-पर-कर (कैस्केडिंग) प्रभाव पैदा किया।
पुरानी पारंपरिक बिक्री कर प्रणाली में प्रत्येक बिक्री स्तर पर संपूर्ण मूल्य पर कर लगाया जाता था और पूर्ववर्ती चरणों में चुकाए गए कर पर इनपुट क्रेडिट प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके कारण कर के ऊपर कर (कैस्केडिंग प्रभाव) लगता था, जिससे वस्तुओं का अंतिम बाजार मूल्य कृत्रिम रूप से अत्यधिक बढ़ जाता था। इसे दूर करने हेतु वैट लाया गया।

50. (C) केवल I और III
जीएसटी के तहत ई-वे बिल प्रणाली देश भर में वस्तुओं के भौतिक परिवहन की निगरानी करने तथा कर चोरी रोकने का एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक साधन है। यह प्रणाली केवल हवाई परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सड़क, रेल, वायु तथा जल मार्ग सहित किसी भी माध्यम से वस्तुओं की आवाजाही पर लागू होती है। प्रेषक, प्रेषिती या परिवहनकर्ता इसे जारी कर सकते हैं।

51. (A) सेवा कर
प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका भुगतान सीधे वही व्यक्ति या संस्था करती है जिस पर यह कानूनन रोपित किया जाता है और इसका वित्तीय भार किसी अन्य पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, जैसे निगम कर, पूंजीगत लाभ कर तथा प्रतिभूति लेनदेन कर। इसके विपरीत, सेवा कर सेवाओं के उपभोग पर रोपित होने वाला एक अप्रत्यक्ष कर होता है।

52. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
जीएसटी दरों के वर्गीकरण के तहत ताज़ा दूध एवं सब्जियों जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को शून्य दर (0%) पर रखकर छूट दी गई है। सोना और बहुमूल्य रत्नों पर 3% की विशेष रियायती जीएसटी दर लागू होती है। मोटर वाहनों को 28% की उच्चतम जीएसटी दर में रखा गया है, जबकि विमानन टर्बाइन ईंधन को वर्तमान में जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।

53. (A) नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट विकल्प है, जबकि करदाताओं के पास पुरानी व्यवस्था को चुनने का विकल्प बना रहता है।
केंद्रीय वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू नीतिगत संशोधनों के अनुसार, व्यक्तिगत आय करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था को 'डिफॉल्ट विकल्प' के रूप में निर्धारित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई नागरिक आयकर रिटर्न दाखिल करते समय किसी प्रणाली का चयन नहीं करता है, तो कर गणना नई व्यवस्था के तहत होगी, यद्यपि पुरानी व्यवस्था का विकल्प बना रहता है।

54. (D) विदेशी कंपनियां सामान्यतः घरेलू फर्मों की तुलना में उच्च कॉर्पोरेट कर दर के अधीन होती हैं।
भारत की प्रत्यक्ष कराधान संरचना में घरेलू कंपनियों और विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर की दरें भिन्न-भिन्न निर्धारित की गई हैं। आमतौर पर विदेशी कॉर्पोरेट संस्थाओं पर घरेलू भारतीय कंपनियों की तुलना में अधिक दर से कॉर्पोरेट कर रोपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट कर की

Click Here to Buy book on Flipkart

गणना कारोबार पर नहीं, बल्कि अर्जित शुद्ध कर योग्य लाभ पर की जाती है।

55. (B) केंद्रीय वित्त मंत्री
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। यह परिषद देश में जीएसटी से संबंधित समस्त नीतिगत निर्णयों की सिफारिश करने हेतु उत्तरदायी है।

56. (C) CGST और SGST दोनों
वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत जब किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति एक ही राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर की जाती है (अर्थात अंतरा-राज्यीय आपूर्ति), तो उस लेन-देन पर दोहरा जीएसटी मॉडल लागू होता है। इस स्थिति में निर्धारित कुल कर दर को दो समान भागों में विभाजित करके केंद्रीय जीएसटी तथा राज्य जीएसटी एक साथ लगाए जाते हैं।

57. (D) विलासिता की वस्तुएं और अहितकर वस्तुएं जैसे तंबाकू और वातित पेय
जीएसटी व्यवस्था में 28 प्रतिशत की उच्चतम मानक कर दर मुख्य रूप से विलासिता पूर्ण वस्तुओं तथा समाज व स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हानिकारक मानी जाने वाली अहितकर वस्तुओं पर रोपित की जाती है। इसमें तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, वातित पेय, महंगे वाहनों आदि शामिल हैं। इस उच्च कराधान का ध्येय अनुत्पादक एवं हानिकारक उपभोग को हतोत्साहित करना तथा राजस्व बढ़ाना है।

58. (A) उन्हें जीएसटी से छूट प्राप्त है।
भारत की सामाजिक नीति तथा लोक कल्याणकारी सिद्धांतों के अनुरूप शैक्षणिक सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से मुक्त रखा गया है। स्कूलों, बोर्डों तथा मान्यता प्राप्त कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा अपने छात्रों, संकायों व कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली मानक शैक्षणिक और प्रवेश संबंधी सेवाओं को जीएसटी भुगतान से पूर्ण छूट दी गई है। इससे शिक्षा सुलभ होती है।

59. (B) कंपोजिशन योजना
सीमित वार्षिक व्यावसायिक कारोबार वालेछोटे करदाताओं और सूक्ष्म व्यवसायों पर कर अनुपालन के प्रशासनिक भार को कम करने के उद्देश्य से जीएसटी के तहत कंपोजिशन योजना शुरू की गई थी। इस योजना को अपनाने वाले पात्र छोटे व्यापारियों को विस्तृत बही-खाते रखे बिना तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिए बिना अपनी कुल बिक्री पर निश्चित कम दर से कर देना होता है।

60. (B) कॉर्पोरेट कर्मचारियों के व्यक्तिगत परिवहन के लिए खरीदे गए मोटर वाहन
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 17(5) के तहत कुछ विशिष्ट आपूर्तियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने को कानूनी रूप से प्रतिबंधित या अवरुद्ध किया गया है। व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा अपने कर्मचारियों के व्यक्तिगत परिवहन के लिए खरीदे गए मोटर वाहनों पर चुकाए गए जीएसटी का ITC प्राप्त नहीं होता है, जब तक कि वे विशेष अपवाद में न आएं।

61. (B) I, III और IV
जीएसटी के कार्यान्वयन ने भारत में चुंगी और अंतर-राज्यीय कर बाधाओं को समाप्त करके एक एकीकृत राष्ट्रीय साझा बाजार का निर्माण किया है। इतने पूर्ववर्ती कई जटिल अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर कर प्रशासन को सरल बनाया है। डिजिटल चालान और ऑनलाइन ट्रैकिंग से काले धन के सृजन पर अंकुश लगा है। हालांकि, इतने अनौपचारिक क्षेत्र को पूर्णतः समाप्त नहीं किया है।

62. (C) चुंगी
वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था लागू होने से पूर्व चुंगी एक स्थानीय अप्रत्यक्ष कर था, जो स्थानीय निकायों या नगर पालिकाओं द्वारा उपभोग, उपयोग या बिक्री हेतु अपने सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले माल पर रोपित किया जाता था। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने पर इस प्रकार के सभी स्थानीय प्रविष्ट करों को जीएसटी में पूरी तरह समाहित कर लिया गया।

63. (D) भारी जुर्माना, ब्याज शुल्क और संभावित आपराधिक मुकदमा चलाना।
कर अधिकारियों द्वारा कर चोरी या धोखाधड़ी का पता चलने पर दोषी करदाता के विरुद्ध सख्त वैधानिक और आपराधिक कानूनी कार्रवाई की जाती है। इस प्रक्रिया में चोरी की गई मूल कर राशि की वसूली के साथ-साथ भारी मौद्रिक जुर्माना और विलंब ब्याज शुल्क आरोपित किया जाता है। गंभीर मामलों में दोषियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे चलाकर कारावास दण्ड दिया जाता है।

64. (A) III, II, IV, I
किसी व्यावसायिक लेन-देन के जीएसटी जीवनचक्र में सबसे पहले आपूर्तिकर्ता और खरीदार लेन-देन तय करके कर चालान जारी करते हैं। तत्पश्चात आपूर्तिकर्ता अपनी बिक्री का ब्यौरा देते हुए ऑनलाइन GSTR-1 फॉर्म दाखिल करता है। इसके बाद आपूर्तिकर्ता अपनी देय शुद्ध कर राशि का भुगतान करके GSTR-3B विवरण-पत्र भरता है। अंतिम चरण में दाखिल रिटर्न के आधार पर खरीदार इनपुट टैक्स क्रेडिट दावा करता है।

65. (B) कर संरचना की समीक्षा करना, उल्टे शुल्क के मुद्दों को ठीक करना और स्लैब के विलय का सुझाव देना।
जीएसटी परिषद द्वारा दर युक्तीकरण हेतु गठित मंत्रियों के समूह का मुख्य ध्येय मौजूदा अप्रत्यक्ष कर ढांचे का व्यापक विश्लेषण करना है। यह समूह विभिन्न उत्पादों पर लागू कर दरों की समीक्षा करता है और उल्टे शुल्क ढांचे की समस्याओं को दूर करने के उपाय सुझाता है। इसके अलावा, यह समूह कर स्लैब की संख्या को सीमित करने का प्रस्ताव देता है।

Downloaded from www.pdf.tube

66. (D) कर राजस्व उस राज्य को प्राप्त होता है जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग होता है।
वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में "गंतव्य सिद्धान्त" एक मौलिक अवधारणा है जिसके अनुसार अप्रत्यक्ष कर का रोपण और राजस्व अधिकार उत्पादक राज्य के स्थान पर उपभोक्ता राज्य को मिलता है। इस नियम के तहत अंतर-राज्यीय बिक्री में कर राजस्व अंततः उस विशिष्ट राज्य सरकार के खाते में जमा होता है जहाँ माल का वास्तविक अंतिम उपभोग किया जाता है।

67. (A) बुनियादी सीमा शुल्क आयात पर जारी रहता है, जिसमें बुनियादी सीमा शुल्क के अतिरिक्त IGST लगाया जाता है।
वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के कार्यान्वयन के बाद भी विदेश से आयातित माल पर बुनियादी सीमा शुल्क पूर्ववत लागू रहता है। जब कोई वस्तु अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके भारत में आयातित की जाती है, तो उस पर सबसे पहले बुनियादी सीमा शुल्क लगाया जाता है। इसके पश्चात उस आयातित वस्तु के मूल्य पर अतिरिक्त रूप से एकीकृत जीएसटी (IGST) रोपित होता है।

68. (C) उनके गृह देश से एक कर रेसीडेंसी प्रमाण पत्र
दोहरा कराधान निवारण समझौते के तहत संधि लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवासी करदाताओं के पास अपने गृह देश के सक्षम सरकारी या कर अधिकारियों द्वारा जारी एक अधिकृत 'कर रेसीडेंसी प्रमाण पत्र' (TRC) होना अनिवार्य है। यह कानूनी दस्तावेज यह आधिकारिक पुष्टि प्रदान करता है कि करदाता संबंधित विदेश का वैध निवासी है, जिससे वह रियायती दर का दावा कर सकता है।

69. (A) राज्यों ने महामारी से संबंधित राजस्व घाटे के कारण जीएसटी मुआवजा बढ़ाने की मांग की।
जून 2022 में जीएसटी कानून के तहत राज्यों को दी जाने वाली 5 वर्षों की वैधानिक मुआवजा गारंटी समयावधि समाप्त हो गई। इस अवधि के अंत में महामारी के कारण राज्यों के स्वयं के कर संग्रह में गिरावट दर्ज की गई थी। इसके चलते अनेक राज्य सरकारों और केंद्र के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि राज्यों ने मुआवजा बढ़ाने की मांग रखी थी।

70. (D) आपूर्ति श्रृंखला के पूर्ववर्ती चरणों में भुगतान किए गए कर राज्य सीमाओं के पार अंतिम कर देनदारियों को निर्बाध रूप से समायोजित करते हैं।
जीएसटी व्यवस्था में "क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह" का अर्थ यह है कि संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के दौरान राज्य सीमाओं की परवाह किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट आसानी से एक चरण से दूसरे चरण में स्थानांतरित होता है। किसी भी राज्य में कच्ची सामग्री पर चुकाया गया कर किसी अन्य राज्य में अंतिम कर दायित्व को समायोजित करने हेतु मान्य होता है।

71. (B) एक गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी, धारा 8 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में संरचित और स्थापित किया गया था। यह संस्था देश भर में जीएसटी के सुचारु संचालन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना, डेटा बेस मंच और डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है। वर्तमान में इसके शेयरधारकों में केंद्र तथा राज्य सरकारों की हिस्सेदारी सम्मिलित है।

72. (C) सदस्यों की कुल संख्या का आधा
101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में किए गए प्रावधानों के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की किसी भी आधिकारिक बैठक को वैध रूप से आयोजित करने हेतु आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का कम से कम आधा (50%) होना अनिवार्य है। इसके बिना वैध निर्णय नहीं लिया जा सकता।

NODIA

73. (D) केंद्र सरकार
भारत के संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की सभी आपूर्तियों पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) लगाने और उसका संग्रहण करने का सर्वाधिकार कानूनन केंद्र सरकार के पास निहित है। केंद्र सरकार द्वारा एकत्र की गई इस राशि को तत्पश्चात संवैधानिक नियमों के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है।

74. (A) यह देय आयकर पर एक प्रतिशत शुल्क है, जो उच्च आय अर्जित करने वालों को लक्षित करता है।
भारत में व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था के तहत अधिभार कोई स्वतंत्र कर नहीं है, बल्कि यह किसी करदाता द्वारा अपनी कुल कर योग्य आय पर संगणित मूल देय आयकर की राशि पर लगाया जाने वाला एक प्रतिशत शुल्क होता है। यह व्यवस्था मुख्य रूप से एक निर्धारित सीमा से अधिक वार्षिक आय अर्जित करने वाले उच्च आय वर्ग पर ही लागू होती है।

75. (C) 15%
भारत में औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने तथा "मेक इन इंडिया" पहल के अंतर्गत नए निवेश आकर्षित करने के ध्येय से कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 2019 पारित किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से स्थापत्य होने वाली नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए रियायती आधार कॉर्पोरेट कर दर 15% निर्धारित की गई थी, जो अत्यंत आकर्षक है।

76. (B) केंद्र और राज्य सरकारें एक साझा आधार पर एक साथ कर लगाती हैं।
भारत में अपनाई गई वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था को "दोहरी जीएसटी" प्रणाली कहा जाता है क्योंकि यह हमारे देश के संवैधानिक संघीय ढांचे पर आधारित है। इस मॉडल के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किसी राज्य के भीतर होने वाली वस्तुओं की प्रत्येक अंतरा-राज्यीय आपूर्ति के साझा मूल्य पर एक साथ CGST और SGST रोपित तथा एकत्र करती हैं।

77. (A) छूट प्राप्त आपूर्तियां ITC पुनर्प्राप्ति की अनुमति नहीं देती हैं, जबकि शून्य-दर आपूर्तियां ITC दावों/रिफंड की अनुमति देती हैं।
जीएसटी कानून में "छूट प्राप्त आपूर्ति" से आशय ऐसी वस्तुओं से है जिन पर कर की दर शून्य है या जिन्हें पूर्ण छूट है, परंतु इनके निर्माण में प्रयुक्त इनपुट पर चुकाए गए कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) प्राप्त नहीं होता। इसके विपरीत, "शून्य-दर आपूर्ति" (जैसे निर्यात) में अंतिम बिक्री पर 0% कर लगता है तथा इनपुट कर का पूर्ण रिफंड मिलता है।

78. (C) 1 से अधिक कर प्लवमानता
कर प्लवमानता की गणना कुल कर संग्रह में प्रतिशत परिवर्तन को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित करके की जाती है। यदि किसी वित्तीय वर्ष में किसी देश की जीडीपी में 8 प्रतिशत की वृद्धि होती है और उसी दौरान कर संग्रह में 12 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो कर प्लवमानता 1.5 होती है जो 1 से अधिक है।

79. (D) कानून द्वारा प्रदान किए गए कर प्रोत्साहनों और कटौतियों का वैध रूप से उपयोग करने के लिए मामलों को व्यवस्थित करना।
कर शमन का तात्पर्य किसी करदाता द्वारा अपनी वित्तीय गतिविधियों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है जिससे वह कर कानूनों के मूल उद्देश्य के अनुसार अधिनियम में दी गई छूटों, कटौतियों तथा कर प्रोत्साहनों का पूर्ण लाभ उठा सके। यह प्रक्रिया पूरी तरह से वैध और कानून-सम्मत मानी जाती है क्योंकि इसमें करदाता वैधानिक लाभों का उपयोग अपनी कर देनदारी घटाने में करता है।

80. (C) लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, पारगमन में देरी को घटाना और व्यापार करने में सुगमता में सुधार करना।
समष्टि अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में, अंतर-राज्यीय जांच चौकियों को समाप्त करने तथा जीएसटी के तहत पूरे देश में एकीकृत कर संरचना लागू करने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार करना था। इससे राज्यों की सीमाओं पर माल वाहनों की अनावश्यक रुकावटें दूर हुईं, पारगमन समय घटा, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आई तथा व्यापार करने की सुगमता में सुधार हुआ।

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

अध्याय 04
राष्ट्रीय आय, वृद्धि एवं विकास

1. किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को निम्नलिखित में से किसके कुल बाजार मूल्य के रूप में सबसे सटीक रूप से परिभाषित किया जाता है?
(A) एक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय सीमा के भीतर उत्पादित सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं
(B) देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं, चाहे उनका भौगोलिक स्थान कुछ भी हो
(C) राष्ट्रीय सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास को घटाकर
(D) एक विशिष्ट अवधि के दौरान राष्ट्रीय सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं

2. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) में परिवर्तित करते समय, निम्नलिखित में से किस घटक को जीडीपी में जोड़ा जाना चाहिए?
(A) निवल अप्रत्यक्ष कर
(B) पूंजी उपभोग भत्ता
(C) विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय
(D) कुल निर्यात आय

3. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (अवधारणा)
P. जीडीपी
Q. जीएनपी
R. एनडीपी
S. एनएनपी
सूची II: (परिभाषा)
1. वैश्विक स्तर पर नागरिकों द्वारा उत्पादित कुल अंतिम उत्पादन
2. घरेलू सीमा के भीतर सकल उत्पादन में से मूल्यह्रास घटाकर
3. घरेलू सीमा के भीतर कुल अंतिम उत्पादन
4. वैश्विक स्तर पर नागरिकों के कुल उत्पादन में से मूल्यह्रास घटाकर
(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-3, Q-1, R-4, S-2
(C) P-1, Q-3, R-2, S-4
(D) P-1, Q-3, R-4, S-2

NODIA

4. आय विधि का उपयोग करके राष्ट्रीय आय की गणना करते समय, निम्नलिखित में से किसे साधन आय के रूप में शामिल नहीं किया जाता है?
(A) कर्मचारियों को भुगतान किया गया वेतन और मजदूरी
(B) संपत्ति से प्राप्त किराया और रॉयल्टी
(C) निगम लाभ और वितरित लाभांश
(D) सरकार द्वारा किया गया अंतरण भुगतान

5. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): वास्तविक जीडीपी को समय के साथ आर्थिक संवृद्धि का नाममात्र जीडीपी की तुलना में अधिक विश्वसनीय संकेतक माना जाता है।
कारण (R): वास्तविक जीडीपी की गणना स्थिर कीमतों पर की जाती है, जिससे उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य पर मुद्रास्फीति के विकृत प्रभाव दूर हो जाते हैं।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परंतु कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है, परंतु कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है, परंतु कारण (R) सही है।

6. निवल राष्ट्रीय उत्पाद (एनएनपी) किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय का प्रतिनिधित्व करता है। इसे गणितीय रूप से प्राप्त किया जाता है:
(A) जीएनपी में से विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय घटाकर
(B) एनडीपी में मूल्यह्रास जोड़कर
(C) जीएनपी में से मूल्यह्रास घटाकर
(D) जीडीपी में से अप्रत्यक्ष कर घटाकर

7. राष्ट्रीय आय की गणना की व्यय विधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसमें निजी अंतिम उपभोग व्यय शामिल है।
II. इसमें सरकारी अंतिम उपभोग व्यय शामिल है।
III. इसमें सकल घरेलू पूंजी निर्माण (निवेश) शामिल नहीं है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

8. जीडीपी अवस्फीतिकारक किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का सबसे व्यापक माप है। निम्नलिखित में से कौन-सा सूत्र जीडीपी अवस्फीतिकारक की सही गणना करता है?
(A) (वास्तविक जीडीपी / नाममात्र जीडीपी) × 100
(B) (नाममात्र जीडीपी - वास्तविक जीडीपी) × 100
(C) (जीएनपी / वास्तविक जीडीपी) × 100
(D) (नाममात्र जीडीपी / वास्तविक जीडीपी) × 100

9. आर्थिक संवृद्धि को अक्सर आर्थिक विकास से भिन्न माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन इस अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) संवृद्धि का संबंध केवल समग्र जीवन स्तर में गुणात्मक सुधारों से है, जबकि विकास कुल राष्ट्रीय उत्पादन में केवल अल्पकालिक मात्रात्मक वृद्धि है।
(B) संवृद्धि भौतिक उत्पादन में मात्रात्मक वृद्धि है, जबकि विकास में संवृद्धि के साथ-साथ जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार भी शामिल हैं।
(C) दोनों शब्द वैश्विक स्तर पर सभी विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में देखी जाने वाली एक ही समष्टि अर्थशास्त्रीय परिघटना को संदर्भित करते हैं।
(D) संवृद्धि सामाजिक-आर्थिक समूहों में न्यायसंगत आय वितरण को मापती है, जबकि विकास केवल औद्योगिक उत्पादन को मापता है।

10. निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों को भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उनके वर्तमान सामान्य प्रतिशत योगदान के आधार पर सही अवरोही क्रम (घटते क्रम) में व्यवस्थित कीजिए:
1. कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र
2. सेवा क्षेत्र
3. उद्योग क्षेत्र
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए:
(A) 2, 3, 1
(B) 1, 3, 2
(C) 2, 1, 3
(D) 3, 2, 1

11. वार्षिक मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) का संकलन और प्रकाशन करने के लिए कौन-सा अंतरराष्ट्रीय संगठन उत्तरदायी है?
(A) विश्व बैंक
(B) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)
(C) विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ)
(D) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)

12. सतत विकास की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसे 1987 में ब्रंडलैंड आयोग की रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था।
II. यह भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने पर बल देता है।
III. यह अंतर-पीढ़ीगत समता पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करता है।
IV. यह सभी औद्योगिक विनिर्माण को पूरी तरह से रोकने का समर्थन करता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और IV
(B) केवल I, II और III
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

13. वर्ष 2019 में, भारत सरकार ने दो मौजूदा सांख्यिकीय निकायों का विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) का गठन किया। किन दो निकायों का विलय किया गया था?
(A) भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)
(B) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ)
(C) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) और श्रम ब्यूरो
(D) भारत का योजना आयोग और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

14. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): भारत में कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर पाई जाती है।
कारण (R): सेवा और उद्योग क्षेत्रों की तुलना में भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परंतु कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है, परंतु कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है, परंतु कारण (R) सही है।

15. बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद से प्रारंभ करके साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद (राष्ट्रीय आय) प्राप्त करने के लिए सही गणितीय क्रम चुनिए:
(A) विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय जोड़ें → निवल अप्रत्यक्ष कर घटाएं → मूल्यह्रास घटाएं
(B) मूल्यह्रास घटाएं → निवल अप्रत्यक्ष कर घटाएं → विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय घटाएं
(C) मूल्यह्रास जोड़ें → विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय जोड़ें → निवल अप्रत्यक्ष कर जोड़ें
(D) मूल्यह्रास घटाएं → निवल अप्रत्यक्ष कर जोड़ें → विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय जोड़ें

Downloaded from www.pdf.tube

16. गिनी गुणांक अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक सांख्यिकीय माप है। यह मुख्य रूप से क्या मापता है?
(A) किसी अर्थव्यवस्था में निरपेक्ष गरीबी की दर और जीवन स्तर
(B) जीडीपी में औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र का तुलनात्मक अनुपात
(C) किसी देश के भीतर आय या धन की असमानता की मात्रा
(D) आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं में मुद्रास्फीति की सामान्य दर

17. वास्तविक जीडीपी और संबंधित समष्टि अर्थशास्त्रीय समुच्चयों की गणना के लिए भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाने वाला वर्तमान आधार वर्ष है:
(A) 2004-05
(B) 2011-12
(C) 2015-16
(D) 2019-20

18. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (राष्ट्रीय आय आकलन की विधियां)
P. मूल्य वर्धित विधि
Q. आय विधि
R. व्यय विधि
S. सकल मूल्य वर्धन (जीवीए)
सूची II: (मुख्य घटक/दृष्टिकोण)
1. मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ का योग
2. उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और निवल निर्यात का योग
3. जीडीपी + सब्सिडी - उत्पादों पर कर
4. विभिन्न क्षेत्रों के प्रत्येक उत्पादक उद्यम के योगदान का योग
(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-4, R-3, S-2
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-1, Q-2, R-4, S-3

19. "समावेशी विकास" के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए:
(A) यह राष्ट्रीय आय वितरण पर इसके प्रभाव पर ध्यान दिए बिना तेजी से दोहरे अंकों की जीडीपी वृद्धि प्राप्त करने को संदर्भित करता है।
(B) इसमें ऐसी आर्थिक संवृद्धि शामिल है जो रोजगार के अवसर पैदा करती है तथा गरीबी और आय असमानता को कम करती है।
(C) यह विशेष रूप से शहरी केंद्रों के तीव्र औद्योगीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने पर ध्यान केंद्रित करता है।
(D) इसका तात्पर्य है कि धन का पुनर्वितरण करने के लिए केंद्र सरकार को सभी प्रमुख निजी उद्योगों का सख्ती से राष्ट्रीयकरण करना चाहिए।

20. निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः भारत की राष्ट्रीय आय के सटीक मापन में एक चुनौती नहीं माना जाता है?
(A) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़े गैर-मुद्रीकृत क्षेत्र की उपस्थिति
(B) अपर्याप्त सांख्यिकीय आंकड़े और उनके संकलन में विलंब
(C) जटिल आपूर्ति श्रृंखलाओं में मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं के बीच अंतर करने में कठिनाई
(D) अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों के बीच व्यापक सटीक लेखांकन पद्धतियां

21. सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. जीवीए उत्पादकों के पक्ष से आर्थिक गतिविधि का एक क्षेत्र-विशिष्ट चित्र प्रदान करता है।
II. मूल कीमतों पर जीवीए, बाजार कीमतों पर जीडीपी - उत्पाद कर + उत्पाद सब्सिडी के बराबर होता है।
III. जीवीए घरेलू उत्पादन की गणना करने के लिए विदेशों से प्राप्त निवल आय को ध्यान में रखता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) केवल III
(D) केवल I और II

22. राष्ट्रीय आय लेखांकन में, "अचल पूंजी का उपभोग" पद किसका पर्यायवाची है?
(A) सकल पूंजी निर्माण
(B) निवल निवेश
(C) मूल्यह्रास
(D) पूंजीगत लाभ

23. यदि किसी अर्थव्यवस्था के लिए विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय (एनएफआईए) ऋणात्मक है, तो इसके जीडीपी और जीएनपी के बीच क्या संबंध होगा?
(A) जीडीपी, जीएनपी से अधिक होगा
(B) जीडीपी, जीएनपी से कम होगा
(C) जीडीपी, जीएनपी के बराबर होगा
(D) जीएनपी शून्य के बराबर हो जाएगा

NODIA

24. भारतीय अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग आधे का योगदान देता है।
II. यह भारत में कुल कार्यबल के एक बड़े हिस्से को रोजगार देता है।
III. इस क्षेत्र में लेन-देन पूरी तरह से डिजिटल और अत्यधिक विनियमित हैं।

IV. यह राष्ट्रीय आय लेखांकन के लिए महत्वपूर्ण मापन चुनौतियां उत्पन्न करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल I, II और IV
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

25. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:

कथन (A): पिछले तीन दशकों में भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान प्रभावी और बढ़ता हुआ रहा है।

कारण (R): 'लीपफ्रॉगिंग' की परिघटना ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पारंपरिक विनिर्माण-नेतृत्व वाले विकास चरण को छोड़कर सीधे सेवा-नेतृत्व वाले विकास चरण में प्रवेश करने की अनुमति दी।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परंतु कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है, परंतु कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है, परंतु कारण (R) सही है।

26. प्रति व्यक्ति आय की अक्सर आर्थिक कल्याण के एक सीमित संकेतक के रूप में आलोचना की जाती है, जिसका मुख्य कारण है:

(A) यह देश के कुल जनसंख्या आकार और जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों का आकलन करने में विफल रहता है।
(B) इसे विश्वसनीय वैश्विक तुलनाओं के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं में आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
(C) यह व्यक्तियों के बीच आय के वितरण की उपेक्षा करता है और असमानता को छिपाता है।
(D) यह केवल औपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यरत व्यक्तियों की कुल आय की गणना करता है।

27. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची I: (अवधारणा / सूचकांक)

P. मानव विकास सूचकांक
Q. सतत विकास
R. जीडीपी के आधार वर्ष का संशोधन
S. सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) आंकड़े जारी करना

सूची II: (संबद्ध संस्था / प्रणेता)

1. ब्रंडलैंड आयोग
2. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)
3. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)
4. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-3, Q-1, R-2, S-4
(C) P-1, Q-3, R-2, S-4
(D) P-1, Q-3, R-4, S-2

28. सतत विकास की अवधारणा को आधिकारिक तौर पर "हमारा साझा भविष्य" शीर्षक वाली रिपोर्ट द्वारा परिभाषित और वैश्विक प्रमुखता में लाया गया था। ब्रंडलैंड आयोग द्वारा यह रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की गई थी?

(A) 1972
(B) 1987
(C) 1992
(D) 2000

29. निम्नलिखित में से किस मद को अपवाद माना जाता है और राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है?

(A) पूर्णकालिक सरकारी स्कूल के शिक्षक को दिया जाने वाला मासिक वेतन
(B) छात्रवृत्ति और पेंशन जैसे अंतरण भुगतान
(C) किसी वाणिज्यिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा अर्जित वार्षिक निवल लाभ
(D) स्व-स्वामित्व वाले आवासीय मकान का अनुमानित आरोपित किराया

30. निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रति व्यक्ति आय का एक संकेतक) के सामान्यतः देखे जाने वाले अवरोही क्रम (घटते क्रम) में व्यवस्थित कीजिए:

1. बिहार
2. गोवा
3. राजस्थान

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए:

(A) 2, 3, 1
(B) 1, 3, 2
(C) 3, 2, 1
(D) 2, 1, 3

31. मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित आयामों पर विचार कीजिए:

I. एक लंबा और स्वस्थ जीवन (जन्म के समय जीवन प्रत्याशा)
II. ज्ञान (स्कूली शिक्षा के अपेक्षित और औसत वर्ष)
III. एक सम्मानजनक जीवन स्तर (प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय)

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

Click Here to Buy book on Flipkart

32. आर्थिक संवृद्धि के मापन के संदर्भ में, "स्थिर कीमतों" पर जीडीपी का मूल्यांकन करने से क्या हासिल होता है?
(A) यह क्षेत्रों में औद्योगिक और विनिर्माण उत्पादन की अधिकतम सैद्धांतिक क्षमता को मापता है।
(B) यह सुनिश्चित करता है कि आयातित उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्यांकन लगातार वित्तीय वर्षों में स्थिर रहे।
(C) यह एक आधार वर्ष की तुलना में मुद्रास्फीति या अवस्फीति के लिए कुल उत्पादन मूल्य को समायोजित करता है।
(D) यह केवल प्रचलित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा विनिमय दरों और व्यापार संतुलन के आधार पर राष्ट्रीय उत्पादन की गणना करता है।

33. जीडीपी की गणना की उत्पादन विधि (मूल्य वर्धित दृष्टिकोण) के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए:
(A) यह घरेलू सीमा के भीतर सभी निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा जोड़े गए मूल्य का योग करती है।
(B) मूल्य वर्धन की गणना उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य को घटाकर की जाती है।
(C) यह केवल प्रत्येक उत्पादन चरण में वृद्धिशील मूल्य पर ध्यान केंद्रित करके दोहरी गणना की समस्या से बचाती है।
(D) यह बड़ी संख्या सुनिश्चित करने के लिए जानबूझकर मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य को शामिल करती है।

34. कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद भारत के जीडीपी विकास के पथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. 2020-21 में प्रारंभिक महामारी लॉकडाउन चरण के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने जीडीपी में गंभीर संकुचन का अनुभव किया।
II. अर्थव्यवस्था के बाद के सुधार को अर्थशास्त्रियों द्वारा मोटे तौर पर L-आकार की स्थिरता के रूप में वर्णित किया गया था।
III. डिजिटल तकनीक के कारण सेवा क्षेत्र महामारी के संकुचन से पूरी तरह मुक्त था।
IV. संपर्क-गहन सेवा क्षेत्रों में महामारी के दौरान सबसे तीव्र गिरावट देखी गई।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?
(A) केवल I और IV
(B) केवल II और III
(C) केवल I, II और IV
(D) केवल I और II

35. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): गैर-मुद्रीकृत लेन-देन, जैसे कि निर्वाह कृषि, भारत जैसे विकासशील देशों में वास्तविक राष्ट्रीय आय के कम आंकलन का कारण बनते हैं।
कारण (R): निर्वाह कृषि उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं किसानों द्वारा उपभोग कर लिया जाता है और यह बाजार में नहीं पहुंचता है, जिससे राष्ट्रीय आय खातों में इसका सटीक मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परंतु कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है, परंतु कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है, परंतु कारण (R) सही है।

36. बाजार कीमतों पर मूल्यांकित जीडीपी और साधन लागत पर मूल्यांकित जीडीपी के बीच सटीक आर्थिक अंतर क्या है?
(A) निवासी इकाइयों द्वारा विदेशों से अर्जित निवल साधन आय
(B) अचल परिसंपत्ति मूल्यह्रास का प्रतिनिधित्व करने वाला पूंजी उपभोग भत्ता
(C) कॉर्पोरेट कर मार्जिन और उद्यमों की प्रतिधारित कमाई
(D) निवल अप्रत्यक्ष कर

37. यदि सॉफ्टवेयर विकास में कार्यरत एक भारतीय इंजीनियर जर्मनी में रहता है और भारत में अपने परिवार को धन (प्रेषण) भेजता है, तो भारत के राष्ट्रीय खातों में इस धन का हिसाब कैसे रखा जाता है?
(A) इसे भारत के जीएनपी में शामिल किया जाता है लेकिन इसके जीडीपी में नहीं।
(B) इसे भारत के जीडीपी में शामिल किया जाता है लेकिन इसके जीएनपी में नहीं।
(C) इसे भारत के जीडीपी और जीएनपी दोनों में शामिल किया जाता है।
(D) इसे भारत के जीडीपी और जीएनपी दोनों से बाहर रखा जाता है।

NODIA

38. हाल के दशकों में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्षों को अपनाने का सही ऐतिहासिक क्रम चुनिए:
(A) 2004-05 → 1993-94 → 1999-2000 → 2011-12
(B) 1993-94 → 1999-2000 → 2004-05 → 2011-12
(C) 1999-2000 → 1993-94 → 2011-12 → 2004-05
(D) 1993-94 → 2004-05 → 1999-2000 → 2011-12

39. यद्यपि जीडीपी अवस्फीतिकारक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) दोनों मुद्रास्फीति को मापते हैं, वे मौलिक रूप से भिन्न हैं क्योंकि:
(A) जीडीपी अवस्फीतिकारक सभी घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करता है, जबकि सीपीआई केवल उपभोग बास्केट को शामिल करता है।
(B) जीडीपी अवस्फीतिकारक केवल भौतिक वस्तुओं की कीमतों को मापता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी परिवारों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल करता है।
(C) जीडीपी अवस्फीतिकारक में सभी आयातित पूंजीगत

वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक विदेशी निर्मित वस्तुओं को पूरी तरह बाहर रखता है।

(D) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एनएसओ द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, जबकि जीडीपी अवस्फीतिकारक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिदिन संकलित और प्रकाशित किया जाता है।

40. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची I: (पद/अवधारणा)

P. 0 का गिनी गुणांक

Q. 1 का गिनी गुणांक

R. उच्च राज्य जीडीपी वृद्धि

S. पिछड़ी राज्य अर्थव्यवस्था

सूची II: (निहितार्थ/मूल्य)

1. पूर्ण आय असमानता (एक व्यक्ति के पास पूरी आय है)
2. कम प्रति व्यक्ति आय और कमजोर बुनियादी ढांचा
3. पूर्ण आय समता (सभी की आय बिल्कुल समान है)
4. राष्ट्रीय उत्पादन में उच्च योगदान और बेहतर जीवन स्तर

(A) P-3, Q-1, R-4, S-2

(B) P-1, Q-3, R-2, S-4

(C) P-3, Q-1, R-2, S-4

(D) P-1, Q-3, R-4, S-2

41. आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. आर्थिक संवृद्धि एक बहुआयामी प्रक्रिया है।

II. आर्थिक विकास आर्थिक संवृद्धि से पूरी तरह स्वतंत्र है।

III. कोई देश महत्वपूर्ण आर्थिक विकास के बिना भी आर्थिक संवृद्धि का अनुभव कर सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?

(A) केवल I और II

(B) केवल II और III

(C) केवल III

(D) केवल I और III

42. निम्नलिखित में से कौन-सा नीतिगत परिणाम सामान्यतः किसी अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास के लक्ष्य से संबंधित नहीं होगा?

(A) वित्तीय समावेशन, सूक्ष्म वित्त और ग्रामीण कारीगरों तथा छोटे किसानों के लिए लक्षित ऋण पहुंच का विस्तार करना

(B) औपचारिक और अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रों में समग्र महिला श्रम बल भागीदारी दर में सुधार करना

(C) औद्योगिक सब्सिडी को केवल राजधानी शहर के भीतर केंद्रित करना

(D) ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे सामाजिक समुदायों के लिए व्यापक कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना

NODIA

43. स्वतंत्रता के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. कुल रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी घटकर 10% से नीचे आ गई है।

II. कुल जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है।

III. विनिर्माण क्षेत्र लंबे समय से जीडीपी के लगभग 15-17% पर स्थिर रहा है।

IV. सेवा क्षेत्र देश के अधिकांश जीडीपी को उत्पन्न करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?

(A) केवल I और II

(B) केवल III और IV

(C) केवल I, II और III

(D) केवल II और IV

44. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक "मध्यवर्ती वस्तु" का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है?

(A) बिक्री के लिए ब्रेड बनाने हेतु बेकरी द्वारा खरीदा गया गेहूं का आटा

(B) खेतों की जुताई के लिए किसान द्वारा खरीदा गया ट्रैक्टर

(C) उपभोग के लिए परिवार द्वारा खरीदी गई ब्रेड

(D) शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए छात्र द्वारा खरीदा गया कंप्यूटर

45. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से निवल घरेलू उत्पाद (एनडीपी) की सटीक गणना करने के लिए, एक अर्थशास्त्री को घटाना होगा:

(A) आयातित वस्तुओं का मूल्य

(B) अचल पूंजी का उपभोग (मूल्यह्रास)

(C) कॉर्पोरेट करों का योग

(D) सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी

46. राष्ट्रीय आय आकलन में "दोहरी गणना" की समस्या से सबसे प्रभावी ढंग से बचा जाता है:

(A) अंतिम गणना में सभी अंतरण भुगतानों को शामिल करके

(B) मूल्य वर्धित विधि का उपयोग करके

(C) केवल अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त कच्चे माल की गणना करके

(D) पुरानी (द्वितीयक) वस्तुओं की बिक्री को शामिल करके

47. एक काल्पनिक "बंद अर्थव्यवस्था" में, निम्नलिखित में से कौन-सा समष्टि अर्थशास्त्रीय संबंध सत्य होता है?

(A) विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय शून्य होती है, जिससे जीडीपी, जीएनपी के बराबर हो जाता है

(B) विदेशी सहायता के कारण सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से काफी अधिक हो जाता है

(C) निवल प्रेषण के कारण सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से काफी कम हो जाता है

(D) राष्ट्रीय निर्यात का कुल मूल्य लगातार राष्ट्रीय आयात के कुल मूल्य से अधिक रहता है

48. जीडीपी की गणना की व्यय विधि के तहत, "सकल घरेलू पूंजी निर्माण" मौलिक रूप से किसका माप है?
(A) बैंकों में कुल घरेलू बचत
(B) शेयर बाजार में कारोबार किए गए शेयरों का कुल मूल्य
(C) अर्थव्यवस्था में कुल निवेश व्यय
(D) सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर सरकारी व्यय

49. राष्ट्रीय आय लेखांकन की आय विधि में प्रयुक्त "प्रचालन अधिशेष" की सबसे उपयुक्त परिभाषा की पहचान कीजिए:
(A) सभी क्षेत्रों में भुगतान किए गए वेतन, मजदूरी और कर्मचारी भत्तों का कुल योग
(B) सभी सामाजिक व्ययों को पूरा करने के बाद सरकार का शेष वित्तीय बजट अधिशेष
(C) केवल अंतरराष्ट्रीय वस्तु निर्यात से उत्पन्न निवल विदेशी व्यापार अधिशेष
(D) संपत्ति और उद्यमशीलता से अर्जित आय

50. "बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद" और "साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद" के बीच मौलिक अंतर क्या है?
(A) मूल्यह्रास लागत
(B) सरकारी सब्सिडी
(C) निवल अप्रत्यक्ष कर
(D) सकल निर्यात राजस्व

51. जीडीपी की गणना की व्यय विधि में निम्नलिखित में से किसे "निवल निर्यात" का एक घटक माना जाता है?
(A) निर्यात का कुल मूल्य + आयात का कुल मूल्य
(B) निर्यात का कुल मूल्य - आयात का कुल मूल्य
(C) केवल निर्यात की गई निर्मित वस्तुओं का मूल्य
(D) केंद्रीय बैंक के पास रखा विदेशी मुद्रा भंडार

52. यदि किसी अर्थव्यवस्था का नाममात्र जीडीपी एक वर्ष में 8% बढ़ता है, लेकिन उसी वर्ष वास्तविक जीडीपी में 2% की गिरावट आती है, तो निकाला जा सकने वाला सबसे निश्चित निष्कर्ष क्या है?
(A) घरेलू उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन की भौतिक मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
(B) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ने प्राथमिक उपभोग क्षेत्रों में गंभीर अवस्फीति का अनुभव किया।
(C) विदेशों से अर्जित निवल साधन आय ने तीव्र ऋणात्मक मूल्य दर्ज किया होगा।
(D) देश ने मुद्रास्फीति का अनुभव किया जो घटते उत्पादन पर हावी रही।

53. किसी देश के लिए परिकलित एचडीआई मूल्य संकेतकों को किस पैमाने पर सामान्यीकृत करता है?
(A) 0 से 1
(B) 1 से 10
(C) 0 से 100
(D) -1 से +1

54. ब्रंडलैंड आयोग, जिसने औपचारिक रूप से सतत विकास की अवधारणा को पेश किया था, किस अंतरराष्ट्रीय निकाय द्वारा स्थापित किया गया था?
(A) विश्व व्यापार संगठन
(B) विश्व आर्थिक मंच
(C) संयुक्त राष्ट्र
(D) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

55. जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष का संशोधन (जैसे इसे बदलकर 2011-12 करना) मुख्य रूप से किसलिए किया जाता है?
(A) संरचनात्मक परिवर्तनों को शामिल करने और वर्तमान उपभोग को दर्शाने के लिए वस्तु बास्केट को अद्यतन करने हेतु।
(B) संभावित विदेशी संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए समग्र जीडीपी वृद्धि दर को कृत्रिम रूप से बढ़ाने हेतु।
(C) कुल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र की सांख्यिकीय गणना को पूरी तरह से समाप्त करने हेतु।
(D) आधिकारिक भारतीय वित्तीय वर्ष को मानक अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष मॉडल के साथ संरेखित करने हेतु।

56. भारत की जीडीपी गणना में 2011-12 के आधार वर्ष संशोधन के संबंध में अकादमिक विवाद का मुख्य बिंदु क्या था?
(A) प्राथमिक राष्ट्रीय लेखांकन से कृषि क्षेत्र के योगदान का पूर्ण संरचनात्मक अपवर्जन।
(B) सभी आधारभूत राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि गणनाओं से तृतीयक सेवा क्षेत्र का पूर्ण निष्कासन।
(C) अवस्फीतिकारक की गणना के लिए थोक मूल्य सूचकांक के बजाय केवल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग।
(D) एमसीए-21 डेटाबेस पर निर्भरता, जिसमें कथित तौर पर फर्जी (शेल) कंपनियां शामिल थीं।

57. भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन करने के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) किसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है?
(A) वित्त मंत्रालय
(B) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
(C) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(D) भारतीय रिजर्व बैंक

58. भारत के लगभग 40-45% श्रम बल को रोजगार देने के बावजूद, सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में कृषि क्षेत्र का योगदान वर्तमान में लगभग कितना है?
(A) 15-20%
(B) 35-40%
(C) 50-55%
(D) 5-10%

Downloaded from www.pdf.tube

59. वह परिघटना जिसमें किसी आर्थिक गतिविधि (जैसे कृषि) में आवश्यक संख्या से अधिक श्रमिक कार्यरत होते हैं, क्या कहलाती है?
(A) संरचनात्मक बेरोजगारी
(B) घर्षणात्मक बेरोजगारी
(C) चक्रीय बेरोजगारी
(D) प्रच्छन्न बेरोजगारी

60. अर्थशास्त्री अक्सर भारतीय विकास गाथा को 'लीपफ्रॉगिंग' के रूप में वर्णित करते हैं क्योंकि:
(A) यह एक मजबूत विनिर्माण चरण को छोड़कर सीधे कृषि से सेवाओं की ओर स्थानांतरित हो गई।
(B) इसने स्वतंत्रता के बाद से लगातार हर साल दोहरे अंकों की वार्षिक वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर हासिल की।
(C) इसने एक ही दशक के भीतर सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गंभीर संरचनात्मक गरीबी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया।
(D) 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के तुरंत बाद इसके मुख्य विनिर्माण क्षेत्र ने कृषि क्षेत्र को तेजी से पीछे छोड़ दिया।

61. निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता कम उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा लाभों का अभाव और महत्वपूर्ण गैर-मुद्रीकृत लेन-देन हैं, जिससे इसकी आय को मापना कठिन हो जाता है?
(A) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
(B) अनौपचारिक / असंगठित क्षेत्र
(C) बड़े पैमाने का कॉर्पोरेट विनिर्माण
(D) विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां

62. निम्नलिखित में से कौन-सा किसी देश के निवासियों के औसत जीवन स्तर का सबसे उपयुक्त संकेतक है?
(A) नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद
(B) प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय
(C) वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद
(D) कुल विदेशी मुद्रा भंडार

63. "स्व-नियोजित की मिश्रित आय" राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि में उपयोग की जाने वाली एक अनूठी श्रेणी है। यह आम तौर पर किसकी आय को संदर्भित करता है?
(A) गैर-निगमित उद्यमों और स्व-नियोजित व्यक्तियों जैसे किसानों और दुकानदारों
(B) कार्यप्रदर्शन प्रोत्साहन और स्टॉक विकल्प प्राप्त करने वाले उच्च वेतनभोगी कॉर्पोरेट अधिकारियों
(C) घरेलू सीमा के भीतर अस्थायी रूप से रहने और काम करने वाले विदेशी नागरिकों
(D) उपार्जित सेवानिवृत्ति पेंशन लाभों के साथ नियमित मासिक वेतन प्राप्त करने वाले स्थायी सरकारी कर्मचारियों

64. भारत में राज्यवार प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े लगातार क्षेत्रीय असमानताओं को उजागर करते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों का कौन-सा समूह ऐतिहासिक रूप से प्रति व्यक्ति आय में उच्चतम स्थान पर है?
(A) बिहार और उत्तर प्रदेश
(B) झारखंड और छत्तीसगढ़
(C) गोवा और सिक्किम
(D) असम और ओडिशा

65. यदि किसी देश का गिनी गुणांक एक दशक में 0.45 से गिरकर 0.32 हो जाता है, तो यह निष्कर्ष निकालना सही है कि:
(A) अर्थव्यवस्था गंभीर मंदी में प्रवेश कर चुकी है।
(B) देश की जनसंख्या में तीव्र गिरावट आई है।
(C) देश के भीतर आय की असमानता बढ़ी है।
(D) देश के भीतर आय की असमानता घटी है।

66. उस आर्थिक सुधार का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जहां विभिन्न क्षेत्र, उद्योग या जनसांख्यिकीय समूह अत्यधिक भिन्न दरों पर आर्थिक झटके से उबरते हैं?
(A) V-आकार का सुधार
(B) U-आकार का सुधार
(C) K-आकार का सुधार
(D) L-आकार की स्थिरता

67. भारत द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए) के तहत, सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) की गणना मुख्य रूप से किस पर की जाती है?
(A) बाजार कीमतों पर
(B) मूल कीमतों पर
(C) साधन लागत पर
(D) खुदरा कीमतों पर

68. हाल के जीडीपी विकास रुझानों का विश्लेषण करते समय, विशेष रूप से महामारी के बाद, "आधार प्रभाव" का अक्सर उल्लेख किया जाता है। यह किसको संदर्भित करता है?
(A) एक गंभीर वित्तीय संकट के बाद बुनियादी आर्थिक ढांचे की स्थायी क्षति।
(B) गरीबी रेखा से ऊपर रहने के लिए एक औसत परिवार के लिए आवश्यक न्यूनतम बुनियादी आय।
(C) सभी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर समान रूप से लागू मानक बुनियादी अप्रत्यक्ष कर दर।
(D) पूर्व वर्ष में एक असामान्य संदर्भ बिंदु के कारण वृद्धि दर में विकृति।

69. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जीडीपी अवस्फीतिकारक की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) यह आयातित उपभोक्ता वस्तुओं को बाहर रखता है क्योंकि यह केवल घरेलू उत्पादन को शामिल करता है।
(B) यह कृषि वस्तुओं और सेवाओं की पूरी तरह से उपेक्षा

NODIA

करते हुए केवल निर्मित औद्योगिक वस्तुओं को शामिल करता है।
(C) यह औद्योगिक वस्तुओं की तुलना में आवश्यक कृषि वस्तुओं की खुदरा कीमतों को अत्यधिक महत्व देता है।
(D) यह आधिकारिक राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना अभ्यास के दौरान दशक में केवल एक बार संकलित और परिकलित किया जाता है।

70. मानक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना में भारत में मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक घरेलू देखभाल कार्य को किस प्रकार माना जाता है?
(A) इसका अनुमान राष्ट्रीय उपग्रह खातों का उपयोग करके व्यवस्थित रूप से लगाया जाता है और सीधे कोर जीडीपी में जोड़ा जाता है।
(B) इसका मूल्य वैधानिक न्यूनतम मजदूरी दर पर लगाया जाता है और कुल राष्ट्रीय आय गणना में औपचारिक रूप से शामिल किया जाता है।
(C) बाजार लेन-देन के अभाव के कारण इसे जीडीपी से बाहर रखा जाता है।
(D) इसे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय के एक प्रमुख घटक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

71. लॉरेंज वक्र किस समष्टि अर्थशास्त्रीय अवधारणा से निकटता से संबंधित एक आरेखीय निरूपण है?
(A) आय या धन की असमानता
(B) कर राजस्व लोच
(C) मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का संतुलन
(D) रोजगार का क्षेत्रीय वितरण

72. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आंकड़े दर्ज करने में महत्वपूर्ण विलंब का सबसे प्रत्यक्ष परिणाम निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) सभी प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में तत्काल और व्यापक अति-मुद्रास्फीति का आरंभ।
(B) देश की अंतरराष्ट्रीय संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में स्वचालित वृद्धि।
(C) अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र के आकार में स्थायी कमी।
(D) प्राधिकारियों द्वारा समय पर समष्टि अर्थशास्त्रीय नीति-निर्माण में बाधा।

73. विकासशील अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करते समय, कृषि रोजगार के उच्च हिस्से के साथ जीडीपी में कृषि के घटते हिस्से का क्या अर्थ है?
(A) अत्यधिक कुशल और मशीनीकृत सतत कृषि पद्धतियों की प्राप्ति।
(B) पर्याप्त गैर-कृषि उत्पादक रोजगार सृजित करने में विफलता।
(C) अत्यधिक प्रतिस्पर्धी निर्यात-उन्मुख वाणिज्यिक कृषि अर्थव्यवस्था की ओर एक तीव्र परिवर्तन।
(D) व्यापक और पूरी तरह से समावेशी संतुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकास की प्राप्ति।

74. सतत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा "अंतर-पीढ़ीगत समता" की अवधारणा का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है?
(A) प्रगतिशील धन कराधान के माध्यम से सभी जीवित आयु वर्ग के लोगों के बीच कुल वर्तमान आय को समान करना।
(B) यह सुनिश्चित करना कि सभी वर्तमान और भावी पीढ़ियों को बिल्कुल समान सार्वभौमिक बुनियादी आय गारंटी प्राप्त हो।
(C) संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना ताकि भावी पीढ़ियों को एक मजबूत संसाधन आधार विरासत में मिले।
(D) सभी संचित सार्वजनिक ऋण और वित्तीय घाटे को केवल अगली पीढ़ी को सौंपना।

75. भारत की समावेशी विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक बहुआयामी गरीबी को संबोधित करना है। निम्नलिखित में से कौन-सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के व्यापक आयामों में से एक नहीं है?
(A) समग्र स्वास्थ्य और पोषण संबंधी परिणाम
(B) शैक्षणिक प्राप्ति और स्कूली शिक्षा
(C) घरेलू जीवन स्तर के संकेतक
(D) शेयर बाजार में भागीदारी

76. राष्ट्रीय आय समुच्चयों के संदर्भ में, "साधन लागत" अनिवार्य रूप से दर्शाती है:
(A) उत्पादन के साधनों को प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई उत्पादन लागत।
(B) किसी वाणिज्यिक खुदरा दुकान पर अंतिम उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई कुल अंतिम बाजार कीमत।
(C) सभी प्रत्यक्ष करों का भुगतान करने के बाद कॉर्पोरेट उत्पादकों द्वारा रखी गई निवल अवशिष्ट लाभ राशि।
(D) किसी व्यापारिक औद्योगिक वस्तु की प्रचलित मानक अंतरराष्ट्रीय निर्यात कीमत।

77. 'मेक इन इंडिया' पहल मूल रूप से भारत के जीडीपी ढांचे के संबंध में किस निरंतर समष्टि अर्थशास्त्रीय चुनौती को संबोधित करने के लिए शुरु की गई थी?
(A) राष्ट्रीय उत्पादन में सेवा क्षेत्र के योगदान में निरंतर संरचनात्मक गिरावट।
(B) जीडीपी के लगभग 16-17% पर विनिर्माण के हिस्से का स्थिर रहना।
(C) ग्रामीण कृषि क्षेत्रों का तीव्र अति-औद्योगीकरण और पर्यावरणीय क्षरण।
(D) प्राथमिक असंसाधित कृषि और निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना।

78. किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद को उसकी मध्य-वर्ष की कुल जनसंख्या से विभाजित करके किस समष्टि अर्थशास्त्रीय संकेतक की गणना की जाती है?
(A) निवल राष्ट्रीय उत्पाद

Click Here to Buy book on Amazon

(B) प्रति व्यक्ति जीडीपी
(C) सकल मूल्य वर्धन
(D) राष्ट्रीय प्रयोज्य आय

79. राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किए जाने के संबंध में निम्नलिखित मदों में से भिन्न मद को पहचानिए:
(A) पिता द्वारा अपने पुत्र को दिया गया जेब खर्च
(B) भारतीय सेना के एक सैनिक का वेतन
(C) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का लाभ
(D) कृषि भूमि पट्टे पर देने से प्राप्त किराया

80. घरेलू आर्थिक गतिविधि के संकेतक के रूप में सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को प्राथमिकता दिए जाने का मुख्य कारण यह है कि:
(A) जीडीपी औद्योगिक उत्पादन के कारण होने वाले कुल पर्यावरणीय क्षरण और प्राकृतिक संसाधन ह्रास का व्यवस्थित रूप से हिसाब रखता है।
(B) जीएनपी अपने राष्ट्रीय लेखांकन ढांचे में प्राथमिक कृषि क्षेत्र के कुल उत्पादन की पूरी तरह उपेक्षा करता है।
(C) जीडीपी भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादन को मापता है, जो घरेलू गतिविधि को दर्शाता है।
(D) किसी भी सांख्यिकीय नमूने या सर्वेक्षण विधियों पर निर्भर हुए बिना जीडीपी की सटीक गणना करना आसान है।

NODIA

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (D) एक विशिष्ट अवधि के दौरान राष्ट्रीय सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं
किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को दर्शाता है। इसमें केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। इसके अंतर्गत देश के निवासियों और विदेशी नागरिकों दोनों द्वारा किया गया कुल उत्पादन शामिल होता है, जो अर्थव्यवस्था के समग्र आकार और उत्पादन क्षमता का सटीक मूल्यांकन करता है।

2. (C) विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय
सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय का माप है, चाहे वह उत्पादन घरेलू सीमा में हुआ हो या बाहर। सकल घरेलू उत्पाद केवल देश की सीमा के भीतर हुए उत्पादन को मापता है। इसलिए घरेलू उत्पाद को राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तित करने हेतु विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय को जोड़ा जाता है। यह राशि निवासियों द्वारा अर्जित आय का निवल मूल्य है।

3. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
राष्ट्रीय आय के विभिन्न समष्टि अर्थशास्त्रीय समुच्चयों की विशिष्ट परिभाषाएं होती हैं। सकल घरेलू उत्पाद देश की घरेलू सीमा के भीतर कुल अंतिम उत्पादन को मापता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद वैश्विक स्तर पर देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित कुल अंतिम उत्पादन को दर्शाता है। निवल घरेलू उत्पाद की प्राप्ति घरेलू सीमा में सकल उत्पादन से मूल्यह्रास घटाकर होती है। इसी प्रकार निवल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर प्राप्त होता है।

4. (D) सरकार द्वारा किया गया अंतरण भुगतान
आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय केवल उत्पादन के साधनों को मिलने वाले भुगतानों को ही शामिल किया जाता है। कर्मचारियों का वेतन, संपत्ति से प्राप्त किराया, रॉयल्टी तथा कंपनियों का लाभ उत्पादन प्रक्रियाओं में दिए गए प्रत्यक्ष योगदान के बदले प्राप्त साधन आय हैं। सरकार द्वारा दिए जाने वाले अंतरण भुगतान जैसे पेंशन और छात्रवृत्ति बिना किसी उत्पादन के दिए जाते हैं, इसलिए ये बाहर हैं।

5. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना एक निश्चित आधार वर्ष की स्थिर कीमतों के आधार पर की जाती है। इससे उत्पादन के मूल्य पर होने वाले मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि के कृत्रिम प्रभावों को निष्प्रभावी कर दिया जाता है। नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद चालू कीमतों पर आधारित होता है, जिससे केवल कीमतों में वृद्धि होने पर भी उत्पादन बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को ही किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक भौतिक वृद्धि का अधिक सटीक और विश्वसनीय मापक माना जाता है।

6. (C) जीएनपी में से मूल्यह्रास घटाकर
निवल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश की वास्तविक और शुद्ध राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित करता है। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त पूंजीगत परिसंपत्तियों के घिसावट मूल्य अर्थात मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में पूंजीगत परिसंपत्तियों के रखरखाव और क्षरण की भरपाई करने के बाद वास्तव में कितनी शुद्ध आय बची है, जिसे उपभोग या नए पूंजी निवेश के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

7. (A) केवल I और II
राष्ट्रीय आय गणना की व्यय विधि अर्थव्यवस्था के भीतर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर किए गए कुल व्यय को मापती है। इसके मुख्य घटकों में निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण अर्थात कुल निवेश व्यय और निवल निर्यात शामिल होते हैं। पूंजी निर्माण निवेश का ही एक रूप है, इसलिए इसे व्यय विधि के अभिन्न घटक के रूप में शामिल किया जाता है। अतः पूंजी निर्माण को बाहर रखने वाला विचार पूरी तरह असत्य सिद्ध होता है।

8. (D) (नाममात्र जीडीपी / वास्तविक जीडीपी) × 100
सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिकारक किसी अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला एक व्यापक संकेतक है। इसकी गणना नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद को वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से विभाजित करके और परिणाम को 100 से गुणा करके की जाती है। यह अनुपात दर्शाता है कि चालू वर्ष में कीमतों में हुआ परिवर्तन आधार वर्ष की कीमतों की तुलना में उत्पादन के कुल मूल्य को कितना प्रभावित कर रहा है।

9. (B) संवृद्धि भौतिक उत्पादन में मात्रात्मक वृद्धि है, जबकि विकास में संवृद्धि के साथ-साथ जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार भी शामिल हैं।
आर्थिक संवृद्धि एक संकीर्ण और मात्रात्मक अवधारणा है, जो किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल भौतिक उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि को संदर्भित करती है। इसके विपरीत, आर्थिक विकास एक व्यापक और बहुआयामी अवधारणा है। इसमें आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ जीवन स्तर में सुधार, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, असमानता में कमी और संरचनात्मक परिवर्तन जैसे सामाजिक-आर्थिक गुणात्मक

Downloaded from www.pdf.tube

पहलू भी शामिल होते हैं। यह मानव कल्याण और सामाजिक प्रगति को समग्र रूप से रेखांकित करता है।

10. (A) 2, 3, 1
भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान भिन्न-भिन्न है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा घटक है, जो कुल मूल्य वर्धन और सकल घरेलू उत्पाद में 50% से अधिक का योगदान देता है। इसके बाद उद्योग या द्वितीयक क्षेत्र का स्थान आता है, जिसका योगदान लगभग 25 से 30% के बीच रहता है। कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान लगभग 15 से 20% के बीच है, जिससे सही अवरोही क्रम सेवा, उद्योग तथा कृषि क्षेत्र बनता है।

11. (D) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट का संकलन और प्रकाशन करता है, जिसमें मानव विकास सूचकांक शामिल होता है। यह सूचकांक 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा विकसित किया गया था। यह केवल आय के आधार पर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के संयुक्त मूल्यांकन द्वारा देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के स्तर को मापता है। यह वैश्विक विकास नीतियों की तुलनात्मक समीक्षा का एक प्रामाणिक साधन माना जाता है।

12. (B) केवल I, II और III
सतत विकास की अवधारणा को 1987 में जारी ब्रंडलैंड आयोग की रिपोर्ट में प्रमुखता से परिभाषित किया गया था। यह दृष्टिकोण वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के कल्याण और संसाधन आवश्यकताओं की सुरक्षा पर बल देता है। यह अंतर-पीढ़ीगत समता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। सतत विकास का उद्देश्य औद्योगीकरण को पूरी तरह रोकना नहीं, बल्कि पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जिम्मेदार हरित औद्योगिक प्रथाओं तथा प्रौद्योगिकियों को अपनाना है।

13. (B) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ)
भारत सरकार ने वर्ष 2019 में देश की सांख्यिकीय प्रणाली को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर दिया। इस एकीकरण के परिणामस्वरूप सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की गई। यह एजेंसी अब राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तथा विभिन्न आर्थिक सर्वेक्षणों के संकलन और प्रकाशन के लिए उत्तरदायी मुख्य संस्था है।

14. (C) कथन (A) सही है, परंतु कारण (R) गलत है।
भारत के कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या व्यापक स्तर पर पाई जाती है, जहाँ आवश्यकता से अधिक लोग कार्य में लगे होते हैं और श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। हालाँकि, अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक नहीं है, बल्कि सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान घटकर लगभग 15 से 20% के बीच रह गया है, इसलिए संबंधित कारण पूरी तरह गलत है।

15. (A) विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय जोड़ें → निवल अप्रत्यक्ष कर घटाएं → मूल्यह्रास घटाएं
बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद से साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए क्रमिक समायोजन आवश्यक हैं। सर्वप्रथम, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय जोड़ने पर बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। इसके पश्चात उत्पाद पर लगाए गए निवल अप्रत्यक्ष करों को घटाने पर साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है। अंत में पूंजीगत घिसावट या मूल्यह्रास को घटाने से साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है।

16. (C) किसी देश के भीतर आय या धन की असमानता की मात्रा
गिनी गुणांक सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एक मापक है, जो किसी राष्ट्र के भीतर आय या संपत्ति के वितरण में असमानता को दर्शाता है। इसका मूल्य 0 से 1 के बीच होता है। 0 का मान पूर्ण आय समानता को प्रदर्शित करता है जहाँ सभी व्यक्तियों की आय समान होती है, जबकि 1 का मान पूर्ण असमानता को दर्शाता है जहाँ पूरी आय केवल एक व्यक्ति के पास होती है। यह नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी है।

NODIA

17. (B) 2011-12
भारत में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और अन्य समष्टि अर्थशास्त्रीय आंकड़ों की गणना के लिए वर्तमान में 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे जनवरी 2015 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा पिछले आधार वर्ष 2004-05 के स्थान पर लागू किया गया था। आधार वर्ष का संशोधन अर्थव्यवस्था में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों, नए औद्योगिक आंकड़ों और अद्यतन उपभोग पैटर्न को राष्ट्रीय आय खातों में सही ढंग से शामिल करने के उद्देश्य से किया जाता है।

18. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
राष्ट्रीय आय आकलन की विभिन्न विधियों का विशिष्ट आधार होता है। मूल्य वर्धित विधि अर्थव्यवस्था की विभिन्न उत्पादक इकाइयों द्वारा जोड़े गए मूल्य का योग करती है। आय विधि के अंतर्गत उत्पादन के साधनों को प्राप्त मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ को जोड़ा जाता है। व्यय विधि उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और निवल निर्यात के कुल योग पर आधारित है। सकल मूल्य वर्धन की गणना सकल घरेलू उत्पाद में सब्सिडी जोड़कर और करों को घटाकर की जाती है।

19. (B) इसमें ऐसी आर्थिक संवृद्धि शामिल है जो रोजगार के अवसर पैदा करती है तथा गरीबी और आय असमानता को कम करती है।
समावेशी विकास का तात्पर्य ऐसी आर्थिक वृद्धि से है जिसके लाभ समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित और हाशिए पर रहने वाले लोगों तक पहुंचे। यह केवल सकल घरेलू उत्पाद की तीव्र वृद्धि दर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उत्पादक

रोजगार के अवसरों का सृजन करती है, गरीबी में कमी लाती है, आय विषमता को घटाती है और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक सर्वसुलभ पहुंच सुनिश्चित करती है। यह संवृद्धि आर्थिक प्रक्रिया में सबकी भागीदारी पर जोर देती है।

20. (D) अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों के बीच व्यापक सटीक लेखांकन पद्धतियां
भारत में राष्ट्रीय आय के सटीक मापन में कई संरचनात्मक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-मुद्रीकृत लेन-देन की उपस्थिति, आंकड़ों के संकलन में देरी और मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तुओं के अंतर को स्पष्ट करने में कठिनाई शामिल हैं। हालाँकि, अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों के पास सटीक लेखांकन पद्धतियों का अभाव होता है। यदि सटीक लेखांकन मौजूद होता तो यह मापन को सरल बनाता, इसलिए इसे सटीक मापन के मार्ग में चुनौती नहीं माना जा सकता।

21. (C) केवल III
सकल मूल्य वर्धन उत्पादकों के नजरिए से आर्थिक गतिविधियों और विभिन्न क्षेत्रों के आपूर्ति पक्ष का चित्र प्रस्तुत करता है। मूल कीमतों पर जीवीए की गणना बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में उत्पाद सब्सिडी जोड़कर और उत्पाद करों को घटाकर की जाती है। सकल मूल्य वर्धन एक घरेलू अवधारणा है, जो घरेलू सीमा के भीतर उत्पादन का आकलन करती है। इसमें विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वह राष्ट्रीय सीमाओं से परे होती है।

22. (C) मूल्यह्रास
राष्ट्रीय आय लेखांकन में अचल पूंजी का उपभोग मूल्यह्रास का ही तकनीकी नाम है। यह उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली स्थायी परिसंपत्तियों जैसे मशीनों, इमारतों और उपकरणों के सामान्य घिसावट, टूट-फूट और अप्रचलन के कारण होने वाली मूल्य हानि को दर्शाता है। सकल आंकड़ों में से अचल पूंजी के उपभोग को घटाने पर निवल आंकड़े प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए सकल घरेलू उत्पाद में से इसे घटाने पर निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है।

23. (A) जीडीपी, जीएनपी से अधिक होगा
सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय जोड़कर की जाती है। जब विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय का मूल्य ऋणात्मक होता है, तो इसका अर्थ है कि देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय की तुलना में विदेशी नागरिकों द्वारा देश के भीतर अर्जित आय अधिक है। ऐसी स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद का मान सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक हो जाता है, क्योंकि घरेलू सीमा का उत्पादन अधिक रहता है।

24. (A) केवल I, II और IV
भारत में अनौपचारिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान देता है और कुल कार्यबल के विशाल बहुसंख्यक हिस्से को रोजगार प्रदान करता है। असंगठित प्रकृति, अनौपचारिक लेन-देन और उचित बहियों के अभाव के कारण यह राष्ट्रीय आय लेखांकन में गंभीर मापन संबंधी बाधाएं पैदा करता है। इस क्षेत्र में लेन-देन मुख्य रूप से नकद में होते हैं और ये अत्यधिक विनियमित नहीं होते हैं।

25. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
पिछले तीन दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ा है और यह अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख चालक बन गया है। इस वृद्धि का मुख्य कारण लीपफ्रॉगिंग परिघटना है, जिसमें भारत ने पारंपरिक विनिर्माण संचालित औद्योगिक चरण से आगे बढ़ते हुए सीधे सेवा संचालित विकास मॉडल को अपनाया। सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और वित्तीय सेवाओं के तीव्र विस्तार ने सेवा क्षेत्र को भारतीय विकास गाथा का मुख्य स्तंभ बना दिया है।

26. (C) यह व्यक्तियों के बीच आय के वितरण की उपेक्षा करता है और असमानता को छिपाता है।
प्रति व्यक्ति आय की गणना कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। यह एक औसत आंकड़ा प्रस्तुत करता है लेकिन यह समाज में आय के वास्तविक वितरण की पूरी तरह उपेक्षा करता है। यदि किसी देश में अत्यंत उच्च आय विषमता हो, तब भी प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा उच्च दिखाई दे सकता है। इस प्रकार यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त आर्थिक असमानता और वास्तविक जीवन स्तर को छुपाने का काम करता है।

27. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वार्षिक रूप से किया जाता है। सतत विकास की वैश्विक अवधारणा को 1987 के ब्रंडलैंड आयोग द्वारा रेखांकित किया गया था। भारत में सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष का संशोधन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। इसके अलावा, क्षेत्रवार सकल मूल्य वर्धन के नियमित आंकड़े संकलित और जारी करने का दायित्व राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पास निहित होता है।

28. (B) 1987
सतत विकास की अवधारणा को आधिकारिक तौर पर 1987 में ब्रंडलैंड आयोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य के माध्यम से वैश्विक पहचान मिली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित इस आयोग ने सतत विकास को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया कि विकास ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे बिना भावी पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए। इसने वैश्विक विकास नीतियों को पर्यावरण संरक्षण के साथ एकीकृत करने की नींव रखी।

29. (B) छात्रवृत्ति और पेंशन जैसे अंतरण भुगतान
राष्ट्रीय आय की गणना में केवल उन भुगतानों को शामिल किया जाता है जो वर्तमान उत्पादन गतिविधियों में दिए गए साधन योगदान के बदले प्राप्त होते हैं। छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा

Click Here to Buy book on Flipkart

पेंशन और बेरोजगारी भत्ते जैसे अंतरण भुगतान सरकार या संस्थाओं द्वारा बिना किसी वस्तु या सेवा के प्रत्यक्ष उत्पादन के हस्तांतरित किए जाते हैं। चूंकि ये केवल आय का पुनर्वितरण हैं और इनसे कोई नया मूल्य वर्धन नहीं होता, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय आय की अंतिम गणना से बाहर रखा जाता है।

30. (A) 2, 3, 1
भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में व्यापक प्रादेशिक विषमताएं देखने को मिलती हैं। गोवा छोटा राज्य होने और पर्यटन तथा सेवाओं के उच्च योगदान के कारण लगातार भारत में उच्चतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में शामिल रहता है। राजस्थान मध्यम श्रेणी की प्रति व्यक्ति आय प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत, बिहार ऐतिहासिक और ढांचागत कारणों से सबसे कम प्रति व्यक्ति आय दर्ज करने वाले राज्यों में बना हुआ है, जिससे सही क्रम 2, 3, 1 है।

31. (D) I, II और III
मानव विकास सूचकांक तीन मूलभूत आयामों का उपयोग करके देशों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति का मापन करता है। पहला आयाम स्वास्थ्य है, जिसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है। दूसरा आयाम ज्ञान या शिक्षा है, जिसका मापन स्कूली शिक्षा के औसत और अपेक्षित वर्षों द्वारा किया जाता है। तीसरा आयाम सम्मानजनक जीवन स्तर है, जिसे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर आंका जाता है। ये तीनों आयाम मिलकर सूचकांक का निर्माण करते हैं।

32. (C) यह एक आधार वर्ष की तुलना में मुद्रास्फीति या अवस्फीति के लिए कुल उत्पादन मूल्य को समायोजित करता है।
स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में हुई वृद्धि को मापना होता है। चालू कीमतों पर आधारित आंकड़े केवल मूल्य वृद्धि के कारण भी अधिक दिखाई दे सकते हैं। एक पूर्व निश्चित आधार वर्ष की स्थिर कीमतों का उपयोग करने से मुद्रास्फीति या अवस्फीति के प्रभावों को निरस्त कर दिया जाता है, जिससे केवल वास्तविक भौतिक उत्पादन परिवर्तन का सटीक और निष्पक्ष आकलन संभव होता है।

33. (D) यह बड़ी संख्या सुनिश्चित करने के लिए जानबूझकर मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य को शामिल करती है।
उत्पाद विधि या मूल्य वर्धित दृष्टिकोण में प्रत्येक उत्पादक इकाई द्वारा जोड़े गए मूल्य का योग किया जाता है। इसकी गणना कुल उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य को घटाकर की जाती है। यह विधि उत्पादन के हर चरण पर केवल निवल वृद्धि को ध्यान में रखती है ताकि वस्तुओं की दोहरी गणना से बचा जा सके। जानबूझकर मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य को शामिल करना पूरी तरह गलत है, क्योंकि इससे राष्ट्रीय आय का मूल्य कृत्रिम रूप से बढ़ जाएगा।

34. (B) केवल II और III
महामारी के दौरान भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में संकुचन देखा गया, जिसके बाद त्वरित वी-आकार का सुधार हुआ। महामारी के दौरान होटल, पर्यटन और परिवहन जैसी संपर्क-गहन सेवाओं में तीव्र गिरावट आई थी, इसलिए सेवा क्षेत्र इससे मुक्त नहीं था। अर्थशास्त्रियों ने सुधार को एल-आकार के बजाय वी-आकार का माना था। अतः दूसरा और तीसरा कथन गलत हैं क्योंकि आर्थिक सुधार स्थिर नहीं रहा था और सेवा क्षेत्र पर भी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

35. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में गैर-मुद्रीकृत गतिविधियाँ जैसे निर्वाह कृषि व्यापक पैमाने पर होती हैं। निर्वाह कृषि में किसान फसलों का उत्पादन मुख्यतः अपने परिवार के उपभोग के लिए करते हैं। यह उत्पादन बाजारों तक नहीं पहुंच पाता और इसका कोई औपचारिक वित्तीय लेन-देन दर्ज नहीं होता है। बाजार लेन-देन और विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव के कारण राष्ट्रीय आय खातों में इस उत्पादन का सटीक मूल्यांकन नहीं हो पाता, जिससे राष्ट्रीय आय का कम आंकलन होता है।

36. (D) निवल अप्रत्यक्ष कर
बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद और साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर निवल अप्रत्यक्ष कर होता है। साधन लागत उन सभी भुगतानों का योग है जो उत्पादन के साधनों को दिए जाते हैं। जब इसमें सरकार द्वारा वसूले गए अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा जाता है और दी गई सब्सिडी को घटाया जाता है, तो बाजार मूल्य प्राप्त होता है। अतः निवल अप्रत्यक्ष कर, जो अप्रत्यक्ष कर घटाव सब्सिडी है, इन दोनों मूल्यों का मुख्य अंतर है।

37. (A) इसे भारत के जीएनपी में शामिल किया जाता है लेकिन इसके जीडीपी में नहीं।
सकल घरेलू उत्पाद केवल देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मापता है, इसलिए विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक द्वारा कमाया गया धन भारत के सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं होता। हालाँकि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय को मापता है, चाहे वे विश्व में कहीं भी हों। इसलिए विदेश से भेजा गया धन भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का हिस्सा बनता है लेकिन सकल घरेलू उत्पाद का नहीं।

38. (B) 1993-94 → 1999-2000 → 2004-05 → 2011-12
भारत में राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद की गणना हेतु समय-समय पर आधार वर्षों का संशोधन किया जाता रहा है। स्वतंत्रता के बाद आर्थिक संरचना और उपभोग पैटर्न में बदलावों को शामिल करने के लिए आधार वर्ष बदले गए। ऐतिहासिक क्रम के अनुसार 1993-94 के बाद आधार वर्ष को बदलकर 1999-2000 किया गया। इसके उपरांत इसे 2004-05 में संशोधित किया गया और वर्तमान में लागू आधार वर्ष 2011-12 है, जिसे सांख्यिकी निकाय द्वारा अपनाया गया।

Downloaded from www.pdf.tube

39. (A) जीडीपी अवस्फीतिकारक सभी घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करता है, जबकि सीपीआई केवल उपभोग बास्केट को शामिल करता है।
सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिकारक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति मापने के दो भिन्न साधन हैं। जीडीपी अवस्फीतिकारक एक व्यापक मापक है क्योंकि यह देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को शामिल करता है। इसके विपरीत, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केवल उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने वाले प्रतिनिधि सामानों की एक निश्चित बास्केट पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त, सीपीआई में आयातित उपभोग वस्तुएं शामिल होती हैं जबकि अवस्फीतिकारक में आयातित वस्तुएं नहीं होतीं।

40. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
शून्य का गिनी गुणांक पूर्ण आय समता को प्रदर्शित करता है, जहाँ सभी व्यक्तियों की आय बराबर होती है। एक का गिनी गुणांक पूर्ण असमानता को दर्शाता है, अर्थात संपूर्ण आय केवल एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है। उच्च राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर राष्ट्रीय उत्पादन में अधिक योगदान और बेहतर जीवन स्तर का संकेत देती है। वहीं पिछड़ी राज्य अर्थव्यवस्थाएं कम प्रति व्यक्ति आय और कमजोर ढांचागत विकास की विशेषताओं से जुड़ी होती हैं।

41. (A) केवल I और II
आर्थिक संवृद्धि मुख्यतः एक एकआयामी और मात्रात्मक प्रक्रिया है जो राष्ट्रीय आय में भौतिक वृद्धि को दर्शाती है, जबकि आर्थिक विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। आर्थिक विकास पूरी तरह से आर्थिक संवृद्धि पर निर्भर होता है, क्योंकि बिना आय और उत्पादन वृद्धि के सामाजिक-आर्थिक कल्याण में सुधार करना संभव नहीं है। हालाँकि, यह भी सत्य है कि कोई देश आय में वृद्धि प्राप्त करके आर्थिक संवृद्धि तो दर्ज कर सकता है लेकिन विकास के बिना रह सकता है।

42. (C) औद्योगिक सब्सिडी को केवल राजधानी शहर के भीतर केंद्रित करना
समावेशी विकास का मुख्य ध्येय आर्थिक प्रगति के अवसरों को समाज के सभी क्षेत्रों और भौगोलिक इलाकों में समान रूप से फैलाना है। वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी में वृद्धि करना और वंचित वर्गों के लिए कौशल प्रशिक्षण आयोजित करना समावेशी विकास के मुख्य स्तंभ हैं। औद्योगिक सब्सिडी को केवल राजधानी शहर में केंद्रित करने से क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ेगा और ग्रामीण आबादी विकास से वंचित रहेगी, जो समावेशी विकास के सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

43. (A) केवल I और II
स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव आए हैं। कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी लगातार घटी है, जबकि कुल रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी अभी भी 40% से अधिक बनी हुई है, न कि 10% से नीचे। विनिर्माण क्षेत्र लंबे समय से जीडीपी के 15-17% पर स्थिर रहा है और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है। अतः पहला और दूसरा कथन गलत हैं।

44. (A) बिक्री के लिए ब्रेड बनाने हेतु बेकरी द्वारा खरीदा गया गेहूं का आटा
मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में किया जाता है या जिन्हें उसी वर्ष पुनः बिक्री के लिए खरीदा जाता है। बेकरी द्वारा ब्रेड बनाने के लिए खरीदा गया गेहूं का आटा उत्पादन प्रक्रिया में पूरी तरह उपयोग हो जाता है, इसलिए यह एक मध्यवर्ती वस्तु है। अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई ब्रेड या किसान द्वारा खरीदा गया ट्रैक्टर अंतिम वस्तु के उदाहरण हैं।

45. (B) अचल पूंजी का उपभोग (मूल्यह्रास)
सकल घरेलू उत्पाद से निवल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए उत्पादित मूल्य में से अचल पूंजी के उपभोग अर्थात मूल्यह्रास को घटाया जाता है। सकल आंकड़ों में उत्पादन के दौरान प्रयुक्त पूंजीगत संपत्तियों के घिसावट का मूल्य शामिल रहता है। जब इस घिसावट लागत को सकल घरेलू उत्पाद में से निकाल दिया जाता है, तो अर्थव्यवस्था का शुद्ध या निवल घरेलू उत्पादन प्राप्त होता है। यह आंकड़ा वास्तविक निवल उत्पादन क्षमता को अधिक शुद्धता से दर्शाता है।

46. (B) मूल्य वर्धित विधि का उपयोग करके
राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को बार-बार शामिल कर लिया जाता है। इस समस्या से बचने का सबसे प्रभावी तरीका मूल्य वर्धित विधि अपनाना है। यह विधि उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर केवल नए जोड़े गए निवल मूल्य की गणना करती है। ऐसा करने से कच्चे माल और अंतिम वस्तु के बीच का अंतर स्पष्ट रहता है और राष्ट्रीय आय का वास्तविक और निष्पक्ष मान प्राप्त होता है।

47. (A) विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय शून्य होती है, जिससे जीडीपी, जीएनपी के बराबर हो जाता है
एक काल्पनिक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसका शेष विश्व के साथ कोई अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वित्तीय लेन-देन या श्रम आवाजाही नहीं होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात पूरी तरह अनुपस्थित होते हैं, जिससे विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय का मान शून्य हो जाता है। जब निवल साधन आय शून्य होती है, तो सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य बिल्कुल एक समान हो जाता है क्योंकि समस्त उत्पादन देश के भीतर ही सीमित रहता है।

48. (C) अर्थव्यवस्था में कुल निवेश व्यय
सकल घरेलू उत्पाद की गणना की व्यय विधि के तहत सकल घरेलू पूंजी निर्माण मुख्य रूप से किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कुल निवेश व्यय को मापता है। इसमें अचल संपत्तियों जैसे बुनियादी ढांचे, भवनों, मशीनों और उपकरणों में किया गया निवेश तथा भंडार में हुआ परिवर्तन शामिल होता है। यह कारक अर्थव्यवस्था की भावी उत्पादन

NODIA

क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आर्थिक विकास का मुख्य आधार बनता है।

49. (D) संपत्ति और उद्यमशीलता से अर्जित आय
राष्ट्रीय आय की आय विधि में प्रयुक्त प्रचालन अधिशेष का तात्पर्य उत्पादन प्रक्रिया में संपत्ति और उद्यमशीलता से उत्पन्न होने वाली कुल आय से है। इसके प्रमुख घटकों में संपत्ति से प्राप्त किराया, रॉयल्टी, ब्याज तथा उद्यमशीलता के बदले मिलने वाला लाभ शामिल होता है। यह कर्मचारियों के मुआवजे और स्व-नियोजितों की मिश्रित आय से अलग एक श्रेणी है, जो व्यावसायिक और व्यावसायिक संपत्तियों से उत्पन्न होने वाले आर्थिक अधिशेष का प्रतिनिधित्व करती है।

50. (C) निवल अप्रत्यक्ष कर
बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का मौलिक अंतर निवल अप्रत्यक्ष कर होता है। साधन लागत उत्पादन के साधनों को मिलने वाले वास्तविक भुगतान का योग प्रदर्शित करती है। जब इसमें सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा जाता है और दी गई सब्सिडी को घटाया जाता है, तो बाजार मूल्य प्राप्त होता है। इस प्रकार निवल अप्रत्यक्ष कर ही दोनों अवधारणाओं को पृथक करता है।

51. (B) निर्यात का कुल मूल्य - आयात का कुल मूल्य
व्यय विधि के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद का निर्धारण करते समय निवल निर्यात एक आवश्यक घटक होता है। निवल निर्यात की गणना किसी देश द्वारा विदेशों को बेचे गए वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात मूल्य में से विदेशों से खरीदे गए कुल आयात मूल्य को घटाकर की जाती है। यदि निर्यात का मूल्य आयात से अधिक होता है तो निवल निर्यात धनात्मक रहता है, अन्यथा यह ऋणात्मक होकर कुल व्यय में से घट जाता है।

52. (D) देश ने मुद्रास्फीति का अनुभव किया जो घटते उत्पादन पर हावी रही।
नाममात्र जीडीपी चालू बाजार कीमतों पर आधारित होता है जबकि वास्तविक जीडीपी स्थिर कीमतों पर भौतिक उत्पादन को दर्शाता है। यदि वास्तविक जीडीपी घटता है तो इसका अर्थ है कि वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में कमी आई है। इसके बावजूद यदि नाममात्र जीडीपी में 8% की वृद्धि होती है, तो यह स्पष्ट करता है कि अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति रही है जिसने भौतिक उत्पादन में आई गिरावट के प्रभाव को दबा दिया और कुल मूल्य बढ़ा दिया।

53. (A) 0 से 1
मानव विकास सूचकांक विभिन्न देशों के सामाजिक-आर्थिक विकास के स्तर की तुलना करने के लिए एक मानकीकृत पैमाने का उपयोग करता है। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय जैसे संकेतकों के मान को 0 से 1 के बीच के पैमाने पर सामान्यीकृत किया जाता है। 0 का मान मानव विकास के सबसे न्यूनतम स्तर को दर्शाता है जबकि 1 का मान उच्चतम संभव मानव विकास स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे पारदर्शी अंतरराष्ट्रीय तुलना संभव हो पाती है।

54. (C) संयुक्त राष्ट्र
ब्रंडलैंड आयोग, जिसे आधिकारिक तौर पर पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग कहा जाता है, की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1983 में की गई थी। इस आयोग का नेतृत्व नार्वे की पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हरलेम ब्रंडलैंड ने किया था। आयोग ने 1987 में अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसने सतत विकास की परिभाषा गढ़ी और वैश्विक नीति निर्माण में पर्यावरण संरक्षण एवं आर्थिक विकास के समन्वय को अनिवार्य बना दिया।

55. (A) संरचनात्मक परिवर्तनों को शामिल करने और वर्तमान उपभोग को दर्शाने के लिए वस्तु बास्केट को अद्यतन करने हेतु।
राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद की गणना में आधार वर्ष का संशोधन अर्थव्यवस्था के यथार्थवादी चित्रण के लिए किया जाता है। समय बीतने के साथ अर्थव्यवस्था में नई प्रौद्योगिकियां, नए उद्योग और नए उपभोग पैटर्न सामने आते हैं। आधार वर्ष बदलने से प्रतिनिधि वस्तु बास्केट को अद्यतन किया जाता है, जिससे आर्थिक संरचना में आए बदलावों और नवीनतम आंकड़ों का सटीक समावेश संभव हो पाता है। इससे जीडीपी वृद्धि दर अधिक प्रासंगिक और विश्वसनीय बनती है।

56. (D) एमसीए-21 डेटाबेस पर निर्भरता, जिसमें कथित तौर पर फर्जी (शेल) कंपनियां शामिल थीं।
भारत में जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 अपनाने के बाद व्यापक अकादमिक बहस शुरु हुई। इस विवाद का प्रमुख कारण कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के एमसीए-21 डेटाबेस का बड़े पैमाने पर उपयोग था। आलोचकों और अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया कि इस डेटाबेस में ऐसी निष्क्रिय या फर्जी कंपनियां शामिल थीं जो वास्तव में कोई उत्पादन नहीं कर रही थीं। इसके कारण विनिर्माण और कॉर्पोरेट क्षेत्र के उत्पादन अनुमानों की सटीकता पर गंभीर सवाल उठाए गए।

57. (B) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत में सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों के संकलन और प्रकाशन के लिए प्रमुख एजेंसी है। यह निकाय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। वर्ष 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय का विलय करके इस एकीकृत कार्यालय का गठन किया गया था ताकि सांख्यिकीय गतिविधियों में दक्षता लाई जा सके।

58. (A) 15-20%
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है, जिसमें देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 40 से 45 प्रतिशत हिस्सा संलग्न है। हालाँकि, कुल सकल मूल्य वर्धन में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों का योगदान घटकर केवल 15 से 20 प्रतिशत के बीच रह गया है। यह अंतर कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता, छोटे जोत आकार और कृषि पर अत्यधिक निर्भरता

Click Here to Buy book on Amazon

को उजागर करता है, जिससे प्रति किसान आय अपेक्षाकृत कम बनी रहती है।

59. (D) प्रच्छन्न बेरोजगारी
प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी आर्थिक कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं। यदि इनमें से कुछ श्रमिकों को कार्य से हटा भी दिया जाए, तो कुल उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। भारत के कृषि क्षेत्र में यह स्थिति व्यापक रूप से देखी जाती है, जहाँ परिवार के कई सदस्य सीमित भूमि पर कार्य करते हैं जबकि उतनी श्रम शक्ति की आवश्यकता नहीं होती।

60. (A) यह एक मजबूत विनिर्माण चरण को छोड़कर सीधे कृषि से सेवाओं की ओर स्थानांतरित हो गई।
आर्थिक विकास के पारंपरिक मॉडल में अर्थव्यवस्थाएं कृषि से विनिर्माण की ओर और फिर सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। भारत के संदर्भ में अर्थशास्त्री 'लीपफ्रॉगिंग' शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक बड़े और मजबूत औद्योगिक तथा विनिर्माण क्षेत्र का विकास किए बिना सीधे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से सेवा संचालित अर्थव्यवस्था में प्रवेश किया। आज भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान आधे से अधिक हो चुका है।

61. (B) अनौपचारिक / असंगठित क्षेत्र
अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र की मुख्य विशेषताओं में असंगठित कार्यस्थल, निम्न उत्पादकता, औपचारिक अनुबंधों का अभाव और सामाजिक सुरक्षा लाभों की अनुपस्थिति शामिल हैं। इस क्षेत्र में अधिकांश लेन-देन नकद में होते हैं और वित्तीय बहियों का रखरखाव नहीं किया जाता है। व्यापक गैर-मुद्रीकृत और अलिखित लेन-देन के कारण राष्ट्रीय आय की गणना में इस क्षेत्र की वास्तविक आय और उत्पादन का सटीक मूल्यांकन करना एक अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य सिद्ध होता है।

62. (B) प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय
किसी देश के निवासियों के औसत जीवन स्तर का आकलन करने के लिए प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय को सबसे उपयुक्त संकेतक माना जाता है। नाममात्र जीडीपी केवल चालू कीमतों को दर्शाता है और कुल जीडीपी जनसंख्या के आकार का ध्यान नहीं रखता। प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय जनसंख्या के आकार और मुद्रास्फीति दोनों के प्रभाव को समायोजित करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि औसतन प्रत्येक नागरिक को वस्तुओं और सेवाओं की कितनी वास्तविक क्रय शक्ति प्राप्त हो रही है।

63. (A) गैर-निगमित उद्यमों और स्व-नियोजित व्यक्तियों जैसे किसानों और दुकानदारों
स्व-नियोजित की मिश्रित आय राष्ट्रीय आय की आय विधि में प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण श्रेणी है। यह उन गैर-निगमित उद्यमों, छोटे किसानों, दुकानदारों और स्वतंत्र पेशेवरों की आय को संदर्भित करती है जो स्वयं के साधनों का उपयोग करते हैं। ऐसे मामलों में श्रम से प्राप्त वेतन, स्वयं की भूमि का किराया और पूंजी का ब्याज पृथक करना कठिन होता है। इसलिए उनकी संपूर्ण अर्जित आय को संयुक्त रूप से मिश्रित आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

64. (C) गोवा और सिक्किम
भारत के राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। गोवा और सिक्किम जैसे छोटे राज्य ऐतिहासिक रूप से प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। गोवा में मजबूत पर्यटन उद्योग और सेवा क्षेत्र इसका मुख्य कारण हैं, जबकि सिक्किम में औद्योगिक प्रोत्साहन और जनसांख्यिकी अनुकूल रही है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे घनी आबादी वाले राज्य प्रति व्यक्ति आय में काफी पीछे हैं।

65. (D) देश के भीतर आय की असमानता घटी है।
गिनी गुणांक आय या संपत्ति के वितरण में असमानता को मापने वाला सांख्यिकीय मापक है। इसका मान 0 से 1 के बीच होता है, जहाँ 0 पूर्ण समता और 1 पूर्ण विषमता को दर्शाता है। यदि किसी देश का गिनी गुणांक 0.45 से घटकर 0.32 हो जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि देश में आय का वितरण पहले की तुलना में अधिक समान हुआ है और नागरिकों के बीच आय की असमानता में कमी आई है।

66. (C) K-आकार का सुधार
के-आकार का सुधार उस आर्थिक स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ किसी आर्थिक मंदी या झटके के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, उद्योग या जनसांख्यिकीय समूह असमान गति से उबरते हैं। इसमें कुछ उच्च आय वर्ग या प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्र तेजी से वृद्धि करते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जबकि कम आय वाले वर्ग, अनौपचारिक क्षेत्र या पारंपरिक उद्योग नीचे की ओर गिरते हैं। यह असमानता 'K' अक्षर के दो भिन्न पथों की तरह दिखाई देती है।

67. (B) मूल कीमतों पर
भारत में अपनाई गई राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के तहत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन का आकलन करने के लिए सकल मूल्य वर्धन की गणना मूल कीमतों पर की जाती है। मूल कीमत वह राशि है जो उत्पादक को क्रेता से वस्तु या सेवा की एक इकाई के बदले प्राप्त होती है। इसमें उत्पाद पर देय करों को घटाया जाता है और प्राप्त सब्सिडी को जोड़ा जाता है। यह उत्पादन पक्ष की वास्तविक आर्थिक गतिविधि का शुद्ध चित्र प्रस्तुत करता है।

68. (D) पूर्व वर्ष में एक असामान्य संदर्भ बिंदु के कारण वृद्धि दर में विकृति।
आधार प्रभाव आर्थिक आंकड़ों की प्रतिशत वृद्धि दर की गणना में आने वाली एक सांख्यिकीय विकृति को संदर्भित करता है। जब किसी पूर्व वर्ष या संदर्भ अवधि में उत्पादन का स्तर असाधारण रूप से कम या अधिक होता है, तो चालू वर्ष में मामूली परिवर्तन भी प्रतिशत के रूप में बहुत बड़ा या छोटा दिखाई देता है। उदाहरण के लिए महामारी वर्ष में उत्पादन में

NODIA

भारी गिरावट के कारण अगले वर्ष की वृद्धि दर असामान्य रुप से अत्यधिक उच्च दर्ज हुई थी।

69. (A) यह आयातित उपभोक्ता वस्तुओं को बाहर रखता है क्योंकि यह केवल घरेलू उत्पादन को शामिल करता है।
सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिकारक मुद्रास्फीति का एक व्यापक संकेतक है, लेकिन इसकी एक मुख्य सीमा यह है कि यह केवल देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को शामिल करता है। यह आयातित उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को पूरी तरह बाहर रखता है। चूंकि आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता आयातित वस्तुओं का भी उपभोग करते हैं, इसलिए यह आम उपभोक्ताओं द्वारा अनुभव की जाने वाली वास्तविक जीवन-यापन लागत को पूरी तरह प्रदर्शित नहीं करता।

70. (C) बाजार लेन-देन के अभाव के कारण इसे जीडीपी से बाहर रखा जाता है।
राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद की मानक गणना में केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है जिनका बाजार में क्रय-विक्रय होता है या जिनके लिए मौद्रिक भुगतान किया जाता है। भारत में मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक घरेलू देखभाल कार्यों में कोई वित्तीय लेन-देन नहीं होता है। किसी प्रत्यक्ष बाजार मूल्य के अभाव के कारण इस महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान को औपचारिक सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों से पूरी तरह बाहर रखा जाता है।

71. (A) आय या धन की असमानता
लॉरेंज वक्र सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में आय या संपत्ति के वितरण की असमानता को आरेखीय रुप से प्रदर्शित करने की एक विधि है। इसे 1905 में मैक्स लॉरेंज द्वारा विकसित किया गया था। यह वक्र जनसंख्या के संचयी प्रतिशत और उनके द्वारा प्राप्त आय के संचयी प्रतिशत के बीच संबंध को रेखांकित करता है। यह रेखा पूर्ण समता रेखा से जितनी अधिक दूरी पर झुकती है, समाज में आय या धन की असमानता उतनी ही अधिक मानी जाती है।

72. (D) प्राधिकारियों द्वारा समय पर समष्टि अर्थशास्त्रीय नीति-निर्माण में बाधा।
राष्ट्रीय सांख्यिकीय आंकड़ों के संकलन और प्रकाशन में देरी से अर्थव्यवस्था के वास्तविक और अद्यतन रुझानों की जानकारी नहीं मिल पाती। इसका सबसे प्रत्यक्ष और गंभीर परिणाम यह होता है कि सरकार और केंद्रीय बैंक जैसी नीतियाँ बनाने वाली संस्थाएं समय पर उचित समष्टि अर्थशास्त्रीय फैसले नहीं ले पातीं। अप्रमाणिक आंकड़ों के आधार पर बनाई गई मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां अर्थव्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने में विफल हो सकती हैं, जिससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है।

73. (B) पर्याप्त गैर-कृषि उत्पादक रोजगार सृजित करने में विफलता।
किसी विकासशील अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी घटना स्वाभाविक है, लेकिन यदि कृषि में कार्यरत श्रमबल का हिस्सा अत्यधिक उच्च बना रहता है, तो यह एक गंभीर समस्या है। यह स्थिति दर्शाती है कि उद्योग और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में पर्याप्त गैर-कृषि उत्पादक रोजगार के अवसर पैदा करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। इसके कारण कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या का भार बना रहता है और प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादकता कम रहती है।

74. (C) संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना ताकि भावी पीढ़ियों को एक मजबूत संसाधन आधार विरासत में मिले।
सतत विकास के संदर्भ में अंतर-पीढ़ीगत समता की अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और साथ ही भावी पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। इसका मुख्य ध्येय पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक पूंजी को बचाए रखना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को समृद्ध और संधारणीय संसाधन आधार विरासत में मिले, जिससे उनका विकास बाधित न हो।

75. (D) शेयर बाजार में भागीदारी
बहुआयामी गरीबी सूचकांक केवल आय आधारित गरीबी के बजाय गैर-आय आयामों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके मुख्य तीन आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर हैं। स्वास्थ्य के तहत पोषण और बाल मृत्यु दर, शिक्षा के तहत स्कूली शिक्षा के वर्ष और नामांकन तथा जीवन स्तर के तहत पेयजल, स्वच्छता, बिजली और आवास शामिल हैं। शेयर बाजार में भागीदारी एक वित्तीय निवेश गतिविधि है, जिसे बहुआयामी गरीबी मापने के आयामों में शामिल नहीं किया जाता।

76. (A) उत्पादन के साधनों को प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई उत्पादन लागत।
राष्ट्रीय आय लेखांकन में साधन लागत का तात्पर्य उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्पादन के साधनों को दिए गए कुल भुगतानों के योग से है। उत्पादन के मुख्य चार साधनों भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता को क्रमशः किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में भुगतान किया जाता है। साधन लागत में सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते और इसमें दी गई सब्सिडी शामिल होती है, जो उत्पादक की वास्तविक उत्पादन लागत दर्शाती है।

77. (B) जीडीपी के लगभग 16-17% पर विनिर्माण के हिस्से का स्थिर रहना।
मेक इन इंडिया पहल वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरु की गई एक प्रमुख नीतिगत योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना था। भारतीय अर्थव्यवस्था में दशकों से विनिर्माण क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 16 से 17 प्रतिशत पर स्थिर बना हुआ था। इस चुनौती से निपटने, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने और विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने हेतु यह पहल लाई गई थी।

Downloaded from www.pdf.tube

78. (B) प्रति व्यक्ति जीडीपी
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद एक प्रमुख समष्टि अर्थशास्त्रीय संकेतक है, जो किसी देश के प्रत्येक नागरिक के औसतन आर्थिक उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी गणना किसी वित्तीय वर्ष में देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद को उस वर्ष की मध्य-वर्ष की अनुमानित कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। यह आंकड़ा विभिन्न देशों के बीच आर्थिक उत्पादन और जीवन स्तर की तुलना करने के लिए एक मानक माप के रूप में प्रयोग किया जाता है।

79. (A) पिता द्वारा अपने पुत्र को दिया गया जेब खर्च
राष्ट्रीय आय की गणना में केवल वे भुगतान शामिल किए जाते हैं जो वस्तुओं या सेवाओं के वर्तमान उत्पादन में साधन योगदान के बदले प्राप्त होते हैं। सैनिक का वेतन श्रम का भुगतान है, कंपनी का लाभ उद्यमशीलता का प्रतिफल है और भूमि का किराया संपत्ति आय है। पिता द्वारा पुत्र को दिया गया जेब खर्च एक हस्तांतरण भुगतान है जिसमें कोई आर्थिक उत्पादन शामिल नहीं है, इसलिए यह अन्य तीनों से पूरी तरह भिन्न है।

80. (C) जीडीपी भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादन को मापता है, जो घरेलू गतिविधि को दर्शाता है।
घरेलू आर्थिक गतिविधियों का आकलन करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद को प्राथमिकता दी जाती है। सकल घरेलू उत्पाद देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं को मापता है, चाहे उत्पादक स्वदेशी हों या विदेशी। यह आंकड़ा किसी देश की घरेलू अर्थव्यवस्था के वास्तविक आकार, रोजगार सृजन और आंतरिक उत्पादन क्षमता का सटीक चित्र प्रस्तुत करता है, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशी आय का प्रभाव भी शामिल रहता है।

NODIA

अध्याय 05
राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति

1. निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति की सबसे सटीक परिभाषा प्रदान करता है?
(A) मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा लागू की गई रणनीति।
(B) अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकार द्वारा कराधान, सार्वजनिक व्यय और ऋण का उपयोग।
(C) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपनी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का प्रबंधन करने के लिए अपनाया गया ढांचा।
(D) सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुल्कों का विनियमन।

2. भारत में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत वर्ष 2016 में किया गया था। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं?
(A) चार सदस्य
(B) पांच सदस्य
(C) छह सदस्य
(D) सात सदस्य

3. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): आर्थिक मंदी के दौरान, सरकार आमतौर पर एक विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाती है।
कारण (R): विस्तारवादी राजकोषीय नीति में समग्र मांग को कम करने के लिए सार्वजनिक व्यय में कमी और करों में वृद्धि शामिल है।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

4. निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणात्मक उपकरण के बजाय मौद्रिक नीति के गुणात्मक (चयनात्मक) उपकरण का एक उदाहरण है?
(A) नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)
(B) वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)
(C) सीमांत (मार्जिन) आवश्यकताएं
(D) खुला बाजार संचालन (ओएमओ)

5. तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति उपकरण है। इसका प्राथमिक कार्य क्या है?
(A) रेपो और रिवर्स रेपो संचालन के माध्यम से दैनिक तरलता विषमताओं (असंतुलन) का प्रबंधन करना।
(B) राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए विस्तारित विकास ऋण और दीर्घकालिक साख प्रदान करना।
(C) वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए कॉर्पोरेट आयकर स्लैब और प्रत्यक्ष कर अनुपालन नियम स्थापित करना।
(D) शेयर बाजारों में वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा इक्विटी शेयरों के सार्वजनिक निर्गमन और व्यापार का पर्यवेक्षण करना।

6. भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यांकन ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करती है।
II. वर्तमान मुद्रास्फीति लक्ष्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत पर निर्धारित है।
III. मुद्रास्फीति की ऊपरी सहनशीलता सीमा 6 प्रतिशत और निचली सहनशीलता सीमा 2 प्रतिशत है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से संयोजन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

7. प्रगतिशील कराधान को एक प्रभावी राजकोषीय उपकरण माना जाता है, मुख्य रूप से क्योंकि यह निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है?
(A) यह सबसे धनी व्यक्तियों के बीच उच्च उपभोग को प्रोत्साहित करता है।
(B) यह धन के न्यायसंगत पुनर्वितरण को बढ़ावा देता है और आय असमानता को कम करता है।
(C) यह सुनिश्चित करता है कि जैसे-जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, कर की दरें घटती जाती हैं।
(D) यह आवश्यक वस्तुओं से अप्रत्यक्ष कर संग्रह को अधिकतम करता है।

8. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के संदर्भ में, रेपो दर क्या दर्शाती है?
(A) वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से तरलता को अवशोषित करता है।

Click Here to Buy book on Flipkart

(B) वह ब्याज दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने सबसे साख वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देते हैं।
(C) वह दर जिस पर आरबीआई स्वीकृत प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धनराशि उधार देता है।
(D) नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने में विफल रहने पर आरबीआई द्वारा बैंकों पर लगाई जाने वाली दंडात्मक दर।

9. सूची I में दिए गए मौद्रिक नीति उपकरणों को सूची II में उनके उपयुक्त कार्यों से सुमेलित कीजिए।
सूची I: मौद्रिक नीति उपकरण
P. रिवर्स रेपो दर
Q. सीमांत स्थायी सुविधा
R. खुला बाजार संचालन
S. नैतिक दबाव
सूची II: कार्य
1. आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय
2. बैंकों के लिए आपातकालीन ओवरनाइट (रात भर की) उधार खिड़की
3. अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला उपकरण
4. वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई की नीतियों का पालन करने के लिए सहमत या प्रेरित करना
(A) P-3, Q-2, R-1, S-4
(B) P-2, Q-3, R-1, S-4
(C) P-3, Q-1, R-2, S-4
(D) P-4, Q-2, R-1, S-3

10. घाटे की वित्तव्यवस्था सरकार द्वारा अपने सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के बीच के अंतर को पाटने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है। अत्यधिक घाटे की वित्तव्यवस्था का सबसे तात्कालिक संभावित जोखिम क्या है?
(A) मुद्रा आपूर्ति में अत्यधिक वृद्धि के कारण मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति।
(B) विदेशी मुद्रा बाजारों में घरेलू मुद्रा के मूल्य में तीव्र वृद्धि।
(C) देश के विदेशी मुद्रा भंडार में अनियंत्रित वृद्धि।
(D) कुल उपभोक्ता मांग में अचानक गिरावट के कारण अवस्फीति।

11. लागत-जन्य मुद्रास्फीति कुल आपूर्ति में कमी के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा लागत-जन्य मुद्रास्फीति का एक सामान्य कारण नहीं है?
(A) वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में अचानक अत्यधिक वृद्धि।
(B) नए बुनियादी ढांचे पर सरकारी पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि।
(C) व्यापक रूप से फसल खराब होना, जिससे कृषि कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि हो।
(D) औद्योगिक श्रमिकों के लिए वैधानिक न्यूनतम मजदूरी में महत्वपूर्ण वृद्धि।

12. भारतीय रिजर्व बैंक तरलता प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतिगत दरों का उपयोग करता है। एक सामान्य तरलता गलियारे के तहत निम्नलिखित दरों को उनकी ब्याज दर के परिमाण के सामान्य आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर
2. रिवर्स रेपो दर
3. रेपो दर
निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है?
(A) 1, 2, 3
(B) 2, 3, 1
(C) 3, 2, 1
(D) 2, 1, 3

13. सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरनाइट धनराशि उधार लेने की अनुमति देती है। एमएसएफ दर सामान्यतः मानक रेपो दर की तुलना में कैसी होती है?
(A) एमएसएफ दर आमतौर पर रेपो दर से अधिक होती है।
(B) एमएसएफ दर हमेशा रेपो दर से कम होती है।
(C) एमएसएफ दर हर समय रेपो दर के समान होती है।
(D) एमएसएफ दर व्यक्तिगत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वतंत्र रुप से निर्धारित की जाती है।

NODIA

14. राजकोषीय नीति को मौद्रिक नीति से अलग करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राजकोषीय नीति सरकार द्वारा तैयार और लागू की जाती है।
II. मौद्रिक नीति मुख्य रुप से कराधान और सार्वजनिक ऋण के माध्यम से संचालित की जाती है।
III. भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के लिए नियंत्रक प्राधिकरण है।
IV. नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन एक राजकोषीय नीति हस्तक्षेप का प्रतिनिधित्व करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा संयोजन सही है?
(A) केवल I और III
(B) केवल II और IV
(C) केवल I, II और III
(D) केवल I, III और IV

15. यदि भारतीय रिजर्व बैंक आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग प्रणाली में तरलता डालने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से कौन सा खुला बाजार संचालन (ओएमओ) करेगा?
(A) वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करना।
(B) सीधे जनता को नए नोट जारी करना।
(C) वाणिज्यिक ऋणों के लिए मार्जिन आवश्यकताओं को बढ़ाना।

(D) वाणिज्यिक बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करना।

16. निम्नलिखित में से किस समष्टि आर्थिक परिदृश्य में संकुचनकारी राजकोषीय नीति सबसे उपयुक्त है?
(A) जब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उच्च बेरोजगारी दरों के साथ गंभीर आर्थिक मंदी का सामना कर रही हो।
(B) जब कुल निजी निवेश पूरी तरह से समाप्त हो गया हो और वास्तविक आर्थिक वृद्धि नकारात्मक हो गई हो।
(C) जब अत्यधिक कुल मांग के कारण उच्च मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति हो।
(D) जब केंद्रीय मौद्रिक प्राधिकरण ने मानक रेपो दर को उसके ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर तक घटा दिया हो।

17. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है।
कारण (R): बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक उच्च अनुपात आरबीआई के पास रखना आवश्यक होता है, जिससे साख सृजन के लिए कम धनराशि उपलब्ध होती है।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

18. मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति तब होती है जब अर्थव्यवस्था में कुल मांग, कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है। निम्नलिखित में से किसकी मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति को उत्पन्न करने की सबसे अधिक संभावना है?
(A) वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अचानक और गंभीर व्यवधान जो उत्पादन को सीमित करता है।
(B) आयातित आवश्यक कच्चे माल की घरेलू बाजार लागत में तीव्र और निरंतर वृद्धि।
(C) औद्योगिक बिजली और वाणिज्यिक ऊर्जा की परिचालन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि।
(D) निचले प्रत्यक्ष करों से प्रेरित उपभोक्ता व्यय में भारी वृद्धि।

19. सार्वजनिक व्यय को मोटे तौर पर पूंजीगत और राजस्व व्यय में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के रूप में सही पहचाना गया है?
(A) एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का निर्माण।
(B) सरकारी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान।
(C) पिछले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज का भुगतान।
(D) मौजूदा सरकारी भवनों के नियमित रख-रखाव पर व्यय।

20. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह एक 6-सदस्यीय निकाय है जिसमें तीन सदस्य आरबीआई से और तीन केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं।
II. केंद्रीय वित्त मंत्री एमपीसी के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
III. एमपीसी का प्राथमिक जनादेश मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से संयोजन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

NODIA

21. जब भारतीय रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो दर बढ़ाता है, तो बैंकिंग प्रणाली पर इसका क्या लक्षित प्रभाव पड़ता है?
(A) यह वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास अधिशेष धनराशि रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
(B) यह वाणिज्यिक बैंकों को साख निर्माण का विस्तार करने और खुदरा उधारकर्ताओं को आक्रामक रूप से ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करता है।
(C) यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहने वाले बैंकों पर नियामक वित्तीय दंड लगाता है।
(D) यह व्यक्तिगत ऋण और बंधक (मॉर्गेज) के लिए खुदरा ऋण ब्याज दरों में तत्काल गिरावट का आदेश देता है।

22. सूची I के आर्थिक परिदृश्यों को सूची II की संबंधित नीतिगत प्रतिक्रियाओं के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: आर्थिक परिदृश्य
P. उच्च बेरोजगारी और अवरुद्ध वृद्धि
Q. मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति के साथ अर्थव्यवस्था का अतितापन
R. उच्च उत्पादन लागत की ओर ले जाने वाले आपूर्ति आघात
S. बैंकों द्वारा अपर्याप्त साख विस्तार
सूची II: नीतिगत प्रतिक्रियाएं
1. विस्तारवादी मौद्रिक नीति (दरों में कटौती)
2. विस्तारवादी राजकोषीय नीति (प्रोत्साहन)
3. संकुचनकारी राजकोषीय नीति (कर वृद्धि)
4. आपूर्ति-पक्ष के हस्तक्षेप (इनपुट पर कर राहत)
(A) P-2, Q-3, R-4, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-4, R-3, S-1
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

23. प्रभावी समष्टि आर्थिक प्रबंधन के लिए राजकोषीय और मौद्रिक प्राधिकारियों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती

है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक महत्वपूर्ण समन्वय चुनौती का वर्णन करती है?

(A) केंद्र सरकार संरचनात्मक राजकोषीय घाटे को लगातार कम करती है जबकि आरबीआई साथ ही मानक रेपो दर में कटौती करता है।

(B) भारी सरकारी उधार ब्याज दरों को बढ़ाता है जबकि आरबीआई नीतिगत दरों को कम रखने का प्रयास करता है।

(C) आरबीआई नियमित रूप से सरकारी बांडों का खुले बाजार में क्रय करता है जबकि केंद्र सरकार संतुलित राजकोषीय बजट बनाए रखती है।

(D) सरकार प्रगतिशील कर अनुसूचियों का विस्तार करती है जबकि केंद्रीय बैंक साथ ही एक नियोजित तरलता समावेश कार्यक्रम निष्पादित करता है।

24. मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरणों के तहत, "प्रत्यक्ष कार्रवाई" से क्या तात्पर्य है?

(A) निजी व्यक्तिगत निवेशकों से दीर्घकालिक वित्तीय प्रतिभूतियों के प्रत्यक्ष खुदरा क्रय में मौद्रिक प्राधिकरण का संलग्न होना।

(B) कार्यपालिका सरकार द्वारा सभी आवश्यक घरेलू वस्तुओं के लिए खुदरा उपभोक्ता मूल्य सीधे प्रशासित और तय करना।

(C) नियमों का पालन न करने वाले बैंकों पर आरबीआई द्वारा दंडात्मक कार्रवाई करना या ऋण सुविधाओं से इनकार करना।

(D) केंद्रीय बैंक द्वारा देशभर में प्राथमिकता वाले आर्थिक क्षेत्रों के उधारकर्ताओं को सीधे गैर-वापसी योग्य नकद सब्सिडी प्रदान करना।

25. आरबीआई द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति कार्रवाई के बाद मौद्रिक संचार तंत्र को दर्शाने वाली घटनाओं के सही तार्किक अनुक्रम का चयन कीजिए।

(A) निवेश और उपभोग में वृद्धि → बैंकों द्वारा कम ऋण दरें → आरबीआई द्वारा रेपो दर में कटौती → उच्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि।

(B) आरबीआई द्वारा रेपो दर में कटौती → बैंकों द्वारा कम ऋण दरें → निवेश और उपभोग में वृद्धि → उच्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि।

(C) बैंकों द्वारा कम ऋण दरें → आरबीआई द्वारा रेपो दर में कटौती → उच्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि → निवेश और उपभोग में वृद्धि।

(D) उच्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि → आरबीआई द्वारा रेपो दर में कटौती → निवेश और उपभोग में वृद्धि → बैंकों द्वारा कम ऋण दरें।

26. लगातार उच्च राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति का जोखिम पैदा कर सकता है। किस तंत्र द्वारा उच्च राजकोषीय घाटा सबसे प्रत्यक्ष रूप से मुद्रास्फीति के दबाव में योगदान देता है?

(A) यह तब अत्यधिक मांग पैदा करता है जब इसे ऋण द्वारा वित्तपोषित किया जाता है जो मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करता है।

(B) यह केंद्र सरकार को सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में बिना किसी शर्त के कॉर्पोरेट कर दरों में कटौती करने के लिए मजबूर करता है।

(C) यह प्रमुख आयातित औद्योगिक विनिर्माण इनपुट की क्रय लागत को कृत्रिम रूप से सब्सिडी देता है और कम करता है।

(D) यह सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की वेतन और पेंशन संरचनाओं में तत्काल वैधानिक कमी को ट्रिगर करता है।

27. निम्नलिखित मौद्रिक नीति उपकरणों पर विचार कीजिए:

I. खुला बाजार संचालन (ओएमओ)

II. मार्जिन आवश्यकताएं

III. वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)

IV. नैतिक दबाव

उपर्युक्त उपकरणों में से कौन सा संयोजन मौद्रिक नीति के विशुद्ध रूप से परिमाणात्मक (मात्रात्मक) उपकरणों का प्रतिनिधित्व करता है?

(A) केवल I और II

(B) केवल I और III

(C) केवल II और IV

(D) केवल III और IV

28. वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के तहत वाणिज्यिक बैंकों को अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों (एनडीटीएल) का एक निर्धारित हिस्सा तरल परिसंपत्तियों के रूप में बनाए रखना आवश्यक होता है। एसएलआर बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक पात्र परिसंपत्ति है?

(A) सबस्टैंडर्ड गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए)

(B) प्रभार-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियां

(C) बैंक के पास रखी गई वाणिज्यिक अचल संपत्ति (रियल एस्टेट)

(D) निजी स्टार्टअप कंपनियों के उच्च जोखिम वाले इक्विटी शेयर

29. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।

अभिकथन (A): महामारी के बाद के चरण में, भारतीय रिजर्व बैंक ने धीरे-धीरे अपने मौद्रिक नीति रुख को "उदारता की वापसी" में स्थानांतरित कर दिया।

कारण (R): मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को स्थिर करने और बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने के लिए यह बदलाव आवश्यक था क्योंकि अर्थव्यवस्था महामारी के झटके से उबल रही थी।

(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।

(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।

(C) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

(D) अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

Downloaded from www.pdf.tube

30. मार्जिन आवश्यकता विशिष्ट क्षेत्रों में साख (ऋण) प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक गुणात्मक उपकरण है। इस संदर्भ में "मार्जिन" वास्तव में किसका प्रतिनिधित्व करता है?
(A) कॉर्पोरेट क्रेडिट ऋण पर एक वाणिज्यिक ऋणदात्री संस्था द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ मार्जिन प्रतिशत।
(B) एक अनुसूचित बैंक को आरबीआई के पास सीधे जमा की जाने वाली न्यूनतम दैनिक नकद आरक्षित शेष राशि।
(C) संपार्श्विक के बाजार मूल्य और मंजूर की गई अधिकतम ऋण राशि के बीच का अंतर।
(D) किसी बैंक की कॉर्पोरेट ऋण दर और खुदरा जमा दर के बीच का शुद्ध ब्याज दर अंतर (स्प्रेड)।

31. निम्नलिखित में से कौन सा उपाय विस्तारवादी राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है?
(A) रेलवे पर सरकारी पूंजीगत व्यय में वृद्धि।
(B) निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट कर दरों में कटौती।
(C) प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण प्रदान करने वाली नई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत।
(D) मध्यम आय वाले परिवारों के लिए प्रत्यक्ष कर दरों में वृद्धि।

32. दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि के दृष्टिकोण से, सरकारी बजट में आमतौर पर राजस्व व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता क्यों दी जाती है?
(A) मानक राजस्व व्यय के विपरीत, पूंजीगत व्यय को वैधानिक संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता से कानूनी रूप से छूट प्राप्त है।
(B) पूंजीगत व्यय चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राथमिक राजकोषीय घाटे में तत्काल स्वचालित कमी उत्पन्न करता है।
(C) यह उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करता है जो भविष्य की राष्ट्रीय आर्थिक क्षमता का विस्तार करती हैं।
(D) घरेलू बाजार उधार पर निर्भर हुए बिना पूंजीगत व्यय पूरी तरह से गैर-वापसी योग्य विदेशी अनुदानों के माध्यम से वित्तपोषित होता है।

33. निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए:
I. उत्पादकता लाभ से बेमेल औद्योगिक मजदूरी दरों में तीव्र वृद्धि।
II. आवश्यक वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष करों में अचानक कमी।
III. आपूर्ति-श्रृंखला की बाधाएं जिनके कारण कच्चे माल की कमी हो।
उपर्युक्त कारकों में से कौन सा संयोजन लागत-जन्य मुद्रास्फीति में योगदान देता है?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

34. सूची I में नीतिगत उद्देश्यों को सूची II में उनके मानक नीतिगत उपकरणों के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: नीतिगत उद्देश्य
P. मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना
Q. मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को गति देना
R. किसी एक संकटग्रस्त बैंक को आपातकालीन तरलता प्रदान करना
S. पुनर्वितरण न्याय सुनिश्चित करना
सूची II: मानक नीतिगत उपकरण
1. प्रगतिशील आयकर लागू करना
2. सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)
3. नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में वृद्धि करना
4. घाटे की वित्तव्यवस्था और करों में कटौती
(A) P-3, Q-4, R-2, S-1
(B) P-4, Q-3, R-1, S-2
(C) P-3, Q-2, R-4, S-1
(D) P-1, Q-4, R-2, S-3

35. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन के बाद, भारत में वैधानिक रुप से एक लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यांकन ढांचा अपनाया गया था। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के गठन के साथइसे किस वर्ष औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था?
(A) 2014
(B) 2016
(C) 2018
(D) 2020

NODIA

36. निम्नलिखित में से कौन सा कथन तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के बीच के मुख्य अंतर का सबसे सटीक वर्णन करता है?
(A) एलएएफ संचालन के तहत, बैंक पूरी तरह से बिना किसी संपार्श्विक के धन उधार लेते हैं, जबकि एमएसएफ में जमानत के रूप में संप्रभु सरकारी बांडों को गिरवी रखना अनिवार्य है।
(B) एलएएफ तरलता खिड़कियां विशेष रुप से पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तक सीमित हैं, जबकि एमएसएफ केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए सुलभ है।
(C) एलएएफ के लिए एसएलआर कोटे से अधिक प्रतिभूतियों को गिरवी रखने की आवश्यकता होती है, जबकि एमएसएफ एक निर्धारित सीमा तक एसएलआर कोटे का उपयोग करने की अनुमति देता है।
(D) एलएएफ रेपो संचालन विशेष रुप से दीर्घकालिक संरचनात्मक तरलता समायोजन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जबकि एमएसएफ विशेष रूप से एक अंतरा-दिवस साख सुविधा के रूप में कार्य करता है।

37. मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के निम्नलिखित उपायों में से, कार्यान्वयन प्राधिकारी के संदर्भ में भिन्न उपाय की पहचान कीजिए।

(A) सरकारी राजस्व व्यय में कमी करना।
(B) रेपो दर में वृद्धि करना।
(C) खुला बाजार संचालन के माध्यम से सरकारी बांड बेचना।
(D) नकद आरक्षित अनुपात बढ़ाना।

38. मुद्रास्फीति लक्ष्यांकन ढांचे के अनुसार, यदि औसत सीपीआई मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक सहनशीलता बैंड की सीमाओं का उल्लंघन करती है तो अनिवार्य संस्थागत प्रक्रिया क्या है? तार्किक चरणों को व्यवस्थित कीजिए:
1. आरबीआई उपचारात्मक कार्रवाइयों और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अनुमानित समय अवधि का खाका तैयार करता है।
2. आरबीआई लक्ष्य हासिल करने में विफलता के कारणों की व्याख्या करते हुए एक औपचारिक रिपोर्ट तैयार करता है।
3. रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाती है।

निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है?
(A) 1, 2, 3
(B) 3, 2, 1
(C) 2, 1, 3
(D) 2, 3, 1

39. केंद्रीय बैंक द्वारा आक्रामक मौद्रिक सख्ती (संकुचनकारी मौद्रिक नीति) का मानक समष्टि आर्थिक प्रभाव क्या होता है?
(A) यह साख बाजारों में उधार लागत को व्यवस्थित रूप से कम करता है, जिससे निजी व्यापार निवेश को प्रोत्साहन मिलता है।
(B) यह ब्याज दरें बढ़ाता है, जिससे उपभोग और निवेश में कमी आती है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि धीमी हो जाती है।
(C) यह मंत्रालय को कानूनी रूप से कर दरों को बढ़ाने के लिए मजबूर करके संरचनात्मक राजकोषीय घाटे को स्वचालित रूप से बढ़ाता है।
(D) यह अंतर्राष्ट्रीय निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए घरेलू मुद्रा का तत्काल अवमूल्यन करता है।

40. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): अत्यधिक उच्च राजकोषीय घाटा आर्थिक मंदी के दौरान भी ब्याज दरों को कम करने की केंद्रीय बैंक की क्षमता को सीमित कर सकता है।
कारण (R): घाटे को पूरा करने के लिए उच्च सरकारी उधार सरकारी बांडों की आपूर्ति को बढ़ाता है, जिससे बांड प्रतिफल बढ़ता है और मुद्रास्फीति में वृद्धि का जोखिम पैदा होता है।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

41. निम्नलिखित में से कौन संकुचनकारी राजकोषीय नीति के उपकरण के रूप में कार्य करता है?
(A) नव स्थापित स्टार्टअप उद्यमों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बहु-वर्षीय कर छूट प्रदान करना।
(B) आयातित औद्योगिक कच्चे माल पर मूल शुल्क दरों और सीमा शुल्क में कटौती करना।
(C) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के लिए अनिवार्य साख आवंटन लक्ष्यों में उल्लेखनीय वृद्धि करना।
(D) सार्वजनिक सब्सिडी (सहायिकी) पर व्यय कम करना।

42. आरबीआई के मौद्रिक नीति बयानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. मौद्रिक नीति समिति की बैठक द्विमासिक (हर दो महीने में) होती है।
II. ये बयान आरबीआई के आर्थिक दृष्टिकोण के संबंध में बाजार को संकेत प्रदान करते हैं।
III. नीतिगत बयान के निर्णयों के लिए एमपीसी के सभी सदस्यों की सर्वसम्मति आवश्यक है।
IV. एमपीसी में मत बराबर होने की स्थिति में आरबीआई गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा संयोजन गलत कथन/कथनों की पहचान करता है?
(A) केवल I और II
(B) केवल III
(C) केवल II और IV
(D) केवल I और IV

43. मान लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर तरलता संकट और औद्योगिक विकास में मंदी का सामना कर रही है। इसका मुकाबला करने के लिए, आरबीआई खुला बाजार संचालन (ओएमओ) आयोजित करने का निर्णय लेता है। वह क्या विशिष्ट कार्रवाई करेगा?
(A) वह खुले वित्तीय बाजार में घरेलू सरकारी बांड और ट्रेजरी बिल बेचेगा।
(B) वह खुले बाजार से सरकारी प्रतिभूतियां क्रय करेगा।
(C) वह सरकारी प्रतिभूतियों के सभी वैधानिक द्वितीयक बाजार व्यापार को पूरी तरह से निलंबित और रोक देगा।
(D) वह केंद्र सरकार को तत्काल उच्च-प्रतिफल वाले कर-मुक्त बुनियादी ढांचा बांड जारी करने का निर्देश देगा।

44. आयकर अक्सर अर्थव्यवस्था में "स्वचालित स्टेबलाइजर" के रूप में कार्य करते हैं। राजकोषीय नीति के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है?
(A) वे लगातार वैधानिक बजट संतुलन बनाए रखते हैं ताकि वार्षिक राजकोषीय घाटा शून्य रहे।
(B) वे नए विधान की आवश्यकता के बिना मांग को शांत करने के लिए आर्थिक उछाल के दौरान कर देनदारियों को बढ़ाते हैं।
(C) वे उच्च मुद्रास्फीति चक्रों के दौरान अघोषित आय को स्वचालित रूप से वैध मुद्रा में परिवर्तित करते हैं।
(D) वे विदेशी मुद्राओं की तुलना में घरेलू मुद्रा की विदेशी

Click Here to Buy book on Amazon

विनिमय दर को सीधे स्थिर और मजबूत करते हैं।

45. सूची I के समष्टि आर्थिक शब्दों को सूची II में उनके सही विवरणों के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: समष्टि आर्थिक शब्द
P. राजकोषीय घाटा
Q. राजस्व घाटा
R. प्राथमिक घाटा
S. मौद्रीकृत घाटा
सूची II: विवरण
1. उधार छोड़कर कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर
2. राजकोषीय घाटा घटाव ब्याज भुगतान
3. राजस्व व्यय घटाव राजस्व प्राप्तियां
4. राजकोषीय घाटे का वह भाग जो आरबीआई से उधार लेकर वित्तपोषित किया जाता है
(A) P-1, Q-3, R-2, S-4
(B) P-3, Q-1, R-2, S-4
(C) P-1, Q-3, R-4, S-2
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

46. भारत में वर्तमान विधायी ढांचे के तहत, मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों के वार्षिक परिचालन लाभप्रदता और लाभांश भुगतान को अधिकतम करना।
(B) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में केंद्र सरकार के लिए सख्ती से संतुलित राजकोषीय बजट की गारंटी देना।
(C) आर्थिक वृद्धि का समर्थन करते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।
(D) अमेरिकी डॉलर जैसी प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में घरेलू मुद्रा के लिए एक निश्चित नाममात्र विनिमय दर बनाए रखना।

47. मौद्रिक नीति चर्चाओं में "रेपो" शब्द का अर्थ पुनर्खरीद समझौता है। जब बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं तो इस लेन-देन की मूल प्रकृति क्या होती है?
(A) केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से स्थायी, गैर-पुनराश्रय आधार पर संकटग्रस्त गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को खरीदता है।
(B) वाणिज्यिक बैंक असुरक्षित ओवरनाइट ऋण प्राप्त करने के लिए अपने ग्राहकों के कुल सावधि जमा खातों को आरबीआई के पास गिरवी रखते हैं।
(C) आरबीआई बैंकों के पास रखे दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा भंडार के बदले सीधे नए नोट छापता और जारी करता है।
(D) बैंक आरबीआई को सरकारी प्रतिभूतियां बेचते हैं और बाद में उन्हें एक निर्धारित कीमत पर पुनः खरीदने के लिए सहमत होते हैं।

48. सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह बैंकिंग प्रणाली के लिए अप्रत्याशित तरलता आघातों के खिलाफ एक सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करता है।
II. यह सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए उपलब्ध है।
III. एमएसएफ के तहत उधार लेने की अनुमति तब भी दी जाती है जब बैंक का एसएलआर पोर्टफोलियो एक स्वीकृत प्रतिशत तक वैधानिक सीमा से नीचे गिर जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से संयोजन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

49. कर संरचना का निर्धारण करते समय, एक सरकार प्रतिगामी कर व्यवस्था की तुलना में प्रगतिशील कर व्यवस्था का अत्यधिक समर्थन करती है। इस राजकोषीय विकल्प के पीछे सबसे संभावित प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) शीर्ष आय वर्ग के बीच पूंजी संकेंद्रण और धन संचय को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना।
(B) व्यक्तियों को उनकी भुगतान करने की क्षमता के आधार पर कर लगाकर समता को बढ़ावा देना।
(C) यह सुनिश्चित करना कि कर का बोझ असमान रूप से कमजोर, कम आय वाले जनसांख्यिकीय समूहों पर पड़े।
(D) संघीय राजस्व संग्रह की वैधानिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाना।

50. आर्थिक मंदी के दौरान विस्तारवादी राजकोषीय नीति लागू करने के प्रभावों के सही तार्किक अनुक्रम का चयन कीजिए।
(A) कुल मांग में वृद्धि → उच्च उत्पादन और रोजगार → सरकार व्यय बढ़ाती है/करों में कटौती करती है → आर्थिक सुधार।
(B) सरकार व्यय बढ़ाती है/करों में कटौती करती है → कुल मांग में वृद्धि → उच्च उत्पादन और रोजगार → आर्थिक सुधार।
(C) आर्थिक सुधार → कुल मांग में वृद्धि → सरकार व्यय बढ़ाती है/करों में कटौती करती है → उच्च उत्पादन और रोजगार।
(D) सरकार व्यय बढ़ाती है/करों में कटौती करती है → उच्च उत्पादन और रोजगार → आर्थिक सुधार → कुल मांग में कमी।

NODIA

51. भारत में क्रमशः राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए कौन से संस्थागत प्राधिकारी जिम्मेदार हैं?
(A) वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक।
(B) भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय।
(C) नीति आयोग और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड।
(D) वित्त आयोग और वाणिज्य मंत्रालय।

52. तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. इसे नरसिम्हम समिति (1998) की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई द्वारा शुरु किया गया था।
II. यह मुख्य रूप से रेपो और रिवर्स रेपो नीलामी के माध्यम से संचालित होता है।
III. इसका उपयोग बहु-वर्षीय परिदृश्य में अर्थव्यवस्था में स्थायी तरलता डालने के लिए किया जाता है।
IV. यह बैंकों के दैनिक तरलता प्रबंधन में मदद करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से संयोजन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, II और IV
(D) केवल I, III और IV

53. यदि भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति लंबी अवधि के लिए 7.5% तक पहुंच जाती है, तो इसका अर्थ है कि मुद्रास्फीति ने ऊपरी सहनशीलता सीमा का उल्लंघन किया है। आरबीआई द्वारा कौन सी नीतिगत प्रतिक्रिया अपनाने की सबसे अधिक संभावना है?
(A) मौद्रिक स्थितियों को कड़ा करने के लिए रेपो दर में बढ़ोतरी की एक श्रृंखला।
(B) नकद आरक्षित अनुपात में महत्वपूर्ण कमी।
(C) विस्तारवादी मौद्रिक नीति रुख की ओर बदलाव।
(D) सरकारी प्रतिभूतियों की व्यापक खुला बाजार खरीद।

54. जब सरकार बड़े राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए अपने सार्वजनिक उधार में काफी वृद्धि करती है, तो इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसे "निष्कासन प्रभाव" के रूप में जाना जाता है। इस प्रभाव में क्या शामिल है?
(A) सरकार घरेलू शेयर बाजारों में भाग लेने से विदेशी संस्थागत निवेशकों को पूरी तरह से विस्थापित और बेदखल कर देती है।
(B) त्वरित सरकारी राजकोषीय खर्च अनजाने में घरेलू फर्मों के बीच व्यापक वित्तीय दिवालियापन को जन्म देता है।
(C) मौद्रिक प्राधिकारी वाणिज्यिक बैंकिंग संस्थाओं को राष्ट्रीय मुद्रा वितरण नेटवर्क में भाग लेने से रोकने के लिए मजबूर होता है।
(D) बढ़े हुए सरकारी उधार से ब्याज दरें बढ़ती हैं, जिससे निजी निवेश घटता है।

55. मानक मौद्रिक नीति का उपयोग करके लागत-जन्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना बेहद कठिन होता है क्योंकि मुद्रा आपूर्ति को कड़ा करने से उत्पादन प्रभावित हो सकता है। लागत-जन्य मुद्रास्फीति के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त उपाय माना जाता है?
(A) निजी प्रयोज्य निधि को दबाने के लिए सभी घरेलू आय वर्गों में प्रत्यक्ष आयकर दरों को आक्रामक रूप से बढ़ाना।
(B) उत्पादकता में सुधार और बाधाओं को कम करने के लिए आपूर्ति-पक्ष की नीतियां।
(C) कुल उपभोक्ता मांग को समाप्त करने के लिए प्रमुख केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व उच्च स्तर तक बढ़ाना।
(D) घरेलू वस्तुओं और उपभोक्ता खरीद पर व्यापक रूप से सब्सिडी देने के लिए राजकोष द्वारा बिना किसी समर्थन के सीधे मुद्रा निर्माण।

56. निम्नलिखित में से किसको छोड़कर, अन्य सभी मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति के मान्यता प्राप्त कारण हैं:
(A) घरेलू वस्तुओं की निर्यात मांग में अचानक उछाल।
(B) केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि।
(C) अप्रत्यक्ष करों में तीव्र कमी जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं की खुदरा कीमतें कम होती हैं।
(D) उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि जिससे अत्यधिक साख का विस्तार होता है।

57. मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरणों के तहत, आरबीआई अक्सर "नैतिक दबाव" का उपयोग करता है। इसमें क्या शामिल है?
(A) नियमों का पालन न करने वाली वाणिज्यिक बैंकिंग संस्थाओं पर भारी वैधानिक मौद्रिक जुर्माना और गंभीर नियामक दंड लगाना।
(B) विशेष रूप से ग्रामीण कृषि क्षेत्रों को साख वितरण के लिए सटीक संख्यात्मक कोटा आवंटन का वैधानिक प्रवर्तन।
(C) इक्विटी और प्राथमिक वस्तुओं द्वारा सुरक्षित वाणिज्यिक ऋणों के लिए जमानत मार्जिन आवश्यकताओं में तेज वैधानिक वृद्धि को अनिवार्य बनाना।
(D) ऋण वितरण को आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाने के लिए बैंकों को अनौपचारिक सलाह जारी करना।

58. एक अर्थव्यवस्था संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारवादी राजकोषीय नीति के संयोजन का सामना कर रही है। ब्याज दरों और कुल मांग पर इसका सबसे संभावित संयुक्त प्रभाव क्या होगा?
(A) ब्याज दरें बढ़ेंगी, जबकि मांग पर प्रभाव नीति की मजबूती/सापेक्ष शक्ति पर निर्भर करता है।
(B) बाजार ब्याज दरों में तेजी से गिरावट आएगी, जबकि कुल समष्टि आर्थिक मांग पर अंतिम शुद्ध परिणाम अत्यधिक अस्पष्ट रहेगा।
(C) प्रमुख बाजार ब्याज दरें और समग्र समष्टि आर्थिक मांग दोनों सभी क्षेत्रों में तीव्र, समकालिक संकुचन का अनुभव करेंगे।
(D) प्रमुख बाजार ब्याज दरें और समग्र समष्टि आर्थिक मांग दोनों पूरे आर्थिक तंत्र में तीव्र, अनियंत्रित विस्तार का अनुभव करेंगे।

59. आरबीआई के तरलता प्रबंधन ढांचे के संदर्भ में, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) नीतिगत गलियारे की ऊपरी सीमा के रूप में कार्य करती है। एक सामान्यीकृत नीतिगत ढांचे के तहत एमएसएफ दर को मानक रेपो दर से आमतौर पर कितने आधार अंक ऊपर बनाए रखा जाता है?

Downloaded from www.pdf.tube

(A) 10 आधार अंक
(B) 25 आधार अंक
(C) 100 आधार अंक
(D) 200 आधार अंक

60. सरकारें राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करती हैं। उस एक भिन्न विकल्प की पहचान कीजिए, जो घाटे की वित्तव्यवस्था की एक विधि नहीं है।
(A) सरकारी बांड जारी करके घरेलू बाजारों से उधार लेना।
(B) वाणिज्यिक बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात को घटाना।
(C) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से उधार लेना।
(D) केंद्रीय बैंक से उधार लेकर घाटे का मौद्रीकरण।

61. सरकारी लेखांकन के दृष्टिकोण से, व्यय के प्रकार और उसके उदाहरण के सही सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए।
(A) राजस्व व्यय – राज्य सरकारों को दिए गए अनुदान।
(B) राजस्व व्यय – एक नई जलविद्युत बांध परियोजना का बुनियादी ढांचा निर्माण।
(C) पूंजीगत व्यय – सक्रिय रक्षा कर्मियों को मासिक वेतन और भत्ते का भुगतान।
(D) पूंजीगत व्यय – ऐतिहासिक संचित सार्वजनिक ऋण पर भुगतान किए गए वार्षिक ब्याज दायित्व।

62. यदि आरबीआई रिवर्स रेपो दर बढ़ाने का निर्णय लेता है, तो वाणिज्यिक बैंकों के व्यवहार पर इसका सबसे प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा?
(A) अत्यधिक अप्रयुक्त वैधानिक तरल भंडार रखने के लिए वाणिज्यिक बैंकों पर गंभीर नियामक जुर्माना लगाया जाएगा।
(B) त्रैमासिक लाभ मार्जिन बनाए रखने के लिए वाणिज्यिक बैंक कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए खुदरा ऋण दरों को आक्रामक रूप से कम करेंगे।
(C) बैंक जनता को ऋण देने के बजाय आरबीआई के पास अधिशेष धनराशि रखना पसंद करेंगे।
(D) वाणिज्यिक बैंकों को तत्काल पात्र संप्रभु सरकारी प्रतिभूतियों की तीव्र राष्ट्रीय कमी का सामना करना पड़ेगा।

63. भारत में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यांकन ढांचे के तहत, +/- 2% सहनशीलता सीमा के साथ 4% सीपीआई मुद्रास्फीति का लक्ष्य एक निर्दिष्ट अवधि के लिए तय किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस मुद्रास्फीति लक्ष्य की समीक्षा और निर्धारण कितनी अवधि में किया जाता है?
(A) प्रत्येक वर्ष
(B) प्रत्येक तीन वर्ष में
(C) प्रत्येक पांच वर्ष में
(D) प्रत्येक दस वर्ष में

64. खुला बाजार संचालन (ओएमओ) में आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद शामिल है। इन संचालनों में आरबीआई जिनके साथ लेन-देन करता है, वे प्राथमिक पात्र प्रतिभागी कौन हैं?
(A) व्यक्तिगत खुदरा निवेशक और परिवार।
(B) विशेष रूप से विदेशी संस्थागत निवेशक।
(C) वाणिज्यिक बैंक और प्राथमिक डीलर।
(D) राज्य सरकार के वित्त विभाग।

NODIA

65. यदि कोई देश असहज रूप से उच्च मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है, तो एक विवेकपूर्ण संकुचनकारी राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से किसके शामिल होने की सबसे अधिक संभावना है?
(A) आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के खर्च में वृद्धि करना।
(B) सरकारी व्यय को कम करना और कराधान (करों) को बढ़ाना।
(C) केंद्रीय बैंक की नीतिगत ब्याज दरों को कम करना।
(D) मध्यम आय वाले लोगों को व्यापक कर छूट प्रदान करना।

66. केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में निरंतर वृद्धि से उधार लेना महंगा हो जाता है। कॉर्पोरेट निवेश और रोजगार सृजन पर इसका मानक व्यावहारिक प्रभाव क्या पड़ता है?
(A) सभी औद्योगिक क्षेत्रों में कॉर्पोरेट पूंजीगत निवेश तेजी से बढ़ता है, जिससे देशभर में त्वरित तत्काल रोजगार सृजन होता है।
(B) कॉर्पोरेट निवेश गतिविधि पूरी तरह से अप्रभावित रहती है क्योंकि पूंजी आवंटन सख्ती से और केवल राजकोषीय नीति मापदंडों पर निर्भर करता है।
(C) वाणिज्यिक उद्यम उत्पादकता लाभ को लागू करने और उच्च उधार लागत की भरपाई के लिए आक्रामक रूप से अतिरिक्त पूर्णकालिक औद्योगिक श्रमिकों को काम पर रखते हैं।
(D) वित्तपोषण लागत बढ़ने से कॉर्पोरेट निवेश धीमा हो जाता है, जिससे रोजगार प्रभावित होता है।

67. मौद्रिक नीति चर्चाओं में "रेपो" शब्द का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका पूर्ण रूप क्या है?
(A) पुनर्खरीद समझौता (रीपरचेज एग्रीमेंट)
(B) रिजर्व पोर्टफोलियो ऑप्शन
(C) रीपरचेज ऑप्शन
(D) रिजर्व परफॉर्मेंस ऑर्डर

68. केंद्रीय बैंक आवश्यक वस्तुओं (जैसे दालों या खाद्य तेलों) की सट्टेबाजी आधारित जमाखोरी को रोकने के लिए मार्जिन आवश्यकताओं का उपयोग करता है। यदि इन विशिष्ट वस्तुओं में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो आरबीआई उनकी मार्जिन आवश्यकता के संबंध में क्या कार्रवाई कर सकता है?
(A) यह सट्टेबाजी व्यापार क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंक ऋण प्रवाह को अधिकतम करने के लिए अनिवार्य मार्जिन

आवश्यकता को काफी कम कर देगा।
(B) यह मुक्त बाजार कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कमोडिटी बाजारों में सभी मार्जिन आवश्यकताओं को पूरी तरह से समाप्त और नियंत्रण मुक्त कर देगा।
(C) यह मार्जिन आवश्यकता को बढ़ा देगा, जिससे व्यापारियों को अधिक स्वयं की धनराशि का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
(D) यह वाणिज्यिक व्यापारियों को सीधे दी जाने वाली प्रत्यक्ष केंद्र सरकार की नकद सब्सिडी के साथ मार्जिन आवश्यकताओं को स्थायी रूप से बदल देगा।

69. निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च राजकोषीय घाटे और मुद्रा आपूर्ति के बीच संबंध को सही ढंग से स्थापित करता है?
(A) नई मुद्रा जारी करके उच्च राजकोषीय घाटे का मौद्रीकरण करने से मुद्रा आपूर्ति का सीधे विस्तार होता है।
(B) एक उच्च सरकारी राजकोषीय घाटा पूरी समष्टि अर्थव्यवस्था में कुल व्यापक मुद्रा आपूर्ति उपायों को लगातार कम करता है।
(C) एक बड़ा राजकोषीय घाटा पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करता है और राष्ट्रीय मुद्रा आपूर्ति मापदंडों के साथ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समष्टि आर्थिक संबंध नहीं रखता है।
(D) अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संप्रभु बाहरी उधार के माध्यम से राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने से घरेलू वाणिज्यिक मुद्रा आपूर्ति स्वचालित रूप से सिकुड़ जाती है।

70. महामारी के बाद, आरबीआई ने "उदार" रुख से "उदारता की वापसी" के रुख में बदलाव किया। एक उदार रुख क्या दर्शाता है?
(A) मौद्रिक प्राधिकारी विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा किए गए वार्षिक राजकोषीय घाटे को अत्यधिक कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
(B) मौद्रिक प्राधिकारी राष्ट्रीय आर्थिक विकास मापदंडों की परवाह किए बिना मानक ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी के लिए प्रतिबद्ध रहता है।
(C) मौद्रिक प्राधिकारी मुद्रा विनिमय दर में वृद्धि लाने के लिए वित्तीय बाजारों से कुल अधिशेष तरलता को आक्रामक रूप से बाहर निकालता है।
(D) केंद्रीय बैंक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करता है और ब्याज दरों में कटौती करता है।

71. विभिन्न प्रकार के कराधान के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) प्रगतिशील कराधान के तहत, जैसे-जैसे कर योग्य आय बढ़ती है, कर की दर बढ़ती जाती है।
(B) प्रगतिशील कराधान आमतौर पर एक विकासशील अर्थव्यवस्था में आय असमानता के अंतर को बढ़ाता है।
(C) आनुपातिक कराधान के तहत, आय के स्तर की परवाह किए बिना कर की दर स्थिर रहती है।
(D) प्रतिगामी कराधान के तहत, कम आय वाले व्यक्ति उच्च आय वाले व्यक्तियों की तुलना में अपनी आय का अधिक प्रतिशत कर के रूप में देते हैं।

72. गंभीर आर्थिक मंदी के दौरान, केन्सियन अर्थशास्त्र द्वारा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की वकालत की जाती है। वह प्राथमिक सैद्धांतिक तंत्र क्या है जिसके द्वारा यह अर्थव्यवस्था की मदद करता है?
(A) यह देश के संचयी संरचनात्मक राजकोषीय घाटे में तत्काल स्वचालित संकुचन उत्पन्न करता है।
(B) यह मौद्रिक प्राधिकारी को मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप करने और घरेलू विनिमय दर को बढ़ाने के लिए मजबूर करता है।
(C) यह मांग को समाविष्ट करता है, जिससे आउटपुट और रोजगार पर एक गुणक प्रभाव उत्पन्न होता है।
(D) यह खुदरा उपभोक्ता वस्तुओं के कीमतों में तत्काल गिरावट का कारण बनता है, जिससे मूल्य मुद्रास्फीति पूरी तरह से रुक जाती है।

73. राजकोषीय और मौद्रिक नीति के बीच "समन्वय की विफलता" निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में सबसे अधिक स्पष्ट है?
(A) मुद्रास्फीति में वृद्धि के दौरान केंद्र सरकार सार्वजनिक व्यय को तेजी से कम करती है जबकि आरबीआई साथ ही मानक रेपो दर बढ़ाता है।
(B) केंद्र सरकार और आरबीआई दोनों गंभीर आर्थिक मंदी के दौरान एक साथ समन्वित विस्तारवादी राजकोषीय और मौद्रिक उपायों को तैनात करते हैं।
(C) केंद्रीय बैंक लगातार अतिरिक्त बैंकिंग तरलता को अवशोषित करता है जबकि केंद्र सरकार एक सख्त वैधानिक संतुलित बजट ढांचा बनाए रखती है।
(D) सरकार घाटे से वित्तपोषित राजकोषीय प्रोत्साहन लागू करती है जबकि आरबीआई मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए दरें बढ़ाता है।

74. निम्नलिखित में से कौन सा घटक वाणिज्यिक बैंक के वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव में शामिल नहीं होता है?
(A) निजी विनिर्माण फर्मों के कॉर्पोरेट बांड।
(B) बैंक के पास नकद राशि।
(C) बैंक के स्वामित्व वाला सोना।
(D) प्रभार-मुक्त केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां।

75. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (मुद्रास्फीति लक्ष्यांकन के लिए यथा संशोधित) के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के लिए एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक करना अनिवार्य है?
(A) दो बार
(B) चार बार
(C) छह बार
(D) बारह बार

Click Here to Buy book on Flipkart

76. यदि आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की भारी बिक्री करता है, तो वाणिज्यिक बैंक के भंडार और मुद्रा आपूर्ति पर सबसे संभावित प्रभाव क्या होगा?
(A) बैंक भंडार में वृद्धि होती है, और मुद्रा आपूर्ति का विस्तार होता है।
(B) बैंक भंडार में कमी आती है, और मुद्रा आपूर्ति में संकुचन होता है।
(C) बैंक भंडार अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन मुद्रा आपूर्ति का विस्तार होता है।
(D) बैंक भंडार में कमी आती है, लेकिन गुणक विफलता के कारण मुद्रा आपूर्ति का विस्तार होता है।

77. एक आर्थिक विश्लेषक देखता है कि औद्योगिक उत्पादन में तीव्र गिरावट और बढ़ती बेरोजगारी के साथ-साथ सामान्य मूल्य स्तर बढ़ रहे हैं। किस प्रकार की स्थिति होने की सबसे अधिक संभावना है?
(A) लागत-जन्य मुद्रास्फीति (मुद्रास्फीतिजनित मंदी / स्टैगफ्लेशन)
(B) मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति
(C) अवस्फीति
(D) अत्यधिक मांग से प्रेरित अति-मुद्रास्फीति

78. आरबीआई के तरलता प्रबंधन ढांचे में, मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य भारित औसत कॉल मनी दर (डब्ल्यूएसीआर) है। आरबीआई का लक्ष्य डब्ल्यूएसीआर को एलएएफ गलियारे के भीतर रखना है। क्रमशः इस गलियारे की ऊपरी सीमा और निचली सीमा क्या बनाते हैं?
(A) मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित मानक रेपो दर और ओवरनाइट केंद्रीय बैंक दर।
(B) वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) न्यूनतम अनुपालन लक्ष्य और वैधानिक नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)।
(C) सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर
(D) प्राथमिक केंद्रीय बैंक दर और प्रमुख ऋणदाताओं द्वारा परिकलित वैधानिक वाणिज्यिक बैंक आधार दर।

79. सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) यह विशेष रूप से अल्पकालिक परिचालन लाभ उत्पन्न करता है और इसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के भीतर नियमित रूप से पुनः किया जाना चाहिए।
(B) इसमें प्रशासनिक सरकारी सेवाओं और चल रहे सार्वजनिक पेंशन दायित्वों पर किया जाने वाला नियमित परिचालन व्यय शामिल है।
(C) यह पूरी तरह से अनुत्पादक रहता है और राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि पर कोई मापने योग्य समष्टि आर्थिक गुणक प्रभाव उत्पन्न करने में विफल रहता है।
(D) यह भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण करता है अथवा वित्तीय देनदारियों को कम करता है।

80. स्थिर, मुद्रास्फीति-रहित आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए, सामान्यतः सबसे प्रभावी समष्टि आर्थिक नीति मिश्रण किसे माना जाता है?
(A) सक्रिय समष्टि आर्थिक नीति निर्माण से केंद्रीय मौद्रिक बैंक को स्थायी रूप से बाहर करते हुए आक्रामक राजकोषीय विस्तार पर पूर्ण, विशेष निर्भरता।
(B) लगातार, अनियंत्रित केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे के खर्च के साथ संयुक्त रूप से गंभीर मौद्रिक सख्ती पर पूर्ण, विशेष निर्भरता।
(C) साझा आर्थिक लक्ष्यों की ओर संरेखित समन्वित प्रति-चक्रीय राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां।
(D) सभी उपभोक्ता क्षेत्रों में अत्यधिक प्रतिगामी अप्रत्यक्ष कराधान के साथ सीधे तौर पर संयुक्त एक स्थायी विस्तारवादी मौद्रिक तरलता नीति।

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकार द्वारा कराधान, सार्वजनिक व्यय और ऋण का उपयोग।
राजकोषीय नीति सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली एक प्रमुख समष्टि आर्थिक नीति है। इसके अंतर्गत सरकार अर्थव्यवस्था को दिशा देने और समग्र मांग को प्रभावित करने के लिए कराधान, सार्वजनिक व्यय और सरकारी उधार का उपयोग करती है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, बेरोजगारी घटाना, मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आय की असमानता को कम करना है। मंदी में व्यय बढ़ाकर तथा मुद्रास्फीति में व्यय घटाकर नियंत्रण पाया जाता है।

2. (C) छह सदस्य
भारत में मौद्रिक नीति समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत वर्ष 2016 में किया गया था। इस निकाय में कुल छह सदस्य होते हैं। इनमें से तीन सदस्य रिजर्व बैंक के पदेन अधिकारी होते हैं, जिनमें गवर्नर शामिल हैं। शेष तीन सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। यह समिति देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत दरें तय करने हेतु उत्तरदायी है।

3. (C) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
आर्थिक मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था में मांग घटने से उत्पादन और रोजगार प्रभावित होते हैं। इसे ठीक करने के लिए सरकार विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाती है। इस नीति के तहत सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती है तथा करों की दरों में कटौती करती है ताकि लोगों की क्रय शक्ति बढ़े और समग्र मांग को बढ़ावा मिले। सार्वजनिक व्यय घटाना तथा कर बढ़ाना संकुचनकारी नीति के उदाहरण हैं।

4. (C) सीमांत (मार्जिन) आवश्यकताएं
केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति को संचालित करने के लिए परिमाणात्मक और गुणात्मक उपकरणों का उपयोग करता है। परिमाणात्मक उपकरण अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति और साख की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, जैसे नकद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात और खुला बाजार संचालन। इसके विपरीत, गुणात्मक या चयनात्मक उपकरण अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों में साख प्रवाह और उपयोग की दिशा को नियंत्रित करते हैं। सीमांत आवश्यकताएं इसी चयनात्मक उपकरण का उदाहरण हैं।

5. (A) रेपो और रिवर्स रेपो संचालन के माध्यम से दैनिक तरलता विषमताओं (असंतुलन) का प्रबंधन करना।
तरलता समायोजन सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख मौद्रिक नीति उपकरण है। इसका प्राथमिक कार्य बैंकिंग प्रणाली में दैनिक तरलता के असंतुलन का प्रबंधन करना है। इस सुविधा के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक रेपो दरों पर अल्पकालिक धनराशि उधार ले सकते हैं या रिवर्स रेपो दरों पर अपनी अधिशेष धनराशि केंद्रीय बैंक के पास जमा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया अल्पकालिक ब्याज दरों को स्थिर रखती है।

NODIA

6. (D) I, II और III
भारत में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यांकन ढांचा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत लागू किया गया है। इसके अंतर्गत भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से प्रत्येक पांच वर्ष में मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4 प्रतिशत तय किया गया है। इसके साथ ही 2 प्रतिशत की निचली सीमा और 6 प्रतिशत की ऊपरी सहनशीलता सीमा निर्धारित की गई है।

7. (B) यह धन के न्यायसंगत पुनर्वितरण को बढ़ावा देता है और आय असमानता को कम करता है।
प्रगतिशील कराधान एक राजकोषीय नीतिगत ढांचा है जिसमें करदाता की आय बढ़ने के साथ-साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य समाज में आय और धन की विषमताओं को कम करना है। उच्च आय वर्ग पर अधिक कर लगाकर एकत्र किए गए राजस्व का उपयोग सरकार निम्न आय वर्ग के कल्याण और सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार के लिए करती है। इससे संसाधनों का न्यायसंगत पुनर्वितरण होता है।

8. (C) वह दर जिस पर आरबीआई स्वीकृत प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धनराशि उधार देता है।
रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में रखकर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धनराशि उधार देता है। जब बैंकों को अपनी दैनिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोष की आवश्यकता होती है, तो वे इस सुविधा का उपयोग करते हैं। रेपो दर में बदलाव से वाणिज्यिक बैंकों की उधार लागत प्रभावित होती है, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था में तरलता नियंत्रित होती है।

9. (A) P-3, Q-2, R-1, S-4
मौद्रिक नीति के विभिन्न उपकरण तरलता और साख को नियंत्रित करते हैं। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक बैंकों से अधिशेष तरलता अवशोषित करता है। सीमांत स्थायी सुविधा बैंकों को आपातकालीन ओवरनाइट ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती है। खुला बाजार संचालन के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय किया जाता है। नैतिक दबाव के तहत केंद्रीय बैंक बैंकों को नीतियों का पालन करने हेतु प्रेरित करता है।

10. (A) मुद्रा आपूर्ति में अत्यधिक वृद्धि के कारण मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति।
घाटे की वित्तव्यवस्था के अंतर्गत सरकार अपने सार्वजनिक व्यय और राजस्व के अंतर को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से उधार लेती है या नई मुद्रा का सृजन करती है। जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक नई मुद्रा पेश की जाती है, तो बाजार में कुल मुद्रा आपूर्ति में तीव्र वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है और वस्तुओं की मांग आपूर्ति से अधिक होकर मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न करती है।

11. (B) नए बुनियादी ढांचे पर सरकारी पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि।
लागत-जन्य मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जब उत्पादन की लागत बढ़ने के कारण कुल आपूर्ति में कमी आती है। कच्चे तेल के वैश्विक मूल्यों में वृद्धि, वैधानिक न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी और फसल खराब होने से कच्चे माल की कीमतें बढ़ती हैं, जो लागत-जन्य मुद्रास्फीति के कारण हैं। इसके विपरीत, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकार द्वारा किया जाने वाला पूंजीगत व्यय अर्थव्यवस्था में कुल मांग को बढ़ाता है, जो मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति का कारक है।

12. (B) 2, 3, 1
भारतीय रिजर्व बैंक के तरलता गलियारे के तहत नीतिगत दरों का एक निश्चित क्रम होता है। रिवर्स रेपो दर वह दर होती है जिस पर बैंक केंद्रीय बैंक के पास धन जमा करते हैं, इसलिए यह सबसे कम होती है। इसके बाद रेपो दर आती है, जिस पर बैंक अल्पकालिक ऋण लेते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा दर आपातकालीन ओवरनाइट उधार दर होने के कारण सबसे अधिक होती है। अतः सही क्रम रिवर्स रेपो, रेपो और सीमांत स्थायी सुविधा है।

13. (A) एमएसएफ दर आमतौर पर रेपो दर से अधिक होती है।
सीमांत स्थायी सुविधा वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक आपातकालीन ऋण खिड़की है। इसके तहत बैंक अपनी वैधानिक तरलता अनुपात सीमा का एक निश्चित हिस्सा गिरवी रखकर भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरनाइट धनराशि उधार ले सकते हैं। चूंकि यह सुविधा बैंकों को अचानक आई तरलता कमी से निपटने के लिए प्रदान की जाती है, इसलिए इस पर ली जाने वाली ब्याज दर मानक रेपो दर की तुलना में हमेशा अधिक रखी जाती है।

14. (A) केवल I और III
राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति दो अलग समष्टि आर्थिक नीतियां हैं। राजकोषीय नीति केंद्र सरकार द्वारा तैयार और लागू की जाती है, जिसमें कराधान, सरकारी व्यय और सार्वजनिक ऋण शामिल हैं। दूसरी ओर, मौद्रिक नीति को देश का केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। नकद आरक्षित अनुपात और ब्याज दरों में परिवर्तन मौद्रिक नीति के उपकरण हैं, न कि राजकोषीय नीति के। इसलिए प्रथम और तृतीय कथन पूरी तरह सही हैं।

15. (D) वाणिज्यिक बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करना।
जब केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना चाहता है, तो वह खुला बाजार संचालन के तहत वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है। इस खरीद के बदले केंद्रीय बैंक बैंकिंग प्रणाली में नकद राशि का प्रवाह करता है। इससे वाणिज्यिक बैंकों के पास अतिरिक्त आरक्षित निधि उपलब्ध हो जाती है, जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता में सुधार होता है और ब्याज दरों में कमी आती है।

16. (C) जब अत्यधिक कुल मांग के कारण उच्च मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति हो।
संकुचनकारी राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अत्यधिक कुल मांग को कम करना होता है। जब अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक गतिविधियों और अत्यधिक उपभोग व्यय के कारण मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, तब यह नीति सबसे उपयुक्त होती है। इसके अंतर्गत सरकार अपने सार्वजनिक व्यय को घटाती है और करों की दरों में वृद्धि करती है। इससे नागरिकों की प्रयोज्य आय घटती है और मुद्रास्फीति शांत होती है।

17. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
नकद आरक्षित अनुपात वाणिज्यिक जमा राशि का वह अनिवार्य प्रतिशत है जिसे बैंकों को नकद रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। जब रिजर्व बैंक इस अनुपात में वृद्धि करता है, तो बैंकों को अपनी कुल जमा का एक बड़ा हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित रखना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप वाणिज्यिक बैंकों के पास आम जनता और व्यवसायों को ऋण देने के लिए उपलब्ध तरलता कम हो जाती है।

18. (D) निचले प्रत्यक्ष करों से प्रेरित उपभोक्ता व्यय में भारी वृद्धि।
मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग उनकी कुल आपूर्ति की तुलना में तेजी से बढ़ती है। जब सरकार प्रत्यक्ष करों में कटौती करती है, तो आम नागरिकों की प्रयोज्य आय बढ़ जाती है। इस अतिरिक्त आय के कारण उपभोक्ता व्यय में भारी उछाल आता है। यदि आपूर्ति तुरंत नहीं बढ़ पाती, तो अत्यधिक मांग के कारण सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होती है।

19. (A) एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का निर्माण।
सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत पूंजीगत व्यय वह खर्च है जो या तो नई भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण करता है या फिर सरकार की वित्तीय देनदारियों को कम करता है। नए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का निर्माण एक उत्पादक परिसंपत्ति बनाता है, जिससे भविष्य में देश की आर्थिक क्षमता बढ़ती है। इसके विपरीत कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और भवनों का रखरखाव नियमित राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं।

20. (B) केवल I और III
मौद्रिक नीति समिति छह सदस्यों वाली एक वैधानिक निकाय है। इसमें तीन सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक से होते हैं और तीन सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस

Click Here to Buy book on Amazon

समिति का प्राथमिक कार्य देश में मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतिगत ब्याज दर तय करना है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इस समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, न कि केंद्रीय वित्त मंत्री।

21. (A) यह वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास अधिशेष धनराशि रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
रिवर्स रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उनके अधिशेष धन को अपने पास जमा करने पर देता है। जब रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो दर में वृद्धि करता है, तो बैंकों को अपनी जोखिम-मुक्त पूंजी पर अधिक ब्याज मिलता है। इससे वाणिज्यिक बैंक आम जनता को ऋण देने के बजाय अपनी अतिरिक्त तरलता को रिजर्व बैंक के पास रखना अधिक पसंद करते हैं, जिससे मुद्रा आपूर्ति घटती है।

22. (A) P-2, Q-3, R-4, S-1
विभिन्न समष्टि आर्थिक परिदृश्यों से निपटने के लिए विशिष्ट नीतिगत साधनों की आवश्यकता होती है। उच्च बेरोजगारी और मंदी के समय सरकार सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर विस्तारवादी राजकोषीय नीति लागू करती है। अत्यधिक मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति के दौरान करों में वृद्धि करके संकुचनकारी राजकोषीय नीति अपनाई जाती है। आपूर्ति आघातों के मामले में इनपुट पर कर राहत दी जाती है, जबकि अपर्याप्त साख विस्तार के समाधान हेतु नीतिगत दरों में कटौती होती है।

23. (B) भारी सरकारी उधार ब्याज दरों को बढ़ाता है जबकि आरबीआई नीतिगत दरों को कम रखने का प्रयास करता है।
समष्टि आर्थिक स्थिरता के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों का परस्पर संरेखित होना आवश्यक है। जब सरकार अपने बड़े घाटे को पूरा करने के लिए वित्तीय बाजार से अत्यधिक उधार लेती है, तो ऋण योग्य कोष की मांग बढ़ जाती है, जिससे बाजार में ब्याज दरें ऊपर जाने लगती हैं। यह स्थिति केंद्रीय बैंक के उस प्रयास को विफल कर देती है जिसके तहत वह आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत दरों को कम रखना चाहता है।

24. (C) नियमों का पालन न करने वाले बैंकों पर आरबीआई द्वारा दंडात्मक कार्रवाई करना या ऋण सुविधाओं से इनकार करना।
मौद्रिक नीति के गुणात्मक या चयनात्मक उपकरणों में प्रत्यक्ष कार्रवाई एक कठोर उपाय है। जब कोई वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक के दिशा-निर्देशों, क्रेडिट कोटा या विनियामक मानकों का बार-बार उल्लंघन करता है, तो केंद्रीय बैंक उसके खिलाफ सीधी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। इस कार्रवाई में बैंक पर वित्तीय जुर्माना लगाना, उसे पुनर्वित्त सुविधाओं से वंचित करना या उसकी ऋण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।

25. (B) आरबीआई द्वारा रेपो दर में कटौती $\rightarrow$ बैंकों द्वारा कम ऋण दरें $\rightarrow$ निवेश और उपभोग में वृद्धि $\rightarrow$ उच्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि।
विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रभाव एक क्रमिक चरणबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से अर्थव्यवस्था में फैलता है। सबसे पहले केंद्रीय बैंक अपनी रेपो दर में कटौती करता है। इसके जवाब में वाणिज्यिक बैंक अपनी उधार दरों को कम करते हैं, जिससे ऋण सस्ता हो जाता है। सस्ती साख उपलब्ध होने से व्यवसायों द्वारा निवेश और उपभोक्ताओं द्वारा खर्च में वृद्धि होती है। अंततः इस बढ़ी हुई कुल मांग से सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में सुधार होता है।

26. (A) यह तब अत्यधिक मांग पैदा करता है जब इसे ऋण द्वारा वित्तपोषित किया जाता है जो मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करता है।
जब सरकार का राजकोषीय घाटा लगातार उच्च बना रहता है, तो उसे पूरा करने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर बाजार से या केंद्रीय बैंक से उधार लेना पड़ता है। यदि इस घाटे को केंद्रीय बैंक के माध्यम से नई मुद्रा के सृजन से वित्तपोषित किया जाता है, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति तेजी से फैलती है। इससे लोगों के हाथों में अतिरिक्त क्रय शक्ति आती है, जो अत्यधिक मांग पैदा करके मुद्रास्फीति को बढ़ाती है।

27. (B) केवल I और III
मौद्रिक नीति के परिमाणात्मक उपकरण पूरी अर्थव्यवस्था में साख की कुल मात्रा और तरलता को समान रूप से प्रभावित करते हैं। खुला बाजार संचालन और वैधानिक तरलता अनुपात परिमाणात्मक उपकरणों के स्पष्ट उदाहरण हैं, क्योंकि ये बैंक आरक्षित निधि और बाजार में उपलब्ध नकद राशि को सीधे बदलते हैं। इसके विपरीत, मार्जिन आवश्यकताएं और नैतिक दबाव गुणात्मक या चयनात्मक उपकरण हैं, जो विशिष्ट क्षेत्रों में साख का उपयोग नियंत्रित करते हैं।

28. (B) प्रभार-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियां
वैधानिक तरलता अनुपात के तहत वाणिज्यिक बैंकों को अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों का एक निश्चित प्रतिशत तरल परिसंपत्तियों के रूप में बनाए रखना अनिवार्य होता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वीकृत तरल परिसंपत्तियों में नकद, सोना और प्रभार-मुक्त संप्रभु सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं। गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां या निजी कंपनियों के इक्विटी शेयर इस अनुपात को बनाए रखने के लिए पात्र नहीं माने जाते हैं।

29. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियों को सहारा देने के लिए केंद्रीय बैंक ने अत्यधिक तरलता और कम ब्याज दरों वाली उदार नीति अपनाई थी। हालांकि, महामारी के बाद जैसे ही आर्थिक गतिविधियां सामान्य हुईं, वैश्विक और घरेलू स्तर पर मुद्रास्फीति का दबाव तेजी से बढ़ा। मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को अंकुश में रखने और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक ने धीरे-धीरे उदारता को वापस लेते हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की।

NODIA

30. (C) संपार्श्विक के बाजार मूल्य और मंजूर की गई अधिकतम ऋण राशि के बीच का अंतर।
मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरणों के अंतर्गत मार्जिन आवश्यकता का तात्पर्य गिरवी रखी गई संपार्श्विक वस्तु के बाजार मूल्य और उस पर दिए जाने वाले अधिकतम ऋण के बीच के अंतर से है। उदाहरण के लिए, यदि 100 रुपये की परिसंपत्ति पर 80 रुपये का ऋण स्वीकृत होता है, तो 20 प्रतिशत का अंतर मार्जिन कहलाता है। केंद्रीय बैंक विशिष्ट क्षेत्रों में सट्टेबाजी या अत्यधिक साख प्रवाह को रोकने के लिए इस मार्जिन को बढ़ाता है।

31. (D) मध्यम आय वाले परिवारों के लिए प्रत्यक्ष कर दरों में वृद्धि।
विस्तारवादी राजकोषीय नीति का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था में कुल मांग, उपभोग और निवेश को बढ़ावा देना होता है। इसके लिए सरकार सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर व्यय बढ़ाती है, करों में कटौती करती है और सामाजिक कल्याण योजनाओं के जरिए नकद हस्तांतरण करती है। इसके विपरीत, प्रत्यक्ष कर दरों में वृद्धि करने से नागरिकों की प्रयोज्य आय कम हो जाती है, जिससे उपभोग घटता है। यह संकुचनकारी राजकोषीय नीति का हिस्सा है।

32. (C) यह उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करता है जो भविष्य की राष्ट्रीय आर्थिक क्षमता का विस्तार करती हैं।
दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत व्यय को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे सड़कें, पुल, कारखाने और बिजली परियोजनाएं जैसी उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। ये परिसंपत्तियां देश की अवसंरचना को मजबूत करती हैं, निजी निवेश को आकर्षित करती हैं और भविष्य की उत्पादन क्षमता का विस्तार करती हैं। इसके विपरीत, राजस्व व्यय केवल नियमित परिचालन खर्चों को पूरा करता है, जिससे नई परिसंपत्ति नहीं बनती।

33. (C) केवल I और III
लागत-जन्य मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जब उत्पादन प्रक्रिया में इनपुट लागत बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति प्रभावित होती है। उत्पादकता लाभ के बिना मजदूरी दरों में अत्यधिक वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों से कच्चे माल की कमी होना, दोनों ही उत्पादन लागत को सीधे बढ़ा देते हैं। दूसरी ओर, अप्रत्यक्ष करों में कटौती करने से वस्तुओं की खुदरा कीमतें कम होती हैं, जो मुद्रास्फीति घटाने में सहायक है।

34. (A) P-3, Q-4, R-2, S-1
समष्टि आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट नीतिगत साधनों का प्रयोग किया जाता है। मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करके तरलता घटाई जाती है। मंदी में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए घाटे की वित्तव्यवस्था का सहारा लिया जाता है। आपातकालीन ओवरनाइट तरलता के लिए सीमांत स्थायी सुविधा उपलब्ध है, जबकि पुनर्वितरण न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रगतिशील आयकर लागू किया जाता है।

35. (B) 2016
भारत में मौद्रिक नीति निर्माण को अधिक पारदर्शी और लक्ष्य-उन्मुख बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके तहत वर्ष 2016 में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यांकन ढांचे को वैधानिक रूप से अपनाया गया। इसी वर्ष छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का औपचारिक गठन किया गया, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति को एक निर्धारित सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए नीतिगत दरें तय करने का अधिकार मिला।

36. (C) एलएएफ के लिए एसएलआर कोटे से अधिक प्रतिभूतियों को गिरवी रखने की आवश्यकता होती है, जबकि एमएसएफ एक निर्धारित सीमा तक एसएलआर कोटे का उपयोग करने की अनुमति देता है।
तरलता समायोजन सुविधा और सीमांत स्थायी सुविधा दोनों ही केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों को अल्पकालिक धनराशि प्रदान करने के साधन हैं। मुख्य अंतर यह है कि सामान्य तरलता समायोजन सुविधा के तहत बैंकों को अपनी वैधानिक तरलता अनुपात सीमा से अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखनी पड़ती हैं। इसके विपरीत, सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत बैंक संकट के समय अपने एसएलआर कोटे में से भी एक निश्चित प्रतिशत तक प्रतिभूतियां गिरवी रख सकते हैं।

37. (A) सरकारी राजस्व व्यय में कमी करना।
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपायों को कार्यान्वयन प्राधिकारी के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है: राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय। सरकारी राजस्व व्यय में कमी करना एक राजकोषीय उपाय है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है। इसके विपरीत, रेपो दर में वृद्धि करना, खुला बाजार संचालन में बांड बेचना और नकद आरक्षित अनुपात बढ़ाना - ये तीनों मौद्रिक नीति के उपाय हैं, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निष्पादित किया जाता है।

38. (C) 2, 1, 3
यदि औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक निर्धारित सहनशीलता सीमा से बाहर रहती है, तो केंद्रीय बैंक को एक वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना होता है। सर्वप्रथम, केंद्रीय बैंक लक्ष्य हासिल न हो पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक औपचारिक रिपोर्ट तैयार करता है। इसके पश्चात, वह स्थिति को सुधारने हेतु उपचारात्मक कदमों का खाका तैयार करता है। अंत में, यह विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाती है।

39. (B) यह ब्याज दरें बढ़ाता है, जिससे उपभोग और निवेश में कमी आती है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि धीमी हो जाती है।
संकुचनकारी मौद्रिक नीति के तहत केंद्रीय बैंक नीतिगत ब्याज दरों में वृद्धि करता है और बाजार से तरलता को अवशोषित करता है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव यह होता है कि वाणिज्यिक बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है, जिससे वे आम जनता और कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए ऋण दरों में वृद्धि कर देते हैं। ऊंची ब्याज दरों के कारण उपभोक्ता खर्च और व्यावसायिक

Downloaded from www.pdf.tube

निवेश में गिरावट आती है, जिससे अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि दर धीमी हो जाती है।

40. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
जब सरकार का राजकोषीय घाटा अत्यधिक बढ़ जाता है, तो उसे पूरा करने के लिए सरकार को बाजार से भारी मात्रा में उधार लेना पड़ता है। सरकारी बांडों की इस अत्यधिक आपूर्ति से बांड प्रतिफल बढ़ जाता है और वित्तीय बाजार में ब्याज दरों पर दबाव पड़ता है। इस स्थिति में, मंदी होने के बावजूद केंद्रीय बैंक के लिए नीतिगत ब्याज दरों में कटौती करना कठिन हो जाता है, क्योंकि इससे मुद्रास्फीति का जोखिम बढ़ता है।

41. (D) सार्वजनिक सब्सिडी (सहायिकी) पर व्यय कम करना।
संकुचनकारी राजकोषीय नीति का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था में कुल मांग और मुद्रा प्रवाह को कम करना होता है। सरकार सार्वजनिक सब्सिडी या अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर किए जाने वाले व्यय में कटौती करके बाजार में उपलब्ध नकद तरलता को कम करती है। इससे नागरिकों की प्रयोज्य आय और उपभोग क्षमता घटती है, जिससे समग्र मांग में कमी आती है। करों में छूट देना विस्तारवादी राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है।

42. (B) केवल III
मौद्रिक नीति समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम चार बार, यानी प्रत्येक दो महीने में एक बार आयोजित की जाती हैं। ये बयान बाजार को भविष्य की आर्थिक दिशा का संकेत देते हैं। निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, जिसके लिए सभी सदस्यों की सर्वसम्मति होना आवश्यक नहीं है। यदि किसी निर्णय पर मत बराबर हो जाते हैं, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास निर्णायक मत देने का अधिकार होता है।

43. (B) वह खुले बाजार से सरकारी प्रतिभूतियां क्रय करेगा।
जब अर्थव्यवस्था गंभीर तरलता संकट और मंदी का सामना कर रही होती है, तो केंद्रीय बैंक बाजार में नकद प्रवाह बढ़ाने का प्रयास करता है। इसके लिए वह खुला बाजार संचालन के तहत वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करता है। प्रतिभूतियों को खरीदने के बदले केंद्रीय बैंक बैंकों को नकद भुगतान करता है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ती है और बैंकों की साख सृजन क्षमता में सुधार होता है।

44. (B) वे नए विधान की आवश्यकता के बिना मांग को शांत करने के लिए आर्थिक उछाल के दौरान कर देनदारियों को बढ़ाते हैं।
प्रगतिशील आयकर अर्थव्यवस्था में स्वतः स्थिरक के रूप में कार्य करते हैं। जब अर्थव्यवस्था में तेजी या आर्थिक उछाल आता है, तो लोगों की आय बढ़ती है। प्रगतिशील कर प्रणाली के कारण नागरिक स्वतः ही उच्च कर स्लैब में चले जाते हैं, जिससे उनकी कर देनदारी बढ़ जाती है। इसके लिए नए कानून की आवश्यकता नहीं होती। कर संग्रह बढ़ने से लोगों की अतिरिक्त प्रयोज्य आय कम हो जाती है, जिससे अत्यधिक मांग स्वतः नियंत्रित हो जाती है।

45. (A) P-1, Q-3, R-2, S-4
विभिन्न घाटे बजट की स्थिति को दर्शाते हैं। राजकोषीय घाटा उधार को छोड़कर कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर है। राजस्व घाटा कुल राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के अंतर को व्यक्त करता है। प्राथमिक घाटा निकालने के लिए राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाया जाता है। मौद्रीकृत घाटा राजकोषीय घाटे के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जिसे सरकार केंद्रीय बैंक से नई मुद्रा के जरिए उधार लेकर पूरा करती है।

NODIA

46. (C) आर्थिक वृद्धि का समर्थन करते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के तहत भारत में मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। इसके साथ ही, मौद्रिक नीति को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि वह देश की स्थायी और समावेशी आर्थिक वृद्धि का समर्थन कर सके। मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 4 प्रतिशत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो निवेश के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है।

47. (D) बैंक आरबीआई को सरकारी प्रतिभूतियां बेचते हैं और बाद में उन्हें एक निर्धारित कीमत पर पुनः खरीदने के लिए सहमत होते हैं।
रेपो लेन-देन एक पुनर्खरीद समझौते पर आधारित अल्पकालिक वित्तीय अनुबंध होता है। जब वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेना होता है, तो वे अपनी प्रभार-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों को रिजर्व बैंक को बेच देते हैं। इसके साथ ही वे एक निश्चित तिथि पर उन प्रतिभूतियों को पूर्व-निर्धारित दर पर वापस खरीदने का कानूनी अनुबंध करते हैं। यह प्रक्रिया बैंकों को सुरक्षित तरलता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

48. (D) I, II और III
सीमांत स्थायी सुविधा बैंकिंग प्रणाली के लिए तरलता आघातों से निपटने हेतु एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। यह सुविधा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए उपलब्ध है। इसके तहत बैंकों को यह विशेष छूट दी जाती है कि वे अपने वैधानिक तरलता अनुपात कोटे की सरकारी प्रतिभूतियों का उपयोग करके भी एक निर्धारित सीमा तक ओवरनाइट ऋण ले सकते हैं। इससे आपात स्थिति में नकद आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है।

49. (B) व्यक्तियों को उनकी भुगतान करने की क्षमता के आधार पर कर लगाकर समता को बढ़ावा देना।
सरकार द्वारा प्रतिगामी व्यवस्था के स्थान पर प्रगतिशील कराधान प्रणाली को अपनाने का मुख्य कारण सामाजिक और आर्थिक समता स्थापित करना है। यह सिद्धांत "भुगतान करने की क्षमता" पर आधारित है, जिसके अनुसार अधिक आय वाले व्यक्तियों पर उच्च दरों से कर लगाया जाता है, जबकि कम आय वाले वर्गों को राहत या छूट प्रदान की जाती है। इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग जन कल्याण में होता है, जिससे आय असमानता घटती है।

50. (B) सरकार व्यय बढ़ाती है/करों में कटौती करती है → कुल मांग में वृद्धि → उच्च उत्पादन और रोजगार → आर्थिक सुधार।
आर्थिक मंदी से उबरने के लिए विस्तारवादी राजकोषीय नीति एक व्यवस्थित क्रम में काम करती है। सर्वप्रथम सरकार बुनियादी ढांचे पर व्यय बढ़ाती है या करों में कटौती करती है। इससे नागरिकों और व्यवसायों के पास नकद राशि बढ़ती है, जिससे अर्थव्यवस्था में कुल मांग में सुधार होता है। बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उद्योग उत्पादन बढ़ाते हैं और नए रोजगार सृजित करते हैं, जिससे अंततः आर्थिक सुधार होता है।

51. (A) वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक।
भारत में समष्टि आर्थिक प्रबंधन दो अलग-अलग प्रमुख संस्थानों द्वारा किया जाता है। देश की राजकोषीय नीति तैयार करने और लागू करने का दायित्व केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के पास होता है, जो कराधान, सार्वजनिक व्यय और बजट प्रबंधन को नियंत्रित करता है। दूसरी ओर, देश की मौद्रिक नीति का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, जो मुद्रा आपूर्ति, साख नियंत्रण और ब्याज दरों का प्रबंधन करता है।

52. (C) केवल I, II और IV
तरलता समायोजन सुविधा को नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2000 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया था। यह सुविधा मुख्य रूप से रेपो और रिवर्स रेपो नीलामियों के माध्यम से संचालित होती है और बैंकों को उनकी दैनिक तरलता आवश्यकताओं के प्रबंधन में सहायता करती है। हालांकि, इसका उपयोग अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक या स्थायी तरलता डालने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि यह केवल अल्पकालिक असंतुलन दूर करता है।

53. (A) मौद्रिक स्थितियों को कड़ा करने के लिए रेपो दर में बढ़ोतरी की एक श्रृंखला।
भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्यांकन ढांचे के तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4 प्रतिशत है, जिसकी ऊपरी सीमा 6 प्रतिशत है। यदि मुद्रास्फीति लंबी अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत तक पहुंच जाती है, तो यह ऊपरी सीमा का उल्लंघन माना जाता है। इसे नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाएगा और रेपो दर में चरणबद्ध बढ़ोतरी करेगा, जिससे ऋण महंगे होंगे और बाजार में मांग घटेगी।

54. (D) बढ़े हुए सरकारी उधार से ब्याज दरें बढ़ती हैं, जिससे निजी निवेश घटता है।
निष्कासन प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब सरकार बड़े राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए वित्तीय बाजार से अत्यधिक मात्रा में धनराशि उधार लेती है। सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर उधार लेने से बाजार में उपलब्ध ऋण योग्य कोष की कमी हो जाती है, जिससे ब्याज दरों में वृद्धि होती है। ऊंची ब्याज दरों के कारण निजी क्षेत्र के लिए उधार लेना और निवेश करना अत्यधिक महंगा हो जाता है, जिससे निजी निवेश में गिरावट आती है।

55. (B) उत्पादकता में सुधार और बाधाओं को कम करने के लिए आपूर्ति-पक्ष की नीतियां।
लागत-जन्य मुद्रास्फीति का मुख्य कारण कच्चे माल की कमी, उच्च मजदूरी या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण उत्पादन लागत का बढ़ना है। इस स्थिति में केवल मौद्रिक सख्ती करने से मांग घट सकती है, लेकिन उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए, इसे नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी उपाय आपूर्ति-पक्ष की नीतियां हैं। इनके अंतर्गत अवसंरचना में सुधार, लॉजिस्टिक्स बाधाओं को दूर करना और उत्पादकता बढ़ाना शामिल है।

56. (C) अप्रत्यक्ष करों में तीव्र कमी जिसके परिणामस्वरुप वस्तुओं की खुदरा कीमतें कम होती हैं।
मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग उनकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है। निर्यात मांग में उछाल, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उपभोक्ता साख का विस्तार - ये सभी अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाते हैं। इसके विपरीत, अप्रत्यक्ष करों में कटौती करने से वस्तुओं की खुदरा कीमतें तुरंत घट जाती हैं, जिससे मूल्य स्तर में गिरावट आती है। अतः यह मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण नहीं है।

57. (D) ऋण वितरण को आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरुप बनाने के लिए बैंकों को अनौपचारिक सलाह जारी करना।
नैतिक दबाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मौद्रिक नीति का एक गुणात्मक साधन है। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता, बल्कि अनौपचारिक बैठकों और दिशा-निर्देशों के माध्यम से बैंकों को सलाह देता है। रिजर्व बैंक उनसे आग्रह करता है कि वे देश की समग्र मौद्रिक नीति प्राथमिकताओं, जैसे मुद्रास्फीति नियंत्रण या प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में साख आवंटन का पालन करें।

58. (A) ब्याज दरें बढ़ेंगी, जबकि मांग पर प्रभाव नीति की मजबूती/सापेक्ष शक्ति पर निर्भर करता है।
संकुचनकारी मौद्रिक नीति के तहत केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है, जबकि विस्तारवादी राजकोषीय नीति में सरकार सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर उधार लेती है, जिससे भी ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव पड़ता है। इस प्रकार, दोनों नीतियों के संयुक्त प्रभाव से बाजार में ब्याज दरें निश्चित रुप से बढ़ेंगी। हालांकि, कुल मांग पर अंतिम असर इस बात पर निर्भर करेगा कि राजकोषीय विस्तार का प्रभाव मौद्रिक सख्ती से अधिक है या नहीं।

59. (B) 25 आधार अंक
भारतीय रिजर्व बैंक के तरलता प्रबंधन ढांचे में नीतिगत ब्याज दरों के लिए एक निर्धारित गलियारा होता है। इस गलियारे की ऊपरी सीमा सीमांत स्थायी सुविधा दर द्वारा निर्धारित होती है, जबकि मध्य बिंदु रेपो दर होता है। सामान्य परिस्थितियों में, सीमांत स्थायी सुविधा दर को मानक रेपो दर से 25 आधार अंक यानी 0.25 प्रतिशत ऊपर बनाए रखा जाता है, ताकि बैंक आपात स्थिति में ही इस उच्च दर पर उधार लें।

Click Here to Buy book on Flipkart

60. (B) वाणिज्यिक बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात को घटाना।
घाटे की वित्तव्यवस्था सरकार द्वारा अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों को संदर्भित करती है। इसमें बांड जारी करके घरेलू बाजार से उधार लेना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से ऋण लेना और केंद्रीय बैंक से उधार लेकर नई मुद्रा छापना शामिल है। वाणिज्यिक बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात में कटौती करना भारतीय रिजर्व बैंक का एक मौद्रिक नीति कदम है, जो तरलता बढ़ाता है, परंतु यह घाटे की वित्तव्यवस्था की विधि नहीं है।

61. (A) राजस्व व्यय — राज्य सरकारों को दिए गए अनुदान।
सरकारी लेखांकन में व्यय को राजस्व और पूंजीगत श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। राजस्व व्यय से किसी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता और न ही देनदारियों में कमी आती है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान इसी राजस्व व्यय का हिस्सा हैं। बांध निर्माण जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूंजीगत व्यय हैं, जबकि वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान नियमित राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं।

62. (C) बैंक जनता को ऋण देने के बजाय आरबीआई के पास अधिशेष धनराशि रखना पसंद करेंगे।
रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अपनी अतिरिक्त तरलता जमा करने पर ब्याज देता है। जब रिजर्व बैंक इस दर को बढ़ाता है, तो बैंकों के लिए जोखिम मुक्त ब्याज आय अधिक आकर्षक हो जाती है। इसके परिणामस्वरुप, वाणिज्यिक बैंक आम जनता को ऋण देने की तुलना में अपने अधिशेष धन को रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखना अधिक पसंद करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में साख प्रवाह घटता है।

63. (C) प्रत्येक पांच वर्ष में
भारत में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यांकन ढांचे को वर्ष 2016 में वैधानिक रूप से लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति का लक्ष्य समीक्षा करके निर्धारित करती है। वर्तमान में यह लक्ष्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित 4 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जिसके साथ 2 प्रतिशत की ऊपरी और निचली सहनशीलता सीमाएं तय की गई हैं।

64. (C) वाणिज्यिक बैंक और प्राथमिक डीलर।
खुला बाजार संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निष्पादित किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण परिमाणात्मक मौद्रिक उपकरण है। इसके तहत केंद्रीय बैंक द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करता है। इस प्रक्रिया में केंद्रीय बैंक के साथ लेन-देन करने वाले प्राथमिक और पात्र प्रतिभागी वाणिज्यिक बैंक और पंजीकृत प्राथमिक डीलर होते हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से ही वित्तीय बाजार और बैंकिंग प्रणाली में तरलता को सीधे नियंत्रित किया जाता है।

65. (B) सरकारी व्यय को कम करना और कराधान (करों) को बढ़ाना।
अत्यधिक मुद्रास्फीति के समय अर्थव्यवस्था में कुल मांग को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। इसके लिए एक विवेकपूर्ण संकुचनकारी राजकोषीय नीति लागू की जाती है। इस नीति के दो मुख्य घटक हैं: पहला, सरकार अपने सार्वजनिक व्यय और सब्सिडी में कटौती करती है; और दूसरा, वह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की दरों में वृद्धि करती है। इससे नागरिकों की प्रयोज्य आय में कमी आती है, उपभोग व्यय घटता है और मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम होती है।

NODIA

66. (D) वित्तपोषण लागत बढ़ने से कॉर्पोरेट निवेश धीमा हो जाता है, जिससे रोजगार प्रभावित होता है।
जब केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर में निरंतर वृद्धि करता है, तो वाणिज्यिक बैंकों के लिए तरलता प्राप्त करना महंगा हो जाता है। बैंक इस बढ़ी हुई लागत का बोझ अपने ग्राहकों पर डालते हुए व्यावसायिक ऋणों की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देते हैं। वित्तपोषण लागत बढ़ने से कॉर्पोरेट घराने अपनी विस्तार योजनाओं और नए पूंजीगत निवेश को टाल देते हैं, जिसके परिणामस्वरुप नई भर्तियों में कमी आती है।

67. (A) पुनर्खरीद समझौता (रीपरचेज एग्रीमेंट)
मौद्रिक नीति शब्दावली में "रेपो" शब्द "पुनर्खरीद समझौता" यानी रीपरचेज एग्रीमेंट का संक्षिप्त रूप है। यह एक अल्पकालिक वित्तीय अनुबंध है जिसके तहत वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से नकद धनराशि उधार प्राप्त करने के लिए अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को बेचते हैं। इसके साथ ही, वे भविष्य की एक निश्चित तिथि पर उन प्रतिभूतियों को पूर्व-निर्धारित दर पर वापस खरीदने की कानूनी प्रतिबद्धता करते हैं। यह तरलता प्रबंधन का मुख्य साधन है।

68. (C) यह मार्जिन आवश्यकता को बढ़ा देगा, जिससे व्यापारियों को अधिक स्वयं की धनराशि का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
जब आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में सट्टेबाजी के कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो केंद्रीय बैंक चयनात्मक साख नियंत्रण के तहत मार्जिन आवश्यकताओं में वृद्धि कर देता है। मार्जिन बढ़ाने का अर्थ है कि व्यापारियों को बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी ओर से अधिक पूंजी लगानी होगी और कम ऋण स्वीकृत होगा। इससे सट्टेबाजों के लिए बैंकों के धन से वस्तुओं की जमाखोरी करना कठिन हो जाता है, जिससे कृत्रिम मांग पर रोक लगती है।

69. (A) नई मुद्रा जारी करके उच्च राजकोषीय घाटे का मौद्रीकरण करने से मुद्रा आपूर्ति का सीधे विस्तार होता है।
जब सरकार का राजकोषीय घाटा अत्यधिक बढ़ जाता है और इसे केंद्रीय बैंक से सीधे नई मुद्रा जारी कराकर यानी घाटे के मौद्रीकरण द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, तो अर्थव्यवस्था में आधार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। यह नई मुद्रा बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से गुणक प्रभाव उत्पन्न करती है, जिससे देश

की कुल व्यापक मुद्रा आपूर्ति का सीधा विस्तार होता है। यदि उत्पादन नहीं बढ़ता, तो यह स्थिति मुद्रास्फीति बढ़ाती है।

70. (D) केंद्रीय बैंक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करता है और ब्याज दरों में कटौती करता है।
केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति में "उदार" रुख का अर्थ यह होता है कि मौद्रिक प्राधिकारी अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि को प्राथमिकता दे रहा है। इस रुख के तहत केंद्रीय बैंक नीतिगत ब्याज दरों में कटौती करता है और बैंकिंग प्रणाली में प्रचुर तरलता उपलब्ध कराता है ताकि ऋण सस्ता हो सके। इससे निवेश और उपभोग गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। "उदारता की वापसी" का अर्थ इस ढील को समाप्त कर दरों को वापस सामान्य बनाना है।

71. (B) प्रगतिशील कराधान आमतौर पर एक विकासशील अर्थव्यवस्था में आय असमानता के अंतर को बढ़ाता है।
प्रगतिशील कराधान के तहत जैसे-जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है, कर की दर भी बढ़ती जाती है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य धनी वर्ग पर अधिक कर लगाकर और गरीबों को राहत देकर आय की असमानता को कम करना है, न कि असमानता को बढ़ाना। इसलिए यह कथन गलत है। आनुपातिक कराधान में सभी के लिए कर दर स्थिर रहती है, जबकि प्रतिगामी कराधान में कम आय वाले वर्ग पर अपनी आय का अधिक प्रतिशत देने का बोझ पड़ता है।

72. (C) यह मांग को समाविष्ट करता है, जिससे आउटपुट और रोजगार पर एक गुणक प्रभाव उत्पन्न होता है।
केन्सियन अर्थशास्त्र के अनुसार, गंभीर मंदी के दौरान निजी उपभोग और निवेश में भारी कमी आ जाती है। इस स्थिति में सरकार द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय में वृद्धि अर्थव्यवस्था में सीधी मांग का सृजन करती है। सरकारी खर्च से लोगों को रोजगार और आय मिलती है, जिसे वे पुनः बाजार में खर्च करते हैं। यह प्रक्रिया एक गुणक प्रभाव उत्पन्न करती है, जिससे कुल उत्पादन और रोजगार में सुधार होता है और मंदी दूर होती है।

73. (D) सरकार घाटे से वित्तपोषित राजकोषीय प्रोत्साहन लागू करती है जबकि आरबीआई मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए दरें बढ़ाता है।
राजकोषीय और मौद्रिक नीति में समन्वय की विफलता तब स्पष्ट होती है जब दोनों प्राधिकारी विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। यदि सरकार अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए घाटे से वित्तपोषित राजकोषीय प्रोत्साहन देती है, तो इससे नकद प्रवाह बढ़ता है। यदि उसी समय केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाता है, तो दोनों नीतियों के प्रभाव एक-दूसरे को बेअसर कर देते हैं, जिससे आर्थिक नीतियां अप्रभावी हो जाती हैं।

74. (A) निजी विनिर्माण फर्मों के कॉर्पोरेट बांड।
वैधानिक तरलता अनुपात के नियमों के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों को अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों का एक निर्धारित हिस्सा तरल और सुरक्षित परिसंपत्तियों के रूप में रखना होता है। इन स्वीकृत परिसंपत्तियों में बैंक के पास मौजूद नकद, बैंक द्वारा धारित सोना और प्रभार-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं। निजी विनिर्माण कंपनियों के कॉर्पोरेट बांड उच्च वित्तीय जोखिम वाले होते हैं, इसलिए इन्हें इस अनुपात के लिए पात्र नहीं माना जाता है।

75. (B) चार बार
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, देश की मौद्रिक नीति समिति के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यद्यपि व्यावहारिक रूप से यह समिति प्रत्येक दो महीने में यानी वर्ष में छह बार द्विमासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन करती है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनिवार्यता प्रतिवर्ष चार बैठकों की है, जिसमें देश की आर्थिक स्थिति और नीतिगत दरों की समीक्षा की जाती है।

76. (B) बैंक भंडार में कमी आती है, और मुद्रा आपूर्ति में संकुचन होता है।
जब भारतीय रिजर्व बैंक खुला बाजार संचालन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की भारी बिक्री करता है, तो वाणिज्यिक बैंक इन प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए अपने आरक्षित फंड का उपयोग करते हैं। इससे बैंकों के पास मौजूद नकद आरक्षित भंडार केंद्रीय बैंक में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे बैंकों के भंडार में कमी आती है। बैंकिंग प्रणाली में नकद भंडार घटने से बैंकों की साख सृजन क्षमता सीमित हो जाती है, जिससे व्यापक मुद्रा आपूर्ति में संकुचन होता है।

77. (A) लागत-जन्य मुद्रास्फीति (मुद्रास्फीतिजनित मंदी / स्टैगफ्लेशन)
जब किसी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन में तीव्र गिरावट, मंदी और बेरोजगारी बढ़ने के साथ-साथ सामान्य मूल्य स्तर में भी लगातार वृद्धि होती है, तो इस स्थिति को मुद्रास्फीतिजनित मंदी या स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। यह स्थिति आमतौर पर आपूर्ति-पक्ष के गंभीर आघातों या कच्चे माल की लागतों में भारी वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली लागत-जन्य मुद्रास्फीति से जुड़ी होती है। इसमें पारंपरिक नीतियों का प्रयोग करना अत्यंत जटिल हो जाता है।

78. (C) सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर
भारतीय रिजर्व बैंक के परिचालन ढांचे में भारित औसत कॉल मनी दर को नीतिगत गलियारे के भीतर बनाए रखा जाता है। इस तरलता समायोजन सुविधा गलियारे की ऊपरी सीमा सीमांत स्थायी सुविधा दर द्वारा निर्धारित की जाती है, जो आपातकालीन ओवरनाइट उधार दर है। वहीं इस गलियारे की निचली सीमा स्थायी जमा सुविधा दर द्वारा तय की जाती है, जिस पर बैंक बिना संपार्श्विक के अधिशेष धन जमा करते हैं। मध्य बिंदु रेपो दर होता है।

NODIA

79. (D) यह भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण करता है अथवा वित्तीय देनदारियों को कम करता है।
सरकारी बजट में पूंजीगत व्यय वह खर्च है जो देश के लिए दीर्घकालिक आर्थिक लाभ उत्पन्न करता है। इसकी परिभाषा के अनुसार, पूंजीगत व्यय या तो नई भौतिक परिसंपत्तियों जैसे सड़क, पुल, स्कूल और अस्पताल का निर्माण करता है, या फिर पूर्व में लिए गए सार्वजनिक ऋणों का भुगतान करके सरकार की वित्तीय देनदारियों को कम करता है। यह व्यय उत्पादक होता है और अर्थव्यवस्था की भविष्य की वृद्धि क्षमता को मजबूत करता है।

80. (C) साझा आर्थिक लक्ष्यों की ओर संरेखित समन्वित प्रति-चक्रीय राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां।
टिकाऊ और मुद्रास्फीति-रहित आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिए सबसे प्रभावी समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण समन्वित प्रति-चक्रीय राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों का संचालन है। इसके अंतर्गत मंदी के समय सरकार और केंद्रीय बैंक मिलकर मांग और निवेश को बढ़ावा देते हैं, जबकि आर्थिक उछाल या उच्च मुद्रास्फीति के समय दोनों निकाय मिलकर मांग को नियंत्रित करते हैं। यह परस्पर संरेखण अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव को कम करके स्थिरता प्रदान करता है।

Downloaded from www.pdf.tube

अध्याय 06

सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य

NODIA

1. आवश्यक वस्तुओं पर सरकारी सब्सिडी प्रदान करने का मूल आर्थिक आधार निम्नलिखित में से किस आर्थिक सिद्धांत द्वारा सबसे सटीक रूप से वर्णित किया गया है?
(A) बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के वितरकों के लाभ मार्जिन को अधिकतम करना
(B) संवेदनशील/वंचित वर्गों के लिए वहनीयता सुनिश्चित करने हेतु मेरिट वस्तुओं की कीमतें घटाकर बाजार की विफलताओं में सुधार करना
(C) आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आयातित आवश्यक वस्तुओं पर व्यापारिक बाधाएं लगाना
(D) कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों में निजी स्वामित्व को समाप्त करना

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत ग्रामीण और शहरी आबादी का कितना प्रतिशत कानूनी रूप से रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का पात्र है?
(A) ग्रामीण आबादी का 50 प्रतिशत और शहरी आबादी का 75 प्रतिशत
(B) ग्रामीण आबादी का 100 प्रतिशत और शहरी आबादी का 33 प्रतिशत
(C) ग्रामीण आबादी का 67 प्रतिशत और शहरी आबादी का 67 प्रतिशत
(D) ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत

3. भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के ढांचे के तहत, निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य केंद्र सरकार के बजाय पूर्णतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है?
(A) पात्र लाभार्थियों की पहचान करना और राशन कार्ड जारी करना
(B) न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खाद्यान्न की खरीद करना
(C) केंद्रीय गोदामों में परिचालन बफर स्टॉक का भंडारण और रखरखाव करना
(D) गरीबी के अनुमानों के आधार पर विभिन्न राज्यों को खाद्यान्न का आवंटन करना

4. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ONORC) योजना भारत में प्रवासी श्रमिकों को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बनाती है।
कारण (R): यह लाभार्थियों को एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश भर की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हक का खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

5. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) तंत्र मुख्य रूप से सरकारी सब्सिडी के वितरण में सुधार करने का लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त करता है?
(A) सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के आधार-संयोजित बैंक खातों में अंतरित करके
(B) डिजिटल सत्यापन के स्थान पर स्थानीय ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा भौतिक रूप से घर-घर जाकर परीक्षण करके
(C) क्षेत्रीय राज्य के गोदामों के भीतर आवश्यक वस्तुओं के भौतिक आवंटन और भंडारण क्षमता में वृद्धि करके
(D) कल्याणकारी सब्सिडी को पूरी तरह से समाप्त करके और केवल प्रतिस्पर्धी मुक्त बाजार तंत्र पर निर्भर रहकर

6. लक्षित सार्वजनिक वितरण कार्यक्रमों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प "अपवर्जन त्रुटि" को सबसे बेहतर परिभाषित करता है?
(A) गरीबी रेखा से ऊपर आय वाले परिवारों को रियायती खाद्यान्न प्रदान करना
(B) अनधिकृत लाभ के लिए उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न को खुले बाजार में व्यपवर्तित करना
(C) गैर-मौजूद या मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन कार्ड जारी करना
(D) पात्र निर्धन परिवारों को रियायती लाभों तक उनकी वैध पहुँच से वंचित करना

7. प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना मूल रूप से निम्नलिखित में से किस सब्सिडी के युक्तीकरण और लक्षित वितरण से संबंधित है?

(A) उर्वरक सब्सिडी
(B) पेट्रोलियम/एलपीजी ईंधन सब्सिडी
(C) खाद्यान्न सब्सिडी
(D) कृषि ऋण सब्सिडी

8. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह मुख्य रूप से यूरिया के बजाय फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर लागू होती है।
II. यह सब्सिडी की राशि को उर्वरक में मौजूद विशिष्ट पोषक तत्व की मात्रा से जोड़ती है।
III. इसका प्राथमिक उद्देश्य मृदा के स्वास्थ्य की परवाह किए बिना तत्काल फसल की पैदावार को अधिकतम करने के लिए उर्वरकों के असंतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

9. भारत के ई-कॉमर्स ढांचे के संदर्भ में, मार्किटप्लेस मॉडल और इन्वेंट्री-आधारित मॉडल के बीच मूलभूत अंतर क्या है?
(A) मार्किटप्लेस मॉडल में, प्लेटफॉर्म सभी सूचीबद्ध वस्तुओं का स्वामी होता है, जबकि इन्वेंट्री मॉडल में, यह ऑनलाइन पारिस्थितिकी तंत्र में केवल क्रेताओं और विक्रेताओं को जोड़ता है।
(B) मार्किटप्लेस मॉडल केवल B2B लेन-देन के लिए आरक्षित है, जबकि इन्वेंट्री-आधारित मॉडल केवल B2C उपभोक्ता बिक्री के लिए आरक्षित है।
(C) मार्किटप्लेस मॉडल को जीएसटी नियमों से पूरी तरह छूट प्राप्त है, जबकि इन्वेंट्री-आधारित मॉडल अनिवार्य टीसीएस (TCS) प्रावधानों के अधीन है।
(D) इन्वेंट्री मॉडल में, संस्था बेची जाने वाली वस्तुओं की स्वामी होती है, जबकि मार्किटप्लेस मॉडल क्रेताओं और विक्रेताओं के लिए एक आईटी प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

10. ई-कॉमर्स क्षेत्र के संबंध में भारत में प्रचलित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सटीक है?
(A) इन्वेंट्री-आधारित मॉडल में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।
(B) मार्किटप्लेस और इन्वेंट्री-आधारित दोनों मॉडलों में एफडीआई पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
(C) ई-कॉमर्स के मार्किटप्लेस मॉडल में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।
(D) मार्किटप्लेस मॉडल में एफडीआई सरकारी स्वीकृति मार्ग के तहत अधिकतम 49 प्रतिशत तक सीमित है।

11. निम्नलिखित में से किसे भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों में ई-कॉमर्स के विकास के लिए एक प्रमुख लॉजिस्टिक चुनौती के रूप में व्यापक रूप से पहचाना जाता है?
(A) उच्च-गति इंटरनेट नेटवर्क की अत्यधिक संतृप्ति जिससे डेटा की बाधाएं उत्पन्न होती हैं
(B) सुदृढ़ अंतिम छोर तक पहुँच अवसंरचना और मानकीकृत डाक मैपिंग का अभाव
(C) महानगरों के बाहर ई-कॉमर्स उत्पादों के लिए उपभोक्ता मांग का पूर्णतः अभाव
(D) अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ई-कॉमर्स वितरण पर कड़े सरकारी प्रतिबंध

12. उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के लिए एक पर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना अनिवार्य बनाते हैं।
II. वे ई-कॉमर्स संस्थाओं को अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तुओं की कीमत में हेरफेर करने से रोकते हैं।
III. वे केवल घरेलू ई-कॉमर्स संस्थाओं पर लागू होते हैं और भारत में कार्य करने वाली विदेशी संस्थाओं को छूट देते हैं।
IV. विक्रेताओं को उनके द्वारा सूचीबद्ध उत्पादों के मूल देश को प्रदर्शित करना आवश्यक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

13. ई-कॉमर्स के लिए जीएसटी प्रावधानों के तहत, टीसीएस (TCS) का क्या अर्थ है?
(A) टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (स्रोत पर कर संग्रहण)
(B) ट्रांजैक्शन कॉस्ट सरचार्ज
(C) टैरिफ कंप्यूटेड सिस्टमैटिकली
(D) ट्रेड कॉमर्स सब्सिडी

14. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) राष्ट्रीय ई-कॉमर्स बाजार पर सरकारी स्वामित्व वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म का पूर्ण परिचालन एकाधिकार स्थापित करना
(B) ऑनलाइन उत्पाद मूल्य निर्धारण को सख्ती से विनियमित करना और सभी निजी ई-कॉमर्स पोर्टलों पर समान खुदरा मूल्य अनिवार्य करना
(C) प्लेटफॉर्म-केंद्रित मॉडल से ओपन-नेटवर्क मॉडल में स्थानांतरित होकर डिजिटल वाणिज्य का लोकतंत्रीकरण करना
(D) डिजिटल खुदरा पारिस्थितिकी तंत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की सक्रिय भागीदारी को प्रतिबंधित करना

Click Here to Buy book on Amazon

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs, you are wasting valuable time.

Research shows that learning from **PRINTED BOOKS** has up to **4× HIGHER RETENTION** than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS** move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND** in competition.

In competitive exams, being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

15. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के रूप में जाने जाने वाले वास्तविक समय (रियल-टाइम) भुगतान प्रणाली के संचालन के लिए कौन-सा संगठन अम्ब्रेला संस्था के रूप में कार्य करता है?
(A) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
(B) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)
(C) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI)
(D) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)

16. सूची I में दी गई सब्सिडी और तंत्रों के प्रकारों को सूची II में उनके संबंधित विवरणों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (सब्सिडी और तंत्र)
P. खाद्य सब्सिडी
Q. उर्वरक सब्सिडी
R. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
S. केरोसिन सब्सिडी
सूची II: (विवरण)
1. वैकल्पिक ईंधन की उपलब्धता के कारण ऐतिहासिक चरणबद्ध समाप्ति रणनीति से जुड़ी हुई
2. लाभार्थी के आधार-संयोजित बैंक खाते में सीधे नकद हस्तांतरण
3. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत प्रबंधित
4. NFSA के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समर्थन करने के लिए वित्तपोषित
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-4, Q-2, R-3, S-1
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

17. भारत सरकार द्वारा केरोसिन सब्सिडी को धीरे-धीरे समाप्त करने का ऐतिहासिक कदम मुख्य रूप से किस नीतिगत परिवर्तन से प्रेरित था?
(A) ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना को बढ़ावा देने की दिशा में देशव्यापी नीतिगत बदलाव
(B) स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी को बढ़ावा देने वाली उज्ज्वल योजना का शुभारंभ
(C) विशाल घरेलू कच्चे तेल के भंडारों की अप्रत्याशित खोज जिससे केरोसिन सब्सिडी पूरी तरह से अनावश्यक हो गई
(D) यह अनिवार्य करने का प्रशासनिक निर्णय कि केरोसिन का पूरा आयात केवल निजी कॉर्पोरेट संस्थाओं के माध्यम से किया जाए

18. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के क्षरण/रिसाव के संदर्भ में, "छद्म लाभार्थी" (गॉस्ट बेनिफिशियरी) शब्द का क्या अर्थ है?
(A) एक वैध परिवार जो अनाज की खराब गुणवत्ता के कारण अपना मासिक आवंटित राशन लेने से लगातार इनकार करता है
(B) एक पात्र निर्धन लाभार्थी जिसे केवल बायोमेट्रिक स्कैनर की विफलता के कारण आवश्यक खाद्यान्न से बार-बार वंचित किया जाता है
(C) एक पंजीकृत मध्यम आय वाला परिवार जो राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए स्वेच्छा से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है
(D) रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने और उसे व्यपवर्तित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक कल्पित या फर्जी पहचान

19. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक मूल्य स्थिरीकरण है। पीडीएस संवेदनशील/वंचित वर्गों के लिए इसे कैसे हासिल करता है?
(A) कम और समान केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं का वितरण करके
(B) खुदरा बाजार मूल्य पर खाद्यान्न खरीदकर और उपभोक्ता मुद्रास्फीति को कृत्रिम रूप से रोकने के लिए अधिशेष स्टॉक को नष्ट करके
(C) सभी निजी स्वतंत्र किराना दुकानों पर अनिवार्य अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) को सख्ती से तय और लागू करके
(D) भुनाने योग्य नकद वाउचर जारी करके जो केवल शहरी केंद्रों में उच्च स्तरीय विलासिता सुपरमार्केट श्रृंखलाओं में मान्य हैं

20. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आपूर्ति श्रृंखला के सही तार्किक क्रम का प्रतिनिधित्व करता है?
(A) FCI द्वारा भंडारण → किसानों से खरीद → FPS के माध्यम से वितरण → राज्यों को आवंटन
(B) राज्यों को आवंटन → किसानों से खरीद → FCI द्वारा भंडारण → FPS के माध्यम से वितरण
(C) किसानों से खरीद → FCI द्वारा भंडारण → राज्यों को आवंटन → FPS के माध्यम से वितरण
(D) किसानों से खरीद → FPS के माध्यम से वितरण → FCI द्वारा भंडारण → राज्यों को आवंटन

NODIA

21. भारतीय अर्थव्यवस्था में "सब्सिडी युक्तीकरण बहस" मुख्य रूप से किन दो परस्पर विरोधी कारकों को संतुलित करने के इर्द-गिर्द घूमती है?
(A) राजकोषीय कोष का बोझ बनाम संवेदनशील/वंचित वर्ग का कल्याण
(B) आक्रामक निर्यात प्रोत्साहन रणनीतियां बनाम व्यापक घरेलू आयात प्रतिस्थापन नीतियां
(C) तीव्र औद्योगिक स्वचालन बनाम शारीरिक श्रम पर पारंपरिक कृषि निर्भरता
(D) विकेंद्रीकृत राज्य सरकार की स्वायत्तता बनाम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विनियामक नियंत्रण

22. यद्यपि सब्सिडी में आधार-संयोजित लक्षित प्रणाली ने रिसाव को सफलतापूर्वक कम किया है, किंतु इसने निम्नलिखित में से किस विषय पर गंभीर चिंताएं भी पैदा की हैं?
(A) समावेशन त्रुटियां जहाँ धनवान व्यक्तियों को निःशुल्क

खाद्यान्न प्राप्त होता है
(B) ग्रामीण बैंकिंग अवसंरचना का पूर्ण रूप से ध्वस्त होना
(C) छोटे और सीमांत किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपभोग
(D) बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफलताओं या लिंक न होने से उत्पन्न अपवर्जन त्रुटियां

23. निम्नलिखित में से कौन-सा सुधार उपाय भारत में उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के आधुनिकीकरण के लिए सामान्यतः लागू नहीं किया जाता है?
(A) सभी खुदरा दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ePoS) उपकरणों की अनिवार्य स्थापना और तैनाती
(B) FPS विक्रेताओं को रियायती अनाज को स्वतंत्र रूप से निर्यात करने की अनुमति देना
(C) वितरण बिंदुओं पर लाभार्थियों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अंगुलिछाप और आईरिस प्रमाणीकरण लागू करना
(D) संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली का एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण और डिजिटल ट्रैकिंग

24. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): भारत सरकार ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री-आधारित मॉडल में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति नहीं देती है।
कारण (R): इस नीति का उद्देश्य घरेलू ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं और एमएसएमई (MSMEs) को अपनी स्वयं की इन्वेंट्री रखने वाली बड़ी बहुराष्ट्रीय संस्थाओं की हिंसक मूल्य निर्धारण नीति से बचाना है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

25. भारत में पारंपरिक खुदरा व्यापार (किराना दुकानों) पर ई-कॉमर्स के तीव्र विकास का एक प्रमुख विघटनकारी प्रभाव क्या माना जाता है?
(A) ऑनलाइन विज्ञापन के कारण भौतिक खुदरा दुकानों पर ग्राहकों की संख्या में अचानक वृद्धि
(B) एक वर्ष के भीतर असंगठित खुदरा क्षेत्र का पूर्ण उन्मूलन
(C) एक सरकारी जनादेश जो किराना दुकानों को पूरी तरह से इन्वेंट्री-आधारित मॉडल पर स्विच करने के लिए मजबूर करता है
(D) मूल्य निर्धारण, सुविधा और होम डिलीवरी की अपेक्षाओं के संबंध में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा

26. ई-कॉमर्स का विकास डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से गहन रूप से कैसे जुड़ा हुआ है?
(A) डिजिटल साक्षरता, कनेक्टिविटी और ऑनलाइन लेन-देन को बढ़ावा देकर
(B) डिजिटल इंडिया पहलों के तहत बढ़ावा दिए गए डिजिटल भुगतान ढांचे पर उपभोक्ता की निर्भरता को सक्रिय रूप से हतोत्साहित करके
(C) केवल समृद्ध शहरी अभिजात वर्ग तक ही उच्च-गति इंटरनेट पहुँच को सीमित करने पर ध्यान केंद्रित करके
(D) पारंपरिक ऑफलाइन डेटा केंद्रों की सुरक्षा के लिए ई-कॉमर्स गतिविधियों पर कानूनी रूप से पूर्ण प्रतिबंध लगाकर

27. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत, "प्राथमिकता वाले परिवार" श्रेणी के तहत वर्गीकृत व्यक्ति के लिए रियायती खाद्यान्न का कानूनी अधिकार क्या है?
(A) प्रति परिवार प्रति माह 35 किग्रा खाद्यान्न
(B) प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किग्रा खाद्यान्न
(C) प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किग्रा खाद्यान्न
(D) प्रति परिवार प्रति माह 15 किग्रा खाद्यान्न

28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में रिसाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उचित मूल्य की दुकान के स्वामियों द्वारा खुले बाजार में खाद्यान्न का व्यपवर्तन किया जाना रिसाव का एक सामान्य रूप है।
II. अपात्र संस्थाओं को फर्जी राशन कार्ड जारी करना पीडीएस रिसाव में योगदान देता है।
III. ePoS मशीनों की शुरुआत के बाद भारत में रिसाव पूरी तरह से समाप्त हो गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

29. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को ई-कॉमर्स द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसर का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) कम प्रवेश लागत पर भौगोलिक सीमाओं से परे बाजार तक पहुँच का विस्तार करना
(B) उनके वाणिज्यिक संचालन को स्थानीयकृत भौतिक पड़ोस के बाजारों तक सख्ती से सीमित करके
(C) छोटे उद्यमों को जीएसटी जैसे किसी भी घरेलू अप्रत्यक्ष कर के भुगतान से पूरी तरह छूट देकर
(D) पंजीकृत व्यावसायिक संस्थाओं को UPI जैसे डिजिटल भुगतान नेटवर्क अपनाने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित करके

30. ई-कॉमर्स क्षेत्र के सामने लगातार बनी रहने वाली चुनौतियों में से एक नकली सामानों की बिक्री है। उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के तहत, इस मुद्दे को संरचनात्मक रूप से कैसे संबोधित किया गया है?
(A) ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को नकली उत्पादों के संबंध में

Downloaded from www.pdf.tube

उपभोक्ता शिकायतों से पूर्ण छूट प्रदान करके
(B) नकली सामान प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को मुआवजा देने के लिए सरकार को बाध्य करके
(C) एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति को अनिवार्य बनाकर और स्पष्ट विक्रेता प्रकटीकरण मानदंड स्थापित करके
(D) डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी रिटर्न और रिफंड पर सख्ती से रोक लगाकर

31. वस्तु-रूप में सब्सिडी वितरण (जैसे PDS) से शुद्ध नकद हस्तांतरण (जैसे DBT) प्रणाली में स्थानांतरित होने का एक प्राथमिक नुकसान निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) नकद हस्तांतरण प्राप्तकर्ता परिवारों को अपनी व्यक्तिगत उपभोग वस्तुओं को चुनने में पूर्ण स्वविवेक की स्वतंत्रता प्रदान करता है
(B) नकद हस्तांतरण वेयरहाउसिंग की तुलना में भौतिक लॉजिस्टिक क्षरण और अनाज भंडारण के खराब होने के प्रति कहीं अधिक संवेदनशील है
(C) नकद हस्तांतरण के लिए राज्य अधिकारियों को विशाल केंद्रीकृत बफर स्टॉक गोदामों का लगातार निर्माण और रखरखाव करना पड़ता है
(D) प्राप्तकर्ताओं को मूल्य मुद्रास्फीति और बाजार की अस्थिरता के जोखिम में डालना

32. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा समर्थित एक पहल है।
II. इसके लिए क्रेताओं और विक्रेताओं को लेन-देन करने के लिए एक ही स्वामित्व वाले एप्लिकेशन का उपयोग करना आवश्यक है।
III. इसका उद्देश्य कुछ बड़े बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के वर्चस्व को कम करना है।
IV. यह कैटलॉगिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन और ऑर्डर पूर्ति जैसे संचालन को मानकीकृत करना चाहता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

33. भारतीय कृषि में अन्य उर्वरकों की तुलना में यूरिया का अत्यधिक उपयोग मुख्य रूप से किस सब्सिडी नीतिगत मुद्दे का परिणाम है?
(A) यूरिया को परिवर्तनशील मौसमी दरों पर लचीली पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के तहत पूरी तरह से कवर किया जाना
(B) यूरिया को NBS से बाहर रखना और इसके खुदरा मूल्य पर भारी सब्सिडी देना
(C) सभी फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों के वाणिज्यिक आयात पर पूर्ण सरकारी प्रतिबंध लागू करना
(D) आधार-संयोजित कृषि ऋण तक पहुंचने के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में केवल यूरिया के उपयोग को बाध्यकारी बनाना

34. उस प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना का क्या नाम है जिसने एलपीजी सब्सिडी को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान की?
(A) पीएम किसान सम्मान निधि योजना
(B) पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना
(C) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना
(D) पहल (PAHAL - प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ)

35. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में उत्तरदायित्वों के विभाजन के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए:
(A) राज्य सरकार – फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना
(B) केंद्र सरकार – कृषि मंडियों से खाद्यान्न की देशव्यापी खरीद
(C) केंद्र सरकार – खरीदे गए खाद्यान्न का परिचालन संबंधी केंद्रीय FCI डिपो तक थोक परिवहन
(D) राज्य सरकार – स्थानीय उचित मूल्य की दुकानों का विनियामक लाइसेंसिंग, प्रशासन और निरंतर पर्यवेक्षण

36. सूची I में दिए गए ई-कॉमर्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शब्दों को सूची II में उनके कार्यात्मक विवरणों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (शब्द)
P. मार्किटप्लेस मॉडल
Q. इन्वेंट्री मॉडल
R. UPI
S. ONDC
सूची II: (कार्यात्मक विवरण)
1. एक वास्तविक समय भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र जो डिजिटल लेन-देन की मात्रा को बढ़ाता है
2. विभिन्न डिजिटल वाणिज्य प्लेटफॉर्मों को आपस में संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक ओपन नेटवर्क
3. ई-कॉमर्स संस्था केवल क्रेता और विक्रेता के बीच एक मध्यस्थ/सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है
4. ई-कॉमर्स संस्था सामान की स्वामी होती है और उन्हें सीधे उपभोक्ताओं को बेचती है
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(A) P-4, Q-3, R-2, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

37. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का एक इच्छित उद्देश्य नहीं है?
(A) निजी कॉरपोरेट अनाज भंडारण एकाधिकार को बढ़ावा देना

NODIA

(B) समाज के आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों को व्यापक खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना
(C) आवश्यक कृषि वस्तुओं का दीर्घकालिक मूल्य स्थिरीकरण और बाजार विनियमन सुनिश्चित करना
(D) सभी राज्यों में सत्यापित कम आय वाले परिवारों को भारी सब्सिडी वाला मुख्य खाद्यान्न वितरित करना

38. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पारिस्थितिकी तंत्र के लेन-देन की मात्रा में भारी वृद्धि के लिए मुख्य रूप से इसकी किस विशेषता को उत्तरदायी माना जाता है?
(A) व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों पर लगातार लगाया जाने वाला उच्च लेन-देन प्रक्रमण शुल्क और सेवा अधिभार
(B) अनिवार्य कानूनी आवश्यकता कि उपयोगकर्ताओं को अपने लिंक किए गए खाते में 10,000 रुपये का न्यूनतम शेष रखना होगा
(C) सख्त विनियामक प्रतिबंध जो इसकी परिचालन उपयोगिता को केवल सीमा पार से प्रेषण तक सीमित करते हैं
(D) मोबाइल उपकरणों पर वास्तविक समय (24x7) अंतर-संचालनीय नि:शुल्क हस्तांतरण

39. उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के तहत, ई-कॉमर्स संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंड प्रदर्शित करना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन-सा इस आवश्यकता का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) तीसरे पक्ष के डिजिटल विज्ञापनदाताओं के साथ सभी उपयोगकर्ता ब्राउज़िंग इतिहास और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को खुले तौर पर साझा करना और उनसे कमाई करना
(B) विक्रेताओं, रिफंड और उत्पाद के मूल स्थान के बारे में स्पष्ट विवरण प्रदान करना
(C) नियामकों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के पूरे प्रोप्राइटरी सोर्स कोड और एल्गोरिदमिक आर्किटेक्चर का खुलासा करना
(D) प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत प्रत्येक उपभोक्ता के संपूर्ण टैक्स रिटर्न और वित्तीय फाइलिंग को प्रतिवर्ष प्रकाशित करना

40. उचित मूल्य की दुकान पर आधार-सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (AePDS) लेन-देन के निम्नलिखित चरणों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. लाभार्थी को भौतिक राशन सौंपना
II. ePoS उपकरण में राशन कार्ड या आधार संख्या दर्ज करना
III. PoS मशीन पर बायोमेट्रिक विवरण का प्रमाणीकरण
IV. केंद्रीय सर्वर से प्राप्त लाभार्थी के पात्रता डेटा का सत्यापन
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही अनुक्रम का चयन कीजिए:
(A) II, IV, III, I
(B) III, II, IV, I
(C) IV, II, I, III
(D) II, III, IV, I

41. आर्थिक सब्सिडी के संदर्भ में, "बाजार की विफलता" मुख्य रुप से तब होती है जब:
(A) किसी दिए गए वित्तीय तिमाही में प्रमुख शेयर बाजार सूचकांकों में तेज और निरंतर गिरावट आती है
(B) निजी कॉर्पोरेट उद्यम स्वेच्छा से खुदरा कीमतों को उनकी उत्पादन की वास्तविक लागत से काफी नीचे कम करते हैं
(C) उपभोक्ता सामूहिक रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आयातित गैर-आवश्यक विलासिता की वस्तुओं को खरीदने से इनकार करते हैं
(D) असमान आवंटन के कारण निर्धन लोगों के लिए आवश्यक वस्तुएं असवहनीय हो जाती हैं

42. भारत सरकार द्वारा पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के तहत निम्नलिखित में से किस कृषि इनपुट का प्रबंधन किया जाता है?
(A) फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक
(B) उच्च उपज देने वाली किस्म के प्रमाणित कृषि बीज
(C) अधिकृत चैनलों के माध्यम से वितरित नीम-लेपित यूरिया
(D) भारी कृषि मशीनरी, ट्रैक्टर और कृषि उपकरण

43. 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ONORC) योजना को विभिन्न राज्य सीमाओं के पार कार्य करने में सक्षम बनाने वाला मूलभूत तकनीकी कारक क्या है?
(A) केवल पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष अंतरराज्यीय प्रवासन वीजा और यात्रा परमिट जारी करना
(B) राशन कार्ड का आधार से जुड़ाव और दुकानों पर ePoS उपकरणों की तैनाती
(C) प्रत्येक लाभार्थी के गृह-राज्य के अनाज कोटे को सीधे उनके नए गंतव्य राज्य में भौतिक रुप से पहुंचाना
(D) प्रत्येक पंजीकृत राशन कार्ड धारक को उच्च स्तरीय इंटरनेट स्मार्टफोन का देशव्यापी मुफ्त वितरण

44. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रुप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए सब्सिडी का युक्तीकरण आवश्यक है।
कारण (R): अनियंत्रित सब्सिडी सरकार पर भारी राजकोषीय बोझ डालती है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है और पूंजीगत व्यय कम होता है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

Click Here to Buy book on Flipkart

45. भारत में ई-कॉमर्स मार्किटप्लेस मॉडल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर लगाया गया एक प्रमुख प्रतिबंध निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) प्लेटफॉर्म संस्थाएं बेची जाने वाली इन्वेंट्री की स्वामी या उस पर नियंत्रण नहीं रख सकती हैं
(B) मार्किटप्लेस संस्थाओं को क्रेताओं को एकीकृत डिजिटल भुगतान गेटवे प्रदान करने से सख्त मनाही है
(C) मार्किटप्लेस संस्थाओं को अपने परिचालन लॉजिस्टिक्स और विक्रेताओं के ऑनबोर्डिंग को केवल टियर-1 शहरों तक ही सीमित रखना होगा
(D) मार्किटप्लेस संस्थाओं को स्वतंत्र एमएसएमई विक्रेताओं को ऑनबोर्ड या पंजीकृत करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है

46. डेटा गोपनीयता को ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उद्धृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन-सा परिदृश्य इस चुनौती का सबसे अच्छा उदाहरण है?
(A) ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों का शिपमेंट के लिए पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग सामग्री पर स्थानांतरित होना
(B) दूरदराज के क्षेत्रों में अपर्याप्त परिवहन कनेक्टिविटी के कारण पार्सल की अंतिम छोर तक पहुँच में अत्यधिक देरी होना
(C) उपयोगकर्ता ब्राउज़िंग और भुगतान डेटा का अनधिकृत मौद्रिक लाभ के लिए उपयोग करना
(D) स्वतंत्र विक्रेताओं द्वारा अपनी सभी सार्वजनिक उत्पाद कैटलॉग सूचियों में मूल देश को स्पष्ट रूप से दर्शाना

47. ई-कॉमर्स क्षेत्र पर लागू होने वाले जीएसटी प्रावधानों के तहत, स्रोत पर कर संग्रहण (TCS) एकत्र करने के लिए कौन उत्तरदायी है?
(A) अंतिम खुदरा उपभोक्ता जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामान खरीदता है
(B) प्लेटफॉर्म पर वाणिज्यिक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला व्यक्तिगत तृतीय-पक्ष विक्रेता
(C) ऑर्डर किए गए सामान का परिवहन करने वाला तृतीय-पक्ष लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी पार्टनर
(D) प्लेटफॉर्म आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने वाला ई-कॉमर्स ऑपरेटर

48. भारत में उचित मूल्य की दुकान (FPS) सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. ePoS मशीनों की शुरुआत का उद्देश्य फर्जी राशन कार्डों को समाप्त करना रहा है।
II. कंप्यूटरीकरण ने FCI डिपो से FPS तक खाद्यान्न की आवाजाही की ट्रैकिंग को बेहतर बनाया है।
III. FPS सुधार कॉर्पोरेट श्रृंखलाओं के लिए पीडीएस अधिकारों के पूर्ण निजीकरण की वकालत करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

49. स्मार्टफोन और इंटरनेट पहुँच में आई क्रांति ने मुख्य रूप से भारत में ई-कॉमर्स बाजार को कैसे प्रभावित किया है?
(A) इसने उपभोक्ताओं को वापस भौतिक खुदरा दुकानों की ओर भेजकर कुल ई-कॉमर्स बाजार को काफी हद तक कम कर दिया है
(B) इसने ग्रामीण उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन खुदरा से जोड़कर बाजार पहुँच का विस्तार किया
(C) इसने डिजिटल शॉपिंग गतिविधियों को पूरी तरह से कॉर्पोरेट कार्यालयों में स्थित डेस्कटॉप कंप्यूटरों तक ही सीमित कर दिया है
(D) इसने ई-कॉमर्स कंपनियों को कानूनी रूप से केवल इन्वेंट्री-आधारित मॉडल के तहत काम करने के लिए मजबूर किया है

50. खाद्यान्न वितरण के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत परिवारों का कानूनी वर्गीकरण क्या है?
(A) केवल गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और गरीबी रेखा से ऊपर (APL) श्रेणियां
(B) मध्यम आय वर्ग (MIG) और उच्च आय वर्ग (HIG)
(C) भूमिधारक किसान और भूमिहीन मजदूर
(D) प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार

51. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली की शुरुआत ने कई कल्याणकारी योजनाओं की वितरण प्रणाली को मौलिक रूप से किस रूप में स्थानांतरित कर दिया?
(A) वस्तु-रूप/भौतिक वितरण से नकद हस्तांतरण में
(B) नकद हस्तांतरण से वस्तु-रूप वितरण में
(C) केंद्र सरकार के वित्तपोषण से स्थानीय पंचायत के वित्तपोषण में
(D) आधार-आधारित लक्षित प्रणाली से सार्वभौमिक अलक्षित वितरण में

52. डिजिटल इंडिया और ई-कॉमर्स के बीच संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. ई-कॉमर्स का विस्तार डिजिटल इंडिया के तहत स्थापित डिजिटल अवसंरचना, जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का लाभ उठाता है।
II. UPI जैसी डिजिटल इंडिया पहलों ने ई-कॉमर्स में भुगतान निपटान को मौलिक रूप से बदल दिया है।
III. ई-कॉमर्स का विकास डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों में सक्रिय रूप से बाधा डालता है।
IV. डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल साक्षरता अभियान ग्रामीण उपभोक्ताओं को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

Downloaded from www.pdf.tube

(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, II और IV
(D) केवल I, III और IV

53. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की लक्षित प्रक्रिया में 'समावेशन त्रुटि' का सीधा परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है?
(A) अपात्र परिवारों को लाभ प्राप्त होता है, जिससे राजकोषीय बोझ बढ़ता है
(B) लाभ से पूर्ण इनकार के कारण कई सत्यापित निर्धन और पात्र परिवारों को गंभीर भुखमरी का सामना करना पड़ता है
(C) राज्य सरकार सफलतापूर्वक आवंटित जन कल्याण कोष का एक बड़ा हिस्सा बचा लेती है
(D) जनता की मांग पूरी तरह न होने के कारण स्थानीय उचित मूल्य की दुकानें स्थायी रूप से बंद होने के लिए मजबूर हो जाती हैं

54. पीडीएस (PDS) रिसाव के संदर्भ में, "खाद्यान्न के व्यपवर्तन" का अर्थ है:
(A) पंजीकृत लाभार्थियों द्वारा अतिरिक्त नकदी के लिए अपने तैयार भोजन को सीधे पड़ोसी परिवारों को बेचना
(B) राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक कानूनी चैनलों के माध्यम से अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न स्टॉक को पुनः आवंटित करना
(C) कृषि किसानों द्वारा अपने प्राथमिक खेती के ध्यान को मुख्य खाद्यान्नों से हटाकर उच्च मूल्य वाली नकदी फसलों पर केंद्रित करना
(D) रियायती अनाज को खुले बाजार में कालाबाजारी के लिए चोरी/व्यपवर्तित करना

55. उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना किसानों के बीच निम्नलिखित में से किस अभ्यास को प्रोत्साहित करने के लिए शुरु की गई थी?
(A) कृषि खेतों पर यूरिया जैसे नाइट्रोजन युक्त रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक और अनन्य उपयोग
(B) मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग
(C) फसल उत्पादन में सभी सिंथेटिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को पूरी तरह से और तुरंत समाप्त करना
(D) पारंपरिक उर्वरकों के स्थान पर भारी सब्सिडी वाले रासायनिक कीटनाशकों का व्यापक प्रतिस्थापन

56. सूची I की पीडीएस लक्षित अवधारणाओं को सूची II की उनकी मानक परिभाषाओं के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अवधारणाएं)
P. समावेशन त्रुटि
Q. अपवर्जन त्रुटि
R. छद्म लाभार्थी
S. व्यपवर्तन

सूची II: (परिभाषाएं)
1. राशन हड़पने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फर्जी या डुप्लिकेट पहचान
2. निर्धन और पात्र परिवारों तक राशन न पहुंच पाना
3. अपात्र, संपन्न परिवारों द्वारा सफलतापूर्वक राशन कार्ड प्राप्त कर लेना
4. रियायती अनाज को खुले चोर बाजार/कालाबाजारी में भेजना

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(A) P-2, Q-3, R-4, S-1
(B) P-3, Q-2, R-4, S-1
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-1, Q-4, R-3, S-2

57. पीडीएस (PDS) के वित्तपोषण तंत्र में, "केंद्रीय निर्गम मूल्य" (CIP) क्या दर्शाता है?
(A) वह आधिकारिक खरीद मूल्य जिस पर भारतीय खाद्य निगम किसानों से मुख्य अनाज खरीदता है
(B) निजी वाणिज्यिक खुदरा श्रृंखलाओं द्वारा स्थापित खाद्यान्नों का प्रचलित बाजार खुदरा मूल्य
(C) अनाज के स्टॉक को ले जाने के लिए रेल और सड़क परिवहन ऑपरेटरों को दिया जाने वाला परिवहन और हैंडलिंग शुल्क
(D) खाद्यान्न आवंटन के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से लिया जाने वाला मूल्य

58. निम्नलिखित में से कौन-सा पिछले एक दशक में भारत में ई-कॉमर्स बाजार के आकार के विस्तार के कारक का सटीक प्रतिबिंब है?
(A) मोबाइल स्मार्टफोन स्वामित्व और सस्ते 4G डेटा में तेजी से वृद्धि
(B) ग्रामीण दूरसंचारीय घनत्व (टेली-डेन्सिटी) और नेटवर्क कवरेज में निरंतर गिरावट और संकुचन
(C) घरेलू डिजिटल भुगतान अनुप्रयोगों पर कड़े विनियामक प्रतिबंध लगाना
(D) सभी ऑफलाइन खुदरा प्रतिष्ठानों को तुरंत भौतिक रूप से बंद करने का आदेश देने वाले सरकारी निर्देश

NODIA

59. उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के तहत, शिकायत अधिकारी को किसी भी उपभोक्ता शिकायत की प्राप्ति की सूचना कितने समय के भीतर देनी होगी?
(A) 24 घंटे के भीतर
(B) 48 घंटे के भीतर
(C) 7 दिनों के भीतर
(D) 15 दिनों के भीतर

60. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुक्रम ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस मॉडल में एक उपभोक्ता के लिए सही मानक ऑर्डर पूर्ति प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है?
(A) चेकआउट और भुगतान → उत्पाद ब्राउज़िंग → ऑर्डर प्रेषण → विक्रेता पुष्टि → डिलीवरी

(B) उत्पाद ब्राउज़िंग → चेकआउट और भुगतान → विक्रेता पुष्टि → ऑर्डर प्रेषण → डिलीवरी
(C) विक्रेता पुष्टि → डिलीवरी → उत्पाद ब्राउज़िंग → चेकआउट और भुगतान → ऑर्डर प्रेषण
(D) उत्पाद ब्राउज़िंग → विक्रेता पुष्टि → डिलीवरी → चेकआउट और भुगतान → ऑर्डर प्रेषण

61. सरकारी सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने (कम करने या पुनर्गठित करने) के पक्ष में आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तर्क निम्नलिखित में से कौन-सा नहीं है?
(A) युक्तीकरण यह सुनिश्चित करता है कि निजी क्षेत्र आवश्यक वस्तुओं पर पूरी तरह से एकाधिकार कर ले।
(B) सब्सिडी अक्सर महत्वपूर्ण समावेशन और अपवर्जन संबंधी लक्षित त्रुटियों से ग्रस्त होती है।
(C) भारी सब्सिडी महत्वपूर्ण अवसंरचना और पूंजीगत व्यय से राजकोषीय संसाधनों को दूर करती है।
(D) मूल्य-विकृत करने वाली सब्सिडी से भूजल या मृदा की गुणवत्ता जैसे संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो सकता है।

62. विश्व के सबसे बड़े नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों में से एक, 'पहल' (PAHAL) योजना ने किसकी रियायती भौतिक आपूर्ति को प्रतिस्थापित किया?
(A) यूरिया उर्वरक
(B) गेहूं और चावल
(C) घरेलू एलपीजी सिलेंडर
(D) नलकूप के लिए बिजली

63. ईंधन सब्सिडी और एलपीजी जुड़ाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उज्ज्वल योजना ने गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की महिलाओं को जमा-मुक्त (डिपॉजिट-फ्री) एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए।
II. इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक खाना पकाने के ईंधनों के उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य खतरों का समाधान करना था।
III. इस योजना के तहत सरकार ने सभी नागरिकों के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत स्थायी रूप से 100 रुपये तय कर दी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

64. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) सब्सिडी वितरण श्रृंखला में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करता है।
कारण (R): DBT तंत्र सब्सिडी का मौद्रिक मूल्य सीधे लक्षित लाभार्थियों के आधार-संयोजित बैंक खातों में स्थानांतरित करता है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

65. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) और स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्मों (जैसे अमेज़ॅन या फ्लिपकार्ट) के बीच तुलना में, ONDC संरचनात्मक रूप से कैसे भिन्न है?
(A) ONDC एक एकल केंद्रीकृत अनिवार्य सरकारी एप्लिकेशन का निर्देश देता है जिसे सभी नागरिकों को ऑनलाइन खरीदारी के लिए उपयोग करना होगा
(B) एक ओपन नेटवर्क जो अंतर-एप्लिकेशन क्रेता-विक्रेता लेन-देन को सक्षम बनाता है
(C) ONDC विशेष रूप से विदेशी बहुराष्ट्रीय खुदरा निगमों को नेटवर्क पर उत्पादों को पंजीकृत करने और बेचने की अनुमति देता है
(D) ONDC पूरी तरह से सरकार द्वारा प्रत्यक्ष स्वामित्व, स्टॉक और संचालित एक इन्वेंट्री-आधारित मॉडल के रूप में कार्य करता है

66. UPI पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन करने वाले भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा किस संस्था के सहयोग से की गई थी?
(A) वित्त मंत्रालय
(B) नीति आयोग
(C) भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)
(D) भारतीय बैंक संघ (IBA)

67. पीडीएस पारिस्थितिकी तंत्र में उचित मूल्य की दुकान (FPS) विक्रेताओं की वित्तीय व्यवहार्यता अक्सर सुधार का विषय रही है। इन FPS विक्रेताओं की आय का प्राथमिक स्रोत क्या है?
(A) वितरित खाद्यान्न की मात्रा पर अर्जित कमीशन या मार्जिन
(B) केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक निश्चित मासिक वेतन
(C) बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए BPL लाभार्थियों से सीधे वसूला जाने वाला उच्च सुविधा शुल्क
(D) DBT तंत्र के माध्यम से उन्हें स्थानांतरित की जाने वाली कृषि सब्सिडी

68. भारत में खाद्य सब्सिडी के वित्तीय तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. खाद्य सब्सिडी बिल की गणना खाद्यान्न की आर्थिक लागत और केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) के बीच के अंतर के रूप में की जाती है।
II. आर्थिक लागत में खरीद लागत, खरीद प्रासंगिक व्यय और वितरण लागत शामिल हैं।

Click Here to Buy book on Amazon

III. राज्य सरकारें NFSA के तहत खाद्य सब्सिडी का पूरा वित्तीय बोझ उठाती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

69. ऐतिहासिक रूप से, सब्सिडी वाले केरोसिन का वितरण पीडीएस का एक प्रमुख घटक था। इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्राथमिक औचित्य क्या था?

(A) डीजल मिलावट में रिसाव और एलपीजी की विस्तारित उपलब्धता
(B) केरोसिन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक विषैला पाया गया और परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया
(C) पूरे देश में सभी घरेलू कच्चे तेल के भंडारों की पूर्ण और अपरिवर्तनीय समाप्ति
(D) उच्चतम न्यायालय का एक बाध्यकारी निर्णय जो ग्रामीण क्षेत्रों में तरल ईंधनों पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश देता है

70. उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के तहत एक विक्रेता के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा अनिवार्य प्रकटीकरण नहीं है?

(A) सभी अतिरिक्त शुल्कों के विस्तृत विवरण सहित सूचीबद्ध वस्तुओं का कुल खुदरा मूल्य
(B) वह विशिष्ट मूल देश जहाँ प्रस्तुत वाणिज्यिक उत्पाद का निर्माण किया गया था
(C) बिक्री के लिए पेश किए गए शीघ्र खराब होने वाले या उपभोग्य सामानों की समाप्ति तिथि और उपयोग की अवधि का विवरण
(D) पूर्व क्रेताओं का निजी पता

71. सब्सिडी वितरण तंत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. नकद हस्तांतरण लाभार्थियों को अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की लचीलापन प्रदान करता है।
II. वस्तु-रूप हस्तांतरण (जैसे PDS) गरीबों के लिए बढ़ती बाजार कीमतों के खिलाफ एक मुद्रास्फीति ढाल के रूप में कार्य करता है।
III. DBT तंत्रों को प्रभावी होने के लिए मजबूत बैंकिंग और डिजिटल अवसंरचना की आवश्यकता होती है।
IV. वस्तु-रूप वितरण सरकार के लिए सभी लॉजिस्टिक और भंडारण लागतों को समाप्त करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा गलत है?

(A) केवल I और II
(B) केवल IV
(C) केवल III और IV
(D) केवल I, II और III

72. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत, अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार प्रति माह कितने खाद्यान्न के हकदार हैं?

(A) 5 किग्रा प्रति परिवार
(B) 10 किग्रा प्रति व्यक्ति
(C) 35 किग्रा प्रति परिवार
(D) 50 किग्रा प्रति परिवार

73. उचित मूल्य की दुकानों (FPS) पर आधार का उपयोग करके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण मुख्य रूप से किस विशिष्ट समस्या को कम करने के लिए पेश किया गया था?

(A) ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी की लगातार विफलता के कारण होने वाली गंभीर अपवर्जन त्रुटियां
(B) असंगठित खुदरा बाजारों में नकली और निम्न गुणवत्ता वाले वाणिज्यिक सामानों का प्रसार
(C) केंद्रीय FCI गोदामों में भौतिक भंडारण क्षमता की भारी कमी
(D) पहचान धोखाधड़ी और छद्म लाभार्थियों के कारण होने वाला रिसाव

74. भारत की एफडीआई नीति के अनुपालन वाले ई-कॉमर्स मार्किटप्लेस मॉडल में वस्तुओं के स्वामित्व का सटीक वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा करता है?

(A) स्वतंत्र पंजीकृत विक्रेता सूचीबद्ध वस्तुओं के स्वामी होते हैं
(B) ई-कॉमर्स मार्किटप्लेस प्लेटफॉर्म संस्था स्वयं सभी सूचीबद्ध वस्तुओं का पूर्ण कानूनी स्वामित्व रखती है
(C) केंद्र सरकार के पास सभी माल/सामग्री में अनिवार्य 51 प्रतिशत बहुसंख्यक इक्विटी स्वामित्व हिस्सेदारी होती है
(D) अनुबंधित तृतीय-पक्ष लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी पार्टनर परिवहन के दौरान वस्तुओं का पूर्ण स्वामित्व ग्रहण करता है

75. जीएसटी ढांचे के तहत कर योग्य आपूर्तियों के शुद्ध मूल्य पर ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा एकत्र किए जाने वाले स्रोत पर कर संग्रहण (TCS) की निर्दिष्ट दर (CGST + SGST संयुक्त) क्या है?

(A) 0.5%
(B) 1.0%
(C) 5.0%
(D) 18.0%

NODIA

76. सूची I के विनियामक/नीतिगत ढांचों को सूची II के उनके संबंधित प्रमुख प्रावधानों के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची I: (ढांचे)

P. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
Q. ई-कॉमर्स में एफडीआई नीति
R. उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020
S. जीएसटी अधिनियम (ई-कॉमर्स प्रावधान)

सूची II: (प्रावधान)

1. प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों द्वारा टीसीएस (TCS) की कटौती को अनिवार्य बनाता है
2. मार्किटप्लेस संस्थाओं को इन्वेंट्री का स्वामित्व रखने से रोकता है
3. लगभग 67% आबादी के लिए रियायती खाद्यान्न का कानूनी अधिकार स्थापित करता है
4. शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य करता है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(A) P-2, Q-3, R-1, S-4
(B) P-3, Q-2, R-4, S-1
(C) P-4, Q-1, R-3, S-2
(D) P-3, Q-4, R-2, S-1

77. निम्नलिखित में से कौन-सा विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि उर्वरक सब्सिडी प्रदान करने का सबसे उपयुक्त आर्थिक औचित्य प्रदान करता है?
(A) उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इनपुट लागत कम करना
(B) कृषि वाणिज्यिक उपज से राज्य सरकारों के लिए अधिकतम अप्रत्यक्ष कर राजस्व उत्पन्न करना
(C) अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंचों पर कारोबार किए जाने वाले मुख्य खाद्यान्नों की निर्यात बाजार कीमतों को कृत्रिम रुप से बढ़ाना
(D) यह सुनिश्चित करना कि रासायनिक उर्वरक निर्माण करने वाले निगम एक स्थायी वैश्विक बाजार एकाधिकार स्थापित करें

78. ई-कॉमर्स क्षेत्र में बाजार के एकाधिकार पर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) का क्या संभावित प्रभाव पड़ने की उम्मीद है?
(A) यह संपूर्ण डिजिटल खुदरा बाजार हिस्सेदारी को तेजी से एक ही प्रभावशाली विदेशी कॉर्पोरेट संस्था में समेकित कर देगा
(B) यह ऑनलाइन स्टोरफ्रंट पर सभी वाणिज्यिक मूल्य निर्धारण पर एक सख्त, केंद्रीकृत सरकारी एकाधिकार स्थापित करेगा
(C) एकीकृत प्लेटफॉर्म एकाधिकार को तोड़ने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं का पृथक्करण करना
(D) यह सभी नए स्थापित प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को डिजिटल ई-कॉमर्स क्षेत्र में प्रवेश करने से कानूनी रुप से प्रतिबंधित करेगा

79. पीडीएस सुधार के संदर्भ में, 1997 में शुरु की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) और पिछली सार्वभौमिक पीडीएस के बीच मुख्य अंतर क्या है?
(A) TPDS ने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वभौमिक पहुँच बनाए रखते हुए केवल शहरी केंद्रों तक ही राशन वितरण को सीमित कर दिया
(B) TPDS ने लाभार्थियों को सीधे नकद हस्तांतरण के पक्ष में भौतिक अनाज वितरण तंत्र को पूरी तरह से छोड़ दिया
(C) TPDS ने खाद्य सब्सिडी का पूरा वित्तीय व्यय और प्रशासनिक बोझ राज्य सरकारों पर डाल दिया
(D) BPL और APL परिवारों के लिए विभेदित दरों/कीमतों और लाभों की शुरुआत करना

80. भारत के खुदरा और वितरण पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित तकनीकी और नीतिगत विकासों को उनके बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के सही ऐतिहासिक/कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पारिस्थितिकी तंत्र का शुभारंभ
II. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) का कार्यान्वयन
III. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) की शुरुआत
IV. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का पारित होना

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही अनुक्रम का चयन कीजिए:
(A) II, IV, I, III
(B) IV, II, III, I
(C) II, I, IV, III
(D) IV, I, II, III

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) संवेदनशील/वंचित वर्गों के लिए वहनीयता सुनिश्चित करने हेतु मेरिट वस्तुओं की कीमतें घटाकर बाजार की विफलताओं में सुधार करना
बाजार की विफलता तब उत्पन्न होती है जब मुक्त बाजार समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है। खाद्यान्न जैसी मेरिट वस्तुएं जन कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। सरकार इन पर सब्सिडी प्रदान करके बाजार की विफलता में सुधार करती है। सब्सिडी से मूल्य घटते हैं, जिससे निर्धन परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा और वहनीयता सुनिश्चित होती है।

2. (D) ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 भारत में कानूनी रूप से खाद्यान्न प्राप्त करने के अधिकारों का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के तहत देश की लगभग 67 प्रतिशत जनसंख्या को रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसके अंतर्गत ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत हिस्सा शामिल किया गया है। यह वर्गीकरण ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक विषमता दर्शाता है।

3. (A) पात्र लाभार्थियों की पहचान करना और राशन कार्ड जारी करना
सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक साझा उत्तरदायित्व वाली व्यवस्था है। केंद्र सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद, केंद्रीय गोदामों में भंडारण तथा राज्यों को खाद्यान्न का थोक आवंटन करती है। इसके विपरीत, पात्र लाभार्थियों की पहचान करना, राशन कार्ड जारी करना तथा उचित मूल्य की दुकानों का पर्यवेक्षण करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

4. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण सुधार है। यह योजना प्रौद्योगिकी पर आधारित है और देश के किसी भी हिस्से में रह रहे प्रवासी श्रमिकों को किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने कोटे का खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा देती है। इसके माध्यम से लाभार्थियों की भौगोलिक बाध्यता समाप्त होती है, जिससे उनका सशक्तिकरण होता है।

5. (A) सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के आधार-संयोजित बैंक खातों में अंतरित करके
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण तंत्र है। इस प्रणाली के तहत सरकारी सब्सिडी की राशि सीधे लक्षित लाभार्थियों के आधार-संयोजित बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। यह प्रक्रिया बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करती है, भौतिक खाद्यान्न के रिसाव को रोकती है तथा केवल वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक ही वित्तीय लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करती है।

6. (D) पात्र निर्धन परिवारों को रियायती लाभों तक उनकी वैध पहुँच से वंचित करना
लक्षित कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अपवर्जन त्रुटि तब होती है जब वास्तव में पात्र और निर्धन परिवारों को सब्सिडी या कल्याणकारी लाभ प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाता है। प्रशासनिक कमियों, गलत सर्वेक्षणों या बायोमेट्रिक सत्यापन विफलताओं के कारण ऐसा होता है। यह स्थिति सामाजिक सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता को कमजोर करती है और वास्तविक जरूरतमंदों को प्रभावित करती है।

NODIA

(B) पेट्रोलियम/एलपीजी ईंधन सब्सिडी
प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना मई 2016 में भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरु की गई थी। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। इसके माध्यम से स्वच्छ ईंधन सब्सिडी का लक्षित वितरण सुनिश्चित किया गया है ताकि महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हो सके।

8. (A) केवल I और II
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना अप्रैल 2010 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी। यह योजना मुख्य रूप से फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर लागू होती है, जबकि यूरिया इससे बाहर है। इस योजना में सब्सिडी की राशि विशिष्ट पोषक तत्वों की मात्रा से तय की जाती है ताकि मृदा स्वास्थ्य हेतु संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा मिले।

9. (D) इन्वेंट्री मॉडल में, संस्था बेची जाने वाली वस्तुओं की स्वामी होती है, जबकि मार्किटप्लेस मॉडल क्रेताओं और विक्रेताओं के लिए एक आईटी प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
भारत के ई-कॉमर्स ढांचे में मार्किटप्लेस और इन्वेंट्री-आधारित मॉडल के बीच स्पष्ट अंतर है। इन्वेंट्री-आधारित मॉडल में ई-कॉमर्स संस्था बेची जाने वाली सभी वस्तुओं का स्वामित्व रखती है, उनका भंडारण करती है और उन्हें सीधे उपभोक्ताओं को बेचती है। इसके विपरीत, मार्किटप्लेस मॉडल में ई-कॉमर्स संस्था केवल एक डिजिटल प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म प्रदान करती है जो स्वतंत्र क्रेताओं और विक्रेताओं को आपस में जोड़कर ऑनलाइन व्यापार की सुविधा देता है।

10. (C) ई-कॉमर्स के मार्किटप्लेस मॉडल में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।
भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार, ई-कॉमर्स क्षेत्र के मार्किटप्लेस मॉडल में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि, इन्वेंट्री-आधारित ई-कॉमर्स मॉडल में एफडीआई पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यह विनियामक ढांचा घरेलू छोटे व्यापारियों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बड़ी कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियों से संरक्षण देने के उद्देश्य से बनाया गया है।

11. (B) सुदृढ़ अंतिम छोर तक पहुँच अवसंरचना और मानकीकृत डाक मैपिंग का अभाव
भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों में ई-कॉमर्स के तीव्र विस्तार के समक्ष अंतिम छोर तक पहुँच अवसंरचना की कमी एक प्रमुख चुनौती है। इन अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मानकीकृत पतों, सटीक डाक मैपिंग तथा सुदृढ़ लॉजिस्टिक केंद्रों का अभाव पाया जाता है। इसके कारण उत्पादों की डिलीवरी में अत्यधिक समय लगता है और परिवहन लागत बढ़ जाती है, जिससे व्यापार की गति धीमी होती है।

12. (B) केवल I, II और IV
उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लागू किए गए हैं। इन नियमों के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना तथा शिकायत अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है। इसके साथ ही, प्लेटफॉर्मों को मूल्य हेरफेर करने से रोका गया है और विक्रेताओं के लिए उत्पादों के मूल देश को प्रदर्शित करना बाध्यकारी बनाया गया है।

13. (A) टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (स्रोत पर कर संग्रहण)
वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून के तहत ई-कॉमर्स क्षेत्र में TCS का पूर्ण अर्थ 'टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स' यानी 'स्रोत पर कर संग्रहण' है। जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, ई-कॉमर्स ऑपरेटर अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से विक्रेताओं द्वारा की गई कर योग्य आपूर्तियों के शुद्ध मूल्य पर निर्धारित दर से कर एकत्र करने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होते हैं। यह प्रक्रिया कर अनुपालन को सुदृढ़ बनाती है।

14. (C) प्लेटफॉर्म-केंद्रित मॉडल से ओपन-नेटवर्क मॉडल में स्थानांतरित होकर डिजिटल वाणिज्य का लोकतंत्रीकरण करना
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा शुरु की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल वाणिज्य को प्लेटफॉर्म-केंद्रित मॉडल से स्थानांतरित कर ओपन-नेटवर्क मॉडल में बदलना है। इसके माध्यम से छोटे विक्रेताओं तथा एमएसएमई को डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में समान अवसर मिलते हैं, जिससे डिजिटल खुदरा व्यापार का व्यापक लोकतंत्रीकरण होता है।

15. (D) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) भारत में वास्तविक समय में अंतर-बैंक धन हस्तांतरण को सक्षम करने वाली एक प्रमुख डिजिटल प्रणाली है। इस क्रांतिकारी भुगतान अवसंरचना का विकास, संचालन तथा प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा किया जाता है। एनपीसीआई देश में खुदरा भुगतान प्रणालियों के नियमन और संचालन के लिए स्थापित एक अम्ब्रेला संस्था है जो भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में कार्य करती है।

16. (C) P-4, Q-3, R-2, S-1
खाद्य सब्सिडी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन करने के लिए प्रदान की जाती है। उर्वरक सब्सिडी को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत प्रबंधित किया जाता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तंत्र के अंतर्गत सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित होती है। वहीं, केरोसिन सब्सिडी को वैकल्पिक स्वच्छ ईंधनों के प्रसार के कारण चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया गया है।

17. (B) स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी को बढ़ावा देने वाली उज्ज्वल योजना का शुभारंभ
भारत सरकार द्वारा केरोसिन सब्सिडी को धीरे-धीरे समाप्त करने का नीतिगत कदम मुख्य रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के क्रियान्वयन से प्रेरित था। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण और निर्धन परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी उपलब्ध कराया गया। एलपीजी के प्रसार से केरोसिन पर निर्भरता घटी और केरोसिन के वाणिज्यिक दुरुपयोग व मिलावट पर भी रोक लगी।

18. (D) रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने और उसे व्यपवर्तित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक कल्पित या फर्जी पहचान
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में "छद्म लाभार्थी" शब्द का तात्पर्य ऐसे फर्जी, गैर-मौजूद या मृत व्यक्तियों के नाम पर जारी राशन पहचान-पत्रों से है जिनका उपयोग अवैध रूप से रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसे कार्डों के माध्यम से खाद्यान्न को खुले बाजार में व्यपवर्तित कर दिया जाता है, जिससे वास्तविक निर्धन व्यक्ति सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

19. (A) कम और समान केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं का वितरण करके
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक प्रमुख उद्देश्य मूल्य स्थिरीकरण सुनिश्चित करना और कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किसानों से खाद्यान्न की खरीद करती है और उसे पूरे देश में रियायती तथा समान केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर राज्यों को आवंटित करती है। इससे खुले बाजार में खाद्यान्न कीमतों की अस्थिरता का प्रभाव निर्धन उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ता है।

Click Here to Buy book on Flipkart

20. (C) किसानों से खरीद → FCI द्वारा भंडारण → राज्यों को आवंटन → FPS के माध्यम से वितरण
भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला का एक निश्चित और तार्किक क्रम होता है। सर्वप्रथम, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खाद्यान्न की खरीद करती है। तत्पश्चात, भारतीय खाद्य निगम इन खाद्यान्नों का भंडारण करता है। इसके बाद, केंद्र सरकार राज्यों को खाद्यान्न आवंटित करती है और अंत में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण होता है।

21. (A) राजकोषीय कोष का बोझ बनाम संवेदनशील/वंचित वर्ग का कल्याण
भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी युक्तीकरण की बहस मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के संतुलन पर केंद्रित है। एक तरफ अनियंत्रित सब्सिडी से सरकारी खजाने पर भारी राजकोषीय बोझ पड़ता है तथा अवसंरचनात्मक पूंजीगत व्यय घटता है। दूसरी तरफ, सब्सिडी समाज के गरीब तथा संवेदनशील वर्गों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण, जीवन-यापन और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत अनिवार्य मानी जाती है।

22. (D) बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफलताओं या लिंक न होने से उत्पन्न अपवर्जन त्रुटियां
यद्यपि आधार-संयोजित प्रणाली ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फर्जी राशन कार्डों और रिसाव को कम करने में सफलता प्राप्त की है, किंतु इसने अपवर्जन त्रुटियों की गंभीर चिंता उत्पन्न की है। ग्रामीण क्षेत्रों में खराब नेटवर्क, तकनीकी कमियों या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की विफलताओं के कारण कई निर्धन और वास्तविक पात्र व्यक्ति अपने वैध कल्याणकारी अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, जो एक प्रमुख प्रशासनिक चुनौती है।

23. (B) FPS विक्रेताओं को रियायती अनाज को स्वतंत्र रूप से निर्यात करने की अनुमति देना
भारत में उचित मूल्य की दुकानों के आधुनिकीकरण और पारदर्शिता के लिए अनेक सुधार लागू किए गए हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों की तैनाती, लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण तथा खाद्यान्न परिवहन का एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण शामिल है। हालांकि, राशन दुकानदारों को रियायती अनाज को स्वतंत्र रूप से खुले बाजार में निर्यात करने की अनुमति देना सार्वजनिक वितरण नियमों का उल्लंघन है और यह स्वीकृत नहीं है।

24. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री-आधारित मॉडल में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। इस नीतिगत प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य बड़ी बहुराष्ट्रीय संस्थाओं को अपनी विशाल पूंजी के बल पर अनुचित छूट देने तथा हिंसक मूल्य निर्धारण से रोकना है। इससे देश के पारंपरिक offline खुदरा विक्रेताओं, छोटे व्यापारियों तथा एमएसएमई क्षेत्रों को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धी माहौल प्राप्त होता है।

25. (D) मूल्य निर्धारण, सुविधा और होम Delivery की अपेक्षाओं के संबंध में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा
भारत में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के तेजी से बढ़ते प्रसार ने पारंपरिक खुदरा क्षेत्र और किराना दुकानों के लिए महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियां उत्पन्न की हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा दी जाने वाली आकर्षक कीमतें, उत्पाद विविधता, डिजिटल भुगतान तथा होम डिलीवरी की सुविधाओं ने उपभोक्ता व्यवहार को बदला है। इससे पारंपरिक व्यापारियों को अपने व्यवसाय को बचाए रखने के लिए नवाचार और आधुनिकीकरण अपनाने पर मजबूर होना पड़ा है।

26. (A) डिजिटल साक्षरता, कनेक्टिविटी और ऑनलाइन लेन-देन को बढ़ावा देकर
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने भारत में ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में व्यापक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, डिजिटल साक्षरता तथा यूपीआई जैसे सुरक्षित डिजिटल भुगतान तंत्र का विकास हुआ है। इन पहलों ने दूरदराज क्षेत्रों के उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों से जुड़ने तथा ऑनलाइन लेन-देन करने में सक्षम बनाया है।

27. (B) प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किग्रा खाद्यान्न
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दो श्रेणियां बनाई गई हैं: अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार। इस अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के अनुसार, प्राथमिकता वाले परिवार श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न निर्धारित अत्यंत सब्सिडी वाली दरों पर प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्रदान किया गया है।

28. (A) केवल I और II
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में रिसाव की समस्या एक गंभीर प्रशासनिक चुनौती रही है। इसके मुख्य कारणों में राशन दुकानदारों द्वारा रियायती अनाज को खुले बाजार में बेचना तथा अपात्र व्यक्तियों को फर्जी राशन कार्ड जारी करना शामिल है। यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीनों ने रिसाव को काफी हद तक नियंत्रित किया है, किंतु यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है।

29. (A) कम प्रवेश लागत पर भौगोलिक सीमाओं से परे बाजार तक पहुँच का विस्तार करना
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों ने भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए विकास के अभूतपूर्व अवसर निर्मित किए हैं। पारंपरिक खुदरा व्यवस्था की तुलना में, डिजिटल व्यापार कम प्रवेश लागत परछोटे उद्यमों को अपनी स्थानीय भौगोलिक सीमाओं से परे राष्ट्रीय तथा वैश्विक बाजारों तक सीधी पहुँच प्रदान करता है। इससे एमएसएमई अपने उत्पादों का प्रभावी विपणन करके व्यापार का तेजी से विस्तार कर सकते हैं।

NODIA

30. (C) एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति को अनिवार्य बनाकर और स्पष्ट विक्रेता प्रकटीकरण मानदंड स्थापित करके
उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 डिजिटल प्लेटफार्मों पर नकली सामानों की बिक्री को रोकने के लिए कड़े संरचनात्मक प्रावधान करते हैं। इन नियमों के तहत प्रत्येक ई-कॉमर्स संस्था के लिए शिकायत अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य की गई है। इसके साथ ही विक्रेताओं के नाम, पते, संपर्क विवरण, उत्पाद के निर्माण देश तथा वापसी नीतियों का स्पष्ट प्रकटीकरण करना कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया गया है।

31. (D) प्राप्तकर्ताओं को मूल्य मुद्रास्फीति और बाजार की अस्थिरता के जोखिम में डालना
सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी व्यवस्था में भौतिक अनाज वितरण के स्थान पर नकद हस्तांतरण अपनाने की एक प्रमुख सीमा यह है कि यह लाभार्थियों को बाजार की मुद्रास्फीति और मूल्य अस्थिरता के जोखिम में डालता है। जब खाद्यान्न की बाजार कीमतें अत्यधिक बढ़ जाती हैं, तो सरकार द्वारा दी जाने वाली निश्चित नकद राशि की वास्तविक क्रय शक्ति घट जाती है, जिससे निर्धन परिवारों की खाद्य सुरक्षा संकट में पड़ सकती है।

32. (B) केवल I, III और IV
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा समर्थित पहल है। इसका उद्देश्य डिजिटल व्यापार में कुछ बड़ी कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करना है। यह कैटलॉगिंग और आर्डर पूर्ति प्रक्रियाओं का मानकीकरण करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए क्रेताओं और विक्रेताओं को किसी एक ही एकल स्वामित्व वाले एप्लिकेशन का उपयोग करने की बाध्यता नहीं है।

33. (B) यूरिया को NBS से बाहर रखना और इसके खुदरा मूल्य पर भारी सब्सिडी देना
भारतीय कृषि में यूरिया का अत्यधिक उपयोग एक प्रमुख नीतिगत विसंगति का परिणाम है। सरकार ने यूरिया को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना से बाहर रखा है और इसके मूल्य पर भारी सब्सिडी देकर इसे बहुत सस्ता बनाए रखा है। अन्य उर्वरकों की तुलना में अत्यधिक सस्ता होने के कारण किसान इसका असंतुलित और अत्यधिक प्रयोग करते हैं, जिससे मृदा प्रभावित होती है।

34. (D) पहल (PAHAL - प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ)
'पहल' योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐतिहासिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य एलपीजी सब्सिडी की राशि को सीधे उपभोक्ताओं के आधार-संयोजित बैंक खातों में स्थानांतरित करना है। इस पारदर्शी व्यवस्था ने बिचौलियों को समाप्त किया है और एलपीजी सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग तथा सब्सिडी के रिसाव पर प्रभावी रोक लगाई है।

35. (A) राज्य सरकार – फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना पूर्णतः केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर किया जाता है। राज्य सरकारें स्थानीय स्तर पर लाभार्थियों की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने तथा उचित मूल्य दुकानों के प्रशासन का कार्य संभालती हैं।

36. (C) P-3, Q-4, R-1, S-2
मार्किटप्लेस मॉडल में ई-कॉमर्स संस्था क्रेता और विक्रेता के बीच केवल एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। इन्वेंट्री मॉडल में ई-कॉमर्स संस्था बेचे जाने वाले सामानों का स्वामित्व रखती है। यूपीआई एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जो डिजिटल वित्तीय लेन-देन को गति प्रदान करती है। वहीं, ओएनडीसी विभिन्न डिजिटल वाणिज्य प्लेटफॉर्मों को आपस में जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया एक ओपन नेटवर्क है।

37. (A) निजी कॉर्पोरेट अनाज भंडारण एकाधिकार को बढ़ावा देना
सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में खाद्य सुरक्षा और सामाजिक कल्याण का एक प्रमुख साधन है। इसके प्राथमिक उद्देश्यों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करना, पोषण स्तर में सुधार करना तथा बाजार में आवश्यक कृषि वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता बनाए रखना शामिल है। निजी कॉर्पोरेट एकाधिकार को बढ़ावा देना इस सरकारी कल्याणकारी नीति का उद्देश्य कभी नहीं रहा है।

38. (D) मोबाइल उपकरणों पर वास्तविक समय (24x7) अंतर-संचालनीय नि:शुल्क हस्तांतरण
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के लेन-देन की मात्रा में अभूतपूर्व वृद्धि का मुख्य कारण इसकी तकनीकी सरलता और उपलब्धता है। यूपीआई स्मार्टफोनों के माध्यम से चौबीसों घंटे वास्तविक समय में अंतर-संचालनीय और नि:शुल्क धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। किसी भी समय तुरंत भुगतान करने की इस सहज प्रक्रिया ने व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं दोनों के बीच डिजिटल लेन-देन को अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया है।

39. (B) विक्रेताओं, रिफंड और उत्पाद के मूल स्थान के बारे में स्पष्ट विवरण प्रदान करना
उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 का मुख्य उद्देश्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों पर पारदर्शिता बढ़ाना और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है। इन नियमों के अनुसार, ई-कॉमर्स संस्थाओं को विक्रेताओं की पहचान, उनके संपर्क विवरण, उत्पादों के मूल निर्माण देश, वापसी एवं रिफंड संबंधी नीतियों तथा शिकायत निवारण तंत्र की स्पष्ट जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है ताकि उपभोक्ताओं को सही तथ्य मिल सकें।

NODIA

40. (A) II, IV, III, I
आधार-सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने की एक निर्धारित चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। सर्वप्रथम, उचित मूल्य दुकान पर लगे उपकरण में राशन कार्ड या आधार संख्या दर्ज की जाती है। इसके पश्चात केंद्रीय डेटाबेस से लाभार्थी की पात्रता का सत्यापन होता है। फिर लाभार्थी का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाता है और अंत में पात्र मात्रा में खाद्यान्न भौतिक रुप से सौंपा जाता है।

41. (D) असमान आवंटन के कारण निर्धन लोगों के लिए आवश्यक वस्तुएं असवहनीय हो जाती हैं
अर्थशास्त्र में बाजार की विफलता की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अनियंत्रित बाजार शक्तियां समाज में संसाधनों का कुशल और न्यायसंगत आवंटन करने में असमर्थ रहती हैं। जब आय की असमानता या अत्यधिक बाजार कीमतों के कारण निर्धन और कमजोर वर्ग आवश्यक वस्तुओं को खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं, तो सरकार सब्सिडी के माध्यम से हस्तक्षेप करके इन आवश्यक वस्तुओं की वहनीयता सुनिश्चित करती है।

42. (A) फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख कृषि नीति है। इस योजना के तहत केवल फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों को कवर किया जाता है, जबकि यूरिया इससे बाहर है। इस व्यवस्था में उर्वरकों में उपस्थित पोषक तत्वों जैसे फास्फोरस, पोटाश और सल्फर की मात्रा के आधार पर सब्सिडी की वार्षिक दरें निर्धारित की जाती हैं।

43. (B) राशन कार्ड का आधार से जुड़ाव और दुकानों पर ePoS उपकरणों की तैनाती
'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना को अंतरराज्यीय स्तर पर सक्षम बनाने वाला प्राथमिक तकनीकी स्तंभ राशन कार्डों का आधार संख्या से संयोजन है। इसके साथ ही देश भर की उचित मूल्य दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीनों की तैनाती की गई है। यह डिजिटल नेटवर्क बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को देश में कहीं भी अपने हिस्से का खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा देता है।

44. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक स्थिरता और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए सब्सिडी का युक्तीकरण अत्यंत आवश्यक है। अनियंत्रित सब्सिडी सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ डालती है जिससे राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता है। इसके परिणामस्वरुप बुनियादी अवसंरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे दूरगामी विकास वाले क्षेत्रों में किया जाने वाला पूंजीगत व्यय सीमित हो जाता है, जिससे समग्र आर्थिक प्रगति बाधित हो सकती है।

45. (A) प्लेटफॉर्म संस्थाएं बेची जाने वाली इन्वेंट्री की स्वामी या उस पर नियंत्रण नहीं रख सकती हैं
भारत की ई-कॉमर्स प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत मार्किटप्लेस मॉडल के लिए एक प्रमुख शर्त निर्धारित है। इसके अनुसार, डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनी बेचे जाने वाले सामान या इन्वेंट्री का स्वामित्व नहीं रख सकती और न ही उस पर नियंत्रण कर सकती है। यह नियम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और स्वतंत्र विक्रेताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है।

46. (C) उपयोगकर्ता ब्राउज़िंग और भुगतान डेटा का अनधिकृत मौद्रिक लाभ के लिए उपयोग करना
ई-कॉमर्स क्षेत्र में डेटा गोपनीयता एक अत्यंत संवेदनशील और प्रमुख चुनौती बनकर उभरी है। इसका स्पष्ट उदाहरण तब देखने को मिलता है जब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत खोज इतिहास, खरीदारी प्राथमिकताओं तथा वित्तीय लेन-देन डेटा का उपयोग बिना उनकी पूर्व अनुमति के व्यावसायिक मौद्रिक लाभ या लक्षित विज्ञापनों के लिए करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के निजता अधिकार का गंभीर उल्लंघन होता है।

47. (D) प्लेटफॉर्म आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने वाला ई-कॉमर्स ऑपरेटर
वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून के प्रावधानों के अनुसार, ई-कॉमर्स लेन-देन में स्रोत पर कर संग्रहण (TCS) एकत्र करने का कानूनी दायित्व ई-कॉमर्स ऑपरेटर पर होता है। जब भी कोई स्वतंत्र विक्रेता प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामान बेचता है, तो ऑपरेटर शुद्ध आपूर्ति मूल्य पर निश्चित दर से कर काटकर उसे सरकारी खजाने में जमा कराने के लिए उत्तरदायी होता है।

48. (A) केवल I और II
भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुधारों के तहत उचित मूल्य दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीनों की तैनाती की गई है, जिससे फर्जी राशन कार्ड समाप्त हुए हैं। संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के डिजिटलीकरण ने केंद्रीय गोदामों से राशन दुकानों तक खाद्यान्न की आवाजाही की निगरानी को सुदृढ़ किया है। ये तकनीकी सुधार पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हैं, न कि निजीकरण करने के लिए।

49. (B) इसने ग्रामीण उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन खुदरा से जोड़कर बाजार पहुँच का विस्तार किया
किफायती स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट डेटा के व्यापक प्रसार ने भारत में ई-कॉमर्स बाजार का अभूतपूर्व विस्तार किया है। इस डिजिटल क्रांति ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के करोड़ों नए उपभोक्ताओं को ऑनलाइन खुदरा प्लेटफॉर्मों से सीधे जोड़ दिया है। इसके परिणामस्वरुप, ई-कॉमर्स का भौगोलिक आधार बढ़ा है और दूरदराज के क्षेत्रों में भी विविध उत्पादों की पहुँच अत्यंत सुलभ हो गई है।

Downloaded from www.pdf.tube

50. (D) प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत कानूनी रूप से खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु परिवारों को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी 'अंत्योदय अन्न योजना' (AAY) है जो समाज के सबसे निर्धन परिवारों को आच्छादित करती है। द्वितीय श्रेणी 'प्राथमिकता वाले परिवार' (PHH) है। इस अधिनियम ने पूर्ववर्ती वर्गीकरण व्यवस्था को प्रतिस्थापित करके लक्षित वितरण तंत्र को अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाया है।

51. (A) वस्तु-रूप/भौतिक वितरण से नकद हस्तांतरण में
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली की शुरुआत ने भारत में कल्याणकारी योजनाओं के वितरण ढांचे में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इस प्रणाली ने भौतिक वस्तु वितरण की पारंपरिक व्यवस्था को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण मॉडल में स्थानांतरित कर दिया। इस सुधार ने वितरण प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका समाप्त की और सब्सिडी के रिसाव को रोककर पारदर्शिता सुनिश्चित की।

52. (C) केवल I, II और IV
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने देश में ई-कॉमर्स क्षेत्र के विकास के लिए एक मजबूत तकनीकी अवसंरचना का निर्माण किया है। इस कार्यक्रम के तहत विस्तारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, यूपीआई जैसी सुगम भुगतान प्रणालियों तथा डिजिटल साक्षरता अभियानों ने ऑनलाइन लेन-देन को अत्यंत सरल बनाया है। इन सुधारात्मक पहलों ने ग्रामीण नागरिकों को भी डिजिटल वाणिज्य से जोड़कर ई-कॉमर्स बाजार का व्यापक विस्तार किया है।

53. (A) अपात्र परिवारों को लाभ प्राप्त होता है, जिससे राजकोषीय बोझ बढ़ता है
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लक्षित प्रक्रिया में समावेशन त्रुटि तब होती है जब आर्थिक रूप से संपन्न और अपात्र परिवार त्रुटिवश अथवा फर्जी तरीकों से लाभार्थी सूची में शामिल हो जाते हैं। इसका सीधा प्रतिकूल परिणाम यह होता है कि सरकार पर अनावश्यक खाद्य सब्सिडी का वित्तीय भार बढ़ जाता है। इससे सीमित राजकोषीय संसाधनों का अपव्यय होता है और वास्तविक निर्धन वर्ग के लिए बजटीय आवंटन प्रभावित हो सकता है।

54. (D) रियायती अनाज को खुले बाजार में कालाबाजारी के लिए चोरी/व्यपवर्तित करना
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न के व्यपवर्तन से तात्पर्य उस अवैध गतिविधि से है जिसमें पात्र गरीबों के लिए निर्धारित रियायती खाद्यान्न को आपूर्ति श्रृंखला के दौरान चुरा लिया जाता है। बिचौलिए या राशन विक्रेता इस रियायती अनाज को अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से खुले बाजार में कालाबाजारी हेतु बेच देते हैं, जिससे लक्षित कल्याणकारी योजना का मूल उद्देश्य बुरी तरह प्रभावित होता है।

55. (B) मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय कृषि में रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है। यूरिया के अत्यधिक प्रयोग से मृदा में पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ रहा था। इस योजना के माध्यम से फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों का उचित मूल्य पर प्रावधान करके किसानों को नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश का संतुलित प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाता है।

56. (C) P-3, Q-2, R-1, S-4
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में समावेशन त्रुटि का अर्थ अपात्र संपन्न परिवारों का योजना में शामिल होना है। अपवर्जन त्रुटि में वास्तविक निर्धन पात्र लोग राशन लाभ से वंचित रह जाते हैं। छद्म लाभार्थी का संबंध फर्जी या डुप्लिकेट पहचान से अवैध राशन प्राप्त करने की गतिविधि से है। वहीं, खाद्यान्न का व्यपवर्तन रियायती अनाज को खुले चोर बाजार में अवैध रूप से बेचना है।

57. (D) खाद्यान्न आवंटन के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से लिया जाने वाला मूल्य
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत "केंद्रीय निर्गम मूल्य" वह दर है जिस पर केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को खाद्यान्न का आवंटन करती है। यह मूल्य खाद्यान्न की खरीद और भंडारण की आर्थिक लागत से काफी कम रखा जाता है। इस आर्थिक लागत और निर्गम मूल्य के अंतर को ही केंद्र सरकार खाद्य सब्सिडी के रूप में वहन करती है।

58. (A) मोबाइल स्मार्टफोन स्वामित्व और सस्ते 4G डेटा में तेजी से वृद्धि
पिछले दशक में भारत में ई-कॉमर्स बाजार के अभूतपूर्व विस्तार का सबसे बड़ा कारक किफायती स्मार्टफोन की उपलब्धता तथा सस्ते इंटरनेट डेटा का प्रसार रहा है। इस डिजिटल क्रांति ने टियर-2 और टियर-3 शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के करोड़ों उपभोक्ताओं को ऑनलाइन खुदरा बाजार से जोड़ा है। इसके साथ ही सुलभ यूपीआई भुगतान प्रणालियों ने डिजिटल व्यापार को और अधिक गति प्रदान की है।

59. (B) 48 घंटे के भीतर
उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में उपभोक्ताओं के हित संवर्धन हेतु समयबद्ध शिकायत निवारण प्रक्रिया तय की गई है। इन प्रावधानों के अनुसार, ई-कॉमर्स संस्था द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह किसी भी उपभोक्ता शिकायत की प्राप्ति की औपचारिक पावती 48 घंटे के भीतर प्रदान करे। इसके पश्चात शिकायत का अंतिम समाधान एक माह की सीमा में करना आवश्यक होता है।

NODIA

60. (B) उत्पाद ब्राउज़िंग → चेकआउट और भुगतान → विक्रेता पुष्टि → ऑर्डर प्रेषण → डिलीवरी
ई-कॉमर्स मार्किटप्लेस मॉडल में ऑनलाइन खरीदारी और ऑर्डर पूर्ति का एक निश्चित तार्किक अनुक्रम होता है। सर्वप्रथम,

उपभोक्ता डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उत्पादों की ब्राउज़िंग करता है। इसके पश्चात वह चेकआउट करके भुगतान प्रक्रिया पूरी करता है। भुगतान के बाद विक्रेता द्वारा ऑर्डर की पुष्टि की जाती है, जिसके उपरांत उत्पाद का प्रेषण किया जाता है और अंततः अंतिम डिलीवरी संपन्न होती है।

61. (A) युक्तीकरण यह सुनिश्चित करता है कि निजी क्षेत्र आवश्यक वस्तुओं पर पूरी तरह से एकाधिकार कर ले।
सरकारी सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने के पक्ष में आर्थिक तर्क दिए जाते हैं कि इससे अवांछित राजकोषीय बोझ कम होता है, लक्षित त्रुटियों में सुधार आता है तथा संसाधनों का विवेकहीन दोहन रुकता है। हालांकि, आवश्यक वस्तुओं के बाजार में निजी क्षेत्र का पूर्ण एकाधिकार स्थापित करना सब्सिडी सुधारों का आर्थिक औचित्य नहीं होता, क्योंकि सरकार का प्राथमिक लक्ष्य जन कल्याण और निष्पक्ष वितरण होता है।

62. (C) घरेलू एलपीजी सिलेंडर
'पहल' योजना विश्व के सबसे विशाल नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों में से एक के रूप में दर्ज है। इस योजना ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की रियायती मूल्य पर भौतिक आपूर्ति की पुरानी प्रणाली को प्रतिस्थापित किया। इस पारदर्शी तंत्र के अंतर्गत उपभोक्ता बाजार दर पर एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करते हैं और सब्सिडी की राशि सीधे उनके आधार-संयोजित बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित कर दी जाती है।

63. (A) केवल I और II
प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना मई 2016 में भारत सरकार द्वारा शुरु की गई एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक ईंधनों के उपयोग से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य खतरों को दूर करना था। हालांकि, एलपीजी की कीमतें स्थायी रूप से निश्चित नहीं की गई हैं।

64. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली सरकारी सब्सिडी वितरण श्रृंखला में बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह से समाप्त करती है। ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि DBT तंत्र के अंतर्गत सब्सिडी की मौद्रिक राशि सीधे लक्षित लाभार्थियों के आधार-संयोजित बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। इस पारदर्शी व्यवस्था से बिचौलियों का हस्तक्षेप समाप्त होता है और सरकारी धन का रिसाव रुकता है, जिससे लक्षित कल्याण सुनिश्चित होता है।

65. (B) एक ओपन नेटवर्क जो अंतर-एप्लिकेशन क्रेता-विक्रेता लेन-देन को सक्षम बनाता है
ओएनडीसी की संरचना निजी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों से भिन्न है। पारंपरिक प्लेटफॉर्म बंद मॉडल पर कार्य करते हैं जहाँ क्रेता और विक्रेता का एक ही ऐप पर होना आवश्यक है। इसके विपरीत, ओएनडीसी एक ओपन नेटवर्क है जो विभिन्न ऐप्स के बीच अंतर-संचालनीय व्यापार की अनुमति देता है। इससे क्रेता किसी भी ऐप से किसी अन्य ऐप के विक्रेता से सामान खरीद सकता है।

66. (D) भारतीय बैंक संघ (IBA)
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) भारत में खुदरा भुगतानों और निपटान प्रणालियों के नियमन हेतु गठित अम्ब्रेला संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय बैंक संघ (IBA) के संयुक्त सहयोग से की गई थी। एनपीसीआई का उद्देश्य देश में एक सुदृढ़ भुगतान अवसंरचना निर्मित करना रहा है, जिसके अंतर्गत इसने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का विकास किया है।

67. (A) वितरित खाद्यान्न की मात्रा पर अर्जित कमीशन या मार्जिन
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान चलाने वाले विक्रेताओं की आय का प्राथमिक स्रोत उनके द्वारा वितरित किए गए खाद्यान्न की मात्रा पर मिलने वाला कमीशन या डीलर मार्जिन होता है। केंद्र और राज्य सरकारें प्रति क्विंटल वितरित अनाज पर एक निश्चित कमीशन तय करती हैं। यह कमीशन राशि ही इन विक्रेताओं की आय का मुख्य साधन होती है, जिससे वे अपनी दुकानें चलाते हैं।

68. (A) केवल I और II
भारत में खाद्य सब्सिडी बिल की गणना खाद्यान्न की कुल आर्थिक लागत और केंद्रीय निर्गम मूल्य के अंतर के रूप में की जाती है। आर्थिक लागत में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, भंडारण, परिवहन और वितरण लागत शामिल होती हैं। इस विशाल खाद्य सब्सिडी का पूरा वित्तीय भार केंद्र सरकार के बजट द्वारा वहन किया जाता है, जबकि राज्य सरकारें वितरण का क्रियान्वयन करती हैं।

69. (A) डीजल मिलावट में रिसाव और एलपीजी की विस्तारित उपलब्धता
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सब्सिडी वाले केरोसिन के वितरण को समाप्त करने के दो प्राथमिक कारण थे। प्रथम, अत्यंत सस्ते केरोसिन का व्यापक पैमाने पर रिसाव होता था और इसका उपयोग व्यावसायिक डीजल में अवैध मिलावट हेतु किया जाता था। द्वितीय, उज्ज्वल योजना के कारण देश भर में एलपीजी की उपलब्धता में भारी वृद्धि हुई, जिससे खाना पकाने के लिए केरोसिन की मांग समाप्त हो गई।

70. (D) पूर्व क्रेताओं का निजी पता
उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के तहत विक्रेताओं के लिए उत्पाद का कुल खुदरा मूल्य, सभी अतिरिक्त शुल्क, उत्पाद का निर्माण देश तथा समाप्ति तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य है। हालांकि, पूर्व में खरीदारी करने वाले ग्राहकों के निजी पते या व्यक्तिगत विवरण को सार्वजनिक करना अनिवार्य प्रकटीकरण का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यह उपभोक्ता डेटा गोपनीयता नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

71. (B) केवल IV
सब्सिडी वितरण के विभिन्न मॉडल की अपनी सीमाएं और विशेषताएं हैं। प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण लाभार्थियों को अपनी

Click Here to Buy book on Amazon

प्राथमिकता अनुसार व्यय का अवसर देता है, जबकि वस्तु-रूप वितरण मूल्य वृद्धि के दौरान गरीबों की रक्षा करता है। हालांकि, यह कथन गलत है कि वस्तु-रूप वितरण से लॉजिस्टिक लागत समाप्त होती है; वास्तव में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भंडारण, हैंडलिंग तथा परिवहन पर विशाल प्रशासनिक व्यय होता है।

72. (C) 35 किग्रा प्रति परिवार
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत आच्छादित प्रत्येक गरीब परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है। समाज के सबसे निर्धन और असहाय परिवारों को भुखमरी से बचाने और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना के तहत खाद्यान्न अत्यंत रियायती दरों पर वितरित किया जाता है।

73. (D) पहचान धोखाधड़ी और छद्म लाभार्थियों के कारण होने वाला रिसाव
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य फर्जी पहचान और छद्म लाभार्थियों द्वारा किए जाने वाले खाद्यान्न रिसाव को समाप्त करना था। अतीत में डुप्लिकेट राशन कार्डों के माध्यम से सब्सिडी वाले अनाज का व्यापक व्यपवर्तन होता था। बायोमेट्रिक सत्यापन व्यवस्था ने वास्तविक पात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करके वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को स्थापित किया है।

74. (A) स्वतंत्र पंजीकृत विक्रेता सूचीबद्ध वस्तुओं के स्वामी होते हैं
भारत की एफडीआई नीति के अनुरूप संचालित ई-कॉमर्स मार्किटप्लेस मॉडल में बेची जाने वाली वस्तुओं का स्वामित्व केवल स्वतंत्र पंजीकृत विक्रेताओं के पास होता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म संचालक कंपनी स्वयं किसी भी सूचीबद्ध सामान या इन्वेंट्री का कानूनी स्वामित्व नहीं रख सकती है। मार्किटप्लेस संस्था केवल डिजिटल मंच प्रदान करती है जहाँ स्वतंत्र क्रेता और विक्रेता आपस में वाणिज्यिक लेन-देन संपन्न करते हैं।

75. (B) 1.0%
वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून के अंतर्गत ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए स्रोत पर कर संग्रहण (TCS) की निर्दिष्ट संयुक्त दर 1.0 प्रतिशत है। इस कुल दर के अंतर्गत 0.5 प्रतिशत केंद्रीय कर (CGST) और 0.5 प्रतिशत राज्य कर (SGST) शामिल होता है। यह कर ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा विक्रेताओं को भुगतान की जाने वाली कर योग्य आपूर्तियों के शुद्ध मूल्य से काटा जाता है।

76. (B) P-3, Q-2, R-4, S-1
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लगभग 67 प्रतिशत आबादी के लिए रियायती खाद्यान्न का विधिक अधिकार स्थापित करता है। ई-कॉमर्स एफडीआई नीति मार्किटप्लेस संस्थाओं को इन्वेंट्री का स्वामित्व रखने से रोकती है। उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स नियम शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति को अनिवार्य बनाते हैं। इसके अतिरिक्त जीएसटी अधिनियम के प्रावधान प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों द्वारा टीसीएस की कटौती को वैधानिक रुप से अनिवार्य बनाते हैं।

77. (A) उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इनपुट लागत कम करना
विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कृषि उर्वरक सब्सिडी प्रदान करने का सबसे उपयुक्त आर्थिक आधार किसानों के लिए इनपुट लागत को कम करना है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए उर्वरक वहनीय बनने से वे अपनी फसलों में इनका उचित प्रयोग कर पाते हैं। इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ता है और देश की समग्र खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।

78. (C) एकीकृत प्लेटफॉर्म एकाधिकार को तोड़ने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं का पृथक्करण करना
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) का मुख्य उद्देश्य ई-कॉमर्स क्षेत्र में एकीकृत प्लेटफॉर्मों के एकाधिकार को समाप्त करना है। यह नेटवर्क आपूर्ति श्रृंखलाओं का पृथक्करण करके विक्रेताओं, लॉजिस्टिक प्रदाताओं तथा भुगतान प्रणालियों को स्वतंत्र रुप से जोड़ता है। इससे किसी एक विशाल कंपनी का बाजार पर नियंत्रण नहीं रहता और छोटे व्यापारियों को डिजिटल व्यापार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धी वातावरण प्राप्त होता है।

79. (D) BPL और APL परिवारों के लिए विभेदित दरों/कीमतों और लाभों की शुरुआत करना
वर्ष 1997 में लागू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) और पूर्ववर्ती सार्वभौमिक पीडीएस के बीच मुख्य अंतर लाभार्थियों का स्पष्ट वर्गीकरण था। सार्वभौमिक प्रणाली सभी नागरिकों को समान दरों पर राशन देती थी, जबकि TPDS ने BPL और APL श्रेणियों की पहचान की। इसके तहत निर्धन BPL परिवारों को खाद्य सुरक्षा देने हेतु अधिक सब्सिडी और विभेदित खाद्यान्न दरें निर्धारित की गईं।

80. (A) II, IV, I, III
भारत में नीतिगत और डिजिटल अवसंरचनात्मक विकास का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम निम्नानुसार है। सर्वप्रथम, वर्ष 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन किया गया। तत्पश्चात, वर्ष 2013 में ऐतिहासिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। इसके बाद, वर्ष 2016 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की शुरुआत हुई और अंततः वर्ष 2022 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) की पहल की गई।

www.nodia.in

NODIA

अध्याय 07

कृषि उद्योग क्षेत्र : स्थिति, समस्याएँ एवं पहल

1. भारत के कृषि क्षेत्रक में अर्थव्यवस्था में इसके योगदान के संबंध में एक स्पष्ट संरचनात्मक असमानता दिखाई देती है। समष्टि अर्थशास्त्र स्तर पर निम्नलिखित में से कौन-सा कथन इस असमानता का सबसे सही वर्णन करता है?

(A) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इस क्षेत्रक की हिस्सेदारी में निरंतर गिरावट आई है, फिर भी यह कार्यबल के सबसे बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करना जारी रखे हुए है।

(B) यह क्षेत्रक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अधिकांश हिस्से के लिए उत्तरदायी है, किंतु कार्यबल के बहुत छोटे हिस्से को रोजगार देता है।

(C) पिछले दो दशकों में कृषि क्षेत्रक का जीडीपी योगदान और रोजगार हिस्सेदारी दोनों आनुपातिक रुप से बढ़े हैं।

(D) इस क्षेत्रक की रोजगार हिस्सेदारी इसके जीडीपी हिस्से की तुलना में तेजी से घटी है, जिससे उच्च प्रति व्यक्ति कृषि आय हुई है।

2. निम्नलिखित कृषि योजनाओं को उनकी प्रमुख विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची I: योजनाएं

P. पीएम-किसान

Q. पीएम फसल बीमा योजना

R. ई-नाम

S. किसान क्रेडिट कार्ड

सूची II: प्रमुख विशेषताएं

1. अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल
2. प्रति वर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता
3. किसानों के लिए अल्पकालिक संस्थागत ऋण
4. गैर-निवारण योग्य जोखिमों के विरुद्ध उपज-आधारित फसल बीमा

(A) P-4, Q-2, R-3, S-1

(B) P-2, Q-1, R-4, S-3

(C) P-2, Q-4, R-1, S-3

(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

3. भारत में निरंतर भूमि विखंडन ने कृषि यांत्रिकीकरण और उत्पादकता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार, राजस्थान में औसत क्रियात्मक जोत का आकार राष्ट्रीय औसत से किस प्रकार तुलनीय है?

(A) राजस्थान का औसत जोत आकार राष्ट्रीय औसत (लगभग 1.08 हेक्टेयर) की तुलना में काफी अधिक (लगभग 2.73 हेक्टेयर) है।

(B) राजस्थान का औसत जोत आकार राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है।

(C) राजस्थान का औसत जोत आकार लगभग राष्ट्रीय औसत के बराबर है।

(D) भूमि चकबंदी के प्रयासों के कारण दोनों औसत 5 हेक्टेयर पर स्थिर हो गए हैं।

4. भारत के जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्रक के हिस्से के ऐतिहासिक ठहराव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. पिछले तीन दशकों से भारत के जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्रक का हिस्सा काफी हद तक 15-17 प्रतिशत के आसपास स्थिर बना हुआ है।

II. समयपूर्व वि-औद्योगिकीकरण और सेवा क्षेत्रक की ओर तेजी से झुकाव ने इस दीर्घकालिक ठहराव में योगदान दिया है।

III. जटिल विनियामक अनुपालन और उच्च रसद व्यय विनिर्माण विकास को रोकने वाली प्रमुख बाधाएं रही हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल I और II

(B) केवल II और III

(C) केवल I और III

(D) I, II और III

5. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्राप्त करने से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है?

(A) 1 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि वाले सीमांत किसान

(B) वे किसान परिवार जिनके एक या अधिक सदस्य संसद के पूर्व या वर्तमान सदस्य हैं

(C) 2 हेक्टेयर तक सिंचित भूमि वाले छोटे किसान

(D) स्थानीय साहूकारों जैसे गैर-संस्थागत ऋण स्रोतों का उपयोग करने वाले किसान

6. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए:

अभिकथन (A): भारत की घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरु की गईं।

कारण (R): पीएलआई योजनाएं उद्योगों को उनके वास्तविक उत्पादन की परवाह किए बिना, नए विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए निश्चित पूंजी सब्सिडी प्रदान करती हैं।

(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R,

Downloaded from www.pdf.tube

A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

7. विश्व बैंक का सुगम व्यापार सूचकांक विनियामक अनुपालन बोझ के मूल्यांकन के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त मापदंड था। इस रिपोर्ट को बंद किए जाने से पहले, भारत ने अंतिम 'डूइंग बिजनेस 2020' रिपोर्ट में ऐतिहासिक छलांग लगाकर कौन-सी रैंक हासिल की थी?
(A) 142वीं
(B) 100वीं
(C) 77वीं
(D) 63वीं

8. 2020 में लागू संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण के अनुसार, संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में उनकी अधिकतम निवेश सीमा के आधार पर निम्नलिखित उद्यम श्रेणियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. लघु उद्यम
2. मध्यम उद्यम
3. सूक्ष्म उद्यम
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही अनुक्रम का चयन कीजिए:
(A) 3, 1, 2
(B) 3, 2, 1
(C) 1, 3, 2
(D) 2, 1, 3

9. अनुबंध कृषि (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) का उद्देश्य मूल्य जोखिम को स्थानांतरित करके किसान की आय को स्थिर करना है। भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर अनुबंध कृषि की प्राथमिक सीमा या जोखिम माना जाता है?
(A) निजी निगमों पर निर्भरता के कारण स्थानीय फसल की कीमतों में भारी विकृति
(B) असमान मोलभाव की क्षमता के कारण कॉर्पोरेट प्रायोजकों द्वारा सम्भावित शोषण
(C) अनिश्चित जलवायु और बाजार के परिवर्तनों के कारण आपूर्ति श्रृंखला में निरंतर व्यवधान
(D) आधुनिक आगत (इनपुट) आपूर्ति और भूमि तैयारी से जुड़ी उच्च परिचालन लागत

10. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 2020 में शुरु किए गए 'उद्यम पंजीकरण' पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) विभिन्न कृषि वस्तुओं और कृषि उत्पादों के निर्बाध अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को सुगम बनाना
(B) एमएसएमई के लिए एक ऑनलाइन, कागजरहित, शून्य-लागत स्व-घोषणा पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान करना
(C) रक्षा विनिर्माण उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमाओं की निगरानी, ट्रैकिंग और विनियमन करना
(D) पात्र ग्रामीण परिवारों को आपातकालीन कृषि ऋण माफी के राज्यवार वितरण पर नज़र रखना और प्रबंधन करना

NODIA

11. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत प्रीमियम दरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. सभी खरीफ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम बीमित राशि का 2 प्रतिशत है।
II. सभी रबी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत है।
III. वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम बीमित राशि का 5 प्रतिशत है।
IV. शेष बीमांकिक प्रीमियम का बोझ बिना किसी राज्य के योगदान के पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

12. उच्च रसद लागत ऐतिहासिक रूप से भारतीय विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता में एक बड़ी बाधा रही है। राष्ट्रीय रसद नीति (2022) का उद्देश्य जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत की रसद लागत को निम्नलिखित में से किस लक्ष्य सीमा तक कम करना है?
(A) वार्षिक राष्ट्रीय उत्पादन के लगभग 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत तक लाना
(B) सभी पंजीकृत एमएसएमई और कृषि निर्यातों के लिए घटाकर शून्य प्रतिशत करना
(C) लगभग 14-18 प्रतिशत से घटाकर 8-9 प्रतिशत के आसपास एक अंक में लाना
(D) सभी अंतर-राज्यीय जांच चौकियों और टोलों को समाप्त करके 2 प्रतिशत से नीचे लाना

13. औद्योगिक गलियारों को उनकी संबद्ध प्रमुख विशेषताओं या क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: औद्योगिक गलियारे
P. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा
Q. अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा
R. चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा
S. वाइजाग-चेन्नई औद्योगिक गलियारा
सूची II: प्रमुख विशेषताएं / क्षेत्र
1. मुख्य रूप से पूर्वी समर्पित माल गलियारे के साथ संरेखित
2. राजस्थान से होकर काफी हद तक गुजरता है, जिसमें खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना जैसे केंद्र शामिल हैं
3. व्यापक ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण खंड

4. दक्षिणी प्रायद्वीप को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-3, R-4, S-1
(C) P-3, Q-1, R-2, S-4
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

14. किसानों को समय पर और पर्याप्त संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन-सा एक पात्र घटक नहीं है जिसके लिए आमतौर पर केसीसी ऋण सीमाएं स्वीकृत की जाती हैं?

(A) फसल कटाई के बाद के खर्च और उपज विपणन ऋण
(B) किसान परिवार की उपभोग आवश्यकताएं
(C) वाणिज्यिक खनन कार्यों के लिए भारी मशीनरी की खरीद
(D) कृषि संपत्तियों और संबद्ध कृषि गतिविधियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी

15. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए:

अभिकथन (A): ई-नाम प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के लिए भाग लेने वाले राज्यों को अपने संबंधित राज्य नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता थी।

कारण (R): भारत में कृषि विपणन राज्य का विषय है, और स्थानीय मंडियां राज्य-विशेष एपीएमसी अधिनियमों द्वारा शासित होती हैं।

(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

16. निम्नलिखित प्रमुख सरकारी पहलों के शुरुआती शुभारंभ वर्षों का सबसे पहले से सबसे नवीनतम तक सही कालानुक्रमिक क्रम चुनिए:

1. मेक इन इंडिया
2. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
3. आत्मनिर्भर भारत अभियान
4. राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही अनुक्रम का चयन कीजिए:

(A) 1 - 4 - 2 - 3
(B) 1 - 2 - 4 - 3
(C) 4 - 1 - 2 - 3
(D) 4 - 2 - 1 - 3

17. भारतीय कृषि में "उपज अंतर" शब्द एक महत्वपूर्ण उत्पादकता मुद्दे को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन-सा इस उपज अंतर को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है?

(A) किसानों द्वारा प्राप्त वास्तविक फसल उपज और सम्भावित आदर्श उपज के बीच का अंतर
(B) खरीफ और रबी कृषि मौसमों में कुल कृषि उत्पादन के बीच का अंतर
(C) घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और वास्तविक बाजार कीमतों के बीच का अंतर
(D) एक वर्ष में कुल उपलब्ध कृषि योग्य भूमि और शुद्ध बोए गए क्षेत्र के बीच का अंतर

18. किसानों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन की गई कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) प्रणाली के अस्तित्व के बावजूद, कई सीमाओं ने एपीएमसी सुधारों की मांग को जन्म दिया। निम्नलिखित में से किसे पारंपरिक एपीएमसी मंडी प्रणाली की एक प्रमुख सीमा के रूप में जाना जाता है?

(A) इसमें किसानों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने की आवश्यकता होती थी, जिससे थोक बिचौलियों का पूरी तरह से उन्मूलन हो गया
(B) इसने सभी मंडी शुल्कों और व्यापारिक कमीशनों को समाप्त कर दिया, जिससे राज्य के राजस्व में भारी कमी आई
(C) इसने बाजार विखंडन, उच्च प्रवेश बाधाएं, बहु-स्तरीय शुल्क और व्यापारियों का सिंडिकेट बनाना उत्पन्न किया
(D) इसने अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी बाजारों में उपज के अप्रतिबंधित सीमा पार परिवहन की अनुमति दी

19. 2011 में शुरू की गई ऐतिहासिक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति ने विनिर्माण क्षेत्रक के लिए एक प्रमुख मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित किया था। वह लक्ष्य क्या था?

(A) जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना और 2022 तक 10 करोड़ (100 मिलियन) रोजगार सृजित करना।
(B) यह सुनिश्चित करना कि एक दशक के भीतर विनिर्माण निर्यात कृषि निर्यात से 50 प्रतिशत अधिक हो जाए।
(C) घरेलू एमएसएमई की सुरक्षा के लिए विनिर्माण क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना।
(D) 2025 तक कृषि क्षेत्रक के 20 करोड़ अतिरिक्त श्रमिकों को सेवा क्षेत्रक में स्थानांतरित करना।

20. कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में शुरू किए गए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. यह भारतीय अर्थव्यवस्था को सभी विदेशी आयातों और निवेशों के लिए बंद करके पूर्ण आत्मनिर्भरता पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है।
II. इसका उद्देश्य लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना और घरेलू विनिर्माण के माध्यम से आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना है।
III. इसमें एमएसएमई, कृषि और श्रम को संबोधित करने वाले व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज शामिल हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल I और II
(B) केवल II और III

Click Here to Buy book on Flipkart

(C) केवल I और III
(D) I, II और III

21. भारत सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार स्पष्ट श्रम संहितों में मिलाकर श्रम कानूनों का एक प्रमुख सुधार किया। निम्नलिखित में से कौन-सा इन चार मूलभूत श्रम संहितों में से एक नहीं है?
(A) मजदूरी संहिता
(B) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संहिता
(C) औद्योगिक संबंध संहिता
(D) व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता

22. औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमाओं को व्यवस्थित रुप से उदार बनाया गया है। वर्तमान में, ग्रीनफील्ड चिकित्सा उपकरण विनिर्माण और अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण के लिए स्वचालित मार्ग के तहत अनुमत मानक एफडीआई सीमा क्या है?
(A) 26 प्रतिशत
(B) 49 प्रतिशत
(C) 74 प्रतिशत
(D) 100 प्रतिशत

23. नई श्रम संहितों के विशिष्ट ध्यान को उनके संबंधित प्रावधानों से सुमेलित कीजिए:
सूची I: श्रम संहिताएं
P. मजदूरी संहिता
Q. औद्योगिक संबंध संहिता
R. सामाजिक सुरक्षा संहिता
S. व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता
सूची II: ध्यान देने योग्य क्षेत्र
1. सभी वेतनभोगी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी और समय पर भुगतान का सार्वभौमीकरण करता है
2. ट्रेड यूनियनों, रोजगार की शर्तों और औद्योगिक विवादों के समाधान को विनियमित करता है
3. गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भविष्य निधि, मातृत्व लाभ और पेंशन का विस्तार करता है
4. कारखाने के परिवेश, काम के घंटे और कार्यस्थल के जोखिमों से संबंधित नियमों को समेकित करता है
(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

24. भारत में कृषि और उद्योग के ऐतिहासिक विकास रुझानों की तुलना करते समय, आर्थिक आंकड़े सामान्यतः दर्शाते हैं कि:
(A) कृषि मौसम-संचालित अस्थिरता दर्शाती है, जबकि उद्योग समष्टि आर्थिक मांग चक्रों का पालन करता है।
(B) औद्योगिक विकास काफी हद तक मानसून पर निर्भर करता है, जबकि कृषि वैश्विक इक्विटी बाजारों का पालन करती है।
(C) स्वतंत्रता के बाद से दोनों क्षेत्रों ने सालाना आठ प्रतिशत की एकसमान वृद्धि दर बनाए रखी है।
(D) पूर्ण सिंचाई के कारण कृषि में शून्य अस्थिरता है, जबकि उद्योग फसल की कीमतों के साथ घटता-बढ़ता है।

25. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए:
अभिकथन (A): केंद्रीय बैंकों और अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रायः बड़े पैमाने पर कृषि ऋण माफी की आलोचना की जाती है।
कारण (R): कृषि ऋण माफी से दीर्घकालिक ऋण संस्कृति बिगड़ने और उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन को क्षति पहुंचने की प्रवृत्ति होती है, जिससे भावी बैंकिंग परिचालन प्रभावित होते हैं।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

26. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। डीएमआईसी की लंबाई या प्रभाव क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत राजस्थान राज्य से होकर गुजरता है?
(A) 5 प्रतिशत
(B) 15 प्रतिशत
(C) 39 प्रतिशत
(D) 75 प्रतिशत

27. ऐतिहासिक रुप से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यापार सुगमता) को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. व्यवसाय शुरु करना
II. निर्माण परमिट प्राप्त करना
III. विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना
IV. विदेश नीति मामलों का संचालन करना
विश्व बैंक के व्यापार सुगमता मूल्यांकन में आधिकारिक रुप से शामिल मापदंडों के संबंध में उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

28. किसी प्रतिभागी किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के परिचालन चक्र में शामिल चरणों के तार्किक क्रम को व्यवस्थित कीजिए:
1. अधिसूचित स्थानीय आपदा की घटना या सीजन के अंत में उपज हानि का आकलन
2. प्रीमियम के किसान के हिस्से का भुगतान और नामांकन
3. राज्य सरकार द्वारा फसलों और क्षेत्रों की अधिसूचना

Downloaded from www.pdf.tube

4. दावों का निपटान और किसान के बैंक खाते में सीधा हस्तांतरण

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही अनुक्रम का चयन कीजिए:
(A) 3, 2, 1, 4
(B) 2, 3, 1, 4
(C) 3, 1, 2, 4
(D) 1, 2, 3, 4

29. "मेक इन इंडिया" पहल 2014 में भारत को एक वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरु की गई थी। निम्नलिखित में से कौन-सा मेक इन इंडिया पहल के स्पष्ट मूलभूत स्तंभों में से एक नहीं है?
(A) व्यवसाय के लिए विनियामक अनुपालन को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित 'नया तंत्र/प्रक्रियाएं'
(B) औद्योगिक गलियारों और स्मार्ट शहरी केंद्रों से युक्त 'नया बुनियादी ढांचा'
(C) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उदारीकरण से जुड़े 'नए क्षेत्रक'
(D) सभी भारी औद्योगिक विनिर्माण फर्मों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण

30. भारत में कौशल विकास के लिए कौन-सा शीर्ष राष्ट्रीय निकाय एक व्यापक विनियामक ढांचे के रूप में कार्य करता है, जो औद्योगिक जनशक्ति आवश्यकताओं के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के संरेखण को सुनिश्चित करता है?
(A) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
(B) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई)
(C) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी)
(D) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

31. आर्थिक क्षेत्रकों को स्वचालित मार्ग के तहत उनकी संबंधित अनुमत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमाओं से सुमेलित कीजिए:

सूची I: क्षेत्रक
P. कृषि (विशिष्ट गतिविधियां जैसे पुष्प कृषि, बीज)
Q. मल्टी-ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग
R. रक्षा विनिर्माण (कुछ शर्तों के अधीन)
S. ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस मॉडल

सूची II: एफडीआई सीमा / मार्ग
1. स्वचालित मार्ग के तहत 100%
2. स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक
3. 51% लेकिन केवल सरकारी मार्ग के माध्यम से
4. स्वचालित मार्ग के तहत 100%

(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-4, Q-2, R-3, S-1

32. आर्थिक विकास के संदर्भ में, "लुईस मॉडल" या संरचनात्मक परिवर्तन सिद्धांत सुझाव देता है कि अधिशेष श्रम को पारंपरिक कृषि क्षेत्रक से आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रक में स्थानांतरित होना चाहिए। भारत में यह स्थानांतरण असामान्य रूप से धीमा रहने का प्राथमिक कारण क्या है?
(A) ग्रामीण कृषि शहरी रोजगार की तुलना में उच्च प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है
(B) कानूनी नियम शहरी औद्योगिक केंद्रों में अंतर-राज्यीय श्रम प्रवास को प्रतिबंधित करते हैं
(C) ग्रामीण श्रमिकों में कारखाने के श्रम के लिए शारीरिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं की कमी है
(D) विनिर्माण क्षेत्रक अधिशेष श्रम के लिए श्रम-गहन रोजगार सृजित करने में विफल रहा है

33. आकार के अनुसार भारत में क्रियात्मक जोतों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. सीमांत जोतें वे हैं जिनका आकार 1 हेक्टेयर से कम है।
II. छोटी/लघु जोतें वे हैं जिनका आकार 1 से 2 हेक्टेयर के बीच है।
III. अर्ध-मध्यम जोतें वे हैं जिनका आकार 10 से 20 हेक्टेयर के बीच है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

NODIA

34. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए:

अभिकथन (A): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रक को भारत में व्यापक रूप से रोजगार सृजन का इंजन माना जाता है।

कारण (R): एमएसएमई क्षेत्रक अत्यधिक पूंजी-गहन है और इसे आगे बढ़ने के लिए श्रम के बजाय भारी विदेशी तकनीकी निवेश की आवश्यकता होती है।

(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

35. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इसके वित्तपोषण पैटर्न के संबंध में "केंद्रीय क्षेत्रक योजना" शब्द का क्या अर्थ है?
(A) यह पूरी तरह से (100%) भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
(B) यह केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्तपोषित है।
(C) यह पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित है लेकिन केंद्र द्वारा डिज़ाइन की गई है।
(D) यह विशेष रूप से विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित है।

36. कुल ऋण वितरण में उनके विशिष्ट हिस्से के आधार पर (उच्चतम हिस्से से निम्नतम हिस्से तक) भारत में कृषि ऋण के संस्थागत स्रोतों का सही क्रम चुनिए:

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2. वाणिज्यिक बैंक
3. सहकारी बैंक

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही अनुक्रम का चयन कीजिए:

(A) 2 - 3 - 1
(B) 1 - 2 - 3
(C) 3 - 2 - 1
(D) 2 - 1 - 3

37. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के लिए कौन-सी नामित एजेंसी मुख्य प्रवर्तक और कार्यान्वयन एजेंसी है?

(A) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)
(B) लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी)
(C) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
(D) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी)

38. अनुबंध कृषि (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करने और किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को एक मॉडल अधिनियम प्रसारित किया। 'मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट' किस वर्ष पेश किया गया था?

(A) 2003
(B) 2014
(C) 2018
(D) 2022

39. हाल के सुधारों से पहले भारत में औद्योगिक विकास पर कठोर श्रम कानूनों के संभावित प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. उन्होंने बड़े पैमाने के विनिर्माण को हतोत्साहित किया क्योंकि फर्मों ने जटिल अनुपालन बोझ से बचने के लिए छोटा बना रहना पसंद किया।
II. उन्होंने "वामनता" (ड्वार्फिज्म) के रूप में वर्णित एक घटना को जन्म दिया, जहां फर्म जीवित तो रहती हैं लेकिन बढ़ती नहीं हैं।
III. उन्होंने अनौपचारिक नौकरियों की कीमत पर औपचारिक क्षेत्रक के रोजगार के तेजी से विस्तार को बढ़ावा दिया।
IV. उनके कारण उद्योगों ने जहां भी संभव हो, श्रम को स्वचालित मशीनरी से प्रतिस्थापित किया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल I, II और IV
(B) केवल I, II और III
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

40. एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि उनका योगदान परिवर्तित होता रहता है, ऐतिहासिक रूप से वे भारत के विनिर्माण जीडीपी और कुल निर्यात के क्रमशः लगभग कितने प्रतिशत के लिए उत्तरदायी हैं?

(A) विनिर्माण जीडीपी का 33% और कुल निर्यात का 45%
(B) विनिर्माण जीडीपी का 5% और कुल निर्यात का 10%
(C) विनिर्माण जीडीपी का 75% और कुल निर्यात का 80%
(D) विनिर्माण जीडीपी का 10% और कुल निर्यात का 5%

41. मानक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) दिशा-निर्देशों के तहत निम्नलिखित में से कौन दावा निपटान के लिए एक वैध जोखिम के रूप में कवर नहीं किया गया है?

(A) वर्षा की कमी के कारण रोके गए बुवाई या रोपण का जोखिम
(B) किसी व्यक्ति द्वारा चोरी या दुर्भावनापूर्ण क्षति के कारण फसल का नुकसान
(C) खेत में सूखने के लिए छोड़ी गई फसलों को चक्रवातीय बारिश के कारण कटाई के बाद होने वाला नुकसान
(D) सूखा, बाढ़ और कीटों जैसे गैर-निवारण योग्य जोखिमों के कारण उपज का नुकसान

42. कृषि विपणन के संदर्भ में, एपीएमसी (APMC) का क्या अर्थ है?

(A) कृषि उपज बाजार समिति (एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी)
(B) एग्रीकल्चरल प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल
(C) एग्रीरियन प्राइजिंग एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन
(D) एसोसिएशन ऑफ प्राइमरी मार्केट कोऑपरेटिव्स

43. पारंपरिक एपीएमसी अधिनियम के तहत, निम्नलिखित में से कौन-सा अभ्यास बाजार विखंडन का एक प्रमुख कारण था?

(A) राज्य के प्राधिकरण के बिना विशेष वैश्विक व्यापारिक पोर्टलों के माध्यम से अनिवार्य ऑनलाइन फसल बिक्री
(B) पारंपरिक मंडी परिसरों के भीतर काम करने वाले कमीशन एजेंटों का पूर्ण उन्मूलन और नियंत्रण मुक्त करना
(C) विभिन्न बाजार क्षेत्रों और राज्य सीमाओं में बहु-स्तरीय मंडी शुल्कों और उपकरों का लगाया जाना
(D) सभी कृषि वस्तुओं के लिए एकसमान एकल-बिंदु कराधान प्रणाली का राष्ट्रव्यापी अपनाव

44. उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने विस्तार से पहले शुरुआत में कुछ प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित किया। आयात निर्भरता कम करने के लिए पीएलआई के तहत लक्षित सबसे शुरुआती और सबसे प्रमुख क्षेत्रों में से कौन-सा एक था?

(A) वाणिज्यिक कच्चा कपास निष्कर्षण और कपड़ा प्रसंकरण कार्य
(B) बुनियादी प्राथमिक शिक्षा डिजिटल शिक्षण उपकरणों का उत्पादन
(C) पारंपरिक हथकरघा बुनाई और कारीगर शिल्प विनिर्माण इकाइयां
(D) मोबाइल फोन और घटकों का बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

Click Here to Buy book on Amazon

45. भारतीय उद्योग को बाधित करने वाली बुनियादी ढांचे की बाधाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. अविश्वसनीय विद्युत आपूर्ति और क्रॉस-सब्सिडीकरण भारत में औद्योगिक विद्युत दरों को वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक बनाते हैं।

II. अपर्याप्त बंदरगाह बुनियादी ढांचा और धीमा टर्नअराउंड समय विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात की कुल लागत को बढ़ाते हैं।

III. औद्योगिक गलियारे सीधे ग्रामीण सब्सिडी के पक्ष में प्रमुख बुनियादी ढांचे के निवेश को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

46. व्यापार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को सुविधाजनक बनाने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, राजस्थान सरकार ने 2019 में एमएसएमई (स्थापना और प्रवर्तन का सुगमीकरण) अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है?

(A) सभी नए पंजीकृत उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट आयकर से स्थायी छूट
(B) उद्यमों के लिए कुल वार्षिक उत्पादन का पचास प्रतिशत निर्यात करने की अनिवार्य आवश्यकता
(C) तीन वर्ष की अवधि के लिए राज्य के कानूनों के तहत निरीक्षणों और अनुमोदनों से अस्थायी छूट
(D) सभी शॉप फ्लोर विनिर्माण कर्मचारियों के लिए पूर्ण सरकारी वेतन सब्सिडी सहायता

47. राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (एनआईएमज़ेड) किस औद्योगिक पहल के तहत परिकल्पित एक महत्वपूर्ण नीतिगत साधन थे?

(A) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
(B) राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011
(C) इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार
(D) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

48. कृषि ऋण के गैर-संस्थागत स्रोत ऐतिहासिक रूप से शोषणकारी रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन कृषि ऋण के गैर-संस्थागत स्रोत का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है?

(A) प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस)
(B) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(C) लघु वित्त बैंक
(D) स्थानीय साहूकार और कमीशन एजेंट

49. भारत में कृषि ऋण माफी से जुड़ी बहस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. समर्थकों का तर्क है कि वे लगातार फसल की विफलता का सामना कर रहे संकटग्रस्त किसानों को तत्काल राहत प्रदान करते हैं।

II. आलोचकों का तर्क है कि वे नैतिक जोखिम को जन्म देते हैं, जहां पुनर्भुगतान करने में सक्षम किसान भी भविष्य में ऋण माफी की उम्मीद में डिफ़ॉल्ट करते हैं।

III. वे राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण राजकोषीय स्थान की खपत करते हैं, जिससे अक्सर कृषि बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय कम हो जाता है।

IV. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र (बैलेंस शीट) को मजबूत करने के साधन के रूप में आमतौर पर उनका स्वागत किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल I, II और IV
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, II और III
(D) केवल I, III और IV

NODIA

50. किसी राज्य की मंडी को ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत करने की प्राथमिक शर्त क्या है?

(A) मंडी को बाजार लेनदेन को सख्ती से प्रमाणित जैविक उत्पाद विकल्पों तक सीमित करना होगा
(B) राज्य को अपने एपीएमसी विधान को पूरी तरह से रद्द करना होगा और सभी बाजार नियमों को समाप्त करना होगा
(C) राज्य एपीएमसी अधिनियम में ई-ट्रेडिंग, एकल-बिंदु शुल्क और एकीकृत राज्य लाइसेंस की अनुमति होनी चाहिए
(D) मंडी में सभी वित्तीय व्यापार का निपटान विदेशी मुद्रा इकाइयों में होना अनिवार्य होना चाहिए

51. भारत और वैश्विक कृषि अग्रणियों के बीच "उपज अंतर" का कारण अक्सर कई कारकों को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा आमतौर पर इस कम उत्पादकता के मुद्दे में योगदान देने वाला कारक नहीं है?

(A) अत्यधिक भूमि जोत आकार जो बड़े पैमाने की बचत की अनुमति देता है
(B) सीमांत किसानों द्वारा उच्च उपज देने वाली किस्मों और आधुनिक तकनीक का कम अपनाया जाना
(C) वर्षा आधारित कृषि पर निर्भरता और अपर्याप्त सिंचाई कवरेज
(D) रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित उपयोग और मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट

52. 2020 में उल्लिखित आत्मनिर्भर भारत अभियान के पांच मुख्य स्तंभों में से निम्नलिखित में से कौन-सा एक नहीं है?

(A) क्रमिक वृद्धि के बजाय क्वांटम जंप पर केंद्रित अर्थव्यवस्था
(B) आधुनिक और तकनीकी प्रगति का प्रतिनिधित्व करने वाला बुनियादी ढांचा
(C) डिजिटल प्रौद्योगिकी और आधुनिक रसद द्वारा संचालित प्रणाली
(D) विदेशी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल करने वाला

पूर्ण पृथकतावाद

53. एमएसएमई को परिभाषित करने के संशोधित समग्र मानदंडों के तहत, निवेश और वार्षिक टर्नओवर दोनों पर विचार किया जाता है। किसी उद्यम को "सूक्ष्म" उद्यम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अधिकतम वार्षिक टर्नओवर सीमा क्या है?
(A) 1 करोड़ रुपये
(B) 5 करोड़ रुपये
(C) 50 करोड़ रुपये
(D) 250 करोड़ रुपये

54. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना शीघ्र पुनर्भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ब्याज छूट प्रदान करती है। यदि कोई किसान नियत तिथि के भीतर शीघ्रता से अल्पकालिक फसल ऋण (3 लाख रुपये तक) चुकाता है, तो किसान द्वारा वहन की जाने वाली प्रभावी ब्याज दर क्या है?
(A) 9 प्रतिशत
(B) 7 प्रतिशत
(C) 4 प्रतिशत
(D) 0 प्रतिशत

55. भारतीय उद्योग में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बुनियादी ढांचे की बाधाओं के कारण वैश्विक स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में इसकी असमर्थता है। अविश्वसनीय बिजली, खराब सड़कों और बंदरगाहों पर देरी के कारण उद्योगों द्वारा वहन की जाने वाली अतिरिक्त लागतों का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है?
(A) जनसांख्यिकी लाभांश देनदारियां
(B) उच्च पूंजी-उत्पाद अनुपात लागत
(C) ब्याज दर सहायता/छूट लागत
(D) रसद और लेनदेन लागत

56. उद्योग के आधुनिकीकरण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय रक्षा क्षेत्रक में, नए औद्योगिक लाइसेंस चाहने वाली कंपनियों के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से वर्तमान में किस सीमा तक एफडीआई की अनुमति है?
(A) 26 प्रतिशत
(B) 49 प्रतिशत
(C) 74 प्रतिशत
(D) 100 प्रतिशत

57. निम्नलिखित में से कौन-सा बैंक/संस्थान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के जारी करने और संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेता है?
(A) वाणिज्यिक बैंक
(B) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(C) सहकारी बैंक
(D) उपर्युक्त सभी

58. ई-नाम प्लेटफॉर्म "मूल्य खोज" में सुधार करके कृषि बाजारों में क्रांति लाने का प्रयास करता है। इस संदर्भ में मूल्य खोज का क्या अर्थ है?
(A) सभी कृषि उत्पादों के लिए स्थिर, गैर-परक्राम्य न्यूनतम कीमतों का सरकार द्वारा निर्धारण
(B) पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक बोली के माध्यम से हाजिर कीमतों का निर्धारण
(C) किसानों को फसल उत्पादन व्यय का पूरा खुलासा करने के लिए बाध्य करने वाला कानूनी जनादेश
(D) राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में स्थानीय खुदरा खाद्य कीमतों का आवधिक प्रकाशन

59. भूमि चकबंदी से तात्पर्य विखंडित भूमि के टुकड़ों को एक ही निकटवर्ती भूखंड में पुनरावंटित करना है। सफल भूमि चकबंदी का प्रत्यक्ष अपेक्षित लाभ निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) उन्नत कृषि यांत्रिकीकरण और कुशल सिंचाई प्रबंधन
(B) सीमांत किसानों की कुल संख्या में निरंतर वृद्धि
(C) कुल उपलब्ध कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में पर्याप्त कमी
(D) परिवारों के लिए कार्यशील ऋण आवश्यकताओं का पूर्ण उन्मूलन

60. पीएम-किसान प्रति वर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करता है। यह राशि पात्र किसान परिवारों को कैसे वितरित की जाती है?
(A) खरीफ सीजन की शुरुआत में 6,000 रुपये के एकमुश्त भुगतान में।
(B) 3,000 रुपये प्रत्येक की दो समान किश्तों में।
(C) 2,000 रुपये प्रत्येक की तीन समान चार-मासिक किश्तों में।
(D) 500 रुपये प्रत्येक की बारह मासिक किश्तों में।

61. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) भारत में विभिन्न उद्योग क्षेत्रों की विकास स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रमुख मापदंड है। आईआईपी की गणना के लिए प्रयुक्त वर्तमान आधार वर्ष क्या है?
(A) 2004-05
(B) 2011-12
(C) 2015-16
(D) 2019-20

62. "स्किल इंडिया मिशन" का उद्देश्य कौशल विकास को औद्योगिक आवश्यकताओं से जोड़ना है। इस मिशन के तहत कौन-सी प्रमुख योजना युवाओं को अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है और उन्हें उद्योग-प्रासंगिक भूमिकाओं के साथ संरेखित करती है?
(A) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
(B) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन
(C) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
(D) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

Downloaded from www.pdf.tube

63. एमएसएमई को संस्थागत ऋण तक पहुंच से रोकने वाली समपाश्विक आवश्यकताओं की समस्या को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने एक विशिष्ट ट्रस्ट फंड की स्थापना की। इसका नाम क्या है?
(A) नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कॉर्पोरेशन
(B) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)
(C) सॉवरेन वेल्थ फंड एंड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एजेंसी
(D) एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कॉर्पोरेशन

64. समर्पित माल गलियारे (डीएफसी) औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे रसद लागत कम करते हैं। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके साथ संरेखित है?
(A) पूर्वी समर्पित माल गलियारा
(B) पश्चिमी समर्पित माल गलियारा
(C) उत्तर-दक्षिण समर्पित माल गलियारा
(D) ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर

65. भारतीय उद्योग में "वामनता" (ड्वार्फिज्म) शब्द किस घटना को संदर्भित करता है?
(A) विनियामक अनुपालन से बचने के लिए रोजगार और टर्नओवर में फर्मों का छोटा बना रहना
(B) अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में औद्योगिक संयंत्रों का भौतिक रूप से छोटा रहना
(C) सभी क्षेत्रों में नए उद्यमशीलता स्टार्टअप में एक तीव्र और निरंतर गिरावट
(D) अस्थायी अल्पकालिक मौसमी श्रम अनुबंधों पर विशेष परिचालन निर्भरता

66. ई-नाम पहल के तहत एक प्रमुख सुधार मंडियों में "गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं" की स्थापना है। इन प्रयोगशालाओं का मूल उद्देश्य क्या है?
(A) राज्य बाजार शुल्कों और व्यापारिक उपकरों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से गणना करना
(B) रोपण से पहले कृषि भूखंडों की मिट्टी के पोषक तत्वों के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना
(C) रिमोट इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाने में सक्षम बनाने के लिए फसल की गुणवत्ता के मापदंडों का ग्रेडिंग करना
(D) अवैध आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज लॉट के लिए स्थानीय बाजारों की जांच करना

67. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?
(A) यह योजना गैर-ऋणी किसानों सहित सभी किसानों के लिए पूरी तरह से अनिवार्य है।
(B) यह फसल के नुकसान के खिलाफ व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है, जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है।
(C) यह खेत में सूखने के लिए रखी गई फसलों के लिए एक निर्दिष्ट अवधि तक कटाई के बाद के नुकसान को कवर करती है।
(D) यह फसल के नुकसान का त्वरित अनुमान लगाने के लिए स्मार्टफोन और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करती है।

68. भारत में कृषि विपणन सुधारों पर बहस ने विभिन्न विनियामक दृष्टिकोणों को उजागर किया। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 का प्राथमिक उद्देश्यों में से एक था:
(A) एपीएमसी मंडियों को गैर-कानूनी घोषित करना और सभी क्षेत्रों में तत्काल बंदी लागू करना
(B) निजी खरीदारों द्वारा सभी कृषि फसलों की खरीद के लिए कानूनी मूल्य गारंटी अनिवार्य करना
(C) कृषि व्यापार का राष्ट्रीयकरण करना और बाजारों में निजी उद्यम की भागीदारी को प्रतिबंधित करना
(D) भौतिक एपीएमसी मंडी परिसरों के बाहर व्यापार करने वाले खरीदारों और विक्रेताओं के लिए विकल्प/चयन को सक्षम करना

69. एमएसएमई के लिए, प्राप्य राशियों की त्वरित वसूली उनकी कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख मुद्दा है। कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों से एमएसएमई के व्यापार प्राप्य बिलों की डिस्काउंटिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए आरबीआई द्वारा कौन-सा प्लेटफॉर्म पेश किया गया था?
(A) ई-कुबेर
(B) टीआरईडीएस (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम)
(C) एनईएफटी
(D) उद्यम असिस्ट पोर्टल

70. भारत में कृषि क्षेत्रक की स्थिति की एक बड़ी आलोचना इसकी कम उत्पादकता है। वह कौन-सी मौलिक क्रियाविधि है जिसके द्वारा भूमि का विखंडन सीधे कृषि उत्पादकता को कम करता है?
(A) यह किसानों को आवश्यक खाद्य फसलों के स्थान पर नकदी फसलों के उत्पादन को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर करता है
(B) यह छोटे भूखंडों के लिए सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी को स्वचालित रूप से अमान्य कर देता है
(C) यह कृषि यांत्रिकीकरण, आधुनिक सिंचाई और बड़े पैमाने की बचत को अव्यवहारिक बना देता है
(D) यह मिट्टी के जैविक तत्व के स्तर को अत्यधिक बढ़ा देता है, जिससे फसल को व्यापक नुकसान होता है

71. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा संशोधित अनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले समपाश्विक-मुक्त कृषि ऋण की अधिकतम सीमा क्या है?
(A) 50,000 रुपये
(B) 1.0 लाख रुपये
(C) 1.6 लाख रुपये
(D) 3.0 लाख रुपये

NODIA

72. एमएसएमई क्षेत्रक के विनियामक अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के लिए, उद्यम पंजीकरण पोर्टल पूरी तरह से निम्नलिखित में से किस सरकारी डेटाबेस के साथ एकीकृत है?
(A) आयकर और जीएसटीआईएन पहचान नेटवर्क
(B) केंद्रीय पीएम-किसान ग्रामीण लाभार्थी डेटाबेस
(C) मतदाता पहचान पत्र डेटाबेस
(D) मनरेगा राष्ट्रीय जॉब कार्डधारक रजिस्ट्री

73. निम्नलिखित में से कौन-सा 'आत्मनिर्भर भारत' रणनीति का एक अपेक्षित घटक/विशेषता नहीं है?
(A) 'वोकल फॉर लोकल' के तहत क्षेत्रीय घरेलू उत्पादों को वैश्विक बाजारों में बढ़ावा देना
(B) स्थायी आयात शुल्क बाधाओं के साथ 1991 से पूर्व की संरक्षणवादी नीति को बहाल करना
(C) रणनीतिक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विस्तार करना
(D) राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों को मजबूत करते हुए कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार करना

74. उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना मुख्य रूप से पात्र विनिर्माण कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन कैसे वितरित करती है?
(A) घरेलू वस्तुओं की संचयी/वृद्धिधर्मी बिक्री पर प्रतिशत प्रोत्साहन देकर
(B) औद्योगिक संयंत्र के निर्माण से पहले अग्रिम नकद सब्सिडी देकर
(C) दस राजकोषीय वर्षों में पूर्ण कॉर्पोरेट आयकर छूट प्रदान करके
(D) विनिर्माण फर्मों द्वारा किए गए कुल भूमि अधिग्रहण व्यय की प्रतिपूर्ति करके

75. "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम का स्पष्ट उद्देश्य बुनियादी ढांचे की बाधाओं को दूर करना है। वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किए गए विनिर्माण के लिए समर्पित क्षेत्रों वाले एक भौगोलिक रूप से क्लस्टर किए गए, व्यापक बुनियादी ढांचे के सेटअप का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है?
(A) प्राथमिक कृषि ऋण सहकारिताएं
(B) क्षेत्रीय कृषि विज्ञान विकास केंद्र
(C) विशेष आर्थिक एवं विनिर्माण क्षेत्र
(D) उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

76. भारत सरकार द्वारा "मेक इन इंडिया" पहल औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू की गई थी?
(A) 2011
(B) 2014
(C) 2017
(D) 2020

77. कृषि में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) इस क्षेत्रक के स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है। कृषि में सार्वजनिक क्षेत्रक के जीसीएफ में गिरावट का रुझान क्या दर्शाता है?
(A) प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं और कृषि अनुसंधान की ओर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि
(B) सभी कृषि योग्य भूमि के पूर्ण निजीकरण की ओर व्यापक नीतिगत बदलाव
(C) चरम कृषि उत्पादकता स्तर तक पहुंचना जिससे आगे सार्वजनिक पूंजी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है
(D) सार्वजनिक धन का दीर्घकालिक परिसंपत्ति निर्माण से अल्पकालिक इनपुट सब्सिडी की ओर स्थानांतरण

78. निम्नलिखित में से कौन-सा मापदंड विश्व बैंक के सुगम व्यापार स्कोर की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 10 सूचकों का हिस्सा नहीं था?
(A) संपत्ति का पंजीकरण
(B) करों का भुगतान
(C) श्रम हड़तालों का आयोजन
(D) अनुबंध लागू करना

79. पीएम-किसान योजना लाभार्थियों की पहचान के उद्देश्य से "परिवार" को परिभाषित करती है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, परिवार का गठन किससे होता है?
(A) आयु या वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना एक ही छत के नीचे रहने वाला एक संयुक्त परिवार।
(B) पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे।
(C) एक सामान्य राशन कार्ड साझा करने वाले व्यक्तियों का कोई भी समूह।
(D) एक वयस्क पुरुष, उसके माता-पिता और उसकी अविवाहित बहनें।

80. शिक्षुता अधिनियम, 1961 का संशोधन 'स्किल इंडिया' पहल के तहत एक महत्वपूर्ण कदम था। उद्योग की आवश्यकताओं के संदर्भ में इस संशोधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?
(A) औद्योगिक फर्मों को उत्पादन सुविधाओं में शिक्षुओं को संलग्न करने से रोकना
(B) सभी शिक्षुओं के लिए वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के पारिश्रमिक पैकेज अनिवार्य करना
(C) प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल वित्तीय लागत को राज्य सरकारों को स्थानांतरित करना
(D) उद्योग के कौशल अंतरालों को पाटने के लिए युवाओं को संलग्न करने वाली फर्मों को लचीलापन प्रदान करना

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Flipkart

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (A) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इस क्षेत्रक की हिस्सेदारी में निरंतर गिरावट आई है, फिर भी यह कार्यबल के सबसे बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करना जारी रखे हुए है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्रक की संरचनात्मक असमानता का मुख्य कारण सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार आवंटन के बीच का असंतुलन है। स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान निरंतर घटकर लगभग 15 से 18 प्रतिशत के बीच आ गया है। इसके विपरीत, देश की कुल कार्यशक्ति का लगभग 45 से 50 प्रतिशत हिस्सा आज भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यह स्थिति प्रति व्यक्ति आय को सीमित करती है।

2. (C) P-2, Q-4, R-1, S-3
भारत में कृषि विकास हेतु अनेक योजनाएं संचालित हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक जोखिमों से हुई फसल क्षति का बीमा संरक्षण देती है। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कृषकों को समय पर अल्पकालिक संस्थागत ऋण सुलभ कराने का कार्य करती है।

3. (A) राजस्थान का औसत जोत आकार राष्ट्रीय औसत (लगभग 1.08 हेक्टेयर) की तुलना में काफी अधिक (लगभग 2.73 हेक्टेयर) है।
कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार भारत में औसत क्रियात्मक जोत का आकार 1.08 हेक्टेयर दर्ज किया गया है। इसके विपरीत राजस्थान में विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल और शुष्क जलवायु परिस्थितियों के कारण औसत जोत का आकार लगभग 2.73 हेक्टेयर है। यद्यपि राजस्थान में जोत का आकार राष्ट्रीय औसत से अधिक है, फिर भी राज्य में लगातार हो रहे पारिवारिक विभाजन के कारण भूमि विखंडन की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

4. (D) I, II और III
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्रक की हिस्सेदारी पिछले तीन दशकों से लगभग 15 से 17 प्रतिशत के आसपास स्थिर बनी हुई है। इस ठहराव के पीछे प्रमुख कारणों में कृषि से सीधे सेवा क्षेत्रक की ओर संक्रमण, समयपूर्व वि-औद्योगिकीकरण, जटिल विनियामक अनुपालन तथा उच्च रसद लागत सम्मिलित हैं। इन बाधाओं ने विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता के पूर्ण दोहन और त्वरित औद्योगिक वृद्धि को निरंतर बाधित किया है।

5. (B) वे किसान परिवार जिनके एक या अधिक सदस्य संसद के पूर्व या वर्तमान सदस्य हैं
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत समाज के उच्च आय वर्ग और संवैधानिक पदधारकों को वित्तीय सहायता के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके नियमों के अनुसार जिन किसान परिवारों के सदस्य संसद के पूर्व या वर्तमान सदस्य, मंत्री, विधायक या संवैधानिक पदों पर आसीन हैं, उन्हें यह आय सहायता नहीं दी जाती है। इस बहिष्करण का मुख्य उद्देश्य केवल जरूरतमंद और वास्तविक कृषकों को लाभ पहुंचाना है।

6. (C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना भारत में घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने और निर्यात बढ़ाने हेतु शुरु की गई है। यह योजना उद्योगों को स्थिर पूंजी सब्सिडी प्रदान नहीं करती, बल्कि पात्र इकाइयों को भारत में निर्मित वस्तुओं की अतिरिक्त बिक्री पर प्रोत्साहन देती है। इस प्रकार, प्रोत्साहन का निर्धारण वास्तविक उत्पादन में हुई वृद्धि के आधार पर किया जाता है न कि संयंत्र स्थापना के आधार पर।

7. (D) 63वीं
विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली डूइंग बिजनेस रिपोर्ट व्यावसायिक नियमों और प्रक्रियाओं के मूल्यांकन का वैश्विक मापदंड थी। भारत ने निरंतर प्रशासनिक और व्यापारिक सुधारों के बल पर उल्लेखनीय प्रगति की। अंतिम डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में भारत ने 190 देशों में 63वीं रैंक हासिल की थी। वर्ष 2014 में भारत 142वें स्थान पर था, जहाँ से उसने व्यापार सुगमता में व्यापक सुधार दर्शाया।

NODIA

8. (A) 3, 1, 2
वर्ष 2020 में संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का पुनर्वर्गीकरण संयंत्र और मशीनरी में निवेश के आधार पर किया गया है। सूक्ष्म उद्यमों के लिए निवेश सीमा 1 करोड़ रुपये तक निर्धारित है। लघु उद्यमों के लिए यह सीमा 10 करोड़ रुपये तक है, जबकि मध्यम उद्यमों के लिए निवेश सीमा 50 करोड़ रुपये तक है। अतः निवेश सीमा के अनुसार आरोही क्रम सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम है।

9. (B) असमान मोलभाव की क्षमता के कारण कॉर्पोरेट प्रायोजकों द्वारा सम्भावित शोषण
अनुबंध कृषि के अंतर्गत किसान और खरीदार के बीच पूर्व-निर्धारित शर्तों पर समझौता होता है। भारत में छोटे और सीमांत किसानों के पास सीमित संसाधन और कानूनी जानकारी होती है। इस कारण बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों और प्रायोजकों के साथ बातचीत में किसानों की मोलभाव करने की क्षमता काफी कमज़ोर होती है। इससे अनुबंधों की शर्तों में विवाद उत्पन्न होने पर किसानों के शोषण की सम्भावना बनी रहती है।

10. (B) एमएसएमई के लिए एक ऑनलाइन, कागजरहित, शून्य-लागत स्व-घोषणा पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान करना
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में उद्यम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई इकाइयों को एक सरल, पूर्णतः ऑनलाइन, डिजिटल, कागजरहित और निपुण पंजीकरण प्रणाली प्रदान करना है। स्व-घोषणा के आधार पर संचालित यह प्रक्रिया व्यवसाय शुरु करने संबंधी प्रशासनिक अनुपालन को सुगम बनाती है और उद्यमियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है।

11. (A) केवल I, II और III
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए रियायती प्रीमियम दरें निर्धारित हैं। खरीफ फसलों हेतु अधिकतम प्रीमियम बीमित राशि का 2 प्रतिशत, रबी फसलों हेतु 1.5 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक और बागवानी फसलों हेतु 5 प्रतिशत है। शेष बीमांकिक प्रीमियम का भुगतान केवल केंद्र सरकार अकेले नहीं करती, बल्कि यह व्यय भार केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है।

12. (C) लगभग 14-18 प्रतिशत से घटाकर 8-9 प्रतिशत के आसपास एक अंक में लाना
राष्ट्रीय रसद नीति (2022) का प्रमुख लक्ष्य भारत में माल परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार करना है। भारत में वर्तमान रसद लागत सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 14 से 18 प्रतिशत है, जो विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक है। इस नीति का उद्देश्य इस उच्च रसद व्यय को घटाकर सकल घरेलू उत्पाद के 8 से 9 प्रतिशत तक लाना है।

13. (D) P-2, Q-1, R-4, S-3
भारत के औद्योगिक गलियारे देश में क्षेत्रीय विकास को गति प्रदान करते हैं। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा राजस्थान से होकर व्यापक रूप से गुजरता है जिसमें खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना केंद्र शामिल हैं। अमृतसर-कोलकाता गलियारा मुख्य रूप से पूर्वी समर्पित माल गलियारे के साथ जुड़ा है। चेन्नई-बेंगलुरु गलियारा दक्षिणी विनिर्माण का प्रमुख केंद्र है तथा वाइजाग-चेन्नई गलियारा ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का महत्वपूर्ण खंड है।

14. (C) वाणिज्यिक खनन कार्यों के लिए भारी मशीनरी की खरीद
किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों की कृषि से जुड़ी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसमें फसल उत्पादन व्यय, कटाई के बाद की लागत, उत्पाद विपणन, परिवार की उपभोग आवश्यकताएं तथा कृषि परिसंपत्तियों व सम्बद्ध गतिविधियों के रख-रखाव हेतु कार्यशील पूंजी शामिल हैं। गैर-कृषि या व्यावसायिक खनन हेतु भारी मशीनरी की खरीद इस योजना के स्वीकृत घटकों के अंतर्गत नहीं आती है।

15. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
भारतीय संविधान के अंतर्गत कृषि एवं कृषि विपणन मुख्य रुप से राज्य सूची का विषय है। देश के विभिन्न राज्यों में कृषि बाजारों का नियमन उनके अपने प्रादेशिक मंडी कानूनों द्वारा होता है। इसी कारण राष्ट्रीय स्तर के एकीकृत ई-नाम प्लेटफॉर्म के सफल संचालन हेतु सभी भाग लेने वाले राज्यों को अपने-अपने संबंधित अधिनियमों में ई-ट्रेडिंग की स्वीकृति हेतु आवश्यक विन्यासी संशोधन करने पड़े।

16. (A) 1 - 4 - 2 - 3
इन प्रमुख राष्ट्रीय पहलों के शुभारंभ का सही कालानुक्रमिक क्रम 2014 से 2020 के बीच है। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत सितंबर 2014 में देश को विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए की गई थी। इसके पश्चात राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में लागू की गई और आत्मनिर्भर भारत अभियान मई 2020 में घोषित किया गया था।

17. (A) किसानों द्वारा प्राप्त वास्तविक फसल उपज और सम्भावित आदर्श उपज के बीच का अंतर
कृषि विज्ञान में "उपज अंतर" से तात्पर्य किसी विशिष्ट कृषि क्षेत्र में किसानों द्वारा अपने खेतों पर प्राप्त वास्तविक फसल उत्पादकता और उन्नत कृषि तकनीकों व आदर्श स्थितियों में प्राप्त की जा सकने वाली सम्भावित उपज के बीच के अंतर से है। यह अंतर सिंचाई की कमी, घटिया गुणवत्ता के बीजों, असंतुलित उर्वरक प्रयोग तथा वैज्ञानिक खेती संबंधी ज्ञान के अभाव के कारण उत्पन्न होता है।

18. (C) इसने बाजार विखंडन, उच्च प्रवेश बाधाएं, बहु-स्तरीय शुल्क और व्यापारियों का सिंडिकेट बनाना उत्पन्न किया
पारंपरिक एपीएमसी मंडी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य किसानों को शोषण से बचाना था, किंतु समय के साथ इसमें गंभीर विकृतियां उत्पन्न हो गईं। इस प्रणाली ने बाजार का विखंडन किया और व्यापारियों के एकाधिकार व सिंडिकेट को बढ़ावा दिया। इसके अलावा, लाइसेंसिंग की कठिन प्रक्रिया, उच्च प्रवेश बाधाएं तथा बहु-स्तरीय मंडी शुल्कों व कमीशन एजेंटों के अत्यधिक प्रभारों के कारण किसानों की लाभप्रदता काफी प्रभावित हुई।

19. (A) जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना और 2022 तक 10 करोड़ (100 मिलियन) रोजगार सृजित करना।
वर्ष 2011 में स्वीकृत राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत की औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने हेतु एक महत्वाकांक्षी खाका थी। इस नीति का प्राथमिक मात्रात्मक लक्ष्य एक दशक के भीतर सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्रक का योगदान बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना था। इसके साथ ही वर्ष 2022 तक इस क्षेत्र में 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजित करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

NODIA

20. (B) केवल II और III
कोविड-19 महामारी के समय प्रारंभ किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान किसी पृथकतावादी या संरक्षणवादी सोच पर आधारित नहीं है। यह भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग करने के बजाय घरेलू विनिर्माण क्षमता मजबूत करने, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थापित करने तथा आयात निर्भरता कम करने पर बल देता है। इसमें एमएसएमई, कृषि तथा श्रम क्षेत्रों को मजबूती देने हेतु व्यापक राहत और प्रोत्साहन पैकेज दिए गए।

21. (B) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संहिता
भारत सरकार ने श्रम क्षेत्र में व्यापक सुधार करते हुए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 सुव्यवस्थित संहितों में समेकित किया है। ये चार संहिताएं हैं: मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एक कंपनी कानून संबंधी प्रावधान है, इसलिए यह भारत की स्वीकृत श्रम संहितों का भाग नहीं है।

22. (D) 100 प्रतिशत
भारत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों को अत्यधिक उदार बनाया है। वर्तमान में ग्रीनफील्ड चिकित्सा उपकरण विनिर्माण तथा अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। इसके लिए किसी पूर्व सरकारी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, जिससे घरेलू उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश और अत्याधुनिक तकनीकों के हस्तांतरण को व्यापक बढ़ावा मिलता है।

23. (D) P-1, Q-2, R-3, S-4
भारत की श्रम संहितों का उद्देश्य श्रम बाजार को आधुनिक बनाना है। मजदूरी संहिता सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी व समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता ट्रेड यूनियनों और विवाद समाधान को विनियमित करती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता गिग व प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भविष्य निधि व सामाजिक सुरक्षा देती है, तथा व्यवसायगत सुरक्षा संहिता कार्यस्थल सुरक्षा व दशाओं का समेकन करती है।

24. (A) कृषि मौसम-संचालित अस्थिरता दर्शाती है, जबकि उद्योग समष्टि आर्थिक मांग चक्रों का पालन करता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक रुझान कृषि और उद्योग के भिन्न व्यवहार को दर्शाते हैं। कृषि क्षेत्रक काफी हद तक मानसून, जलवायु परिस्थितियों और मौसमी बदलावों पर निर्भर रहता है, जिसके कारण इसमें वर्ष-दर-वर्ष अनिश्चितता और अस्थिरता देखी जाती है। इसके विपरीत, औद्योगिक क्षेत्रक का विकास समष्टि आर्थिक मांग, निवेश चक्रों, वैश्विक व्यापार प्रवृत्तियों और मौद्रिक व राजकोषीय नीतियों की गतिशीलता से प्रभावित होता है।

25. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
केंद्रीय बैंकों और अर्थशास्त्रियों द्वारा व्यापक कृषि ऋण माफी की प्रायः आलोचना की जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि ऋण माफी से किसानों में पुनर्भुगतान न करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। इससे दीर्घकालिक ऋण अनुशासन बिगड़ता है और नैतिक जोखिम उत्पन्न होता है। इसके परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली का वित्तीय स्वास्थ्य प्रभावित होता है तथा भावी बैंकिंग परिचालन में अनिश्चितता उत्पन्न होती है।

26. (C) 39 प्रतिशत
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा भारत की एक विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना है जो छह राज्यों से होकर गुजरती है। इस गलियारे का लगभग 39 प्रतिशत संरेखित क्षेत्र अकेले राजस्थान राज्य से होकर गुजरता है। इस कारण राजस्थान में भारी निवेश, औद्योगिक क्लस्टरों के निर्माण और नए रोजगार अवसरों के सृजन की अपार सम्भावनाएं विद्यमान हैं, जो राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने में सक्षम हैं।

27. (A) केवल I, II और III
विश्व बैंक की सुगम व्यापार सूचकांक रिपोर्ट व्यावसायिक वातावरण का आकलन 10 विशिष्ट मापदंडों के आधार पर करती थी। इनमें व्यवसाय शुरू करना, निर्माण परमिट प्राप्त करना, विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना, संपत्ति का पंजीकरण, करों का भुगतान तथा अनुबंध लागू करना सम्मिलित थे। विदेश नीति मामलों का संचालन एक संप्रभु सरकारी कार्य है, अतः यह व्यापार सुगमता के मूल्यांकन मापदंडों में शामिल नहीं था।

28. (A) 3, 2, 1, 4
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में एक स्पष्ट तार्किक चरणबद्ध प्रक्रिया का पालन किया जाता है। सर्वप्रथम राज्य सरकारें फसलों और क्षेत्रों को अधिसूचित करती हैं। इसके पश्चात पात्र किसान अपने प्रीमियम अंश का भुगतान करके योजना में नामांकन कराते हैं। किसी आपदा या प्रतिकूल स्थिति के कारण फसल नुकसान होने पर उसका सटीक आकलन किया जाता है और अंत में सीधे खाते में दावा राशि अंतरित होती है।

29. (D) सभी भारी औद्योगिक विनिर्माण फर्मों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण
वर्ष 2014 में शुरू की गई 'मेक इन इंडिया' पहल का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण और डिजाइन का केंद्र बनाना है। यह पहल मुख्य रूप से चार स्तंभों पर आधारित है: नई प्रक्रियाएं (प्रशासनिक सुगमता), नया बुनियादी ढांचा (औद्योगिक गलियारे), नए क्षेत्रक (एफडीआई उदारीकरण) तथा नई सोच (प्रशासक के बजाय सुगमकर्ता की भूमिका)। इसमें निजी फर्मों के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रावधान शामिल नहीं है।

30. (C) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी)
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद भारत में व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण तथा कौशल विकास का शीर्ष नियामक निकाय है। इसकी स्थापना देश में कौशल

Downloaded from www.pdf.tube

प्रशिक्षण के मानकों को एकीकृत करने, प्रमाणन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने तथा औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु की गई है। यह निकाय विभिन्न कौशल निकायों का भी नियमन करता है।

31. (B) P-1, Q-3, R-2, S-4
भारत की एफडीआई नीति विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न निवेश सीमाओं को अनुमत करती है। कृषि की विशिष्ट गतिविधियों (जैसे पुष्प कृषि व बीज उत्पादन) में स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई अनुमत है। मल्टी-ब्रांड रिटेल में 51 प्रतिशत एफडीआई केवल सरकारी मार्ग से स्वीकृत है। रक्षा क्षेत्र में शर्तों के अधीन स्वचालित मार्ग से 74 प्रतिशत तथा ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस मॉडल में 100 प्रतिशत एफडीआई स्वीकृत है।

32. (D) विनिर्माण क्षेत्रक अधिशेष श्रम के लिए श्रम-गहन रोजगार सृजित करने में विफल रहा है
अर्थशास्त्र का लुईस मॉडल यह मानता है कि विकासशील देशों में कृषि का अधिशेष श्रम आधुनिक विनिर्माण क्षेत्रक में स्थानांतरित होता है। भारत में यह संरचनात्मक रूपांतरण धीमा रहा है क्योंकि भारत का विनिर्माण क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में श्रम-गहन नौकरियों का सृजन नहीं कर सका। भारत में विकास सीधे कृषि से पूंजी-गहन सेवा क्षेत्रक की ओर स्थानांतरित हो गया, जिससे कृषि पर श्रम का अत्यधिक दबाव बना रहा।

33. (A) केवल I और II
भारत की कृषि संगणना के अनुसार क्रियात्मक जोतों को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली जोतों को सीमांत जोत कहा जाता है, जबकि 1 से 2 हेक्टेयर के बीच की जोतों को छोटी या लघु जोत माना जाता है। 2 से 4 हेक्टेयर की जोतें अर्ध-मध्यम कहलाती हैं, जबकि 10 हेक्टेयर से अधिक आकार वाली जोतें बड़ी श्रेणी में आती हैं।

34. (C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रक रोजगार सृजन का प्रमुख इंजन है। कृषि के बाद यह क्षेत्र देश में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। हालांकि, एमएसएमई क्षेत्रक मुख्य रूप से श्रम-गहन प्रकृति का है न कि अत्यधिक पूंजी-गहन। कम पूंजी निवेश के साथ अधिक रोजगार पैदा करने की क्षमता ही इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख विशेषता है, जो इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाती है।

35. (A) यह पूरी तरह से (100%) भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। "केंद्रीय क्षेत्रक योजना" का तात्पर्य यह है कि इस योजना का शत-प्रतिशत (100%) वित्तीय पोषण सीधे भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा कोई वित्तीय अंशदान नहीं दिया जाता। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश केवल पात्र किसान परिवारों की पहचान करने तथा उनके डेटा को सत्यापित करने का कार्य करते हैं।

36. (A) 2 - 3 - 1
भारत में कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने वाले संस्थागत स्रोतों में वाणिज्यिक बैंक सबसे अग्रणी हैं। कृषि ऋण के कुल वितरण में सबसे बड़ा हिस्सा वाणिज्यिक बैंकों का है, जिसके बाद सहकारी बैंकों का स्थान आता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तीसरे स्थान पर आते हैं। अतः संस्थागत कृषि ऋण वितरण में उनके अंश के आधार पर सही अवरोही क्रम वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है।

37. (B) लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी)
इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) का क्रियान्वयन और प्रबंधन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ द्वारा किया जाता है। एसएफएसी ई-नाम प्लेटफॉर्म को लागू करने वाली मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करती है। यह संस्था सॉफ्टवेयर के संचालन, मंडियों को जोड़ने, तकनीकी सहायता प्रदान करने तथा राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रमुख कार्य करती है।

38. (C) 2018
केंद्र सरकार ने भारत में अनुबंध कृषि को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए वर्ष 2018 में एक मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम जारी किया था। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल उत्पादन पूर्व निश्चित दरों पर बिक्री का आश्वासन देना तथा उनके भूमि अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस मॉडल अधिनियम को अपनाने हेतु राज्यों को उनके स्थानीय कृषि विपणन ढांचे के अनुसार प्रेषित किया गया था।

NODIA

39. (A) केवल I, II और IV
भारत के ऐतिहासिक और जटिल श्रम कानूनों ने विनिर्माण इकाइयों के विस्तार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। विनियामक अनुपालन और कठोर नियमों से बचने के लिए कई फर्मों ने छोटा बना रहना पसंद किया, जिसे आर्थिक सर्वेक्षणों में "वामनता" कहा गया है। इन विनियामक जटिलताओं के कारण औपचारिक रोजगार के विस्तार में रुकावट आई तथा उद्योगों ने श्रम के स्थान पर स्वचालित पूंजी और ऑटोमेशन को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया।

40. (A) विनिर्माण जीडीपी का 33% और कुल निर्यात का 45%
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रक भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐतिहासिक आंकड़ों और आर्थिक समीक्षा के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र भारत के कुल विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 33 प्रतिशत का योगदान देता है। इसके अतिरिक्त, देश से होने वाले कुल वस्तुओं के निर्यात में इस क्षेत्रक की हिस्सेदारी लगभग 45 प्रतिशत है, जो इसके व्यापक आर्थिक महत्व को दर्शाती है।

41. (B) किसी व्यक्ति द्वारा चोरी या दुर्भावनापूर्ण क्षति के कारण फसल का नुकसान
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत गैर-निवारण योग्य प्राकृतिक जोखिमों से होने वाली फसल क्षति को कवर किया जाता है। इसमें प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, कीट प्रकोप, रोकी गई बुवाई और कटाई के बाद प्राकृतिक कारणों से हुआ नुकसान शामिल हैं। परंतु मानवीय दुर्भावना, चोरी, दंगे या जानबूझकर पहुंचाई गई क्षति को इस योजना के तहत बीमा कवर के लिए पात्र जोखिम नहीं माना जाता।

42. (A) कृषि उपज बाजार समिति (एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी)
भारतीय कृषि व्यवस्था में एपीएमसी (APMC) का पूर्ण रूप कृषि उपज बाजार समिति (एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी) है। यह राज्य सरकारों द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जिसे कृषि उत्पादों के व्यापार, विपणन, खरीद-बिक्री तथा मंडी शुल्क संग्रह को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है। इसका प्राथमिक ध्येय मंडियों में पारदर्शी व्यापार प्रक्रिया स्थापित करना और किसानों को शोषणमुक्त मंच प्रदान करना है।

43. (C) विभिन्न बाजार क्षेत्रों और राज्य सीमाओं में बहु-स्तरीय मंडी शुल्कों और उपकरों का लगाया जाना
पारंपरिक एपीएमसी अधिनियमों के तहत कृषि विपणन में बाजार विखंडन का सबसे बड़ा कारण राज्यों द्वारा अलग-अलग बाजार क्षेत्रों में लगाए जाने वाले बहु-स्तरीय मंडी शुल्क, विकास उपकर और लाइसेंसिंग शर्तें थीं। एक बाजार क्षेत्र से दूसरे में या अंतर-राज्यीय स्तर पर कृषि उत्पाद ले जाने पर बार-बार शुल्क चुकाने पड़ते थे, जिससे पूरे देश में एक एकीकृत कृषि बाजार का निर्माण बाधित हुआ।

44. (D) मोबाइल फोन और घटकों का बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण
भारत सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र, विशेषकर मोबाइल फोन और उनके घटकों के बड़े पैमाने पर विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना, वैश्विक दिग्गजों को भारत में इकाइयां स्थापित करने हेतु आकर्षित करना और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के घरेलू विनिर्माण व निर्यात को तीव्र गति प्रदान करना था।

45. (A) केवल I और II
भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के समक्ष बुनियादी ढांचे संबंधी अनेक चुनौतियां हैं। अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति और वाणिज्यिक बिजली दरों पर अत्यधिक क्रॉस-सब्सिडीकरण के कारण भारत में औद्योगिक बिजली वैश्विक स्तर की तुलना में महंगी है। इसके अलावा बंदरगाहों पर अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और धीमे परिचालन समय के कारण निर्यात लागत बढ़ती है। औद्योगिक गलियारे बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु ही बनाए गए हैं।

46. (C) तीन वर्ष की अवधि के लिए राज्य के कानूनों के तहत निरीक्षणों और अनुमोदनों से अस्थायी छूट
राजस्थान सरकार द्वारा पारित एमएसएमई (स्थापना और प्रवर्तन का सुगमीकरण) अधिनियम, 2019 का उद्देश्य राज्य में नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देना है। इस कानून की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह नए एमएसएमई उद्यमों को अपनी गतिविधि शुरू करने के पश्चात प्रथम तीन वर्षों की अवधि तक राज्य के विभिन्न कानूनों के तहत आवधिक निरीक्षणों और सरकारी अनुमोदनों से छूट प्रदान करता है।

47. (B) राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011
राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (एनआईएमज़ेड) अवधारणा की परिकल्पना 'राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011' के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण नीतिगत साधन के रूप में की गई थी। एनआईएमज़ेड विशाल आकार के औद्योगिक टाउनशिप हैं, जिन्हें अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, विश्वस्तरीय सुविधाओं, भूमि उपयोग सरलीकरण तथा व्यापार अनुकूल विनियामक परिवेश के साथ विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था ताकि देश में विनिर्माण विकास को अभूतपूर्व गति दी जा सके।

48. (D) स्थानीय साहूकार और कमीशन एजेंट
भारत में कृषि ऋण के गैर-संस्थागत स्रोतों का प्रतिनिधित्व स्थानीय साहूकारों, महाजनों, व्यापारियों, कमीशन एजेंटों तथा भूस्वामियों द्वारा किया जाता है। ये स्रोत औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर होते हैं और बिना किसी विनियामक तंत्र के कार्य करते हैं। ये साहूकार अत्यधिक ब्याज दरें वसूलते हैं और प्रायः पारदर्शी शर्तों का अभाव होने के कारण छोटे व सीमांत किसानों को दीर्घकालिक ऋण जाल में उलझा देते हैं।

49. (C) केवल I, II और III
कृषि ऋण माफी पर विविध दृष्टिकोण हैं। समर्थकों का तर्क है कि इससे फसल विफलता से जूझ रहे संकटग्रस्त कृषकों को तत्काल वित्तीय राहत मिलती है। आलोचकों के अनुसार यह नैतिक जोखिम पैदा करती है जिससे सक्षम कृषक भी ऋण चुकाने में चूक करते हैं। इसके अलावा इससे राज्य के राजकोषीय संसाधनों पर दबाव पड़ता है जिससे कृषि बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय घटता है।

50. (C) राज्य एपीएमसी अधिनियम में ई-ट्रेडिंग, एकल-बिंदु शुल्क और एकीकृत राज्य लाइसेंस की अनुमति होनी चाहिए
किसी राज्य की मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) से जोड़ने के लिए तीन मुख्य विनियामक शर्तों का पालन अनिवार्य है। राज्य के एपीएमसी अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए, पूरे राज्य के लिए एक एकीकृत व्यापार लाइसेंस जारी करने का प्रावधान होना चाहिए, तथा संपूर्ण राज्य में कृषि उत्पादों की बिक्री हेतु एकल-बिंदु मंडी शुल्क की व्यवस्था लागू की जानी आवश्यक है।

Click Here to Buy book on Amazon

51. (A) अत्यधिक भूमि जोत आकार जो बड़े पैमाने की बचत की अनुमति देता है
वैश्विक स्तर की तुलना में भारतीय कृषि में उत्पादकता कम होने के कारणों में छोटी व विखंडित भूमि जोतें, वर्षा आधारित कृषि पर उच्च निर्भरता, असंतुलित उर्वरक प्रयोग तथा आधुनिक तकनीक व उच्च उपज वाले बीजों को अपनाने की धीमी दर शामिल हैं। अत्यधिक भूमि जोत का आकार भारत में मौजूद नहीं है, बल्कि भारत में जोत का छोटा आकार ही बचत प्राप्त करने में बाधक है।

52. (D) विदेशी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल करने वाला पूर्ण पृथकतावाद
आत्मनिर्भर भारत अभियान अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है: अर्थव्यवस्था (क्वांटम जंप), बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली, जीवंत जनसांख्यिकी तथा मांग। यह रणनीति वैश्विक व्यापार से पूर्ण पृथकतावाद या विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन नहीं करती, बल्कि यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की अधिक मजबूत और कुशल भागीदारी का समर्थन करती है।

53. (B) 5 करोड़ रुपये
वर्ष 2020 में लागू एमएसएमई की संशोधित परिभाषा में निवेश और वार्षिक टर्नओवर दोनों का समावेश किया गया है। किसी उद्यम को सूक्ष्म श्रेणी में वर्गीकृत होने के लिए संयंत्र व उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपये तक तथा वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक होना चाहिए। यदि वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपये की सीमा को पार कर जाता है, तो उद्यम लघु श्रेणी में स्थानांतरित हो जाता है।

54. (C) 4 प्रतिशत
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण की सामान्य ब्याज दर 9 प्रतिशत है। इसमें सरकार द्वारा 2 प्रतिशत की ब्याज छूट दी जाती है। इसके उपरांत, जो किसान नियत समय के भीतर अपने ऋण का भुगतान कर देते हैं, उन्हें 3 प्रतिशत की अतिरिक्त शीघ्र भुगतान छूट मिलती है, जिससे कृषकों हेतु प्रभावी ब्याज दर घटकर 4 प्रतिशत रह जाती है।

55. (D) रसद और लेनदेन लागत
भारतीय विनिर्माण क्षेत्रक को प्रभावित करने वाली बुनियादी ढांचागत कमियों जैसे अविश्वसनीय विद्युत आपूर्ति, खराब सड़क कनेक्टिविटी, बंदरगाहों पर देरी तथा जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण व्यवसायों को अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। आर्थिक और व्यावसायिक शब्दावली में इन अतिरिक्त लागतों को "रसद और लेनदेन लागत" कहा जाता है। यह लागत भारतीय उत्पादों की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करती है।

56. (C) 74 प्रतिशत
भारत सरकार ने देश में रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और नवीनतम प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने के लिए रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में नए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से अनुमत एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया है। 74 प्रतिशत से अधिक निवेश हेतु सरकारी मंजूरी आवश्यक होती है।

57. (D) उपर्युक्त सभी
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना भारत में कृषि ऋण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 1998 में शुरु की गई थी। इस योजना के क्रियान्वयन और निर्गमन में भारत की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली भाग लेती है। इसके अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राज्य व जिला स्तरीय सहकारी बैंक सभी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और पात्र किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं।

NODIA

58. (B) पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक बोली के माध्यम से हाजिर कीमतों का निर्धारण
कृषि विपणन और ई-नाम प्लेटफॉर्म के संदर्भ में "मूल्य खोज" का अर्थ एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तंत्र से है, जिसके द्वारा कृषि उपज की वास्तविक बाजार दर निर्धारित होती है। यह प्रक्रिया अखिल भारतीय स्तर पर खरीदारों द्वारा ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी बोली लगाकर संचालित की जाती है। इससे बिचौलियों का प्रभाव समाप्त होता है और किसानों को उनकी फसल का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त होता है।

59. (A) उन्नत कृषि यांत्रिकीकरण और कुशल सिंचाई प्रबंधन
भूमि चकबंदी का मुख्य उद्देश्य किसानों के दूर-दराज बिखरे हुए छोटे-छोटे भूखंडों को एक स्थान पर बड़े और निकटवर्ती खेत में एकत्रित करना है। सफल चकबंदी का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष लाभ यह होता है कि इससे खेतों का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे आधुनिक कृषि यंत्रों, ट्रैक्टरों तथा नलकूपों के प्रयोग से कृषि यांत्रिकीकरण और कुशल सिंचाई प्रबंधन सम्भव हो पाता है।

60. (C) 2,000 रुपये प्रत्येक की तीन समान चार-मासिक किश्तों में।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र कृषक परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय आय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि एकमुश्त न देकर चार-चार महीने के अंतराल पर 2,000-2,000 रुपये की तीन समान किश्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में आधार-संबद्ध प्रत्यक्ष लाभ अंतरण माध्यम से अंतरित की जाती है ताकि कृषि इनपुट खर्चों में सहायता मिल सके।

61. (B) 2011-12
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) भारत में खनन, विनिर्माण तथा विद्युत जैसे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की अल्पकालिक विकास दर का आकलन करने वाला एक प्रमुख समष्टि आर्थिक सूचक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले आईआईपी की गणना के लिए वर्तमान में प्रयुक्त आधार वर्ष 2011-12 है। इस आधार वर्ष को वर्ष 2017 में 2004-05 की पुरानी श्रृंखला के स्थान पर लागू किया गया था।

62. (C) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली प्रमुख योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे वे बेहतर आजीविका कमाने और औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। इसमें सफल प्रशिक्षुओं को वित्तीय पुरस्कार एवं प्रमाणन भी दिया जाता है।

63. (B) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)
भारत सरकार तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संयुक्त रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की गई। इस ट्रस्ट का प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना किसी समपाश्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के संस्थागत वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि नए उद्यम प्रोत्साहित हो सकें।

64. (B) पश्चिमी समर्पित माल गलियारा
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) भारत की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी समर्पित माल गलियारे के साथ संरेखित है। पश्चिमी माल गलियारा दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक विस्तृत है। डीएमआईसी इस गलियारे के माल परिवहन बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स हब और स्मार्ट शहरों का समग्र विकास सुनिश्चित करता है।

65. (A) विनियामक अनुपालन से बचने के लिए रोजगार और टर्नओवर में फर्मों का छोटा बना रहना
भारतीय अर्थशास्त्र और आर्थिक समीक्षा में "वामनता" शब्द का उपयोग उन औद्योगिक फर्मों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो वर्षों पुरानी होने के बावजूद आकार और रोजगार में छोटी बनी रहती हैं। भारत के जटिल श्रम कानूनों और विनियामक अनुपालन के अत्यधिक बोझ से बचने के लिए कई विनिर्माण इकाइयां जानबूझकर अपना विस्तार नहीं करती हैं, जिससे वे पिछड़ जाती हैं।

66. (C) रिमोट इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाने में सक्षम बनाने के लिए फसल की गुणवत्ता के मापदंडों का ग्रेडिंग करना
ई-नाम पहल के तहत कृषि उपज मंडियों में आधुनिक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। इन प्रयोगशालाओं का मुख्य उद्देश्य मंडियों में आने वाली फसलों के मापदंडों की वैज्ञानिक जांच और ग्रेडिंग करना है। फसल की गुणवत्ता का प्रामाणिक ब्योरा ऑनलाइन उपलब्ध होने से दूर-दराज के व्यापारी भी बिना मंडी पहुंचे आत्मविश्वास के साथ इलेक्ट्रॉनिक बोली लगा सकते हैं।

67. (A) यह योजना गैर-ऋणी किसानों सहित सभी किसानों के लिए पूरी तरह से अनिवार्य है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में यह धारणा असत्य है कि यह सभी किसानों के लिए अनिवार्य है। वर्ष 2020 में संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार यह योजना सभी किसानों के लिए पूरी तरह से ऐच्छिक बना दी गई है। यह योजना फसल नुकसान से व्यापक वित्तीय सुरक्षा देती है, कटाई के बाद के नुकसान को कवर करती है तथा तकनीकों का उपयोग करती है।

68. (D) भौतिक एपीएमसी मंडी परिसरों के बाहर व्यापार करने वाले खरीदारों और विक्रेताओं के लिए विकल्प/चयन को सक्षम करना
कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 का प्राथमिक उद्देश्य किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अधिक विकल्प और स्वतंत्रता प्रदान करना था। इसने राज्य एपीएमसी की अधिसूचित भौतिक मंडियों के परिसरों के बाहर कृषि उत्पादों के निर्बाध और बाधामुक्त व्यापार को सुगम बनाया, जिससे किसानों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अपनी उपज बेचने का वैकल्पिक मंच उपलब्ध हो सका।

69. (B) टीआरईडीएस (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम)
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा टीआरईडीएस (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया गया। इस प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कॉर्पोरेट खरीदारों व सरकारी संस्थाओं से प्राप्य व्यापारिक बिलों की ऑनलाइन डिस्काउंटिंग और नीलामी को सुगम बनाना है। इससे एमएसएमई इकाइयों को अपने बकाये की त्वरित वसूली होती है और उनकी कार्यशील पूंजी तरलता बनी रहती है।

70. (C) यह कृषि यांत्रिकीकरण, आधुनिक सिंचाई और बड़े पैमाने की बचत को अव्यवहारिक बना देता है
भारत में भूमि का अत्यधिक विखंडन कृषि उत्पादकता में गिरावट का एक प्रमुख कारण है। जब कृषि भूमि पीढ़ियों के विभाजन के कारण छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट जाती है, तो उन पर आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर तथा उन्नत सिंचाई तकनीकों का प्रयोग करना आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप श्रम तथा संसाधनों की बर्बादी होती है और उत्पादकता घटती है।

71. (C) 1.6 लाख रुपये
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने किसानों को बिना किसी समपाश्विक (जमानत) के संस्थागत ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बदलाव किया है। संशोधित नियमों के अनुसार समपाश्विक-मुक्त कृषि ऋण की अधिकतम सीमा को 1.0 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को बिना संपत्ति बंधक रखे ऋण मिल पाता है।

Downloaded from www.pdf.tube

72. (A) आयकर और जीएसटीआईएन पहचान नेटवर्क
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पंजीकरण को पूरी तरह से डिजिटल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल की स्थापना की गई है। यह पोर्टल भारत सरकार के आयकर और वस्तु एवं सेवा कर पहचान नेटवर्क डेटाबेस के साथ स्वतः एकीकृत है। इसके माध्यम से उद्यम का निवेश और टर्नओवर डेटा स्वतः सत्यापित हो जाता है, जिससे कागजी दस्तावेजों की आवश्यकता समाप्त होती है।

73. (B) स्थायी आयात शुल्क बाधाओं के साथ 1991 से पूर्व की संरक्षणवादी नीति को बहाल करना
आत्मनिर्भर भारत रणनीति का उद्देश्य 1991 से पूर्व की उच्च आयात शुल्क और बंद अर्थव्यवस्था वाली संरक्षणवादी नीतियों की ओर लौटना नहीं है। इसके विपरीत, यह पहल भारत की घरेलू विनिर्माण क्षमता को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने, स्थानीय उत्पादों का प्रचार करने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत के एकीकरण को सुदृढ़ करने का काम करती है।

74. (A) घरेलू वस्तुओं की संचयी/वृद्धिधर्मी बिक्री पर प्रतिशत प्रोत्साहन देकर
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत पात्र विनिर्माण कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रत्यक्ष नकद सब्सिडी या अग्रिम राशि के रूप में नहीं दिया जाता है। यह प्रोत्साहन भारत में निर्मित वस्तुओं की एक आधार वर्ष की तुलना में हुई वृद्धिधर्मी बिक्री के निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में प्रदान किया जाता है ताकि कंपनियां उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित हों।

75. (C) विशेष आर्थिक एवं विनिर्माण क्षेत्र
मेक इन इंडिया पहल के तहत औद्योगिक विकास और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने हेतु विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे से सुसज्जित एकीकृत क्षेत्रों को विकसित किया जाता है। ऐसे क्लस्टर-आधारित औद्योगिक क्षेत्रों को विशेष आर्थिक एवं विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। ये क्षेत्र उद्योग स्थापित करने के लिए निर्बाध बिजली, कनेक्टिविटी, त्वरित विनियामक मंजूरी तथा आधुनिक रसद सुविधाएं प्रदान करते हैं।

76. (B) 2014
भारत को एक वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा "मेक इन इंडिया" पहल की औपचारिक शुरुआत सितंबर 2014 में की गई थी। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का प्राथमिक ध्येय निवेश को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहित करना, कौशल विकास को मजबूत करना, बौद्धिक संपदा की रक्षा करना तथा देश में सर्वोत्तम विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना था।

77. (D) सार्वजनिक धन का दीर्घकालिक परिसंपत्ति निर्माण से अल्पकालिक इनपुट सब्सिडी की ओर स्थानांतरण
कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र की घटती हिस्सेदारी चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकारों द्वारा बजटीय संसाधनों का बड़ा हिस्सा दीर्घकालिक परिसंपत्तियों (जैसे सिंचाई नहरें, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, अनुसंधान व भंडारण) के निर्माण के स्थान पर अल्पकालिक इनपुट सब्सिडी पर अधिक व्यय किया जाता है, जिससे दीर्घकालिक क्षमता विकास प्रभावित होता है।

78. (C) श्रम हड़तालों का आयोजन
विश्व बैंक की ऐतिहासिक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसी देश में व्यावसायिक सुगमता का मूल्यांकन 10 विशिष्ट संकेतक समूहों के आधार पर करती थी। इन संकेतकों में व्यवसाय शुरु करना, निर्माण परमिट, विद्युत कनेक्शन, संपत्ति का पंजीकरण, ऋण प्राप्त करना, करों का भुगतान तथा अनुबंध लागू करना शामिल थे। श्रम हड़तालों का आयोजन या राजनीतिक विरोध प्रदर्शन इस वैश्विक मूल्यांकन सूचकांक का हिस्सा नहीं थे।

79. (B) पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु "किसान परिवार" को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। योजना के अनुसार एक परिवार का अर्थ पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चों से है। यदि किसी परिवार में इस संरचना के तहत कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व दर्ज है, तो उस पूरे परिवार को एक इकाई माना जाता है।

NODIA

80. (D) उद्योग के कौशल अंतरालों को पाटने के लिए युवाओं को संलग्न करने वाली फर्मों को लचीलापन प्रदान करना
स्किल इंडिया पहल के तहत शिक्षुता अधिनियम, 1961 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इसका प्राथमिक उद्देश्य विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की कंपनियों को अपनी जरूरतों के अनुसार शिक्षुओं को प्रशिक्षित करने और नियुक्त करने हेतु अधिक लचीलापन प्रदान करना था। इन बदलावों ने उद्योगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रक्रियाओं से सीधे जोड़कर कौशल अंतराल को दूर करने और युवाओं को अनुभव प्रदान करने में सहायता की।

www.nodia.in

अध्याय 08
सेवा व्यापार : क्षेत्र, वर्तमान स्थिति, समस्याएँ एवं पहल

1. हाल के वर्षों में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सेवा क्षेत्र का अनुमानित योगदान कितना है?
   (A) 30 प्रतिशत से कम
   (B) 35 से 45 प्रतिशत के बीच
   (C) 50 प्रतिशत से अधिक
   (D) ठीक 75 प्रतिशत

2. शास्त्रीय आर्थिक मॉडलों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प भारतीय अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक संरचनात्मक परिवर्तन का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
   (A) सेवाओं की वृद्धि दर विनिर्माण से आगे निकल गई, जिससे सेवा-संचालित संवृद्धि मॉडल का निर्माण हुआ।
   (B) सेवाओं के विस्तार से पहले आर्थिक उत्पादन में विनिर्माण का प्रभुत्व था।
   (C) राष्ट्रीय आर्थिक उत्पादन में कृषि का प्राथमिक हिस्सा बना रहा।
   (D) उद्योग और कृषि में समान रूप से वृद्धि हुई, जबकि सेवाएं स्थिर रहीं।

3. भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वर्तमान हिस्सेदारी के घटते क्रम में निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्रों के सही क्रम को निरूपित करता है?
   (A) कृषि > उद्योग > सेवाएं
   (B) सेवाएं > उद्योग > कृषि
   (C) उद्योग > सेवाएं > कृषि
   (D) सेवाएं > कृषि > उद्योग

4. भारतीय आईटी और आईटीईएस क्षेत्र मुख्य रूप से किस रूप में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है?
   (A) उच्च तकनीक वाले घरेलू आईटी हार्डवेयर विनिर्माण कार्यों का वैश्विक केंद्र
   (B) भारी औद्योगिक मशीनरी डिजाइन का प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय केंद्र
   (C) उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी प्रणालियों का दुनिया भर में एक प्रमुख निर्यातक
   (D) वैश्विक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और सॉफ्टवेयर निर्यात केंद्र

5. भारत में आईटी और आईटीईएस क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   I. यह भारत के विदेशी मुद्रा अर्जन में एक प्रमुख योगदानकर्ता है।
   II. यह अत्यधिक कुशल मानव पूंजी पर बहुत अधिक निर्भर है।
   III. यह अकुशल ग्रामीण श्रम के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (A) केवल I
   (B) केवल I और II
   (C) केवल II और III
   (D) I, II और III

6. "रोजगारहीन संवृद्धि" (जॉबलेस ग्रोथ) शब्द अक्सर सेवा क्षेत्र के कुछ उप-खंडों से जोड़ा जाता है। इस परिघटना का प्राथमिक कारण क्या है?
   (A) यह क्षेत्र अनौपचारिक श्रम पर बहुत अधिक निर्भर है जो निरंतर उत्पादकता बनाए रखने में असमर्थ है।
   (B) संवृद्धि पूंजी-गहन, कुशल उप-क्षेत्रों द्वारा संचालित होती है जो सीमित श्रम को अवशोषित करते हैं।
   (C) उच्च वार्षिक राजस्व वृद्धि के बावजूद यह क्षेत्र लंबे समय से आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है।
   (D) सरकारी नियम प्रमुख सेवा कंपनियों में पूर्णकालिक भर्ती को सख्ती से सीमित करते हैं।

7. भारत की निर्यात आय के संदर्भ में, संक्षिप्त नाम आईटीईएस का पूर्ण रूप क्या है?
   (A) इंटरनल ट्रेड एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज
   (B) इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स
   (C) इंटरनेशनल टैरिफ एंड एक्सपोर्ट सेक्रेटेरिएट
   (D) इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज

8. राजस्थान जैसे क्षेत्रों सहित भारत में पर्यटन क्षेत्र को नीति निर्माताओं द्वारा मुख्य रूप से इसलिए बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि यह:
   (A) रोजगार-गहन है और विविध श्रम कौशल स्तरों को अवशोषित करने में सक्षम है
   (B) एक पूंजी-गहन उद्योग है जो मुख्य रूप से विदेशी अवसंरचना पर निर्भर है
   (C) निजी व्यावसायिक निवेशों से पूरी तरह से स्वतंत्र होकर कार्य करता है

Click Here to Buy book on Flipkart

(D) संघीय कानून द्वारा किसी भी मानक घरेलू कर के भुगतान से मुक्त है

9. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: सेवा उप-क्षेत्र
P. पर्यटन
Q. आईटी और आईटीईएस
R. खुदरा
S. रियल एस्टेट
सूची II: प्रमुख विशेषताएं
1. प्रमुख वैश्विक आउटसोर्सिंग केंद्र
2. उच्च अनौपचारिकता और पारंपरिक संचालन
3. रोजगार-गहन विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला
4. रेरा नियामक सुधारों के अधीन
(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

10. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): पर्यटन क्षेत्र भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
कारण (R): अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आवास, यात्रा और स्थानीय हस्तशिल्प पर विदेशी मुद्रा में खर्च करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

11. भारत सरकार द्वारा शुरू की गई "स्वदेश दर्शन" योजना का प्राथमिक उद्देश्य है:
(A) मूल नागरिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय अवकाश यात्रा को सब्सिडी देना
(B) ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारकों और सार्वजनिक विरासत स्थलों का निजीकरण करना
(C) विदेशी पर्यटकों को नि:शुल्क अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा प्रदान करना
(D) भारत के प्रमुख क्षेत्रों में विषय-आधारित (थीम-बेस्ड) पर्यटक सर्किट का विकास करना

12. भारत को एक वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए "अतुल्य भारत" (इन्क्रेडिबल इंडिया) अभियान शुरू किया गया था। कौन-सा केंद्रीय मंत्रालय इस पहल का नेतृत्व करता है?
(A) विदेश मंत्रालय
(B) पर्यटन मंत्रालय
(C) संस्कृति मंत्रालय
(D) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

13. स्वदेश दर्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?
(A) इसमें विशेष पर्यटक सर्किटों का विकास शामिल है।
(B) 'डेजर्ट सर्किट' राजस्थान जैसे राज्यों के लिए लक्षित सर्किटों में से एक है।
(C) यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित है।
(D) यह पर्यटक स्थलों पर अवसंरचना और यात्री सुविधाओं में सुधार पर केंद्रित है।

14. वित्तीय सेवा क्षेत्र में, 'फिनटेक' के तीव्र विस्तार से मुख्य रूप से क्या हुआ है?
(A) डिजिटल खुदरा लेनदेन के सभी रूपों में तेजी से प्रणालीगत गिरावट
(B) पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकों का बड़े पैमाने पर संस्थागत बंद होना
(C) सीमा पार अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक हस्तांतरण पर एक सख्त वैधानिक प्रतिबंध
(D) वित्तीय समावेशन में वृद्धि और सुगम डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण

15. वित्तीय सेवा क्षेत्र के भीतर म्यूचुअल फंड का मुख्य कार्य क्या है?
(A) प्रतिभूतियों के एक विविध पोर्टफोलियो को खरीदने के लिए निवेशकों से पूंजी एकत्र करना
(B) केंद्रीय बैंक की ओर से आधिकारिक कागजी मुद्रा नोट छापना और जारी करना
(C) अनौपचारिक क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूरों को प्रत्यक्ष टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रदान करना
(D) राजकोष द्वारा रखे गए विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन, रखरखाव और नियमन करना

16. भारत में बीमा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: बीमा क्षेत्र का विस्तार वित्तीय गहनता (फाइनेंशियल डीपनिंग) में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
कथन II: बीमा क्षेत्र केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर निर्भर है, जिसमें किसी भी निजी भागीदारी की अनुमति नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

17. किसी अर्थव्यवस्था में 'वित्तीय गहनता' (फाइनेंशियल डीपनिंग) शब्द का सामान्यतः तात्पर्य है:
(A) विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए विशेष अपतटीय वित्तीय व्यापार क्षेत्रों का नीतिगत निर्माण
(B) उपकरणों के व्यापक विकल्पों के साथ वित्तीय सेवाओं

Downloaded from www.pdf.tube

के प्रावधान में वृद्धि
(C) केंद्रीय मौद्रिक अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित कुल मुद्रा आपूर्ति की प्रणालीगत तरलता में कमी
(D) खुदरा वित्तीय संस्थानों में सभी उपभोक्ता डिजिटल बैंकिंग चैनलों का क्रमिक प्रशासनिक उन्मूलन

18. भारत के सेवा क्षेत्र में "कौशल अंतर" (स्किल गैप) के मुद्दे को सबसे अच्छी तरह से किस रूप में परिभाषित किया गया है?
(A) उद्योग द्वारा मांगी गई कुशलताओं और कार्यबल के कौशल सेट के बीच बेमेल होना
(B) प्रमुख उच्च शिक्षा केंद्रों और आईटी हब को अलग करने वाली भौगोलिक दूरियां
(C) सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों में बुनियादी व्यावहारिक साक्षरता की पूर्ण अनुपस्थिति
(D) वाणिज्यिक उद्योगों में दिए जाने वाले कर्मचारी वेतनों में लिंग-आधारित असमानता

19. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) जैसी संस्थाएं मुख्य रूप से किस उद्देश्य से स्किल इंडिया मिशन के व्यापक दायरे के तहत काम करती हैं?
(A) सभी स्नातकों को प्रत्यक्ष बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना
(B) औद्योगिक श्रमिकों को कृषि नौकरियों में स्थानांतरित करना
(C) विभिन्न बढ़ते क्षेत्रों की कुशल जनशक्ति (मैनपावर) की जरूरतों को पूरा करना
(D) औपचारिक विश्वविद्यालयी शिक्षा को पूरी तरह से अल्पकालिक पाठ्यक्रमों से बदलना

20. सेवा क्षेत्र में कौशल अंतर (स्किल गैप) के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. पुराना शैक्षणिक पाठ्यक्रम जो आधुनिक उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।
II. तीव्र तकनीकी प्रगति जिसके कारण मौजूदा कौशल अप्रचलित हो रहे हैं।
III. उद्योग और अकादमिक क्षेत्र के बीच अपर्याप्त सहयोग।
IV. पारंपरिक विश्वविद्यालयों में सैद्धांतिक डिग्री की तुलना में व्यावहारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण पर अत्यधिक बल देना।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I और III
(D) I, II, III और IV

21. सेवा अर्थव्यवस्था के भीतर कौन-सा उप-क्षेत्र भारत में अनौपचारिक रोजगार के सबसे बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार है?
(A) आईटी और आईटीईएस
(B) वाणिज्यिक बैंकिंग और बीमा
(C) खुदरा व्यापार और घरेलू काम
(D) नागरिक उड्डयन और दूरसंचार

22. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): भारत में सेवा क्षेत्र एक दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है जिसका एक बड़ा खंड उच्च अनौपचारिकता द्वारा लक्षित है।
कारण (R): स्ट्रीट रिटेल (रेहड़ी-पटरी व्यापार) और घरेलू काम जैसे क्षेत्र मुख्य रूप से औपचारिक रोजगार अनुबंधों या सामाजिक सुरक्षा लाभों के बिना काम करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

23. सेवा क्षेत्र के भीतर रोजगार की औपचारिकताओं के संदर्भ में विषम (अलग) विकल्प की पहचान कीजिए:
(A) एक पंजीकृत बहुराष्ट्रीय आईटी फर्म में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर
(B) एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में एक प्रोबेशनरी ऑफिसर
(C) एक बीमा निगम में एक स्थायी दावों का समायोजक (क्लेम एडजस्टर)
(D) स्थानीय बाजार में फास्ट फूड बेचने वाला एक स्ट्रीट वेंडर (फेरीवाला)

24. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प भारत के समग्र व्यापार संतुलन की स्थिति का सटीक वर्णन करता है?
(A) वस्तु व्यापार घाटे में रहता है, जबकि सेवा व्यापार अधिशेष (सरप्लस) में बना रहता है।
(B) विदेशी व्यापार संतुलन लगातार वस्तुओं और सेवाओं के बाजारों में संरचनात्मक अधिशेष बनाए रखता है।
(C) वस्तु निर्यात व्यापार अधिशेष बनाए रखता है, जबकि सेवा आयात व्यापार लगातार घाटा पैदा करता है।
(D) विदेशी व्यापार संतुलन लगातार वस्तु और सेवा दोनों क्षेत्रों में संरचनात्मक घाटे का सामना करता है।

25. भारत के सेवा व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएं भारत के सेवा निर्यात का एक नगण्य हिस्सा हैं।
II. सेवा व्यापार अधिशेष वस्तु व्यापार घाटे की आंशिक भरपाई करने में मदद करता है।
III. विदेशों में काम कर रहे भारतीयों से प्राप्त प्रेषण (रेमिटेंस) को वस्तु व्यापार खाते का हिस्सा माना जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से गलत है/हैं?
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

NODIA

26. कौन-सा विशिष्ट सेवा उप-क्षेत्र भारत की सेवा निर्यात आय में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है?
(A) कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं
(B) वाणिज्यिक बैंकिंग, संपत्ति प्रबंधन और खुदरा वित्तीय सेवाएं
(C) आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी), अंतरराष्ट्रीय विरासत यात्रा और अवकाश पर्यटन सेवाएं
(D) अवसंरचना विकास, इंजीनियरिंग और सिविल निर्माण सेवाएं

27. भारत की विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) एफटीपी एक सदी लंबे निश्चित चक्र पर लागू किया जाता है और किसी भी अंतरिम नीति संशोधनों को सख्ती से प्रतिबंधित करता है।
(B) एफटीपी विशेष रूप से कृषि वस्तुओं के आयात को विनियमित करने, निगरानी करने और शुल्क लगाने से संबंधित है।
(C) एफटीपी सभी सेवा-संबंधित उत्पादों के निर्यात को प्रतिबंधित करने वाला एक पूर्ण वैधानिक प्रतिबंध लागू करता है।
(D) गतिशील वैश्विक व्यापार के अनुकूल होने और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एफटीपी को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

28. भारत के व्यापार नीति ढांचे में आरओडीटीईपी जैसी योजनाओं को शुरू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) सभी विदेशी आयातित इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता वस्तुओं पर काफी उच्च वैधानिक टैरिफ दरें लगाना
(B) निर्यातकों को अंतर्निहित (एम्बेडेड) केंद्रीय, राज्य और स्थानीय करों की वापसी (रिफंड) करके निर्यात को बढ़ावा देना
(C) राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा भंडार के व्यावसायिक बहिर्वाह को गंभीर रूप से प्रतिबंधित और सीमित करना
(D) आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार खुदरा मूल्य की ऊपरी सीमाओं की निगरानी और नियमन करना

29. सिंगल-विंडो प्रणाली के तहत निर्यात सुगमता चक्र के मानक तार्किक क्रम में निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित कीजिए:
1. सीमा शुल्क निकासी और शुल्क भुगतान
2. सिंगल-विंडो पोर्टल पर पंजीकरण
3. वाणिज्यिक दस्तावेजों (बीजक/इनवॉइस, पैकिंग सूची) का अपलोडिंग
4. अंतिम निकासी प्रमाण पत्र (लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर) जारी करना

निम्नलिखित में से कौन-सा सही क्रम है?
(A) 2, 3, 1, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 3, 1, 2, 4
(D) 2, 1, 3, 4

30. व्यापार सुगमता के लिए 'सिंगल-विंडो क्लीयरेंस' के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?
(A) इनका उद्देश्य व्यवसायों के लिए अनुपालन प्रसंस्करण समय और प्रशासनिक परिचालन लागत को काफी कम करना है।
(B) ये व्यापक राष्ट्रीय 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार सुगमता) ढांचे के भीतर एक मूलभूत कोर सुधार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
(C) ये एक एकीकृत केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से वैधानिक नियामक दस्तावेजों के डिजिटल सबमिशन को सक्षम बनाते हैं।
(D) ये क्रमिक रूप से कई सरकारी कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाने को अनिवार्य बनाते हैं।

31. भारत की निर्यात संवर्धन पहलों के संदर्भ में, आरओडीटीईपी का क्या अर्थ है?
(A) रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स
(B) रिफंड ऑफ डोमेस्टिक टैरिफ्स ऑन एक्सपोर्टेड प्रोड्यूस
(C) रेगुलेशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स
(D) रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन

32. भारत सरकार ने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) को आरओडीटीईपी योजना से क्यों प्रतिस्थापित किया?
(A) एमईआईएस ने आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं में व्यापक घरेलू बाजार मूल्य मुद्रास्फीति उत्पन्न की।
(B) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के व्यापार नियमों का पालन न करने के कारण एमईआईएस को चुनौती दी गई थी।
(C) आरओडीटीईपी को विशेष रूप से छोटे कृषि निर्यातकों को प्रत्यक्ष नकद सब्सिडी वितरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
(D) निर्यातकों ने उच्च कॉर्पोरेट आयकर निर्धारण दरों को शुरू करने के लिए केंद्रीय मंत्रालय से औपचारिक रूप से लॉबिंग की।

33. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: व्यापार और व्यावसायिक शब्द
P. एफटीपी
Q. आरओडीटीईपी
R. सिंगल-विंडो क्लीयरेंस
S. एमईआईएस

सूची II: विवरण
1. एक सामान्य मंच पर नियामक दस्तावेज जमा करने का तंत्र
2. डब्ल्यूटीओ अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, पूर्व निर्यात प्रोत्साहनों को बदलने के लिए शुरू की गई योजना
3. देश के आयात-निर्यात पथ को निर्देशित करने के लिए

Click Here to Buy book on Amazon

समय-समय पर संशोधित एक ढांचा
4. एक पूर्व निर्यात प्रोत्साहन योजना जिसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया था

(A) P-3, Q-2, R-1, S-4
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-2, S-4
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

34. आरओडीटीईपी योजना मुख्य रूप से "अंतर्निहित करों" (एम्बेडेड टैक्सेस) की छूट/वापसी के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका क्या अर्थ है?
(A) निर्यात उत्पादन के दौरान उपभोग किए गए ईंधन, बिजली और टिकटों पर गैर-प्रतिपूर्तियोग्य करों की वापसी करना
(B) निर्यात निगमों के शुद्ध वार्षिक राजस्व पर प्रत्यक्ष संघीय आयकर लगाना
(C) वस्तुओं के विदेशी वाणिज्यिक खरीदारों के खिलाफ सीधे नए आयात सीमा शुल्क लागू करना
(D) निर्यात फर्मों को कॉर्पोरेट करों का भुगतान करने से पूरी तरह से वैधानिक छूट प्रदान करना

35. सेवा क्षेत्र में "ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस" की अवधारणा शासन के डिजिटलीकरण पर बहुत अधिक निर्भर करती है। कौन-सी सरकारी पहल इसके लिए सीधे डिजिटल अवसंरचना प्रदान करती है?
(A) स्वच्छ भारत अभियान
(B) आयुष्मान भारत
(C) डिजिटल इंडिया
(D) पीएम किसान सम्मान निधि

36. राजस्थान जैसे राज्यों में 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार सुगमता) सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. सिंगल-विंडो क्लीयरेंस पोर्टलों का कार्यान्वयन।
II. श्रम कानून अनुपालन का सरलीकरण।
III. संपत्ति पंजीकरण का डिजिटलीकरण।
IV. सभी मामूली प्रशासनिक स्वीकृतियों के लिए अनिवार्य व्यक्तिगत निरीक्षण।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I, II और IV
(B) केवल I, II और III
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

37. सेवा क्षेत्र के संबंध में 'स्टार्टअप इंडिया' पहल की निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता नहीं है?
(A) यह स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त जैसे क्षेत्रों में तकनीक-संचालित समाधानों को प्रोत्साहित करता है।
(B) यह एक निश्चित अवधि के लिए मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को कर छूट प्रदान करता है।
(C) यदि स्टार्टअप विफल हो जाता है तो यह संस्थापकों को सरकारी नौकरियों की गारंटी देता है।
(D) इसका उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

NODIA

38. 'स्टार्टअप इंडिया' पहल प्राथमिक रूप से सेवा क्षेत्र की संवृद्धि से किस प्रकार जुड़ी हुई है?
(A) केंद्रीय सार्वजनिक वित्तपोषण को पूरी तरह से भारी इस्पात विनिर्माण और धातुकर्म प्रसंस्करण संयंत्रों की ओर निर्देशित करके
(B) प्रौद्योगिकी-संचालित प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्थाओं और सेवा एग्रीगेटर्स को प्रोत्साहित करके
(C) सभी निजी वाणिज्यिक सेवा क्षेत्र के उद्यमों और क्षेत्रीय परिवहन फर्मों का व्यवस्थित रूप से राष्ट्रीयकरण करके
(D) पूंजीगत सहायता को विशेष रूप से भारी कृषि मशीनरी और ग्रामीण सिंचाई उपकरणों तक सीमित करके

39. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): स्टार्टअप इंडिया पहल ने सेवा क्षेत्र के ई-कॉमर्स और एड-टेक खंडों को काफी बढ़ावा दिया है।
कारण (R): यह पहल नए तकनीक-संचालित उद्यमों को नियामक सुगमता, फंडिंग सहायता और इनक्यूबेशन सुविधाएं प्रदान करती है।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

40. सेवा क्षेत्र के संबंध में डिजिटल इंडिया अभियान के प्राथमिक फोकस का सबसे उपयुक्त वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना
(B) सभी स्थायी निवासियों को सीधे मुफ्त मोबाइल स्मार्टफोन वितरित करना
(C) प्रमाणित कक्षा शिक्षकों को स्वचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों से बदलना
(D) सभी घरेलू वाणिज्यिक खुदरा लेनदेन में विदेशी मुद्राओं के उपयोग को अनिवार्य बनाना

41. डिजिटल इंडिया का एक प्रमुख स्तंभ, ई-गवर्नेंस, सार्वजनिक सेवा वितरण में मुख्य रूप से कैसे सुधार करता है?
(A) सभी प्रमुख महानगरीय शहरों में भौतिक प्रशासनिक सरकारी शाखा कार्यालयों का विस्तार करके
(B) राज्य के प्रशासनिक डेटा की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक सूचना पहुंच और आधिकारिक पोर्टल पारदर्शिता को प्रतिबंधित करके
(C) भ्रष्टाचार को कम करने और प्रसंस्करण समय को छोटा

करने के लिए मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करके
(D) साइबर सुरक्षा जोखिमों को खत्म करने के लिए सार्वजनिक संस्थानों में कागजी रिकॉर्ड अभिलेखागार को अनिवार्य बनाकर

42. वित्तीय सेवाओं में आई तेजी को संचालित करने वाली भारत की डिजिटल भुगतान प्रणालियों के विकास का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) एनईएफटी/आरटीजीएस → कागजी चेक → यूपीआई → सीबीडीसी (ई-रुपया)
(B) कागजी चेक → एनईएफटी/आरटीजीएस → यूपीआई → सीबीडीसी (ई-रुपया)
(C) यूपीआई → सीबीडीसी (ई-रुपया) → कागजी चेक → एनईएफटी/आरटीजीएस
(D) कागजी चेक → यूपीआई → एनईएफटी/आरटीजीएस → सीबीडीसी (ई-रुपया)

43. डिजिटल इंडिया के मूल स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. प्रत्येक नागरिक को एक मूल उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना का निर्माण।
II. मांग पर शासन और सेवाएं।
III. सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों का पूर्ण निजीकरण।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

44. वह परिघटना जिसमें भारत की आर्थिक वृद्धि मुख्य रूप से सेवाओं द्वारा संचालित थी, जो सामूहिक विनिर्माण वृद्धि के पारंपरिक चरण को दरकिनार करती हुई प्रतीत होती है, किस रूप में जानी जाती है?
(A) दीर्घकालिक औद्योगिक विनिर्माण गतिरोध (स्टैग्नेशन)
(B) लीपफ्रॉगिंग संरचनात्मक रूपांतरण
(C) निरंतर कृषि उत्पादन प्रतिगमन
(D) अनियंत्रित अंतरराष्ट्रीय पूंजी बहिर्वाह

45. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: भारत में सेवा क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से संवृद्धि दर के मामले में कृषि और उद्योग दोनों से आगे रहा है।
कथन II: सकल घरेलू उत्पाद में उच्च हिस्सेदारी के बावजूद, कुल रोजगार में सेवा क्षेत्र का हिस्सा आनुपातिक रूप से कम है, जो औपचारिक खंडों में उच्च श्रम उत्पादकता को दर्शाता है।
निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

46. अर्थव्यवस्था में किस संरचनात्मक बदलाव के दौरान भारत के सेवा क्षेत्र के तेजी से विस्तार को प्रमुख गति मिली?
(A) 1969 के दौरान प्रमुख वाणिज्यिक बैंकिंग संस्थानों का वैधानिक संघीय राष्ट्रीयकरण
(B) 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य के विकास लक्ष्यों का सूत्रीकरण और निष्पादन
(C) हरित क्रांति के दौरान उच्च उपज वाली कृषि फसलों को देश भर में अपनाना
(D) 1991 में लागू किए गए आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण सुधार

47. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए "मांग-पक्ष प्रोत्साहन" के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह:
(A) कम आय वाले परिवारों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है, जिससे चिकित्सा सेवाओं की मांग बढ़ती है
(B) लक्जरी निजी अस्पतालों के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष केंद्रीय बजटीय अनुदान आवंटित करता है
(C) निजी चिकित्सकों को राज्य की सब्सिडी के बिना मुफ्त देखभाल प्रदान करने का आदेश देता है
(D) सार्वजनिक दवा उद्यमों को कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं बनाने का निर्देश देता है

48. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: सरकारी योजना/नीति
P. आयुष्मान भारत
Q. स्वदेश दर्शन
R. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति
S. रेरा
सूची II: लक्षित सेवा क्षेत्र
1. रियल एस्टेट
2. पर्यटन
3. परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला
4. स्वास्थ्य सेवा
(A) P-4, Q-2, R-3, S-1
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-1, Q-2, R-4, S-3

49. भारत में शिक्षा सेवाओं के संदर्भ में, हाल के दशकों में कौन-सी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है?
(A) उच्च शैक्षणिक संस्थानों से निजी कॉर्पोरेट संस्थाओं की पूर्ण वैधानिक वापसी
(B) शैक्षणिक क्षमता का विस्तार करने वाली उच्च निजी क्षेत्र की भागीदारी
(C) तकनीकी इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक केंद्रों को प्रशासनिक रूप से पूरी तरह बंद करना
(D) दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन विश्वविद्यालय डिग्री कार्यक्रमों को प्रतिबंधित करने वाले सख्त नीतिगत प्रतिबंध

Downloaded from www.pdf.tube

50. आयुष्मान भारत योजना (पीएम-जेएवाई) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?
(A) लाभार्थी सख्ती से केवल सार्वजनिक सरकारी अस्पतालों तक ही सीमित हैं।
(B) प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का वित्तीय स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करता है।
(C) माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने के चिकित्सा खर्चों को कवर करता है।
(D) जनगणना के आंकड़ों द्वारा पहचाने गए गरीब और कमजोर परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाता है।

51. भारत में 'एड-टेक' (शिक्षा प्रौद्योगिकी) सेवाओं के विस्फोटक विकास को मुख्य रूप से किसके द्वारा उत्प्रेरित किया गया था?
(A) स्कूलों में पारंपरिक आमने-सामने की कक्षा शिक्षण को प्रतिबंधित करने वाले पूर्ण वैधानिक प्रतिबंध
(B) शहरी महानगरीय क्षेत्रों में स्कूली उम्र की युवा आबादी में गंभीर जनसांख्यिकीय गिरावट
(C) स्मार्टफोन को अपनाना, कम लागत वाला डेटा और दूरस्थ शिक्षा में वृद्धि
(D) सभी छात्रों को आधुनिक व्यक्तिगत लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने का आदेश देने वाले कार्यकारी आदेश

52. सेवा क्षेत्र के भीतर "प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था" का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) स्थानीय नगरपालिका के पड़ोस के बाजारों में संचालित पारंपरिक भौतिक खुदरा दुकानें
(B) ऊंचे संरचनात्मक नींवों पर डिज़ाइन किए गए भारी औद्योगिक विनिर्माण परिसर
(C) वाणिज्यिक व्यापार वितरण को नियंत्रित करने वाले अनन्य केंद्र सरकार के प्रशासनिक एकाधिकार
(D) उपभोक्ताओं, व्यापारियों और गिग श्रमिकों को जोड़ने वाले डिजिटल ढांचे

53. सेवा क्षेत्र पर ई-कॉमर्स के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसने लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग (भंडारण) सेवाओं की आवश्यकता को काफी कम कर दिया है।
II. इसने लास्ट-माइल डिलीवरी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा किए हैं।
III. यह डिजिटल भुगतान अवसंरचना पर बहुत अधिक निर्भर करता है।
IV. यह पारंपरिक परिवहन नेटवर्क से पूरी तरह स्वतंत्र होकर कार्य करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से गलत है/हैं?
(A) केवल I और IV
(B) केवल II और III
(C) केवल I, II और IV
(D) केवल I और III

54. "गिग वर्कर" शब्द, जिसने ई-कॉमर्स और सर्विस एग्रीगेटर्स के उदय के साथ प्रमुखता हासिल की है, ऐसे कार्यकर्ता को संदर्भित करता है जो:
(A) पेंशन अधिकारों के साथ एक स्थायी, आवधिक सरकारी नागरिक सेवा पद रखता है
(B) डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मध्यस्थता वाले लचीले, गैर-स्थायी काम करता है
(C) भारी औद्योगिक मशीनरी संयंत्रों के भीतर विशेष रूप से दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता है
(D) एक बहुराष्ट्रीय फर्म के प्राथमिक बहुसंख्यक मालिक और मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करता है

55. ई-कॉमर्स क्षेत्र के तीव्र विकास का एक प्रत्यक्ष परिणाम निम्नलिखित में से किस सहायक सेवा की मांग में वृद्धि होना है?
(A) गहरी भूमिगत व्यावसायिक कोयला खनन गतिविधियां
(B) भारी औद्योगिक धातु प्रसंस्करण और धातुकर्म
(C) पारंपरिक प्रिंट समाचार पत्र और पत्रिका विज्ञापन
(D) लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और डिलीवरी सेवाएं

NODIA

56. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): ई-कॉमर्स क्षेत्र एक मजबूत और कुशल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर बहुत अधिक निर्भर करता है।
कारण (R): वस्तुओं की समय पर और लागत प्रभावी डिलीवरी ऑनलाइन खुदरा का मूल मूल्य प्रस्ताव है।
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

57. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) अनावश्यक यात्री राजमार्ग यात्रा को प्रतिबंधित करने के लिए वाणिज्यिक परिवहन टोल लागत में काफी वृद्धि करना
(B) राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले सभी निजी वाणिज्यिक ट्रकिंग बेड़ों का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण और केंद्रीकरण करना
(C) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के सापेक्ष राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स लागत को वैश्विक बेंचमार्क स्तरों तक कम करना
(D) सभी घरेलू माल परिवहन के लिए राज्य रेल नेटवर्क पर अनन्य निर्भरता लागू करने वाला वैधानिक जनादेश

58. वाणिज्यिक लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. खुदरा विक्रेता/ग्राहक तक अंतिम-मील वितरण

2. कच्चे माल/वस्तुओं की खरीद
3. वेयरहाउसिंग और भंडारण
4. लाइन-हॉल परिवहन

निम्नलिखित में से कौन-सा सही क्रम है?

(A) 2, 3, 4, 1
(B) 2, 4, 3, 1
(C) 3, 2, 1, 4
(D) 4, 2, 3, 1

59. यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य से शुरू किया गया था?

(A) विशेष रूप से घरेलू रेल पर्यटन आरक्षण के लिए एक एकीकृत डिजिटल बुकिंग सेवा पोर्टल स्थापित करना
(B) परिवहन कर्मचारियों के लिए आधार वेतन दरों और न्यूनतम मजदूरी मुआवजे को निर्धारित करने वाला वैधानिक नियम
(C) लॉजिस्टिक्स फर्मों में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश को प्रतिबंधित करने वाला एक व्यापक वैधानिक प्रतिबंध लगाना
(D) वास्तविक समय (रियल-टाइम) ट्रैकिंग और दृश्यता के लिए अंतर-मंत्रालयी लॉजिस्टिक्स डेटा को एकीकृत करना

60. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के एकल अंक वाले प्रतिशत तक कम करना है।
II. यह लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अपनाने और कौशल विकास पर केंद्रित है।
III. यह बहुविध (मल्टीमॉडल) परिवहन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

61. खुदरा सेवा क्षेत्र में, "संगठित खुदरा" की विशेषता है:

(A) अनौपचारिक स्ट्रीट वेंडिंग, सड़क किनारे के स्टॉल और आवधिक ग्रामीण साप्ताहिक बाजार व्यवस्थाएं
(B) पूरी तरह से अनौपचारिक नकद लेनदेन पर निर्भर अपंजीकृत पास-पड़ोस की किराना दुकानें
(C) औपचारिक कर अनुपालन और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं वाले कॉर्पोरेट खुदरा विक्रेता
(D) औपचारिक राष्ट्रीय मुद्रा भुगतान चैनलों के बाहर काम करने वाले पारंपरिक मुद्राहीन वस्तु-विनिमय व्यापार नेटवर्क

62. संगठित और पारंपरिक (असंगठित) खुदरा व्यापार की तुलना करते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: पारंपरिक खुदरा व्यापार की तुलना में भारत में कुल खुदरा व्यापार में संगठित खुदरा व्यापार का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कम है।

कथन II: पारंपरिक खुदरा व्यापार को आमतौर पर बड़े पैमाने पर पैमाने की बचत (इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल) और निर्माताओं से सीधे थोक खरीद का लाभ मिलता है।

निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

63. निम्नलिखित में से कौन-सी भारत में असंगठित खुदरा क्षेत्र की सामान्य विशेषता नहीं है?

(A) भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) जैसे औपचारिक कर्मचारी लाभों की उच्च डिग्री
(B) प्रवेश के लिए कम पूंजी की आवश्यकता
(C) व्यक्तिगत ग्राहक संबंध और स्थानीय उधार प्रणाली
(D) विखंडित और विकेंद्रीकृत आपूर्ति श्रृंखलाएं

64. रियल एस्टेट क्षेत्र के संदर्भ में, संक्षिप्त नाम 'रेरा' का पूर्ण रूप क्या है?

(A) रीजनल इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग एक्ट
(B) रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी
(C) रूरल एस्टेट रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी
(D) रिटेल एंड एस्टेट रेगुलेटरी एजेंसी

65. रेरा (जैसे राजस्थान में राज-रेरा) को लागू करने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य क्या था?

(A) शहरी बहुमंजिला आवासीय अपार्टमेंट परियोजनाओं में बाजार बिक्री कीमतों को व्यवस्थित रूप से बढ़ाना
(B) पारदर्शिता, डेवलपर की जवाबदेही और घर खरीदारों की सुरक्षा को बढ़ाना
(C) शहरी बाजारों से निजी रियल एस्टेट वाणिज्यिक आवास डेवलपर्स को बेदखल और समाप्त करना
(D) शहरी आवासीय भूमि भूखंडों का पुनर्वर्गीकरण करना और उन्हें कम घनत्व वाले कृषि उपयोग क्षेत्रों में परिवर्तित करना

66. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:

सूची I: नियामक/नीतिगत निकाय

P. रेरा
Q. ट्राई
R. इरडा
S. आरबीआई

सूची II: विनियमित/संवर्धित सेवा क्षेत्र

1. दूरसंचार
2. रियल एस्टेट
3. बैंकिंग और मौद्रिक नीति
4. बीमा

(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4

Click Here to Buy book on Flipkart

(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

67. रेरा के दिशा-निर्देशों के तहत, रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए खरीदारों से एकत्र की गई राशि का एक विशिष्ट प्रतिशत एस्क्रो खाते में जमा करना अनिवार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) विशेष रूप से कॉर्पोरेट डेवलपर के निजी खर्चों को वित्तपोषित करने के लिए व्यावसायिक निवेश ब्याज जमा करना
(B) निर्माण कार्य शुरू करने से पहले नगरपालिका संपत्ति करों और राज्य लाइसेंसिंग शुल्क के पूर्ण अग्रिम भुगतान को निर्देशित करना
(C) यह सुनिश्चित करना कि पूंजी निर्दिष्ट आवास परियोजना के निर्माण के लिए ही समर्पित हो
(D) एकत्र की गई पूंजी को अपतटीय विदेशी निवेशक खातों में सीधे विदेशी इलेक्ट्रॉनिक वायर ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करना

68. भारत के दूरसंचार सेवा क्षेत्र में 2016 के बाद की "डेटा क्रांति" मुख्य रूप से किसके द्वारा शुरू हुई थी?
(A) मोबाइल वॉयस कॉल पर पूरे देश में पूर्ण प्रतिबंध लागू करने वाले वैधानिक केंद्र सरकार के कार्यकारी आदेश
(B) घरेलू दूरसंचार उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत इंटरनेट डेटा उपभोग को सीमित करने वाली नियामक सीमाएं
(C) सेलुलर प्रदाताओं को आधुनिक नेटवर्क छोड़कर 2जी उपकरणों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करने वाले रणनीतिक नीतिगत निर्णय
(D) किफायती 4जी डेटा की पेशकश करने वाले एक विघटनकारी (डिस्ट्रप्टिव) ऑपरेटर का प्रवेश जिसने टैरिफ वॉर शुरू कर दिया

69. "बीमा पहुंच" (इंश्योरेंस पेनिट्रेशन) वित्तीय सेवा क्षेत्र के विकास का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख मीट्रिक है। इसे किस रूप में परिभाषित किया गया है?
(A) देश के भीतर काम कर रहे प्रमाणित सक्रिय बीमा बिक्री प्रतिनिधियों की कुल जनगणना संख्या
(B) घरेलू बीमाकर्ताओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से रखी गई इक्विटी पूंजी का वैधानिक प्रतिशत हिस्सा
(C) राष्ट्रीय जीडीपी के सापेक्ष लिखित कुल बीमा प्रीमियम का अनुपात
(D) गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों की तुलना में सक्रिय जीवन बीमा अनुबंधों का तुलनात्मक गणितीय अनुपात

70. बैंकिंग और बीमा सेवाओं की संवृद्धि में योगदान देने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. जनसंख्या में बढ़ती वित्तीय साक्षरता।
II. पीएम जन धन योजना जैसी वित्तीय समावेशन के लिए सरकारी पहलें।
III. बैंकिंग सेवाओं का डिजिटलीकरण जिससे पहुंच आसान हुई है।
IV. उच्च प्रारंभिक पूंजी आवश्यकता जो नए घरेलू निजी खिलाड़ियों के लिए प्रवेश बाधा के रूप में कार्य करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I और II
(D) I, II, III और IV

71. पिछले दशक में दूरसंचार क्षेत्र में भीषण टैरिफ वॉर का एक प्रमुख परिणाम क्या रहा है?
(A) अभूतपूर्व वैधानिक मूल्य वृद्धि जिससे आवासीय ग्राहकों के लिए मोबाइल डेटा एक्सेस लागत बढ़ गई है
(B) गंभीर बाजार विखंडन जिसने वायरलेस दूरसंचार सेवा को सैकड़ों छोटे क्षेत्रीय वाहकों में विभाजित कर दिया है
(C) राष्ट्रीय दूरसंचार बाजार से सभी निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों का तत्काल संरचनात्मक कॉर्पोरेट निकास
(D) प्रमुख सेवा प्रदाताओं के एक छोटे अल्पधिकार में बाजार का समेकन

72. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारत के सेवा क्षेत्र के संवृद्धि पथ के विरोधाभास की सही पहचान करता है?
(A) यह क्षेत्र जीडीपी में आधे से अधिक का योगदान देता है लेकिन कार्यबल के आनुपातिक रूप से बहुत छोटे हिस्से को रोजगार देता है।
(B) यह क्षेत्र उच्च रोजगार लोच प्रदर्शित करता है, जो अधिकांश जनसंख्या को रोजगार देता है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान नगण्य है।
(C) संचालन का विस्तार करने के लिए इस क्षेत्र को विशाल मात्रा में कृषि भूमि की आवश्यकता होती है।
(D) यह क्षेत्र डिजिटल तकनीक के उपयोग के बिना पूरी तरह से विकसित हुआ है।

NODIA

73. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: दूरसंचार क्षेत्र भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई-कॉमर्स तेजी की मूलभूत रीढ़ है।
कथन II: डिजिटल इंडिया पहलों के सफल कार्यान्वयन के लिए एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी दूरसंचार क्षेत्र आवश्यक है।
निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

74. आर्थिक संवृद्धि के संदर्भ में, कुछ सेवा क्षेत्रों में "रोजगारहीन संवृद्धि" विशेष रूप से यह दर्शाती है कि:
(A) अनुपातिक रोजगार सृजन के बिना जीडीपी योगदान का विस्तार होता है
(B) व्यापक समष्टि आर्थिक संकुचन जहाँ प्रमुख क्षेत्रों में वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन में गंभीर गिरावट आती है

(C) मानव संज्ञानात्मक कार्यबल के सभी रूपों को बदलने वाले पूर्ण स्वचालन के कारण संरचनात्मक श्रम बाजार की विफलता
(D) सभी सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक क्षेत्रों में कामकाजी उम्र के वयस्कों का सार्वभौमिक स्वैच्छिक इस्तीफा

75. निम्नलिखित में से कौन-सा सेवा उप-क्षेत्र अपनी अत्यधिक विशिष्ट, पूंजी-गहन प्रकृति के कारण "रोजगारहीन संवृद्धि" उत्पन्न करने की आलोचना के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है?
(A) पर्यटन और आतिथ्य
(B) खुदरा व्यापार
(C) निर्माण और रियल एस्टेट
(D) आईटी और वित्तीय सेवाएं

76. इसके विपरीत, निम्नलिखित में से कौन-सा सेवा क्षेत्र उच्च रोजगार तीव्रता के लिए जाना जाता है, लेकिन अनौपचारिकता के कारण आम तौर पर प्रति व्यक्ति श्रम उत्पादकता कम होती है?
(A) वायरलेस सेलुलर दूरसंचार और उपग्रह डेटा नेटवर्क
(B) असंगठित खुदरा व्यापार और घरेलू काम
(C) हाई-एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग और एंटरप्राइज प्रोग्रामिंग
(D) वाणिज्यिक नागरिक उड्डयन परिवहन और हवाई अड्डा लॉजिस्टिक्स प्रणाली

77. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प हाल के वर्षों में सेवा उप-क्षेत्र को उसकी प्रमुख वृद्धि प्रवृत्ति या पहल के साथ सही सुमेलित करता है?
(A) खुदरा क्षेत्र - असंगठित बाजारों का पूर्ण उन्मूलन
(B) रियल एस्टेट क्षेत्र - विनियममुक्ति और सभी आवास कानूनों का उन्मूलन
(C) लॉजिस्टिक्स - लागत में कमी और बहुविध (मल्टीमॉडल) कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करना
(D) आईटी क्षेत्र - डिजिटल सेवाओं से वापस मैनुअल बही-खाता रखने की ओर बदलाव

78. पिछली विदेश व्यापार नीतियों में, एमईआईएस का क्या अर्थ था?
(A) मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट इंसेंटिव सिस्टम
(B) मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सर्विसेज
(C) म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इंडियन सर्विसेज
(D) मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम

79. भारत की सेवा अर्थव्यवस्था में एक बड़े अनौपचारिक खंड के बने रहने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है?
(A) औपचारिक रोजगार वृद्धि कृषि से श्रम आपूर्ति के विस्तार की तुलना में पीछे रह गई
(B) औपचारिक उद्योग प्रचुर मात्रा में रोजगार के विकल्प उत्पन्न करता है, लेकिन नौकरी चाहने वाले प्रत्यक्ष कराधान से बचने के लिए अनौपचारिक व्यवस्था को प्राथमिकता देते हैं
(C) वैधानिक नियामक ढांचा असंगठित खुदरा परिचालनों को औपचारिक व्यावसायिक स्थिति में परिवर्तित होने से सख्ती से रोकता है
(D) केंद्र सरकार के व्यापार नियम प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश को औपचारिक वाणिज्यिक सेवा उद्योगों में प्रवेश करने से रोकते हैं

80. सेवा क्षेत्र के साथ उनके प्राथमिक संबंध के आधार पर प्रमुख सरकारी पहलों की निम्नलिखित सूची में से विषम (अलग) विकल्प की पहचान कीजिए:
(A) स्टार्टअप इंडिया
(B) मेक इन इंडिया
(C) डिजिटल इंडिया
(D) पीएम-जेएवाई (आयुष्मान भारत)

www.nodia.in

NODIA

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (C) 50 प्रतिशत से अधिक
भारत के आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान समय में देश के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत से अधिक है। व्यापार, परिवहन, वित्तीय सेवाएं और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे उप-क्षेत्र इस वृद्धि को गति देते हैं। इस क्षेत्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि संरचना से सीधे आधुनिक सेवा-संचालित संवृद्धि मॉडल की ओर स्थानांतरित करने में अग्रणी योगदान दिया है।

2. (A) सेवाओं की वृद्धि दर विनिर्माण से आगे निकल गई, जिससे सेवा-संचालित संवृद्धि मॉडल का निर्माण हुआ।
शास्त्रीय आर्थिक विकास मॉडल के अनुसार अर्थव्यवस्थाएं कृषि से विनिर्माण और फिर सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक संरचनात्मक परिवर्तन के दौरान विनिर्माण क्षेत्र का पूर्ण विकास होने से पहले ही सेवाओं की वृद्धि दर विनिर्माण से आगे निकल गई। इसके परिणामस्वरूप भारत में एक विशिष्ट सेवा-संचालित संवृद्धि मॉडल का निर्माण हुआ, जो कि विश्व की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के ऐतिहासिक विकास क्रम से भिन्न है।

3. (B) सेवाएं > उद्योग > कृषि
भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी का विश्लेषण करने पर एक स्पष्ट पदानुक्रम दिखाई देता है। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की है, जिसके बाद दूसरे स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र आता है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान न्यूनतम बना हुआ है। अतः घटते क्रम में सही व्यवस्था सेवाएं, उसके बाद उद्योग और अंत में कृषि क्षेत्र है।

4. (D) वैश्विक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और सॉफ्टवेयर निर्यात केंद्र
भारत का सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है। यह क्षेत्र वैश्विक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और सॉफ्टवेयर निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। कुशल तकनीकी जनशक्ति, अंग्रेजी भाषा में दक्षता और लागत लाभ के कारण विश्वभर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यावसायिक प्रक्रियाओं एवं सॉफ्टवेयर विकास के लिए भारतीय तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र पर अत्यधिक निर्भर हैं।

5. (B) केवल I और II
सूचना प्रौद्योगिकी तथा इसकी सक्षम सेवाओं का क्षेत्र विदेशी मुद्रा अर्जित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है और यह उच्च कुशल मानव पूंजी पर निर्भर करता है। हालांकि, इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर मुख्य रूप से शिक्षित और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कार्यबल तक सीमित हैं। यह अकुशल ग्रामीण श्रम बल के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करने में असमर्थ है, इसलिए केवल प्रथम दो विवरण ही तार्किक दृष्टि से सटीक हैं।

6. (B) संवृद्धि पूंजी-गहन, कुशल उप-क्षेत्रों द्वारा संचालित होती है जो सीमित श्रम को अवशोषित करते हैं।
सेवा क्षेत्र में रोजगारहीन संवृद्धि की समस्या का मुख्य कारण इसकी आंतरिक संरचना में निहित है। इस क्षेत्र की वृद्धि दर मुख्य रूप से पूंजी-गहन और अत्यधिक कुशल उप-क्षेत्रों द्वारा संचालित होती है। वित्तीय सेवाओं और सॉफ्टवेयर प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में उच्च मूल्यवर्धन होता है, परंतु वे सीमित संख्या में ही कर्मचारियों को रोजगार दे पाते हैं। इसके कारण सकल उत्पाद में वृद्धि की तुलना में रोजगार सृजन काफी कम रहता है।

7. (D) इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज
भारतीय सेवा निर्यात में आईटीईएस एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली है। इसका पूर्ण रूप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज है। इसके अंतर्गत वे सभी व्यावसायिक प्रक्रियाएं शामिल हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, जैसे कि कॉल सेंटर, बीपीओ, डेटा एनालिटिक्स और दूरस्थ बैक-ऑफिस संचालन। इस क्षेत्र ने भारत के विदेशी मुद्रा अर्जन और सेवा निर्यात वृद्धि में निर्णायक योगदान दिया है।

8. (A) रोजगार-गहन है और विविध श्रम कौशल स्तरों को अवशोषित करने में सक्षम है
राजस्थान सहित पूरे भारत में पर्यटन क्षेत्र आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है। नीति निर्माताओं द्वारा इसे मुख्य रूप से इसलिए बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक रोजगार-गहन क्षेत्र है। यह आतिथ्य, परिवहन, हस्तशिल्प और गाइड सेवाओं के माध्यम से कुशल, अर्ध-कुशल तथा अकुशल श्रम को बड़े पैमाने पर अवशोषित करता है। इससे समावेशी विकास को बल मिलता है और स्थानीय स्तर पर आय के अवसर निर्मित होते हैं।

9. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
सेवा उप-क्षेत्रों की विविध विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके विशिष्ट योगदान को दर्शाती हैं। पर्यटन क्षेत्र रोजगार-गहन होने के साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, जबकि आईटी और आईटीईएस वैश्विक आउटसोर्सिंग का केंद्र है। खुदरा क्षेत्र में उच्च अनौपचारिकता तथा पारंपरिक संचालन देखने को मिलता है। दूसरी ओर, रियल एस्टेट क्षेत्र पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए रेरा जैसे नियामक सुधारों और दिशानिर्देशों के अधीन कार्य करता है।

Downloaded from www.pdf.tube

10. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
भारत के भुगतान संतुलन को मजबूत करने में पर्यटन क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटक जब भारत की यात्रा करते हैं तो वे आवास, स्थानीय परिवहन, भोजन और हस्तशिल्प वस्तुओं की खरीदारी पर विदेशी मुद्रा व्यय करते हैं। यह प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा आवक देश के अदृश्य निर्यात का हिस्सा बनती है। इसलिए विदेशी पर्यटकों द्वारा किया जाने वाला यह व्यय सीधे तौर पर भारत की विदेशी मुद्रा आय को बढ़ाने का काम करता है।

11. (D) भारत के प्रमुख क्षेत्रों में विषय-आधारित (थीम-बेस्ड) पर्यटक सर्किट का विकास करना
स्वदेश दर्शन योजना का शुभारंभ भारत में पर्यटन अवसंरचना के सुनियोजित विकास के उद्देश्य से किया गया था। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य देश भर में विशिष्ट विषय-आधारित (थीम-बेस्ड) पर्यटक सर्किटों की पहचान करना और उनका समग्र विकास करना है। इसके अंतर्गत बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट और हिमालयन सर्किट जैसे विविध क्षेत्रों में विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जाती हैं, जिससे घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

12. (B) पर्यटन मंत्रालय
अतुल्य भारत अभियान की शुरुआत भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अग्रणी और आकर्षक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए की गई थी। इस राष्ट्रव्यापी विपणन पहल का नेतृत्व केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और विविधता का वैश्विक मंच पर प्रचार करना है, ताकि अधिक से अधिक विदेशी तथा घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।

13. (C) यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित है।
स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, न कि पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित केंद्र प्रायोजित योजना। इसके तहत विषय-आधारित पर्यटक सर्किटों के विकास और स्थलों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार के लिए संपूर्ण वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना में राजस्थान जैसे राज्यों के लिए डेजर्ट सर्किट सहित कई अन्य प्रमुख पर्यटन सर्किटों का विकास शामिल किया गया है।

14. (D) वित्तीय समावेशन में वृद्धि और सुगम डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण
वित्तीय सेवा क्षेत्र में वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी फिनटेक के विस्तार ने बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। इसके परिणामस्वरूप देश में वित्तीय समावेशन को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिला है। सुगम एवं सुरक्षित डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण से समाज के दूर-दराज के क्षेत्रों और अनौपचारिक वर्गों तक औपचारिक वित्तीय सेवाओं की पहुंच संभव हो सकी है, जिससे नकद लेनदेन पर निर्भरता घटी है।

15. (A) प्रतिभूतियों के एक विविध पोर्टफोलियो को खरीदने के लिए निवेशकों से पूंजी एकत्र करना
वित्तीय सेवा क्षेत्र के अंतर्गत म्यूचुअल फंड एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ संस्था के रूप में कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य छोटे और बड़े निवेशकों से पूंजी एकत्र करना तथा उस राशि को शेयरों, बांडों और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियों के एक विविध पोर्टफोलियो में निवेश करना होता है। व्यावसायिक फंड प्रबंधकों द्वारा इस पूंजी का संचालन किया जाता है, जिससे आम निवेशकों को कम जोखिम में बेहतर रिटर्न और विविधीकरण का लाभ प्राप्त होता है।

16. (C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
बीमा क्षेत्र का विस्तार अर्थव्यवस्था में बचत को दीर्घकालिक निवेश में बदलकर वित्तीय गहनता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, यह क्षेत्र केवल सार्वजनिक कंपनियों तक सीमित नहीं है। वर्ष 2000 में हुए सुधारों के बाद से भारत में बीमा क्षेत्र को निजी एवं विदेशी प्रतिस्पर्धियों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया था। वर्तमान में अनेक निजी कंपनियां बीमा बाजार में सक्रिय रूप से सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

17. (B) उपकरणों के व्यापक विकल्पों के साथ वित्तीय सेवाओं के प्रावधान में वृद्धि
अर्थव्यवस्था में वित्तीय गहनता का अर्थ वित्तीय परिसंपत्तियों और मध्यस्थों के आकार, विविधता तथा दक्षता में विस्तार होना है। जब किसी देश में बचतकर्ताओं और निवेशकों के लिए वित्तीय उपकरणों के व्यापक विकल्प उपलब्ध होते हैं तथा कुल जीडीपी के अनुपात में वित्तीय परिसंपत्तियों की मात्रा बढ़ती है, तो इसे वित्तीय गहनता कहा जाता है। यह प्रक्रिया संसाधनों के कुशल आवंटन और समग्र आर्थिक वृद्धि को सुगम बनाने में सहायता करती है।

18. (A) उद्योग द्वारा मांगी गई कुशलताओं और कार्यबल के कौशल सेट के बीच बेमेल होना
भारत के सेवा क्षेत्र में कौशल अंतर या स्किल गैप एक गंभीर संरचनात्मक चुनौती बनी हुई है। इसका तात्पर्य व्यावसायिक उद्योगों द्वारा मांगी जाने वाली आधुनिक कार्य-कुशलताओं और शैक्षणिक संस्थानों से निकलने वाले स्नातकों के पास उपलब्ध व्यावहारिक कौशल सेट के बीच असंतुलन या बेमेल होना है। इस अंतर के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद कई युवा रोजगार पाने में असमर्थ रहते हैं, जबकि उद्योगों को उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते।

19. (C) विभिन्न बढ़ते क्षेत्रों की कुशल जनशक्ति (मैनपावर) की जरूरतों को पूरा करना
राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम जैसी राज्य स्तरीय संस्थाएं स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत कार्य करती हैं। इनका प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये संस्थाएं विभिन्न तेजी से बढ़ते सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों

NODIA

के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करती हैं, जिससे युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होती है और उद्योगों की जनशक्ति आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं।

20. (A) केवल I, II और III
सेवा क्षेत्र में कौशल अंतर के प्रमुख कारणों में उद्योग की जरूरतों से मेल न खाने वाला पुराना शैक्षणिक पाठ्यक्रम, तीव्र तकनीकी प्रगति के कारण मौजूदा कौशलों का अप्रासंगिक होना तथा अकादमिक जगत व उद्योग के मध्य अपर्याप्त समन्वय शामिल हैं। पारंपरिक विश्वविद्यालयों द्वारा व्यावहारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण के बजाय अत्यधिक सैद्धांतिक शिक्षा पर बल देना इस अंतर को बढ़ाता है, न कि व्यावहारिक प्रशिक्षण पर बल देना। अतः प्रथम तीन विवरण सही हैं।

21. (C) खुदरा व्यापार और घरेलू काम
भारतीय सेवा अर्थव्यवस्था में एक विस्तृत अनौपचारिक खंड मौजूद है, जिसमें खुदरा व्यापार और घरेलू काम सबसे बड़े हिस्सेदार हैं। इन उप-क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारियों के पास औपचारिक रोजगार अनुबंध, निश्चित वेतन या सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध नहीं होते हैं। रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, छोटे दुकानदारों और घरेलू सहायकों की विशाल संख्या के कारण यह खंड देश में अनौपचारिक रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है।

22. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
भारत का सेवा क्षेत्र एक स्पष्ट दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है। जहाँ एक तरफ उच्च वेतन वाला अत्याधुनिक आईटी क्षेत्र है, वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर अनौपचारिक उप-क्षेत्र मौजूद हैं। स्ट्रीट रिटेल, परिवहन और घरेलू काम जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकांश व्यक्ति बिना किसी औपचारिक लिखित अनुबंध, सामाजिक सुरक्षा लाभों या पेंशन सुरक्षा के कार्य करते हैं। यही अनौपचारिक गतिविधियां सेवा क्षेत्र में दोहरेपन की स्थिति उत्पन्न करती हैं।

23. (D) स्थानीय बाजार में फास्ट फूड बेचने वाला एक स्ट्रीट वेंडर (फेरीवाला)
औपचारिक रोजगार में लिखित अनुबंध, निश्चित वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ शामिल होते हैं, जैसे बहुराष्ट्रीय फर्म का इंजीनियर, सार्वजनिक बैंक का अधिकारी तथा बीमा समायोजक। इसके विपरीत, स्थानीय बाजार में खाद्य सामग्री बेचने वाला विक्रेता असंगठित क्षेत्र में आता है। यहाँ न तो कोई औपचारिक अनुबंध होता है और न ही सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलते हैं, इसलिए यह अनौपचारिक रोजगार का सटीक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

24. (A) वस्तु व्यापार घाटे में रहता है, जबकि सेवा व्यापार अधिशेष (सरप्लस) में बना रहता है।
भारत के समग्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन की एक प्रमुख संरचनात्मक विशेषता इसका दोहरा स्वरूप है। भारत का वस्तु व्यापार या मर्चेंडाइज व्यापार लगातार बड़े घाटे का सामना करता है क्योंकि ईंधन और इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात अधिक होता है। इसके विपरीत, सॉफ्टवेयर प्रणालियों और व्यावसायिक सेवाओं के मजबूत निर्यात के बल पर भारत का सेवा व्यापार निरंतर अधिशेष में बना रहता है, जो वस्तु व्यापार घाटे को कम करता है।

25. (C) केवल I और III
सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर सेवाएं भारत के सेवा निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा निर्मित करती हैं। इसके अतिरिक्त, विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा भेजा जाने वाला धन चालू खाते के अदृश्य मदों में निजी अंतरण माना जाता है, न कि वस्तु व्यापार। चूंकि सेवा व्यापार का अधिशेष वस्तु घाटे की आंशिक भरपाई करने में सहायक होता है, इसलिए केवल प्रथम तथा तृतीय विवरण ही गलत पाए जाते हैं।

26. (A) कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं
भारत की कुल सेवा निर्यात आय में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का योगदान सर्वाधिक है। सॉफ्टवेयर विकास, आईटी परामर्श, सिस्टम एकीकरण और बीपीओ सेवाओं के माध्यम से भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में एक प्रमुख स्थिति बनाए हुए हैं। यह विशिष्ट उप-क्षेत्र देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सशक्त बनाने और वैश्विक सेवा व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को निरंतर बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

27. (D) गतिशील वैश्विक व्यापार के अनुकूल होने और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एफटीपी को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
भारत की विदेश व्यापार नीति अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य में होने वाले बदलावों के अनुरूप ढलने के लिए एक गतिशील ढांचा प्रदान करती है। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुकूल होने तथा देश की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को निरंतर बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इस नीति को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। इसका उद्देश्य निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

28. (B) निर्यातकों को अंतर्निहित (एम्बेडेड) केंद्रीय, राज्य और स्थानीय करों की वापसी (रिफंड) करके निर्यात को बढ़ावा देना
भारत सरकार द्वारा शुरु की गई आरओडीटीईपी योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस योजना के माध्यम से निर्यातित वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया में लगने वाले उन अंतर्निहित केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय करों व शुल्कों की वापसी की जाती है, जो किसी अन्य तंत्र के तहत प्रतिपूर्तियोग्य नहीं होते हैं। इससे करों का निर्यात रोकने में मदद मिलती है।

29. (A) 2, 3, 1, 4
व्यापार सुगमता के तहत सिंगल-विंडो प्रणाली में प्रक्रियाओं का एक निर्धारित तार्किक क्रम होता है। सर्वप्रथम व्यवसायों को सिंगल-विंडो पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होता है। इसके पश्चात आवश्यक वाणिज्यिक दस्तावेजों जैसे बीजक और पैकिंग सूची को अपलोड किया जाता है। अगली चरण में

Click Here to Buy book on Amazon

सीमा शुल्क निकासी और संबंधित शुल्कों का भुगतान संपन्न होता है। अंत में, प्राधिकारियों द्वारा माल के प्रस्थान हेतु अंतिम निकासी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

30. (D) ये क्रमिक रूप से कई सरकारी कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाने को अनिवार्य बनाते हैं।
व्यापार सुगमता का मुख्य ध्येय लालफीताशाही और प्रशासनिक जटिलताओं को समाप्त करना है। इसके लिए लागू की गई सिंगल-विंडो क्लीयरेंस प्रणाली व्यापारियों को एक ही डिजिटल मंच पर सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की सुविधा देती है। यह प्रणाली विभिन्न सरकारी कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाने की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त करती है, जिससे व्यापार संचालन में लगने वाले समय और लागत में अभूतपूर्व कमी आती है।

31. (A) रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स
अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आरओडीटीईपी एक महत्वपूर्ण निर्यात संवर्धन ढांचा है, जिसका पूर्ण रूप रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स है। इस योजना को भारत सरकार द्वारा निर्यातित वस्तुओं पर लगने वाले अप्रत्यक्ष करों और शुल्कों की भरपाई करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि देश से केवल वस्तुओं का निर्यात हो, उन पर लगने वाले घरेलू करों का निर्यात न हो।

32. (B) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के व्यापार नियमों का पालन न करने के कारण एमईआईएस को चुनौती दी गई थी।
भारत सरकार ने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम के स्थान पर आरओडीटीईपी योजना को लागू किया। पूर्ववर्ती योजना को विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत विवाद निवारण पैनल द्वारा चुनौती दी गई थी, क्योंकि इसे निर्यात-संबद्ध नकद सब्सिडी माना गया था जो वैश्विक व्यापार नियमों के प्रतिकूल थी। डब्ल्यूटीओ के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कर वापसी पर आधारित एक नई पारदर्शी प्रणाली विकसित की गई।

33. (A) P-3, Q-2, R-1, S-4
व्यापारिक नीतियों और प्रणालियों के सटीक मिलान से भारत के निर्यात ढांचे की समझ स्पष्ट होती है। विदेश व्यापार नीति देश के व्यापार मार्ग को निर्देशित करती है, जबकि आरओडीटीईपी डब्ल्यूटीओ के अनुकूल पूर्व प्रोत्साहनों का स्थान लेती है। सिंगल-विंडो क्लीयरेंस एक ही मंच से नियामक दस्तावेज जमा करने का तंत्र है। दूसरी तरफ, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम एक पुरानी प्रोत्साहन योजना थी जिसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया।

34. (A) निर्यात उत्पादन के दौरान उपभोग किए गए ईंधन, बिजली और टिकटों पर गैर-प्रतिपूर्तियोग्य करों की वापसी करना
आरओडीटीईपी योजना का मूल सिद्धांत अंतर्निहित करों की वापसी पर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं के निर्माण और परिवहन प्रक्रिया में उपयोग किए गए ईंधन, बिजली, मंडी शुल्क तथा स्टाम्प ड्यूटी जैसे मदों पर जो कर लगते हैं और जिनकी जीएसटी प्रणाली के तहत वापसी नहीं मिलती, उन गैर-प्रतिपूर्तियोग्य करों को निर्यातकों को वापस लौटाया जाता है। इससे भारतीय उत्पादों की लागत अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनती है।

35. (C) डिजिटल इंडिया
भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार सुगमता को बेहतर बनाने के लिए प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की आवश्यकता थी। डिजिटल इंडिया पहल इस परिवर्तन के लिए मौलिक डिजिटल अवसंरचना प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं, अनुपालन प्रपत्रों और व्यापारिक मंजूरियों को ऑनलाइन मंच पर स्थानांतरित किया गया है, जिससे पारदर्शी, सुगम और त्वरित व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है तथा भ्रष्टाचार में कमी आई है।

36. (B) केवल I, II और III
राजस्थान में व्यापार सुगमता में सुधार के लिए कई प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं। इनमें सिंगल-विंडो क्लीयरेंस पोर्टलों का कार्यान्वयन, श्रम कानून अनुपालन प्रक्रियाओं का सरलीकरण और संपत्ति पंजीकरण का डिजिटलीकरण शामिल हैं। इसके विपरीत, सभी मामूली स्वीकृतियों के लिए अनिवार्य व्यक्तिगत निरीक्षण की व्यवस्था व्यापार प्रक्रिया को जटिल बनाती है, इसलिए सुधारों के तहत निरीक्षणों को डिजिटल और जोखिम-आधारित बनाकर भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को कम किया गया है।

37. (C) यदि स्टार्टअप विफल हो जाता है तो यह संस्थापकों को सरकारी नौकरियों की गारंटी देता है।
स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य देश में नवाचार, उद्यमिता और तकनीक-संचालित समाधानों को बढ़ावा देना है। इसके तहत पात्र नए उद्यमों को कर में छूट, सरल स्व-सत्यापन और बौद्धिक संपदा सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। हालांकि, यह पहल संस्थापकों को किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं प्रदान करती है। व्यावसायिक विफलता का जोखिम पूरी तरह से बाजार की परिस्थितियों और उद्यमियों के निजी निर्णयों पर निर्भर रहता है।

38. (B) प्रौद्योगिकी-संचालित प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्थाओं और सेवा एग्रीगेटर्स को प्रोत्साहित करके
स्टार्टअप इंडिया पहल ने सेवा क्षेत्र के आधुनिक विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पहल नवीन विचारों, प्रौद्योगिकी-संचालित प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्थाओं और सेवा एग्रीगेटर्स को विशेष प्रोत्साहन तथा वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त और आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का अभूतपूर्व विकास हुआ है, जिसने पारंपरिक सेवा मॉडल को एक नई दिशा और व्यापक व्यावसायिक विस्तार प्रदान किया है।

39. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
भारत में स्टार्टअप इंडिया पहल के लागू होने से ई-कॉमर्स और एड-टेक जैसे डिजिटल सेवा खंडों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई

NODIA

स्क्रिप प्रदान करके भारतीय निर्यातकों को वित्तीय प्रोत्साहन देना था। हालांकि, विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप ढलने के लिए इसे बाद में समाप्त करके नई कर वापसी योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

79. (A) औपचारिक रोजगार वृद्धि कृषि से श्रम आपूर्ति के विस्तार की तुलना में पीछे रह गई
भारत की सेवा अर्थव्यवस्था में एक विस्तृत अनौपचारिक खंड के बने रहने का प्राथमिक कारण यह है कि अर्थव्यवस्था में औपचारिक नौकरियों का सृजन कृषि क्षेत्र से बाहर निकलने वाले विशाल श्रम बल की तुलना में काफी धीमा रहा है। कृषि से स्थानांतरित होने वाले अधिकांश श्रमिकों के पास उच्च कौशल का अभाव होता है, जिसके कारण वे औपचारिक आईटी या वित्तीय नौकरियों के बजाय असंगठित खुदरा या घरेलू सेवाओं में शामिल हो जाते हैं।

80. (B) मेक इन इंडिया
मेक इन इंडिया पहल प्राथमिक रुप से द्वितीयक यानी विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरु की गई थी। इसके विपरीत, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और आयुष्मान भारत जैसी अन्य योजनाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र के विभिन्न घटकों जैसे प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स और स्वास्थ्य सेवाओं के संवर्धन व विस्तार से जुड़ी हुई हैं। अतः मेक इन इंडिया सेवा क्षेत्र से अलग है।

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from
PRINTED BOOKS has up to
4× HIGHER RETENTION
than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY
PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

49. (B) शैक्षणिक क्षमता का विस्तार करने वाली उच्च निजी क्षेत्र की भागीदारी
भारत में शिक्षा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत हाल के दशकों में एक प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। बढ़ती मांग और सार्वजनिक संसाधनों की सीमाओं को देखते हुए उच्च तथा तकनीकी शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी में भारी वृद्धि हुई है। निजी विश्वविद्यालयों, अभियांत्रिकी कॉलेजों और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के आगमन से देश में शैक्षणिक क्षमता का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, जिसने युवाओं को विविध उच्च शिक्षा विकल्प प्रदान किए हैं।

50. (A) लाभार्थी सख्ती से केवल सार्वजनिक सरकारी अस्पतालों तक ही सीमित हैं।
आयुष्मान भारत (पीएम-जेएवाई) योजना के तहत लाभार्थी केवल सरकारी अस्पतालों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी कैशलेस और पेपरलेस इलाज प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान करती है, जो जनगणना के आंकड़ों से पहचाने गए गरीब परिवारों के लिए है। यह द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों को पूरी तरह कवर करती है।

51. (C) स्मार्टफोन को अपनाना, कम लागत वाला डेटा और दूरस्थ शिक्षा में वृद्धि
भारत में शिक्षा प्रौद्योगिकी यानी एड-टेक सेवाओं के असाधारण विस्तार के मुख्य चालकों में किफायती स्मार्टफोन की व्यापक उपलब्धता और विश्व में सबसे सस्ती इंटरनेट डेटा दरें शामिल हैं। इन तकनीकी कारकों ने दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षण सामग्री तक पहुंच को अत्यंत आसान बना दिया। इसके साथ ही ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और दूरस्थ शिक्षा की बढ़ती स्वीकार्यता ने एड-टेक क्षेत्र को एक नई ऊँचाई प्रदान की।

52. (D) उपभोक्ताओं, व्यापारियों और गिग श्रमिकों को जोड़ने वाले डिजिटल ढांचे
आधुनिक सेवा अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था उस डिजिटल ढांचे को संदर्भित करती है जो नेटवर्क प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विभिन्न समूहों को आपस में जोड़ती है। यह डिजिटल संरचना उपभोक्ताओं, व्यापारियों, सेवा प्रदाताओं और गिग कार्यकर्ताओं के बीच सुगम संपर्क, वित्तीय लेनदेन तथा सेवाओं के आदान-प्रदान को सक्षम बनाती है। इसके प्रमुख उदाहरणों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, राइड-हैलिंग ऐप्स और डिजिटल भुगतान नेटवर्क शामिल हैं, जो व्यावसायिक मॉडल बदल रहे हैं।

53. (A) केवल I और IV
ई-कॉमर्स के तीव्र विस्तार ने लॉजिस्टिक्स, भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की मांग को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है, न कि इसे कम किया है। इसके अतिरिक्त, ई-कॉमर्स पूरी तरह से पारंपरिक सड़क, रेल और वायु परिवहन नेटवर्क पर निर्भर होकर कार्य करता है। चूंकि यह डिजिटल भुगतान पर निर्भर है और अंतिम-मील वितरण में व्यापक रोजगार निर्मित करता है, इसलिए प्रथम और चतुर्थ विवरण पूरी तरह से असत्य पाए जाते हैं।

54. (B) डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मध्यस्थता वाले लचीले, गैर-स्थायी काम करता है
ई-कॉमर्स और डिजिटल सेवा एग्रीगेटर्स के प्रसार के साथ गिग वर्कर की अवधारणा अत्यंत लोकप्रिय हुई है। एक गिग वर्कर वह व्यक्ति होता है जो पारंपरिक दीर्घकालिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के बाहर रहकर लचीले, अनुबंध-आधारित या कार्य-विशिष्ट रोजगार में संलग्न होता है। ये श्रमिक आमतौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भोजन वितरण, सवारी सेवाएं या अन्य अल्पकालिक स्वतंत्र कार्य करते हैं, जहाँ कार्य के घंटे और प्रकृति काफी लचीली होती है।

55. (D) लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और डिलीवरी सेवाएं
ई-कॉमर्स उद्योग के तेजी से विस्तार का सीधा और प्रत्यक्ष प्रभाव सहायक सेवा क्षेत्रों पर पड़ा है। इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी बढ़ने से माल के सुरक्षित भंडारण के लिए अत्याधुनिक वेयरहाउसिंग और त्वरित आपूर्ति के लिए लॉजिस्टिक्स तथा लास्ट-माइल डिलीवरी सेवाओं की मांग में भारी उछाल आया है। इस मांग ने देश भर में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और परिवहन सेवाओं के नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार किया है।

56. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
ई-कॉमर्स उद्योग की सफलता एक कुशल, त्वरित और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर पूरी तरह निर्भर करती है। ऑनलाइन व्यापार में ग्राहक संतुष्टि का सबसे मुख्य आधार ऑर्डर की समय पर और कम लागत में सुरक्षित डिलीवरी होना है। इसलिए, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए उनके मूल मूल्य प्रस्ताव को पूरा करने का प्राथमिक माध्यम बनती है, जो इस क्षेत्र की संवृद्धि में निर्णायक भूमिका निभाती है।

NODIA

57. (C) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के सापेक्ष राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स लागत को वैश्विक बेंचमार्क स्तरों तक कम करना
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की परिचालन दक्षता को बढ़ाना है। इसका मुख्य लक्ष्य वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 13 से 14 प्रतिशत रहने वाली लॉजिस्टिक्स लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के अनुरूप एकल अंक यानी 8 से 9 प्रतिशत तक लाना है। इससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारतीय उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा और आपूर्ति श्रृंखला अधिक सुगम बनेगी।

58. (A) 2, 3, 4, 1
व्यावसायिक लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रिया का एक सुव्यवस्थित तार्किक क्रम होता है। सबसे पहले उत्पादकों द्वारा कच्चे माल या निर्मित वस्तुओं की खरीद की जाती है। इसके पश्चात उन वस्तुओं को सुरक्षित वेयरहाउसिंग और भंडारण के लिए गोदामों में भेजा जाता है। इसके बाद लंबी दूरी

28. हरित क्रांति प्रौद्योगिकियों को शुरुआती दौर में अपनाने से पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा?
(A) इसके कारण देश भर में ग्रामीण कृषि श्रम बाज़ार तत्काल और पूर्णतः ध्वस्त हो गया
(B) बहु-फसली मांगों के कारण ग्रामीण श्रम अवशोषण में वृद्धि हुई
(C) इसने रोजगार में भारी कमी की क्योंकि रासायनिक उर्वरकों ने पूरी तरह से शारीरिक खेती का स्थान ले लिया
(D) इसने लगभग सभी कृषि श्रमिकों को सीधे भारी विनिर्माण क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया

29. हरित क्रांति के बाद के चरणों में कृषि में रोजगार की लोच घटने लगी। इसका प्राथमिक कारण क्या था?
(A) कृषि यंत्रीकरण में तीव्र वृद्धि
(B) प्रमुख राज्यों में कृषि योग्य भूमि की अत्यधिक और गंभीर कमी
(C) जलवायु परिवर्तन के कारण उच्च उपज वाले बीजों की व्यापक विफलता
(D) मौसमी कृषि मजदूरों को काम पर रखने पर सख्त सरकारी नियम

30. भारत में कौन-सी कृषि क्रांति विशेष रूप से 'तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन' से जुड़ी है?
(A) रजत क्रांति
(B) स्वर्ण क्रांति
(C) पीली क्रांति
(D) गुलाबी क्रांति

31. सूची I में दिए गए व्यक्ति/संगठन को सूची II में उनके मुख्य सम्बद्ध योगदान के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (व्यक्ति/संगठन)
P. वर्गीज कुरियन
Q. एम.एस. स्वामीनाथन
R. एनडीडीबी
S. आईसीएआर
सूची II: (योगदान)
1. "सदाबहार क्रांति" शब्द गढ़ना
2. डेयरी सहकारी समितियों के राष्ट्रीय नेटवर्क की स्थापना करना
3. कृषि अनुसंधान और तकनीकी विस्तार को बढ़ावा देना
4. ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व करना
सही कूट का चयन कीजिए:
(A) P-2, Q-3, R-4, S-1
(B) P-4, Q-2, R-1, S-3
(C) P-3, Q-1, R-2, S-4
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

32. भारत में गुलाबी क्रांति मुख्य रूप से किन दो क्षेत्रों में तकनीकी और उत्पादन प्रगति का प्रतीक है?
(A) व्यावसायिक टमाटर उत्पादन और अरहर की खेती
(B) औद्योगिक गुलाब की खेती और जैविक सौंदर्य प्रसाधन निर्माण
(C) मांस प्रसंस्करण और औषध निर्माण
(D) व्यावसायिक झींगा पालन और अंतर्देशीय संश्लेषित उर्वरक

33. रजत क्रांति के परिणामस्वरूप कृषि से जुड़े निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उत्पादन में वृद्धि हुई?
(A) रेशम उत्पादन (रेशम कीट पालन)
(B) अंडे और कुक्कुट उत्पादन
(C) कपास उत्पादन
(D) दुग्ध प्रसंस्करण

34. विभिन्न कृषि क्रांतियों की अवधि के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्राथमिक जनादेश क्या था?
(A) सभी नई विकसित फसलों के लिए नियमित रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गणना और घोषणा करना
(B) देश भर में सीधे ग्राम पंचायतों को सब्सिडी वाले रासायनिक उर्वरकों का प्रबंधन और वितरण करना
(C) डेयरी और समुद्री उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात व्यापार को व्यापक रूप से विनियमित करना
(D) कृषि अनुसंधान, बीज विकास और विस्तार सेवाएं प्रदान करना

35. "सदाबहार क्रांति" की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसकी वकालत डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी।
II. यह सतत कृषि और पारिस्थितिक संरक्षण पर जोर देती है।
III. यह उपज की बाधाओं को तोड़ने के लिए रासायनिक उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग को बढ़ावा देती है।
IV. यह दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षरण के बिना उत्पादकता वृद्धि चाहती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) I, II और III
(B) I, II और IV
(C) II, III और IV
(D) I, III और IV

36. नीतिगत ध्यान का हरित क्रांति से सदाबहार क्रांति की ओर संक्रमण मूल रूप से किस प्रकार का बदलाव है?
(A) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से कच्चे माल के निर्यात की ओर नीतिगत बदलाव
(B) पारंपरिक वर्षा आधारित कृषि से पूरी तरह से कृत्रिम ग्रीनहाउस खेती की ओर बदलाव
(C) किसी भी कीमत पर उपज के अधिकतमीकरण से सतत उत्पादकता की ओर बदलाव
(D) सहकारी खेती मॉडल से कॉर्पोरेट अनुबंध खेती की ओर संरचनात्मक बदलाव

Click Here to Buy book on Flipkart

भारी गिरावट आई, जिससे देश भर में डिजिटल कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन का उपयोग और ई-सेवाओं का प्रसार अभूतपूर्व रूप से बढ़ा।

69. (C) राष्ट्रीय जीडीपी के सापेक्ष लिखित कुल बीमा प्रीमियम का अनुपात
वित्तीय सेवा क्षेत्र के विकास का मूल्यांकन करने के लिए बीमा पहुंच एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानक है। इसे देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के सापेक्ष किसी विशेष वर्ष में दर्ज या लिखित कुल बीमा प्रीमियम के प्रतिशत अनुपात के रूप में गणितीय रूप से परिभाषित किया जाता है। बीमा पहुंच का बढ़ता हुआ स्तर अर्थव्यवस्था में बढ़ती वित्तीय सुरक्षा, बचत के संस्थानीकरण और बीमा सेवाओं के व्यापक विस्तार का स्पष्ट संकेत देता है।

70. (D) I, II, III और IV
बैंकिंग और बीमा सेवाओं की तीव्र वृद्धि कई कारकों से संचालित होती है। बढ़ती वित्तीय साक्षरता से लोग आधुनिक उत्पादों को अपनाते हैं। पीएम जन धन योजना जैसी पहलें वित्तीय समावेशन बढ़ाती हैं। इसके अतिरिक्त, सेवाओं का डिजिटलीकरण बैंकिंग को सुलभ बनाता है। वहीं, नए निजी खिलाड़ियों के लिए उच्च प्रारंभिक पूंजी आवश्यकता प्रवेश बाधा का काम करती है जो बाजार की स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मक संरचना को प्रभावित करती है।

71. (D) प्रमुख सेवा प्रदाताओं के एक छोटे अल्पधिकार में बाजार का समेकन
पिछले दशक के दौरान भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में चली तीव्र प्रतिस्पर्धा और मूल्य युद्ध का एक दूरगामी परिणाम सामने आया। अत्यधिक वित्तीय दबाव और घटती कमाई के कारण कई छोटी और वित्तीय रूप से कमजोर टेलीकॉम कंपनियां बाजार से बाहर हो गईं या उनका विलय हो गया। इसके परिणामस्वरूप देश का दूरसंचार बाजार व्यापक स्तर पर समेकित होकर केवल तीन निजी और एक सरकारी कंपनी के एक छोटे अल्पधिकार में परिवर्तित हो गया।

72. (A) यह क्षेत्र जीडीपी में आधे से अधिक का योगदान देता है लेकिन कार्यबल के आनुपातिक रूप से बहुत छोटे हिस्से को रोजगार देता है।
भारतीय सेवा क्षेत्र के विकास पथ का सबसे बड़ा संरचनात्मक विरोधाभास इसकी उत्पादन और रोजगार क्षमता के बीच का असंतुलन है। यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है, परंतु कुल कार्यबल के आनुपातिक रूप से बहुत छोटे हिस्से को ही रोजगार प्रदान कर पाता है। इसका मुख्य कारण आईटी और वित्त जैसे उच्च मूल्यवर्धित खंडों की पूंजी-गहन तथा कुशल श्रम पर अत्यधिक निर्भरता है।

73. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
दूरसंचार क्षेत्र आधुनिक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई-कॉमर्स गतिविधियों तथा वित्तीय प्रौद्योगिकी के प्रसार का आधारभूत स्तंभ है। इसके बिना डिजिटल सेवाओं का त्वरित वितरण असंभव है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल इंडिया जैसी व्यापक राष्ट्रीय पहलों के सफल कार्यान्वयन और आम नागरिकों तक ई-गवर्नेंस पहुंचाने के लिए एक सुदृढ़, प्रतिस्पर्धी तथा तकनीकी रूप से उन्नत दूरसंचार अवसंरचना का होना अनिवार्य है। अतः दोनों दिए गए विवरण पूरी तरह सत्य हैं।

74. (A) अनुपातिक रोजगार सृजन के बिना जीडीपी योगदान का विस्तार होता है
रोजगारहीन संवृद्धि अथवा जॉबलेस ग्रोथ एक ऐसी समष्टि आर्थिक स्थिति को संदर्भित करती है जहाँ कोई क्षेत्र जीडीपी और राष्ट्रीय आय में उच्च वृद्धि दर दर्ज करता है, परंतु उस अनुपात में नए रोजगार अवसरों का सृजन करने में विफल रहता है। सेवा क्षेत्र के कुछ तकनीकी और पूंजी-गहन उप-क्षेत्रों में उच्च उत्पादकता के कारण उत्पादन तेजी से बढ़ता है, लेकिन श्रमबल की मांग सीमित बनी रहती है, जिससे यह समस्या उत्पन्न होती है।

75. (D) आईटी और वित्तीय सेवाएं
सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाएं अपनी अत्यधिक विशिष्ट, ज्ञान-आधारित तथा पूंजी-गहन प्रकृति के कारण रोजगारहीन संवृद्धि उत्पन्न करने की आलोचना के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील हैं। ये उप-क्षेत्र स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल प्रणालियों के बल पर विशाल राजस्व और जीडीपी योगदान अर्जित करते हैं, परंतु इन्हें संचालित करने के लिए केवल सीमित संख्या में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। इसके कारण ये बड़े पैमाने पर रोजगार नहीं निर्मित कर पाते।

76. (B) असंगठित खुदरा व्यापार और घरेलू काम
असंगठित खुदरा व्यापार और घरेलू काम जैसे सेवा उप-क्षेत्र अपनी उच्च रोजगार तीव्रता के लिए जाने जाते हैं। ये क्षेत्र बिना किसी उच्च तकनीकी योग्यता वाले लाखों श्रमिकों को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। हालांकि, उच्च अनौपचारिकता, आधुनिक तकनीकों की कमी तथा कम पूंजी निवेश के कारण इन क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति श्रम उत्पादकता का स्तर काफी कम बना रहता है, जिससे श्रमिकों की आय भी सीमित रहती है।

77. (C) लॉजिस्टिक्स - लागत में कमी और बहुविध (मल्टीमॉडल) कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करना
भारतीय सेवा क्षेत्र के विभिन्न उप-क्षेत्रों में से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र वर्तमान में एक बड़ा परिवर्तन देख रहा है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के माध्यम से इस क्षेत्र की मुख्य रणनीति कुल परिचालन लागत को कम करने और सड़क, रेल तथा जल परिवहन के एकीकरण हेतु बहुविध कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह रणनीति भारत के आंतरिक और विदेशी व्यापार की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में क्रांतिकारी योगदान दे रही है।

78. (D) मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम
भारत की पिछली विदेश व्यापार नीतियों के तहत निर्यात प्रोत्साहन के लिए एमईआईएस एक प्रमुख योजना थी, जिसका पूर्ण रूप मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम है। इस योजना का उद्देश्य निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात पर शुल्क क्रेडिट

Downloaded from www.pdf.tube

का लाइन-हॉल परिवहन संपन्न होता है। अंतिम चरण में माल को खुदरा विक्रेता या अंतिम ग्राहक तक अंतिम-मील वितरण के माध्यम से पहुँचाया जाता है।

59. (D) वास्तविक समय (रियल-टाइम) ट्रैकिंग और दृश्यता के लिए अंतर-मंत्रालयी लॉजिस्टिक्स डेटा को एकीकृत करना
यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल के रूप में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और परिवहन एजेंसियों के पास उपलब्ध लॉजिस्टिक्स डेटा को एक ही डिजिटल मंच पर एकीकृत करना है। इससे माल की वास्तविक समय ट्रैकिंग, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के सभी हितधारकों के बीच निर्बाध सूचना आदान-प्रदान संभव हो पाता है।

60. (D) I, II और III
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का बहुआयामी दृष्टिकोण भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार लाना है। यह नीति लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के एकल अंक तक लाने का लक्ष्य रखती है। इसके अलावा, यह क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने, श्रम कौशल के विकास तथा बहुविध यानी मल्टीमॉडल परिवहन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर विशेष बल देती है। अतः इस नीति के संदर्भ में दिए गए तीनों कथन पूरी तरह से सही हैं।

61. (C) औपचारिक कर अनुपालन और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं वाले कॉर्पोरेट खुदरा विक्रेता
खुदरा क्षेत्र में संगठित खुदरा व्यापार की मुख्य विशेषता इसका औपचारिक और कॉर्पोरेट ढांचा है। संगठित खुदरा विक्रेताओं के पास पंजीकृत व्यावसायिक अस्तित्व, औपचारिक कर अनुपालन जैसे जीएसटी पंजीकरण, पारदर्शी खाता बहियां तथा आधुनिक एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाएं होती हैं। ये संस्थान बड़े सुपरमार्केट, चेन स्टोर या पंजीकृत ई-कॉमर्स संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं, जो अनौपचारिक या असंगठित पड़ोस की छोटी दुकानों से पूर्णतः भिन्न होते हैं।

62. (C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
भारत में कुल खुदरा बाजार में संगठित खुदरा का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है, परंतु असंगठित क्षेत्र का दबदबा अब भी बना हुआ है। हालांकि, बड़े पैमाने की बचत, थोक खरीद और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं का लाभ संगठित खुदरा विक्रेताओं को मिलता है, न कि असंगठित या पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं को। पारंपरिक दुकानदार छोटे पैमाने पर काम करते हैं और बिचौलियों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए द्वितीय कथन असत्य है।

63. (A) भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) जैसे औपचारिक कर्मचारी लाभों की उच्च डिग्री
भारत का असंगठित खुदरा क्षेत्र मुख्य रूप से पास-पड़ोस की छोटी किराना दुकानों और फेरीवालों द्वारा संचालित होता है। इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है, व्यक्तिगत ग्राहक संबंध होते हैं और विखंडित आपूर्ति श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। हालांकि, इसमें काम करने वाले कर्मचारियों के पास भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा या पेंशन जैसे औपचारिक कर्मचारी लाभों का पूर्ण अभाव होता है। अतः यह विकल्प इसकी विशेषता नहीं है।

64. (B) रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी
रियल एस्टेट कानून के तहत गठित नियामक निकाय का संक्षिप्त नाम रेरा है, जिसका पूर्ण रूप रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण है। संसद द्वारा पारित रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के माध्यम से इस संस्था की स्थापना की गई थी। इसका प्राथमिक दायित्व देश भर में अचल संपत्ति से जुड़ी आवास परियोजनाओं के पारदर्शी नियमन और प्रबंधन को सुनिश्चित करना है।

65. (B) पारदर्शिता, डेवलपर की जवाबदेही और घर खरीदारों की सुरक्षा को बढ़ाना
राजस्थान में राज-रेरा सहित देश भर में रेरा कानून लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र का कायाकल्प करना था। इसका मुख्य ध्येय आवास परियोजनाओं में अत्यधिक पारदर्शिता लाना, समय पर निर्माण पूरा करने हेतु बिल्डरों की जवाबदेही तय करना तथा घर खरीदारों के हितों और वित्तीय निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस नियामक ढांचे ने संपत्ति बाजार में उपभोक्ताओं के विश्वास को पुनः बहाल करने में मदद की है।

NODIA

66. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
भारत के सेवा क्षेत्र के समुचित विकास में विभिन्न नियामक निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेरा का संबंध रियल एस्टेट क्षेत्र के नियमन से है, जबकि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण या ट्राई दूरसंचार बाजार को विनियमित करता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा बीमा क्षेत्र की देखरेख करता है। दूसरी तरफ, भारतीय रिजर्व बैंक देश की बैंकिंग प्रणाली और मौद्रिक नीति का केंद्रीय संचालक है।

67. (C) यह सुनिश्चित करना कि पूंजी निर्दिष्ट आवास परियोजना के निर्माण के लिए ही समर्पित हो
रेरा अधिनियम के प्रावधानों के तहत रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए किसी परियोजना हेतु खरीदारों से प्राप्त कुल राशि का 70 प्रतिशत हिस्सा एक पृथक एस्क्रो खाते में जमा करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य धन की हेराफेरी रोकना और यह गारंटी देना है कि एकत्र की गई पूंजी का उपयोग केवल उसी विशिष्ट आवास परियोजना के निर्माण तथा भूमि लागत को पूरा करने के लिए ही हो।

68. (D) किफायती 4जी डेटा की पेशकश करने वाले एक विघटनकारी (डिस्ट्रप्टिव) ऑपरेटर का प्रवेश जिसने टैरिफ वॉर शुरू कर दिया
भारत के दूरसंचार क्षेत्र में 2016 के बाद आई डेटा क्रांति का मुख्य श्रेय बाजार में अत्यंत कम दरों पर 4जी डेटा सेवाएं देने वाले एक नए विघटनकारी ऑपरेटर के प्रवेश को जाता है। इस प्रवेश ने उद्योग में भीषण प्रतिस्पर्धा और टैरिफ वॉर को जन्म दिया। इसके परिणामस्वरूप इंटरनेट डेटा की कीमतों में

अध्याय 09
हरित, श्वेत एवं नीली क्रांति

1. 1960 के दशक में भारत को पीएल-480 कार्यक्रम पर अत्यधिक निर्भर होने के लिए बाध्य करने वाली प्राथमिक घरेलू स्थिति क्या थी?
(A) मोटे अनाजों का अत्यधिक उत्पादन जिसके लिए निर्यात बाज़ारों की आवश्यकता थी
(B) एक गंभीर घरेलू खाद्य संकट और व्यापक भुखमरी का संकट
(C) औद्योगीकरण के लिए कृषि यंत्रों का आयात करने की आवश्यकता
(D) अमेरिकी डेयरी प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता

2. अपने प्रारंभिक चरण में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) भूमि पुनर्वितरण के माध्यम से ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन करना
(B) भारतीय कृषि को पूर्णतः जैविक खेती में परिवर्तित करना
(C) कपास और जूट जैसी नकदी फसलों के निर्यात को अधिकतम करना
(D) खाद्यान्न उत्पादन में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना

3. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): हरित क्रांति ने अमेरिका के पीएल-480 खाद्य आयात कार्यक्रम पर भारत की निर्भरता को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया।
कारण (R): उच्च उपज वाली किस्म के बीजों और आधुनिक आगतों के उपयोग से घरेलू खाद्यान्न उपज में भारी वृद्धि हुई।
सही विकल्प का चयन कीजिए:
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।

4. हरित क्रांति के प्रारंभिक वर्षों के दौरान उच्च उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम का मुख्य ध्यान किन विशिष्ट फसलों पर था?
(A) दलहन और तिलहन
(B) गन्ना और कपास
(C) गेहूं और चावल
(D) ज्वार और बाजरा

5. हरित क्रांति के दौरान भारत में लाई गई प्रसिद्ध अर्ध-बौनी, उच्च उपज वाली गेहूं की किस्में मूल रूप से किस देश में विकसित की गई थीं?
(A) मैक्सिको
(B) संयुक्त राज्य अमेरिका
(C) फिलीपींस
(D) ऑस्ट्रेलिया

6. हरित क्रांति के दौरान, चावल की एक प्रमुख उच्च उपज वाली किस्म शुरू की गई जिसने उपज में उल्लेखनीय वृद्धि की। इसका लोकप्रिय नाम क्या था?
(A) कल्याण सोना
(B) सोनालिका
(C) शरबाती सोनोरा
(D) आईआर-8

7. हरित क्रांति की तकनीकी आवश्यकताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसके लिए सुनिश्चित और नियंत्रित सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता थी।
II. इसके लिए रासायनिक उर्वरकों के गहन उपयोग की आवश्यकता थी।
III. यह मुख्य रूप से पारंपरिक, स्वदेशी बीजों की किस्मों पर निर्भर थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

8. पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति के दौरान सिंचाई के विस्तार की सबसे प्रमुख विशेषता किसकी तीव्र वृद्धि थी?
(A) टपकन (ड्रिप) सिंचाई प्रणाली
(B) वर्षा जल संचयन संरचनाएं
(C) नहर तंत्र और नलकूप
(D) गहरे समुद्र के विलवणीकरण संयंत्र

9. उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बड़े पैमाने पर वृद्धि की आवश्यकता क्यों पड़ी?
(A) बीज प्राकृतिक खाद को अस्वीकार करने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किए गए थे
(B) बिना रसायनों के उच्च उपज वाले पौधों में स्थानीय कीटों

Click Here to Buy book on Amazon

के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता की कमी थी
(C) अंकुरण के लिए मृदा का तापमान बढ़ाने हेतु रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता थी
(D) उच्च उपज वाली फसलों को अपनी अधिकतम उपज क्षमता प्राप्त करने के लिए उच्च पोषक आगतों की आवश्यकता थी

10. हरित क्रांति प्रारंभ में भारत के विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों तक ही सीमित थी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने प्रथम चरण में सबसे उल्लेखनीय सफलता का अनुभव किया?
(A) पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश
(B) बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्वी मैदान
(C) महाराष्ट्र का दक्कन पठारी क्षेत्र
(D) आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय डेल्टा

11. सूची I में दी गई कृषि क्रांतियों को सूची II में उनके प्रभाव के प्राथमिक क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (क्रांति)
P. हरित क्रांति
Q. श्वेत क्रांति
R. नीली क्रांति
S. पीली क्रांति
सूची II: (प्रभाव का क्षेत्र)
1. तिलहन
2. मत्स्य पालन और जलकृषि
3. डेयरी और दुग्ध
4. खाद्यान्न
सही कूट का चयन कीजिए:
(A) P-4, Q-2, R-3, S-1
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-1, Q-3, R-2, S-4

12. हरित क्रांति की एक प्रमुख सामाजिक आलोचना यह है कि उसने:
(A) सभी क्षेत्रों में नकदी फसल की खेती को तत्काल और पूर्णतः समाप्त कर दिया
(B) धनी और सीमांत किसानों के बीच आय की असमानताओं को बढ़ा दिया
(C) शहरी औद्योगिक श्रमिकों का ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पलायन कराया
(D) संपूर्ण उत्तर भारत में कृषि सहकारी समितियों की संरचनात्मक भूमिका को समाप्त कर दिया

13. निम्नलिखित में से कौन-सा हरित क्रांति के दौरान बढ़ावा दी गई "एकल-फसली पद्धति" से जुड़े पर्यावरणीय जोखिम का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) मृदा स्वास्थ्य का क्षरण और कीटों के प्रति फसलों की संवेदनशीलता में वृद्धि
(B) इसने पारंपरिक देशी फसलों की प्राकृतिक कीट प्रतिरोधक क्षमता को स्थायी रूप से बढ़ा दिया
(C) इसके कारण कृषि फसलों की आनुवंशिक विविधता में दीर्घकालिक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई
(D) इसके परिणामस्वरूप ऊपरी मृदा में जैविक पदार्थों का भारी संचय हुआ

14. हरित क्रांति के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसने संपूर्ण भारत में कृषि विकास में गंभीर क्षेत्रीय असमानताएं पैदा कीं।
II. इसके कारण उत्तर-पश्चिमी राज्यों में भूजल का चिंताजनक दोहन हुआ।
III. इसने रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता को समाप्त कर दिया।
IV. इसने जैविक आगतों के बिना दीर्घकालिक मृदा उर्वरता को सफलतापूर्वक बनाए रखा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल III और IV
(C) केवल I, II और III
(D) I, II, III और IV

15. पंजाब और हरियाणा में जल स्तर का तेजी से गिरना प्रत्यक्ष रूप से किसका एक दीर्घकालिक परिणाम है?
(A) पारंपरिक कृषि से भारी विनिर्माण उद्योगों की ओर तीव्र संरचनात्मक बदलाव
(B) 1980 के दशक में लगातार दस वर्षों तक मौसमी मानसून की अभूतपूर्व विफलता
(C) सतलुज नदी पर बड़ी जलविद्युत बांध परियोजनाओं का अत्यधिक निर्माण
(D) नलकूपों का उपयोग करके अत्यधिक जल-गहन धान की गहन खेती

16. 1970 में शुरू किया गया 'ऑपरेशन फ्लड' निम्नलिखित में से किस कृषि परिवर्तन का पर्याय है?
(A) प्रमुख नदी प्रणालियों का स्थिरीकरण
(B) नीली क्रांति
(C) श्वेत क्रांति
(D) सदाबहार क्रांति

NODIA

17. ऑपरेशन फ्लड को वैश्विक स्तर पर किस विशिष्ट क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े विकास कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है?
(A) अंतर्देशीय जलकृषि
(B) डेयरी और दुग्ध उत्पादन
(C) उच्च उपज वाली गेहूं की खेती
(D) कुक्कुट और अंडा उत्पादन

18. निम्नलिखित में से किसे भारत में "श्वेत क्रांति के जनक" के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है?
(A) एम.एस. स्वामीनाथन
(B) नॉर्मन बोरलॉग
(C) सैम पित्रोदा

(D) वर्गीज कुरियन

19. श्वेत क्रांति की सफलता का आधारभूत संस्थागत ढांचा "आनंद पैटर्न" पर आधारित था। आनंद पैटर्न क्या है?
(A) दुग्ध उत्पादकों के स्वामित्व वाली एक त्रि-स्तरीय सहकारी संरचना
(B) पूर्णतः राज्य के स्वामित्व वाला और केंद्रीय रूप से संचालित सार्वजनिक डेयरी फार्म नेटवर्क
(C) डेयरी क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा संचालित एक बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट मॉडल
(D) दुग्ध के खुदरा मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने के लिए एक सख्त सरकारी नियामक ढांचा

20. आनंद पैटर्न डेयरी सहकारी मॉडल के संरचनात्मक स्तरों को ग्राम स्तर से शीर्ष राज्य स्तर तक व्यवस्थित कीजिए:
1. राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ
2. ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति
3. जिला दुग्ध उत्पादक संघ

सही क्रम का चयन कीजिए:
(A) 1, 2, 3
(B) 3, 2, 1
(C) 2, 3, 1
(D) 2, 1, 3

21. श्वेत क्रांति के दौरान संपूर्ण भारत में अमूल सहकारी मॉडल की सफलता को दोहराने के लिए किस राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई थी?
(A) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
(B) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
(C) भारतीय खाद्य निगम
(D) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

22. अमूल मॉडल के तहत, डेयरी आपूर्ति श्रृंखला से बिचौलियों को समाप्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) राज्य सरकार द्वारा एकत्रित वार्षिक कर राजस्व में अत्यधिक वृद्धि करना
(B) पड़ोसी देशों को शुष्क दुग्ध (मिल्क पाउडर) के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात पर भारी सब्सिडी देना
(C) दुग्ध के घरेलू बाज़ार मूल्य को बढ़ाने के लिए इसके कुल उत्पादन को कृत्रिम रूप से कम करना
(D) उपभोक्ता मूल्य का अधिकतम हिस्सा किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना

23. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): श्वेत क्रांति ने सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ में काफी सुधार किया।
कारण (R): डेयरी व्यवसाय ने आय का एक पूरक और निरंतर स्रोत प्रदान किया जिसके लिए बड़ी जोत की आवश्यकता नहीं थी।
सही विकल्प का चयन कीजिए:
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।

24. भारत में नीली क्रांति की अवधारणा किस प्राथमिक उद्देश्य के साथ तैयार की गई थी?
(A) नील और संश्लेषित रंजक के औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना
(B) नदी घाटियों में जल-गहन नकदी फसलों की व्यापक खेती को बढ़ावा देना
(C) मत्स्य उत्पादन और जलकृषि के विकास में वृद्धि करना
(D) उत्तर भारत की प्रमुख प्रदूषित नदी प्रणालियों की व्यापक सफाई करना

25. नीली क्रांति के तहत मत्स्य पालन का रणनीतिक विस्तार निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को लक्षित करता है?
(A) विशेष रूप से गहरे समुद्र के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों और महासागरीय जल को
(B) विशेष रूप से मीठे पानी की नदियों, धाराओं और प्राकृतिक झीलों पर ध्यान केंद्रित करना
(C) विशेष रूप से कृत्रिम शहरी एक्वेरियम और सार्वजनिक प्रदर्शनों का विकास करना
(D) अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य पालन दोनों को

26. निम्नलिखित में से कौन-सी योजना मत्स्य पालन क्षेत्र के केंद्रित और सतत विकास के लिए भारत सरकार की वर्तमान प्रमुख पहल है?
(A) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
(B) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
(C) परंपरागत कृषि विकास योजना
(D) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

27. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसका उद्देश्य मछुआरों और मत्स्य पालकों की आय को दोगुना करना है।
II. यह आधुनिक कोल्ड चेन के माध्यम से फसल पश्चात की क्षति को कम करने पर केंद्रित है।
III. यह स्पष्ट रूप से जलकृषि में महिलाओं की भागीदारी को हतोत्साहित करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I
(B) केवल I और II
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

Downloaded from www.pdf.tube

है। इस वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि इस पहल द्वारा नए प्रौद्योगिकी-आधारित उद्यमों को नियामक अनुपालन में ढील, शुरुआती फंडिंग में सहायता और इनक्यूबेशन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यह सहायता तंत्र नवोन्मेषी विचारों को व्यावसायिक रूप से सफल बनाने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करता है।

40. (A) ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना
डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य ध्यान देश को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने पर केंद्रित है। सेवा क्षेत्र के संदर्भ में यह पहल ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाओं और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देती है। इसका लक्ष्य नागरिकों और व्यवसायों तक निर्बाध, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं पहुंचाना है, जिससे दैनिक जीवन और व्यापारिक गतिविधियों को अधिक सुलभ एवं कुशल बनाया जा सके।

41. (C) भ्रष्टाचार को कम करने और प्रसंस्करण समय को छोटा करने के लिए मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करके
डिजिटल इंडिया का एक मुख्य आधार ई-गवर्नेंस है, जो सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में क्रांतिकारी सुधार लाता है। डिजिटल पोर्टलों के माध्यम से प्रक्रियाओं को स्वचालित करके यह प्रणाली प्रशासनिक कार्यप्रणाली में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम कर देती है। इससे अनुपालन समय में काफी कमी आती है, बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है और भ्रष्टाचार के अवसरों पर अंकुश लगता है, जिससे शासन प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ती है।

42. (B) कागजी चेक → एनईएफटी/आरटीजीएस → यूपीआई → सीबीडीसी (ई-रुपया)
भारत में डिजिटल भुगतान प्रणालियों का विकास एक क्रमिक और तकनीकी परिवर्तन को दर्शाता है। शुरुआती दौर में लेन-देन मुख्य रूप से कागजी चेक और नकद पर निर्भर था। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हेतु एनईएफटी तथा आरटीजीएस जैसी प्रणालियां आईं। बाद में यूपीआई ने खुदरा भुगतानों को अत्यधिक सुगम और त्वरित बना दिया। वर्तमान समय में केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी या ई-रुपया) का विकास इस श्रृंखला का नवीनतम चरण है।

43. (A) केवल I और II
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तीन प्रमुख विजन क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना का निर्माण, मांग पर शासन व सेवाएं तथा नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पूर्ण निजीकरण करना बिल्कुल नहीं है। बैंकिंग प्रणाली में डिजिटलीकरण को लागू करना सेवा वितरण का हिस्सा है, परंतु स्वामित्व हस्तांतरण इस अभियान का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है।

44. (B) लीपफ्रॉगिंग संरचनात्मक रूपांतरण
पारंपरिक आर्थिक सिद्धांतों में विकास का क्रम कृषि से विनिर्माण और अंततः सेवा क्षेत्र की ओर होता है। परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था ने विनिर्माण क्षेत्र के पूर्ण परिपक्व होने से पहले ही सीधे सेवा क्षेत्र में उच्च संवृद्धि हासिल की। इस अनोखी प्रक्रिया को आर्थिक विकास के संदर्भ में लीपफ्रॉगिंग संरचनात्मक रूपांतरण कहा जाता है। इसने भारत को विनिर्माण-संचालित विकास के बजाय एक प्रमुख सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक स्तर पर स्थापित किया।

45. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
भारत में ऐतिहासिक रूप से सेवा क्षेत्र की संवृद्धि दर कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों की तुलना में लगातार अधिक रही है। इसके साथ ही, सकल घरेलू उत्पाद में अत्यधिक योगदान देने के बावजूद कुल राष्ट्रीय रोजगार में सेवाओं का हिस्सा आनुपातिक रूप से काफी कम है। यह स्थिति सेवा क्षेत्र के आधुनिक और औपचारिक खंडों में उच्च श्रम उत्पादकता तथा पूंजी-गहन तकनीकों के व्यापक उपयोग को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

46. (D) 1991 में लागू किए गए आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण सुधार
भारतीय सेवा क्षेत्र के अभूतपूर्व विस्तार को वास्तविक गति 1991 के आर्थिक सुधारों से प्राप्त हुई। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश और वैश्विक व्यापार के लिए खोल दिया। इसके परिणामस्वरूप दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं, बीमा और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निजी भागीदारी बढ़ी, विदेशी पूंजी का आगमन हुआ और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर सेवा क्षेत्र ने रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की।

NODIA

47. (A) कम आय वाले परिवारों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है, जिससे चिकित्सा सेवाओं की मांग बढ़ती है
आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए मांग-पक्ष प्रोत्साहन का कार्य करती है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर प्रदान करती है। वित्तीय बाधाओं के दूर होने से गरीब आबादी द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा देखभाल का लाभ उठाने में सक्षम होती है। इससे अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग में व्यापक वृद्धि होती है, जो चिकित्सा क्षेत्र को गति देती है।

48. (A) P-4, Q-2, R-3, S-1
भारत में लागू विभिन्न सरकारी नीतियां और कानून विशिष्ट सेवा क्षेत्रों के संवर्धन व नियमन से जुड़े हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में सुधार करती है, जबकि स्वदेश दर्शन योजना का संबंध पर्यटन क्षेत्र से है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का मुख्य ध्यान परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर केंद्रित है। वहीं, रेरा का गठन रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु किया गया है।

37. निम्नलिखित में से कौन-सा डेयरी सहकारी समितियों के आनंद पैटर्न का स्वीकृत स्तर नहीं है?
(A) जिला परिषद दुग्ध आवंटन बोर्ड
(B) ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति
(C) जिला दुग्ध उत्पादक संघ
(D) राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ

38. दशकों से हरित, श्वेत और नीली क्रांतियों के संयुक्त प्रभाव ने मुख्य रूप से भारत की समष्टि आर्थिक स्थिति को किस प्रकार परिवर्तित किया है?
(A) भारत को स्थायी रूप से प्रसंस्कृत पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का विश्व में सबसे बड़ा शुद्ध आयातकों में से एक बना दिया
(B) सभी राज्यों में घरेलू कृषि कार्यबल की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया
(C) संपूर्ण ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से समुद्री और सी-फूड निर्यात की ओर मोड़ दिया
(D) भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश से एक प्रमुख वैश्विक उत्पादक में बदल दिया

39. किसानों द्वारा हरित क्रांति की तकनीक को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी एक महत्वपूर्ण ढांचागत पूर्व-शर्त थी?
(A) प्रमुख गहरे समुद्री बंदरगाह निर्यात सुविधाओं से सीधी भौगोलिक निकटता
(B) ऋण और रियायती आगतों तक पहुंच
(C) पूरी तरह से स्वचालित उच्च तकनीक वाली ग्रीनहाउस प्रणालियों का व्यक्तिगत निजी स्वामित्व
(D) स्थानीय ग्राम दुग्ध सहकारी समितियों में अनिवार्य वैधानिक सदस्यता

40. निम्नलिखित में से कौन-सा इन प्रमुख कृषि मील के पत्थरों की शुरुआत का सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाता है?
(A) मैक्सिकन गेहूं की शुरुआत → ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ → तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का शुभारंभ → प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ
(B) ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ → मैक्सिकन गेहूं की शुरुआत → प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ → तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का शुभारंभ
(C) तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का शुभारंभ → ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ → मैक्सिकन गेहूं की शुरुआत → प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ
(D) मैक्सिकन गेहूं की शुरुआत → तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का शुभारंभ → ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ → प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ

41. हरित क्रांति के दौरान रासायनिक कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता का एक प्रत्यक्ष प्रतिकूल परिणाम क्या था?
(A) उपजाऊ मृदा में लाभदायक केंचुओं का तेजी से और अभूतपूर्व गुणात्मक विकास
(B) देश भर में पौधों के सभी ज्ञात विषाणुजन्य रोगों का पूर्ण और स्थायी उन्मूलन
(C) कृषि मैदानों के परिवेशी सूक्ष्म-जलवायु तापमान में महत्वपूर्ण दीर्घकालिक गिरावट
(D) प्रतिरोधी द्वितीयक कीटों का उद्भव और खाद्य श्रृंखला की विषाक्तता

42. नीली क्रांति के संदर्भ में, किन जल निकायों को मुख्य रूप से 'अंतर्देशीय मत्स्य पालन' के तहत वर्गीकृत किया गया है?
(A) नदियां, झीलें और जलाशय
(B) 200 समुद्री मील तक फैला संपूर्ण अनन्य आर्थिक क्षेत्र
(C) खारे तटीय बैकवाटर, ज्वारीय खाड़ियां और ज्वारनदमुख
(D) तटीय जल से परे गहरा महाद्वीपीय मग्नतट

43. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक घोषित उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र में 'अनुमार्गेयता' (पता लगाने की क्षमता) को बढ़ाना है। इसका क्या अर्थ है?
(A) गहरे समुद्र की व्हेल और बड़े स्तनधारियों के सटीक वार्षिक महासागरीय प्रवास पैटर्न को ट्रैक करना
(B) सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मछली को पकड़े जाने से लेकर उपभोक्ता तक ट्रैक करना
(C) अंतर्देशीय जलकृषि इकाइयों के लिए भूमिगत मीठे पानी के गहरे जलभृतों की भूगर्भीय पहचान करना
(D) तटीय मछुआरों को विशिष्ट, डिजिटल रूप से पता लगाने योग्य समुद्री राज्य सीमाओं तक ही सख्ती से सीमित करना

44. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): हरित क्रांति की प्रौद्योगिकियों की आलोचना सीमांत किसानों की तुलना में बड़े भूस्वामियों का पक्ष लेने के लिए की गई थी।
कारण (R): उच्च उपज वाली किस्म के बीजों, उर्वरकों और नलकूप सिंचाई के लिए भारी शुरुआती पूंजी निवेश की आवश्यकता थी जिसे छोटे किसान वहन नहीं कर सकते थे।
सही विकल्प का चयन कीजिए:
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।

45. सुनिश्चित सिंचाई बुनियादी ढांचे की कमी के कारण हरित क्रांति के शुरुआती गहन चरण के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को छोड़ दिया गया था?
(A) मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के शुष्क क्षेत्र
(B) पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपजाऊ और नहर-सिंचित मैदान
(C) पंजाब राज्य का नदी-समृद्ध कृषि केंद्र
(D) हरियाणा राज्य का गहन कृषि वाला अर्ध-शुष्क क्षेत्र

Click Here to Buy book on Flipkart

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) एक गंभीर घरेलू खाद्य संकट और व्यापक भुखमरी का संकट
1960 के दशक के मध्य में भारत को लगातार दो वर्षों तक भयंकर सूखे और अकाल जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा था। देश में खाद्यान्न उत्पादन अत्यधिक गिर गया था और भुखमरी का बड़ा संकट पैदा हो गया था। इस गंभीर घरेलू संकट से निपटने और नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए भारत को अमेरिकी पीएल-480 कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करने हेतु बाध्य होना पड़ा था।

2. (D) खाद्यान्न उत्पादन में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक के उत्तरार्ध में खाद्य संकट से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी। उस समय देश विदेशी खाद्यान्न सहायता पर अत्यधिक निर्भर था। इस कार्यक्रम का मुख्य ध्येय आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से गेहूं तथा चावल का उत्पादन बढ़ाकर देश को खाद्यान्न क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना था।

3. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
भारत ने हरित क्रांति के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की। उच्च उपज वाली बीजों की किस्मों, रासायनिक उर्वरकों और बेहतर सिंचाई तकनीकों के संयुक्त प्रयोग से देश में गेहूं और चावल की पैदावार अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गई। इस विशाल उत्पादन वृद्धि ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया और विदेशी सहायता पर देश की निर्भरता को पूरी तरह समाप्त कर दिया।

4. (C) गेहूं और चावल
हरित क्रांति के शुरुआती चरण में मुख्य रूप से खाद्यान्न सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस उद्देश्य को शीघ्र प्राप्त करने के लिए उच्च उपज देने वाली संकर किस्मों के बीजों का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया गया। यह संपूर्ण तकनीकी कार्यक्रम विशेष रूप से गेहूं और चावल की फसलों पर केंद्रित था, क्योंकि ये देश की प्रमुख मुख्य फसलें थीं और इनकी पैदावार बढ़ाकर त्वरित परिणाम प्राप्त किए जा सकते थे।

5. (A) मैक्सिको
भारत में लाई गई बौनी एवं उच्च उपज वाली गेहूं की नई किस्में मूल रूप से मैक्सिको में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र में विकसित की गई थीं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने इन आनुवंशिक रूप से उन्नत अर्ध-बौनी किस्मों को तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इन बीजों ने प्रतिकूल मौसम का सामना करते हुए अत्यधिक दाने पैदा करने की क्षमता प्रदर्शित की थी।

6. (D) आईआर-8
हरित क्रांति के काल में चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आईआर-8 नामक अर्ध-बौनी किस्म की शुरुआत की गई थी। इस विशेष किस्म को फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया था। इस किस्म ने पारंपरिक चावल के पौधों की तुलना में प्रति हेक्टेयर अत्यधिक उच्च उपज क्षमता प्रदान की, जिससे भारत में चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ गया।

7. (A) केवल I और II
हरित क्रांति की सफलता आधुनिक तकनीकी आगतों के एक समन्वित पैकेज पर निर्भर थी। उच्च उपज वाले बीजों को अपनी पूर्ण क्षमता प्रदर्शित करने के लिए प्रचुर मात्रा में नियमित जल और रासायनिक उर्वरकों के सही उपयोग की सख्त आवश्यकता थी। यह नवीन पद्धति पारंपरिक तथा स्वदेशी बीजों पर आधारित नहीं थी, बल्कि प्रयोगशालाओं में विकसित आनुवंशिक रूप से संकर किस्मों पर पूरी तरह निर्भर थी।

8. (C) नहर तंत्र और नलकूप
पंजाब और हरियाणा में कृषि के तीव्र विकास के लिए पानी की निरंतर और नियंत्रित आपूर्ति आवश्यक थी। उच्च उपज वाले बीजों की जल मांग को पूरा करने के लिए भूजल निष्कर्षण हेतु नलकूपों का व्यापक निर्माण किया गया तथा सरकारी स्तर पर नहरों के नेटवर्क का विस्तार किया गया। इस दोहरे सिंचाई ढांचे ने इन उत्तर-पश्चिमी राज्यों में हरित क्रांति को सफल बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाई।

9. (D) उच्च उपज वाली फसलों को अपनी अधिकतम उपज क्षमता प्राप्त करने के लिए उच्च पोषक आगतों की आवश्यकता थी
उच्च उपज वाली फसलों की चयापचय दर और विकास गति पारंपरिक फसलों की तुलना में बहुत अधिक होती है। इन आनुवंशिक रूप से विकसित बीजों को पौधे के तेजी से विकास और अत्यधिक दाने बनाने के लिए बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मिट्टी में प्राकृतिक पोषक तत्व इस मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थे, इसलिए रसायनों का गहन उपयोग अनिवार्य हो गया था।

10. (A) पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश
हरित क्रांति का पहला चरण भारत के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र तक मुख्य रूप से सीमित रहा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले से मौजूद बेहतर सिंचाई अवसंरचना, बड़े भू-भाग और वित्तीय रूप से सक्षम किसानों की उपस्थिति के कारण यह नई तकनीक तेजी से अपनाई गई। परिणामस्वरूप, इस विशिष्ट क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन और उत्पादकता में अभूतपूर्व तथा ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई।

NODIA

बंद कर देना चाहिए और पश्चिम से संशोधित जीवों का आयात करना चाहिए।
(C) उन्होंने राष्ट्रीय कृषि वित्तपोषण को स्थायी रूप से वाणिज्यिक वानिकी और लकड़ी उत्पादन की ओर मोड़ने का प्रयास किया।
(D) हरित क्रांति की तकनीकें अपूरणीय पारिस्थितिक क्षति पहुंचा रही थीं।

55. श्वेत क्रांति की सफलता के कारण एक विशाल राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड का निर्माण हुआ। इस ग्रिड का प्राथमिक कार्य क्या था?
(A) यूरोपीय वाणिज्यिक बाजारों में सीधे अनुपचारित कच्चे दूध की थोक खेप का नियमित रूप से निर्यात करना
(B) आपूर्ति को संतुलित करने के लिए दुग्ध-कमी वाले क्षेत्रों को अधिशेष क्षेत्रों से जोड़ना।
(C) सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में प्रसंस्कृत दूध के दैनिक उपभोग को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाना
(D) देश भर में सभी अधिशेष दूध को विशेष रूप से औद्योगिक रसायनों में व्यवस्थित रूप से परिवर्तित करना

56. रजत क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसके कारण अंडों और कुक्कुट के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई।
II. यह काफी हद तक आधुनिक वैज्ञानिक कुक्कुट पालन तरीकों को अपनाने से प्रेरित थी।
III. यह विशेष रूप से स्वदेशी, कम उपज वाली घरेलू पोल्ट्री के प्रजनन पर केंद्रित थी।
IV. इसे पशु चिकित्सा टीकों में चिकित्सा प्रगति से महत्वपूर्ण लाभ मिला।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) I, II और III
(B) I, II और IV
(C) II, III और IV
(D) I, III और IV

57. हरित क्रांति के शुरुआती चरण के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की पैदावार में सबसे महत्वपूर्ण सफलता देखी गई?
(A) चावल
(B) मक्का
(C) जौ
(D) गेहूं

58. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए:
(A) यह सभी भू-आबद्ध राज्यों में अंतर्देशीय जलकृषि को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती है।
(B) इसका उद्देश्य मत्स्य मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करना है।
(C) इसका उद्देश्य एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा तैयार करना है।
(D) यह मत्स्य श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा में सुधार करना चाहती है।

59. हरित क्रांति ने कृषि आगतों के किस वर्ग पर अत्यधिक निर्भरता पैदा की जो वैश्विक जीवाश्म ईंधन की कीमतों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थे?
(A) पारंपरिक जैव-निम्नीकरणीय जैविक खाद और हरी खाद
(B) संश्लेषित नाइट्रोजन युक्त उर्वरक
(C) प्राकृतिक रूप से प्राप्त जैव-कीटनाशक और वानस्पतिक अर्क
(D) स्वदेशी रूप से उत्पादित नीम-लेपित पारंपरिक बीजों की किस्में

60. अमूल सहकारी दुग्ध संग्रहण और प्रसंस्करण चक्र के निम्नलिखित तार्किक चरणों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. जिला संघ डेयरी संयंत्र में प्रसंस्करण और पैकेजिंग
2. ग्राम सहकारी समिति में शीतलन और संग्रहण
3. किसान द्वारा मवेशियों का दूध निकालना
4. राज्य महासंघ द्वारा विपणन और वितरण
सही क्रम का चयन कीजिए:
(A) 3, 2, 1, 4
(B) 2, 3, 1, 4
(C) 3, 1, 2, 4
(D) 1, 2, 3, 4

61. पंजाब में हरित क्रांति की सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक भूमि जोत की चकबंदी थी। यह क्यों महत्वपूर्ण थी?
(A) इसने निजी नलकूप और ट्रैक्टर यंत्रीकरण को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाया
(B) इसने बड़े पैमाने पर राज्य के स्वामित्व वाले सामूहिक कृषि फार्मों के केंद्रीय निर्माण को सक्षम बनाया
(C) इसने सीमांत किसानों को काम के लिए शहरी औद्योगिक केंद्रों में पलायन करने के लिए मजबूर किया
(D) इसने उपजाऊ कृषि भूमि को कारखानों में तेजी से और तत्काल बदलने की सुविधा प्रदान की

62. भारत में कौन-सा केंद्रीय मंत्रालय मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है?
(A) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(B) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
(C) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(D) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

NODIA

63. आनंद पैटर्न के त्रि-स्तरीय ढांचे के तहत, राज्य महासंघ (जैसे गुजरात में जीसीएमएमएफ) की मुख्य भूमिका क्या है?
(A) व्यक्तिगत ग्रामीण घरों से तरल दूध की सीधी दैनिक खरीद का प्रबंधन करना
(B) मवेशियों के लिए व्यापक पशु चिकित्सा उपचार और कृत्रिम गर्भाधान प्रदान करना
(C) डेयरी किसानों को सीधे कम ब्याज वाले संस्थागत कृषि

44. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
हरित क्रांति की तकनीक पूंजी-गहन थी, जिसके लिए उन्नत बीज, उर्वरक और सिंचाई उपकरणों में बड़े वित्तीय निवेश की आवश्यकता थी। संसाधनों की प्रचुरता के कारण बड़े भूस्वामी इन महंगे आगतों को आसानी से खरीद सके और अत्यधिक लाभ कमाया। इसके विपरीत, छोटे और सीमांत किसान आवश्यक पूंजी की कमी के कारण इस दौड़ में पिछड़ गए, जिससे सामाजिक-आर्थिक विषमता बढ़ी।

45. (A) मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के शुष्क क्षेत्र
हरित क्रांति के शुरुआती चरण में केवल उन्हीं क्षेत्रों को चुना गया जहाँ सुनिश्चित सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध थीं। मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के शुष्क एवं वर्षा-आधारित क्षेत्रों में सिंचाई नहरों और भूजल अवसंरचना का अभाव था। परिणामस्वरुप, इन क्षेत्रों को शुरुआत में इस तकनीकी विस्तार से बाहर रखा गया और ध्यान मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिमी सिंचित मैदानी भागों पर ही केंद्रित रहा।

46. (C) समिति के दुग्ध उत्पादक किसान सदस्य
अमूल का प्रशासनिक और ढांचागत मॉडल लोकतांत्रिक सहकारिता के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्राथमिक ग्राम दुग्ध सहकारी समिति के स्तर पर पंजीकृत दुग्ध उत्पादक किसान ही समिति के वास्तविक मालिक होते हैं। ये सभी किसान सदस्य मिलकर निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया द्वारा अपनी स्थानीय प्रबंध समिति के सदस्यों का चुनाव करते हैं, जो समिति के दैनिक कार्यों और निर्णयों का संचालन करते हैं।

47. (D) तिलहन जैसे सरसों और सोयाबीन
भारत में पीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश को खाद्य तेलों के उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना था। इस क्रांति के तहत तिलहन फसलों जैसे सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी और तिल के रकबे तथा उत्पादकता में भारी वृद्धि की गई। नई कृषि तकनीकों और उन्नत बीजों के माध्यम से तिलहन फसलों के उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया था।

48. (B) केवल II और III
हरित क्रांति के तहत नाइट्रोजन युक्त रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण वे बारिश के पानी में घुलकर भूजल में मिल गए, जिससे नाइट्रेट प्रदूषण बढ़ा। इसके अतिरिक्त, केवल गेहूं और चावल जैसी दो प्रमुख फसलों की व्यापक खेती पर बल देने से पारंपरिक देशी फसलों और स्थानीय कृषि जैव विविधता को भारी नुकसान पहुँचा, जिससे पारिस्थितिक असंतुलन की समस्या पैदा हुई।

49. (B) Fish Farmers Development Agencies
भारत में नीली क्रांति की नींव रखने और ग्रामीण स्तर पर मत्स्य पालन को व्यावसायिक रुप देने में एफएफडीए की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एफएफडीए का पूर्ण रुप 'फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसीज' (मत्स्य कृषक विकास एजेंसियां) है। इन जिलास्तरीय एजेंसियों की स्थापना किसानों को मत्स्य पालन की नई तकनीकें सिखाने, वित्तीय सहायता प्रदान करने और जल निकायों के आवंटन हेतु की गई थी।

50. (C) 20-25%
मत्स्य क्षेत्र में शीतलन, परिवहन और वैज्ञानिक भंडारण जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण पकड़ी गई 20-25% मछलियां सड़कर नष्ट हो जाती हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य आधुनिक कोल्ड-चैन अवसंरचना, आधुनिक मत्स्य बंदरगाहों और कुशल मूल्य श्रृंखला का निर्माण करके इस कटाई-पश्चात की भारी बर्बादी को घटाकर न्यूनतम स्तर तक लाना है।

51. (A) निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता मानकों को पूरा करना
गुलाबी क्रांति के तहत मांस प्रसंस्करण इकाइयों और बूचड़खानों का तकनीकी आधुनिकीकरण करने का मुख्य उद्देश्य प्रसंस्कृत मांस के गुणवत्ता एवं स्वच्छता मानकों में सुधार करना था। विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धी बनने और कड़े अंतरराष्ट्रीय फाइटोसैनिटरी मानकों को पूरा करने के लिए आधुनिक तकनीकों, रोगाणुमुक्त वातावरण और वैज्ञानिक पैकेजिंग पद्धतियों को अपनाना अनिवार्य था, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके।

52. (C) P-4, Q-2, R-3, S-1
विभिन्न कृषि क्रांतियों की सफलता विशिष्ट आगतों पर आधारित थी। हरित क्रांति मुख्य रूप से रासायनिक उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों पर निर्भर थी। श्वेत क्रांति की प्रगति में कृत्रिम गर्भाधान और पशु चिकित्सा का मुख्य योगदान था। नीली क्रांति के लिए आधुनिक हैचरी तथा मत्स्य बीजों का विकास आवश्यक था, जबकि रजत क्रांति पोल्ट्री लेयर्स के संकरण पर केंद्रित थी।

53. (A) हरित क्रांति ने बड़े भूस्वामियों का पक्ष लिया; श्वेत क्रांति ने भूमिहीन और सीमांत किसानों को एकीकृत किया।
हरित क्रांति में महंगी मशीनों और उर्वरकों की आवश्यकता के कारण बड़े भूस्वामियों को अधिक लाभ मिला, जबकि संसाधनहीन छोटे किसान पिछड़ गए। इसके विपरीत, श्वेत क्रांति ने भूमिहीन मजदूरों और सीमांत किसानों को एक-दो मवेशियों के साथ सहभागी बनाया। डेयरी सहकारिता ने बिना किसी बड़े भूमि निवेश के इन निर्धन परिवारों को संगठित कर उनकी नियमित दैनिक आय सुनिश्चित की।

54. (D) हरित क्रांति की तकनीकें अपूरणीय पारिस्थितिक क्षति पहुंचा रही थीं।
डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन ने देखा कि हरित क्रांति के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन, मिट्टी की उर्वरता का क्षरण और रासायनिक रसायनों का जहरीला प्रभाव पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुँचा रहा था। इस पारिस्थितिक संकट को रोकने और दीर्घकालिक कृषि सुरक्षा बनाए रखने के लिए उन्होंने एक ऐसी प्रणाली की वकालत की जो प्रकृति को नुकसान पहुँचाए बिना फसलों की उत्पादकता बढ़ा सके।

Downloaded from www.pdf.tube

73. सूची I में दिए गए पारिस्थितिक परिणाम को सूची II की उस विशिष्ट हरित क्रांति पद्धति से सुमेलित कीजिए जिसके कारण यह प्रत्यक्ष रूप से हुआ:

सूची I: (पारिस्थितिक परिणाम)

P. भूजल का क्षरण
Q. मृदा लवणता और जलजमाव
R. पीने के पानी में नाइट्रेट प्रदूषण
S. स्वदेशी बीज किस्मों की हानि

सूची II: (पद्धति)

1. नाइट्रोजन युक्त रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग
2. इलेक्ट्रिक नलकूपों के माध्यम से अत्यधिक पंपिंग
3. अस्तर रहित नहर नेटवर्क के माध्यम से अत्यधिक सिंचाई
4. कुछ मानकीकृत उच्च उपज वाले बीजों को सार्वभौमिक रूप से अपनाना

सही कूट का चयन कीजिए:

(A) P-3, Q-2, R-4, S-1
(B) P-2, Q-1, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-1, S-2
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

74. दवा (फार्मास्युटिकल) क्षेत्र में गुलाबी क्रांति किसकी तीव्र वृद्धि से दृढ़ता से जुड़ी हुई है?

(A) जेनेरिक दवाएं और टीके
(B) पारंपरिक आयुर्वेदिक और हर्बल औषधीय सूत्र
(C) उन्नत सर्जिकल उपकरण और नैदानिक उपकरण निर्माण
(D) जैविक हर्बल सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद और त्वचा देखभाल उपचार

75. हरित क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन लाभों के बावजूद, 'क्षेत्रीय असमानताओं' को जन्म देने के लिए इसकी भारी आलोचना की गई थी। क्रांति के पहले दो दशकों के दौरान कौन-सा क्षेत्र विशेष रूप से पीछे छूट गया था?

(A) आंध्र प्रदेश राज्य का डेल्टाई तटीय क्षेत्र
(B) पूर्वी भारत (बिहार, यूपी, ओडिशा)
(C) पंजाब और हरियाणा राज्यों का उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र
(D) पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपजाऊ नहर-सिंचित मैदान

76. डेयरी विकास के संदर्भ में, एनडीडीबी का पूर्ण रूप क्या है?

(A) नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ डेयरी बिजनेस
(B) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड
(C) न्यू दिल्ली डेयरी ब्यूरो
(D) नेशनल डेयरी डिस्ट्रिब्यूशन ब्रांच

77. गुलाबी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. इसमें मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र का आधुनिकीकरण शामिल है।
II. इसमें जल्द खराब होने वाले सामानों के लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है।
III. यह प्रसंस्कृत मांस उत्पादों के निर्यात को सख्ती से प्रतिबंधित करती है।
IV. यह भारत की फार्मास्युटिकल निर्माण क्षमताओं के विकास के अनुकूल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) I, II और III
(B) I, II और IV
(C) II, III और IV
(D) I, III और IV

NODIA

78. निम्नलिखित में से कौन-सा नीली क्रांति के तहत बढ़ावा दी गई 'जलकृषि' की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है?

(A) भारी यंत्रीकृत ट्रॉलेरों का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय जल में जंगली मछलियों का खुले समुद्र में शिकार
(B) अपतटीय समुद्री रिग से कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक निष्कर्षण
(C) जलीय जीवों का नियंत्रित प्रजनन और कटाई/संग्रहण
(D) प्रमुख नदियों पर बड़े बहुउद्देशीय जलविद्युत बांधों का इंजीनियरिंग और निर्माण

79. ग्रामीण भारत पर श्वेत क्रांति का एक गहरा दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव क्या था?

(A) मेगा-डेयरी संयंत्रों के लिए भूमि खाली कराने हेतु ग्रामीणों का बड़े पैमाने पर विस्थापन
(B) किसानों द्वारा निजी दूध की खपत को प्रतिबंधित करने वाले सख्त कानूनी प्रतिबंधों को लागू करना
(C) वाणिज्यिक मवेशी पालन के साथ सभी फसल खेती का व्यवस्थित प्रतिस्थापन
(D) डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण

80. निम्नलिखित में से कौन-सा खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण के सही क्रम को दर्शाता है?

(A) पीएल-480 आयातों पर निर्भरता → हरित क्रांति की उच्च उपज वाली तकनीक को अपनाना → आत्मनिर्भरता की प्राप्ति → सदाबहार क्रांति स्थिरता की ओर बदलाव
(B) हरित क्रांति की उच्च उपज वाली तकनीक को अपनाना → पीएल-480 आयातों पर निर्भरता → सदाबहार क्रांति स्थिरता की ओर बदलाव → आत्मनिर्भरता की प्राप्ति
(C) सदाबहार क्रांति स्थिरता की ओर बदलाव → आत्मनिर्भरता की प्राप्ति → पीएल-480 आयातों पर निर्भरता → हरित क्रांति की उच्च उपज वाली तकनीक को अपनाना
(D) आत्मनिर्भरता की प्राप्ति → सदाबहार क्रांति स्थिरता की ओर बदलाव → हरित क्रांति की उच्च उपज वाली तकनीक को अपनाना → पीएल-480 आयातों पर निर्भरता

ऋण जारी करना
(D) एक साझा ब्रांड के तहत प्रसंस्कृत डेयरी उत्पादों का विपणन करना

64. हरित क्रांति से पहले भारत द्वारा प्राप्त पीएल-480 खेपों का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) द्विपक्षीय सैन्य हार्डवेयर सहायता और रक्षा सहायता प्रदान करना
(B) अंतरिक्ष और उपग्रह संचार उपकरणों के तकनीकी हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाना
(C) कमी को पूरा करने के लिए रियायती दरों पर गेहूं का आयात
(D) प्रमुख बहुउद्देशीय बांधों के निर्माण के लिए गैर-वापसी योग्य वित्तीय अनुदान प्रदान करना

65. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): हरित क्रांति के कारण प्राथमिक रूप से अपनाने वाले क्षेत्रों में दालों और मोटे अनाजों की खेती में गिरावट आई।
कारण (R): अत्यधिक लाभदायक उपज में सफलता और सुनिश्चित खरीद मूल्य मुख्य रूप से गेहूं और चावल की ओर झुके हुए थे।
सही विकल्प का चयन कीजिए:
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।

66. डेयरी सहकारी समितियों का "आनंद पैटर्न" पारंपरिक सरकारी डेयरियों की तुलना में अत्यधिक टिकाऊ और सफल साबित हुआ, मुख्य रूप से क्योंकि:
(A) यह लगभग पूरी तरह से सब्सिडी वाले आयातित तरल दूध के स्टॉक पर निर्भर होकर संचालित होता था
(B) इसने सभी स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय करों से पूर्ण स्थायी छूट प्राप्त की
(C) इसने अपने प्रसंस्करण और विपणन को विशेष रूप से अभिजात वर्ग के उच्च आय वाले शहरी उपभोक्ताओं पर केंद्रित किया
(D) इसमें किसानों द्वारा चुने गए बोर्डों के प्रति जवाबदेह पेशेवर प्रबंधन था

67. नीली क्रांति ने भारत के निर्यात परिदृश्य को काफी बदल दिया है। मूल्य के आधार पर भारत के सी-फूड निर्यात में किस विशिष्ट समुद्री उत्पाद का हिस्सा सबसे बड़ा है?
(A) फ्रोजन झींगा
(B) प्रसंस्कृत फ्रोजन टूना फिलेट्स
(C) डिब्बाबंद अपतटीय सार्डिन
(D) धूप में सुखाई गई बॉम्बे डक (बम्बिल) मछली

68. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि अनुसंधान का समन्वय करने वाला शीर्ष निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है?
(A) हैदराबाद
(B) करनाल
(C) नई दिल्ली
(D) लुधियाना

69. पीली क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसे खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था।
II. तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन (1986) एक प्रमुख उत्प्रेरक था।
III. इसके परिणामस्वरूप भारत द्वारा सभी खाद्य तेल आयातों पर स्थायी रूप से रोक लगा दी गई।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

70. ऑपरेशन फ्लड को अपने शुरुआती चरणों में किसके द्वारा उपहार में दी गई वस्तुओं (स्कीम्ड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल) की बिक्री के माध्यम से भारी धन प्राप्त हुआ था?
(A) पीएल-480 कार्यक्रम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका विदेशी सहायता प्रशासन
(B) विशेष द्विपक्षीय व्यापार संधियों के माध्यम से सोवियत संघ सरकार
(C) मानवीय कृषि अनुदान के माध्यम से अफ्रीकी संघ विकास एजेंसी
(D) यूरोपीय आर्थिक समुदाय और विश्व खाद्य कार्यक्रम

71. रजत क्रांति ने आधुनिक पोल्ट्री फार्मिंग पर जोर दिया। इस संदर्भ में 'लेयर्स' और 'ब्रॉयलर्स' के बीच मौलिक अंतर क्या है?
(A) लेयर्स को मांस के लिए पाला जाता है, जबकि ब्रॉयलर्स को अंडों के लिए पाला जाता है।
(B) लेयर्स को अंडों के लिए पाला जाता है, जबकि ब्रॉयलर्स को मांस के लिए पाला जाता है।
(C) लेयर्स देशी नस्लें हैं, जबकि ब्रॉयलर्स विदेशी नस्लें हैं।
(D) लेयर्स समुद्री पक्षी हैं, जबकि ब्रॉयलर्स मैदानी पक्षी हैं।

72. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन कीट प्रबंधन के प्रति "सदाबहार क्रांति" के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है?
(A) शक्तिशाली संश्लेषित आर्गेनोक्लोरीन रासायनिक छिड़काव पर अनन्य और पूर्ण निर्भरता
(B) खेतों की सीमाओं से कीड़ों की सभी प्रजातियों का व्यवस्थित और पूर्ण उन्मूलन
(C) जैविक और न्यूनतम रासायनिक नियंत्रणों को संयोजित करने वाला एकीकृत कीट प्रबंधन
(D) सभी कीट नियंत्रण और फसल सुरक्षा उपायों का पूर्ण नियामक परित्याग

Click Here to Buy book on Amazon

11. (B) P-4, Q-3, R-2, S-1
भारत में विभिन्न कृषि क्रांतियों ने विशिष्ट क्षेत्रों का कायाकल्प किया। हरित क्रांति का संबंध मुख्य खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने से था। श्वेत क्रांति ने डेयरी उद्योग और दुग्ध आपूर्ति में क्रांतिकारी बदलाव किया। नीली क्रांति का ध्यान मत्स्य पालन और जलकृषि संवर्धन पर केंद्रित था, जबकि पीली क्रांति ने देश को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया।

12. (B) धनी और सीमांत किसानों के बीच आय की असमानताओं को बढ़ा दिया
हरित क्रांति की तकनीक काफी खर्चीली थी, जिसके तहत महंगे बीजों, उर्वरकों और सिंचाई उपकरणों के क्रय के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े और धनी किसान इन संसाधनों को आसानी से जुटाने में सक्षम थे, जिससे उनकी आय में अत्यधिक वृद्धि हुई। इसके विपरीत, संसाधनों की कमी के कारण छोटे और सीमांत किसान इस क्रांति का पूर्ण लाभ उठाने से वंचित रह गए।

13. (A) मृदा स्वास्थ्य का क्षरण और कीटों के प्रति फसलों की संवेदनशीलता में वृद्धि
एक ही प्रकार की फसलों को बड़े पैमाने पर बार-बार उगाने से मिट्टी के प्राकृतिक पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है। हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की लगातार खेती से मृदा स्वास्थ्य में गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, आनुवंशिक रूप से एक समान फसलों के विस्तृत विस्तार ने फसलों को विशिष्ट कीटों और बीमारियों के हमलों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील और असुरक्षित बना दिया।

14. (A) केवल I और II
हरित क्रांति ने उत्तर-पश्चिमी राज्यों को अत्यधिक समृद्ध बनाया, जबकि पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र शुरुआत में पीछे छूट गए, जिससे गंभीर क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ। गहन नलकूप सिंचाई के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ। इसके अलावा, इस पद्धति में रासायनिक कीटनाशकों और कृत्रिम उर्वरकों का व्यापक उपयोग किया गया, जिसने दीर्घकालिक रूप से प्राकृतिक मृदा स्वास्थ्य एवं जैविक उर्वरता को नुकसान पहुँचाया।

15. (D) नलकूपों का उपयोग करके अत्यधिक जल-गहन धान की गहन खेती
पंजाब और हरियाणा की भौगोलिक स्थिति पारंपरिक रूप से धान की खेती के लिए अनुकूल नहीं थी। हरित क्रांति के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य और सुनिश्चित खरीद के कारण किसानों ने अत्यधिक पानी की खपत वाली धान की फसल उगाना शुरु किया। इसके लिए डीजल और बिजली के नलकूपों से भूजल का निरंतर दोहन किया गया, जिससे इस क्षेत्र में भूजल स्तर खतरनाक गहराई तक गिर गया।

16. (C) श्वेत क्रांति
वर्ष 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरु किया गया 'ऑपरेशन फ्लड' भारत की श्वेत क्रांति का आधार स्तंभ था। इस राष्ट्रव्यापी पहल का मुख्य उद्देश्य दूध उत्पादन में भारी वृद्धि करना, ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को संगठित करना और देश भर में एक सुदृढ़ डेयरी मूल्य श्रृंखला स्थापित करना था। इसने भारत को दुग्ध की कमी वाले देश से विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनाया।

17. (B) डेयरी और दुग्ध उत्पादन
ऑपरेशन फ्लड को वैश्विक स्तर पर ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा और सफल कार्यक्रम माना जाता है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बिखरे हुए लाखों छोटे दुग्ध उत्पादकों को सहकारी समितियों से जोड़ा। इसके माध्यम से डेयरी क्षेत्र में प्रसंस्करण, शीतलन और वितरण का व्यापक ढांचा खड़ा किया गया, जिससे देश में दूध का उत्पादन अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया।

18. (D) वर्गीज कुरियन
डॉ. वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने अमूल के सफल सहकारी मॉडल की स्थापना की और ऑपरेशन फ्लड का कुशल नेतृत्व किया। उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण और संगठनात्मक प्रयासों के कारण लाखों छोटे और सीमांत किसानों को डेयरी व्यवसाय के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया गया, जिससे भारत दुनिया में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राष्ट्र बन सका।

19. (A) दुग्ध उत्पादकों के स्वामित्व वाली एक त्रि-स्तरीय सहकारी संरचना
आनंद पैटर्न एक त्रि-स्तरीय सहकारी संरचना पर आधारित मॉडल है जिसमें प्राथमिक स्तर पर ग्राम दुग्ध समितियाँ, जिला स्तर पर दुग्ध संघ और राज्य स्तर पर दुग्ध महासंघ कार्य करते हैं। इस ढाँचे का पूरा स्वामित्व और नियंत्रण स्वयं दुग्ध उत्पादक किसानों के हाथों में होता है। यह व्यवस्था बिचौलियों को समाप्त करके उत्पादकों को उनके दूध का उचित मूल्य प्रदान करती है।

NODIA

20. (C) 2, 3, 1
आनंद पैटर्न का संगठनात्मक ढांचा नीचे से ऊपर की ओर एक सुव्यवस्थित त्रि-स्तरीय प्रणाली का अनुसरण करता है। सबसे निचले यानी गांव के स्तर पर ग्रामीण दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां कार्य करती हैं। ये ग्रामीण समितियां जिला स्तर पर एकीकृत होकर जिला दुग्ध उत्पादक संघ का निर्माण करती हैं। अंततः, शीर्ष राज्य स्तर पर विपणन के संचालन के लिए राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ कार्यरत होता है।

21. (A) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
गुजरात के आनंद में अमूल की अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने इस सहकारी मॉडल को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया। इसके क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई। इस संस्था की जिम्मेदारी देश के विभिन्न राज्यों में आनंद पैटर्न पर आधारित डेयरी सहकारी समितियों का गठन और संचालन सुनिश्चित करना था।

22. (D) उपभोक्ता मूल्य का अधिकतम हिस्सा किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना
पारंपरिक दुग्ध व्यापार में बिचौलिए और व्यापारी किसानों से कम कीमत पर दूध खरीदकर उपभोक्ताओं को महंगे दामों पर बेचते थे। अमूल मॉडल ने प्रत्यक्ष संग्रह और पारदर्शी माप प्रणालियों के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला से मध्यस्थों को हटा दिया। इससे प्रसंस्करण और विपणन लागत कम हुई और उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि का अधिकतम हिस्सा सीधे किसानों के खाते में पहुँचा।

23. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
श्वेत क्रांति ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों और छोटे किसानों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार किया। खेती के विपरीत, पशुपालन के लिए बड़ी भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। डेयरी व्यवसाय ने इन निर्धन परिवारों को साल भर नियमित दैनिक आय प्रदान की, जिससे वे फसल कटाई के मौसम के बाहर भी अपनी आजीविका सुरक्षित करने में पूरी तरह सक्षम बने।

24. (C) मत्स्य उत्पादन और जलकृषि के विकास में वृद्धि करना
भारत में नीली क्रांति का मूल विचार देश के जल संसाधनों का वैज्ञानिक और सतत उपयोग करके मत्स्य उत्पादन को अत्यधिक बढ़ाना था। इस पहल का उद्देश्य जलीय कृषि, तटीय मत्स्य विकास और अंतर्देशीय जल निकायों में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर मछली पकड़ने तथा पालन के तरीकों का आधुनिकीकरण करना था ताकि मछुआरों की आय और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

25. (D) अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य पालन दोनों को
नीली क्रांति की रणनीति का दायरा केवल तटीय क्षेत्रों तक सीमित न होकर बहुआयामी था। इसके अंतर्गत समुद्रों में गहराई तक जाकर मछली पकड़ने की आधुनिक क्षमताओं के विकास के साथ-साथ नदियों, तालाबों, झीलों और जलाशयों में अंतर्देशीय मत्स्य पालन को भी समान रूप से प्रोत्साहित किया गया। इस व्यापक दृष्टिकोण से देश के सभी क्षेत्रों में जलीय उत्पादन को बढ़ावा मिला।

26. (A) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र का सतत और उत्तरदायी विकास करना है। इस योजना के माध्यम से अवसंरचना विकास, आधुनिक तकनीक को अपनाने, मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने और फसल पश्चात की क्षति को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे मछुआरों और मत्स्य पालकों का आर्थिक कल्याण संभव हो सके।

27. (B) केवल I और II
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य ध्यान मछुआरों की आय बढ़ाने और मत्स्य क्षेत्र का समग्र कायाकल्प करने पर है। यह योजना आधुनिक कोल्ड चेन, प्रसंस्करण इकाइयों और परिवहन सुविधाओं का निर्माण करके कटाई के बाद होने वाले नुकसान को नियंत्रित करती है। साथ ही, यह योजना जलीय कृषि गतिविधियों में महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी को भी बढ़ावा देती है।

28. (B) बहु-फसली मांगों के कारण ग्रामीण श्रम अवशोषण में वृद्धि हुई
हरित क्रांति के शुरुआती वर्षों में सिंचाई और लघु-अवधि की फसलों की शुरुआत से वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाना संभव हो गया। बहु-फसली चक्र लागू होने से बुआई, निराई, कटाई और थ्रेसिंग जैसी गतिविधियों में अचानक भारी वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई और स्थानीय रोजगार बढ़ा।

29. (A) कृषि यंत्रीकरण में तीव्र वृद्धि
हरित क्रांति के उत्तरार्ध में किसानों ने उत्पादन बढ़ाने और समय की बचत के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर और सीड ड्रिल जैसी आधुनिक मशीनों का बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू कर दिया। मशीनीकरण के इस विस्तार के कारण कृषि कार्यों में शारीरिक श्रम की आवश्यकता काफी कम हो गई, जिससे कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन के अनुपात में रोजगार सृजन की दर घटने लगी।

30. (C) पीली क्रांति
भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से शुरू की गई पीली क्रांति का सीधा संबंध 'तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन' से है। वर्ष 1986 में शुरू किए गए इस मिशन का मुख्य उद्देश्य तिलहन फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादकता को बढ़ाना, नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना तथा तेल प्रसंस्करण उद्योग को आधुनिक एवं कुशल बनाना था।

31. (D) P-4, Q-1, R-2, S-3
डॉ. वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व करके देश में डेयरी विकास की नींव रखी। डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन ने पर्यावरणीय संतुलन के साथ कृषि उत्पादकता बनाए रखने हेतु 'सदाबहार क्रांति' की अवधारणा दी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने देश भर में डेयरी सहकारी नेटवर्क स्थापित किया, जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और तकनीकी विकास का कार्य करती है।

32. (C) मांस प्रसंस्करण और औषध निर्माण
भारत में गुलाबी क्रांति मुख्य रूप से दो प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति से जुड़ी हुई है। पहला क्षेत्र मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण है, जिसके तहत बूचड़खानों के स्वच्छता मानकों में सुधार किया गया। दूसरा क्षेत्र फार्मास्युटिकल उद्योग का विस्तार है, जिसके अंतर्गत भारत ने कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं और टीकों के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर बड़ी सफलता हासिल की।

33. (B) अंडे और कुक्कुट उत्पादन
रजत क्रांति का मुख्य ध्यान भारत में पोल्ट्री उद्योग को आधुनिक बनाना और अंडों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हासिल करना

Downloaded from www.pdf.tube

था। वैज्ञानिक प्रबंधन पद्धतियों, संकर नस्ल के पक्षियों की शुरुआत और उन्नत पशु चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से पोल्ट्री फार्मिंग को एक व्यावसायिक दर्जा दिया गया। इससे देश में पोल्ट्री उत्पादों की उपलब्धता में भारी वृद्धि हुई और प्रोटीन पोषण में सुधार हुआ।

34. (D) कृषि अनुसंधान, बीज विकास और विस्तार सेवाएं प्रदान करना
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश में कृषि शिक्षा और अनुसंधान का समन्वय करने वाली शीर्ष संस्था है। विभिन्न कृषि क्रांतियों के दौरान इस परिषद की मुख्य भूमिका नई उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों का विकास करना, फसल संरक्षण पद्धतियों पर शोध करना और प्रयोगशालाओं में विकसित नवीन कृषि तकनीकों को किसानों तक पहुँचाने हेतु विस्तार सेवाएँ प्रदान करना था।

35. (B) I, II और IV
डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा प्रतिपादित सदाबहार क्रांति का मुख्य दर्शन पर्यावरणीय क्षति के बिना कृषि उत्पादकता में निरंतर वृद्धि करना है। यह दृष्टिकोण रासायनिक आगतों के अत्यधिक और अंधाधुंध उपयोग का कड़ा विरोध करता है। इसके बजाय, यह जैविक खेती, मृदा संरक्षण, कुशल जल प्रबंधन और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हुए दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल देता है।

36. (C) किसी भी कीमत पर उपज के अधिकतमीकरण से सतत उत्पादकता की ओर बदलाव
हरित क्रांति में प्राकृतिक संसाधनों की चिंता किए बिना केवल उत्पादन की मात्रा बढ़ाने पर जोर दिया गया था, जिससे जल संकट और मृदा प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं। सदाबहार क्रांति की ओर बदलाव यह स्वीकार करता है कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा केवल तभी संभव है जब उत्पादकता में वृद्धि पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ हो और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए।

37. (A) जिला परिषद दुग्ध आवंटन बोर्ड
आनंद पैटर्न केवल तीन विशिष्ट प्रशासनिक स्तरों पर आधारित एक संगठनात्मक ढांचा है। इसमें ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, जिला स्तर पर दुग्ध उत्पादक संघ तथा राज्य स्तर पर सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ शामिल हैं। 'जिला परिषद दुग्ध आवंटन बोर्ड' जैसी कोई संस्था इस स्वीकृत मॉडल का हिस्सा नहीं है और इसका इस त्रि-स्तरीय संरचना से कोई संबंध नहीं है।

38. (D) भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश से एक प्रमुख वैश्विक उत्पादक में बदल दिया
हरित, श्वेत और नीली क्रांतियों के सम्मिलित प्रभाव ने भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी। स्वतंत्रता के बाद विदेशी सहायता पर निर्भर रहने वाला देश आज अनाज, दूध और मत्स्य उत्पादों के प्रमुख वैश्विक उत्पादकों एवं निर्यातकों में शामिल है। इन क्रांतियों ने देश को खाद्य संकट से बाहर निकालकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, पोषण और ग्रामीण समृद्धि को मजबूती प्रदान की।

39. (B) ऋण और रियायती आगतों तक पहुंच
हरित क्रांति की तकनीक को अपनाने के लिए किसानों को महंगे संकर बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और नलकूप लगाने हेतु पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता थी। जिन किसानों के पास संस्थागत कृषि ऋण और रियायती दरों पर सरकारी सब्सिडी वाले आगत सुलभ थे, वे ही इस नई प्रणाली को सफलतापूर्वक अपना सके। इसलिए, वित्तीय सहायता तक पहुंच इसके क्रियान्वयन की मुख्य शर्त थी।

40. (A) मैक्सिकन गेहूं की शुरुआत → ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ → तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का शुभारंभ → प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ
भारतीय कृषि में इन पहलों का ऐतिहासिक क्रम इस प्रकार है: 1960 के दशक के मध्य में मैक्सिकन गेहूं के बीजों की शुरुआत हुई। इसके बाद वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ हुआ। तिलहन उत्पादन को गति देने के लिए 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया गया, और सबसे अंत में वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरु की गई।

41. (D) प्रतिरोधी द्वितीयक कीटों का उद्भव और खाद्य श्रृंखला की विषाक्तता
हरित क्रांति के दौरान फसलों पर रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध और अत्यधिक छिड़काव किया गया। इसके परिणामस्वरुप मित्र कीट नष्ट हो गए और हानिकारक कीटों में इन रसायनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई, जिससे द्वितीयक कीटों का प्रकोप बढ़ गया। इसके अतिरिक्त, ये जहरीले रसायन मिट्टी और पानी के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जीवों में संचित होने लगे।

42. (A) नदियां, झीलें और जलाशय
नीली क्रांति के संदर्भ में 'अंतर्देशीय मत्स्य पालन' का तात्पर्य गैर-समुद्री या मीठे पानी के संसाधनों से है। इसके अंतर्गत देश की भूमि सीमा के भीतर स्थित नदियाँ, नहरें, प्राकृतिक झीलें, तालाब, दलदली भूमि और कृत्रिम जलाशय शामिल हैं। इन जल निकायों में मछली पालन और पकड़ने की तकनीकों को आधुनिक बनाकर मत्स्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई थी।

NODIA

43. (B) सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मछली को पकड़े जाने से लेकर उपभोक्ता तक ट्रैक करना
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अनुमार्गेयता का अर्थ एक डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली स्थापित करना है। इसके माध्यम से मछली को जल निकाय से पकड़े जाने से लेकर प्रसंस्करण, भंडारण और अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचने के पूरे सफर को ट्रैक किया जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता मानकों का पालन और निर्यात बाजारों में भारतीय समुद्री खाद्य की साख सुनिश्चित होती है।

46. अमूल मॉडल की संरचनात्मक सफलता काफी हद तक इसकी लोकतांत्रिक प्रकृति पर निर्भर करती है। गांव के स्तर पर, दुग्ध सहकारी समिति की प्रबंधन समिति का चुनाव कौन सीधे करता है?
(A) जिले की सेवा करने वाले स्थानीय रूप से निर्वाचित विधानसभा सदस्य
(B) डेयरी मामलों के प्रभारी कैबिनेट रैंक के राज्य सहकारिता मंत्री
(C) समिति के दुग्ध उत्पादक किसान सदस्य
(D) जिला कलेक्टर के रूप में कार्यरत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

47. "पीली क्रांति" ने किस विशिष्ट फसल श्रेणी के उत्पादन में एक बड़ी सफलता हासिल की?
(A) उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय खट्टे फल जैसे नींबू और संतरे
(B) हल्दी और केसर सहित उच्च मूल्य वाले वाणिज्यिक मसाले
(C) मीठे मक्के और चारे वाले मक्के की संकर पीली किस्में
(D) तिलहन जैसे सरसों और सोयाबीन

48. हरित क्रांति की पर्यावरणीय आलोचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उसने पारंपरिक, सूखा-प्रतिरोधी मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया।
II. इसके कारण उर्वरक अपवाह के कारण भूजल में गंभीर नाइट्रेट प्रदूषण हुआ।
III. इसके कारण कृषि जैव विविधता में चिंताजनक गिरावट आई।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

49. भारत में नीली क्रांति को प्रेरित करने वाला एक प्रमुख कारक एफएफडीए (FFDA) की स्थापना थी। एफएफडीए का पूर्ण रूप क्या है?
(A) फेडरल फिशरीज डिस्ट्रिब्यूशन अथॉरिटी
(B) फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसीज
(C) फॉरेन फिशिंग डिरेगुलेशन एक्ट
(D) फ्रेशवॉटर फ्लोरा डेवलपमेंट एसोसिएशन

50. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य मत्स्य क्षेत्र में फसल पश्चात की क्षति को काफी कम करना है। इस क्षति का सामान्यतः अनुमानित आधार स्तर क्या है जिसे योजना कम करना चाहती है?
(A) 1-2%
(B) 5-10%
(C) 20-25%
(D) 50-60%

51. गुलाबी क्रांति के अंतर्गत बूचड़खानों और मांस प्रसंस्करण इकाइयों का तकनीकी आधुनिकीकरण शामिल है। इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण के पीछे प्राथमिक कारक क्या है?
(A) निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता मानकों को पूरा करना
(B) पूरी घरेलू आबादी को तेजी से मांस आधारित प्रोटीन आहार में स्थानांतरित करना
(C) सिंथेटिक कपड़ा उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे जैविक पदार्थों का निष्कर्षण करना
(D) पारंपरिक फसल खेती को पूरी तरह से पशुपालन पद्धतियों से बदलना

52. सूची I की क्रांति को सूची II के विशिष्ट कृषि आगत या ध्यान केंद्रित क्षेत्र से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (क्रांति)
P. हरित क्रांति
Q. श्वेत क्रांति
R. नीली क्रांति
S. रजत क्रांति
सूची II: (आगत / ध्यान केंद्रित क्षेत्र)
1. पोल्ट्री लेयर्स का संकरण
2. कृत्रिम गर्भाधान और पशु चिकित्सा देखभाल
3. हैचरी और मत्स्य बीज
4. रासायनिक उर्वरक और उच्च उपज वाले बीज
सही कूट का चयन कीजिए:
(A) P-4, Q-3, R-2, S-1
(B) P-2, Q-4, R-1, S-3
(C) P-4, Q-2, R-3, S-1
(D) P-1, Q-2, R-4, S-3

53. निम्नलिखित में से कौन-सा किसान स्तर पर संचालन के पैमाने के संबंध में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बीच प्राथमिक अंतर को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त करता है?
(A) हरित क्रांति ने बड़े भूस्वामियों का पक्ष लिया; श्वेत क्रांति ने भूमिहीन और सीमांत किसानों को एकीकृत किया।
(B) अत्यधिक पूंजी-गहन श्वेत क्रांति के विपरीत, हरित क्रांति में किसानों से शून्य पूंजी निवेश की आवश्यकता थी।
(C) श्वेत क्रांति भौगोलिक रूप से उत्तरी राज्यों तक सीमित थी, जबकि हरित क्रांति देश भर में समान रूप से लागू की गई थी।
(D) हरित क्रांति विशेष रूप से किसान सहकारी समितियों द्वारा संचालित थी, जबकि श्वेत क्रांति निजी कॉर्पोरेट एकाधिकार पर निर्भर थी।

54. डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन ने मुख्य रूप से किस कारण से "सदाबहार क्रांति" की आवश्यकता पर बल दिया?
(A) उनका उद्देश्य मैदानी कृषि को पूरी तरह से समाप्त करना और औद्योगिक सिंथेटिक खाद्य निर्माण को शुरू करना था।
(B) उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत को घरेलू बीज अनुसंधान

Click Here to Buy book on Flipkart

55. (B) आपूर्ति को संतुलित करने के लिए दुग्ध-कमी वाले क्षेत्रों को अधिशेष क्षेत्रों से जोड़ना।
ऑपरेशन फ्लड के तहत निर्मित राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड का मुख्य ध्येय देश भर में दूध के वितरण को संतुलित करना था। इस नेटवर्क ने प्रशीतित टैंकरों के माध्यम से दूध अधिशेष वाले ग्रामीण उत्पादक क्षेत्रों को दूध की कमी वाले बड़े शहरी उपभोग केंद्रों से जोड़ा। इससे ग्रामीण किसानों को दूध का उचित मूल्य मिला और शहरी उपभोक्ताओं को वर्ष भर स्थिर आपूर्ति प्राप्त हुई।

56. (B) I, II और IV
भारत में रजत क्रांति ने वैज्ञानिक प्रबंधन और उच्च उपज वाली विदेशी तथा संकर मुर्गियों की किस्मों को अपनाकर पोल्ट्री क्षेत्र का कायाकल्प किया। इस प्रगति में आधुनिक पशु चिकित्सा टीकों और पोषण संबंधी सुधारों ने बीमारियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने पारंपरिक कम उपज वाली देशी नस्लों के स्थान पर व्यावसायिक उत्पादन प्रणालियों को स्थापित करने पर जोर दिया।

57. (D) गेहूं
1960 के दशक के उत्तरार्ध में लागू की गई हरित क्रांति के शुरुआती चरण में सबसे नाटकीय और तीव्र सफलता गेहूं के उत्पादन में प्राप्त हुई। मैक्सिकन बौनी किस्मों को अपनाने और अनुकूल सिंचाई सुविधाओं के कारण पंजाब और हरियाणा में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज में कई गुना वृद्धि हुई। इस ऐतिहासिक सफलता के कारण हरित क्रांति को शुरुआत में 'गेहूं क्रांति' भी कहा गया।

58. (A) यह सभी भू-आबद्ध राज्यों में अंतर्देशीय जलकृषि को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक समावेशी पहल है जो तटीय राज्यों के साथ-साथ सभी भू-आबद्ध (लैंडलॉक्ड) राज्यों में भी अंतर्देशीय जलकृषि के विकास को सक्रिय रुप से बढ़ावा देती है। यह योजना नदियों, तालाबों और जलाशयों में मत्स्य पालन को आधुनिक बनाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा मछुआरों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

59. (B) संश्लेषित नाइट्रोजन युक्त उर्वरक
हरित क्रांति की उच्च उपज वाली किस्में भारी मात्रा में संश्लेषित नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों पर निर्भर थीं। यूरिया जैसे इन रासायनिक उर्वरकों के निर्माण में कच्चे माल और ऊर्जा के रूप में प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम का उपयोग होता है। परिणामस्वरूप, भारतीय कृषि आगतों की लागत अंतरराष्ट्रीय बाजार में जीवाश्म ईंधनों और कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो गई।

60. (A) 3, 2, 1, 4
अमूल मॉडल की पूरी प्रक्रिया एक निश्चित और तार्किक क्रम का पालन करती है। सबसे पहले किसान द्वारा मवेशियों का दूध निकाला जाता है। इसके पश्चात उस दूध को ग्राम सहकारी समिति में लाकर मापा और ठंडा किया जाता है। फिर टैंकरों द्वारा दूध जिला संघ के प्रसंस्करण संयंत्र में पैकेजिंग हेतु भेजा जाता है, और अंततः राज्य महासंघ द्वारा इसका विपणन किया जाता है।

61. (A) इसने निजी नलकूप और ट्रैक्टर यंत्रीकरण को आर्थिक रुप से व्यावहारिक बनाया
पंजाब में हरित क्रांति से पूर्व किसानों की भूमि छोटे और बिखरे हुए टुकड़ों में बंटी हुई थी। राज्य सरकार द्वारा भूमि जोत की चकबंदी (चकबंदी कानून) करने से किसानों को एक स्थान पर बड़ा भू-भाग मिल गया। इस बड़े आकार के खेतों के कारण निजी नलकूपों की स्थापना, नहरों का निर्माण और ट्रैक्टर जैसे आधुनिक यंत्रीकरण का उपयोग आर्थिक रुप से अत्यधिक व्यावहारिक एवं लाभदायक बन गया।

62. (C) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण और क्रियान्वयन भारत सरकार के 'मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय' के अंतर्गत आने वाले मत्स्यपालन विभाग द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय देश भर में नीली क्रांति को गति देने, नीतियों का निर्माण करने और योजना के एकीकृत विकास हेतु वित्तीय संसाधनों का आवंटन एवं पर्यवेक्षण करने का कार्य करता है।

63. (D) एक साझा ब्रांड के तहत प्रसंस्कृत डेयरी उत्पादों का विपणन करना
आनंद पैटर्न के त्रि-स्तरीय ढांचे में शीर्ष स्तर पर स्थित राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ की मुख्य जिम्मेदारी राज्य भर के प्रसंस्कृत डेयरी उत्पादों का एक एकीकृत ब्रांड (जैसे अमूल) के तहत विपणन और विक्रय करना है। यह महासंघ बाजार अनुसंधान, उत्पाद पैकेजिंग, वितरण नेटवर्क के प्रबंधन और बड़े पैमाने पर ब्रांड विज्ञापन का कार्य कुशलतापूर्वक संभालता है।

64. (C) कमी को पूरा करने के लिए रियायती दरों पर गेहूं का आयात
1950 और 1960 के दशक में भारत गंभीर खाद्यान्न कमी और सूखे की समस्या से जूझ रहा था। इस कठिन समय में अमेरिकी सरकार के पीएल-480 (पब्लिक लॉ 480) कार्यक्रम के तहत भारत ने रियायती दरों और आसान शर्तों पर विशाल मात्रा में गेहूं का आयात किया था। इस आयात का प्राथमिक ध्येय देश में अकाल को रोकना और नागरिकों को न्यूनतम खाद्य सुरक्षा देना था।

65. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
हरित क्रांति के दौरान सरकारी नीतियों का पूरा ध्यान गेहूं और चावल पर केंद्रित था। सरकार द्वारा इन दो फसलों के लिए नई तकनीकों, सब्सिडी और सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की गई। अत्यधिक लाभदायक होने के कारण किसानों ने दालों और मोटे अनाजों की खेती छोड़कर गेहूं और चावल उगाना शुरु कर दिया, जिससे इन पारंपरिक फसलों के रकबे में बड़ी गिरावट आई।

Downloaded from www.pdf.tube

अध्याय 10

पंचवर्षीय योजनाएँ एवं नियोजन प्रणाली

NODIA

1. स्वतंत्रता के बाद, भारत ने एक केंद्रीकृत नियोजन मॉडल अपनाया जो निम्नलिखित में से किसकी आर्थिक नियोजन प्रणाली से अत्यधिक प्रेरित था?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका
(B) सोवियत संघ
(C) यूनाइटेड किंगडम
(D) पश्चिम जर्मनी

2. भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी?
(A) हैरोड-डोमर मॉडल
(B) महालनोबिस नियोजन मॉडल
(C) सोलो-स्वान संवृद्धि मॉडल
(D) लुईस द्वि-क्षेत्र मॉडल

3. प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) का प्राथमिक ध्यान केंद्रित करने वाला क्षेत्र कौन-सा था?
(A) भारी उद्योग और विनिर्माण
(B) सेवा क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी
(C) कृषि और सिंचाई
(D) गरीबी उन्मूलन और रोजगार

4. प्रथम से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में संक्रमण के दौरान रणनीतिक फोकस में कौन-सा मौलिक बदलाव आया?
(A) केंद्रीकृत नियोजन से विकेंद्रीकृत नियोजन की ओर
(B) भारी उद्योग से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की ओर
(C) सांकेतिक नियोजन से निर्देशात्मक नियोजन की ओर
(D) कृषि से सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व वाले भारी उद्योग की ओर

5. सूची I की पंचवर्षीय योजनाओं का सूची II में उनके प्राथमिक रणनीतिक फोकस या मॉडल के साथ मिलान कीजिए।
सूची I: पंचवर्षीय योजना
P. प्रथम योजना
Q. द्वितीय योजना
R. छठी से आठवीं योजनाएं
S. बारहवीं योजना
सूची II: फोकस या मॉडल
1. गरीबी उन्मूलन
2. कृषि एवं सिंचाई
3. तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास
4. भारी उद्योगों पर बल
(A) P-4, Q-2, R-3, S-1
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-1, Q-3, R-2, S-4

6. महालनोबिस मॉडल, जिसने द्वितीय पंचवर्षीय योजना को आधार प्रदान किया, ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किसके तीव्र विस्तार की वकालत की?
(A) निजी क्षेत्र के उपभोक्ता सामान और खुदरा बाजार
(B) सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजीगत वस्तुएं और भारी उद्योग
(C) सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
(D) कृषि निर्यात और ग्रामीण वाणिज्यिक खेती

7. तीसरी से पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आत्मनिर्भरता की ओर रणनीतिक बदलाव निम्नलिखित में से किस कारक से अत्यधिक प्रभावित था?
(A) शुरुआती कृषि हरित क्रांति पहलों की तीव्र सफलता
(B) ऐतिहासिक 1991 के आर्थिक सुधारों का पूर्ण कार्यान्वयन
(C) एक राष्ट्रीय थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग की औपचारिक स्थापना
(D) बाहरी सैन्य संघर्ष और लगातार गंभीर सूखा

8. भारत के नियोजन इतिहास के संदर्भ में, "गरीबी हटाओ" (गरीबी उन्मूलन) का नारा किस योजना क्रम के दौर से सबसे निकटता से जुड़ा हुआ है?
(A) प्रथम से तीसरी योजनाएं
(B) तीसरी और चौथी योजनाएं
(C) छठी से आठवीं योजनाएं
(D) दसवीं और ग्यारहवीं योजनाएं

9. आठवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) इसने 1991 के बाजार सुधारों के साथ सीधे तौर पर मेल खाते हुए एक प्रमुख आर्थिक संक्रमण काल को चिह्नित किया।
(B) इसने व्यवस्थित रूप से बाजार-निर्देशित सांकेतिक नियोजन की ओर एक रणनीतिक समष्टि आर्थिक बदलाव की शुरुआत की।
(C) इसने निजी क्षेत्र की भागीदारी के बिना विशुद्ध रूप से निर्देशात्मक नियोजन दृष्टिकोण को बनाए रखा।
(D) इसने व्यापक गरीबी उन्मूलन और आर्थिक पुनर्गठन ढांचे का एक मुख्य घटक बनाया।

77. (B) I, II और IV
गुलाबी क्रांति का मुख्य ध्यान मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण उद्योगों के तकनीकी आधुनिकीकरण पर केंद्रित है। इसमें खराब होने वाले मांस उत्पादों के भंडारण हेतु कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है। यह क्रांति प्रसंस्कृत मांस के निर्यात को प्रतिबंधित करने के बजाय अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करके निर्यात को बढ़ावा देती है। साथ ही, यह जेनेरिक दवा निर्माण क्षेत्र से भी जुड़ी है।

78. (C) जलीय जीवों का नियंत्रित प्रजनन और कटाई/संग्रहण
नीली क्रांति के तहत प्रोत्साहित 'जलकृषि' (एक्वाकल्चर) का तात्पर्य नियंत्रित या कृत्रिम जलीय वातावरण में मछलियों, झींगों, केकड़ों और अन्य जलीय वनस्पतियों तथा जीवों का वैज्ञानिक पालन-पोषण, प्रजनन और संवर्धन करना है। यह प्राकृतिक जल निकायों में खुली मछली पकड़ने से भिन्न है क्योंकि इसमें जलीय जीवों के जीवन चक्र और विकास का प्रबंधन मानवीय देखरेख एवं आधुनिक तकनीकों द्वारा किया जाता है।

79. (D) डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण
ग्रामीण भारत में मवेशियों की देखभाल और दूध निकालने का पारंपरिक कार्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता था। श्वेत क्रांति ने जब आनंद मॉडल के तहत गांव-गांव में दुग्ध समितियां स्थापित कीं, तो महिलाओं को सीधे दूध बेचने और उसका भुगतान पाने का अवसर मिला। इस व्यवस्था ने ग्रामीण महिलाओं के हाथों में स्वतंत्र आय देकर उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यधिक सशक्त बनाया।

80. (A) पीएल-480 आयातों पर निर्भरता → हरित क्रांति की उच्च उपज वाली तकनीक को अपनाना → आत्मनिर्भरता की प्राप्ति → सदाबहार क्रांति स्थिरता की ओर बदलाव
भारत की खाद्य सुरक्षा यात्रा का कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है: 1960 के दशक की शुरुआत में देश अमेरिकी पीएल-480 आयातों पर निर्भर था। इसके बाद 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति की उच्च उपज वाली तकनीक अपनाई गई। इसके परिणामस्वरूप 1970 और 1980 के दशक में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। वर्तमान में, पर्यावरण संरक्षण हेतु सदाबहार क्रांति और सतत कृषि की ओर बदलाव जारी है।

Click Here to Buy book on Amazon

NODIA

66. (D) इसमें किसानों द्वारा चुने गए बोर्डों के प्रति जवाबदेह पेशेवर प्रबंधन था
आनंद पैटर्न की अद्वितीय सफलता का रहस्य इसके अनोखे सांगठनिक ढांचे में निहित है। इस मॉडल में स्वामित्व और अंतिम नीतियां दुग्ध उत्पादक किसानों द्वारा निर्वाचित बोर्ड के हाथों में होती हैं, जबकि दैनिक व्यावसायिक संचालन का जिम्मा उच्च कुशल और पेशेवर प्रबंधकों को सौंपा जाता है। इस व्यवस्था ने नौकरशाही हस्तक्षेप को समाप्त कर पारदर्शिता और उच्च कार्यकुशलता सुनिश्चित की।

67. (A) फ्रोजन झींगा
नीली क्रांति के फलस्वरुप भारत का समुद्री खाद्य निर्यात उद्योग अत्यंत सुदृढ़ हुआ है। वर्तमान में, कुल मूल्य और मात्रा के आधार पर भारत से होने वाले सी-फूड निर्यात में 'फ्रोजन झींगा' का योगदान सबसे अधिक है। तटीय राज्यों में झींगा कृषि (श्रिम्प फार्मिंग) के व्यापक विस्तार और अत्याधुनिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत को शीर्ष स्थान दिलाया है।

68. (C) नई दिल्ली
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। यह संपूर्ण देश में कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों का समन्वय करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण संस्थान का केंद्रीय मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, जहाँ से यह राष्ट्रीय कृषि नीतियों का मार्गदर्शन करता है।

69. (A) केवल I और II
भारत में पीली क्रांति का मुख्य ध्येय खाद्य तेलों के भारी आयात को कम करना और देश को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था। वर्ष 1986 में स्थापित तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन ने बीजों के सुधार और प्रसंस्करण तकनीक में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यद्यपि इससे तिलहन उत्पादन में भारी वृद्धि दर्ज की गई, परंतु बाद के वर्षों में बढ़ती मांग के कारण आयात पूरी तरह बंद नहीं हो सका।

70. (D) यूरोपीय आर्थिक समुदाय और विश्व खाद्य कार्यक्रम
ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण के वित्तपोषण के लिए एक अनूठी रणनीति अपनाई गई। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से भारत को भारी मात्रा में स्कीम्ड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल उपहार स्वरुप दान किया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इन वस्तुओं को मेट्रो शहरों में बेचकर धन जुटाया और उस पूंजी का उपयोग डेयरी बुनियादी ढांचे के निर्माण में किया।

71. (B) लेयर्स को अंडों के लिए पाला जाता है, जबकि ब्रॉयलर्स को मांस के लिए पाला जाता है।
रजत क्रांति के तहत आधुनिक पोल्ट्री फार्मिंग को दो विशिष्ट व्यावसायिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। 'लेयर्स' पक्षियों की वे विशिष्ट नस्लें होती हैं जिन्हें व्यावसायिक रुप से केवल अंडे देने के लिए वैज्ञानिक पोषण दिया जाता है। इसके विपरीत, 'ब्रॉयलर्स' पक्षियों की वे तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रजातियां होती हैं जिन्हें मुख्य रुप से गुणवत्तापूर्ण मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाला जाता है।

72. (C) जैविक और न्यूनतम रासायनिक नियंत्रणों को संयोजित करने वाला एकीकृत कीट प्रबंधन
सदाबहार क्रांति का दृष्टिकोण केवल रसायनों पर निर्भर रहने के बजाय पर्यावरण-अनुकूल खेती पर बल देता है। कीट प्रबंधन के संदर्भ में यह 'एकीकृत कीट प्रबंधन' पद्धति को अपनाती है। इस प्रणाली के तहत मित्र कीड़ों का संरक्षण, फसल चक्र, नीम आधारित जैविक कीटनाशकों और जैव-नियंत्रक एजेंटों का प्राथमिकता से उपयोग किया जाता है, जबकि हानिकारक रसायनों का प्रयोग केवल अंतिम विकल्प के रुप में होता है।

73. (D) P-2, Q-3, R-1, S-4
हरित क्रांति की प्रथाओं के गंभीर पारिस्थितिक परिणाम सामने आए। इलेक्ट्रिक नलकूपों से अत्यधिक जल निष्कर्षण के कारण भूजल का क्षरण हुआ। अस्तर-रहित नहरों से अत्यधिक पानी मिलने पर जलजमाव और मृदा लवणता बढ़ी। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से पीने के पानी में हानिकारक नाइट्रेट प्रदूषण फैला, और कुछ मानकीकृत संकर बीजों को सार्वभौमिक रुप से अपनाने से स्वदेशी बीजों की प्रजातियाँ विलुप्त हो गईं।

74. (A) जेनेरिक दवाएं और टीके
फार्मास्युटिकल क्षेत्र के संदर्भ में गुलाबी क्रांति भारत की उस ऐतिहासिक क्षमता से जुड़ी है जिसके द्वारा देश ने विश्व स्तर पर किफायती जेनेरिक दवाओं और टीकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त किया। उच्च गुणवत्ता, कम निर्माण लागत और उन्नत प्रयोगशाला अनुसंधान के बल पर भारतीय दवा उद्योग ने दुनिया भर के विकासशील देशों को जीवन रक्षक दवाएं प्रदान कीं।

75. (B) पूर्वी भारत (बिहार, यूपी, ओडिशा)
हरित क्रांति के शुरुआती दो दशकों के दौरान मुख्य ध्यान उत्तर-पश्चिमी भारत पर ही केंद्रित रहा। सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं और बेहतर वित्तीय अवसंरचना के अभाव के कारण पूर्वी भारत के राज्य जैसे बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल इस तकनीकी दौड़ में काफी पीछे छूट गए। इसके परिणामस्वरुप देश में कृषि समृद्धि और विकास की गंभीर क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न हो गईं।

76. (B) National Dairy Development Board
डेयरी विकास और ग्रामीण सहकारिता के संदर्भ में एनडीडीबी का पूर्ण रुप 'नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड' (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) है। इस वैधानिक निकाय की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। इस संस्थान का मुख्य कार्यालय गुजरात के आनंद में स्थित है और इसने पूरे भारत में ऑपरेशन फ्लड की योजना बनाने, उसे वित्तपोषित करने और सफलतापूर्वक लागू करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है।

10. द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी।
II. इसने सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व में पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया।
III. इसने प्राथमिक ध्यान पूरी तरह से औद्योगीकरण से हटाकर कृषि की ओर स्थानांतरित कर दिया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

11. नौवीं से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं ने राष्ट्रीय नियोजन विमर्श को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय की ओर स्थानांतरित कर दिया?
(A) सभी भारी उद्योगों का तीव्र निजीकरण
(B) पंचायतों को वित्तीय शक्तियों का पूर्ण विकेंद्रीकरण
(C) निर्यात-संचालित विकास पर विशेष ध्यान
(D) सामाजिक न्याय के साथ विकास और समावेशी विकास

12. बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) का मुख्य विषय (विषय-वस्तु) क्या था?
(A) रणनीतिक आत्मनिर्भरता और शुद्ध विदेशी सहायता का पूर्ण उन्मूलन
(B) तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास
(C) राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण के साथ व्यवस्थित गरीबी उन्मूलन
(D) शुद्ध बाजार अर्थव्यवस्था की स्थापना की ओर पूर्ण संक्रमण

13. जनवरी 2015 में भारत की नियोजन प्रणाली में हुए बदलाव का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा करता है?
(A) योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।
(B) राष्ट्रीय विकास परिषद ने वित्त आयोग का स्थान लिया।
(C) योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया।
(D) नीति आयोग का वित्त मंत्रालय में विलय कर दिया गया।

14. कौन-सी संस्था भारत सरकार के प्राथमिक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है?
(A) वित्त आयोग
(B) राष्ट्रीय विकास परिषद
(C) अंतर-राज्यीय परिषद
(D) नीति आयोग

15. नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
II. यह योजना व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय संसाधन आवंटित करता है।
III. इसकी शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं।
IV. इसने 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से गलत है/हैं?
(A) केवल I और III
(B) केवल II
(C) केवल III और IV
(D) केवल I, II और IV

16. नीति आयोग के संगठनात्मक ढांचे में शासी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है?
(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) भारत के प्रधानमंत्री
(C) केंद्रीय वित्त मंत्री
(D) नीति आयोग के उपाध्यक्ष

17. भारत में निर्देशात्मक नियोजन से सांकेतिक नियोजन की ओर संक्रमण किस प्रमुख घटना के बाद सबसे प्रमुख हो गया?
(A) 1969 में प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का देशव्यापी राष्ट्रीयकरण
(B) 1991 के आर्थिक उदारीकरण के सुधार
(C) 1950 में भारत के संविधान का औपचारिक अंगीकरण
(D) 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधिकारिक शुभारंभ

18. 1991 के बाद भारत द्वारा अपनाया गया सांकेतिक नियोजन, आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस तंत्र पर निर्भर करता है?
(A) बाजार संकेत और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी
(B) केंद्रीय औद्योगिक उत्पादन के लिए अनिवार्य राज्य-प्रवर्तित उत्पादन कोटा
(C) सभी राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तुओं पर पूर्ण और विशेष राज्य स्वामित्व
(D) मुख्य रणनीतिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का पूर्ण उन्मूलन और निषेध

19. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, किसी जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए किस निकाय को अनिवार्य किया गया है?
(A) राज्य योजना एवं विकास बोर्ड
(B) क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा विकास प्राधिकरण
(C) जिला योजना समिति (डीपीसी)
(D) जिला परिषद स्थायी कार्यकारी समिति

20. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): भारत के योजना आयोग को भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया।

Downloaded from www.pdf.tube

कारण (R): सरकार ऊपर-से-नीचे (शीर्ष-से-नीचे) नियोजन दृष्टिकोण से सहकारी संघवाद मॉडल की ओर बढ़ना चाहती थी।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

21. कौन-सा वैश्विक ढांचा नीति आयोग द्वारा शुरु की गई भारत की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रक्रिया के अनुरूप है?
(A) विश्व व्यापार संगठन दोहा विकास एजेंडा
(B) उत्सर्जन पर पेरिस जलवायु समझौता ढांचा
(C) सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)
(D) संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी)

22. निम्नलिखित में से कौन-सा संबंधित पंचवर्षीय योजनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है?
(A) हैरोड-डोमर मॉडल योजना, समावेशी विकास योजना की ओर बदलाव, गरीबी हटाओ दौर की योजना, अंतिम पंचवर्षीय योजना
(B) हैरोड-डोमर मॉडल योजना, गरीबी हटाओ दौर की योजना, समावेशी विकास योजना की ओर बदलाव, अंतिम पंचवर्षीय योजना
(C) गरीबी हटाओ दौर की योजना, हैरोड-डोमर मॉडल योजना, अंतिम पंचवर्षीय योजना, समावेशी विकास योजना की ओर बदलाव
(D) समावेशी विकास योजना की ओर बदलाव, अंतिम पंचवर्षीय योजना, हैरोड-डोमर मॉडल योजना, गरीबी हटाओ दौर की योजना

23. भारत में पंचवर्षीय योजना प्रणाली की एक प्रमुख उपलब्धि कृषि उत्पादकता के लिए संस्थागत सहायता का निर्माण करना था। इस सहायता ने सीधे तौर पर निम्नलिखित में से किसको सुगम बनाया?
(A) श्वेत क्रांति
(B) वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण
(C) विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना
(D) हरित क्रांति

24. केंद्रीकृत नियोजन युग (1991 से पूर्व) की एक प्रमुख आलोचना अक्षमताओं को उत्पन्न करने की इसकी प्रवृत्ति थी। इसे मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारण माना गया था?
(A) लालफीताशाही (नौकरशाही में देरी) और अकुशल सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश
(B) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह पर अत्यधिक समष्टि आर्थिक निर्भरता
(C) औद्योगिक विकास में किसी भी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के हस्तक्षेप का पूर्ण अभाव
(D) देश भर में भारी पूंजीगत वस्तु उद्योगों की पूर्ण संरचनात्मक अनुपस्थिति

NODIA

25. सूची I में दिए गए नियोजन निकायों या अवधारणाओं का सूची II में उनकी प्रमुख विशेषताओं के साथ मिलान कीजिए।
सूची I: निकाय या अवधारणा
P. योजना आयोग
Q. नीति आयोग
R. सांकेतिक नियोजन
S. जिला योजना समिति
सूची II: प्रमुख विशेषता
1. स्थानीय स्तर पर नीचे-से-ऊपर नियोजन
2. बाजार-निर्देशित संसाधन आवंटन
3. निधि आवंटन की शक्ति
4. थिंक टैंक की भूमिका
(A) P-4, Q-3, R-1, S-2
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-3, Q-4, R-2, S-1
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

26. योजना आयोग के युग में, उपाध्यक्ष की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या थी?
(A) पंचवर्षीय योजनाओं के दैनिक निर्माण और निष्पादन की देखरेख करना
(B) राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों की औपचारिक अध्यक्षता और संचालन करना
(C) आयोग के प्राथमिक औपचारिक और प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करना
(D) संसद के भीतर केंद्रीय बजट पेश करना, बहस करना और पारित करना

27. वित्तीय शक्तियों के संबंध में नीति आयोग पूर्ववर्ती योजना आयोग से मौलिक रूप से किस प्रकार भिन्न है?
(A) नीति आयोग योजना आयोग की तुलना में राज्यों को काफी अधिक वित्तीय अनुदान सीधे आवंटित करता है।
(B) नीति आयोग स्पष्ट रूप से सीधे केंद्र से राज्य के वार्षिक बजटीय व्यय को निर्धारित और अनिवार्य करता है।
(C) नीति आयोग विशेष रूप से निजी क्षेत्र की संस्थाओं को सीधे पूंजीगत विकास निधि वितरित करता है।
(D) नीति आयोग के पास निधि आवंटित करने का कोई जनादेश नहीं है, यह विशुद्ध रूप से एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।

28. योजना आयोग से स्वतंत्र, गैर-योजना व्यय के लिए राज्यों को केंद्रीय वित्तीय सहायता निर्धारित करने के लिए ऐतिहासिक रूप से कौन-सी संस्था जिम्मेदार रही है?
(A) अंतर-राज्यीय परिषद
(B) वित्त आयोग
(C) राष्ट्रीय विकास परिषद
(D) भारतीय रिजर्व बैंक

29. नीति आयोग द्वारा शुरु किया गया आकांक्षी जिला कार्यक्रम मुख्य रूप से किस विकास मॉडल पर आधारित है?
(A) ऊपर-से-नीचे (शीर्ष-से-नीचे) निर्देशात्मक नियोजन
(B) पिछड़े जिलों के लिए विशेष विदेशी वित्तपोषण
(C) केंद्रीय और राज्य योजनाओं का अभिसरण
(D) जिला प्रशासन का निजीकरण

30. आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसकी निगरानी नीति आयोग द्वारा की जाती है।
II. यह जिलों के बीच अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है।
III. इसका उद्देश्य कम विकसित जिलों का तेजी से कायाकल्प करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

31. वैश्विक विकास लक्ष्यों पर भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन की निरंतर निगरानी और रैंकिंग के लिए नीति आयोग किस उपकरण का उपयोग करता है?
(A) एसडीजी इंडिया इंडेक्स
(B) बहुआयामी गरीबी सूचकांक
(C) मानव विकास सूचकांक
(D) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स

32. पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत नियोजन को पूरे भारत में मुख्य रूप से किस संवैधानिक संशोधन के बाद व्यवस्थित रूप से संरचित किया गया था?
(A) 42वां संशोधन
(B) 73वां संशोधन
(C) 44वां संशोधन
(D) 86वां संशोधन

33. 1991 के बाद भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की वृद्धि नियोजन प्रक्रिया में किस बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है?
(A) राज्य के सार्वजनिक वित्तपोषण परिव्यय द्वारा सभी निजी निवेशों का पूर्ण प्रतिस्थापन
(B) निजी निवेश द्वारा सार्वजनिक नियोजन परिव्यय का पूरक और प्रतिस्थापन होना
(C) राज्य सरकारों द्वारा सभी निजी उद्यम संचालनों का व्यवस्थित रूप से अधिग्रहण और राष्ट्रीयकरण करना
(D) सभी आवश्यक सेवाओं में सार्वजनिक क्षेत्र का पूर्ण संरचनात्मक उन्मूलन

34. पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति के बाद, नीति आयोग ने एक नया दीर्घकालिक नियोजन ढांचा पेश किया। इस ढांचे के तहत प्रस्तावित विजन डॉक्यूमेंट (दृष्टि दस्तावेज) की अवधि क्या है?
(A) 5 वर्ष
(B) 7 वर्ष
(C) 10 वर्ष
(D) 15 वर्ष

35. 2015 के बाद भारत की नियोजन रणनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15-वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट लाया गया।
II. दृष्टिकोण को लागू करने के लिए एक 7-वर्षीय रणनीति पत्र पेश किया गया था।
III. तत्काल नीतिगत कार्रवाइयों के लिए 3-वर्षीय कार्य एजेंडा तैयार किया गया था।
IV. राज्य योजना बोर्डों को सार्वभौमिक रूप से समाप्त कर दिया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा संयोजन सही है?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I और IV
(D) I, II, III और IV

36. भारत में नियोजन प्रणाली के मौलिक पुनर्गठन से पहले कौन-सी पंचवर्षीय योजना तैयार और निष्पादित की जाने वाली अंतिम योजना थी?
(A) दसवीं योजना
(B) ग्यारहवीं योजना
(C) तेरहवीं योजना
(D) बारहवीं योजना

37. कौन-सा राज्य-स्तरीय निकाय संवैधानिक रूप से ग्रामीण और शहरी योजनाओं को जिले के लिए एक एकल व्यापक प्रारूप विकास योजना में एकीकृत करने के लिए निर्मित किया गया है?
(A) राज्य वित्त एवं विकास आयोग
(B) जिला परिषद कार्यकारी स्थायी समिति
(C) जिला योजना समिति
(D) शहरी नगर निगम परिषद

38. नीति आयोग के संगठनात्मक ढांचे में पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं। उनके अलावा आयोग के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कौन कार्य करता है?
(A) भारत सरकार के कैबिनेट सचिव
(B) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)
(C) वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव
(D) योजना आयोग के उपाध्यक्ष

39. निम्नलिखित में से कौन-सा नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है?
(A) सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना
(B) रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतिगत ढांचे का निर्माण

Click Here to Buy book on Flipkart

पंचायतों को संवैधानिक मान्यता और दर्जा प्रदान किया।
(B) विकेंद्रीकृत नियोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास रणनीतियों में विविध स्थानीय आवश्यकताओं को व्यवस्थित रूप से शामिल करना है।
(C) जिला योजना समितियां विशेष रूप से शहरी नगर पालिका क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं तैयार करती हैं।
(D) नीचे-से-ऊपर सहयोगी नियोजन नीति आयोग के मार्गदर्शक ढांचे के एक मुख्य मूलभूत सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है।

58. योजना आयोग से नीति आयोग की ओर बदलाव ने निम्नलिखित में से किस पर बल देकर राज्य स्तरीय नियोजन को महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया:
(A) प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद
(B) राज्य निधियों का केंद्रीकृत आवंटन
(C) राज्य बजटों का उन्मूलन
(D) राज्य के परामर्श के बिना केंद्रीय योजनाओं का एक समान थोपना

59. नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स का उपयोग करने की रणनीति राज्यों को किस तंत्र के माध्यम से अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करती है?
(A) खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों को केंद्रीय कर अंतरण हिस्सों में सीधी दंडात्मक कटौती
(B) राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का अनिवार्य राष्ट्रीयकरण और केंद्रीय अधिग्रहण
(C) सभी केंद्रीय वित्तीय विकास सहायता को पूरी तरह से वापस लेना और रद्द करना
(D) रैंकिंग दृश्यता द्वारा संचालित प्रतिस्पर्धी संघवाद

60. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): 1991 के बाद, भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की तीव्र वृद्धि देखी।
कारण (R): उच्च विकास के लिए आवश्यक विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को स्वतंत्र रूप से वित्तपोषित करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त पूंजी संसाधनों की कमी थी।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

61. नीति आयोग के ढांचे के तहत, किस विशिष्ट दस्तावेज ने तीन साल के क्षितिज पर देश की तत्काल नीतिगत प्राथमिकताओं की रुपरेखा तैयार करने के लिए पारंपरिक व्यापक पंचवर्षीय योजना का स्थान लिया?
(A) 7-वर्षीय रणनीति पत्र
(B) 15-वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट
(C) 3-वर्षीय कार्य एजेंडा
(D) वार्षिक वित्तीय विवरण

62. निम्नलिखित में से कौन-सा क्रम 1951 से वर्तमान तक भारत के व्यापक नियोजन दर्शन में आए बदलाव को सटीक रूप से दर्शाता है?
(A) केंद्रीकृत निर्देशात्मक नियोजन → सांकेतिक नियोजन → सहकारी संघवाद आधारित थिंक टैंक नियोजन
(B) सांकेतिक नियोजन → सहकारी संघवाद आधारित थिंक टैंक नियोजन → केंद्रीकृत निर्देशात्मक नियोजन
(C) सहकारी संघवाद आधारित थिंक टैंक नियोजन → केंद्रीकृत निर्देशात्मक नियोजन → सांकेतिक नियोजन
(D) केंद्रीकृत निर्देशात्मक नियोजन → सहकारी संघवाद आधारित थिंक टैंक नियोजन → सांकेतिक नियोजन

63. द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारी उद्योग पर बल देने की मुख्य उपलब्धियों में से एक भारत में कई इस्पात संयंत्रों की स्थापना थी। इस पूंजी-गहन दृष्टिकोण को निम्नलिखित में से किस मॉडल ने प्रेरित किया था?
(A) महालनोबिस मॉडल
(B) हैरोड-डोमर मॉडल
(C) पुरा (PURA) मॉडल
(D) गांधीवादी मॉडल

NODIA

64. नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं में बदलाव ने एक अवधारणात्मक बदलाव लाया, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि केवल आर्थिक विकास ही पर्याप्त नहीं था। इसके कारण किस नीतिगत उद्देश्य को स्पष्ट रूप से अपनाया गया?
(A) व्यापक आयात प्रतिस्थापन और व्यापार संरक्षणवाद
(B) समावेशी विकास और सामाजिक न्याय
(C) विनियामक-मुक्त अहस्तक्षेप बाजार पूंजीवाद
(D) निजी औद्योगिक पूंजी का पूर्ण राष्ट्रीयकरण

65. सूची I में नीति आयोग से संबंधित दस्तावेजों का सूची II में उनकी निर्धारित अवधि के साथ मिलान कीजिए।
सूची I: दस्तावेज या ढांचा
P. विजन डॉक्यूमेंट
Q. रणनीति पत्र
R. कार्य एजेंडा
S. सतत विकास लक्ष्य क्षितिज
सूची II: अवधि या क्षितिज
1. 3 वर्ष
2. 7 वर्ष
3. 15 वर्ष
4. 2030 के लिए लक्षित
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-2, R-1, S-4
(C) P-3, Q-1, R-2, S-4
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

(D) विशुद्ध रूप से क्लासिकल हैरोड-डोमर आर्थिक विकास मॉडल पर वापस लौटना

49. नीति आयोग द्वारा अत्यधिक बल दी गई "सहकारी संघवाद" की अवधारणा, नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संबंध को दर्शाती है?
(A) राज्यों को केंद्र सरकार के सभी नीतिगत निर्देशों का सख्ती से सहयोग और प्रत्यक्ष रूप से पालन करना चाहिए।
(B) केंद्र और राज्य राष्ट्रीय विकास में समान भागीदारों के रूप में सहयोग करते हैं।
(C) व्यक्तिगत राज्य केंद्र सरकार की किसी भी भागीदारी के बिना विशेष रूप से एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं।
(D) केंद्र सरकार सभी संप्रभु विदेश नीति निर्णयों को सीधे व्यक्तिगत राज्यों को सौंपती है।

50. (ऐतिहासिक रूप से) वित्त आयोग बनाम योजना आयोग की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है।
II. योजना आयोग संसद के एक अधिनियम द्वारा निर्मित एक वैधानिक निकाय था।
III. योजना आयोग राज्यों के लिए योजना अनुदान निर्धारित करता था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

51. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन योजना आयोग और नीति आयोग के बीच मौलिक अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) योजना आयोग ने कठोरता से नीचे-से-ऊपर की नीति दृष्टिकोण का पालन किया, जबकि नीति आयोग विशेष रूप से एक केंद्रीकृत ऊपर-से-नीचे नियोजन दृष्टिकोण लागू करता है।
(B) योजना आयोग में स्वाभाविक रूप से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे, जबकि नीति आयोग उन्हें अपने शासी निकायों से पूरी तरह से बाहर रखता है।
(C) योजना आयोग के पास निधि आवंटन की शक्तियां थीं, जबकि नीति आयोग एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
(D) योजना आयोग को एक पूर्ण संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, जबकि नीति आयोग एक गैर-वैधानिक अनौपचारिक मंच के रूप में कार्य करता है।

52. बारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज ने अपने विकास लक्ष्य को परिभाषित करने के लिए स्पष्ट रूप से तीन मुख्य विशेषणों का उपयोग किया। उनमें से दो "सतत" और "अधिक समावेशी" थे। तीसरा विशेषण क्या था?
(A) धीमा
(B) संतुलित
(C) स्वतंत्र
(D) तीव्र

53. भारतीय नियोजन में किस अवधि को युद्धों और सूखे के कारण हुए गंभीर आर्थिक व्यवधानों के कारण प्रसिद्ध रूप से "योजना अवकाश" (प्लान हॉलिडे) कहा जाता है?
(A) 1951-1954
(B) 1966-1969
(C) 1978-1980
(D) 1990-1992

54. आकांक्षी जिला कार्यक्रम कई मुख्य सामाजिक-आर्थिक विषयों के तहत जिलों का मूल्यांकन करता है। निम्नलिखित में से कौन-सा आमतौर पर इन प्राथमिक विषयों में से एक नहीं है?
(A) स्वास्थ्य और पोषण
(B) भारी औद्योगिक उत्पादन
(C) शिक्षा
(D) कृषि और जल संसाधन

55. 1991 के बाद भारत के नियोजन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसने बुनियादी ढांचे में कम होते सार्वजनिक निवेश को प्रतिस्थापित करने में मदद की।
II. इसने आवश्यक सेवाओं में निजी क्षेत्र के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया।
III. इसने निजी पूंजी और विशेषज्ञता के आगमन को सुगम बनाया।
IV. यह दसवीं योजना के बाद से पंचवर्षीय योजनाओं में एक मुख्य रणनीति बन गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा संयोजन सही है?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

NODIA

56. किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रगति को प्रस्तुत करने के लिए नीति आयोग स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा तैयार करता है?
(A) सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच
(B) वैश्विक शासन पर विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक
(C) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास पर G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन
(D) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की वार्षिक बैठकें

57. भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने औपचारिक रूप से

करना
(C) अंतर-क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना
(D) राज्य सरकारों को केंद्रीय योजना निधियों का आवंटन करना

40. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): तीसरी पंचवर्षीय योजना अपनी लक्षित संवृद्धि दर प्राप्त करने में विफल रही।
कारण (R): यह अवधि भारत-चीन युद्ध, भारत-पाक युद्ध और लगातार गंभीर सूखे से प्रभावित थी।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

41. योजना आयोग के युग के दौरान योजना वित्तपोषण के संदर्भ में, राज्यों को केंद्रीय सहायता ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध सूत्र पर आधारित थी?
(A) महालनोबिस भारी विकास सूत्र
(B) हैरोड-डोमर आर्थिक विकास सूत्र
(C) गाडगिल-मुखर्जी सूत्र
(D) केलकर कर सुधार कार्यदल सूत्र

42. भारत में निम्नलिखित आर्थिक नियोजन के मील के पत्थरों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. महालनोबिस मॉडल की शुरुआत
II. हैरोड-डोमर मॉडल की शुरुआत
III. नीति आयोग द्वारा 15-वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट का शुभारंभ
IV. "गरीबी हटाओ" दौर की योजनाओं की शुरुआत
(A) II, I, IV, III
(B) I, II, III, IV
(C) II, IV, I, III
(D) I, II, IV, III

43. भारत में राज्य स्तरीय नियोजन में, ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया शुरू करने में कौन-सी संस्था सबसे निचला स्तर बनाती है?
(A) पंचायत समिति
(B) जिला परिषद
(C) जिला योजना समिति
(D) ग्राम पंचायत

44. हरित क्रांति के लिए संस्थागत सहायता मुख्य रूप से भारत के नियोजन के किस चरण के दौरान समेकित की गई थी?
(A) प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि
(B) तीसरी योजना और उत्तरवर्ती वार्षिक योजनाएं
(C) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना विकास युग
(D) ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना विस्तार चरण

45. सूची I के फोकस क्षेत्रों का सूची II में उनकी संबंधित पंचवर्षीय योजना अवधि से मिलान कीजिए।
सूची I: फोकस क्षेत्र
P. औद्योगिक आधार का निर्माण
Q. समावेशी विकास पर बल
R. बाजार-निर्देशित नियोजन की ओर संक्रमण
S. कृषि एवं सिंचाई
सूची II: योजना अवधि
1. प्रथम योजना
2. द्वितीय योजना
3. आठवीं योजना
4. ग्यारहवीं योजना
(A) P-1, Q-2, R-4, S-3
(B) P-2, Q-3, R-1, S-4
(C) P-2, Q-4, R-3, S-1
(D) P-3, Q-4, R-2, S-1

46. एसडीजी इंडिया इंडेक्स विभिन्न सतत विकास मापदंडों पर राज्यों की रैंकिंग की गणना करता है। कौन-सा संगठन इस सूचकांक को प्रकाशित करता है?
(A) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
(B) वित्त आयोग
(C) भारतीय रिजर्व बैंक
(D) नीति आयोग

47. सांकेतिक नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: इसमें राज्य द्वारा निर्धारित अनिवार्य लक्ष्य शामिल होते हैं जिन्हें निजी उद्योगों को कानूनी दंड के तहत प्राप्त करना होता है।
कथन II: यह राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाजार प्रोत्साहन, नीतिगत मार्गदर्शन और सार्वजनिक-निजी सहयोग पर निर्भर करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

48. 1991 में संक्रमण के दौरान, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को गंभीर समष्टि आर्थिक चुनौतियों के अनुकूल होना पड़ा। आठवीं योजना के दौरान नियोजन प्रणाली के अनुकूलन की एक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन-सी थी?
(A) प्रमुख उद्योगों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण और केंद्रीय राज्य स्वामित्व
(B) विनियामक ढील (उदारीकरण) और निजी पूंजी की भूमिका का विस्तार
(C) केंद्रीय योजना आयोग को तत्काल समाप्त और भंग करना

Downloaded from www.pdf.tube

66. नीति आयोग अपनी शासी परिषद में विशेष आमंत्रितों को शामिल करता है। इन विशेष आमंत्रितों को मनोनीत करने का अधिकार किसके पास है?
(A) भारत के प्रधानमंत्री
(B) मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति
(C) संसद के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष
(D) कैबिनेट समिति के प्रमुख केंद्रीय वित्त मंत्री

67. निम्नलिखित में से किसे भारत में 1991 से पूर्व की केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण बाधा या आलोचना माना जाता है?
(A) कृषि निर्यात पर अत्यधिक निर्भरता
(B) किसी भी औद्योगिक उत्पादन का अभाव
(C) लालफीताशाही और नौकरशाही में देरी
(D) सार्वजनिक परिसंपत्तियों का तत्काल निजीकरण

68. "रोलिंग प्लान" (अनवरत योजना) की अवधारणा को भारतीय नियोजन इतिहास में निम्नलिखित में से किस योजना अवधि के बीच संक्षिप्त रूप से पेश किया गया था?
(A) दूसरी और तीसरी योजनाएं
(B) चौथी और पांचवीं योजनाएं
(C) पांचवीं और छठी योजनाएं
(D) सातवीं और आठवीं योजनाएं

69. 74वें संविधान संशोधन द्वारा यथा अनिवार्य जिला योजना समिति की संरचना का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा कथन करता है?
(A) इसमें विशेष रूप से राज्य के राज्यपाल द्वारा सीधे मनोनीत वरिष्ठ प्रशासनिक सदस्य शामिल होते हैं।
(B) इसमें विशुद्ध रूप से नीति आयोग द्वारा नियुक्त विशेष तकनीकी विशेषज्ञ और आर्थिक सलाहकार शामिल होते हैं।
(C) सदस्यों का चार-पांचवां (4/5) हिस्सा जिला पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा अपने में से ही निर्वाचित होता है।
(D) इसकी अध्यक्षता अनिवार्य रूप से राज्य के मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री द्वारा पदेन रूप से की जाती है।

70. भारत द्वारा अपनाए गए सोवियत-प्रेरित केंद्रीकृत नियोजन मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसमें आर्थिक लक्ष्यों का केंद्रीकृत निर्माण शामिल था।
II. यह राज्य के हस्तक्षेप के बिना पूरी तरह से बाजार की शक्तियों पर निर्भर था।
III. इसने ऐतिहासिक रूप से अर्थव्यवस्था की सर्वोपरि ऊंचाइयों (कमांडिंग हाइट्स) पर मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण का पक्ष लिया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

71. राजनीतिक अस्थिरता और गंभीर आर्थिक संकट के कारण 1990 में आठवीं पंचवर्षीय योजना शुरु नहीं हो सकी, जिसके परिणामस्वरुप दो वार्षिक योजनाएं बनीं। आठवीं योजना आखिरकार किस वर्ष शुरु की गई थी?
(A) 1991
(B) 1992
(C) 1993
(D) 1994

72. भारत की नियोजन रणनीति में निम्नलिखित अवधारणात्मक बदलावों को ऐतिहासिक रूप से उभरने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. तीव्र औद्योगीकरण और भारी उद्योगों पर जोर
II. संरचनात्मक आर्थिक सुधारों और सांकेतिक नियोजन की ओर बदलाव
III. खाद्य संकट को हल करने के लिए कृषि क्षेत्र पर प्रमुख ध्यान
IV. पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर विजन और एक्शन ढांचा लाना
(A) III, I, II, IV
(B) I, III, II, IV
(C) III, II, I, IV
(D) I, II, III, IV

NODIA

73. जल संसाधन प्रबंधन में राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें रैंक देने के लिए नीति आयोग द्वारा विकसित किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है?
(A) राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी और वंचन सूचकांक
(B) राज्य स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रदर्शन सूचकांक
(C) समग्र जल प्रबंधन सूचकांक
(D) राष्ट्रीय निर्यात तैयारी और प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक

74. बारहवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा असंगत है?
(A) निजी क्षेत्र का उन्मूलन
(B) समग्र आर्थिक विकास को तेज करना
(C) दीर्घकालिक पर्यावरण और आर्थिक सतत विकास को बढ़ावा देना
(D) न्यायसंगत और व्यापक समावेशी विकास प्राप्त करना

75. योजना वित्तपोषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. केंद्रीय योजना सहायता के लिए ऐतिहासिक रूप से योजना आयोग के अनुमोदन की आवश्यकता होती थी।
II. योजना आयोग के उन्मूलन के बाद, केंद्रीय बजट से योजनागत और गैर-योजनागत व्यय के अंतर को हटा दिया गया।
III. वित्त आयोग अब राज्यों को केंद्रीय कर हस्तांतरण का प्राथमिक तंत्र है।

विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढाँचे के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया।

10. (A) केवल I और II
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित थी। इस योजना ने सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में भारी उद्योगों और पूंजीगत वस्तु निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। इसमें कृषि क्षेत्र की उपेक्षा पूरी तरह से नहीं की गई थी, बल्कि बुनियादी औद्योगिक ढांचे का निर्माण करके अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति अपनाई गई थी। इसलिए कृषि से ध्यान पूरी तरह हटाने का कथन असत्य है।

11. (D) सामाजिक न्याय के साथ विकास और समावेशी विकास
नौवीं से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारत के आर्थिक नियोजन का केंद्र बिंदु केवल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर तक सीमित न रहकर व्यापक सामाजिक कल्याण की ओर मुड़ गया। नौवीं योजना का मुख्य नारा सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि था, जबकि ग्यारहवीं योजना ने तीव्र और अधिक समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया। इस दौर में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण रोजगार और क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने की नीतियों को प्राथमिकता दी गई।

12. (B) तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास
भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना बारहवीं योजना (2012-17) थी। इसका मुख्य विषय तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास निर्धारित किया गया था। इस योजना का लक्ष्य उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त करने के साथ-साथ गरीबी में कमी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं में सुधार, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करना था। इसमें यह माना गया कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और पर्यावरण का ध्यान रखा जाना चाहिए।

13. (C) योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया।
1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) की स्थापना की। यह बदलाव केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था से नीतिगत मार्गदर्शन और थिंक टैंक मॉडल की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना और राज्यों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं को आकार देना है।

14. (D) नीति आयोग
नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीतिगत सलाहकार संस्था और थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों को रणनीतिक तथा तकनीकी सलाह प्रदान करता है। इसका मूल ढांचा सहकारी संघवाद की भावना पर आधारित है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर राष्ट्रीय विकास के एजेंडे को दिशा देती हैं। यह संस्था ऊपर-से-नीचे के दृष्टिकोण के बजाय नीचे-से-ऊपर के नियोजन दृष्टिकोण को प्राथमिकता देती है।

15. (B) केवल II
नीति आयोग भारत सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और वर्ष 2015 में इसने पूर्ववर्ती योजना आयोग का स्थान लिया। इसकी शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं। हालांकि, योजना आयोग के विपरीत, नीति आयोग के पास राज्यों या मंत्रालयों को वित्तीय संसाधन या योजना व्यय आवंटित करने की कोई शक्ति नहीं है। वित्तीय संसाधनों का आवंटन अब वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

16. (B) भारत के प्रधानमंत्री
नीति आयोग की शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) इसकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इस परिषद की अध्यक्षता पदेन रूप से भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और दिल्ली व पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। यह मंच राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, नीतियों और विकास रणनीतियों पर अंतर-सरकारी चर्चा और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है।

17. (B) 1991 के आर्थिक उदारीकरण के सुधार
वर्ष 1991 में शुरू किए गए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने अपनी नियोजन पद्धति में बड़ा बदलाव किया। इसके तहत राज्य द्वारा संचालित कठोर निर्देशात्मक नियोजन के स्थान पर बाजार-अनुकूल सांकेतिक नियोजन को अपनाया गया। सांकेतिक नियोजन में सरकार सीधी औद्योगिक गतिविधियों में शामिल होने के बजाय अर्थव्यवस्था में सुगमकर्ता की भूमिका निभाती है और निजी क्षेत्र को आर्थिक विकास का मुख्य चालक बनने का अवसर प्रदान करती है।

18. (A) बाजार संकेत और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी
सांकेतिक नियोजन एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें सरकार अनिवार्य उत्पादन लक्ष्य या कठोर नियंत्रण थोपने के बजाय व्यापक राष्ट्रीय विकास लक्ष्य निर्धारित करती है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार मुख्य रूप से बाजार संकेतों, राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहनों तथा निजी क्षेत्र के साथ सहयोग पर निर्भर करती है। 1991 के सुधारों के बाद भारत में राज्य की भूमिका संसाधनों के प्रत्यक्ष आवंटन से हटकर निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने वाली बन गई।

19. (C) जिला योजना समिति (डीपीसी)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZD के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति (डीपीसी) का गठन करना अनिवार्य है। यह प्रावधान 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। इस समिति का मुख्य कार्य जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई स्थानीय विकास योजनाओं को समेकित करना और पूरे जिले के लिए एक एकीकृत प्रारूप विकास योजना तैयार करना है ताकि संतुलित क्षेत्रीय विकास हो सके।

Click Here to Buy book on Amazon

उत्तर (व्याख्या सहित)

NODIA

1. (B) सोवियत संघ
स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने आर्थिक विकास को गति देने के लिए केंद्रीकृत नियोजन मॉडल अपनाया। यह मॉडल सोवियत संघ की आर्थिक प्रणाली से गहराई से प्रेरित था। सोवियत प्रणाली में राज्य आर्थिक संसाधनों के नियंत्रण और प्राथमिकताओं के अनुसार आवंटन का कार्य करता था। भारत ने भी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक न्याय और तीव्र विकास हासिल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को सर्वोपरि भूमिका देते हुए पंचवर्षीय योजनाओं की संरचना तैयार की।

2. (A) हैरोड-डोमर मॉडल
भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से 1956 की अवधि के लिए लागू की गई थी। यह योजना मुख्य रूप से हैरोड-डोमर आर्थिक वृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इस मॉडल का मुख्य ध्यान बचत दर को बढ़ाने और पूंजी निर्माण के माध्यम से अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता का विस्तार करने पर था। इस दौरान कृषि विकास, बुनियादी ढांचे के निर्माण और सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई ताकि देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

3. (C) कृषि और सिंचाई
स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत गंभीर खाद्यान्न संकट, शरणार्थी समस्या और मुद्रास्फीति की चुनौतियों का सामना कर रहा था। इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) में कृषि और सिंचाई क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान भाखड़ा-नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसी विशाल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत की गई। इन प्रयासों से खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और देश की कृषि संरचना मजबूत हुई।

4. (D) कृषि से सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व वाले भारी उद्योग की ओर
भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र कृषि क्षेत्र था, जबकि द्वितीय योजना (1956-61) में रणनीतिक बदलाव करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व में तीव्र औद्योगीकरण और भारी उद्योगों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा तैयार इस रणनीति का उद्देश्य देश में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना, विदेशी निर्भरता कम करना और दीर्घकालिक आर्थिक विकास की मजबूत नींव तैयार करना था।

5. (C) P-2, Q-4, R-1, S-3
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में समय के साथ विकास की प्राथमिकताएं बदलती रहीं। प्रथम योजना में कृषि और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया था। द्वितीय योजना में महालनोबिस मॉडल के तहत भारी और बुनियादी उद्योगों के विकास को प्राथमिकता मिली। छठी से आठवीं योजनाओं के दौरान गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और मानव विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। अंतिम यानी बारहवीं योजना में तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

6. (B) सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजीगत वस्तुएं और भारी उद्योग
प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित दो-क्षेत्रीय और चार-क्षेत्रीय आर्थिक मॉडल ने भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) की नींव रखी। इस मॉडल में सार्वजनिक क्षेत्र के तहत भारी उद्योगों और पूंजीगत वस्तुओं, जैसे इस्पात, मशीनरी और रसायन के उत्पादन पर बल दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करना, आयात पर निर्भरता घटाना और औद्योगिक आधार का निर्माण करना था ताकि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को तीव्र गति दी जा सके।

7. (D) बाहरी सैन्य संघर्ष और लगातार गंभीर सूखा
तीसरी से पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत को 1962 में चीन के साथ तथा 1965 एवं 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्धों का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त 1960 के दशक के मध्य में देश में लगातार भीषण सूखा पड़ा, जिससे गंभीर खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। इन परिस्थितियों ने विदेशी सहायता पर निर्भरता के खतरों को उजागर किया, जिसके कारण नीति निर्माताओं ने खाद्य सुरक्षा और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्राथमिक उद्देश्य बनाया।

8. (C) छठी से आठवीं योजनाएं
भारत में नियोजन के शुरुआती दशकों में आर्थिक संवृद्धि पर मुख्य ध्यान केंद्रित था, लेकिन 1970 के दशक से निर्धनता उन्मूलन को सीधी रणनीति बनाया गया। "गरीबी हटाओ" का विचार पांचवीं योजना में उभरा और छठी से आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इसे केंद्रीय नीति के रूप में लागू किया गया। इस अवधि में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसे विशिष्ट लक्षित गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी।

9. (C) इसने निजी क्षेत्र की भागीदारी के बिना विशुद्ध रूप से निर्देशात्मक नियोजन दृष्टिकोण को बनाए रखा।
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) की शुरुआत 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों के बाद हुई थी। इस योजना में भारत ने पुरानी निर्देशात्मक नियोजन प्रणाली को छोड़कर सांकेतिक नियोजन दृष्टिकोण अपनाया। इसमें राज्य का नियंत्रण कम किया गया तथा बाजार तंत्र एवं निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। इसके अंतर्गत मानव संसाधन

69. (C) सदस्यों का चार-पांचवां (4/5) हिस्सा जिला पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा अपने में से ही निर्वाचित होता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZD के अनुसार जिला योजना समिति (डीपीसी) की कुल सदस्यता का कम से कम चार-पांचवां (80 प्रतिशत) हिस्सा जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही निर्वाचित किया जाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। यह चुनाव जिले की ग्रामीण और शहरी आबादी के अनुपात के अनुसार होता है। शेष सदस्यों में राज्य सरकार के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं ताकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित हो सके।

70. (B) केवल I और III
स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा अपनाया गया सोवियत-प्रेरित नियोजन मॉडल केंद्रीकृत योजना निर्माण पर आधारित था। इसमें सरकार केंद्रीय स्तर पर उत्पादन और निवेश के लक्ष्य तय करती थी। इस मॉडल का मुख्य दर्शन अर्थव्यवस्था की 'सर्वोपरि ऊंचाइयों' (कमांडिंग हाइट्स) यानी भारी उद्योगों, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण स्थापित करना था। यह मॉडल राज्य के हस्तक्षेप से रहित मुक्त बाजार व्यवस्था पर निर्भर नहीं था, इसलिए कथन II गलत है।

71. (B) 1992
सातवीं पंचवर्षीय योजना 1990 में पूरी हुई थी, लेकिन देश में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, केंद्र में तेजी से बदलती सरकारों और 1991 के गंभीर भुगतान संतुलन के विदेशी मुद्रा संकट के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990 में शुरू नहीं हो सकी। इसके स्थान पर वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए दो पृथक वार्षिक योजनाएं लागू की गईं। उदारीकरण और संरचनात्मक समायोजन सुधारों के क्रियान्वयन के बाद आखिरकार 1992 में आठवीं योजना शुरू हुई।

72. (A) III, I, II, IV
भारत की नियोजन रणनीति में आए अवधारणात्मक बदलावों का सही ऐतिहासिक क्रम इस प्रकार है: प्रथम योजना (1951-56) में गंभीर खाद्य संकट को हल करने के लिए कृषि क्षेत्र पर प्रमुख ध्यान दिया गया। द्वितीय योजना (1956-61) में तीव्र औद्योगीकरण और भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद सांकेतिक नियोजन की ओर बदलाव हुआ। अंततः 2015 में नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का स्थान विजन व एक्शन फ्रेमवर्क द्वारा लिया।

73. (C) समग्र जल प्रबंधन सूचकांक
नीति आयोग ने देश में जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स) विकसित किया है। यह सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन जल संसाधनों के कायाकल्प, भूजल पुनर्भरण, सिंचाई पद्धतियों, ग्रामीण व शहरी पेयजल आपूर्ति और जल नीति जैसे विभिन्न मापदंडों पर करता है। इसका मुख्य उद्देश्य जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी संघवाद विकसित करना है।

74. (A) निजी क्षेत्र का उन्मूलन
बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) का मुख्य विषय "तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास" था। इसके प्रमुख उद्देश्यों में आर्थिक संवृद्धि को गति देना, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना, निर्धनता में कमी लाना तथा स्वास्थ्य व शिक्षा का विस्तार करना शामिल था। उदारीकृत अर्थव्यवस्था के युग में निजी क्षेत्र का उन्मूलन इस योजना का उद्देश्य नहीं था, बल्कि बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्रों में निजी निवेश व सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना था।

75. (A) केवल I, II और III
योजना आयोग के दौर में राज्यों को केंद्रीय योजना सहायता आवंटित करने के लिए आयोग के अनुमोदन की आवश्यकता होती थी। वर्ष 2015-16 से केंद्रीय बजट में व्यय के पारंपरिक वर्गीकरण यानी योजनागत और गैर-योजनागत व्यय के अंतर को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में वित्त आयोग ही राज्यों को केंद्रीय करों के हस्तांतरण का प्राथमिक संवैधानिक माध्यम है। नीति आयोग के पास वित्तीय संसाधनों के आवंटन का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कथन IV गलत है।

76. (B) इंदिरा गांधी
भारत में "गरीबी हटाओ" (गरीबी उन्मूलन) का प्रसिद्ध नारा तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1970 के दशक की शुरुआत में दिया गया था। यह नारा 1971 के आम चुनाव का मुख्य राजनीतिक व आर्थिक एजेंडा बना। इसके बाद पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) और छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान निर्धनता उन्मूलन और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को राष्ट्रीय नियोजन की केंद्रीय प्राथमिकता के रूप में मजबूती से लागू किया गया।

77. (C) 1991 के भुगतान संतुलन के संकट ने उदारीकरण और निजी निवेश पर निर्भरता को अनिवार्य बना दिया।
वर्ष 1991 में भारत को अभूतपूर्व भुगतान संतुलन संकट और विदेशी मुद्रा भंडार की गंभीर कमी का सामना करना पड़ा। इस वित्तीय आपातकाल ने भारत को अपनी बंद और राज्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए मजबूर किया। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के सहयोग तथा बाजार सुधारों के तहत सरकार ने निर्देशात्मक नियोजन को त्यागकर सांकेतिक नियोजन अपनाया, जिससे निजी पूंजी, विदेशी निवेश और बाजार शक्तियों को आर्थिक विकास का मुख्य इंजन बनाया जा सके।

78. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।
योजना आयोग की एक बड़ी सीमा यह थी कि वह देश के सभी राज्यों पर 'एक ही आकार सब पर लागू' (वन साइज़ फिट्स ऑल) का एकसमान केंद्रीकृत मॉडल थोपता था, जिससे स्थानीय और क्षेत्रीय विविधताओं की उपेक्षा होती थी। इस कमी को दूर करने के लिए वर्ष 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का मूल जनादेश सहकारी संघवाद को मजबूत करना तथा राज्यों की विशिष्ट परिस्थितियों,

Downloaded from www.pdf.tube

20. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। योजना आयोग की मुख्य आलोचना यह थी कि वह एक केंद्रीकृत, ऊपर-से-नीचे वाले नियोजन मॉडल का पालन करता था, जिसमें राज्यों की भागीदारी सीमित थी। इसके विपरीत, नीति आयोग की स्थापना सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और नीचे-से-ऊपर के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए की गई, जिससे राज्यों को नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी मिल सके।

21. (C) सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)
संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2030 तक प्राप्त करने के लिए निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नीति आयोग भारत की नोडल एजेंसी है। नीति आयोग संयुक्त राष्ट्र के उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए भारत की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट तैयार करता है। इस रिपोर्ट में देश में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति, चुनौतियों और रणनीतिक पहलों का व्यापक विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

22. (B) हैरोड-डोमर मॉडल योजना, गरीबी हटाओ दौर की योजना, समावेशी विकास योजना की ओर बदलाव, अंतिम पंचवर्षीय योजना
भारतीय नियोजन का इतिहास एक क्रमिक विकास दर्शाता है। सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसके बाद पांचवीं और छठी योजनाओं (1970 और 1980 के दशक) के दौरान "गरीबी हटाओ" पर ध्यान केंद्रित किया गया। ग्यारहवीं योजना (2007-12) के साथ नीतिगत ध्यान समावेशी विकास की ओर स्थानांतरित हुआ, और अंत में बारहवीं योजना (2012-17) भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना के रूप में निष्पादित की गई।

23. (D) हरित क्रांति
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं ने देश में कृषि अवसंरचना, सिंचाई सुविधाओं, उर्वरक संयंत्रों और कृषि अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करके मजबूत संस्थागत आधार तैयार किया। इसी संस्थागत सहायता और योजनागत निवेश के बल पर 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हरित क्रांति को सफलता के साथ लागू किया जा सका। उच्च उपज वाले किस्म के बीजों, रासायनिक उर्वरकों और बेहतर सिंचाई तकनीकों के प्रयोग से देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में सफल रहा।

24. (A) लालफीताशाही (नौकरशाही में देरी) और अकुशल सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश
1991 से पूर्व भारत में लागू केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली को व्यापक नौकरशाही नियंत्रण, लाइसेंस-परमिट राज और अत्यधिक लालफीताशाही के लिए जाना जाता था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विशाल संसाधनों के आवंटन के बावजूद व्यावसायिक दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभप्रदता की कमी बनी रही। व्यावसायिक निर्णयों में अत्यधिक देरी, कठोर विनियामक ढांचे और बाजार स्पर्धा के अभाव के कारण आर्थिक संसाधनों का अकुशल उपयोग हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था की समग्र उत्पादकता और संवृद्धि दर बाधित हुई।

25. (C) P-3, Q-4, R-2, S-1
भारत की विभिन्न नियोजन संस्थाओं और प्रशासनिक अवधारणाओं की अपनी विशिष्ट कार्यप्रणाली रही है। पूर्ववर्ती योजना आयोग के पास केंद्रीय बजटीय संसाधनों से राज्यों को सीधे निधि आवंटित करने की शक्ति थी। इसके विपरीत, नीति आयोग केवल एक सलाहकार विचार मंच या थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। सांकेतिक नियोजन बाजार-निर्देशित व्यवस्था को दर्शाता है, जबकि जिला योजना समिति स्थानीय स्तर पर नीचे-से-ऊपर नियोजन प्रक्रिया का संचालन करती है।

26. (A) पंचवर्षीय योजनाओं के दैनिक निर्माण और निष्पादन की देखरेख करना
योजना आयोग का औपचारिक पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता था, परंतु आयोग के कार्यकारी और प्रशासनिक प्रमुख की वास्तविक जिम्मेदारी उपाध्यक्ष की होती थी। उपाध्यक्ष पूर्णकालिक रूप से पंचवर्षीय योजनाओं के दैनिक निर्माण, अंतर-मंत्रालयी समन्वय, राज्यों के साथ बैठकों और योजनाओं के निष्पादन की देखरेख के लिए उत्तरदायी होता था। उपाध्यक्ष को प्रायः केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था और वह आयोग के संचालन का मुख्य आधार था।

27. (D) नीति आयोग के पास निधि आवंटित करने का कोई जनादेश नहीं है, यह विशुद्ध रूप से एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।
पूर्ववर्ती योजना आयोग के पास राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों की विकासात्मक योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों और योजना अनुदानों को आवंटित करने की व्यापक वित्तीय शक्तियां थीं। इसके विपरीत, नीति आयोग के पास कोई वित्तीय या वित्तीय आवंटन की शक्तियां निहित नहीं हैं। यह संस्था विशुद्ध रूप से एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। अब केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी और वित्तीय आवंटन का कार्य वित्त आयोग एवं वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

28. (B) वित्त आयोग
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है। ऐतिहासिक रूप से, जब योजना आयोग योजना व्यय के लिए निधियों का आवंटन करता था, तब वित्त आयोग गैर-योजना व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय करों के शुद्ध आगमों के वितरण और राज्यों को सहायता अनुदान का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार संवैधानिक संस्था थी।

29. (C) केंद्रीय और राज्य योजनाओं का अभिसरण
वर्ष 2018 में नीति आयोग द्वारा शुरु किया गया आकांक्षी जिला कार्यक्रम भारत के सबसे पिछड़े जिलों के त्वरित कायाकल्प के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से तीन प्रमुख सिद्धांतों यानी केंद्र व राज्य की योजनाओं का अभिसरण, अधिकारियों व हितधारकों का आपसी सहयोग, और जिलों

NODIA

रणनीतियों को आकार देने में बराबर की भागीदार हैं। नीति आयोग राज्यों को एक समान मंच प्रदान करके उनके बीच निरंतर संवाद और सहयोग को बढ़ावा देता है।

50. (C) केवल I और III
वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 द्वारा निर्मित एक संवैधानिक निकाय है, जबकि योजना आयोग न तो संवैधानिक निकाय था और न ही संसद के किसी अधिनियम द्वारा गठित वैधानिक निकाय, बल्कि इसे केवल एक कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से योजना आयोग राज्यों को उनकी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए योजना अनुदान आवंटित करता था। इसलिए योजना आयोग को वैधानिक निकाय बताने वाला कथन असत्य है।

51. (C) योजना आयोग के पास निधि आवंटन की शक्तियां थीं, जबकि नीति आयोग एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
पूर्ववर्ती योजना आयोग और नीति आयोग के बीच सबसे मौलिक अंतर उनकी वित्तीय शक्तियों और नियोजन दृष्टिकोण में है। योजना आयोग के पास राज्यों और मंत्रालयों को योजनागत निधियों तथा बजटीय अनुदानों का आवंटन करने का प्रत्यक्ष अधिकार था। इसके विपरीत, नीति आयोग के पास कोई वित्तीय आवंटन की शक्ति नहीं है; यह केवल एक सलाहकार निकाय और नीतिगत थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है जो सरकार को केवल रणनीतिक सलाह प्रदान करता है।

52. (D) तीव्र
भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना के रूप में कार्यान्वित बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) का आधिकारिक शीर्षक और मुख्य लक्ष्य "तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास" निर्धारित किया गया था। इस योजना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि उच्च आर्थिक विकास दर (तीव्र विकास) प्राप्त करना अति आवश्यक है ताकि देश में रोजगार के पर्याप्त अवसर निर्मित किए जा सकें, निर्धनता में कमी लाई जा सके और सामाजिक सेवाओं के विस्तार के लिए संसाधन जुटाए जा सकें।

53. (B) 1966-1969
भारत के नियोजन इतिहास में वर्ष 1966 से 1969 तक की तीन वर्ष की अवधि को "योजना अवकाश" (प्लान हॉलिडे) कहा जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत-चीन युद्ध (1962), भारत-पाक युद्ध (1965) और 1965-66 के भीषण सूखे के कारण अर्थव्यवस्था अत्यधिक दबाव में आ गई थी। इन गंभीर आर्थिक झटकों और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को टालना पड़ा और इसके स्थान पर तीन लगातार वार्षिक योजनाएं लागू की गईं।

54. (B) भारी औद्योगिक उत्पादन
नीति आयोग का आकांक्षी जिला कार्यक्रम भारत के पिछड़े जिलों के मानव विकास संकेतकों को तेजी से बेहतर बनाने पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से 5 सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों: स्वास्थ्य व पोषण, शिक्षा, कृषि व जल संसाधन, वित्तीय समावेशन व कौशल विकास, तथा बुनियादी अवसंरचना के तहत जिलों का मूल्यांकन करता है। भारी औद्योगिक उत्पादन इस कार्यक्रम का प्राथमिक विषय नहीं है, क्योंकि इसका मुख्य ध्यान जमीनी मानव कल्याण पर है।

55. (B) केवल I, III और IV
1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की नियोजन नीति में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल एक प्रमुख स्तंभ बन गया। इस मॉडल ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बजटीय संसाधनों की कमी को पूरा किया और निजी पूंजी, आधुनिक तकनीक व प्रबंधन विशेषज्ञता को आकर्षित करने में मदद की। दसवीं योजना के बाद से पीपीपी को पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष प्राथमिकता दी गई। इस मॉडल का उद्देश्य निजी क्षेत्र को प्रतिबंधित करना नहीं, बल्कि उसका विस्तार करना था।

56. (A) सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच
नीति आयोग सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच में प्रस्तुत करने के लिए भारत की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट तैयार करता है। यह रिपोर्ट वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले 17 सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में देश की प्रगति, कार्यान्वियन रणनीतियों, सर्वोत्तम प्रथाओं और चुनौतियों का व्यापक विवरण प्रदान करती है। इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत सतत विकास लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को वैश्विक समुदाय के समक्ष व्यक्त करता है।

57. (C) जिला योजना समितियां विशेष रूप से शहरी नगर पालिका क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं तैयार करती हैं।
74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गठित जिला योजना समिति (डीपीसी) का कार्य केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। बल्कि इसका संवैधानिक जनादेश जिले में पंचायतों (ग्रामीण) और नगरपालिकाओं (शहरी) दोनों द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं को एकीकृत और समेकित करना है। यह समिति पूरे जिले के लिए एक साझा प्रारूप विकास योजना तैयार करती है। इसलिए यह कहना गलत है कि डीपीसी केवल शहरी नगर पालिकाओं के लिए कार्य करती है।

58. (A) प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद
योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना ने भारत में राज्य स्तरीय नियोजन के परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। नीति आयोग ने ऊपर-से-नीचे के केंद्रीकृत दृष्टिकोण को समाप्त करके प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद के मॉडल को बढ़ावा दिया। इसके तहत राज्यों को नीति निर्माण प्रक्रिया में समान साझेदार बनाया गया है तथा विभिन्न विकास सूचकांकों के माध्यम से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि राज्य अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार नियोजन कर सकें।

59. (D) रैंकिंग दृश्यता द्वारा संचालित प्रतिस्पर्धी संघवाद
नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स सतत विकास मापदंडों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का पारदर्शी मूल्यांकन करता है। इस सूचकांक में राज्यों को

Click Here to Buy book on Flipkart

आयोग के पास राज्यों को केंद्रीय वित्तीय या योजना निधियों का आवंटन करने की कोई शक्ति नहीं है।

40. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।
तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) के दौरान 5.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर केवल 2.4 प्रतिशत ही हासिल हो सकी। इस विफलता का मुख्य कारण यह था कि भारत को 1962 में चीन तथा 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। इसके अलावा 1965-66 में देश में भीषण सूखा पड़ा, जिससे कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई और वित्तीय संसाधनों को रक्षा की ओर मोड़ना पड़ा।

41. (C) गाडगिल-मुखर्जी सूत्र
योजना आयोग के युग में राज्यों को पंचवर्षीय योजनाओं के तहत केंद्रीय सहायता आवंटित करने के लिए गाडगिल-मुखर्जी सूत्र का उपयोग किया जाता था। धनंजय रामचंद्र गाडगिल और प्रणब मुखर्जी के नाम पर आधारित इस सूत्र में राज्यों की जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, कर प्रयास, वित्तीय अनुशासन और विशेष समस्याओं जैसे मापदंडों के आधार पर भारित अंक दिए जाते थे। इसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करके क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना था।

42. (A) II, I, IV, III
भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख मील के पत्थरों का सही कालानुक्रमिक क्रम यह है: सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना में हैरोड-डोमर मॉडल लागू हुआ। इसके पश्चात द्वितीय योजना में महालनोबिस मॉडल की शुरुआत हुई। पांचवीं व छठी योजनाओं के दौरान "गरीबी हटाओ" दौर की शुरुआत की गई। अंततः वर्ष 2015 के बाद नीति आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15-वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट का शुभारंभ किया गया।

43. (D) ग्राम पंचायत
भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में योजना निर्माण का सबसे निचला और प्राथमिक स्तर ग्राम पंचायत है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद, ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और संसाधनों का आकलन करके ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार की जाती है। यह प्रक्रिया लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक मजबूत करने का कार्य करती है।

44. (B) तीसरी योजना और उत्तरवर्ती वार्षिक योजनाएं
भारत में हरित क्रांति के लिए संस्थागत और नीतिगत सहायता मुख्य रूप से तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) और उसके बाद की तीन वार्षिक योजनाओं (1966-69) के दौरान समेकित की गई। 1960 के दशक के मध्य में गंभीर खाद्यान्न संकट का सामना करने के बाद भारत ने उन्नत किस्म के बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई विस्तार पर आधारित गहन कृषि विकास रणनीति अपनाई, जिससे कृषि उत्पादकता में क्रांतिकारी वृद्धि हुई।

45. (C) P-2, Q-4, R-3, S-1
भारत के नियोजन इतिहास में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अपने विशिष्ट फोकस क्षेत्र रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लिए कृषि और सिंचाई पर बल दिया गया। द्वितीय योजना में भारी उद्योगों के जरिए मजबूत औद्योगिक आधार के निर्माण को प्राथमिकता मिली। आठवीं योजना में उदारीकरण के साथ बाजार-निर्देशित नियोजन की ओर बदलाव हुआ, जबकि ग्यारहवीं योजना ने समावेशी विकास को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया।

46. (D) नीति आयोग
नीति आयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से एसडीजी इंडिया इंडेक्स विकसित और प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। राज्यों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर की श्रेणियों में वर्गीकृत करके प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रोत्साहन दिया जाता है।

47. (D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
सांकेतिक नियोजन व्यवस्था में राज्य निजी उद्योगों पर कोई बाध्यकारी या कानूनी रूप से लागू उत्पादन लक्ष्य नहीं थोपता है। इसके विपरीत, अनिवार्य लक्ष्य और दंडात्मक प्रावधान निर्देशात्मक नियोजन की विशेषताएं हैं। सांकेतिक नियोजन में सरकार केवल व्यापक राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करती है और उन्हें प्राप्त करने के लिए बाजार प्रोत्साहनों, नीतिगत दिशानिर्देशों, वित्तीय रियायतों तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी का सहारा लेती है ताकि निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल सके।

48. (B) विनियामक ढील (उदारीकरण) और निजी पूंजी की भूमिका का विस्तार
वर्ष 1991 के गंभीर भुगतान संतुलन संकट के बाद शुरू की गई आठवीं पंचवर्षीय योजना ने भारत के नियोजन मॉडल में बड़ा परिवर्तन किया। इस योजना के दौरान राज्य ने प्रत्यक्ष औद्योगिक उत्पादक के स्थान पर एक सुगमकर्ता की भूमिका अपनाई। औद्योगिक लाइसेंसिंग में ढील, आयात उदारीकरण, विनियामक प्रतिबंधों को कम करना और बुनियादी ढांचे तथा विनिर्माण क्षेत्र में निजी व विदेशी पूंजी की व्यापक भूमिका को स्वीकार करना इस दौर की मुख्य विशेषताएं थीं।

49. (B) केंद्र और राज्य राष्ट्रीय विकास में समान भागीदारों के रूप में सहयोग करते हैं।
नीति आयोग के परिचालन का मुख्य आधार सहकारी संघवाद का सिद्धांत है। यह अवधारणा इस बात को रेखांकित करती है कि मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। नियोजन के संदर्भ में इसका तात्पर्य यह है कि केंद्र और सभी राज्य सरकारें राष्ट्रीय विकास के प्राथमिक लक्ष्यों, नीतियों और

Downloaded from www.pdf.tube

के बीच प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। इसका उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाकर प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में त्वरित सुधार लाना है।

30. (D) I, II और III
नीति आयोग का आकांक्षी जिला कार्यक्रम भारत के 112 अति पिछड़े जिलों का तीव्र सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। नीति आयोग द्वारा संचालित यह कार्यक्रम अभिसरण, सहयोग और जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों पर कार्य करता है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि इन जिलों का तेजी से कायाकल्प किया जा सके।

31. (A) एसडीजी इंडिया इंडेक्स
नीति आयोग द्वारा विकसित एसडीजी इंडिया इंडेक्स (सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक) एक व्यापक उपकरण है, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन और रैंकिंग करता है। यह सूचकांक राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देता है और नीति निर्माताओं को सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय मापदंडों पर साक्ष्य-आधारित नीतियां बनाने में सहायता करता है।

32. (B) 73वां संशोधन
वर्ष 1992 में पारित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इस ऐतिहासिक संशोधन ने संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़कर त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर) को अनिवार्य बनाया। इसने स्थानीय स्वशासी निकायों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने का अधिकार दिया, जिससे देश में विकेंद्रीकृत नियोजन की नींव बेहद मजबूत हुई।

33. (B) निजी निवेश द्वारा सार्वजनिक नियोजन परिव्यय का पूरक और प्रतिस्थापन होना
1991 के बाद भारत में अपनाई गई नियोजन रणनीति में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल का तीव्र विस्तार देखा गया। इस मॉडल ने बुनियादी ढांचे, परिवहन, ऊर्जा और शहरी विकास में सार्वजनिक बजटरी संसाधनों की कमी को पूरा करने का काम किया। इसमें सरकार की भूमिका केवल बजटीय आवंटनकर्ता के बजाय निजी क्षेत्र की पूंजी, दक्षता और प्रबंधन क्षमता का उपयोग करके सार्वजनिक विकास परियोजनाओं का पूरक और विस्तार करने की बन गई।

34. (D) 15 वर्ष
पंचवर्षीय योजनाओं की व्यवस्था समाप्त होने के बाद नीति आयोग ने एक नया बहु-स्तरीय नियोजन ढांचा पेश किया। इस नए ढांचे में दीर्घकालिक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 15-वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट (दृष्टि दस्तावेज) शामिल है। यह 15-वर्षीय विजन राष्ट्र के समग्र विकास की दीर्घकालिक दिशा तय करता है, जिसे लागू करने के लिए मध्यकालिक और अल्पकालिक रणनीतियों के साथ एकीकृत किया गया है।

35. (A) केवल I, II और III
वर्ष 2015 के बाद नीति आयोग ने पारंपरिक पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर एक नया तीन-स्तरीय नियोजन ढांचा लागू किया। इसमें 15-वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट, 7-वर्षीय राष्ट्रीय विकास रणनीति पत्र और तत्काल कार्यान्वयन के लिए 3-वर्षीय कार्य एजेंडा (एक्शन एजेंडा) शामिल है। राज्य योजना बोर्डों को सार्वभौमिक रूप से समाप्त नहीं किया गया, बल्कि कई राज्यों ने अपनी आवश्यकतानुसार उन्हें राज्य नीति आयोगों के रूप में पुनर्गठित किया।

36. (D) बारहवीं योजना
भारत की अंतिम आधिकारिक पंचवर्षीय योजना बारहवीं योजना थी, जिसका कालखंड वर्ष 2012 से 2017 निर्धारित किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास हासिल करना था। वर्ष 2015 में नीति आयोग के गठन के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की ऐतिहासिक प्रणाली को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद 15-वर्षीय विजन, 7-वर्षीय रणनीति और 3-वर्षीय कार्य एजेंडा पर आधारित नया ढांचा अपनाया गया।

37. (C) जिला योजना समिति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZD के तहत गठित जिला योजना समिति एक संवैधानिक निकाय है। इसका प्राथमिक दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतों तथा शहरी क्षेत्रों की नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई स्थानीय विकास योजनाओं को समेकित करना है। यह समिति प्राकृतिक संसाधनों के साझा उपयोग, बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पूरे जिले के लिए एक एकीकृत प्रारूप विकास योजना तैयार करती है।

38. (B) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)
नीति आयोग के संगठनात्मक ढांचे में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य और पदेन सदस्य शामिल होते हैं। इनके अतिरिक्त आयोग के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कार्य करता है। सीईओ की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए की जाती है और वह भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है, जो आयोग के प्रशासनिक और दैनिक कार्यों का संचालन करता है।

39. (D) राज्य सरकारों को केंद्रीय योजना निधियों का आवंटन करना
नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार के एक थिंक टैंक और नीतिगत सलाहकार निकाय के रूप में की गई है। इसके मुख्य उद्देश्यों में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना, और रणनीतिक व दीर्घकालिक नीतिगत ढांचे का निर्माण करना शामिल है। पूर्ववर्ती योजना आयोग के विपरीत, नीति

NODIA

प्राप्तांकों के आधार पर सार्वजनिक रूप से रैंक दी जाती है। रैंकिंग की यह दृश्यता राज्यों के बीच स्वस्थ और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा पैदा करती है। दंडात्मक वित्तीय कटौतियों के बजाय रैंकिंग दृश्यता द्वारा संचालित यह प्रतिस्पर्धी संघवाद राज्यों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है।

60. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।
1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की उच्च आर्थिक विकास दर को बनाए रखने के लिए राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और ऊर्जा जैसे बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में भारी निवेश की आवश्यकता थी। चूंकि सरकार के पास राजकोषीय बाधाओं के कारण इन सभी विशाल परियोजनाओं को स्वतंत्र रूप से वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त पूंजी संसाधनों की कमी थी, इसलिए सरकार ने निजी क्षेत्र की पूंजी, दक्षता और प्रबंधन का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल को बढ़ावा दिया।

61. (C) 3-वर्षीय कार्य एजेंडा
नीति आयोग द्वारा अपनाए गए नए नियोजन ढांचे के तहत पारंपरिक पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर तीन अलग-अलग समय-सीमा वाले दस्तावेज लागू किए गए। इनमें दीर्घकालिक प्राथमिकताओं के लिए 15-वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट, मध्यम अवधि के लिए 7-वर्षीय रणनीति पत्र, और अल्पकालिक कार्यान्वयन के लिए 3-वर्षीय कार्य एजेंडा (एक्शन एजेंडा) शामिल है। 3-वर्षीय कार्य एजेंडा सरकार की तत्काल नीतिगत प्राथमिकताओं और बजटीय पुनर्गठन के लिए एक व्यावहारिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

62. (A) केंद्रीकृत निर्देशात्मक नियोजन → सांकेतिक नियोजन → सहकारी संघवाद आधारित थिंक टैंक नियोजन
भारत का नियोजन दर्शन स्वतंत्रता के बाद से तीन प्रमुख चरणों से गुजरा है। 1951 से 1991 तक सोवियत मॉडल से प्रेरित केंद्रीकृत निर्देशात्मक नियोजन लागू था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व था। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उदारीकरण के साथ बाजार-अनुकूल सांकेतिक नियोजन अपनाया गया। अंततः 2015 में नीति आयोग की स्थापना के साथ भारत सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धी विकास और 'नीचे-से-ऊपर' दृष्टिकोण पर आधारित थिंक टैंक नियोजन प्रणाली की ओर स्थानांतरित हुआ।

63. (A) महालनोबिस मॉडल
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा तैयार किए गए नेहरू-महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस मॉडल में सार्वजनिक क्षेत्र के तहत भारी और बुनियादी पूंजीगत वस्तु उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। इसी नीति के परिणामस्वरूप भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में तीन विशाल एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य भारत में तीव्र औद्योगीकरण की मजबूत नींव रखना और आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करना था।

64. (B) समावेशी विकास और सामाजिक न्याय
नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं में भारतीय नियोजन के दर्शन में महत्वपूर्ण अवधारणात्मक बदलाव आया। नीति निर्माताओं ने यह स्वीकार किया कि केवल उच्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर ही निर्धनता और विषमता को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके परिणामस्वरूप नियोजन का मुख्य ध्यान समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की ओर स्थानांतरित हुआ। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, लैंगिक समानता और ग्रामीण रोजगार सृजन जैसी प्राथमिकताओं पर विशेष बल दिया गया।

65. (B) P-3, Q-2, R-1, S-4
नीति आयोग द्वारा पेश किए गए नए नियोजन ढांचे के तहत विभिन्न दस्तावेजों के लिए विशिष्ट समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं। विजन डॉक्यूमेंट राष्ट्र के दीर्घकालिक लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए 15 वर्ष की अवधि को कवर करता है। रणनीति पत्र मध्यम अवधि के नीतिगत रोडमैप के लिए 7 वर्ष की अवधि का होता है। कार्य एजेंडा तात्कालिक प्राथमिकताओं के कार्यान्वयन हेतु 3 वर्ष की अवधि का है, जबकि सतत विकास लक्ष्य 2030 तक लक्षित हैं।

66. (A) भारत के प्रधानमंत्री
नीति आयोग के संगठनात्मक ढांचे में विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होते हैं, जो संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ, ज्ञानवान व्यक्ति या अभ्यासकर्ता होते हैं। नीति आयोग की शासी परिषद तथा आयोग की अन्य संरचनाओं में इन विशेष आमंत्रितों को मनोनीत करने का सर्वाधिकार भारत के प्रधानमंत्री के पास होता है। इन विशेषज्ञों का मुख्य कार्य आयोग को विविध विषयों, जैसे तकनीकी नवाचार, आर्थिक विकास और सामाजिक नीति पर प्रासंगिक व विशेषज्ञ सलाह प्रदान करना है।

67. (C) लालफीताशाही और नौकरशाही में देरी
वर्ष 1991 से पूर्व लागू भारत की केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली की सबसे बड़ी कमी और आलोचना अत्यधिक नौकरशाही नियंत्रण तथा लालफीताशाही थी। योजना आयोग द्वारा संचालित इस मॉडल में व्यापक लाइसेंसिंग, परमिट प्रणाली और अत्यधिक विनियंत्रण था, जिसके कारण व्यावसायिक और औद्योगिक प्रस्तावों की स्वीकृति मिलने में वर्षों लग जाते थे। नौकरशाही में होने वाली इस अत्यधिक देरी ने निजी पहल को हतोत्साहित किया और आर्थिक विकास की गति को धीमा कर दिया।

68. (C) पांचवीं और छठी योजनाएं
भारत में 'रोलिंग प्लान' (अनवरत योजना) की अवधारणा जनता पार्टी सरकार द्वारा वर्ष 1978 में पेश की गई थी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया और 1978-83 की अवधि के लिए अनवरत योजना शुरू की। हालांकि, वर्ष 1980 में कांग्रेस सरकार के पुनः सत्ता में आने पर इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और 1980-85 की अवधि के लिए नई छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई।

Click Here to Buy book on Amazon

IV. नीति आयोग के पास राज्य के वित्तीय आवंटन पर पूर्ण अधिकार है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा संयोजन सही है?

(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I और IV
(D) I, II, III और IV

76. पांचवीं योजना से छठी योजना में ऐतिहासिक संक्रमण में गरीबी उन्मूलन पर गहरा ध्यान केंद्रित किया गया था। इस व्यापक नियोजन युग के दौरान "गरीबी हटाओ" अभियान शुरु करने के लिए कौन-से प्रधानमंत्री सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं?

(A) जवाहरलाल नेहरु
(B) इंदिरा गांधी
(C) लाल बहादुर शास्त्री
(D) राजीव गांधी

77. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प 1990 के दशक में भारत द्वारा सांकेतिक नियोजन की ओर रुख करने का सबसे उपयुक्त औचित्य प्रस्तुत करता है?

(A) 1980 के दशक में सोवियत संघ के आर्थिक पतन ने निर्णायक रूप से साबित कर दिया कि केंद्रीय निर्देशात्मक नियोजन अप्रचलित था।
(B) घरेलू कृषि क्षेत्र देश भर में पूरी तरह से चरमरा गया, जिससे तत्काल भारी राज्य औद्योगिक हस्तक्षेप की मांग की गई।
(C) 1991 के भुगतान संतुलन के संकट ने उदारीकरण और निजी निवेश पर निर्भरता को अनिवार्य बना दिया।
(D) बाहरी विदेशी दाता सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने योजना आयोग को तत्काल समाप्त करने का जनादेश दिया।

78. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।

अभिकथन (A): क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में रखे बिना सभी भारतीय राज्यों में नीतियों का मानकीकरण करने के लिए योजना आयोग को गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ा।

कारण (R): नीति आयोग की स्थापना सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और विशिष्ट राज्य वास्तविकताओं के अनुरूप दृष्टिकोण तैयार करने के जनादेश के साथ की गई थी।

(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

79. सीमावर्ती और मरुस्थलीय क्षेत्रों सहित राज्यों में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए नीति आयोग की रणनीति का एक प्रमुख कार्यात्मक घटक कौन-सा है?

(A) कई राज्यों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने के लिए बुलाई गई क्षेत्रीय परिषदें
(B) केंद्र में राज्य के सभी प्रशासनिक और वित्तीय आवंटन शक्तियों को व्यवस्थित रूप से केंद्रित करना
(C) स्थानीय विधायी मामलों पर राज्य विधानसभाओं को सीधे बाध्यकारी कार्यकारी आदेश जारी करना
(D) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासी निकायों को पूरी तरह से भंग और समाप्त करना

80. विकेंद्रीकृत नियोजन के मूल दर्शन का तात्पर्य है कि नियोजन प्रक्रिया आदर्श रूप से निम्नलिखित में से किस स्तर पर शुरु होनी चाहिए?

(A) राज्य की राजधानी में स्थित योजना सचिवालय
(B) जमीनी स्तर और स्थानीय स्वशासन का स्तर
(C) केंद्र सरकार के मंत्रालयों के भीतर केंद्रीकृत निर्णय लेने वाले निकाय
(D) अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों के रणनीतिक नीति प्रभाग

www.nodia.in
NODIA

जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरुप योजना निर्माण को बढ़ावा देना है।

79. (A) कई राज्यों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने के लिए बुलाई गई क्षेत्रीय परिषदें
नीति आयोग के संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदों का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। ये परिषदें विशिष्ट भौगोलिक व अंतर-राज्यीय मुद्दों, जैसे सीमावर्ती विकास, मरुस्थलीय क्षेत्र प्रबंधन, और साझा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को संबोधित करने के लिए बुलाई जाती हैं। इन क्षेत्रीय परिषदों में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल मिलकर अपनी साझा समस्याओं और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए ठोस रणनीति बनाते हैं।

80. (B) जमीनी स्तर और स्थानीय स्वशासन का स्तर
विकेंद्रीकृत नियोजन का मूल दर्शन 'नीचे-से-ऊपर' दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका तात्पर्य यह है कि विकास योजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया केंद्रीय सचिवालय में बैठने के बजाय जमीनी स्तर पर स्थित स्थानीय स्वशासी निकायों, जैसे ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं में शुरु होनी चाहिए। स्थानीय नागरिक और निकाय अपनी आवश्यकताओं को सबसे बेहतर समझते हैं, इसलिए जमीनी स्तर पर बनाई गई योजनाएं अधिक व्यावहारिक और प्रभावी होती हैं।

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

चूक (Sovereign Default)
(B) विदेशी पूंजी के पलायन के कारण घरेलू शेयर बाज़ार का पूर्ण पतन
(C) विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जबर्दस्ती अधिग्रहण (Hostile Takeover)
(D) घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष 50 प्रतिशत से अधिक की अति-मुद्रास्फीति (Hyperinflation) का चक्र

14. समष्टि आर्थिक लेखांकन (Macroeconomic Accounting) में, एक निरंतर चालू खाता घाटा (CAD) यह दर्शाता है कि कोई देश मूलभूत रूप से:
(A) विश्व के बाकी हिस्सों के व्यापारिक भागीदारों से आयात की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं का काफी अधिक निर्यात कर रहा है
(B) राष्ट्रीय जन कल्याण और विकास कार्यक्रमों पर खर्च की तुलना में कहीं अधिक सरकारी कर राजस्व उत्पन्न कर रहा है
(C) अपने निर्यात की तुलना में अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आयात कर रहा है, तथा घरेलू व्यय को वित्तपोषित करने के लिए विदेशी बचत का उपयोग कर रहा है
(D) सकल घरेलू उपभोक्ता मांग की निरंतर कमी के कारण निरंतर समष्टि आर्थिक अवस्फीति (Deflation) का सामना कर रहा है

15. 1991 में आईएमएफ (IMF) और विश्व बैंक द्वारा भारत पर थोपी गई संरचनात्मक समायोजन शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उन्होंने अर्थव्यवस्था को वैश्विक व्यापार के लिए खोलने के लिए औसत आयात शुल्कों में महत्वपूर्ण कटौती का अनिवार्य निर्देश दिया।
II. उन्होंने सरकारी खर्च को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार को राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए बाध्य किया।
III. उन्होंने निर्यातों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भारतीय रुपये के तीव्र अवमूल्यन की आवश्यकता पर बल दिया।
IV. उन्होंने अधिकांश विनिर्माण क्षेत्रों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त करने पर बल दिया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

16. 1991 के उदारीकरण एजेंडे का एक मुख्य स्तंभ औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति थी। हालांकि, उद्योगों की एक छोटी ऋणात्मक सूची (Negative List) के लिए लाइसेंसिंग को जानबूझकर बनाए रखा गया था, जिसका मुख्य कारण था:
(A) वे उद्योग असाधारण रूप से लाभदायक थे और सरकारी स्वामित्व ने राजकोषीय व्यय के लिए निरंतर उच्च लाभांश आय सुनिश्चित की
(B) वे रणनीतिक उद्योग विशेष रूप से विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ संयुक्त उद्यमों के लिए आरक्षित थे
(C) वे उद्योग सुरक्षा, रणनीतिक चिंताओं, खतरनाक रसायनों और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित थे
(D) वे सरकारी स्वामित्व वाले उद्योग तकनीकी रूप से अप्रचलित थे और उन्हें व्यावहारिक बनाए रखने के लिए निरंतर सरकारी संरक्षण की आवश्यकता थी

17. मुक्त बाज़ार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए 1991 के बाद के नियामक सुधारों के हिस्से के रूप में, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार (MRTP) अधिनियम, 1969 को समाप्त कर अंततः निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया?
(A) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999
(B) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
(C) कंपनी अधिनियम, 2013
(D) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2006

18. 1991 के सुधारों के बाद भारत के बैंकिंग क्षेत्र में ब्याज दरों का विनियमन (Deregulation) मुख्य रूप से किस समिति की सिफारिशों पर किया गया था?
(A) केलकर सलाहकार समिति
(B) चेलैया समिति
(C) तेंदुलकर समिति
(D) नरसिम्हम समिति

19. 1991 के आर्थिक सुधार पैकेज का मूल्यांकन करते समय, 'समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण' (Macroeconomic Stabilization) के उपाय मूलभूत रूप से 'संरचनात्मक समायोजन' (Structural Adjustment) के उपायों से किस प्रकार भिन्न हैं?
(A) स्थिरीकरण अल्पकालिक भुगतान संतुलन और मुद्रास्फीति को संबोधित करता है, जबकि संरचनात्मक समायोजन दीर्घकालिक आर्थिक दक्षता में सुधार करता है
(B) स्थिरीकरण मुख्य रूप से दीर्घकालिक संस्थागत नियामक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि संरचनात्मक समायोजन विशेष रूप से तत्काल नोट छपाई से संबंधित है
(C) स्थिरीकरण नीति ढांचे का प्रबंधन विशेष रूप से विश्व बैंक द्वारा किया जाता है, जबकि संरचनात्मक समायोजन पैकेज का प्रबंधन विशेष रूप से केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है
(D) स्थिरीकरण व्यवस्थित रूप से आयात शुल्क बढ़ाने पर केंद्रित है, जबकि संरचनात्मक समायोजन प्रत्यक्ष सरकारी सब्सिडी में भारी वृद्धि करने पर केंद्रित है

20. निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
कथन (A): 1991 में विश्व बैंक और आईएमएफ (IMF) द्वारा भारत को दिए गए संरचनात्मक समायोजन ऋणों के साथ

NODIA

7. 'मांग-जनित मुद्रास्फीति' (Demand-Pull Inflation) आमतौर पर किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थिति में उत्पन्न होती है?
(A) जब महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल की लागत तेज़ी से बढ़ती है, जिससे उत्पादक अंतिम बाज़ार कीमतों को बढ़ाने के लिए मजबूर होते हैं
(B) जब वस्तुओं और सेवाओं की सकल मांग अर्थव्यवस्था की सकल उत्पादन क्षमता से अधिक हो जाती है
(C) जब किसी देश की मुद्रा का विनिमय बाज़ार में अत्यधिक मूल्यवर्धन होता है, जिससे उसके निर्यात महंगे हो जाते हैं
(D) जब निरंतर आपूर्ति श्रृंखला बाधाएँ निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ता बाज़ारों तक प्रभावी ढंग से पहुँचने से रोकती हैं

8. भारत के समष्टि अर्थशास्त्र (Macroeconomic) ढांचे में, निम्नलिखित में से कौन-सी व्याख्या 'आयातित मुद्रास्फीति' (Imported Inflation) की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करती है?
(A) विलासितापूर्ण आयातित ऑटोमोबाइल और विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए घरेलू उपभोक्ता मांग में भारी वृद्धि से संचालित मुद्रास्फीति
(B) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा घरेलू शेयर बाज़ार में भारी खरीदारी और अत्यधिक मौद्रिक तरलता डालने के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति
(C) आवश्यक आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पन्न मुद्रास्फीति, जो अक्सर घरेलू मुद्रा के मूल्यह्रास से और बढ़ जाती है
(D) सरकार द्वारा गैर-आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और औद्योगिक घटकों पर आयात शुल्क बढ़ाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न मुद्रास्फीति

9. अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि निरंतर उच्च मुद्रास्फीति एक अत्यधिक प्रतिगामी कर (Regressive Tax) के रूप में कार्य करती है। मुद्रास्फीति धनवान वर्गों की तुलना में समाज के गरीब वर्गों को असमान रूप से अधिक नुकसान क्यों पहुँचाती है?
(A) क्योंकि गरीब अपनी व्यक्तिगत बचत का एक बड़ा हिस्सा शेयर बाज़ारों में निवेश करते हैं, जिन्हें मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान भारी नुकसान होता है
(B) क्योंकि गरीब अपनी कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट जैसी भौतिक संपत्तियों में रखते हैं, जो मुद्रास्फीति के दौरान वास्तविक मूल्य खो देती हैं
(C) क्योंकि मुद्रास्फीति सरकार को राजकोषीय व्यय को तत्काल कम करने और गरीबों के लिए कल्याणकारी प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण लाभों में कटौती करने के लिए मजबूर करती है
(D) क्योंकि गरीब परिवारों की आय का एक बड़ा हिस्सा आवश्यक उपभोग्य वस्तुओं पर खर्च होता है, और उनकी नाममात्र (Nominal) आय पूर्ण रूप से मुद्रास्फीति के साथ समायोजित नहीं होती है

10. भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक गरीबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. संरचनात्मक गरीबी प्राथमिक रूप से भूमि के असमान वितरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच के अभाव जैसी दीर्घकालिक, प्रणालीगत बाधाओं से प्रेरित होती है।
II. क्षणिक (अस्थायी) गरीबी के विपरीत, संरचनात्मक गरीबी को केवल अल्पकालिक राजकोषीय प्रोत्साहन या मौद्रिक ढील के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है।
III. 1991 के बाद की उदारीकरण नीतियों ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में संरचनात्मक गरीबी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

11. 1991 के भुगतान संतुलन (BoP) संकट के चरमोत्कर्ष के दौरान, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अत्यंत गंभीर स्तर तक गिर गया था। उस मोड़ पर यह विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितने सप्ताहों के आवश्यक आयातों के लिए पर्याप्त था?
(A) 3 सप्ताह से भी कम
(B) लगभग 8 सप्ताह
(C) लगभग 12 सप्ताह
(D) लगभग 24 सप्ताह

12. 1991 के संकट से जुड़ी निम्नलिखित महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं को उनके सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. खाड़ी युद्ध के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में अचानक और तीव्र वृद्धि
II. भारत के स्वर्ण भंडार को बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास गिरवी रखने के लिए हवाई मार्ग से ले जाना
III. लाइसेंस राज को पूरी तरह से समाप्त करने वाली नई औद्योगिक नीति की घोषणा
IV. भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से आपातकालीन संरचनात्मक समायोजन ऋण प्राप्त करना
निम्नलिखित में से कौन-सा सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है?
(A) I, II, III, IV
(B) II, I, IV, III
(C) I, III, II, IV
(D) III, I, IV, II

13. 1991 में राष्ट्रीय स्वर्ण भंडार को गिरवी रखने का कठोर कदम मुख्य रूप से किस आसन्न गंभीर परिणाम से बचने के लिए उठाना आवश्यक हो गया था?
(A) भारत के अल्पकालिक बाहरी ऋण दायित्वों पर संप्रभु

Click Here to Buy book on Flipkart

पुनरआवंटन
(D) सार्वजनिक-निजी परियोजनाओं के लिए प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति और सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) को अनिवार्य बनाना

55. 1991 के भुगतान संतुलन (BoP) संकट के अंतर्निहित संरचनात्मक कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. 1980 के पूरे दशक के दौरान निरंतर उच्च राजकोषीय घाटे के कारण बड़े पैमाने पर सरकारी उधार और समष्टि आर्थिक अस्थिरता की स्थिति बनी।
II. अत्यधिक संरक्षित और गैर-प्रतिस्पर्धी घरेलू औद्योगिक क्षेत्र के परिणामस्वरूप निराशाजनक निर्यात प्रदर्शन हुआ।
III. सोवियत संघ के अचानक विघटन ने भारतीय रुपये-व्यापार निर्यातों के लिए एक प्रमुख, स्थिर बाज़ार को समाप्त कर दिया।
IV. 1980 के दशक के उत्तरार्ध में विदेशी मुद्रा भंडार के विशाल संचय के कारण रुपये का मूल्य अधिक (Overvalued) हो गया, जिससे निर्यात कृत्रिम रूप से दब गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से अंतर्निहित संरचनात्मक कारणों की पहचान करते हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, III और IV
(D) I, II, III और IV

56. जुलाई 1991 में गंभीर भुगतान संतुलन संकट का मुकाबला करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रुपये का दो चरणों में अवमूल्यन (Devaluation) किया। भुगतान संतुलन संकट के दौरान राष्ट्रीय मुद्रा के अवमूल्यन के पीछे प्राथमिक आर्थिक तर्क क्या है?
(A) घरेलू उपभोक्ता आयातों को सस्ता बनाना और उच्च आय वाले नागरिकों के लिए विलासिता की विदेशी वस्तुओं को अधिक सुलभ बनाना
(B) स्थानीय रूप से राष्ट्रीय मुद्रा की क्रय शक्ति में स्थायी रूप से वृद्धि करके घरेलू मुद्रास्फीति दरों को कम करना
(C) निर्यातों को सस्ता और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए आयात लागत बढ़ाना
(D) जब भी विदेशी मुद्रा भंडार 1 बिलियन डॉलर से नीचे गिरता है तो लागू होने वाली अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करना

57. जबकि भारत ने 1994 में चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता (Convertibility) को अपना लिया, इसने पूंजी खाते की परिवर्तनीयता के लिए एक प्रबंधित दृष्टिकोण बनाए रखा है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता में प्राथमिक रूप से क्या शामिल है?
(A) बिना कोई सीमा शुल्क या कर चुकाए विदेशी उपभोक्ता वस्तुओं का आयात करने का अप्रतिबंधित वैधानिक अधिकार
(B) विदेशी केंद्रीय बैंकों और बहुपक्षीय निकायों का स्थानीय मुद्रा बैंक नोटों को स्वतंत्र रूप से छापने का पूर्ण अधिकार
(C) कृषि निर्यातों पर सभी परिमाणात्मक सीमाओं का पूर्ण उन्मूलन
(D) बाज़ार दरों पर स्थानीय वित्तीय संपत्तियों को विदेशी वित्तीय संपत्तियों में परिवर्तित करने की अप्रतिबंधित स्वतंत्रता

58. 1991 के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया और अचानक सीमा शुल्क (टैरिफ) कटौती ने घरेलू सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को महत्वपूर्ण चुनौतियों के सामने ला खड़ा किया, मुख्य रूप से क्योंकि:
(A) एमएसएमई (MSME) को सस्ते आयात की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जबकि वे अवसंरचनात्मक बाधाओं और उच्च ऋण लागतों से जूझ रहे थे
(B) केंद्र सरकार ने सभी लघु और मध्यम उद्यमों को विदेशी बाज़ारों में निर्मित वस्तुओं का निर्यात करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था
(C) विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों ने व्यवस्थित रूप से सभी संचालित घरेलू सूक्ष्म और लघु उद्यमों का अधिग्रहण और समापन कर दिया
(D) विश्व बैंक ने राज्य समर्थित सभी एमएसएमई क्लस्टर को तत्काल बंद करने का स्पष्ट आदेश दिया था

NODIA

59. निम्नलिखित कारकों में से 'भिन्न' की पहचान कीजिए। इनमें से तीन लागत-प्रेरित (Cost-Push) मुद्रास्फीति के मान्यता प्राप्त कारक हैं, जबकि एक मांग-जनित (Demand-Pull) मुद्रास्फीति का कारक है:
(A) प्रमुख कृषि खाद्य जिंसों के लिए केंद्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में अचानक, देशव्यापी वृद्धि
(B) बड़े पैमाने पर चुनाव पूर्व नकद हस्तांतरण योजना के साथ करों में कटौती
(C) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री माल भाड़ा प्रभार और वैश्विक शिपिंग कंटेनर लागत में एक अप्रत्याशित, तीव्र वृद्धि
(D) एक गंभीर सूखा जो घरेलू खाद्यान्न फसल के बड़े हिस्से को नष्ट कर देता है

60. निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
कथन (A): भारत में दूसरी पीढ़ी के सुधार साधन बाज़ारों (Factor Markets), विशेष रूप से भूमि और श्रम के पुनर्गठन पर भारी ज़ोर देते हैं।
कारण (R): 1991 के सुधारों ने मुख्य रूप से उत्पाद बाज़ारों और व्यापार का उदारीकरण किया, जिससे जटिल, अत्यधिक विनियमित भूमि और श्रम ढांचे काफी हद तक अछूते रह गए, जो अब विनिर्माण वृद्धि को बाधित कर रहे हैं।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।

कड़ी समष्टि आर्थिक नीतिगत शर्तें जुड़ी हुई थीं।
कारण (R): अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान यह सुनिश्चित करने के लिए शर्तें लगाते हैं कि उधार लेने वाला देश ऐसे सुधार लागू करे जो आर्थिक स्थिरता और ऋण पुनर्भुगतान क्षमता को बहाल करें।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

21. 1991 के उदारीकरण के बाद, भारत द्वारा अपने चालू खाता घाटे (CAD) के वित्तपोषण के तरीके में एक रणनीतिक बदलाव आया। निम्नलिखित में से कौन-सा CAD के वित्तपोषण का पसंदीदा, गैर-ऋण सृजनकारी (Non-debt creating) माध्यम बन गया?
(A) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और पोर्टफोलियो इक्विटी प्रवाह
(B) विदेशी वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक संप्रभु उधार
(C) विदेशी सरकारों से दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहायता
(D) वैश्विक स्तर पर बड़ी मात्रा में संप्रभु स्वर्ण बांड जारी करना

22. समकालीन भारतीय आर्थिक विमर्श में, "दूसरी पीढ़ी के सुधार" (Second-Generation Reforms) मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करते हैं?
(A) रणनीतिक क्षेत्रों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को फिर से लागू करना
(B) दूरसंचार, बैंकिंग और नागरिक उड्डयन जैसे प्रमुख उभरते सेवा क्षेत्रों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण
(C) अमेरिकी डॉलर और यूरोपीय मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये के लिए सख्त स्थिर विनिमय दर प्रणाली को फिर से स्थापित करना
(D) साधन बाज़ार (Factor Markets), विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण, श्रम कानून और पूंजी बाज़ार

23. भारत की निजीकरण नीति के संदर्भ में, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) में नियमित अल्पसंख्यक हिस्सेदारी की बिक्री से 'रणनीतिक विनिवेश' (Strategic Disinvestment) को विशेष रूप से क्या अलग करता है?
(A) रणनीतिक विनिवेश बजटीय राजस्व को अधिकतम करने के लिए कानूनी रूप से केवल अत्यधिक लाभदायक सरकारी उद्यमों तक सीमित है
(B) रणनीतिक विनिवेश में एक निजी संस्था को प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ पर्याप्त सरकारी शेयरधारिता की बिक्री शामिल है
(C) रणनीतिक विनिवेश में प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के माध्यम से विशेष रूप से घरेलू खुदरा निवेशकों को उद्यम इक्विटी शेयर बेचना शामिल है
(D) रणनीतिक विनिवेश का अर्थ बिना किसी नकद विनिमय के सरकारी शेयरों को सीधे दूसरे सार्वजनिक उद्यम में स्थानांतरित करना है

24. निम्नलिखित में से कौन-सा उद्यम उदारीकरण के बाद के युग में भारत सरकार द्वारा प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण से जुड़े पूर्ण रणनीतिक निजीकरण के पहले प्रमुख उदाहरण का प्रतिनिधित्व करता है?
(A) भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)
(B) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)
(C) मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(D) भारतीय स्टेट बैंक (SBI)

25. सूची I में निजीकरण से संबंधित पदों को सूची II में उनकी परिभाषाओं से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (निजीकरण संबंधी पद)
P. सांकेतिक विनिवेश (Token Disinvestment)
Q. रणनीतिक विनिवेश (Strategic Disinvestment)
R. स्वर्णिम शेयर (Golden Share)
S. राष्ट्रीयकरण (Nationalization)
सूची II: (परिभाषा)
1. निजी स्वामित्व वाली संपत्तियों को सार्वजनिक स्वामित्व में स्थानांतरित करना
2. नियंत्रण छोड़े बिना प्राथमिक रूप से राजकोषीय राजस्व जुटाने के लिए अल्पसंख्यक हिस्सेदारी की बिक्री
3. एक नाममात्र का शेयर अपने पास रखना जो सरकार को कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णयों पर वीटो शक्ति देता है
4. प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ इक्विटी की बिक्री
निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित है?
(A) P-2, Q-4, R-3, S-1
(B) P-4, Q-2, R-1, S-3
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

26. 2021 में एयर इंडिया का सफल निजीकरण एक ऐतिहासिक आर्थिक घटना के रूप में देखा गया, मुख्य रूप से क्योंकि:
(A) इसने घाटे में चल रहे विमानन क्षेत्र से सरकार के पूर्ण निकास (Exit) को चिह्नित किया
(B) यह पहला ऐतिहासिक उदाहरण था जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख उपक्रम (PSU) को पूरी तरह से विदेशी स्वामित्व वाली वैश्विक एयरलाइन को बेचा गया था
(C) इसने उस विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजकोषीय घाटे को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए पर्याप्त प्रत्यक्ष राजस्व उत्पन्न किया
(D) इसके परिणामस्वरूप भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का तत्काल विघटन हुआ

NODIA

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) शुरू किया। यह प्रमुख योजना मुख्य रूप से किस आर्थिक तंत्र पर निर्भर करती है?

(A) ग्रामीण उद्यमियों को अत्यधिक सब्सिडी वाला औपचारिक ऋण प्रदान करना
(B) वंचित समुदायों को मुफ्त कृषि भूमि वितरित करना
(C) रोजगार की स्थिति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के माध्यम से सार्वभौमिक बुनियादी आय की पेशकश करना
(D) ग्रामीण परिवारों को अकुशल शारीरिक कार्य में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देना

42. सार्वजनिक क्षेत्र के सुधारों के संदर्भ में, 'निजीकरण' (Privatization) और 'अल्पसंख्यक विनिवेश' (Minority Disinvestment) के बीच मूलभूत अंतर यह है कि:

(A) निजीकरण प्रबंधन नियंत्रण को निजी हाथों में स्थानांतरित करता है, जबकि अल्पसंख्यक विनिवेश बहुसंख्यक सरकारी स्वामित्व को बनाए रखता है
(B) निजीकरण में विदेशी कॉर्पोरेट संस्थाओं को पूर्ण इक्विटी स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल है, जबकि अल्पसंख्यक विनिवेश घरेलू खरीदारों के लिए आरक्षित है
(C) निजीकरण राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के तहत निष्पादित किया जाता है, जबकि अल्पसंख्यक विनिवेश केंद्रीय बैंक द्वारा प्रशासित किया जाता है
(D) निजीकरण के लिए औपचारिक संसदीय मंजूरी अनिवार्य है, जबकि अल्पसंख्यक विनिवेश सीधे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निष्पादित किया जाता है

43. निम्नलिखित में से कौन-सा 1991 से पूर्व की व्यवस्था के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की एक परिभाषित विशेषता नहीं थी?

(A) आयातित वस्तुओं पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों और उच्च शुल्कों का व्यापक वैधानिक उपयोग
(B) अधिकांश क्षेत्रों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए स्वचालित स्वीकृति की व्यवस्था
(C) प्रशासित ब्याज दरों वाला एक अत्यधिक विनियमित वित्तीय क्षेत्र
(D) निजी क्षेत्र की क्षमता और उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए सख्त औद्योगिक लाइसेंसिंग

44. निम्नलिखित समष्टि आर्थिक कमजोरियों और उनके प्राथमिक परिभाषित संकेतकों में से गलत युग्म की पहचान कीजिए:

(A) भुगतान संतुलन संकट — विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट
(B) रोजगारहीन वृद्धि — उच्च रोजगार लोच के साथ उच्च जीडीपी वृद्धि
(C) राजकोषीय संकट — जीडीपी के मुकाबले संप्रभु ऋण का बढ़ता अनुपात
(D) बेकाबू मुद्रास्फीति — क्रय शक्ति का तीव्र, निरंतर और अनियंत्रित ह्रास

45. सूची I की समष्टि आर्थिक नीतियों/संस्थानों को सूची II में 1991 के बाद की उनकी संबंधित स्थिति से सुमेलित कीजिए:

सूची I: (1991 से पूर्व का नीतिगत क्षेत्र)
P. आयात कोटा (परिमाणात्मक प्रतिबंध)
Q. एमआरटीपी (MRTP) अधिनियम, 1969
R. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA)
S. औद्योगिक लाइसेंसिंग

सूची II: (1991 के बाद की स्थिति)
1. एक नकारात्मक सूची को छोड़कर लगभग सभी उद्योगों के लिए समाप्त कर दिया गया
2. वस्तुओं में मुक्त व्यापार की अनुमति देने के लिए व्यवस्थित रूप से चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया
3. बाज़ार दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित
4. बाहरी व्यापार और भुगतानों को सुगम बनाने के लिए फेमा (FEMA) द्वारा प्रतिस्थापित

निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित है?

(A) P-2, Q-3, R-4, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-2, Q-4, R-3, S-1

46. 1991 के बाद के व्यापार उदारीकरण के मार्ग के तहत, गैर-कृषि आयातों पर भारत के उच्चतम सीमा शुल्क में एक नाटकीय बदलाव आया। निम्नलिखित में से कौन-सा इस परिवर्तन का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

(A) घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए उच्चतम शुल्क को 50% से बढ़ाकर 300% से अधिक कर दिया गया था
(B) उच्चतम शुल्क को पूरी तरह से आंतरिक वस्तु एवं सेवा करों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिससे सीमा शुल्क पूरी तरह समाप्त हो गया
(C) उच्चतम शुल्क 1991 में 150% से अधिक से घटाकर 2000 के दशक के उत्तरार्ध तक लगभग 10% कर दिया गया था
(D) राजस्व स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम शुल्क दो दशकों तक पूरी तरह से अपरिवर्तित रहा

47. मौद्रिक नीतिगत निर्णय लेते समय केंद्रीय बैंक अक्सर 'कोर मुद्रास्फीति' (Core Inflation) पर विचार करते हैं। कोर मुद्रास्फीति को हेडलाइन मुद्रास्फीति (Headline Inflation) से क्या अलग करता है?

(A) कोर मुद्रास्फीति केवल आवश्यक कृषि जिंसों के मूल्य वृद्धि को मापती है
(B) कोर मुद्रास्फीति खुदरा मार्जिन की उपेक्षा करते हुए पूरी तरह से थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तनों को मापती है
(C) कोर मुद्रास्फीति केवल सबसे कम आय वाले वर्ग के परिवारों द्वारा अनुभव की जाने वाली विशिष्ट मुद्रास्फीति दर का प्रतिनिधित्व करती है
(D) कोर मुद्रास्फीति अंतर्निहित मूल्य प्रवृत्तियों को पकड़ने के लिए अस्थिर खाद्य और ऊर्जा कीमतों को शामिल नहीं करती है (बाहर रखती है)

Downloaded from www.pdf.tube

34. भारत की उदारीकरण के बाद की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर आनुभविक (Empirical) अध्ययन बताते हैं कि तटीय और दक्षिणी राज्यों ने प्रति व्यक्ति आय वृद्धि के मामले में सामान्यतः कई उत्तरी और पूर्वी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। इस असमानता का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत आर्थिक कारण क्या है?
(A) दक्षिणी राज्यों ने केंद्रीय औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्ति नीतियों को लागू करने से पूरी तरह इनकार कर दिया, जिससे राज्य के एकाधिकार की रक्षा हुई
(B) भू-आबद्ध (Landlocked) उत्तरी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा 2010 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया था
(C) तटीय राज्य संरचनात्मक रूप से कम मुख्य मुद्रास्फीति दर बनाए रखते हैं क्योंकि उनकी स्थानीय आबादी कृषि जिंसों का उपभोग नहीं करती है
(D) तटीय राज्यों में बेहतर बंदरगाह और मानव पूंजी उपलब्ध थी, जिससे वे निर्यात वृद्धि और आईटी (IT) सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम हुए

35. उदारीकरण के बाद की अर्थव्यवस्था में 'समावेशी संवृद्धि' (Inclusive Growth) प्राप्त करने की चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. समावेशी संवृद्धि की मांग है कि जीडीपी विस्तार के लाभ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों में समतापूर्ण रूप से वितरित हों।
II. संरचनात्मक बेरोजगारी की उच्च दरें स्वाभाविक रूप से समावेशी संवृद्धि के उद्देश्यों को कमजोर करती हैं।
III. समावेशी संवृद्धि पर्यावरणीय सततता की उपेक्षा करते हुए केवल भारी उद्योगों के विस्तार को लक्षित करती है।
IV. गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुँच का विस्तार करना समावेशी संवृद्धि का एक मुख्य स्तंभ माना जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

36. समष्टि आर्थिक ढांचे में, 'राजकोषीय घाटा' (Fiscal Deficit) तब होता है जब:
(A) किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में देश की वस्तुओं और सेवाओं का कुल वाणिज्यिक आयात उसके कुल निर्यात से अधिक हो जाता है
(B) केंद्रीय बैंक अपने तिजोरियों में रखे कुल भौतिक स्वर्ण भंडार की तुलना में अत्यधिक कागज़ी मुद्रा नोट जारी करता है
(C) सरकार का कुल व्यय उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक हो जाता है
(D) प्रचलित वार्षिक मुद्रास्फीति दर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बचत पर दी जाने वाली नाममात्र ब्याज दरों से अधिक हो जाती है

37. 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक रुपांतरण का विश्लेषण करते हुए, किस क्षेत्र ने पारंपरिक विनिर्माण चरण को पीछे छोड़ते हुए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख योगदानकर्ता का स्थान हासिल किया?
(A) तृतीयक सेवा क्षेत्र
(B) प्राथमिक कृषि क्षेत्र
(C) द्वितीयक भारी विनिर्माण क्षेत्र
(D) चतुर्थक अनौपचारिक कारीगर क्षेत्र

38. भारत के वार्षिक केंद्रीय बजट का एक महत्वपूर्ण घटक 'विनिवेश लक्ष्य' (Disinvestment Target) है। इस लक्ष्य को पूरा करने से उत्पन्न प्राप्तियों को सरकारी खातों में किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है?
(A) राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts)
(B) ऋण-सृजन करने वाली दीर्घकालिक पूंजीगत प्राप्तियां
(C) चालू खाता अंतरण (Current Account Transfers)
(D) गैर-ऋण सृजनकारी पूंजीगत प्राप्तियां (Non-debt creating Capital Receipts)

39. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम मुख्य रूप से किस दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था?
(A) घरेलू मुद्रा की विदेशी विनिमय दर में निरंतर और अनियंत्रित अस्थिरता
(B) आर्थिक स्थिरता को खतरा पहुँचाने वाले उच्च राजकोषीय और राजस्व घाटे
(C) छोटे और सीमांत किसानों के लिए औपचारिक संस्थागत साख/ऋण की प्रणालीगत कमी
(D) शिक्षित शहरी युवाओं और स्नातकों के बीच संरचनात्मक बेरोजगारी की अभूतपूर्व दरें

40. निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:
कथन (A): नीति निर्माताओं द्वारा मुद्रास्फीति को अक्सर कराधान (Taxation) के सबसे प्रतिगामी रूप के रूप में वर्णित किया जाता है।
कारण (R): उच्च मुद्रास्फीति धन की क्रय शक्ति को तेज़ी से समाप्त करती है, जिससे कम आय वाले समूह असमान रूप से प्रभावित होते हैं जिनकी मजदूरी कीमतों के साथ-साथ नहीं बढ़ती है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

41. संरचनात्मक गरीबी और ग्रामीण बेरोजगारी का सीधे मुकाबला करने के लिए, भारत सरकार ने महात्मा गांधी

NODIA

अध्याय 11
आर्थिक समस्याएँ, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण

1. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सी व्याख्या 'संरचनात्मक बेरोजगारी' की आर्थिक अवधारणा का सबसे सटीक वर्णन करती है?
(A) विभिन्न नौकरियों के बीच बदलाव के दौरान श्रमिकों में उत्पन्न होने वाली अस्थायी बेरोजगारी
(B) श्रमिकों के पास मौजूद कौशल और आधुनिक उद्योगों द्वारा माँगी जाने वाली कौशल आवश्यकताओं के बीच मूलभूत बेमेल के कारण उत्पन्न बेरोजगारी
(C) चक्रीय आर्थिक मंदी के दौरान सकल मांग में अस्थायी कमी के परिणामस्वरूप उत्पन्न बेरोजगारी
(D) कृषि क्षेत्र में गैर-कटाई के विशिष्ट महीनों के दौरान पूर्वानुमानित रूप से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी

2. 'हेडकाउंट अनुपात' (Headcount Ratio) एक सांख्यिकीय सूचकांक है जिसका उपयोग अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए सामान्यतः किया जाता है?
(A) कार्यशील आयु वाली जनसंख्या का वह अनुपात जो वर्तमान में बेरोजगार है
(B) कुल कार्यशील आयु वाली जनसंख्या से आश्रित व्यक्तियों का अनुपात
(C) ग्रामीण जनसंख्या का वह प्रतिशत जो प्रतिवर्ष शहरी केंद्रों की ओर प्रवास करता है
(D) आधिकारिक तौर पर परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत

3. 1991 के बाद के भारत के आर्थिक पथ के विश्लेषण में, 'रोजगारहीन वृद्धि' (Jobless Growth) शब्द का प्रयोग बार-बार किया जाता है। यह परिघटना विशिष्ट रूप से किसे दर्शाती है?
(A) ऐसी स्थिति जहाँ सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में तेज़ी से वृद्धि होती है, लेकिन रोजगार सृजन की दर स्थिर या आनुपातिक रूप से अत्यंत कम बनी रहती है
(B) एक ऐसा आर्थिक चरण जहाँ अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार तेज़ी से बढ़ता है जबकि औपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में संकुचन होता है
(C) वह अवधि जहाँ कुल आर्थिक उत्पादन में गिरावट आती है, जिससे विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर छंटनी होती है
(D) एक जनसांख्यिकीय परिवर्तन जहाँ कार्यशील आयु वाली जनसंख्या आर्थिक विस्तार की दर की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ती है

4. भारत में गरीबी आकलन पद्धतियों के संदर्भ में, तेंदुलकर समिति (2009) ने प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से क्या करके पूर्व के आकलनों से एक महत्वपूर्ण बदलाव किया?
(A) विशेष रूप से आवास लागत के आधार पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक समान गरीबी रेखा की सिफारिश करना
(B) पारंपरिक निरपेक्ष गरीबी मानदंड के स्थान पर सापेक्ष गरीबी की अवधारणा को पेश करना
(C) गरीबी रेखा के आधार को केवल कैलोरी सेवन से हटाकर एक व्यापक उपभोग बास्केट पर केंद्रित करना, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय शामिल हैं
(D) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के उपभोग आंकड़ों के बजाय पूरी तरह से सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के आंकड़ों पर निर्भर रहना

5. गरीबी आकलन के लिए भारत सरकार द्वारा गठित निम्नलिखित विशेषज्ञ समितियों का सबसे पहले से सबसे नवीनतम तक सही कालानुक्रमिक क्रम पहचानिए:
(A) अलघ समिति, लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति
(B) लकड़ावाला समिति, अलघ समिति, रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति
(C) अलघ समिति, तेंदुलकर समिति, लकड़ावाला समिति, रंगराजन समिति
(D) लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति, अलघ समिति, रंगराजन समिति

6. निम्नलिखित परिदृश्यों में से कौन-सा 'पूर्ति-आघात' (Supply-Shock) मुद्रास्फीति का सबसे सटीक उदाहरण है?
(A) प्रमुख क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक अवसंरचना व्यय में भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप कीमतों में सामान्य वृद्धि
(B) व्यक्तिगत आयकर दरों में महत्वपूर्ण कटौती से खर्च में वृद्धि के कारण टिकाऊ उपभोग्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि
(C) केंद्रीय बैंक द्वारा निरंतर नीतिगत दरों में कटौती के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति का तेज़ी से विस्तार करने के कारण समग्र मूल्य स्तरों में वृद्धि
(D) भू-राजनीतिक संघर्ष के कारण वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति में बड़े पैमाने पर आए व्यवधान से घरेलू मुद्रास्फीति में हुई अचानक वृद्धि

Click Here to Buy book on Amazon

48. 2014 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर अपने प्राथमिक मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण मापदंड को आधिकारिक तौर पर बदल दिया। वर्तमान में भारत की मौद्रिक नीति के प्राथमिक एंकर के रूप में किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है?
(A) थोक मूल्य सूचकांक (WPI)
(B) उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) - राष्ट्रीय
(C) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) - संयुक्त
(D) जीडीपी डिफ्लेटर (GDP Deflator)

49. जब कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि होती है, तो भारत को आमतौर पर आयातित मुद्रास्फीति की लहर का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण यह है कि:
(A) भारत बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का निर्यात करता है और घरेलू स्तर पर कमी आ जाती है
(B) भारत अपने कच्चे तेल का 80-85% आयात करता है, इसलिए उच्च लागत परिवहन और विनिर्माण क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डालती है
(C) विदेशी संस्थागत निवेशक तुरंत बाज़ार से इक्विटी पूंजी वापस ले लेते हैं, जिससे ईंधन खुदरा विक्रेता कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाते हैं
(D) बढ़ते वैश्विक तेल आयात खर्चों की भरपाई के लिए सरकार व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट आयकर में भारी वृद्धि करती है

50. 1991 के बाद भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के उदारीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. एफडीआई के लिए स्वचालित मार्ग (Automatic Route) की शुरुआत की गई, जिससे विदेशी निवेशकों को पूर्व सरकारी मंजूरी के बिना अधिकांश क्षेत्रों में निवेश करने की अनुमति मिली।
II. स्वचालित मार्ग के अंतर्गत न आने वाले आवेदनों को संसाधित करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की स्थापना की गई थी।
III. मल्टी-ब्रांड रिटेल में एफडीआई को पूरी तरह से नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है, जिससे बिना किसी सोर्सिंग प्रतिबंध के 100% स्वचालित स्वीकृति की अनुमति मिलती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

51. वैश्वीकरण और पूंजी प्रवाह के संदर्भ में, उभरते बाज़ारों के नीति निर्माताओं द्वारा विदेशी संस्थागत निवेश (FII) को अक्सर 'हॉट मनी' (Hot Money) के रूप में वर्णित किया जाता है। इस शब्द का अर्थ है कि FII:
(A) वैश्विक ब्याज दरों में बदलाव या बाज़ार में घबराहट के कारण तेज़ी से बाहर जाने (बहिर्वाह) के प्रति संवेदनशील है
(B) विशेष रूप से उच्च-प्रौद्योगिकी वाले स्टार्ट-अप को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग किया जाता है
(C) घरेलू कॉर्पोरेट और पूंजीगत करों से बचने के लिए विदेशी ऑफशोर टैक्स हैवन के माध्यम से शोधित अवैध धन है
(D) असाधारण रूप से उच्च वाणिज्यिक ब्याज दरों पर विस्तारित द्विपक्षीय सरकार-से-सरकार संप्रभु विकास ऋण है

NODIA

52. गरीबी, रोजगार और ग्रामीण अवसंरचना को संबोधित करने वाली निम्नलिखित प्रमुख सरकारी फ्लैगशिप योजनाओं के शुभारंभ को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)
II. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
III. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)
IV. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
निम्नलिखित में से कौन-सा सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है?
(A) I, III, II, IV
(B) I, II, III, IV
(C) III, I, II, IV
(D) I, III, IV, II

53. भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च राजकोषीय घाटे की दीर्घकालिक चुनौती में पारंपरिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाला कारक निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) सब्सिडी, ब्याज और वेतन पर भारी खर्च के साथ निरंतर कर राजस्व में कमी
(B) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चलाने की असाधारण रूप से उच्च प्रशासनिक लागत
(C) विदेशी देशों को घरेलू स्वर्ण भंडार का निरंतर भौतिक निर्यात
(D) संघीय कर मॉडल में अप्रत्यक्ष उपभोग करों की तुलना में प्रत्यक्ष व्यक्तिगत आयकर पर संरचनात्मक अत्यधिक निर्भरता

54. भूमि बाज़ार की चुनौतियों का समाधान करना दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों का एक मुख्य घटक है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (LARR अधिनियम) ने अनिवार्य करके भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं में मूलभूत बदलाव किया:
(A) किसी भी निजी औद्योगिक उद्देश्य के लिए बहु-फसली कृषि भूमि के अधिग्रहण का पूर्ण निषेध
(B) भूमि अधिग्रहण की शक्तियों का पूरी तरह से राज्य सरकारों से स्थानीय ग्राम पंचायतों में स्थानांतरण
(C) मौद्रिक मुआवजा दिए बिना सभी अप्रयुक्त निजी औद्योगिक भूमि का अनिवार्य राष्ट्रीयकरण और

27. वैश्वीकरण के हिस्से के रूप में, भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी संस्थागत निवेश (FII) दोनों के लिए मार्ग खोले। दोनों के बीच मूलभूत अंतर क्या है?
(A) FDI विशेष रूप से बिना सरकारी मंजूरी के भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से संचालित होता है, जबकि FII को किसी भी वित्तीय नियामक निगरानी की आवश्यकता नहीं होती है
(B) FDI में दीर्घकालिक भौतिक संपत्ति का निर्माण और प्रबंधन नियंत्रण शामिल है, जबकि FII में अल्पकालिक बाज़ार निवेश शामिल है
(C) FDI कानूनी रूप से केवल भारी विनिर्माण क्षेत्रों में अनुमत है, जबकि FII केवल प्राथमिक कृषि जिंस बाज़ारों में अनुमत है
(D) FDI पूंजी प्रवाह संप्रभु बाहरी वाणिज्यिक उधारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि FII प्रवाह गैर-वापसी योग्य बहुपक्षीय विदेशी अनुदानों का प्रतिनिधित्व करते हैं

28. भारत में निम्नलिखित ऐतिहासिक समष्टि आर्थिक नीतिगत बदलावों का सबसे पहले से सबसे नवीनतम तक सही क्रमिक क्रम पहचानिए:
(A) 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, MRTP अधिनियम का अधिनियमन, एलपीजी (LPG) सुधारों की शुरुआत, FRBM अधिनियम का अधिनियमन
(B) MRTP अधिनियम का अधिनियमन, 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, एलपीजी (LPG) सुधारों की शुरुआत, FRBM अधिनियम का अधिनियमन
(C) 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, एलपीजी (LPG) सुधारों की शुरुआत, MRTP अधिनियम का अधिनियमन, FRBM अधिनियम का अधिनियमन
(D) MRTP अधिनियम का अधिनियमन, एलपीजी (LPG) सुधारों की शुरुआत, 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, FRBM अधिनियम का अधिनियमन

29. हाल ही के दूसरी पीढ़ी के श्रम सुधारों के एक मुख्य घटक के रूप में, भारत सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार अलग-अलग श्रम संहितों (Labour Codes) में समेकित किया। निम्नलिखित में से कौन-सी इन चार कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संहितों में से एक नहीं है?
(A) श्रमिकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संहिता
(B) मजदूरी संहिता (Code on Wages)
(C) औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code)
(D) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code)

30. भारत की औद्योगीकरण की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था में भूमि सुधार और अधिग्रहण की समकालीन चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. डिजिटल और निर्णायक भूमि स्वामित्व प्रणाली का अभाव औद्योगिक भूमि अधिग्रहण के लिए गंभीर कानूनी बाधाएं पैदा करता है।
II. अनुमानित (Presumptive) भूमि स्वामित्व से निर्णायक (Conclusive) भूमि स्वामित्व में परिवर्तन भारत के सभी राज्यों में पूरी तरह से पूरा हो चुका है।
III. जटिल भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप अक्सर प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की लागत और समय में भारी वृद्धि होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

31. भारत के 1991 के आर्थिक पैकेज के विशिष्ट संदर्भ में, 'वैश्वीकरण' (Globalization) को प्राथमिक रूप से कार्यात्मक रूप से किस प्रकार परिभाषित किया गया था?
(A) सभी कृषि उत्पादों पर घरेलू करों को पूरी तरह से समाप्त करने की प्रक्रिया
(B) सभी घरेलू विनिर्माण निगमों के लिए न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर सूचीबद्ध करने की अनिवार्य वैधानिक आवश्यकता
(C) भारतीय रुपये को सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत वैश्विक मुद्रा से पूरी तरह बदलना
(D) व्यापारिक बाधाओं को हटाकर और पूंजी प्रवाह का उदारीकरण करके घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर एकीकृत करना

32. 1991 के सुधारों के बाद, भारत सरकार ने उच्चतम सीमा शुल्क (Peak Customs Tariffs) को व्यवस्थित रूप से कम करने का मार्ग अपनाया। यह विशिष्ट व्यापार उदारीकरण नीति काफी हद तक किसकी सिफारिशों से निर्देशित थी?
(A) केलकर टास्क फोर्स
(B) रंगराजन आयोग
(C) चेलैया समिति
(D) शांता कुमार समिति

33. निम्नलिखित में से किसे भारत में 1991 के बाद के संवृद्धि मॉडल का एक नकारात्मक, अनपेक्षित परिणाम माना जाता है, जिसे अक्सर 'गैर-समावेशी संवृद्धि' (Non-inclusive growth) की चुनौती के तहत वर्गीकृत किया जाता है?
(A) सभी प्रमुख राज्यों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अत्यधिक निरपेक्ष गरीबी दरों में तीव्र और अभूतपूर्व वृद्धि
(B) न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा वाले 80% से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले एक बड़े अनौपचारिक क्षेत्र का बना रहना
(C) घरेलू आधुनिक सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से उच्च-वृद्धि वाले सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार का पूर्ण संरचनात्मक पतन
(D) राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा भंडार में 1990 में देखे गए गंभीर संकट के स्तर से नीचे तीव्र और निरंतर कमी

Downloaded from www.pdf.tube

(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

61. श्रम नियमों के हालिया पुनर्गठन में, ऐतिहासिक ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को किस नई श्रम संहिता के तहत समाहित किया गया है?
(A) औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code)
(B) सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security)
(C) मजदूरी संहिता (Code on Wages)
(D) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code)

62. केंद्रीय बजट के राजकोषीय घटकों का विश्लेषण करते समय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री के माध्यम से उत्पन्न विनिवेश प्राप्तियों को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है?
(A) कर राजस्व प्राप्तियां
(B) गैर-कर राजस्व प्राप्तियां
(C) पूंजीगत प्राप्तियां
(D) राजस्व व्यय

63. केवल आर्थिक संवृद्धि से 'समावेशी संवृद्धि' (Inclusive Growth) की ओर बढ़ने की चुनौती किस पंचवर्षीय योजना के आधिकारिक समष्टि आर्थिक नीति दस्तावेज़ में एक केंद्रीय, स्पष्ट रूप से घोषित उद्देश्य बन गई?
(A) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990)
(B) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997)
(C) प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956)
(D) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)

64. सुधारों के बाद की क्षेत्रीय आर्थिक असमानता एक मान्यता प्राप्त संरचनात्मक मुद्दा है। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने 1991 के बाद के निजी औद्योगिक निवेश के बड़े हिस्से को आकर्षित किया। इस विशिष्ट क्षेत्रीय लाभ के लिए निम्नलिखित में से किसे सबसे कम महत्वपूर्ण कारण माना जाता है?
(A) कार्यात्मक समुद्री बंदरगाहों और विद्युत आपूर्ति सहित श्रेष्ठ भौतिक अवसंरचना
(B) अपेक्षाकृत बेहतर कुशल शहरी कार्यबल और पूर्व-मौजूद औद्योगिक क्लस्टर
(C) सिंधु-गंगा के मैदान की तुलना में कृषि उत्पादन में पूर्ण समानता
(D) अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण को सुविधाजनक बनाने वाले वैश्विक समुद्री मार्गों से निकटता

NODIA

65. सूची I में विशेषज्ञ समितियों को सूची II में 1991 के बाद मुख्य रूप से उनके द्वारा संबोधित आर्थिक सुधार के विशिष्ट क्षेत्र से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (विशेषज्ञ समिति)
P. राजा चेलैया समिति
Q. एम. नरसिम्हम समिति
R. सी. रंगराजन समिति
S. ओंकार गोस्वामी समिति
सूची II: (आर्थिक सुधार का क्षेत्र)
1. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश
2. वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र के सुधार
3. व्यापक कर सुधार
4. औद्योगिक रुग्णता और कॉर्पोरेट पुनर्गठन
निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित है?
(A) P-3, Q-2, R-1, S-4
(B) P-2, Q-3, R-4, S-1
(C) P-3, Q-2, R-4, S-1
(D) P-1, Q-4, R-2, S-3

66. 1991 के व्यापक औद्योगिक लाइसेंसिंग उन्मूलन के बाद, रणनीतिक आधार पर केवल कुछ ही क्षेत्रों को विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया था। 1991 की नीति के तुरंत बाद सरकार के लिए सख्ती से आरक्षित रहे दो क्षेत्रों की सही पहचान निम्नलिखित में से कौन करता है?
(A) नागरिक उड्डयन और दूरसंचार
(B) वाणिज्यिक बैंकिंग और भारी मशीनरी
(C) कोयला खनन और ऑटोमोबाइल विनिर्माण
(D) परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन

67. आयात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा पर भौतिक सीमाएँ, जिन्हें परिमाणात्मक प्रतिबंध (QRs) के रूप में जाना जाता है, भारत की उदारीकरण-पूर्व अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता थीं। डब्ल्यूटीओ (WTO) के एक फैसले के बाद, भारत ने किस वर्ष सभी शेष वस्तुओं (मुख्य रूप से उपभोग्य वस्तुओं और कृषि उत्पादों) पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से पूरी की?
(A) 1991
(B) 1995
(C) 2001
(D) 2014

68. आर्थिक नियोजन में 'निरपेक्ष गरीबी' (Absolute Poverty) और 'सापेक्ष गरीबी' (Relative Poverty) के बीच का अंतर मूलभूत है। निरपेक्ष गरीबी को सबसे अच्छे रूप में किस प्रकार परिभाषित किया गया है?
(A) एक सापेक्ष आर्थिक स्थिति जहाँ किसी व्यक्ति के परिवार की आय राष्ट्रीय औसत आय स्तर से काफी कम बनी रहती है
(B) नागरिकों के सबसे अमीर दसवें हिस्से (डेसाइल) और सबसे गरीब दसवें हिस्से के बीच मापी गई धन वितरण में संरचनात्मक असमानता की मात्रा

को सकल घरेलू उत्पाद के निश्चित प्रतिशत तक सीमित करने के वैधानिक लक्ष्य निर्धारित किए।

40. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मुद्रास्फीति को अक्सर अर्थशास्त्रियों द्वारा एक अत्यधिक प्रतिगामी कर के रूप में वर्णित किया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि मुद्रास्फीति देश में रखी मुद्रा और निश्चित आय की वास्तविक क्रय शक्ति को लगातार कम करती है। चूंकि कम आय वाले निर्धन वर्गों की मजदूरी मूल्य वृद्धि के साथ समायोजित नहीं होती, इसलिए उन पर अत्यधिक असमान बोझ पड़ता है।

41. (D) ग्रामीण परिवारों को अकुशल शारीरिक कार्य में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देना
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत में ग्रामीण निर्धनता और बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए शुरू की गई एक अधिकार-आधारित प्रमुख कल्याणकारी योजना है। यह योजना प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का कानूनी अधिकार देती है।

42. (A) निजीकरण प्रबंधन नियंत्रण को निजी हाथों में स्थानांतरित करता है, जबकि अल्पसंख्यक विनिवेश बहुसंख्यक सरकारी स्वामित्व को बनाए रखता है
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन में 'निजीकरण' और 'अल्पसंख्यक विनिवेश' के बीच मौलिक अंतर स्वामित्व और नियंत्रण का है। अल्पसंख्यक विनिवेश में सरकार सार्वजनिक उपक्रम की अल्पमत इक्विटी शेयर बेचती है, जबकि बहुसंख्यक हिस्सेदारी और प्रबंधन नियंत्रण अपने पास रखती है। इसके विपरीत, निजीकरण में बहुसंख्यक हिस्सेदारी और प्रबंधन नियंत्रण निजी संस्था को पूरी तरह से सौंप दिया जाता है।

43. (B) अधिकांश क्षेत्रों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए स्वचालित स्वीकृति की व्यवस्था
1991 के ऐतिहासिक उदारीकरण से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था एक अत्यधिक संरक्षित और विनियमित मॉडल पर आधारित थी। इस पूर्व-सुधार व्यवस्था में अधिकांश क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 100 प्रतिशत स्वचालित स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं था; इसके स्थान पर विदेशी पूंजी पर कठोर प्रतिबंध लागू थे। उदारीकरण के बाद ही स्वचालित स्वीकृति मार्ग स्थापित किया गया था।

44. (B) रोजगारहीन वृद्धि — उच्च रोजगार लोच के साथ उच्च जीडीपी वृद्धि
समष्टि आर्थिक अवधारणाओं के संदर्भ में रोजगारहीन वृद्धि का अर्थ उच्च जीडीपी वृद्धि दर के साथ उच्च रोजगार लोच का होना नहीं है, बल्कि यह इसके ठीक विपरीत स्थिति को दर्शाता है। रोजगारहीन वृद्धि उस स्थिति को निरुपित करती है जहाँ सकल घरेलू उत्पाद में तो वृद्धि होती है, परंतु रोजगार सृज़न की दर अत्यंत निम्न बनी रहती है।

45. (A) P-2, Q-3, R-4, S-1
1991 के बाद भारत में नीतिगत सुधारों का सही सुमेलन इस प्रकार है: उदारीकरण के तहत आयात कोटा या परिमाणात्मक प्रतिबंधों को मुक्त व्यापार हेतु चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया। पुराने एमआरटीपी अधिनियम के स्थान पर बाज़ार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु प्रतिस्पर्धा अधिनियम लाया गया। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) को फेमा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और औद्योगिक लाइसेंसिंग को केवल एक छोटी ऋणात्मक सूची तक सीमित कर समाप्त किया गया।

46. (C) उच्चतम शुल्क 1991 में 150% से अधिक से घटाकर 2000 के दशक के उत्तरार्ध तक लगभग 10% कर दिया गया था
1991 के बाद व्यापार उदारीकरण के क्रियान्वयन के अंतर्गत भारत सरकार ने अपनी आयात शुल्क संरचना में क्रांतिकारी बदलाव किया। 1991 से पूर्व भारत में गैर-कृषि आयातों पर उच्चतम सीमा शुल्क 150 प्रतिशत से अधिक की अत्यधिक उच्च दरों पर लागू था। सिफारिशों के अनुरूप सरकार ने दरों में कटौती की, जिससे यह घटकर लगभग 10 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गया।

47. (D) कोर मुद्रास्फीति अंतर्निहित मूल्य प्रवृत्तियों को पकड़ने के लिए अस्थिर खाद्य और ऊर्जा कीमतों को शामिल नहीं करती है (बाहर रखती है)
समष्टि अर्थशास्त्र में मौद्रिक नीति का संचालन करते समय केंद्रीय बैंक मुख्य रूप से 'कोर मुद्रास्फीति' पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कोर मुद्रास्फीति और हेडलाइन मुद्रास्फीति के बीच मुख्य अंतर यह है कि कोर मुद्रास्फीति से खाद्य और ऊर्जा जैसे अत्यधिक अस्थिर घटकों को बाहर रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अंतर्निहित मूल्य प्रवृत्तियों को सटीक रूप से मापा जा सके।

48. (C) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) - संयुक्त
भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2014 में उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर अपने मौद्रिक नीति ढांचे में एक महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन किया। इससे पूर्व केंद्रीय बैंक निर्णय लेने के लिए थोक मूल्य सूचकांक (WPI) को अपना प्राथमिक एंकर मानता था। परंतु इस सुधार के बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-संयुक्त) को भारत में प्राथमिक मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण एंकर और मौद्रिक नीति संचालन के आधिकारिक मापदंड के रूप में अपनाया गया है।

49. (B) भारत अपने कच्चे तेल का 80-85% आयात करता है, इसलिए उच्च लागत परिवहन और विनिर्माण क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डालती है
भारत की समष्टि आर्थिक स्थिरता अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से अत्यधिक प्रभावित होती है। इसका कारण यह है कि भारत अपनी कुल घरेलू खपत का लगभग 80 से 85 प्रतिशत हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। जब तेल के दाम बढ़ते हैं, तो आयात बिल बढ़ता

Click Here to Buy book on Flipkart

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from
PRINTED BOOKS has up to
4× HIGHER RETENTION
than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

परिस्थिति में ट्रेड यूनियन बनाने या हड़ताल करने का अधिकार पूरी तरह से छीन लेती हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सुधार के औचित्य और विशेषताओं का सही प्रतिनिधित्व करते हैं?

(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

76. एक मुद्रास्फीतिकारी समष्टि आर्थिक माहौल में, 'राजकोषीय खिंचाव' (Fiscal Drag) के रूप में जानी जाने वाली परिघटना किसे संदर्भित करती है?

(A) सकल मांग को दबाने और आर्थिक वृद्धि को धीमा करने के लिए सरकार द्वारा सार्वजनिक अवसंरचना निवेश परियोजनाओं को जानबूझकर रोकना
(B) मुद्रास्फीति के अनुरूप नाममात्र मजदूरी में वृद्धि के कारण करदाताओं का उच्च कर स्लैब में प्रवेश करना, जिससे वास्तविक कर बोझ बढ़ता है
(C) खुले बाज़ार में दीर्घकालिक सरकारी बांड बेचकर वाणिज्यिक बैंकों से मौद्रिक तरलता को आक्रामक रूप से निकालने वाला केंद्रीय बैंक
(D) उच्च कॉर्पोरेट कर दरों के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में निरंतर गिरावट

77. निम्नलिखित में से कौन-सा परिदृश्य 'स्टैगफ्लेशन' (Stagflation / मुद्रास्फीतिजनित मंदी) के रूप में जानी जाने वाली जटिल आर्थिक स्थिति को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है?

(A) उच्च मुद्रास्फीति के साथ-साथ होने वाली लंबी आर्थिक मंदी और उच्च बेरोजगारी की अवधि
(B) अति-मुद्रास्फीति (Hyperinflation) के साथ उच्च, तीव्र आर्थिक वृद्धि की विशेषता वाली अवधि
(C) एक ऐसी आर्थिक स्थिति जहाँ रोजगार बढ़ने के साथ-साथ कीमतें लगातार गिर रही हों
(D) एक ऐसी राजकोषीय स्थिति जहाँ सरकार भारी बजट अधिशेष बनाए रखती है जबकि निजी उद्यम क्षेत्र गंभीर मंदी से गुज़रता है

78. निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें:

कथन (A): निर्णायक (Conclusive) भूमि स्वामित्व प्राप्त करना भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा माना जाता है।

कारण (R): स्पष्ट, कानूनी रूप से अकाट्य भूमि शीर्षक किसानों को सस्ते औपचारिक संस्थागत ऋण तक पहुँचने के लिए अपनी भूमि को संपार्श्विक (Collateral) के रूप में आसानी से उपयोग करने की अनुमति देते हैं, जिससे अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भरता कम होती है।

(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

79. भुगतान संतुलन संकट के प्रति किसी देश की संवेदनशीलता का आकलन करते समय, अर्थशास्त्री इसके विदेशी मुद्रा भंडार की निगरानी करते हैं। भारत में, इन भंडारों में पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से कौन-से घटक शामिल हैं?

(A) केवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (Foreign Currency Assets)
(B) विशेष रूप से घरेलू रुपये के मुद्रा नोटों और वाणिज्यिक बैंक भंडारों के साथ संयुक्त विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां
(C) केवल स्वर्ण भंडार और घरेलू संप्रभु बांड
(D) विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, एसडीआर (SDRs) और आईएमएफ (IMF) रिजर्व ट्रेंच स्थिति

80. सूची I में समष्टि आर्थिक घाटे की अवधारणाओं को सूची II में उनके विवरणों से सुमेलित कीजिए:

सूची I: (घाटे की अवधारणा)

P. राजकोषीय घाटा
Q. राजस्व घाटा
R. प्राथमिक घाटा
S. मौद्रीकृत घाटा

सूची II: (विवरण)

1. कुल राजस्व व्यय घटाव कुल राजस्व प्राप्तियां
2. उधारों को छोड़कर कुल व्यय घटाव कुल प्राप्तियां
3. राजकोषीय घाटा घटाव अतीत के ऋणों पर ब्याज भुगतान
4. राजकोषीय घाटे का वह हिस्सा जो केंद्रीय बैंक द्वारा नए पैसे छापकर वित्तपोषित किया जाता है

निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित है?

(A) P-2, Q-1, R-3, S-4
(B) P-1, Q-2, R-4, S-3
(C) P-2, Q-3, R-1, S-4
(D) P-3, Q-1, R-2, S-4

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) श्रमिकों के पास मौजूद कौशल और आधुनिक उद्योगों द्वारा माँगी जाने वाली कौशल आवश्यकताओं के बीच मूलभूत बेमेल के कारण उत्पन्न बेरोजगारी
संरचनात्मक बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब श्रम बाज़ार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल और नियोक्ताओं द्वारा माँगी जाने वाली योग्यताओं के बीच गहरा असंतुलन होता है। यह स्थिति प्रायः तकनीकी परिवर्तन, औद्योगिक पुनर्गठन या अर्थशास्त्र में दीर्घकालिक बदलावों के कारण उत्पन्न होती है। इसमें अर्थव्यवस्था में नौकरियाँ तो उपलब्ध होती हैं, परंतु श्रमिकों के पास उपयुक्त प्रशिक्षण और प्रासंगिक दक्षता न होने से वे लंबे समय तक बेरोजगार बने रहते हैं।

2. (D) आधिकारिक तौर पर परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत
हेडकाउंट अनुपात गरीबी मापने का एक प्रमुख सांख्यिकीय सूचकांक है। यह किसी देश या क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उन व्यक्तियों के प्रतिशत को दर्शाता है जिनकी आय या उपभोग व्यय निर्धारित आधिकारिक गरीबी रेखा से नीचे होता है। यह सूचकांक नीति निर्माताओं को समाज में निरपेक्ष निर्धनता के फैलाव और प्रसार की सीमा का आकलन करने में सहायता करता है। यह निर्धनता की तीव्र भयावहता और व्यापकता को सरलता से प्रदर्शित करता है।

3. (A) ऐसी स्थिति जहाँ सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में तेज़ी से वृद्धि होती है, लेकिन रोजगार सृजन की दर स्थिर या आनुपातिक रूप से अत्यंत कम बनी रहती है
रोजगारहीन वृद्धि उस आर्थिक स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पादन में तो उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जाती है, परंतु उसके अनुपात में नए रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं होता है। यह परिघटना तब घटित होती है जब आर्थिक वृद्धि मुख्य रूप से पूंजी-गहन तकनीकों, स्वचालन और उत्पादकता में वृद्धि से संचालित होती है, जिससे श्रम की माँग सीमित हो जाती है और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बनी रहती है।

4. (C) गरीबी रेखा के आधार को केवल कैलोरी सेवन से हटाकर एक व्यापक उपभोग बास्केट पर केंद्रित करना, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय शामिल हैं
तेंदुलकर समिति ने वर्ष 2009 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भारत में निर्धनता आकलन की पुरानी विधि में व्यापक बदलाव किया। समिति ने केवल न्यूनतम कैलोरी सेवन पर आधारित दृष्टिकोण को खारिज कर दिया और उपभोग बास्केट में स्वास्थ्य, शिक्षा, वस्त्र तथा प्रकाश जैसे आवश्यक गैर-खाद्य मदों पर होने वाले निजी व्यय को शामिल किया। इस पद्धति ने गरीबी रेखा को अधिक यथार्थवादी और समकालीन जीवन स्तर के अनुकूल बनाने का प्रयास किया।

5. (A) अलघ समिति, लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति
भारत में गरीबी आकलन के लिए गठित विशेषज्ञ समितियों का सही ऐतिहासिक क्रम अलघ समिति, लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति है। वाई. के. अलघ समिति का गठन 1979 में न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता निर्धारित करने के लिए हुआ था। इसके पश्चात 1993 में लकड़ावाला समिति, 2009 में तेंदुलकर समिति और 2014 में सी. रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिन्होंने उपभोग बास्केट को निरंतर अद्यतन किया।

6. (D) भू-राजनीतिक संघर्ष के कारण वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति में बड़े पैमाने पर आए व्यवधान से घरेलू मुद्रास्फीति में हुई अचानक वृद्धि
पूर्ति-आघात मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में किसी महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति अचानक बाधित होती है या उसकी उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हो जाती है। जब वैश्विक घटनाओं या भू-राजनीतिक तनावों के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति रुकती है, तो परिवहन और उत्पादन लागत तेज़ी से बढ़ जाती है। लागत में यह वृद्धि अंततः अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा देती है और समग्र मुद्रास्फीति को जन्म देती है।

7. (B) जब वस्तुओं और सेवाओं की सकल मांग अर्थव्यवस्था की सकल उत्पादन क्षमता से अधिक हो जाती है
मांग-जनित मुद्रास्फीति उस आर्थिक स्थिति को दर्शाती है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल माँग उपलब्ध कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है। जब उपभोक्ता, व्यवसाय और सरकार मिलकर देश की पूर्ण उत्पादन क्षमता से अधिक खरीद का प्रयास करते हैं, तो अत्यधिक धन सीमित वस्तुओं का पीछा करता है। इसके परिणामस्वरूप विक्रेता कीमतों में वृद्धि करते हैं, जिससे सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर उछाल आता है।

8. (C) आवश्यक आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पन्न मुद्रास्फीति, जो अक्सर घरेलू मुद्रा के मूल्यह्रास से और बढ़ जाती है
आयातित मुद्रास्फीति तब होती है जब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में आवश्यक वस्तुओं, जैसे कच्चे तेल या घटकों, के दामों में वृद्धि के कारण घरेलू बाज़ार में मूल्य स्तर बढ़ जाता है। जब विदेशी वस्तुओं का आयात महँगा हो जाता है अथवा घरेलू मुद्रा का विनिमय मूल्य गिरता है, तो आयातित वस्तुओं को खरीदने के लिए अधिक स्थानीय मुद्रा चुकानी पड़ती है। इससे देश के भीतर समग्र विनिर्माण एवं उपभोग लागत बढ़ जाती है।

NODIA

9. (D) क्योंकि गरीब परिवारों की आय का एक बड़ा हिस्सा आवश्यक उपभोग्य वस्तुओं पर खर्च होता है, और उनकी नाममात्र (Nominal) आय पूर्ण रूप से मुद्रास्फीति के साथ समायोजित नहीं होती है
मुद्रास्फीति को एक प्रतिगामी कर माना जाता है क्योंकि यह समाज के निर्धन वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करती है। गरीब परिवार अपनी कुल आय का अधिकांश भाग भोजन और ईंधन जैसी अत्यंत आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करते हैं। इसके अतिरिक्त, उनकी नाममात्र आय में कीमतों की दर से वृद्धि नहीं होती है। नतीजतन, मुद्रास्फीति उनकी वास्तविक क्रय शक्ति को तेजी से क्षीण करती है, जबकि धनवानों की परिसंपत्तियाँ मूल्य वृद्धि से सुरक्षित रहती हैं।

10. (A) केवल I और II
भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक गरीबी मुख्य रूप से परिसंपत्तियों के असंतुलित वितरण, शिक्षा और कौशल के अभाव जैसी दीर्घकालिक प्रणालीगत बाधाओं का परिणाम है। इस प्रकार की गरीबी केवल अल्पकालिक राजकोषीय सहायता या मौद्रिक राहत से दूर नहीं की जा सकती, इसके लिए गहरे संस्थागत सुधारों की आवश्यकता होती है। यद्यपि 1991 के बाद आर्थिक सुधार लागू किए गए, परंतु वे ग्रामीण क्षेत्रों से संरचनात्मक गरीबी को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाए।

11. (A) 3 सप्ताह से भी कम
वर्ष 1991 के मध्य में भारत को अभूतपूर्व समष्टि आर्थिक एवं भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा। खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि और घटते प्रेषण के कारण भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर लगभग 1.2 बिलियन डॉलर रह गया था। यह संचित विदेशी भंडार केवल 3 सप्ताह से भी कम समय के आवश्यक आयातों के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त था, जिससे संप्रभु चूक का संकट मंडराने लगा था।

12. (A) I, II, III, IV
1991 के आर्थिक संकट से जुड़ी घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है: सबसे पहले 1990 में खाड़ी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में तीव्र उछाल आया। इसके पश्चात मई 1991 में आपातकालीन विदेशी मुद्रा जुटाने हेतु भारत ने अपना स्वर्ण भंडार इंग्लैंड और जापान के पास गिरवी रखा। तत्पश्चात जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति घोषित की गई और अंततः अंतर्राष्ट्रीय ऋण मिला।

13. (A) भारत के अल्पकालिक बाहरी ऋण दायित्वों पर संप्रभु चूक (Sovereign Default)
मई-जून 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अत्यधिक निम्न स्तर पर पहुँच गया था, जिससे देश के पास अपने अल्पकालिक बाहरी ऋण दायित्वों के पुनर्भुगतान और आवश्यक आयातों के भुगतान के लिए पर्याप्त धन नहीं बचा था। संप्रभु चूक के विनाशकारी आर्थिक संकट से बचने और वैश्विक बाज़ारों में अपनी वित्तीय विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सरकार ने स्वर्ण भंडार गिरवी रखकर तरलता जुटाई।

14. (C) अपने निर्यात की तुलना में अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आयात कर रहा है, तथा घरेलू व्यय को वित्तपोषित करने के लिए विदेशी बचत का उपयोग कर रहा है
समष्टि आर्थिक लेखांकन में चालू खाता घाटा तब होता है जब किसी देश द्वारा वस्तुओं, सेवाओं और अंतरणों का कुल आयात उसके कुल निर्यात से अधिक हो जाता है। निरंतर चालू खाता घाटा यह दर्शाता है कि वह देश अपनी कुल राष्ट्रीय आय से अधिक व्यय कर रहा है। इस अंतर को पूरा करने के लिए देश को विदेशी बचत पर निर्भर रहना पड़ता है।

15. (B) केवल I, III और IV
1991 के संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने सहायता ऋण के बदले भारत पर व्यापक संरचनात्मक समायोजन शर्तें लागू की थीं। इनमें व्यापार को बढ़ावा देने हेतु सीमा शुल्क दरों में कटौती करना, निर्यात बढ़ाने हेतु रुपये का तीव्र अवमूल्यन करना और विनिर्माण हेतु औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था समाप्त करना शामिल था। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना था।

16. (C) वे उद्योग सुरक्षा, रणनीतिक चिंताओं, खतरनाक रसायनों और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित थे
1991 के औद्योगिक सुधारों में अधिकांश उद्योगों को लाइसेंसिंग से मुक्त किया गया, परंतु कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को लाइसेंसिंग की ऋणात्मक सूची में बनाए रखा गया। इसका मुख्य कारण राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक प्राथमिकताओं, खतरनाक रसायनों के विनियमन और पर्यावरण संतुलन की रक्षा करना था। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि सुरक्षा और जनस्वास्थ्य से जुड़े पहलू पूरी तरह संरक्षित रहें।

17. (B) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
उदारीकरण के बाद के दौर में मुक्त बाज़ार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और अनुचित व्यापार पद्धतियों को रोकने के लिए पुराने एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार (MRTP) अधिनियम, 1969 को निरस्त कर दिया गया। इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 पारित किया गया, जिसने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की। इस नए कानून का उद्देश्य बाज़ार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।

18. (D) नरसिम्हम समिति
1991 के आर्थिक संकट के बाद भारत के वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के लिए एम. नरसिम्हम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के आधार पर ही बैंकिंग प्रणाली में जमा एवं ऋण ब्याज दरों को नियंत्रणमुक्त किया गया, आरक्षित अनुपातों में कटौती की गई और निजी तथा विदेशी बैंकों को प्रवेश की अनुमति दी गई।

19. (A) स्थिरीकरण अल्पकालिक भुगतान संतुलन और मुद्रास्फीति को संबोधित करता है, जबकि संरचनात्मक समायोजन दीर्घकालिक आर्थिक दक्षता में सुधार करता है
1991 के सुधारों में समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण उपाय अल्पकालिक नीतियां थीं जिनका उद्देश्य तात्कालिक भुगतान

Click Here to Buy book on Amazon

संतुलन संकट को दूर करना, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना था। इसके विपरीत, संरचनात्मक समायोजन उपाय दीर्घकालिक नीतियां थीं जिनका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था की समग्र दक्षता में सुधार करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और व्यापार, उद्योग तथा वित्तीय क्षेत्रों का व्यापक उदारीकरण करना था।

20. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
1991 के भुगतान संतुलन संकट के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता और ऋण प्राप्त करने के लिए बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं से संपर्क किया था। ये संस्थाएं विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करते समय कड़े समष्टि आर्थिक नीतिगत दिशानिर्देश लागू करती हैं। इन शर्तों का मुख्य उद्देश्य उधारकर्ता देश में राजकोषीय अनुशासन स्थापित करना, संरचनात्मक कमियों को दूर करना और ऋण पुनर्भुगतान सुनिश्चित करना होता है।

21. (A) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और पोर्टफोलियो इक्विटी प्रवाह
1991 के सुधारों के बाद भारत ने अपने चालू खाता घाटे का वित्तपोषण करने के लिए विदेशी ऋणों पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को कम किया। इसके स्थान पर देश ने गैर-ऋण सृजनकारी पूंजी प्रवाहों को प्राथमिकता दी, जिनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो इक्विटी निवेश प्रमुख हैं। ये प्रवाह देश के संप्रभु ऋण दायित्वों को बढ़ाए बिना तरलता प्रदान करते हैं।

22. (D) साधन बाज़ार (Factor Markets), विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण, श्रम कानून और पूंजी बाज़ार
भारतीय अर्थव्यवस्था में "दूसरी पीढ़ी के सुधार" उन गहरी संरचनात्मक नीतिगत पहलों को संदर्भित करते हैं जो साधन बाज़ारों के पुनर्गठन पर केंद्रित हैं। जहाँ 1991 के पहली पीढ़ी के सुधारों ने मुख्य रूप से व्यापार और औद्योगिक लाइसेंसिंग पर ध्यान केंद्रित किया था, वहीं दूसरी पीढ़ी के सुधारों का लक्ष्य भूमि अधिग्रहण, श्रम विधानों और कृषि बाज़ारों को आधुनिक बनाना है।

23. (B) रणनीतिक विनिवेश में एक निजी संस्था को प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ पर्याप्त सरकारी शेयरधारिता की बिक्री शामिल है
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में, रणनीतिक विनिवेश सामान्य या सांकेतिक विनिवेश से मूलभूत रूप से भिन्न है। सांकेतिक विनिवेश में सरकार केवल अपनी अल्पमत हिस्सेदारी बाज़ार में बेचती है और स्वामित्व तथा प्रबंधन नियंत्रण अपने पास बनाए रखती है। इसके विपरीत, रणनीतिक विनिवेश में सरकार अपनी बहुसंख्यक हिस्सेदारी बेचने के साथ-साथ प्रबंधन नियंत्रण भी निजी भागीदार को हस्तांतरित कर देती है।

24. (C) मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
1991 के सुधारों के बाद भारत में किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरित होने का पहला रणनीतिक निजीकरण मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का था। वर्ष 2000 में सरकार ने इस कंपनी में अपनी 74% हिस्सेदारी और प्रबंधन नियंत्रण निजी कंपनी को बेच दिया था। बाद में बची हुई शेष हिस्सेदारी भी हस्तांतरित कर दी गई थी।

NODIA

25. (A) P-2, Q-4, R-3, S-1
निजीकरण संबंधी अवधारणाओं का सही सुमेलन इस प्रकार है: सांकेतिक विनिवेश में सरकार प्रबंधन नियंत्रण छोड़े बिना केवल राजकोषीय राजस्व प्राप्त करने के लिए अपनी अल्पमत हिस्सेदारी बेचती है। रणनीतिक विनिवेश में बहुसंख्यक हिस्सेदारी के साथ प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरित किया जाता है। स्वर्णिम शेयर सरकार को निर्णयों पर वीटो शक्ति प्रदान करता है, और राष्ट्रीयकरण निजी संपत्तियों को सार्वजनिक स्वामित्व में लाता है।

26. (A) इसने घाटे में चल रहे विमानन क्षेत्र से सरकार के पूर्ण निकास (Exit) को चिह्नित किया
वर्ष 2021 में एयर इंडिया का टाटा समूह को रणनीतिक हस्तांतरण भारत की नई निजीकरण नीति का एक प्रमुख उदाहरण था। यह घटना इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने निरंतर भारी वित्तीय घाटे में चल रही एयरलाइन से सरकार के पूर्ण निकास को चिह्नित किया। इससे गैर-रणनीतिक क्षेत्रों से सरकार की व्यावसायिक उपस्थिति समाप्त करने की प्रतिबद्धता सिद्ध हुई।

27. (B) FDI में दीर्घकालिक भौतिक संपत्ति का निर्माण और प्रबंधन नियंत्रण शामिल है, जबकि FII में अल्पकालिक बाज़ार निवेश शामिल है
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश के बीच मुख्य अंतर उनकी प्रकृति और नियंत्रण में है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में किसी देश की भौतिक संपत्तियों, कारखानों या व्यवसायों में दीर्घकालिक पूंजी लगाई जाती है और प्रबंधन नियंत्रण प्राप्त होता है। इसके विपरीत, विदेशी संस्थागत निवेश मुख्य रूप से शेयर और बांड खरीदने हेतु किया जाने वाला अल्पकालिक पोर्टफोलियो निवेश है।

28. (B) MRTP अधिनियम का अधिनियमन, 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, एलपीजी (LPG) सुधारों की शुरुआत, FRBM अधिनियम का अधिनियमन
भारत के ऐतिहासिक समष्टि आर्थिक नीतिगत बदलावों का सही कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है: सबसे पहले 1969 के प्रारंभ में एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम पारित हुआ। इसके पश्चात जुलाई 1969 में 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तत्पश्चात जुलाई 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों की शुरुआत हुई, और अंततः 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया।

29. (A) श्रमिकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संहिता
भारत सरकार ने व्यापार सुगमता और श्रमिकों के कल्याण को संतुलित करने के लिए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। ये चार मान्यता प्राप्त संहिताओं

हैं: मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य स्थिति संहिता। शैक्षणिक योग्यता संबंधी कोई संहिता इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है।

30. (B) केवल I और III
भारत में औद्योगिक विकास और अवसंरचना निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसका मुख्य कारण एक स्पष्ट और निर्णायक डिजिटल भूमि स्वामित्व प्रणाली का अभाव है, जिससे कई कानूनी विवाद उत्पन्न होते हैं। इन जटिल भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं के कारण परियोजनाओं में देरी होती है और उनकी लागत अत्यधिक बढ़ जाती है। अभी यह प्रणाली पूर्ण नहीं हुई है।

31. (D) व्यापारिक बाधाओं को हटाकर और पूंजी प्रवाह का उदारीकरण करके घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर एकीकृत करना
1991 के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में 'वैश्वीकरण' से तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था का शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ संरचनात्मक एकीकरण से है। इसके कार्यान्वियन हेतु सरकार ने आयात शुल्कों में भारी कटौती की, परिमाणात्मक आयात प्रतिबंधों को समाप्त किया तथा प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो विदेशी पूंजी निवेश का उदारीकरण किया। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जोड़ना था।

32. (C) चेलैया समिति
1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की कर संरचना को आधुनिक बनाने और व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देने में राजा जे. चेलैया समिति ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी। चेलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर ही भारत सरकार ने गैर-कृषि आयातों पर उच्चतम सीमा शुल्क दरों को घटाकर उत्तरोत्तर कम करने और करों को सुव्यवस्थित करने की नीति अपनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था।

33. (B) न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा वाले 80% से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले एक बड़े अनौपचारिक क्षेत्र का बना रहना
1991 के बाद भारत ने तेजी से आर्थिक वृद्धि हासिल की, परंतु इस संवृद्धि मॉडल का एक प्रमुख नकारात्मक परिणाम 'गैर-समावेशी संवृद्धि' के रूप में सामने आया। सेवा क्षेत्र में तीव्र विकास के बावजूद, विनिर्माण क्षेत्र पर्याप्त औपचारिक नौकरियां पैदा करने में विफल रहा। नतीजतन, देश का 80 प्रतिशत से अधिक कार्यबल बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता रहा।

34. (D) तटीय राज्यों में बेहतर बंदरगाह और मानव पूंजी उपलब्ध थी, जिससे वे निर्यात वृद्धि और आईटी (IT) सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम हुए
1991 के उदारीकरण के पश्चात भारत में क्षेत्रीय आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों ने अन्य राज्यों की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास आकर्षित किया। इसका मुख्य कारण यह था कि तटीय राज्यों के पास पहले से ही बेहतर समुद्री बंदरगाह, मजबूत अवसंरचना और कुशल मानव पूंजी बहुतायत में उपलब्ध थी।

35. (B) केवल I, II और IV
समावेशी संवृद्धि एक ऐसा समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण है जो यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित समूहों, तक समतापूर्ण रूप से पहुँचें। उच्च संरचनात्मक बेरोजगारी समावेशी वृद्धि में बाधा डालती है क्योंकि यह बड़ी आबादी को बाहर रखती है। इसलिए, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा का विस्तार करना इसके अनिवार्य प्राथमिक स्तंभ हैं।

36. (C) सरकार का कुल व्यय उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक हो जाता है
समष्टि आर्थिक ढांचे में राजकोषीय घाटा किसी वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल उधारी आवश्यकता का एक प्रमुख संकेतक है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सरकार का कुल बजटीय व्यय उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों (जैसे ऋणों की वसूली और विनिवेश) के योग से अधिक हो जाता है। इस वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को बाज़ार से ऋण लेना पड़ता है।

37. (A) तृतीयक सेवा क्षेत्र
1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पथ में एक अनूठा परिवर्तन देखा गया। पारंपरिक रूप से औद्योगिक चरण से गुज़रने के स्थान पर, भारत ने कृषि से सीधे तृतीयक सेवा क्षेत्र की ओर तीव्र रुपांतरण किया। सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण आज तृतीयक सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा और प्रमुख योगदानकर्ता क्षेत्र बन गया है।

38. (D) गैर-ऋण सृजनकारी पूंजीगत प्राप्तियां (Non-debt creating Capital Receipts)
सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी या परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि को केंद्रीय बजट में 'गैर-ऋण सृजनकारी पूंजीगत प्राप्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये प्राप्तियां पूंजीगत श्रेणी में आती हैं क्योंकि ये सरकार की वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं। चूंकि इन प्राप्तियों के माध्यम से भविष्य का कोई ऋण या पुनर्भुगतान दायित्व पैदा नहीं होता, इसलिए इन्हें गैर-ऋण प्राप्ति मानते हैं।

39. (B) आर्थिक स्थिरता को खतरा पहुँचाने वाले उच्च राजकोषीय और राजस्व घाटे
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2003 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका प्राथमिक समष्टि आर्थिक उद्देश्य देश में संस्थागत राजकोषीय अनुशासन स्थापित करना, निरंतर बने रहने वाले उच्च राजकोषीय और राजस्व घाटों को नियंत्रित करना तथा दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना था। इस कानून ने केंद्र सरकार के लिए राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण

Downloaded from www.pdf.tube

60. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारत में आर्थिक नीतियों के विश्लेषण से पता चलता है कि 1991 के पहली पीढ़ी के सुधारों ने मुख्य रूप से उत्पाद बाज़ारों और व्यापार का उदारीकरण किया था। हालांकि, उत्पादन के साधनों, विशेष रूप से भूमि और श्रम से जुड़े ढांचे अछूते रह गए। यही कारण है कि दूसरी पीढ़ी के सुधारों में साधन बाज़ारों पर बल दिया जा रहा है।

61. (A) औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code)
भारत सरकार द्वारा श्रम सुधारों के अंतर्गत वर्ष 2020 में पारित 'औद्योगिक संबंध संहिता, 2020' ने तीन प्रमुख ऐतिहासिक केंद्रीय श्रम अधिनियमों को अपने भीतर समेकित कर लिया है। इन समाहित अधिनियमों में ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 शामिल हैं। इसका उद्देश्य विवादों का सरलीकरण करना तथा व्यापार वातावरण को सुगम बनाना है।

62. (C) पूंजीगत प्राप्तियां
केंद्र सरकार के बजट में प्राप्तियों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों—राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां—में वर्गीकृत किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिस्सेदारी बेचने से प्राप्त होने वाली विनिवेश प्राप्तियों को 'पूंजीगत प्राप्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बजटीय लेन-देन सरकार की संपत्ति या परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी लाता है, यद्यपि इससे सरकार पर कोई नया ऋण दायित्व निर्मित नहीं होता।

63. (D) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)
भारत की राष्ट्रीय नियोजन प्रक्रिया के इतिहास में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। इस योजना का आधिकारिक शीर्षक और स्पष्ट रूप से घोषित मुख्य उद्देश्य "तीव्र और अधिक समावेशी संवृद्धि की ओर" था। इसने भारत की समष्टि आर्थिक नीति का ध्यान केवल जीडीपी वृद्धि दर से हटाकर विकास के लाभों को समाज के सभी वंचित वर्गों तक समतापूर्ण तरीके से पहुँचाने पर केंद्रित किया।

64. (C) सिंधु-गंगा के मैदान की तुलना में कृषि उत्पादन में पूर्ण समानता
1991 के सुधारों के बाद गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे तटीय राज्यों ने उत्तरी और पूर्वी भू-आबद्ध राज्यों की तुलना में अधिक औद्योगिक निवेश और उच्च विकास दर हासिल की। इस क्षेत्रीय असमानता के मुख्य कारणों में तटीय राज्यों के बंदरगाहों की उपलब्धता, बेहतर बिजली आपूर्ति, विकसित अवसंरचना और कुशल कार्यबल शामिल थे। कृषि उत्पादन की समानता इस विषमता का प्रासंगिक कारण नहीं थी।

65. (A) P-3, Q-2, R-1, S-4
भारत में 1991 के बाद के आर्थिक सुधारों को दिशा देने वाली समितियों का सही सुमेलन इस प्रकार है: राजा जे. चेलैया समिति ने व्यापक कर सुधारों की सिफारिश की थी। एम. नरसिम्हम समिति ने बैंकिंग क्षेत्र के पुनर्गठन का खाका तैयार किया। सी. रंगराजन समिति ने उपक्रमों के विनिवेश पर अपनी रिपोर्ट दी, जबकि ओंकार गोस्वामी समिति ने औद्योगिक रुग्णता का अध्ययन किया।

66. (D) परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन
जुलाई 1991 की नई औद्योगिक नीति के माध्यम से भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों को लाइसेंसिंग और सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षण से मुक्त कर दिया था। हालाँकि, रणनीतिक और सुरक्षा कारणों से केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को विशेष रूप से सरकार के लिए आरक्षित रखा गया था। ये दो प्रमुख क्षेत्र परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन थे।

NODIA

67. (C) 2001
1991 के सुधारों के पश्चात् भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए, परंतु कृषि और उपभोक्ता वस्तुओं पर आयात कोटा बने रहे। विश्व व्यापार संगठन में दर्ज एक विवाद के बाद भारत के खिलाफ फैसला आया। इसके अनुपालन में भारत सरकार ने वर्ष 2001 में सभी शेष उपभोग्य एवं कृषि वस्तुओं पर से परिमाणात्मक प्रतिबंध पूरी तरह समाप्त कर दिए।

68. (C) एक निश्चित गरीबी रेखा के सापेक्ष भोजन, जल और आश्रय जैसी बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं का अत्यधिक अभाव
आर्थिक नियोजन और निर्धनता मापन में निरपेक्ष गरीबी उस स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें किसी व्यक्ति या परिवार की आय या उपभोग व्यय इतना कम होता है कि वह जीवन जीने की न्यूनतम मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, स्वच्छ पेयजल, वस्त्र और आश्रय को पूरा करने में असमर्थ होता है। यह एक निश्चित आधिकारिक गरीबी रेखा के आधार पर मापी जाती है।

69. (A) सटीकता सुनिश्चित करने और स्वामित्व मुकदमों को कम करने वाले राज्य-गारंटीकृत भूमि शीर्षक (Land Titles)
भारत के भूमि प्रशासन में वर्तमान में 'अनुमानित' भूमि स्वामित्व प्रणाली लागू है, जहाँ भूमि विलेख केवल लेन-देन को दर्शाते हैं और संपत्ति के स्वामित्व की पूर्ण कानूनी गारंटी नहीं देते हैं। सुधारों का प्राथमिक लक्ष्य 'निर्णायक' भूमि स्वामित्व में परिवर्तन करना है। इसमें सरकार भूमि शीर्षकों की शुद्धता और स्वामित्व की राज्य-गारंटी प्रदान करती है, जिससे कानूनी भूमि विवाद पूरी तरह समाप्त होते हैं।

70. (A) केवल I और II
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम केंद्र सरकार के लिए राजकोषीय और राजस्व घाटे को कम करने हेतु स्पष्ट वैधानिक लक्ष्य निर्धारित करता है। इस कानून में 'अपवाद खंड' का भी प्रावधान शामिल है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा संकट या आपदाओं के समय सरकार को लक्ष्यों से विचलन

है, जिससे परिवहन और विनिर्माण लागत बढ़कर व्यापक आयातित मुद्रास्फीति को जन्म देती है।

50. (A) केवल I और II
1991 के बाद भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों को अत्यधिक उदार बनाया। विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए 'स्वचालित मार्ग' शुरू किया गया, जिसके तहत निवेशकों को पूर्व मंजूरी के बिना निवेश की अनुमति मिली। अन्य प्रस्तावों के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड गठित किया गया था। हालाँकि, मल्टी-ब्रांड रिटेल में स्वचालित मार्ग से 100% स्वीकृति नहीं दी गई है।

51. (A) वैश्विक ब्याज दरों में बदलाव या बाज़ार में घबराहट के कारण तेज़ी से बाहर जाने (बहिर्वाह) के प्रति संवेदनशील है
अंतर्राष्ट्रीय वित्त और अर्थव्यवस्था में विदेशी संस्थागत निवेश को अक्सर 'हॉट मनी' कहा जाता है। यह शब्द इस प्रकार के वित्तीय निवेश की अत्यधिक तरल और चंचल प्रकृति को प्रदर्शित करता है। निवेशक मुख्य रूप से शेयर बाज़ारों में अल्पकालिक लाभ के लिए पूंजी लगाते हैं। वैश्विक परिस्थितियों में परिवर्तन होते ही यह पूंजी तेज़ी से देश से बाहर बहिर्वाह कर जाती है।

52. (A) I, III, II, IV
भारत की प्रमुख कल्याणकारी और अवसंरचनात्मक योजनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है: सबसे पहले निर्धनता उन्मूलन हेतु एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) वर्ष 1978-79 में शुरु किया गया था। इसके पश्चात ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) वर्ष 2000 में शुरु हुई। तत्पश्चात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) वर्ष 2005 में लागू हुआ, और अंततः पीएम-किसान योजना वर्ष 2019 में आरंभ की गई।

53. (A) सब्सिडी, ब्याज और वेतन पर भारी खर्च के साथ निरंतर कर राजस्व में कमी
भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर उच्च राजकोषीय घाटे की दीर्घकालिक चुनौती का मुख्य कारण सरकार का उच्च राजस्व व्यय और अपेक्षाकृत कम कर राजस्व संग्रह है। भारत सरकार के बजटीय व्यय का एक बड़ा हिस्सा भारी सब्सिडी, अतीत के ऋणों पर दिए जाने वाले ब्याज भुगतान और सरकारी वेतन पर खर्च होता है, जिससे राजकोषीय घाटा लगातार उच्च बना रहता है।

54. (D) सार्वजनिक-निजी परियोजनाओं के लिए प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति और सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) को अनिवार्य बनाना
भारत में भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के लिए वर्ष 2013 में एक नया कानून लागू किया गया। इस कानून ने पुराने औपनिवेशिक भूमि अधिग्रहण ढांचे को निरस्त कर दिया। इसने सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए 70 प्रतिशत तथा निजी परियोजनाओं के लिए 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति अनिवार्य कर दी। साथ ही, भूमि अधिग्रहण से पूर्व सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) कराने का वैधानिक प्रावधान लागू किया।

55. (A) केवल I, II और III
1991 के ऐतिहासिक भुगतान संतुलन संकट के पीछे कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक कारण उत्तरदायी थे। पूरे 1980 के दशक के दौरान भारत का राजकोषीय घाटा लगातार उच्च बना रहा, जिससे सरकार को भारी ऋण लेना पड़ा। अत्यधिक संरक्षणवादी और लाइसेंसिंग नीतियों के कारण घरेलू उद्योग वैश्विक स्तर पर गैर-प्रतिस्पर्धी रहे, जिससे निर्यात वृद्धि ठप हो गई। इसके अलावा, सोवियत संघ के विघटन से भारत का पारंपरिक निर्यात बाज़ार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ।

56. (C) निर्यातों को सस्ता और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए आयात लागत बढ़ाना
भुगतान संतुलन संकट के दौरान जुलाई 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रुपये का दो चरणों में अवमूल्यन किया गया था। मुद्रा के अवमूल्यन का प्राथमिक आर्थिक तर्क यह होता है कि इससे विदेशी खरीदारों के लिए देश का निर्यात सस्ता और प्रतिस्पर्धी बन जाता है। साथ ही, आयात महँगा होने से विदेशी मुद्रा भंडार की प्रभावी बचत होती है।

57. (D) बाज़ार दरों पर स्थानीय वित्तीय संपत्तियों को विदेशी वित्तीय संपत्तियों में परिवर्तित करने की अप्रतिबंधित स्वतंत्रता
भुगतान संतुलन लेखांकन में मुद्रा की परिवर्तनीयता से तात्पर्य स्थानीय मुद्रा को बाज़ार चालित विनिमय दर पर अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता से है। जबकि भारत ने 1994 में चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता अपनाई, पूंजी खाते को प्रबंधित रखा गया। पूंजी खाता परिवर्तनीयता वित्तीय परिसंपत्तियों और पूंजी प्रवाहों के अप्रतिबंधित विनिमय और हस्तांतरण को संदर्भित करती है।

58. (A) एमएसएमई (MSME) को सस्ते आयात की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जबकि वे अवसंरचनात्मक बाधाओं और उच्च ऋण लागतों से जूझ रहे थे
1991 के व्यापार उदारीकरण और सीमा शुल्क दरों में की गई तीव्र कटौती के कारण भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आयात शुल्क कम होने से बाज़ार में सस्ते विदेशी निर्मित उत्पादों की बाढ़ आ गई। घरेलू उद्यमों को उच्च ब्याज दरों और अवसंरचनात्मक कमियों के बीच भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था।

59. (B) बड़े पैमाने पर चुनाव पूर्व नकद हस्तांतरण योजना के साथ करों में कटौती
मुद्रास्फीति के कारणों को मांग-जनित और लागत-प्रेरित घटकों में वर्गीकृत किया जाता है। कृषि फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि, समुद्री माल भाड़े में उछाल तथा गंभीर सूखा लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति के उदाहरण हैं क्योंकि ये आपूर्ति लागत बढ़ाते हैं। इसके विपरीत, चुनाव पूर्व नकद हस्तांतरण और करों में कटौती जनता के हाथों में प्रयोज्य आय बढ़ा देती है, जिससे उपभोक्ता मांग में वृद्धि होकर मांग-जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है।

Click Here to Buy book on Flipkart

(C) एक निश्चित गरीबी रेखा के सापेक्ष भोजन, जल और आश्रय जैसी बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं का अत्यधिक अभाव
(D) मौसमी नौकरियों के बीच बदलाव करने वाले श्रमिकों द्वारा अनुभव की जाने वाली आय की अस्थायी हानि

69. भारत में ग्रामीण ऋण विस्तार और कृषि आधुनिकीकरण में एक बड़ी बाधा 'अनुमानित' (Presumptive) भूमि स्वामित्व का बना रहना है। 'निर्णायक' (Conclusive) भूमि स्वामित्व में परिवर्तन का मूलभूत लक्ष्य क्या है?
(A) सटीकता सुनिश्चित करने और स्वामित्व मुकदमों को कम करने वाले राज्य-गारंटीकृत भूमि शीर्षक (Land Titles)
(B) कृषि भूमि के सभी निजी स्वामित्व को समाप्त करना
(C) सभी विखंडित छोटे कृषि जोतों को बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट वाणिज्यिक खेतों में जबरन समेकित करना
(D) भूमि शीर्षक पंजीकरण पर सभी प्रशासनिक और नियामक प्राधिकरण को भारतीय रिजर्व बैंक में स्थानांतरित करना

70. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. एफआरबीएम (FRBM) अधिनियम केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटे में कमी के लिए निश्चित लक्ष्य निर्धारित करने का आदेश देता है।
II. एफआरबीएम (FRBM) अधिनियम में 'अपवाद खंड' (Escape Clauses) शामिल हैं जो असाधारण परिस्थितियों, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा संकट या गंभीर आर्थिक आघात के तहत सरकार को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार करने की अनुमति देते हैं।
III. एफआरबीएम (FRBM) अधिनियम सरकार को घरेलू वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेने से पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

71. उदारीकरण के बाद भारत के औद्योगिक क्षेत्र में एक संरचनात्मक समस्या का वर्णन करने के लिए अक्सर "मिसिंग मिडिल" (Missing Middle) वाक्यांश का उपयोग किया जाता है। यह किसे संदर्भित करता है?
(A) सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में योग्य मध्य-प्रबंधन प्रशासनिक अधिकारियों की पूर्ण अनुपस्थिति
(B) कई छोटी अनौपचारिक इकाइयों और कुछ विशाल फर्मों वाली औद्योगिक संरचना, लेकिन जिसमें मध्यम आकार के औपचारिक संयंत्र अनुपस्थित हैं
(C) तटीय गलियारों के साथ विनिर्माण उद्योगों का भारी भौगोलिक संकेंद्रण, जिससे मध्य भू-आबद्ध क्षेत्र संयंत्रों से वंचित रह गए हैं
(D) माध्यमिक विद्यालय छोड़ने वालों के लिए नौकरियां पैदा करने में सेवा क्षेत्र की विफलता

72. किसी अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित और निरंतर मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान, निम्नलिखित में से कौन-सा समूह आम तौर पर वास्तविक संदर्भों में आर्थिक लाभ या धन के हस्तांतरण का अनुभव करता है?
(A) निश्चित आय वाले पेंशनभोगी
(B) ऋणदाता (Creditors) जिन्होंने निश्चित नाममात्र ब्याज दरों पर दीर्घकालिक ऋण जारी किए हैं
(C) देनदार/ऋणी (Debtors) जिन पर निश्चित नाममात्र ब्याज दरों पर ऋण बकाया है
(D) दिहाड़ी मजदूर जिनकी मजदूरी सालाना समायोजित की जाती है

73. 1991 के संकट के दौरान, विश्व बैंक द्वारा भारत को दिए गए संरचनात्मक समायोजन ऋण मुख्य रूप से किससे संबंधित शर्तों पर केंद्रित थे?
(A) आपातकालीन मुद्रा मुद्रण तंत्र
(B) पश्चिमी आर्थिक गुट के साथ घरेलू विदेश नीति का तत्काल और औपचारिक भू-राजनीतिक संरेखण
(C) राज्य प्रायोजित घरेलू अंतरिक्ष अन्वेषण और परमाणु अनुसंधान कार्यक्रमों का अनिवार्य वित्तपोषण-रोक और विघटन
(D) व्यापार उदारीकरण, निजीकरण और विनियमनमुक्ति (Deregulation) पर केंद्रित क्षेत्रीय नीतिगत सुधार

NODIA

74. गरीबी पर 1991 के सुधारों के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए, सांख्यिकीय साक्ष्य दर्शाते हैं कि:
(A) उच्च आर्थिक वृद्धि से प्रेरित होकर, सुधार-पूर्व दशकों की तुलना में 2000 के बाद गरीबी उन्मूलन में तेज़ी आई
(B) पूरे 1990 और 2000 के दशकों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी दर में लगातार और निरंतर वृद्धि हुई
(C) वर्ष 2005 तक निरपेक्ष गरीबी का पूरी तरह से उन्मूलन हो गया था
(D) 1991 के बाद की उदारीकरण नीतियों ने केंद्र सरकार को किसी भी लक्षित गरीबी उन्मूलन योजना को वित्तपोषित करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था

75. भारत के श्रम कानूनों के हालिया संहिताकरण (Codification) के औचित्य की रूपरेखा देने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. 29 अतिव्यापी (Overlapping) केंद्रीय श्रम कानूनों की बहुलता ने उद्योगों के लिए अनुपालन का अत्यधिक बोझ पैदा किया।
II. पुरातन, कठोर श्रम कानूनों ने औपचारिक रोजगार सृजन को सक्रिय रूप से हतोत्साहित किया और कार्यबल के अनौपचारीकरण को बढ़ावा दिया।
III. नई संहिताओं का उद्देश्य अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार करना है।
IV. ये संहिताएं सभी औपचारिक श्रमिकों से किसी भी

की अनुमति प्रदान करता है। हालाँकि, यह सरकार को बैंकों से बाज़ार उधार लेने से पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं करता है।

71. (B) कई छोटी अनौपचारिक इकाइयों और कुछ विशाल फर्मों वाली औद्योगिक संरचना, लेकिन जिसमें मध्यम आकार के औपचारिक संयंत्र अनुपस्थित हैं
भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में "मिसिंग मिडिल" की समस्या एक गंभीर संरचनात्मक कमजोरी को प्रदर्शित करती है। यह इस स्थिति को दर्शाती है कि भारत के औद्योगिक ढांचे में एक तरफ तो लाखों छोटी, असंगठित और अनौपचारिक सूक्ष्म इकाइयां मौजूद हैं और दूसरी तरफ कुछ विशाल संयंत्र हैं, परंतु बीच में मध्यम आकार के औपचारिक विनिर्माण कारखानों का लगभग पूर्ण अभाव है।

72. (C) देनदार/ऋणी (Debtors) जिन पर निश्चित नाममात्र ब्याज दरों पर ऋण बकाया है
अनपेक्षित और उच्च मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में वास्तविक धन का पुनर्वितरण घटित होता है। इस स्थिति में निश्चित नाममात्र ब्याज दरों पर ऋण लेने वाले देनदार (ऋणी) लाभ में रहते हैं, जबकि ऋणदाता नुकसान उठाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ऋणी अपना ऋण चुकाते हैं, तो चुकाई गई मुद्रा का वास्तविक मूल्य और क्रय शक्ति घट चुकी होती है।

73. (D) व्यापार उदारीकरण, निजीकरण और विनियमनमुक्ति (Deregulation) पर केंद्रित क्षेत्रीय नीतिगत सुधार
1991 के भुगतान संतुलन संकट के समय विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत को स्वीकृत आपातकालीन संरचनात्मक समायोजन ऋण व्यापक नीतिगत शर्तों के साथ जुड़े हुए थे। इन शर्तों का मुख्य ध्यान अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन पर था, जिसमें सीमा शुल्क घटाकर व्यापार उदारीकरण करना, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना और औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर विनियमनमुक्ति लाना शामिल था।

74. (A) उच्च आर्थिक वृद्धि से प्रेरित होकर, सुधार-पूर्व दशकों की तुलना में 2000 के बाद गरीबी उन्मूलन में तेज़ी आई
1991 के बाद लागू किए गए आर्थिक सुधारों के प्रभाव का विश्लेषण करने वाले आनुभविक अध्ययन दर्शाते हैं कि उच्च समष्टि आर्थिक संवृद्धि दर के कारण गरीबी उन्मूलन की गति में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। यद्यपि 1990 के दशक में दर धीमी रही, परंतु वर्ष 2000 के पश्चात उच्च वृद्धि और कल्याणकारी योजनाओं के कारण निरपेक्ष गरीबी में तीव्र और अभूतपूर्व गिरावट दर्ज की गई।

75. (A) केवल I, II और III
भारत के श्रम विधानों के पुनर्गठन और चार श्रम संहितों के निर्माण के पीछे ठोस आर्थिक औचित्य विद्यमान था। 29 केंद्रीय श्रम कानूनों की जटिलता ने उद्योगों के लिए अत्यधिक अनुपालन बोझ पैदा किया था। इन कठोर नियमों ने अनौपचारीकरण को बढ़ावा दिया। नई संहितों का लक्ष्य असंगठित और गिग श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा लाभों का व्यापक विस्तार करना है।

76. (B) मुद्रास्फीति के अनुरूप नाममात्र मजदूरी में वृद्धि के कारण करदाताओं का उच्च कर स्लैब में प्रवेश करना, जिससे वास्तविक कर बोझ बढ़ता है
राजकोषीय खिंचाव एक ऐसी समष्टि आर्थिक स्थिति है जो प्रगतिशील कर प्रणाली में उच्च मुद्रास्फीति के समय उत्पन्न होती है। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो व्यक्तियों की नाममात्र मजदूरी में भी वृद्धि होती है, भले ही उनकी वास्तविक क्रय शक्ति न बढ़ी हो। इस नाममात्र आय वृद्धि के कारण करदाता उच्च कर स्लैब में पहुँच जाते हैं और उनका वास्तविक कर बोझ बढ़ जाता है।

77. (A) उच्च मुद्रास्फीति के साथ-साथ होने वाली लंबी आर्थिक मंदी और उच्च बेरोजगारी की अवधि
मुद्रास्फीतिजनित मंदी (स्टैगफ्लेशन) एक अत्यंत जटिल और प्रतिकूल समष्टि आर्थिक स्थिति को संदर्भित करती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की दर अत्यधिक धीमी हो जाती है या मंदी आ जाती है, बेरोजगारी का स्तर उच्च बना रहता है और इसके साथ ही उच्च मुद्रास्फीति भी बनी रहती है।

78. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और ग्रामीण समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्णायक भूमि स्वामित्व लागू करना एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। वर्तमान में अस्पष्ट भूमि शीर्षकों के कारण किसानों को साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब राज्य द्वारा अकाट्य भूमि शीर्षक प्रदान किए जाते हैं, तो किसान अपनी भूमि को संपार्श्विक रखकर औपचारिक बैंक ऋण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

79. (D) विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, एसडीआर (SDRs) और आईएमएफ (IMF) रिजर्व ट्रेंच स्थिति
भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार देश की बाह्य वित्तीय तरलता और भुगतान संतुलन की मजबूती का एक प्रमुख मापक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित इस आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार में मुख्य रूप से चार घटक शामिल होते हैं: विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में विशेष आहरण अधिकार और कोष के पास रिजर्व ट्रेंच स्थिति।

80. (A) P-2, Q-1, R-3, S-4
समष्टि आर्थिक घाटे की अवधारणाओं का सही सुमेलन इस प्रकार है: राजकोषीय घाटा उधारों को छोड़कर कुल व्यय और प्राप्तियों के अंतर को दर्शाता है। राजस्व घाटा कुल राजस्व व्यय घटाव कुल राजस्व प्राप्तियां है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाकर प्राप्त होता है, तथा मौद्रीकृत घाटा नए नोट छापकर वित्तपोषित किया जाने वाला घाटे का हिस्सा है।

NODIA

अध्याय 12
राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्यिक फसलें

1. निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की कृषि अर्थव्यवस्था की मूल प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) मुख्य रूप से रोपण/बागान आधारित, जिसमें निर्यात-उन्मुख नकद फसलों पर अत्यधिक निर्भरता है
(B) मुख्य रूप से मानसून पर अत्यधिक निर्भरता के साथ शुष्क और अर्ध-शुष्क शुष्कभूमि कृषि पर निर्भर
(C) सघन नदी नेटवर्क के कारण गहन आर्द्रभूमि धान की खेती की प्रधानता
(D) नगण्य वर्षाधारित कृषि के साथ पूर्णतः नहर सिंचाई पर निर्भर

2. राजस्थान में मुख्य रूप से नहरी सिंचाई के कारण गेहूं के दो सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन-से हैं?
(A) जोधपुर और जैसलमेर
(B) बांसवाड़ा और डूंगरपुर
(C) चूरू और सीकर
(D) श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़

3. पश्चिमी राजस्थान में गेहूं की खेती व्यापक होने के बजाय अत्यधिक स्थानीयकृत (सीमित क्षेत्र तक) होने का प्राथमिक कारण क्या है?
(A) गेहूं अत्यधिक जल-गहन रबी फसल है, जो IGNP (इंदिरा गांधी नहर परियोजना) जैसी नहर सिंचाई पर अत्यधिक निर्भर है
(B) गेहूं की खेती के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो इस क्षेत्र में पूर्णतः अनुपस्थित है
(C) गेहूं पाले के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जो पश्चिमी जिलों में प्रतिदिन पड़ता है
(D) पश्चिमी राजस्थान के किसान केवल जैविक खेती करते हैं, जो गेहूं का समर्थन नहीं करती है

4. राजस्थान में खरीफ ऋतु के दौरान किस फसल का बोया गया क्षेत्र सर्वाधिक है?
(A) मक्का
(B) कपास
(C) बाजरा
(D) मूंगफली

5. बाजरा पश्चिमी राजस्थान की कृषि-जलवायु परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल क्यों है?
(A) इसमें सूखा सहन करने की उच्च क्षमता होती है और यह कम नमी वाली बलुई मिट्टी में भी अच्छी तरह पनपता है
(B) इसे अपने संपूर्ण विकास चक्र के दौरान भारी और निरंतर मानसूनी वर्षा की आवश्यकता होती है
(C) यह एक शीतकालीन फसल है, जिसे मरुस्थल में तीव्र शीत लहर से अत्यधिक लाभ होता है
(D) अंकुरण के लिए इसे गहरी दोमट मिट्टी और भारी मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग की आवश्यकता होती है

6. राजस्थान में मक्का की खेती के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) यह मुख्य रूप से बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जैसे दक्षिणी जिलों में उगाई जाती है
(B) यह इस क्षेत्र की जनजातीय जनसंख्या के मुख्य भोजन का एक भाग है
(C) लाल दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है
(D) यह थार मरुस्थल की बलुई मिट्टी में सबसे अच्छी तरह पनपती है

7. राजस्थान की कृषि के संदर्भ में, चना किस प्रकार की फसल है?
(A) एक प्रमुख खरीफ खाद्यान्न फसल
(B) एक प्रमुख रबी दलहन फसल
(C) एक जायद चारा फसल
(D) एक खरीफ तिलहन फसल

8. राजस्थान में कृषि के संबंध में दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन (A): राजस्थान में गेहूं की खेती मुख्य रूप से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में केंद्रित है।
कारण (R): ये जिले राज्य में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जिससे सिंचाई अनावश्यक हो जाती है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

9. निम्नलिखित में से कौन-से जिले पारंपरिक रूप से राजस्थान में जौ के प्रमुख उत्पादक के रूप में पहचाने जाते हैं?
(A) जैसलमेर और बाड़मेर
(B) कोटा और झालावाड़
(C) डूंगरपुर और बांसवाड़ा
(D) जयपुर और सीकर

Downloaded from www.pdf.tube

10. राजस्थान में सरसों उत्पादन में उनके विशिष्ट योगदान के आधार पर निम्नलिखित जिलों को अवरोही क्रम (उच्चतम से निम्नतम) में व्यवस्थित कीजिए:
1. भरतपुर
2. टोंक
3. उदयपुर
4. डूंगरपुर

(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 4, 3, 2, 1
(D) 1, 3, 2, 4

11. सरसों के राष्ट्रीय उत्पादन में राजस्थान का कौन-सा स्थान है?
(A) प्रथम
(B) द्वितीय
(C) तृतीय
(D) पांचवां

12. श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के सिंचित क्षेत्रों में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली "नरमा" किस्म किस फसल से संबंधित है?
(A) गेहूं
(B) कपास
(C) गन्ना
(D) ग्वार

13. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कूट का चयन कीजिए:
सूची I: (फसल)
P. सरसों
Q. धनिया
R. मक्का
S. जीरा
सूची II: (प्रमुख उत्पादक जिला/क्षेत्र)
1. बारां
2. भरतपुर
3. जोधपुर
4. बांसवाड़ा

(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

14. मूंगफली के उच्च गुणवत्ता और प्रचुर उत्पादन के कारण राजस्थान के किस कस्बे को प्रायः "राजस्थान का राजकोट" कहा जाता है?
(A) फलोदी
(B) सूरतगढ़
(C) लूणकरणसर
(D) पोकरण

15. बीकानेर के अतिरिक्त, राजस्थान में मूंगफली का अन्य प्रमुख उत्पादक जिला कौन-सा है?
(A) जालौर
(B) प्रतापगढ़
(C) धौलपुर
(D) नागौर

16. निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक फसल में भारत के कुल उत्पादन का अधिकांश हिस्सा योगदान कर राजस्थान लगभग एकाधिकार रखता है?
(A) गन्ना
(B) सोयाबीन
(C) ग्वार (क्लस्टर बीन)
(D) कपास

17. ग्वार फसल की प्राथमिक औद्योगिक उपयोगिता, जो इसकी व्यावसायिक मांग को बढ़ाती है, किसका निष्कर्षण है?
(A) उच्च श्रेणी के सौंदर्य प्रसाधनों में उपयोग के लिए व्यापक रूप से निष्कर्षित वाष्पशील तेल
(B) व्यावसायिक खाद्य प्रसंस्करण और हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में प्रयुक्त ग्वार गम
(C) भारी औद्योगिक मशीनों और परिवहन के लिए परिष्कृत बायो-डीजल ईंधन
(D) मानव पोषण संबंधी उपभोग के लिए प्रसंस्कृत उच्च-प्रोटीन आटा

18. राजस्थान में बाजरा की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह बोए गए क्षेत्र के आधार पर राज्य की सबसे बड़ी खरीफ खाद्यान्न फसल है।
II. इसके इष्टतम विकास के लिए भारी सिंचाई और लंबे समय तक जलभराव की आवश्यकता होती है।
III. यह सूखे की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहनशील है और बलुई मिट्टी में अच्छी तरह पनपती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

NODIA

19. राजस्थान की "जीरा पट्टी" में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन-से जिले शामिल हैं?
(A) जोधपुर, नागौर और बाड़मेर
(B) कोटा, बूंदी और बारां
(C) अलवर, भरतपुर और धौलपुर
(D) बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर

20. राजस्थान के किस क्षेत्र को धनिया उत्पादन के लिए व्यापक रूप से "मसाला कटोरा" (स्पाइस बाउल) के रूप में जाना जाता है?
(A) शेखावाटी क्षेत्र (सीकर, झुंझुनू, चूरू)

79. राष्ट्रीय स्तर पर मसालों के उत्पादन में राजस्थान की स्थिति की क्या विशेषता है?
(A) यह सभी मसालों का नगण्य उत्पादक है
(B) यह काली मिर्च और इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है
(C) यह केवल घरेलू राज्य उपभोग के लिए मसालों का उत्पादन करता है, जिसमें निर्यात पर प्रतिबंध है
(D) यह जीरा, धनिया और मेथी जैसे बीजीय मसालों का अग्रणी उत्पादक है

80. राजस्थान में कृषि के संबंध में दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन (A): सुदूर पश्चिमी राजस्थान के किसान प्रायः अपनी कृषि उपज का कम मूल्य मिलने से संघर्ष करते हैं।
कारण (R): नियमित मंडियों की अधिक दूरी के कारण उच्च परिवहन लागत उनके शुद्ध लाभ मार्जिन को कम कर देती है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

(A) सेब
(B) अनानास
(C) अनार
(D) लीची

31. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प अपने जीवन चक्र के दौरान जल आवश्यकता के बढ़ते क्रम (न्यूनतम से अधिकतम) में फसलों के सही क्रम को दर्शाता है?
(A) गन्ना, गेहूं, चना, बाजरा
(B) बाजरा, गेहूं, चना, गन्ना
(C) चना, बाजरा, गन्ना, गेहूं
(D) बाजरा, चना, गेहूं, गन्ना

32. पश्चिमी राजस्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) का सबसे महत्वपूर्ण कृषि प्रभाव क्या रहा है?
(A) घने व्यावसायिक इमारती लकड़ी के वनों द्वारा सभी देशी मरुस्थलीय वनस्पतियों का पूर्ण प्रतिस्थापन
(B) पूरे राज्य में सभी आवर्ती कृषि कीट समस्याओं का पूर्ण उन्मूलन
(C) सूखा-सहनशील जीवन-निर्वाह फसलों से जल-गहन व्यावसायिक नकद फसलों की ओर बदलाव
(D) सभी कृषि योग्य भूमि का बड़े औद्योगिक निर्माण क्षेत्रों में तीव्र परिवर्तन

33. कृषि शब्दावली में, "बीज प्रतिस्थापन दर" (SRR) का क्या अर्थ है?
(A) वह दर जिस पर पारंपरिक खाद्यान्न फसलों को व्यवस्थित रूप से व्यावसायिक नकद फसलों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है
(B) खेत में बचाकर रखे गए बीजों के बजाय प्रमाणित बीजों से बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत
(C) शुष्क मिट्टी में बीजों के अंकुरित होने के लिए आवश्यक औसत समय
(D) संकर (हाइब्रिड) बीज किस्मों को खरीदने के लिए किसानों हेतु कानूनी रूप से अनिवार्य सरकारी कोटा

34. राजस्थान में कृषि के संबंध में दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन (A): मक्का राजस्थान के दक्षिणी जिलों जैसे बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में एक प्रमुख फसल है।
कारण (R): दक्षिणी अरावली क्षेत्र में पाई जाने वाली लाल दोमट मिट्टी मक्का की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

35. राजस्थान में अनुबंध कृषि (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) फसलों की किस श्रेणी के लिए सबसे प्रमुखता से उभर रही है?
(A) व्यावसायिक फसलें जैसे ग्वार, औषधीय पौधे और मसाले
(B) पारंपरिक जीवन-निर्वाह खाद्यान्न फसलें जैसे बाजरा और ज्वार
(C) गहन आर्द्रभूमि कृषि फसलें जैसे धान और जूट
(D) गौण गैर-इमारती वन उत्पाद जैसे तेंदू पत्ता

NODIA

36. राजस्थान में क्लस्टर-आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से कौन-सी योजना कार्यान्वित की जा रही है?
(A) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
(B) ई-नाम (e-NAM)
(C) परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
(D) मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान

37. राष्ट्रीय कृषि में राजस्थान के योगदान के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) राजस्थान सरसों, बाजरा और ग्वार के उत्पादन में भारत में अग्रणी है
(B) राजस्थान वर्तमान में भारत में आर्द्रभूमि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है
(C) राजस्थान भारत के कुल राष्ट्रीय गेहूं उत्पादन में 50% से अधिक का योगदान देता है
(D) राजस्थान व्यावसायिक रूप से किसी भी प्रमुख या गौण तिलहन फसल का उत्पादन नहीं करता है

38. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) राजस्थान में व्यावसायिक फसल किसानों को मुख्य रूप से किस प्रकार सहायता प्रदान करती है?
(A) कृषि नलकूपों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करके
(B) बाजार दर से दोगुनी कीमत पर सभी काटी गई फसलों की सीधी सरकारी खरीद की गारंटी देकर
(C) सीमांत किसानों को सीधे निःशुल्क आधुनिक ट्रैक्टर और मशीनरी की आपूर्ति करके
(D) गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों से फसल के नुकसान के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करके

39. राजस्थान में ग्वार (क्लस्टर बीन) की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. भारत के कुल ग्वार उत्पादन में राजस्थान का योगदान 70% से अधिक है।
II. बाड़मेर-जोधपुर-बीकानेर पट्टी इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है।
III. यह एक अत्यधिक जल-गहन फसल है जिसके लिए निरंतर नहर सिंचाई की आवश्यकता होती है।
IV. ग्वार की खेती के लिए अनुबंध कृषि (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) व्यवस्था का उपयोग लगातार बढ़ रहा है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) I, II और III
(B) II, III और IV
(C) I, II और IV

(D) I, III और IV

40. निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में एक खरीफ व्यावसायिक फसल है?
(A) गेहूं
(B) सरसों
(C) कपास
(D) चना

41. निम्नलिखित में से कौन-सा मसाला राजस्थान में आमतौर पर बड़े पैमाने पर व्यावसायिक रूप से नहीं उगाया जाता है?
(A) जीरा
(B) धनिया
(C) मेथी
(D) इलायची

42. राजस्थान में जौ की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह मुख्य रूप से बाजरा के साथ खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है।
II. गेहूं की तुलना में इसे अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है।
III. यह पशु आहार और माल्टिंग उद्योग के लिए व्यावसायिक रूप से मूल्यवान है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

43. नागौर और जोधपुर जैसे जिले जीरे की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त क्यों हैं?
(A) जीरे को निरंतर भारी वर्षा की आवश्यकता होती है जो इन शुष्क जिलों में मानसून के दौरान होती है
(B) शुष्क ठंडी रबी जलवायु और अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी जीरे की वृद्धि के अनुकूल होती है
(C) इन शुष्क जिलों में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक दलदली भूमि पाई जाती है जो जीरे की गहरी जड़ों के लिए आवश्यक है
(D) जीरा केवल छाया में उगने वाली फसल है जो घने क्षेत्रीय वनों के नीचे ही पनपती है

44. राजस्थान के एक किसान के लिए ई-नाम (e-NAM - राष्ट्रीय कृषि बाजार) पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) अनिवार्य राज्य जैविक खेती प्रमाणन के लिए व्यक्तिगत कृषि जोतों का पंजीकरण करना
(B) विभिन्न मंडियों में कृषि जिंसों के व्यापार के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करना
(C) IGNP प्राधिकरण से मौसमी नहर जल आपूर्ति आवंटन कोटा के लिए सीधे आवेदन करना
(D) कृषि ट्रैक्टर दुर्घटनाओं के लिए राज्य प्रायोजित बीमा मुआवजे का दावा दायर करना

45. उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में कड़ाके की शीतकालीन रातों के दौरान कौन-सी फसल अक्सर पाले की समस्या से ग्रस्त होती है, जिससे उपज में भारी नुकसान होता है?
(A) सरसों
(B) बाजरा
(C) मक्का
(D) ज्वार

46. राजस्थान में विशिष्ट कृषि ऋतु के आधार पर भिन्न/विषम फसल की पहचान कीजिए।
(A) गेहूं
(B) चना
(C) मूंगफली
(D) सरसों

47. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) पश्चिमी राजस्थान में फसल विविधीकरण में क्या भूमिका निभाती है?
(A) इसने स्थानीय मरुस्थलीय किसानों को केवल पारंपरिक बाजरा किस्मों की खेती करने तक सीमित कर दिया है
(B) इसने मैदानी फसलों की कीमत पर कृषि का ध्यान पूरी तरह से व्यावसायिक बागवानी पर केंद्रित कर दिया है
(C) इसने क्षेत्रीय मिट्टी को पूरी तरह से लवणीय बना दिया है, जिससे किसी भी फसल की वृद्धि स्थायी रूप से रुक गई है
(D) इसने मरुस्थलीय जिलों में कपास, मूंगफली और गेहूं जैसी नकद फसलों के आगमन को सुगम बनाया है

48. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कूट का चयन कीजिए:
सूची I: (बागवानी फसल)
P. किन्नू
Q. अनार
R. संतरा
S. ईसबगोल
सूची II: (प्रमुख उत्पादक क्षेत्र)
1. झालावाड़
2. जालौर
3. श्रीगंगानगर
4. बाड़मेर
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-2, R-1, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

49. निम्नलिखित में से कौन-सी दलहनी फसल राजस्थान में खरीफ ऋतु के दौरान मुख्य रूप से उगाई जाती है?
(A) चना
(B) मूंग
(C) मसूर

Downloaded from www.pdf.tube

(D) मटर

50. वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने और मृदा की उर्वरता में सुधार करने की क्षमता के कारण कौन-सी फसल राजस्थान में फसल चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है?
(A) गेहूं
(B) कपास
(C) जौ
(D) चना

51. राजस्थान में उगाई जाने वाली "देशी" कपास और "नरमा" कपास के बीच प्राथमिक अंतर क्या है?
(A) देशी छोटे रेशे वाली स्वदेशी कपास है, जबकि नरमा मध्यम/लंबे रेशे वाली अमेरिकी कपास है
(B) देशी कपास के लिए भारी रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है, जबकि नरमा की खेती पूरी तरह से जैविक है
(C) देशी कपास केवल ठंडी रबी ऋतु में उगाई जाती है, जबकि नरमा विशेष रूप से जायद फसल के रूप में उगाई जाती है
(D) नरमा से मोटा काले रंग का रेशा प्राप्त होता है, जबकि देशी कपास से महीन मुलायम सफेद रंग का रेशा प्राप्त होता है

52. राजस्थान में मसालों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. कोटा-बारां-झालावाड़ क्षेत्र को धनिया के लिए "मसाला कटोरा" (स्पाइस बाउल) के रूप में जाना जाता है।
II. नागौर और जोधपुर प्रमुख "जीरा पट्टी" का निर्माण करते हैं।
III. नागौर क्षेत्र में मेथी की खेती व्यावसायिक रूप से प्रमुख है।
IV. राजस्थान की शुष्क जलवायु बीजीय मसालों की व्यावसायिक खेती को रोकती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) I, II और III
(B) I, II और IV
(C) II, III और IV
(D) I, III और IV

53. निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में कृषि उत्पादकता के लिए सबसे प्रमुख बाधक कारक माना जाता है?
(A) अपर्याप्त और परिवर्तनशील जल की उपलब्धता
(B) पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की गंभीर निरंतर कमी
(C) उपयुक्त समतल भूभाग की पूर्ण संरचनात्मक अनुपस्थिति
(D) सस्ते कृषि श्रम की अत्यधिक प्रचुरता

54. राजस्थान में एक फसल और उसके सर्वोच्च उत्पादक जिले को दर्शाने वाले सही युग्म की पहचान कीजिए।
(A) मक्का - जैसलमेर
(B) मूंगफली - डूंगरपुर
(C) कपास - धौलपुर
(D) गेहूं - श्रीगंगानगर

55. राजस्थान में व्यावसायिक फसल उत्पादकों के लिए अनुबंध कृषि (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) का मुख्य लाभ क्या है?
(A) यह मानसून के शुष्क दौर के दौरान नियमित कृत्रिम वर्षा की गारंटी देता है
(B) यह पूर्व-निर्धारित क्रय मूल्यों के माध्यम से किसानों को मूल्य अस्थिरता से बचाता है
(C) यह भाग लेने वाले किसानों को किसी भी राज्य कृषि कर का भुगतान करने से पूरी तरह छूट देता है
(D) यह निजी भूमि स्वामित्व अधिकारों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को स्थायी रूप से स्थानांतरित करता है

56. राजस्थान में कृषि के संबंध में दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन (A): पिछले कुछ दशकों में बीकानेर क्षेत्र में मूंगफली और सरसों जैसी व्यावसायिक फसलों की खेती में काफी वृद्धि हुई है।
कारण (R): इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विस्तार ने इन पूर्व शुष्क क्षेत्रों को निश्चित सिंचाई प्रदान की है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

57. दुर्लभ जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम बनाने के लिए जालौर-बाड़मेर अनार पट्टी में किस कृषि पद्धति का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है?
(A) प्लावावी/प्रवाह सिंचाई (फ्लड इरिगेशन)
(B) नहर विचलन (कनाल डायवर्जन)
(C) केवल गहरी बावड़ियों में वर्षा जल संचयन
(D) ड्रिप (टपकन) और सूक्ष्म-फव्वारा सिंचाई

NODIA

58. राजस्थान में किसानों के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा करने से पहले भारत में किस निकाय द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है?
(A) कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)
(B) नीति आयोग
(C) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
(D) वाणिज्य मंत्रालय

59. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प पश्चिम से पूर्व की ओर प्रमुख ग्वार उत्पादक जिलों के सही भौगोलिक क्रम को दर्शाता है?
(A) दौसा, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर
(B) जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, दौसा
(C) जोधपुर, दौसा, जैसलमेर, जयपुर
(D) जयपुर, जैसलमेर, दौसा, जोधपुर

(B) मेवाड़ क्षेत्र (उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा)
(C) हाड़ौती क्षेत्र (कोटा, बारां, झालावाड़)
(D) मारवाड़ क्षेत्र (जोधपुर, पाली, नागौर)

21. नागौर जिले का ताऊसर गांव किस मसाला फसल के उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है?
(A) मेथी
(B) धनिया
(C) हल्दी
(D) लहसुन

22. पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के बीच व्यावसायिक फसलों की सिंचाई निर्भरता में सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है?
(A) पूर्वी राजस्थान पूरी तरह से प्रमुख नहर प्रणालियों पर निर्भर है, जबकि पश्चिमी राजस्थान केवल अनिश्चित मौसमी वर्षा पर निर्भर है
(B) दोनों क्षेत्र अपनी सभी प्रमुख व्यावसायिक नकद फसलों के लिए पारंपरिक तालाब सिंचाई प्रणाली पर समान रूप से निर्भर हैं
(C) भूजल के कारण पश्चिमी राजस्थान केवल गहरे नलकूपों का उपयोग करता है, जबकि पूर्वी राजस्थान केवल नहर नेटवर्क का उपयोग करता है
(D) पूर्वी राजस्थान नलकूपों और कुओं का उपयोग करता है, जबकि पश्चिमी कृषि IGNP जैसी नहर प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर है

23. निम्नलिखित में से कौन-सा राजस्थान में एक व्यावसायिक फसल और उसके प्रमुख उत्पादक जिले का गलत युग्म है?
(A) किन्नू - श्रीगंगानगर
(B) जीरा - जैसलमेर
(C) अनार - बाड़मेर
(D) धनिया - झालावाड़

24. राजस्थान में सरसों उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राजस्थान भारत में सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है।
II. यह मुख्य रूप से भरतपुर-अलवर-श्रीगंगानगर पट्टी में उगाई जाती है।
III. यह बाजरा के साथ खरीफ ऋतु के दौरान बोई जाती है।
IV. यह अपनी पुष्पन (फूल आने की) अवस्था के दौरान पाले के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) I, II और III
(B) I, II और IV
(C) II, III और IV
(D) I, III और IV

25. राजस्थान में सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) संचालन के तहत, कौन-सी एजेंसी आमतौर पर तिलहन और दलहन की खरीद के लिए प्राथमिक राज्य-स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है?
(A) RIICO
(B) RSRTC
(C) RSMM
(D) RAJFED

26. कौन-सी परिघटना पश्चिमी राजस्थान में फसल उपज की स्थिरता के लिए सबसे बड़ा आवर्ती खतरा पैदा करती है?
(A) अनिश्चित वर्षा पैटर्न और लंबी शुष्क अवधि (सूखा)
(B) नदियों के उफान के कारण आने वाली गंभीर आवर्ती बाढ़
(C) ग्रीष्मकाल के दौरान पाला पड़ने की अत्यधिक घटनाएं
(D) मृदा अम्लता का अत्यधिक उच्च स्तर

27. पश्चिमी राजस्थान के सुदूर क्षेत्रों में व्यावसायिक फसलें उगाने वाले किसानों के समक्ष बाजार पहुंच की एक प्रमुख चुनौती क्या है?
(A) स्थानीय प्रसंस्करण इकाइयों की प्रचुरता जिससे कीमतें अत्यधिक बढ़ जाती हैं
(B) नियमित मंडियों की अधिक दूरी जिसके परिणामस्वरूप उच्च परिवहन लागत आती है
(C) गांव के बाहर उपज बेचने पर राज्य सरकार द्वारा पूर्ण प्रतिबंध
(D) सभी उपज का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात करने की अनिवार्य आवश्यकता

28. राजस्थान का कौन-सा जिला साइट्रस फल 'किन्नू' का अग्रणी उत्पादक है?
(A) झालावाड़
(B) श्रीगंगानगर
(C) सिरोही
(D) बीकानेर

29. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कूट का चयन कीजिए:
सूची I: (फसल की किस्म)
P. नरमा
Q. माही कंचन
R. राज 3077
S. वरुणा
सूची II: (फसल)
1. मक्का
2. गेहूं
3. सरसों
4. कपास
(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-4, R-3, S-2
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

30. जालौर और बाड़मेर के शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्र में किस फल की बागवानी खेती में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है?

Click Here to Buy book on Flipkart

(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

70. कौन-सी फसल उत्तरी राजस्थान के सिंचित क्षेत्रों में एक व्यावसायिक नकद फसल के रूप में विशिष्ट रूप से जानी जाती है, जबकि असिंचित थार मरुस्थल में पूरी तरह से अनुपस्थित रहती है?
(A) बाजरा
(B) मोठ
(C) ग्वार
(D) कपास

71. हाड़ौती क्षेत्र में धनिया की व्यापक खेती का सबसे उपयुक्त कारण क्या है?
(A) यह कानूनी रूप से राजस्थान का एकमात्र ऐसा क्षेत्र नामित है जहां व्यावसायिक मसाला खेती की अनुमति है
(B) काली दोमट मिट्टी और उपयुक्त वर्षा इसके अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं
(C) यह क्षेत्र पूरी तरह से शुष्क है, जिसकी आवश्यकता धनिया को पौधे पर ही प्राकृतिक रूप से सूखने के लिए होती है
(D) यह बिना किसी वैज्ञानिक जलवायु आधार के पूरी तरह से एक प्राचीन पारंपरिक प्रथा पर आधारित है

72. राजस्थान में चने की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह रबी ऋतु के दौरान उगाई जाने वाली एक प्रमुख दलहनी फसल है।
II. इसके पूरे जीवन चक्र में भारी और लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है।
III. बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ इसके प्रमुख उत्पादक जिलों में से हैं।
IV. यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मृदा उर्वरता बढ़ाने में मदद करती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) I, II और III
(B) I, III और IV
(C) II, III और IV
(D) I, II और IV

73. IGNP कमान क्षेत्र में व्यावसायिक फसलों के लिए अत्यधिक नहर सिंचाई का नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से किसे माना जाता है?
(A) गहरे भूजल जलभृतों (एक्वीफर्स) का गंभीर क्षरण
(B) सभी स्थानीय मरुस्थलीय वन्यजीवों का पूर्ण विनाश
(C) वायुमंडलीय आर्द्रता के स्तर में भारी स्थायी कमी
(D) जलभराव और मृदा लवणता (सेम की समस्या)

74. राजस्थान में किसी किसान के लिए जैविक खेती में स्थानांतरित होने का सबसे वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त तरीका निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) रूपांतरण अवधि के दौरान वर्मीकंपोस्ट और जैव-कीटनाशकों का उपयोग करके रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना
(B) सभी कृषि फसलों की सभी कृत्रिम सिंचाई और पानी देना तुरंत बंद करना
(C) संपूर्ण कृषि उत्पादन को मिट्टी के बिना व्यावसायिक ग्रीनहाउस में फसलें उगाने पर स्थानांतरित करना
(D) केवल वर्षाकालीन मानसूनी अवधि के दौरान ही सभी कृषि फसलों को लगाना

75. उस फसल की पहचान कीजिए जो राजस्थान की कृषि निर्यात टोकरी में प्रमुख योगदानकर्ता नहीं है।
(A) ग्वार गम
(B) रबर
(C) जीरा
(D) धनिया

76. राजस्थान में कृषि बाजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. मंडियों की अधिक दूरी पश्चिमी राजस्थान में किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति में एक बाधा के रूप में कार्य करती है।
II. कृषि उपज मंडियों को डिजिटल रूप से एकीकृत करने के लिए ई-नाम (e-NAM) शुरू किया गया है।
III. किसानों से सीधे खरीदारी करने वाले निजी व्यापारियों के लिए MSP पर खरीद करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

77. निम्नलिखित में से कौन-सा फसल-जिला युग्म राजस्थान में एक विशिष्ट बागवानी फसल को उसके प्रमुख उत्पादक जिले के साथ सही सुमेलित करता है?
(A) संतरा - झालावाड़
(B) सेब - जैसलमेर
(C) अनानास - चूरू
(D) नारियल - उदयपुर

78. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प उत्तर से दक्षिण की ओर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से प्रमुख सिंचाई लाभ प्राप्त करने वाले जिलों का सही क्रम दर्शाता है?
(A) बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़
(B) बीकानेर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर
(C) हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर
(D) जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, बीकानेर

Downloaded from www.pdf.tube

60. निम्नलिखित में से कौन-सा राजस्थान में निम्न गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता (निम्न बीज प्रतिस्थापन दर) का परिणाम नहीं है?
(A) फसल की कम उपज
(B) नकद फसलों में स्वतः उत्परिवर्तन (म्यूटेशन)
(C) कीटों और रोगों के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता
(D) फसल का असमान परिपक्व होना

61. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) के कृषि प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसने पश्चिमी राजस्थान में सूखा-सहनशील फसलों से नकद फसलों की ओर बदलाव को सुगम बनाया है।
II. इसने कमान क्षेत्र में जलभराव और मृदा लवणता की समस्या को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।
III. इसने श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में गेहूं और कपास की बड़े पैमाने पर खेती को सक्षम बनाया है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

62. निम्नलिखित में से किस फसल को लगभग 210 पाला-रहित दिनों की आवश्यकता होती है, जिससे इसकी खेती राजस्थान में विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों और सिंचित क्षेत्रों तक सीमित हो जाती है?
(A) सरसों
(B) जौ
(C) कपास
(D) चना

63. कौन-सा जिला पारंपरिक रूप से राजस्थान के मुख्य मक्का उत्पादक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है?
(A) बांसवाड़ा
(B) चित्तौड़गढ़
(C) उदयपुर
(D) चूरू

64. जैसलमेर और बाड़मेर जैसे सीमावर्ती जिलों के किसानों के लिए कृषि मंडियों में उचित मूल्य प्राप्त करने में मुख्य बाधा क्या है?
(A) उच्च स्थानीय उपभोग जिससे शून्य अधिशेष बचता है
(B) स्थानीय पंचायतों द्वारा कृषि व्यापार पर प्रतिबंध
(C) प्रमुख नियमित बाजारों तक परिवहन की अधिक दूरी
(D) गांवों को जोड़ने वाले सड़क बुनियादी ढांचे का पूर्ण अभाव

65. राजस्थान में खरीफ फसलों के लिए व्यावहारिक रूप से अपनाए जाने वाले सही कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित कृषि कार्यों को व्यवस्थित कीजिए:
1. बुआई
2. कटाई
3. खेत की तैयारी
4. निराई-गुड़ाई (खरपतवार निकालना)
(A) 3, 1, 4, 2
(B) 1, 3, 4, 2
(C) 3, 1, 2, 4
(D) 1, 4, 3, 2

66. राजस्थान में चने की खेती के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) यह मुख्य रूप से पूरे क्षेत्र में ठंडे मौसम की रबी फसल के रूप में उगाई जाती है
(B) राजस्थान लगातार भारत में चने के शीर्ष उत्पादकों में स्थान रखता है
(C) बीकानेर और चूरू जिलों को चने के महत्वपूर्ण उत्पादकों के रूप में जाना जाता है
(D) इसके अंकुरण के लिए जलभराव की स्थिति आवश्यक है

67. राजस्थान कृषि में "जायद" शब्द का अर्थ है:
(A) रबी और खरीफ के बीच उगाई जाने वाली सिंचित ग्रीष्मकालीन फसलें
(B) कड़ाके की शीत ऋतु के दौरान उगाई जाने वाली व्यावसायिक फसलें
(C) मानसूनी वर्षा के दौरान प्राकृतिक रूप से उगने वाली जंगली देशी घास
(D) रासायनिक उर्वरकों के बिना उगाई जाने वाली जैविक खाद्यान्न फसलें

68. निम्नलिखित में से कौन-सा जिला सरसों और गेहूं जैसी व्यावसायिक फसलों के लिए नलकूप सिंचाई पर उच्च निर्भरता के लिए जाना जाता है?
(A) जैसलमेर
(B) बांसवाड़ा
(C) अलवर
(D) डूंगरपुर

69. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कूट का चयन कीजिए:
सूची I: (कृषि शब्दावली)
P. बीज प्रतिस्थापन दर
Q. अनुबंध कृषि (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग)
R. जैविक खेती
S. न्यूनतम समर्थन मूल्य
सूची II: (प्रासंगिकता/परिभाषा)
1. विशिष्ट फसलों के लिए पूर्व-सहमत मूल्य और क्रय
2. खेत में बचाए गए बीजों के बजाय उपयोग किए जाने वाले प्रमाणित बीजों का अनुपात
3. खरीद के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य
4. रासायनिक इनपुट के बिना खेती
(A) P-2, Q-1, R-4, S-3

NODIA

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) मुख्य रुप से मानसून पर अत्यधिक निर्भरता के साथ शुष्क और अर्ध-शुष्क शुष्कभूमि कृषि पर निर्भर
राजस्थान की कृषि मुख्य रूप से शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु परिस्थितियों से संचालित होती है। राज्य का एक बड़ा भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है, जहाँ वर्षा अनिश्चित, न्यून तथा अत्यधिक असमान होती है। यहाँ की अधिकांश कृषि योग्य भूमि सिंचाई सुविधाओं के अभाव में केवल मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। जल संसाधनों की सीमित उपलब्धता और बलुई मृदा के कारण शुष्कभूमि कृषि का बाहुल्य है।

2. (D) श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़
श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित हैं और राज्य के प्रमुख खाद्यान्न भंडार माने जाते हैं। भाखड़ा नांगल नहर प्रणाली और इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निरंतर एवं पर्याप्त जल आपूर्ति मिलने के कारण इन जिलों में रबी ऋतु के दौरान बड़े पैमाने पर गेहूं की गहन खेती की जाती है। अनुकूल नहरी सिंचाई तंत्र तथा उपजाऊ मिट्टी के कारण ये अग्रणी हैं।

3. (A) गेहूं अत्यधिक जल-गहन रबी फसल है, जो IGNP (इंदिरा गांधी नहर परियोजना) जैसी नहर सिंचाई पर अत्यधिक निर्भर है
गेहूं एक प्रमुख रबी फसल है जिसके विकास एवं परिपक्वता के लिए पर्याप्त एवं नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। पश्चिमी राजस्थान की जलवायु अत्यंत शुष्क है और यहाँ प्राकृतिक वर्षा न्यूनतम होती है। इस भौगोलिकता के कारण गेहूं की खेती पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र में फैले होने के बजाय केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित है जहाँ इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई उपलब्ध हो पाती है।

4. (C) बाजरा
राजस्थान में खरीफ ऋतु के दौरान कुल बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से बाजरा सबसे प्रमुख फसल है। यह राज्य के पश्चिमी एवं अर्ध-शुष्क जिलों में व्यापक स्तर पर बोया जाता है। बाजरा शुष्क जलवायु, उच्च तापमान तथा कम जल उपलब्धता की परिस्थितियों के प्रति असाधारण रूप से अनुकूलित है। वर्षा की अनिश्चितता के बावजूद यह न्यूनतम पानी में अच्छी उपज देने में सक्षम फसल है।

5. (A) इसमें सूखा सहन करने की उच्च क्षमता होती है और यह कम नमी वाली बलुई मिट्टी में भी अच्छी तरह पनपता है
बाजरा एक सी-4 श्रेणी का पौधा है जो कम पानी और उच्च तापमान वाले वातावरण में भी कुशलतापूर्वक प्रकाश-संश्लेषण कर सकता है। पश्चिमी राजस्थान की रेतीली तथा बलुई मिट्टी में जल धारण क्षमता अत्यंत कम होती है, फिर भी बाजरे की गहरी जड़ प्रणाली नमी शोषित कर लेती है। सूखे को सहन करने की क्षमता के कारण यह फसल यहाँ सरलता से पनपती है।

6. (D) यह थार मरुस्थल की बलुई मिट्टी में सबसे अच्छी तरह पनपती है
मक्का राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों की एक प्रमुख फसल है। इसके उत्पादन के लिए मध्यम से भारी वर्षा, अच्छी जल निकासी वाली लाल दोमट मिट्टी तथा अनुकूल आर्द्रता की आवश्यकता होती है। थार मरुस्थल की अत्यधिक शुष्क जलवायु और रेतीली मिट्टी मक्का की खेती के लिए अनुपयुक्त है। अतः यह मरुस्थलीय बालू मिट्टी में नहीं पनप सकती।

7. (B) एक प्रमुख रबी दलहन फसल
चना राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण दाल फसलों में से एक है, जिसकी बुआई अक्टूबर-नवंबर के महीनों में शीतकाल के प्रारंभ में की जाती है तथा कटाई मार्च-अप्रैल में होती है। इस प्रकार यह रबी चक्र की एक प्रमुख दलहनी फसल है। यह फसल कम पानी और ठंडी जलवायु में बढ़ती है। चने की फसल नाइट्रोजन स्थिर करके भूमि की उर्वरता बढ़ाती है।

8. (C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
राजस्थान में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक हैं। किंतु इसका मुख्य कारण प्रचुर वर्षा न होकर भाखड़ा प्रणाली और इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा विकसित गहन नहरी सिंचाई नेटवर्क है। ये उत्तरी जिले वस्तुतः राज्य के शुष्क एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आते हैं, जहाँ नहरों के बिना गेहूं का व्यावसायिक उत्पादन संभव नहीं था। अतः कारण असत्य है।

9. (D) जयपुर और सीकर
जौ एक महत्वपूर्ण रबी खाद्यान्न फसल है जो कम पानी और हल्की क्षारीय मृदा की परिस्थितियों में भी उगने में सक्षम है। राजस्थान के जयपुर, सीकर, श्रीगंगानगर और अलवर जिलों में पारंपरिक रूप से जौ की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। विशेष रूप से जयपुर और सीकर जिलों की परिस्थितियाँ अत्यधिक अनुकूल हैं। इसका उपयोग माल्ट निर्माण में होता है।

10. (A) 1, 2, 3, 4
राजस्थान में सरसों के उत्पादन का वितरण क्षेत्रीय जलवायु और सिंचाई पर आधारित है। पूर्वी राजस्थान का भरतपुर जिला राज्य में सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है, जिसे सरसों का कटोरा भी कहते हैं। इसके पश्चात टोंक का स्थान आता है। दक्षिणी जिलों उदयपुर तथा डूंगरपुर में पहाड़ी भूभाग के कारण सरसों का उत्पादन क्रमबद्ध रूप से काफी कम मिलता है।

Click Here to Buy book on Amazon

35. (A) व्यावसायिक फसलें जैसे ग्वार, औषधीय पौधे और मसाले
राजस्थान में अनुबंध कृषि का मॉडल मुख्य रुप से उच्च मूल्य वाली व्यावसायिक फसलों, बीजीय मसालों, ग्वार तथा औषधीय पौधों के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। प्रसंस्करण उद्योग और निर्यात एजेंसियां किसानों के साथ पूर्व-निर्धारित दरों पर फसल उत्पादन हेतु समझौते करती हैं, जिससे किसानों को बाजार की अनिश्चितता से वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होती है। यह नया रुझान है।

36. (C) परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
राजस्थान में क्लस्टर-आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए "परंपरागत कृषि विकास योजना" कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के समूहों को जैविक खेती अपनाने, जैविक खाद तैयार करने तथा उत्पादों के प्रमाणीकरण एवं विपणन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बल मिलता है। यह प्रमुख योजना है।

37. (A) राजस्थान सरसों, बाजरा और ग्वार के उत्पादन में भारत में अग्रणी है
राजस्थान राष्ट्रीय कृषि परिदृश्य में तिलहन और शुष्क फसलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान रखता है। राज्य सरसों, बाजरा तथा ग्वार के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। इसकी जलवायु और विस्तृत भूभाग इन फसलों के लिए अनुकूल हैं। इसके अतिरिक्त बीजीय मसालों के उत्पादन में भी राज्य का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यह कथन पूर्णतः सत्य है।

38. (D) गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों से फसल के नुकसान के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करके
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राजस्थान के किसानों को अनियंत्रित प्राकृतिक आपदाओं, जैसे सूखा, ओलावृष्टि, पाला और कीटों के प्रकोप से होने वाले फसल नुकसान के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। योजना के तहत किसानों को न्यूनतम प्रीमियम दर पर फसल का बीमा आवरण मिलता है, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी से राहत मिलती है। यह वित्तीय संबल प्रदान करती है।

39. (C) I, II और IV
भारत के कुल ग्वार उत्पादन का 70% से अधिक योगदान राजस्थान का है, जिसमें बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर जिले प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। ग्वार गम की औद्योगिक मांग के कारण इस फसल के लिए अनुबंध कृषि का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। ग्वार एक कम पानी चाहने वाली शुष्क फसल है, न कि जल-गहन। अतः कथन सही माने जाते हैं।

40. (C) कपास
कपास राजस्थान की एक प्रमुख खरीफ नकद एवं व्यावसायिक फसल है, जिसकी बुआई मानसून के आगमन पर जून-जुलाई में की जाती है तथा चुनाई शरद ऋतु में होती है। यह वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल प्रदान करती है। इसके विपरीत गेहूं, सरसों और चना रबी ऋतु की मुख्य फसलें हैं जिनकी बुआई शीतकाल में की जाती है। यह अंतर है।

41. (D) इलायची
इलायची एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की मसाला फसल है, जिसकी खेती के लिए अत्यधिक वर्षा, आर्द्रता और पहाड़ी ढलानों की आवश्यकता होती है। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत में उगाई जाती है। राजस्थान की शुष्क एवं गर्म जलवायु इलायची के लिए अनुपयुक्त है, जबकि जीरा, धनिया और मेथी जैसे मसालों का राज्य में व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। यह स्पष्ट है।

42. (B) केवल II और III
जौ राजस्थान की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है, जिसकी बुआई शीतकाल के दौरान की जाती है। गेहूं की तुलना में इसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है और यह क्षारीय मृदा में भी उग सकता है। इसका व्यावसायिक उपयोग पशु आहार तथा माल्टिंग उद्योग में बहुतायत से किया जाता है। अतः दिए गए कथनों में केवल II और III सही हैं।

43. (B) शुष्क ठंडी रबी जलवायु और अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी जीरे की वृद्धि के अनुकूल होती है
जीरा एक संवेदनशील रबी मसाला फसल है जिसे अपनी वृद्धि के दौरान शुष्क, ठंडे और साफ़ मौसम की आवश्यकता होती है। पश्चिमी राजस्थान के नागौर और जोधपुर जिलों में पाई जाने वाली बलुई दोमट मिट्टी तथा शुष्क जलवायु जीरे के विकास के लिए अत्यधिक अनुकूल मानी जाती है। यह परिस्थितियां उच्च गुणवत्ता का उत्पादन सुनिश्चित करती हैं। यह मुख्य कारण है।

44. (B) विभिन्न मंडियों में कृषि जिंसों के व्यापार के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करना
राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) एक डिजिटल व्यापार पोर्टल है, जो देश और राज्य की कृषि मंडियों को आपस में जोड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि उपज के क्रय-विक्रय के लिए एक एकीकृत, पारदर्शी और ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराना है। इससे किसान विभिन्न मंडियों के भाव देखकर अपनी फसल का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। यह क्रांतिकारी व्यवस्था है।

45. (A) सरसों
सरसों राजस्थान की एक प्रमुख रबी तिलहन फसल है। उत्तरी एवं पूर्वी राजस्थान में शीतकाल के दौरान जब तापमान अत्यधिक गिर जाता है, तब पाला पड़ने से सरसों की फसल बुरी तरह प्रभावित होती है। विशेष रूप से पुष्पन और फली बनने की अवस्था में पाला लगने से दानों का विकास रुक जाता है तथा भारी आर्थिक नुकसान होता है। यह संवेदनशील है।

NODIA

46. (C) मूंगफली
राजस्थान की कृषि ऋतुओं के वर्गीकरण के आधार पर मूंगफली एक खरीफ मौसम की फसल है, जिसकी बुआई मानसून के आगमन पर की जाती है। इसके विपरीत गेहूं, चना और सरसों तीनों ही रबी मौसम की मुख्य फसलें हैं जिनकी बुआई शीतकाल में होती है। इस प्रकार मूंगफली अपनी बुआई की ऋतु के आधार पर अन्य तीनों से भिन्न है।

23. (B) जीरा - जैसलमेर
राजस्थान में जीरे का मुख्य उत्पादन जोधपुर, बाड़मेर, नागौर और जालौर जिलों में होता है, जो राज्य के प्राथमिक जीरा उत्पादक क्षेत्र हैं। जैसलमेर जीरे का प्रमुख या सर्वोच्च उत्पादक जिला नहीं है। इसके विपरीत श्रीगंगानगर में किन्नू, बाड़मेर में अनार तथा झालावाड़ में धनिया का व्यावसायिक उत्पादन होता है और वे अग्रणी उत्पादक माने जाते हैं। अतः यह अशुद्ध युग्म है।

24. (B) I, II और IV
राजस्थान भारत में सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इसका मुख्य उत्पादन भरतपुर, अलवर तथा श्रीगंगानगर पट्टी में केंद्रित है। सरसों रबी मौसम की एक प्रमुख फसल है, न कि खरीफ मौसम की। शीतकाल के दौरान जब सरसों के पौधों में फूल आने की अवस्था होती है, उस समय पाला पड़ने से फसल को नुकसान पहुँचता है। अतः कथन सही हैं।

25. (D) RAJFED
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड (राजफेड) राज्य में तिलहन और दलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए प्राथमिक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। जब बाजार में तिलहनों और दालों के दाम गिरते हैं, तब राजफेड किसानों से सीधे जिंसों की खरीद करके उन्हें उचित मूल्य दिलाना सुनिश्चित करता है। यह महत्वपूर्ण संस्था है।

26. (A) अनिश्चित वर्षा पैटर्न और लंबी शुष्क अवधि (सूखा)
पश्चिमी राजस्थान में कृषि उत्पादन के सामने सबसे बड़ा आवर्ती खतरा मानसून की अनिश्चितता, वर्षा का कम होना तथा लंबी शुष्क अवधि है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की अनियमितता और सूखा बार-बार फसल की विफलता का कारण बनता है। अधिकांश कृषि क्षेत्र असिंचित होने के कारण मानसून के रुकने से फसलों के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह गंभीर समस्या है।

27. (B) नियमित मंडियों की अधिक दूरी जिसके परिणामस्वरूप उच्च परिवहन लागत आती है
पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थलीय जिलों में भौगोलिक विस्तार अत्यधिक बड़ा है और दूरियां बहुत अधिक हैं। नियमित कृषि उपज मंडियों की दूरी अधिक होने से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए भारी परिवहन लागत वहन करनी पड़ती है। यह उच्च परिवहन व्यय किसानों के लाभ मार्जिन को अत्यधिक घटा देता है। यह बड़ी चुनौती है।

28. (B) श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर जिला राजस्थान में रसीले खट्टे फलों, विशेष रूप से 'किन्नू' के उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान रखता है। इस जिले की नहर सिंचित मिट्टी और अनुकूल उपोष्णकटिबंधीय जलवायु परिस्थितियां साइट्रस फलों के बागानों के लिए अत्यंत उपजाऊ सिद्ध हुई हैं। श्रीगंगानगर में उत्पादित किन्नू को देश के विभिन्न राज्यों तथा विदेशों में भी भेजा जाता है। यह अग्रणी है।

29. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
विभिन्न फसलों की उन्नत किस्में उनकी पहचान निर्धारित करती हैं। "नरमा" कपास की एक सिंचित लंबे रेशे वाली किस्म है जो उत्तरी भागों में उगाई जाती है। "माही कंचन" मक्का की एक प्रसिद्ध किस्म है। "राज 3077" गेहूं की एक बहुप्रचलित किस्म है, जबकि "वरुणा" सरसों की एक उच्च उपज देने वाली किस्म मानी जाती है। यह सही सुमेल है।

30. (C) अनार
राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध-शुष्क जिले जालौर और बाड़मेर में हाल के वर्षों में अनार की व्यावसायिक बागवानी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ड्रिप सिंचाई तकनीक और आधुनिक कृषि पद्धतियों के प्रयोग से किसानों ने मरुस्थलीय परिस्थितियों में अनार के उच्च गुणवत्ता वाले बगीचे विकसित किए हैं। इस पहल ने क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है।

31. (D) बाजरा, चना, गेहूं, गन्ना
विभिन्न फसलों की जल आवश्यकता उनकी संरचना और जीवन काल पर निर्भर करती है। बाजरा सबसे कम पानी चाहने वाली शुष्क फसल है। इसके बाद रबी दलहन चना आता है जिसे सीमित पानी चाहिए। गेहूं एक जल-गहन रबी फसल है जिसे नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि गन्ना अत्यधिक जल खपत करने वाली बहुवर्षीय फसल है। यह सही क्रम है।

32. (C) सूखा-सहनशील जीवन-निर्वाह फसलों से जल-गहन व्यावसायिक नकद फसलों की ओर बदलाव
इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल की पारंपरिक कृषि प्रणाली में बड़ा परिवर्तन किया है। नहर के आगमन से पूर्व यहाँ केवल वर्षा आधारित सूखा सहनशील जीवन-निर्वाह फसलें उगाई जाती थीं। नहरी जल की उपलब्धता के कारण अब किसान गेहूं, मूंगफली, कपास और सरसों जैसी जल-गहन व्यावसायिक फसलों की खेती करने लगे हैं। यह प्रमुख प्रभाव है।

33. (B) खेत में बचाकर रखे गए बीजों के बजाय प्रमाणित बीजों से बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत
बीज प्रतिस्थापन दर (SRR) कृषि विज्ञान का एक महत्वपूर्ण मापदंड है, जो यह दर्शाता है कि किसानों द्वारा पारंपरिक रूप से खेत में बचाकर रखे गए बीजों के स्थान पर प्रमाणित बीजों से कितना क्षेत्र बोया गया है। उच्च दर फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करती है, जिससे खेती अत्यधिक लाभप्रद बनती है। यह प्रमुख कारक है।

34. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
राजस्थान के दक्षिणी जिलों जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में मक्का एक प्रमुख फसल के रूप में बोई जाती है। अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इन दक्षिणी जिलों में पाई जाने वाली लाल दोमट मिट्टी मक्का की वृद्धि के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। अतः दिए गए कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा व्याख्या सही है।

Downloaded from www.pdf.tube

(D) जोधपुर

19. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): राजस्थान में ग्वार गम प्रसंस्करण उद्योग अत्यधिक निर्यात-उन्मुख है।
कारण (R): ग्वार गम पाउडर के व्यापक औद्योगिक अनुप्रयोग हैं, विशेष रूप से वैश्विक शेल गैस और तेल फ्रैकिंग उद्योग में गाढ़ा करने वाले पदार्थ के रूप में।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

20. निम्नलिखित में से कौन सा गुण ग्वार गम को औद्योगिक अनुप्रयोगों में एक उच्च मूल्य वाला प्रसंस्कृत कृषि-उत्पाद बनाता है?
(A) उच्च प्राकृतिक ज्वलनशीलता जिससे यह औद्योगिक कोयले के स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन के रूप में कार्य करता है
(B) तीव्र रासायनिक विषाक्तता जो इसे फसल सुरक्षा के लिए अत्यधिक प्रभावी जैव-कीटनाशक बनाती है
(C) जलीय प्रणालियों में एक अत्यधिक प्रभावी बंधक (बाइंडिंग) और गाढ़ा करने वाले पदार्थ के रूप में कार्य करना
(D) जैविक तेलों की प्राकृतिक श्यानता को बदले बिना उनमें तीव्रता से घुलने की क्षमता

21. नागौर जिले का कौन सा नगर जीरा के प्रमुख व्यापारिक और प्रसंस्करण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है?
(A) मेड़ता सिटी
(B) मकराना
(C) लाडनूँ
(D) डीडवाना

22. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: राजस्थान और गुजरात मिलकर भारत के अधिकांश जीरा उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं।
कथन II: मसाला प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए वर्ष भर अत्यधिक आर्द्रता और निरंतर मानसून की स्थिति आवश्यक होती है।
सही उत्तर चुनिए:
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

23. निम्नलिखित में से कौन सा मसाला राजस्थान के शुष्क और अर्ध-शुष्क कृषि-जलवायु क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से नहीं उगाया और प्रसंस्कृत नहीं किया जाता है?
(A) जीरा
(B) काली मिर्च
(C) धनिया
(D) मेथी

24. कोटा जिले में स्थित रामगंज मंडी किस मसाले के प्रमुख प्रसंस्करण और व्यापारिक केंद्र के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है?
(A) हल्दी
(B) लाल मिर्च
(C) धनिया
(D) इलायची

25. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (मसाला प्रसंस्करण केंद्र)
P. रामगंज मंडी (कोटा)
Q. मेड़ता (नागौर)
R. मथानिया (जोधपुर)
S. छबड़ा (बारां)
सूची II: (संबंधित मसाला)
1. लाल मिर्च
2. लहसुन
3. धनिया
4. जीरा
(A) P-4, Q-3, R-2, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

26. राजस्थान में कृषि-आधारित उद्योगों के स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है?
(A) सेब साइडर प्रसंस्करण - जैसलमेर
(B) ईसबगोल प्रसंस्करण - जालौर
(C) किन्नू प्रसंस्करण - श्रीगंगानगर
(D) सोयाबीन प्रसंस्करण - कोटा

27. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना के तहत स्थापित ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क राजस्थान में कहाँ स्थित है?
(A) बोरानाडा (जोधपुर)
(B) रूपनगढ़ (अजमेर)
(C) सीतापुरा (जयपुर)
(D) भिवाड़ी (अलवर)

NODIA

28. राजस्थान में मेगा फूड पार्क योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसका उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाकर कृषि उत्पादन को

47. (D) इसने मरुस्थलीय जिलों में कपास, मूंगफली और गेहूं जैसी नकद फसलों के आगमन को सुगम बनाया है
इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने पश्चिमी राजस्थान के शुष्क जिलों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करके फसल विविधीकरण को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। नहरी सिंचाई के कारण किसानों ने केवल बाजरा उगाने के बजाय अब कपास, मूंगफली, गेहूं और सरसों जैसी नकद फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरु किया है। यह महत्वपूर्ण बदलाव सिद्ध हुआ है। यह सही प्रभाव है।

48. (C) P-3, Q-4, R-1, S-2
राजस्थान की बागवानी और औषधीय फसलों के उत्पादक क्षेत्र जलवायु पर आधारित हैं। श्रीगंगानगर किन्नू उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अनार की खेती बाड़मेर के शुष्क क्षेत्रों में व्यापक रुप से हो रही है। संतरा झालावाड़ की मुख्य फसल है जिसे 'राजस्थान का नागपुर' कहते हैं, जबकि ईसबगोल का प्रमुख उत्पादक जिला जालौर माना जाता है। यह सही सुमेल है।

49. (B) मूंग
राजस्थान में मूंग खरीफ ऋतु के दौरान उगाई जाने वाली एक प्रमुख दलहनी फसल है। इसकी बुआई मानसून के प्रारंभ में जून-जुलाई में की जाती है। यह कम पानी में शीघ्र पकने वाली फसल है जो नागौर, पाली और जोधपुर जैसे जिलों में बहुतायत से बोई जाती है। इसके विपरीत चना, मसूर और मटर रबी ऋतु की दालें हैं। यह सही है।

50. (D) चना
चना एक दलहनी फसल है, जिसकी जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करने की क्षमता रखते हैं। यह प्रक्रिया भूमि की उर्वरता और पोषक तत्वों के स्तर में सुधार करती है। इसी कारण राजस्थान की कृषि प्रणाली में मृदा स्वास्थ्य सुधारने हेतु चने को फसल चक्र का अनिवार्य घटक माना जाता है। यह लाभकारी है।

51. (A) देशी कपास छोटे रेशे वाली स्वदेशी कपास है, जबकि नरमा मध्यम/लंबे रेशे वाली अमेरिकी कपास है
राजस्थान में उगाई जाने वाली "देशी कपास" छोटे एवं मोटे रेशे वाली स्वदेशी किस्म है जो कम पानी में भी सहनशील है। इसके विपरीत "नरमा" अमेरिकन प्रजाति की कपास है जिसके रेशे मध्यम से लंबे, सफेद और महीन होते हैं। नरमा की खेती मुख्य रुप से उत्तरी सिंचित जिलों में नहरी जल की सहायता से की जाती है। यह मुख्य अंतर है।

52. (A) I, II और III
कोटा-बारां-झालावाड़ क्षेत्र धनिया उत्पादन के कारण "मसाला कटोरा" कहलाता है। नागौर और जोधपुर जिले जीरा उत्पादन की प्रमुख पट्टी का निर्माण करते हैं। नागौर में कसूरी मेथी की व्यावसायिक खेती बड़े पैमाने पर होती है। शुष्क जलवायु बीजीय मसालों के विकास में सहायक होती है, न कि बाधक। अतः पहले तीनों कथन पूर्णतः सत्य पाए जाते हैं। यह सही उत्तर है।

53. (A) अपर्याप्त और परिवर्तनशील जल की उपलब्धता
राजस्थान में कृषि उत्पादकता के समक्ष सबसे बड़ी और गंभीर चुनौती जल की सीमित एवं अनिश्चित उपलब्धता है। राज्य में मानसूनी वर्षा अत्यंत कम, अनिश्चित और स्थान के अनुसार असमान होती है, तथा भूजल का स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। पर्याप्त जल के अभाव में कृषि का विकास तथा फसल चक्र निरंतर प्रभावित होता रहता है। यह मुख्य बाधक है।

54. (D) गेहूं - श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर जिला राजस्थान में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिस कारण इसे राज्य का "अन्न का कटोरा" भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर और भाखड़ा नहर से मिलने वाली नहरी सिंचाई के कारण यहाँ गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त होता है। अन्य विकल्पों में दिए गए जिले संबंधित फसलों के मुख्य उत्पादक नहीं हैं। यह सही युग्म है।

55. (B) यह पूर्व-निर्धारित क्रय मूल्यों के माध्यम से किसानों को मूल्य अस्थिरता से बचाता है
अनुबंध कृषि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें फसल की बुआई से पूर्व ही खरीद की दरें तय कर ली जाती हैं। इससे राजस्थान के किसानों को बाजार में होने वाली कीमतों की अस्थिरता और अचानक आने वाली गिरावट के वित्तीय जोखिम से सुरक्षा मिलती है। उन्हें अपनी उपज का निश्चित और उचित दाम प्राप्त होता रहता है।

56. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
बीकानेर जिला पूर्व में एक अत्यंत शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र था जहाँ केवल असिंचित फसलें ही बोई जाती थीं। किंतु इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विस्तार के पश्चात इस क्षेत्र को नियमित सिंचाई जल उपलब्ध हुआ है। इस सिंचाई सुविधा ने मूंगफली और सरसों जैसी व्यावसायिक नकद फसलों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की है। अतः कथन और कारण दोनों सत्य हैं।

57. (D) ड्रिप (टपकन) और सूक्ष्म-फव्वारा सिंचाई
जालौर और बाड़मेर जैसे शुष्क जिलों में सीमित जल संसाधनों के कुशल उपयोग हेतु अनार की बागवानी में ड्रिप (टपकन) और सूक्ष्म-फव्वारा सिंचाई पद्धतियों को व्यापक स्तर पर अपनाया गया है। यह तकनीक पौधों की जड़ों तक सीधे जल पहुँचाती है, जिससे वाष्पीकरण द्वारा जल हानि रुकती है और अनार का प्रचुर उत्पादन संभव हो पाता है। यह सर्वोत्तम विधि है।

58. (A) कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)
भारत में विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करने हेतु "कृषि लागत और मूल्य आयोग" (CACP) द्वारा सिफारिशें भेजी जाती हैं। यह आयोग खेती की कुल लागत, बाजार दरों, मांग तथा आपूर्ति के आंकड़ों का मूल्यांकन करके मूल्य तय करता है। इन सिफारिशों के आधार पर ही सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है। यह संवैधानिक व्यवस्था है।

Click Here to Buy book on Flipkart

11. (A) प्रथम
राजस्थान संपूर्ण भारत में सरसों और राई का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल सरसों उत्पादन का लगभग 40% से अधिक हिस्सा अकेला योगदान करता है। पूर्वी एवं उत्तरी राजस्थान के जिले जैसे भरतपुर, अलवर, श्रीगंगानगर इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। शुष्क रबी जलवायु राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर बनाए रखने में सहायता करती है।

12. (B) कपास
"नरमा" राजस्थान में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली अमेरिकन कपास की एक उन्नत और लंबे रेशे वाली किस्म है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जैसे उत्तरी सिंचित जिलों में होता है जहाँ नहरों से पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है। यह व्यावसायिक नकद फसल कपड़ा उद्योग के लिए उच्च गुणवत्ता वाला सूत प्रदान करने हेतु जानी जाती है।

13. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
राजस्थान की विभिन्न फसलों के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र उनकी स्थानीय जलवायु पर निर्भर हैं। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन भरतपुर में होता है। धनिया का उत्पादन हाड़ौती क्षेत्र के बारां जिले में केंद्रित है। मक्का मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में उगाई जाती है, जबकि जीरे का उत्पादन पश्चिमी शुष्क जिले जोधपुर में प्रचुर मात्रा में होता है।

14. (C) लूणकरणसर
बीकानेर जिले के लूणकरणसर क्षेत्र को "राजस्थान का राजकोट" कहा जाता है। गुजरात का राजकोट शहर मूंगफली के प्रचुर उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है, और ठीक उसी प्रकार लूणकरणसर में इंदिरा गांधी नहर के पश्चात मूंगफली का भारी उत्पादन प्रारंभ हुआ। रेतीली-दोमट मृदा और नहरी सिंचाई के कारण यहाँ उत्पादित मूंगफली की उपज राज्य में सर्वोच्च पाई जाती है।

15. (D) नागौर
राजस्थान में बीकानेर जिला मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, किंतु नागौर जिला भी राज्य के दूसरे प्रमुख मूंगफली उत्पादक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। नागौर की हलकी बलुई-दोमट मिट्टी मूंगफली की फलियों के विकास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नलकूपों और फव्वारा सिंचाई पद्धतियों के कारण नागौर में मूंगफली का व्यावसायिक उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है।

16. (C) ग्वार (क्लस्टर बीन)
राजस्थान भारत के कुल ग्वार उत्पादन का लगभग 70 से 80 प्रतिशत हिस्सा अकेले उत्पादित करता है, जिससे राज्य का इस जिंस पर लगभग एकाधिकार स्थापित है। ग्वार एक शुष्क जलवायु वाली फसल है जो बहुत कम पानी और रेतीली मिट्टी में भी आसानी से उग सकती है। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर इसके सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में हैं।

17. (B) व्यावसायिक खाद्य प्रसंस्करण और हाइड्रोलिक फ्रेक्चरिंग में प्रयुक्त ग्वार गम
ग्वार के बीजों से "ग्वार गम" नामक गोंद निकाला जाता है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अत्यधिक मांग है। इस गम का उपयोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में तथा पेट्रोलियम उद्योग में शेल गैस निष्कर्षण की फ्रेक्चरिंग प्रक्रिया में किया जाता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज़ और औषधि उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है, जिससे ग्वार एक प्रमुख निर्यात फसल बन गई है।

18. (C) केवल I और III
राजस्थान में बाजरा बोए गए कुल क्षेत्रफल के आधार पर खरीफ मौसम की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। यह फसल थार मरुस्थल की शुष्क जलवायु, कम वर्षा और रेतीली मिट्टी के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें सूखे को सहन करने की क्षमता होती है। बाजरे को भारी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, अत्यधिक जलभराव से फसल नष्ट हो जाती है। अतः सही है।

19. (A) जोधपुर, नागौर और बाड़मेर
राजस्थान के पश्चिमी अर्ध-शुष्क जिले जोधपुर, नागौर और बाड़मेर संयुक्त रूप से राज्य की प्रसिद्ध "जीरा पट्टी" का निर्माण करते हैं। इस क्षेत्र में रबी मौसम के दौरान पाई जाने वाली शुष्क एवं ठंडी जलवायु तथा अच्छी मिट्टी जीरे की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। यहाँ उत्पादित जीरा उच्च सुगंध के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यह प्रमुख बेल्ट है।

20. (C) हाड़ौती क्षेत्र (कोटा, बारां, झालावाड़)
राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ आते हैं, को धनिया के प्रचुर उत्पादन के कारण राज्य का "मसाला कटोरा" कहा जाता है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली उपजाऊ काली दोमट मृदा और नदियों से सिंचाई की उपलब्धता धनिया की खेती के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करती हैं। यहाँ से प्रचुर उत्पादन प्राप्त होता है।

21. (A) मेथी
नागौर जिले का ताऊसर गांव पूरे भारत में अपनी विशेष सुगंधित कसूरी मेथी (पान मेथी) के उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। इस गाँव और इसके आसपास के क्षेत्रों में उगाई जाने वाली पान मेथी अपनी विशिष्ट तीखी सुगंध तथा उच्च गुणवत्ता के कारण जानी जाती है। ताऊसर की मेथी की मांग देश-विदेश में अत्यधिक बनी रहती है। यह लाभदायक फसल है।

22. (D) पूर्वी राजस्थान नलकूपों और कुओं का उपयोग करता है, जबकि पश्चिमी कृषि IGNP जैसी नहर प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर है
राजस्थान की सिंचाई रुपरेखा में क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। पूर्वी और मध्य-पूर्वी जिलों में भूजल स्तर अपेक्षाकृत बेहतर होने के कारण फसलों की सिंचाई मुख्य रूप से कुओं और नलकूपों से की जाती है। इसके विपरीत, पश्चिमी राजस्थान का भूजल अत्यधिक गहरा एवं खारा है, जिससे वहाँ की कृषि इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर अत्यधिक आश्रित रहती है। यह अंतर स्पष्ट है।

NODIA

नमी बनाए रखने की असाधारण क्षमता होती है, जो धनिया के पौधों के विकास और बीजों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। यह मुख्य कारण है।

72. (B) I, III और IV
चना राजस्थान में शीतकाल में उगाई जाने वाली एक प्रमुख रबी दलहनी फसल है। बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। चने की फसल अपनी जड़ों द्वारा नाइट्रोजन स्थिर करके मृदा की क्षमता बढ़ाती है। चने को कम पानी चाहिए, अत्यधिक सिंचाई इसके लिए हानिकारक है। अतः कथन I, III और IV पूर्णतः सत्य पाए जाते हैं। यह सही है।

73. (D) जलभराव और मृदा लवणता (सेम की समस्या)
इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में अत्यधिक नहरी सिंचाई और जल के रिसाव के कारण भूजल स्तर सतह के अत्यंत निकट आ गया है। इससे कृषि भूमि पर जलभराव और मृदा क्षारीयता (सेम की समस्या) का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। मिट्टी में लवणों के एकत्र होने से भूमि की उपजाऊ क्षमता नष्ट हो रही है। यह नकारात्मक प्रभाव है।

74. (A) रूपांतरण अवधि के दौरान वर्मीकंपोस्ट और जैव-कीटनाशकों का उपयोग करके रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना
रसायन आधारित खेती से जैविक प्रणाली में स्थानांतरण हेतु एक निश्चित रूपांतरण समय लगता है। इस दौरान रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग को क्रमबद्ध रूप से घटाकर उनके स्थान पर वर्मीकंपोस्ट, जैव-उर्वरक और प्राकृतिक तरीकों को अपनाया जाता है। यह तरीका मृदा के जैविक स्वास्थ्य को पुनः स्थापित करने का सबसे वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक मार्ग माना जाता है। यह सही है।

75. (B) रबर
रबर एक उष्णकटिबंधीय पौधे से प्राप्त होने वाला उत्पाद है जिसकी खेती के लिए अत्यधिक वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। राजस्थान की शुष्क एवं कम वर्षा वाली भौगोलिक परिस्थितियां रबर उत्पादन के सर्वथा प्रतिकूल हैं। अतः रबर राजस्थान के कृषि निर्यात का हिस्सा नहीं है, जबकि ग्वार गम, जीरा और धनिया प्रमुख निर्यात वस्तुएं हैं। यह सही है।

76. (A) केवल I और II
पश्चिमी राजस्थान के सुदूर क्षेत्रों में कृषि मंडियों की अधिक दूरी किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ई-नाम योजना मंडियों के डिजिटल एकीकरण हेतु शुरु की गई है। निजी व्यापारियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं होता। इसलिए दिए गए कथनों में केवल I और II सही पाए जाते हैं। यह सही है।

77. (A) संतरा - झालावाड़
झालावाड़ जिला राजस्थान में संतरे के उत्पादन में शीर्ष स्थान रखता है। इस जिले की उपजाऊ काली मिट्टी और पर्याप्त वर्षा के कारण यहाँ संतरे का भारी उत्पादन दर्ज किया जाता है, जिससे इसे 'राजस्थान का नागपुर' कहा जाता है। अन्य विकल्पों में दिए गए फल राज्य की जलवायु के अनुकूल नहीं हैं। अतः यह सही सुमेलित युग्म माना जाता है।

78. (C) हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर
इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के उत्तरी भाग में प्रवेश करके दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर बहती है। मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण की ओर नहरी सिंचाई प्राप्त करने वाले जिलों का सही क्रम हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर है। नहर सर्वप्रथम हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है तथा इसका अंतिम बिंदु बाड़मेर जिले में स्थित है। यह भौगोलिक अनुक्रम है।

79. (D) यह जीरा, धनिया और मेथी जैसे बीजीय मसालों का अग्रणी उत्पादक है
राजस्थान भारत में बीजीय मसालों के कुल उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान रखता है। राज्य जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ और ईसबगोल जैसी मसाला फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान का शुष्क और ठंडा रबी मौसम बीजीय मसालों में सुगंधित तेलों के विकास के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करता है। यह इसकी मुख्य विशेषता को प्रदर्शित करता है।

80. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
सुदूर पश्चिमी राजस्थान के किसानों को अपनी कृषि उपज का उचित और लाभप्रद मूल्य प्राप्त करने में निरंतर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण नियमित कृषि मंडियों की अत्यधिक दूरी होना है, जिससे उच्च परिवहन लागत उनके शुद्ध लाभ मार्जिन को अत्यधिक घटा देती है। अतः दिया गया कथन और कारण दोनों सत्य हैं। यह सही है।

NODIA

www.nodia.in

59. (B) जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, दौसा
राजस्थान के मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए जिलों का सही क्रम जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और दौसा है। थार मरुस्थल में स्थित जैसलमेर राज्य के सुदूर पश्चिमी भाग में है, इसके पूर्व में क्रमशः जोधपुर, जयपुर तथा दौसा स्थित हैं। यह भौगोलिक क्रम ग्वार उत्पादक क्षेत्रों की स्थिति को सटीक रुप से प्रदर्शित करता है। यह सही है।

60. (B) नकद फसलों में स्वतः उत्परिवर्तन (म्यूटेशन)
खराब गुणवत्ता के बीजों के उपयोग से फसल उत्पादकता में गिरावट आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और फसल का पकना असमान हो जाता है। परंतु, निम्न गुणवत्ता वाले बीजों के कारण नकद फसलों में किसी प्रकार का 'स्वतः उत्परिवर्तन' (म्यूटेशन) घटित नहीं होता। उत्परिवर्तन एक अलग आनुवंशिक प्रक्रिया है। अतः यह इसका परिणाम नहीं माना जाता है।

61. (C) केवल I और III
इंदिरा गांधी नहर ने पश्चिमी राजस्थान में शुष्क फसलों से नकद फसलों की ओर बदलाव को सुगम बनाया है तथा श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ में गेहूं व कपास की बड़े पैमाने पर खेती संभव बनाई है। हालांकि, अत्यधिक सिंचाई से जलभराव और मृदा लवणता (सेम की समस्या) में वृद्धि हुई है, कमी नहीं। अतः केवल I और III सत्य पाए जाते हैं।

62. (C) कपास
कपास के सफल विकास के लिए लगभग 210 पाला-रहित दिनों और खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। अत्यधिक ठंड या पाला इसके डोडे और रेशे की गुणवत्ता को नष्ट कर देता है। इस विशिष्ट जलवायु मांग के कारण ही राजस्थान में कपास का उत्पादन केवल उन सिंचित जिलों तक सीमित है जहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। यह सटीक उत्तर है।

63. (D) चूरू
राजस्थान में मक्का का मुख्य उत्पादन दक्षिणी जिलों जैसे बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में केंद्रित है। इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली लाल दोमट मिट्टी मक्का के अनुकूल है। चूरू जिला अत्यंत शुष्क मरुस्थलीय जलवायु और बालू मिट्टी वाला क्षेत्र है जहाँ मक्का की खेती नहीं की जाती है, बल्कि यहाँ बाजरा उगाने की प्रधानता पाई जाती है। यह भिन्न है।

64. (C) प्रमुख नियमित बाजारों तक परिवहन की अधिक दूरी
जैसलमेर और बाड़मेर जैसे पश्चिमी सीमावर्ती मरुस्थलीय जिलों में गांवों से प्रमुख नियमित कृषि मंडियों की दूरी अत्यधिक अधिक है। इस बड़ी दूरी के कारण किसानों को अपनी कृषि उपज को मंडियों तक ले जाने में भारी परिवहन खर्च उठाना पड़ता है। उच्च परिवहन लागत उनके शुद्ध लाभ को काफी कम कर देती है, जो मुख्य बाधक सिद्ध होती है।

65. (A) 3, 1, 4, 2
राजस्थान में किसी भी खरीफ फसल के उत्पादन चक्र में कृषि कार्यों का सही क्रम इस प्रकार है: सर्वप्रथम जुताई करके खेत की तैयारी की जाती है। इसके बाद अनुकूल नमी मिलने पर बीजों की बुआई होती है। तत्पश्चात खरपतवार नियंत्रण हेतु निराई-गुड़ाई की जाती है और अंत में परिपक्व फसल की कटाई संपादित की जाती है। यह तार्किक क्रम है।

66. (D) इसके अंकुरण के लिए जलभराव की स्थिति आवश्यक है
चना राजस्थान की एक प्रमुख रबी दलहनी फसल है, जो बीकानेर और चूरू जैसे जिलों में प्रचुरता से उगाई जाती है। यह फसल कम सिंचाई में भी अच्छा उत्पादन देती है। चने के बीजों के अंकुरण तथा विकास के लिए जलभराव की स्थिति हानिकारक होती है, न कि आवश्यक। जलभराव से जड़ें सड़ जाती हैं। अतः चौथा कथन गलत है।

67. (A) रबी और खरीफ के बीच उगाई जाने वाली सिंचित ग्रीष्मकालीन फसलें
राजस्थान के कृषि चक्र में "जायद" वह अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है, जो मुख्य रबी फसलों की कटाई के बाद तथा खरीफ की बुआई से पूर्व मार्च से जून के मध्य आती है। इस मौसम में सिंचाई के साधनों पर निर्भर रहकर मुख्य रुप से फल, सब्जियां, तरबूज तथा हरा चारा उगाया जाता है। यह सही अर्थ को दर्शाता है।

68. (C) अलवर
पूर्वी राजस्थान का अलवर जिला अपनी कृषि सिंचाई के लिए मुख्य रुप से नलकूपों और कुओं पर निर्भर है। इस जिले में नलकूप सिंचाई का सघन ढांचा विकसित है, जिसकी सहायता से किसान रबी ऋतु में सरसों, गेहूं तथा विभिन्न सब्जियों का बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन करते हैं। यह जिला नलकूप सिंचाई में अग्रणी माना जाता है। यह सही है।

69. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
विभिन्न कृषि शब्दावलियों की सटीक परिभाषाएं उनके विशिष्ट कार्यों को स्पष्ट करती हैं। बीज प्रतिस्थापन दर पुराने बीजों की तुलना में प्रमाणित बीजों के उपयोग का अनुपात है। अनुबंध कृषि पूर्व-सहमत मूल्य पर फसल क्रय की व्यवस्था है। जैविक खेती रासायनिक इनपुट के बिना की जाने वाली कृषि है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा तय गारंटीकृत मूल्य है। यह सही है।

70. (D) कपास
कपास उत्तरी राजस्थान के नहरी सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाने वाली एक प्रमुख व्यावसायिक नकद फसल है। इसके सफल उत्पादन के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है। पश्चिमी असिंचित थार मरुस्थल में जल स्रोतों की कमी और अत्यधिक शुष्कता के कारण कपास की खेती करना संभव नहीं है। अतः यह मरुस्थल में अनुपस्थित पाई जाती है। यह सही है।

71. (B) काली दोमट मिट्टी और उपयुक्त वर्षा इसके अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं
दक्षिण-पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाने वाली उपजाऊ काली दोमट मिट्टी तथा पर्याप्त मानसूनी वर्षा धनिया की खेती के लिए अत्यधिक अनुकूल स्थितियां प्रदान करती हैं। काली मृदा में

Downloaded from www.pdf.tube

(B) बांसवाड़ा और डूंगरपुर को शामिल करने वाली दक्षिणी जनजातीय पट्टी
(C) भरतपुर, अलवर और धौलपुर को शामिल करने वाले पूर्वी जिले
(D) अजमेर, टोंक और राजसमंद को शामिल करने वाली मध्य जिला पट्टी

9. सरसों प्रसंस्करण उद्योग में भरतपुर को क्या विशिष्ट लाभ प्राप्त है?
(A) यहाँ राज्य की सबसे अधिक वार्षिक वर्षा होती है, जिससे वर्ष भर निरंतर सरसों की खेती सुनिश्चित होती है।
(B) इसे प्रमुख गहरे समुद्री बंदरगाह टर्मिनलों से लाभ मिलता है, जिससे प्रसंस्कृत सरसों के तेल का सीधा थोक निर्यात संभव होता है।
(C) यह पड़ोसी देशों से आयातित सरसों के बीज की बड़ी मात्रा पर अत्यधिक निर्भर करता है।
(D) यहाँ ICAR-सरसों अनुसंधान निदेशालय (DRMR) स्थित है और कच्चे माल की प्रचुर आपूर्ति उपलब्ध है।

10. राजस्थान में खाद्य तेल उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राजस्थान भारत में सरसों के तेल के प्रमुख उत्पादकों में से एक है।
II. इस उद्योग की विशेषता "भार-वृद्धि" उद्योग के रूप में है, जो दूरस्थ बाजारों पर अत्यधिक निर्भर है।
III. राज्य में अधिकांश खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाइयाँ कच्चे माल के उत्पादक क्षेत्रों के निकट स्थित हैं।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

11. 1932 में स्थापित राजस्थान की पहली चीनी मिल, "द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड", कहाँ स्थापित की गई थी?
(A) केशवरायपाटन
(B) भोपालसागर
(C) श्रीगंगानगर
(D) सूरतगढ़

12. गन्ने के अलावा, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल द्वारा चीनी उत्पादन के लिए ऐतिहासिक रूप से किस वैकल्पिक कच्चे माल का प्रसंस्करण किया गया है?
(A) मीठा ज्वार
(B) चुकंदर
(C) ताड़ का रस
(D) मीठी मक्का

13. राजस्थान में चीनी उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) राजस्थान अपने घरेलू स्तर पर उत्पादित अधिकांश चीनी का यूरोपीय देशों को निर्यात करता है।
(B) उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तुलना में यह अत्यधिक सीमित है।
(C) यह उद्योग मुख्य रूप से गन्ने पर निर्भर है, जो अत्यधिक जल-गहन फसल है।
(D) राज्य में चीनी मिलें अधिकांशतः सिंचित क्षेत्रों या ऐतिहासिक देशी रियासतों में केंद्रित हैं।

14. राजस्थान में सहकारी आंदोलन के तहत डेयरी विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए शीर्ष निकाय कौन सा है?
(A) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड
(B) राजस्थान राज्य एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन
(C) राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF)
(D) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड राजस्थान शाखा

15. राजस्थान में डेयरी प्रसंस्करण उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह आनंद प्रारूप के रूप में जाने जाने वाले त्रि-स्तरीय सहकारी ढांचे पर कार्य करता है।
II. प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ गाँव के स्तर पर कार्य करती हैं।
III. जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ जिला स्तर पर प्रसंस्करण और खरीद का प्रबंधन करते हैं।
IV. यह क्षेत्र केवल दूध का प्रसंस्करण करता है और घी तथा पनीर जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण को प्रतिबंधित करता है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

16. राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF) अपने प्रसंस्कृत दूध और दुग्ध उत्पादों का विपणन किस ब्रांड नाम के तहत करता है?
(A) अमूल
(B) सुधा
(C) सरस
(D) पयस

NODIA

17. उद्योग की प्रकृति के आधार पर बेमेल की पहचान कीजिए:
(A) सूती ओटाई (जिनिंग) कार्य
(B) पोर्टलैंड सीमेंट उद्योग
(C) चीनी मिलिंग कार्य
(D) ग्वार गम प्रसंस्करण इकाइयाँ

18. राजस्थान का कौन सा जिला ग्वार गम प्रसंस्करण के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र के रूप में विकसित हुआ है?
(A) बांसवाड़ा
(B) भरतपुर
(C) प्रतापगढ़

अध्याय 13
राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग

1. कृषि-आधारित उद्योग को निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है?
   (A) ऐसा उद्योग जो कृषि मशीनरी और उर्वरकों का निर्माण करता है
   (B) ऐसा उद्योग जो पौधों और पशुओं से प्राप्त कृषि उत्पादों का उपयोग अपने प्राथमिक कच्चे माल के रूप में करता है
   (C) ऐसा उद्योग जो विशेष रूप से कृषि सहकारी समितियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है
   (D) ऐसा उद्योग जो खेती के उपकरणों के लिए धात्विक खनिजों का निष्कर्षण करता है

2. कृषि-प्रसंस्करण के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक प्रसंस्करण गतिविधि माना जाता है?
   (A) कच्चे गेहूं की सफाई और श्रेणीकरण
   (B) ताजे किन्नू की छंटाई और पैकेजिंग
   (C) ताजे कटे हुए धनिए को धूप में सुखाना
   (D) गेहूं को पीसकर मैदा बनाना

3. राजस्थान में कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने का प्राथमिक सामाजिक-आर्थिक महत्व क्या है?
   (A) यह फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करता है और ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार पैदा करता है
   (B) यह पूरी ग्रामीण आबादी को शहरी महानगरों में स्थानांतरित करता है
   (C) यह कृषि क्षेत्र की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर देता है
   (D) यह शीर्ष राजस्व उत्पादक के रूप में खनिज-आधारित उद्योगों को प्रतिस्थापित करता है

4. सूती वस्त्र और कृत्रिम धागा उद्योगों के अत्यधिक संकेंद्रण के कारण किस जिले को व्यापक रूप से "वस्त्र नगरी" और "राजस्थान का मैनचेस्टर" कहा जाता है?
   (A) पाली
   (B) जोधपुर
   (C) भीलवाड़ा
   (D) जयपुर

5. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
   अभिकथन (A): भीलवाड़ा राजस्थान में सबसे बड़े सूती वस्त्र निर्माण केंद्र के रूप में उभरा है।
   कारण (R): भीलवाड़ा जिला भारत में उगाए जाने वाले कच्चे कपास के 80 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन करता है।
   (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
   (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
   (C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
   (D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

6. राजस्थान के पाली क्षेत्र में सूती वस्त्र रंगाई और छपाई उद्योग को मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय चिंता के कारण गंभीर नियामक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है?
   (A) औद्योगिक ग्रीनहाउस गैसों का अत्यधिक वायुमंडलीय उत्सर्जन, जिससे स्थानीय वायु प्रदूषण होता है
   (B) भारी मशीनों से होने वाला अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण, जिससे आसपास के वन्यजीव अभयारण्य प्रभावित होते हैं
   (C) रंगाई उष्मकों (बॉयलरों) को ईंधन देने के लिए आवश्यक अनियंत्रित वनों की कटाई, जिससे भूमि क्षरण होता है
   (D) बांडी नदी में अनुपचारित विषैले रासायनिक अपशिष्टों का विसर्जन, जिससे जल प्रदूषण होता है

7. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
   सूची I: (कृषि-आधारित उद्योग)
   P. सूती वस्त्र
   Q. सरसों का तेल
   R. चीनी
   S. ऊन प्रसंस्करण
   सूची II: (राजस्थान में प्रमुख प्रसंस्करण केंद्र)
   1. भरतपुर
   2. बीकानेर
   3. भीलवाड़ा
   4. श्रीगंगानगर
   (A) P-1, Q-3, R-2, S-4
   (B) P-3, Q-1, R-4, S-2
   (C) P-3, Q-4, R-1, S-2
   (D) P-4, Q-2, R-3, S-1

8. राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से अपने सरसों के बीज उत्पादन और उसके बाद के खाद्य तेल प्रसंस्करण उद्योगों के लिए जाना जाता है?
   (A) जैसलमेर और बाड़मेर को शामिल करने वाली शुष्क पश्चिमी पट्टी

Click Here to Buy book on Amazon

बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र प्रदान करना है।

II. यह संग्रह केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों और एक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र वाले "हब एवं स्पोक" मॉडल पर कार्य करता है।

III. यह खाद्य प्रसंस्करण में निजी क्षेत्र के उद्यमों की भागीदारी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

29. मेगा फूड पार्क की अवधारणा मूलभूत रूप से निम्नलिखित में से किसे कम करने के लिए डिज़ाइन की गई है?

(A) फसल कटाई के बाद होने वाले कृषि नुकसान
(B) कुल औद्योगिक विनिर्माण निर्यात
(C) ग्रामीण रोजगार के अवसर
(D) ताजी वस्तुओं की कुल भंडारण अवधि

30. राजस्थान के किस शहर को एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी के रूप में जाना जाता है?

(A) जैसलमेर
(B) चूरू
(C) बीकानेर
(D) सीकर

31. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।

अभिकथन (A): बीकानेर में एक अत्यधिक विकसित ऊनी धागा और कालीन बुनाई उद्योग है।

कारण (R): इस क्षेत्र में ऊन देने वाली भेड़ की नस्लों की उच्च आबादी है और यह पश्चिमी राजस्थान से कच्ची ऊन के लिए एक केंद्रीय संग्रह केंद्र के रूप में कार्य करता है।

(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

32. राजस्थान में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (CWDB) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

(A) जयपुर
(B) उदयपुर
(C) जोधपुर
(D) अजमेर

33. राजस्थान में ऊन-आधारित उद्योग के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।

(A) राजस्थान लगातार भारत के कुल वार्षिक कच्चे ऊन उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा योगदान देता है।
(B) राजस्थान में उत्पादित सभी कच्चे ऊन की खपत स्थानीय स्तर पर शून्य अंतरराज्यीय व्यापार के साथ होती है।
(C) राजस्थान की ऊन का एक बड़ा हिस्सा मोटे प्रकार का होता है, जो कालीन निर्माण इकाइयों के लिए आदर्श है।
(D) ऊन क्षेत्र ग्रामीण पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण टिकाऊ आजीविका और रोजगार पैदा करता है।

34. वेबर के औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत के आधार पर, राजस्थान में चीनी मिलें (जैसे श्रीगंगानगर में) गन्ना उत्पादक खेतों के निकट क्यों स्थित हैं?

(A) गन्ना प्रसंस्करण के दौरान एक भार-वर्धक कच्चा माल है
(B) तैयार उत्पाद के रूप में चीनी को तत्काल प्रशीतित करने की आवश्यकता होती है
(C) गन्ना किसान अपनी उपज को गाँव की सीमाओं से बाहर ले जाने से इनकार करते हैं
(D) गन्ना एक भार-ह्रासी और शीघ्र नष्ट होने वाला कच्चा माल है

35. राजस्थान में कृषि-आधारित उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए:

I. कच्चे माल के स्रोतों से निकटता।

II. निरंतर बिजली आपूर्ति की उपलब्धता।

III. राज्य की सीमाओं के भीतर गहरे समुद्री बंदरगाह अवसंरचना तक पहुँच।

IV. शीत श्रृंखला (कोल्ड चेन) और भंडारण सुविधाओं का विकास।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

36. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट करता है कि कपास ओटाई (जिनिंग) और दबाई (प्रेसिंग) इकाइयाँ हनुमानगढ़ और गंगानगर जैसे कपास उगाने वाले क्षेत्रों में अत्यधिक केंद्रित क्यों हैं, जबकि बड़ी कपड़ा रंगाई इकाइयाँ भीलवाड़ा या पाली में हैं?

(A) जिनिंग संचालन पूरी तरह से ताजे नदी के पानी के विशाल भंडार पर निर्भर करता है जो विशेष रूप से हनुमानगढ़ में उपलब्ध है।
(B) कपड़ा रंगाई प्रक्रियाओं में अत्यंत विनाशकारी जैविक रंगों का उपयोग होता है जो तुरंत संसाधित न होने पर घंटों में नष्ट हो जाते हैं।
(C) जिनिंग एक भार-ह्रासी और कच्चे माल से बंधी प्रक्रिया है, जबकि रंगाई पूंजी, पानी और कुशल श्रम पर निर्भर करती है।
(D) सख्त प्रशासनिक राज्य नियम कानूनी रूप से सभी वस्त्र रंगाई इकाइयों को दक्षिणी राजस्थान में संचालित करने के लिए बाध्य करते हैं।

NODIA

(A) 3 - 1 - 4 - 5 - 2
(B) 1 - 3 - 4 - 5 - 2
(C) 3 - 4 - 1 - 2 - 5
(D) 4 - 3 - 1 - 5 - 2

72. राजस्थान सरकार ने किस वर्ष इस क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा देने के लिए व्यापक "राजस्थान कृषि-प्रसंस्करण, कृषि-व्यवसाय और कृषि-निर्यात प्रोत्साहन नीति" शुरू की?
(A) 2010
(B) 2015
(C) 2019
(D) 2023

73. राजस्थान कृषि-प्रसंस्करण नीति (2019) की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह पूंजीगत निवेश अनुदान (सब्सिडी) प्रदान करती है। यह नीति आवेदकों के बीच अंतर कैसे करती है?
(A) यह व्यक्तिगत किसानों को स्पष्ट रूप से बाहर करते हुए विशेष रूप से बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों को पूंजीगत अनुदान प्रदान करती है।
(B) यह अनिवार्य करती है कि औद्योगिक आवेदकों को राज्य अनुदान के लिए पात्र होने के लिए राजस्थान राज्य की सीमाओं के बाहर पंजीकृत होना चाहिए।
(C) यह परिचालन पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी पंजीकृत व्यावसायिक आवेदकों पर 10% की मानकीकृत, समान अनुदान दर लागू करती है।
(D) यह बाहरी आवेदकों की तुलना में स्थानीय किसानों, एफपीओ और राज्य के मूल निवासियों को उच्च पूंजी अनुदान प्रदान करती है।

74. राज्य की हालिया कृषि-प्रसंस्करण नीतियों के तहत विशेष प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता क्षेत्र माना जाता है?
(A) मोटे अनाज (श्रीअन्न) और वन उपज का प्रसंस्करण
(B) सिंथेटिक टेक्सटाइल कपड़ों का बड़े पैमाने पर विनिर्माण
(C) कच्चे पेट्रोलियम का व्यावसायिक निष्कर्षण और परिष्करण
(D) आयातित व्यावसायिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की असेंबली

75. एक स्नातक उद्यमी टमाटर केचप निर्माण इकाई स्थापित करना चाहता है। औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांतों के अनुसार, इस इकाई के लिए सबसे आर्थिक रूप से व्यावहारिक स्थान कौन सा है?
(A) दूरस्थ रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहाँ कच्ची भूमि अधिग्रहण की लागत न्यूनतम हो
(B) मजबूत परिवहन संपर्कों वाले टमाटर कृषि क्लस्टर के निकट
(C) परिवेशीय शीतलन का लाभ उठाने के लिए उच्च ऊंचाई वाले पर्वतीय स्थानों पर
(D) भारी औद्योगिक कोयला खनन कार्यों के ठीक निकट

76. निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि राजस्थान कृषि-प्रसंस्करण, कृषि-व्यवसाय और कृषि-निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत प्रोत्साहन के लिए स्पष्ट रूप से पात्र नहीं होगी?
(A) एक आधुनिक, उच्च क्षमता वाली वाणिज्यिक दाल मिलिंग सुविधा स्थापित करना
(B) नायलॉन जैसे कृत्रिम सिंथेटिक कपड़ों का निर्माण करना
(C) ताजे किन्नू फल के लिए विशेष शीत भंडारण अवसंरचना का निर्माण करना
(D) जीरा की यांत्रिक छंटाई और ग्रेडिंग के लिए एक एकीकृत पैक-हाउस सुविधा का संचालन करना

77. राजस्थान कृषि-प्रसंस्करण, कृषि-व्यवसाय और कृषि-निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत सब्सिडी के निष्पादन और वितरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी नोडल एजेंसी जिम्मेदार है?
(A) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड
(B) राजस्थान राज्य पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि.
(C) राजस्थान पर्यटन विकास निगम बोर्ड
(D) राज्य खान एवं भूविज्ञान निदेशालय

78. कृषि बाजारों को एकीकृत करने और कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों को देश भर से पारदर्शिता के साथ कच्चा माल खरीदने की अनुमति देने के लिए, राजस्थान की मंडियों द्वारा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल अपनाया गया है?
(A) ई-चौपाल
(B) ई-मित्र
(C) ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार)
(D) ई-प्रक्योर

79. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: राजस्थान के औद्योगिक नीति ढांचे में खाद्य प्रसंस्करण को प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया गया है।
कथन II: राज्य में प्रचुर मात्रा में कच्चा माल है लेकिन ऐतिहासिक रूप से आनुपातिक प्रसंस्करण अवसंरचना का अभाव था, जिसके कारण इसे प्राथमिकता का दर्जा मिला।
सही उत्तर चुनिए:
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

80. राजस्थान में कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त व्यापक लक्ष्य क्या है?
(A) ग्रामीण कृषि श्रमिकों को सीधे शहरी सेवा क्षेत्र के रोजगार में व्यवस्थित रूप से स्थानांतरित करना।
(B) केंद्रीकृत राज्य सरकार के नियंत्रण के तहत सभी निजी कृषि जोतों का कानूनी रूप से राष्ट्रीयकरण करना।
(C) किसानों की आय दोगुनी करना, फसल के नुकसान को कम करना और ग्रामीण उद्योग का विस्तार करना।
(D) पड़ोसी भारतीय राज्यों से सभी प्रसंस्कृत पैक्ड भोजन के आयात पर राज्य की निर्भरता को स्थानांतरित करना।

Downloaded from www.pdf.tube

प्रतिबंधित करते हैं।
(D) मुख्य अनाजों और दालों के प्रसंस्करण कार्यों में ताजे फलों की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है।

46. डेयरी किसानों की सहायता के लिए सहकारी रूप से प्रबंधित राजस्थान में बड़े पैमाने पर पशु आहार निर्माण संयंत्रों का सीधा संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है?
(A) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO)
(B) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC)
(C) राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF)
(D) निवेश संवर्धन ब्यूरो (BIP)

47. निम्नलिखित में से कौन सा चारा-आधारित कृषि-उद्योग में पशु आहार की परिवहन क्षमता और भंडारण अवधि को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया की सटीक पहचान करता है?
(A) सूखे कृषि भूसे का ईंधन एथेनॉल में बड़े पैमाने पर सूक्ष्मजीव किण्वन
(B) सूखी चारा घास की रासायनिक रंगाई ताकि इसकी दृश्य बाज़ार अपील को बढ़ाया जा सके
(C) खेत के गेहूं के अवशेषों से वाष्पशील आवश्यक तेलों का औद्योगिक निष्कर्षण
(D) सूखे फसल चारे की सघन छर्रों में यांत्रिक गठरी बनाना (बेलिंग) और संघनन

48. राजस्थान में पशु आहार और चारा उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह आंतरिक रूप से राजस्थान की बड़ी पशुधन आबादी से जुड़ा हुआ है।
II. प्रसंस्कृत पशु आहार डेयरी पशुओं के लिए पोषण संबंधी संतुलित आहार सुनिश्चित करता है, जिससे दूध की उपज में सुधार होता है।
III. चारा बैंक और प्रसंस्करण इकाइयाँ बार-बार पड़ने वाले सूखे के प्रभावों को कम करने में मदद करती हैं।
IV. यह उद्योग विशेष रूप से तटीय राज्यों से आयातित कच्चे माल पर निर्भर है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

49. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, दाल मिलों, तेल मिलों और कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियों जैसी कृषि-प्रसंस्करण इकाइयाँ मुख्य रूप से किस विशिष्ट प्रकार का रोजगार उत्पन्न करती हैं?
(A) प्राथमिक कृषि रोजगार
(B) ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार
(C) शहरी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र रोजगार
(D) भारी धातुकर्म रोजगार

50. निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर राजस्थान में लघु और मध्यम कृषि-आधारित उद्योगों के लिए एक प्रमुख परिचालन चुनौती के रूप में उद्धृत नहीं किया जाता है?
(A) औद्योगिक बिजली आपूर्ति के लिए बार-बार व्यवधान और अत्यधिक उच्च शुल्क दरें
(B) कम ब्याज वाले, संस्थागत कार्यशील पूंजी ऋण हासिल करने में गंभीर प्रशासनिक कठिनाइयाँ
(C) अपर्याप्त सड़क अवसंरचना और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर लॉजिस्टिकल माल ढुलाई कनेक्टिविटी
(D) कम लागत वाले, अत्यधिक कुशल रोबोटिक्स इंजीनियरों और स्वचालन विशेषज्ञों की स्थानीय अत्यधिक आपूर्ति

NODIA

51. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): छोटे पैमाने की कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों को अक्सर गंभीर कार्यशील पूंजी की कमी का सामना करना पड़ता है।
कारण (R): कृषि कच्चे माल का खरीद सीजन कम होता है, जिसके लिए इकाइयों को थोक खरीदारी करने और वर्ष भर कच्चे माल का भंडारण करने की आवश्यकता होती है।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

52. राजस्थान से निर्यात-उन्मुख प्रमुख प्रसंस्कृत वस्तुओं की निम्नलिखित सूची में से बेमेल की पहचान कीजिए:
(A) परिष्कृत ग्वार गम स्प्लिट पाउडर और व्युत्पन्न औद्योगिक म्यूसिलेज
(B) जीरा और धनिया सहित मूल्यवर्धित पिसे हुए मसालों के मिश्रण
(C) प्रसंस्कृत आयामी पत्थर जैसे परिष्कृत संगमरमर (मार्बल) और ग्रेनाइट
(D) हाथ से बने पारंपरिक ऊनी कालीन और बुने हुए गलीचे

53. राज्य में कृषि यांत्रीकरण और कृषि-उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन (RSAIC) की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
(A) 1956
(B) 1969
(C) 1980
(D) 1991

54. राजस्थान राज्य एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की प्राथमिक पारंपरिक भूमिका क्या रही है?
(A) राज्य के वित्तीय एक्सचेंजों में इक्विटी ट्रेडिंग और शेयर बाजार के लेनदेन को विनियमित करना।
(B) राज्य के विभागों के लिए प्रशासनिक सिविल सेवा

प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करना।
(C) प्रमुख शहरों में नगरपालिका जल आपूर्ति वितरण अवसंरचना की देखरेख और प्रबंधन करना।
(D) कृषि मशीनों का वितरण करना और स्थानीय किसानों को कस्टम हायरिंग उपकरण सेवाएं प्रदान करना।

55. एक विशिष्ट चीनी मिल में चीनी उत्पादन के मानक चरणों को सही तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. अपकेंद्रीकरण (शीरे से चीनी के क्रिस्टल अलग करना)
2. रस निकालने के लिए गन्ने की पेराई
3. श्रेणीकरण और पैकेजिंग
4. गाढ़ा रस बनाने के लिए रस का स्पष्टीकरण और वाष्पीकरण
5. क्रिस्टलीकरण (क्रिस्टल बनाने के लिए रस को उबालना)

सही कूट का चयन कीजिए:
(A) 2 - 4 - 5 - 1 - 3
(B) 2 - 5 - 4 - 1 - 3
(C) 4 - 2 - 5 - 1 - 3
(D) 2 - 1 - 4 - 5 - 3

56. राजस्थान के किस प्रसंस्कृत कृषि-उत्पाद में मुख्य रूप से इसके औषधीय गुणों और आहार फाइबर के रूप में उपयोग के कारण अत्यधिक लाभदायक निर्यात क्षमता है?
(A) संवर्धित परिष्कृत गेहूं का आटा
(B) लंबे रेशे वाला कच्चा कपास का रेशा
(C) ईसबगोल का बीज
(D) महीन प्रसंस्कृत परिष्कृत चीनी

57. कृषि-औद्योगिक प्रसंस्करण क्लस्टर और उसके प्राथमिक उत्पाद का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है?
(A) रामगंज मंडी (कोटा) - ग्वार गम प्रसंस्करण
(B) बीकानेर - कॉटन जिनिंग
(C) हनुमानगढ़ - संतरा प्रसंस्करण
(D) आबू रोड (सिरोही) - ईसबगोल प्रसंस्करण

58. राजस्थान से ग्वार गम के निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप में बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है।
II. इसकी निर्यात मात्रा वैश्विक पेट्रोलियम और फ्रैकिंग उद्योग में उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
III. राजस्थान का भारत के कुल ग्वार उत्पादन में 10% से भी कम हिस्सा है, जो इसकी निर्यात क्षमता को सीमित करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

59. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (कृषि-उद्योग का प्रकार)
P. वस्त्र
Q. डेयरी
R. खाद्य तेल
S. चीनी

सूची II: (प्राथमिक कच्चा माल स्रोत)
1. गन्ना/चुकंदर
2. सरसों/सोयाबीन के बीज
3. कपास का रेशा
4. कच्चा दूध

(A) P-4, Q-3, R-1, S-2
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-3, Q-2, R-4, S-1
(D) P-1, Q-4, R-2, S-3

60. स्थानीय प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए, सरकार "कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर" पर जोर देती है। ऐसे क्लस्टर की मूल परिभाषा क्या है?
(A) एक बहुराष्ट्रीय निगम के स्वामित्व वाली एक विशाल, लंबवत एकीकृत औद्योगिक प्रसंस्करण सुविधा
(B) जुड़े हुए कृषि-व्यवसायों, आपूर्तिकर्ताओं और सहायक संस्थानों का एक भौगोलिक केंद्र
(C) विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि मेलों के दौरान स्थापित एक मौसमी, अस्थायी व्यापार बाजार
(D) प्रत्यक्ष कृषि कर संग्रह का प्रबंधन करने वाला एक विशेष नगरपालिका प्रशासनिक सरकारी कार्यालय

61. प्राथमिक कृषि-औद्योगिक कच्चे माल और राजस्थान में इसके प्रमुख उत्पादक जिले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है?
(A) गन्ना - जैसलमेर जिला
(B) व्यावसायिक सोयाबीन - बारां जिला
(C) गुणवत्तापूर्ण मूंगफली - बीकानेर क्षेत्र
(D) पीली सरसों - अलवर पट्टी क्षेत्र

62. कृषि उपज के संदर्भ में "मूल्य संवर्धन" का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है?
(A) कच्चे गेहूं को तीन वर्ष के लिए गोदाम में भंडारित करके रखना
(B) कच्चे टमाटरों को सीधे खेत से स्थानीय सब्जी विक्रेता तक पहुँचाना
(C) ताजे टमाटरों को पैक्ड केचप और प्यूरी में बदलना
(D) फसल के अवशेषों को वापस मिट्टी में जोतना

63. कृषि-आधारित उद्योगों के संबंध में कृषि उपज मंडी समितियों (KUMS) का प्राथमिक कार्य क्या है?
(A) वे सीधे वाणिज्यिक कृषि सहकारिताओं को भारी बिजली मशीनरी का निर्माण और वितरण करती हैं।
(B) वे निगमों को दीर्घकालिक ऋण देने वाली विशेष राज्य

Click Here to Buy book on Flipkart

बैंकिंग संस्थाओं के रूप में कार्य करती हैं।
(C) वे शहरी बाज़ारों में सभी प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों पर मूल्य सीमाओं को सख्ती से नियंत्रित और लागू करती हैं।
(D) वे प्रत्यक्ष, नीलामी-आधारित कच्चे माल की खरीद के लिए विनियमित बाज़ार प्रांगण प्रदान करती हैं।

64. राजस्थान में नियामक ढांचे के तहत, कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा एकत्र किए गए बाजार शुल्क (मंडी टैक्स) का मुख्य रूप से उपयोग कैसे किया जाता है?
(A) राष्ट्रीय रक्षा कोष और केंद्रीय सैन्य व्यय खातों में पूरी तरह से स्थानांतरित किया जाता है।
(B) पंजीकृत निजी आढ़तियों (कमीशन एजेंटों) के बीच मौसमी नकद लाभ लाभांश के रूप में सीधे वितरित किया जाता है।
(C) मंडी अवसंरचना, किसान सुविधाओं और जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कों में पुनर्निवेश किया जाता है।
(D) अकादमिक कृषि वैज्ञानिकों के वार्षिक मूल वेतन पैकेज का भुगतान करने के लिए विशेष रूप से आवंटित किया जाता है।

65. एक विनियमित प्रणाली में खेत से प्रसंस्करण इकाई तक जाने वाली कृषि उपजों के लिए संस्थागत आपूर्ति श्रृंखला का सही सामान्य क्रम चुनिए:
(A) प्रसंस्करणकर्ता → किसान → कमीशन एजेंट → KUMS यार्ड
(B) किसान → KUMS यार्ड → कमीशन एजेंट (आढ़तिया) → कृषि-प्रसंस्करणकर्ता
(C) कमीशन एजेंट → प्रसंस्करणकर्ता → किसान → KUMS यार्ड
(D) KUMS यार्ड → प्रसंस्करणकर्ता → कमीशन एजेंट → किसान

66. सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजस्थान में "स्पाइस पार्क्स" की अवधारणा शुरू की गई है। राज्य में दो प्रमुख स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं?
(A) जयपुर और उदयपुर शहर
(B) बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र
(C) अलवर और भरतपुर क्षेत्र
(D) जोधपुर और कोटा जिले

67. कृषि-उद्योगों के लिए क्लस्टर विकास दृष्टिकोण अपनाने के निम्नलिखित लाभों पर विचार कीजिए:
I. परीक्षण प्रयोगशालाओं और अपशिष्ट उपचार संयंत्रों जैसी साझा अवसंरचना का विकास।
II. पैमाने की मितव्ययिता की प्राप्ति।
III. खरीद और विपणन के लिए सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि।
IV. व्यक्तिगत प्रसंस्करण इकाइयों के बीच बढ़ा हुआ अलगाव और शून्य अंतःक्रिया।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

68. कौन सा कथन राजस्थान की कृषि क्षेत्र नीति में एक प्रमुख प्रवृत्ति की सही पहचान करता है?
(A) कच्चे, अप्रसंस्कृत थोक फसल उपज के निर्यात पर विशेष रूप से केंद्रित एक सख्त रणनीति लागू करना।
(B) कृषि वस्तुओं के सभी अंतरराज्यीय परिवहन और निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करना।
(C) कच्चे माल के निर्यात से स्थानीय द्वितीयक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की ओर स्थानांतरण।
(D) खेती को भारी उद्योग से प्रतिस्थापित करने वाली व्यापक भूमि अधिग्रहण नीतियों का कार्यान्वयन।

69. कृषि-प्रसंस्करण के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन "प्राथमिक प्रसंस्करण" को "द्वितीयक प्रसंस्करण" से स्पष्ट रूप से अलग करता है?
(A) प्राथमिक प्रसंस्करण उपज को साफ और छांटता है, जबकि द्वितीयक प्रसंस्करण इसे एक नए उत्पाद में परिवर्तित करता है।
(B) प्राथमिक प्रसंस्करण आणविक रासायनिक संरचनाओं को बदलता है, जबकि द्वितीयक प्रसंस्करण केवल भौतिक माल ढुलाई स्थान को बदलता है।
(C) प्राथमिक प्रसंस्करण पूरी तरह से यांत्रिक मशीनरी पर निर्भर करता है, जबकि द्वितीयक प्रसंस्करण विशेष रूप से शारीरिक श्रम द्वारा किया जाता है।
(D) दोनों शब्द औद्योगिक क्षेत्र के दिशानिर्देशों और सरकारी दस्तावेजों में कानूनी और परिचालन रूप से समानार्थी हैं।

70. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: कृषि में द्वितीयक मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में काफी वृद्धि होती है।
कथन II: प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद आमतौर पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अधिक कीमतें प्राप्त करते हैं और उनका शेल्फ जीवन अधिक लंबा होता है।
सही उत्तर चुनिए:
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

71. कच्चे माल से तैयार उत्पाद तक सूती वस्त्र मूल्य श्रृंखला के निम्नलिखित चरणों को सही क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. कताई (धागा बनाना)
2. वस्त्र निर्माण (कपड़े सिलना)
3. जिनिंग (बीज से कपास को अलग करना)
4. बुनाई (कपड़ा बनाना)
5. रंगाई और छपाई
सही कूट का चयन कीजिए:

Downloaded from www.pdf.tube

31. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
बीकानेर में ऊनी धागा निर्माण और हाथ से बुने कालीन उद्योग का व्यापक विकास हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि बीकानेर क्षेत्र तथा आसपास के पश्चिमी राजस्थान में मोगरा, चोकला और नाली जैसी उच्च गुणवत्ता वाली भेड़ की नस्लों की विशाल आबादी है। बीकानेर एक केंद्रीय संग्रहण केंद्र के रूप में प्रचुर कच्ची ऊन प्राप्त करता है, जो स्थानीय कताई मिलों और कालीन निर्माण इकाइयों को पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध कराता है।

32. (C) जोधपुर
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (Central Wool Development Board) का मुख्यालय राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। इस बोर्ड का गठन देश में ऊन क्षेत्र के समग्र विकास, भेड़पालकों के कल्याण, ऊन के मानकीकरण, गुणवत्ता सुधार और ऊन प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था। जोधपुर में इसका मुख्यालय होने से राजस्थान के पशुपालकों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मिलती है।

33. (B) राजस्थान में उत्पादित सभी कच्चे ऊन की खपत स्थानीय स्तर पर शून्य अंतरराज्यीय व्यापार के साथ होती है।
राजस्थान भारत के कुल कच्चे ऊन उत्पादन में लगभग 30 से 40 प्रतिशत का योगदान देता है। हालांकि, यह कथन पूरी तरह से गलत है कि राज्य की संपूर्ण कच्ची ऊन की खपत केवल स्थानीय स्तर पर ही होती है। राजस्थान से कच्ची ऊन और ऊनी धागे का पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात जैसे अन्य राज्यों को व्यापक अंतरराज्यीय व्यापार और निर्यात किया जाता है, जो स्थानीय खपत से कहीं अधिक है।

34. (D) गन्ना एक भार-ह्रासी और शीघ्र नष्ट होने वाला कच्चा माल है
अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत के अनुसार, गन्ना एक भार-ह्रासी और शीघ्र नष्ट होने वाला कच्चा माल है। कटाई के बाद गन्ने में मौजूद सुक्रोज की मात्रा तेजी से घटने लगती है, जिससे रस की मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा, गन्ने के कुल वजन का केवल एक छोटा हिस्सा ही चीनी में परिवर्तित होता है। इसलिए परिवहन लागत बचाने और सुक्रोज की हानि रोकने के लिए चीनी मिलें गन्ने के खेतों के पास लगाई जाती हैं।

35. (B) केवल I, II और IV
राजस्थान में कृषि-आधारित उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के स्रोतों से निकटता, निर्बाध विद्युत आपूर्ति और शीत श्रृंखला सुविधाओं की उपलब्धता से गहराई से प्रभावित होती है। चूंकि राजस्थान एक भू-आबद्ध (लैंडलॉक्ड) राज्य है, इसलिए इसके पास अपनी सीमाओं के भीतर कोई भी गहरा समुद्री बंदरगाह नहीं है। अतः तीसरा कथन असत्य है, जबकि पहला, दूसरा और चौथा कारक औद्योगिक अवस्थिति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

36. (C) जिनिंग एक भार-ह्रासी और कच्चे माल से बंधी प्रक्रिया है, जबकि रंगाई पूंजी, पानी और कुशल श्रम पर निर्भर करती है।
कपास ओटाई (जिनिंग) प्रक्रिया में कच्चे कपास से बिनौले और अशुद्धियां अलग की जाती हैं, जिससे वजन में भारी कमी आती है। इसलिए परिवहन लागत घटाने के लिए जिनिंग इकाइयां कपास उत्पादक जिलों जैसे हनुमानगढ़ में केंद्रित होती हैं। इसके विपरीत, टेक्सटाइल रंगाई और छपाई एक पूंजी-गहन और प्रसंस्करण प्रक्रिया है, जिसके लिए प्रचुर जल, रासायनिक अवसंरचना, कुशल श्रम और पारंपरिक बाजारों की आवश्यकता होती है, जो भीलवाड़ा और पाली में उपलब्ध हैं।

37. (A) राजस्थान इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन स्कीम
"RIPS" का पूर्ण रूप "राजस्थान इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन स्कीम" (Rajasthan Investment Promotion Scheme) है। राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर (जैसे RIPS 2014, RIPS 2019 और RIPS 2022) यह नीति जारी की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में कृषि-प्रसंस्करण सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में नए निवेश को आकर्षित करना, कर रियायतें देना, वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना और रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना है।

NODIA

38. (A) केवल I और II
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के तहत राज्य में नई कृषि-प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने वाले उद्यमियों को बिजली शुल्क और मंडी शुल्क में 100% तक छूट की रियायत दी जाती है। हालांकि, यह योजना राज्य में कहीं भी मुफ्त कृषि भूमि प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं करती। निवेशकों को औद्योगिक भूखंड नियमानुसार खरीदने या लीज पर लेने होते हैं। अतः केवल कथन I और II सही हैं।

39. (B) मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और किसानों की आय में वृद्धि करना
राजस्थान में कृषि-उद्योगों को सरकारी प्रोत्साहन और सब्सिडी देने का मूल उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निजी और संस्थागत निवेश को आकर्षित करना है। इसके माध्यम से प्राथमिक कृषि उपज में स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन (वैल्यू एडिशन) को बढ़ावा दिया जाता है। इससे फसल कटाई के बाद के नुकसान में कमी आती है, ग्रामीण रोजगार का सृजन होता है और अंततः किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने से उनकी आय में वृद्धि होती है।

40. (C) प्राकृतिक रूप से जमने वाला वातावरण जो कृत्रिम शीतलन इकाइयों की किसी भी आवश्यकता को समाप्त कर देता है
राजस्थान एक गर्म और शुष्क जलवायु वाला राज्य है, जहाँ ग्रीष्मकाल में तापमान अत्यधिक उच्च हो जाता है। यहाँ कोई प्राकृतिक रूप से जमने वाला वातावरण मौजूद नहीं है जो कृत्रिम शीतलन की आवश्यकता को समाप्त कर सके। वास्तव में, राजस्थान में शीत भंडारण उद्योगों को उच्च प्रारंभिक पूंजी लागत, बिजली की कटौती और अधिक परिचालन व्यय जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अतः तीसरा कथन एक चुनौती नहीं बल्कि गलत तथ्य है।

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) ऐसा उद्योग जो पौधों और पशुओं से प्राप्त कृषि उत्पादों का उपयोग अपने प्राथमिक कच्चे माल के रूप में करता है
कृषि आधारित उद्योग वे औद्योगिक इकाइयां होती हैं जो अपनी उत्पादन प्रक्रिया में वनस्पतियों और पशुओं से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करती हैं। ये उद्योग कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। इनके माध्यम से प्राथमिक कृषि उपज का प्रसंस्करण करके निर्मित माल तैयार किया जाता है। सूती वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल, डेयरी उत्पाद तथा खाद्य प्रसंस्करण इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं।

2. (D) गेहूं को पीसकर मैदा बनाना
कृषि प्रसंस्करण में द्वितीयक प्रसंस्करण का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पाद के मूल स्वरूप में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन करके एक नया उत्पाद निर्मित किया जाता है। गेहूं को पीसकर मैदा बनाने की प्रक्रिया में अनाज की संरचना बदल जाती है और मूल्य संवर्धन होता है। केवल सफाई, छंटाई, श्रेणीकरण या सुखाने जैसी गतिविधियां प्राथमिक प्रसंस्करण के अंतर्गत आती हैं, जबकि आटा या मैदा बनाना द्वितीयक श्रेणी में शामिल होता है।

3. (A) यह फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करता है और ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार पैदा करता है
राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने से बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। यह व्यवस्था कटाई के बाद होने वाले कृषि उपज के नुकसान को नियंत्रित करने में सहायक होती है। इसके साथ ही यह ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार के नए अवसर सृजित करती है, जिससे केवल कृषि पर निर्भरता घटती है। मूल्य संवर्धन के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलता है और ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि होती है।

4. (C) भीलवाड़ा
राजस्थान का भीलवाड़ा जिला अपने विशाल वस्त्र उद्योग, सूती धागे और कृत्रिम कपड़े के अत्यधिक उत्पादन के लिए संपूर्ण देश में प्रसिद्ध है। इस शहर में कताई, बुनाई और वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयों का एक बड़ा केंद्र स्थापित है। विशाल औद्योगिक संकेंद्रण तथा उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ा निर्माण की क्षमता के कारण ही इस जिले को व्यापक रूप से वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई है। यह राजस्थान के निर्यात में बड़ा योगदान देता है।

5. (C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
भीलवाड़ा निश्चित रूप से राजस्थान में सूती वस्त्र निर्माण का सबसे बड़ा और प्रमुख केंद्र है, जहाँ अत्याधुनिक कताई और बुनाई मिलें स्थित हैं। हालांकि, यह दावा तथ्यात्मक रूप से असत्य है कि भीलवाड़ा जिला भारत के कुल कच्चे कपास का 80 प्रतिशत से अधिक उत्पादित करता है। भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों द्वारा किया जाता है। इसलिए पहला कथन पूर्णतः सत्य है जबकि दूसरा कारण गलत है।

6. (D) बांडी नदी में अनुपचारित विषैले रासायनिक अपशिष्टों का विसर्जन, जिससे जल प्रदूषण होता है
राजस्थान के पाली क्षेत्र में स्थित टेक्सटाइल प्रोसेसिंग और डाइंग इकाइयां बांडी नदी में बिना उपचारित किए विषैले रासायनिक अपशिष्ट और रंगीन जल का विसर्जन करती रही हैं। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय भौमजल और नदी जल अत्यधिक प्रदूषित हो गए हैं, जिससे कृषि भूमि की उर्वरता और जनस्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस गंभीर जल प्रदूषण के कारण न्यायालयों और पर्यावरण नियामकों ने इन औद्योगिक इकाइयों पर कड़े प्रतिबंध और चुनौतियां लागू की हैं।

7. (B) P-3, Q-1, R-4, S-2
राजस्थान के औद्योगिक भूगोल में विभिन्न कृषि आधारित उद्योगों के विशिष्ट केंद्र स्थापित हैं। भीलवाड़ा सूती वस्त्र और कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है। भरतपुर अपनी प्रचुर सरसों फसल के कारण सरसों के तेल निष्कर्षण का मुख्य केंद्र है। श्रीगंगानगर में गन्ने की खेती के कारण चीनी मिलों की उपस्थिति रही है। बीकानेर राज्य की सबसे बड़ी ऊन मंडी के साथ ऊन प्रसंस्करण का केंद्रीय स्थल है। इस प्रकार यह मिलान पूर्णतः सुसंगत है।

8. (C) भरतपुर, अलवर और धौलपुर को शामिल करने वाले पूर्वी जिले
राजस्थान का पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली जिले शामिल हैं, राज्य में सरसों और राई का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। अनुकूल जलोढ़ मिट्टी और सिंचित परिस्थितियों के कारण यहाँ सरसों का भारी उत्पादन होता है। इसी कच्चे माल की प्रचुरता के कारण इस पूर्वी पट्टी में तेल मिलों और खाद्य तेल प्रसंस्करण उद्योगों का सघन संकेंद्रण देखने को मिलता है, जिसे इंजन छाप तेल के लिए भी जाना जाता है।

9. (D) यहाँ ICAR-सरसों अनुसंधान निदेशालय (DRMR) स्थित है और कच्चे माल की प्रचुर आपूर्ति उपलब्ध है।
भरतपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है, जो सरसों की उन्नत किस्मों, रोग प्रतिरोधक क्षमता और तेल सामग्री को बढ़ाने पर शोध करता है। अनुसंधान सहायता के साथ-साथ भरतपुर और उसके आसपास के पूर्वी जिलों में सरसों कच्चे माल की व्यापक उपलब्धता है। इन दोनों कारकों के समन्वय ने भरतपुर को

Click Here to Buy book on Amazon

सरसों प्रसंस्करण और खाद्य तेल निर्माण के क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान प्रदान किया है।

10. (B) केवल I और III
राजस्थान भारत में सरसों और खाद्य तेल उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। इसके प्रसंस्करण उद्योग की मुख्य विशेषता यह है कि यह कच्चे माल आधारित अर्थात भार-ह्रासी उद्योग है, जिसके कारण अधिकांश तेल मिलें सरसों उत्पादक क्षेत्रों के पास ही स्थापित की जाती हैं। यह कोई भार-वृद्धि उद्योग नहीं है जो कच्चे माल के स्रोतों के स्थान पर केवल दूरस्थ बाजारों पर ही निर्भर हो। इसलिए पहला और तीसरा कथन सही हैं।

11. (B) भोपालसागर
वर्ष 1932 में स्थापित "द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड" राजस्थान राज्य की सबसे पहली चीनी मिल थी। यह निजी क्षेत्र की मिल चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित भोपालसागर नामक स्थान पर शुरु की गई थी। उस समय मेवाड़ रियासत के इस उपजाऊ क्षेत्र में गन्ने का पर्याप्त उत्पादन होता था, जिससे मिल को कच्चा माल प्राप्त होता था। यह स्थापना राजस्थान में आधुनिक कृषि-आधारित चीनी प्रसंस्करण उद्योग की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है।

12. (B) चुकंदर
श्रीगंगानगर स्थित राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल ने चीनी उत्पादन के लिए एक अनूठा प्रयोग करते हुए गन्ने के अलावा चुकंदर का उपयोग शुरु किया था। वर्ष 1968 में यहाँ चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया था। इस नवाचार का उद्देश्य केवल गन्ने पर निर्भरता कम करना और वर्ष के गैर-गन्ना सीजन में भी मिल के संचालन को जारी रखना था, जिससे एशिया में अपनी तरह का यह पहला प्रयास बना।

13. (A) राजस्थान अपने घरेलू स्तर पर उत्पादित अधिकांश चीनी का यूरोपीय देशों को निर्यात करता है।
राजस्थान में गन्ने का उत्पादन सीमित जल संसाधनों और शुष्क जलवायु के कारण उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तुलना में काफी कम है। इसलिए राजस्थान की चीनी मिलें मुख्य रुप से घरेलू मांग को भी मुश्किल से पूरा कर पाती हैं। राजस्थान से यूरोपीय देशों को बड़े पैमाने पर चीनी का निर्यात किए जाने का दावा तथ्यात्मक रुप से पूरी तरह गलत है, क्योंकि राज्य स्वयं अन्य राज्यों से चीनी आपूर्ति पर निर्भर रहता है।

14. (C) राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF)
राजस्थान में सहकारी आंदोलन के तहत डेयरी विकास कार्यक्रमों के शीर्ष प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए 'राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन' सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 1977 में राज्य में आनंद मॉडल पर आधारित त्रि-स्तरीय सहकारी डेयरी संरचना को लागू करने के लिए की गई थी। यह संस्था दूध की खरीद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन और पशुपालकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए संपूर्ण राज्य में व्यापक रणनीतियां और नीतियां लागू करती है।

15. (A) केवल I, II और III
राजस्थान में डेयरी प्रसंस्करण उद्योग त्रि-स्तरीय आनंद मॉडल पर आधारित है, जिसमें प्राथमिक समितियां ग्राम स्तर पर, जिला संघ जिला स्तर पर और राज्य फेडरेशन शीर्ष स्तर पर कार्यरत हैं। यह क्षेत्र केवल दूध का प्रसंस्करण ही नहीं करता, बल्कि घी, मक्खन, पनीर और छाछ जैसे उच्च मूल्यवर्धित उत्पादों का भी बड़े पैमाने पर निर्माण करता है। अतः चौथा कथन असत्य होने के कारण केवल I, II और III सही हैं।

16. (C) सरस
राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) अपने सभी प्रसंस्कृत दूध और डेयरी उत्पादों का विपणन प्रसिद्ध "सरस" ब्रांड नाम के तहत करता है। सरस ब्रांड के अंतर्गत सरस टोंड दूध, सरस घी, छाछ, मक्खन, लस्सी और पनीर जैसे उत्पाद बेचे जाते हैं। यह ब्रांड राजस्थान के प्रत्येक जिले में अत्यंत लोकप्रिय है और राज्य के लाखों पशुपालक किसानों को सीधे उपभोक्ताओं और शहरी बाजारों से जोड़ने का कार्य करता है।

17. (B) पोर्टलैंड सीमेंट उद्योग
सूती ओटाई, चीनी मिलिंग और ग्वार गम प्रसंस्करण इकाइयां पूरी तरह से कृषि उत्पादों (क्रमशः कपास, गन्ना और ग्वार) को कच्चे माल के रुप में उपयोग करने वाले कृषि-आधारित उद्योग हैं। इसके विपरीत, पोर्टलैंड सीमेंट उद्योग एक खनिज-आधारित उद्योग है, जो चूना पत्थर, जिप्सम और क्ले जैसे प्राकृतिक खनिजों पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी प्रकृति और कच्चे माल के स्रोत के आधार पर पोर्टलैंड सीमेंट उद्योग अन्य विकल्पों से भिन्न है।

NODIA

18. (D) जोधपुर
राजस्थान का जोधपुर जिला ग्वार गम के निष्कर्षण, रिफाइनिंग और प्रसंस्करण का विश्व स्तरीय प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। पश्चिमी राजस्थान के शुष्क जिलों में ग्वार फसल का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। जोधपुर में स्थित अत्याधुनिक प्रसंस्करण मिलें इस कच्चे ग्वार से ग्वार गम पाउडर और स्प्लिट तैयार करती हैं। यहाँ निर्मित ग्वार गम का बड़ा हिस्सा अमेरिका और यूरोप सहित कई देशों में निर्यात किया जाता है।

19. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
राजस्थान का ग्वार गम उद्योग बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों को आपूर्ति करता है, जिससे यह एक अत्यधिक निर्यात-उन्मुख क्षेत्र है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रसंस्कृत ग्वार गम पाउडर का उपयोग वैश्विक शेल गैस और तेल निष्कर्षण (हाइड्रॉलिक फ्रैकिंग) में गाढ़ा करने वाले घटक के रुप में अत्यधिक किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा उद्योग में इसकी विशाल मांग के कारण राजस्थान से इसका भारी निर्यात होता है। अतः दोनों कथन सही हैं।

20. (C) जलीय प्रणालियों में एक अत्यधिक प्रभावी बंधक (बाइंडिंग) और गाढ़ा करने वाले पदार्थ के रुप में कार्य करना
ग्वार गम के बीजों के भ्रूणपोष से प्राप्त प्राकृतिक गाढ़ा पदार्थ पानी को सोखने और अत्यधिक श्यानता (विस्कोसिटी) उत्पन्न

करने की अद्भुत क्षमता रखता है। यह जलीय घोल में एक बेहतरीन बंधक, श्यानता वर्धक और पायसीकारक के रूप में कार्य करता है। इसी अनूठे भौतिक-रासायनिक गुण के कारण ग्वार गम का उपयोग खाद्य उद्योग, वस्त्र उद्योग, कागज निर्माण, भेषज (दवा) उद्योग और तेल-गैस उत्खनन में उच्च मूल्यवर्धित उत्पाद के रूप में किया जाता है।

21. (A) मेड़ता सिटी
राजस्थान के नागौर जिले में स्थित मेड़ता सिटी अपनी विशाल कृषि उपज मंडी और विशेष रूप से जीरा के व्यापार तथा प्रसंस्करण के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में उत्पादित जीरा अपनी उच्च सुगंध और गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। मेड़ता सिटी मंडी में जीरा की सफाई, श्रेणीकरण, पैकिंग और थ्रेसिंग की व्यापक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके कारण यह पश्चिमी राजस्थान में जीरे का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बना है।

22. (C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
भारत के कुल जीरा उत्पादन का अधिकांश भाग राजस्थान और गुजरात राज्यों द्वारा मिलकर उत्पादित किया जाता है, अतः कथन I बिल्कुल सत्य है। हालांकि, मसाला प्रसंस्करण और सुखाई की प्रक्रियाओं के लिए अत्यधिक आर्द्रता नुकसानदेह होती है। मसालों को सुखाने और प्रसंस्कृत करने के लिए शुष्क तथा कम आर्द्रता वाला मौसम आवश्यक होता है न कि निरंतर आर्द्रता और मानसून। इसलिए कथन II पूरी तरह गलत है।

23. (B) काली मिर्च
काली मिर्च एक उष्णकटिबंधीय मसाला फसल है, जिसके सफल विकास के लिए अत्यधिक वर्षा, उच्च आर्द्रता और निरंतर गर्म-नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थितियां मुख्य रूप से भारत के केरल और कर्नाटक जैसे पश्चिमी घाट के तटीय राज्यों में पाई जाती हैं। राजस्थान के शुष्क और अर्ध-शुष्क कृषि-जलवायु क्षेत्रों में जीरा, धनिया, मेथी और सौंफ जैसी बीजीय मसाला फसलों की खेती तो होती है, किंतु काली मिर्च यहाँ नहीं उगाई जाती।

24. (C) धनिया
कोटा जिले में स्थित रामगंज मंडी को एशिया की सबसे बड़ी धनिया मंडी के रूप में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र (कोटा, बारां, झालावाड़) धनिया की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। रामगंज मंडी में धनिया की विशाल आवक होती है, जहाँ आधुनिक ग्रेडिंग, सफाई, पिसाई और पैकेजिंग इकाइयां स्थापित हैं। यहाँ से उच्च गुणवत्ता वाला धनिया देश के विभिन्न राज्यों और वैश्विक बाजारों में आपूर्ति किया जाता है।

25. (D) P-3, Q-4, R-1, S-2
राजस्थान में मसालों का प्रसंस्करण उनके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के आसपास केंद्रित है। कोटा जिले की रामगंज मंडी धनिया प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। नागौर जिले का मेड़ता शहर जीरा व्यापार और प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। जोधपुर का मथानिया क्षेत्र अपनी तीखी और लाल मिर्च के उत्पादन एवं प्रसंस्करण के लिए मशहूर है। इसके अलावा बारां जिले का छबड़ा क्षेत्र लहसुन के बड़े बाजार और प्रसंस्करण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है।

26. (A) सेब साइडर प्रसंस्करण - जैसलमेर
सेब एक समशीतोष्ण (ठंडे) जलवायु का फल है, जिसकी खेती मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में होती है। जैसलमेर राजस्थान का एक अत्यधिक शुष्क और गर्म रेगिस्तानी जिला है, जहाँ सेब का उत्पादन या सेब साइडर प्रसंस्करण असंभव है। अन्य सभी जोड़े सही हैं, जैसे जालौर में ईसबगोल, श्रीगंगानगर में किन्नू और कोटा में सोयाबीन का प्रसंस्करण बड़े पैमाने पर किया जाता है।

27. (B) रुपनगढ़ (अजमेर)
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है, जो अजमेर जिले के रुपनगढ़ गाँव में स्थापित किया गया है। यह पार्क अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना, कोल्ड स्टोरेज, ड्राई वेयरहाउस, केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला और गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं से सुसज्जित है। यह पार्क क्षेत्र के किसानों और खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं को आपस में जोड़कर मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देता है।

28. (A) केवल I और II
मेगा फूड पार्क योजना का मुख्य उद्देश्य खेतों से लेकर खुदरा बाजारों तक एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना है, जो 'हब एंड स्पोक' मॉडल पर आधारित होती है। इसमें प्राथमिक संग्रहण केंद्र (स्पोक) और केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (हब) शामिल होते हैं। यह योजना निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करती है और निजी भागीदारी को प्रतिबंधित नहीं करती। अतः केवल पहला और दूसरा कथन सही हैं, जबकि तीसरा कथन गलत है।

29. (A) फसल कटाई के बाद होने वाले कृषि नुकसान
मेगा फूड पार्क की अवधारणा का मूल उद्देश्य कृषि उपज की कटाई के बाद होने वाले भारी नुकसान (पोस्ट-हार्वेस्ट लॉस) को न्यूनतम करना है। भारत में कोल्ड चेन और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के अभाव में बड़ी मात्रा में फल, सब्जियां और अनाज खराब हो जाते हैं। मेगा फूड पार्क एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला, प्रशीतन और आधुनिक प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करके कृषि उपज के जीवनकाल को बढ़ाता है और बर्बादी को रोकता है।

30. (C) बीकानेर
राजस्थान का बीकानेर शहर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी (वूल मार्केट) के रूप में विख्यात है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिलों में भेड़ पालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। बीकानेर इस पूरे रेगिस्तानी क्षेत्र से एकत्र की जाने वाली कच्ची ऊन का मुख्य व्यापारिक और प्रसंस्करण केंद्र है, जहाँ से ऊन का धागा बनाकर देश-विदेश के कालीन उद्योगों को आपूर्ति की जाती है।

Downloaded from www.pdf.tube

37. राज्य नीति "RIPS" का पूर्ण रूप क्या है जो कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र को पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करती है?
(A) राजस्थान इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन स्कीम
(B) राजस्थान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्कीम
(C) राजस्थान इंसेंटिव फॉर प्रोसेसिंग सब्सिडीज
(D) रूरल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोक्योरमेंट सिस्टम

38. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के तहत कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों को आमतौर पर दिए जाने वाले निम्नलिखित लाभों पर विचार कीजिए:
I. एक निर्दिष्ट अवधि के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान से 100% छूट।
II. एक निर्दिष्ट अवधि के लिए मंडी शुल्क के भुगतान से 100% छूट।
III. राज्य में कहीं भी निःशुल्क कृषि भूमि का प्रावधान।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

39. निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में कृषि-उद्योगों को सरकारी प्रोत्साहन प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य का सटीक वर्णन करता है?
(A) कृषि क्षेत्र में निजी स्वामित्व को हतोत्साहित करना
(B) मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और किसानों की आय में वृद्धि करना
(C) सभी कृषि उपज को भोजन की खपत से हटाकर औद्योगिक जैव ईंधन की ओर मोड़ना
(D) पारंपरिक कृषि उपज मंडी समितियों को समाप्त करना

40. निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में शीत भंडारण (कोल्ड स्टोरेज) अवसंरचना द्वारा सामना की जाने वाली एक प्रमुख चुनौती नहीं है?
(A) उन्नत प्रशीतन मशीनरी खरीदने के लिए पर्याप्त शुरुआती पूंजीगत निवेश की आवश्यकताएं
(B) दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बार-बार कटौती और अनियमित बिजली वितरण नेटवर्क
(C) प्राकृतिक रूप से जमने वाला वातावरण जो कृत्रिम शीतलन इकाइयों की किसी भी आवश्यकता को समाप्त कर देता है
(D) असामान्य रूप से उच्च दैनिक परिचालन व्यय और निरंतर उपकरण रखरखाव का बोझ

41. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग के अस्तित्व के लिए एक मजबूत शीत श्रृंखला अवसंरचना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
कथन II: शीत भंडारण पकने की प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे बाजार के स्टॉक को साफ़ करने के लिए फल शीघ्रता से खराब होते हैं।
सही उत्तर चुनिए:
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

NODIA

42. उद्यानिकी उपज के लिए एक मानक शीत श्रृंखला लॉजिस्टिक्स प्रणाली में चरणों का सही तार्किक क्रम चुनिए:
(A) शीत गृह → फुटकर वितरण → पूर्व-शीतलन → कटाई
(B) कटाई → पूर्व-शीतलन → शीत गृह → प्रशीतित परिवहन → फुटकर
(C) फुटकर → प्रशीतित परिवहन → शीत गृह → पूर्व-शीतलन → कटाई
(D) पूर्व-शीतलन → कटाई → फुटकर → प्रशीतित परिवहन → शीत गृह

43. झालावाड़ जिले को राज्य सरकार द्वारा किस विशिष्ट फल की फसल के लिए प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने हेतु लक्षित किया गया है?
(A) सेब
(B) संतरा
(C) अनानास
(D) अंगूर

44. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (फल)
P. किन्नू
Q. संतरा
R. अमरूद
S. अनार
सूची II: (राजस्थान में प्रमुख उत्पादक/प्रसंस्करण क्षेत्र)
1. सवाई माधोपुर
2. बाड़मेर/जालौर
3. श्रीगंगानगर
4. झालावाड़
(A) P-4, Q-3, R-2, S-1
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

45. अनाज और दलहन प्रसंस्करण क्षेत्र की तुलना में राजस्थान में फल और सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र की ऐतिहासिक रूप से धीमी वृद्धि का सबसे उपयुक्त कारण क्या है?
(A) अपर्याप्त शीत भंडारण, उपज का अत्यधिक शीघ्र-नष्ट होना और शुष्क जलवायु परिस्थितियाँ।
(B) बागवानी फसलों में प्राकृतिक प्रणालीगत विषाक्त पदार्थ होते हैं जो उन्हें औद्योगिक खाद्य प्रसंस्करण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं।
(C) सख्त नियामक राज्य कानून जो व्यावसायिक फल और सब्जी प्रसंस्करण सुविधाओं को कानूनी रूप से

41. (C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
ताजे फल और सब्जियां शीघ्र नष्ट होने वाली फसलें हैं, इसलिए उनके संरक्षण और विपणन के लिए एक मजबूत शीत श्रृंखला अवसंरचना अत्यंत आवश्यक होती है। हालांकि, कथन II असत्य है क्योंकि शीत भंडारण (कोल्ड स्टोरेज) फलों के पकने और खराब होने की प्रक्रिया को धीमा करता है, न कि तेज करता है। कम तापमान पर जैविक श्वसन दर घटने से उपज की भंडारण अवधि बढ़ जाती है। अतः पहला कथन सही और दूसरा गलत है।

42. (B) कटाई → पूर्व-शीतलन → शीत गृह → प्रशीतित परिवहन → फुटकर
बागवानी फसलों के लिए शीत श्रृंखला आपूर्ति व्यवस्था में एक निश्चित क्रमिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। सर्वप्रथम खेत से उपज की कटाई की जाती है। इसके तुरंत बाद खेत की गर्मी को दूर करने के लिए प्री-कूलिंग (पूर्व-शीतलन) की जाती है। इसके बाद उपज को मुख्य शीत गृह (कोल्ड स्टोरेज) में रखा जाता है। फिर प्रशीतित वाहनों द्वारा परिवहन करके अंततः फुटकर विक्रेताओं और उपभोक्ताओं तक सुरक्षित पहुँचाया जाता है।

43. (B) संतरा
राजस्थान का झालावाड़ जिला संतरा के अत्यधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है। झालावाड़ की विशिष्ट जलवायु और मृदा संतरा बागवानी के पूर्णतः अनुकूल है, जिसके कारण इसे अक्सर 'राजस्थान का नागपुर' भी कहा जाता है। राज्य सरकार ने झालावाड़ जिले में संतरा प्रसंस्करण, जूस निर्माण, वैक्सिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना को विशेष रुप से प्रोत्साहित किया है ताकि बागवानी किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले।

44. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
राजस्थान के विभिन्न फल उत्पादक क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट पहचान है। किन्नू का सर्वाधिक उत्पादन और प्रसंस्करण उत्तर-पश्चिमी सिंचित जिले श्रीगंगानगर में होता है। संतरे का प्रमुख उत्पादक केंद्र झालावाड़ जिला है। अमरूद के उत्पादन और प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए सवाई माधोपुर जिला प्रसिद्ध है। अनार की व्यावसायिक खेती और प्रसंस्करण पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर तथा जालौर जिलों में व्यापक रुप से विकसित हुआ है।

45. (A) अपर्याप्त शीत भंडारण, उपज का अत्यधिक शीघ्र-नष्ट होना और शुष्क जलवायु परिस्थितियाँ।
अनाज और दालों की तुलना में ताजे फल और सब्जियां नमी की मात्रा अधिक होने के कारण बहुत तेजी से सड़ते और खराब होते हैं। राजस्थान की शुष्क व अत्यधिक गर्म जलवायु इस सड़न को और तेज कर देती है। इसके अलावा, राज्य में ग्रामीण स्तर पर शीत गृहों (कोल्ड स्टोरेज) और प्रशीतित लॉजिस्टिक्स का ऐतिहासिक अभाव रहा है। इन्हीं अवसंरचनात्मक बाधाओं के कारण फल-सब्जी प्रसंस्करण की वृद्धि धीमी रही।

46. (C) राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF)
राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF) राज्य में दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों को संतुलित एवं पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर पशु आहार संयंत्रों (कैटल फीड प्लांट्स) का संचालन करता है। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और पाली जैसे स्थानों पर आरसीडीएफ के अंतर्गत पशु आहार कारखाने कार्यरत हैं। ये संयंत्र सहकारी आधार पर सरस ब्रांड के तहत गुणवत्तापूर्ण पशु आहार का निर्माण और वितरण करते हैं।

47. (D) सूखे फसल चारे की सघन छर्रों में यांत्रिक गठरी बनाना (बेलिंग) और संघनन
चारा-आधारित कृषि उद्योगों में सूखे फसल अवशेषों और भूसे के आयतन को घटाने के लिए यांत्रिक बेलिंग (गठरी बनाना) और कॉम्पैक्शन (संघनन) तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसके तहत चारे को दबाकर सघन ब्लॉक या पलेट्स (छर्रों) में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया से चारे का आयतन घट जाता है, जिससे परिवहन की लागत कम होती है, भंडारण की अवधि बढ़ती है और आपातकालीन सूखा स्थितियों में चारे का परिवहन आसान हो जाता है।

48. (A) केवल I, II और III
राजस्थान में पशु आहार और चारा उद्योग राज्य की विशाल पशुधन आबादी से सीधे जुड़ा हुआ है। प्रसंस्कृत संतुलित आहार दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करता है। साथ ही चारा बैंक अकाल और सूखे की स्थिति में पशुधन की सुरक्षा करते हैं। यह उद्योग स्थानीय कृषि उप-उत्पाद और खली का उपयोग करता है, अतः तटीय राज्यों के आयात पर निर्भर रहने वाला चौथा कथन गलत है।

49. (B) ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार
दाल मिलों, तेल पेराई इकाइयों और कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियों जैसे कृषि-प्रसंस्करण उद्यमों की ग्रामीण इलाकों में स्थापना से 'ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार' का व्यापक सृजन होता है। ये इकाइयां खेत के मजदूरी कार्यों से अलग हटकर प्रसंस्करण, पैकेजिंग, लोडिंग, मशीन संचालन और परिवहन जैसी गतिविधियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करती हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता आती है और केवल खेती पर निर्भर रहने का दबाव कम होता है।

50. (D) कम लागत वाले, अत्यधिक कुशल रोबोटिक्स इंजीनियरों और स्वचालन विशेषज्ञों की स्थानीय अत्यधिक आपूर्ति
राजस्थान में लघु एवं मध्यम कृषि-आधारित उद्योगों को बिजली की महंगी दरों, कार्यशील पूंजी ऋण की कमी और दूरस्थ क्षेत्रों में परिवहन लॉजिस्टिक्स जैसी कई परिचालन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रोबोटिक्स इंजीनियरों या स्वचालन विशेषज्ञों की अत्यधिक स्थानीय आपूर्ति की बात करना एक असत्य कथन है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उच्च तकनीक विशेषज्ञों का अभाव होता है न कि प्रचुर आपूर्ति। अतः यह कोई परिचालन चुनौती नहीं है।

Click Here to Buy book on Flipkart

की कताई (1) करके धागा बनाया जाता है। इसके पश्चात धागे की बुनाई (4) करके कपड़ा तैयार होता है। तत्पश्चात कपड़े की रंगाई और छपाई (5) की जाती है। अंत में उस कपड़े से वस्त्र निर्माण या सिलाई (2) की प्रक्रिया संपन्न होती है।

72. (C) 2019
राजस्थान सरकार ने राज्य में कृषि-प्रसंस्करण अवसंरचना, कृषि-व्यवसाय और कृषि-निर्यात को व्यापक बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019 में "राजस्थान कृषि-प्रसंस्करण, कृषि-व्यवसाय और कृषि-निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019" की घोषणा की। इस नीति का मुख्य लक्ष्य राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय अनुदान, पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और मंडी शुल्क में छूट देकर निवेशकों तथा किसानों को प्रोत्साहित करना और निर्यात में वृद्धि करना है।

73. (D) यह बाहरी आवेदकों की तुलना में स्थानीय किसानों, एफपीओ और राज्य के मूल निवासियों को उच्च पूंजी अनुदान प्रदान करती है।
राजस्थान कृषि-प्रसंस्करण, कृषि-व्यवसाय और कृषि-निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की एक अनूठी विशेषता यह है कि यह पूंजीगत सब्सिडी देने में भेदभावपूर्ण प्राथमिकता तय करती है। यह नीति सामान्य गैर-कृषक या बाहरी उद्यमियों की तुलना में स्थानीय किसानों, कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) और राज्य के मूल निवासियों को अधिक प्रतिशत में (उच्चतर दर पर) पूंजीगत निवेश अनुदान और वित्तीय छूट प्रदान करती है ताकि किसान स्वयं उद्यमी बन सकें।

74. (A) मोटे अनाज (श्रीअन्न) और वन उपज का प्रसंस्करण
राजस्थान की हालिया कृषि-प्रसंस्करण नीतियों में मोटे अनाज (श्रीअन्न) जैसे बाजरा, ज्वार तथा लघु वन उपज के प्रसंस्करण को विशेष प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया गया है। राजस्थान देश में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मोटे अनाज की उच्च पोषण गुणवत्ता और रेगिस्तानी जलवायु में आसानी से उगने की क्षमता को देखते हुए, सरकार इनके प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और निर्यात प्रोत्साहन के लिए विशेष वित्तीय लाभ दे रही है।

75. (B) मजबूत परिवहन संपर्कों वाले टमाटर कृषि क्लस्टर के निकट
औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांतों के अनुसार, टमाटर केचप विनिर्माण जैसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिए सबसे उपयुक्त स्थान वह है जो टमाटर उत्पादक कृषि क्लस्टर के निकट हो और सुदृढ़ परिवहन नेटवर्क से जुड़ा हो। टमाटर एक अति-नष्टनशील (नाशवान) और भार-ह्रासी कृषि उत्पाद है। खेत के पास प्रसंस्करण इकाई होने से परिवहन के दौरान सड़न और वजन में कमी से होने वाला नुकसान घटता है तथा ताजे कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती है।

76. (B) नायलॉन जैसे कृत्रिम सिंथेटिक कपड़ों का निर्माण करना
राजस्थान कृषि-प्रसंस्करण, कृषि-व्यवसाय और कृषि-निर्यात प्रोत्साहन नीति केवल कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और वनोपज से प्राप्त जैविक प्राथमिक कच्चे माल के प्रसंस्करण पर लागू होती है। नायलॉन जैसे कृत्रिम सिंथेटिक वस्त्रों का निर्माण पेट्रोकेमिकल और गैर-कृषि आधारित औद्योगिक गतिविधि है। इसलिए नायलॉन कपड़ा निर्माण इस विशेष कृषि-प्रसंस्करण नीति के तहत वित्तीय प्रोत्साहन या सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।

77. (A) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड
राजस्थान कृषि-प्रसंस्करण, कृषि-व्यवसाय और कृषि-निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के निष्पादन, आवेदनों की जांच और सब्सिडी वितरण के लिए 'राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड' (RSAMB) को मुख्य नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। यह बोर्ड राज्य में कृषि विपणन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के साथ-साथ पात्र कृषि-प्रसंस्करणकर्ताओं, एफपीओ और किसानों को नीति के तहत तय पूंजीगत और ब्याज अनुदान का त्वरित ऑनलाइन वितरण सुनिश्चित करता है।

78. (C) ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार)
राजस्थान की कृषि उपज मंडियों को एकीकृत करने और अखिल भारतीय पारदर्शी व्यापार को सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार के 'ई-नाम' (e-NAM - राष्ट्रीय कृषि बाजार) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल को अपनाया गया है। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राजस्थान के किसान और कृषि-प्रसंस्करणकर्ता देश भर की किसी भी मंडी से कृषि उपज का पारदर्शी क्रय-विक्रय कर सकते हैं, जिससे मध्यस्थों का प्रभाव घटता है और बेहतर मूल्य खोज संभव होती है।

79. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
राजस्थान की औद्योगिक नीतियों में खाद्य प्रसंस्करण को एक 'प्राथमिकता क्षेत्र' (थ्रस्ट सेक्टर) घोषित किया गया है, अतः कथन I बिल्कुल सही है। इसका कारण यह है कि राजस्थान में तिलहन, दलहन, मसालों और ग्वार जैसे कच्चे माल का प्रचुर उत्पादन होता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से द्वितीयक प्रसंस्करण अवसंरचना का अभाव था। इस कमी को दूर करने के लिए ही सरकार ने इसे प्राथमिकता का दर्जा दिया है। अतः दोनों कथन सही हैं।

80. (C) किसानों की आय दोगुनी करना, फसल के नुकसान को कम करना और ग्रामीण उद्योग का विस्तार करना
राजस्थान में कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने का व्यापक और प्राथमिक लक्ष्य राज्य के किसानों की आय में निरंतर वृद्धि करना, कटाई के उपरांत होने वाले फसलों के नुकसान को कम करना और ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक अवसरों का विस्तार करना है। प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास से कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन होता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है और युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए द्वार खुलते हैं।

NODIA

है। जैसलमेर राजस्थान का अत्यधिक शुष्क, रेतीला और न्यूनतम वर्षा वाला रेगिस्तानी जिला है, जहाँ गन्ने का व्यावसायिक उत्पादन नहीं होता। इसके विपरीत, बारां में सोयाबीन, बीकानेर में मूंगफली और अलवर क्षेत्र में पीली सरसों का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। अतः पहला युग्म पूरी तरह असत्य है।

62. (C) ताजे टमाटरों को पैक्ड केचप और प्यूरी में बदलना
कृषि में "मूल्य संवर्धन" (वैल्यू एडिशन) से तात्पर्य किसी प्राथमिक कृषि उपज का प्रसंस्करण करके उसे अधिक मूल्यवान, उपयोगी और लंबे समय तक टिकाऊ उत्पाद में परिवर्तित करने से है। ताजे टमाटरों को पैक्ड केचप, सॉस या प्यूरी में बदलना इसका सटीक उदाहरण है। इस प्रक्रिया से उत्पाद का बाजार मूल्य बढ़ता है, शेल्फ लाइफ लंबी होती है और उपभोक्ता के लिए इसकी उपयोगिता में अत्यधिक वृद्धि होती है।

63. (D) वे प्रत्यक्ष, नीलामी-आधारित कच्चे माल की खरीद के लिए विनियमित बाज़ार प्रांगण प्रदान करती हैं।
कृषि उपज मंडी समितियां (KUMS) राजस्थान में कृषि-आधारित उद्योगों के लिए एक पारदर्शी और विनियमित बाजार मंच का कार्य करती हैं। ये समितियां मंडी प्रांगण में किसानों और कृषि-प्रसंस्करणकर्ताओं के बीच खुली नीलामी प्रणाली द्वारा कच्चे माल की प्रत्यक्ष खरीद की व्यवस्था करती हैं। इससे प्रसंस्करण इकाइयों को उचित गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी दरों पर कच्चा माल मिलता है तथा किसानों को उनकी उपज का सही दाम सुनिश्चित होता है।

64. (C) मंडी अवसंरचना, किसान सुविधाओं और जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कों में पुनर्निवेश किया जाता है।
कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा एकत्र किए गए बाजार शुल्क (मंडी टैक्स) का उपयोग कानूनी रूप से कृषि और ग्रामीण विकास कार्यों के पुनर्निवेश में किया जाता है। इस राजस्व से मंडी प्रांगणों की अवसंरचना मजबूत की जाती है, शेड और गोदाम बनाए जाते हैं, किसानों के लिए विश्राम गृह व पीने के पानी की व्यवस्था होती है तथा खेतों को मंडी से जोड़ने वाली ग्रामीण लिंक सड़कों (मंडी सड़कों) का निर्माण व रखरखाव किया जाता है।

65. (B) किसान → KUMS यार्ड → कमीशन एजेंट (आढ़तिया) → कृषि-प्रसंस्करणकर्ता
संस्थागत कृषि आपूर्ति श्रृंखला में खेत से प्रसंस्करण इकाई तक उपज का प्रवाह एक व्यवस्थित क्रम में होता है। सर्वप्रथम, किसान अपनी फसल की कटाई करके उसे कृषि उपज मंडी समिति (KUMS) के विनियमित प्रांगण में लाता है। मंडी यार्ड में लाइसेंस प्राप्त कमीशन एजेंट (आढ़तिया) उस उपज की नीलामी का संचालन करता है। इसके बाद कृषि-प्रसंस्करणकर्ता या व्यापारी उच्चतम बोली लगाकर माल खरीदता है और प्रसंस्करण इकाई में ले जाता है।

66. (D) जोधपुर और कोटा जिले
राजस्थान में मसालों की गुणवत्ता सुधार, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य के दो प्रमुख जिलों - जोधपुर और कोटा में 'स्पाइस पार्क' स्थापित किए गए हैं। जोधपुर स्पाइस पार्क मुख्य रूप से जीरा, मथानिया मिर्च और अन्य शुष्क मसालों के प्रसंस्करण पर केंद्रित है, जबकि कोटा स्थित स्पाइस पार्क (रामगंज मंडी) धनिया और हाड़ौती क्षेत्र के मसालों की सफाई, ग्रेडिंग व पैकेजिंग के लिए जाना जाता है।

67. (A) केवल I, II और III
कृषि-उद्योगों में क्लस्टर विकास मॉडल अपनाने से कई साझा लाभ प्राप्त होते हैं। इससे प्रयोगशालाओं और अपशिष्ट उपचार संयंत्रों जैसी सामूहिक अवसंरचना का निर्माण संभव होता है। बड़े पैमाने पर संचालन से पैमाने की मितव्ययिता (इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल) हासिल होती है और कच्चे माल की खरीद तथा बिक्री में सौदेबाजी की क्षमता बढ़ती है। चौथा कथन गलत है क्योंकि क्लस्टर अलगाव नहीं बल्कि इकाइयों के मध्य आपसी सहयोग को बढ़ाता है।

68. (C) कच्चे माल के निर्यात से स्थानीय द्वितीयक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की ओर स्थानांतरण।
राजस्थान की वर्तमान कृषि नीति में एक स्पष्ट संरचनात्मक बदलाव देखा जा रहा है, जिसमें केवल कच्चे अप्रसंस्कृत कृषि माल के निर्यात के बजाय राज्य के भीतर ही द्वितीयक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, स्पाइस पार्क और एग्रो-क्लस्टर स्थापित करना है ताकि कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन हो सके, रोजगार पैदा हो और राज्य की जीडीपी में कृषि-उद्योग का योगदान बढ़ सके।

69. (A) प्राथमिक प्रसंस्करण उपज को साफ और छांटता है, जबकि द्वितीयक प्रसंस्करण इसे एक नए उत्पाद में परिवर्तित करता है।
प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण में केवल कच्ची उपज की सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई, ओटाई या सुखाने जैसी क्रियाएं शामिल होती हैं, जिनसे उपज का मूल रासायनिक या भौतिक स्वरूप नहीं बदलता। इसके विपरीत, द्वितीयक प्रसंस्करण में प्राथमिक उत्पाद को आटा, तेल, चीनी, केचप या धागे जैसे बिल्कुल नए रूप में परिवर्तित किया जाता है। इस परिवर्तन से उत्पाद की भौतिक और रासायनिक संरचना बदल जाती है और मूल्य संवर्धन होता है।

NODIA

70. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
कृषि क्षेत्र में द्वितीयक मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देने से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, अतः कथन I सत्य है। इसके अलावा, कथन II भी पूरी तरह सही है क्योंकि प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद अपनी बेहतर गुणवत्ता और लंबे शेल्फ जीवन के कारण बाजार में अधिक कीमतें प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया ग्रामीण आय में वृद्धि करती है और राज्य के आर्थिक विकास को गति देती है।

71. (A) 3 - 1 - 4 - 5 - 2
सूती वस्त्र उद्योग की मूल्य श्रृंखला में एक निश्चित क्रमिक प्रक्रिया होती है। सर्वप्रथम, खेतों से प्राप्त कपास की जिनिंग या ओटाई (3) करके बीज और रेशा अलग किए जाते हैं। फिर रेशे

(C) केवल I और III
(D) I, II और III

46. कोटा में बलुआ पत्थर प्रसंस्करण इकाइयाँ निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए विशिष्ट रूप से जानी जाती हैं?
(A) विशेष वास्तुकला कांच निर्माण के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए उच्च-स्पष्टता वाले पारदर्शी पत्थर के पैनल
(B) आधुनिक माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर निर्माण में विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली अति-शुद्ध चूर्णित सिलिका रेत
(C) टिकाऊ फर्श और क्लैडिंग के लिए पतली विभाजित पत्थर की टाइलें
(D) सिंथेटिक रेजिन के साथ पिसे हुए पत्थर की धूल को जोड़कर निर्मित उच्च घनत्व वाली इंटरलॉकिंग पेवमेंट ईंटें

47. भारत के खनिज-आधारित औद्योगिक परिदृश्य में राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) राजस्थान सीमेंट का केवल एक मामूली उत्पादक बना हुआ है, जो दक्षिणी उत्पादक राज्यों से निरंतर थोक आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।
(B) क्षेत्रीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अवसंरचना के पूर्ण अभाव के कारण राजस्थान में किसी संगठित आधुनिक सिरामिक उद्योग का अभाव है।
(C) राजस्थान प्रसंस्करण के लिए कच्चा ग्रेनाइट आयात करता है, लेकिन अपनी सीमाओं के भीतर किसी भी स्वदेशी वाणिज्यिक ग्रेनाइट चट्टान के भंडार से पूरी तरह से रहित है।
(D) राजस्थान देश के सभी सीसा और जस्ता का उत्पादन करता है, जो राष्ट्र के स्मेल्टर्स को सहायता प्रदान करता है।

48. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): राजस्थान में कांच उद्योग काफी हद तक धौलपुर, अलवर और जयपुर जैसे जिलों में केंद्रित है।
कारण (R): इन जिलों की उच्च गुणवत्ता वाले सिलिका रेत के भंडारों तक आसान पहुंच है और ये ऊर्जा स्रोतों तथा प्रमुख खपत वाले बाजारों से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं।
उपर्युक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

49. ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय अनुपालन में सुधार के लिए चंदेरिया सीसा-जस्ता स्मेल्टर में कौन-सी उन्नत स्मेल्टिंग तकनीक अपनाई गई थी?
(A) ओपन-हर्थ भट्टी तकनीक
(B) ऑसमेल्ट तकनीक
(C) बेसेमर परिवर्तक तकनीक
(D) पुडलिंग भट्टी तकनीक

50. खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स एक ऐसी सुविधा के साथ एकीकृत है जो स्मेल्टिंग प्रक्रिया से होने वाले सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए करती है?
(A) प्लास्टर ऑफ पेरिस
(B) सोडा ऐश
(C) कास्टिक सोडा
(D) सल्फ्यूरिक अम्ल

51. खेतड़ी में तांबा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना का सबसे उपयुक्त कारण कौन-सा है?
(A) खेतड़ी-सिंघाना में चालकोपायराइट तांबा अयस्क निक्षेपों से समीपता
(B) पूरे झुंझुनू क्षेत्र में कम लागत वाली प्रचुर जलविद्युत की निर्बाध उपलब्धता
(C) परिष्कृत तांबे के थोक निर्यात के लिए पास में एक प्रमुख गहरे पानी के बंदरगाह की रणनीतिक मौजूदगी
(D) विशेष रूप से थार मरुस्थल के मुख्य भाग के औद्योगिकीकरण के उद्देश्य से केंद्र सरकार का एक बाध्यकारी नीतिगत जनादेश

52. निम्नलिखित उद्योगों पर विचार कीजिए:
I. पोर्टलैंड सीमेंट निर्माण
II. प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्माण
III. कृषि (क्षारीय मृदा के लिए मृदा सुधारक के रूप में)
IV. कांच निर्माण
उपर्युक्त में से कौन-सा/से विकल्प राजस्थान में निष्कर्षित जिप्सम के प्रमुख अंतिम-उपयोग क्षेत्रों का सटीक प्रतिनिधित्व करता है/करते हैं?
(A) I, II और IV
(B) I, II और III
(C) II, III और IV
(D) I, III और IV

53. राजस्थान में बलुआ पत्थर उद्योग के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) बलुआ पत्थर प्रसंस्करण इकाइयों को गालक के रूप में अत्यधिक मात्रा में चूना पत्थर की आवश्यकता होती है।
(B) बलुआ पत्थर मुख्य रूप से राज्य के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में उत्खनित किया जाता है।
(C) यह उद्योग अत्यधिक निर्यात-उन्मुख है, जो यूरोपीय और मध्य पूर्वी बाजारों में डिमेंशनल पत्थरों का निर्यात करता है।

Downloaded from www.pdf.tube

अध्याय 14

राजस्थान के खनिज आधारित उद्योग

NODIA

1. राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन-सा जिला मुख्य रुप से निरंतर चूना पत्थर के प्रचुर भंडारों की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है?
(A) जैसलमेर
(B) चित्तौड़गढ़
(C) बाड़मेर
(D) दौसा

2. राजस्थान का किशनगढ़ निम्नलिखित में से किस खनिज-आधारित प्रसंस्करण उद्योग के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है?
(A) सिरामिक निर्माण
(B) जस्ता प्रगलन
(C) तांबा शोधन
(D) संगमरमर कटाई और प्रसंस्करण

3. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): चंदेरिया सीसा-जस्ता स्मेल्टर संयंत्र चित्तौड़गढ़ जिले में स्थापित किया गया था।
कारण (R): चित्तौड़गढ़, रामपुरा आगूचा की सहबद्ध खदानों के समीप स्थित है तथा विश्वसनीय विद्युत और जल आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
उपर्युक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

4. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (खनिज-आधारित उद्योग)
P. ग्रेनाइट प्रसंस्करण
Q. लाल बलुआ पत्थर प्रसंस्करण
R. बॉल क्ले आधारित सिरामिक
S. तांबा प्रगलन
सूची II: (संकेंद्रण का प्राथमिक जिला)
1. धौलपुर
2. बीकानेर
3. जालौर
4. झुंझुनू
(A) P-1, Q-3, R-2, S-4
(B) P-3, Q-2, R-1, S-4
(C) P-3, Q-1, R-2, S-4
(D) P-2, Q-1, R-3, S-4

5. धौलपुर और अलवर जैसे जिलों में स्थित कांच निर्माण इकाइयों के लिए निम्नलिखित में से किस कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है?
(A) बॉक्साइट
(B) सिलिका रेत
(C) सोडा ऐश
(D) चूना पत्थर

6. खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स (KCC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह झुंझुनू जिले में स्थित एक एकीकृत तांबा खनन एवं स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स है।
II. इस कॉम्प्लेक्स में तांबा अयस्क के स्मेल्टिंग के दौरान सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रमुख उप-उत्पाद के रूप में उत्पादित होता है।
III. यह कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से आयातित तांबा सांद्र पर निर्भर है और राजस्थान में इसकी कोई सहबद्ध खदान नहीं है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

7. राजस्थान के सीमेंट संयंत्रों में पोर्टलैंड सीमेंट की निर्माण प्रक्रिया में जिप्सम का प्राथमिक कार्य क्या है?
(A) अंतिम कंक्रीट मिश्रण को संरचनात्मक मजबूती प्रदान करना
(B) सीमेंट के जमने की समय-अवधि को बढ़ाना
(C) क्लिंकर के पिघलने के तापमान को कम करने के लिए गालक के रूप में कार्य करना
(D) सीमेंट को हल्का रंग प्रदान करना

8. किशनगढ़ में संगमरमर प्रसंस्करण इकाइयों के एकत्रीकरण से महत्वपूर्ण औद्योगिक लाभ प्राप्त हुए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प "संवहन अर्थव्यवस्था" का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

51. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
लघु कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों को अक्सर गंभीर कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण यह है कि कृषि कच्चे माल की आवक केवल फसल कटाई के अल्पकालिक मौसमी सीजन के दौरान ही होती है। प्रसंस्करण इकाइयों को पूरे वर्ष उत्पादन जारी रखने के लिए इस कम समय में ही थोक में कच्चा माल खरीदकर भंडारित करना पड़ता है, जिसके लिए भारी नकद राशि की आवश्यकता होती है।

52. (C) प्रसंस्कृत आयामी पत्थर जैसे परिष्कृत संगमरमर (मार्बल) और ग्रेनाइट
परिष्कृत संगमरमर (मार्बल) और ग्रेनाइट खनन एवं खनिज क्षेत्र से संबंधित उत्पाद हैं, न कि कृषि-आधारित या प्रसंस्कृत कृषि वस्तुएं। ग्वार गम पाउडर, मूल्यवर्धित मसाले तथा हाथ से बने ऊनी कालीन कृषि और पशुपालन क्षेत्र से प्राप्त प्राथमिक कच्चे माल पर आधारित उत्पाद हैं जिनका निर्यात किया जाता है। इसलिए कृषि-आधारित प्रसंस्कृत निर्यात वस्तुओं की सूची में आयामी पत्थर एक असंगत और बेमेल विकल्प है।

53. (B) 1969
राजस्थान राज्य एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन (RSAIC) की स्थापना वर्ष 1969 में राज्य सरकार द्वारा की गई थी। इस निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य में कृषि के यंत्रीकरण को बढ़ावा देना, किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण, ट्रैक्टर तथा थ्रेशर उपलब्ध कराना और कृषि-आधारित प्रसंस्करण गतिविधियों को प्रोत्साहन देना था। इसने राज्य में हरित क्रांति के दौर में कृषि मशीनीकरण और कस्टम हायरिंग सेवाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

54. (D) कृषि मशीनों का वितरण करना और स्थानीय किसानों को कस्टम हायरिंग उपकरण सेवाएं प्रदान करना
राजस्थान राज्य एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन (RSAIC) की पारंपरिक प्राथमिक भूमिका राज्य के किसानों को रियायती दरों पर आधुनिक कृषि उपकरण, ट्रैक्टर, प्लांटिंग मशीनें और थ्रेशर वितरित करना रही है। इसके अलावा, यह निगम उन छोटे और सीमान्त किसानों को कस्टम हायरिंग केंद्र (CHCs) के माध्यम से किराए पर महंगी कृषि मशीनरी सेवाएं प्रदान करता है जो स्वयं महंगे उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं हैं।

55. (A) 2 - 4 - 5 - 1 - 3
एक वाणिज्यिक चीनी मिल में चीनी निर्माण का क्रमिक चरण निर्धारित होता है। सर्वप्रथम, रस निकालने के लिए गन्ने की पेराई (2) की जाती है। इसके पश्चात, गन्ने के रस का स्पष्टीकरण और वाष्पीकरण करके उसे गाढ़ा (4) किया जाता है। तत्पश्चात, गाढ़े रस को उबालकर क्रिस्टलीकरण (5) किया जाता है। इसके बाद अपकेंद्रीकरण (1) द्वारा शीरे से चीनी क्रिस्टल अलग किए जाते हैं। अंत में, चीनी का श्रेणीकरण एवं पैकेजिंग (3) होती है।

56. (C) ईसबगोल का बीज
ईसबगोल (साइलियम हस्क) राजस्थान का एक प्रमुख प्रसंस्कृत कृषि-उत्पाद है, जिसमें प्राकृतिक आहार फाइबर और पाचन संबंधी औषधीय गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जालौर, बाड़मेर और सिरोही जिले ईसबगोल के उत्पादन व प्रसंस्करण के मुख्य केंद्र हैं। अपने उच्च स्वास्थ्य लाभों के कारण प्रसंस्कृत ईसबगोल भूसी की अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों में भारी अंतरराष्ट्रीय मांग है, जिससे यह राजस्थान के लिए उच्च निर्यात राजस्व उत्पन्न करता है।

57. (D) आबू रोड (सिरोही) - ईसबगोल प्रसंस्करण
आबू रोड (सिरोही जिला) और समीपवर्ती जालौर क्षेत्र ईसबगोल के प्रसंस्करण तथा भूसी (हस्क) निर्माण की अत्याधुनिक औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसलिए आबू रोड और ईसबगोल प्रसंस्करण का युग्म पूर्णतः सही है। इसके विपरीत, रामगंज मंडी धनिया के लिए प्रसिद्ध है न कि ग्वार गम के लिए; बीकानेर ऊन के लिए प्रसिद्ध है न कि कॉटन जिनिंग के लिए; और श्रीगंगानगर किन्नू के लिए जाना जाता है।

58. (A) केवल I और II
राजस्थान से ग्वार गम का बड़े पैमाने पर उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता है, जहाँ इसका उपयोग शेल गैस फ्रैकिंग में होता है। अतः इसकी निर्यात मात्रा अंतरराष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस बाजार की उतार-चढ़ाव भरी स्थिति पर बहुत अधिक निर्भर करती है। हालांकि, तीसरा कथन गलत है क्योंकि राजस्थान भारत के कुल ग्वार उत्पादन में 70% से 80% का विशाल योगदान देता है, न कि 10% से कम।

59. (B) P-3, Q-4, R-2, S-1
कृषि-आधारित उद्योगों की निर्भरता उनके विशिष्ट कच्चे माल पर होती है। सूती वस्त्र उद्योग का प्राथमिक कच्चा माल कपास का रेशा है। डेयरी उद्योग का मुख्य आधार ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्र किया जाने वाला कच्चा दूध है। खाद्य तेल उद्योग मुख्य रुप से सरसों और सोयाबीन के बीजों की पेराई पर निर्भर है। चीनी उद्योग गन्ने और चुकंदर जैसे मीठे कृषि कच्चे माल का उपयोग करता है।

60. (B) जुड़े हुए कृषि-व्यवसायों, आपूर्तिकर्ताओं और सहायक संस्थानों का एक भौगोलिक केंद्र
कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर का तात्पर्य किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में स्थित परस्पर जुड़े कृषि-व्यवसायों, प्रसंस्करण इकाइयों, कच्चे माल आपूर्तिकर्ताओं और सहायक संस्थानों के एक सघन केंद्र से है। इसका मूल उद्देश्य साझा अवसंरचना, परीक्षण सुविधाओं और विपणन नेटवर्क का सामूहिक लाभ उठाकर उत्पादन लागत को कम करना और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता में व्यापक सुधार करना है। यह क्लस्टर की परिभाषा है।

61. (A) गन्ना - जैसलमेर जिला
गन्ना अत्यधिक जल-गहन फसल है, जिसकी सफल खेती के लिए प्रचुर सिंचाई और आर्द्र वातावरण की आवश्यकता होती

Click Here to Buy book on Amazon

IV. कच्चे माल का सम्मिश्रण और पूर्व-तापन
(A) II, IV, III, I
(B) II, III, IV, I
(C) IV, II, III, I
(D) II, I, IV, III

18. खनिज उद्योग और इसके प्राथमिक जिले का निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है?
(A) बलुआ पत्थर प्रसंस्करण - भरतपुर
(B) जस्ता प्रगलन - चित्तौड़गढ़
(C) ग्रेनाइट कटाई - जालौर
(D) जिप्सम प्रसंस्करण - बांसवाड़ा

19. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): बीकानेर जिले में सिरामिक और पॉटरी उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
कारण (R): बीकानेर और इसके आसपास के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली बॉल क्ले और फायर क्ले के व्यापक भंडार मौजूद हैं।
उपर्युक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

20. कोटा और धौलपुर जैसे जिलों में बलुआ पत्थर काटने की इकाइयों से उत्पन्न सूक्ष्म सिलिका धूल के लंबे समय तक श्वास के साथ अंदर जाने से एक व्यावसायिक स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया है। कौन-सा विशिष्ट श्वसन रोग इस जोखिम से सर्वाधिक संबंधित है?
(A) एस्बेस्टोसिस
(B) बिसिनोसिस
(C) सिलिकोसिस
(D) सिडरोसिस

21. राजस्थान में कौन-सा नीतिगत ढांचा खनिज क्षेत्र में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने का स्पष्ट लक्ष्य रखता है, जो कच्चे खनिजों के निर्यात से प्रसंस्कृत वस्तुओं के स्थानीय निर्माण की ओर संक्रमण को प्रोत्साहित करता है?
(A) राजस्थान औद्योगिक विकास नीति
(B) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता परियोजना
(C) राजस्थान पर्यटन इकाई नीति
(D) राजस्थान वन उपज अधिनियम

22. राजस्थान में खनन क्षेत्रों की पर्यावरणीय और पुनर्वास चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. व्यापक अवैज्ञानिक खनन कार्यों ने स्थानीय भूजल स्तर को गंभीर रूप से कम कर दिया है।
II. खदान बंद करने की योजनाओं के लिए समाप्त हो चुकी खदानों के भराव और पारिस्थितिक बहाली की आवश्यकता होती है।
III. स्टोन स्लरी के जमाव ने खनन पट्टियों में स्थानीय वनस्पतियों की वृद्धि में सकारात्मक योगदान दिया है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल III
(C) केवल II और III
(D) केवल I और III

23. राजस्थान में सीसा-जस्ता स्मेल्टिंग प्रक्रिया के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) राजस्थान में जस्ता और सीसा के निक्षेप आमतौर पर प्रकृति में जटिल सल्फाइड अयस्कों के रूप में एक साथ पाए जाते हैं।
(B) चंदेरिया स्मेल्टर बिना किसी पायरोधात्विक क्षमता के पूरी तरह से हाइड्रोधात्विक इकाइयों पर कार्य करता है।
(C) जटिल सीसा-जस्ता अयस्कों की स्मेल्टिंग के दौरान चांदी अत्यधिक उच्च मूल्य वाले धात्विक उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है।
(D) सल्फाइड अयस्कों के भर्जन के दौरान सल्फ्यूरिक अम्ल एक उप-उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है और क्षेत्रीय उर्वरक संयंत्रों को आपूर्ति किया जाता है।

24. जिप्सम-आधारित औद्योगिक इकाइयाँ मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी जिलों में केंद्रित हैं क्योंकि:
(A) इन जिलों में सर्वाधिक वर्षा होती है, जो जिप्सम की धुलाई के लिए आवश्यक है।
(B) इस क्षेत्र में अन्य प्रमुख उद्योगों का अभाव है, जिससे सरकार विशेष रूप से जिप्सम के लिए सब्सिडी देती है।
(C) बीकानेर, नागौर और श्रीगंगानगर में राज्य के जिप्सम के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं।
(D) जिप्सम विशेष रूप से बाड़मेर में स्थानीय पेट्रोलियम रिफाइनरियों के उप-उत्पाद के रूप में निकाला जाता है।

25. राजस्थान के किस विशिष्ट बलुआ पत्थर का, जो अपनी अनूठी गुलाबी-लाल रंगत के लिए जाना जाता है, ऐतिहासिक रूप से दिल्ली के लाल किले के निर्माण में और हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में उपयोग किया गया था?
(A) जोधपुर लाल बलुआ पत्थर
(B) बिजोलिया स्प्लिटिंग बलुआ पत्थर
(C) खाटू बफ बलुआ पत्थर
(D) बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर

NODIA

26. संसाधन संरक्षण के साथ औद्योगिक विकास को संतुलित करने के लिए, राजस्थान में पत्थर प्रसंस्करण उद्योग के लिए निम्नलिखित में से किस अभ्यास की सबसे दृढ़ता से वकालत की जाती है?
(A) बंद-पाश जल पुनर्चक्रण को अपनाना और ईंट बनाने में

(A) क्षेत्रीय एकाधिकार को बढ़ावा देने और उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए कच्चे माल के निर्यात पर रणनीतिक प्रतिबंध
(B) सभी क्षेत्रीय औद्योगिक इकाइयों द्वारा एकसमान आधार मूल्य निर्धारण और सख्त उत्पादन कोटा का नियामक प्रवर्तन
(C) साझा स्थानीय अवसंरचना, विशिष्ट श्रम और आपूर्तिकर्ता नेटवर्क के कारण उत्पादन लागत में कमी
(D) राज्य के सभी उत्खनित संगमरमर का प्रसंस्करण विशेष रूप से किशनगढ़ शहर की सीमाओं के भीतर करने का वैधानिक जनादेश

9. राजस्थान में डिमेंशनल स्टोन उद्योग (जैसे संगमरमर और ग्रेनाइट) की मूल्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने वाले सही तार्किक क्रम का चयन कीजिए।
(A) ब्लॉक उत्खनन - स्लैब कटाई - एज पॉलिशिंग - मूल्य-वर्धित डिजाइनिंग - निर्यात
(B) स्लैब कटाई - एज पॉलिशिंग - ब्लॉक उत्खनन - मूल्य-वर्धित डिजाइनिंग - निर्यात
(C) मूल्य-वर्धित डिजाइनिंग - ब्लॉक उत्खनन - एज पॉलिशिंग - स्लैब कटाई - निर्यात
(D) ब्लॉक उत्खनन - मूल्य-वर्धित डिजाइनिंग - स्लैब कटाई - एज पॉलिशिंग - निर्यात

10. राजस्थान में पत्थर कटाई उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: संगमरमर और ग्रेनाइट प्रसंस्करण इकाइयों से उत्पन्न स्लरी मृदा की सतह पर एक अप्रवेश्य परत बना देती है, जिससे भूजल पुनर्भरण बाधित होता है।
कथन II: खुली भूमि में स्टोन स्लरी का निपटान जैविक उर्वरक के रूप में कार्य करता है, जिससे मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है।
निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

11. जालौर-सिरोही पट्टी किस विशिष्ट प्रकार के डिमेंशनल स्टोन के प्रसंस्करण और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है?
(A) स्लेट पत्थर
(B) ग्रेनाइट
(C) गुलाबी संगमरमर
(D) फाइलाइट

12. राजस्थान में विभिन्न खनिज-आधारित उद्योगों को रॉक फॉस्फेट, लिग्नाइट और जिप्सम के निष्कर्षण और आपूर्ति में कौन-सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?
(A) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको)
(B) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (RSMML)
(C) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL)
(D) राजस्थान वित्त निगम (RFC)

13. सिलिका रेत की स्थानीय उपलब्धता और हाई-टेक प्रिसिजन ग्लास फैक्टरी जैसी राज्य सरकार की पहलों के कारण राजस्थान का कौन-सा जिला ऐतिहासिक रूप से अपने कांच उद्योग के लिए जाना जाता है?
(A) धौलपुर
(B) जोधपुर
(C) उदयपुर
(D) सीकर

14. राजस्थान में सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसे भार-ह्रासकारी उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए इसके संयंत्र चूना पत्थर की खदानों के पास स्थित हैं।
II. पाली, नागौर और चित्तौड़गढ़ बड़े पैमाने पर सीमेंट निर्माण इकाइयों की मेजबानी करने वाले प्रमुख जिले हैं।
III. राजस्थान के भीतर सहबद्ध खदानों से कोयले की उपलब्धता इन संयंत्रों में कम ऊर्जा लागत का प्राथमिक कारण है।
IV. पश्चिमी राजस्थान में व्यापक रूप से उपलब्ध जिप्सम इन सीमेंट संयंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) I, II और III
(B) II, III और IV
(C) I, II और IV
(D) I, III और IV

15. राजस्थान में प्रमुख सिरामिक और पॉटरी (मृद्भांड) उद्योग केंद्रों के संदर्भ में बेमेल विकल्प का चयन कीजिए।
(A) बीकानेर
(B) जयपुर
(C) थानागाजी (अलवर)
(D) खुर्जा

16. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) राजस्थान में प्रमुख जस्ता-सीसा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स का संचालन करता है। निम्नलिखित में से कौन-सा स्थान राज्य में HZL से संबद्ध स्मेल्टिंग स्थान नहीं है?
(A) चंदेरिया
(B) देबारी
(C) जावर
(D) दरीबा

17. सीमेंट निर्माण प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. जिप्सम के साथ क्लिंकर की पिसान
II. चूना पत्थर का उत्खनन और पेषण
III. भट्टी में तापन और क्लिंकर का निर्माण

Downloaded from www.pdf.tube

(A) सूक्ष्म दानेदार चूना पत्थर
(B) सूक्ष्म दानेदार बलुआ पत्थर
(C) चूनामय बलुआ पत्थर
(D) क्वार्टजाइट

36. प्राथमिक औद्योगिक उत्पादन के वर्गीकरण के आधार पर बेमेल विकल्प का चयन कीजिए।
(A) चंदेरिया सीसा-जस्ता स्मेल्टर कॉम्प्लेक्स
(B) खेतड़ी एकीकृत तांबा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स
(C) किशनगढ़ स्टोन क्लस्टर
(D) देबारी हाइड्रो-धात्विक जस्ता स्मेल्टर

37. धौलपुर और भरतपुर जिले किस प्राकृतिक भवन निर्माण सामग्री के प्रसंस्करण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं?
(A) बलुआ पत्थर
(B) अभ्रक
(C) एस्बेस्टस
(D) रॉक फॉस्फेट

38. राजस्थान में सिरामिक उद्योग से संबंधित निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए:
I. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज पर निर्भरता।
II. बीकानेर और बाड़मेर में पाए जाने वाले उच्च श्रेणी के मिट्टी निक्षेपों का उपयोग।
III. प्राकृतिक गैस या कोयले जैसी निरंतर ईंधन आपूर्ति की आवश्यकता वाली उच्च ऊर्जा खपत।
IV. बिना किसी विट्रिफाइड टाइल निर्माण के केवल कम मूल्य वाले टेराकोटा बर्तनों का विशेष उत्पादन।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन राज्य में सिरामिक उद्योग की विशेषताओं का सही प्रतिनिधित्व करता है/करते हैं?
(A) I, II और III
(B) II, III और IV
(C) I, III और IV
(D) I, II और IV

39. राजस्थान में कांच के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा प्राथमिक खनिज कच्चा माल आवश्यक है?
(A) डोलोमाइट अयस्क
(B) सिलिका रेत
(C) हैवी बेराइट्स
(D) कैलसाइट पत्थर

40. रामपुरा आगूचा खदान से निकाला गया जस्ता-सीसा अयस्क मुख्य रुप से किस उद्देश्य से खदान स्थल पर ही प्राथमिक पेषण और सांद्रण से गुजरता है?
(A) लंबी दूरी के परिवहन से पहले कच्चे अयस्क के कुल भार में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए
(B) प्राथमिक निष्कर्षण चरण में सीसा और जस्ता धातुओं का पूर्ण रासायनिक पृथक्करण प्राप्त करने के लिए
(C) स्मेल्टर तक परिवहन लागत को कम करने के लिए अयस्क ग्रेड में सुधार करने के लिए
(D) नगर निगम और राज्य खनन रॉयल्टी लागू करने से पहले सभी बहुमूल्य चांदी खनिज सामग्री को निकालने के लिए

41. कौन-सा प्रमुख सीमेंट समूह क्षेत्रीय चूना पत्थर पट्टियों का लाभ उठाते हुए पाली और अजमेर जिलों में कई बड़े पैमाने की निर्माण इकाइयों का संचालन करता है?
(A) इंडिया सीमेंट्स
(B) रामको सीमेंट्स
(C) डालमिया भारत
(D) श्री सीमेंट

NODIA

42. नागौर जिले में सफेद सीमेंट निर्माण का एक मजबूत औद्योगिक आधार है। इस क्षेत्र में किस कच्चे माल की उच्च शुद्धता और कम लोहा सामग्री सफेद सीमेंट उत्पादन को व्यावहारिक बनाती है?
(A) कम-लोहा युक्त चूना पत्थर
(B) उच्च श्रेणी का ईंधन लिग्नाइट
(C) क्रिस्टलीय सेलेनाइट जिप्सम
(D) औद्योगिक बेंटोनाइट क्ले

43. निम्नलिखित में से किस जिले में बड़े पैमाने के पोर्टलैंड सीमेंट निर्माण संयंत्रों की महत्वपूर्ण उपस्थिति नहीं है?
(A) चित्तौड़गढ़
(B) चूरू
(C) सिरोही
(D) बूंदी

44. राजस्थान में खनिज-आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक अवस्थिति कारक नहीं माना जाता है?
(A) खनिज भंडारों से समीपता
(B) नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की उपलब्धता
(C) एक विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति ग्रिड तक पहुंच
(D) राष्ट्रीय राजमार्गों और माल ढुलाई गलियारों के माध्यम से कनेक्टिविटी

45. राजस्थान में मूल्य-वर्धित पत्थर उत्पादों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. कच्चे पत्थर के ब्लॉकों के निर्यात की तुलना में पत्थर की कलाकृतियों और विशेष टाइलों को डिजाइन करने से अधिक लाभ मार्जिन प्राप्त होता है।
II. प्रसंस्कृत संगमरमर और ग्रेनाइट का निर्यात मूल्य राजस्थान के कुल औद्योगिक निर्यात का एक प्रमुख घटक है।
III. भारी स्वचालन के कारण मूल्यवर्धन से पत्थर क्षेत्र में रोजगार की संभावना कम हो जाती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III

स्लरी का उपयोग करना
(B) पत्थर काटने और प्रसंस्करण की सभी इकाइयों को स्थायी रूप से राज्य की सीमाओं से बाहर स्थानांतरित करना
(C) आधुनिक मशीनीकृत कटाई प्रक्रियाओं को पूरी तरह से पारंपरिक हस्तशिल्प श्रम पद्धतियों से बदलना
(D) कच्चे और प्रसंस्कृत डिमेंशनल पत्थरों के लिए राज्य के सभी निर्यात लाइसेंसों पर पूरी तरह से रोक लगाना

27. राजस्थान के खनिज-आधारित प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा उत्पन्न निर्यात मूल्य में निम्नलिखित में से कौन-सा एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता नहीं है?
(A) पॉलिश की गई ग्रेनाइट की स्लैब
(B) अप्रसंस्कृत लिग्नाइट कोयला
(C) डिजाइनर सिरामिक टाइलें
(D) मूल्य-वर्धित संगमरमर की कलाकृतियां

28. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (पत्थर की विशिष्ट किस्म)
P. पीला चूना पत्थर/बलुआ पत्थर
Q. हरा संगमरमर
R. सफेद संगमरमर
S. कोटा स्टोन
सूची II: (संबंधित जिला)
1. उदयपुर
2. मकराना (नागौर)
3. जैसलमेर
4. कोटा / झालावाड़
(A) P-1, Q-3, R-4, S-2
(B) P-3, Q-1, R-2, S-4
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

29. राजस्थान के खनिज उद्योग के संदर्भ में, "डिमेंशनल स्टोन" शब्द का तात्पर्य है:
(A) विशिष्ट ब्लॉक या स्लैब आयामों में उत्खनित और तराशी गई प्राकृतिक चट्टान
(B) मुख्य रूप से सड़क निर्माण के लिए छोटे गिट्टी में तोड़े गए मोटे पत्थर
(C) कैरेट में मापे और बेचे जाने वाले उच्च मूल्य वाले बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य रत्न
(D) रासायनिक रेजिन के साथ संगमरमर की धूल को मिलाकर निर्मित कृत्रिम पत्थर

30. विशेष रूप से डिमेंशनल स्टोन क्षेत्र के लिए अनुसंधान, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में किस विशेष संस्थान की स्थापना की गई थी?
(A) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम एंड ज्वेलरी (IIGJ)
(B) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (RSMDC)
(C) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स (CDOS)
(D) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT)

31. पिछले एक दशक में राजस्थान के खनिज-आधारित उद्योगों में निजी क्षेत्र के निवेश के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) सीमेंट निर्माण क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश पर कड़ाई और कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
(B) निजी उद्यमों को कानूनी रूप से केवल अलोह तांबा स्मेल्टिंग उद्योग में काम करने की अनुमति है।
(C) पूरे राज्य में वाणिज्यिक संगमरमर के भंडारों के पूरी तरह समाप्त होने के कारण समग्र निवेश में भारी गिरावट आई है।
(D) निवेश केवल निष्कर्षण से हटकर स्थानीय मूल्य-वर्धित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की ओर स्थानांतरित हुआ है।

32. सीमेंट निर्माण संयंत्र की स्थापना में कौन-सा अवस्थिति कारक सबसे निर्णायक भूमिका निभाता है?
(A) निर्यात परिवहन के लिए गहरे पानी के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों से समीपता
(B) तेजी से बढ़ते बड़े महानगरीय उपभोक्ता बाजारों से समीपता
(C) चूना पत्थर जैसे भारी कच्चे माल से समीपता
(D) निरंतर बायोमास ईंधन की आपूर्ति करने वाले प्रमुख कृषि क्षेत्रों से समीपता

33. राज्य में स्थापित सबसे पहले सीमेंट संयंत्र के स्थान की पहचान करते हुए, राजस्थान में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के सही ऐतिहासिक क्रम का चयन कीजिए।
(A) लाखेरी (पहला) → सवाई माधोपुर → निंबाहेड़ा
(B) निंबाहेड़ा (पहला) → लाखेरी → ब्यावर
(C) सवाई माधोपुर (पहला) → निंबाहेड़ा → लाखेरी
(D) ब्यावर (पहला) → लाखेरी → सवाई माधोपुर

34. राजस्थान में संगमरमर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: प्रसंस्करण इकाइयाँ अत्यधिक मात्रा में सूक्ष्म संगमरमर धूल उत्पन्न करती हैं, जो उचित प्रबंधन न होने पर गंभीर वायु और मृदा प्रदूषण का कारण बन सकती है।
कथन II: राज्य सरकार सिंथेटिक जिप्सम और निर्माण ईंटों के उत्पादन में संगमरमर स्लरी के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है।
निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

35. "कोटा स्टोन", जिसका पूरे भारत में फर्श सामग्री के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तकनीकी रूप से निम्नलिखित में से किस चट्टान का एक प्रकार है?

Click Here to Buy book on Flipkart

(D) मशीनीकृत गैंग आरी और वायर आरी ने बलुआ पत्थर के ब्लॉकों की कटाई को आधुनिक बना दिया है।

54. जालौर ग्रेनाइट की कौन-सी विशेषता इसे प्रसंस्करण और निर्यात के लिए अत्यधिक वांछनीय बनाती है?
(A) इसकी असाधारण कोमलता और कम घनत्व, जिससे साधारण हस्त उपकरणों का उपयोग करके इसे तराशना बेहद आसान हो जाता है
(B) इसकी असामान्य रूप से उच्च सतह सरंध्रता, जो इसे पानी और जलीय घोल को तेजी से अवशोषित करने की अनुमति देती है
(C) इसकी रासायनिक अस्थिरता और प्रत्यक्ष प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर तेजी से अपघटित होने की क्षमता
(D) सौंदर्यात्मक विविधता, उत्कृष्ट पॉलिश और संरचनात्मक स्थायित्व

55. परिवहन कनेक्टिविटी राजस्थान के खनिज-आधारित उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवस्थिति कारक है। हाल के किस अवसंरचनात्मक विकास से राज्य में पत्थर और सिरामिक क्षेत्रों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है?
(A) मुख्य इंदिरा गांधी नहर नेटवर्क का पूर्ण परिचालन विस्तार
(B) समर्पित माल ढुलाई गलियारा मार्ग
(C) उपनगरीय औद्योगिक क्षेत्रों में जयपुर मेट्रो रेल नेटवर्क का शहरी परिवहन विस्तार
(D) अटल सुरंग के माध्यम से राजमार्ग पारगमन मार्ग का रणनीतिक निर्माण और उद्घाटन

56. पत्थर प्रसंस्करण उद्योग में व्यावसायिक खतरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: सुरक्षात्मक उपायों के बिना सिलिका-समृद्ध पत्थरों की सूखी ड्रिलिंग और क्रशिंग से श्रमिकों में सिलिकोसिस की उच्च घटना होती है।
कथन II: राज्य सरकार ने प्रभावित श्रमिकों को वित्तीय सहायता और पुनर्वास प्रदान करने के लिए राजस्थान न्यूमोकोनिओसिस नीति शुरू की है।
निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

57. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (खनिज उद्योग प्रक्रिया)
P. पत्थर की कटाई और पॉलिशिंग
Q. आधार धातु स्मेल्टिंग
R. विवृत खनन
S. सीमेंट निर्माण

सूची II: (प्राथमिक पर्यावरणीय चिंता)
1. सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन और भारी धातु का स्लैग
2. स्लरी जनरेशन से मृदा की सरंध्रता में रुकावट
3. उच्च कणिकीय पदार्थ उत्सर्जन
4. वनों की कटाई और भूदृश्य का क्षरण
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-4, R-1, S-3
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

58. राजस्थान के औद्योगिक और खनिज क्षेत्र से संबंधित अपने मूल जनादेश के आधार पर निम्नलिखित सरकारी निकायों/संस्थानों में से बेमेल विकल्प की पहचान कीजिए।
(A) RSRTC (सड़क परिवहन निगम)
(B) RSMML (राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड)
(C) DMG (राज्य खान एवं भूविज्ञान निदेशालय)
(D) CDOS (स्वायत्त पत्थर विकास केंद्र)

59. राजस्थान के डिमेंशनल स्टोन निर्यात पोर्टफोलियो में निम्नलिखित में से किस प्रसंस्कृत खनिज का निर्यात मूल्य सबसे बड़ा हिस्सा बनाता है?
(A) कैलिब्रेटेड प्रसंस्कृत स्लेट टाइलें
(B) संगमरमर और ग्रेनाइट
(C) उत्खनित अपरिष्कृत लिग्नाइट ब्लॉक
(D) अप्रसंस्कृत कच्ची अभ्रक शीट

60. संगमरमर उद्योग के निम्नलिखित मूल्यवर्धन चरणों को सही परिचालन क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. पैकिंग और निर्यात
II. ब्लॉक उत्खनन
III. पॉलिशिंग और रेजिन उपचार
IV. गैंग आरी का उपयोग करके कटाई
(A) II, IV, III, I
(B) II, III, IV, I
(C) IV, II, III, I
(D) II, I, IV, III

61. कच्चे खनिज के निष्कर्षण को औद्योगिक आपूर्ति से जोड़ने वाली प्रमुख एजेंसी, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (RSMML) का कॉर्पोरेट मुख्यालय कहाँ स्थित है?
(A) उदयपुर
(B) जयपुर
(C) जोधपुर
(D) कोटा

62. राजस्थान में डिमेंशनल स्टोन और इसके आधुनिक बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक मशीनीकृत उपकरण का निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही है?
(A) संगमरमर ब्लॉक - केवल हाथ से पकड़े जाने वाली छेनी और लकड़ी के हथौड़े

Downloaded from www.pdf.tube

जैविक उर्वरक नहीं है बल्कि मृदा उत्पादकता को नुकसान पहुँचाती है।

11. (B) ग्रेनाइट
राजस्थान का जालौर और सिरोही जिला क्षेत्र देश भर में ग्रेनाइट के प्रसंस्करण, कटाई और निर्यात का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस क्षेत्र में मालानी आग्नेय चट्टानों के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, जिनमें विभिन्न रंगों का ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ स्थित सैकड़ों प्रसंस्करण इकाइयाँ इन पत्थरों को पॉलिश करके उच्च गुणवत्ता वाली स्लैब तैयार करती हैं, जिन्हें विदेशों में भी निर्यात करते हैं।

12. (B) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (RSMML)
राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड राज्य सरकार का एक प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम है जो गैर-धात्विक खनिजों के उत्खनन में संलग्न है। यह संस्था रॉक फॉस्फेट, जिप्सम तथा लिग्नाइट का व्यावसायिक उत्खनन करती है। यह उपक्रम देश के उर्वरक, सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा बिजली क्षेत्रों को कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

13. (A) धौलपुर
धौलपुर जिला ऐतिहासिक रूप से राजस्थान में कांच उद्योग के एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है। इस जिले में उच्च गुणवत्ता वाली सिलिका रेत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो कांच निर्माण का प्राथमिक घटक है। यहाँ हाई-टेक प्रिसिजन ग्लास फैक्टरी जैसी इकाइयों के माध्यम से वैज्ञानिक उपकरण और अन्य कांच सामानों का उत्पादन होता रहा है।

14. (C) I, II और IV
सीमेंट उद्योग में भार-ह्रासकारी कच्चे माल का उपयोग होता है, अतः इसके संयंत्र चूना पत्थर खदानों के पास स्थित होते हैं। नागौर, पाली और चित्तौड़गढ़ इसके प्रमुख केंद्र हैं। इसके निर्माण में पश्चिमी राजस्थान का जिप्सम अत्यंत उपयोगी है। परंतु इन संयंत्रों के लिए कोयला अन्य राज्यों से परिवहन किया जाता है, इसलिए स्थानीय कोयले से कम ऊर्जा लागत का दावा सही नहीं है।

15. (D) खुर्जा
खुर्जा उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध सिरामिक क्लस्टर है, जो राजस्थान की सीमाओं के अंतर्गत नहीं आता है। इसके विपरीत, बीकानेर जिला उच्च गुणवत्ता वाली बॉल क्ले के लिए प्रसिद्ध है, जयपुर अपनी पारंपरिक हस्तशिल्प ब्लू पॉटरी कला के लिए जाना जाता है, तथा अलवर का थानागाजी क्षेत्र सिरामिक निर्माण का स्थानीय केंद्र है। अतः यह बेमेल है।

16. (C) जावर
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा संचालित जावर एक प्रमुख भूमिगत खनन स्थल है जहाँ से जस्ता-सीसा अयस्क निकाला जाता है, न कि कोई स्मेल्टिंग परिसर। इसके विपरीत, चंदेरिया, देबारी और दरीबा में कंपनी के आधुनिक धातु स्मेल्टिंग संयंत्र स्थित हैं, जहाँ अयस्क का प्रगलन करके शुद्ध जस्ता, सीसा और चांदी का उत्पादन किया जाता है। अतः जावर केवल खनन क्षेत्र है।

17. (A) II, IV, III, I
सीमेंट निर्माण की प्रक्रिया एक क्रमिक औद्योगिक चरण का पालन करती है। सबसे पहले चूना पत्थर का खनन करके उसे बारीक पीसा जाता है। दूसरे चरण में इस कच्चे माल का सम्मिश्रण करके पूर्व-तापन किया जाता है। तीसरे चरण में घूर्णी भट्टी में तापन द्वारा क्लिंकर निर्मित होता है। अंतिम चरण में जिप्सम मिलाकर क्लिंकर की पिसान की जाती है।

18. (D) जिप्सम प्रसंस्करण - बांसवाड़ा
राजस्थान में जिप्सम के मुख्य निक्षेप और प्रसंस्करण उद्योग पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी जिलों जैसे बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर में केंद्रित हैं। इसके विपरीत, दक्षिणी राजस्थान में स्थित बांसवाड़ा जिला मुख्य रूप से मैंगनीज और डोलोमाइट खनिजों के लिए जाना जाता है। बांसवाड़ा में जिप्सम का कोई व्यावसायिक उत्खनन या औद्योगिक प्रसंस्करण आधार उपलब्ध नहीं है, अतः यह असंगत है।

19. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
बीकानेर जिले में सिरामिक और पॉटरी उद्योग का तीव्र विकास हुआ है, जिसका मुख्य कारण यहाँ उच्च श्रेणी की बॉल क्ले, फायर क्ले और चाइना क्ले के विशाल निक्षेपों की मौजूदगी है। कच्चे माल की इस सहज उपलब्धता और प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास से बीकानेर एक प्रमुख सिरामिक औद्योगिक केंद्र बनकर उभरा है, जहाँ टाइल्स का निर्माण किया जाता है।

NODIA

20. (C) सिलिकोसिस
कोटा और धौलपुर जैसे जिलों में बलुआ पत्थर की खदानों तथा प्रसंस्करण इकाइयों में सूखी कटाई और घिसाई के दौरान सिलिका धूल के बारीक कण वायुमंडल में फैल जाते हैं। सुरक्षा साधनों के बिना लगातार इस धूल में सांस लेने से खदान श्रमिकों के फेफड़ों में सिलिकोसिस नामक एक असाध्य एवं गंभीर व्यावसायिक श्वसन बीमारी हो जाती है, जो उन्हें प्रभावित करती है।

21. (A) राजस्थान औद्योगिक विकास नीति
राजस्थान औद्योगिक विकास नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में खनिज संसाधनों का केवल निष्कर्षण करने के बजाय उनका स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन सुनिश्चित करना है। यह नीति कच्चे पत्थरों तथा अयस्कों को बिना प्रसंस्कृत किए बाहर भेजने के स्थान पर राज्य के भीतर आधुनिक इकाइयाँ स्थापित करने को प्रोत्साहित करती है, जिससे स्थानीय रोजगार एवं राजस्व में वृद्धि होती है।

22. (B) केवल III
राजस्थान में अवैज्ञानिक एवं अनियंत्रित खनन गतिविधियों के कारण जल तालिका में भारी गिरावट आई है, जिससे स्थानीय पर्यावरण प्रभावित हुआ है। खनन नियमों के तहत समाप्त हो

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from
PRINTED BOOKS has up to
4× HIGHER RETENTION
than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY
PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

(D) मृदा को स्थिर करने और मृदा प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए पौधों का उपयोग करना

71. राजस्थान में खनिज-आधारित उद्योगों की अवस्थिति निर्धारित करने वाले निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए:
I. कच्चे माल बनाम तैयार माल की भाड़ा लागत
II. निरंतर और सस्ती विद्युत शक्ति की उपलब्धता
III. अनुकूल राज्य औद्योगिक नीतियां और कर प्रोत्साहन
IV. 50 किमी के दायरे में समुद्री बंदरगाहों की उपलब्धता
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन राजस्थान में औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले वास्तविक कारकों का प्रतिनिधित्व करता है/करते हैं?
(A) I, II और IV
(B) I, II और III
(C) II, III और IV
(D) I, III और IV

72. कटाई इकाइयों से स्टोन स्लरी के अनियंत्रित निर्वहन का स्थानीय जलविज्ञान पर सबसे गंभीर प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है?
(A) यह सतह के जल वाष्पीकरण को पूरी तरह से रोककर स्थानीय भूमिगत जल स्तर में काफी वृद्धि करता है।
(B) यह सभी हानिकारक जैविक संदूषकों को सक्रिय रूप से छानकर स्थानीय भूजल आपूर्ति को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करता है।
(C) जल निकासी प्रणालियों को अवरुद्ध करना और मृदा के रंध्रों को बंद करना, जिससे रिसाव रुक जाता है
(D) यह तीव्र गति से गहरे भूमिगत चूना पत्थर के आधारशैल को रासायनिक रूप से घोल देता है, जिससे बड़े पैमाने पर धंसाव उत्पन्न होते हैं।

73. खनिज उद्योग के लिए सरकारी नीतिगत समर्थन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: राजस्थान औद्योगिक विकास नीति खनिज प्रसंस्करण में लगे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को पूंजीगत निवेश सब्सिडी प्रदान करती है।
कथन II: यह नीति अनिवार्य करती है कि निजी खनिज उद्योगों द्वारा उत्पन्न 100% लाभ राज्य के खजाने में जमा किया जाना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

74. निम्नलिखित में से कौन-सा राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (RSMML) का मूल कार्य नहीं है?
(A) निजी खनिकों को पर्यावरणीय स्वीकृतियां जारी करना
(B) उच्च श्रेणी के रॉक फॉस्फेट निक्षेपों का वाणिज्यिक खनन और घरेलू विपणन
(C) क्षेत्रीय तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्रों के लिए लिग्नाइट कोयले का मशीनीकृत निष्कर्षण
(D) उद्योगों को उच्च श्रेणी के जिप्सम का बड़े पैमाने पर निष्कर्षण और वाणिज्यिक बिक्री

75. सिरामिक विट्रिफाइड टाइलों के निर्माण के लिए, खनिजों का कौन-सा संयोजन प्राथमिक बॉडी सामग्री के रूप में कार्य करता है?
(A) बॉक्साइट अयस्क और परिष्कृत लौह अयस्क
(B) क्ले (मिट्टी), फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज
(C) गैलेना अयस्क और धात्विक स्फेलेराइट
(D) प्राकृतिक जिप्सम और रॉक हैलाइट

76. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (प्रमुख खनिज इनपुट)
P. सीसा-जस्ता अयस्क
Q. बॉल क्ले
R. सीमेंट-ग्रेड चूना पत्थर
S. तांबा अयस्क
सूची II: (स्थानीय उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रमुख उत्पादक जिला)
1. चित्तौड़गढ़
2. झुंझुनू
3. भीलवाड़ा (रामपुरा आगूचा)
4. बीकानेर
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

77. स्मेल्टिंग उद्योग की उपस्थिति ने राजस्थान में उर्वरक उद्योग के विकास को प्रोत्साहित किया है। कौन-सा स्मेल्टिंग उप-उत्पाद सुपरफॉस्फेट उर्वरकों के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में कार्य करता है?
(A) सल्फ्यूरिक अम्ल
(B) परिष्कृत जिंक ऑक्साइड पाउडर
(C) दानेदार वात्या भट्टी स्लैग सीमेंट
(D) रिफाइनरी इलेक्ट्रो-स्लाइम एनोड मड

78. जिप्सम और अन्य क्षेत्रों के बीच औद्योगिक संबंध के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) पोर्टलैंड सीमेंट की जलयोजन दर को नियंत्रित करने के लिए सीमेंट उद्योग में जिप्सम अपरिहार्य है।
(B) राजस्थान में क्षारीय मृदा के सुधार के लिए कृषि में कच्चे जिप्सम का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है।
(C) प्लास्टर ऑफ पेरिस का उत्पादन 1000°C से अधिक तापमान पर जिप्सम को पूरी तरह से पिघलाकर किया जाता है।
(D) RSMML राजस्थान और पड़ोसी राज्यों के सीमेंट संयंत्रों को जिप्सम का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।

Click Here to Buy book on Amazon

79. जालौर-सिरोही क्षेत्र में ग्रेनाइट प्रसंस्करण इकाइयों के संकेंद्रण का सबसे उपयुक्त कारण क्या है?
(A) इस क्षेत्र में भारी पत्थर के निर्यात के लिए विशेष रूप से कानूनी रूप से नामित देश का एकमात्र अंतर्देशीय माल डिपो मौजूद है।
(B) इस क्षेत्र में राज्य की उच्चतम वार्षिक मानसूनी वर्षा होती है, जिससे पत्थर काटने की आरियों के लिए निरंतर प्रचुर जल आपूर्ति मिलती है।
(C) सख्त राज्य पर्यावरण संरक्षण कानून राजस्थान के किसी भी अन्य जिले में ग्रेनाइट कटाई और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रतिबंधित करते हैं।
(D) मालानी आग्नेय समूह के ग्रेनाइट अंतर्वेशनों से समीपता, जिससे परिवहन लागत कम होती है

80. कुल मिलाकर, खनिज-आधारित उद्योग संरचनात्मक रूप से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान करते हैं?
(A) वे गैर-कटाई के मौसम के दौरान कृषि श्रमिकों को अस्थायी रोजगार प्रदान करके विशेष रूप से प्राथमिक क्षेत्र का समर्थन करते हैं, जबकि न्यूनतम आर्थिक निर्यात मूल्य उत्पन्न करते हैं।
(B) वे खनिज व्यापार और पर्यटन के माध्यम से राज्य के तृतीयक सेवा क्षेत्र में लगभग पूरी तरह से योगदान करते हैं, जबकि औद्योगिक निर्माण उत्पादन पर उनका कोई मापने योग्य प्रभाव नहीं पड़ता है।
(C) वे विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, व्यापक रोजगार सृजित करते हैं, और द्वितीयक क्षेत्र का समर्थन करते हैं।
(D) वे कुल राज्य सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत से भी कम हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं और वर्तमान में गंभीर घरेलू संसाधन क्षरण के कारण नीति निर्माताओं द्वारा उन्हें धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है।

NODIA

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान में सीमेंट निर्माण का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस जिले में उच्च गुणवत्ता वाले चूना पत्थर के विशाल और निरंतर निक्षेप पाए जाते हैं, जो सीमेंट उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल हैं। कच्चे माल की प्रचुर उपलब्धता, परिवहन साधनों के विकास तथा जल एवं विद्युत की सुलभता ने चित्तौड़गढ़ को एक विशाल औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया है, जहाँ कई बड़े सीमेंट संयंत्र कार्यरत हैं।

2. (D) संगमरमर कटाई और प्रसंस्करण
राजस्थान का अजमेर जिले में स्थित किशनगढ़ शहर संगमरमर प्रसंस्करण और व्यापार के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक प्रसिद्ध है। यहाँ राज्य तथा अन्य क्षेत्रों से उत्खनित कच्चे संगमरमर के ब्लॉकों को लाया जाता है। अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से इनकी कटाई, घिसाई और पॉलिशिंग करके स्लैब तथा टाइलें तैयार की जाती हैं। सुदृढ़ आपूर्तिकर्ता नेटवर्क और व्यापारिक अवसंरचना के कारण किशनगढ़ एशिया का सबसे बड़ा संगमरमर बाजार बन चुका है।

3. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित चंदेरिया सीसा-जस्ता स्मेल्टर संयंत्र एशिया के सबसे बड़े जस्ता-सीसा प्रगलन परिसरों में से एक है। इसकी स्थापना में कच्चे माल की निकटता ने निर्णायक भूमिका निभाई है, क्योंकि भीलवाड़ा जिले में स्थित रामपुरा आगूचा खदान यहाँ से पास स्थित है। इसके साथ ही, इसे निरंतर संचालन हेतु आवश्यक विद्युत और जलापूर्ति सुचारू रूप से प्राप्त होती है, जिससे प्रगलन लागत काफी घटती है।

4. (C) P-3, Q-1, R-2, S-4
राजस्थान में खनिज-आधारित उद्योगों का प्रादेशिक वितरण स्थानीय कच्चे माल पर निर्भर करता है। जालौर जिला अपने ग्रेनाइट प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है, जबकि धौलपुर अपने लाल बलुआ पत्थर की कटाई के लिए जाना जाता है। बीकानेर में बॉल क्ले के प्रचुर भंडार होने से यह सिरामिक उद्योग का केंद्र है, तथा झुंझुनू जिला खेतड़ी के कारण तांबा प्रगलन एवं शोधन का प्रमुख केंद्र है।

5. (A) बॉक्साइट
कांच निर्माण मुख्य रूप से सिलिका आधारित खनिज उद्योग है। कांच के उत्पादन के लिए सिलिका रेत प्राथमिक कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाती है, जबकि soda ऐश और चूना पत्थर का उपयोग गालक तथा स्थायित्व प्रदान करने वाले घटकों के रूप में किया जाता है। इसके विपरीत, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है तथा कांच निर्माण में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है।

6. (A) केवल I और II
खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की एक एकीकृत इकाई है, जो तांबा उत्खनन और स्मेल्टिंग कार्य करती है। सल्फाइड अयस्क के भर्जन के दौरान निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है, जो एक उप-उत्पाद है। यह कॉम्प्लेक्स स्थानीय कोलिहान जैसी सहबद्ध खदानों से प्राप्त तांबा सांद्र का प्रसंस्करण करता है, अतः केवल आयात आधारित नहीं है।

7. (B) सीमेंट के जमने की समय-अवधि को बढ़ाना
पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में जिप्सम एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंदक के रूप में मिलाया जाता है। जब क्लिंकर को पीसा जाता है, तब उसमें लगभग 3 से 5 प्रतिशत जिप्सम मिलाया जाता है। यह जल मिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। इससे सीमेंट तुरंत जमने के बजाय धीरे-धीरे सामर्थ्य प्राप्त करता है, जिससे निर्माण कार्य हेतु पर्याप्त समय मिल जाता है।

8. (C) साझा स्थानीय अवसंरचना, विशिष्ट श्रम और आपूर्तिकर्ता नेटवर्क के कारण उत्पादन लागत में कमी
संवहन अर्थव्यवस्था वह आर्थिक लाभ है जो समान उद्योगों के एक ही भौगोलिक क्षेत्र में समूहित होने से प्राप्त होता है। किशनगढ़ में सैकड़ों संगमरमर प्रसंस्करण इकाइयाँ, कुशल श्रम, परिवहन नेटवर्क और व्यापारिक संगठन एक साथ केंद्रित हैं। इस भौगोलिक निकटता के कारण सभी इकाइयों को साझा अवसंरचना, कच्चे माल की आसानी और विपणन में परिचालन लागत में कमी का सीधा लाभ प्राप्त होता है।

9. (A) ब्लॉक उत्खनन - स्लैब कटाई - एज पॉलिशिंग - मूल्य-वर्धित डिजाइनिंग - निर्यात
डिमेंशनल स्टोन उद्योग में मूल्य श्रृंखला का एक निश्चित तार्किक क्रम होता है। सर्वप्रथम खदानों से भारी पत्थरों के ब्लॉक का उत्खनन किया जाता है। इसके पश्चात इन ब्लॉकों को प्रसंस्करण इकाइयों में लाकर स्लैब में काटा जाता है। तत्पश्चात सतह एवं किनारों की पॉलिशिंग की जाती है। फिर आवश्यकतानुसार मूल्य-वर्धित डिजाइनिंग की जाती है और अंत में इन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात करते हैं।

10. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
पत्थर प्रसंस्करण में कटाई के दौरान अत्यधिक बारीक स्लरी उप-उत्पाद के रूप में निकलती है। जब इस स्लरी को खुली भूमि पर फेंका जाता है, तो यह सूखकर मिट्टी के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे जल रिसाव रुकता है और भूजल पुनर्भरण बाधित होता है। यह स्लरी अकार्बनिक होती है, अतः यह

Downloaded from www.pdf.tube

जयपुर उद्योग द्वारा विशाल सीमेंट कारखाने की शुरुआत की गई। तत्पश्चात चित्तौड़गढ़ जिले के निंबाहेड़ा में बड़े पैमाने पर सीमेंट उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया। अतः यह सही क्रम है।

34. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
संगमरमर की कटाई और पॉलिशिंग प्रक्रिया में भारी मात्रा में बारीक चूना धूल जनित स्लरी निकलती है। यदि इसका उचित निस्तारण न किया जाए, तो यह हवा में उड़कर वायु प्रदूषण और भूमि पर जमा होकर मृदा प्रदूषण फैलाती है। इस समस्या से निपटने हेतु राजस्थान सरकार इस स्लरी का उपयोग ईंटों तथा सिंथेटिक जिप्सम निर्माण में प्रोत्साहित कर रही है।

35. (A) सूक्ष्म दानेदार चूना पत्थर
कोटा स्टोन मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कोटा और झालावाड़ जिलों में उत्खनित होने वाला एक विशिष्ट प्राकृतिक पत्थर है। भूवैज्ञानिक रूप से यह अत्यधिक सूक्ष्म दानेदार, सघन और अवसादी प्रकार का चूना पत्थर है। इसकी उच्च मजबूती और आकर्षक प्राकृतिक रंगों के कारण इसका उपयोग पूरे भारत में भवनों की फर्श सामग्री के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है।

36. (C) किशनगढ़ स्टोन क्लस्टर
चंदेरिया सीसा-जस्ता स्मेल्टर, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स और देबारी स्मेल्टर प्राथमिक धात्विक प्रगलन उद्योग हैं जहाँ रासायनिक एवं तापीय प्रक्रियाओं द्वारा अयस्कों से शुद्ध धातुओं का निष्कर्षण होता है। इसके विपरीत, किशनगढ़ स्टोन क्लस्टर एक गैर-धात्विक पत्थर कटाई और पॉलिशिंग क्लस्टर है। यहाँ यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पत्थरों की घिसाई होती है, न कि धातुओं का स्मेल्टिंग, अतः यह भिन्न वर्गीकरण है।

37. (A) बलुआ पत्थर
राजस्थान का पूर्वी भाग, विशेष रूप से धौलपुर और भरतपुर जिले, अपने प्रचुर बलुआ पत्थर भंडार और इसके प्रसंस्करण उद्योग के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। धौलपुर का लाल बलुआ पत्थर तथा भरतपुर का बंशी पहाड़पुर पत्थर अपनी महीन बनावट और नक्काशी योग्य विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। यहाँ स्थापित इकाइयाँ इसका प्रसंस्करण करके विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु आपूर्ति करती हैं।

38. (A) I, II और III
राजस्थान में सिरामिक उद्योग स्थानीय फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, बॉल क्ले और चाइना क्ले के भंडारों पर आधारित है। बीकानेर और बाड़मेर जिले इन उच्च श्रेणी की मिट्टियों के मुख्य स्रोत हैं। सिरामिक उत्पादों को पकाने हेतु भट्टियों के संचालन के लिए निरंतर उच्च तापीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। राज्य में विट्रिफाइड टाइल्स का बड़े पैमाने पर आधुनिक उत्पादन होता है।

39. (B) सिलिका रेत
कांच निर्माण प्रक्रिया में सिलिका रेत प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण खनिज कच्चा माल है, जो कांच के मुख्य ढाँचे का निर्माण करती है। धौलपुर, जयपुर, बाड़मेर और बीकानेर जैसे राजस्थान के जिलों में उच्च गुणवत्ता वाली सिलिका रेत के निक्षेप उपलब्ध हैं। इस सिलिका रेत को अन्य रसायनों के साथ मिलाकर भट्टियों में पिघलाकर विविध कांच उत्पाद तैयार किए जाते हैं।

40. (C) स्मेल्टर तक परिवहन लागत को कम करने के लिए अयस्क ग्रेड में सुधार करने के लिए
रामपुरा आगूचा खदान से निकाला गया कच्चा अयस्क कम धात्विक सांद्रता वाला होता है और इसमें बड़ी मात्रा में व्यर्थ चट्टानी पदार्थ होता है। यदि कच्चे अयस्क को सीधे दूर स्थित स्मेल्टर तक भेजा जाए, तो परिवहन व्यय बहुत अधिक होगा। इसलिए खदान स्थल पर ही पेषण द्वारा अयस्क का सांद्रण करके धातु ग्रेड बढ़ाया जाता है ताकि परिवहन लागत कम हो।

41. (D) श्री सीमेंट
श्री सीमेंट समूह भारत की अग्रणी सीमेंट उत्पादक कंपनियों में से एक है, जिसका मुख्य औद्योगिक आधार राजस्थान में स्थित है। यह समूह पाली जिले के रास तथा अजमेर जिले के ब्यावर में आधुनिक और विशाल सीमेंट निर्माण संयंत्रों का संचालन करता है। इस क्षेत्र में उपलब्ध चूना पत्थर पट्टियों का लाभ उठाकर कंपनी ने बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता स्थापित की है।

42. (A) कम-लोहा युक्त चूना पत्थर
नागौर जिले के गोटन और खारिया खंगार क्षेत्रों में सफेद सीमेंट का विशाल आधार है। साधारण सीमेंट का धूसर रंग उसमें उपस्थित लोहे की मात्रा के कारण होता है। नागौर में अति उच्च शुद्धता वाला चूना पत्थर मिलता है जिसमें लोहा अत्यंत कम होता है। इस कम-लोहा युक्त चूना पत्थर के कारण यहाँ सफेद सीमेंट का उत्पादन संभव हुआ है।

43. (B) चूरू
राजस्थान में बड़े पैमाने के पोर्टलैंड सीमेंट संयंत्र चूना पत्थर भंडारों वाली प्रमुख पट्टियों में स्थित हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी, पाली और नागौर जिले। इसके विपरीत, चूरू जिला उत्तरी थार मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है, जहाँ वाणिज्यिक गुणवत्ता वाले सीमेंट चूना पत्थर के विशाल भंडारों का अभाव है। अतः यहाँ कोई बड़ा सीमेंट कारखाना स्थापित नहीं हुआ है।

44. (B) नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की उपलब्धता
राजस्थान एक भू-आबद्ध राज्य है जो मुख्य रूप से शुष्क एवं अर्ध-शुष्क जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य में वर्षभर बहने वाली नौगम्य अंतर्देशीय नदियां या जलमार्ग पूरी तरह से अनुपस्थित हैं। इसलिए, नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की उपस्थिति यहाँ खनिज-आधारित उद्योगों की अवस्थिति का कारक नहीं है। इसके स्थान पर कच्चे माल की समीपता, निर्बाध विद्युत आपूर्ति और सड़क-रेल परिवहन नेटवर्क ही प्राथमिक स्थान निर्धारक कारक हैं।

45. (A) केवल I और II
कच्चे अनगढ़ पत्थरों के सीधे निर्यात की तुलना में पॉलिश की गई स्लैब, नक्काशीदार जालियों और हस्तशिल्प कलाकृतियों

NODIA

चुकी खदानों को भरकर उनका पुनरुद्धार और पारिस्थितिक बहाली करना अनिवार्य होता है। परंतु स्टोन स्लरी का जमाव वनस्पतियों की वृद्धि को बाधित करता है, अतः यह सकारात्मक योगदान नहीं देता है।

23. (B) चंदेरिया स्मेल्टर बिना किसी पायरोधात्विक क्षमता के पूरी तरह से हाइड्रोधात्विक इकाइयों पर कार्य करता है।
चंदेरिया सीसा-जस्ता स्मेल्टर संयंत्र एक अत्यधिक उन्नत परिसर है जो पायरोधात्विक और हाइड्रोधात्विक दोनों प्रकार की तकनीकों का उपयोग करता है। इसमें इंपीरियल स्मेल्टिंग फर्नेस जैसी पायरोधात्विक प्रक्रिया मौजूद है, जो सीसा एवं जस्ता धातुओं का प्रगलन कर सकती है। अतः यह कहना गलत है कि यह केवल हाइड्रोधात्विक प्रणाली पर कार्य करता है। यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल भी बनता है।

24. (C) बीकानेर, नागौर और श्रीगंगानगर में राज्य के जिप्सम के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं।
राजस्थान में जिप्सम आधारित औद्योगिक इकाइयाँ मुख्य रूप से बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में केंद्रित हैं। इसका प्राथमिक कारण यह है कि भारत के कुल जिप्सम भंडार का 90% से अधिक हिस्सा राजस्थान के इन्हीं पश्चिमी एवं उत्तर-पश्चिमी जिलों में निक्षेपों के रूप में पाया जाता है। कच्चे माल की इस प्रचुर उपलब्धता के कारण इकाइयाँ यहीं स्थापित हैं।

25. (D) बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर
भरतपुर जिले में स्थित बंशी पहाड़पुर का बलुआ पत्थर अपनी विशिष्ट गुलाबी-लाल रंगत, बेहतरीन नक्काशी क्षमता और दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए प्रसिद्ध है। इस ऐतिहासिक पत्थर का उपयोग ऐतिहासिक काल में दिल्ली के लाल किले के निर्माण में किया गया था। वर्तमान समय में भी इसकी उत्कृष्ट वास्तुशिल्प गुणवत्ता के कारण अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में इसका उपयोग हुआ है।

26. (A) बंद-पाश जल पुनर्चक्रण को अपनाना और ईंट बनाने में स्लरी का उपयोग करना
सतत औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान के पत्थर प्रसंस्करण क्षेत्र में संसाधन दक्षता अपनाना अत्यंत अनिवार्य है। पत्थर काटने की प्रक्रिया में जल का बंद-पाश पुनर्चक्रण करने से ताजे पानी की खपत में कमी आती है। इसके अलावा, कटाई से निकलने वाली स्टोन स्लरी का उपयोग निर्माण ईंटों तथा अन्य उत्पादों में करने से पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रित होता है।

27. (B) अप्रसंस्कृत लिग्नाइट कोयला
राजस्थान में पाया जाने वाला लिग्नाइट कोयला मुख्य रूप से कम ग्रेड का कोयला है, जिसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। इसका उपयोग राज्य के भीतर ही तापीय विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पादन हेतु किया जाता है। इसे निर्यात नहीं किया जाता है। इसके विपरीत, पॉलिश ग्रेनाइट स्लैब, सिरामिक टाइलें और संगमरमर कलाकृतियां राज्य के प्रमुख निर्यात घटक हैं।

28. (B) P-3, Q-1, R-2, S-4
राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित हैं। जैसलमेर जिला अपने पीले बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर जिला हरे संगमरमर के उत्खनन और प्रसंस्करण का मुख्य केंद्र है। नागौर का मकराना अपने प्रसिद्ध सफेद संगमरमर के लिए जाना जाता है, जबकि कोटा और झालावाड़ जिले अपनी फर्श सामग्री 'कोटा स्टोन' के प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध हैं।

29. (A) विशिष्ट ब्लॉक या स्लैब आयामों में उत्खनित और तराशी गई प्राकृतिक चट्टान
"डिमेंशनल स्टोन" शब्द का तात्पर्य उन प्राकृतिक चट्टानों से है जिन्हें खदानों से विशिष्ट आकारों, मोटाई और निश्चित आयामों वाले ब्लॉकों या स्लैबों में काटा और तराशा जाता है। संगमरमर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर तथा कोटा स्टोन इसके मुख्य उदाहरण हैं। इन पत्थरों का उपयोग इमारतों में फर्श, दीवार क्लैडिंग, काउंटरटॉप्स और विभिन्न वास्तुकला घटकों के रूप में व्यापक रुप से किया जाता है।

30. (C) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स (CDOS)
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स (CDOS) राजस्थान सरकार और रीको द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था है, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना विशेष रूप से डिमेंशनल स्टोन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु की गई थी। यह संस्थान पत्थर उद्योग में अनुसंधान, कौशल संवर्धन, आधुनिक तकनीकों के परीक्षण तथा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजनों द्वारा पत्थर व्यापार को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

31. (D) निवेश केवल निष्कर्षण से हटकर स्थानीय मूल्य-वर्धित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की ओर स्थानांतरित हुआ है।
हाल के दशकों में राजस्थान के खनिज-आधारित उद्योगों में निजी क्षेत्र का निवेश केवल खदानों से कच्चे अयस्क या पत्थर निकालने तक सीमित नहीं रहा है। राज्य सरकार की प्रोत्साहन नीतियों और आधुनिक तकनीकों के आगमन के साथ निजी निवेशकों ने पूंजी को मूल्य-वर्धित प्रसंस्करण इकाइयों में लगाया है। इनमें आधुनिक गैंग आरी, स्वचालित पॉलिशिंग लाइनें और सिरामिक इकाइयाँ शामिल हैं।

32. (C) चूना पत्थर जैसे भारी कच्चे माल से समीपता
सीमेंट उद्योग एक विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर भारी और भार-ह्रासकारी उद्योग है। पोर्टलैंड सीमेंट के एक टन उत्पादन के लिए लगभग 1.4 से 1.5 टन चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। चूना पत्थर एक भारी वस्तु है, जिसकी लंबी दूरी तक परिवहन लागत अत्यधिक होती है। इसलिए, परिवहन व्यय को न्यूनतम करने के लिए सीमेंट संयंत्र चूना पत्थर खदानों के पास स्थापित किए जाते हैं।

33. (A) लाखेरी (पहला) → सवाई माधोपुर → निंबाहेड़ा
राजस्थान में आधुनिक सीमेंट निर्माण का इतिहास बूंदी जिले के लाखेरी में शुरु हुआ, जहाँ वर्ष 1915 में राज्य का पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था। इसके बाद सवाई माधोपुर में

Click Here to Buy book on Flipkart

पुनर्वास प्रदान करने हेतु राज्य सरकार ने न्यूमोकोनिओसिस नीति लागू की है।

57. (D) P-2, Q-1, R-4, S-3
प्रत्येक खनिज उद्योग प्रक्रिया एक विशिष्ट पर्यावरणीय चिंता पैदा करती है। पत्थर की कटाई और पॉलिशिंग से जनित स्लरी मृदा की सरंध्रता को प्रभावित करती है। धातु स्मेल्टिंग से सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन तथा स्लैग पैदा होता है। विवृत खनन से वनों की कटाई और भूदृश्य क्षरण होता है, जबकि सीमेंट निर्माण उच्च कणिकीय पदार्थ उत्सर्जन का मुख्य कारण बनता है।

58. (A) RSRTC (सड़क परिवहन निगम)
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम राज्य में केवल सार्वजनिक बस परिवहन और यात्री सेवाओं के संचालन हेतु उत्तरदायी निकाय है। इसका खनिज क्षेत्र, खनन नीतियों अथवा औद्योगिक विकास से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इसके विपरीत, RSMML, भूविज्ञान निदेशालय तथा CDOS जैसे निकाय राज्य के खनन, खनिज विकास एवं पत्थर उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु समर्पित रूप से कार्यरत संस्थाएँ हैं।

59. (B) संगमरमर और ग्रेनाइट
राजस्थान के डिमेंशनल स्टोन निर्यात पोर्टफोलियो में प्रसंस्कृत संगमरमर और ग्रेनाइट का योगदान सबसे अधिक है। राज्य से प्रतिवर्ष विशाल मात्रा में पॉलिश की गई संगमरमर तथा ग्रेनाइट स्लैब, टाइलें और नक्काशीदार उत्पाद विभिन्न देशों को निर्यात किए जाते हैं। आधुनिक मशीनीकरण और स्वचालित पॉलिशिंग से निर्मित ये प्रसंस्कृत उत्पाद राज्य के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने के प्रमुख साधन हैं।

60. (A) II, IV, III, I
संगमरमर प्रसंस्करण की प्रक्रिया में एक क्रमिक परिचालन क्रम शामिल होता है। सबसे पहले खदानों से भारी संगमरमर ब्लॉकों का उत्खनन किया जाता है। दूसरे चरण में इन ब्लॉकों को प्रसंस्करण इकाइयों में गैंग आरी द्वारा स्लैबों में काटा जाता है। तीसरे चरण में स्लैबों की पॉलिशिंग एवं रेजिन उपचार किया जाता है। अंतिम चरण में पैकिंग करके निर्यात करते हैं।

61. (A) उदयपुर
राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड का कॉर्पोरेट मुख्यालय उदयपुर शहर में स्थित है। उदयपुर दक्षिणी राजस्थान के उस खनन क्षेत्र में स्थित है जहाँ झामरकोटड़ा जैसी विश्वस्तरीय रॉक फॉस्फेट खदान स्थित है। यह सार्वजनिक उपक्रम राज्य में रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, लिग्नाइट तथा चूना पत्थर के व्यावसायिक खनन एवं वितरण गतिविधियों का केंद्रीय प्रबंधन उदयपुर कार्यालय से संचालित करता है।

62. (C) ग्रेनाइट स्लैब - डायमंड वायर सॉ और मल्टी-ब्लेड ब्लॉक कटर
ग्रेनाइट एक अत्यंत कठोर आग्नेय चट्टान है, जिसकी कटाई और प्रसंस्करण के लिए पारंपरिक साधारण उपकरण पूरी तरह अनुपयुक्त होते हैं। आधुनिक ग्रेनाइट प्रसंस्करण इकाइयों में भारी ग्रेनाइट ब्लॉकों को काटने के लिए डायमंड वायर सॉ और मल्टी-ब्लेड ब्लॉक कटर जैसे अत्याधुनिक मशीनीकृत उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ये आधुनिक उपकरण अत्यधिक कठोर ग्रेनाइट को भी उच्च परिशुद्धता के साथ सपाट और पतली स्लैबों में आसानी से काटते हैं।

63. (A) केवल I और II
राजस्थान में परित्यक्त गहरी विवृत खदानों के सुरक्षित पुनर्वास हेतु खदानों को भरकर वनीकरण और पारिस्थितिक बहाली की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही, पुराने स्मेल्टिंग स्थलों के पास भारी धातुओं से भूजल संदूषण एक गंभीर चिंता है। वर्तमान खनन नीतियां कानूनी रूप से खदानों को बिना उपचार छोड़ने की अनुमति नहीं देतीं, अतः तीसरा कथन गलत साबित होता है।

64. (C) अपरिष्कृत, अनगढ़ बलुआ पत्थर के बोल्डर
मूल्य-वर्धित उत्पाद उन वस्तुओं को संदर्भित करते हैं जिनमें प्राथमिक उत्खनन के बाद प्रसंस्करण, कटाई, शेपिंग, नक्काशी या फिनिशिंग जैसी यांत्रिक प्रक्रियाएँ करके उनका आर्थिक मूल्य बढ़ाया गया हो। अपरिष्कृत और अनगढ़ बलुआ पत्थर के बोल्डर खदान से निकले सीधे कच्चे प्राथमिक पत्थर होते हैं, जिन पर कोई यांत्रिक या औद्योगिक प्रसंस्करण नहीं किया गया होता है। अतः इन्हें मूल्य-वर्धित उत्पाद नहीं माना जाता है।

65. (B) प्रत्यक्ष प्रसंस्करण नौकरियां तथा अप्रत्यक्ष व्यापार और रसद रोजगार
किशनगढ़ संगमरमर क्लस्टर राजस्थान में बड़े पैमाने पर औद्योगिक रोजगार सृजन का एक मुख्य केंद्र है। यह क्लस्टर दोहरे स्तर पर रोजगार उत्पन्न करता है। प्रथम, संगमरमर प्रसंस्करण इकाइयों में मशीन ऑपरेटरों, कटिंग कारीगरों और श्रमिकों के रूप में प्रत्यक्ष रोजगार। द्वितीय, पत्थर व्यापार, माल परिवहन लॉजिस्टिक्स, क्रेन संचालन, मशीनरी मरम्मत और विपणन के माध्यम से व्यापक अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मित होता है।

66. (D) सीएनसी स्टोन मशीनों और गैंग आरी का संचालन
आधुनिक पत्थर प्रसंस्करण क्षेत्र में कच्चे पत्थरों के अपव्यय को कम करने और उच्च परिशुद्धता वाले उत्पाद बनाने के लिए सीएनसी स्टोन मशीनों, डायमंड वायर आरी और मल्टी-ब्लेड गैंग आरी का संचालन सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी कौशल बन चुका है। इन आधुनिक मशीनों के संचालन से कम समय में सटीक कटाई और सुचारु पॉलिशिंग सम्भव होती है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है।

67. (A) प्राकृतिक गैस की मदद से सिरामिक और कांच के केंद्रों में निजी निवेश बढ़ा है।
राजस्थान में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार ने सिरामिक और कांच उद्योगों में निजी क्षेत्र के निवेश को गति प्रदान की है। बीकानेर, नीमराणा, घिलोठ और अलवर क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस की सुलभता ने निवेशकों को विट्रिफाइड टाइल और कांच इकाइयाँ स्थापित करने के लिए आकर्षित किया है, जिससे भारी निवेश प्राप्त हुआ है।

NODIA

जैसे मूल्य-वर्धित पत्थर उत्पादों से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। प्रसंस्कृत संगमरमर और ग्रेनाइट राजस्थान के कुल औद्योगिक निर्यात का एक बहुत प्रमुख हिस्सा हैं। मूल्यवर्धन की इस प्रक्रिया में कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, जिससे रोजगार बढ़ता ही है, अतः तीसरा कथन असत्य है।

46. (C) टिकाऊ फर्श और क्लैडिंग के लिए पतली विभाजित पत्थर की टाइलें
कोटा और झालावाड़ जिलों में स्थित बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर प्रसंस्करण इकाइयाँ विशेष रुप से प्राकृतिक स्प्लिट टाइलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। यह पत्थर अपनी परतों के साथ पतली और सपाट टाइलों में आसानी से विभाजित हो जाता है। इन विभाजित टाइलों का उपयोग भवनों में टिकाऊ फर्श, दीवार क्लैडिंग और फुटपाथ बनाने में किया जाता है।

47. (D) राजस्थान देश के सभी सीसा और जस्ता का उत्पादन करता है, जो राष्ट्र के स्मेल्टर्स को सहायता प्रदान करता है।
राजस्थान भारत के खनिज परिदृश्य में एक एकाधिकारवादी स्थान रखता है। यह देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो सीसा और जस्ता अयस्क का 100% उत्पादन करता है। रामपुरा आगूचा और जावर जैसे विशाल निक्षेपों के कारण राजस्थान में संपूर्ण सीसा-जस्ता खनन और प्रगलन उद्योग केंद्रित है। उत्पादित धातुएं देश के स्मेल्टर्स और उद्योगों की मांग को पूरा करती हैं।

48. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
राजस्थान में कांच उद्योग का संकेंद्रण मुख्य रूप से धौलपुर, अलवर और जयपुर जिलों में देखा जाता है। इसका प्राथमिक भूवैज्ञानिक और आर्थिक कारण इन जिलों में उच्च शुद्धता वाली सिलिका रेत के प्रचुर भंडारों की सुलभ निकटता है। इसके अतिरिक्त, ये जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पास स्थित होने के कारण विशाल खपत बाजारों, सुदृढ़ परिवहन नेटवर्क और ऊर्जा आपूर्ति से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं।

49. (B) ऑसमेल्ट तकनीक
चित्तौड़गढ़ में स्थित चंदेरिया सीसा-जस्ता स्मेल्टर में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए उन्नत 'ऑसमेल्ट' तकनीक को अपनाया गया था। यह एक आधुनिक जलमग्न प्रगलन तकनीक है, जो कम ऊर्जा खपत के साथ उच्च धातु पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करती है। यह तकनीक सल्फर डाइऑक्साइड गैस का कुशलतापूर्वक सल्फ्यूरिक अम्ल में रूपांतरण करके पर्यावरणीय मानकों का पालन करती है।

50. (D) सल्फ्यूरिक अम्ल
खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स में सल्फाइड तांबा अयस्क के भर्जन और स्मेल्टिंग के दौरान अत्यधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। यदि यह वायुमंडल में छोड़ी जाए तो पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचता है। इसलिए इस परिसर में एक सल्फ्यूरिक अम्ल संयंत्र स्थापित है, जो इस उत्सर्जन को अवशोषित करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है, जिसका उपयोग उर्वरक निर्माण में होता है।

51. (A) खेतड़ी-सिंघाना में चालकोपायराइट तांबा अयस्क निक्षेपों से समीपता
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की स्थापना का प्राथमिक कारण खेतड़ी-सिंघाना तांबा पट्टी में चालकोपायराइट तांबा अयस्क के प्रचुर निक्षेपों की उपस्थिति है। तांबा अयस्क एक भारी और कम धातु सांद्रता वाला कच्चा माल है, अतः परिवहन व्यय से बचने के लिए स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स खदानों के पास ही स्थापित किया गया है ताकि प्रगलन लाभप्रद रहे।

52. (B) I, II और III
राजस्थान में निष्कर्षित जिप्सम का उपयोग कई प्रमुख क्षेत्रों में किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट उद्योग में जिप्सम एक आवश्यक घटक है जो इसके जमने के समय को नियंत्रित करता है। इसे निर्जलीकृत करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। कृषि में इसका उपयोग क्षारीय मृदा के सुधार हेतु किया जाता है। परंतु कांच निर्माण में जिप्सम की भूमिका नहीं होती है।

53. (A) बलुआ पत्थर प्रसंस्करण इकाइयों को गालक के रूप में अत्यधिक मात्रा में चूना पत्थर की आवश्यकता होती है।
बलुआ पत्थर मुख्य रूप से यांत्रिक कटाई, तराशने, पॉलिशिंग और नक्काशी पर आधारित एक भौतिक डिमेंशनल स्टोन उद्योग है। इसके प्रसंस्करण में किसी भी प्रकार के रासायनिक प्रगलन की आवश्यकता नहीं होती, अतः गालक के रूप में चूना पत्थर का कोई उपयोग नहीं होता है। यह पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्वी जिलों से निकाला जाता है तथा बड़े पैमाने पर निर्यात होता है।

54. (D) सौंदर्यात्मक विविधता, उत्कृष्ट पॉलिश और संरचनात्मक स्थायित्व
जालौर का ग्रेनाइट अपनी विशिष्ट क्रिस्टलीय संरचना, अत्यधिक कठोरता और उच्च स्थायित्व के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। यह विभिन्न रंगों की विस्तृत सौंदर्यात्मक विविधता प्रस्तुत करता है। जब इसे आधुनिक आरी से काटा जाता है और स्वचालित मशीनों से पॉलिश किया जाता है, तो इसकी सतह पर उत्कृष्ट चमक प्राप्त होती है। इसकी उच्च मजबूती के कारण यह लोकप्रिय है।

NODIA

55. (B) समर्पित माल ढुलाई गलियारा मार्ग
समर्पित माल ढुलाई गलियारा राजस्थान के कई प्रमुख खनिज एवं पत्थर उत्पादक जिलों से होकर गुजरता है। भारी पत्थरों, सिरामिक टाइलों और सीमेंट के परिवहन में माल भाड़ा एक बड़ा घटक होता है। यह समर्पित रेल नेटवर्क मालगाड़ियों की गति बढ़ाकर और परिवहन लागत घटाकर पश्चिमी बंदरगाहों तक तीव्र पहुँच प्रदान करता है, जिससे राज्य की निर्यात क्षमता में वृद्धि होती है।

56. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
पत्थर प्रसंस्करण और खनन इकाइयों में सिलिका-समृद्ध पत्थरों की बिना सुरक्षा साधनों के सूखी ड्रिलिंग से सिलिका धूल हवा में घुल जाती है। सांस के माध्यम से यह धूल फेफड़ों में पहुंचकर सिलिकोसिस रोग उत्पन्न करती है। इस गंभीर स्वास्थ्य संकट से प्रभावित श्रमिकों को वित्तीय सहायता तथा

(B) बलुआ पत्थर - रासायनिक घुलनशील वैट
(C) ग्रेनाइट स्लैब - डायमंड वायर सॉ और मल्टी-ब्लेड ब्लॉक कटर
(D) स्लेट - थर्मल स्मेल्टिंग भट्टियां

63. राजस्थान में खनन और खनिज प्रसंस्करण क्षेत्रों की पुनर्वास चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. गहरी विवृत खदानों की बहाली के लिए व्यवस्थित भराव और वनीकरण की आवश्यकता होती है।
II. पुराने स्मेल्टिंग स्थलों के पास भारी धातुओं से भूजल का संदूषण एक गंभीर चिंता का विषय है।
III. यदि खनन कंपनी खुद को दिवालिया घोषित कर देती है, तो पुनर्वास नीतियां कानूनी रूप से छोड़ी गई खदानों को बिना उपचार के छोड़ने की अनुमति देती हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

64. निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर राजस्थान में पत्थर उद्योग के मूल्य-वर्धित उत्पाद के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है?
(A) कैलिब्रेटेड और चैम्फर्ड ग्रेनाइट टाइलें
(B) सीएनसी-उत्कीर्ण संगमरमर की जालियां
(C) अपरिष्कृत, अनगढ़ बलुआ पत्थर के बोल्डर
(D) एज-प्रोफाइल्ड स्टोन काउंटरटॉप्स

65. किशनगढ़ संगमरमर क्लस्टर औद्योगिक रोजगार सृजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह क्लस्टर मुख्य रूप से किस प्रकार का रोजगार उत्पन्न करता है?
(A) विशेष रूप से विशिष्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम इंजीनियरों के लिए आरक्षित प्रत्यक्ष उच्च-वेतनभोगी तकनीकी रोजगार
(B) प्रत्यक्ष प्रसंस्करण नौकरियां तथा अप्रत्यक्ष व्यापार और रसद रोजगार
(C) मानसून के ऑफ-सीजन के दौरान क्षेत्रीय कृषि श्रमिकों के लिए केवल मौसमी अप्रत्यक्ष अनौपचारिक रोजगार
(D) राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से सृजित सख्ती से स्थायी सरकारी प्रशासनिक नौकरियां

66. कच्चे माल के अपव्यय को कम करने के लिए खनिज प्रसंस्करण क्षेत्र में कौशल विकास महत्वपूर्ण है। आधुनिक पत्थर प्रसंस्करण इकाइयों में श्रमिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा तकनीकी कौशल सबसे महत्वपूर्ण है?
(A) मौसमी कृषि फसल चक्र का गहन ज्ञान
(B) खतरनाक भूमिगत विस्फोटक ब्लास्टिंग तकनीकों में उन्नत दक्षता
(C) जटिल पारंपरिक कपड़ा पैटर्न की हाथ से बुनाई में हस्तशिल्प विशेषज्ञता
(D) सीएनसी स्टोन मशीनों और गैंग आरी का संचालन

67. राजस्थान के खनिज-आधारित उद्योगों में हाल के निवेश रुझानों के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) प्राकृतिक गैस की मदद से सिरामिक और कांच के केंद्रों में निजी निवेश बढ़ा है।
(B) मूल्य-वर्धित खनिज प्रसंस्करण से दूर एक तीव्र संरचनात्मक बदलाव आया है, जिसमें पूंजी निवेशक पूरी तरह से कच्चे, अनपेक्षित उत्खनित अयस्कों का निर्यात करना पसंद कर रहे हैं।
(C) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के सभी रूप राजस्थान के गैर-धात्विक सीमेंट और सिरामिक निर्माण क्षेत्रों में कड़ाई से और पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।
(D) राज्य में सभी वाणिज्यिक पत्थर की खदानों के पूर्ण भौतिक समापन के कारण क्षेत्रीय पत्थर कटाई उद्योग में पूंजी निवेश पूरी तरह से बंद हो गया है।

68. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): सततता की चिंताएं राजस्थान में पत्थर प्रसंस्करण उद्योग को चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।
कारण (R): अनियंत्रित प्रसंस्करण और स्लरी डंपिंग के परिणामस्वरूप तीव्र संसाधन क्षरण, पर्यावरणीय अवनति और दीर्घकालिक आर्थिक अव्यावहारिकता होती है।
उपर्युक्त दो कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

69. हालांकि किशनगढ़ सबसे बड़ा प्रसंस्करण केंद्र है, राजस्थान का कौन-सा शहर ऐतिहासिक रूप से प्राचीन सफेद संगमरमर के प्राथमिक निष्कर्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है?
(A) मकराना
(B) मोरबड़
(C) ऋषभदेव
(D) बांसवाड़ा

70. खनिज प्रसंस्करण से प्रभावित क्षेत्रों की पारिस्थितिक बहाली में अक्सर फाइटोरिमेडिएशन शामिल होता है। यह किसे संदर्भित करता है?
(A) बड़ी मात्रा में औद्योगिक रासायनिक क्षारों का उपयोग करके अत्यधिक अम्लीय स्लरी अपवाह को उदासीन करना
(B) घोषित औद्योगिक क्षेत्रों से दूर पूरी ग्रामीण बस्तियों और गांवों को स्थायी रूप से स्थानांतरित करना
(C) सतह की धूल को पूरी तरह से ढकने के लिए सभी परित्यक्त विवृत खदानों को कंक्रीट की मोटी परतों से पक्का करना

Downloaded from www.pdf.tube

68. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
राजस्थान का पत्थर प्रसंस्करण उद्योग अत्यधिक जल खपत और स्टोन स्लरी जनरेशन के कारण गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। अनियंत्रित स्लरी डंपिंग से भूजल दूषित होता है और वायु प्रदूषण बढ़ता है, जिससे संसाधन क्षरण होता है। इस अवनति से निपटने और दीर्घकालिक आर्थिक अव्यावहारिकता से बचने के लिए यह उद्योग चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं को अपना रहा है।

69. (A) मकराना
नागौर जिले में स्थित मकराना शहर प्राचीन काल से ही विश्वप्रसिद्ध सफेद कैल्सीटिक संगमरमर के प्राथमिक खनन और निष्कर्षण का केंद्र रहा है। मकराना का संगमरमर अपनी असाधारण सफेदी और सदियों तक चमक न खोने की विशेषता के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक धरोहर आगरा के ताज महल का निर्माण इसी मकराना खदानों से निकाले गए संगमरमर से हुआ था।

70. (D) मृदा को स्थिर करने और मृदा प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए पौधों का उपयोग करना
फाइटोरिमेडिएशन एक पर्यावरण-अनुकूल जैविक तकनीक है जिसमें खदानों से प्रभावित मृदा और दूषित जल निकायों को बहाल करने के लिए विशिष्ट पौधों का उपयोग किया जाता है। ये पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से भारी धातुओं और विषैले तत्वों को अवशोषित करके उन्हें निष्प्रभावी करते हैं। यह प्रक्रिया खनन क्षेत्रों की मिट्टी को स्थिर करके सुधार करती है।

71. (B) I, II और III
राजस्थान में खनिज-आधारित उद्योगों की अवस्थिति का निर्धारण कई वास्तविक कारकों द्वारा होता है। कच्चे माल की भार-ह्रासकारी प्रकृति के कारण भाड़ा लागत एक प्रमुख कारक है। प्रगलन और कटाई संयंत्रों हेतु निरंतर विद्युत शक्ति अनिवार्य है। राज्य सरकार की नीतियाँ भी स्थान चयन को प्रभावित करती हैं। राजस्थान में 50 किमी के दायरे में बंदरगाह का दावा असत्य है।

72. (C) जल निकासी प्रणालियों को अवरुद्ध करना और मृदा के रंध्रों को बंद करना, जिससे रिसाव रुक जाता है
पत्थर कटाई और प्रसंस्करण इकाइयों से निकलने वाली स्टोन स्लरी का अनियंत्रित निर्वहन स्थानीय जलविज्ञान पर विनाशकारी प्रभाव डालता है। यह बारीक स्लरी प्राकृतिक जल निकासी नालियों में बहकर उन्हें अवरुद्ध कर देती है। भूमि पर जमने के बाद यह एक अप्रवेश्य परत बना देती है जो मिट्टी के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे भूजल रिसाव रुकता है।

73. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
राजस्थान औद्योगिक विकास नीति राज्य में खनिज प्रसंस्करण और पत्थर कटाई क्षेत्रों में लगे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु पूँजीगत निवेश सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान करती है। हालाँकि, यह नीति निजी उद्योगों के 100% लाभ को राज्य कोष में जमा करने का कोई जनादेश लागू नहीं करती, अतः दूसरा कथन पूरी तरह से गलत साबित होता है।

74. (A) निजी खनिकों को पर्यावरणीय स्वीकृतियां जारी करना
राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड राज्य सरकार का एक वाणिज्यिक खनन उपक्रम है। इसका मूल कार्य रॉक फॉस्फेट, जिप्सम और लिग्नाइट का उत्खनन एवं विपणन करना है। इसके विपरीत, निजी खनिकों को पर्यावरणीय स्वीकृतियां जारी करना पर्यावरण मंत्रालय तथा राज्य पर्यावरण प्राधिकरण का नियामक कार्य है। यह RSMML का कार्य नहीं है, अतः यह विकल्प असंगत माना जाता है।

75. (B) क्ले (मिट्टी), फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज
सिरामिक विट्रिफाइड टाइलों के निर्माण के लिए खनिजों का एक त्रि-घटकीय मिश्रण प्राथमिक कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें बॉल क्ले टाइल को आकार और प्लास्टिसिटी प्रदान करती है, फेल्डस्पार एक गालक के रूप में कार्य करता है जो गलनांक घटाकर विट्रिफाइड ढाँचा बनाता है, तथा क्वार्ट्ज संरचनात्मक मजबूती प्रदान करता है। यह सही संयोजन है।

76. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
राजस्थान में प्रमुख खनिज इनपुट और उनके प्राथमिक उत्पादक जिलों का संबंध स्पष्ट है। भीलवाड़ा जिले का रामपुरा आगूचा क्षेत्र सीसा-जस्ता अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर जिला बॉल क्ले का प्रमुख उत्पादक है। चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट-ग्रेड चूना पत्थर का मुख्य केंद्र है, तथा झुंझुनू जिला खेतड़ी तांबा अयस्क के लिए जाना जाता है। अतः यह सही सुमेलित कूट है।

77. (A) सल्फ्यूरिक अम्ल
राजस्थान में धातु स्मेल्टिंग परिसरों से सल्फाइड अयस्कों के भर्जन के दौरान भारी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यह सल्फ्यूरिक अम्ल रासायनिक उर्वरक उद्योग के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कच्चा माल है। जब इस सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया रॉक फॉस्फेट के साथ कराई जाती है, तो सिंगल सुपरफॉस्फेट उर्वरकों का बड़े पैमाने पर सफल निर्माण होता है।

78. (C) प्लास्टर ऑफ पेरिस का उत्पादन 1000°C से अधिक तापमान पर जिप्सम को पूरी तरह से पिघलाकर किया जाता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का उत्पादन जिप्सम को 1000°C से अधिक उच्च तापमान पर पिघलाकर नहीं किया जाता है। इसके विपरीत, जिप्सम को केवल लगभग 150°C से 160°C के नियंत्रित तापमान पर गर्म करके आंशिक रूप से निर्जलीकृत किया जाता है, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अतः अत्यधिक उच्च तापमान पर जिप्सम को पूरी तरह पिघलाने वाला यह कथन पूरी तरह असत्य है।

NODIA

(B) यह बीकानेर रियासत के वित्तीय योगदान के बिना ब्रिटिश शासन द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष पूंजीगत अनुदान के माध्यम से पूरी तरह से वित्तपोषित थी।
(C) इसे पंजाब को बीकानेर रियासत से जोड़ने वाले एक व्यावसायिक अंतर्देशीय नौवहन मार्ग के रूप में विशेष रूप से निर्मित और डिज़ाइन किया गया था।
(D) इसने स्वतंत्रता के बाद वृहद राजस्थान नहर (IGNP) की योजना को प्रेरित किया।

51. राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में कार्यान्वित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (CADP) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) सृजित और वास्तव में उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर को समाप्त करना
(B) प्रमुख अंतर-राज्यीय नदी बेसिनों के साथ नए बड़े पैमाने पर बहुउद्देशीय भंडारण बांधों का वित्तपोषण और निर्माण करना
(C) बड़े बांध जलाशयों के निर्माण से विस्थापित मूल आबादी का स्थायी रूप से पुनर्वसन करना
(D) राज्य के संपूर्ण कृषि उत्पादन को पारंपरिक खाद्य फसलों से व्यवस्थित रूप से नकदी फसलों में स्थानांतरित करना

52. कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (CADP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसे सृजित और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर को कम करने के लिए शुरु किया गया था।
II. यह मुख्य रूप से अंतर-राज्यीय नदियों पर प्राथमिक भंडारण बांधों के निर्माण पर केंद्रित है।
III. इसमें खेत पर विकास कार्य जैसे फील्ड चैनल, भूमि समतलीकरण और आकार देना शामिल है।
IV. यह बारी-बारी से जल आपूर्ति प्रणालियों के माध्यम से जल के समान वितरण को बढ़ावा देता है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

53. राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन के संदर्भ में, "वाराबंदी" शब्द विशेष रूप से किसे संदर्भित करता है?
(A) कमान क्षेत्र के किसानों के बीच जल के न्यायसंगत वितरण की एक घूर्णन प्रणाली
(B) शेखावाटी क्षेत्र में व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली वर्षा जल संचयन की सदियों पुरानी पारंपरिक प्रणाली
(C) इलेक्ट्रिक नलकूप पंप खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली एक प्रत्यक्ष वित्तीय सब्सिडी योजना
(D) कटी हुई कृषि उपज के वाणिज्यिक परिवहन और बिक्री पर लगाया जाने वाला एक अनिवार्य स्थानीय कर

54. खेत पर विकास (OFD) कार्य नहरी क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर OFD गतिविधि नहीं माना जाता है?
(A) फील्ड चैनलों का निर्माण
(B) भूमि समतलीकरण और आकार देना
(C) खेतों की सीमाओं का पुनर्गठन
(D) मुख्य नदी बैराज का निर्माण

55. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) - 'प्रति बूंद अधिक फसल' घटक के तहत, राजस्थान सरकार सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देती है। इस प्रोत्साहन की प्राथमिक विधि क्या है?
(A) सभी पारंपरिक सतही प्रवाह सिंचाई तकनीकों पर पूर्ण राज्यव्यापी प्रतिबंध लागू करना
(B) ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली स्थापित करने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करना
(C) अनियंत्रित भूजल पंपिंग के लिए कृषि भूमि स्वामियों को पूरी तरह से मुफ्त बिजली की आपूर्ति करना
(D) अधिक जल-गहन नकदी फसलों की उच्च उपज वाली बीज किस्मों का सीधे आयात और मुफ्त वितरण करना

56. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के नहर-सिंचित क्षेत्रों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के कार्यान्वयन को दृढ़ता से बढ़ावा दिया जाता है।
कारण (R): ये सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ पारंपरिक प्रवाह सिंचाई के कारण होने वाली जलभराव और मृदा लवणता की समस्याओं को काफी हद तक कम करती हैं।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

57. राजस्थान की किस प्रमुख सिंचाई परियोजना को राज्य में पहली ऐसी परियोजना होने का गौरव प्राप्त है जहाँ पूरे कमान क्षेत्र के लिए सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया था?
(A) बीसलपुर परियोजना
(B) माही बजाज सागर परियोजना
(C) गंग नहर परियोजना
(D) नर्मदा नहर परियोजना

58. गंग नहर और चंबल नेटवर्क जैसी पुरानी परियोजनाओं में मुख्य नहरों और वितरिकाओं को कंक्रीट से पक्का करने का कार्य मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है?
(A) रिसाव की हानि को कम करने और जल परिवहन दक्षता में सुधार करने के लिए
(B) जिलों में छोटी मालवाहक नौकाओं के सुगम व्यावसायिक नौवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए

Click Here to Buy book on Amazon

अध्याय 15
राजस्थान की प्रमुख सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएँ

1. निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कृषि विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक बाधा माना जाता है?
(A) संपूर्ण राज्य में उपजाऊ जलोढ़ मृदा की कमी
(B) कम औसत वर्षा और सीमित बारहमासी सतही जल संसाधन
(C) अत्यधिक शीत मौसम जो फसल चक्र को सीमित करता है
(D) कृषि योग्य भूमि को सीमित करने वाले घने वनों की अत्यधिक प्रचुरता

2. राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस स्रोत से प्राप्त होता है?
(A) नहरें
(B) तालाब और पोखर
(C) लिफ्ट सिंचाई योजनाएं
(D) नलकूप और कुएं

3. चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और किस अन्य राज्य के बीच एक संयुक्त बहुउद्देशीय उपक्रम है, तथा इसमें लागत और लाभ के साझाकरण का स्वीकृत अनुपात क्या है?
(A) मध्य प्रदेश, 50:50
(B) गुजरात, 50:50
(C) मध्य प्रदेश, 45:55
(D) हरियाणा, 60:40

4. चंबल नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण के दौरान किन दो संरचनाओं का निर्माण पूरा किया गया था?
(A) राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध
(B) राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज
(C) गांधी सागर बांध और कोटा बैराज
(D) गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध

5. राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
(A) चित्तौड़गढ़
(B) कोटा
(C) बूंदी
(D) सवाई माधोपुर

6. चंबल श्रृंखला के अन्य तीन बांधों की तुलना में कोटा बैराज की विशिष्ट परिचालन विशेषता क्या है?
(A) यह नेटवर्क का एकमात्र प्रमुख बांध है जिसका निर्माण पारंपरिक चिनाई कार्य से किया गया है
(B) यह अपने संगृहीत जल का 100 प्रतिशत जल मध्य प्रदेश राज्य को आपूर्ति करता है
(C) यह मुख्य रूप से बिना किसी नहर नेटवर्क प्रणाली के बाढ़-नियंत्रण बांध के रूप में कार्य करता है
(D) इसका उपयोग विशेष रूप से सिंचाई के लिए किया जाता है और इससे कोई जलविद्युत उत्पादित नहीं होती है

NODIA

7. चंबल नदी घाटी परियोजना के निम्नलिखित बांधों को उद्गम/ऊपरी प्रवाह (दक्षिण) से निचले प्रवाह (उत्तर) की ओर भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. जवाहर सागर बांध
2. राणा प्रताप सागर बांध
3. कोटा बैराज
4. गांधी सागर बांध

(A) 4, 2, 1, 3
(B) 2, 4, 1, 3
(C) 4, 1, 2, 3
(D) 1, 2, 3, 4

8. चंबल नदी घाटी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है।
II. गांधी सागर बांध भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है।
III. राजस्थान के बांधों में राणा प्रताप सागर बांध की जल भंडारण क्षमता सबसे अधिक है।
IV. जवाहर सागर बांध मुख्य रूप से पिक-अप बांध के रूप में कार्य करता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

9. सूची I में दिए गए बांधों को सूची II में दी गई उनकी संबंधित नदियों से सुमेलित कीजिए:
सूची I: बांध
P. गांधी सागर
Q. बीसलपुर
R. जवाई
S. माही बजाज सागर
सूची II: नदी

79. (D) मालानी आग्नेय समूह के ग्रेनाइट अंतर्वेशनों से समीपता, जिससे परिवहन लागत कम होती है

जालौर और सिरोही जिलों में ग्रेनाइट प्रसंस्करण इकाइयों के भारी संकेंद्रण का सबसे उपयुक्त अवस्थिति कारण मालानी आग्नेय शैल समूह के प्रचुर अंतर्वेशनों से समीपता है। कच्चे ग्रेनाइट के भारी ब्लॉक खदानों से कम दूरी पर ही प्रसंस्करण इकाइयों तक पहुँच जाते हैं। कच्चे माल की इस भौगोलिक निकटता के कारण परिवहन लागत में भारी कमी आती है, जिससे संचालन लाभप्रद रहता है।

80. (C) वे विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, व्यापक रोजगार सृजित करते हैं, और द्वितीयक क्षेत्र का समर्थन करते हैं।

खनिज-आधारित उद्योग राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संरचनात्मक भूमिका निभाते हैं। ये उद्योग कच्चे खनिजों को सीमेंट, प्रसंस्कृत संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता और तांबे जैसी तैयार वस्तुओं में बदलकर राज्य के द्वितीयक विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये उद्योग लाखों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करते हैं और निर्यात से भारी विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं।

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

3. हनुमानगढ़
4. टोंक

(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-1, Q-3, R-4, S-2
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

20. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म किसी नदी घाटी परियोजना को उसके प्राथमिक जनजातीय लाभार्थी क्षेत्र से सही रूप से सुमेलित करता है?
(A) बीसलपुर परियोजना - बारां जिले में रहने वाली सहरिया जनजातीय जनसंख्या
(B) जवाई बांध परियोजना - सिरोही जिले में बसा गरासिया जनजातीय समुदाय
(C) माही बजाज सागर परियोजना - बांसवाड़ा और डूंगरपुर की भील और मीणा जनजातियां
(D) सिधमुख-नोहर परियोजना - चूरू में रहने वाला कालबेलिया अर्ध-घुमंतू समुदाय

21. माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात के बीच एक संयुक्त उपक्रम है। इसके मुख्य बांध के निर्माण के लिए लागत साझाकरण अनुपात क्या है?
(A) राजस्थान 45 : गुजरात 55
(B) राजस्थान 50 : गुजरात 50
(C) राजस्थान 55 : गुजरात 45
(D) राजस्थान 60 : गुजरात 40

22. माही बजाज सागर समझौते के अंतर्गत, इस परियोजना से उत्पादित जलविद्युत में राजस्थान का हिस्सा कितना है?
(A) 45 प्रतिशत
(B) 50 प्रतिशत
(C) 55 प्रतिशत
(D) 100 प्रतिशत

23. माही बजाज सागर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया है।
II. यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है।
III. यह मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के शुष्क जिलों को सिंचाई लाभ प्रदान करता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

24. ऐतिहासिक गंग नहर किस वर्ष बनकर तैयार हुई और लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था?
(A) 1915
(B) 1935
(C) 1927
(D) 1947

25. गंग नहर किस प्रमुख नदी से जल प्राप्त करती है?
(A) रावी
(B) ब्यास
(C) चेनाब
(D) सतलुज

26. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): वर्ष 1927 में गंग नहर के सफल निर्माण ने बीकानेर रियासत के कृषि परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया।
कारण (R): यह पहली बार हिमालयी नदियों के जल को शुष्क थार मरुस्थल क्षेत्र में लाया, जिससे बड़े पैमाने पर मरुस्थलीय सिंचाई की व्यावहारिकता स्थापित हुई।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

27. सिधमुख-नोहर सिंचाई परियोजना राजस्थान के मुख्य रूप से किन दो जिलों को सिंचाई प्रदान करने के लिए निर्मित की गई थी?
(A) गंगानगर और बीकानेर
(B) हनुमानगढ़ और चूरू
(C) जैसलमेर और बाड़मेर
(D) सीकर और झुंझुनू

NODIA

28. सिधमुख-नोहर परियोजना किस नदी तंत्र से आवंटित अतिरिक्त जल में से राजस्थान के हिस्से का उपयोग करती है?
(A) यमुना
(B) रावी और ब्यास
(C) चंबल और बनास
(D) सतलुज

29. सिधमुख-नोहर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसका उद्देश्य रावी और ब्यास नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग करना है।
II. यह मुख्य रूप से हनुमानगढ़ और चूरू जिलों को सिंचाई प्रदान करती है।
III. यह परियोजना प्रारंभ में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की गई थी।
IV. यह चूरू के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए बिना किसी लिफ्ट तंत्र के पूरी तरह से प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण प्रवाह प्रणाली के रूप में कार्य करती है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल I, II और III

(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

30. रावी-ब्यास नदियों के अतिरिक्त जल का आवंटन, जिससे सिधमुख-नोहर जैसी परियोजनाओं को लाभ होता है, किस विशिष्ट न्यायाधिकरण द्वारा अधिनिर्णित किया गया था?
(A) दक्षिणी राज्यों के लिए कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण
(B) कावेरी नदी जल विवाद अधिनिर्णयन न्यायाधिकरण
(C) इराडी आयोग (रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण)
(D) गोदावरी नदी जल विवाद अधिनिर्णयन न्यायाधिकरण

31. सूची I में दी गई लघु/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को सूची II में दिए गए उनके संबंधित जिलों से सुमेलित कीजिए:
सूची I: परियोजना
P. छापी परियोजना
Q. ओराई परियोजना
R. परवन परियोजना
S. नारायण सागर
सूची II: जिला
1. चित्तौड़गढ़
2. झालावाड़
3. बारां
4. अजमेर
(A) P-2, Q-1, R-3, S-4
(B) P-1, Q-2, R-4, S-3
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

32. भीलवाड़ा को जल आपूर्ति करने के लिए एक महत्वपूर्ण मध्यम सिंचाई परियोजना, मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है?
(A) खारी
(B) मानसी
(C) कोठारी
(D) चंद्रभागा

33. राजस्थान के सबसे ऊंचे बांधों में से एक जाखम बांध किस जिले में स्थित है?
(A) उदयपुर
(B) प्रतापगढ़
(C) डूंगरपुर
(D) बांसवाड़ा

34. सोम-कमला-अंबा मध्यम सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से किस जिले से संबंधित है?
(A) बांसवाड़ा
(B) चित्तौड़गढ़
(C) राजसमंद
(D) डूंगरपुर

35. करौली जिले में स्थित पांचना बांध राजस्थान के सिंचाई बुनियादी ढांचे में किस विशिष्ट संरचनात्मक विशेषता के लिए उल्लेखनीय है?
(A) पांच नदी धाराओं के संगम पर निर्मित एक मिट्टी का बांध
(B) यह राज्य में सबसे बड़ी कंक्रीट गुरुत्व बांध संरचना के रूप में कार्य करता है
(C) इसे राजस्थान में स्थित एकमात्र चालू चाप बांध के रूप में डिज़ाइन किया गया है
(D) यह मुगल काल के दौरान पूरी तरह से एक सिंचाई जलाशय के रूप में निर्मित किया गया था

36. नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान को सरदार सरोवर बांध से जल प्रदान करती है। इस बहुउद्देशीय परियोजना में कौन-से चार राज्य औपचारिक भागीदार हैं?
(A) गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा
(B) गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब
(C) गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान
(D) मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार

37. नर्मदा नहर जालौर और बाड़मेर को सिंचाई प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य में किस स्थान पर प्रवेश करती है?
(A) सीलू गांव, जालौर
(B) गडरारोड, बाड़मेर
(C) सुमेरपुर, पाली
(D) सांचौर, जालौर

38. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): चंबल नदी घाटी परियोजना के बांधों में कोटा बैराज अद्वितीय है।
कारण (R): यह चंबल श्रृंखला का एकमात्र बांध है जो बड़े पैमाने पर जलविद्युत उत्पादन संयंत्र से सुसज्जित है।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

39. भाखड़ा-नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में राजस्थान का औपचारिक प्रतिशत हिस्सा कितना है?
(A) 10.50 प्रतिशत
(B) 15.22 प्रतिशत
(C) 20.00 प्रतिशत
(D) 25.50 प्रतिशत

40. यमुना जल के आवंटन के अंतर-राज्यीय समझौते के तहत, राजस्थान के कौन-से दो जिले मुख्य रूप से गुड़गांव नहर और भरतपुर नहर के माध्यम से सिंचाई का जल प्राप्त करते हैं?
(A) धौलपुर और करौली
(B) भरतपुर और धौलपुर

Click Here to Buy book on Flipkart

(C) अलवर और भरतपुर
(D) जयपुर और दौसा

41. राजस्थान में सिंचाई के साधनों का उनके कुल सिंचित क्षेत्र के कवरेज के आधार पर सही घटता हुआ क्रम चुनिए:
(A) नलकूप और कुएं > नहरें > तालाब
(B) नहरें > नलकूप और कुएं > तालाब
(C) नलकूप और कुएं > तालाब > नहरें
(D) नहरें > तालाब > नलकूप और कुएं

42. उत्तरी जिलों गंगानगर और हनुमानगढ़ में गहन नहर सिंचाई की शुरुआत ने पारंपरिक वर्षा आधारित फसलों से किस व्यावसायिक फसल पैटर्न में एक प्रमुख ऐतिहासिक बदलाव किया है?
(A) बाजरा और मोठ से कपास और गेहूं
(B) मक्का और ज्वार से गन्ना और चावल
(C) ग्वार और तिल से जूट और चाय
(D) ईसबगोल और जीरा से सोयाबीन और मूंगफली

43. बड़ोपल (हनुमानगढ़) जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक नहर रिसाव के कारण उत्पन्न जलभराव और उसके बाद मृदा लवणता की गंभीर समस्या का वर्णन करने के लिए किस स्थानीय शब्द का प्रयोग किया जाता है?
(A) खड़ीन
(B) सेम
(C) जोहड़
(D) बावड़ी

44. भौगोलिक रूप से, अनुकूल भूजल जलभृतों के कारण नलकूप और कुओं द्वारा सिंचाई राजस्थान के किस क्षेत्र में सबसे अधिक केंद्रित है?
(A) पश्चिमी शुष्क मैदान
(B) पूर्वी और मध्य मैदान
(C) दक्षिणी जनजातीय पट्टी
(D) दक्षिण-पूर्वी हाड़ौती पठार

45. वह मूलभूत परिचालन आवश्यकता क्या है जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना को मानक प्रवाह नहर परियोजना से अलग करती है?
(A) यह यांत्रिक रूप से जल को प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण के विपरीत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पंप करती है।
(B) इसके लिए कंक्रीट संरचनाओं के बजाय मिट्टी के तटबंध का निर्माण करना अनिवार्य है।
(C) यह बारहमासी नदियों के प्रवाह के बजाय पूरी तरह से स्थानीय मौसमी वर्षा के अपवाह पर निर्भर करती है।
(D) यह सभी एकत्रित जल के उपयोग को strictly नगर पालिका पेयजल आपूर्ति तक सीमित करती है।

46. भूजल और नहर के अंतर-संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. अस्तर रहित नहरों से रिसाव स्थानीय उथले जलभृतों के पुनर्भरण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
II. पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अत्यधिक नहर रिसाव के कारण गंभीर जलभराव हुआ है।
III. लिफ्ट सिंचाई पूरी तरह से नहर रिसाव के जल के प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण प्रवाह पर निर्भर करती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

47. निम्नलिखित में से कौन-सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) प्रणाली से जुड़ी एक स्थापित लिफ्ट सिंचाई परियोजना नहीं है?
(A) कंवर सेन लिफ्ट नहर
(B) गंधेली साहावा लिफ्ट नहर
(C) पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर
(D) नर्मदा लिफ्ट नहर

48. राजस्थान के जल प्रबंधन के संदर्भ में, कमान क्षेत्र में "जल के संयुक्त उपयोग" से क्या तात्पर्य है?
(A) संगृहीत मीठे जल का विशेष रूप से भारी औद्योगिक कार्यों और शहरी घरेलू उपभोग के लिए एक साथ दोहरा उपयोग
(B) फसल के खेतों में प्रयोग करने से पहले नगर पालिका के उपचारित अपशिष्ट जल को ताजे नहरी जल के साथ मिलाने की व्यवस्थित कृषि पद्धति
(C) दक्षता को अधिकतम करने और जलभराव को रोकने के लिए सतही नहर जल और भूजल दोनों का समन्वित एवं नियोजित उपयोग
(D) सक्रिय दक्षिण-पश्चिम मानसून सत्र की अवधि के दौरान पारंपरिक वर्षा जल संचयन संरचनाओं पर विशेष क्षेत्रीय निर्भरता

49. जिन क्षेत्रों में प्रमुख नहरें अस्तर रहित रहती हैं, वहां आसपास के कृषि वातावरण पर सबसे सामान्य तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ता है?
(A) ऊपरी मिट्टी में गाद के निक्षेपण के माध्यम से प्राकृतिक मृदा उर्वरता में तीव्र और व्यापक वृद्धि
(B) उच्च रिसाव हानि जिससे स्थानीय जलभराव और जल स्तर बढ़ता है
(C) मृदा संघनन के कारण स्थानीय भूजल स्तर में अचानक और तीव्र गिरावट
(D) तटों के किनारे प्राकृतिक रूप से उगने वाली आक्रामक खरपतवार प्रजातियों का पूर्ण उन्मूलन

50. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गंग नहर के ऐतिहासिक महत्व को सही ढंग से उजागर करता है?
(A) यह 1927 में अपने निर्माण के दौरान कंक्रीट चिनाई से पूरी तरह से पक्की की जाने वाली संपूर्ण भारत की पहली नहर प्रणाली थी।

Downloaded from www.pdf.tube

(B) जिला कलेक्टर
(C) जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता
(D) स्थानीय जल उपभोक्ता संगम (किसान)

67. वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, जल उपभोक्ता संगमों (WUAs) को अक्सर किसके लिए अधिकृत किया जाता है?
(A) किसानों से जल प्रभार (आबियाना) एकत्र करने और स्थानीय रखरखाव के लिए एक हिस्सा अपने पास रखने
(B) कमान क्षेत्रों में काम कर रहे ग्रामीण व्यवसायों से सीधे स्थानीयकृत आयकर अधिभार लगाने और एकत्र करने
(C) बड़े बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए पूंजी जुटाने हेतु राज्य द्वारा समर्थित संप्रभु नगर निगम राजस्व बॉन्ड जारी करने
(D) विशेष रूप से क्षेत्रीय कृषि वस्तुओं के व्यापार के लिए आरक्षित स्थानीयकृत आधिकारिक मुद्रा छापने और प्रसारित करने

68. जल उपभोक्ता संगम (WUA) की संरचना मूलभूत रूप से कैसी होती है?
(A) निरंकुश, जिसमें सीधे राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त कार्यकारी अधिकारी शामिल होते हैं
(B) कॉर्पोरेट, जो पंजीकृत निजी बहुराष्ट्रीय कृषि-निगमों द्वारा लाभ के लिए स्वामित्व और संचालित होती है
(C) लोकतांत्रिक, जिसमें स्थानीय कमान क्षेत्र के किसानों द्वारा चुनी गई एक प्रबंध समिति होती है
(D) नौकरशाही, जो पूरी तरह से राज्य सिविल सेवाओं के पूर्णकालिक अधिकारियों से बनी होती है

69. राजस्थान में प्रमुख नहर परियोजनाओं के लिए नियमित गाद निकालना एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा रखरखाव चुनौती के रूप में क्यों पहचाना जाता है?
(A) गाद का जमाव नहर के अनुप्रस्थ-काट को छोटा कर देता है, जिससे जल-वहन क्षमता घट जाती है
(B) गाद का संचयन संरचनात्मक सीमाओं से परे नहर की आयतन क्षमता को अत्यधिक बढ़ा देता है, जिससे बाढ़ आती है
(C) गाद निकालने की प्रक्रिया स्थानीय उथले भूजल भंडारों को भारी धातुओं से दूषित करती है
(D) जमा हुई गाद को हटाने से संरचनात्मक कंक्रीट लाइनिंग पैनल स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं

70. दशकों से नहर के अस्तर का संरचनात्मक क्षरण कृषि उत्पादकता के लिए आमतौर पर किन दो एक साथ होने वाले नकारात्मक परिणामों का कारण बनता है?
(A) कृषि मृदा उर्वरता के उन्नत स्तरों के साथ समग्र जल प्रवाह वेग में ध्यान देने योग्य कमी
(B) नहरों में कम खरपतवार वृद्धि के साथ-साथ जलविद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि
(C) क्षेत्रीय बाढ़ की दीर्घकालिक रोकथाम और भूजल शुद्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि
(D) अंतिम छोर पर जल की कमी और शुरुआती भाग में जलभराव

71. प्रस्तावित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP), जो भविष्य की एक प्रमुख सिंचाई और पेयजल पहल है, को मुख्य रूप से किस प्रमुख नदी तंत्र के उप-बेसिनों से मानसून के अतिरिक्त जल का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है?
(A) लूनी
(B) चंबल
(C) साबरमती
(D) माही

72. निर्माणाधीन परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से हाड़ौती क्षेत्र के किन जिलों की कृषि भूमि और पेयजल आवश्यकताओं को लाभान्वित करेगी?
(A) जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर
(B) उदयपुर, राजसमंद और सिरोही
(C) बारां, झालावाड़ और कोटा
(D) अलवर, भरतपुर और धौलपुर

73. ईसरदा बांध परियोजना का निर्माण क्षेत्र की पेयजल और सिंचाई आपूर्ति को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यह किस मौजूदा प्रमुख बांध के निचले प्रवाह में स्थित है?
(A) राणा प्रताप सागर बांध
(B) माही बजाज सागर बांध
(C) जवाई बांध
(D) बीसलपुर बांध

74. राजस्थान में सिंचाई के रुझानों और भावी प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को लूनी नदी बेसिन से अतिरिक्त जल का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
II. राजस्थान में शुद्ध सिंचित क्षेत्र के अधिकांश हिस्से के लिए नलकूप और कुएं उत्तरदायी हैं।
III. जैसलमेर जैसे शुष्क पश्चिमी जिलों में तालाब सिंचाई सबसे प्रमुख सिंचाई रुप है।
IV. सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के संवर्धन को PMKSY के तहत पर्याप्त सरकारी सब्सिडी प्राप्त होती है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन असत्य हैं?
(A) केवल I और III
(B) केवल II और IV
(C) I, II और III
(D) केवल III और IV

75. निम्नलिखित में से कौन-सा राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जो प्रतापगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है?
(A) माही बजाज सागर बांध
(B) जाखम बांध
(C) बीसलपुर बांध
(D) कोटा बैराज

NODIA

(C) आक्रामक जलीय जीवों के अनियंत्रित प्रजनन को रोकने के लिए
(D) तेजी से बहते नहर के जल के औसत सतह तापमान को काफी कम करने के लिए

59. सूची I में दी गई सिंचाई प्रबंधन अवधारणाओं को सूची II में दिए गए उनके विवरणों से सुमेलित कीजिए:
सूची I: अवधारणा
P. वाराबंदी
Q. कमान क्षेत्र
R. लिफ्ट सिंचाई
S. नहर रिसाव
सूची II: विवरण
1. किसी विशिष्ट परियोजना द्वारा सिंचित किए जाने में सक्षम कुल क्षेत्र
2. गुरुत्वाकर्षण के विपरीत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जल पंप करना
3. किसानों को जल के समान वितरण की घूर्णन प्रणाली
4. अस्तर रहित नहर के तल से नीचे की ओर जल की हानि
(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

60. राजस्थान के कृषि नहर नेटवर्क के संदर्भ में "जल उपयोग दक्षता" को सर्वश्रेष्ठ रूप से किस प्रकार परिभाषित किया गया है?
(A) वह औसत वेग और गति जिससे भंडारण बांधों से अंतिम छोर के किसानों तक नहरों में जल बहता है
(B) फसलों द्वारा उपयोग किए गए जल का स्रोत से निकाले गए कुल जल से अनुपात
(C) मानसून के मौसम में हेडवर्क्स जलाशयों में संगृहीत जल की अधिकतम आयतन क्षमता
(D) छोड़े गए नहर के प्रति घन मीटर जल से उत्पादित जलविद्युत का शुद्ध विद्युत उत्पादन

61. राज्य सरकार का कौन-सा विभाग राजस्थान में प्रमुख और मध्यम नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए प्राथमिक संस्थागत कार्यकारी एजेंसी के रूप में कार्य करता है?
(A) जल संसाधन विभाग (WRD)
(B) कृषि विभाग
(C) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED)
(D) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

62. जल उपभोक्ता संगमों (WUAs) को कानूनी रूप से सशक्त बनाने के लिए 'राजस्थान सिंचाई प्रणालियों के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम' किस वर्ष पारित किया गया था?
(A) 1985
(B) 1992
(C) 2000
(D) 2012

63. मुख्य जल स्रोत से किसान के खेत तक नहर सिंचाई वितरण प्रणाली के विशिष्ट पदानुक्रमित घटकों को व्यवस्थित कीजिए:
1. वितरिका
2. मुख्य नहर
3. खाला/फील्ड चैनल
4. शाखा नहर
5. माइनर/लघु नहर
(A) 2, 4, 1, 5, 3
(B) 2, 1, 4, 3, 5
(C) 4, 2, 1, 5, 3
(D) 2, 4, 5, 1, 3

64. राजस्थान में जल उपभोक्ता संगमों (WUAs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इनका गठन सहभागी सिंचाई प्रबंधन (PIM) दृष्टिकोण के तहत किया जाता है।
II. इनकी प्राथमिक भूमिका प्रमुख अंतर-राज्यीय बहुउद्देशीय बांधों का निर्माण करना है।
III. वे माइनर नहर स्तर पर न्यायसंगत जल वितरण और बुनियादी रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

65. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): राजस्थान के जल संसाधन विभाग ने बीसलपुर और कोटा बैराज जैसे प्रमुख बांधों का कानूनी स्वामित्व और परिचालन नियंत्रण पूरी तरह से स्थानीय जल उपभोक्ता संगमों को स्थानांतरित कर दिया है।
कारण (R): सहभागी सिंचाई प्रबंधन का उद्देश्य सूक्ष्म स्तर (माइनर नहरों और नालियों) पर जल के वितरण और रखरखाव में किसानों को शामिल करना है।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

66. सहभागी सिंचाई प्रबंधन (PIM) मॉडल के तहत, खेत की नालियों की मामूली गाद निकालने और खरपतवार सफाई जैसे नियमित भौतिक रखरखाव की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से किसकी है?
(A) केंद्रीय जल आयोग

Click Here to Buy book on Amazon

1. लूनी बेसिन
2. चंबल
3. माही
4. बनास

(A) P-2, Q-4, R-1, S-3
(B) P-4, Q-2, R-1, S-3
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-2, Q-4, R-3, S-1

10. चंबल नहर प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?
(A) दाईं मुख्य नहर केवल मध्य प्रदेश को सिंचाई प्रदान करती है।
(B) बाईं मुख्य नहर कोटा और बूंदी जिलों को सिंचाई प्रदान करती है।
(C) यह नहर प्रणाली कमान क्षेत्र में जलभराव और मृदा लवणता की समस्याओं से ग्रस्त है।
(D) राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों इस परियोजना के सिंचाई लाभ साझा करते हैं।

11. बीसलपुर बांध राजस्थान की किस प्रमुख नदी पर बनाया गया है?
(A) लूनी
(B) बनास
(C) चंबल
(D) माही

12. हालांकि बीसलपुर परियोजना कई जिलों के लिए पेयजल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन इसका समर्पित कृषि सिंचाई कमान क्षेत्र मुख्य रूप से किस जिले तक सीमित है?
(A) जयपुर
(B) टोंक
(C) अजमेर
(D) दौसा

13. बीसलपुर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह टोंक जिले में बनास नदी पर निर्मित है।
II. यह मुख्य रूप से अजमेर जिले को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करता है।
III. यह जयपुर और अजमेर सहित प्रमुख शहरी केंद्रों को पेयजल की आपूर्ति करता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

14. जवाई बांध का निर्माण जवाई नदी पर किया गया था, जो किस नदी तंत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है?
(A) साबरमती
(B) बनास
(C) लूनी
(D) माही

15. जवाई बांध राजस्थान के किस जिले में सुमेरपुर के पास स्थित है?
(A) जालौर
(B) सिरोही
(C) बाड़मेर
(D) पाली

16. पश्चिमी राजस्थान में इसके अत्यधिक महत्व के कारण निम्नलिखित में से किस प्रमुख सिंचाई परियोजना को स्थानीय भाषा में "मारवाड़ का अमृत सरोवर" कहा जाता है?
(A) इंदिरा गांधी नहर
(B) बीसलपुर बांध
(C) जवाई बांध
(D) नर्मदा नहर परियोजना

17. वर्तमान समय में जवाई बांध परियोजना के सबसे सटीक द्वितीयक उपयोग का वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है?
(A) क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड को सीधे जलविद्युत की बड़ी मात्रा में आपूर्ति करना
(B) पाली और जोधपुर जिलों को महत्वपूर्ण पेयजल की आपूर्ति करना
(C) माल ढुलाई के लिए एक मौसमी अंतर्देशीय व्यावसायिक नौवहन जलमार्ग के रूप में कार्य करना
(D) भारी उद्योगों के लिए जल को पूरी तरह से साबरमती नदी बेसिन में मोड़ना

18. राजस्थान में निम्नलिखित प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के प्रारंभ होने के सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन कीजिए:
(A) गंग नहर, जवाई बांध, माही बजाज सागर, बीसलपुर बांध
(B) जवाई बांध, गंग नहर, बीसलपुर बांध, माही बजाज सागर
(C) गंग नहर, माही बजाज सागर, जवाई बांध, बीसलपुर बांध
(D) जवाई बांध, बीसलपुर बांध, गंग नहर, माही बजाज सागर

19. सूची I में दी गई सिंचाई परियोजनाओं को सूची II में दिए गए उनके प्राथमिक लाभार्थी जिलों से सुमेलित कीजिए:
सूची I: सिंचाई परियोजना
P. सिधमुख-नोहर
Q. मेजा बांध
R. सोम-कमला-अंबा
S. बीसलपुर (सिंचाई)
सूची II: प्राथमिक लाभार्थी जिला
1. भीलवाड़ा
2. डूंगरपुर

NODIA

76. निम्नलिखित में से किस बांध को राजस्थान का सबसे लंबा बांध होने का गौरव प्राप्त है?
(A) राणा प्रताप सागर बांध
(B) माही बजाज सागर बांध
(C) जवाई बांध
(D) गांधी सागर बांध

77. तुलनात्मक जिलावार सिंचित क्षेत्र के आंकड़ों के आधार पर, किस जिले के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत है?
(A) गंगानगर
(B) बाड़मेर
(C) चूरु
(D) झालावाड़

78. राजस्थान में सिंचाई की वर्तमान स्थिति के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए:
(A) जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने का व्यवस्थित रुप से प्रचार किया जाता है।
(B) अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद कभी-कभी आवंटित जल के हिस्सों के इष्टतम उपयोग में विलंब करते हैं।
(C) कुएं और नलकूप मिलकर राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र के 30 प्रतिशत से भी कम हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
(D) भूजल के अत्यधिक दोहन के परिणामस्वरुप अधिकांश ब्लॉक 'डार्क' या 'अति-दोहित' श्रेणी में आ गए हैं।

79. राजस्थान के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को निष्पादित करने का अंतिम और सबसे व्यापक उद्देश्य क्या है?
(A) व्यावसायिक अंतर्देशीय मतस्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन पर पूर्ण राज्य वाणिज्यिक एकाधिकार सुनिश्चित करना
(B) एक ही दशक के भीतर भूजल भंडारों पर क्षेत्रीय कृषि निर्भरता को पूरी तरह से समाप्त करना
(C) अत्यधिक शुष्क थार मरुस्थल क्षेत्र को कृत्रिम रुप से एक सतत घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र में बदलना
(D) सूखे की संवेदनशीलता को कम करके खाद्य सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना

80. लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर प्रणाली का एक अपरिहार्य घटक क्यों हैं, इसका सबसे उपयुक्त वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) वे मुख्य रुप से मरुस्थलीय पारिस्थितिक पर्यटन और स्थानीय रिसॉर्ट विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्मित सजावटी झरनों के रूप में कार्य करती हैं
(B) अंतरराष्ट्रीय नदी जल साझाकरण संधियों के तहत नहर के प्रवाह वेग को धीमा करने के लिए वे अनिवार्य हैं
(C) प्राकृतिक स्थलाकृति मुख्य नहर की तुलना में अधिक ऊंची है, जिसके लिए जल को ऊपर की ओर पंप करने की आवश्यकता होती है
(D) नहर का जल मुख्य कृषि खेतों में प्रवेश करने से पहले वे अपने आप मोटे रेत और भारी गाद जमाव को छान लेते हैं

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

जलविद्युत ऊर्जा में राजस्थान राज्य का हिस्सा शत-प्रतिशत अर्थात 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

23. (A) केवल I और II
माही बजाज सागर बांध का नाम स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया है। बांसवाड़ा जिले में स्थित यह बांध 3109 मीटर लंबाई के साथ राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। हालांकि, यह बांध पश्चिमी राजस्थान के शुष्क जिलों को नहीं, बल्कि राज्य के दक्षिणी जनजातीय जिलों बांसवाड़ा और डूंगरपुर को सिंचाई लाभ प्रदान करता है। अतः प्रथम एवं द्वितीय कथन सत्य हैं।

24. (C) 1927
बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह के दूरदर्शी प्रयासों से गंग नहर का निर्माण 1922 में प्रारंभ हुआ था। लगभग पांच वर्षों के निरंतर निर्माण के पश्चात यह ऐतिहासिक नहर परियोजना वर्ष 1927 में पूर्ण हुई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 26 अक्टूबर 1927 को पंजाब के हुसैनीवाला हेडवर्क्स पर इस नहर का औपचारिक उद्घाटन कर जल प्रवाहित किया था।

25. (D) सतलुज
गंग नहर पंजाब में फिरोजपुर के निकट स्थित हुसैनीवाला हेडवर्क्स से सतलुज नदी के जल को मोड़कर निकाली गई है। यह नहर फिरोजपुर से प्रारंभ होकर राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में खखां गांव के पास प्रवेश करती है। सतलुज नदी का निरंतर बहने वाला पानी इस नहर के माध्यम से उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के शुष्क इलाकों में सिंचाई उपलब्ध कराता है।

26. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
गंग नहर के निर्माण से पूर्व बीकानेर रियासत का उत्तरी भाग एक जलविहीन मरुस्थलीय क्षेत्र था। 1927 में सतलुज नदी से गंग नहर द्वारा हिमालयी जल लाए जाने से इस क्षेत्र की कायापलट हो गई। इस अभूतपूर्व परियोजना ने सिद्ध कर दिया कि मरुभूमि में भी नहरी सिंचाई संभव है। इस सफलता ने अन्य बड़ी परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त किया। अतः दोनों कथन सत्य हैं।

27. (B) हनुमानगढ़ और चूरू
सिधमुख-नोहर सिंचाई परियोजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर-पूर्वी राजस्थान के शुष्क इलाकों को कृषि हेतु जल देना है। यह परियोजना मुख्य रूप से हनुमानगढ़ जिले की नोहर एवं भादरा तहसीलों तथा चूरू जिले की राजगढ़ एवं तारानगर तहसीलों के दर्जनों गांवों में व्यापक सिंचाई सुविधाएं और पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए निर्मित एवं संचालित की गई थी।

28. (B) रावी और ब्यास
सिधमुख-नोहर परियोजना रावी और ब्यास नदियों के अधिशेष जल का उपयोग करती है जो अंतर-राज्यीय जल आवंटन समझौतों के तहत राजस्थान को आवंटित किया गया है। यह जल नहरी तंत्र के माध्यम से लाया जाता है। पंजाब और हरियाणा से होकर गुजरने वाली नहरों द्वारा जल राजस्थान की सीमा में पहुँचता है, जहाँ इसे हनुमानगढ़ तथा चूरू में वितरित किया जाता है।

29. (A) केवल I, II और III
सिधमुख-नोहर परियोजना रावी-ब्यास नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग करती है और हनुमानगढ़ तथा चूरू जिलों को सिंचित करती है। इसके निर्माण में यूरोपीय आर्थिक समुदाय से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी। हालांकि, चूरू के उच्च इलाकों तक पानी पहुँचाने के लिए लिफ्ट नहरों का उपयोग किया जाता है, यह केवल गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं है। अतः केवल प्रथम तीन कथन सही हैं।

30. (C) इराडी आयोग (रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण)
1985 के पंजाब समझौते के तहत रावी-ब्यास जल के पुनरावलोकन एवं अधिशेष जल के आवंटन हेतु इराडी आयोग (रावी एवं ब्यास जल न्यायाधिकरण) का गठन किया गया था। इस आयोग ने राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच जल के हिस्सों का निर्धारण किया। इराडी आयोग द्वारा राजस्थान को आवंटित जल के आधार पर ही सिधमुख-नोहर परियोजना हेतु जल सुरक्षा तय हुई।

31. (A) P-2, Q-1, R-3, S-4
छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित एक मध्यम सिंचाई परियोजना है। ओराई परियोजना चित्तौड़गढ़ जिले में ओराई नदी पर निर्मित है जो स्थानीय कृषि को सिंचित करती है। परवन सिंचाई परियोजना बारां जिले के क्षेत्रों को लाभान्वित करती है। नारायण सागर बांध अजमेर जिले में खारी नदी पर स्थित है। अतः सही जिला सुमेल P-2, Q-1, R-3, S-4 बनता है।

NODIA

32. (C) कोठारी
मेजा बांध का निर्माण भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के पास मेजा गांव में कोठारी नदी के प्रवाह पर किया गया है। कोठारी नदी बनास नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह बांध भीलवाड़ा शहर को पेयजल आपूर्ति करने के साथ-साथ जिले के आसपास के ग्रामीण इलाकों की कृषि भूमि को सिंचाई प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण ढांचा रहा है।

33. (B) प्रतापगढ़
जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। यह जल संरचना प्रतापगढ़ जिले के अनूपपुरा गांव के पास सीतामाता अभयारण्य के भीतर जाखम नदी पर बनाई गई है। जाखम नदी माही नदी की सहायक नदी है। यह बांध मुख्य रूप से प्रतापगढ़ तथा आसपास के दक्षिणी जनजातीय जिलों के कृषि क्षेत्रों को सिंचाई प्रदान करता है।

34. (D) डूंगरपुर
सोम-कमला-अंबा मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित एक प्रमुख जल परियोजना है। यह परियोजना माही की सहायक सोम नदी पर निर्मित है और डूंगरपुर जिले की तहसीलों के आदिवासी क्षेत्रों की कृषि भूमि को सिंचाई लाभ प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, इस

के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी के प्रवाह पर किया गया है। यह बांध एक विशाल संरचना है। यह परियोजना जयपुर, अजमेर, तथा टोंक जिलों को निरंतर पेयजल उपलब्ध कराने के साथ-साथ टोंक जिले के कमान क्षेत्र को पर्याप्त सिंचाई जल आपूर्ति करती है।

12. (B) टोंक
यद्यपि बीसलपुर बांध पेयजल परियोजना के रूप में जयपुर, अजमेर, और टोंक जिलों को जल देता है, परंतु इसके समर्पित नहरी सिंचाई कमान क्षेत्र का विस्तार मुख्य रूप से टोंक जिले तक ही सीमित है। बीसलपुर की नहरी प्रणाली के माध्यम से केवल टोंक जिले की तहसीलों की कृषि भूमि को ही सिंचाई हेतु जल आपूर्ति किया जाता है।

13. (B) केवल I और III
बीसलपुर परियोजना टोंक जिले में बनास नदी पर निर्मित एक प्रसिद्ध बांध परियोजना है। यह परियोजना जयपुर, अजमेर, और टोंक जैसे प्रमुख शहरी और ग्रामीण अंचलों को निरंतर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करती है। हालांकि, इस परियोजना का नहरी सिंचाई लाभ मुख्य रूप से टोंक जिले के कृषि क्षेत्रों को प्राप्त होता है, अजमेर को नहीं। अतः पहला और तीसरा कथन सही हैं।

14. (C) लूनी
जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जल भंडार है। यह बांध जवाई नदी पर निर्मित है, जो अरावली पहाड़ियों से निकलकर बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी लूनी की एक प्रमुख सहायक नदी है। लूनी नदी बेसिन का जलसम्भर क्षेत्र शुष्क जलवायु में कृषि और जल आवश्यकताओं को पूरा करता है। जवाई नदी अंततः लूनी नदी में मिल जाती है।

15. (D) पाली
जवाई बांध का निर्माण जोधपुर रियासत के महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा 1946 में प्रारंभ करवाया गया था, जो 1957 में पूर्ण हुआ। यह पत्थरों से निर्मित एक भव्य बांध है जो राजस्थान के पाली जिले में सुमेरपुर कस्बे के निकट जवाई नदी पर स्थित है। यह बांध मारवाड़ क्षेत्र के पाली तथा आसपास के जिलों हेतु जल का प्रमुख आधार है।

16. (C) जवाई बांध
पाली जिले में स्थित जवाई बांध को अपनी विशाल भंडारण क्षमता और मारवाड़ क्षेत्र में जीवनदायिनी भूमिका के कारण "मारवाड़ का अमृत सरोवर" कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जहाँ सतही जल का अभाव रहता है, वहाँ यह जलाशय पाली और जोधपुर के लिए पेयजल तथा कृषि सिंचाई जल का सबसे बड़ा संचित स्रोत बनकर जीवन रक्षा करता है।

17. (B) पाली और जोधपुर जिलों को महत्वपूर्ण पेयजल की आपूर्ति करना
जवाई बांध यद्यपि मूलतः सिंचाई विस्तार के उद्देश्य से बनाया गया था, परंतु वर्तमान समय में बढ़ते जल संकट के कारण इसका प्राथमिक द्वितीयक उपयोग पाली और जोधपुर शहरों तथा आसपास के सैकड़ों गांवों को पेयजल आपूर्ति प्रदान करना बन गया है। जब बांध में जलस्तर घटता है, तब प्राथमिकता के आधार पर पेयजल आपूर्ति को ही सुरक्षित रखा जाता है।

18. (A) गंग नहर, जवाई बांध, माही बजाज सागर, बीसलपुर बांध
राजस्थान में इन परियोजनाओं का ऐतिहासिक निर्माण कालक्रम इस प्रकार है: गंग नहर 1927 में पूर्ण हुई। इसके पश्चात पाली जिले का जवाई बांध 1957 में बनकर तैयार हुआ। इसके बाद माही नदी पर माही बजाज सागर बांध का निर्माण 1980 के दशक में संपन्न हुआ। अंत में, टोंक जिले का बीसलपुर बांध 1990 के दशक के उत्तरार्ध में बनकर पूर्ण हुआ था।

19. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
सिधमुख-नोहर सिंचाई परियोजना का कमान क्षेत्र हनुमानगढ़ तथा चूरू जिलों को सिंचित करता है। मेजा बांध भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर बना है जो सिंचाई आवश्यकताएँ पूरी करता है। सोम-कमला-अंबा परियोजना डूंगरपुर जिले में स्थित एक मध्यम योजना है। बीसलपुर परियोजना का नहरी सिंचाई क्षेत्र टोंक जिले में फैला है। अतः सही मिलान P-3, Q-1, R-2, S-4 बनता है।

20. (C) माही बजाज सागर परियोजना - बांसवाड़ा और डूंगरपुर की भील और मीणा जनजातियां
माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान के दक्षिणी जनजातीय बहुल क्षेत्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में स्थित है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य वागड़ क्षेत्र की कृषि उपज को बढ़ाना और स्थानीय भील तथा मीणा जनजातीय आबादी का सामाजिक-आर्थिक उत्थान करना है। इसकी नहर प्रणाली के माध्यम से इन जनजातीय क्षेत्रों में सिंचित कृषि का अभूतपूर्व विकास संभव हो सका है।

21. (A) राजस्थान 45 : गुजरात 55
माही नदी जल विवाद के समाधान हेतु 1966 में राजस्थान तथा गुजरात के मध्य माही बजाज सागर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के अंतर्गत मुख्य बांध के निर्माण की कुल वित्तीय लागत को दोनों राज्यों में विभाजित किया गया था। स्वीकृत शर्तों के अनुसार निर्माण लागत का 45 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान द्वारा तथा 55 प्रतिशत हिस्सा गुजरात द्वारा वहन किया गया।

22. (D) 100 प्रतिशत
माही बजाज सागर बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित 1966 के अंतर-राज्यीय समझौते के प्रावधानों के अनुसार, हालांकि बांध निर्माण लागत में गुजरात का योगदान था, परंतु इससे उत्पादित होने वाली संपूर्ण जलविद्युत का उपयोग करने का सर्वाधिकार केवल राजस्थान को दिया गया है। इसलिए उत्पादित कुल

Click Here to Buy book on Flipkart

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) कम औसत वर्षा और सीमित बारहमासी सतही जल संसाधन
राजस्थान की भौगोलिक स्थिति अत्यंत शुष्क तथा अर्ध-शुष्क है। राज्य में वर्षा की मात्रा बहुत कम तथा अनिश्चित होती है। चंबल नदी के अलावा यहाँ बारहमासी सतही नदियाँ नहीं हैं। जल संसाधनों की इस अत्यधिक कमी तथा कम वर्षा के कारण राज्य में कृषि का विकास गंभीर रुप से बाधित होता है। सिंचाई के लिए भूजल पर अत्यधिक निर्भरता रहती है, जिससे कृषि उत्पादन अनिश्चितताओं से प्रभावित रहता है।

2. (D) नलकूप और कुएं
राजस्थान में सिंचाई संसाधनों में नलकूपों तथा कुओं का योगदान सर्वाधिक है। राज्य के कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 66 से 70 प्रतिशत भाग नलकूपों और पारंपरिक कुओं के माध्यम से सिंचित होता है। विशेष रुप से जयपुर, अलवर, भरतपुर तथा पूर्वी मैदानी भागों में भूजल निष्कर्षण कृषि का मुख्य साधन है। नहरी सिंचाई का स्थान इसके बाद आता है जो मुख्यतः उत्तरी राजस्थान में सीमित है।

3. (A) मध्य प्रदेश, 50:50
चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की एक महत्वपूर्ण अंतर-राज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1953 में प्रारंभ हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत दोनों राज्यों के मध्य जल संसाधनों, विद्युत उत्पादन और निर्माण लागत का समान विभाजन किया गया है। स्वीकृत समझौते के अनुसार व्यय लागत एवं प्राप्त लाभों का अनुपात 50:50 निर्धारित किया गया है।

4. (C) गांधी सागर बांध और कोटा बैराज
चंबल नदी घाटी परियोजना का विकास तीन चरणों में पूरा किया गया था। इस बहुउद्देशीय परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत दो प्रमुख जल संरचनाओं का निर्माण हुआ। इनमें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध और राजस्थान के कोटा जिले में कोटा बैराज शामिल हैं। गांधी सागर बांध जल भंडारण एवं जलविद्युत उत्पादन करता है, जबकि कोटा बैराज केवल सिंचाई हेतु निर्मित है।

5. (A) चित्तौड़गढ़
राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी घाटी परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत निर्मित एक प्रमुख बांध है। यह जल संरचना राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले की रावतभाटा तहसील में स्थित है। इस बांध का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। यह राजस्थान का जल भंडारण क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। यहाँ जलविद्युत उत्पादन केंद्र भी संचालित किया जाता है।

6. (D) इसका उपयोग विशेष रुप से सिंचाई के लिए किया जाता है और इससे कोई जलविद्युत उत्पादित नहीं होती है
चंबल नदी पर निर्मित चार बांधों की श्रृंखला में कोटा बैराज की कार्यात्मक विशेषता इसे अन्य तीन बांधों से भिन्न बनाती है। श्रृंखला के अन्य तीन बांधों में जल भंडारण के साथ-साथ जलविद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसके विपरीत, कोटा बैराज से किसी प्रकार का विद्युत उत्पादन नहीं होता है। इसका उपयोग केवल नहरी प्रणालियों द्वारा सिंचाई जल वितरण हेतु किया जाता है।

7. (A) 4, 2, 1, 3
चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में जनापाव की पहाड़ियों से होता है। दक्षिण से उत्तर की ओर नदी के प्राकृतिक प्रवाह के क्रम में सबसे पहले गांधी सागर बांध आता है। इसके पश्चात आगे बढ़ने पर राणा प्रताप सागर बांध, फिर जवाहर सागर बांध और अंत में सबसे निचले भाग में कोटा बैराज स्थित है। इनका भौगोलिक अनुक्रम 4, 2, 1, 3 है।

8. (D) I, II, III और IV
चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। इसका प्रथम बांध गांधी सागर भौगोलिक रुप से मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। राजस्थान में स्थित बांधों में राणा प्रताप सागर बांध की क्षमता सर्वाधिक है। जवाहर सागर बांध पिक-अप बांध के रुप में कार्य करता है, जो कोटा बैराज हेतु जल प्रवाह बनाए रखता है। ये सभी कथन सत्य हैं।

9. (A) P-2, Q-4, R-1, S-3
गांधी सागर बांध चंबल नदी पर निर्मित परियोजना का भाग है। बीसलपुर बांध टोंक जिले में बनास नदी पर बनाया गया है। जवाई बांध लूनी नदी की सहायक जवाई नदी पर पाली में स्थित है, जो लूनी बेसिन में आता है। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में माही नदी पर निर्मित है। इनका सही सुमेल P-2, Q-4, R-1, S-3 बनता है।

NODIA

10. (A) दाईं मुख्य नहर केवल मध्य प्रदेश को सिंचाई प्रदान करती है।
कोटा बैराज से निकलने वाली चंबल नहर प्रणाली दो मुख्य शाखाओं में विभाजित है। बाईं मुख्य नहर मुख्यतः कोटा और बूंदी जिलों को सिंचाई जल प्रदान करती है। वहीं दाईं मुख्य नहर राजस्थान के कोटा तथा बारां जिलों से होकर मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। अतः यह दाईं नहर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के कृषि क्षेत्रों को सिंचाई लाभ पहुँचाती है।

11. (B) बनास
बीसलपुर बांध परियोजना राजस्थान की एक महत्वपूर्ण पेयजल एवं सिंचाई परियोजना है। इसका निर्माण टोंक जिले

परियोजना से उदयपुर जिले के कुछ सीमावर्ती गांवों को भी नहरी सिंचाई प्राप्त होती है।

35. (A) पांच नदी धाराओं के संगम पर निर्मित एक मिट्टी का बांध
पांचना बांध करौली जिले के भद्रावती गांव के पास स्थित है। इस बांध की सबसे विशिष्ट संरचनात्मक विशेषता यह है कि यह पूरी तरह से मिट्टी से निर्मित एक विशाल बांध है। इसका नाम "पांचना" इसलिए पड़ा क्योंकि यह पांच स्थानीय नदी धाराओं—अटा, माची, भद्रावती, बरखेड़ा और भैंसावट के संगम पर बनाया गया है। यह सिंचाई का प्रमुख स्रोत है।

36. (C) गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान
नर्मदा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार नर्मदा नदी जल के बंटवारे हेतु चार राज्यों का एक संयुक्त अंतर-राज्यीय ढांचा तैयार किया गया था। नर्मदा नहर परियोजना में भागीदार चार राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान हैं। गुजरात में स्थित सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नहर निकाली गई है, जो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में जल पहुँचाती है।

37. (A) सीलू गांव, जालौर
गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निकलने वाली नर्मदा मुख्य नहर गुजरात में दूरी तय करने के पश्चात राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है। यह नहर राजस्थान में जालौर जिले की सांचौर तहसील के सीलू गांव में प्रवेश करती है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 74 किलोमीटर है, जो जालौर और बाड़मेर जिलों को सिंचाई तथा पेयजल प्रदान करती है।

38. (C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
चंबल नदी पर बने चार बांधों में कोटा बैराज वास्तव में अद्वितीय है क्योंकि इसका निर्माण केवल नहरी सिंचाई प्रणाली के विकास के लिए किया गया है। कारण वाला कथन गलत है क्योंकि कोटा बैराज चंबल श्रृंखला का एकमात्र ऐसा बांध है जिससे जलविद्युत का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है। जलविद्युत उत्पादन श्रृंखला के अन्य तीनों बांधों में किया जाता है।

39. (B) 15.22 प्रतिशत
भाखड़ा-नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का एक विशाल संयुक्त उपक्रम है। सतलुज नदी पर निर्मित इस परियोजना से प्राप्त होने वाले जल और विद्युत संसाधनों का आवंटन साझेदार राज्यों के बीच किया गया है। अंतर-राज्यीय समझौतों के अनुसार इस विशाल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 15.22 प्रतिशत निर्धारित है। इससे उत्तरी जिलों को निरंतर लाभ मिलता है।

40. (C) अलवर और भरतपुर
1994 में हुए यमुना जल समझौते के अंतर्गत राजस्थान को यमुना नदी के जल का हिस्सा आवंटित किया गया था। इस आवंटित जल को पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए गुड़गांव नहर और भरतपुर नहर प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। इन नहरों के माध्यम से मुख्यतः अलवर और भरतपुर जिलों की कृषि भूमि को सिंचाई जल प्राप्त होता है।

41. (A) नलकूप और कुएं > नहरें > तालाब
राजस्थान में सिंचित क्षेत्र के स्रोतों का सही घटता क्रम इस प्रकार है: सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों और कुओं के माध्यम से होती है, जो कुल सिंचित भूमि के लगभग 66-70% भाग को कवर करते हैं। दूसरे स्थान पर नहरी सिंचाई आती है, जो लगभग 30% क्षेत्र में फैली है। तीसरे स्थान पर तालाब आते हैं, जिनका योगदान नगण्य है। अतः क्रम सही है।

NODIA

42. (A) बाजरा और मोठ से कपास और गेहूं
नहरों के आगमन से पूर्व गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में शुष्क जलवायु के कारण बाजरा, मोठ, और ग्वार जैसी कम जल आवश्यकता वाली पारंपरिक फसलें बोई जाती थीं। नहरी सिंचाई के नियमित विस्तार के कारण भूमि की नमी में सुधार हुआ, जिससे किसानों ने उच्च मूल्य वाली व्यावसायिक फसलों जैसे कपास तथा गेहूं की खेती व्यापक स्तर पर प्रारंभ कर दी थी।

43. (B) सेम
नहरी कमान क्षेत्रों में अत्यधिक पानी के रिसाव और जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से भूजल स्तर ऊपर उठ जाता है। इस स्थिति को स्थानीय भाषा में "सेम" की समस्या कहा जाता है। हनुमानगढ़ जिले के बड़ोपल और आसपास के क्षेत्रों में सेम की समस्या के कारण कृषि भूमि दलदली तथा लवणीय होकर कृषि हेतु अनुपजाऊ बन चुकी है।

44. (B) पूर्वी और मध्य मैदान
राजस्थान के पूर्वी और मध्य मैदानी भाग, जिनमें जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा और अजमेर जिले शामिल हैं, उपजाऊ मृदा संरचना से युक्त हैं। इन क्षेत्रों में पर्याप्त पुनर्भरण और अनुकूल भूजल जलभृत विद्यमान हैं। इस भौगोलिक अनुकूलता के कारण नलकूपों तथा कुओं द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक संकेंद्रण राज्य के इसी पूर्वी मैदानी कृषि क्षेत्र में सदैव पाया जाता है।

45. (A) यह यांत्रिक रूप से जल को प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण के विपरीत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पंप करती है।
मानक प्रवाह नहर प्रणाली में जल प्राकृतिक ढलान और गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर स्वतः बहता है। इसके विपरीत, लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उपयोग तब किया जाता है जब सिंचित की जाने वाली भूमि का धरातल नहर के जलस्तर से अधिक ऊँचा होता है। ऐसी स्थिति में यांत्रिक पंपों से जल ऊपर उठाया जाता है।

46. (A) केवल I और II
अस्तर रहित नहरों के तल से पानी का रिसाव स्थानीय उथले जलभृतों के पुनर्भरण में सहायता करता है। हालाँकि, नहरी कमान क्षेत्रों में अत्यधिक रिसाव के कारण व्यापक जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। तीसरा कथन असत्य है क्योंकि लिफ्ट सिंचाई में जल को पंपों द्वारा ऊपर उठाया जाता है। अतः केवल पहला और दूसरा कथन ही सत्य हैं।

(D) यह भारी मशीनों को पहाड़ियों की चोटी से मैदानों की ओर आसानी से आवाजाही की अनुमति देता है।

9. निम्नलिखित में से कौन-सी गतिविधि आमतौर पर जलागम विकास परियोजना के मुख्य घटक के रूप में अनुमेय नहीं है?
(A) परिधीय चेक डैम और मिट्टी के बांधों (अर्थन बंड) का निर्माण
(B) सामाजिक वानिकी और सामुदायिक चरागाह विकास को बढ़ावा देना
(C) तीव्र पहाड़ी ढलानों पर विषम समुच्च खाइयों (स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच) की खुदाई करना
(D) व्यावसायिक खेती के लिए गहरे नलकूपों की खुदाई करना

10. केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जो मरुस्थल सुधार के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
(A) जोधपुर
(B) बीकानेर
(C) जैसलमेर
(D) बाड़मेर

11. राजस्थान में भीषण सूखे की अवधि के दौरान, सरकार "चारा शिविर" (चारा डिपो) स्थापित करती है। इन शिविरों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) किसानों को उच्च उपज वाली विदेशी मवेशियों की नस्लें मुफ्त में वितरित करना
(B) पशुधन की संकटग्रस्त बिक्री और भुखमरी से होने वाली मृत्यु को रोकना
(C) पड़ोसी राज्यों में अधिशेष सूखे चारे का निर्यात करना
(D) कृषि योग्य भूमि को स्थायी चरागाहों में बदलना अनिवार्य करना

12. राजस्थान में लवणता के कारणों और प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में लवणता मुख्य रूप से अत्यधिक सिंचाई और उप-सतही जल निकासी की कमी के कारण होती है।
II. जिप्सम का प्रयोग क्षारीय/सोडिक मृदा के सुधार की एक मानक विधि है।
III. मृदा लवणता को कम करने के लिए गहरी जड़ों वाली, अत्यधिक जल-गहन फसलों की खेती की सिफारिश की जाती है।
IV. पश्चिमी राजस्थान में उच्च वाष्पीकरण दर प्राकृतिक रूप से लवणों की ऊपर की ओर केशिकत्व गति में योगदान देती है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

13. तरुण भारत संघ (टीबीएस), एक प्रमुख गैर-सरकारी संगठन, ने 'जोहड़' नामक पारंपरिक संरचनाओं का उपयोग करके क्षरित भूमि को बहाल करने और भूजल को पुनर्भृत करने के लिए समुदायों को लामबंद करने हेतु अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल की है। टीबीएस ने मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले से अपना सफल हस्तक्षेप शुरू किया था?
(A) अलवर
(B) जोधपुर
(C) बांसवाड़ा
(D) चूरू

14. परियोजना कार्यान्वयन अवधि समाप्त होने के बाद जलागम विकास परियोजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में निम्नलिखित में से किसे एक बड़ी चुनौती माना जाता है?
(A) केंद्र सरकार से अपर्याप्त प्रारंभिक परियोजना वित्तपोषण आवंटन
(B) परियोजना नियोजन के दौरान तकनीकी दिशा-निर्देशों की पूर्ण अनुपलब्धता
(C) स्थानीय सामुदायिक स्वामित्व की कमी के कारण निर्मित परिसंपत्तियों का खराब रख-रखाव
(D) सतही अपवाह का अत्यधिक संचयन जिससे गंभीर स्थानीय बाढ़ आती है

15. भारत में निम्नलिखित क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के शुभारंभ के सही कालानुक्रमिक क्रम का सबसे पहले से सबसे नवीनतम के रूप में चयन कीजिए।
(A) सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम → मरुस्थल विकास कार्यक्रम → एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम
(B) मरुस्थल विकास कार्यक्रम → एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम → सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम
(C) सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम → एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम → मरुस्थल विकास कार्यक्रम
(D) एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम → मरुस्थल विकास कार्यक्रम → सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम

16. पश्चिमी राजस्थान में बालुका स्तूप स्थिरीकरण के संदर्भ में, स्थानीय रूप से उपलब्ध झाड़ियों का उपयोग करके "सूक्ष्म पवन-रोधक" लगाने का उद्देश्य क्या है?
(A) तत्काल घरेलू उपभोग के लिए सतही वर्षा जल अपवाह को एकत्र करना
(B) प्रवासी स्थानीय पशुपालकों के लिए अस्थायी रात्रिकालीन आश्रयों का निर्माण करना
(C) मृदा-सतह पर वायु के वेग को कम करना और नए पौधों की रक्षा करना
(D) आसपास की वायुमंडलीय आर्द्रता से नमी निकालना

17. राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में बालुका स्तूप स्थिरीकरण और रक्षक मेखला (शेल्टरबेल्ट) वृक्षारोपण के लिए निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति को सबसे व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जाता है?

Downloaded from www.pdf.tube

प्रवाह बढ़ता है, कमान क्षेत्र के अंतिम छोर तक पानी पहुँचता है, मार्ग में जलभराव रुकता है और जल परिवहन की समग्र दक्षता में व्यापक सुधार दर्ज किया जाता है।

59. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
वाराबंदी किसानों को बारी-बारी से जल वितरण की एक व्यवस्था है। कमान क्षेत्र परियोजना द्वारा सिंचित किए जाने योग्य कुल क्षेत्र है। लिफ्ट सिंचाई गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जल को ऊंचे स्थानों पर उठाने की प्रक्रिया है। नहर रिसाव कच्ची नहर के तल से होने वाली भूमिगत जल हानि को दर्शाता है। अतः सही सुमेल P-3, Q-1, R-2, S-4 बनता है।

60. (B) फसलों द्वारा उपयोग किए गए जल का स्रोत से निकाले गए कुल जल से अनुपात
नहरी नेटवर्क में "जल उपयोग दक्षता" की सटीक परिभाषा यह है कि मुख्य जल स्रोत से निकाले गए कुल जल की मात्रा में से वास्तव में फसलों द्वारा वृद्धि हेतु कुशलतापूर्वक उपयोग किए गए जल का अनुपात कितना है। उच्च जल उपयोग दक्षता का अर्थ है कि परिवहन और रिसाव के दौरान न्यूनतम जल व्यर्थ हुआ है तथा अधिकांश जल फसल उत्पादन में प्रयुक्त हुआ है।

61. (A) जल संसाधन विभाग (WRD)
राजस्थान में जल संसाधन विभाग राज्य की सभी प्रमुख और मध्यम नदी घाटी परियोजनाओं के सर्वेक्षण, नियोजन, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार प्राथमिक कार्यकारी एजेंसी है। यह विभाग राज्य के सतही जल संसाधनों के आवंटन, नहर प्रणालियों के संचालन और बांधों की सुरक्षा की देखरेख करता है ताकि कृषि हेतु निरंतर जल उपलब्धता बनी रहे।

62. (C) 2000
राजस्थान में सहभागी सिंचाई प्रबंधन को कानूनी मान्यता देने तथा जल उपभोक्ता संगमों का गठन करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2000 में विशेष अधिनियम पारित किया गया था। इस ऐतिहासिक कानून ने नहरी जल के वितरण, रखरखाव और प्रबंधन में स्थानीय किसानों को प्रत्यक्ष अधिकार तथा कानूनी शक्तियाँ प्रदान कीं, जिससे किसान सशक्त बने।

63. (A) 2, 4, 1, 5, 3
मुख्य जल स्रोत से किसान के खेत तक नहरी सिंचाई वितरण प्रणाली का संरचनात्मक क्रम इस प्रकार है: जल सबसे पहले मुख्य नहर में प्रवेश करता है। मुख्य नहर से यह शाखा नहर में जाता है, जिसके बाद पानी वितरिका में प्रवाहित होता है। वितरिका से जल माइनर में पहुँचता है और अंत में खाला/फील्ड चैनल द्वारा खेत में जाता है।

64. (B) केवल I और III
जल उपभोक्ता संगमों का गठन सहभागी सिंचाई प्रबंधन दृष्टिकोण के तहत किया जाता है। इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी माइनर नहर स्तर पर किसानों के बीच न्यायसंगत जल वितरण और नालियों का रखरखाव करना है। बड़े बांधों का निर्माण जल संसाधन विभाग करता है, न कि ये संगम। अतः केवल पहला और तीसरा कथन ही पूर्णतः सत्य हैं।

65. (D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।
अभिकथन पूरी तरह असत्य है क्योंकि जल संसाधन विभाग ने बीसलपुर या कोटा बैराज जैसे विशाल बांधों का स्वामित्व किसान संगमों को हस्तांतरित नहीं किया है। कारण कथन सत्य है क्योंकि सहभागी सिंचाई प्रबंधन का वास्तविक उद्देश्य केवल माइनर नहरों के सूक्ष्म स्तर पर जल वितरण में किसानों की भागीदारी बढ़ाना है। अतः अभिकथन असत्य है जबकि कारण पूर्णतः सत्य है।

66. (D) स्थानीय जल उपभोक्ता संगम (किसान)
सहभागी सिंचाई प्रबंधन मॉडल की अवधारणा के तहत माइनर नहरों और खेतों की नालियों की नियमित गाद निकालने, खरपतवार हटाने तथा मामूली भौतिक रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय जल उपभोक्ता संगमों की होती है। इसमें कमान क्षेत्र के कृषक स्वयं संगठित होकर अपने नहरी ढांचे की देखरेख करते हैं, जिससे जल प्रवाह बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलता रहे।

67. (A) किसानों से जल प्रभार (आबियाना) एकत्र करने और स्थानीय रखरखाव के लिए एक हिस्सा अपने पास रखने
जल उपभोक्ता संगमों की वित्तीय आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें वैधानिक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों के तहत संगम अपने कमान क्षेत्र के किसानों से जल प्रभार (आबियाना) एकत्र करते हैं। इस संगृहीत राजस्व का एक निश्चित भाग संगमों को दिया जाता है जिसका उपयोग वे नहरी नालियों के स्थानीय मरम्मत और रखरखाव कार्यों में करते हैं।

68. (C) लोकतांत्रिक, जिसमें स्थानीय कमान क्षेत्र के किसानों द्वारा चुनी गई एक प्रबंध समिति होती है
जल उपभोक्ता संगम एक विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक संस्थागत ढांचा है। इसका गठन किसी सरकारी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि संबंधित माइनर कमान क्षेत्र के सभी किसान इसके सदस्य होते हैं। ये किसान लोकतांत्रिक चुनाव द्वारा एक प्रबंध समिति का चुनाव करते हैं जो जल वितरण, वाराबंदी सारणी और नहरी रखरखाव संबंधी सभी निर्णय लेती है।

69. (A) गाद का जमाव नहर के अनुप्रस्थ-काट को छोटा कर देता है, जिससे जल-वहन क्षमता घट जाती है
राजस्थान में बहने वाली नदियों के जल में मिट्टी और रेत की भारी मात्रा आती है, जो समय के साथ नहरों के तल में जम जाती है। गाद का यह अत्यधिक जमाव नहर के अनुप्रस्थ-काट क्षेत्रफल को संकीर्ण कर देता है। इसके परिणामस्वरूप नहर की कुल जल-वहन क्षमता में भारी गिरावट आती है, जिससे दूरस्थ किसानों तक पानी नहीं पहुँचता।

70. (D) अंतिम छोर पर जल की कमी और शुरुआती भाग में जलभराव
दशकों से नहरों की पक्की सतह में टूट-फूट और क्षरण होने से दो गंभीर समस्याएं एक साथ उत्पन्न होती हैं। नहर के शुरुआती भाग में टूटी लाइनिंग से भारी जल रिसाव होता है, जिससे वहाँ जलभराव और सेम की समस्या बनती है। इस रिसाव के कारण

NODIA

47. (D) नर्मदा लिफ्ट नहर
कंवर सेन, गंधेली साहावा, और पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहरें इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रणाली से जुड़ी प्रमुख लिफ्ट नहरें हैं जो बीकानेर तथा चूरू जिलों को जल पहुँचाती हैं। इसके विपरीत, नर्मदा नहर परियोजना एक पृथक प्रणाली है जो सरदार सरोवर बांध से जल प्राप्त करती है और यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रणाली से संबंधित नहीं है।

48. (C) दक्षता को अधिकतम करने और जलभराव को रोकने के लिए सतही नहर जल और भूजल दोनों का समन्वित एवं नियोजित उपयोग
कमान क्षेत्र विकास में जल के संयुक्त उपयोग का तात्पर्य सतही नहरी जल और भूजल का एक साथ संतुलित तथा समन्वित तरीके से उपयोग करना है। जब केवल नहरी जल का अत्यधिक उपयोग होता है, तो जलभराव की समस्या पैदा होती है। नहरी जल के साथ नलकूपों द्वारा भूजल उपयोग करने से जलस्तर नियंत्रित रहता है और दक्षता बढ़ती है।

49. (B) उच्च रिसाव हानि जिससे स्थानीय जलभराव और जल स्तर बढ़ता है
जिन नहरी क्षेत्रों में मुख्य नहरें और वितरिकाएं अस्तर रहित होती हैं, वहां से बड़ी मात्रा में पानी का निरंतर रिसाव होता है। इस अनियंत्रित रिसाव के कारण आसपास के कृषि क्षेत्रों में उथला भूजल स्तर तेजी से ऊपर उठ जाता है। इसके तात्कालिक दुष्परिणाम के रूप में खेत जलभराव का शिकार हो जाते हैं और मृदा लवणता बढ़ती है।

50. (D) उसने स्वतंत्रता के बाद वृहद राजस्थान नहर (IGNP) की योजना को प्रेरित किया।
1927 में निर्मित गंग नहर ने यह सिद्ध कर दिया था कि दूरस्थ हिमालयी नदियों के पानी को नहरों के माध्यम से थार मरुस्थल तक लाकर बंजर भूमि को हरा-भरा किया जा सकता है। गंग नहर की इस सफलता ने ही स्वतंत्रता के पश्चात विशालकाय राजस्थान नहर (वर्तमान इंदिरा गांधी नहर परियोजना) के निर्माण की योजना को प्रत्यक्ष प्रेरणा दी।

51. (A) सृजित और वास्तव में उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर को समाप्त करना
कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 1974-75 में शुरु किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में जलाशयों एवं नहरों द्वारा निर्मित सिंचाई क्षमता और किसानों के खेतों में वास्तव में उपयोग की जा रही क्षमता के बीच के अंतर को समाप्त करना है। इसके लिए ऑन-फार्म विकास कार्य एवं सुव्यवस्थित जल प्रबंधन कर जल उपयोग क्षमता बढ़ाई जाती है।

52. (B) केवल I, III और IV
कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य निर्मित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के अंतर को दूर करना है। इसके तहत खेत स्तर पर विकास कार्य जैसे फील्ड चैनल निर्माण तथा वाराबंदी प्रणाली द्वारा न्यायसंगत जल वितरण किया जाता है। यह प्राथमिक भंडारण बांधों के निर्माण पर केंद्रित नहीं है। अतः केवल कथन I, III और IV ही सत्य हैं।

53. (A) कमान क्षेत्र के किसानों के बीच जल के न्यायसंगत वितरण की एक घूर्णन प्रणाली
राजस्थान के नहरी कमान क्षेत्रों में "वाराबंदी" जल प्रबंधन की एक समयबद्ध घूर्णन प्रणाली है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक किसान को उसकी भूमि के आकार के अनुपात में निश्चित समय अंतराल के लिए नहरी पानी का आवंटन किया जाता है। इससे कमान क्षेत्र के अंतिम छोर पर स्थित किसानों तक भी सिंचाई जल का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित होता है।

54. (D) मुख्य नदी बैराज का निर्माण
खेत पर विकास कार्यों में वे सभी गतिविधियाँ शामिल होती हैं जो किसान के खेत स्तर पर जल वितरण हेतु की जाती हैं। इनमें खाला निर्माण, भूमि समतलीकरण तथा खेतों की सीमाओं का पुनर्गठन शामिल है। इसके विपरीत, मुख्य नदी बैराज या बड़े बांधों का निर्माण एक वृहद बुनियादी ढांचा कार्य है जो OFD गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आता है।

55. (B) ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली स्थापित करने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करना
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 'प्रति बूंद अधिक फसल' घटक के तहत राजस्थान सरकार सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दे रही है। इस प्रोत्साहन का मुख्य तरीका किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों की स्थापना पर भारी सब्सिडी प्रदान करना है। इससे पारंपरिक प्रवाह सिंचाई की तुलना में जल की बचत होती है और फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है।

56. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के नहरी क्षेत्रों में ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये आधुनिक पद्धतियाँ पौधों की जड़ों में नियंत्रित जल देती हैं। परिणामस्वरुप, पारंपरिक सिंचाई से उत्पन्न जलभराव और मृदा लवणता की समस्याएं काफी हद तक कम हो जाती हैं। अतः दोनों कथन सही हैं।

57. (D) नर्मदा नहर परियोजना
नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान की पहली ऐसी सिंचाई परियोजना है जिसमें सम्पूर्ण कमान क्षेत्र के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का उपयोग पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। बिना सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित किए किसी भी किसान को नहरी पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाता, जिससे जल की अधिकतम बचत एवं सिंचाई दक्षता सुनिश्चित होती है।

58. (A) रिसाव की हानि को कम करने और जल परिवहन दक्षता में सुधार करने के लिए
पुरानी नहरी परियोजनाओं में मुख्य नहरों और वितरिकाओं को पक्का करने का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के रिसाव द्वारा होने वाले जल नुकसान को रोकना है। नहरों को पक्का करने से जल

Click Here to Buy book on Amazon

अध्याय 16
बंजर भूमि एवं सूखा-प्रवण क्षेत्र विकास परियोजनाएँ

1. राजस्थान के भू-राजस्व अभिलेखों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प "कृषि योग्य व्यर्थ भूमि" को सर्वोत्तम रुप से परिभाषित करता है?
(A) वह भूमि जिसकी अत्यधिक पथरीले भू-भाग के कारण कभी जुताई नहीं की गई है
(B) वह भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध है, किंतु चालू वर्ष तथा पिछले लगातार पाँच वर्षों या उससे अधिक समय से उस पर कृषि नहीं की गई है
(C) वह भूमि जो अत्यधिक लवणता के कारण पूरी तरह से अनुपयोगी हो गई है
(D) वह भूमि जो वर्तमान में स्थायी चरागाह के अंतर्गत है और किसी भी कृषि फसल के लिए उपयोग नहीं की जा सकती है

2. राजस्थान के पश्चिमी शुष्क जिलों में बंजर भूमि के निर्माण का सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) बारहमासी नदियों द्वारा तीव्र अवनालिका अपरदन
(B) अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण जलभराव
(C) सतही मृदा को प्रदूषित करने वाला औद्योगिक अपशिष्ट विसर्जन
(D) वायु अपरदन और स्थानांतरित बालुका स्तूप

3. मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने और पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ प्रारंभ किया गया था। यह केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम किस वर्ष शुरु किया गया था?
(A) 1973-74
(B) 1977-78
(C) 1985-86
(D) 1994-95

4. मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं?
(A) 11 जिले
(B) 16 जिले
(C) 21 जिले
(D) 33 जिले

5. सूची I की मदों को सूची II की मदों से सुमेलित कीजिए।
सूची I: क्षरण की समस्याएँ
P. तीव्र अवनालिका अपरदन
Q. जलभराव और द्वितीयक लवणता
R. स्थानांतरित बालुका स्तूप
S. अरावली ढलानों का वनोन्मूलन
सूची II: जिले/क्षेत्र
1. जैसलमेर और बीकानेर
2. कोटा और सवाई माधोपुर
3. उदयपुर और राजसमंद
4. हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर
(A) P-2, Q-4, R-1, S-3
(B) P-4, Q-2, R-1, S-3
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-1, Q-4, R-2, S-3

6. राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) मुख्य रुप से किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र को लक्षित करता है?
(A) विरल वनस्पति की विशेषता वाले अति-शुष्क क्षेत्र
(B) उच्च-ऊँचाई और आर्द्र पर्वतीय जलवायु क्षेत्र
(C) तटीय क्षेत्र और डेल्टा क्षेत्र की लवणीय पारिस्थितिकी भूमि
(D) अर्द्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्र

NODIA

7. एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसे सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) का विलय करके प्रारंभ किया गया था।
II. यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के वित्तपोषण पैटर्न पर कार्य करता है।
III. यह मृदा और जल संरक्षण के लिए कटक से घाटी (रिज-टू-वैली) दृष्टिकोण का पालन करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

8. जलागम विकास में, "कटक से घाटी" (रिज-टू-वैली) उपचार दृष्टिकोण अपनाने का प्राथमिक तर्क क्या है?
(A) यह घाटी क्षेत्रों को पहले विकसित करके शीघ्र वित्तीय लाभ प्रदान करता है।
(B) यह सुनिश्चित करता है कि घाटी में गहरे बोरवेल सीधे कटक के ऊपरी हिस्सों से पुनर्भरण प्राप्त करें।
(C) यह निचले क्षेत्रों में निर्मित मृदा संरक्षण संरचनाओं को बहने से रोकता है।

नहर के अंतिम छोर पर पहुँचते-पहुँचते पानी का भारी अभाव उत्पन्न हो जाता है।

71. (B) चंबल
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राज्य के 13 पूर्वी जिलों की सिंचाई और पेयजल समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रस्तावित एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य मानसून में चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के उप-बेसिनों में बहने वाले अधिशेष सतही जल का संचयन करके जल-कमी वाले बनास तथा अन्य नदी बेसिनों में मोड़कर जल आपूर्ति बढ़ाना है।

72. (C) बारां, झालावाड़ और कोटा
निर्माणाधीन परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना हाड़ौती अंचल की एक अति महत्वपूर्ण जल योजना है। यह परियोजना चंबल की सहायक परवन नदी पर झालावाड़ जिले में निर्मित की जा रही है। इस बहुउद्देशीय परियोजना से मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र के तीन जिलों—झालावाड़, बारां और कोटा के सैकड़ों गांवों को सिंचाई सुविधाएं मिलने के साथ-साथ शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा।

73. (D) बीसलपुर बांध
ईसरदा बांध परियोजना का निर्माण सवाई माधोपुर जिले में बनास नदी पर किया जा रहा है। यह बांध बीसलपुर बांध के निचले प्रवाह भाग में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य बीसलपुर बांध से ओवरफ्लो होकर बहने वाले अतिरिक्त जल को रोकना है ताकि जयपुर, दौसा, और सवाई माधोपुर जिलों को पेयजल तथा सिंचाई जल उपलब्ध कराया जा सके।

74. (A) केवल I और III
पहला कथन असत्य है क्योंकि ERCP चंबल नदी बेसिन के जल का उपयोग करती है, लूनी का नहीं। तीसरा कथन भी असत्य है क्योंकि जैसलमेर जैसे शुष्क जिलों में तालाब सिंचाई नहीं होती, बल्कि वहाँ नहरी सिंचाई पाई जाती है। दूसरा और चौथा कथन सत्य हैं। अतः दिए गए कथनों में से केवल I और III असत्य हैं।

75. (B) जाखम बांध
जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी कुल ऊंचाई 81 मीटर है। यह बांध प्रतापगढ़ जिले के पास जाखम नदी पर बनाया गया है। जाखम नदी माही की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य प्रतापगढ़ तथा आसपास के दक्षिणी आदिवासी बहुल क्षेत्रों की कृषि भूमि को सिंचाई सुविधाएं तथा जलापूर्ति प्रदान करना है।

76. (B) माही बजाज सागर बांध
राजस्थान में स्थित बांधों में से माही बजाज सागर बांध को राज्य का सबसे लंबा बांध होने का गौरव प्राप्त है। यह विशाल बांध बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा गांव के पास माही नदी पर निर्मित किया गया है। इस बांध के मुख्य ढांचे की कुल लंबाई 3109 मीटर है। यह दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई का मुख्य आधार है।

77. (A) गंगानगर
राजस्थान के जिलावार सिंचित आंकड़ों के अनुसार, श्रीगंगानगर जिला अपने शुद्ध बोए गए क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशत भाग पर नहरी सिंचाई का उपयोग करता है। गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर प्रणाली के नेटवर्क के कारण श्रीगंगानगर की अधिकांश कृषि भूमि नहरों द्वारा सिंचित होती है। इसी नहरी सुविधा के कारण इसे अन्न भंडार भी कहा जाता है।

78. (C) कुएं और नलकूप मिलकर राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र के 30 प्रतिशत से भी कम हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
राजस्थान में सिंचाई के आंकड़ों के संबंध में तीसरा कथन असत्य है। वास्तविकता यह है कि कुएं और नलकूप मिलकर राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र के 30 प्रतिशत से कम नहीं, बल्कि सर्वाधिक 66 से 70 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य में नहरी सिंचाई का हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत है। अतः यह कथन पूर्णतः असत्य है।

79. (D) सूखे की संवेदनशीलता को कम करके खाद्य सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना
राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में नदी घाटी तथा नहरी परियोजनाओं को लागू करने का अंतिम उद्देश्य बार-बार पड़ने वाले अकाल और सूखे के दुष्प्रभावों को कम करना है। सिंचाई जल की नियमित उपलब्धता से कृषि में स्थिरता आती है, जिससे खाद्य सुरक्षा मजबूत होती है, ग्रामीण रोजगार बढ़ता है तथा मरुस्थलीय आबादी का सामाजिक-आर्थिक जीवन स्तर बेहतर एवं सुदृढ़ होता है।

80. (C) प्राकृतिक स्थलाकृति मुख्य नहर की तुलना में अधिक ऊंची है, जिसके लिए जल को ऊपर की ओर पंप करने की आवश्यकता होती है
पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर प्रणाली में लिफ्ट नहरों का निर्माण इसलिए अनिवार्य है क्योंकि नहर के पूर्व की ओर के क्षेत्रों की प्राकृतिक स्थलाकृति मुख्य नहर के जलस्तर से अधिक ऊँची है। जल प्राकृतिक रुप से बिना ढलान के ऊँचे स्थानों की ओर नहीं बह सकता। इसलिए पंपों द्वारा पानी को ऊँचे क्षेत्रों तक लिफ्ट किया जाता है।

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

(A) टेक्टोना ग्रैंडिस (व्यावसायिक सागौन का वृक्ष)
(B) प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा (विलायती बबूल)
(C) शोरिया रोबस्टा (उष्णकटिबंधीय साल का वृक्ष)
(D) मैंगिफेरा इंडिका (कृषि योग्य आम का वृक्ष)

18. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) स्व-स्थाने मृदा नमी संरक्षण पर अत्यधिक बल देता है।
कारण (R): डीपीएपी के अंतर्गत आने वाले अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र गंभीर वर्षा परिवर्तनशीलता और आवधिक शुष्क दौरों का सामना करते हैं।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

19. इंदिरा गांधी नहर के किनारे बड़े पैमाने पर रक्षक मेखला (शेल्टरबेल्ट) वृक्षारोपण किया गया था। इस विशिष्ट वनीकरण के लिए प्राथमिक तकनीकी आवश्यकता क्या थी?
(A) स्थानांतरित बालुका स्तूपों को नहर को अवरुद्ध करने और गाद भरने से रोकना
(B) स्थानीयकृत नहर लॉक्स के निर्माण के लिए संरचनात्मक काष्ठ प्रदान करना
(C) तीव्र सौर विकिरण के कारण होने वाले नहर के पानी के नुकसान को रोकना
(D) मौसमी पशु प्रवास के लिए क्षेत्रीय वन्यजीव गलियारे स्थापित करना

20. जलागम विकास परियोजनाओं के संस्थागत ढांचे के तहत, सूक्ष्म-जलागम (गांव) स्तर पर कार्यों के निष्पादन के लिए प्राथमिक रूप से कौन-सा निकाय उत्तरदायी है?
(A) राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी का कार्यकारी बोर्ड
(B) जिला जलागम प्रकोष्ठ-सह-डेटा केंद्र
(C) ग्राम पंचायत स्तर पर जलागम समिति
(D) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का निदेशालय

21. गाँव के स्तर पर सूक्ष्म-जलागम परियोजना के लिए अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी देने का वैधानिक अधिकार किस संस्था के पास है?
(A) ग्राम सभा
(B) राज्य विधानसभा
(C) जिला कलेक्टर
(D) परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी

22. बंजर भूमि विकास के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का अभिसरण मुख्य रूप से किस दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है?
(A) औपचारिक ग्रामीण बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार करते हुए प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी को समाप्त करना
(B) गाँवों को पुनः प्राकृतिक रूप में बदलते हुए संवेदनशील ग्रामीण आबादी को शहरी औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करना
(C) राज्य सरकार के कर राजस्व को बढ़ाते हुए साझा संपत्ति भूमि संसाधनों का निजीकरण करना
(D) टिकाऊ प्राकृतिक संसाधन परिसंपत्तियों का निर्माण करते हुए मजदूरी रोजगार उत्पन्न करना

23. सूखे के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. मौसम संबंधी सूखे को केवल दीर्घकालिक औसत की तुलना में वर्षा की लंबी कमी द्वारा परिभाषित किया जाता है।
II. जलवैज्ञानिक सूखा तब होता है जब फसल उत्पादन का समर्थन करने के लिए मृदा की नमी अपर्याप्त होती है।
III. कृषि सूखे की विशेषता झीलों और जलभृतों जैसे सतही और उप-सतही जल संसाधनों का ह्रास होना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से गलत हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

24. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, किसी दिए गए क्षेत्र में वर्षा की कमी इसके दीर्घकालिक औसत के कितने प्रतिशत से अधिक होने पर "भीषण" मौसम संबंधी सूखा घोषित किया जाता है?
(A) 10%
(B) 25%
(C) 50%
(D) 75%

NODIA

25. निम्नलिखित में से कौन-सा किसी संवेदनशील क्षेत्र को सूखा-रोधी बनाने के लिए अभियांत्रिकी उपाय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है?
(A) सूखा-सहनशील बीजों की किस्मों को पेश करना
(B) फसल बीमा योजना लागू करना
(C) ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली का पुनर्गठन करना
(D) रिसाव तालाबों (परकोलेशन टैंक) और एनीकटों का निर्माण करना

26. 1899-1900 ईस्वी में राजस्थान में पड़ा कौन-सा ऐतिहासिक अकाल, मानव और पशुधन आबादी पर इसके विनाशकारी प्रभाव के लिए व्यापक रूप से प्रलेखित है, जो संगठित सूखा राहत की आवश्यकता पर बल देता है?
(A) छप्पनिया अकाल

चरागाह विकास और जल संचयन तकनीकों पर उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। इसके द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों ने पश्चिमी राजस्थान की बंजर भूमि के सुधार और कृषि-वानिकी को बढ़ावा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक योगदान दिया है।

11. (B) पशुधन की संकटग्रस्त बिक्री और भुखमरी से होने वाली मृत्यु को रोकना
राजस्थान में भीषण सूखे के दौरान चारे की गंभीर कमी हो जाती है, जिससे पशुधन के लिए भुखमरी का संकट उत्पन्न होता है। सरकार द्वारा स्थापित चारा शिविर पशुपालकों को रियायती या मुफ्त दरों पर सूखा चारा उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पशुओं की भुखमरी से होने वाली मौतों को रोकना और किसानों को मजबूरी में अपने मवेशियों को औने-पौने दामों में बेचने से बचाना है।

12. (B) केवल I, II और IV
इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई से जलभराव और द्वितीयक लवणता पैदा हुई है। क्षारीय मृदा के सुधार के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में तीव्र वाष्पीकरण से लवण केशिकत्व क्रिया द्वारा सतह पर आते हैं। लवणता कम करने के लिए जल-गहन फसलों के बजाय कम जल खपत वाली और लवण-सहनशील फसलों की खेती की सिफारिश की जाती है, ताकि मृदा स्वास्थ्य बना रहे।

13. (A) अलवर
तरुण भारत संघ ने राजस्थान के अलवर जिले से पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं जैसे जोहड़ के पुनर्निर्माण का सफल अभियान शुरू किया था। समुदाय-आधारित इस प्रयास ने सुखी नदियों को पुनर्जीवित किया, भूजल स्तर में सुधार किया और बंजर होती भूमि को पुनः हरा-भरा बनाया। इस जन-भागीदारी मॉडल को जल संरक्षण और पारिस्थितिक बहाली के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सराहना तथा मान्यता प्राप्त हुई है।

14. (C) स्थानीय सामुदायिक स्वामित्व की कमी के कारण निर्मित परिसंपत्तियों का खराब रख-रखाव
जलागम विकास परियोजनाओं के समाप्त होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती निर्मित जल और मृदा संरक्षण संरचनाओं का सतत रख-रखाव है। यदि स्थानीय ग्रामीण समुदाय में स्वामित्व की भावना विकसित नहीं होती है, तो चेक डैम, तालाब और खाइयों जैसी परिसंपत्तियां समय के साथ जर्जर और बेकार हो जाती हैं। अतः दीर्घकालिक सफलता के लिए सामुदायिक समितियों और उपयोगकर्ता समूहों का सक्रिय जुड़ाव अत्यंत आवश्यक होता है।

15. (A) सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम → मरुस्थल विकास कार्यक्रम → एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम
भारत में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1973-74 में हुई थी। इसके पश्चात मरुस्थल विकास कार्यक्रम को वर्ष 1977-78 में प्रारंभ किया गया। बाद में, वर्ष 2009-10 में पूर्ववर्ती विभिन्न क्षेत्र विकास योजनाओं का विलय करके एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह सही कालानुक्रमिक क्रम भारत में बंजर भूमि विकास और जल संरक्षण नीतियों के क्रमिक विकास तथा एकीकरण को दर्शाता है।

16. (C) मृदा-सतह पर वायु के वेग को कम करना और नए पौधों की रक्षा करना
पश्चिमी राजस्थान के गतिशील बालुका स्तूपों पर स्थानीय झाड़ियों की शाखाओं का उपयोग करके चेकरबोर्ड पैटर्न में सूक्ष्म पवन-रोधक बनाए जाते हैं। ये बाड़ या रुकावटें मृदा की सतह पर पवन के वेग को कम करती हैं और उड़ती हुई रेत को रोकती हैं। इससे रोपे गए नए पौधों को उखड़ने और रेत में दबने से सुरक्षा मिलती है, जिससे वनस्पति का विकास और स्तूप का स्थिरीकरण संभव होता है।

17. (B) प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा (विलायती बबूल)
राजस्थान के शुष्क और बंजर क्षेत्रों में बालुका स्तूपों के स्थिरीकरण तथा पवन-रोधक मेखला के निर्माण के लिए प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा का व्यापक उपयोग किया गया है। यह प्रजाति अत्यधिक कम पानी, उच्च तापमान और कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों में तेजी से बढ़ने में सक्षम है। इसकी गहरी जड़ें और सघन फैलाव उड़ती हुई रेत को बांधने तथा वायु अपरदन की दर को नियंत्रित करने में अत्यधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं।

18. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के तहत स्व-स्थाने मृदा नमी संरक्षण पर विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम और अनिश्चित होती है। इन क्षेत्रों में आवधिक शुष्क दौरों के कारण फसलों को जल तनाव का सामना करना पड़ता है। खेत में ही नमी को बनाए रखने से फसलों को लंबे शुष्क अंतराल के दौरान जीवनदायिनी नमी मिलती है, जिससे कृषि उत्पादन में स्थिरता बनी रहती है।

19. (A) स्थानांतरित बालुका स्तूपों को नहर को अवरुद्ध करने और गाद भरने से रोकना
इंदिरा गांधी नहर के किनारों पर व्यापक रक्षक मेखला वृक्षारोपण की प्राथमिक आवश्यकता तीव्र हवाओं द्वारा उड़कर आने वाली रेत को रोकना थी। शुष्क क्षेत्रों में स्थानांतरित होते बालुका स्तूप नहर की धारा में गिरकर उसे अवरुद्ध कर देते हैं और गाद से भर देते हैं। नहर के समानांतर सघन वृक्षारोपण करने से पवन वेग घटता है और रेत का नहर में प्रवेश रुक जाता है।

20. (C) ग्राम पंचायत स्तर पर जलागम समिति
जलागम विकास परियोजनाओं के संस्थागत ढांचे में सूक्ष्म-जलागम यानी गाँव स्तर पर कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी जलागम समिति की होती है। इस समिति का गठन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों, महिलाओं और वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व शामिल होता है। यह समिति

Click Here to Buy book on Flipkart

1. अवनालिका अपरदन
2. बौछार अपरदन
3. परत अपरदन
4. रिल अपरदन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम का चयन कीजिए:
(A) 2 → 3 → 4 → 1
(B) 3 → 2 → 1 → 4
(C) 2 → 4 → 3 → 1
(D) 4 → 3 → 2 → 1

36. किस पारंपरिक जल संचयन प्रणाली में जल संग्रहण क्षेत्र के निचले ढलानों पर मिट्टी के बांधों का निर्माण शामिल है, जिसका उपयोग जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा कृषि का समर्थन करने के लिए प्रमुखता से किया जाता था?
(A) बावड़ी
(B) टोबा
(C) खदीन
(D) झालरा

37. राजस्थान का कौन-सा राज्य वृक्ष वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके, सूखे के दौरान चारा प्रदान करके और बालुका स्तूपों को स्थिर करके शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाता है?
(A) प्रोसोपिस सिनेरेरिया (खेजड़ी)
(B) टिकोमेला अंडुलाटा (रोहिड़ा)
(C) अकेसिया सेनेगल (कुमट)
(D) जिजिफस मौरितियाना (बेर)

38. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): भूजल का ह्रास राजस्थान के अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में कृषि सूखे को अत्यधिक गंभीर बनाता है।
कारण (R): अर्द्ध-शुष्क राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकांश भाग नलकूपों और कुओं की सिंचाई पर अत्यधिक निर्भर है।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

39. मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) यह मूल रूप से राष्ट्रीय कृषि आयोग की प्रमुख सिफारिशों के आधार पर शुरू किया गया था।
(B) यह केवल पश्चिमी राजस्थान तक सीमित है और शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों को बाहर रखता है।
(C) वनीकरण, सामाजिक वानिकी और चरागाह विकास इसकी केंद्रीय कार्यान्वयन गतिविधियाँ हैं।
(D) इस कार्यक्रम के तहत जलागम के आधार पर मृदा और नमी संरक्षण कार्यों को व्यवस्थित रूप से निष्पादित किया जाता है।

40. सरकारी सूखा राहत योजनाओं के संदर्भ में, "अनुग्रह सहायता" शब्द का तात्पर्य है:
(A) ग्रामीण मनरेगा परियोजना स्थलों पर काम करने वाले सक्षम व्यक्तियों को प्रदान किया जाने वाला दैनिक मजदूरी भुगतान
(B) श्रमिकों की व्यापक छंटनी को रोकने के लिए बड़े निजी उद्योगों को सीधे दी जाने वाली वित्तीय सब्सिडी
(C) सूखे के दौरान वृद्धों, अशक्तों और निराश्रित व्यक्तियों को दी जाने वाली निःशुल्क सहायता
(D) व्यापक कृषि फसल नुकसान के दावों को निपटाने के लिए बीमा कंपनियों को दिया जाने वाला मौद्रिक मुआवजा

41. रक्षक मेखला (शेल्टरबेल्ट) वृक्षारोपण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वे आम तौर पर हवा को तेज़ी से दिशा देने के लिए प्रचलित हवा की दिशा के समानांतर लगाए जाते हैं।
II. इनमें वायु वेग को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई पेड़ों और झाड़ियों की पंक्तियाँ शामिल होती हैं।
III. वे पवन-विमुख (लीवर्ड) कृषि क्षेत्रों में मृदा की नमी के वाष्पीकरण को कम करने में मदद करते हैं।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

42. किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के साथ वनीकरण और रक्षक मेखला वृक्षारोपण परियोजना के लिए महत्वपूर्ण बाह्य सहायता प्रदान की?
(A) ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड / जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन
(B) विश्व बैंक
(C) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
(D) एशियाई विकास बैंक

43. निम्नलिखित में से कौन-सा एक सफल जलागम प्रबंधन कार्यक्रम का लक्षित परिणाम नहीं है?
(A) स्थानीय भूजल स्तर में उल्लेखनीय दीर्घकालिक वृद्धि
(B) जल-गहन फसलों की एकल-फसल प्रणाली की ओर स्थायी स्थानांतरण
(C) सतही अपवाह और ऊपरी मृदा के अपरदन की दर में भारी कमी
(D) फसल सघनता और समग्र कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि

Downloaded from www.pdf.tube

(B) सहसा-मदसा अकाल
(C) पंच-काल
(D) त्रिशूल अकाल

27. राजस्थान में बंजर भूमि सुधार के लिए 'वन-चारागाह' प्रणालियों के विकास की अत्यधिक सिफारिश की जाती है। 'वन-चारागाह' पद्धति किन तत्वों को एकीकृत करती है?
(A) हाइड्रोपोनिक सब्जी खेती के साथ संयुक्त व्यावसायिक मत्स्य पालन
(B) वृक्ष, चारा फसलें और पशुधन प्रबंधन
(C) मधुमक्खी पालन के साथ संयुक्त सघन फल बागान वृक्षारोपण
(D) व्यावसायिक पुष्प कृषि के लिए पुनर्चक्रित शहरी अपशिष्ट जल उपचार

28. सूची I की मदों को सूची II की मदों से सुमेलित कीजिए।
सूची I: योजनाएं
P. एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)
Q. महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा)
R. राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) तंत्र
S. राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (वनीकरण)
सूची II: केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
2. गृह मंत्रालय
3. ग्रामीण विकास मंत्रालय
4. जल शक्ति मंत्रालय
(A) P-3, Q-3, R-2, S-1
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-2, R-3, S-1

29. लसियुरस सिंडिकस राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में चारे की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण एक अत्यधिक पौष्टिक और सूखा-रोधी घास है। इस घास को स्थानीय भाषा में सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है?
(A) सेवण
(B) खस
(C) मुंज
(D) धामण

30. गंभीर सूखे के दौरान, पश्चिमी राजस्थान के पशुपालक जल और चारे की तलाश में अपने मवेशियों के झुंड के साथ पड़ोसी राज्यों में प्रवास करते हैं। इस मौसमी प्रवास पैटर्न को भौगोलिक रूप से क्या कहा जाता है?
(A) स्थानांतरी कृषि
(B) फसल चक्र
(C) ऋतु प्रवास
(D) मिश्रित खेती

31. बंजर भूमि विकास में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. गैर-सरकारी संगठन अक्सर जलागम कार्यक्रमों में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं।
II. गैर-सरकारी संगठन क्षमता निर्माण और स्वयं सहायता समूहों को संगठित करने में सहायता करते हैं।
III. गैर-सरकारी संगठनों के पास जलागम लेआउट के संबंध में ग्राम सभा के प्रस्तावों को एकतरफा निरस्त करने का अधिकार है।
IV. गैर-सरकारी संगठन पारदर्शिता और सामुदायिक लामबंदी सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

32. राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संस्थागत पदानुक्रम में, जिला स्तर पर जलागम परियोजनाओं की देखरेख और प्रबंधन के लिए कौन-सी एजेंसी उत्तरदायी है?
(A) राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी निदेशालय
(B) जिला कृषि विज्ञान केंद्र
(C) जलागम प्रकोष्ठ-सह-डेटा केंद्र
(D) राज्य राजस्व प्रशासन बोर्ड

33. मनरेगा कार्यों में सामग्री घटक (सामग्री हिस्सा, जो अक्सर सूखा-रोधी कार्यों के लिए अभिसरित होता है) के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तपोषण पैटर्न सामान्यतः किस अनुपात में बनाए रखा जाता है?
(A) 50 : 50
(B) 60 : 40
(C) 75 : 25
(D) 100 : 0

NODIA

34. भूमि उपयोग आंकड़ों में 'बंजर एवं अनुपयोगी भूमि' और 'कृषि योग्य व्यर्थ भूमि' के बीच मूलभूत अंतर क्या है?
(A) बंजर भूमि पूरी तरह से निजी स्वामित्व में होती है, जबकि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि पर केवल ग्राम पंचायतों का स्वामित्व होता है।
(B) बंजर भूमि में एक वर्ष के लिए बिना जोती गई परती भूमि शामिल होती है, जबकि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में ऊंची पर्वत चोटियाँ शामिल होती हैं।
(C) कोई मूलभूत कानूनी या सांख्यिकी अंतर नहीं है; दोनों शब्दों का उपयोग सभी राज्य राजस्व अभिलेखों में एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है।
(D) कृषि योग्य व्यर्थ भूमि को खेती के लिए पुनः उपजाऊ बनाया जा सकता है, जबकि बंजर भूमि पर आर्थिक रूप से खेती नहीं की जा सकती है।

35. जल अपरदन के निम्नलिखित चरणों को, जो बंजर भूमि के निर्माण में भारी योगदान देते हैं, उनके घटित होने के सही क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:

52. जलागम प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प 'जल ग्रहण क्षेत्र' को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है?
(A) मनोनीत केंद्रीय थोक बाजार जहां क्षेत्रीय कृषि उपज का व्यापार किया जाता है
(B) एक सघन कंक्रीट वाला शहरी क्षेत्र जो भूमिगत जल पुनर्भरण को पूरी तरह से रोकता है
(C) वह संपूर्ण क्षेत्र जिसका जल बहकर एक साझा निकास बिंदु में जाता है
(D) सीधे ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली साझा भूमि का विशिष्ट सीमांकित टुकड़ा

53. सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) और मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) के कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से कौन-सा केंद्रीय मंत्रालय उत्तरदायी है?
(A) ग्रामीण विकास मंत्रालय
(B) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(C) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(D) जल शक्ति मंत्रालय

54. राजस्थान में मृदा अपरदन के सामान्य कारणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. अतिचारण वनस्पतियों के आवरण को हटा देता है, जिससे मृदा वायु और जल के संपर्क में आ जाती है।
II. अरावली पहाड़ियों में वनोन्मूलन से सतही अपवाह की दर बढ़ जाती है।
III. समुच्च रेखा जुताई को अपनाने से परत अपरदन तेज़ होता है।
IV. अवैज्ञानिक खनन गतिविधियाँ ऊपरी मृदा के क्षरण में योगदान देती हैं।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

55. जलागम विकास परियोजना के दौरान गठित "उपयोगकर्ता समूहों" का प्राथमिक कार्य क्या है?
(A) स्थानीय ग्राम पंचायत के वित्तीय खातों का औपचारिक रूप से लेखापरीक्षण और निरीक्षण करना
(B) परियोजना पूरी होने के बाद निर्मित परिसंपत्तियों का संचालन और रख-रखाव करना
(C) केंद्र सरकार से वार्षिक वित्तीय अनुदान सीधे मंजूर करना और जारी करना
(D) काटी गई फसल उपज की अंतिम थोक बाजार कीमतों को विनियमित और निर्धारित करना

56. राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) सूखा सहित अधिसूचित आपदाओं की अनुक्रिया के लिए राज्य सरकारों के पास उपलब्ध प्राथमिक निधि है। राजस्थान जैसे सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए एसडीआरएफ में मानक केंद्र सरकार का योगदान क्या है?
(A) 25%
(B) 50%
(C) 75%
(D) 100%

57. राजस्थान में बालुका स्तूपों के वानस्पतिक स्थिरीकरण के संबंध में बेमेल की पहचान कीजिए।
(A) अकेसिया टॉर्टिलिस (इजराइली बबूल)
(B) प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा (विलायती बबूल)
(C) लसियुरस सिंडिकस (सेवण घास)
(D) जलकुंभी

58. सूखा राहत के संदर्भ में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) जल संरक्षण और जल संचयन कार्यों को कम प्राथमिकता वाले कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
(B) यह प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है, जिसे गंभीर सूखे के दौरान बढ़ाया जा सकता है।
(C) यह योजना कृषि विफलताओं के दौरान ग्रामीण परिवारों के लिए एक स्वचालित सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करती है।
(D) अधिकांश कार्यों के लिए ग्राम पंचायतें मुख्य कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

59. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) ने डीपीएपी, डीडीपी और आईडब्ल्यूडीपी जैसी पूर्ववर्ती पृथक क्षेत्र विकास योजनाओं को प्रतिस्थापित कर दिया।
कारण (R): संसाधनों के अतिव्यापन और क्षेत्र विकास प्रयासों के विखंडन को रोकने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक था।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

60. भारत में सूखा निगरानी, जो राजस्थान जैसे राज्यों को सूखा घोषणा और प्रबंधन में सहायता करती है, मुख्य रूप से उपग्रह डेटा का उपयोग करके किस संगठन/एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित की जाती है?
(A) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
(B) महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र

Click Here to Buy book on Amazon

(B) इसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के रूप में पुनर्वगीकृत किया जाता है।
(C) यह ग्राम पंचायत की निजी संपत्ति बन जाती है।
(D) इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

77. निम्नलिखित में से कौन-सा शुष्क भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में मरुस्थलीकरण का संकेतक नहीं है?
(A) पौष्टिक स्वदेशी चरागाह घासों का प्रसार
(B) क्षेत्रीय भूमिगत भूजल स्तर में निरंतर और तीव्र गिरावट
(C) स्थानीय रेत और धूल भरे तूफानों की समग्र आवृत्ति और तीव्रता में उल्लेखनीय वृद्धि
(D) ऊपरी मृदा में लवणता, सोडिकता और क्षारियता की सांद्रता में प्रगतिशील वृद्धि

78. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): राजस्थान के डीपीएपी क्षेत्रों में गन्ना जैसी अत्यधिक जल-गहन फसलों की खेती को काफी हतोत्साहित किया जाता है।
कारण (R): डीपीएपी क्षेत्र नाजुक भूजल भंडार वाले अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र हैं जो उच्च-सिंचाई कृषि को सहन नहीं कर सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

79. मनरेगा योजना के तहत सूखा-रोधी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित कार्यों को कैसे प्राथमिकता दी जाती है?
(A) उन्हें निष्पादित करने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि वे भारी मोटर चालित मशीनों के रोजगार को अनिवार्य बनाते हैं
(B) उन्हें केवल तभी स्वीकृति दी जाती है जब जिले में कोई सिविल सड़क निर्माण या बुनियादी ढांचे के कार्य उपलब्ध न हों
(C) वे ग्राम सभा या गाँव से परामर्श किए बिना केवल निजी व्यावसायिक ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं
(D) वे ग्राम पंचायत कार्य योजना का एक अनिवार्य, उच्च-प्राथमिकता वाला घटक बनते हैं।

80. इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने पश्चिमी राजस्थान में बंजर भूमि के बड़े हिस्से को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया। हालाँकि, इसने कुछ कमान क्षेत्रों में एक बड़ी द्वितीयक बंजर भूमि समस्या भी उत्पन्न कर दी। यह समस्या क्या है?
(A) आसन्न समुद्री सीमा क्षेत्रों में गंभीर तटीय तरंग अपरदन
(B) घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन छत्रों की अत्यधिक कटाई और वनोन्मूलन
(C) खराब जल निकासी के कारण जलभराव और द्वितीयक लवणीकरण
(D) सीधे नहर के अस्तर के कारण गहरे भूमिगत जलभृतों का अत्यधिक ह्रास

NODIA

www.nodia.in

(D) P-1, Q-2, R-4, S-3

69. वर्तमान सूखा प्रबंधन नियमावली दिशा-निर्देशों के तहत राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा सूखा घोषित करने का आधार निम्नलिखित में से क्या है?
(A) वर्षा विचलन, फसल क्षेत्र, वनस्पति सूचकांक और मृदा नमी का एक संयुक्त सूचकांक
(B) मान्यता प्राप्त स्थानीय समाचार पत्र पत्रकारों द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत अनौपचारिक और विशुद्ध रूप से व्यक्तिपरक क्षेत्रीय आकलन
(C) प्रमुख व्यावसायिक नकदी फसलों की थोक कृषि बाजार कीमतों में देखे गए अल्पकालिक उतार-चढ़ाव
(D) पिछले वर्षों की तुलना में तिमाही राज्य वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में दर्ज की गई कुल प्रतिशत कमी

70. अर्द्ध-शुष्क बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों में कृषि-उद्यानिकी (जैसे फसलों के साथ बेर या आंवला लगाना) के संवर्धन को प्रोत्साहन क्यों दिया जाता है?
(A) यह सघन बाढ़ सिंचाई तकनीकों को आवश्यक बनाता है, जिससे स्थानीय किसान स्थायी नहर नेटवर्क बनाने के लिए मजबूर होते हैं।
(B) ये फलदार वृक्ष सभी कृषि कीटों के प्रति पूर्ण जैविक प्रतिरक्षा प्रदर्शित करते हैं और शून्य मौसमी रख-रखाव की मांग करते हैं।
(C) यह एक अभेद्य दीवार बनाता है जो हवा की धाराओं को प्रशासनिक गाँव की सीमाओं में प्रवेश करने से पूरी तरह रोकती है।
(D) यह पूरक आय प्रदान करता है और सूखे के दौरान पूरी फसल नष्ट होने के जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है।

71. जलागम सीमाओं के संदर्भ में, "कटक रेखा" शब्द का क्या अर्थ है?
(A) नदी घाटी में सबसे निचला स्थलाकृतिक बिंदु जहां सतही अपवाह लगातार जमा होता है
(B) सबसे उच्च ऊंचाइयों पर निकटवर्ती जल निकासी द्रोणियों को अलग करने वाली रेखा
(C) आने वाले मौसमी बाढ़ के पानी को मोड़ने के लिए खोदी गई एक गहरी कृत्रिम अपवर्तन खाई
(D) निजी कृषि योग्य भूमि को संरक्षित वन क्षेत्रों से अलग करने वाली आधिकारिक प्रशासनिक सीमा रेखा

72. बंजर भूमि सुधार परियोजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आवश्यक निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए:
I. परियोजना के बाद के रख-रखाव के लिए सुरक्षित वित्तपोषण और कोष।
II. सक्रिय स्थानीय नेतृत्व और कार्यात्मक जलागम समितियां।
III. सभी विकसित साझा भूमियों का बड़े निगमों को तत्काल निजीकरण।
IV. मौजूदा ग्रामीण आजीविका योजनाओं के साथ अभिसरण।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

73. राजस्थान में बार-बार आने वाले सूखे के प्रभावों को कम करने के लिए सबसे प्रभावी दीर्घकालिक रणनीति किसे माना जाता है?
(A) ग्रीष्मकाल के दौरान शुष्क क्षेत्रों में आपातकालीन रेलवे जल टैंकर भेजने पर पूरी तरह निर्भर रहना
(B) दीर्घकालिक प्राकृतिक संसाधन नियोजन की उपेक्षा करते हुए अनिश्चित काल के लिए मुफ्त आपातकालीन खाद्यान्न राशन वितरित करना
(C) सभी निजी पशुधन पालन और पशुपालन संचालन पर राज्यव्यापी विधायी प्रतिबंध लगाना
(D) जलागम प्रबंधन, वनीकरण और जल-कुशल खेती को बढ़ावा देना

74. अल्पकालिक सूखा राहत और दीर्घकालिक सूखा-रोधी उपायों के बीच अंतर के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) नकद सहायता देना दीर्घकालिक सूखा-रोधी तंत्र का एक क्लासिक उदाहरण है।
(B) अल्पकालिक राहत में चारा डिपो और पानी के टैंकर चलाने जैसे तत्काल उपाय शामिल हैं।
(C) दीर्घकालिक सूखा-रोधी उपाय भविष्य में वर्षा की कमी के खिलाफ पारिस्थितिक लचीलापन का निर्माण करते हैं।
(D) वनीकरण और वर्षा जल संचयन दीर्घकालिक सूखा-रोधी उपायों के मुख्य घटक हैं।

75. सूक्ष्म-जलागम परियोजना के निष्पादन में शामिल निम्नलिखित प्रशासनिक चरणों को उनके तार्किक क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी
2. अंतिम मूल्यांकन और परियोजना की समाप्ति/वापसी
3. सामुदायिक विश्वास बनाने के लिए प्रवेश बिंदु गतिविधियां
4. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों का निष्पादन
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम का चयन कीजिए:
(A) $3 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2$
(B) $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2$
(C) $3 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 2$
(D) $1 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2$

76. 'शुद्ध बोया गया क्षेत्र' की अवधारणा 'बंजर भूमि' से अलग है। 'वर्तमान परती भूमि' के रूप में वर्गीकृत भूमि का क्या होता है यदि इसे लगातार पांच वर्ष से अधिक समय तक बिना जोते छोड़ दिया जाता है?
(A) यह स्वचालित रूप से वन भूमि में परिवर्तित हो जाती है।

Downloaded from www.pdf.tube

(C) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(D) भारतीय सर्वेक्षण विभाग

61. बंजर भूमि विकास परियोजनाओं की सफलता के लिए स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी को अनिवार्य क्यों माना जाता है?
(A) क्योंकि स्थानीय ज्ञान नियोजन को अनुकूलित करता है और परिसंपत्ति रख-रखाव सुनिश्चित करता है
(B) क्योंकि केंद्रीय प्रशासनिक विभागों में सूक्ष्म संरचनाओं को डिज़ाइन करने के लिए आवश्यक सिविल इंजीनियरों की कमी है
(C) क्योंकि स्थानीय समुदाय के सदस्यों को कुल परियोजना लागत का 100% वित्तपोषित करना कानूनी रूप से आवश्यक है
(D) क्योंकि गैर-सरकारी संगठनों को ग्रामीण जिलों में काम करने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है

62. निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग विशेष रूप से सतही और भूजल की उपलब्धता में लंबे समय तक व्यापक कमी का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो अक्सर लगातार मौसम संबंधी सूखे के परिणामस्वरूप होता है?
(A) सामाजिक-आर्थिक सूखा
(B) कृषि सूखा
(C) जलवैज्ञानिक सूखा
(D) पारिस्थितिक सूखा

63. "सामाजिक वानिकी" का उद्देश्य लकड़ी, ईंधन की लकड़ी और चारे की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आम आदमी द्वारा वृक्षारोपण करना है। सामाजिक वानिकी का कौन-सा विशिष्ट घटक अकृषित पंचायत भूमि और गाँव की आम भूमि पर पेड़ लगाने पर केंद्रित है?
(A) कृषि वानिकी
(B) विस्तार वानिकी
(C) व्यावसायिक वानिकी
(D) सामुदायिक वानिकी

64. जोधपुर में स्थित शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (अफरी) की स्थापना के सही उद्देश्य की पहचान कीजिए।
(A) गहरे समुद्र में समुद्री मत्स्य पालन उत्पादन प्रणालियों पर उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान करना
(B) प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों में शहरी परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की निगरानी, विनियमन और उन्हें लागू करना
(C) शुष्क क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ाने के लिए वानिकी अनुसंधान आयोजित करना
(D) नीतियाँ तैयार करना और प्रमुख बंदरगाहों से अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक लकड़ी निर्यात को सख्ती से विनियमित करना

65. राजस्थान में चारा सुरक्षा के लिए घास के मैदान (चरागाह) विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. चक्रीय चराई से घासों के प्राकृतिक पुनरुद्भव में मदद मिलती है।
II. अप्रतिबंधित, निरंतर चराई से सामुदायिक चरागाहों पर दीर्घकालिक चारा उपज अधिकतम होती है।
III. क्षरित चरागाहों में उच्च उपज वाली बारहमासी घास की प्रजातियों के बीज बोने से वहन क्षमता में सुधार होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

66. सरकारी सूखा राहत कार्यों के संदर्भ में, "पशु शिविर" क्या होता है?
(A) व्यावसायिक मांस उत्पादन के लिए मवेशियों को संसाधित करने हेतु शुष्क जिलों में स्थापित एक स्थायी सरकार द्वारा संचालित सुविधा
(B) एक संगठित व्यावसायिक पशुधन मेला जिसका उद्देश्य विशेष रूप से अमीर भूस्वामियों द्वारा उच्च उपज वाली विदेशी डेयरी मवेशी नस्लों को खरीदना है
(C) जंगली मरुस्थलीय मवेशियों की आबादी की रक्षा के लिए राज्य पर्यावरण अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से स्थापित एक संरक्षित वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र
(D) सूखे के दौरान पशुधनों को आपातकालीन आश्रय, चारा और देखभाल प्रदान करने वाली सुविधा

NODIA

67. "भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस" जो बंजर भूमि के विस्तार का मानचित्रण करता है, किस प्रमुख संस्थान द्वारा तैयार किया जाता है?
(A) अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (एसएसी), इसरो
(B) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी मंत्रालय
(C) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय
(D) नीति आयोग

68. सूची I की मदों को सूची II की मदों से सुमेलित कीजिए।
सूची I: पारंपरिक जल संरचनाएं
P. टांका
Q. नाडी
R. जोहड़
S. खदीन
सूची II: कार्यात्मक विशेषताएं
1. मिट्टी का चेक डैम जो मुख्य रूप से अलवर क्षेत्र में भूजल पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है
2. घरों में पीने के लिए वर्षा जल एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमिगत टंकी
3. सामुदायिक उपयोग के लिए सतही अपवाह एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाने वाला गाँव का तालाब
4. जैसलमेर में निचले ढलानों में अपनाई जाने वाली अपवाह खेती प्रणाली
(A) P-2, Q-3, R-1, S-4
(B) P-3, Q-2, R-1, S-4
(C) P-2, Q-1, R-3, S-4

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) वह भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध है, किंतु चालू वर्ष तथा पिछले लगातार पाँच वर्षों या उससे अधिक समय से उस पर कृषि नहीं की गई है
राजस्थान के भू-राजस्व अभिलेखों में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि उस भूमि को माना जाता है जो कृषि उत्पादन के लिए पूरी तरह उपयुक्त है, परंतु चालू वर्ष तथा पिछले लगातार पाँच या उससे अधिक वर्षों से अकृषित पड़ी है। ऐसी भूमि को उपयुक्त जल संचयन, मृदा सुधार और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रयोग से पुनः उपजाऊ बनाकर कृषि गतिविधियों के लिए सफलतापूर्वक उपयोग में लाया जा सकता है।

2. (D) वायु अपरदन और स्थानांतरित बालुका स्तूप
राजस्थान के पश्चिमी शुष्क जिलों में तीव्र गति से चलने वाली हवाएं ऊपरी मृदा के बारीक कणों को उड़ा ले जाती हैं, जिससे व्यापक वायु अपरदन होता है। इसके साथ ही स्थानांतरित होते बालुका स्तूप उपजाऊ कृषि भूमि और वनस्पति को ढक लेते हैं। वर्षा की अत्यधिक कमी और तेज वाष्पीकरण के कारण यह प्रक्रिया और तीव्र हो जाती है, जो बंजर भूमि निर्माण का प्रमुख कारण बनती है।

3. (B) 1977-78
मरुस्थल विकास कार्यक्रम वर्ष 1977-78 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोकना, पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना और शुष्क क्षेत्रों में जल, मृदा तथा वनस्पति संसाधनों का सतत विकास करना था। यह कार्यक्रम विशेष रूप से गंभीर शुष्क पारिस्थितिकी तंत्रों में कृषि उत्पादन और आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया था।

4. (B) 16 जिले
राजस्थान में मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 16 जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने, भूमि क्षरण को कम करने और स्थानीय पारिस्थितिकी को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न जल संचयन तथा वनीकरण कार्य किए जाते हैं। यह कार्यक्रम शुष्क एवं अति-शुष्क क्षेत्रों में सूखे के प्रभाव को कम करने और कृषि तथा पशुपालन को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक है।

5. (A) P-2, Q-4, R-1, S-3
राजस्थान के चंबल नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोटा और सवाई माधोपुर जिले तीव्र अवनालिका अपरदन से प्रभावित हैं। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के कारण जलभराव और लवणता की समस्या उत्पन्न हुई है। जैसलमेर और बीकानेर में स्थानांतरित बालुका स्तूप प्रमुख समस्या हैं, जबकि उदयपुर और राजसमंद में अरावली पहाड़ियों का ढलान वनोन्मूलन तथा जल द्वारा मिट्टी के क्षरण का सामना करता है।

6. (D) अर्द्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्र
राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम मुख्य रूप से अर्द्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र जलवायु क्षेत्रों को लक्षित करता है। इन क्षेत्रों में वर्षा की अनिश्चितता, अपर्याप्त जल संसाधन और बार-बार सूखे की स्थिति बनी रहती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जल संसाधनों के संरक्षण, मृदा नमी के रखरखाव, वनीकरण और कृषि-उत्पादकता में सुधार लाकर भूमि की प्राकृतिक क्षमता तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुदृढ़ किया जाता है।

7. (B) केवल I और III
एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम को सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को मिलाकर शुरु किया गया था। यह कार्यक्रम जल और मृदा संरक्षण हेतु कटक से घाटी दृष्टिकोण अपनाता है, जिससे ऊपरी क्षेत्रों से बहने वाले जल को रोककर निचले क्षेत्रों को संरक्षित किया जा सके। इस कार्यक्रम में वित्तपोषण का पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच 90:10 का अनुपात रहता है।

8. (C) यह निचले क्षेत्रों में निर्मित मृदा संरक्षण संरचनाओं को बहने से रोकता है।
जलागम विकास में कटक से घाटी दृष्टिकोण अपनाने का प्राथमिक उद्देश्य ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में जल के वेग को कम करना और मृदा अपरदन को रोकना है। यदि कटक क्षेत्र पर जल प्रबंधन नहीं किया जाता है, तो तीव्र गति से बहता अपवाह निचले इलाकों में बनाई गई जल और मृदा संरक्षण संरचनाओं को क्षतिग्रस्त कर सकता है। अतः ऊपरी भाग में उपचार करने से पूरी प्रणाली सुरक्षित रहती है।

9. (D) व्यावसायिक खेती के लिए गहरे नलकूपों की खुदाई करना
जलागम विकास परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ प्रबंधन, भूजल पुनर्भरण और मृदा संरक्षण करना है। व्यावसायिक खेती के लिए गहरे नलकूपों की खुदाई करना अत्यधिक भूजल निष्कर्षण को बढ़ावा देता है, जिससे भूजल स्तर में भारी गिरावट आती है। इसलिए इस प्रकार की गतिविधियों को जलागम कार्यक्रमों के मुख्य घटकों में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि यह पारिस्थितिक संतुलन और जल संरक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

10. (A) जोधपुर
केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। यह संस्थान शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण को रोकने, बालुका स्तूपों को स्थिर करने,

Click Here to Buy book on Flipkart

44. वनस्पति आवरण स्थापित होने से पहले गतिशील बालुका स्तूपों के प्रसार को तुरंत रोकने के लिए पश्चिमी राजस्थान में उपयोग की जाने वाली सबसे आम यांत्रिक विधि कौन-सी है?
(A) गतिशील स्तूपों की चोटियों पर सीधे भारी कंक्रीट स्लैब डालना
(B) झाड़ियों की चेकरबोर्ड रुकावटों का निर्माण करना
(C) सांद्रित रासायनिक मृदा बाइंडरों और भारी उर्वरकों का छिड़काव करना
(D) स्तूप की रेत की खुदाई करना और इसे दूर सूखी नदी के घाटियों में ले जाना

45. एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के राज्य स्तर से लेकर गाँव स्तर तक के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत पदानुक्रम के सही क्रम का चयन कीजिए।
(A) राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी → जिला जलागम प्रकोष्ठ → परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी → जलागम समिति
(B) परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी → राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी → जलागम समिति → जिला जलागम प्रकोष्ठ
(C) जिला जलागम प्रकोष्ठ → राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी → परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी → जलागम समिति
(D) राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी → परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी → जिला जलागम प्रकोष्ठ → जलागम समिति

46. सूखा-रोधी उपाय के रूप में 'चारा बैंक' की अवधारणा का तात्पर्य है:
(A) केवल मवेशियों की खरीद के लिए रियायती सूक्ष्म-ऋण प्रदान करने वाला एक विशेष वित्तीय संस्थान
(B) ग्रामीण चरागाह भूमि के मानचित्रण और पंजीकरण के लिए समर्पित एक राज्य सरकार का प्रशासनिक विभाग
(C) सूखे की अवधि के लिए अच्छी वर्षा वाले वर्षों से अधिशेष चारे का भंडारण करना
(D) शुष्क मौसम के दौरान ताजा हरा चारा आयात करने के उद्देश्य से किया गया एक अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौता

47. निम्नलिखित में से कौन-सी स्थिति "कृषि सूखा" का निर्माण करती है?
(A) जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा ऐतिहासिक पचास-वर्षीय औसत वर्षा से मेल खाती है
(B) जब खेतों के स्वास्थ्य की परवाह किए बिना प्रमुख नगर पालिकाओं के जल निकाय बीस प्रतिशत क्षमता से नीचे आ जाते हैं
(C) जब कृषि कच्चे माल की कमी के कारण विनिर्माण उद्योगों का कुल आर्थिक उत्पादन घट जाता है
(D) जब मृदा की नमी इतनी कम हो जाती है कि फसल की पैदावार अत्यधिक घट जाती है या फसल नष्ट हो जाती है

48. सूची I की मदों को सूची II की मदों से सुमेलित कीजिए।
सूची I: सूखा शमन हस्तक्षेप
P. फसलों की बुवाई की तिथियों में बदलाव करना
Q. किसानों को इनपुट सब्सिडी प्रदान करना
R. चेक डैम का निर्माण
S. पूर्व चेतावनी मौसम स्टेशनों की स्थापना
सूची II: श्रेणियां
1. अभियांत्रिकी/संरचनात्मक उपाय
2. तकनीकी/सूचना उपाय
3. शस्य वैज्ञानिक उपाय
4. वित्तीय/नीतिगत उपाय
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-1, Q-4, R-3, S-2

49. राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में, बार-बार आने वाले सूखे के चक्रों के दौरान आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक किसान के लिए प्रथाओं का कौन-सा संयोजन सबसे उपयुक्त है?
(A) गन्ना और धान जैसी पानी की अधिक मांग वाली फसलों की सघन व्यावसायिक खेती करना
(B) सूखा-सहनशील फसलों, पशुधन और कृषि-वानिकी का संयोजन करना
(C) उच्च-जल वाली शीतकालीन गेहूं की खेती के लिए केवल निरंतर गहरे नलकूप निष्कर्षण पर निर्भर रहना
(D) खानाबदोश शिकार और संग्रहण गतिविधियों के लिए स्थायी खेती को पूरी तरह से छोड़ देना

50. जलागम विकास के दिशा-निर्देशों के तहत, गाँव के स्तर पर गठित 'जलागम समिति' में अनिवार्य रुप से निम्नलिखित में से किस समूह का प्रतिनिधित्व शामिल होना चाहिए?
(A) केवल पांच हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले बड़े कृषि भूमि स्वामी
(B) केवल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रमाणित सिविल और तकनीकी इंजीनियर
(C) क्षेत्र में काम कर रही निजी कॉर्पोरेट निवेश फर्मों के प्रतिनिधि
(D) महिलाएँ, भूमिहीन श्रमिक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य

51. राजसमंद जिले का "पिपलांत्री" गाँव मॉडल बंजर भूमि सुधार और सामाजिक-पारिस्थितिक विकास की एक सफल कहानी के रूप में प्रसिद्ध है। इस गाँव से जुड़ी अनूठी प्रथा क्या है?
(A) बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए बालिका के जन्म पर 111 वृक्ष लगाना
(B) घने प्राकृतिक वनों की स्थापना के लिए सभी कृषि गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना
(C) व्यावसायिक पवन टर्बाइन फार्मों का उपयोग करके गाँव की कुल बिजली का 100% उत्पादन करना
(D) मरुस्थल की भीषण गर्मी से बचने के लिए पूरी तरह से भूमिगत आवासीय भवनों का निर्माण करना

NODIA

स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार जल संरक्षण, मृदा उपचार और वनीकरण के जमीनी कार्यों का सीधे कार्यान्वयन और निगरानी करती है।

21. (A) ग्राम सभा
सूक्ष्म-जलागम विकास परियोजनाओं में विकेंद्रीकृत योजना और सामुदायिक सहभागिता को सर्वोपरि महत्व दिया जाता है। गाँव के लिए तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अंतिम अनुमोदन करने का वैधानिक अधिकार ग्राम सभा के पास होता है। ग्राम सभा यह सुनिश्चित करती है कि प्रस्तावित जल और मृदा संरक्षण कार्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल हैं तथा संसाधनों का न्यायसंगत आवंटन गांव के सभी वर्गों के हित में किया गया है।

22. (D) टिकाऊ प्राकृतिक संसाधन परिसंपत्तियों का निर्माण करते हुए मजदूरी रोजगार उत्पन्न करना
बंजर भूमि विकास और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का अभिसरण ग्रामीण क्षेत्रों में दोहरा लाभ प्रदान करता है। इससे एक ओर अकुशल ग्रामीण श्रमिकों को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर जल संचयन, एनिकट निर्माण, चरागाह विकास और वनीकरण जैसी टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया ग्रामीण पारिस्थितिकी में सुधार और आजीविका सुरक्षा दोनों को एक साथ सुनिश्चित करती है।

23. (B) केवल II और III
मौसम संबंधी सूखा केवल वर्षा में दीर्घकालिक औसत की तुलना में बड़ी कमी से संबंधित है। कृषि सूखा तब होता है जब मृदा की नमी फसल के पनपने के लिए अपर्याप्त हो जाती है। जलवैज्ञानिक सूखा नदियों, झीलों, जलाशयों और भूजल जैसे जल निकायों के जल स्तर में भारी गिरावट से परिभाषित होता है। अतः कृषि और जलवैज्ञानिक सूखे की परिभाषाओं को एक-दूसरे से बदलना पूरी तरह गलत है।

24. (C) 50%
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मानकों के अनुसार, जब किसी विशेष क्षेत्र में मौसमी वर्षा उसके दीर्घकालिक औसत की तुलना में 26 से 50 % तक कम होती है, तो उसे सामान्य सूखा माना जाता है। परंतु यदि वर्षा में यह कमी दीर्घकालिक औसत के 50 % से अधिक हो जाती है, तो उस क्षेत्र को "भीषण" मौसम संबंधी सूखा क्षेत्र घोषित किया जाता है, जिससे आपातकालीन राहत कार्य आवश्यक हो जाते हैं।

25. (D) रिसाव तालाबों (परकोलेशन टैंक) और एनीकटों का निर्माण करना
संवेदनशील क्षेत्रों को सूखा-रोधी बनाने के लिए अभियांत्रिकी या संरचनात्मक उपाय भौतिक जल संचयन अवसंरचना के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रिसाव तालाबों, एनिकटों और चेक डैम का निर्माण वर्षा जल के सतही अपवाह को रोकता है और भूजल रीचार्ज की दर को बढ़ाता है। इससे शुष्क मौसम के दौरान कुओं में जल स्तर बना रहता है और कृषि तथा पेयजल की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

26. (A) छप्पनिया अकाल
वर्ष 1899-1900 ईस्वी में पड़ा ऐतिहासिक अकाल विक्रम संवत 1956 में आने के कारण "छप्पनिया अकाल" के नाम से जाना जाता है। यह एक भयंकर त्रिकाल था, जिसमें अन्न, जल और चारे तीनों का पूर्ण अभाव हो गया था। इस अकाल ने भारी संख्या में जनहानि और पशुधन का विनाश किया, जिसके बाद संगठित तथा संस्थागत अकाल एवं सूखा राहत कार्यों की आवश्यकता पर अत्यधिक बल दिया गया।

27. (B) वृक्ष, चारा फसलें और पशुधन प्रबंधन
वन-चारागाह पद्धति एक एकीकृत भूमि उपयोग प्रणाली है जो बहुउद्देशीय वृक्षों, चारा फसलों और पशुधन प्रबंधन को एक साथ संयोजित करती है। इसमें क्षरित और बंजर भूमि पर छायादार तथा चारा देने वाले वृक्ष लगाए जाते हैं, जिनके बीच घास एवं चारा फसलें उगाई जाती हैं। यह प्रणाली मृदा संरक्षण में मदद करती है, पशुओं के लिए निरंतर चारा उपलब्ध कराती है और शुष्क पारिस्थितिकी को पुनर्स्थापित करती है।

28. (A) P-3, Q-3, R-2, S-1
एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना दोनों केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन संचालित होते हैं। राज्य आपदा मोचन निधि के दिशा-निर्देशों का प्रबंधन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन वनीकरण तथा पारिस्थितिक बहाली से संबंधित होने के कारण केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

29. (A) सेवण
लसियुरस सिंडिकस को स्थानीय भाषा में सामान्यतः "सेवण" घास के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान के अति-शुष्क क्षेत्रों, विशेषकर जैसलमेर जिले में पाई जाने वाली एक अत्यंत पौष्टिक और सूखा-रोधी बारहमासी घास है। यह कम वर्षा और उच्च तापमान में भी पनपती है तथा थार मरुस्थल के पशुधन के लिए चारे का प्रमुख स्रोत होने के साथ-साथ मृदा अपरदन को रोकने में अत्यधिक सहायक है।

30. (C) ऋतु प्रवास
पश्चिमी राजस्थान में गंभीर सूखे के समय जल और चारे की तीव्र कमी हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय पशुपालक अपने मवेशियों के साथ पड़ोसी राज्यों या जल-समृद्ध क्षेत्रों की ओर अस्थायी रूप से पलायन करते हैं। मौसम और परिस्थितियों के अनुसार होने वाले इस मौसमी जनसंख्या तथा पशुधन संचलन को भूगोल की भाषा में "ऋतु प्रवास" कहा जाता है, जो शुष्क क्षेत्रों में जीवन रक्षा की रणनीति है।

31. (B) केवल I, II और IV
गैर-सरकारी संगठन जलागम विकास कार्यक्रमों में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। वे ग्रामीणों में क्षमता निर्माण, स्वयं सहायता समूहों के गठन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, गैर-सरकारी संगठनों के पास ग्राम सभा के प्रस्तावों को निरस्त करने

NODIA

(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) I, II और III
(D) केवल I और III

12. निम्नलिखित में से कौन-सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रत्यक्ष कमान क्षेत्र या पेयजल लाभान्वित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है?
(A) चूरू
(B) प्रतापगढ़
(C) बाड़मेर
(D) झुंझुनू

13. निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना के राजस्थान फीडर नहर भाग का प्राथमिक कार्य है?
(A) राजस्थान क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले पंजाब और हरियाणा के बीच जल को समान रूप से वितरित करना।
(B) केवल गंगानगर कृषि जिले को प्रत्यक्ष सिंचाई लाभ प्रदान करना।
(C) इसके मार्ग में बिना सिंचाई किए न्यूनतम जल हानि के साथ मुख्य नहर तक जल पहुँचाना।
(D) पूर्वी अरावली की पहाड़ियों के साथ स्थित क्षेत्रीय भूमिगत जलभृत प्रणाली को पुनर्भरित करना।

14. इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एकमात्र कौन-सी शाखा इसके बाएँ तट से निकलती है?
(A) सूरतगढ़ शाखा
(B) पूगल शाखा
(C) दंतौर शाखा
(D) रावतसर शाखा

15. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कमान क्षेत्र में देखे गए निम्नलिखित पर्यावरणीय परिणामों पर विचार कीजिए:
I. निचले समतल भूभाग में गंभीर जलभराव।
II. केशिका क्रिया के कारण मृदा का द्वितीयक लवणीकरण।
III. देशी मरुस्थलीय जीवों के प्राकृतिक आवास का ह्रास।
IV. नमी-प्रेमी कृषि कीटों का उन्मूलन।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) I, II और III
(B) I, II और IV
(C) II, III और IV
(D) I, III और IV

16. इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में "सेम" की समस्या विशेष रूप से किस परिघटना से संबंधित है?
(A) रेतीले तूफानों द्वारा नहर की पक्की दीवारों का क्षतिग्रस्त होना
(B) गंभीर जलभराव के कारण पारिस्थितिक क्षरण
(C) किसानों के मध्य जल वितरण को लेकर विवाद
(D) आक्रामक मरुस्थलीय खरपतवारों का तीव्र प्रसार

17. निम्नलिखित में से कौन-सी भौगोलिक विशेषता इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत हनुमानगढ़ जैसे जिलों में जलभराव की समस्या को बढ़ा देती है?
(A) अरावली पर्वत श्रृंखला से निकटता
(B) उप-सतह में जिप्सम की कठोर परत (हार्डपैन) की उपस्थिति
(C) किसानों द्वारा निरंतर अत्यधिक मात्रा में भूजल का निष्कर्षण
(D) लूनी नदी बेसिन की ओर प्राकृतिक ढलान

18. सूची I में दी गई लिफ्ट नहरों के पूर्व नामों को सूची II में उनके वर्तमान नामों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: पूर्व नाम
P. बीकानेर-लूणकरणसर लिफ्ट नहर
Q. गजनेर लिफ्ट नहर
R. फलोदी लिफ्ट नहर
S. पोकरण लिफ्ट नहर
सूची II: वर्तमान नाम
1. पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर
2. कंवर सैन लिफ्ट नहर
3. जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर
4. गुरु जंभेश्वर लिफ्ट नहर
(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

19. अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति हेतु इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत कितनी मुख्य लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है?
(A) 5
(B) 7
(C) 9
(D) 11

20. इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन-सी है, जो मुख्य रूप से बीकानेर शहर की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करती है?
(A) डॉ. करणी सिंह लिफ्ट नहर
(B) चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट नहर
(C) वीर तेजाजी लिफ्ट नहर
(D) कंवर सैन लिफ्ट नहर

21. राजीव गांधी लिफ्ट नहर को राजस्थान के किस शहर में पेयजल संकट को दूर करने के लिए निर्मित किया गया था?
(A) जैसलमेर
(B) बाड़मेर
(C) जोधपुर
(D) नागौर

Downloaded from www.pdf.tube

42. (A) ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड / जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन
इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के साथ व्यापक वनीकरण, चरागाह विकास और बालुका स्तूप स्थिरीकरण के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (अब जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन) ने वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की। इस अंतरराष्ट्रीय सहयोग वाली परियोजना ने नहर प्रणाली के किनारे रक्षक मेखलाएँ बनाकर उड़ती रेत को रोका, नहर में गाद जमने से बचाई और आसपास के शुष्क पर्यावरण में भारी सुधार किया।

43. (B) जल-गहन फसलों की एकल-फसल प्रणाली की ओर स्थायी स्थानांतरण
जलागम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना और जल का टिकाऊ उपयोग करना है। जल-गहन फसलों की एकल-फसल प्रणाली की ओर बढ़ना भूजल का अत्यधिक दोहन करता है, जो जलागम के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। एक सफल जलागम कार्यक्रम भूजल स्तर बढ़ाता है, अपवाह एवं मृदा अपरदन को घटाता है, तथा विविध, कम जल खपत वाली फसल प्रणालियों को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादकता को बढ़ाता है।

44. (B) झाड़ियों की चेकरबोर्ड रुकावटों का निर्माण करना
पश्चिमी राजस्थान में वानस्पतिक आवरण स्थापित होने से पहले गतिशील बालुका स्तूपों के प्रसार को तुरंत रोकने के लिए यांत्रिक विधि के रूप में स्थानीय झाड़ियों की टहनियों से चेकरबोर्ड रुकावटें बनाई जाती हैं। स्तूपों पर वर्गाकार जालीदार बाड़ लगाने से हवा का वेग सतह पर कम हो जाता है। इससे उड़ती रेत रुकती है, जिससे बाद में रोपे गए वृक्षों और घासों के बीज आसानी से अंकुरित और स्थापित हो पाते हैं।

45. (A) राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी → जिला जलागम प्रकोष्ठ → परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी → जलागम समिति
एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम का संस्थागत ढांचा राज्य स्तर पर 'राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी' से शुरु होता है। जिला स्तर पर 'जिला जलागम प्रकोष्ठ-सह-डेटा केंद्र' योजना की निगरानी करता है। इसके नीचे 'परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी' होती है जो तकनीकी सहायता देती है। सबसे निचले यानी सूक्ष्म-जलागम या गाँव के स्तर पर 'जलागम समिति' का गठन किया जाता है जो स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से सभी कार्यों का प्रत्यक्ष निष्पादन करती है।

46. (C) सूखे की अवधि के लिए अच्छी वर्षा वाले वर्षों से अधिशेष चारे का भंडारण करना
चारा बैंक की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य अच्छी मानसून वर्षा वाले वर्षों के दौरान उत्पादित अधिशेष हरे और सूखे चारे को वैज्ञानिक रूप से संग्रहित एवं संरक्षित करना है। जब शुष्क मौसम या सूखे की स्थिति पैदा होती है, तब इस संग्रहित चारे का उपयोग संकटग्रस्त पशुधन को बचाने के लिए किया जाता है। इससे सूखे के समय चारे के दामों में होने वाली वृद्धि और पशुओं की भुखमरी को रोका जा सकता है।

47. (D) जब मृदा की नमी इतनी कम हो जाती है कि फसल की पैदावार अत्यधिक घट जाती है या फसल नष्ट हो जाती है
कृषि सूखा उस विशिष्ट स्थिति को संदर्भित करता है जब वर्षा की कमी या वाष्पीकरण के कारण मृदा में उपलब्ध नमी का स्तर फसलों की सामान्य वृद्धि और विकास की आवश्यकता से नीचे गिर जाता है। इसके परिणामस्वरूप फसलें मुरझाने लगती हैं, जिससे कृषि उत्पादन और पैदावार में भारी गिरावट आती है या पूरी फसल नष्ट हो जाती है। यह सीधे तौर पर किसानों की आजीविका को प्रभावित करता है।

48. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
बुवाई की तिथियों में बदलाव करना फसल प्रबंधन से संबंधित शस्य वैज्ञानिक उपाय है। किसानों को सब्सिडी देना वित्तीय और नीतिगत सहायता के अंतर्गत आता है। चेक डैम जैसी भौतिक संरचनाओं का निर्माण करना अभियांत्रिकी या ढांचागत उपाय है। मौसम पूर्वानुमान स्टेशनों की स्थापना पूर्व चेतावनी देने वाला तकनीकी तथा सूचनात्मक उपाय है। ये सभी अलग-अलग उपाय मिलकर सूखा शमन की एक पूर्ण रणनीति का निर्माण करते हैं।

49. (B) सूखा-सहनशील फसलों, पशुधन और कृषि-वानिकी का संयोजन करना
राजस्थान के शुष्क और वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में बार-बार आने वाले सूखे के प्रभाव से बचने के लिए विविधीकृत कृषि प्रणाली सबसे उपयुक्त है। इसमें बाजरा या ग्वार जैसी कम पानी वाली सूखा-सहनशील फसलों के साथ पशुपालन और खेजड़ी या रोहिड़ा जैसी कृषि-वानिकी का संयोजन शामिल है। यदि कम वर्षा के कारण फसलें पूरी तरह विफल हो जाती हैं, तो पशुधन और वृक्ष किसान को सुरक्षित आजीविका प्रदान करते हैं।

50. (D) महिलाएँ, भूमिहीन श्रमिक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य
जलागम विकास के दिशानिर्देशों के अनुसार गाँव स्तर पर गठित जलागम समिति में समाज के सभी वर्गों की समावेशी भागीदारी अनिवार्य है। इसमें महिलाओं, भूमिहीन कृषि मजदूरों, और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जल और भूमि विकास परियोजनाओं का लाभ केवल बड़े भूस्वामियों तक सीमित न रहकर गाँव के सबसे गरीब वर्गों तक पहुँचे।

51. (A) बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए बालिका के जन्म पर 111 वृक्ष लगाना
राजसमंद जिले का पिपलांत्री गाँव अपनी अभिनव सामाजिक-पारिस्थितिक पहल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस गाँव में जब भी किसी बालिका का जन्म होता है, तो ग्रामीण उत्सव मनाते हुए गाँव की बंजर भूमि पर 111 फलदार वृक्ष लगाते हैं। इस अनूठी प्रथा ने न केवल पर्यावरण सुधार, जल स्तर वृद्धि और बंजर भूमि के पुनरुद्धार में मदद की है, बल्कि कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई को भी मिटाया है।

NODIA

अत्यंत कठिन था।

IV. विस्तृत लिफ्ट सिंचाई नेटवर्क की आवश्यकता से परिचालन ऊर्जा लागत में वृद्धि हुई।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) I, II और IV
(B) I, II और III
(C) II, III और IV
(D) I, III और IV

32. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के साथ प्रारंभ किए गए कमान क्षेत्र विकास (CAD) कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में कृषि का पूर्ण यांत्रीकरण करना।
(B) न्यायसंगत जल वितरण और भूमि समतलीकरण सुनिश्चित करना।
(C) पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन गतिविधियों को प्रतिबंधित करना।
(D) संपूर्ण नहर कमान क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में परिवर्तित करना।

33. मुख्य नहर के सापेक्ष स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन-सी शाखा अन्य तीन से भिन्न है?
(A) सूरतगढ़ शाखा
(B) रावतसर शाखा
(C) अनूपगढ़ शाखा
(D) पूगल शाखा

34. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में, "चक" शब्द का क्या अर्थ है?
(A) एक जलमार्ग (आउटलेट) द्वारा सिंचित भूमि का खंड
(B) वर्षा जल संचयन की पारंपरिक संरचना
(C) नहर के जल उपयोग पर लगाया जाने वाला कर
(D) नहर की सफाई करने वाली मशीन

35. इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जल वितरण तंत्र के अवरोही क्रम (बड़े से छोटे) का सही विकल्प चुनिए:
(A) मुख्य नहर → वितरिका → शाखा → जलमार्ग → माइनर
(B) मुख्य नहर → शाखा → वितरिका → माइनर → जलमार्ग
(C) शाखा → मुख्य नहर → माइनर → वितरिका → जलमार्ग
(D) मुख्य नहर → माइनर → शाखा → वितरिका → जलमार्ग

36. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण शुष्क घास के मैदानों के कृषि भूमि में बदलने से किस देशी पक्षी/जीव के आवास को गंभीर क्षति पहुँची है?
(A) भारतीय मोर
(B) सारस क्रेन
(C) नीलगाय
(D) गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड)

37. निम्नलिखित में से कौन-से जिले मुख्य रूप से नोहर-साहवा (चौधरी कुम्भाराम) लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं?
(A) जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर
(B) बीकानेर, नागौर और फलोदी
(C) हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू
(D) उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा

38. सूची I में दी गई शाखाओं को सूची II में स्थित संबंधित जिलों से सुमेलित कीजिए:
सूची I: शाखा
P. सूरतगढ़ शाखा
Q. पूगल शाखा
R. सागरमल गोपा शाखा
S. रावतसर शाखा
सूची II: जिला
1. बीकानेर
2. श्रीगंगानगर
3. हनुमानगढ़
4. जैसलमेर
(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

39. थार मरुस्थल क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सकारात्मक पारिस्थितिक प्रभाव कौन-सा है?
(A) वायुमंडलीय आर्द्रता में अत्यधिक कमी
(B) कंटीली वनस्पतियों का विनाश
(C) भूमिगत जल स्तर में गिरावट
(D) मरुस्थलीकरण और बालुका स्तूपों के प्रसार पर रोक

40. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।
कथन II: कमान क्षेत्र में फसल प्रारूप कपास, मूंगफली और सरसों जैसी व्यावसायिक फसलों की ओर परिवर्तित हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

41. बीकानेर और जोधपुर जिलों को सिंचाई एवं पेयजल सुविधा प्रदान करने वाली कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है?
(A) वीर तेजाजी लिफ्ट नहर
(B) गुरु जंभेश्वर लिफ्ट नहर
(C) डॉ. करणी सिंह लिफ्ट नहर
(D) पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर

Click Here to Buy book on Amazon

जलाशयों और भूजल स्तर जैसे सतही तथा उप-सतही जल निकायों में जल की उपलब्धता अत्यधिक घट जाती है। यह आमतौर पर लंबे समय तक मौसम संबंधी सूखा बने रहने का सीधा परिणाम होता है। इसके कारण पेयजल की भारी किल्लत और सिंचाई के लिए पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है।

63. (D) सामुदायिक वानिकी
सामुदायिक वानिकी सामाजिक वानिकी का वह विशिष्ट घटक है जो सार्वजनिक, अकृषित पंचायत भूमि, चरागाहों और गाँव की साझा संपत्ति पर स्थानीय ग्रामीणों की सामूहिक भागीदारी से पेड़ लगाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे गाँव के लिए ईंधन की लकड़ी, हरा चारा, फल और निर्माण काष्ठ की साझा आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिससे सामुदायिक बंजर भूमि का पुनरुद्धार और हरियाली में वृद्धि संभव होती है।

64. (C) शुष्क क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ाने के लिए वानिकी अनुसंधान आयोजित करना
शुष्क वन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के जोधपुर में स्थित भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का एक प्रमुख संस्थान है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान और गुजरात के शुष्क तथा अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में वन संरक्षण, मरुस्थलीकरण नियंत्रण, हरित आवरण बढ़ाने, और मृदा तथा जल संरक्षण की वैज्ञानिक तकनीकों का विकास करना है। इसके अनुसंधान से बंजर भूमि को पुनः उपजाऊ बनाने में अत्यधिक वैज्ञानिक मदद मिलती है।

65. (C) केवल I और III
चरागाह विकास के लिए चक्रीय चराई प्रणाली अपनाई जाती है, जिससे घासों को पुनः पनपने का समय मिलता है। क्षरित भूमि में सेवण, धामण जैसी पौष्टिक बारहमासी घासों के बीज बोने से भूमि की वहन क्षमता बढ़ती है। इसके विपरीत, अप्रतिबंधित और निरंतर चराई कराने से घासों की जड़ें पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं और भूमि स्थायी रूप से बंजर हो जाती है, इसलिए निरंतर चराई हानिकारक होती है।

66. (D) सूखे के दौरान पशुधनों को आपातकालीन आश्रय, चारा और देखभाल प्रदान करने वाली सुविधा
गंभीर सूखे और अकाल की स्थिति में जब ग्रामीण क्षेत्रों में चारा और पीने के पानी का पूर्ण अभाव हो जाता है, तब सरकार या स्वयंसेवी संस्थाएं "पशु शिविर" स्थापित करती हैं। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त मवेशियों को सुरक्षित आश्रय, पौष्टिक चारा, पीने का पानी और पशुचिकित्सा देखभाल प्रदान करना है, ताकि भुखमरी और बीमारियों के कारण होने वाली पशुओं की मौतों को रोका जा सके।

67. (A) अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (एसएसी), इसरो
"भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस" भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष उपयोग केंद्र द्वारा तैयार किया जाता है। यह संस्थान उपग्रह रिमोट सेंसिंग आंकड़ों का उपयोग करके देश भर में मरुस्थलीकरण की दर, बंजर भूमि की सीमाओं और भूमि क्षरण के कारणों का वैज्ञानिक मानचित्रण और नियमित आकलन करता है। यह नीति निर्माताओं को भूमि प्रबंधन योजनाएँ बनाने में मदद करता है।

68. (A) P-2, Q-3, R-1, S-4
टांका पश्चिमी राजस्थान में पक्के भूमिगत कुएँ के रूप में पीने के लिए वर्षा जल एकत्र करने की संरचना है। नाडी गाँव का पारंपरिक तालाब है जहाँ सामुदायिक उपयोग का जल संचित होता है। जोहड़ अलवर क्षेत्र में मिट्टी का छोटा बांध है जो मुख्य रूप से भूजल रीचार्ज करता है। खदीन जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त ढलानदार अपवाह कृषि और जल संचयन की पारंपरिक पद्धति है।

69. (A) वर्षा विचलन, फसल क्षेत्र, वनस्पति सूचकांक और मृदा नमी का एक संयुक्त सूचकांक
वर्तमान सूखा प्रबंधन नियमावली के अनुसार राजस्थान में आधिकारिक सूखा घोषित करने के लिए वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग किया जाता है। इसमें वर्षा की कमी या विचलन, बोए गए फसल क्षेत्र में गिरावट, उपग्रह द्वारा मापे गए वनस्पति सूचकांक और मृदा में उपलब्ध नमी के आंकड़ों का एक एकीकृत संयुक्त विश्लेषण किया जाता है। इस बहु-सूचकांक प्रणाली से सूखे की गंभीरता का सटीक और निष्पक्ष आकलन संभव होता है।

NODIA

70. (D) यह पूरक आय प्रदान करता है और सूखे के दौरान पूरी फसल नष्ट होने के जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है।
अर्द्ध-शुष्क बंजर भूमि में कृषि-उद्यानिकी को बढ़ावा देना एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। इसमें पारंपरिक फसलों के साथ बेर, आंवला या अनार जैसे सूखा-सहनशील फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं। कम वर्षा के कारण यदि पारंपरिक मौसमी फसलें नष्ट भी हो जाती हैं, तब भी ये मजबूत वृक्ष फल देकर किसानों को पूरक आय प्रदान करते हैं, जिससे सूखे के आर्थिक जोखिम से सुरक्षा मिलती है।

71. (B) सबसे उच्च ऊंचाइयों पर निकटवर्ती जल निकासी द्रोणियों को अलग करने वाली रेखा
जलागम प्रबंधन में "कटक रेखा" सबसे ऊँचे पहाड़ी स्थलों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा है जो दो निकटवर्ती जल निकासी द्रोणियों को परस्पर अलग करती है। इस रेखा के एक ओर गिरने वाला वर्षा का पानी एक दिशा में बहता है, जबकि दूसरी ओर का पानी दूसरी जलधारा में जाता है। जलागम उपचार की शुरुआत इसी कटक रेखा के शीर्ष बिंदु से की जाती है।

72. (B) केवल I, II और IV
बंजर भूमि सुधार परियोजनाओं की दीर्घकालिक सफलता के लिए परियोजना के बाद रख-रखाव कोष, सक्रिय स्थानीय जलागम समितियां और मनरेगा जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण आवश्यक है। हालांकि, विकसित साझा भूमि का बड़े निजी निगमों को निजीकरण करना दीर्घकालिक स्थिरता का कारक नहीं है, क्योंकि यह स्थानीय ग्रामीणों के साझा संपत्ति अधिकारों को छीनता है और सामुदायिक भागीदारी को कमजोर करता है, जिससे असंतोष पैदा होता है।

का कोई वैधानिक अधिकार नहीं होता, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा को ही सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

32. (C) जलागम प्रकोष्ठ-सह-डेटा केंद्र
राजस्थान में बंजर भूमि और जलागम विकास के संस्थागत ढांचे में जिला स्तर पर "जलागम प्रकोष्ठ-सह-डेटा केंद्र" उत्तरदायी निकाय है। यह जिला परिषद के अधीन कार्य करता है और जिले में स्वीकृत सभी जलागम विकास परियोजनाओं के नियोजन, तकनीकी पर्यवेक्षण, कोष जारी करने तथा प्रगति की निगरानी के लिए जिम्मेदार होता है। यह राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी और मैदानी कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करता है।

33. (C) 75 : 25
मनरेगा योजना के अंतर्गत सामग्री घटक के लिए वित्तपोषण का पैटर्न भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में निर्धारित होता है। इसमें 75 % हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है, जबकि शेष 25 % हिस्सा राज्य सरकार को वहन करना होता है। इस निधि का उपयोग पक्के जल संरक्षण ढांचे, चेक डैम और एनीकट निर्माण में किया जाता है।

34. (D) कृषि योग्य व्यर्थ भूमि को खेती के लिए पुनः उपजाऊ बनाया जा सकता है, जबकि बंजर भूमि पर आर्थिक रूप से खेती नहीं की जा सकती है।
भू-राजस्व वर्गीकरण में बंजर भूमि से तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो अत्यधिक चट्टानी, शुष्क या क्षरित होने के कारण वर्तमान तकनीक से खेती के अयोग्य होती है। इसके विपरीत, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वह भूमि है जो पाँच वर्ष से अधिक समय से अकृषित है, परंतु उचित मृदा सुधार, जल प्रबंधन और निवेश के माध्यम से पुनः उपजाऊ बनाकर आर्थिक रूप से सफलतापूर्वक खेती योग्य बनाई जा सकती है।

35. (A) 2 → 3 → 4 → 1
जल अपरदन की प्रक्रिया की शुरुआत वर्षा की बूंदों के प्रभाव से होती है जिसे बौछार अपरदन कहते हैं। इसके बाद जब जल सतह पर बहता है तो पतली परत के रूप में मिट्टी बहती है जिसे परत अपरदन कहते हैं। निरंतर अपवाह से छोटी उथली नालियां बनती हैं जिसे रिल अपरदन कहते हैं, और अंततः ये नालियां गहरी होकर अवनालिका अपरदन में परिवर्तित हो जाती हैं।

36. (C) खदीन
खदीन जैसलमेर क्षेत्र में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित एक पारंपरिक और वैज्ञानिक जल संचयन प्रणाली है। इसमें ढलान वाले जल ग्रहण क्षेत्र के निचले हिस्से में मिट्टी का बांध बनाकर वर्षा जल को रोका जाता है। इससे जल भूमि में रिसकर नमी बढ़ाता है और भूजल रीचार्ज करता है। जल सूखने के बाद उस समृद्ध नमी युक्त भूमि पर रबी की फसलें सफलतापूर्वक उगाई जाती हैं।

37. (A) प्रोसोपिस सिनेरेरिया (खेजड़ी)
प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जिसे स्थानीय रूप से खेजड़ी कहा जाता है, राजस्थान का कल्पवृक्ष और राज्य वृक्ष है। इसकी जड़ें गहरी होती हैं और यह अपनी जड़ों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके मृदा की उर्वरता बढ़ाता है। यह वृक्ष भयंकर सूखे में भी हरा-भरा रहकर पशुओं के लिए लोंग (चारा) प्रदान करता है तथा अपनी जड़ों से बालुका स्तूपों को बांधकर मरुस्थल के प्रसार को रोकने में मदद करता है।

38. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
अर्द्ध-शुष्क राजस्थान में नलकूप और कुएँ ही सिंचाई का मुख्य आधार हैं। अत्यधिक सिंचाई के कारण जब भूजल का निरंतर ह्रास होता है, तो भूजल स्तर बहुत गहरा चला जाता है। कम वर्षा की स्थिति में जब सतही जल उपलब्ध नहीं होता और भूजल भंडार भी सूख जाते हैं, तो फसलों को पानी देना असंभव हो जाता है। इससे कृषि सूखा और अधिक गंभीर तथा विनाशकारी रूप धारण कर लेता है।

39. (B) यह केवल पश्चिमी राजस्थान तक सीमित है और शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों को बाहर रखता है।
मरुस्थल विकास कार्यक्रम केवल पश्चिमी राजस्थान के गर्म मरुस्थल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के अन्य राज्यों के शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों जैसे लद्दाख, लाहौल-स्पीति आदि में भी लागू किया गया है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों पर आधारित इस कार्यक्रम में वनीकरण, जल संचयन, मृदा संरक्षण और चरागाह विकास को एकीकृत रूप से लागू किया जाता है ताकि मरुस्थलीकरण की दर को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके।

40. (C) सूखे के दौरान वृद्धों, अशक्तों और निराश्रित व्यक्तियों को दी जाने वाली निःशुल्क सहायता
अकाल और सूखा राहत कार्यों में "अनुग्रह सहायता" का तात्पर्य उस वित्तीय या खाद्यान्न सहायता से है जो सरकार द्वारा समाज के उन असहाय वर्गों को बिना किसी कार्य के निःशुल्क दी जाती है जो शारीरिक रूप से श्रम करने में सक्षम नहीं हैं। इसमें वृद्ध, विकलांग, गंभीर रूप से बीमार और निराश्रित व्यक्ति शामिल होते हैं, ताकि भयंकर अकाल के समय उनकी जीवन रक्षा और न्यूनतम पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

41. (B) केवल II और III
रक्षक मेखला वृक्षारोपण में पेड़ों और झाड़ियों की पंक्तियां प्रचलित हवाओं की दिशा के समकोण पर लगाई जाती हैं, न कि समानांतर। यह व्यवस्था हवा के वेग को प्रभावी रूप से तोड़ती है। इससे पवन द्वारा होने वाले मृदा अपरदन में कमी आती है और वायु-विमुख दिशा में स्थित कृषि क्षेत्रों में वाष्पोत्सर्जन घटता है, जिससे मृदा की नमी अधिक समय तक संरक्षित रहती है और फसलें सुरक्षित रहती हैं।

Downloaded from www.pdf.tube

अध्याय 17
इंदिरा गांधी नहर परियोजना

1. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उद्गम स्थल, हरिके बैराज पर कौन-सी दो नदियाँ मिलती हैं?
   (A) रावी और चेनाब
   (B) सतलुज और ब्यास
   (C) झेलम और रावी
   (D) सतलुज और यमुना

2. राजस्थान नहर का नाम बदलकर 'इंदिरा गांधी नहर' किस वर्ष किया गया था?
   (A) 1975
   (B) 1980
   (C) 1984
   (D) 1989

3. निम्नलिखित में से किसे 1948 की एक रिपोर्ट के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना की परिकल्पना करने वाले मुख्य परिकल्पनाकार के रूप में जाना जाता है?
   (A) महाराजा गंगा सिंह
   (B) डॉ. करणी सिंह
   (C) कंवर सैन
   (D) जयनारायण व्यास

4. वर्ष 1948 की उस मूल रिपोर्ट का शीर्षक क्या था जिसने इंदिरा गांधी नहर के लिए वैचारिक आधार तैयार किया था?
   (A) डेजर्ट रिक्लेमेशन इन राजपूताना
   (B) द थार इरिगेशन प्रोजेक्ट
   (C) इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ वेस्टर्न राजस्थान
   (D) वाटर रिक्वायरमेंट्स इन बीकानेर स्टेट

5. राजस्थान फीडर नहर की कुल लंबाई कितनी है, जो हरिके बैराज से मुख्य नहर के शुरुआती बिंदु तक पानी ले जाती है?
   (A) 170 किमी
   (B) 204 किमी
   (C) 345 किमी
   (D) 445 किमी

6. उन राज्यों का सही क्रम चुनिए जिनसे होकर इंदिरा गांधी नहर का पानी अपने उद्गम से मुख्य कमान क्षेत्र तक प्रवाहित होता है।
   (A) पंजाब → हरियाणा → राजस्थान
   (B) हरियाणा → पंजाब → राजस्थान
   (C) पंजाब → राजस्थान → हरियाणा
   (D) राजस्थान → पंजाब → हरियाणा

NODIA

7. राजस्थान फीडर नहर राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवेश करती है?
   (A) बाड़मेर जिले में स्थित गडरारोड
   (B) जैसलमेर जिले में स्थित मोहनगढ़
   (C) बीकानेर जिले में स्थित पूगल
   (D) हनुमानगढ़ जिले में मसीतावाली हेड

8. दिए गए कथन (A) और कारण (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
   कथन (A): इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सभी लिफ्ट नहरें इसके बाएँ तट पर स्थित हैं।
   कारण (R): मुख्य नहर के बाएँ (पूर्वी) ओर की भू-आकृतिक ऊँचाई नहर के गुरुत्वाकर्षण प्रवाह स्तर से अधिक है।
   (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
   (B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
   (C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
   (D) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

9. इंदिरा गांधी मुख्य नहर की कुल लंबाई (फीडर नहर को छोड़कर) कितनी है?
   (A) 204 किमी
   (B) 445 किमी
   (C) 649 किमी
   (D) 820 किमी

10. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम छोर (ज़ीरो पॉइंट) का विस्तार किस स्थान तक किया गया है?
   (A) बाड़मेर में गडरारोड
   (B) जैसलमेर में मोहनगढ़
   (C) जैसलमेर में रामगढ़
   (D) बीकानेर में कोलायत

11. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   I. इसमें मुख्य रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के कुछ भाग शामिल थे।
   II. यह गुरुत्वाकर्षण प्रवाह के बजाय पूरी तरह से लिफ्ट नहर प्रणाली पर निर्भर था।
   III. द्वितीय चरण की तुलना में इस चरण में भूभाग अपेक्षाकृत कम उबड़-खाबड़ था।
   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

52. (C) वह संपूर्ण क्षेत्र जिसका जल बहकर एक साझा निकास बिंदु में जाता है
जलागम या जल ग्रहण क्षेत्र एक सुस्पष्ट भू-आकृतिक भौगोलिक इकाई है, जहाँ वर्षा का जल ढलान के अनुसार बहकर एक ही प्राकृतिक जलधारा, नदी, नाले या जलाशय के साझा निकास बिंदु तक पहुँचता है। इस संपूर्ण क्षेत्र की मृदा, वनस्पति और जल संसाधन परस्पर एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। इसी प्राकृतिक इकाई को आधार बनाकर एकीकृत भूमि और जल संरक्षण की प्रभावी योजनाएँ बनाई जाती हैं।

53. (A) ग्रामीण विकास मंत्रालय
सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम दोनों ही भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। यह मंत्रालय देश के शुष्क, अर्द्ध-शुष्क और बंजर क्षेत्रों में जल प्रबंधन, मृदा संरक्षण, वनीकरण और ग्रामीण आजीविका के संवर्धन के लिए केंद्रीय नीतियों और वित्तीय अनुदानों का प्रबंधन तथा राज्य सरकारों के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है।

54. (B) केवल I, II और IV
अतिचारण से भूमि का वानस्पतिक आवरण नष्ट हो जाता है, जिससे वायु और जल द्वारा मृदा अपरदन बढ़ता है। अरावली पहाड़ियों में वनों की कटाई से तीव्र जल अपवाह होता है और अवैवैज्ञानिक खनन से ऊपरी उपजाऊ मिट्टी नष्ट होती है। इसके विपरीत, समुच्च रेखा जुताई ढलान के समकोण पर की जाती है, जो जल के प्रवाह को रोककर मृदा अपरदन को कम करती है, न कि उसे बढ़ाती है।

55. (B) परियोजना पूरी होने के बाद निर्मित परिसंपत्तियों का संचालन और रख-रखाव करना
जलागम विकास परियोजनाओं में "उपयोगकर्ता समूह" उन स्थानीय ग्रामीणों और किसानों के समूह होते हैं जो परियोजना के तहत निर्मित किसी विशिष्ट परिसंपत्ति जैसे चेक डैम, तालाब या चरागाह का प्रत्यक्ष लाभ उठाते हैं। इनका प्राथमिक कार्य परियोजना की औपचारिक अवधि समाप्त होने के बाद भी उन निर्मित जल और मृदा संरक्षण परिसंपत्तियों का निरंतर संचालन, रख-रखाव और सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि दीर्घकालिक लाभ मिलता रहे।

56. (C) 75%
राज्य आपदा मोचन निधि सूखा, बाढ़ जैसी अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तत्काल राहत कार्य चलाने के लिए प्राथमिक वित्तीय तंत्र है। राजस्थान जैसे सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए इस निधि में केंद्र सरकार द्वारा 75 % अनुदान दिया जाता है, जबकि शेष 25 % राशि राज्य सरकार अपने बजट से प्रदान करती है। इस राशि का उपयोग किसानों और प्रभावित आबादी को त्वरित आर्थिक सहायता देने में होता है।

57. (D) जलकुंभी
राजस्थान में बालुका स्तूपों के वानस्पतिक स्थिरीकरण के लिए शुष्क परिस्थितियों को सहन करने वाले पौधों का चयन किया जाता है। इजराइली बबूल, विलायती बबूल और सेवण घास अत्यधिक शुष्क वातावरण में तेजी से पनपते हैं और अपनी जड़ों से उड़ती रेत को बांधते हैं। इसके विपरीत, जलकुंभी एक जलीय पौधा है जो केवल ताजे जल निकायों में उगता है, इसलिए इसका मरुस्थलीय बालुका स्तूप स्थिरीकरण से कोई संबंध नहीं है।

58. (A) जल संरक्षण और जल संचयन कार्यों को कम प्राथमिकता वाले कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
मनरेगा के तहत जल संरक्षण, जल संचयन, तालाबों की खुदाई और एनिकट निर्माण को सबसे उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों में रखा गया है, न कि कम प्राथमिकता वाले। यह योजना ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देती है, जिसे भयंकर सूखे के समय बढ़ाकर 150 दिन किया जा सकता है। यह योजना कृषि संकट के समय ग्रामीणों को आजीविका और सुरक्षा प्रदान करने का सशक्त साधन है।

59. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
पूर्व में संचालित विभिन्न क्षेत्र विकास योजनाएं जैसे डीपीएपी, डीडीपी और आईडब्ल्यूडीपी अलग-अलग स्वरुप में कार्य करती थीं, जिससे संसाधनों का दोहराव और प्रयासों का विखंडन होता था। इस समस्या को दूर करने और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2009-10 में इन सभी योजनाओं को मिलाकर एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो कटक से घाटी दृष्टिकोण पर आधारित है।

60. (B) महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र
भारत में राष्ट्रीय स्तर पर उपग्रह डेटा और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करके सूखे की वैज्ञानिक निगरानी महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र द्वारा की जाती है। यह केंद्र उपग्रहों से प्राप्त वनस्पति सूचकांक, वर्षा विचलन और मृदा नमी के आंकड़ों का विश्लेषण करता है। इन वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर राजस्थान जैसे राज्यों को सूखा घोषित करने और प्रभावित क्षेत्रों में राहत योजनाएं बनाने में सटीक मदद मिलती है।

61. (A) क्योंकि स्थानीय ज्ञान नियोजन को अनुकूलित करता है और परिसंपत्ति रख-रखाव सुनिश्चित करता है
बंजर भूमि विकास परियोजनाओं में स्थानीय ग्रामीणों के पास सूक्ष्म-स्तर की पारंपरिक जल और मिट्टी की जानकारी होती है। जब समुदाय योजना बनाने और निष्पादन में सक्रिय रूप से भाग लेता है, तो परियोजना की संरचनाएं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सटीक बनती हैं। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक जुड़ाव से परियोजना पूरी होने के बाद भी जल और वनीकरण परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा रख-रखाव की दीर्घकालिक जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है।

62. (C) जलवैज्ञानिक सूखा
जलवैज्ञानिक सूखा उस स्थिति को संदर्भित करता है जब लगातार कम वर्षा होने के कारण नदियों, झीलों, तालाबों,

Click Here to Buy book on Flipkart

22. इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा लाए गए कृषि परिवर्तन के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए:
(A) इस क्षेत्र में पारंपरिक जीवन-निर्वाह कृषि से व्यावसायिक फसलों की ओर बदलाव हुआ है।
(B) अत्यधिक नमी के कारण कमान क्षेत्र में फसल सघनता में भारी कमी आई है।
(C) मरुस्थलीय क्षेत्र में चावल और कपास जैसी जल-गहन फसलों की कृषि प्रारंभ हुई है।
(D) सिंचित क्षेत्रों में बाजरा और ज्वार जैसी सूखा-प्रतिरोधी फसलों का स्थान गेहूं और सरसों ने ले लिया है।

23. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसके कारण "चक" के रूप में जानी जाने वाली नई नियोजित कृषि बस्तियों की स्थापना हुई।
II. इसके कारण कमान क्षेत्र में कृषि भूमि के मूल्य में भारी गिरावट आई।
III. इसने पड़ोसी राज्यों से कृषि श्रमिकों और किसानों के अंतःप्रवासन को प्रोत्साहित किया।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) I, II और III
(D) केवल I और III

24. किस जल-समझौते के माध्यम से राजस्थान नहर परियोजना के लिए रावी और ब्यास नदियों के जल का आवंटन सुरक्षित किया गया?
(A) सिंधु जल संधि (1960)
(B) गंगा जल संधि (1996)
(C) यमुना समझौता (1994)
(D) नर्मदा जल विवाद अधिकरण (1979)

25. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण बढ़ी हुई मृदा नमी और कृषि विस्तार के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस देशी मरुस्थलीय घास प्रजाति के प्राकृतिक आवास का अत्यधिक नुकसान हुआ है?
(A) यूकेलिप्टस
(B) जलकुंभी
(C) सेवण घास
(D) विलायती बबूल

26. इंदिरा गांधी मुख्य नहर की निम्नलिखित शाखाओं का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम चुनिए:
1. सूरतगढ़ शाखा
2. पूगल शाखा
3. दंतौर शाखा
4. सागरमल गोपा शाखा
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 4, 3, 2, 1
(C) 1, 3, 2, 4
(D) 2, 1, 4, 3

27. जर्मनी के सहयोग से संचालित "आपणी योजना" का संबंध इंदिरा गांधी नहर परियोजना के किस पहलू से है?
(A) कमान क्षेत्र के किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराना।
(B) जल रिसाव रोकने हेतु मुख्य नहर को पक्का करना।
(C) जैव-जल निकासी (बायो-ड्रेनेज) द्वारा सेम की समस्या को समाप्त करना।
(D) चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू के गांवों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करना।

28. दिए गए कथन (A) और कारण (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन (A): इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में मृदा का द्वितीयक लवणीकरण एक बढ़ती हुई समस्या है।
कारण (R): उच्च वाष्पीकरण दर वाले शुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई से केशिका क्रिया के माध्यम से भूगर्भिक लवण सतह पर आ जाते हैं।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

29. इराडी आयोग (1986) का गठन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मुद्दे के समाधान हेतु किया गया था?
(A) द्वितीय चरण के क्षेत्रों में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करना
(B) थार मरुस्थल के विस्थापित पशुपालकों का पुनर्वास करना
(C) रावी और ब्यास नदियों के अधिशेष जल के आवंटन का पुनः परीक्षण करना
(D) नहर निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं की जाँच करना

30. किस जिले में इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई सर्वाधिक है?
(A) जैसलमेर
(B) हनुमानगढ़
(C) बाड़मेर
(D) बीकानेर

31. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. उबड़-खाबड़ भूभाग और स्थानांतरित बालुका स्तूपों के कारण कई भागों में गुरुत्वाकर्षण प्रवाह संभव नहीं था।
II. रेतीले तूफानों के कारण नहर में अत्यधिक गाद व रेत जमा हो जाती है।
III. प्रारंभ में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण भूमि अधिग्रहण

Downloaded from www.pdf.tube

73. (D) जलागम प्रबंधन, वनीकरण और जल-कुशल खेती को बढ़ावा देना
राजस्थान में बार-बार आने वाले सूखे के स्थायी समाधान के लिए एकीकृत जलागम प्रबंधन, बड़े पैमाने पर वनीकरण और फव्वारा या ड्रिप जैसी जल-कुशल कृषि तकनीकों को अपनाना सबसे प्रभावी दीर्घकालिक रणनीति है। यह दृष्टिकोण भूजल रीचार्ज बढ़ाता है, मिट्टी की नमी को संरक्षित करता है और पारिस्थितिक लचीलापन विकसित करता है, जिससे वर्षा की कमी के बावजूद कृषि और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव बहुत कम पड़ता है।

74. (A) नकद सहायता देना दीर्घकालिक सूखा-रोधी तंत्र का एक क्लासिक उदाहरण है।
प्रभावित किसानों को सीधे नकद सहायता या खाद्यान्न देना अल्पकालिक अकाल राहत का उदाहरण है, न कि दीर्घकालिक सूखा-रोधी उपाय। अल्पकालिक राहत संकट के समय तत्काल राहत पहुँचाती है, जबकि दीर्घकालिक सूखा-रोधी उपायों में वनीकरण, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और चरागाह विकास शामिल हैं जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाकर भविष्य में आने वाले सूखे के प्रतिकूल प्रभावों का स्थायी रूप से शमन करते हैं।

75. (A) $3 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2$
सूक्ष्म-जलागम परियोजना के निष्पादन में सबसे पहले ग्रामीणों का विश्वास जीतने के लिए प्रवेश बिंदु गतिविधियां की जाती हैं। इसके पश्चात वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है। तत्पश्चात स्वीकृत रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जल-मृदा संरक्षण के कार्य निष्पादित किए जाते हैं। अंत में परियोजना का निष्पक्ष मूल्यांकन और परियोजना की औपचारिक समाप्ति तथा समुदाय को सुपुर्दगी होती है।

76. (B) इसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।
भू-राजस्व आंकड़ों के अनुसार यदि कोई कृषि योग्य भूमि केवल चालू वर्ष में बिना जोते छोड़ी जाती है, तो उसे चालू परती भूमि कहते हैं। यदि यह एक से पाँच वर्ष तक अकृषित रहती है, तो इसे अन्य परती भूमि माना जाता है। परंतु यदि वही भूमि लगातार पाँच वर्ष से अधिक समय तक बिना जोते या खेती किए पड़ी रहती है, तो उसे राजस्व अभिलेखों में "कृषि योग्य व्यर्थ भूमि" के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है।

77. (A) पौष्टिक स्वदेशी चरागाह घासों का प्रसार
शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में मरुस्थलीकरण के लक्षणों में भूजल स्तर में भारी गिरावट, धूल भरे तूफानों की बढ़ती आवृत्ति और मृदा की ऊपरी परत में लवणता तथा क्षारियता में वृद्धि शामिल है। इसके विपरीत, सेवण या धामण जैसी पौष्टिक स्वदेशी चरागाह घासों का व्यापक प्रसार होना स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और भूमि के पुनरुद्धार का सकारात्मक प्रतीक है, जो मरुस्थलीकरण का संकेतक बिल्कुल नहीं है।

78. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
राजस्थान के सूखा संभाव्य क्षेत्रों में जल की भीषण कमी और सीमित भूजल भंडार होते हैं। इन क्षेत्रों में गन्ना जैसी अत्यधिक जल-गहन फसलों की खेती करने से भूजल का तीव्र गति से दोहन होता है, जिससे जल संकट अत्यंत गहरा हो जाता है। इसलिए इन संवेदनशील अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण बनाए रखने हेतु उच्च-सिंचाई वाली फसलों के स्थान पर कम पानी की मांग वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाता है।

79. (D) वे ग्राम पंचायत कार्य योजना का एक अनिवार्य, उच्च-प्राथमिकता वाला घटक बनते हैं।
मनरेगा योजना के दिशानिर्देशों के तहत सूखा-रोधी तंत्र और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के कार्यों को ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसमें जल संचयन संरचनाओं, चेक डैम, एनीकट, चरागाह विकास और वनीकरण के कार्यों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। ये कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा प्रदान करने और पारिस्थितिकी को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

80. (C) खराब जल निकासी के कारण जलभराव और द्वितीयक लवणीकरण
इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने मरुस्थल को उपजाऊ खेतों में बदला, लेकिन अत्यधिक भाड़ सिंचाई और खराब उप-सतही जल निकासी के कारण कमान क्षेत्रों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई। जलभराव से भूजल स्तर बहुत ऊपर आ गया और वाष्पीकरण के कारण मिट्टी की सतह पर लवणों का जमाव हो गया। इस द्वितीयक लवणीकरण और जलभराव ने उपजाऊ कृषि भूमि के बड़े हिस्सों को द्वितीयक बंजर भूमि में बदल दिया।

NODIA

www.nodia.in

42. इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जलभराव (सेम) की समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित में से कौन-से उपाय उपयुक्त हैं?
- I. सफेदा (यूकेलिप्टस) के वृक्ष लगाकर जैव-जल निकासी को बढ़ावा देना।
- II. उप-सतही जल निकासी (सब-सरफेस ड्रेनेज) नेटवर्क का निर्माण करना।
- III. लवणों को बहाने हेतु प्रति हेक्टेयर जल का आबंटन बढ़ाना।
- IV. फव्वारा सिंचाई एवं जल के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करना।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- (A) I, II और IV
- (B) I, II और III
- (C) II, III और IV
- (D) I, III और IV

43. निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य हरिके बैराज प्रणाली के जल-बँटवारे में भागीदार नहीं है?
- (A) पंजाब
- (B) हरियाणा
- (C) राजस्थान
- (D) गुजरात

44. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- I. यह विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणालियों में से एक है जो मरुस्थलीय वातावरण में निर्मित है।
- II. भूजल पुनर्भरण हेतु मुख्य नहर को कच्चा (unlined) रखा गया है।
- III. जैसलमेर और बाड़मेर की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण परियोजना का द्वितीय चरण अधिक चुनौतीपूर्ण था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- (A) केवल I और II
- (B) केवल I और III
- (C) केवल II और III
- (D) I, II और III

45. इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा लक्षित सकल कमान क्षेत्र (GCA) कितना है?
- (A) 0.5 मिलियन हेक्टेयर
- (B) 1.0 मिलियन हेक्टेयर
- (C) 1.96 मिलियन हेक्टेयर
- (D) 4.5 मिलियन हेक्टेयर

46. जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर का पूर्व नाम क्या था?
- (A) फलोदी लिफ्ट नहर
- (B) गजनेर लिफ्ट नहर
- (C) बांगड़सर लिफ्ट नहर
- (D) पोकरण लिफ्ट नहर

47. इंदिरा गांधी नहर की भौतिक संरचना के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए:
- (A) जल रिसाव को कम करने हेतु मुख्य नहर और प्रमुख शाखाओं को पक्का (lined) किया गया है।
- (B) राजस्थान फीडर नहर पंजाब के कृषि क्षेत्रों को प्रत्यक्ष सिंचाई प्रदान करती है।
- (C) जैसे-जैसे मुख्य नहर दक्षिण की ओर बढ़ती है, इसके तल की चौड़ाई बढ़ती जाती है।
- (D) मुख्य नहर जल के लिए केवल मानसूनी वर्षा पर निर्भर है।

48. दिए गए कथन (A) और कारण (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।

कथन (A): इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में मलेरिया जैसी जलजनित बीमारियों के मामलों में वृद्धि हुई है।

कारण (R): समतल मरुस्थलीय भूभाग में बारहमासी जल की उपस्थिति और जलभराव से मच्छरों के पनपने के अनुकूल स्थान बनते हैं।
- (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
- (B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
- (D) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

49. निम्नलिखित में से कौन-सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहर नहीं है?
- (A) गुरु जंभेश्वर लिफ्ट नहर
- (B) नर्मदा लिफ्ट नहर
- (C) वीर तेजाजी लिफ्ट नहर
- (D) जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर

50. मोहनगढ़ से गडरारोड तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम विस्तार को किस नाम से जाना जाता है?
- (A) बाबा रामदेव उप-शाखा
- (B) सागरमल गोपा मुख्य शाखा
- (C) बरकतुल्लाह खान लिंक नहर
- (D) सरस्वती लिंक नहर

51. इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पेयजल आपूर्ति भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- I. यह बीकानेर शहर को पेयजल आपूर्ति करती है।
- II. यह जोधपुर शहर हेतु प्राथमिक सतही जल स्रोत है।
- III. इसने उदयपुर संभाग की पेयजल समस्या का समाधान किया है।
- IV. यह पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से दूरस्थ मरुस्थलीय गांवों को जल उपलब्ध कराती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- (A) I, II और III
- (B) II, III और IV

Click Here to Buy book on Amazon

(C) I, II और IV
(D) I, III और IV

52. हरिके बैराज से सीधे सिंचाई नहरें निकालने के स्थान पर राजस्थान फीडर नहर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) पड़ोसी राज्यों को जल पर अधिकार जताने से रोकना।
(B) जलविद्युत उत्पादन हेतु अरावली ढलान का उपयोग करना।
(C) पंजाब और राजस्थान के बीच नौगम्य जलमार्ग बनाना।
(D) मरुस्थलीय कमान क्षेत्र तक जल पहुँचाने में जल की हानि को रोकना तथा प्रवाह गति बनाए रखना।

53. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण का निर्माण कार्य मुख्य रूप से किस दशक में पूरा हुआ?
(A) 1960 का दशक
(B) 1970 का दशक
(C) 1990 का दशक
(D) 2010 का दशक

54. इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाओं और उनकी स्थिति के संबंध में कौन-सा युग्म गलत है?
(A) सूरतगढ़ शाखा - दायाँ तट
(B) रावतसर शाखा - दायाँ तट
(C) अनूपगढ़ शाखा - दायाँ तट
(D) बीरसलपुर शाखा - दायाँ तट

55. इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम चुनिए:
1. सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर
2. कंवर सैन रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण
3. राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर करना
4. हरिके बैराज/नहर निर्माण कार्य का प्रारंभ
(A) 2, 4, 1, 3
(B) 2, 1, 4, 3
(C) 4, 2, 1, 3
(D) 1, 2, 4, 3

56. किस भौगोलिक कारण से इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहर प्रणाली का निर्माण आवश्यक हुआ?
(A) मुख्य नहर के पूर्व एवं दक्षिण की भूमि का स्तर गुरुत्वाकर्षण प्रवाह की तुलना में ऊँचा है।
(B) भूमि का ढलान तीव्र होने से गहरे खड्ड बन गए हैं।
(C) संपूर्ण क्षेत्र कठोर चट्टानी पठारों से आच्छादित है।
(D) भूभाग समुद्र तल से नीचे स्थित है।

57. इंदिरा गांधी नहर के उत्तरी कमान क्षेत्र (श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़) में पारंपरिक शुष्क खाद्यान्न फसलों के स्थान पर किस फसल के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है?
(A) जूट
(B) कॉफी
(C) कपास
(D) सोयाबीन

58. सूची I में दिए गए शब्दों को सूची II में उनकी सही परिभाषाओं से सुमेलित कीजिए:
सूची I: शब्द
P. सेम
Q. हार्डपैन (कठोर परत)
R. चक
S. कमान क्षेत्र
सूची II: परिभाषा
1. जिप्सम/मृदा की उप-सतही अभेद्य परत
2. एक जलमार्ग हेतु निर्धारित सिंचित क्षेत्र
3. परियोजना द्वारा सिंचाई हेतु उपयुक्त क्षेत्र
4. अत्यधिक जलभराव एवं मृदा क्षरण की समस्या
(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-4, R-3, S-2
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-2, S-4

59. बीकानेर-लूणकरणसर लिफ्ट नहर परियोजना के तहत निर्मित प्रथम लिफ्ट नहर थी। इसका वर्तमान नाम क्या है?
(A) गुरु जंभेश्वर लिफ्ट नहर
(B) पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर
(C) डॉ. करणी सिंह लिफ्ट नहर
(D) कंवर सैन लिफ्ट नहर

NODIA

60. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने लूनी नदी के प्रवाह की दिशा को पूरी तरह से उलट दिया है।
कथन II: इंदिरा गांधी नहर परियोजना थार मरुस्थल के प्राकृतिक अपवाह बेसिन के बाहर से जल लाती है।
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

61. इंदिरा गांधी नहर की उपस्थिति के कारण मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान (डेजर्ट नेशनल पार्क) क्षेत्र में हुए पारिस्थितिक परिवर्तन का सबसे सही वर्णन कौन-सा है?
(A) भारी मशीनों के उपयोग से बालुका स्तूपों का विनाश
(B) कृत्रिम झीलों में खारे पानी के मगरमच्छों की उपस्थिति
(C) आर्द्रता वृद्धि एवं समोद्भिद (मेसोफाइटिक) वनस्पतियों द्वारा मूल शुष्क आवास में परिवर्तन
(D) यूकेलिप्टस वृक्षारोपण के कारण जंगलों में आग लगना

62. इंदिरा गांधी नहर के रखरखाव से संबंधित चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. ग्रीष्मकाल में तीव्र पवनों द्वारा उड़कर आई रेत से नहर में गाद जमा हो जाती है, जिसकी सफाई आवश्यक होती है।

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from
PRINTED BOOKS has up to
4× HIGHER RETENTION
than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY
PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

II. नहर की दीवारों का टूटना दुर्लभ है क्योंकि नहर का निर्माण ठोस चट्टानों के मध्य हुआ है।
III. जलीय खरपतवारों की वृद्धि से वितरिकाओं में जल प्रवाह बाधित होता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) I, II और III
(D) केवल I और III

63. निम्नलिखित में से किस जिले को चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट नहर से सिंचाई सुविधा प्राप्त नहीं होती है?
(A) जैसलमेर
(B) हनुमानगढ़
(C) चूरू
(D) झुंझुनू

64. इंदिरा गांधी मुख्य नहर के प्रथम चरण का अंतिम बिंदु निम्नलिखित में से किस स्थान पर है?
(A) मोहनगढ़
(B) पूगल
(C) गडरारोड
(D) रामगढ़

65. मृदा लवणीकरण की समस्या से निपटने के लिए इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में किस कृषि पद्धति को प्रोत्साहित किया जाता है?
(A) निरंतर अत्यधिक सिंचाई करना
(B) दलहनी फसलों के साथ फसल चक्र अपनाना तथा सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का उपयोग करना
(C) झूम/स्थानांतरित कृषि पद्धति अपनाना
(D) वर्ष भर केवल चावल की खेती करना

66. जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों को लाभान्वित करने वाली फलोदी लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है?
(A) गुरु जंभेश्वर लिफ्ट नहर
(B) पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर
(C) जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर
(D) वीर तेजाजी लिफ्ट नहर

67. इंदिरा गांधी नहर प्रणाली की कुल लंबाई 649 किमी है। इसमें शामिल हैं:
(A) 170 किमी फीडर नहर और 479 किमी मुख्य नहर
(B) 300 किमी फीडर नहर और 349 किमी मुख्य नहर
(C) 204 किमी फीडर नहर और 445 किमी मुख्य नहर
(D) 250 किमी फीडर नहर और 399 किमी मुख्य नहर

68. इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. नए सिंचित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
II. घुमंतू पशुपालकों को राज्य से जबरन बेदखल कर दिया गया।
III. नए कृषि मंडी नगरों का तीव्र विकास हुआ है।
IV. कृषि भूमि के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) I, II और III
(B) II, III और IV
(C) I, II, III और IV
(D) I, III और IV

69. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन "बांगड़सर लिफ्ट नहर" का सही विवरण प्रस्तुत करता है?
(A) यह जोधपुर शहर को जल आपूर्ति करने वाली सबसे लंबी लिफ्ट नहर है।
(B) यह मुख्य नहर के दाएँ तट पर स्थित एकमात्र लिफ्ट नहर है।
(C) इसका नया नाम वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है, जो बीकानेर जिले को जल उपलब्ध कराती है।
(D) यह गुजरात के साथ जल साझा करने वाली अंतरराज्यीय नहर है।

70. इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने पश्चिमी राजस्थान की पारंपरिक पशुपालन अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया है?
(A) इसने मवेशी पालन को अवैध घोषित करके स्थानीय डेयरी व्यवसाय को समाप्त कर दिया।
(B) इसने घुमंतू पशुपालन को एकीकृत पशुधन एवं मिश्रित कृषि में परिवर्तित कर दिया।
(C) इसने अर्थव्यवस्था को केवल ऊँट पालन तक सीमित कर दिया।
(D) इसका पारंपरिक चरवाहा गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

71. दिए गए कथन (A) और कारण (R) को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन (A): इंदिरा गांधी नहर ने पश्चिमी राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
कारण (R): जल की बारहमासी उपलब्धता से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थायी नागरिक बस्तियों एवं अवसंरचना का विकास हुआ है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

72. सीमावर्ती जिले बाड़मेर की पेयजल एवं औद्योगिक जल आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्य रूप से किस नहर द्वारा होती है?
(A) बाबा रामदेव उप-शाखा
(B) जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर

Downloaded from www.pdf.tube

का बहाव गुरुत्वाकर्षण प्रवाह पर आधारित था। द्वितीय चरण की तुलना में यहाँ निर्माण कार्य अधिक सुलभ और तीव्र गति से संपन्न हुआ।

12. (B) प्रतापगढ़
दक्षिणी राजस्थान में स्थित प्रतापगढ़ जिला अरावली पर्वतमाला के पहाड़ी क्षेत्र में आता है और यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कमान क्षेत्र अथवा पेयजल क्षेत्र में शामिल नहीं है। यह नहर प्रणाली मुख्य रुप से उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय जिलों की कृषि तथा पीने के पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निर्मित की गई एक विशाल योजना है।

13. (C) इसके मार्ग में बिना सिंचाई किए न्यूनतम जल हानि के साथ मुख्य नहर तक जल पहुँचाना।
राजस्थान फीडर नहर का मुख्य उद्देश्य हरिके बैराज से पानी को बिना किसी मध्यवर्ती रिसाव, वाष्पीकरण हानि या सिंचाई उपयोग के सीधे मुख्य कमान क्षेत्र तक पहुँचाना है। 204 किलोमीटर लंबी यह नहर पूर्णतः पक्की बनाई गई है ताकि जल की क्षति न्यूनतम हो। पंजाब और हरियाणा में इसमें से कोई सिंचाई नहीं की जाती है। यह केवल जल परिवहन करती है।

14. (D) रावतसर शाखा
इंदिरा गांधी नहर की नौ प्रमुख शाखाओं में से केवल रावतसर शाखा ही ऐसी एकमात्र शाखा है जो मुख्य नहर के बाएँ तट से निकलती है। मुख्य नहर के बाएँ भाग की ऊँचाई अधिक है, परंतु हनुमानगढ़ जिले का यह क्षेत्र ढलानयुक्त होने से गुरुत्वाकर्षण द्वारा सिंचित होता है। शेष आठ शाखाएँ दाहिने तट पर स्थित हैं। यह एक अपवाद है।

15. (A) I, II और III
इंदिरा गांधी नहर के कमान क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई के कारण निचले इलाकों में गंभीर जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई है। इसके साथ ही उच्च वाष्पीकरण तथा केशिका क्रिया के कारण मृदा का लवणीकरण बढ़ा है। कृषि विस्तार से प्राकृतिक घास के मैदान नष्ट हुए हैं, जिससे मरुस्थलीय जीवों के प्राकृतिक आवासों को भारी क्षति पहुँची है। यह चिंताजनक विषय है।

16. (B) गंभीर जलभराव के कारण पारिस्थितिक क्षरण
कमान क्षेत्र में "सेम" की समस्या का तात्पर्य नहरों से जल के रिसाव और अत्यधिक सिंचाई के कारण भूजल स्तर के ऊपर उठने से उत्पन्न गंभीर जलभराव से है। इसके परिणामस्वरुप भूमि दलदली हो जाती है और मृदा में लवणता बढ़ जाती है। यह स्थिति कृषि योग्य भूमि को अनुपजाऊ बना देती है तथा पारिस्थितिकी को भारी क्षति पहुँचाती है।

17. (B) उप-सतह में जिप्सम की कठोर परत (हार्डपैन) की उपस्थिति
हनुमानगढ़ और बीकानेर जैसे जिलों की भूगर्भिक बनावट में भूमि की उप-सतह पर जिप्सम की एक कठोर अभेद्य परत पाई जाती है। जब नहरों और खेतों से जल का रिसाव होता है, तो यह परत जल को नीचे जाने से रोकती है। इसके कारण जल सतह पर ही एकत्र होने लगता है और जलभराव तथा सेम की समस्या बढ़ाता है।

18. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों के पूर्व नामों का पुनर्नामकरण किया गया है। बीकानेर-लूणकरणसर लिफ्ट नहर को अब कंवर सैन लिफ्ट नहर कहा जाता है। गजनेर लिफ्ट नहर को पन्नालाल बारुपाल, फलोदी को गुरु जंभेश्वर तथा पोकरण लिफ्ट नहर को जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर नाम दिया गया है। इन लिफ्ट नहरों द्वारा शुष्क क्षेत्रों को निरंतर जल उपलब्ध कराया जाता है।

19. (B) 7
इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाएँ तट पर स्थित अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पेयजल तथा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्य रुप से 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। इन लिफ्ट नहरों के माध्यम से जल को पंप करके ऊँचा उठाया जाता है। ये लिफ्ट नहरें पश्चिमी राजस्थान के विभिन्न शुष्क जिलों की प्रमुख जीवनरेखा बनी हुई हैं।

20. (D) कंवर सैन लिफ्ट नहर
कंवर सैन लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे पहली और सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। यह मुख्य रुप से बीकानेर जिले की कृषि भूमि की सिंचाई करने के साथ-साथ बीकानेर शहर तथा आसपास के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों को पीने का स्वच्छ जल प्रदान करती है। इस लिफ्ट नहर ने क्षेत्रीय सामाजिक व आर्थिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

21. (C) जोधपुर
राजीव गांधी लिफ्ट नहर का निर्माण मुख्य रुप से जोधपुर शहर और उसके आसपास के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मंडराते गंभीर पेयजल संकट का स्थायी समाधान करने हेतु किया गया था। यह नहर इंदिरा गांधी मुख्य नहर से जल प्राप्त करती है। इस परियोजना से जोधपुर शहर को वर्ष भर स्वच्छ पेयजल की निर्बाध आपूर्ति निरंतर सुनिश्चित होती रहती है।

22. (B) अत्यधिक नमी के कारण कमान क्षेत्र में फसल सघनता में भारी कमी आई है।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आगमन से थार मरुस्थल में कृषि परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। नियमित जलापूर्ति के कारण कमान क्षेत्र में फसल सघनता में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। किसान अब वर्ष में कई फसलें उगाने लगे हैं। जीवन-निर्वाह खेती का स्थान गेहूँ, सरसों तथा कपास जैसी व्यावसायिक फसलों ने ले लिया है। यह एक बड़ा बदलाव है।

NODIA

23. (D) केवल I और III
इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने पश्चिमी राजस्थान में योजनाबद्ध कृषि बस्तियों की स्थापना को बढ़ावा दिया, जिन्हें स्थानीय स्तर पर "चक" कहा जाता है। सिंचित कृषि के विस्तार से कमान क्षेत्र में कृषि भूमि के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई। जलापूर्ति और रोजगार के अवसरों से पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में किसानों

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) सतलुज और ब्यास
पंजाब के फिरोजपुर जिले में स्थित हरिके बैराज का निर्माण सतलुज और ब्यास नदियों के पवित्र संगम पर किया गया है। यह स्थान उत्तर-पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणालियों में से एक को जल आपूर्ति प्रदान करने का मुख्य आधार है। इन नदियों से प्राप्त हिमालयी जल को राजस्थान फीडर नहर के माध्यम से थार मरुस्थल तक पहुँचाया जाता है। यह संगम जीवनदायिनी सिद्ध हुआ है।

2. (C) 1984
इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मूल रुप से राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात उनकी स्मृति का सम्मान करने के उद्देश्य से 2 नवंबर 1984 को इस नहर का नाम आधिकारिक रुप से परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। यह परियोजना मरुस्थलीय भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक सिद्ध हुई है।

3. (C) कंवर सैन
बीकानेर राज्य के तत्कालीन मुख्य अभियंता कंवर सैन को इस महान नहर प्रणाली का मुख्य सूत्रधार तथा परिकल्पनाकार माना जाता है। उन्होंने वर्ष 1948 में अपनी ऐतिहासिक तकनीकी रिपोर्ट के माध्यम से हिमालय की नदियों के जल को राजस्थान के शुष्क थार मरुस्थल तक लाने का विस्तृत खाका तैयार किया था। उनकी दूरदर्शी योजना ने मरुस्थलीय क्षेत्र का कायाकल्प करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

4. (D) वाटर रिक्वायरमेंट्स इन बीकानेर स्टेट
इंजीनियर कंवर सैन ने वर्ष 1948 में "वाटर रिक्वायरमेंट्स इन बीकानेर स्टेट" शीर्षक से एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस रिपोर्ट में बीकानेर राज्य और आसपास के शुष्क क्षेत्रों में गंभीर पेयजल एवं सिंचाई संकट का स्थायी समाधान प्रस्तुत करने हेतु सतलुज व ब्यास नदियों के अतिरिक्त जल को लाने का सुझाव दिया गया था। यही दस्तावेज नहर का मुख्य आधार बना।

5. (B) 204 किमी
हरिके बैराज से मुख्य नहर के शुरुआती बिंदु तक जल पहुँचाने वाली राजस्थान फीडर नहर की कुल लंबाई 204 किलोमीटर है। इस फीडर नहर का प्राथमिक उद्देश्य बिना किसी जल निष्कर्षण अथवा मध्यवर्ती सिंचाई के पानी को तेजी से और न्यूनतम रिसाव हानि के साथ राजस्थान की सीमा तक पहुँचाना है। इसमें से 170 किलोमीटर भाग पंजाब व हरियाणा में स्थित है।

6. (A) पंजाब → हरियाणा → राजस्थान
इंदिरा गांधी नहर प्रणाली में जल का प्रवाह पंजाब राज्य के फिरोजपुर में स्थित हरिके बैराज से प्रारंभ होता है। इसके पश्चात जल राजस्थान फीडर के माध्यम से पंजाब के मैदानी भागों तथा हरियाणा के कुछ हिस्सों से गुजरते हुए अंततः राजस्थान राज्य की सीमा में प्रवेश करता है। इस प्रकार जल प्रवाह का क्रम पंजाब, हरियाणा और फिर राजस्थान है।

7. (D) हनुमानगढ़ जिले में मसीतावाली हेड
पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों से प्रवाहित होने के पश्चात राजस्थान फीडर नहर राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित मसीतावाली हेड पर प्रवेश करती है। मसीतावाली हेड वह रणनीतिक बिंदु है जहाँ 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर समाप्त होती है और यहाँ से मुख्य नहर प्रारंभ होती है। यह स्थल जल वितरण नियंत्रण हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।

8. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
इंदिरा गांधी मुख्य नहर के बाएँ अर्थात् पूर्वी भाग की भौगोलिक बनावट और धरातलीय ऊँचाई अधिक होने के कारण जल का प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण प्रवाह संभव नहीं है। इस तकनीकी समस्या के समाधान हेतु सभी सात लिफ्ट नहरों का निर्माण बाएँ तट पर किया गया है ताकि पानी को ऊँचे क्षेत्रों तक पहुँचाया जा सके। दायाँ तट ढलानयुक्त होने से स्वतः बहता है।

9. (B) 445 किमी
इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर मसीतावाली हेड से प्रारंभ होकर जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ तक विस्तृत है, जिसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। यदि इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर को भी जोड़ दिया जाए, तो संपूर्ण प्रणाली की लंबाई 649 किलोमीटर हो जाती है। यह मुख्य नहर मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल आपूर्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार बनी हुई है।

10. (A) बाड़मेर में गडरारोड
इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर का अंतिम बिंदु मोहनगढ़ से आगे बढ़ाकर बाड़मेर जिले के गडरारोड तक कर दिया गया है। बाबा रामदेव उप-शाखा के माध्यम से गडरारोड तक जल पहुँचाने के कारण यह स्थान इस नहर का ज़ीरो पॉइंट कहलाता है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में पेयजल सुविधा का विस्तार संभव हो सका है।

11. (D) केवल I और III
इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में मुख्य रुप से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों के समतल भागों को शामिल किया गया था। इस चरण का भूभाग अपेक्षाकृत कम उबड़-खाबड़ था, जिसके कारण अधिकांश क्षेत्र में पानी

Click Here to Buy book on Flipkart

फिर वितरिकाओं तथा माइनर से होता हुआ अंततः जलमार्गों के माध्यम से खेतों तक पहुँचता है। यह एक अत्यधिक सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक जल वितरण ढाँचा माना जाता है।

36. (D) गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड)
राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण शुष्क एवं खुले घास के मैदानों का मूल निवासी है। इंदिरा गांधी नहर के आगमन से इन शुष्क क्षेत्रों का कृषि भूमि में परिवर्तन हो गया। इस आवास क्षरण और पारिस्थितिक बदलाव के कारण गोडावण के प्राकृतिक प्रजनन स्थलों को भारी क्षति पहुँची है, जिससे इनकी संख्या में अत्यंत तीव्र कमी दर्ज की गई है।

37. (C) हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू
चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट नहर, जिसे पहले नोहर-साहवा लिफ्ट नहर कहा जाता था, मुख्य रूप से हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिलों को लाभान्वित करती है। यह लिफ्ट नहर इन क्षेत्रों में कृषि सिंचाई के साथ-साथ पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान करती है। इसके माध्यम से सैकड़ों गांवों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाता है। यह एक वरदान सिद्ध हुई है।

38. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
इंदिरा गांधी नहर की विभिन्न शाखाएँ संबंधित जिलों में जल प्रवाहित करती हैं। सूरतगढ़ शाखा श्रीगंगानगर जिले में, पूगल शाखा बीकानेर में, सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर में तथा रावतसर शाखा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इन शाखाओं के माध्यम से संपूर्ण कमान क्षेत्र में कृषि तथा पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति सुचारु रूप से की जाती है। यह एक व्यापक प्रणाली है।

39. (D) मरुस्थलीकरण और बालुका स्तूपों के प्रसार पर रोक
इंदिरा गांधी नहर परियोजना का थार मरुस्थल पर सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव मरुस्थलीकरण की गति को रोकना तथा गतिशील बालुका स्तूपों के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण लगाना है। नहर के किनारे किए गए व्यापक वृक्षारोपण, चारागाह विकास और कृषि विस्तार से मृदा अपरदन में भारी कमी आई है और पर्यावरण में स्थिरता प्राप्त हुई है। यह एक वरदान सिद्ध हुआ है।

40. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन को समाप्त नहीं किया है, बल्कि इसे डेयरी विकास के साथ जोड़ा है। कमान क्षेत्र में सिंचित कृषि के विस्तार से फसल प्रारूप में बदलाव आया है। पारंपरिक फसलों का स्थान अब कपास, मूंगफली तथा सरसों जैसी व्यावसायिक नकदी फसलों ने ले लिया है। इससे किसानों की आय में भारी वृद्धि हुई है।

41. (C) डॉ. करणी सिंह लिफ्ट नहर
कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम डॉ. करणी सिंह लिफ्ट नहर रखा गया है। यह लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी मुख्य नहर से जल प्राप्त करके मुख्य रूप से बीकानेर और जोधपुर जिलों के शुष्क क्षेत्रों को सिंचाई तथा पेयजल सुविधा प्रदान करती है। बीकानेर के पूर्व महाराजा डॉ. करणी सिंह की स्मृति में यह नामकरण किया गया है। यह महत्वपूर्ण नहर है।

42. (A) I, II और IV
इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में जलभराव से निपटने के लिए सफेदा के पौधे लगाकर जैव-जल निकासी बढ़ाना, उप-सतही जल निकासी नेटवर्क बनाना तथा फव्वारा व सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का उपयोग करना सबसे प्रभावी उपाय हैं। सिंचाई हेतु जल की मात्रा बढ़ाना इस समस्या को अधिक गंभीर बना सकता है, इसलिए जल का नियंत्रित प्रयोग ही वैज्ञानिक समाधान माना जाता है।

43. (D) गुजरात
हरिके बैराज सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित जल ढाँचा है, जिसके जल-बँटवारे में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान भागीदार हैं। गुजरात राज्य इस प्रणाली का हिस्सा नहीं है, क्योंकि गुजरात को नर्मदा जल विवाद अधिकरण के तहत नर्मदा नदी से जल प्राप्त होता है, न कि हरिके बैराज से। यह एक स्पष्ट भौगोलिक विभाजन है।

44. (B) केवल I और III
इंदिरा गांधी नहर परियोजना मरुस्थलीय पर्यावरण में निर्मित विश्व की सबसे विशाल नहर प्रणालियों में से एक है। जल रिसाव को रोकने हेतु मुख्य नहर को पूर्णतः पक्का बनाया गया है। जैसलमेर और बाड़मेर की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों तथा विशाल बालुका स्तूपों के कारण परियोजना का द्वितीय चरण अत्यधिक चुनौतीपूर्ण एवं जटिल सिद्ध हुआ था। यह एक महान अभियांत्रिकी उपलब्धि है।

45. (C) 1.96 मिलियन हेक्टेयर
इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सकल कमान क्षेत्र लगभग 1.96 मिलियन हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। यह विशाल क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान के विभिन्न मरुस्थलीय जिलों में फैला हुआ है। इस परियोजना का लक्ष्य इस विस्तृत भूभाग को सिंचाई तथा स्वच्छ पेयजल सुविधाओं के अंतर्गत लाकर क्षेत्र का समग्र आर्थिक एवं सामाजिक कायाकल्प करना रहा है। यह एक विशाल लक्ष्य है।

46. (D) पोकरण लिफ्ट नहर
जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर का पूर्व नाम पोकरण लिफ्ट नहर था। राजस्थान के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के नाम पर इसका नामकरण किया गया। यह लिफ्ट नहर मुख्य रूप से जैसलमेर तथा जोधपुर जिलों के शुष्क ग्रामीण क्षेत्रों को सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति प्रदान करती है। इससे क्षेत्रीय जल संकट का निवारण सफलता से हुआ है।

47. (A) जल रिसाव को कम करने हेतु मुख्य नहर और प्रमुख शाखाओं को पक्का (lined) किया गया है।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य विशेषता जल रिसाव तथा नुकसान को न्यूनतम करना है। इसके लिए मुख्य नहर, फीडर नहर और प्रमुख शाखाओं को सीमेंट एवं टाइलों से

NODIA

का अंतःप्रवासन हुआ। यह एक ऐतिहासिक परिवर्तन साबित हुआ।

24. (A) सिंधु जल संधि (1960)
वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के अंतर्गत पूर्वी नदियों के जल पर भारत को पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ। इस संधि के तहत प्राप्त जल का उपयोग करते हुए रावी और ब्यास नदियों का जल राजस्थान नहर परियोजना हेतु आवंटित किया गया। इस ऐतिहासिक समझौते ने मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थायी जलापूर्ति की नींव रखी।

25. (C) सेवण घास
थार मरुस्थल की प्राकृतिक वनस्पति में सेवण घास एक अत्यंत पौष्टिक देशी घास है, जो कम वर्षा और शुष्क परिस्थितियों में पनपती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण मिट्टी में नमी बढ़ने तथा कृषि विस्तार के चलते सेवण घास के प्राकृतिक चरागाहों का भारी नुकसान हुआ है। इससे मरुस्थलीय जैव विविधता एवं पारंपरिक पशुपालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

26. (A) 1, 2, 3, 4
इंदिरा गांधी मुख्य नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही भौगोलिक अनुक्रम सूरतगढ़ शाखा, पूगल शाखा, दंतौर शाखा तथा सागरमल गोपा शाखा है। यह क्रम मुख्य नहर के प्रवाह की दिशा का अनुकरण करता है, जो उत्तर में श्रीगंगानगर से प्रारंभ होकर दक्षिण-पश्चिम में जैसलमेर की ओर बढ़ता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण भौगोलिक क्रम माना जाता है।

27. (D) चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू के गांवों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करना।
"आपणी योजना" जर्मनी की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से प्रारंभ की गई एक पेयजल परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग करके चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू जिलों के अनेक मरुस्थलीय गांवों में शुद्ध पेयजल पहुँचाना है। इस योजना ने फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ जल की उपलब्धता को सुनिश्चित किया है। यह एक सफल मॉडल है।

28. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
थार मरुस्थल की तीव्र वाष्पीकरण दर तथा अत्यधिक सिंचाई के कारण भूजल स्तर में वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप केशिका क्रिया द्वारा भूगर्भ में मौजूद घुलनशील लवण जल के साथ मिट्टी की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। जल के वाष्पीकृत होने पर लवण की परत जम जाती है, जिससे द्वितीयक लवणीकरण की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। यह हानिकारक प्रक्रिया है।

29. (C) रावी और ब्यास नदियों के अधिशेष जल के आवंटन का पुनः परीक्षण करना
वर्ष 1986 में गठित न्यायमूर्ति वी. इराडी आयोग का मुख्य उद्देश्य रावी और ब्यास नदियों के अधिशेष जल के अंतरराज्यीय बंटवारे का पुनः परीक्षण करना था। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच जल दावों का मूल्यांकन करके इस आयोग ने इंदिरा गांधी नहर हेतु जल की उपलब्धता को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह एक प्रमुख न्यायिक निकाय था।

30. (D) बीकानेर
इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर का सबसे बड़ा भाग बीकानेर जिले में स्थित है। बीकानेर जिले की भौगोलिक स्थिति और विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र को देखते हुए मुख्य नहर की सर्वाधिक लंबाई इसी जिले के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त यहाँ कई लिफ्ट नहरें भी निर्मित की गई हैं, जो जलापूर्ति को सुनिश्चित बनाती हैं। यह प्रमुख केंद्र है।

NODIA

31. (A) I, II और IV
इंदिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण में अत्यधिक उबड़-खाबड़ भूभाग, विशाल स्थानांतरित बालुका स्तूप तथा उच्च ऊर्जा लागत वाली लिफ्ट प्रणाली जैसी कठिन चुनौतियाँ मौजूद थीं। रेतीले तूफानों से नहर में गाद जमा होना भी मुख्य बाधा थी। जनघनत्व कम होने से भू-अधिग्रहण यहाँ कोई बड़ी समस्या नहीं था। निर्माण कार्य अत्यंत जटिल तथा खर्चीला सिद्ध हुआ था। यह चुनौतीपूर्ण रहा।

32. (B) न्यायसंगत जल वितरण और भूमि समतलीकरण सुनिश्चित करना।
कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सृजित सिंचाई क्षमता का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना था। इसके अंतर्गत जल का न्यायसंगत वितरण, भूमि समतलीकरण, खेतों तक पक्की नालियों का निर्माण तथा जल प्रबंधन जैसे कार्य शामिल थे। इस पहल ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और जल की बर्बादी को रोकने में अत्यधिक सहायता प्रदान की। यह एक सफल नीति थी।

33. (B) रावतसर शाखा
इंदिरा गांधी मुख्य नहर के सापेक्ष स्थिति के आधार पर रावतसर शाखा अन्य शाखाओं से भिन्न है। रावतसर शाखा मुख्य नहर के बाएँ तट से निकलने वाली एकमात्र शाखा है, जबकि सूरतगढ़, अनूपगढ़ और पूगल शाखाएँ मुख्य नहर के दाहिने तट पर स्थित हैं। यह भौगोलिक बनावट और भूमि के ढलान के कारण निर्मित हुआ एक विशिष्ट अपवाद माना गया है।

34. (A) एक जलमार्ग (आउटलेट) द्वारा सिंचित भूमि का खंड
इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कमान क्षेत्र में "चक" शब्द एक विशिष्ट जल-प्रबंधन इकाई को दर्शाता है। यह किसी एक जलमार्ग अथवा आउटलेट द्वारा सिंचित किए जाने वाले कृषि भूमि के खंड को संदर्भित करता है। इसी चक के आधार पर किसानों के बीच जल का न्यायसंगत बंटवारा तथा वारबंदी प्रणाली लागू की जाती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है।

35. (B) मुख्य नहर → शाखा → वितरिका → माइनर → जलमार्ग
इंदिरा गांधी नहर प्रणाली में जल वितरण का अवरोही क्रम इस प्रकार है: मुख्य नहर, शाखा, वितरिका, माइनर और अंत में जलमार्ग। जल सबसे पहले मुख्य नहर से शाखाओं में बहता है,

60. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
इंदिरा गांधी नहर ने लूनी नदी के प्रवाह को परिवर्तित नहीं किया है, क्योंकि लूनी एक पृथक नदी प्रणाली है। हालाँकि, यह नहर पंजाब की सतलुज और ब्यास नदियों का जल हिमालयी क्षेत्रों से थार मरुस्थल में लाती है, जो इसके अपने अपवाह बेसिन के बाहर का स्रोत है। यह अंतर-बेसिन जल स्थानांतरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है।

61. (C) आर्द्रता वृद्धि एवं समोद्भिद (मेसोफाइटिक) वनस्पतियों द्वारा मूल शुष्क आवास में परिवर्तन
इंदिरा गांधी नहर के जल प्रवाह से वातावरण और मृदा की नमी में भारी वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप पारंपरिक मरुस्थलीय वनस्पतियों का स्थान आर्द्रता-प्रिय समोद्भिद पौधों ने ले लिया है। इस परिवर्तन ने थार के मूल शुष्क पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित किया है, जिससे स्थानीय मरुस्थलीय प्रजातियों के प्राकृतिक आवास में बदलाव आया है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है।

62. (D) केवल I और III
इंदिरा गांधी नहर के रखरखाव में मरुस्थलीय हवाओं द्वारा बहकर आने वाली रेत का जमाव एक मुख्य चुनौती है। ग्रीष्मकाल में नहर में रेत भर जाने से निरंतर गाद सफाई की आवश्यकता होती है। साथ ही, जलीय खरपतवारों के तेजी से पनपने के कारण वितरिकाओं में जल प्रवाह में रुकावट आती है। यह निरंतर ध्यान देने योग्य समस्या बनी हुई है।

63. (A) जैसलमेर
चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट नहर मुख्य रूप से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर जिलों को जल उपलब्ध कराती है। जैसलमेर जिला इस लिफ्ट नहर के कमान क्षेत्र में शामिल नहीं है। जैसलमेर को जल आपूर्ति मुख्य रूप से सागरमल गोपा शाखा, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर तथा बाबा रामदेव उप-शाखा के माध्यम से प्रदान की जाती है। यह एक भिन्न क्षेत्र है।

64. (B) पूगल
इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत मुख्य नहर का निर्माण हनुमानगढ़ के मसीतावाली हेड से बीकानेर जिले के पूगल तक किया गया था। इसलिए प्रथम चरण का अंतिम बिंदु पूगल ही माना जाता है। इसके बाद द्वितीय चरण में मुख्य नहर को पूगल से आगे मोहनगढ़ तक विस्तारित किया गया था। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण चरण सीमा है।

65. (B) दलहनी फसलों के साथ फसल चक्र अपनाना तथा सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का उपयोग करना
कमान क्षेत्र में बढ़ती मृदा लवणीकरण और जलभराव की समस्या से निपटने हेतु सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों जैसे फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही दलहनी फसलों के साथ फसल चक्र अपनाने की सलाह दी जाती है। यह उपाय जल की बचत करने के साथ-साथ मृदा की उपजाऊ क्षमता को पुनर्स्थापित करने में सहायक हैं।

66. (A) गुरु जंभेश्वर लिफ्ट नहर
फलोदी लिफ्ट नहर का नया नामकरण संत गुरु जंभेश्वर के नाम पर "गुरु जंभेश्वर लिफ्ट नहर" किया गया है। यह लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी मुख्य नहर से जल प्राप्त करती है। यह जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों के शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों को सिंचाई तथा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करती है। इससे क्षेत्रीय विकास को अत्यधिक गति प्राप्त हुई है। यह उपयोगी है।

67. (C) 204 किमी फीडर नहर और 445 किमी मुख्य नहर
इंदिरा गांधी नहर प्रणाली की कुल 649 किलोमीटर लंबाई दो मुख्य भागों में विभाजित है। प्रथम भाग 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर नहर है जो हरिके बैराज से मसीतावाली हेड तक आती है। द्वितीय भाग 445 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर है जो मसीतावाली हेड से मोहनगढ़ तक विस्तृत है। इन दोनों का योग 649 किलोमीटर होता है। यह विशाल संरचना है।

68. (D) I, III और IV
इंदिरा गांधी नहर के कारण कमान क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि उपज के व्यापार हेतु अनेक नए मंडी कस्बों का तेजी से विकास हुआ है। सिंचित भूमि के बाजार मूल्य में अत्यधिक उछाल आया है। घुमंतू पशुपालक स्थायी कृषि एवं सम्बद्ध व्यवसायों में अपना स्थान बना चुके हैं। यह एक सकारात्मक सामाजिक बदलाव है।

69. (C) इसका नया नाम वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है, जो बीकानेर जिले को जल उपलब्ध कराती है।
बांगड़सर लिफ्ट नहर का नया नाम बदलकर लोक देवता तेजाजी के सम्मान में "वीर तेजाजी लिफ्ट नहर" कर दिया गया है। यह लिफ्ट नहर मुख्य रूप से बीकानेर जिले के शुष्क ग्रामीण क्षेत्रों को पीने का पानी तथा सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। यह परियोजना बीकानेर के सीमित भूभाग में जल संकट दूर करने में अत्यंत सहायक साबित हुई है।

70. (B) इसने घुमंतू पशुपालन को एकीकृत पशुधन एवं मिश्रित कृषि में परिवर्तित कर दिया।
नहर के निर्माण से पूर्व पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से घुमंतू पशुपालन पर आधारित थी। नहर से वर्ष भर जल और हरे चारे की उपलब्धता होने के कारण पशुपालक स्थायी रूप से बस गए। इससे पारंपरिक घुमंतू प्रथा एकीकृत पशुधन प्रबंधन, मिश्रित कृषि और संगठित डेयरी व्यवसाय में परिवर्तित हो गई है। यह एक महान आर्थिक रूपांतरण है।

71. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जल संकट के कारण पूर्व में आबादी अत्यंत विरल थी। इंदिरा गांधी नहर से जल मिलने से वहाँ स्थायी नागरिक बस्तियाँ, मार्ग तथा सैन्य ढाँचा विकसित हो सका। सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय स्थायित्व और नागरिक उपस्थिति ने सीमाओं की चौकसी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह एक रणनीतिक उपलब्धि है।

Downloaded from www.pdf.tube

पूर्णतः पक्का बनाया गया है। यह पक्का निर्माण रेतीली मिट्टी में जल के रिसाव को रोकता है और अंतिम छोर तक पानी का सुचारु प्रवाह सुनिश्चित करता है। यह एक मुख्य ढांचा है।

48. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
नहर के आगमन से पूर्व यह क्षेत्र शुष्क था जहाँ मच्छरों का पनपना कठिन था। परंतु इंदिरा गांधी नहर में बारहमासी जल प्रवाह तथा जलभराव के कारण मच्छरों के प्रजनन हेतु अनुकूल माहौल बन गया। इसके परिणामस्वरूप कमान क्षेत्र के निवासियों में मलेरिया जैसी जलजनित बीमारियों के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। यह स्वास्थ्य संबंधी एक चुनौती बनी है।

49. (B) नर्मदा लिफ्ट नहर
नर्मदा लिफ्ट नहर नर्मदा नदी परियोजना से संबंधित है, जो राजस्थान के जालोर तथा बाड़मेर जिलों को सिंचित करती है। यह इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट प्रणाली का हिस्सा नहीं है। इसके विपरीत, गुरु जंभेश्वर, वीर तेजाजी और जयनारायण व्यास लिफ्ट नहरें इंदिरा गांधी नहर की ही स्वीकृत लिफ्ट नहरें हैं। यह एक पूर्णतः भिन्न जल परियोजना मानी जाती है।

50. (A) बाबा रामदेव उप-शाखा
इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विस्तार को जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ से आगे बाड़मेर के गडरारोड तक बढ़ाया गया है, जिसे बाबा रामदेव उप-शाखा के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव के नाम पर निर्मित यह उप-शाखा सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों को सिंचाई तथा पेयजल उपलब्ध कराती है। इससे जनजीवन में व्यापक सुधार दर्ज किया गया है।

51. (C) I, II और IV
इंदिरा गांधी नहर बीकानेर और जोधपुर शहरों के लिए पेयजल का प्राथमिक सतही स्रोत है। इसके अतिरिक्त, पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से यह दूरस्थ मरुस्थलीय गांवों तक पीने का पानी पहुँचाती है। हालाँकि, इसका दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वहाँ की जल व्यवस्था स्थानीय स्रोतों पर ही निर्भर करती है। यह एक सत्य तथ्य है।

52. (D) मरुस्थलीय कमान क्षेत्र तक जल पहुँचाने में जल की हानि को रोकना तथा प्रवाह गति बनाए रखना।
हरिके बैराज से मुख्य कमान क्षेत्र की दूरी अत्यधिक होने से सीधे सिंचाई नहरें निकालने पर भारी जल हानि होती। अतः राजस्थान फीडर नहर को एक पक्की बंद प्रणाली के रूप में बनाया गया ताकि रास्ते में रिसाव और वाष्पीकरण न हो तथा जल बिना किसी रुकावट के सीधे राजस्थान के कमान क्षेत्र तक पहुँच सके। यह एक रणनीतिक निर्णय था।

53. (C) 1990 का दशक
इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण का निर्माण कार्य, जिसमें फीडर नहर, मुख्य नहर का उत्तरी भाग तथा प्रथम लिफ्ट नहर शामिल थी, मुख्य रूप से 1990 के दशक में पूरा हुआ। इस चरण के पूर्ण होने से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में सिंचित कृषि का अभूतपूर्व विस्तार संभव हो सका था। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था।

54. (B) रावतसर शाखा - दायाँ तट
रावतसर शाखा इंदिरा गांधी मुख्य नहर के दाएँ तट पर नहीं, बल्कि बाएँ तट से निकलने वाली एकमात्र शाखा है। सूरतगढ़, अनूपगढ़ और बीरसलपुर शाखाएँ मुख्य नहर के दाहिने तट पर ही निर्मित की गई हैं। दाहिना तट ढलानयुक्त होने के कारण वहाँ जल का गुरुत्वाकर्षण प्रवाह आसानी से संभव हो पाता है। यह एक मुख्य अंतर माना जाता है।

55. (A) 2, 4, 1, 3
इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी घटनाओं का सही कालानुक्रम इस प्रकार है: सबसे पहले 1948 में कंवर सैन ने अपनी रिपोर्ट दी। इसके पश्चात हरिके बैराज का निर्माण शुरु हुआ। वर्ष 1960 में सिंधु जल संधि संपन्न हुई और अंत में 1984 में नहर का नया नामकरण किया गया। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विकास क्रम को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है।

56. (A) मुख्य नहर के पूर्व एवं दक्षिण की भूमि का स्तर गुरुत्वाकर्षण प्रवाह की तुलना में ऊँचा है।
इंदिरा गांधी मुख्य नहर के पूर्वी तथा बाएँ तट का धरातल मुख्य नहर के जल-स्तर की तुलना में काफी ऊँचा है। इस ऊँचाई के कारण पानी का स्वाभाविक गुरुत्वाकर्षण बहाव संभव नहीं हो पाता था। इस भौगोलिक विषमता को दूर करने हेतु लिफ्ट नहर प्रणाली अपनाई गई, जिसमें जल को पंपों द्वारा ऊँचा उठाकर वितरित किया जाता है। यह आवश्यक था।

57. (C) कपास
इंदिरा गांधी नहर द्वारा निरंतर जलापूर्ति होने से श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में कृषि ढाँचा बदल गया। पारंपरिक शुष्क खाद्यान्न के स्थान पर अधिक जल चाहने वाली नकदी फसल कपास के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। ये जिले अब राज्य के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र बन चुके हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में भारी सुधार हुआ है। यह प्रमुख उपलब्धि है।

NODIA

58. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
नहर परियोजना से संबंधित पारिभाषिक शब्दों का सही मिलान इस प्रकार है: "सेम" अत्यधिक जलभराव एवं मृदा क्षरण की स्थिति है, "हार्डपैन" उप-सतह की अभेद्य जिप्सम परत है, "चक" एक जलमार्ग द्वारा सिंचित क्षेत्र है, तथा "कमान क्षेत्र" सिंचाई हेतु उपयुक्त सम्पूर्ण भूभाग होता है। ये सभी अवधारणाएँ जल प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यह एक सटीक विवरण है।

59. (D) कंवर सैन लिफ्ट नहर
बीकानेर-लूणकरणसर लिफ्ट नहर इस परियोजना की प्रथम लिफ्ट नहर थी। इसका वर्तमान नाम इस योजना के मुख्य सूत्रधार इंजीनियर कंवर सैन के सम्मान में "कंवर सैन लिफ्ट नहर" रखा गया है। यह नहर बीकानेर जिले में कृषि विकास तथा पेयजल आपूर्ति का मुख्य जरिया बनी हुई है। इसने क्षेत्रीय खुशहाली में ऐतिहासिक योगदान दिया है। यह एक प्रमुख उपलब्धि है।

(C) राजीव गांधी लिफ्ट नहर
(D) कंवर सैन लिफ्ट नहर

73. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जल स्रोत के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए:
(A) यह सिंधु जल संधि के प्रावधानों के अनुसार जल आबंटन प्राप्त करती है।
(B) हरिके बैराज सतलुज और ब्यास के संगम के निचले प्रवाह में स्थित है।
(C) इसका जल प्रवाह केवल स्थानीय मानसूनी वर्षा पर निर्भर है।
(D) हिमालय के हिमनदों का पिघलना नदियों में बारहमासी जल प्रवाह सुनिश्चित करता है।

74. थार क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन-सा कृषि परिवर्तन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का परिणाम नहीं है?
(A) यांत्रिक कृषि के स्थान पर पारंपरिक बैल-जुताई को बढ़ावा मिलना
(B) रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का व्यापक उपयोग
(C) शुष्क फसलों के स्थान पर अधिक जल-मांग वाली नकदी फसलों को अपनाना
(D) जीवन-निर्वाह कृषि से व्यावसायिक फल/बागवानी कृषि की ओर परिवर्तन

75. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण पूर्णतः ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा किया गया था।
कथन II: इस परियोजना के निर्माण में अत्यधिक लागत वृद्धि और विलंब हुआ, जिससे यह कई दशकों तक चली।
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

76. सूची I की लिफ्ट नहरों को सूची II के संबंधित लाभार्थी जिलों से सुमेलित कीजिए:
सूची I: लिफ्ट नहर
P. कंवर सैन लिफ्ट नहर
Q. राजीव गांधी लिफ्ट नहर
R. पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर
S. जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर
सूची II: लाभार्थी जिला
1. जोधपुर
2. बीकानेर, नागौर
3. बीकानेर
4. जैसलमेर, जोधपुर
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-1, R-2, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

77. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के मार्ग की स्थलाकृति का सबसे सटीक विवरण कौन-सा है?
(A) उपजाऊ जलोढ़ मैदान
(B) अत्यधिक उबड़-खाबड़ पहाड़ी भूभाग
(C) विरली वनस्पति वाले स्थानांतरित बालुका स्तूपों का विशाल क्षेत्र
(D) तटीय दलदली क्षेत्र

78. राजस्थान फीडर नहर की कुल 204 किमी लंबाई में से कितना भाग राजस्थान में प्रवेश करने से पूर्व पंजाब तथा हरियाणा से होकर बहता है?
(A) 34 किमी
(B) 100 किमी
(C) 170 किमी
(D) 204 किमी

79. इंदिरा गांधी नहर बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) नहर परियोजना के निर्माण, कार्यान्वयन एवं प्रबंधन की देखरेख करना
(B) सीमा सुरक्षा अभियानों का संचालन करना
(C) कृषि उपज के निर्यात का प्रबंधन करना
(D) अंतर्राष्ट्रीय जल समझौतों पर बातचीत करना

80. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक स्थायित्व (सस्टेनेबिलिटी) चुनौती कौन-सी है?
(A) सतलुज नदी का पूर्णतः सूखना
(B) शुष्क पर्यावरण में जलभराव, मृदा लवणीकरण एवं जल निकासी का प्रबंधन
(C) हरिके बैराज का क्षतिग्रस्त होना
(D) कमान क्षेत्र से जनसंख्या का पलायन

Click Here to Buy book on Amazon

72. (A) बाबा रामदेव उप-शाखा
बाड़मेर जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम छोर पर स्थित है। मुख्य नहर के मोहनगढ़ से गडरारोड तक विस्तारित भाग को बाबा रामदेव उप-शाखा कहा जाता है। यह उप-शाखा बाड़मेर जिले के शुष्क मरुस्थलीय इलाकों, सीमावर्ती गांवों तथा औद्योगिक इकाइयों को पीने का पानी एवं औद्योगिक जल उपलब्ध कराती है। यह बाड़मेर की मुख्य जीवनदायिनी जलधारा बनी हुई है।

73. (C) इसका जल प्रवाह केवल स्थानीय मानसूनी वर्षा पर निर्भर है।
इंदिरा गांधी नहर का जल प्रवाह केवल स्थानीय मानसूनी वर्षा पर निर्भर नहीं है। इस नहर को हिमालय से निकलने वाली सतलुज और ब्यास नदियों से जल प्राप्त होता है। हिमालयी हिमनदों के पिघलने तथा बांधों द्वारा जल नियंत्रण के कारण इन नदियों में वर्ष भर बारहमासी प्रवाह बना रहता है, जिससे मरुस्थल को सतत जल मिलता है। यह महत्वपूर्ण है।

74. (A) यांत्रिक कृषि के स्थान पर पारंपरिक बैल-जुताई को बढ़ावा मिलना
इंदिरा गांधी नहर के निर्माण से थार क्षेत्र में कृषि का तीव्र यांत्रिकीकरण हुआ है। पारंपरिक बैल-जुताई के स्थान पर आधुनिक ट्रैक्टरों और मशीनों का उपयोग अत्यधिक बढ़ गया है। इसके साथ ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा है तथा जीवन-निर्वाह कृषि के स्थान पर व्यावसायिक फसलों एवं फल-बागवानी को व्यापक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। यह एक आधुनिक बदलाव है।

75. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण ब्रिटिश शासन काल में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1958 में शुरु हुआ था। थार मरुस्थल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, बालुका स्तूपों तथा विशाल वित्तीय आवश्यकताओं के कारण इसके निर्माण में कई दशकों का समय लगा और लागत में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह एक अत्यंत दीर्घकालिक राष्ट्रीय परियोजना साबित हुई थी।

76. (B) P-3, Q-1, R-2, S-4
इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों का जिलों से सही संबंध इस प्रकार है: कंवर सैन लिफ्ट नहर बीकानेर को, राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर को, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर बीकानेर व नागौर को, तथा जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर जैसलमेर व जोधपुर जिलों को जल प्रदान करती है। इन लिफ्ट नहरों से जलापूर्ति सुचारु बनी हुई है। यह महत्वपूर्ण व्यवस्था है।

77. (C) विरली वनस्पति वाले स्थानांतरित बालुका स्तूपों का विशाल क्षेत्र
इंदिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण का मार्ग मुख्य रूप से बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों से गुजरता है। इस क्षेत्र की स्थलाकृति विशाल स्थानांतरित बालुका स्तूपों, अत्यधिक शुष्कता, तीव्र हवाओं तथा विरली कंटीली वनस्पतियों से युक्त है। ऐसे विषम रेतीले भूभाग में नहर का निर्माण एवं जल प्रवाह बनाए रखना एक अत्यंत कठिन तकनीकी चुनौती साबित हुआ था। यह सत्य है।

NODIA

78. (C) 170 किमी
राजस्थान फीडर नहर की कुल लंबाई 204 किलोमीटर है। इसमें से 170 किलोमीटर का विशाल भाग राजस्थान में प्रवेश करने से पूर्व पंजाब और हरियाणा राज्यों से होकर बहता है। राजस्थान के भीतर इसकी लंबाई केवल 34 किलोमीटर है। यह फीडर नहर बिना किसी रिसाव और जल उपयोग के सीधे जल को राजस्थान तक पहुँचाने का मुख्य कार्य करती है।

79. (A) नहर परियोजना के निर्माण, कार्यान्वयन एवं प्रबंधन की देखरेख करना
इंदिरा गांधी नहर बोर्ड की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य इस विशाल नहर परियोजना के निर्माण, विकास, वित्तीय आवंटन तथा प्रशासनिक प्रबंधन की समग्र देखरेख करना था। यह बोर्ड विभिन्न अंतरराज्यीय विभागों तथा मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करके नहर निर्माण और जल बंटवारे को सुगम एवं प्रभावी बनाने हेतु उत्तरदायी शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है। यह महत्वपूर्ण है।

80. (B) शुष्क पर्यावरण में जलभराव, मृदा लवणीकरण एवं जल निकासी का प्रबंधन
इंदिरा गांधी नहर परियोजना के समक्ष सबसे प्रमुख दीर्घकालिक चुनौती कमान क्षेत्र में उत्पन्न जलभराव (सेम), मृदा का लवणीकरण तथा उचित जल निकासी व्यवस्था का न होना है। अत्यधिक जल प्रयोग से उपजाऊ कृषि भूमि की गुणवत्ता घट रही है। इस मरुस्थलीय पर्यावरण में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हुए कृषि का सतत विकास करना अत्यंत आवश्यक एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है।

www.nodia.in

16. भामाशाह टेक्नो हब जैसे राज्य के बुनियादी ढांचे के सहयोग से कौन-सा शहर राजस्थान में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्र बनकर उभरा है?
(A) जोधपुर
(B) उदयपुर
(C) जयपुर
(D) कोटा

17. जयपुर में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?
(A) यह महिंद्रा ग्रुप और रीको के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित है।
(B) यह मुख्य रूप से एक बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के रूप में कार्य करता है।
(C) इसमें आईटी/आईटीईएस, इंजीनियरिंग और हस्तशिल्प के लिए समर्पित क्षेत्र शामिल हैं।
(D) यह विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के लिए आरक्षित है।

18. राज्य सरकार की कौन-सी पहल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को राज्य के कानूनों के तहत आवश्यक अनुमोदनों और निरीक्षणों के बिना प्रारंभिक अवधि के लिए स्थापित करने और संचालित करने की अनुमति देती है?
(A) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
(B) राजस्थान निवेश संवर्धन योजना
(C) राजस्थान एमएसएमई (स्थापना और प्रवर्तन का सुगमीकरण) अधिनियम
(D) राजस्थान औद्योगिक विकास नीति

19. रीको ने हाल के वर्षों में औद्योगिक विकास को विकेंद्रीकृत करने और प्रमुख शहरों में अत्यधिक शहरी भीड़भाड़ को रोकने के लिए मुख्य रूप से कौन-सी रणनीति अपनाई है?
(A) प्रमुख जिला मुख्यालयों के भीतर किसी भी नई मध्यम या बड़ी विनिर्माण इकाई की स्थापना पर पूर्ण वैधानिक प्रतिबंध लगाना
(B) ब्लॉक और तहसील स्तरों पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना
(C) मरु राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के आसपास के नामित क्षेत्रों में मौजूदा विनिर्माण इकाइयों के भौतिक स्थानांतरण को अनिवार्य बनाना
(D) सभी नई पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों को 100% निर्यात-उन्मुख संस्थाओं के रूप में संचालित करने को अनिवार्य बनाने वाले कड़े वैधानिक नियमों को लागू करना

20. निम्नलिखित विशेष आर्थिक क्षेत्रों / औद्योगिक पार्कों को उनके स्थित जिलों के वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए:
I. बोरानाडा एग्रो फूड पार्क
II. जापानी क्षेत्र (नीमराना)
III. महिंद्रा वर्ल्ड सिटी
IV. सफेद सीमेंट केंद्र (गोटन)
(A) I, II, III, IV
(B) IV, III, I, II
(C) II, I, IV, III
(D) II, III, I, IV

21. बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी) के तहत भारत सरकार द्वारा राजस्थान जैसे राज्यों की औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन करने के लिए मुख्य रूप से किस मीट्रिक का उपयोग किया जाता है?
(A) व्यापार सुगमता (ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस) सुधारों का कार्यान्वयन
(B) पूरे राज्य में उत्खनित महत्वपूर्ण कच्चे खनिज संसाधनों की कुल वार्षिक मात्रा
(C) भारी औद्योगिक उपयोग के लिए कानूनी रूप से परिवर्तित उपजाऊ कृषि भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल
(D) स्थापित राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों की कुल संख्या

22. राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के अंतर्वाह के संदर्भ में, हाल के वर्षों में किस क्षेत्र ने लगातार सबसे अधिक विदेशी निवेश आकर्षित किया है?
(A) व्यावसायिक गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, एक्वाकल्चर और समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण
(B) उन्नत वाणिज्यिक विमानन, ड्रोन विनिर्माण और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग
(C) नवीकरणीय ऊर्जा और धातुकर्म उद्योग
(D) अंतर्देशीय वाणिज्यिक जहाज निर्माण, डॉकयार्ड सेवाएं और महासागर बंदरगाह बुनियादी ढांचा

23. औद्योगिक कार्यबल की आवश्यकताओं और कौशल विकास के बीच अंतर को पाटने के लिए, राजस्थान सरकार मुख्य रूप से किन संस्थानों के माध्यम से 'प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली' पर दृढ़ता से जोर देती है?
(A) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)
(B) कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके)
(C) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)
(D) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)

24. निम्नलिखित में से किस जिले को राजस्थान के प्रमुख सीमेंट निर्माण पट्टी के भीतर एक प्राथमिक केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है?
(A) चित्तौड़गढ़
(B) नागौर
(C) पाली
(D) जैसलमेर

25. राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (रिप्स) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के आधार पर निवेश सब्सिडी प्रदान करता है।

Downloaded from www.pdf.tube

स्टोन) प्रसंस्करण

8. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (रिप्स) के मुख्य उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) सरकारी विनिर्माण सुविधाओं के भीतर ग्रामीण शिक्षित युवाओं को प्रत्यक्ष सार्वजनिक रोजगार के अवसर प्रदान करना
(B) अव्यवहारिक निजी क्षेत्र की औद्योगिक विनिर्माण इकाइयों का व्यवस्थित रूप से राष्ट्रीयकरण और वित्तीय पुनर्गठन करना
(C) सूक्ष्म उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल के बाजार मूल्य निर्धारण को सख्ती से विनियमित और नियंत्रित करना
(D) नई निवेश इकाइयों के लिए लक्षित वित्तीय प्रोत्साहन, पूंजीगत सब्सिडी और कर छूट प्रदान करना

9. राजस्थान में औद्योगिक बुनियादी ढांचे के संदर्भ में रीको की प्राथमिक भूमिका क्या है?
(A) व्यक्तिगत पंजीकृत कारीगरों को अल्पकालिक कार्यशील पूंजी ऋण और प्रत्यक्ष सूक्ष्म ऋण सुविधाएं प्रदान करना
(B) औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना, भूमि आवंटित करना और नागरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना
(C) सभी विनिर्माण इकाइयों में कड़े पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मानकों और अनिवार्य अपशिष्ट उपचार को लागू करना
(D) सभी कच्चे कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए एकमात्र राज्य-संचालित कैनालाइजिंग और निर्यात एजेंसी के रूप में कार्य करना

10. राजस्थान में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लगभग 39 प्रतिशत संरेखण राजस्थान से होकर गुजरता है।
II. खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र (केबीएनआईआर) को डीएमआईसी के तहत एक प्रमुख नोड के रूप में विकसित किया जा रहा है।
III. राजस्थान में डीएमआईसी परियोजना को विशेष रूप से विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल II और III
(B) केवल I और III
(C) केवल I और II
(D) I, II और III

11. 'व्यापार सुगमता' (ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस) में सुधार के लिए, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सुगमकर्ता और अनुमोदन अधिनियम पारित करके समयबद्ध स्वीकृतियों के लिए एक वैधानिक ढांचा स्थापित किया?
(A) 1998
(B) 2005
(C) 2011
(D) 2019

NODIA

12. जयपुर का सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र एक समर्पित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है, जो विशेष रूप से किन वस्तुओं के निर्यात को लक्षित करता है?
(A) रत्न और आभूषण
(B) सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)
(C) ऑटो-कंपोनेंट्स और इंजीनियरिंग सामान
(D) तैयार वस्त्र (रेडीमेड गारमेंट्स) और ऊनी कपड़े

13. चित्तौड़गढ़-पाली-नागौर पट्टी में सीमेंट उद्योग का अत्यधिक संकेंद्रण मुख्य रूप से किस अवस्थितिक कारक द्वारा निर्धारित होता है?
(A) सीमेंट निर्यात के लिए प्रमुख समुद्री बंदरगाहों से निकटता
(B) उच्च श्रेणी के चूना पत्थर के भंडारों की प्रचुर उपलब्धता
(C) शीतलन आवश्यकताओं के लिए बड़ी बारहमासी नदियों की उपस्थिति
(D) क्षेत्र में विशेष कुशल श्रम का उच्च संकेंद्रण

14. राजस्थान द्वारा बिजली अधिशेष स्थिति प्राप्त करने के बावजूद, राज्य के पश्चिमी भागों में भारी धातुकर्म उद्योगों की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक बाधा बनी हुई है?
(A) प्रमुख भूकंपीय और विवर्तनिक गतिविधियों की उच्च आवृत्ति और जोखिम
(B) बारहमासी सतही ताजे पानी के स्रोतों की अत्यधिक कमी
(C) परिचालन योग्य ब्रॉड-गेज मालगाड़ी रेलवे कनेक्टिविटी का पूर्ण अभाव
(D) उच्च वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता जिसके कारण धातु के उपकरणों में तेजी से जंग लगता है

15. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): भीलवाड़ा राजस्थान के प्रमुख वस्त्र केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
कारण (R): पश्चिमी राजस्थान की शुष्क जलवायु प्राकृतिक वायुमंडलीय आर्द्रता प्रदान करती है जो अनुकूलतम सूती धागे की कताई के लिए आवश्यक है।
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

अध्याय 18

राजस्थान में औद्योगिक विकास एवं उद्योगों का अवस्थिति

1. स्वतंत्रता से पूर्व, राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन-सी थी?
(A) प्रचुर स्थानीय अयस्कों पर आधारित बड़े पैमाने के धातुकर्म उद्योग
(B) सभी रियासतों में समान रूप से वितरित संगठित सूती वस्त्र मिलें
(C) अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारी इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कार्यशालाएं
(D) स्थानीय संरक्षण द्वारा पोषित पारंपरिक हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग

2. राजस्थान में पारंपरिक हस्तशिल्प-आधारित अर्थव्यवस्था से आधुनिक औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन को 1969 में किस शीर्ष निकाय की स्थापना के साथ महत्वपूर्ण संस्थागत गति मिली?
(A) राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी)
(B) निवेश संवर्धन ब्यूरो (बीआईपी)
(C) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम (आरएसआईएमडीसी)
(D) राजस्थान लघु उद्योग निगम (आरएसआईसी)

3. भीलवाड़ा जिले ने मुख्य रूप से किस विशिष्ट वस्त्र उप-क्षेत्र में अपने अत्यधिक संकेंद्रण के कारण राजस्थान की "वस्त्र नगरी" (टेक्सटाइल सिटी) का उपनाम अर्जित किया है?
(A) रेशम कीट पालन प्रसंस्करण, रेशम बुनाई और तैयार वस्त्र (रेडीमेड गारमेंट्स)
(B) सिंथेटिक ब्लेंडिंग, कताई और सूटिंग फैब्रिक उत्पादन
(C) पारंपरिक हथकरघा सूती प्रसंस्करण और खादी कपड़े का उत्पादन
(D) उच्च श्रेणी के ऊनी कालीन की बुनाई और विशेष धागे की कताई

4. पाली औद्योगिक क्लस्टर को ऐतिहासिक रूप से मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय मुद्दे के कारण राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा गंभीर नियामक चुनौतियों और लगातार बंदी का सामना करना पड़ा है?
(A) अनियंत्रित कोयला आधारित तापीय कैप्टिव बिजली संयंत्रों के कारण गंभीर परिवेशी वायु प्रदूषण
(B) अनियंत्रित गहरे चूना पत्थर खनन के परिणामस्वरूप व्यापक भू-धंसाव और सिंकहोल
(C) व्यावसायिक चमड़ा शोधन इकाइयों से खतरनाक ठोस अपशिष्ट का अत्यधिक उत्पादन और निस्तारण
(D) वस्त्र रंगाई इकाइयों से बांडी नदी में अनुपचारित रासायनिक अपशिष्ट का विसर्जन

5. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I: (औद्योगिक पार्क/क्षेत्र)
P. जापानी औद्योगिक क्षेत्र
Q. मेगा फूड पार्क
R. फिनटेक पार्क
S. स्पाइसेज (मसाला) पार्क
सूची II: (जिला स्थिति)
1. जयपुर
2. जोधपुर
3. अलवर
4. अजमेर
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

6. राजस्थान में एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के तीव्र उद्भव का मुख्य कारण कौन-सा अवस्थितिक लाभ है?
(A) उत्तरी राजस्थान में भारी उद्योगों के लिए प्राथमिक समर्पित विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में इसकी परिचालन स्थिति
(B) वाणिज्यिक श्रेणी के लौह अयस्क भंडारों और उच्च कैलोरी मान वाले धातुकर्म कोकिंग कोल की प्रचुर स्थानीय उपलब्धता
(C) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) तथा गुरुग्राम-मानसर औद्योगिक केंद्र से निकटता
(D) स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्व-पश्चिम फ्रेट कॉरिडोर के प्राथमिक चौराहे पर रणनीतिक स्थिति

7. भिवाड़ी विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों के उच्च संकेंद्रण के लिए देश भर में जाना जाता है?
(A) ऑटो-कंपोनेंट्स और हल्के इंजीनियरिंग सामान
(B) रत्न और आभूषण की कटाई और पॉलिशिंग
(C) भारी रसायन और उर्वरक उत्पादन
(D) पारंपरिक हस्तशिल्प और नक्काशीदार पत्थर (डायमेंशन

Click Here to Buy book on Flipkart

II. यह पात्र इकाइयों को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए विद्युत शुल्क पर 100% छूट प्रदान करता है।
III. यह केवल विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेवा क्षेत्र के लिए किसी भी प्रोत्साहन को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है।
IV. यह लक्षित अतिरिक्त लाभों के लिए विशिष्ट "उभरते/प्राथमिकता वाले क्षेत्रों" की पहचान करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, III और IV
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

26. विशिष्ट विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, रीको ने किस क्षेत्र में एक समर्पित दक्षिण कोरियाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया?
(A) सीतापुरा, जयपुर
(B) बोरानाडा, जोधपुर
(C) घिलोठ, अलवर
(D) मंडोर, जोधपुर

27. राजस्थान में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, की स्थापना 1889 में किस शहर में की गई थी, जो राज्य के औद्योगिक इतिहास में एक प्रारंभिक मील का पत्थर थी?
(A) भीलवाड़ा
(B) पाली
(C) किशनगढ़
(D) ब्यावर

28. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I: (औद्योगिक उत्पाद/क्षेत्र)
P. संगमरमर प्रसंस्करण
Q. काँच निर्माण
R. वस्त्र रंगाई और छपाई
S. ऑटो-कंपोनेंट्स

सूची II: (राजस्थान में अग्रणी जिला)
1. धौलपुर
2. किशनगढ़ (अजमेर)
3. भिवाड़ी (अलवर)
4. पाली

(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

29. कौन-सा समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म राजस्थान में सभी आवश्यक औद्योगिक स्वीकृतियों और अनुमोदनों को प्रदान करने के लिए एकल-खिड़की केंद्र के रूप में कार्य करता है?
(A) राजकाज
(B) राजनिवेश
(C) ई-मित्र
(D) राजकौशल

30. राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?
(A) राजस्थान पूरे भारत में संगमरमर, ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर जैसे उच्च श्रेणी के डायमेंशन पत्थरों का लगातार अग्रणी वाणिज्यिक उत्पादक बना हुआ है।
(B) राज्य के पास सस्ते औद्योगिक माल परिवहन के लिए जलमार्गों का एक पूर्ण विकसित अंतर्देशीय नेटवर्क है।
(C) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) राज्य भर में संचालित पंजीकृत औद्योगिक विनिर्माण इकाइयों के अत्यधिक बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
(D) राज्य सीसा, जस्ता, सांद्र और वोलास्टोनाइट सहित प्रमुख रणनीतिक खनिजों में पूर्ण देशव्यापी उत्पादन एकाधिकार बनाए हुए है।

31. विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अधिनियम के तहत, राजस्थान में स्थापित सेज की परिचालन विशेषता क्या है?
(A) इसे व्यापार संचालन, शुल्क और करों के लिए विदेशी क्षेत्र माना जाता है।
(B) यह पंजीकृत औद्योगिक विनिर्माण इकाइयों को सभी राष्ट्रीय पर्यावरणीय और वैधानिक श्रम नियमों से पूरी छूट के साथ संचालित करने की अनुमति देता है।
(C) इसे विशेष रूप से घरेलू ग्रामीण खुदरा बाजारों को लक्षित कम लागत वाले उपभोक्ता सामानों के निर्माण के लिए डिज़ाइन और विनियमित किया गया है।
(D) यह एक प्रतिबंधित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में कार्य करता है जहां निजी निवेश पूंजी सख्ती से प्रतिबंधित है, केवल राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों की अनुमति है।

32. राजस्थान सरकार की 'आईस्टार्ट' पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह स्टार्टअप्स, निवेशकों और इनक्यूबेटरों के लिए एकल-खिड़की संसाधन के रूप में कार्य करता है।
II. यह सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (डीओआईटी एंड सी) के तत्वावधान में संचालित होता है।
III. यह केवल महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल II और III
(B) केवल I और III
(C) केवल I और II
(D) I, II और III

33. पाली औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) का मुख्य उद्देश्य किस औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न प्रदूषण को कम करना है?
(A) चमड़ा कमाना और सुखाना
(B) संगमरमर की कटाई और स्लरी निर्माण

Downloaded from www.pdf.tube

(C) सीमेंट निर्माण और क्लिंकर कूलिंग
(D) वस्त्र रंगाई और प्रसंस्करण

34. राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल देती है?
(A) आगामी सभी नई भारी औद्योगिक परियोजनाओं को केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कॉरिडोर के भीतर संकेंद्रित करना अनिवार्य बनाना
(B) मौजूदा स्थापित विनिर्माण क्लस्टरों को लक्षित सभी आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर पूर्ण विधायी प्रतिबंध लागू करना
(C) पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में समर्पित प्राथमिकता-क्षेत्र औद्योगिक पार्क स्थापित करना
(D) जिलों में रीको द्वारा विकसित सभी मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों के प्रबंधन और स्वामित्व का व्यवस्थित रूप से निजीकरण करना

35. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): राजस्थान में सीमेंट उद्योग चित्तौड़गढ़ और निंबाहेड़ा जैसे क्षेत्रों के पास अत्यधिक स्थानीयकृत है।
कारण (R): सीमेंट निर्माण एक भार-ह्रासकारी उद्योग है, जिसमें परिवहन लागत को कम करने के लिए चूना पत्थर जैसे भारी कच्चे माल के निकट होना आवश्यक है।
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

36. राजस्थान में कौन-सा संस्थागत निकाय विशेष रूप से राज्य में मेगा और बड़े निवेश प्रस्तावों को सुगम बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत है?
(A) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको)
(B) राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी)
(C) उद्योग निदेशालय
(D) निवेश संवर्धन ब्यूरो (बीआईपी)

37. औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांतों के संदर्भ में, जयपुर के समर्पित टेक पार्कों में विकसित होने वाले आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योगों को किस प्रकार के उद्योग के रूप में सबसे अच्छी तरह से वर्गीकृत किया गया है?
(A) फुटलूस उद्योग
(B) भार-ह्रासकारी उद्योग
(C) संसाधन-उन्मुख उद्योग
(D) भारी धातुकर्म उद्योग

38. स्थानीय हाइड्रोकार्बन संसाधनों का लाभ उठाने के लिए पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) की स्थापना राजस्थान के किस जिले से संबंधित है?
(A) जैसलमेर
(B) बीकानेर
(C) बाड़मेर
(D) गंगानगर

39. तटीय राज्यों की तुलना में राजस्थान में विनिर्माण क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक प्रतिकूलता (नुकसान) माना जाता है?
(A) प्रत्यक्ष समुद्री बंदरगाह कनेक्टिविटी की कमी के परिणामस्वरूप उच्च माल ढुलाई लागत
(B) उच्च क्षमता वाले चार लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों और आपस में जुड़े राज्य सड़क नेटवर्क का पूर्ण संरचनात्मक अभाव
(C) बड़े पैमाने पर औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने के लिए उपयुक्त अकृष्य बंजर भूमि की गंभीर भौगोलिक कमी
(D) परिचालन योग्य ब्रॉड-गेज रेलवे लाइनों और समर्पित औद्योगिक रेल माल ढुलाई गलियारों का पूर्ण अभाव

NODIA

40. निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तर से दक्षिण की ओर राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का सही भौगोलिक क्रम दर्शाता है?
(A) नीमराना → भिवाड़ी → पाली → किशनगढ़
(B) भिवाड़ी → नीमराना → किशनगढ़ → पाली
(C) पाली → किशनगढ़ → नीमराना → भिवाड़ी
(D) किशनगढ़ → भिवाड़ी → नीमराना → पाली

41. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) मुख्य रूप से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र का समर्थन कैसे करता है?
(A) सभी निजी मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयों के दैनिक विनिर्माण कार्यों की प्रत्यक्ष निगरानी, वित्तपोषण और प्रबंधन करके
(B) वर्तमान औद्योगिक जनशक्ति मांग से जुड़े कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर
(C) सभी असंगठित कारखाना श्रमिकों को पूर्ण वैधानिक आयकर छूट और प्रत्यक्ष सामाजिक सुरक्षा नकद भुगतान प्रदान करके
(D) सभी स्थानीय रूप से निर्मित उपभोक्ता वस्तुओं के लिए अनिवार्य न्यूनतम खुदरा बिक्री मूल्य प्रशासनिक रूप से निर्धारित और लागू करके

42. राजस्थान में उद्योगों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. ताजे पानी के संसाधनों की कमी जल-गहन उद्योगों के विकास को सीमित करती है।
II. राज्य का भू-आबद्ध भूगोल आयात-निर्यात लॉजिस्टिक्स लागत को बढ़ाता है।
III. बिजली उत्पादन में गंभीर घाटा है, जिससे बार-बार

औद्योगिक बिजली कटौती होती है।
IV. अत्यधिक कुशल तकनीकी श्रम को बनाए रखना राज्य के बाहर महानगरीय केंद्रों में प्रवास के कारण चुनौतीपूर्ण है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल II, III और IV
(B) केवल I, II और III
(C) केवल I, II और IV
(D) केवल I, III और IV

43. अजमेर जिले के किशनगढ़ औद्योगिक क्षेत्र ने मुख्य रूप से किस प्राकृतिक संसाधन के प्रसंस्करण के लिए वैश्विक प्रसिद्धि हासिल की है?
(A) अपतटीय कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक निष्कर्षण और शोधन
(B) मूल्यवान और अर्द्ध-मूल्यवान रत्न खनिजों का खनन, कटाई और पॉलिशिंग
(C) रॉक फॉस्फेट और जिप्सम का बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक निष्कर्षण और रासायनिक प्रसंस्करण
(D) संगमरमर और ग्रेनाइट जैसे डायमेंशन पत्थरों का प्रसंस्करण

44. राजस्थान जैसे भू-आबद्ध राज्य में उद्योगों के लिए आयात-निर्यात (एग्ज़िम) व्यापार को सुगम बनाने के लिए, सरकार ने किन विशिष्ट बुनियादी ढांचा सुविधाओं की स्थापना को बढ़ावा दिया है?
(A) अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) और शुष्क बंदरगाह
(B) कृत्रिम गहरे पानी के समुद्री बंदरगाह
(C) फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसीफिकेशन यूनिट्स (एफएसआरयू)
(D) विशेष कार्गो पनडुब्बी अड्डे

45. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प रीको द्वारा अपने नए औद्योगिक पार्कों में हाल ही में बढ़ावा दी गई "प्लग एंड प्ले" बुनियादी ढांचा अवधारणा को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है?
(A) कच्चे अविकसित भूखंड सीमाओं का आवंटन जहां नई पंजीकृत विनिर्माण इकाइयों को शुरू से सभी प्राथमिक पहुंच सड़कों, उपयोगिता कनेक्शनों और बिजली लाइनों का निर्माण करना अनिवार्य है
(B) तत्काल परिचालन सेटअप के लिए बुनियादी उपयोगिताओं के साथ प्लग-एंड-प्ले शेड प्रदान करना
(C) सभी पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण इकाइयों को सीधे पूर्ण सब्सिडी वाले, राज्य-वित्तपोषित कच्चे माल इनपुट और घटक इन्वेंट्री प्रदान करना
(D) नामित भारी विनिर्माण क्षेत्रों के ठीक निकट इको-टूरिज्म सार्वजनिक मनोरंजन पार्क और मनोरंजन सुविधाओं का निर्माण करना

46. नागौर जिले में गोटन और जोधपुर जिले में खारिया खंगार किस विशिष्ट वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र हैं?
(A) पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट
(B) सफेद सीमेंट
(C) सिंथेटिक रेयान
(D) अग्निसह ईंटें

47. भीलवाड़ा के वस्त्र उद्योग के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) यह क्लस्टर सिंथेटिक धागे की कताई और सूटिंग फैब्रिक उत्पादन पर केंद्रित है।
(B) संपूर्ण औद्योगिक प्रसंस्करण बुनियादी ढांचा सख्ती से जिले की सीमा के भीतर उत्पादित कच्चे लंबे रेशे वाले कपास पर निर्भर करता है।
(C) स्वचालित शटललेस लूम तकनीक को अपनाने में पूर्ण विफलता के परिणामस्वरुप क्लस्टर को गंभीर आर्थिक गिरावट का सामना करना पड़ा है।
(D) सभी प्रमुख कताई और बुनाई इकाइयों का स्वामित्व सख्ती से सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पास है।

48. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I: (नीति/अधिनियम/योजना)
P. राजस्थान औद्योगिक विकास नीति
Q. राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (रिप्स)
R. राजस्थान एमएसएमई (सुगमीकरण) अधिनियम
S. राजस्थान स्टार्टअप नीति
सूची II: (2022 तक नवीनतम प्रमुख पुनरावृत्ति/अधिनियमन का वर्ष)
1. 2022
2. 2019
3. 2015
4. 2022 (संशोधित)
(A) P-1, Q-2, R-4, S-3
(B) P-2, Q-4, R-2, S-1
(C) P-2, Q-1, R-3, S-4
(D) P-2, Q-1, R-2, S-4

49. राजस्थान में कार्यान्वित 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) पहल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या प्राप्त करना है?
(A) आंतरिक बाजार प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए यह अनिवार्य करना कि प्रत्येक जिला प्रशासनिक रूप से सभी स्थानीय वाणिज्यिक औद्योगिक गतिविधियों को केवल एक ही उत्पाद लाइन तक सीमित रखे
(B) ऐसे सख्त अंतर-जिला व्यापार अवरोधों को लागू करना जो किसी जिले के नामित विशेष उत्पाद को उसकी प्रशासनिक सीमाओं से बाहर कहीं भी बेचने से कानूनी रूप से रोकते हों
(C) प्रमुख विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए हर एक प्रशासनिक जिले में कम से कम एक बड़े पैमाने का विनिर्माण संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य बनाना
(D) निर्यात बाजारों के लिए अनूठे स्थानीय शिल्पों और पारंपरिक जिला उत्पादों को बढ़ावा देना और ब्रांडिंग

Click Here to Buy book on Amazon

करना

50. राजस्थान सरकार की कौन-सी योजना विशेष रूप से नए सूक्ष्म और लघु उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए ऋण पर ब्याज अनुदान (सब्सिडी) प्रदान करती है?
(A) मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
(B) मुख्यमंत्री राजस्थान युवा संबल योजना (बेरोजगारी भत्ता योजना)
(C) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (एमएलयूपीवाई)
(D) इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

51. राजस्थान की औद्योगिक नीतियों के तहत, "उभरते/प्राथमिकता वाले क्षेत्रों" के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों को प्रदान किया जाने वाला प्राथमिक लाभ क्या है?
(A) उन्हें राज्य और राष्ट्रीय श्रम कल्याण और सुरक्षा नियमों के अनुपालन से पूर्ण वैधानिक छूट दी जाती है।
(B) वे गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की तुलना में उच्च पूंजीगत सब्सिडी और लंबी कर छूट प्राप्त करते हैं।
(C) उनके लिए अपने कुल वार्षिक निर्मित उत्पादन का 100% अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात करना कानूनी रूप से आवश्यक है।
(D) वे रीको के वरिष्ठ राज्य अधिकारियों द्वारा सीधे स्वामित्व, संचालित और प्रशासनिक रूप से प्रबंधित होते हैं।

52. निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए:
I. सस्ते और कुशल प्रवासी श्रम की उपलब्धता।
II. निकटवर्ती क्षेत्र में लंबे रेशे वाले कपास की प्रचुर स्थानीय खेती।
III. सक्रिय उद्यमी पूंजी और स्थानीयकृत बुनियादी ढांचे का विकास।
उपर्युक्त में से किन कारकों ने भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) I, II और III
(D) केवल I और III

53. निर्यात के लिए तकनीकी वस्त्रों और तैयार कपड़ों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, रीको ने किस स्थान पर एक समर्पित परिधान (एपेरल) पार्क विकसित किया है?
(A) महल, जगतपुरा (जयपुर)
(B) बोरानाडा (जोधपुर)
(C) चोपनकी (भिवाड़ी)
(D) मंडोर (जोधपुर)

54. राजस्थान की सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम में "माना गया अनुमोदन" (डीम्ड अप्रूवल) की अवधारणा का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है?
(A) यदि प्रसंस्करण विभाग अनिवार्य पंद्रह दिनों की समयावधि के भीतर जवाब देने में विफल रहते हैं, तो औद्योगिक निवेश आवेदन स्वतः खारिज और रद्द हो जाते हैं।
(B) किसी भी विनिर्माण उद्यम की स्थापना से पहले वैधानिक मंजूरी आवेदनों की समीक्षा, हस्ताक्षर और स्वीकृति व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री द्वारा की जानी चाहिए।
(C) यदि प्राधिकरण वैधानिक समय सीमा के भीतर निर्णय लेने में विफल रहता है तो मंजूरी स्वीकृत मानी जाती है।
(D) सभी पंजीकृत लघु उद्यमों को किसी भी राज्य विधान के तहत कोई भी पर्यावरणीय या नगर पालिक स्वीकृति प्राप्त करने से स्थायी रूप से छूट दी जाती है।

55. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
कथन (A): राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन और उपकरण निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए अत्यधिक आकर्षक है।
कारण (R): राजस्थान में भारत में सबसे अधिक सौर विकिरण तीव्रता है और इसके साथ ही बड़े सौर पार्कों के लिए उपयुक्त बंजर भूमि का विशाल क्षेत्र है।
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

56. राजस्थान में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) विकसित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) विशेष रूप से प्रवासी औद्योगिक कारखाना श्रमिकों के लिए राज्य-सब्सिडी वाली आवासीय आवास कॉलोनियों और टाउनशिप सुविधाओं का निर्माण और प्रबंधन करना
(B) विस्तारशील महानगरीय औद्योगिक क्लस्टरों के निकट प्रमुख वाणिज्यिक मनोरंजक हब, लक्ज़री रिसॉर्ट्स और इको-टूरिज्म पार्क स्थापित करना
(C) अधिशेष कृषि उपज के आंतरिक वितरण और थोक विपणन तक सीमित समर्पित माल ढुलाई हब संचालित करना
(D) औद्योगिक रसद लागत को कम करने के लिए रेल और सड़क माल परिवहन को एकीकृत करना

57. पाली जिले का पारंपरिक बंधेज हस्तशिल्प काफी हद तक किस आधुनिक औद्योगिक गतिविधि में परिवर्तित हो गया है, जिससे यह एक प्रमुख क्लस्टर बन गया है?
(A) शुद्ध रेशम की पॉवरलूम बुनाई
(B) मशीनीकृत ब्लॉक प्रिंटिंग और सिंथेटिक कपड़े की रंगाई
(C) तैयार ऊनी कपड़ों का स्वचालित निर्माण
(D) जैविक (ऑर्गेनिक) कपास की खेती

58. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से निकटता एक लाभ होने के बावजूद, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र को मुख्य रूप से किस

NODIA

कारक के कारण बार-बार परिचालन व्यवधानों का सामना करना पड़ता है?
(A) उत्तरी अरब सागर बेसिन से उत्पन्न होने वाली बार-बार गंभीर चक्रवाती मौसम प्रणालियां और तेज हवा वाले तटीय तूफान
(B) मानसून के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में बार-बार होने वाली विनाशकारी मौसमी अचानक बाढ़ और व्यापक जलभराव
(C) गंभीर एनसीआर वायु प्रदूषण के कारण लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) प्रतिबंध
(D) लंबे समय से चले आ रहे सशस्त्र श्रमिक संघ विवाद, बार-बार श्रमिकों की हड़ताल और अनिवार्य न्यूनतम मजदूरी भुगतान पर औद्योगिक संघर्ष

59. निम्नलिखित में से कौन-सा ऊर्जा स्रोत राजस्थान की सीमेंट पट्टी में क्लिंकर भट्टियों के संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में कार्य करता है, जिसके लिए अक्सर महंगे अंतर-राज्यीय आयात की आवश्यकता होती है?
(A) सौर ऊर्जा
(B) प्राकृतिक गैस
(C) बायोमास
(D) कोयला

60. निम्नलिखित में से कौन-सा राजस्थान में प्रमुख औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना का सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाता है?
(A) उद्योग निदेशालय → राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) → रीको → निवेश संवर्धन ब्यूरो (बीआईपी)
(B) राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) → उद्योग निदेशालय → बीआईपी → रीको
(C) रीको → राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) → उद्योग निदेशालय → बीआईपी
(D) बीआईपी → रीको → उद्योग निदेशालय → राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी)

61. राजस्थान सरकार किस जिले में फार्मास्युटिकल और चिकित्सा उपकरण निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित "मेडिकल डिवाइस पार्क" सक्रिय रूप से विकसित कर रही है?
(A) उदयपुर
(B) जोधपुर
(C) बीकानेर
(D) कोटा

62. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसे जापान सरकार से वित्तीय और तकनीकी सहायता द्वारा अत्यधिक समर्थन प्राप्त है।
II. वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस परियोजना की मुख्य लॉजिस्टिकल रीढ़ है।
III. इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ स्मार्ट औद्योगिक शहरों का विकास करना है।
IV. यह गुजरात को सीधे हरियाणा से जोड़ने के लिए राजस्थान को पूरी तरह से बायपास करता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और IV
(B) केवल I, II और III
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

63. रिप्स ढांचे के तहत, मानक पात्र औद्योगिक इकाइयां आमतौर पर शुरुआती निर्दिष्ट अवधि के लिए बिजली शुल्क पर कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त करती हैं?
(A) 25%
(B) 50%
(C) 75%
(D) 100%

64. नमक-आधारित रासायनिक उद्योगों का संकेंद्रण, विशेष रूप से सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड का उत्पादन करने वाले उद्योगों का संकेंद्रण, राजस्थान के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है?
(A) दक्षिणी मेवाड़ पथरीला भूभाग और पहाड़ी क्षेत्र
(B) दक्षिण-पूर्वी हाड़ौती बेसाल्टिक पठारी क्षेत्र
(C) सांभर-पचपदरा-डीडवाना पट्टी
(D) दक्षिण-पश्चिमी माही नदी बेसिन के मैदान

65. बीकानेर और बाड़मेर के पश्चिमी जिलों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कौन-सा कच्चा माल राज्य के सिरामिक और अग्निसह (रिफ्रेक्ट्री) उद्योगों का समर्थन करता है?
(A) व्यावसायिक बॉक्साइट खनिज भंडार
(B) उच्च श्रेणी के मैंगनीज अयस्क भंडार
(C) धातुकर्म क्रोमाइट भंडार
(D) बॉल क्ले और फायर क्ले

66. व्यापार सुगमता के संदर्भ में, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाला 'बुनियादी ढांचा विकास और निवेश संवर्धन बोर्ड' (बीआईडीआई) क्या करता है?
(A) यह जिलों भर में सभी सूक्ष्म उद्यमों की दैनिक परिचालन दिनचर्या, पेरोल और स्थानीय अनुपालन की सीधे निगरानी, अनुमोदन और प्रबंधन करता है।
(B) यह विशेष रूप से मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार के कार्यान्वयन और फंड वितरण की देखरेख करने वाली केंद्रीय राज्य स्तरीय निगरानी और ऑडिट एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
(C) यह मेगा परियोजना की बाधाओं को दूर करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति को अधिकार प्रदान करता है।
(D) यह सरकारी एम्पोरियम का प्रबंधन करने वाली प्राथमिक सार्वजनिक खुदरा एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जो सीधे विदेशी पर्यटकों को स्थानीय पारंपरिक हस्तशिल्प का विपणन करती है।

Downloaded from www.pdf.tube

67. रीको ने किस शहर में मुख्य रूप से आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियों की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक समर्पित 'साइबर पार्क' विकसित किया है?
(A) अजमेर
(B) जोधपुर
(C) भीलवाड़ा
(D) अलवर

68. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I: (औद्योगिक खनिज)
P. रॉक फॉस्फेट
Q. सिलिका सैंड (बालू)
R. चूना पत्थर (लाइमस्टोन)
S. टंगस्टन
सूची II: (प्रमुख औद्योगिक अनुप्रयोग)
1. सीमेंट निर्माण
2. उर्वरक उत्पादन
3. काँच निर्माण
4. रक्षा और फिलामेंट उद्योग
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

69. राजस्थान में भारी, एकीकृत लौह और इस्पात संयंत्रों की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन-सी सबसे महत्वपूर्ण बाधा के रूप में कार्य करती है?
(A) कोकिंग कोल और पर्याप्त ताजे पानी की कमी
(B) पेशेवर रूप से प्रशिक्षित प्रबंधकीय प्रतिभा और तकनीकी इंजीनियरिंग कार्यबल का पूर्ण अभाव
(C) सभी भारी धातुकर्म प्रसंस्करण इकाइयों को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने वाला कड़ा राज्य पर्यावरण विधान
(D) औद्योगिक विकास पर पारंपरिक कृषि नकदी फसल की खेती पर राज्य का व्यापक अत्यधिक आर्थिक झुकाव

70. "मुख्यमंत्री युवा संबल योजना" श्रम बल के किस पहलू पर ध्यान केंद्रित करके औद्योगिक क्षेत्र का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करती है?
(A) नए भारी विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष पूंजी अनुदान, इक्विटी वित्तपोषण और मशीनरी सब्सिडी प्रदान करना
(B) सभी निजी क्षेत्र के उद्योगों को केवल स्थानीय विश्वविद्यालय स्नातकों को ही नियुक्त करने के लिए बाध्य करने वाले सख्त अनिवार्य कोटा लागू करना
(C) कौशल प्रशिक्षण से जुड़े युवा बेरोजगारी भत्ते प्रदान करना
(D) सभी पंजीकृत औद्योगिक कारखाने के श्रमिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन पास व्यय और दैनिक आवागमन लागत को सब्सिडी देना

71. हाल के वर्षों में, राजस्थान ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और ईवी बैटरी के निर्माण को आक्रामक रूप से बढ़ावा दिया है। कौन-सी योजना राज्य में ईवी के खरीदारों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर विशेष रूप से रिप्स की पूरक बनती है?
(A) राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (आरईवीपी)
(B) मुख्यमंत्री राज्य विद्युत प्रोत्साहन योजना
(C) राजस्थान व्यापक सौर ऊर्जा नीति ढांचा
(D) राष्ट्रीय हरित ऊर्जा पारेषण गलियारा योजना

72. राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इससे पश्चिमी बंदरगाहों तक राजस्थान के निर्यातों के पारगमन समय में काफी कमी आने की उम्मीद है।
II. यह विशेष रूप से पूर्वी जिलों के कृषि विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
III. इसमें अपने प्रभाव क्षेत्र के साथ विशेष निवेश क्षेत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास शामिल है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) I, II और III
(D) केवल I और III

NODIA

73. कौन-सा विशिष्ट रीको औद्योगिक क्षेत्र अपने ऐतिहासिक धातुकर्म कौशलों का लाभ उठाते हुए, विशेष हस्त औजारों और कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है?
(A) जैसलमेर
(B) नागौर
(C) प्रतापगढ़
(D) डूंगरपुर

74. राजस्थान में एक सामान्य रीको औद्योगिक क्षेत्र और एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के बीच मौलिक अंतर क्या है?
(A) नियमित औद्योगिक क्षेत्र सख्ती से अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट निवेश के लिए आरक्षित हैं, जबकि सेज विशेष रूप से घरेलू सूक्ष्म उद्यमों के लिए स्थापित किए गए हैं।
(B) नियमित औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से सब्सिडी वाली मुफ्त बिजली और पानी की पेशकश करते हैं, जबकि सेज अत्यधिक बढ़ी हुई उपयोगिता दरों और प्रीमियम बुनियादी ढांचा पहुंच शुल्क लगाते हैं।
(C) सेज निर्यात पर केंद्रित शुल्क-मुक्त एन्क्लेव हैं, जबकि नियमित औद्योगिक क्षेत्र घरेलू और निर्यात बाजारों दोनों की सेवा करते हैं।
(D) सेज प्रत्यक्ष संघीय क्षेत्राधिकार के तहत कार्य करते हैं, जो परिचालन से सभी राज्य प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय नगरपालिका देखरेख को बाहर करते हैं।

75. भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र का हिस्सा

है।

II. इसे दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से निकटता का महत्वपूर्ण लाभ मिलता है।

III. यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अपनी स्थिति के कारण सीमा पार पर्यावरणीय नियामक मुद्दों से ग्रस्त है।

IV. यह राज्य में कच्चे लंबे रेशे वाले कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल I, III और IV
(B) केवल II, III और IV
(C) I, II, III और IV
(D) केवल I, II और III

76. चमड़ा उद्योग का समर्थन करने और इसकी विशिष्ट पर्यावरणीय आवश्यकताओं का प्रबंधन करने के लिए, रीको ने किस स्थान पर एक समर्पित लेदर कॉम्प्लेक्स स्थापित किया है?

(A) मानपुरा माचेड़ी, जयपुर
(B) सीतापुरा, जयपुर
(C) बोरानाडा, जोधपुर
(D) करणी, बीकानेर

77. पारंपरिक चूना पत्थर पर सीमेंट उद्योग की निर्भरता को कम करने और अपशिष्ट उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान में आधुनिक सीमेंट संयंत्र तापीय ऊर्जा संयंत्रों के किस उप-उत्पाद का तेजी से उपयोग कर रहे हैं?

(A) स्लैग (धातुमल)
(B) फ्लाई एश (उड़न राख)
(C) सिलिका फ्यूम
(D) रेड मड (लाल कीचड़)

78. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।

कथन (A): पाली में वस्त्र रंगाई और छपाई उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा दिए गए आदेशों के कारण बार-बार परिचालन बंदी का सामना करना पड़ता है।

कारण (R): अधिकांश इकाइयां अपने सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) को पर्याप्त रूप से अपग्रेड और बनाए रखने में विफल रहती हैं, जिससे बांडी नदी का गंभीर प्रदूषण होता है।

निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

79. निम्नलिखित में से कौन जोधपुर और बाड़मेर जैसे शुष्क पश्चिमी जिलों में स्थित प्रमुख रीको औद्योगिक क्षेत्रों में निरंतर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी बनाता है?

(A) इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी)
(B) बहु-स्तरीय चम्बल नदी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं
(C) माही बजाज सागर बांध की प्रमुख भंडारण सुविधाएं
(D) एकीकृत बीसलपुर बांध पेयजल पाइपलाइन नेटवर्क

80. भीलवाड़ा क्लस्टर की एकीकृत वस्त्र मिलों में आमतौर पर देखी जाने वाली वस्त्र निर्माण प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को कच्चे माल से तैयार उत्पाद तक सही क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:

I. बुनाई (नीटिंग)
II. कताई (धागा उत्पादन)
III. वस्त्र निर्माण / सिलाई
IV. रंगाई और प्रसंस्करण

निम्नलिखित में से कौन-सा सही क्रमिक क्रम दर्शाता है?

(A) II, I, IV, III
(B) I, II, IV, III
(C) II, IV, I, III
(D) IV, II, I, III

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Flipkart

एक बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती प्रस्तुत करती है। कच्चे माल के आयात और तैयार माल के निर्यात के लिए गुजरात या महाराष्ट्र के बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे माल ढुलाई लागत बढ़ जाती है और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

40. (B) भिवाड़ी → नीमराना → किशनगढ़ → पाली
राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का उत्तर से दक्षिण दिशा में भौगोलिक क्रम देखने पर भिवाड़ी सबसे उत्तर में अलवर जिले में स्थित है। इसके बाद नीमराना अलवर के दक्षिणी हिस्से में आता है। आगे दक्षिण की ओर बढ़ने पर अजमेर जिले में किशनगढ़ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। सबसे अंत में दक्षिण-पश्चिमी दिशा में पाली औद्योगिक क्लस्टर आता है। अतः भिवाड़ी, नीमराना, किशनगढ़ और पाली का क्रम भौगोलिक दृष्टि से पूरी तरह सही है।

41. (B) वर्तमान औद्योगिक जनशक्ति मांग से जुड़े कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर
राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम राज्य के औद्योगिक क्षेत्र की जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह संस्था उद्योगों की वर्तमान माँगों के अनुरूप युवाओं के लिए विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। युवाओं को व्यावहारिक और तकनीकी प्रशिक्षण देकर यह निगम उन्हें रोजगार योग्य बनाता है। इससे उद्योगों को कुशल कार्यबल प्राप्त होता है और राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करने में सहायता मिलती है।

42. (C) केवल I, II और IV
राजस्थान में औद्योगिक विकास के सामने कई गंभीर चुनौतियाँ हैं। ताजे जल संसाधनों की कमी जल-गहन उद्योगों को बाधित करती है और भू-आबद्ध भौगोलिक स्थिति से परिवहन लागत बढ़ती है। इसके अलावा कुशल श्रम का अन्य राज्यों में पलायन भी एक समस्या है। हालाँकि, यह कहना गलत है कि राज्य में बिजली उत्पादन में गंभीर घाटा है, क्योंकि राजस्थान अब सौर और तापीय ऊर्जा में एक अधिशेष राज्य बन चुका है।

43. (D) संगमरमर और ग्रेनाइट जैसे डायमेंशन पत्थरों का प्रसंस्करण
अजमेर जिले का किशनगढ़ औद्योगिक क्षेत्र पूरे विश्व में संगमरमर और ग्रेनाइट जैसे डायमेंशन पत्थरों के प्रसंस्करण और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देश-विदेश से कच्चा संगमरमर लाया जाता है और उसकी कटाई, पॉलिशिंग तथा ग्रेडिंग की जाती है। किशनगढ़ में निर्मित संगमरमर की पट्टियों और टाइलों का व्यापक व्यापार होता है। यह क्षेत्र अत्याधुनिक पत्थर प्रसंस्करण तकनीकों और विशाल बाजार सुविधाओं के लिए जाना जाता है।

44. (A) अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) और शुष्क बंदरगाह
राजस्थान जैसे भू-आबद्ध राज्य में प्रत्यक्ष समुद्री तट न होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने के लिए अंतर्देशीय कंटेनर डिपो तथा शुष्क बंदरगाहों की स्थापना की गई है। ये ड्राई पोर्ट बंदरगाहों की तरह ही सीमा शुल्क निकासी, माल भंडारण और कंटेनर हैंडलिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। इस बुनियादी ढाँचे से राज्य के निर्यातकों को अपने उत्पाद सीधे विदेशी बाजारों तक भेजने में सुविधा और लागत राहत मिलती है।

45. (B) तत्काल परिचालन सेटअप के लिए बुनियादी उपयोगिताओं के साथ प्लग-एंड-प्ले शेड प्रदान करना
रीको द्वारा नए औद्योगिक पार्कों में अपनाई गई "प्लग एंड प्ले" अवधारणा का उद्देश्य उद्यमियों को बिना किसी शुरुआती देरी के व्यवसाय शुरु करने की सुविधा देना है। इसके तहत रीको बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी उपयोगिताओं से सुसज्जित पहले से बने शेड और तैयार इमारतें आवंटित करता है। इससे नए निवेशकों को भूमि अधिग्रहण और निर्माण में लगने वाला समय बचता है और वे तुरंत अपना विनिर्माण कार्य शुरु कर पाते हैं।

46. (B) सफेद सीमेंट
नागौर जिले में स्थित गोटन और जोधपुर जिले में स्थित खारिया खंगार भारत में सफेद सीमेंट उत्पादन के अग्रणी केंद्र हैं। गोटन में देश का पहला सफेद सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था, जबकि खारिया खंगार में उच्च क्षमता वाला आधुनिक संयंत्र संचालित है। इन क्षेत्रों में उच्च शुद्धता वाले चूना पत्थर की प्रचुरता के कारण सफेद सीमेंट उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है, जो निर्माण क्षेत्र को प्रीमियम उत्पाद प्रदान करता है।

47. (A) यह क्लस्टर सिंथेटिक धागे की कताई और सूटिंग फैब्रिक उत्पादन पर केंद्रित है।
भीलवाड़ा क्लस्टर मुख्य रूप से सिंथेटिक धागे की कताई और सूटिंग कपड़े के विनिर्माण पर केंद्रित है। यह औद्योगिक क्षेत्र आधुनिक पावरलूम और कताई तकनीकों का उपयोग करता है। यहाँ कच्चा माल केवल स्थानीय कपास तक सीमित नहीं है, बल्कि बाहर से मंगाए गए सिंथेटिक रेशों का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। यहाँ की अधिकांश इकाइयाँ निजी स्वामित्व में हैं और यह क्लस्टर भारत के कपड़ा बाजार में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।

48. (C) P-2, Q-1, R-3, S-4
राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक नीतियों के लागू होने के वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति वर्ष 2019 में घोषित की गई थी। राजस्थान निवेश संवर्धन योजना का नवीनतम संस्करण वर्ष 2022 में लागू हुआ। राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सुगमकर्ता अधिनियम वर्ष 2015 में लाया गया था। इसके अलावा राजस्थान की संशोधित स्टार्टअप नीति को भी वर्ष 2022 में अधिसूचित किया गया था, जो नवाचारों को बढ़ावा देती है।

49. (D) निर्यात बाजारों के लिए अनूठे स्थानीय शिल्पों और पारंपरिक जिला उत्पादों को बढ़ावा देना और ब्रांडिंग करना
'एक जिला एक उत्पाद' पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले के विशिष्ट और पारंपरिक उत्पादों की पहचान करके उन्हें वैश्विक पहचान दिलाना है। इस योजना के अंतर्गत जिलों के अनूठे हस्तशिल्प, कृषि प्रसंस्करण उत्पादों और स्थानीय कारीगरी की ब्रांडिंग, गुणवत्ता सुधार तथा विपणन सहायता

NODIA

9. (B) औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना, भूमि आवंटित करना और नागरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, जिसे रीको के नाम से जाना जाता है, राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए जिम्मेदार शीर्ष एजेंसी है। इसकी प्राथमिक भूमिका योजनाबद्ध औद्योगिक क्षेत्रों का अधिग्रहण और विकास करना, उद्यमियों को भूमि आवंटित करना तथा सड़कों, बिजली और पानी जैसी नागरिक सुविधाओं का निर्माण करना है। रीको राज्य के संतुलित क्षेत्रीय और औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

10. (C) केवल I और II
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना में राजस्थान की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लगभग 39 प्रतिशत भाग राज्य से होकर गुजरता है। इसके अंतर्गत खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र को एक प्रमुख औद्योगिक नोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। हालाँकि, यह परियोजना केवल विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित नहीं है, बल्कि इसमें भारत सरकार और जापान सरकार का संयुक्त वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग शामिल है। इसलिए केवल शुरुआती दो कथन सत्य हैं।

11. (C) 2011
राजस्थान में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने और औद्योगिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2011 में राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सुगमकर्ता और अनुमोदन अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों से आवश्यक लाइसेंस और अनुमतियाँ प्राप्त करने के लिए एक समयावधि तय की गई थी। इस वैधानिक ढाँचे ने नौकरशाही की देरी को कम किया और राज्य में नए उद्योगों की स्थापना को सुगम बनाया।

12. (A) रत्न और आभूषण
जयपुर का सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध विशेष आर्थिक क्षेत्र की मेजबानी करता है। यह विशेष आर्थिक क्षेत्र मुख्य रूप से रत्न और आभूषणों के प्रसंस्करण, निर्माण तथा निर्यात को लक्षित करता है। जयपुर ऐतिहासिक रूप से कीमती पत्थरों की कटाई और पॉलिशिंग का एक प्रमुख केंद्र रहा है। इस सेज के माध्यम से आधुनिक तकनीक और विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा प्रदान करके अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आभूषणों के निर्यात को व्यापक प्रोत्साहन दिया जाता है।

13. (B) उच्च श्रेणी के चूना पत्थर के भंडारों की प्रचुर उपलब्धता
चित्तौड़गढ़, पाली और नागौर की भौगोलिक पट्टी में सीमेंट उद्योग का अत्यधिक संकेंद्रण मुख्य रूप से चूना पत्थर के समृद्ध भंडारों की उपलब्धता पर निर्भर है। चूना पत्थर सीमेंट निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण और भार-ह्रासकारी कच्चा माल है। परिवहन लागत को कम करने के लिए सीमेंट कारखानों की स्थापना खदानों के पास ही की जाती है। इस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले चूना पत्थर के विशाल भंडार मौजूद हैं, जो उद्योग को अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं।

14. (B) बारहमासी सतही ताजे पानी के स्रोतों की अत्यधिक कमी
राजस्थान के पश्चिमी भागों में बिजली की उपलब्धता में सुधार होने के बावजूद, बारहमासी सतही ताजे पानी के स्रोतों की गंभीर कमी भारी धातुकर्म उद्योगों की स्थापना में सबसे बड़ी भौगोलिक बाधा बनी हुई है। धातुकर्म और अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों में शीतलन तथा विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए भारी मात्रा में ताजे जल की आवश्यकता होती है। शुष्क जलवायु और सीमित भूजल के कारण पश्चिमी क्षेत्रों में जल-गहन भारी उद्योगों का विकास सीमित रहता है।

15. (C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
भीलवाड़ा राजस्थान के प्रमुख वस्त्र केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ बड़े पैमाने पर सिंथेटिक और सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। हालाँकि, पश्चिमी राजस्थान की शुष्क जलवायु प्राकृतिक वायुमंडलीय आर्द्रता प्रदान नहीं करती है। सूती कताई के लिए उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है, जो प्राकृतिक रूप से शुष्क क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होती। इसलिए भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग का विकास स्थानीय पूंजी, कताई मिलों और सिंथेटिक तकनीकों पर आधारित है।

16. (C) जयपुर
जयपुर शहर राजस्थान में आधुनिक स्टार्टअप और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित भामाशाह टेक्नो हब जैसी अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा सुविधाओं ने यहाँ के नए उद्यमियों को इनक्यूबेशन, मेंटरशिप और वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस हब के कारण जयपुर सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल समाधान और नए दौर के तकनीकी उद्यमों के लिए एक आकर्षक केंद्र बन गया है, जिससे रोजगार के अनेक अवसर पैदा हो रहे हैं।

17. (D) यह विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के लिए आरक्षित है।
जयपुर में स्थित महिंद्रा वर्ल्ड सिटी महिंद्रा समूह और रीको का एक संयुक्त उद्यम है, जो एक बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, हल्के इंजीनियरिंग और हस्तशिल्प क्षेत्रों के लिए समर्पित क्षेत्र शामिल हैं। यह कथन कि यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आरक्षित है, पूरी तरह से गलत है। यह निजी, राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संचालन के लिए भी पूरी तरह से खुला है।

NODIA

18. (C) राजस्थान एमएसएमई (स्थापना और प्रवर्तन का सुगमीकरण) अधिनियम
राजस्थान एमएसएमई अधिनियम राज्य सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना है। इस अधिनियम के तहत नए उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के बाद शुरुआती तीन से पांच वर्षों के लिए राज्य के कानूनों के तहत कई आवश्यक स्वीकृतियों और सरकारी निरीक्षणों से छूट दी जाती है। इससे लालफीताशाही समाप्त होती है और नए उद्योगों की स्थापना प्रक्रिया में काफी आसानी आती है।

19. (B) ब्लॉक और तहसील स्तरों पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना
राजस्थान में औद्योगिक विकास को केवल बड़े शहरों तक सीमित न रखकर विकेंद्रीकृत करने के लिए रीको ने विशेष रणनीति अपनाई है। इसके तहत राज्य के ब्लॉक और तहसील स्तरों पर छोटे तथा मध्यम औद्योगिक क्षेत्रों का तेजी से विकास किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रमुख महानगरीय केंद्रों में अत्यधिक भीड़भाड़ और दबाव को रोकना तथा ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

20. (D) II, III, I, IV
दिए गए औद्योगिक क्षेत्रों को उनके संबंधित जिलों के हिन्दी वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। जापानी क्षेत्र नीमराना अलवर जिले में स्थित है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में स्थित है, बोरानाडा एग्रो फूड पार्क जोधपुर जिले में आता है तथा गोटन नागौर जिले में स्थित है। जब जिलों के नाम अलवर, जयपुर, जोधपुर और नागौर के क्रम में लिखे जाते हैं, तो सही अनुक्रम II, III, I और IV प्राप्त होता है।

21. (A) व्यापार सुगमता (ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस) सुधारों का कार्यान्वयन
भारत सरकार द्वारा राज्यों की औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता और निवेश वातावरण का आकलन करने के लिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत व्यापार सुगमता रैंकिंग का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत विनिर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों को आसान बनाने के लिए प्रशासनिक सुधारों, एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली, पारदर्शी श्रम नियमों तथा डिजिटल मंजूरियों के क्रियान्वयन की स्थिति को मापा जाता है। यह रैंकिंग राज्यों को अपने निवेश माहौल में सुधार करने हेतु प्रेरित करती है।

22. (C) नवीकरणीय ऊर्जा और धातुकर्म उद्योग
हाल के वर्षों में राजस्थान ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। राज्य में विशाल भूमि संसाधनों और उच्च सौर विकिरण की उपलब्धता के कारण नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में भारी विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही, समृद्ध खनिज संपदा के कारण धातुकर्म उद्योगों में भी विदेशी निवेशकों ने गहरी रुचि दिखाई है, जिससे राज्य की औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिला है।

23. (A) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)
राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र की बढ़ती जनशक्ति आवश्यकताओं और कुशल कार्यबल के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली पर बल देती है। इस प्रणाली के तहत छात्रों को कक्षाओं में सैद्धांतिक शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ कारखानों में व्यावहारिक औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे प्रशिक्षुओं को आधुनिक तकनीकों का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है और उद्योगों को कुशल श्रम उपलब्ध होता है।

24. (D) जैसलमेर
राजस्थान की प्रमुख सीमेंट विनिर्माण पट्टी में चित्तौड़गढ़, नागौर, पाली, सिरोही और बूंदी जैसे जिले शामिल हैं, जहाँ उच्च ग्रेड चूना पत्थर के विशाल भंडार मौजूद हैं। हालाँकि, जैसलमेर जिले को राज्य की मुख्य सीमेंट विनिर्माण पट्टी के प्राथमिक केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। यद्यपि वहाँ कुछ चूना पत्थर पाया जाता है, लेकिन विशाल सीमेंट कारखानों का संकेंद्रण मुख्य रूप से दक्षिणी और मध्य-पूर्वी जिलों तक ही सीमित रहा है।

25. (B) केवल I, II और IV
राजस्थान निवेश संवर्धन योजना के तहत विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों को राज्य वस्तु एवं सेवा कर के आधार पर निवेश सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह पात्र औद्योगिक इकाइयों को एक निश्चित अवधि के लिए विद्युत शुल्क में 100% की छूट भी देती है। इसके अतिरिक्त, इस योजना में विशिष्ट प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों की पहचान करके उन्हें अतिरिक्त लाभ दिए जाते हैं। यह कहना गलत है कि सेवा क्षेत्र के प्रोत्साहनों पर प्रतिबंध है।

26. (C) घिलोठ, अलवर
राजस्थान में विशिष्ट विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से रीको ने अलवर जिले के घिलोठ में एक समर्पित दक्षिण कोरियाई औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की है। नीमराना में जापानी क्षेत्र की शानदार सफलता के बाद घिलोठ को विकसित किया गया ताकि कोरियाई विनिर्माण कंपनियों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा प्रदान किया जा सके। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो-कंपोनेंट्स और उपभोक्ता सामान बनाने वाली कई प्रमुख विदेशी इकाइयाँ सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं।

27. (D) ब्यावर
राजस्थान में आधुनिक औद्योगिक युग की शुरुआत वर्ष 1889 में ब्यावर शहर में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना के साथ हुई थी। यह राज्य की पहली संगठित सूती वस्त्र मिल थी, जिसने राजस्थान के पारंपरिक वस्त्र उद्योग को आधुनिक मशीनीकृत स्वरुप प्रदान किया। ब्यावर में इस ऐतिहासिक मिल की स्थापना ने राज्य में वस्त्र उद्योग के भावी विकास का मार्ग प्रशस्त किया और औद्योगिक रोजगार के नए अवसर पैदा किए।

28. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
राजस्थान के विभिन्न जिले अपनी विशिष्ट औद्योगिक गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। अजमेर जिले का किशनगढ़ संगमरमर प्रसंस्करण का सबसे बड़ा केंद्र है। धौलपुर जिला अपने उन्नत काँच निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है। पाली शहर कपड़ा रंगाई और छपाई उद्योग में अग्रणी स्थान रखता है। इसके अलावा अलवर का भिवाड़ी क्षेत्र ऑटो-कंपोनेंट्स और हल्के इंजीनियरिंग विनिर्माण में देश भर में प्रमुख स्थान रखता है।

29. (B) राजनिवेश
राजस्थान सरकार ने राज्य में औद्योगिक स्वीकृतियों और अनुमतियों को सुगम बनाने के लिए 'राजनिवेश' नामक एक

Downloaded from www.pdf.tube

समर्पित ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल एकल-खिड़की केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहाँ उद्यमी विभिन्न विभागों से जुड़ी स्वीकृतियों के लिए एक ही स्थान पर आवेदन कर सकते हैं। इसने समयबद्ध मंजूरी सुनिश्चित करके लालफीताशाही को घटाया है और राज्य में व्यवसाय संचालन को अत्यधिक सरल और पारदर्शी बनाया है।

30. (B) राज्य के पास सस्ते औद्योगिक माल परिवहन के लिए जलमार्गों का एक पूर्ण विकसित अंतर्देशीय नेटवर्क है।
राजस्थान का औद्योगिक परिदृश्य काफी विविध है। राज्य संगमरमर, ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर जैसे पत्थरों का प्रमुख उत्पादक है तथा सूक्ष्म और लघु उद्यम यहाँ की रीढ़ हैं। इसके अलावा राज्य सीसा, जस्ता और वोलास्टोनाइट में एकाधिकार रखता है। हालाँकि, यह कहना गलत है कि राज्य में अंतर्देशीय जलमार्गों का नेटवर्क है, क्योंकि राजस्थान एक भू-आबद्ध राज्य है जहाँ बारहमासी नौगम्य नदियों का पूर्ण अभाव है।

31. (A) इसे व्यापार संचालन, शुल्क और करों के लिए विदेशी क्षेत्र माना जाता है।
विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत स्थापित सेज का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी मुद्रा अर्जित करना है। व्यावसायिक संचालन, सीमा शुल्क और कराधान के संदर्भ में सेज को विदेशी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ स्थापित औद्योगिक इकाइयों को शुल्क-मुक्त आयात, कर रियायतें और सरल विनियामक प्रक्रियाएँ प्रदान की जाती हैं। यह व्यवस्था निर्यात-उन्मुख विनिर्माण को प्रतिस्पर्धी बनाती है और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बड़े पैमाने पर आकर्षित करती है।

32. (C) केवल I और II
राजस्थान सरकार की 'आईस्टार्ट' पहल सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के तहत संचालित होती है। यह मंच स्टार्टअप्स, निवेशकों और इनक्यूबेटरों के लिए एक एकीकृत एकल-खिड़की संसाधन के रूप में कार्य करता है। यह योजना किसी भी वर्ग या लिंग के योग्य उद्यमियों को वित्तीय, तकनीकी और मेंटरशिप सहायता प्रदान करती है। इसलिए यह कथन गलत है कि यह सहायता केवल महिला उद्यमियों तक सीमित है, जबकि पहले दो कथन सत्य हैं।

33. (D) वस्त्र रंगाई और प्रसंस्करण
पाली औद्योगिक क्षेत्र वस्त्र रंगाई और प्रसंस्करण इकाइयों का एक विशाल क्लस्टर है। इन इकाइयों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट से बांडी नदी और आसपास के भूजल में अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न होता है। इस पर्यावरणीय समस्या से निपटने के लिए यहाँ सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इन संयंत्रों का प्राथमिक उद्देश्य वस्त्र प्रसंस्करण से निकले दूषित पानी का उपचार करना और पर्यावरण में होने वाले नुकसान को कम करना है।

34. (C) पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में समर्पित प्राथमिकता-क्षेत्र औद्योगिक पार्क स्थापित करना
राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 का मुख्य ध्येय राज्य में समावेशी और संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। इस नीति के अंतर्गत पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में समर्पित प्राथमिकता-क्षेत्र औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर विशेष बल दिया गया है। इससे बुनियादी ढाँचे का विस्तार ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों तक होता है, जिससे स्थानीय संसाधनों का कुशल उपयोग होता है और क्षेत्रीय विषमता दूर करने में मदद मिलती है।

35. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।
राजस्थान में सीमेंट उद्योग का मुख्य जमाव चित्तौड़गढ़ और निंबाहेड़ा जैसे क्षेत्रों में केंद्रित है। सीमेंट विनिर्माण एक भार-ह्रासकारी प्रक्रिया है, जिसमें प्रयुक्त कच्चा माल जैसे चूना पत्थर भारी और सस्ता होता है। दूर तक परिवहन करने पर लागत अत्यधिक बढ़ जाती है, इसलिए कारखानों की स्थापना खदानों के समीप की जाती है। इस प्रकार कारण (R) पूरी तरह से कथन (A) की सही और तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करता है।

36. (D) निवेश संवर्धन ब्यूरो (बीआईपी)
राजस्थान में बड़े और विशाल निवेश प्रस्तावों को आकर्षित करने तथा उन्हें सुचारू रूप से लागू करने के लिए निवेश संवर्धन ब्यूरो शीर्ष नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह संस्था वृहद निवेशकों को एक ही स्थान पर सभी प्रकार की प्रशासनिक सहायता, परियोजना सुविधाएँ और अंतर-विभागीय स्वीकृतियाँ प्रदान करती है। बीआईपी का मुख्य उद्देश्य राज्य में प्रत्यक्ष निवेश को सुगम बनाना और बड़े उद्योगों की स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर करना है।

37. (A) फुटलूस उद्योग
जयपुर के टेक पार्कों में स्थित सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर उद्योगों को फुटलूस उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन उद्योगों की स्थापना किसी विशेष कच्चे माल के स्रोत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इन्हें केवल कुशल मानव संसाधन, उच्च गति इंटरनेट और विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ये उद्योग किसी भी स्थान पर आसानी से संचालित किए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें कच्चे माल से मुक्त यानी फुटलूस उद्योग कहा जाता है।

NODIA

38. (C) बाड़मेर
बाड़मेर जिले में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों की खोज के बाद यहाँ पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का तीव्र विकास हुआ है। स्थानीय हाइड्रोकार्बन संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए बाड़मेर में पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स निवेश क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना राज्य में पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योगों, प्लास्टिक निर्माण और संबद्ध रासायनिक विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

39. (A) प्रत्यक्ष समुद्री बंदरगाह कनेक्टिविटी की कमी के परिणामस्वरूप उच्च माल ढुलाई लागत
राजस्थान एक भू-आबद्ध राज्य है, जिसके पास कोई प्रत्यक्ष समुद्री तट रेखा या बंदरगाह सुविधा मौजूद नहीं है। तटीय राज्यों की तुलना में यह स्थिति यहाँ के विनिर्माण क्षेत्र के लिए

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (D) स्थानीय संरक्षण द्वारा पोषित पारंपरिक हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग
स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में औद्योगिक ढाँचा अत्यंत सीमित और अविकसित था। उस समय संपूर्ण राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पारंपरिक हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों पर निर्भर थी। स्थानीय राजाओं और सामंतों के संरक्षण में इन उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता था। राज्य में आधुनिक भारी उद्योगों, विशाल निर्माण कारखानों और संगठित विनिर्माण ढाँचे का अभाव था। कपड़ा बुनाई, धातु शिल्प, आभूषण तथा नक्काशी ही स्थानीय आजीविका के प्रमुख माध्यम थे। यह हस्तशिल्प प्रणाली स्थानीय संसाधनों पर पूरी तरह आधारित थी।

2. (C) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम (आरएसआईएमडीसी)
राजस्थान में पारंपरिक हस्तशिल्प आधारित अर्थव्यवस्था से आधुनिक औद्योगिक संरचना में परिवर्तन को गति देने के लिए वर्ष 1969 में राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। इस संस्थागत निकाय ने राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढाँचे के विकास, खनिज संसाधनों के दोहन और योजनाबद्ध औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाई। बाद में वर्ष 1980 में खनिज विकास को अलग करके रीको के रूप में इसे पुनर्गठित किया गया।

3. (B) सिंथेटिक ब्लेंडिंग, कताई और सूटिंग फैब्रिक उत्पादन
भीलवाड़ा जिला राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल है। इसे मुख्य रूप से सिंथेटिक ब्लेंडिंग, कताई और सूटिंग फैब्रिक उत्पादन में अत्यधिक संकेंद्रण के कारण राजस्थान की वस्त्र नगरी के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में आधुनिक पावरलूम और कताई मिलों का एक विशाल नेटवर्क स्थापित है, जो देश के कुल सिंथेटिक कपड़े के बहुत बड़े हिस्से का उत्पादन करता है। यहाँ निर्मित सूटिंग फैब्रिक की राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में व्यापक माँग रहती है।

4. (D) वस्त्र रंगाई इकाइयों से बांडी नदी में अनुपचारित रासायनिक अपशिष्ट का विसर्जन
पाली औद्योगिक क्लस्टर कपड़ा रंगाई और छपाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हालाँकि, इन इकाइयों से निकलने वाले अनुपचारित रासायनिक अपशिष्ट को बांडी नदी में बहा दिए जाने के कारण गंभीर जल और मृदा प्रदूषण उत्पन्न हुआ है। इस पर्यावरणीय क्षति के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने क्षेत्र की अनेक औद्योगिक इकाइयों पर सख्त नियामक नियम लागू किए और कई बार बंदी के आदेश जारी किए। अपशिष्ट उपचार संयंत्रों के अभाव ने यहाँ गंभीर संकट उत्पन्न किया।

5. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
राजस्थान में विशिष्ट औद्योगिक पार्कों की स्थापना विभिन्न जिलों की स्थानिक विशेषताओं के अनुसार की गई है। जापानी औद्योगिक क्षेत्र नीमराना में स्थित है, जो अलवर जिले के अंतर्गत आता है। मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ में स्थित है, जो अजमेर जिले में स्थित है। फिनटेक पार्क राज्य की राजधानी जयपुर में विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्पाइसेज अथवा मसाला पार्क जोधपुर जिले में स्थापित किया गया है। यह व्यवस्था क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को संतुलित बनाती है।

6. (C) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) तथा गुरुग्राम-मानसर औद्योगिक केंद्र से निकटता
भिवाड़ी राजस्थान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र है। इसकी तीव्र औद्योगिक प्रगति का मुख्य कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित होना और गुरुग्राम तथा मानसर जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से इसकी भौगोलिक निकटता है। इस रणनीतिक अवस्थिति के कारण यहाँ परिवहन लागत कम होती है और विशाल उपभोक्ता बाजारों तक सीधी पहुँच सुलभ हो जाती है। इसके अलावा उत्कृष्ट सड़क ढाँचे ने यहाँ भारी निवेश आकर्षित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

7. (A) ऑटो-कंपोनेंट्स और हल्के इंजीनियरिंग सामान
अलवर जिले में स्थित भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र पूरे देश में ऑटो-कंपोनेंट्स और हल्के इंजीनियरिंग सामानों के विनिर्माण हब के रूप में विख्यात है। यहाँ अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल घटकों के निर्माण संयंत्र स्थित हैं। दिल्ली-एनसीआर से निकटता और आधुनिक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के कारण यह क्षेत्र वाहन निर्माण कलपुर्जों की आपूर्ति श्रृंखला में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यहाँ निर्मित इंजीनियरिंग घटकों का बड़े पैमाने पर निर्यात भी किया जाता है।

8. (D) नई निवेश इकाइयों के लिए लक्षित वित्तीय प्रोत्साहन, पूंजीगत सब्सिडी और कर छूट प्रदान करना
राजस्थान निवेश संवर्धन योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में नए औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की इकाइयों को लक्षित वित्तीय प्रोत्साहन, पूंजीगत सब्सिडी, बिजली शुल्क में राहत और कर छूट प्रदान की जाती है। यह नीतिगत ढाँचा राज्य में व्यापार की लागत को कम करता है और निवेश योग्य वातावरण का निर्माण करके औद्योगिक विकास को गति देता है।

Click Here to Buy book on Amazon

की जाती है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, रोजगार के नए साधन सृजित होते हैं और उत्पादों का निर्यात बढ़ता है।

50. (C) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (एमएलयूपीवाई)
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य राजस्थान में नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत नए उद्यमियों तथा मौजूदा उद्योगों के विस्तार के लिए बैंकों से प्राप्त ऋण पर रियायती ब्याज दरें और ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। इससे उद्यमियों को सस्ती दरों पर पूंजी उपलब्ध होती है, जिससे राज्य में नए स्वरोजगार और औद्योगिक विनिर्माण को व्यापक संबल प्राप्त होता है।

51. (B) वे गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की तुलना में उच्च पूंजीगत सब्सिडी और लंबी कर छूट प्राप्त करते हैं।
राजस्थान की औद्योगिक नीतियों में "उभरते या प्राथमिकता वाले क्षेत्रों" के रूप में पहचाने गए उद्योगों को विशेष वित्तीय और रणनीतिक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इन क्षेत्रों को सामान्य गैर-प्राथमिकता उद्योगों की तुलना में अधिक पूंजीगत सब्सिडी, लंबी अवधि के लिए कर छूट और विद्युत शुल्क राहत प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च तकनीक, हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी निर्माण जैसे भविष्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है।

52. (D) केवल I और III
भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग की अभूतपूर्व सफलता में कुशल प्रवासी श्रम की प्रचुर उपलब्धता और स्थानीय उद्यमियों की सक्रिय पूंजी तथा बुनियादी ढाँचे के विकास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि, यह क्षेत्र किसी स्थानीय लंबे रेशे वाले कपास उत्पादन पर आश्रित नहीं है, क्योंकि यह मुख्य रूप से सिंथेटिक और मिश्रित धागे के विनिर्माण पर केंद्रित है। अतः पहला और तीसरा कारक भीलवाड़ा के औद्योगिक विकास के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

53. (A) महल, जगतपुरा (जयपुर)
रीको ने तैयार कपड़ों और तकनीकी वस्त्रों के निर्माण तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जयपुर के जगतपुरा स्थित महल में एक समर्पित परिधान पार्क विकसित किया है। इस पार्क में आधुनिक बुनियादी ढाँचा, प्लग-एंड-प्ले सुविधाएँ और निर्यात सहायता तंत्र उपलब्ध कराया गया है। यह केंद्र परिधान निर्माताओं को उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र तैयार करने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भेजने के लिए अनुकूल वातावरण और बुनियादी सेवाएँ प्रदान करता है।

54. (C) यदि प्राधिकरण वैधानिक समय सीमा के भीतर निर्णय लेने में विफल रहता है तो मंजूरी स्वीकृत मानी जाती है।
सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम में "माना गया अनुमोदन" की अवधारणा प्रशासनिक गति बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसके अंतर्गत यदि संबंधित विनियामक प्राधिकरण निर्धारित वैधानिक समयावधि के भीतर किसी औद्योगिक आवेदन पर निर्णय लेने या अनुमति देने में विफल रहता है, तो उस मंजूरी को स्वतः स्वीकृत मान लिया जाता है। यह व्यवस्था अधिकारियों की जवाबदेही तय करती है और उद्यमियों को अनावश्यक प्रशासनिक देरी से राहत दिलाती है।

55. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।
राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन और उपकरण विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए देश का सबसे पसंदीदा गंतव्य है। इसका मुख्य भौगोलिक कारण यह है कि राज्य में वर्ष भर उच्च सौर विकिरण तीव्रता प्राप्त होती है और विशाल बंजर भूमि उपलब्ध है। यह भूमि बड़े सौर पार्कों और संबंधित विनिर्माण इकाइयों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। अतः कारण (R) पूरी तरह से कथन (A) की व्याख्या करता है।

56. (D) औद्योगिक रसद लागत को कम करने के लिए रेल और सड़क माल परिवहन को एकीकृत करना
मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक लॉजिस्टिक्स लागत को घटाना और आपूर्ति श्रृंखला को अधिक कुशल बनाना है। यह पार्क रेल, सड़क और अंतर्देशीय माल परिवहन सुविधाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत करता है। इससे माल का स्थानांतरण, भंडारण और निर्बाध परिवहन आसान हो जाता है। यह बुनियादी ढाँचा राजस्थान के औद्योगिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक प्रतिस्पर्धी दरों पर पहुँचाने में मदद करता है।

NODIA

57. (B) मशीनीकृत ब्लॉक प्रिंटिंग और सिंथेटिक कपड़े की रंगाई
पाली जिले की पारंपरिक बंधेज और हस्तशिल्प कला समय के साथ एक आधुनिक औद्योगिक क्लस्टर में परिवर्तित हो चुकी है। अब यह क्षेत्र मशीनीकृत ब्लॉक प्रिंटिंग, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग और सिंथेटिक कपड़ों की रंगाई का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। इस परिवर्तन ने पारंपरिक हुनर को व्यावसायिक स्तर पर पहुँचाया है, जिससे यहाँ बड़े पैमाने पर कपड़े का उत्पादन होता है और यह क्लस्टर देश भर के बाजारों में परिधान पहुँचाता है।

58. (C) गंभीर एनसीआर वायु प्रदूषण के कारण लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) प्रतिबंध
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से निकटता भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के लिए अत्यंत लाभदायक है, लेकिन यही स्थिति इसके लिए चुनौती भी प्रस्तुत करती है। सर्दियों के मौसम में पूरे एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब होने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के प्रतिबंध लागू कर दिए जाते हैं। इन पर्यावरणीय दिशानिर्देशों के कारण यहाँ के कारखानों, निर्माण गतिविधियों और जेनरेटरों के संचालन पर अस्थायी रोक लग जाती है, जिससे औद्योगिक उत्पादन बाधित होता है।

59. (D) कोयला
राजस्थान की सीमेंट पट्टी में क्लिंकर भट्टियों के संचालन के लिए कोयला सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य तापीय ऊर्जा स्रोत है। चूना पत्थर से क्लिंकर बनाने की प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, जो कोयले के दहन से प्राप्त होता है। राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के सीमित स्रोतों के कारण सीमेंट उद्योग को छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे

80. (A) II, I, IV, III
भीलवाड़ा के एकीकृत वस्त्र उद्योग में कपड़े के निर्माण की प्रक्रिया एक निश्चित क्रमिक क्रम का पालन करती है। सबसे पहले कताई प्रक्रिया द्वारा कच्चे रेशों से धागे का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद बुनाई चरण में धागे से कच्चा कपड़ा तैयार होता है। तीसरे चरण में कपड़े की रंगाई और प्रसंस्करण करके उसे अंतिम रूप दिया जाता है। सबसे अंत में सिलाई और परिधान निर्माण करके बिक्री हेतु तैयार वस्त्र बनाए जाते हैं।

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

70. (C) कौशल प्रशिक्षण से जुड़े युवा बेरोजगारी भत्ते प्रदान करना
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण से जोड़कर औद्योगिक क्षेत्र का अप्रत्यक्ष समर्थन करती है। इस योजना के तहत पात्र युवाओं को मासिक बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए अनिवार्य रूप से कौशल प्रशिक्षण और सरकारी विभागों में इंटर्नशिप करनी होती है। इससे युवाओं का कौशल विकास होता है, जिससे वे राज्य के उद्योगों की कार्यबल आवश्यकताओं के लिए तैयार होते हैं।

71. (A) राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (आरईवीपी)
राजस्थान सरकार ने राज्य में ई-वाहनों के निर्माण और उनके व्यापक उपयोग को गति देने के लिए राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की है। यह नीति ई-वाहन खरीदारों को प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन और रोड टैक्स में राहत प्रदान करके रिप्स की पूरक बनती है। इस पहल से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की माँग बढ़ती है, जिससे ईवी विनिर्माण इकाइयों, बैटरी निर्माताओं और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को व्यापक प्रोत्साहन मिलता है।

72. (D) केवल I और III
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना का राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह पश्चिमी समुद्री बंदरगाहों तक माल परिवहन के समय में भारी कमी लाती है और इसके प्रभाव क्षेत्र में विशेष निवेश क्षेत्रों तथा औद्योगिक शहरों का विकास शामिल है। हालाँकि, यह कहना गलत है कि यह पूर्वी जिलों के कृषि विकास पर केंद्रित है, क्योंकि यह मुख्य रूप से औद्योगिक विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचे पर केंद्रित है।

73. (B) नागौर
नागौर का रीको औद्योगिक क्षेत्र अपने ऐतिहासिक धातुकर्म कौशलों और पारंपरिक लोहार परंपरा का उपयोग करते हुए विशेष हस्त औजारों तथा कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। यहाँ बने कुल्हाड़ी, हथौड़े, कृषि हल और कटाई के औजार अपनी स्थायित्व और गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। इस पार पारंपरिक कौशल को आधुनिक विनिर्माण तकनीकों के साथ जोड़कर एक मजबूत लघु उद्योग क्लस्टर के रूप में विकसित किया गया है।

74. (C) सेज निर्यात पर केंद्रित शुल्क-मुक्त एन्क्लेव हैं, जबकि नियमित औद्योगिक क्षेत्र घरेलू और निर्यात दोनों की सेवा करते हैं।
राजस्थान में नियमित रीको औद्योगिक क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र के बीच मुख्य अंतर उनके बाजार लक्ष्य और कर संरचना में है। सेज मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा कमाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुल्क-मुक्त विदेशी क्षेत्र माने जाते हैं। इसके विपरीत, सामान्य रीको औद्योगिक क्षेत्र घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ निर्यात दोनों के लिए उत्पादन करने वाली सभी प्रकार की सामान्य औद्योगिक इकाइयों की मेजबानी करते हैं।

75. (D) केवल I, II और III
भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र का एक प्रमुख भाग है। इसे दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से निकटता का अत्यधिक भौगोलिक लाभ मिलता है, लेकिन एनसीआर में स्थित होने के कारण इसे कड़े पर्यावरणीय नियमों का सामना करना पड़ता है। चौथा कथन गलत है क्योंकि भिवाड़ी लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादक नहीं है, बल्कि यह मुख्यतः एक ऑटो-कंपोनेंट और इंजीनियरिंग सामानों का विनिर्माण केंद्र है।

76. (A) मानपुरा माचेड़ी, जयपुर
चमड़ा उद्योग के संकेंद्रण और उससे उत्पन्न होने वाले विशिष्ट अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन के लिए रीको ने जयपुर जिले के मानपुरा माचेड़ी में एक समर्पित लेदर कॉम्प्लेक्स स्थापित किया है। इस कॉम्प्लेक्स में चमड़ा प्रसंस्करण इकाइयों, फुटवियर निर्माताओं और हस्तशिल्पकारों के लिए एकीकृत बुनियादी ढाँचा तथा अपशिष्ट उपचार सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। यह कॉम्प्लेक्स पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ चमड़ा शिल्प और निर्यात को बढ़ावा देने में सहायक है।

77. (B) फ्लाई एश (उड़न राख)
राजस्थान के आधुनिक सीमेंट संयंत्र पारंपरिक चूना पत्थर पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को कम करने और औद्योगिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली फ्लाई एश का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं। पोज़ोलाना सीमेंट के निर्माण में फ्लाई एश का मिश्रण करने से सीमेंट की मजबूती बढ़ती है और पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। यह प्रक्रिया सीमेंट उद्योग को अधिक टिकाऊ और लागत-प्रभावी बनाती है।

NODIA

78. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।
पाली में कपड़ा रंगाई और छपाई उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों के कारण बार-बार कारखाने बंद करने पड़ते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि कई प्रसंस्करण इकाइयाँ अपने सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों को उन्नत बनाने में विफल रहती हैं, जिससे विषैला रासायनिक अपशिष्ट बांडी नदी में बहकर गंभीर प्रदूषण फैलाता है। इस प्रकार कारण (R) पूरी तरह से कथन (A) में दी गई स्थिति की सत्य व्याख्या करता है।

79. (A) इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी)
जोधपुर और बाड़मेर जैसे शुष्क पश्चिमी जिलों में स्थित प्रमुख रीको औद्योगिक क्षेत्रों के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना पानी की निर्बाध आपूर्ति की मुख्य रीढ़ की हड्डी है। इन अत्यंत शुष्क भौगोलिक क्षेत्रों में स्थानीय सतही जल का अभाव होने के कारण नहर के पानी को लिफ्ट परियोजनाओं के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुँचाया जाता है। यह जल आपूर्ति पश्चिमी राजस्थान में कारखानों के सुचारु संचालन और औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

राज्यों से महंगे रेल माल भाड़े के माध्यम से कोयला आयात करना पड़ता है।

60. (A) उद्योग निदेशालय → राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) → रीको → निवेश संवर्धन ब्यूरो (बीआईपी)
राजस्थान में औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना का सही कालानुक्रमिक क्रम देखना आवश्यक है। उद्योग निदेशालय की स्थापना स्वतंत्रता के तुरंत बाद वर्ष 1949 में हुई थी। इसके बाद वर्ष 1955 में राजस्थान वित्त निगम का गठन किया गया। रीको को वर्ष 1969 में स्थापित करके 1980 में पुनर्गठित किया गया। अंत में, बड़े निवेशों को सुगम बनाने के लिए वर्ष 1991 में निवेश संवर्धन ब्यूरो का गठन किया गया था।

61. (B) जोधपुर
राजस्थान सरकार जोधपुर जिले में फार्मास्युटिकल और चिकित्सा उपकरण निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित 'मेडिकल डिवाइस पार्क' विकसित कर रही है। इस पार्क का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए आधुनिक चिकित्सा उपकरणों, सर्जिकल सामानों और नैदानिक प्रणालियों के स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। यहाँ अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा और परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा रही हैं, जिससे राज्य में उच्च-तकनीक आधारित स्वास्थ्य उद्योगों को प्रोत्साहन मिल रहा है।

62. (B) केवल I, II और III
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना को जापान सरकार से तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्राप्त है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस परियोजना की मुख्य लॉजिस्टिक्स रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है, जिसका ध्येय स्मार्ट औद्योगिक शहरों का विकास करना है। चौथा कथन पूरी तरह गलत है क्योंकि यह परियोजना राजस्थान को बायपास नहीं करती, बल्कि राजस्थान का लगभग 39% कॉरिडोर क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, जो इसके केंद्र में है।

63. (D) 100%
राजस्थान निवेश संवर्धन योजना के नीतिगत ढाँचे के तहत राज्य में स्थापित होने वाली मानक पात्र औद्योगिक इकाइयों को एक निर्दिष्ट शुरुआती अवधि के लिए बिजली शुल्क पर 100% की पूर्ण छूट दी जाती है। इस शत-प्रतिशत छूट का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की शुरुआती परिचालन लागत को कम करना है, जिससे निवेशक राज्य में अपने कारखाने स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित हों और विनिर्माण गतिविधियों में तेजी आ सके।

64. (C) सांभर-पचपदरा-डीडवाना पट्टी
राजस्थान में नमक-आधारित रासायनिक उद्योग मुख्य रूप से सांभर, पचपदरा और डीडवाना की खारी झील पट्टी में संकेंद्रित हैं। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से खारे पानी के विशाल स्रोत और नमक के भंडार मौजूद हैं। इस कच्चे माल का उपयोग करके सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड जैसी औद्योगिक रसायनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। यह पट्टी राज्य की रासायनिक निर्माण गतिविधियों का एक मुख्य आधार केंद्र है।

65. (D) बॉल क्ले और फायर क्ले
बीकानेर और बाड़मेर जिलों के शुष्क पश्चिमी क्षेत्रों में बॉल क्ले और फायर क्ले जैसे औद्योगिक खनिजों के विशाल भंडार मौजूद हैं। ये मिट्टी खनिज उच्च तापमान को सहन करने की क्षमता रखते हैं, जिसके कारण ये सिरामिक, चीनी मिट्टी के बर्तन और अग्निसह ईंटों के निर्माण में प्राथमिक कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इन खनिजों की प्रचुरता ने राज्य में सिरामिक विनिर्माण उद्योग को मजबूत आधार प्रदान किया है।

66. (C) यह मेगा परियोजना की बाधाओं को दूर करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति को अधिकार प्रदान करता है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाला बुनियादी ढांचा विकास और निवेश संवर्धन बोर्ड एक अत्यंत सशक्त उच्च-स्तरीय निकाय है। इसका मुख्य कार्य राज्य में बड़े आकार की मेगा औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की प्रशासनिक तथा विनिमायक बाधाओं को तुरंत दूर करना है। यह बोर्ड अंतर-विभागीय मुद्दों को सुलझाता है, नीतिगत फैसले लेता है और त्वरित स्वीकृतियाँ प्रदान करके राज्य में बड़े निवेशों के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।

67. (B) जोधपुर
रीको ने जोधपुर शहर में सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर कंपनियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक समर्पित 'साइबर पार्क' विकसित किया है। यह पार्क आईटी कंपनियों को आधुनिक कनेक्टिविटी, बिजली बैकअप और उच्च स्तरीय ढांचागत सुविधाएँ प्रदान करता है। जोधपुर में स्थापित यह साइबर पार्क पश्चिमी राजस्थान में सॉफ्टवेयर विकास, आईटीईएस सेवाओं और तकनीकी स्वरोजगार को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण संस्थागत केंद्र के रूप में उभर रहा है।

68. (D) P-2, Q-3, R-1, S-4
राजस्थान के विभिन्न औद्योगिक खनिजों का विशिष्ट उद्योगों में महत्वपूर्ण उपयोग होता है। रॉक फॉस्फेट का प्राथमिक उपयोग रासायनिक उर्वरक उत्पादन में होता है। सिलिका सैंड का उपयोग मुख्य रूप से काँच निर्माण उद्योग में किया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट निर्माण का मुख्य कच्चा माल है, जबकि टंगस्टन का उपयोग रक्षा उपकरणों तथा बल्ब के फिलामेंट बनाने वाले उद्योगों में उच्च गलनांक के कारण किया जाता है।

69. (A) कोकिंग कोल और पर्याप्त ताजे पानी की कमी
राजस्थान में भारी और एकीकृत लौह तथा इस्पात संयंत्रों की स्थापना न हो पाने का सबसे मुख्य कारण धातुकर्म श्रेणी के कोकिंग कोल और पर्याप्त ताजे पानी की गंभीर कमी है। इस्पात निर्माण में लोहे को पिघलाने के लिए कोकिंग कोल अनिवार्य है, जो राज्य में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जल-गहन विनिर्माण प्रक्रिया के कारण राज्य की शुष्क जलवायु और सीमित नदियाँ भारी इस्पात संयंत्रों के संचालन में बाधा बनती हैं।

Click Here to Buy book on Flipkart

अध्याय 19

राजस्थान के लघु, कुटीर एवं ग्रामोद्योग

1. निम्नलिखित में से कौन-सी राजस्थान के पारंपरिक कुटीर उद्योग की प्रमुख विशेषता है?
   (A) यह पूरी तरह से वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त आयातित विदेशी कच्चे माल पर निर्भर करता है।
   (B) यह आमतौर पर गृह-आधारित होता है और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित होता है।
   (C) यह मुख्य रूप से औद्योगिक संयंत्रों में स्थापित आधुनिक स्वचालित मशीनों द्वारा संचालित होता है।
   (D) इसके संचालन के लिए न्यूनतम 10 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत निवेश की आवश्यकता होती है।

2. पारंपरिक ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
   (A) 1947
   (B) 1955
   (C) 1972
   (D) 1995

3. निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर राजस्थान में पारंपरिक ग्रामीण या कुटीर उद्योग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है?
   (A) चमड़े की मोज़री निर्माण
   (B) हथकरघा बुनाई
   (C) पेट्रोलियम शोधन
   (D) मिट्टी के बर्तन (मृद्भांड) बनाना

4. स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को बेचने के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसिको) द्वारा स्थापित आधिकारिक खुदरा विपणन ब्रांड का नाम क्या है?
   (A) राजदर्पण
   (B) शिल्पग्राम
   (C) राजक्राफ्ट्स
   (D) राजस्थली

5. जयपुर की प्रसिद्ध 'ब्लू पॉटरी' की पारंपरिक निर्माण प्रक्रिया में किस कच्चे माल का उपयोग स्पष्ट रूप से वर्जित किया जाता है?
   (A) क्वार्ट्ज़ पाउडर
   (B) सोडियम सल्फेट
   (C) सामान्य मिट्टी
   (D) मुल्तानी मिट्टी

6. कुटीर एवं ग्रामोद्योगों को राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
   (A) वे ग्रामीण जिलों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्राथमिक गंतव्य के रूप में कार्य करते हैं।
   (B) वे कम पूंजीगत निवेश के साथ ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार उत्पन्न करते हैं।
   (C) वे खनिजों के प्रसंस्करण के लिए भारी औद्योगिक बुनियादी ढांचे और बिजली ग्रिड का उपयोग करते हैं।
   (D) वे आधिकारिक तौर पर आयकर से पूरी तरह मुक्त एकमात्र संस्थाओं के रूप में नामित हैं।

7. 'मोज़री' के नाम से प्रसिद्ध पारंपरिक चमड़े के जूते राजस्थान के किस प्रमुख क्लस्टर में मुख्य रूप से कुटीर उद्योग के रूप में निर्मित किए जाते हैं?
   (A) जैसलमेर और बाड़मेर
   (B) कोटा और बूंदी
   (C) डूंगरपुर और बांसवाड़ा
   (D) जोधपुर और बीकानेर

8. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
   अभिकथन (A): कुटीर उद्योग ग्रामीण राजस्थान में महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
   कारण (R): अधिकांश पारंपरिक शिल्प-आधारित गतिविधियां घरेलू जिम्मेदारियों के साथ-साथ घर से संचालित की जा सकती हैं, जो महिलाओं को वित्तीय स्वावलंबन प्रदान करती हैं।
   (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
   (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
   (C) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
   (D) अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

9. राजस्थान में 'मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना' के तहत 25 लाख रुपये तक के बैंक ऋण पर प्रदान की जाने वाली अधिकतम ब्याज अनुदान दर कितनी है?
   (A) 5 प्रतिशत
   (B) 6 प्रतिशत
   (C) 8 प्रतिशत
   (D) 10 प्रतिशत

Downloaded from www.pdf.tube

28. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रुप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग हासिल करने से सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट जैसे राजस्थान के पारंपरिक शिल्पों के निर्यात संवर्धन में मदद मिलती है।
कारण (R): जीआई टैग अनधिकृत नकल के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है और वैश्विक खरीदारों को उत्पाद की भौगोलिक प्रामाणिकता की गारंटी देता है।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

29. स्थानीय उद्योगों को समर्थन देने के लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद (आरईपीसी) का गठन किया गया था। इसकी औपचारिक स्थापना किस वर्ष की गई थी?
(A) 1980
(B) 1991
(C) 2005
(D) 2022

30. पारंपरिक शिल्प और उसके मुख्य कच्चे माल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित है?
(A) ब्लू पॉटरी — मानक लाल मिट्टी और नदी की रेत
(B) मोज़री शिल्प — बुना हुआ सूती धागा
(C) कोटा डोरिया — ऊंट की हड्डी और सींग
(D) थेवा कला — रंगीन कांच और सोने का वर्क (पन्नी)

31. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है। ग्रामोद्योगों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इसे कौन-सी नोडल एजेंसी लागू करती है?
(A) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)
(B) भारतीय रिज़र्व बैंक
(C) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(D) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

32. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: हस्तशिल्प/वस्त्र
P. दाबू प्रिंट
Q. लकड़ी के खिलौने
R. पिछवाई पेंटिंग्स
S. संगमरमर की मूर्तियां
सूची II: राजस्थान का प्रसिद्ध केंद्र
1. नाथद्वारा
2. आकोला
3. किशनगढ़
4. बस्सी (चित्तौड़गढ़)
निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित है?
(A) P-2, Q-4, R-1, S-3
(B) P-4, Q-2, R-3, S-1
(C) P-1, Q-3, R-2, S-4
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

33. निम्नलिखित में से कौन-सा राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसिको) का मुख्य उद्देश्य नहीं है?
(A) एम्पोरियम के माध्यम से पारंपरिक शिल्पों का विपणन।
(B) बड़े पैमाने पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों का संचालन करना।
(C) छोटी इकाइयों को कच्चे माल के वितरण को सुगम बनाना।
(D) कारीगरों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना।

34. राजस्थान के हस्तशिल्प क्षेत्र में आधुनिकीकरण और परंपरा के बीच अंतर्निहित तनाव को किस कथन द्वारा सबसे अच्छी तरह से समझाया गया है?
(A) मशीनों पर प्राचीन डिजाइनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रामाणिक शिल्प पहचान को नष्ट कर सकता है।
(B) कारीगर अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्राकृतिक इनपुट के बजाय जानबूझकर सस्ते सिंथेटिक सामग्री को पसंद करते हैं।
(C) आधुनिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की आंतरिक गुणवत्ता को स्वचालित रुप से कम कर देते हैं।
(D) पारंपरिक कारीगर शुद्ध सौंदर्य मूल्यों के पक्ष में व्यावसायिक मौद्रिक लाभों को पूरी तरह से खारिज करते हैं।

NODIA

35. राजस्थान में कुटीर उद्योगों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वे सीधे बाजार जुड़ाव के अभाव से जूझते हैं और बिचौलियों पर अत्यधिक निर्भर हैं।
II. उनके पास सभी निजी बैंकों से असीमित, संपार्श्विक-मुक्त ऋण तक पहुंच है।
III. वे सस्ते, मशीन से बने नकली उत्पादों से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

36. 'कशीदा' या पारंपरिक कढ़ाई का काम, जो महिलाओं को पूरक आय प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है, राजस्थान के किस क्षेत्र में मुख्य रुप से प्रसिद्ध है?
(A) कोटा और बूंदी से मिलकर बना हाड़ौती क्षेत्र
(B) अलवर और भरतपुर से मिलकर बना मेवात क्षेत्र
(C) डूंगरपुर और बांसवाड़ा से मिलकर बना वागड़ क्षेत्र
(D) पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र (बाड़मेर, जैसलमेर)

(D) केवीआईबी → रुड़ा → राजसिको

19. कुटीर उद्योग का कौन-सा उप-क्षेत्र वर्तमान में ग्रामीण राजस्थान में सर्वाधिक महिलाओं को रोजगार प्रदान करता है?
(A) गौण खनिजों का खनन और उत्खनन
(B) लोहा ढलाई और भारी धातु कास्टिंग
(C) हथकरघा वस्त्र और हस्तशिल्प
(D) ऑटोमोबाइल घटकों और पुर्जों का निर्माण

20. राजस्थान में एमएसएमई और कुटीर उद्योगों के संवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और संचालन का सुगमीकरण) अधिनियम नई इकाइयों को कुछ वर्षों के लिए विशिष्ट स्वीकृतियों और निरीक्षणों से छूट देता है।
II. उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए 'जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट' प्रमाणन को प्रोत्साहित किया जाता है।
III. राज्य पात्र नए सूक्ष्म उद्यमों को पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है।
IV. राज्य के कानून द्वारा कारीगरों को अपने सामान का सीधे निर्यात करने से प्रतिबंधित किया गया है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) I, II और III
(B) II, III और IV
(C) I, III और IV
(D) I, II और IV

21. राजस्थान में हथकरघा उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन पूरी तरह से गलत है?
(A) हथकरघा बुनाई राज्य भर में सबसे पुराने और सबसे व्यापक पारंपरिक कुटीर उद्योगों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है।
(B) इसे आधुनिक यंत्रीकृत उच्च गति वाले पावरलूमों से निरंतर और तीव्र बाजार प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
(C) राज्य में सभी हथकरघा उत्पादों को सरकार द्वारा खरीदा जाना अनिवार्य है।
(D) इस क्षेत्र को कौशल संरक्षण और तकनीकी बुनाई के रखरखाव के लिए विशेष संस्थागत सहायता की आवश्यकता होती है।

22. ग्रामोद्योग बोर्डों द्वारा अपनाई गई सामान्य परिभाषाओं के अनुसार, 'ग्रामोद्योग' की मुख्य विशेषता क्या होती है?
(A) प्रति निर्माण इकाई 500 से अधिक पूर्णकालिक औद्योगिक श्रमिकों का निरंतर नियोजन।
(B) प्रति व्यक्ति सीमित पूंजी निवेश के साथ ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति।
(C) प्रथम श्रेणी (टियर-1) महानगरीय शहर की नगर निगम क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थायी संचालन।
(D) प्रमुख विदेशी बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेट संस्थाओं के साथ अनिवार्य वाणिज्यिक साझेदारी समझौते।

23. राजस्थान में ग्रामीण कारीगरों को डिजिटल विपणन और ई-कॉमर्स को अपनाने का प्रयास करते समय किस मुख्य बाधा का सामना करना पड़ता है?
(A) सभी ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति वाले फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट बुनियादी ढांचे की अत्यधिक अति-संतृप्ति।
(B) सांस्कृतिक विरासत उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के खिलाफ सख्त संवैधानिक निषेध लागू होना।
(C) सभी ग्रामीण जिलों में सार्वजनिक डाक और कूरियर डिलीवरी नेटवर्क की पूर्ण संरचनात्मक अनुपस्थिति।
(D) डिजिटल साक्षरता और प्लेटफॉर्म लॉजिस्टिक्स के ज्ञान का अभाव।

24. राजस्थान सरकार द्वारा अक्सर आयोजित किए जाने वाले 'अमृता हाट' का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों का विपणन करना।
(B) बड़े निजी विनिर्माण क्षेत्रों के लिए उन्नत भारी औद्योगिक मशीनरी खरीदना।
(C) व्यावसायिक कृषि उत्पादकों को सब्सिडी वाले सिंथेटिक रासायनिक उर्वरक वितरित करना।
(D) अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव फोटोग्राफरों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए इको-टूरिज्म पैकेज को बढ़ावा देना।

25. राजस्थान के ग्रामोद्योगों में सहकारी समितियों की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वे कारीगरों के लिए उचित दरों पर कच्चे माल की थोक खरीद में मदद करती हैं।
II. वे ग्रामीण बिचौलियों को खत्म करने के लिए सामूहिक विपणन सुनिश्चित करती हैं।
III. वे अनिवार्य करती हैं कि कारीगरों को अपनी सभी निजी भूमि सरकार को सौंपनी होगी।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

26. 'नमदा', एक पारंपरिक ऊनी फेल्ट शिल्प जिसमें बुनाई के बजाय दबाने की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, ऐतिहासिक रूप से राजस्थान के किस जिले में केंद्रित है?
(A) टोंक
(B) उदयपुर
(C) बांसवाड़ा
(D) श्रीगंगानगर

27. राज्य सरकार द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री बुनकर सम्मान योजना' का प्राथमिक लाभार्थी कौन-सा विशिष्ट कारीगर समूह है?
(A) मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार
(B) चमड़ा कारीगर
(C) ब्लू पॉटरी कारीगर
(D) हथकरघा बुनकर

Click Here to Buy book on Amazon

47. कौन-सी योजना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करती है जो राजस्थान के पारंपरिक कारीगरों को व्यापक कागजी कार्रवाई के बिना आधिकारिक रूप से खुद को एमएसएमई के रूप में पंजीकृत करने में सक्षम बनाती है?
(A) उद्यम पंजीकरण
(B) ई-ग्राम स्वराज
(C) किसान सुविधा
(D) वाहन पोर्टल

48. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): राजस्थान के हथकरघा बुनकरों को अक्सर आजीविका की निरंतरता के गंभीर संकट का सामना करना पड़ता है।
कारण (R): पावरलूम पारंपरिक हथकरघा डिजाइनों को बहुत तेजी से और काफी कम उत्पादन लागत पर दोहरा सकते हैं।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

49. 'गोटा पत्ती' कसीदाकारी, जो सोने या चांदी के रिबन के साथ एप्लिक कार्य वाला एक प्रसिद्ध पारंपरिक कुटीर उद्योग है, मुख्य रूप से कहां और इसके आसपास केंद्रित है?
(A) जैसलमेर, पोकरण और आसपास के रेगिस्तानी क्षेत्र
(B) जयपुर और खंडेला (सीकर)
(C) उदयपुर, नाथद्वारा और आसपास की पहाड़ियां
(D) बीकानेर, चूरू और पास की ग्रामीण पट्टियां

50. ग्रामीण गैर-कृषि विकास एजेंसी (रूड़ा) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसकी स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 1995 में की गई थी।
II. इसका उद्देश्य कृषि से इतर रोजगार के वैकल्पिक अवसर पैदा करना है।
III. यह पारंपरिक कारीगरों के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण आयोजित करती है।
IV. यह विशेष रूप से किसानों को भारी ट्रैक्टरों के वितरण का प्रबंधन करती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) I, II और III
(B) II, III और IV
(C) I, III और IV
(D) I, II, III और IV

51. 'तारकशी' (लकड़ी में चांदी के बारीक तारों की जड़ाई का काम) का पारंपरिक शिल्प राजस्थान के किस शहर में सबसे प्रसिद्ध है?
(A) जयपुर
(B) जोधपुर
(C) नाथद्वारा
(D) पुष्कर

52. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: संस्थान
P. राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
Q. राजस्थान लघु उद्योग निगम
R. राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम
S. ग्रामीण गैर-कृषि विकास एजेंसी
सूची II: स्थापना का वर्ष
1. 1961
2. 1984
3. 1995
4. 1955
निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित है?
(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-4, R-3, S-2
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

NODIA

53. केंद्र सरकार द्वारा शुरु की गई 'पहचान' पहचान पत्र पहल राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है क्योंकि यह:
(A) सभी पंजीकृत सीमांत किसानों को अत्यधिक सब्सिडी वाला डीजल ईंधन खरीदने की अनुमति देती है।
(B) सभी ग्रामीण निवासियों को सालाना मुफ्त अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पास प्रदान करती है।
(C) सरकारी योजनाओं और व्यापार मेलों तक पहुंच प्रदान करने के लिए कारीगरों का पंजीकरण करती है।
(D) सभी राष्ट्रीय और राज्य मतदान उद्देश्यों के लिए मानक आधार कार्ड को आधिकारिक रूप से बदल देती है।

54. ग्रामीण शिल्प क्लस्टर के लिए 'कॉमन फैसिलिटी सेंटर' (सीएफसी) स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या है?
(A) सभी प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त स्थायी भोजन और आवासीय रहने की सुविधा प्रदान करना।
(B) प्रसंस्करण, परीक्षण और पैकेजिंग के लिए महंगी मशीनों को साझा करना।
(C) स्थानीय ग्रामीण चोरी से सुरक्षा के लिए एक समर्पित सशस्त्र पुलिस चौकी के रूप में कार्य करना।
(D) सभी पारंपरिक हस्त-निर्माण पद्धतियों को पूर्ण कारखाना स्वचालन से स्थायी रूप से बदलना।

55. ग्रामीण बाड़मेर का एक कारीगर अपने अजरक प्रिंट वस्त्रों को दिल्ली के ग्राहकों को सीधे बेचना चाहता है, लेकिन उसके पास दुकान स्थापित करने के लिए सीमित पूंजी है। कौन-सा आधुनिक उपाय इस विशिष्ट बाजार जुड़ाव चुनौती को सबसे प्रभावी ढंग से हल करता है?
(A) एक पूरी तरह से स्वचालित, बड़े पैमाने पर पावरलूम कपड़ा कारखाना स्थापित करना।

37. केंद्र सरकार द्वारा शुरु की गई 'पीएम विश्वकर्मा' योजना मुख्य रूप से राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित किस विशिष्ट समूह को लक्षित करती है?
(A) विशेष आर्थिक क्षेत्रों में आईटी पेशेवर
(B) बड़े पैमाने के यंत्रीकृत किसान
(C) पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार
(D) कॉरपोरेट रिटेल मैनेजर

38. पारंपरिक ग्रामोद्योगों के लिए 'क्लस्टर विकास दृष्टिकोण' में शामिल तार्किक चरणों को शुरुआती चरण से अंतिम परिणाम तक व्यवस्थित कीजिए:
1. कारीगर विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) / सहकारी समिति का गठन।
2. किसी विशिष्ट शिल्प के भौगोलिक संकेंद्रण की पहचान।
3. सामूहिक वैश्विक विपणन और निर्यात जुड़ाव।
4. साझा प्रसंस्करण के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) की स्थापना।

सही क्रम का चयन कीजिए:
(A) 1, 2, 4, 3
(B) 2, 1, 4, 3
(C) 2, 4, 1, 3
(D) 4, 2, 1, 3

39. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन राजस्थान में ग्रामीण गैर-कृषि विकास एजेंसी (रुड़ा) के जनादेश को सही ढंग से रेखांकित करता है?
(A) यह ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक कृषि फसल बीमा नीतियों का सख्ती से निपटान करती है।
(B) यह विशेष रूप से शहरी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को दीर्घकालिक आवासीय गृह ऋण प्रदान करती है।
(C) यह नागरिक उड्डयन बुनियादी ढाँचे और राज्य के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन का प्रबंधन करती है।
(D) यह चमड़ा, ऊन और खनिजों के क्षेत्र में गैर-कृषि रोजगार को बढ़ावा देती है।

40. राजस्थान के निम्नलिखित शिल्पों पर विचार कीजिए:
I. बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट
II. सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट
III. जयपुर की ब्लू पॉटरी
IV. पोकरण पॉटरी

उपर्युक्त में से किन पारंपरिक शिल्पों को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्रदान किया गया है?
(A) केवल I और II
(B) केवल I, II और III
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

41. राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसे कुटीर उद्योग माने जाने की संभावना सबसे कम है?
(A) कालीन और दरी बुनाई
(B) पापड़, मंगोड़ी और अचार बनाना
(C) स्टील रोलिंग मिल
(D) बीड़ी बनाना

42. पारंपरिक बुनकरों की सहायता के लिए राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम (आरएचडीसी) की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी?
(A) 1969
(B) 1984
(C) 1995
(D) 2002

43. मजबूत कुटीर एवं ग्रामोद्योग राजस्थान में गांव से शहर की ओर होने वाले पलायन को रोकने में किस प्रकार मदद करते हैं?
(A) ग्रामीण कारीगरों को प्रमुख औद्योगिक शहरों में यात्रा करने से कानूनी रूप से रोककर।
(B) कृषि उपज को कृत्रिम रूप से कम करके ताकि खेत मजदूर वापस रुकने के लिए मजबूर हों।
(C) पंजीकृत ग्रामीण कारीगरों को मुफ्त सब्सिडी वाले शहरी आवासीय अपार्टमेंट प्रदान करके।
(D) गांवों में ही टिकाऊ स्थानीय रोजगार के अवसर प्रदान करके।

44. बीकानेर शहर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गांव स्तर के किस विशिष्ट खाद्य प्रसंस्करण कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसके पास जीआई टैग प्राप्त है?
(A) बीकानेरी ब्लू पॉटरी
(B) बीकानेरी भुजिया
(C) बीकानेरी टेराकोटा
(D) बीकानेरी अजरक

45. कागज की तरह पतली होने की विशिष्ट विशेषता के लिए जानी जाने वाली पारंपरिक 'कागजी पॉटरी' राजस्थान के किस जिले से संबंधित है?
(A) जोधपुर
(B) राजसमंद
(C) अलवर
(D) बांसवाड़ा

46. वैश्विक स्तर पर और भारत में एमएसएमई वर्गीकरण के तहत, एक 'सूक्ष्म' उद्यम को मुख्य रूप से किस आधार पर 'लघु' उद्यम से अलग किया जाता है?
(A) वेतन-सूची पर पूर्णकालिक महिला कर्मचारियों की कुल संख्या।
(B) राज्य की राजधानी से विनिर्माण उद्यम की सटीक भौगोलिक दूरी।
(C) संस्थापक के पास मौजूद औपचारिक शैक्षणिक योग्यताएं और तकनीकी डिग्रियां।
(D) उपकरणों में निवेश की सीमा और वार्षिक टर्नओवर।

Downloaded from www.pdf.tube

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) यह आमतौर पर गृह-आधारित होता है और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित होता है।
राजस्थान के पारंपरिक कुटीर उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत का आधार रहे हैं। इन उद्योगों की प्रमुख विशेषता यह है कि ये मुख्यतः गृह-आधारित होते हैं और इनमें स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों एवं कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। इन इकाइयों का संचालन मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, जिससे न्यूनतम पूंजी निवेश में व्यापक स्वरोजगार उत्पन्न होता है। यह मॉडल ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

2. (B) 1955
राजस्थान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने और खादी तथा अन्य ग्रामोद्योगों की संगठित स्थापना एवं संवर्धन हेतु वर्ष 1955 में राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था। यह बोर्ड राज्य भर में पारंपरिक ग्रामीण शिल्पियों को वित्तीय, तकनीकी एवं विपणन सहायता उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार के अवसरों का निरंतर विस्तार किया गया है, जिससे हस्तशिल्पियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार संभव हो सका है।

3. (C) पेट्रोलियम शोधन
पारंपरिक कुटीर और ग्रामीण उद्योगों की श्रेणी में वे गतिविधियां शामिल होती हैं जो कम पूंजी, स्थानीय संसाधनों और हस्तकौशल पर आधारित होती हैं, जैसे चमड़े के उत्पाद, हथकरघा बुनाई तथा मृद्भांड निर्माण। इसके विपरीत, पेट्रोलियम शोधन एक अत्यधिक पूंजी-गहन और बड़े पैमाने का भारी औद्योगिक उपक्रम है। इसमें आधुनिक तकनीक, विशाल बुनियादी ढांचे और जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसे कुटीर या ग्रामीण उद्योग की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

4. (D) राजस्थली
राजस्थान लघु उद्योग निगम सीमित, जिसे संक्षिप्त रूप में राजसिको कहा जाता है, राज्य के कारीगरों और हस्तशिल्पियों के उत्पादों के विपणन हेतु प्रयासरत है। इस संस्था द्वारा स्थापित आधिकारिक खुदरा विपणन एम्पोरियम और ब्रांड का नाम 'राजस्थली' है। इसके माध्यम से राजस्थान के पारंपरिक हस्तशिल्प, जैसे टेराकोटा, वस्त्र और आभूषणों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक स्थायी पहचान मिलती है, जिससे कारीगरों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

5. (C) सामान्य मिट्टी
जयपुर की प्रसिद्ध 'ब्लू पॉटरी' अपनी अनूठी निर्माण शैली के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसमें पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों की तरह सामान्य मिट्टी का प्रयोग पूरी तरह वर्जित होता है। इसके निर्माण में मुख्य रूप से क्वार्ट्ज़ पाउडर, काँच, मुल्तानी मिट्टी और प्राकृतिक खनिजों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। इस विशेष सामग्री के कारण यह चीनी मिट्टी के बर्तनों की भांति चिकनी, हल्की और पारभासी होती है, तथा इसमें दरारें नहीं पड़ती हैं, जो इसे अत्यंत विशिष्ट बनाती हैं।

6. (B) वे कम पूंजीगत निवेश के साथ ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार उत्पन्न करते हैं।
ग्रामीण राजस्थान की सामाजिक-आर्थिक संरचना में कुटीर एवं ग्रामोद्योग अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उद्योग अत्यंत सीमित पूंजीगत निवेश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर गैर-कृषि रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। चुकी अधिकांश ग्रामीण आबादी कृषि पर निर्भर है, जो मौसमी होती है, इसलिए ये लघु उद्योग वर्ष भर पूरक आय प्रदान करते हैं। इसके फलस्वरूप ग्रामीण गरीबी में कमी आती है और स्थानीय संसाधनों का प्रभावी एवं सतत उपयोग संभव हो पाता है।

7. (D) जोधपुर और बीकानेर
राजस्थान में चमड़े से निर्मित पारंपरिक जूतियों को 'मोज़री' के नाम से जाना जाता है, जो अपनी कलात्मक कढ़ाई और स्थायित्व के लिए प्रसिद्ध हैं। जोधपुर और बीकानेर जिले मोज़री निर्माण के प्रमुख क्लस्टर और केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन क्षेत्रों में कारीगर पीढ़ियों से हस्तनिर्मित तकनीकों का प्रयोग करके आकर्षक डिज़ाइनों में मोज़री तैयार करते हैं। यह उद्योग स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ राज्य की हस्तशिल्प परंपरा को जीवित रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

8. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
ग्रामीण राजस्थान में कुटीर उद्योग महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त साधन साबित हुए हैं। अधिकांश पारंपरिक हस्तशिल्प, कताई और बुनाई जैसी गतिविधियां घर से ही संचालित की जा सकती हैं। यह महिलाओं को अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को प्रभावित किए बिना आर्थिक रूप से उत्पादक कार्यों में संलग्न होने का अवसर प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं की पारिवारिक आय में भागीदारी बढ़ती है, उन्हें वित्तीय स्वावलंबन प्राप्त होता है और समाज में उनकी निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है।

NODIA

(B) स्थानीय अनौपचारिक साहूकारों से उच्च ब्याज वाला व्यावसायिक ऋण लेना।
(C) प्राकृतिक छपाई से पूरी तरह से सिंथेटिक डाई निर्माण की ओर रुख करना।
(D) ई-कॉमर्स हस्तशिल्प प्लेटफॉर्मों पर उत्पादों को सूचीबद्ध करना।

56. राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन-सा जिला पारंपरिक रूप से एक प्रमुख हस्त-ब्लॉक प्रिंटिंग कपड़ा क्लस्टर से नहीं जुड़ा है?
(A) झुंझुनूं
(B) जयपुर
(C) बाड़मेर
(D) चित्तौड़गढ़

57. उदयपुर में प्रमुख रूप से स्थापित 'शिल्पग्राम' अवधारणा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) उन्नत आधुनिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर का निर्माण करना।
(B) गन्ना और कपास जैसे भारी वाणिज्यिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण करना।
(C) ग्रामीण कला, शिल्प और संस्कृति को प्रदर्शित और संरक्षित करना।
(D) कॉरपोरेट आईटी क्षेत्र के कर्मचारियों को आधुनिक सॉफ्टवेयर विकास कौशल में प्रशिक्षित करना।

58. संयंत्र और मशीनरी/उपकरणों में निवेश सीमा के आधार पर एमएसएमई वर्गीकरण का सही क्रम (सबसे छोटी से सबसे बड़ी श्रेणी) चुनिए:
(A) लघु → सूक्ष्म → मध्यम
(B) सूक्ष्म → लघु → मध्यम
(C) सूक्ष्म → मध्यम → लघु
(D) मध्यम → लघु → सूक्ष्म

59. स्वतंत्रता के बाद के भारत में जयपुर की विलुप्त होती 'ब्लू पॉटरी' कला को पुनर्जीवित करने वाले अग्रदूत के रूप में ऐतिहासिक रूप से किसे श्रेय दिया जाता है?
(A) राम सिंह द्वितीय
(B) हिसामुद्दीन उस्ता
(C) देवकीनंदन शर्मा
(D) कृपाल सिंह शेखावत

60. प्रसिद्ध 'टाई एंड डाई' (बंधेज/बांधनी) कुटीर उद्योग मुख्य रूप से राजस्थान के किन क्षेत्रों में केंद्रित है?
(A) भरतपुर, धौलपुर और करौली
(B) जोधपुर, जयपुर और सीकर
(C) बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़
(D) गंगानगर और हनुमानगढ़

61. राजस्थान में 'खादी' उत्पादन के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) खादी को हाथ से काते गए सूत से हथकरघे पर बुने गए किसी भी कपड़े के रूप में परिभाषित किया गया है।
(B) यह आत्मनिर्भरता और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देती है।
(C) खादी का सूत सख्ती से बड़े पैमाने की यंत्रीकृत कताई मिलों का उपयोग करके निर्मित किया जाता है।
(D) खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड खादी कताई करने वालों को सक्रिय रूप से सब्सिडी प्रदान करता है।

62. राज्य सरकार द्वारा 2022 में क्षमता निर्माण और निर्यात संवर्धन के प्रावधानों के साथ लघु उद्यमों, हथकरघा और ग्रामोद्योगों के विकास को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए कौन-सी प्रमुख नीति जारी की गई थी?
(A) राजस्थान पर्यटन नीति 2022
(B) राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2022
(C) राजस्थान कृषि निर्यात नीति 2022
(D) राजस्थान एमएसएमई नीति 2022

63. जोधपुर जिले का सालावास गांव निम्नलिखित में से किस पारंपरिक कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है?
(A) बुनी हुई दरियां
(B) ब्लू पॉटरी
(C) टेराकोटा के घोड़े
(D) सोने के आभूषण (थेवा कला)

64. राजस्थान के कुटीर उद्योगों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी का सबसे उपयुक्त कारण निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) सख्त राज्य औद्योगिक कानून वयस्क पुरुषों को ग्रामीण उद्यमों में काम करने से सख्ती से रोकते हैं।
(B) शिल्प गतिविधियां लचीली, घर-आधारित कार्य स्थितियां प्रदान करती हैं।
(C) राज्य विधान द्वारा महिलाओं को विशेष रूप से कुटीर उद्योगों में काम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया गया है।
(D) कुटीर उद्योग लगातार शहरी क्षेत्रों के आईटी क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक वेतन देते हैं।

65. राजस्थान के पारंपरिक हस्तशिल्प की निर्यात क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राजस्थान के कुल निर्मित निर्यातों में हस्तशिल्प का नगण्य हिस्सा है।
II. भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग वाले उत्पाद अक्सर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेहतर मूल्य प्राप्त करते हैं।
III. व्यापार मेलों जैसी सरकार प्रायोजित प्रदर्शनियों से कारीगरों को थोक में निर्यात ऑर्डर प्राप्त करने में मदद मिलती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III

Click Here to Buy book on Flipkart

(D) I, II और III

66. 'पीएम एफएमई' (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना) राजस्थान में किस प्रकार के ग्रामोद्योग के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है?
(A) पापड़, अचार और मसाले बनाने वाली सूक्ष्म इकाइयां।
(B) पारंपरिक ग्रामीण हथकरघा कपड़ा बुनाई और रंगाई क्लस्टर।
(C) पारंपरिक चमड़े की मोज़री बनाने वाले कुशल कारीगर संघ।
(D) सजावटी टेराकोटा की मूर्तियां और पट्टिकाएं बनाने वाले ग्रामीण कुम्हार।

67. राजस्थान में ग्रामोद्योग उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्राप्त करने का कौन-सा लाभ नहीं है?
(A) यह उस विशिष्ट क्षेत्र के मूल शिल्प उत्पादकों को सख्ती से व्यापक कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
(B) यह अनधिकृत कॉरपोरेट संस्थाओं को पंजीकृत भौगोलिक ब्रांड नाम का उपयोग करने से प्रभावी रूप से रोकता है।
(C) यह दुनिया भर के किसी भी उत्पादक को पंजीकृत नाम का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति देता है।
(D) यह ब्रांड निर्माण में महत्वपूर्ण सहायता करता है और प्रामाणिक उत्पादों के लिए बाजार की मांग को लगातार बढ़ाता है।

68. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): संपार्श्विक-आधारित ऋण मॉडल पारंपरिक कारीगरों को अपने कुटीर व्यवसायों का विस्तार करने से गंभीर रूप से रोकते हैं।
कारण (R): ग्रामीण राजस्थान में कारीगरों के पास अक्सर वाणिज्यिक बैंकों में सुरक्षा/जमानत के रूप में गिरवी रखने के लिए पंजीकृत भूमि संपत्तियों या पर्याप्त भौतिक परिसंपत्तियों का अभाव होता है।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

69. 'मथेरना' और 'उस्ता' कलाएं, जो क्रमशः भित्ति चित्रों और ऊंट की खाल के काम से संबंधित पारंपरिक कुटीर शिल्प हैं, मुख्य रूप से कहां केंद्रित हैं?
(A) जैसलमेर
(B) उदयपुर
(C) बीकानेर
(D) अजमेर

NODIA

70. ग्रामीण कारीगर सहकारी समितियों को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) जैसे प्लेटफॉर्मों से जोड़ने का मुख्य लाभ क्या है?
(A) यह कानूनी रूप से ग्रामीण कारीगरों को अपनी कृषि भूमि बड़ी कॉरपोरेट संस्थाओं को बेचने के लिए मजबूर करता है।
(B) यह छोटी कुटीर इकाइयों को बिना बड़े बजट के देश भर के खरीदारों तक पहुंचने की अनुमति देता है।
(C) यह पारंपरिक हाथ से बने डिजाइनों को सख्ती से मानकीकृत करता है, जिससे सभी तैयार हस्तशिल्प एक जैसे दिखते हैं।
(D) यह पारंपरिक कारीगरों को स्थानीय ग्रामीण बाजारों में अपने निर्मित सामान बेचने से कानूनी रूप से रोकता है।

71. बारां जिले का मांगरोल कस्बा ऐतिहासिक रूप से कैथून के साथ-साथ किस पारंपरिक ग्रामोद्योग के लिए जाना जाता है?
(A) जयपुर ब्लू पॉटरी और ग्लेज्ड टाइल निर्माण
(B) बलुआ पत्थर की जटिल वास्तुकला नक्काशी
(C) हस्तनिर्मित पारंपरिक चमड़े की मोज़री
(D) कोटा डोरिया बुनाई

72. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: वस्त्र शिल्प का प्रकार
P. अजरक प्रिंट
Q. दाबू प्रिंट
R. कोटा डोरिया
S. लप्पा-लप्पी (गोटा कार्य)
सूची II: संबंधित क्षेत्र
1. खंडेला
2. कैथून
3. आकोला
4. बाड़मेर
निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित है?
(A) P-4, Q-3, R-2, S-1
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-4, Q-2, R-3, S-1
(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

73. राजस्थान में ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य स्तरीय संस्थान प्रमुख 'खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी' का आयोजन करता है?
(A) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(B) राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आरटीडीसी)
(C) राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
(D) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको)

74. कौन-सी अवधारणा उस रणनीति की व्याख्या करती है जहां एक गांव में कई छोटे कारीगर परिवार थोक में कच्चा माल खरीदने और एक साझा कार्यशाला साझा करने के लिए धन एकत्र करते हैं, जिससे व्यक्तिगत लागत कम हो जाती है?

(A) क्लस्टर विकास दृष्टिकोण
(B) समष्टि आर्थिक घाटे की वित्तपोषण नीतियां
(C) अंतरराष्ट्रीय विदेशी पोर्टफोलियो निवेश
(D) निजी औद्योगिक एकाधिकार पूंजीवाद

75. राज्य सरकार की वह कौन-सी योजना है जो कारीगरों, सूक्ष्म उद्यमों और बुनकरों को 10 करोड़ रुपये तक की अपनी इकाइयों की स्थापना या विस्तार के लिए ब्याज अनुदान प्रदान करती है?
(A) मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान
(B) इंदिरा गांधी नहर परियोजना
(C) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना
(D) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

76. राजस्थानी कुटीर शिल्प और उसकी मुख्य विशेषता के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए।
(A) ब्लू पॉटरी – बिना किसी ग्लेज के अत्यधिक कम तापमान पर पकाना।
(B) थेवा कला – रंगीन कांच पर सोने की बारीक काम की गई शीट (पन्नी) को मिलाना।
(C) कोटा डोरिया – घनी कढ़ाई वाले भारी शीतकालीन ऊनी कंबल।
(D) मोलेला का टेराकोटा – धातु की तलवारें और ढाल बनाना।

77. अत्यधिक आधुनिकीकरण और बड़े पैमाने पर उत्पादन का पारंपरिक कुटीर उद्योगों पर निम्नलिखित में से किसे नकारात्मक प्रभाव माना जाता है?
(A) सभी पंजीकृत कारीगरों के लिए मुफ्त राज्य स्वास्थ्य बीमा नीतियों की सार्वभौमिक उपलब्धता।
(B) दूरस्थ औद्योगिक गांवों में सीधे आवश्यक कच्चे माल का उच्च गति परिवहन।
(C) सौंदर्य मूल्य की हानि और मशीनों द्वारा कारीगरों का विस्थापन।
(D) कारीगर सहकारी समितियों के लिए आधुनिक डिजिटल लेखांकन और स्वचालित बिलिंग सॉफ्टवेयर का प्रावधान।

78. ई-कॉमर्स के माध्यम से एक अंतरराष्ट्रीय खरीदार तक पहुंचने वाले पारंपरिक कारीगर उत्पाद (जैसे हस्तनिर्मित मोज़री) के विशिष्ट मूल्य श्रृंखला चरणों को क्रमानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए:
1. शिल्प की डिजिटल कैटलॉगिंग और फोटोग्राफी।
2. कच्चे चमड़े की खरीद और उत्पाद का हस्त-निर्माण।
3. वैश्विक लॉजिस्टिक्स के माध्यम से पैक किए गए उत्पाद को भेजना।
4. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर और भुगतान प्राप्त करना।

सही क्रम का चयन कीजिए:
(A) 1, 2, 4, 3
(B) 2, 1, 4, 3
(C) 2, 4, 1, 3
(D) 1, 4, 2, 3

79. राजस्थान के निम्नलिखित पारंपरिक विरासत शिल्पों में से उनके प्राथमिक कच्चे माल के आधार पर विषम (अलग) की पहचान कीजिए:
(A) उस्ता कला
(B) सांगानेरी प्रिंट
(C) बगरू प्रिंट
(D) अजरक प्रिंट

NODIA

80. राजस्थान सरकार पारंपरिक ग्रामीण इकाइयों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए जागरुकता बढ़ाने और नई योजनाएं शुरु करने के लिए 'एमएसएमई दिवस' मनाती है। विश्व स्तर पर एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है?
(A) 15 अगस्त
(B) 27 जून
(C) 26 जनवरी
(D) 2 अक्टूबर

www.nodia.in

10. राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसिको) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी।
II. यह 'राजस्थली' एम्पोरियम के माध्यम से कारीगरों को विपणन सहायता प्रदान करता है।
III. यह निर्यात को सुगम बनाने के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो का संचालन करता है।
IV. यह राजस्थान में सीमेंट संयंत्रों को बड़े पैमाने पर भारी मशीनरी प्रदान करता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) I, II और III
(B) II, III और IV
(C) I, III और IV
(D) I, II, III और IV

11. राजस्थान का कौन-सा गांव अपने पारंपरिक टेराकोटा कुटीर उद्योग, विशेष रूप से स्थानीय देवताओं की मिट्टी की पट्टिकाएं बनाने के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है?
(A) कैथून
(B) आकोला
(C) पीपाड़
(D) मोलेला

12. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए:
सूची I: पारंपरिक शिल्प
P. उस्ता कला
Q. थेवा कला
R. अजरक प्रिंट
S. बादला (जस्ते से निर्मित पानी के पात्र)
सूची II: राजस्थान का प्रमुख जिला/केंद्र
1. जोधपुर
2. बाड़मेर
3. प्रतापगढ़
4. बीकानेर
निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित है?
(A) P-4, Q-3, R-2, S-1
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-4, Q-2, R-3, S-1
(D) P-1, Q-3, R-2, S-4

13. राजस्थान सरकार द्वारा 1995 में चमड़ा, ऊन और गैर-खाद्य (गौण) खनिजों सहित ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से किस एजेंसी की स्थापना की गई थी?
(A) रीको
(B) राजसिको
(C) रुड़ा
(D) आरएफसी

14. राजस्थान में पारंपरिक ग्रामीण कारीगरों को औपचारिक संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करने का सबसे सामान्य कारण क्या है?
(A) वे अत्यधिक उच्च क्रेडिट रेटिंग बनाए रखते हैं जो उन्हें राज्य सब्सिडी प्राप्त करने से अयोग्य बनाती है।
(B) वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंकिंग नियमों द्वारा कुटीर इकाइयों को वित्तपोषित करने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है।
(C) कारीगर स्थानीय बैंकिंग ऋणों के बजाय अंतरराष्ट्रीय वेंचर कैपिटल वित्तपोषण को प्राथमिकता देते हैं।
(D) उनके पास पंजीकृत भूमि स्वामित्व या पूंजीगत संपत्ति जैसी संपार्श्विक का अभाव होता है।

15. राजस्थान में 'मोज़री' शिल्प के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह एक प्रमुख पारंपरिक चमड़ा शिल्प है जो महत्वपूर्ण ग्रामीण रोजगार प्रदान करता है।
II. लागत बचाने के लिए यह पूरी तरह से सिंथेटिक प्लास्टिक और रबर का उपयोग करके निर्मित किया जाता है।
III. इस शिल्प की कुछ क्षेत्रीय किस्मों को भौगोलिक संकेतक (जीआई) रजिस्ट्री के तहत मान्यता दी गई है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

16. लघु उद्योगों को बढ़ावा देने में भौगोलिक क्लस्टर दृष्टिकोण मुख्य रूप से इसलिए लाभदायक है क्योंकि:
(A) यह सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए पारंपरिक कारीगरों को शहरी बाजार की प्रतिस्पर्धा से पूरी तरह अलग करता है।
(B) यह साझा संसाधनों, सामान्य बुनियादी ढाँचे और कुशल श्रम को सक्षम बनाता है।
(C) यह वित्तीय अनुदान या सरकारी सब्सिडी हस्तक्षेप की आवश्यकता को स्थायी रूप से समाप्त करता है।
(D) यह भाग लेने वाले कारीगरों को क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर अपने निर्मित सामान बेचने से कानूनी रूप से रोकता है।

17. प्रसिद्ध 'कोटा डोरिया' कपड़ा पारंपरिक रूप से मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस ग्रामीण क्लस्टर में हथकरघे पर बुना जाता है?
(A) सांगानेर
(B) कैथून
(C) आकोला
(D) पीपाड़

18. राजस्थान में निम्नलिखित औद्योगिक विकास संस्थाओं की स्थापना का सबसे पहले से सबसे बाद का सही कालानुक्रमिक क्रम चुनिए:
(A) केवीआईबी → राजसिको → रुड़ा
(B) राजसिको → केवीआईबी → रुड़ा
(C) रुड़ा → राजसिको → केवीआईबी

Downloaded from www.pdf.tube

9. (C) 8 प्रतिशत
राजस्थान में नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना तथा पुराने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 'मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना' लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपये तक के बैंक ऋण पर राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 8 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। इस वित्तीय सहायता का मुख्य उद्देश्य नए उद्यमियों एवं पारंपरिक कारीगरों पर ब्याज का बोझ कम करना और उन्हें व्यवसाय स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना है।

10. (A) I, II और III
राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसिको) की स्थापना वर्ष 1961 में लघु इकाइयों और हस्तशिल्पियों की सहायता हेतु की गई थी। यह संस्था 'राजस्थली' एम्पोरियम के माध्यम से विपणन सेवाएं उपलब्ध कराती है तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो का संचालन भी करती है। हालांकि, भारी औद्योगिक सीमेंट संयंत्रों को मशीनरी प्रदान करना इसके अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है। यह संस्था मुख्यतः छोटे उद्यमियों, कारीगरों और निर्यातकों को बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित है।

11. (D) मोलेला
राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव अपनी अनूठी टेराकोटा कला के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। इस गांव के पारंपरिक कुम्हार स्थानीय मिट्टी का उपयोग करके विभिन्न लोक देवताओं और धार्मिक प्रतीकों की सुंदर मिट्टी की पट्टिकाएं (रिलीफ प्लाक) बनाते हैं। यह पारंपरिक कुटीर उद्योग पीढ़ियों से चला आ रहा है और इन पट्टिकाओं का उपयोग मुख्यतः स्थानीय एवं क्षेत्रीय धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। मोलेला की यह विशिष्ट हस्तशिल्प कला राजस्थान की धरोहर का प्रतीक मानी जाती है।

12. (A) P-4, Q-3, R-2, S-1
राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट हस्तकलाएं हैं। बीकानेर की उस्ता कला ऊंट की खाल पर की जाने वाली स्वर्ण नक्काशी के लिए जानी जाती है, जबकि प्रतापगढ़ की थेवा कला कांच पर सोने के बारीक कार्य के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर अपनी पारंपरिक अजरक प्रिंट सूती छपाई के लिए प्रसिद्ध है और जोधपुर में जस्ते से निर्मित पानी के पात्र, जिन्हें बादला कहा जाता है, बनाए जाते हैं। ये सभी शिल्प अपने-अपने क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करते हैं।

13. (C) रुड़ा
राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1995 में 'ग्रामीण गैर-कृषि विकास एजेंसी' (रुड़ा) की स्थापना की गई थी। इस संस्था का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चमड़ा, ऊन तथा गैर-खाद्य (गौण) खनिजों पर आधारित गैर-कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना है। रुड़ा विभिन्न कौशलों के प्रशिक्षण, उत्पाद डिजाइन सुधार और विपणन सहायता के माध्यम से ग्रामीण कारीगरों की आजीविका में सुधार करती है। यह संस्था ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने में निरंतर प्रयासरत है।

14. (D) उनके पास पंजीकृत भूमि स्वामित्व या पूंजीगत संपत्ति जैसी संपार्श्विक का अभाव होता है।
राजस्थान के पारंपरिक ग्रामीण कारीगरों को बैंकों से औपचारिक ऋण प्राप्त करने में मुख्य रूप से संपार्श्विक (कोलेटरल) की कमी का सामना करना पड़ता है। वाणिज्यिक बैंक ऋण स्वीकृत करने के लिए आमतौर पर पंजीकृत भूमि स्वामित्व या पर्याप्त परिसंपत्तियों की मांग करते हैं, जो गरीब कारीगरों के पास उपलब्ध नहीं होती हैं। इसके परिणामस्वरूप, कारीगरों को अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते हैं और उनका आर्थिक शोषण करते हैं।

15. (C) केवल I और III
राजस्थान की मोज़री शिल्प एक महत्वपूर्ण पारंपरिक चमड़ा उद्योग है, जो हजारों ग्रामीण कारीगरों को आजीविका प्रदान करता है। इस शिल्प में प्राकृतिक रूप से प्रसंस्कृत चमड़े और जटिल रेशमी या सूती धागों की कढ़ाई का उपयोग किया जाता है, न कि सिंथेटिक प्लास्टिक का। इस कलात्मक और भौगोलिक विशेषता को ध्यान में रखते हुए, मोज़री की कुछ विशिष्ट क्षेत्रीय किस्मों को भौगोलिक संकेतक (जीआई) का दर्जा प्राप्त है, जो इसकी प्रामाणिकता और अंतरराष्ट्रीय पहचान को मजबूत बनाता है।

16. (B) यह साझा संसाधनों, सामान्य बुनियादी ढाँचे और कुशल श्रम को सक्षम बनाता है।
औद्योगिक विकास में भौगोलिक क्लस्टर दृष्टिकोण लघु और कुटीर इकाइयों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। जब एक ही प्रकार के शिल्पकार एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित होते हैं, तो वे साझी अवसंरचना, सामान्य सुविधा केंद्रों और कुशल श्रम का सामूहिक लाभ उठा सकते हैं। इससे कच्चे माल की खरीद लागत में कमी आती है और विपणन में सुगमता होती है। क्लस्टर दृष्टिकोण से नवाचार को बढ़ावा मिलता है और कारीगरों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि होती है।

17. (B) कैथून
कोटा जिले में स्थित कैथून गांव प्रसिद्ध 'कोटा डोरिया' कपड़े के निर्माण का मुख्य केंद्र है। यह कपड़ा अपनी हल्की, पारदर्शी संरचना और विशेष वर्गाकार बुनाई (खत) के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है। कैथून के बुनकर पारंपरिक हथकरघों का उपयोग करके सूती और रेशमी धागों के संयोजन से यह उत्कृष्ट वस्त्र बुनते हैं। इस शिल्प को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग भी प्राप्त है, जिसने इस ग्रामीण क्लस्टर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है।

18. (A) केवीआईबी → राजसिको → रुड़ा
राजस्थान में ग्रामीण और लघु उद्योगों के विकास हेतु विभिन्न संस्थाएं समय-समय पर स्थापित की गईं। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। इसके पश्चात राज्य में छोटे उद्योगों और हस्तशिल्प के प्रोत्साहन हेतु राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसिको) का गठन वर्ष 1961 में किया गया। अंततः ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र के विकास के

NODIA

(आकोला का दाबू प्रिंट) शामिल हैं। ये जिले प्राकृतिक रंगों और लकड़ी के ठप्पों से कपड़े पर छपाई के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके विपरीत, झुंझुनूं जिला ऐतिहासिक रूप से अपनी कलात्मक हवेली भित्तिचित्रों (फ्रेश्को पेंटिंग्स) के लिए जाना जाता है, न कि किसी पारंपरिक हस्त-ब्लॉक प्रिंटिंग कपड़ा क्लस्टर के रूप में।

57. (C) ग्रामीण कला, शिल्प और संस्कृति को प्रदर्शित और संरक्षित करना।
उदयपुर में स्थित 'शिल्पग्राम' एक प्रसिद्ध ग्रामीण हस्तशिल्प परिसर है, जिसकी स्थापना पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत, विशेष रुप से राजस्थान की विलुप्त होती ग्रामीण कलाओं, पारंपरिक हस्तशिल्पों, लोक नृत्य और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना एवं संरक्षित करना है। यह परिसर ग्रामीण कारीगरों को अपने जीवंत प्रदर्शन और निर्मित उत्पादों को पर्यटकों के सामने सीधे प्रस्तुत करने के लिए एक स्थाई और इंटरैक्टिव मंच प्रदान करता है।

58. (B) सूक्ष्म → लघु → मध्यम
भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का वर्गीकरण संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों में किए जाने वाले पूंजीगत निवेश तथा टर्नओवर के बढ़ते क्रम के आधार पर किया जाता है। इसमें सबसे छोटी श्रेणी 'सूक्ष्म' (माइक्रो) उद्यम की होती है, जिसके बाद आकार और निवेश सीमा के आधार पर 'लघु' (स्मॉल) उद्यम का स्थान आता है। इस श्रृंखला में सबसे बड़ी श्रेणी 'मध्यम' (मीडियम) उद्यम की होती है, जो सही आरोही क्रम को प्रदर्शित करता है।

59. (D) कृपाल सिंह शेखावत
स्वतंत्रता के पश्चात जयपुर की प्रसिद्ध 'ब्लू पॉटरी' कला विलुप्त होने के कगार पर पहुँच गई थी। इस पारंपरिक हस्तकला को पुनर्जीवित करने और इसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने का श्रेय पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत को दिया जाता है। उन्होंने ब्लू पॉटरी की पारंपरिक शैली में नए रंगों और नवोन्मेषी डिज़ाइनों का समावेश करके इसे एक नई पहचान दी। उनके इस अतुलनीय योगदान के कारण ही आज जयपुर की ब्लू पॉटरी विश्व स्तर पर अत्यधिक सराही जाती है।

60. (B) जोधपुर, जयपुर और सीकर
राजस्थान में कपड़े को बांधकर रंगने की कला, जिसे 'टाई एंड डाई' या बंधेज/बांधनी कहा जाता है, एक अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध कुटीर उद्योग है। यह कला मुख्य रूप से जोधपुर, जयपुर और सीकर (शेखावाटी क्षेत्र) जिलों में केंद्रित है। यहाँ के कारीगर सूती, रेशमी और जॉर्जेट के कपड़ों पर धागों से बारीक गांठें बांधकर अत्यंत जटिल और आकर्षक लहरिया, चुनरी और पचरंगा पैटर्न तैयार करते हैं। यह उद्योग हजारों महिलाओं और स्थानीय कारीगरों को रोजगार देता है।

61. (C) खादी का सूत सख्ती से बड़े पैमाने की यंत्रीकृत कताई मिलों का उपयोग करके निर्मित किया जाता है।
खादी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और आत्मनिर्भरता का एक ऐतिहासिक प्रतीक है। खादी वस्त्र की मूल परिभाषा ही यह है कि इसे चरखे पर हाथ से काते गए सूत से हथकरघे पर हाथ से बुना जाता है। अतः खादी के सूत का निर्माण बड़े पैमाने की यंत्रीकृत कताई मिलों में होना पूरी तरह से गलत और असत्य कथन है। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कताई करने वालों को सब्सिडी प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में हस्त-कताई और बुनाई के माध्यम से स्वरोजगार को प्रोत्साहित करता है।

62. (D) राजस्थान एमएसएमई नीति 2022
राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, हथकरघा बुनकरों और पारंपरिक ग्रामोद्योगों के समावेशी विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'राजस्थान एमएसएमई नीति 2022' जारी की गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य इन उद्योगों को आसान वित्तीय ऋण, अवसंरचनात्मक विकास, कौशल विकास प्रशिक्षण, गुणवत्ता प्रमाणन और निर्यात प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना है। इसके लागू होने से राज्य में निवेश और रोजगार सृजन के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

63. (A) बुनी हुई दरियां
जोधपुर जिले में स्थित सालावास गांव अपने पारंपरिक कुटीर उद्योग के रूप में हस्तनिर्मित बुनी हुई दरियों (कॉटन एवं वूलन ड्यूरीज) के लिए देश-विदेश में विख्यात है। सालावास के बुनकर परिवार पीढ़ियों से सूती और ऊनी धागों का उपयोग करके ज्यामितीय, प्राकृतिक और लोक डिज़ाइनों में मजबूत दरियों की बुनाई करते हैं। यह गांव एक प्रमुख हस्तशिल्प पर्यटन केंद्र बन चुका है, जहाँ पर्यटक सीधे बुनकरों से प्रामाणिक दरियां खरीदने आते हैं।

64. (B) शिल्प गतिविधियां लचीली, घर-आधारित कार्य स्थितियां प्रदान करती हैं।
राजस्थान के ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्रों में महिलाओं की व्यापक भागीदारी का सबसे बड़ा कारण इन व्यवसायों की अनुकूल कार्य प्रकृति है। कताई, बुनाई, कढ़ाई, बंधेज और खाद्य प्रसंस्करण जैसी शिल्प गतिविधियां घर से ही संचालित की जा सकती हैं। यह महिलाओं को समय की लचीलापन प्रदान करता है, जिससे वे अपने घर और बच्चों की देखभाल करने के साथ-साथ फुर्सत के समय में आर्थिक गतिविधियों में भाग ले सकती हैं और परिवार की आय बढ़ा सकती हैं।

65. (B) केवल II और III
राजस्थान का हस्तशिल्प क्षेत्र राज्य के कुल निर्मित निर्यातों में एक महत्वपूर्ण और बड़ा हिस्सा रखता है, इसलिए इसे नगण्य मानना गलत है। भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्राप्त उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी प्रामाणिकता के कारण बेहतर मूल्य प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही, सरकार द्वारा आयोजित व्यापार मेलों और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों से ग्रामीण कारीगरों को विदेशी खरीदारों से सीधे जुड़ने और थोक निर्यात ऑर्डर प्राप्त करने में अपार सहायता मिलती है, जो निर्यातों को बढ़ाता है।

66. (A) पापड़, अचार और मसाले बनाने वाली सूक्ष्म इकाइयां।
'प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना' (पीएम एफएमई) केंद्र सरकार की एक विशेष पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की सूक्ष्म इकाइयों का

Click Here to Buy book on Amazon

28. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट जैसे पारंपरिक शिल्पों को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग मिलने से इनके वैश्विक निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। जीआई टैग एक विधिक संरक्षण प्रदान करता है जो अनधिकृत व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा नकली उत्पादों के निर्माण और बिक्री को कानूनी रूप से रोकता है। यह अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को उत्पाद के मूल उद्गम स्थल और उसकी पारंपरिक गुणवत्ता की पूर्ण गारंटी देता है, जिससे वैश्विक बाजार में सांगानेरी प्रिंट की मांग और विश्वसनीयता निरंतर बनी रहती है।

29. (D) 2022
राजस्थान से होने वाले कुल निर्यातों को गति देने और स्थानीय हस्तशिल्प तथा लघु उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने हेतु वर्ष 2022 में राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद (आरईपीसी) का गठन किया गया था। यह परिषद राज्य के सूक्ष्म, लघु और कुटीर उद्योगों को निर्यात प्रक्रियाओं, अवसंरचनात्मक सुविधाओं और गुणवत्ता सुधार के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसके माध्यम से स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को वैश्विक व्यापार मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सहायता मिलती है।

30. (D) थेवा कला — रंगीन कांच और सोने का वर्क (पत्री)
प्रतापगढ़ की 'थेवा कला' एक अत्यंत सूक्ष्म और विशिष्ट पारंपरिक हस्तकला है। इस कला में विशेष रूप से बेल्जियम के रंगीन कांच के आधार पर सोने के बेहद बारीक वर्क या पत्री से जटिल नक्काशीदार डिज़ाइन बनाए जाते हैं। यह कला केवल सीमित परिवारों द्वारा पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित की जाती रही है। इसमें कांच और सोने का यह अनूठा संयोजन अत्यधिक कलात्मक सौंदर्य उत्पन्न करता है, जो इसे राजस्थान के अन्य शिल्पों से पूरी तरह भिन्न और विशिष्ट बनाता है।

31. (A) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जिसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करके रोजगार के अवसर पैदा करना है। राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु 'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग' (केवीआईसी) को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। राज्य स्तर पर यह योजना केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी बोर्डों और जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से प्रभावी ढंग से लागू की जाती है।

32. (A) P-2, Q-4, R-1, S-3
राजस्थान के प्रमुख हस्तशिल्प केंद्र अपनी विशिष्ट कलाकृतियों के लिए विख्यात हैं। चित्तौड़गढ़ का आकोला गांव मिट्टी के अवरोध से की जाने वाली 'दाबू प्रिंट' छपाई के लिए प्रसिद्ध है, जबकि बस्सी (चित्तौड़गढ़) लकड़ी के कलात्मक खिलौनों और कावड़ निर्माण का केंद्र है। नाथद्वारा शहर भगवान श्रीनाथजी के कपड़ों के पीछे लगाए जाने वाले 'पिछवाई' चित्रकारी के लिए जाना जाता है, और किशनगढ़ तथा जयपुर का क्षेत्र संगमरमर की सुंदर मूर्तियों के निर्माण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

33. (B) बड़े पैमाने पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों का संचालन करना।
राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसिको) की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, हस्तशिल्पियों और पारंपरिक कारीगरों को सहायता प्रदान करना है। इसके मुख्य कार्यों में एम्पोरियम द्वारा विपणन, छोटी इकाइयों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था और कौशल विकास प्रशिक्षण शामिल हैं। परमाणु ऊर्जा उत्पादन अत्यंत जटिल, संवेदनशील और राष्ट्रीय स्तर का भारी ऊर्जा क्षेत्र है, जो पूरी तरह से केंद्रीय एजेंसियों के अधीन होता है। अतः यह कार्य राजसिको के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है।

NODIA

34. (A) मशीनों पर प्राचीन डिजाइनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रामाणिक शिल्प पहचान को नष्ट कर सकता है।
हस्तशिल्प क्षेत्र में आधुनिकीकरण और पारंपरिक पद्धतियों के बीच एक मौलिक संघर्ष देखने को मिलता है। जब प्राचीन और हस्तनिर्मित डिज़ाइनों का कारखानों में मशीनों द्वारा अत्यधिक कम लागत पर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, तो इससे हस्तनिर्मित उत्पादों की मौलिकता, प्रामाणिकता और विशिष्टता प्रभावित होती है। इसके कारण हस्तशिल्प की अद्वितीय कलात्मक पहचान को नुकसान पहुँचता है और हस्तशिल्पी आर्थिक रूप से पिछड़ने लगते हैं, जो इस पारंपरिक क्षेत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है।

35. (B) केवल I और III
राजस्थान के कुटीर उद्योग वर्तमान में कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन इकाइयों के पास प्रत्यक्ष विपणन ढांचे का अभाव है, जिसके कारण वे उत्पादों को बेचने के लिए बिचौलियों पर अत्यधिक निर्भर रहती हैं। इसके अलावा, इन्हें बाजार में मशीनों से बने सस्ते और नकली उत्पादों से कड़ी प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ती है। बैंक ऋण हेतु संपार्श्विक की कमी भी एक बड़ी बाधा है, इसलिए यह धारणा गलत है कि इनके पास बैंकों से असीमित ऋण की सुविधा उपलब्ध है।

36. (D) पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र (बाड़मेर, जैसलमेर)
राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र, विशेष रूप से बाड़मेर और जैसलमेर जिले, पारंपरिक 'कशीदा' यानी हाथ की बारीक कढ़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस क्षेत्र में ग्रामीण महिलाएं वस्त्रों, चद्दरों और सजावटी सामग्रियों पर शीशों (मिरर वर्क) और रंगीन धागों का उपयोग करके उत्कृष्ट कशीदाकारी करती हैं। यह गृह-आधारित कुटीर उद्योग न केवल मरुस्थलीय संस्कृति और परंपरा को जीवंत बनाए रखता है, बल्कि महिलाओं को उनकी आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण पूरक आय भी प्रदान करता है।

37. (C) पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार
केंद्र सरकार द्वारा शुरु की गई 'पीएम विश्वकर्मा' योजना का मुख्य लक्ष्य हाथों और पारंपरिक औजारों से काम करने वाले ग्रामीण कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान

लिए वर्ष 1995 में ग्रामीण गैर-कृषि विकास एजेंसी (रुड़ा) की स्थापना की गई, जो सही कालानुक्रम दर्शाता है।

19. (C) हथकरघा वस्त्र और हस्तशिल्प
ग्रामीण राजस्थान में हथकरघा वस्त्र और हस्तशिल्प का क्षेत्र महिलाओं के रोजगार का सबसे बड़ा आधार है। कताई, बुनाई, बंधेज, ब्लॉक प्रिंटिंग और कशीदाकारी जैसी पारंपरिक कलाओं में महिला कारीगरों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। चुकी ये कार्य घर के भीतर या पास में ही संचालित किए जा सकते हैं, इसलिए ग्रामीण महिलाएं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ इन गतिविधियों को सहजता से पूरा करती हैं। यह क्षेत्र महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता में क्रांतिकारी भूमिका निभाता है।

20. (A) I, II और III
राजस्थान सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम लागू किया है, जो नई इकाइयों को शुरुआती वर्षों में कई अनिवार्य मंजूरियों से छूट देता है। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता सुधार हेतु 'जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट' प्रमाणन और नई सूक्ष्म इकाइयों के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं है जो कारीगरों को प्रत्यक्ष निर्यात करने से रोकता हो, बल्कि सरकार निर्यात को निरंतर प्रोत्साहित करती है।

21. (C) राज्य में सभी हथकरघा उत्पादों को सरकार द्वारा खरीदा जाना अनिवार्य है।
राजस्थान में हथकरघा उद्योग सबसे प्राचीन और व्यापक कुटीर उद्योगों में से एक है, जो सांस्कृतिक विरासत को सहेजे हुए है। इस उद्योग को आधुनिक पावरलूमों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और इसे कौशल संरक्षण तथा संस्थागत सहायता की अत्यधिक आवश्यकता होती है। हालांकि, सरकार द्वारा सभी हथकरघा उत्पादों की शत-प्रतिशत खरीद की कोई कानूनी या नीतिगत अनिवार्यता नहीं है। बुनकर अपने उत्पादों को खुले बाजार, मेलों और निजी माध्यमों से बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

22. (B) प्रति व्यक्ति सीमित पूंजी निवेश के साथ ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति।
ग्रामोद्योगों की मानक परिभाषा के अनुसार, 'ग्रामोद्योग' से तात्पर्य ऐसे किसी भी उद्योग से है जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो और जहाँ प्रति कारीगर या श्रमिक सीमित पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इन उद्योगों का मुख्य उद्देश्य कम लागत पर स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न करना और स्थानीय कच्चे माल का कुशल प्रसंस्करण करना होता है। ये इकाइयां किसी विशाल औद्योगिक ढांचे या महानगरीय क्षेत्रों पर निर्भर नहीं होती हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा बनी रहती हैं।

23. (D) डिजिटल साक्षरता और प्लेटफॉर्म लॉजिस्टिक्स के ज्ञान का अभाव।
आधुनिक युग में ई-कॉमर्स और डिजिटल विपणन पारंपरिक कारीगरों के लिए व्यापक अवसर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन राजस्थान के ग्रामीण कारीगरों को इसमें कई व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुख्य बाधा डिजिटल साक्षरता की कमी, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों के संचालन का सीमित ज्ञान और आधुनिक लॉजिस्टिक्स प्रणालियों से अपरिचित होना है। इसके कारण कारीगर अपने बेहतरीन उत्पादों को ऑनलाइन बाजारों में प्रदर्शित करने और सीधे शहरी ग्राहकों या निर्यातकों तक पहुँचाने में कठिनाई महसूस करते हैं।

24. (A) महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों का विपणन करना।
'अमृता हाट' का आयोजन राजस्थान सरकार के महिला अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य के महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा निर्मित विभिन्न हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्कृत वस्तुओं और पारंपरिक उत्पादों के विपणन हेतु एक प्रत्यक्ष मंच प्रदान करना है। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों को बेचने का अवसर मिलता है, जिससे बिचौलियों का विलोपन होता है और महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है।

25. (A) केवल I और II
राजस्थान के ग्रामोद्योगों में सहकारी समितियां महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ये समितियां कारीगरों को सस्ती दरों पर कच्चे माल की थोक खरीद में सहायता करती हैं और उनके उत्पादों के सामूहिक विपणन को सुनिश्चित करती हैं, जिससे ग्रामीण बिचौलियों का प्रभाव समाप्त होता है। हालांकि, सहकारी समितियों में शामिल होने के लिए कारीगरों द्वारा अपनी निजी संपत्ति या भूमि सरकार को सौंपने की कोई शर्त नहीं होती है। यह व्यवस्था पूरी तरह से कारीगरों के कल्याण और आर्थिक सहयोग पर आधारित है।

26. (A) टोंक
'नमदा' राजस्थान का एक प्रसिद्ध पारंपरिक ऊनी वस्त्र शिल्प है, जिसका मुख्य केंद्र टोंक जिला है। इस शिल्प की विशेषता यह है कि इसमें भेड़ की ऊन को बुनाई करने के बजाय पानी, साबुन और दबाव की मदद से आपस में जमाया (फेल्टिंग) जाता है। इसके पश्चात इस पर रंगीन धागों से आकर्षक कढ़ाई और डिज़ाइन बनाए जाते हैं। टोंक के नमदे देश और विदेश में अत्यंत लोकप्रिय हैं और यह शिल्प स्थानीय कारीगरों की आजीविका का मुख्य आधार है।

27. (D) हथकरघा बुनकर
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री बुनकर सम्मान योजना' का मुख्य उद्देश्य राज्य के पारंपरिक हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करना और उन्हें वित्तीय संबल प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से उत्कृष्ट कार्य करने वाले बुनकरों को नकद पुरस्कार, प्रशिक्षण सुविधाएं और आधुनिक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इसका लक्ष्य हथकरघा कला के संरक्षण के साथ-साथ बुनकर समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है ताकि यह पारंपरिक कला भावी पीढ़ियों के लिए भी निरंतर जीवंत बनी रहे।

Downloaded from www.pdf.tube

47. (A) उद्यम पंजीकरण
भारत सरकार द्वारा शुरु किया गया 'उद्यम पंजीकरण' एक पूरी तरह से निःशुल्क, कागज रहित और डिजिटल ऑनलाइन पोर्टल है। यह पोर्टल राजस्थान के पारंपरिक कारीगरों, कुटीर उद्यमियों और छोटे निर्माताओं को बिना किसी जटिल कागजी कार्रवाई या भौतिक सत्यापन के स्वयं को आधिकारिक रुप से एमएसएमई के रूप में पंजीकृत करने की सुविधा देता है। इसके माध्यम से पंजीकृत इकाइयों को सरकारी योजनाओं, बैंक ऋणों में प्राथमिकता और विभिन्न वित्तीय सब्सिडी का सीधा लाभ प्राप्त करने में सुगमता होती है।

48. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
राजस्थान के पारंपरिक हथकरघा बुनकरों के सामने आजीविका का गंभीर संकट मंडरा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि आधुनिक पावरलूम उद्योग पारंपरिक हाथ से बुने जाने वाले जटिल डिज़ाइनों और पैटर्नों को अत्याधुनिक मशीनों की मदद से बहुत तेजी से और बेहद कम लागत पर दोहरा लेते हैं। इसके परिणामस्वरुप, बाजार में सस्ते मशीन-निर्मित कपड़े की भरमार हो जाती है, जिससे महंगे और समय-साध्य हस्तनिर्मित हथकरघा वस्त्रों की मांग घटती है और बुनकरों की आय प्रभावित होती है।

49. (B) जयपुर और खंडेला (सीकर)
'गोटा पत्ती' कसीदाकारी राजस्थान की एक अत्यंत प्रसिद्ध और पारम्परिक वस्त्र अलंकरण कला है। इसमें सोने या चांदी के चमकीले रिबन को विभिन्न आकारों में काटकर कपड़ों पर सुंदर एप्लिक वर्क किया जाता है। इस शिल्प का मुख्य केंद्र जयपुर शहर और सीकर जिले का खंडेला कस्बा है। खंडेला अपने उच्च गुणवत्ता वाले गोटा, लप्पा-लप्पी और ताड़ी निर्माण के लिए जाना जाता है, जबकि जयपुर इसके विपणन और तैयार वस्त्रों के निर्माण का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है।

50. (A) I, II और III
ग्रामीण गैर-कृषि विकास एजेंसी (रुड़ा) की स्थापना वर्ष 1995 में राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से की गई थी। यह एजेंसी पारंपरिक कारीगरों के कौशल उन्नयन, उत्पाद विकास और विपणन हेतु निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है। हालांकि, भारी कृषि संयंत्रों या ट्रैक्टरों का वितरण करना रुड़ा के कार्यों में शामिल नहीं है, क्योंकि इसका मुख्य ध्यान केवल हस्तशिल्प, चमड़ा, ऊन और खनिज-आधारित लघु कुटीर उद्योगों पर ही केंद्रित रहता है।

51. (C) नाथद्वारा
'तारकशी' की कला लकड़ी की वस्तुओं और फर्नीचर पर चांदी के बारीक तारों की नक्काशीदार जड़ाई (इनले वर्क) करने का एक प्रसिद्ध पारंपरिक शिल्प है। यह कला मुख्य रुप से राजसमंद जिले के नाथद्वारा शहर में केंद्रित है। नाथद्वारा के कुशल कारीगर शीशम या सागौन की लकड़ी पर बेहद सूक्ष्मता से चांदी के तारों को जमाकर आकर्षक सजावटी सामान और डिब्बियां तैयार करते हैं। यह शिल्प राजस्थान की उत्कृष्ट और प्रामाणिक हस्तकला परंपरा का एक अद्वितीय उदाहरण माना जाता है।

52. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
राजस्थान में ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु स्थापित विभिन्न संस्थाएं अपने गठन के वर्षों से जुड़ी हैं। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। इसके बाद छोटे उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में की गई। हथकरघा बुनकरों के विकास हेतु राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम का गठन 1984 में हुआ, तथा ग्रामीण गैर-कृषि विकास एजेंसी (रुड़ा) की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी।

53. (C) सरकारी योजनाओं और व्यापार मेलों तक पहुंच प्रदान करने के लिए कारीगरों का पंजीकरण करती है।
केंद्र सरकार द्वारा कपड़ा मंत्रालय के माध्यम से शुरु की गई 'पहचान' पहचान पत्र पहल हस्तशिल्प कारीगरों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस पहल के तहत राजस्थान सहित देश भर के प्रामाणिक कारीगरों को एक डिजिटल पहचान पत्र प्रदान किया जाता है। यह पहचान पत्र कारीगरों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनी मेलों में निःशुल्क स्टॉल, रियायती दरों पर कच्चा माल, कौशल विकास प्रशिक्षण और सरकारी वित्तीय योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध होता है।

54. (B) प्रसंस्करण, परीक्षण और पैकेजिंग के लिए महंगी मशीनों को साझा करना।
ग्रामीण शिल्प क्लस्टरों में 'कॉमन फैसिलिटी सेंटर' (सीएफसी) स्थापित करने का प्राथमिक उद्देश्य छोटे कारीगरों को आधुनिक तकनीक तक पहुँच प्रदान करना है। चुकी व्यक्तिगत कारीगर महंगी प्रसंस्करण, गुणवत्ता परीक्षण, लेजर कटिंग और उन्नत पैकेजिंग मशीनें खरीदने में असमर्थ होते हैं, इसलिए सीएफसी में ये सुविधाएं सामूहिक रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे कारीगर साझा आधार पर न्यूनतम शुल्क देकर इन मशीनों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उत्पादन लागत घटती है और गुणवत्ता में सुधार होता है।

NODIA

55. (D) ई-कॉमर्स हस्तशिल्प प्लेटफॉर्मों पर उत्पादों को सूचीबद्ध करना।
दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगरों के लिए बड़े शहरी बाजारों तक प्रत्यक्ष पहुंच बनाना सदैव कठिन रहा है। बाड़मेर के अजरक प्रिंट कारीगर जैसे छोटे उत्पादकों के लिए ई-कॉमर्स हस्तशिल्प प्लेटफॉर्मों पर अपने उत्पादों को सूचीबद्ध करना सबसे प्रभावी और आधुनिक समाधान है। इस माध्यम से कारीगरों को दूसरे शहरों में भौतिक दुकान खोलने के लिए भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं पड़ती, और वे बिना बिचौलियों के सीधे देश-विदेश के खरीदारों से जुड़कर अपने उत्पाद बेच सकते हैं।

56. (A) झुंझुनूं
राजस्थान में हस्त-ब्लॉक प्रिंटिंग (छपाई) कपड़े की एक अत्यंत समृद्ध परंपरा रही है, जिसके प्रमुख केंद्रों में जयपुर (सांगानेर एवं बगरु), बाड़मेर (अजरक एवं मलीर प्रिंट) और चित्तौड़गढ़

करना है। इसमें सुथार, लोहार, कुम्हार, बुनकर और मोज़री बनाने वाले जैसे पारंपरिक कारीगर शामिल हैं। यह योजना इन कारीगरों को रियायती दर पर ऋण, आधुनिक औजार किट, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण और ब्रांडिंग सहायता प्रदान करती है, जिससे राजस्थान की ग्रामीण हस्तशिल्प अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्राप्त हो रही है।

38. (B) 2, 1, 4, 3
क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को लागू करने के लिए एक व्यवस्थित क्रम अपनाया जाता है। सर्वप्रथम, किसी विशिष्ट हस्तशिल्प के भौगोलिक संकेंद्रण और कारीगरों की उपस्थिति की पहचान की जाती है। इसके पश्चात, कारीगरों को संगठित करने हेतु एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) या सहकारी समिति का गठन किया जाता है। तीसरे चरण में, साझा तकनीकी प्रक्रियाओं के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) स्थापित किया जाता है। अंत में, निर्मित उत्पादों के लिए सामूहिक वैश्विक विपणन और निर्यात नेटवर्क विकसित किया जाता है।

39. (D) यह चमड़ा, ऊन और खनिजों के क्षेत्र में गैर-कृषि रोजगार को बढ़ावा देती है।
ग्रामीण गैर-कृषि विकास एजेंसी (रुड़ा) का मुख्य जनादेश राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा रोजगार के वैकल्पिक अवसर सृजित करना है। यह संस्था विशेष रूप से तीन उप-क्षेत्रों - चमड़ा, ऊन और गैर-खाद्य खनिजों - पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। रुड़ा इन क्षेत्रों से जुड़े पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक डिजाइन, उन्नत औजार, तकनीकी प्रशिक्षण और विपणन सहायता प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और कृषि क्षेत्र पर अतिरिक्त दबाव कम होता है।

40. (D) I, II, III और IV
राजस्थान के हस्तशिल्प अपनी अनूठी प्रामाणिकता के लिए पहचाने जाते हैं और इनमें से कई को भौगोलिक संकेतक (जीआई) रजिस्ट्री द्वारा आधिकारिक जीआई टैग प्रदान किया गया है। बगरु और सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट्स अपनी प्राकृतिक रंगाई शैली के लिए, जयपुर की ब्लू पॉटरी अपनी चीनी मिट्टी रहित कला के लिए, और पोकरण पॉटरी अपने पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों के लिए जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं। ये सभी दर्जा प्राप्त उत्पाद राजस्थान की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं।

41. (C) स्टील रोलिंग मिल
राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योगों की श्रेणी में वे गतिविधियां आती हैं जिन्हें कम पूंजी, हस्तकौशल और घरेलू स्तर पर संचालित किया जा सकता है, जैसे कालीन बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण (पापड़-मंगोड़ी) और बीड़ी निर्माण। इसके विपरीत, स्टील रोलिंग मिल एक भारी औद्योगिक विनिर्माण इकाई है। इसके संचालन के लिए विशाल पूंजी निवेश, उच्च विद्युत खपत, बड़ी भूमि और भारी यंत्रीकृत संयंत्रों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे कुटीर उद्योग की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है।

42. (B) 1984
राजस्थान में हथकरघा क्षेत्र का विकास करने और पारंपरिक बुनकरों के हितों का संरक्षण करने हेतु वर्ष 1984 में राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम (आरएचडीसी) की स्थापना की गई थी। यह संस्था बुनकरों को गुणवत्तापूर्ण सूत और कच्चा माल उपलब्ध कराने, उन्हें आधुनिक डिजाइनों का प्रशिक्षण देने तथा उनके द्वारा निर्मित वस्त्रों की बिक्री हेतु विपणन सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। इससे राज्य की समृद्ध बुनकरी परंपरा को निरंतर आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त होता रहता है।

43. (D) गांवों में ही टिकाऊ स्थानीय रोजगार के अवसर प्रदान करके।
ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होने वाला अवांछित पलायन एक बड़ी सामाजिक-आर्थिक चुनौती है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग गांवों में ही स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों और कौशल का उपयोग करके टिकाऊ गैर-कृषि रोजगार उत्पन्न करते हैं। जब ग्रामीण कारीगरों और युवाओं को उनके घर के निकट ही नियमित आय और आजीविका के साधन प्राप्त हो जाते हैं, तो उन्हें रोजगार की तलाश में बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं रहती, जिससे ग्रामीण पलायन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होता है।

44. (B) बीकानेरी भुजिया
बीकानेर शहर अपने विशिष्ट खाद्य प्रसंस्करण कुटीर उद्योग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसे 'बीकानेरी भुजिया' के नाम से जाना जाता है। बेसन, मोठ के आटे और स्थानीय मसालों के अनूठे मिश्रण से बनने वाला यह व्यंजन अपनी विशिष्ट क्रिस्पी गुणवत्ता और स्वाद के लिए पहचाना जाता है। बीकानेरी भुजिया को आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्रदान किया गया है। यह उद्योग बीकानेर में हजारों परिवारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।

45. (C) अलवर
राजस्थान का अलवर जिला अपनी अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी 'कागजी पॉटरी' (कागजी मृद्भांड) कला के लिए जाना जाता है। इस पॉटरी की मुख्य विशेषता यह है कि इसके बर्तन और सजावटी पात्र कागज़ की तरह बेहद पतले, हल्के और नाजुक होते हैं। स्थानीय कुम्हार विशेष प्रकार की मिट्टी का उपयोग करके और अत्यंत कुशलता से इन्हें आकार देते हैं। कागजी पॉटरी अपनी महीन बनावट और कलात्मक सुंदरता के लिए हस्तशिल्प प्रेमियों के बीच विशेष स्थान रखती है।

46. (D) उपकरणों में निवेश की सीमा और वार्षिक टर्नओवर।
भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास अधिनियम के तहत उद्योगों का वर्गीकरण स्पष्ट रूप से निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। संशोधित परिभाषा के अनुसार, एक 'सूक्ष्म' उद्यम को 'लघु' उद्यम से अलग करने का मुख्य आधार संयंत्र, मशीनरी या उपकरणों में किए गए पूंजीगत निवेश की सीमा और इकाई का कुल वार्षिक टर्नओवर होता है। सूक्ष्म उद्यमों के लिए निवेश और टर्नओवर की कानूनी सीमाएं लघु उद्यमों की तुलना में काफी कम रखी गई हैं।

Click Here to Buy book on Flipkart

आधुनिकीकरण और वित्तीय सशक्तीकरण करना है। यह योजना राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित पापड़, मंगोड़ी, अचार, भुजिया और मसाले बनाने वाली पारंपरिक सूक्ष्म इकाइयों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। इसके माध्यम से इन छोटी इकाइयों को तकनीक, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और ऋण सब्सिडी की सुविधा प्राप्त होती है।

67. (C) यह दुनिया भर के किसी भी उत्पादक को पंजीकृत नाम का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति देता है।
किसी उत्पाद को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग मिलने का मुख्य उद्देश्य उस क्षेत्र विशेष की पारंपरिक कला और उत्पादकों के अधिकारों की सुरक्षा करना होता है। जीआई टैग अनधिकृत बाहरी व्यक्तियों या वैश्विक निर्माताओं को पंजीकृत भौगोलिक नाम का उपयोग करने से कानूनी रूप से रोकता है। अतः दुनिया भर के किसी भी उत्पादक को इस पंजीकृत नाम का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति देना जीआई टैग के सिद्धांतों और कानूनों के पूरी तरह विपरीत है।

68. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
राजस्थान के पारंपरिक कारीगरों के लिए अपने कुटीर व्यवसायों का विस्तार करने में बैंकों का संपार्श्विक-आधारित ऋण मॉडल सबसे बड़ी वित्तीय बाधा है। वाणिज्यिक बैंक ऋण देने के बदले ज़मानत के रूप में पंजीकृत भूमि या मूल्यवान संपत्ति गिरवी रखने की मांग करते हैं। चुकी ग्रामीण कारीगरों के पास औपचारिक संपत्ति दस्तावेज या पर्याप्त पूंजीगत परिसंपत्तियों का अभाव होता है, इसलिए वे बैंकिंग प्रणाली से संस्थागत ऋण पाने से वंचित रह जाते हैं, जिससे उनका व्यावसायिक विकास रुक जाता है।

69. (C) बीकानेर
'मथेरना कला' और 'उस्ता कला' राजस्थान के बीकानेर जिले की दो अत्यंत प्रसिद्ध पारंपरिक हस्तशिल्प शैलियां हैं। मथेरना कला के अंतर्गत धार्मिक पौराणिक विषयों पर भित्तिचित्र और पन्ने पर चित्रकारी की जाती है। दूसरी ओर, उस्ता कला में प्रसंस्कृत ऊंट की खाल से बनी वस्तुओं, कुप्पियों और महराबों पर सोने की सुक्ष्म नक्काशी (गोल्ड एम्बॉस वर्क) की जाती है। ये दोनों कलाएं बीकानेर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्ट शिल्प कौशल का मुख्य प्रतीक मानी जाती हैं।

70. (B) यह छोटी कुटीर इकाइयों को बिना बड़े बजट के देश भर के खरीदारों तक पहुंचने की अनुमति देता है।
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) जैसे आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों से ग्रामीण कारीगर सहकारी समितियों को जोड़ने का मुख्य लाभ यह है कि इससे छोटे कुटीर उद्योगों का लोकतंत्रीकरण होता है। इसके माध्यम से छोटे कारीगर बिना किसी भारी मध्यस्थ शुल्क या विशाल विपणन बजट के सीधे पूरे भारत के ग्राहकों और ई-कॉमर्स खरीदारों तक पहुँच सकते हैं। इससे कारीगरों की बिक्री में वृद्धि होती है और उन्हें अपने हस्तशिल्प का उचित एवं पारदर्शी मूल्य प्राप्त होता है।

71. (D) कोटा डोरिया बुनाई
बारां जिले में स्थित मांगरोल कस्बा, कोटा जिले के कैथून के साथ-साथ, प्रसिद्ध 'कोटा डोरिया' कपड़ा बुनाई का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। मांगरोल के बुनकर समुदाय सदियों से पारंपरिक हथकरघों का उपयोग करके सूत और रेशम के बारीक ताने-बाने से पारदर्शी खतदार कोटा डोरिया साड़ियां और फैब्रिक बुनते आ रहे हैं। मांगरोल क्लस्टर इस समृद्ध हथकरघा परंपरा को बनाए रखने और ग्रामीण क्षेत्र में बुनकरों को स्थायी रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

72. (A) P-4, Q-3, R-2, S-1
राजस्थान के वस्त्र शिल्प अपने विशिष्ट क्षेत्रीय केंद्रों से जुड़े हुए हैं। बाड़मेर जिला अपने प्रसिद्ध 'अजरक प्रिंट' के लिए जाना जाता है, जिसमें लाल और नीले रंगों का प्रयोग होता है। चित्तौड़गढ़ का आकोला गांव 'दाबू प्रिंट' के लिए प्रसिद्ध है, कोटा का कैथून क्षेत्र 'कोटा डोरिया' की बारीक बुनाई के लिए विख्यात है, और सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा कार्य में उपयोग होने वाले 'लप्पा-लप्पी' निर्माण का प्रमुख केंद्र माना जाता है।

73. (C) राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों को लोकप्रिय बनाने तथा कारीगरों को प्रत्यक्ष विपणन अवसर प्रदान करने हेतु 'राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड' प्रमुख संस्था के रूप में कार्य करता है। यह बोर्ड राज्य के प्रमुख शहरों में नियमित रूप से राज्य स्तरीय 'खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी' और मेलों का आयोजन करता है। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से ग्रामीण कताईकर्ताओं, बुनकरों और लघु ग्रामोद्योग इकाइयों को अपने उत्पादों को उपभोक्ताओं को सीधे बेचने के लिए एक बेहतर मंच प्राप्त होता है।

74. (A) क्लस्टर विकास दृष्टिकोण
'क्लस्टर विकास दृष्टिकोण' एक ऐसी आर्थिक और औद्योगिक रणनीति है जिसमें किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के कई छोटे कारीगर और कुटीर इकाइयां आपस में सहयोग करती हैं। इसके तहत वे कच्चा माल थोक में खरीदने, आधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर साझा करने और विपणन प्रयासों को एकजुट करने के लिए समूह बनाती हैं। इस सामूहिक प्रयास से प्रत्येक व्यक्तिगत कारीगर की उत्पादन लागत में भारी कमी आती है, कार्यकुशलता बढ़ती है और बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता काफी मजबूत होती है।

75. (D) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
राजस्थान सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना' राज्य में नए उद्यमों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण को वित्तीय गति प्रदान करने हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के कारीगरों, बुनकरों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को 10 करोड़ रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर सरकार द्वारा 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक का ब्याज अनुदान (सब्सिडी) प्रदान किया जाता है। इससे नए उद्यमियों को संबल मिलता है।

Downloaded from www.pdf.tube

(R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

9. ग्वार गम के उत्पादन और निर्यात में राजस्थान वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्थान रखता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मांग को बढ़ाने वाला प्राथमिक औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है?
(A) उच्च गति वाले व्यावसायिक विमानों में संरचनात्मक समग्र घटकों का विनिर्माण
(B) शेल गैस निष्कर्षण में हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग (फ्रैकिंग)
(C) सिंथेटिक टेक्सटाइल रसायनों के लिए प्राथमिक स्थिरीकरण एजेंट और आधार माध्यम
(D) लिथियम-आयन बैटरी सेल के निर्माण में व्यापक रूप से प्रयुक्त बाइंडिंग एजेंट

10. राजस्थानी चमड़े की वस्तुओं के निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. मोजड़ी जूते/चप्पल पारंपरिक चमड़ा हस्तशिल्प निर्यात के एक महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
II. जोधपुर और जयपुर कारीगरों द्वारा निर्मित चमड़े के सामान के प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।
III. यह क्षेत्र पूरी तरह से भारी स्वचालित मशीनों पर निर्भर है और इसमें हस्तशिल्प का कोई योगदान नहीं है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

11. राजस्थान में निर्यातकों को सुविधा प्रदान करने, शिकायत निवारण मंच के रूप में कार्य करने और वैश्विक बाजारों में राज्य के उत्पादों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से किस राज्य स्तरीय संस्थान की स्थापना की गई थी?
(A) राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद (आरईपीसी)
(B) राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी)
(C) राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आरटीडीसी)
(D) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आरएसएमएमएल)

12. भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग निर्यातकों को प्रीमियम बाजार मूल्य दिलाने और प्रामाणिकता की रक्षा करने में सहायता करते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा जीआई-टैग प्राप्त उत्पाद और राजस्थान में उसके संबंधित क्षेत्र का गलत युग्म है?
(A) बगरू प्रिंट - जयपुर
(B) कोटा डोरिया - कोटा
(C) मोलेला क्ले वर्क (मूर्तिकला) - बीकानेर
(D) थेवा कला - प्रतापगढ़

13. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प निर्यात बाजार में सांगानेरी प्रिंट जैसे पारंपरिक राजस्थानी वस्त्रों के लिए भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्राप्त करने के रणनीतिक लाभ का सटीक वर्णन करता है?
(A) यह विदेशी खरीदार देशों द्वारा लगाए जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और आयात शुल्कों को पूरी तरह से समाप्त कर देता है।
(B) यह केवल आधुनिक उच्च गति वाले स्वचालित पावरलूम का उपयोग करके निर्मित किए जाने वाले कपड़ों के विनिर्देशों को अनिवार्य करता है।
(C) यह अनधिकृत विदेशी शोषण को रोकने के लिए व्यावसायिक बिक्री को केवल घरेलू बाजारों तक ही सख्ती से सीमित करता है।
(D) यह प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने के लिए भौगोलिक उत्पत्ति और पारंपरिक तरीकों को कानूनी रूप से प्रमाणित करता है।

NODIA

14. राजस्थान के काष्ठ (लकड़ी) शिल्प निर्यात के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: राजस्थान के पारंपरिक काष्ठ शिल्प निर्यात में मुख्य रूप से आधुनिक मॉड्यूलर प्लाईवुड फर्नीचर शामिल हैं।
कथन II: जोधपुर को हस्तनिर्मित ठोस लकड़ी के फर्नीचर और प्राचीन प्रतिकृतियों के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है।
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

15. राजस्थान की हस्तशिल्प प्रोत्साहन योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वे कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।
II. वे हथकरघा की सुरक्षा के लिए मशीन से बने कपड़ों के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाती हैं।
III. इनमें वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए कौशल उन्नयन और डिजाइन हस्तक्षेप कार्यक्रम शामिल हैं।
IV. वे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कारीगरों को जोड़ने में सुविधा प्रदान करती हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

16. राजस्थान में "निर्यात बनो" मिशन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शुरु किया गया था?
(A) राज्य में विदेशी विलासिता मोटर वाहनों के व्यावसायिक आयात को व्यवस्थित रूप से हतोत्साहित और दंडित करना।
(B) सख्त वैधानिक जनादेश लागू करना कि राज्य में निर्मित सभी वस्तुओं का निर्यात किया जाना चाहिए।

अध्याय 20

राजस्थान के निर्यात योग्य हस्तशिल्प

1. भारत की निर्यात टोकरी में राजस्थान का एक विशिष्ट स्थान है। ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस व्यापक श्रेणी का राजस्थान के कुल विनिर्माण और हस्तशिल्प निर्यात में प्रमुख हिस्सा है?
(A) इंजीनियरिंग वस्तुएं, वस्त्र और हस्तशिल्प
(B) भारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर
(C) समुद्री उत्पाद और तटीय कृषि उत्पाद
(D) भारी व्यावसायिक वाहन और विमान के पुर्जे

2. जयपुर वैश्विक रत्न एवं आभूषण निर्यात बाजार में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विशिष्ट प्रक्रिया में अपनी विशेषज्ञता के कारण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है?
(A) कच्चे सोने और प्लैटिनम का बड़े पैमाने पर निष्कर्षण और खनन
(B) गहरे समुद्र में मोती निकालना और विशिष्ट अपतटीय समुद्री संवर्धन
(C) पन्ने और रंगीन रत्नों की कटाई एवं पॉलिशिंग
(D) भारी औद्योगिक हीरा ड्रिल बिट्स का सटीक विनिर्माण

3. राजस्थान के भीलवाड़ा जिले ने वैश्विक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विशिष्ट वस्त्र क्षेत्र में एक प्रमुख निर्यात बाजार उपस्थिति हासिल की है?
(A) सिंथेटिक वर्स्टेड सूटिंग कपड़ा और धागा
(B) हस्तनिर्मित पारंपरिक शहतूत हथकरघा रेशमी साड़ियाँ
(C) कच्चे बिना कते हुए कपास की गांठों का व्यावसायिक प्रसंस्करण
(D) बुने हुए पर्यावरण-अनुकूल जूट और नारियल जटा के पायदान

4. राजस्थान की पारंपरिक बंधाई और रंगाई (बंधेज) कपड़ा शिल्प कला, जिसकी निर्यात बाजार में मजबूत उपस्थिति है, को मूल रूप से निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है?
(A) कलमकारी
(B) इकत
(C) चिकनकारी
(D) बंधेज (बंधानी)

5. सूची I में दिए गए राजस्थान के प्रमुख निर्यात-उन्मुख हस्तशिल्प क्लस्टरों का सूची II में दिए गए उनकी प्राथमिक शिल्प विशेषज्ञता के साथ मिलान कीजिए।
सूची I: (निर्यात क्लस्टर)
P. जयपुर
Q. जोधपुर
R. भीलवाड़ा
S. किशनगढ़
सूची II: (शिल्प विशेषज्ञता)
1. प्रसंस्कृत संगमरमर स्लैब
2. रंगीन रत्न
3. नक्काशीदार लकड़ी के फर्नीचर
4. सिंथेटिक सूटिंग कपड़ा
(A) P-2, Q-3, R-4, S-1
(B) P-3, Q-2, R-1, S-4
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

6. निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर राजस्थान के पत्थर निर्यात क्लस्टरों से निर्यात किए जाने वाले प्राथमिक आयामी पत्थर (डायमेंशनल स्टोन) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है?
(A) बलुआ पत्थर
(B) ग्रेनाइट
(C) बेसाल्ट
(D) संगमरमर

7. राजस्थान की ब्लू पॉटरी एक विशिष्ट सजावटी शिल्प निर्यात क्षेत्र के रूप में उभरी है। राजस्थानी ब्लू पॉटरी के मिश्रण की पारंपरिक तैयारी में निम्नलिखित में से किस आधार सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है?
(A) क्वार्ट्ज पाउडर
(B) मुल्तानी मिट्टी
(C) कच्चा काँच
(D) प्राकृतिक मिट्टी (चिकनी मिट्टी)

8. राजस्थान के हस्तशिल्प निर्यातकों के रसद (लॉजिस्टिक्स) के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन (A): गुजरात या महाराष्ट्र जैसे राज्यों के निर्यातकों की तुलना में राजस्थान के हस्तशिल्प निर्यातकों को अपेक्षाकृत अधिक अंतर्देशीय रसद और परिवहन लागत का सामना करना पड़ता है।
कारण (R): राजस्थान एक भू-आबद्ध (लैंडलॉक्ड) राज्य है, जहाँ से समुद्री परिवहन से पूर्व माल को दूरस्थ तटीय बंदरगाहों या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) के माध्यम से ले जाना आवश्यक होता है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण

Click Here to Buy book on Amazon

76. (B) थेवा कला — रंगीन कांच पर सोने की बारीक काम की गई शीट (पन्नी) को मिलाना।
राजस्थानी कुटीर शिल्पों में प्रतापगढ़ की 'थेवा कला' अपनी अद्वितीय तकनीक के लिए विख्यात है। इस कला के अंतर्गत विशेष रुप से तैयार किए गए रंगीन बेल्जियम कांच के आधार पर सोने की अत्यंत बारीक और नक्काशीदार वर्क (पन्नी) को संयोजित करके आभूषण और सजावटी पात्र बनाए जाते हैं। यह कलात्मक प्रक्रिया अत्यधिक सूक्ष्म और कठिन होती है, जो केवल सीमित कुशल कारीगरों द्वारा ही संपन्न की जाती है। यह युग्म थेवा कला की मूल विशेषता को पूरी तरह से निरुपित करता है।

77. (C) सौंदर्य मूल्य की हानि और मशीनों द्वारा कारीगरों का विस्थापन।
अत्यधिक आधुनिकीकरण और कारखानों में मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन का पारंपरिक कुटीर उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मशीनी उत्पादन के कारण हाथ से बने शिल्पों की अनूठी कलात्मकता, मानवीय संवेदना और पारंपरिक सौंदर्य मूल्य में कमी आती है। इसके अतिरिक्त, सस्ते और तेजी से बनने वाले मशीन-निर्मित उत्पाद बाजार पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे पीढ़ियों से काम कर रहे कुशल कारीगरों का विस्थापन होता है और उनकी आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा हो जाता है।

78. (B) 2, 1, 4, 3
ई-कॉमर्स के माध्यम से पारंपरिक हस्तशिल्प (जैसे मोज़री) को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने की एक तार्किक मूल्य श्रृंखला होती है। सर्वप्रथम, कारीगर द्वारा कच्चे चमड़े की खरीद करके उत्पाद का हस्त-निर्माण किया जाता है। इसके पश्चात, तैयार उत्पाद की डिजिटल कैटलॉगिंग और फोटोग्राफी की जाती है। तीसरे चरण में, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ऑर्डर और भुगतान प्राप्त होता है। अंततः, वैश्विक लॉजिस्टिक्स साझेदारों के माध्यम से पैक किए गए उत्पाद को ग्राहक तक भेजा जाता है।

79. (A) उस्ता कला
राजस्थान के पारंपरिक शिल्पों में उस्ता कला प्राथमिक कच्चे माल के आधार पर अन्य तीनों शिल्पों से पूरी तरह भिन्न है। उस्ता कला में प्रसंस्कृत ऊंट की खाल और चमड़े का उपयोग आधार के रूप में किया जाता है, जिस पर सोने की नक्काशी की जाती है। इसके विपरीत, सांगानेरी प्रिंट, बगरु प्रिंट और अजरक प्रिंट तीनों ही मुख्य रुप से सूती कपड़ों पर प्राकृतिक रंगों और लकड़ी के ब्लॉक से की जाने वाली वस्त्र छपाई (टेक्सटाइल प्रिंटिंग) से संबंधित शिल्प हैं।

80. (B) 27 जून
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के आर्थिक महत्व, रोजगार सृजन और सतत विकास में उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करने हेतु प्रतिवर्ष 27 जून को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'एमएसएमई दिवस' मनाया जाता है। राजस्थान सरकार भी इस अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जहाँ नए उद्यमियों को सम्मानित किया जाता है, नीतियां जारी की जाती हैं और पारंपरिक कुटीर एवं ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जागरुकता अभियान चलाए जाते हैं।

www.nodia.in

NODIA

(C) विनिर्माण क्षेत्र में कृषि श्रमिकों को कम कुशल कारखाने की नौकरियों में तेज़ी से स्थानांतरित करना।
(D) स्थानीय फर्मों को सक्रिय निर्यातक बनने के लिए पंजीकृत करना, प्रशिक्षित करना और सहायता प्रदान करना।

17. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म राजस्थान की पारंपरिक हस्तशिल्प निर्यात रणनीति को तेज़ी से बदल रहे हैं। स्थानीय कारीगरों के लिए इस डिजिटल मार्केटप्लेस एकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण लाभ निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) निर्यात बिचौलियों को दरकिनार करते हुए प्रत्यक्ष बी2सी (उपभोक्ता को प्रत्यक्ष बिक्री) वैश्विक पहुँच प्रदान करता है।
(B) भौतिक उत्पाद प्रबंधन, भंडारण और समुद्री शिपिंग की तार्किक आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त करता है।
(C) ग्रामीण शिल्प उत्पादकों को अनिवार्य अंतर्राष्ट्रीय निर्यात गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुपालन से छूट देता है।
(D) लक्षित ग्राहकों तक पहुँच को विशेष रूप से विदेश में रहने वाले अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) समुदायों तक सीमित करता है।

18. निम्नलिखित पारंपरिक राजस्थानी शिल्पों में से कौन-सा मूल रूप से वस्त्र या कपड़े पर आधारित निर्यात के रूप में प्रसिद्ध नहीं है?
(A) बगरू प्रिंट
(B) कोटा डोरिया
(C) उस्ता कला
(D) सांगानेरी प्रिंट

19. वैश्विक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा पारंपरिक राजस्थानी ठप्पा छपाई (ब्लॉक प्रिंटिंग) कपड़ों के निर्यात बाजार हिस्सेदारी के लिए सबसे गंभीर चुनौती पैदा करता है?
(A) मशीन से बनी सस्ती स्क्रीन-प्रिंटेड प्रतिकृतियों की आवक।
(B) अंतर्राष्ट्रीय जिंस (कमोडिटी) बाजारों में प्रमाणित जैविक कच्चे कपास की भारी कमी और बढ़ती खरीद लागत।
(C) सभी हस्तनिर्मित भारतीय वस्त्रों के आयात पर पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंध।
(D) केवल सिंथेटिक भारी ऊनी कपड़े पहनने की ओर उपभोक्ता प्राथमिकताओं में तीव्र संरचनात्मक बदलाव।

20. राजस्थान में किसी कारीगर उद्यम को औपचारिक हस्तशिल्प निर्यात शुरू करने के लिए उठाए जाने वाले बुनियादी चरणों के सही क्रमिक क्रम का चयन कीजिए:
1. डीजीएफटी से आयात-निर्यात कोड (आईईसी) प्राप्त करना।
2. एक कानूनी व्यावसायिक इकाई का पंजीकरण करना।
3. संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) की सदस्यता प्राप्त करना।
4. अंतर्राष्ट्रीय क्रय आदेश प्राप्त करना और सीमा शुल्क निकासी की व्यवस्था करना।
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 1, 3, 2, 4

21. बंशी पहाड़पुर, राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र है जो स्मारकीय वास्तुकला में अपने सामग्री योगदान के लिए जाना जाता है, यह किस आयामी पत्थर (डायमेंशनल स्टोन) के निर्यात का एक प्रमुख स्रोत है?
(A) सफेद संगमरमर
(B) गुलाबी बलुआ पत्थर
(C) काला ग्रेनाइट
(D) पीला चूना पत्थर

22. हस्तशिल्प में भावी निर्यात वृद्धि के लिए राजस्थान सरकार द्वारा अपनाई गई मान्यता प्राप्त रणनीतियों में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी शामिल हैं?
(A) नए भौगोलिक बाजारों में विविधता लाना।
(B) समकालीन वैश्विक सौंदर्यशास्त्र से मेल खाने के लिए डिजाइन नवाचार को बढ़ावा देना।
(C) मात्रा को सीमित करने के लिए पारंपरिक शिल्पों पर भारी राज्य निर्यात शुल्क लगाना।
(D) निर्यात-ग्रेड कारीगरी के लिए गुणवत्ता और कौशल प्रमाणन की सुविधा प्रदान करना।

23. राजस्थान में निर्यात संवर्धन ब्यूरो (ईपीबी) की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन-सा प्राथमिक कार्य शामिल है?
(A) आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा विनिमय दरों और मौद्रिक शुल्कों का निर्धारण और स्थापना करना।
(B) केवल राज्य प्रशासनिक उपयोग के लिए स्थानीय कारीगरों से सीधे सभी हस्तशिल्प सूची की खरीद करना।
(C) घरेलू बाजारों में आवश्यक घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य तय करना और विनियमित करना।
(D) निर्यातक मुद्दों को हल करने के लिए एकल-खिड़की (सिंगल-विंडो) नोड के रूप में कार्य करना।

24. अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों द्वारा राजस्थानी लकड़ी के हस्तशिल्प निर्यातकों से किस महत्वपूर्ण गुणवत्ता आश्वासन आवश्यकता की मांग तेज़ी से की जा रही है?
(A) कानूनी लकड़ी सोर्सिंग, टिकाऊ वानिकी और लकड़ी के उपचार का प्रमाण।
(B) यह साबित करने वाला अनिवार्य प्रमाणन कि लकड़ी की कटाई केवल आदिम गैर-धातु हस्त उपकरणों का उपयोग करके की गई थी।
(C) यह सत्यापित करने वाले वैधानिक दस्तावेज कि कच्ची लकड़ी सामग्री सीधे प्रमाणित अमेज़न वर्षावनों से आयात की गई थी।
(D) यह पुष्टि करने वाला सत्यापित प्रयोगशाला परीक्षण कि संरचनात्मक जोड़ के दौरान शून्य सिंथेटिक रासायनिक

Downloaded from www.pdf.tube

(फुटप्रिंट) नहीं है।

III. हस्तशिल्प और लकड़ी के फर्नीचर मुख्य रूप से जोधपुर जैसे क्लस्टरों से निर्यात किए जाते हैं।

IV. राज्य सरकार निर्यात संवर्धन ब्यूरो के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

56. जोधपुर के हस्तनिर्मित लकड़ी के फर्नीचर निर्यात उद्योग में पारंपरिक रूप से और सबसे व्यापक रूप से निम्नलिखित में से किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है?

(A) शीशम और आम की लकड़ी
(B) सुगंधित सफेद चंदन की लकड़ी
(C) अति-हल्की व्यावसायिक बाल्सा लकड़ी
(D) आयातित उच्च-ग्रेड कैनेडियन पाइन (चीड़) की लकड़ी

57. राजस्थान के हस्तशिल्प क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: वैश्विक बाजार में राजस्थान के हस्तशिल्प क्षेत्र का प्राथमिक तुलनात्मक लाभ इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक डिजाइन सौंदर्यशास्त्र है।

कथन II: वैश्विक खरीदार हस्तनिर्मित आयातों के लिए सततता और न्यायसंगत व्यापार (फेयर-ट्रेड) मानकों के अनुपालन की मांग बढ़ा रहे हैं।

निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

58. क्षेत्र-विशिष्ट निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य आमतौर पर ईपीसी द्वारा नहीं किया जाता है?

(A) अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जानकारी एकत्र करना और उसे निर्यातकों के साथ साझा करना।
(B) स्थानीय कारीगरों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सीधे हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्माण करना।
(C) निर्यात लाभों के लिए आवश्यक पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) जारी करना।
(D) खरीदार-विक्रेता बैठकों और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन करना।

59. डिजिटल मार्केटप्लेस के माध्यम से राजस्थान के कारीगर उत्पादों की वैश्विक पहुँच निम्नलिखित में से किस द्वितीयक लॉजिस्टिक्स चुनौती को हल करने पर अत्यधिक निर्भर करती है?

(A) ग्रामीण क्लस्टरों से विश्वसनीय फर्स्ट-माइल लॉजिस्टिक्स और पार्सल शिपिंग।
(B) प्रत्येक ग्रामीण कारीगर गाँव में पूरी तरह से चालू कार्गो हवाई अड्डों और निजी हवाई पट्टियों का निर्माण करना।
(C) मैक्रो-स्तरीय वैश्विक दूरसंचार और इंटरनेट बैंडविड्थ थ्रूपुट की बाधाओं को पूरी तरह से हल करना।
(D) हर प्रमुख यूरोपीय राजधानी शहर में राज्य के स्वामित्व वाले भौतिक (ब्रिक-एंड-मोर्टार) खुदरा फ्लैगशिप स्टोर स्थापित करना।

60. जयपुर रत्न और आभूषण निर्यात उद्योग में मूल्य संवर्धन (वैल्यू एडिशन) प्रक्रिया को दर्शाने वाले सही क्रम का चयन कीजिए:

1. रत्न की कटाई, पॉलिशिंग और फेसेटिंग (पहल काटना)।
2. अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू बाजारों से कच्चे रंगीन रत्नों की खरीद।
3. तैयार रत्न या जड़ित आभूषणों का वैश्विक बाजारों में निर्यात करना।
4. पॉलिश किए गए रत्न को बहुमूल्य धातु आभूषण डिजाइनों में जड़ना (सेट करना)।

(A) 2, 1, 4, 3
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 4, 1, 3
(D) 4, 1, 2, 3

61. बगरू प्रिंट्स का निर्यात कपड़ा बाजार में अत्यधिक मूल्यवान है। निम्नलिखित में से कौन-सा प्रामाणिक बगरू ब्लॉक प्रिंटिंग की एक प्रमुख विशिष्ट विशेषता है?

(A) नियॉन सिंथेटिक रासायनिक रसायनों के व्यापक उपयोग के माध्यम से प्राप्त उज्ज्वल रंग।
(B) प्रसंस्कृत भारी जानवरों की खाल और चमड़े की चादरों पर प्रतिरोध ब्लॉक रूपांकनों का विशेष अनुप्रयोग।
(C) सिंथेटिक्स पर आधुनिक ज्यामितीय अमूर्त पैटर्नों को पुनरुत्पादित करने वाली उच्च गति डिजिटल सब्लिमेशन प्रिंटिंग।
(D) गहरे नील (इंडिगो) या मजीठ (मैडर) पृष्ठभूमि पर प्राकृतिक रंगों से छपाई करना।

62. निम्नलिखित में से कौन-सी राजस्थान सरकार द्वारा स्थानीय हस्तशिल्प कारीगरों की सहायता के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली निर्यात प्रोत्साहन योजना या पहल नहीं है?

(A) भू-आबद्ध (लैंडलॉक्ड) परिचालन पारगमन लागत की भरपाई के लिए व्यापक परिवहन और माल ढुलाई सब्सिडी प्रदान करना।
(B) विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए कारीगरों को व्यापक वित्तीय अनुदान प्रदान करना।
(C) विदेशी पर्यटकों के स्थानीय शिल्प गाँवों के भ्रमण पर प्रतिबंध लगाना।
(D) आधुनिक मशीनों से सुसज्जित अत्याधुनिक शिल्प-विशिष्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करना।

NODIA

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs, you are wasting valuable time.

Research shows that learning from **PRINTED BOOKS** has up to **4× HIGHER RETENTION** than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS** move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND** in competition.

In competitive exams, being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

(D) राज्य और केंद्रीय निर्यात संवर्धन परिषदें पंजीकृत निर्यातकों को व्यापक विपणन और संस्थागत सहायता प्रदान करती हैं।

32. वस्त्र निर्यात के संदर्भ में, पारंपरिक "बांधणी" (बंधेज) तकनीक को कपड़ा प्रसंस्करण की किस श्रेणी के अंतर्गत सबसे अच्छी तरह से वर्गीकृत किया गया है?
(A) जैक्वार्ड बुनाई
(B) रोलर प्रिंटिंग
(C) डिजिटल सब्लिमेशन प्रिंटिंग
(D) प्रतिरोध रंगाई

33. राजस्थान में निर्यात अवसंरचना और उसके प्राथमिक कार्य के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए:
(A) अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) - भू-आबद्ध निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क निकासी और कंटेनर माल ढुलाई का प्रबंधन करता है।
(B) राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) - यूरोपीय बाजारों में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का प्रत्यक्ष आयोजन, वित्तपोषण और प्रबंधन करता है।
(C) निर्यात संवर्धन ब्यूरो (ईपीबी) - टेक्सटाइल मिलों के लिए कच्चे कपास की कृषि खेती और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की सीधे निगरानी करता है।
(D) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) - निर्यात मात्रा को जानबूझकर रोकने के लिए अधिकतम वैधानिक शुल्क और प्रतिबंधात्मक नियामक कोटा लगाता है।

34. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में राजस्थान की ब्लू पॉटरी का क्या विशिष्ट स्थान है?
(A) रासायनिक प्रसंस्करण संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले भारी औद्योगिक सिरेमिक
(B) इस्पात गलाने की भट्ठियों के लिए उच्च तापमान वाली फायरक्ले दुर्दम्य ईंटें
(C) सजावटी आंतरिक कलाकृतियाँ और बर्तन
(D) विट्रिफाइड भूमिगत जल निकासी और नगरपालिका सीवरेज पाइप

35. राजस्थानी हस्तशिल्प निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से कम लागत वाली, बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा है।
II. मशीन से बने नकली उत्पाद प्रामाणिक हस्तनिर्मित वस्तुओं के मूल्य को कम करते हैं।
III. उच्च अंतर्देशीय परिवहन समय फास्ट-फैशन अंतर्राष्ट्रीय समय सीमाओं को पूरा करने में चंचलता/सक्रियता को कम करता है।
IV. कारीगरों को जटिल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुपालनों को स्वतंत्र रूप से संभालने में कोई बाधा नहीं आती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

36. भू-आबद्ध (लैंडलॉक्ड) राज्य होने के लॉजिस्टिक्स नुकसान को कम करने के लिए, मुंद्रा और कांडला जैसे समुद्री बंदरगाहों तक कार्गो को सुचारु रूप से पहुँचाने के लिए राजस्थान के संगमरमर और कपड़ा निर्यातकों द्वारा किस महत्वपूर्ण अवसंरचना का उपयोग किया जाता है?
(A) समर्पित क्षेत्रीय घरेलू यात्री हवाई अड्डों का राज्यव्यापी नेटवर्क
(B) इंदिरा गांधी नहर नेटवर्क के साथ नौगम्य औद्योगिक बजरा (बार्ज) मार्ग
(C) आस-पास के राज्य की सीमाओं को जोड़ने वाले सीमा पार हवाई भारी-पेलोड रोप-वे
(D) अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) और माल गलियारे (फ्रेट कॉरिडोर)

37. डिजाइन हस्तक्षेप कार्यक्रम राजस्थानी हस्तशिल्प निर्यात में किस प्रकार सहायता करते हैं, इसका सबसे उपयुक्त वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) इनका उद्देश्य ऐतिहासिक विरासत रुपांकनों को व्यवस्थित रूप से समाप्त करना और उन्हें समकालीन पश्चिमी सौंदर्यशास्त्र पैटर्नों से बदलना है।
(B) वे आधुनिक वैश्विक उपभोक्ता प्राथमिकताओं के अनुकूल पारंपरिक शिल्प कौशलों को ढालने में मदद करते हैं।
(C) वे मुख्य रूप से ग्रामीण हथकरघा बुनाई इकाइयों को बड़े पैमाने की भारी औद्योगिक रासायनिक निर्माण सुविधाओं में परिवर्तित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
(D) वे पारंपरिक शिल्प कारीगरों को अपने पारंपरिक व्यवसायों को छोड़ने और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

38. राजस्थान में प्रमुख पारंपरिक निर्यात-उन्मुख शिल्प क्लस्टरों के संदर्भ में विषम (बेमेल) विकल्प का चयन कीजिए:
(A) जयपुर - रत्न और आभूषण
(B) जोधपुर - काष्ठ हस्तशिल्प
(C) मुरादाबाद - पीतल के बर्तन
(D) भीलवाड़ा - सूटिंग कपड़ा

39. राजस्थान में कपड़ा निर्यात के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: 'सांगानेरी' के रूप में बेचे जाने वाले नकली मशीन-प्रिंटेड कपड़े प्रामाणिक ब्लॉक-प्रिंट कारीगरों की आजीविका को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
कथन II: भौगोलिक संकेतक (जीआई) रजिस्ट्री पंजीकृत क्षेत्रीय शिल्प नामों के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग को दंडित करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करती है।
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

Click Here to Buy book on Flipkart

चिपकने वाले पदार्थों का उपयोग किया गया था।

25. सूची I में जीआई-टैग प्राप्त राजस्थानी निर्यात उत्पादों का सूची II में उनकी विशिष्ट विशेषताओं के साथ मिलान कीजिए।

सूची I: (उत्पाद)

P. सांगानेरी प्रिंट

Q. बगरू प्रिंट

R. कोटा डोरिया

S. ब्लू पॉटरी

सूची II: (प्रमुख विशेषता)

1. सूती-रेशम के मिश्रण में बुने गए विशिष्ट 'खाट' या चौकोर चेक पैटर्न
2. क्वार्ट्ज रेत का उपयोग किया जाता है और प्राकृतिक मिट्टी का उपयोग नहीं होता है
3. आमतौर पर गहरे या प्राकृतिक रंगे हुए पृष्ठभूमि का उपयोग करने वाली ब्लॉक प्रिंटिंग
4. सफेद या हल्की सफेद पृष्ठभूमि पर जीवंत पुष्प पैटर्न के लिए जानी जाने वाली ब्लॉक प्रिंटिंग

(A) P-4, Q-3, R-1, S-2

(B) P-3, Q-4, R-1, S-2

(C) P-4, Q-3, R-2, S-1

(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

26. जयपुर और जोधपुर स्थित निर्यातकों द्वारा अक्सर भाग लिया जाने वाला कौन-सा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पारंपरिक और समकालीन शिल्पों के लिए एशिया के सबसे बड़े बी2बी सोर्सिंग कार्यक्रमों में से एक के रूप में कार्य करता है?

(A) डेफएक्सपो इंडिया

(B) इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट्स फेयर (आईएचजीएफ) दिल्ली मेला

(C) एरो इंडिया शो

(D) इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो (आईआईजेएस)

27. जीआई-टैग प्राप्त राजस्थानी उत्पादों का निर्यात मूल्य रुझान मुख्य रूप से बाजार में प्रीमियम दर (उच्च मूल्य) प्रदर्शित करता है क्योंकि:

(A) जीआई टैग जागरूक खरीदारों के लिए प्रामाणिक विरासत, उत्पत्ति और कारीगरी कौशल को सत्यापित करते हैं।

(B) विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत वैश्विक व्यावसायिक खरीदारों के लिए प्रमाणित वस्तुओं को खरीदना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

(C) आधिकारिक प्रमाणन इस बात की गारंटी देता है कि विनिर्माण लागत पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी युक्त है।

(D) वस्तुओं का खुदरा मूल्य उच्च होता है क्योंकि वे केवल आयातित प्रीमियम कच्चे माल का उपयोग करके निर्मित होती हैं।

28. हस्तशिल्प निर्यात क्लस्टरों में गुणवत्ता मानकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।

कथन (A): राजस्थान के पारंपरिक हस्तशिल्प निर्यात क्लस्टरों के अस्तित्व के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रमाणन को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

कारण (R): अंतर्राष्ट्रीय बाजारों ने पारंपरिक हस्तनिर्मित विविधताओं को समायोजित करने के लिए अपने गुणवत्ता मानकों को सख्ती से कम कर दिया है।

(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

(D) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

29. राजस्थान के प्रसंस्कृत संगमरमर स्लैब और कलात्मक कृतियों का एक मजबूत निर्यात बाजार है। राजस्थान में किस शहर को सबसे बड़े संगमरमर प्रसंस्करण और व्यापारिक क्लस्टर के रूप में सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है, जो इन निर्यातों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है?

(A) फलोदी

(B) माउंट आबू

(C) नीमराणा

(D) किशनगढ़

30. राजस्थान से ग्वार गम के निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. भारत के कुल ग्वार उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 70% से अधिक है, जो इसे एक महत्वपूर्ण निर्यात जिंस (कमोडिटी) बनाता है।

II. ग्वार गम निर्यात को पारंपरिक सांस्कृतिक हस्तशिल्प के तहत सख्ती से वर्गीकृत किया गया है।

III. अमेरिका अपने शेल गैस निष्कर्षण उद्योग के कारण प्रमुख गंतव्य बाजारों में से एक है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?

(A) केवल I और II

(B) केवल II

(C) केवल III

(D) केवल I और III

NODIA

31. राजस्थान के रत्न और आभूषण निर्यात क्षेत्र के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।

(A) जयपुर को पन्ना की सटीक कटाई, पॉलिशिंग और व्यापार गतिविधियों के प्राथमिक केंद्र के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है।

(B) राजस्थान में सक्रिय हीरे की खदानें हैं जो सभी औद्योगिक रत्नों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

(C) घरेलू क्षेत्र लगभग पूरी तरह से पारंपरिक कारीगरों पर निर्भर है जो हाथ से पत्थरों की कटाई और पॉलिशिंग में विशेषज्ञता रखते हैं।

राज्य द्वारा सब्सिडी वाले विलासिता आवासीय आतिथ्य परिसर के रूप में कार्य करना।
(B) कारीगरों को उन्नत मशीनों, परीक्षण प्रयोगशालाओं और डिजाइन उपकरणों तक साझा पहुँच प्रदान करना।
(C) स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादन पर केंद्र सरकार के टैरिफ कर्तव्यों को लागू करने वाले प्रशासनिक कर संग्रह कार्यालय के रूप में कार्य करना।
(D) घरेलू बाजार में खुदरा वितरण से पहले आयातित विदेशी विलासिता की वस्तुओं के भंडारण के लिए एक सुरक्षित बॉन्डेड वेयरहाउस सुविधा के रूप में कार्य करना।

48. राजस्थान में निर्यात संवर्धन योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन (A): राजस्थान की निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी को अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है और बढ़ावा दिया जाता है।
कारण (R): व्यापार मेले पारंपरिक कारीगरों को थोक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के साथ सीधे जुड़ने और वैश्विक बाजार के रुझानों को समझने के लिए महत्वपूर्ण बी2बी मंच प्रदान करते हैं।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

49. राजस्थान के निम्नलिखित पारंपरिक चमड़े के उत्पादों में से कौन-सा हस्तशिल्प निर्यात का एक विशिष्ट लेकिन सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण खंड है?
(A) कढ़ाईदार चमड़े की मोजड़ियां
(B) भारी-भरकम प्रबलित औद्योगिक सुरक्षा हार्नेस
(C) व्यावसायिक श्रेणी के चमड़े के यांत्रिक ट्रांसमिशन बेल्ट
(D) कस्टम सिंथेटिक चमड़े के ऑटोमोबाइल असबाब (अपहोल्स्ट्री) कवर

50. राजस्थान के निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली लॉजिस्टिक्स चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. भू-आबद्ध (लैंडलॉक्ड) होना स्वाभाविक रूप से प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों तक परिवहन समय को बढ़ाता है।
II. अंतर्देशीय माल ढुलाई लागत आमतौर पर संगमरमर और पत्थर जैसे भारी निर्यातों को मूल्य की दृष्टि से कम प्रतिस्पर्धी बनाती है।
III. राजस्थान के व्यापक तटीय बंदरगाह सभी भूमि परिवहन मुद्दों की पूरी तरह से भरपाई करते हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

51. राजस्थानी हस्तशिल्प निर्यात पर ई-कॉमर्स के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?
(A) यह ऑनलाइन बिक्री के लिए भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्राप्त करने को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना देता है।
(B) यह पारंपरिक बिचौलियों पर ग्रामीण कारीगरों की निर्भरता को कम करता है।
(C) इसके लिए डिजिटल साक्षरता और कैटलॉगिंग कौशल की आवश्यकता होती है जिसके लिए सरकारी कौशल हस्तक्षेप आवश्यक है।
(D) यह विशिष्ट पारंपरिक शिल्पों को वैश्विक स्तर पर सूक्ष्म-बाजार (माइक्रो-मार्केट्स) खोजने की अनुमति देता है।

52. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म राजस्थान के एक पारंपरिक निर्यात शिल्प और उसके प्राथमिक कच्चे माल का सही मिलान करता है?
(A) सांगानेरी प्रिंट - उच्च श्रेणी का सिंथेटिक नायलॉन
(B) मोजड़ी - बुना हुआ नारियल जटा और जूट फाइबर
(C) बांधणी (बंधेज) - पॉलिश किया हुआ औद्योगिक प्रसंस्कृत संगमरमर
(D) ब्लू पॉटरी - क्वार्ट्ज और काँच

NODIA

53. विश्व स्तर पर कम लागत वाले, मशीन से निर्मित नकली उत्पादों की चुनौती से निपटने के लिए राजस्थानी कारीगरों के लिए सबसे टिकाऊ भावी निर्यात वृद्धि रणनीति क्या है?
(A) असंगठित अनौपचारिक श्रम के व्यवस्थित शोषण के माध्यम से थोक निर्यात मूल्य संरचनाओं को अत्यधिक कम करना।
(B) जीआई टैग का लाभ उठाना और प्रीमियम विशिष्ट बाजारों में प्रामाणिकता को उजागर करना।
(C) सिंथेटिक वस्तुओं के मशीनीकृत, उच्च-मात्रा वाले कारखाने निर्माण में परिवर्तन के लिए कारीगरी उत्पादन को पूरी तरह से समाप्त करना।
(D) केवल स्थानीय ग्रामीण गाँव के साप्ताहिक बाजारों के भीतर हथकरघा सूची बेचने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालन समाप्त करना।

54. निम्नलिखित वस्तुओं में से बेमेल विकल्प का चयन कीजिए, क्योंकि यह राजस्थान से भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्राप्त उत्पाद का प्रतिनिधित्व नहीं करता है:
(A) बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट
(B) कोटा डोरिया
(C) फुलकारी
(D) सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट

55. राजस्थान की निर्यात प्रोफाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इंजीनियरिंग उत्पाद और वस्त्र राज्य के कुल निर्यात मूल्य का एक बड़ा हिस्सा हैं।
II. जयपुर का रत्न उद्योग मुख्य रूप से घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करता है और इसका कोई निर्यात पदचिह्न

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (A) इंजीनियरिंग वस्तुएं, वस्त्र और हस्तशिल्प
राजस्थान की अर्थव्यवस्था और निर्यात परिदृश्य में विनिर्माण और हस्तशिल्प क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। राज्य से निर्यात होने वाली प्रमुख व्यापक श्रेणियों में इंजीनियरिंग वस्तुएं, वस्त्र तथा हस्तशिल्प शामिल हैं। ये तीन क्षेत्र कुल विनिर्माण और हस्तशिल्प निर्यात का एक बड़ा हिस्सा प्रस्तुत करते हैं। इंजीनियरिंग उद्योग में उपकरण, वस्त्र उद्योग में सूटिंग कपड़े, और हस्तशिल्प में पारंपरिक कलाकृतियां वैश्विक मांग को पूरा करती हैं।

2. (C) पन्ने और रंगीन रत्नों की कटाई एवं पॉलिशिंग
जयपुर को वैश्विक स्तर पर रत्न एवं आभूषणों के केंद्र के रूप में जाना जाता है। विशेष रूप से पन्ने और रंगीन बहुमूल्य रत्नों की कटाई तथा पॉलिशिंग में यहाँ के कारीगरों की विशेषज्ञता अद्वितीय है। ऐतिहासिक रूप से प्राप्त इस पारंपरिक कौशल और व्यावसायिक नेटवर्क के कारण जयपुर का वैश्विक निर्यात बाजार में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह क्षेत्र राज्य के लिए महत्वपूर्ण राजस्व सृजित करता है।

3. (A) सिंथेटिक वर्स्टेड सूटिंग कपड़ा और धागा
राजस्थान का भीलवाड़ा जिला भारत का प्रमुख वस्त्र उत्पादन केंद्र है और इसे वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा ने वैश्विक स्तर पर मुख्य रूप से सिंथेटिक वर्स्टेड सूटिंग कपड़ा और धागा क्षेत्र में एक मजबूत निर्यात उपस्थिति बनाई है। यहाँ स्थापित आधुनिक स्पिनिंग तथा वीविंग इकाइयाँ उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े का निर्माण करती हैं, जिनकी यूरोपीय और एशियाई बाजारों में भारी मांग बनी रहती है।

4. (D) बंधेज (बंधानी)
राजस्थान की पारंपरिक वस्त्र कलाओं में बंधेज या बंधानी का एक प्रमुख स्थान है। यह तकनीक कपड़े को धागे से बांधकर फिर रंगने की एक विशिष्ट प्रतिरोध रंगाई विधि पर आधारित है। इस कला के माध्यम से लहरिया, चुनरी और मोठड़ा जैसे आकर्षक पैटर्न निर्मित किए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय वस्त्र और परिधान बाजार में इस पारंपरिक हस्तशिल्प कला की अत्यधिक मांग है और यह निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

5. (A) P-2, Q-3, R-4, S-1
राजस्थान के विभिन्न शहर अपनी विशिष्ट हस्तशिल्प और औद्योगिक विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध हैं। जयपुर रंगीन रत्नों की कटाई और पॉलिशिंग के लिए जाना जाता है, जबकि जोधपुर में नक्काशीदार लकड़ी के फर्नीचर का निर्माण होता है। भीलवाड़ा जिला सिंथेटिक सूटिंग कपड़े का प्रमुख केंद्र है तथा किशनगढ़ प्रसंस्कृत संगमरमर स्लैब के व्यापार और प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। यह विविधता राज्य की निर्यात क्षमता को मजबूत बनाती है।

6. (C) बेसाल्ट
राजस्थान खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य है, जहाँ से विविध प्रकार के आयामी पत्थरों का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और संगमरमर राज्य के प्राथमिक पत्थर निर्यात क्लस्टरों के मुख्य उत्पाद हैं। इसके विपरीत, बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है, जिसका उपयोग राजस्थान से मुख्य आयामी पत्थर के रूप में नहीं किया जाता है। बलुआ पत्थर तथा संगमरमर वास्तुकला एवं निर्माण उद्योग में प्रसिद्ध हैं।

7. (D) प्राकृतिक मिट्टी (चिकनी मिट्टी)
जयपुर की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी शिल्प कला अपनी अनूठी निर्माण प्रक्रिया के लिए जानी जाती है। पारंपरिक सिरेमिक कलाओं के विपरीत, राजस्थानी ब्लू पॉटरी के आटे की तैयारी में प्राकृतिक मिट्टी या चिकनी मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बजाय, इस मिश्रण में मुख्य रूप से क्वार्ट्ज पाउडर, कच्चा काँच, मुल्तानी मिट्टी, साज्जी और गोंद का उपयोग किया जाता है। यह विशेषता इस कला को विशिष्ट बनाती है।

8. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।
राजस्थान एक भू-आबद्ध राज्य है, जिसकी कोई प्रत्यक्ष समुद्री सीमा नहीं है। इस कारण यहाँ से हस्तशिल्प उत्पादों को निर्यात करने के लिए माल को पहले दूरस्थ तटीय बंदरगाहों या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो तक ले जाना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप गुजरात या महाराष्ट्र जैसे तटीय राज्यों की तुलना में राजस्थानी निर्यातकों को अधिक अंतर्देशीय परिवहन और लॉजिस्टिक्स लागत वहन करनी पड़ती है। अतः कथन और कारण दोनों सत्य हैं।

9. (B) शेल गैस निष्कर्षण में हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग (फ्रैकिंग)
ग्वार गम का उत्पादन मुख्य रूप से राजस्थान में होता है, जो विश्व आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करता है। इसकी वैश्विक मांग का प्राथमिक औद्योगिक कारण शेल गैस और तेल निष्कर्षण में प्रयुक्त हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रक्रिया है। ग्वार गम का उपयोग फ्रैक्चरिंग तरल पदार्थ में चिपचिपापन बढ़ाने और घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग खाद्य और औषधीय उद्योगों में भी होता है।

10. (A) केवल I और II
राजस्थान में निर्मित चमड़े की वस्तुएं पारंपरिक हस्तशिल्प निर्यात का महत्वपूर्ण अंग हैं। कलात्मक कढ़ाई वाली मोजड़ी जूते और चप्पलें सांस्कृतिक पहचान के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पसंद की जाती हैं। जोधपुर और जयपुर इस हस्तशिल्प के प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। यह उद्योग पूरी तरह से पारंपरिक कारीगरों के हस्तकौशल पर आधारित है, न कि भारी स्वचालित

Downloaded from www.pdf.tube

63. राजस्थान में पॉलिश किए गए ग्रेनाइट आयामी पत्थर के निर्यात का प्राथमिक केंद्र, जिसे अक्सर "ग्रेनाइट सिटी" कहा जाता है, कौन-सा है?
(A) बीकानेर
(B) जालौर
(C) अलवर
(D) चूरू

64. राजस्थान के निर्यात के लिए बाजार विविविधता दृष्टिकोणों में आम तौर पर शामिल है:
(A) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बचते हुए पारंपरिक शिल्पों की बिक्री को विशेष रूप से घरेलू स्थानीय बाजारों तक सीमित करना।
(B) बिक्री रणनीति को विशेष रूप से एक ही विदेशी देश पर केंद्रित करने के लिए विदेशी व्यापार गंतव्यों को जानबूझकर कम करना।
(C) राज्य के नियमों के माध्यम से यह अनिवार्य करना कि सभी स्थानीय कारीगर सभी क्लस्टरों में केवल एक ही मानकीकृत वस्तु का उत्पादन करें।
(D) लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप के गैर-पारंपरिक बाजारों में प्रवेश करना।

65. सूची I में दिए गए विशिष्ट राजस्थानी निर्यात उत्पाद का सूची II में उसके प्रमुख संबंधित भौगोलिक क्लस्टर के साथ मिलान कीजिए।
सूची I: (निर्यात उत्पाद)
P. ग्वार गम
Q. पन्ना पॉलिशिंग
R. वर्स्टेड सूटिंग
S. काष्ठ हस्तशिल्प
सूची II: (भौगोलिक क्लस्टर)
1. जयपुर
2. जोधपुर
3. भीलवाड़ा
4. राजस्थान (सामान्य प्रभुत्व/पश्चिमी शुष्क क्षेत्र)
(A) P-4, Q-1, R-3, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-1, S-2
(D) P-3, Q-1, R-2, S-4

66. राजस्थान की हस्तशिल्प निर्यात रणनीति में कौशल प्रमाणन की भूमिका के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) व्यापार संघों द्वारा कौशल प्रमाणन को आधिकारिक तौर पर हतोत्साहित किया जाता है क्योंकि प्रमाणित कारीगर उच्च न्यूनतम मजदूरी की मांग करते हैं।
(B) नियामक कौशल प्रमाणन केवल स्थानीय गाँव की सीमाओं के भीतर व्यावसायिक रूप से बेची जाने वाली हस्तनिर्मित वस्तुओं के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है।
(C) यह वैश्विक खरीदारों को निरंतर गुणवत्ता और नैतिक श्रम मानकों का आश्वासन देता है।
(D) केंद्र सरकार के वैधानिक निकायों ने पारंपरिक शिल्पों के लिए कौशल प्रमाण पत्र जारी करने पर पूरे देश में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

67. कम लागत वाले नकली उत्पादों की उपस्थिति प्रामाणिक राजस्थानी हस्तशिल्प निर्यातों की मूल्य निर्धारण रणनीति को सीधे कैसे प्रभावित करती है?
(A) यह मार्जिन को कम करता है, जिससे प्रीमियम कीमतों को सही ठहराने के लिए जीआई टैग की आवश्यकता होती है।
(B) यह पारंपरिक मास्टर कारीगरों को हस्तशिल्प छोड़ने और सीधे उच्च-मात्रा वाले मशीन निर्माण में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है।
(C) यह शून्य मापने योग्य आर्थिक प्रभाव डालता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खुदरा खरीदार हैंड-ब्लॉक प्रिंट और स्क्रीन प्रिंट के बीच अंतर करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं।
(D) यह ग्रामीण कारीगरों को असली हाथ से तराशी गई विरासत वस्तुओं की तुलना में काफी अधिक बाजार दरों पर बड़े पैमाने पर उत्पादित सिंथेटिक नकल बेचने में सक्षम बनाता है।

68. पारंपरिक कारीगरों के लिए डिजिटल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन (A): डिजिटल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पारंपरिक राजस्थानी कारीगरों के लिए एक अत्यधिक प्रभावी भावी निर्यात वृद्धि रणनीति प्रदान करते हैं।
कारण (R): ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म किसी भी गुणवत्ता जाँच की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, जिससे घटिया सामान आसानी से निर्यात किया जा सकता है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

69. मकराना ऐतिहासिक रूप से किस प्रीमियम आयामी पत्थर (डायमेंशनल स्टोन) के निर्यात के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग स्मारकीय वास्तुकला में प्रमुखता से किया गया है?
(A) गुलाबी ग्रेनाइट
(B) सफेद संगमरमर
(C) लाल बलुआ पत्थर
(D) काला स्लेट

70. राजस्थान में निर्यात सुविधा ढाँचे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद (आरईपीसी) आधुनिक उद्योगों के साथ-साथ पारंपरिक शिल्पों पर भी अत्यधिक ध्यान केंद्रित करती है।
II. वैश्विक प्रदर्शनियों में राज्य द्वारा प्रायोजित भागीदारी का

NODIA

उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बी2बी खरीदारों से जोड़ना है।
III. राजस्थान के निर्यातक राज्य की सीमाओं के भीतर गहरे पानी के समुद्री बंदरगाहों तक प्रत्यक्ष पहुँच का आनंद लेते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

71. राजस्थानी वस्त्रों के निर्यात के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) भीलवाड़ा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के टेक्सटाइल सिटी (वस्त्र नगरी) के रूप में मान्यता प्राप्त है।
(B) बगरू और सांगानेरी जैसे पारंपरिक ब्लॉक प्रिंट की एथनिक फैशन खंडों में मजबूत निर्यात मांग है।
(C) बंधेज (बांधणी) टाई-डाई शिल्पों का निर्यात थान के कपड़े और तैयार परिधान दोनों के रूप में किया जाता है।
(D) भारत के रेडीमेड वस्त्र निर्यात क्षेत्र में राजस्थान का कोई योगदान नहीं है।

72. निम्नलिखित में से कौन-सा एक राजस्थानी हस्तशिल्प का उसके भावी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक मुख्य डिजाइन नवाचार रणनीति के साथ सही युग्म है?
(A) पारंपरिक नक्काशी को आधुनिक न्यूनतम उपयोगिता डिजाइनों के साथ मिलाना।
(B) ब्लू पॉटरी - स्थायित्व बढ़ाने के लिए सीसा (लेड) जैसी भारी धातुओं को शामिल करना।
(C) कोटा डोरिया - सूती और रेशम को पूरी तरह से भारी पॉलिएस्टर से बदलना।
(D) बगरू प्रिंट्स - हैंड-ब्लॉक प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए पूरी तरह से डिजिटल प्रिंटिंग में स्थानांतरित होना।

73. राजस्थान के अनगढ़े बहुमूल्य पत्थरों का प्रमुख प्राथमिक खननकर्ता न होने के बावजूद, जयपुर के रंगीन रत्नों के प्रसंस्करण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) राज्य के वैधानिक नियम सख्ती से यह अनिवार्य करते हैं कि सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयातित अनगढ़े रत्नों का जयपुर के भीतर अनिवार्य प्रसंस्करण होना चाहिए।
(B) सदियों के शाही संरक्षण ने रत्न प्रसंस्करण में एक कुशल कारीगर आधार का निर्माण किया।
(C) जयपुर भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े गहरे पानी के प्राकृतिक समुद्री बंदरगाह की मेजबानी करता है जो विशेष रूप से बिना कटे बहुमूल्य खनिज पत्थरों के आयात के लिए डिज़ाइन किया गया है।
(D) जयपुर विश्व स्तर पर एकमात्र ऐसी नगरपालिका के रूप में विशिष्ट रूप से प्रसिद्ध है जिसके पास स्वचालित लेजर पत्थर-कटाई मशीनरी तक तकनीकी पहुँच है।

74. राजस्थान से प्रमुख निर्यात-उन्मुख औद्योगिक और कृषि वस्तुओं के संदर्भ में बेमेल विकल्प का चयन कीजिए:
(A) ग्वार गम
(B) कच्ची समुद्री मछली
(C) प्रसंस्कृत संगमरमर स्लैब
(D) सिंथेटिक वर्स्टेड धागा

75. राजस्थान के निर्यात के लिए संस्थागत सहायता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. निर्यात संवर्धन ब्यूरो निर्यातक की शिकायतों के निवारण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
II. अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन (जैसे आईएसओ) प्राप्त करने के लिए एमएसएमई को अक्सर वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाता है।
III. विपणन सहायता योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की उपेक्षा करती हैं और केवल राज्य स्तरीय मेलों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
IV. पारंपरिक शिल्प क्लस्टरों की सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा जीआई-पंजीकरण को सक्रिय रूप से सुविधाजनक बनाया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

76. वैश्विक संदर्भ में, कौन-सा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के ग्वार गम व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव) के लिए सबसे बड़ी थोक निर्यात मांग पैदा करता है?
(A) वैश्विक वाणिज्यिक एयरोस्पेस और हल्के समग्र सामग्री क्षेत्र
(B) उच्च सटीकता वाला वैश्विक सेमीकंडक्टर वेफर निर्माण उद्योग
(C) पेट्रोलियम और शेल गैस निष्कर्षण उद्योग
(D) वैश्विक सिंथेटिक रबर और औद्योगिक बहुलक (पॉलिमर) निर्माण क्षेत्र

77. भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग इस बात की गारंटी देता है कि उत्पाद में स्वाभाविक रूप से या उसकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण कुछ विशिष्ट गुण मौजूद हैं।
कथन II: जीआई टैग दुनिया में कहीं भी किसी भी निर्माता को कानूनी रूप से उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति देता है जब तक कि वे डिजाइन की सटीक नकल करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

Click Here to Buy book on Amazon

78. राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन-सा शिल्प क्षेत्र विशिष्ट कारीगरी निर्यात के लिए, व्यावसायिक रूप से प्राप्त लकड़ी के साथ-साथ देशी वृक्ष प्रजातियों "खेजड़ी" और "रोहिड़ा" पर अत्यधिक निर्भर करता है?

(A) ब्लू पॉटरी काँचलेपन (ग्लेज) के लिए रासायनिक कच्चे माल का निर्माण
(B) वस्त्रों के लिए प्राकृतिक जैविक रसायनों का वनस्पति निष्कर्षण
(C) पारंपरिक काष्ठ (लकड़ी) हस्तशिल्प
(D) मोजड़ियों के लिए चमड़े की खाल का पारंपरिक वनस्पति शोधन (टैनिंग)

79. राजस्थानी संगमरमर के निर्यात के संदर्भ में "मूल्य संवर्धन" (वैल्यू एडिशन) शब्द सबसे सटीक रूप से किसे संदर्भित करता है?

(A) द्वितीयक प्रसंस्करण के बिना खुले खदान स्थलों से सीधे कच्चे, बिना गढ़े, बिना कटे संगमरमर ब्लॉक का निर्यात करना।
(B) कच्चे संगमरमर को पॉलिश की गई स्लैब और नक्काशीदार कलाकृतियों में प्रसंस्कृत करना।
(C) अप्रसंस्कृत कच्चे खनिज पत्थर की शिपमेंट पर उच्च प्रशासनिक निर्यात शुल्क और वैधानिक शुल्क लगाना।
(D) फसल की उपज बढ़ाने के लिए संगमरमर के अपशिष्ट धूल को बारीक पीसकर कृषि मृदा बिस्तरों में मिलाना।

80. किसी पारंपरिक राजस्थानी शिल्प के निर्यात मूल्य की रक्षा के लिए कानूनी रूप से भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग सुरक्षित करने में शामिल सामान्य चरणों को व्यवस्थित कीजिए:

1. जीआई रजिस्ट्री द्वारा पूर्व-परीक्षण और विसंगतियों को दूर करना।
2. उत्पादकों के संघ या सरकारी निकाय द्वारा औपचारिक आवेदन दाखिल करना।
3. सार्वजनिक आपत्ति के लिए जीआई जर्नल में प्रकाशन।
4. उत्पत्ति के ऐतिहासिक प्रमाण, विशिष्ट विशेषताओं को एकत्र करना और भौगोलिक क्षेत्र को परिभाषित करना।
5. अंतिम पंजीकरण और जीआई प्रमाण पत्र जारी करना।

(A) 4, 2, 1, 3, 5
(B) 2, 4, 1, 3, 5
(C) 4, 1, 2, 3, 5
(D) 2, 1, 4, 3, 5

NODIA

(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

40. राजस्थान के किसी ग्रामीण कारीगर के लिए अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स निर्यात आदेश को पूरा करने के कालानुक्रमिक चरणों को व्यवस्थित कीजिए:
1. अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय कूरियर या डाक निर्यात नेटवर्क के माध्यम से भेजना।
2. वैश्विक बी2सी डिजिटल मार्केटप्लेस पर हस्तनिर्मित उत्पाद को सूचीबद्ध करना।
3. अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना।
4. डिजिटल कैटलॉगिंग और उच्च गुणवत्ता वाली उत्पाद फोटोग्राफी।

(A) 4, 2, 3, 1
(B) 2, 4, 1, 3
(C) 4, 3, 2, 1
(D) 2, 1, 3, 4

41. राजस्थान से प्रसंस्कृत संगमरमर और आयामी पत्थरों का निर्यात मुख्य रूप से किस वैश्विक उद्योग की जरूरतों को पूरा करता है?
(A) वैश्विक दवा निर्माण क्षेत्र में सक्रिय कच्चे माल का संश्लेषण
(B) अंतर्राष्ट्रीय निर्माण और वास्तुकला क्षेत्र
(C) वैश्विक एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र के भीतर व्यावसायिक संरचनात्मक निर्माण
(D) हाई-टेक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सटीक घटक संयोजन

42. निम्नलिखित में से कौन-सा कारक राजस्थान के ग्वार गम की वैश्विक निर्यात मांग में योगदान नहीं देता है?
(A) खाद्य उद्योग में गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में इसकी उपयोगिता
(B) परमाणु रिएक्टरों के लिए प्राथमिक ईंधन स्रोत के रूप में इसका उपयोग
(C) तेल के कुओं की फ्रैक्चरिंग (फ्रैकिंग) में घर्षण कम करने वाले एजेंट के रूप में इसका उपयोग
(D) सौंदर्य प्रसाधनों में स्थिरीकरण एजेंट के रूप में इसका अनुप्रयोग

43. जोधपुर का भौगोलिक क्लस्टर विश्व स्तर पर मुख्य रूप से निर्मित वस्तुओं की किस विशिष्ट श्रेणी के निर्यात के लिए जाना जाता है?
(A) हस्तनिर्मित लकड़ी के फर्नीचर और लोहे की कलाकृतियाँ
(B) वाणिज्यिक समुद्री जहाजों के लिए विशिष्ट सटीक नेविगेशन उपकरण
(C) प्रयोगशाला में निर्मित सिंथेटिक हीरे और औद्योगिक अपघर्षक क्रिस्टल
(D) भारी-भरकम डीजल कृषि ट्रैक्टर और मशीनीकृत कृषि मशीनरी

44. कोटा डोरिया को कौन-सी विशिष्ट दृश्य विशेषता मिलती है जो हल्के एथनिक परिधानों के निर्यात बाजार में अत्यधिक मूल्यवान है?
(A) केवल शुद्ध धात्विक सोने और चांदी के तारों से की गई जटिल भारी जरदोजी कढ़ाई।
(B) उच्च श्रेणी के शहतूत रेशम के धागों के साथ घने बुने हुए ऊँट के ऊन के मोटे हाथ के कते धागे।
(C) विभिन्न धागे के ग्रिड पैटर्न द्वारा निर्मित चौकोर चेक वाले 'खाट'।
(D) कपड़े की सतह को पूरी तरह से वॉटरप्रूफ बनाने के लिए उस पर लगाई गई जैविक मोम की कई परतें।

45. सूची I में दिए गए संस्थान/अवधारणा का सूची II में राजस्थान के निर्यात में उनकी प्राथमिक भूमिका के साथ मिलान कीजिए।
सूची I: (संस्थान/अवधारणा)
P. आरईपीसी
Q. जीआई टैग
R. आईसीडी
S. ईपीबी

सूची II: (भूमिका)
1. समुद्री बंदरगाहों तक कंटेनरीकृत रेल परिवहन की सुविधा प्रदान करना
2. निर्यातकों का समर्थन करने वाली शीर्ष राज्य स्तरीय परिषद
3. क्षेत्रीय शिल्पों की बौद्धिक संपदा की रक्षा करना
4. एकल-खिड़की सुविधा ब्यूरो के रूप में कार्य करना

(A) P-2, Q-3, R-1, S-4
(B) P-3, Q-2, R-4, S-1
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-2, Q-1, R-3, S-4

46. राजस्थान के कपड़ा निर्यात परिदृश्य के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) राजस्थान केवल अप्रसंस्कृत कच्चे कपास की गांठों का निर्यात करता है और इसमें तैयार परिधान निर्माण इकाइयों का अभाव है।
(B) केंद्र सरकार के कानून के तहत सभी पारंपरिक हथकरघा वस्त्रों के व्यावसायिक निर्यात पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
(C) भीलवाड़ा सिंथेटिक मिश्रित सूटिंग कपड़े के निर्यात का एक प्रमुख केंद्र है।
(D) हल्के कोटा डोरिया बुने हुए कपड़े मुख्य रूप से भारी औद्योगिक तरल निस्पंदन (फ़िल्टर) प्रणालियों के लिए विदेश में निर्यात किए जाते हैं।

47. सरकारी हस्तशिल्प विकास योजनाओं के संदर्भ में, शिल्प क्लस्टरों में स्थापित "कॉमन फैसिलिटी सेंटर" (सीएफसी) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमंडलों और पर्यटकों के लिए

Downloaded from www.pdf.tube

मशीनों पर। इसलिए तीसरा कथन असत्य है जबकि प्रथम दो कथन सही हैं।

11. (A) राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद (आरईपीसी)
राजस्थान में निर्यातकों को संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद (आरईपीसी) का गठन किया गया है। यह राज्य स्तरीय संस्था निर्यातकों की समस्याओं के निवारण, शिकायत समाधान और वैश्विक बाजारों में स्थानीय उत्पादों के प्रचार-प्रसार का कार्य करती है। यह संस्था राज्य से होने वाले निर्यात को बढ़ाने, नई नीतियां लागू करने तथा निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान करती है।

12. (C) मोलेला क्ले वर्क (मूर्तिकला) - बीकानेर
भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग किसी विशेष क्षेत्र के प्रामाणिक उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। राजस्थान में बगरू प्रिंट जयपुर से, कोटा डोरिया कोटा से और थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित जीआई-टैग प्राप्त उत्पाद हैं। मोलेला क्ले वर्क राजसमंद जिले के मोलेला गाँव से संबंधित है, न कि बीकानेर से। अतः मोलेला क्ले वर्क और बीकानेर का युग्म असत्य तथा गलत है।

13. (D) यह प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने के लिए भौगोलिक उत्पत्ति और पारंपरिक तरीकों को कानूनी रूप से प्रमाणित करता है।
सांगानेरी प्रिंट जैसे पारंपरिक राजस्थानी वस्त्रों के लिए भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्राप्त करने से उत्पाद की विशिष्टता और भौगोलिक उत्पत्ति की कानूनी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। यह अनधिकृत नकल और जाली उत्पादों के निर्माण को रोकता है। इसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उत्पाद की विश्वसनीयता बढ़ती है और कारीगरों को उनके पारंपरिक कौशल के लिए प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलती है, जिससे निर्यात बढ़ता है।

14. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
राजस्थान का काष्ठ हस्तशिल्प निर्यात मुख्य रूप से ठोस लकड़ी के हस्तनिर्मित फर्नीचर, प्राचीन कलाकृतियों और नक्काशीदार वस्तुओं पर आधारित है, न कि आधुनिक मॉड्यूलर प्लाईवुड फर्नीचर पर। जोधपुर को ठोस लकड़ी के शीशम और आम की लकड़ी के फर्नीचर तथा प्राचीन प्रतिकृतियों के निर्माण और निर्यात के वैश्विक केंद्र के रूप में पहचाना जाता है। अतः पहला कथन असत्य है और दूसरा कथन पूर्णतः सत्य है।

15. (B) केवल I, III और IV
राजस्थान सरकार की हस्तशिल्प प्रोत्साहन योजनाएं कारीगरों के कल्याण और निर्यात वृद्धि पर केंद्रित हैं। ये योजनाएं अंतरराष्ट्रीय मेलों में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, वैश्विक गुणवत्ता मानकों हेतु कौशल उन्नयन कार्यक्रम चलाती हैं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने में सहायता करती हैं। हालाँकि, मशीन से बने कपड़ों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, इसलिए दूसरा कथन गलत है तथा अन्य कथन सही हैं।

16. (D) स्थानीय फर्मों को सक्रिय निर्यातक बनने के लिए पंजीकृत करना, प्रशिक्षित करना और सहायता प्रदान करना।
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया "निर्यात बनो" मिशन राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्थानीय फर्मों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शामिल करने के लिए लक्षित कार्यक्रम है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य नए और इच्छुक व्यवसायियों को निर्यातक के रूप में पंजीकृत करना, आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना, दस्तावेज प्रक्रिया में मार्गदर्शन देना तथा उन्हें प्रत्यक्ष निर्यात गतिविधियों को शुरू करने में पूरी सहायता प्रदान करना है।

17. (A) निर्यात बिचौलियों को दरकिनार करते हुए प्रत्यक्ष बी2सी (उपभोक्ता को प्रत्यक्ष बिक्री) वैश्विक पहुँच प्रदान करता है।
डिजिटल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने राजस्थान के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग के लिए वैश्विक व्यापार परिदृश्य को बदल दिया है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि ग्रामीण कारीगर और स्थानीय उत्पादक पारंपरिक बिचौलियों या मध्यस्थों को दरकिनार करके सीधे अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं तक पहुँच सकते हैं। यह बी2सी मॉडल कारीगरों के लाभ मार्जिन को बढ़ाता है और वैश्विक बाजार की बदलती प्राथमिकताओं की सीधी जानकारी देता है।

18. (C) उस्ता कला
राजस्थान के वस्त्र शिल्पों में बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट और कोटा डोरिया विश्व प्रसिद्ध कपड़ा-आधारित हस्तशिल्प हैं जिनका व्यापक रूप से निर्यात किया जाता है। इसके विपरीत, उस्ता कला बीकानेर की एक प्रसिद्ध पारंपरिक कला शैली है जिसमें ऊँट की खाल या लकड़ी पर सुनहरी नक्काशी और मुनव्वत का काम किया जाता है। यह वस्त्र या कपड़े पर आधारित शिल्प नहीं है, इसलिए यह भिन्न श्रेणी में आता है।

19. (A) मशीन से बनी सस्ती स्क्रीन-प्रिंटेड प्रतिकृतियों की आवक।
राजस्थान की पारंपरिक ठप्पा छपाई कला को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सबसे बड़ी चुनौती मशीन से बनी सस्ती स्क्रीन-प्रिंटेड और डिजिटल प्रतिकृतियों से मिलती है। ये नकली उत्पाद कम लागत और कम समय में तैयार हो जाते हैं, जिससे वास्तविक हस्तनिर्मित ब्लॉक-प्रिंटेड वस्त्रों के बाजार मूल्य और मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे वास्तविक कारीगरों को प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ता है।

20. (B) 2, 1, 3, 4
राजस्थान में किसी कारीगर उद्यम के लिए औपचारिक निर्यात प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होता है। सर्वप्रथम एक कानूनी व्यावसायिक इकाई का पंजीकरण किया जाता है। इसके पश्चात विदेश व्यापार महानिदेशालय से आयात-निर्यात कोड प्राप्त किया जाता है। फिर संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद की सदस्यता ली जाती है। अंत में अंतरराष्ट्रीय क्रय आदेश प्राप्त करके सीमा शुल्क निकासी के माध्यम से माल भेजा जाता है।

21. (B) गुलाबी बलुआ पत्थर
राजस्थान का बंशी पहाड़पुर क्षेत्र अपने उच्च गुणवत्ता वाले गुलाबी बलुआ पत्थर के खनन और निर्यात के लिए विश्व स्तर

NODIA

42. (B) परमाणु रिएक्टरों के लिए प्राथमिक ईंधन स्रोत के रूप में इसका उपयोग
ग्वार गम एक प्राकृतिक हाइड्रोकोलॉइड है जो ग्वार के बीजों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग खाद्य उद्योग में गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में, शेल तेल निष्कर्षण में फ्रैकिंग द्रव के रूप में तथा सौंदर्य प्रसाधनों में स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इसका कोई उपयोग नहीं है। अतः परमाणु ईंधन वाला विकल्प असत्य है और वैश्विक मांग का कारण नहीं है।

43. (A) हस्तनिर्मित लकड़ी के फर्नीचर और लोहे की कलाकृतियाँ
जोधपुर को विश्व स्तर पर 'हैंडीक्राफ्ट सिटी' के रूप में जाना जाता है। यह क्लस्टर मुख्य रूप से हस्तनिर्मित लकड़ी के फर्नीचर, एंटीक फिनिशिंग वाली वस्तुओं और गढ़े हुए लोहे की कलाकृतियों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बने शीशम और आम की लकड़ी के फर्नीचर तथा सजावटी सामान अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में बड़े पैमाने पर निर्यात किए जाते हैं।

44. (C) विभिन्न धागे के ग्रिड पैटर्न द्वारा निर्मित चौकोर चेक वाले 'खाट'।
कोटा डोरिया राजस्थान का एक प्रसिद्ध जीआई-टैग प्राप्त बुनाई शिल्प है। इसकी सबसे विशिष्ट दृश्य विशेषता इसके कपड़े में दिखने वाली छोटी-छोटी चौकोर जालीदार संरचनाएं हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में 'खाट' कहा जाता है। यह पैटर्न सूती और रेशमी धागों के विशेष ग्रिड संयोजन से बुना जाता है। यह हल्का, पारदर्शी और आरामदायक कपड़ा अंतरराष्ट्रीय एथनिक परिधान बाजार में अत्यधिक पसंद किया जाता है।

45. (A) P-2, Q-3, R-1, S-4
राजस्थान के विभिन्न निर्यात संस्थानों की अपनी विशिष्ट भूमिकाएँ हैं। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद (आरईपीसी) निर्यातकों का समर्थन करने वाली शीर्ष संस्था है। भौगोलिक संकेतक (जीआई) क्षेत्रीय शिल्पों की बौद्धिक संपदा की रक्षा करता है। अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) बंदरगाहों तक रेल परिवहन की सुविधा देता है और निर्यात संवर्धन ब्यूरो (ईपीबी) एकल-खिड़की सुविधा मंच के रूप में कार्य करता है। अतः प्रथम विकल्प सही मिलान प्रदर्शित करता है।

46. (C) भीलवाड़ा सिंथेटिक मिश्रित सूटिंग कपड़े के निर्यात का एक प्रमुख केंद्र है।
राजस्थान में वस्त्र उद्योग अत्यधिक विकसित और विविध है। भीलवाड़ा जिला भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिंथेटिक मिश्रित सूटिंग कपड़े और धागे के निर्माण तथा निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है। राजस्थान केवल कच्चे कपास का निर्यात नहीं करता बल्कि यहाँ तैयार परिधान और पारंपरिक ब्लॉक प्रिंट भी निर्मित होते हैं। अतः भीलवाड़ा से संबंधित कथन पूरी तरह सही है, जबकि अन्य विकल्प गलत हैं।

47. (B) कारीगरों को उन्नत मशीनों, परीक्षण प्रयोगशालाओं और डिजाइन उपकरणों तक साझा पहुँच प्रदान करना।
हस्तशिल्प क्लस्टरों में स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) का मुख्य उद्देश्य छोटे कारीगरों और सूक्ष्म इकाइयों को आधुनिक ढाँचागत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इन केंद्रों में आधुनिक मशीनरी, कच्चे माल के उपचार की सुविधाएं, परीक्षण प्रयोगशालाएं और डिजाइन उपकरण स्थापित किए जाते हैं। साझा पहुँच होने से व्यक्तिगत कारीगरों को भारी निवेश नहीं करना पड़ता और उनके उत्पादों की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो जाती है।

48. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।
राजस्थान सरकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने वाले कारीगरों और निर्यातकों को स्टॉल किराए तथा यात्रा पर वित्तीय सब्सिडी प्रदान करती है। यह सब्सिडी इसलिए दी जाती है क्योंकि ये मेले पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बी2बी खरीदारों से सीधे संवाद करने, नए ऑर्डर प्राप्त करने और वैश्विक फैशन रुझानों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। अतः कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा सही व्याख्या करते हैं।

49. (A) कढ़ाईदार चमड़े की मोजड़ियां
राजस्थान का चमड़ा उद्योग अपने पारंपरिक हस्तशिल्प और सांस्कृतिक उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें रेशम, सूती धागों या ज़री से कढ़ाई की गई चमड़े की मोजड़ियां एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। जयपुर, जोधपुर और जालौर में निर्मित ये मोजड़ियां एथनिक फैशन और सांस्कृतिक उपहारों के रूप में विदेशों में निर्यात की जाती हैं। यह हस्तशिल्प क्षेत्र ग्रामीण कारीगरों को प्रत्यक्ष रोजगार और अंतरराष्ट्रीय पहचान प्रदान करता है।

50. (A) केवल I और II
राजस्थान एक भू-आबद्ध राज्य है, जिसके पास अपना कोई समुद्री बंदरगाह नहीं है। तटीय सीमाओं का अभाव माल को गुजरात या महाराष्ट्र के बंदरगाहों तक भेजने के लिए परिवहन समय और माल ढुलाई लागत को बढ़ा देता है। यह लागत संगमरमर और पत्थर जैसे भारी उत्पादों के लिए विशेष रूप से अधिक होती है। अतः प्रथम और द्वितीय कथन सही हैं, जबकि तटीय बंदरगाहों वाला तृतीय कथन पूरी तरह असत्य है।

51. (A) यह ऑनलाइन बिक्री के लिए भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्राप्त करने को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना देता है।
ई-कॉमर्स ने राजस्थानी हस्तशिल्प के लिए नए वैश्विक अवसर खोले हैं। यह बिचौलियों पर निर्भरता कम करता है और कारीगरों को सीधे विदेशी बाजारों से जोड़ता है। हालाँकि, यह कहना गलत है कि जीआई टैग अप्रासंगिक हो जाता है। वास्तव में, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर खरीदार प्रामाणिकता की तलाश करते हैं, जिससे जीआई टैग की महत्ता और बढ़ जाती है। अतः प्रथम विकल्प गलत कथन है।

Click Here to Buy book on Flipkart

कारीगरों, कटाई विशेषज्ञता और सरकारी तथा संस्थागत सहायता के बल पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती से टिका है।

32. (D) प्रतिरोध रंगाई
राजस्थान की पारंपरिक बांधणी या बंधेज तकनीक कपड़ा प्रसंस्करण की प्रतिरोध रंगाई श्रेणी के अंतर्गत आती है। इस प्रक्रिया में कपड़े के विशिष्ट हिस्सों को धागे से कसकर बांध दिया जाता है ताकि रंग उन हिस्सों में प्रवेश न कर सके। इसके बाद कपड़े को रंगा जाता है, जिससे सुंदर बिंदु और डिजाइन उभरते हैं। यह प्रतिरोध रंगाई विधि अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में एथनिक परिधानों के लिए प्रसिद्ध है।

33. (A) अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) - भू-आबद्ध निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क निकासी और कंटेनर माल ढुलाई का प्रबंधन करता है।
राजस्थान जैसे भू-आबद्ध राज्य के लिए अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) एक महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक सुविधा है। यह स्थल शुष्क बंदरगाह के रूप में कार्य करता है जहाँ सीमा शुल्क जांच, कागजी कार्रवाई और माल का डिब्बों में भंडारण पूरा किया जाता है। इसके बाद माल को सीधे समुद्री बंदरगाहों के लिए रवाना कर दिया जाता है। अन्य विकल्प गलत हैं क्योंकि वे संबंधित संस्थाओं के प्राथमिक कार्यों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते।

34. (C) सजावटी आंतरिक कलाकृतियाँ और बर्तन
जयपुर की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी अनूठी हस्तकला और नीले-सफेद रंग-संयोजन के लिए पहचानी जाती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सजावटी आंतरिक कलाकृतियों, फूलदानों, तश्तरियों, टाइलों और बर्तनों के निर्माण में होता है। यह एक ललित कलात्मक हस्तशिल्प उत्पाद है, न कि भारी औद्योगिक सिरेमिक या सीवरेज पाइप। वैश्विक स्तर पर गृह सज्जा के शौकीन इस कलाकृतियों का बड़े पैमाने पर आयात करते हैं।

35. (A) केवल I, II और III
राजस्थानी हस्तशिल्प निर्यातक वैश्विक स्तर पर सस्ती मशीन-निर्मित वस्तुओं, नकली उत्पादों और उच्च अंतर्देशीय लॉजिस्टिक्स देरी जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण कारीगरों के लिए जटिल अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सीमा शुल्क अनुपालनों को स्वतंत्र रूप से संभालना अत्यधिक कठिन होता है। इसलिए चतुर्थ कथन गलत है कि उन्हें कोई बाधा नहीं आती, जबकि प्रथम, द्वितीय और तृतीय कथन पूर्णतः सत्य हैं।

36. (D) अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) और माल गलियारे (फ्रेट कॉरिडोर)
भू-आबद्ध राज्य होने के कारण राजस्थान से समुद्री बंदरगाहों तक माल पहुँचाना एक चुनौती है। इस दूरी को कम करने और संगमरमर तथा कपड़ों के निर्यात को सुचारू बनाने के लिए राज्य में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और समर्पित माल गलियारों का उपयोग किया जाता है। ये व्यवस्थाएं मुंद्रा और कांडला जैसे गुजरात के बंदरगाहों तक माल को तेजी से और कम लागत में पहुँचाने में मदद करती हैं।

37. (B) वे आधुनिक वैश्विक उपभोक्ता प्राथमिकताओं के अनुकूल पारंपरिक शिल्प कौशलों को ढालने में मदद करते हैं।
डिजाइन हस्तक्षेप कार्यक्रम राजस्थानी हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों के कौशल और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हुए उनके उत्पादों को आधुनिक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की बदलती प्राथमिकताओं और उपयोगिताओं के अनुकूल बनाना है। इससे पारंपरिक शिल्पों में समकालीन सौंदर्यशास्त्र का समावेश होता है, जिससे विदेशी बाजारों में राजस्थानी उत्पादों की मांग और बिक्री में वृद्धि होती है।

38. (C) मुरादाबाद - पीतल के बर्तन
राजस्थान में कई प्रसिद्ध हस्तशिल्प और औद्योगिक क्लस्टर स्थित हैं, जैसे जयपुर में रत्न एवं आभूषण, जोधपुर में काष्ठ हस्तशिल्प और भीलवाड़ा में सिंथेटिक सूटिंग वस्त्र। इसके विपरीत, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, यह राजस्थान का भाग नहीं है। अतः मुरादाबाद का राजस्थान के पारंपरिक क्लस्टरों से संबंध बेमेल और असंगत विकल्प है।

39. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
सांगानेरी प्रिंट्स की नाम पर बेची जाने वाली नकली मशीन-निर्मित वस्तुएं प्रामाणिक हाथ से ब्लॉक-प्रिंटिंग करने वाले पारंपरिक कारीगरों की आय और बाजार हिस्सेदारी को नुकसान पहुँचाती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए भौगोलिक संकेतक (जीआई) रजिस्ट्री एक कानूनी ढांचा प्रदान करती है, जिसके तहत पंजीकृत क्षेत्रीय शिल्प नामों के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अतः दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं।

40. (A) 4, 2, 3, 1
ग्रामीण कारीगर द्वारा अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स निर्यात पूरा करने का सही क्रम इस प्रकार है: सबसे पहले उत्पादों की डिजिटल कैटलॉगिंग और उच्च गुणवत्ता वाली फोटोग्राफी की जाती है। इसके बाद उत्पाद को वैश्विक बी2सी डिजिटल मार्केटप्लेस पर सूचीबद्ध किया जाता है। ग्राहक द्वारा ऑर्डर देने पर भुगतान गेटवे के माध्यम से राशि प्राप्त होती है और अंत में अधिकृत अंतरराष्ट्रीय कूरियर के जरिए शिपमेंट भेजा जाता है।

41. (B) अंतर्राष्ट्रीय निर्माण और वास्तुकला क्षेत्र
राजस्थान से निर्यात होने वाले प्रसंस्कृत संगमरमर, ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर वैश्विक स्तर पर निर्माण और वास्तुकला उद्योग की जरूरतों को पूरा करते हैं। इन आयामी पत्थरों का उपयोग व्यावसायिक इमारतों, महंगे आवासीय परिसरों, स्मारकों और सार्वजनिक स्थलों में फर्श, क्लैडिंग तथा सजावटी संरचनाओं के लिए किया जाता है। मध्य पूर्व, यूरोप और अमेरिका के निर्माण बाजारों में राजस्थानी पत्थरों की सौंदर्य और मजबूती के कारण अत्यधिक मांग रहती है।

Downloaded from www.pdf.tube

अध्याय 21

गरीबी : अवधारणा, प्रकार एवं कारण

1. आर्थिक मापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा "निरपेक्ष निर्धनता" को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है?
   (A) एक ऐसी स्थिति जहाँ किसी व्यक्ति की आय समाज की औसत आय से काफी कम होती है।
   (B) एक ऐसी स्थिति जहाँ किसी व्यक्ति के पास भोजन, आवास और वस्त्र जैसे बुनियादी जीवन स्तर को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आय का अभाव होता है।
   (C) ऐसी स्थिति जहाँ किसी देश में आय असमानता विश्व स्तर पर स्वीकृत गिनी गुणांक की सीमा से अधिक हो जाती है।
   (D) अतिमुद्रास्फीति के कारण जनसंख्या की क्रय शक्ति में निरंतर गिरावट।

2. "सापेक्ष निर्धनता" की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस आर्थिक उपकरण का उपयोग करके सबसे प्रभावी ढंग से मापा जाता है?
   (A) सिरगणन अनुपात
   (B) निर्धनता अंतराल सूचकांक
   (C) बहुआयामी निर्धनता सूचकांक
   (D) लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक

3. तेंदुलकर समिति की कार्यप्रणाली (2009) के अनुसार, निर्धनता रेखा के अनुमान में कौन-सा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था?
   (A) यह कैलोरी-आधारित मानकों से इतर उपभोग बास्केट में स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर व्यय को शामिल करने की ओर स्थानांतरित हुआ।
   (B) इसने निर्धनता अनुमान के आधार को विशेष रूप से न्यूनतम कैलोरी सेवन मानकों पर पुनः स्थानांतरित कर दिया।
   (C) इसने ग्रामीण और शहरी बास्केट के लिए पूरी तरह से अलग उपभोग वस्तुओं की सिफारिश की।
   (D) इसने सभी उपभोग वस्तुओं के लिए विशेष रूप से समान संदर्भ अवधि (URP) का उपयोग किया।

4. रंगराजन समिति (2014) ने निर्धनता अनुमान कार्यप्रणाली में संशोधन किया। वर्ष 2011-12 के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः संशोधित प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय निर्धनता रेखा क्या थी?
   (A) ग्रामीण के लिए 816 रुपये और शहरी के लिए 1000 रुपये
   (B) ग्रामीण के लिए 972 रुपये और शहरी के लिए 1407 रुपये
   (C) ग्रामीण के लिए 1050 रुपये और शहरी के लिए 1250 रुपये
   (D) ग्रामीण के लिए 1200 रुपये और शहरी के लिए 1500 रुपये

5. वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI) तीन प्रमुख आयामों के आधार पर तीव्र बहुआयामी निर्धनता को मापता है। निम्नलिखित में से कौन-सा इन आयामों में से एक नहीं है?
   (A) वित्तीय समावेशन
   (B) स्वास्थ्य
   (C) शिक्षा
   (D) जीवन स्तर

6. भारत में ग्रामीण निर्धनता के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक कारण माना जाता है?
   (A) ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक विनिर्माण उद्योगों का उच्च संकेंद्रण
   (B) अत्यधिक औपचारिक ऋण उपलब्धता जिसके कारण व्यापक रूप से जानबूझकर व्यतिक्रम होता है
   (C) सभी कृषि राज्यों में निर्यात-उन्मुख नकदी फसलों पर अत्यधिक निर्भरता
   (D) कृषि भूमि और उत्पादक परिसंपत्तियों का असमान वितरण

7. निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   I. इसे अर्थशास्त्री राग्नार नर्कसे द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था।
   II. पूर्ति पक्ष पर, कम आय से कम बचत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कम निवेश और तत्पश्चात कम पूंजी निर्माण होता है।
   III. मांग पक्ष पर, उच्च जनसंख्या वृद्धि सीधे क्रय शक्ति को बढ़ाती है, जिससे निर्धनता का जाल टूट जाता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (A) केवल I और II
   (B) केवल II और III
   (C) केवल I और III
   (D) I, II और III

8. भारत में शहरी निर्धनता को काफी हद तक निम्नलिखित में से किस परिघटना द्वारा देखा जाता है?
   (A) व्यापक कृषि संकट जो शहरी निवासियों की रहने की स्थितियों को प्रभावित करता है

NODIA

52. (D) ब्लू पॉटरी - क्वाट्र्ज और काँच
राजस्थान के पारंपरिक शिल्पों में उनकी कच्ची सामग्री का विशेष महत्व है। जयपुर की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी में प्राकृतिक मिट्टी का उपयोग न करके क्वाट्र्ज पाउडर, कच्चा काँच, मुल्तानी मिट्टी और साज्जी का उपयोग किया जाता है। अतः ब्लू पॉटरी और क्वाट्र्ज-काँच का मिलान पूरी तरह सही है। सांगानेरी प्रिंट सूती कपड़े पर होता है और मोजड़ी चमड़े से बनती है, इसलिए अन्य विकल्प गलत हैं।

53. (B) जीआई टैग का लाभ उठाना और प्रीमियम विशिष्ट बाजारों में प्रामाणिकता को उजागर करना।
वैश्विक बाजार में सस्ते, मशीन से बने नकली उत्पादों का मुकाबला करने के लिए राजस्थानी कारीगरों के लिए सबसे प्रभावी रणनीति जीआई टैग का उपयोग करना है। प्रामाणिकता, समृद्ध विरासत और हस्तनिर्मित गुणवत्ता को उजागर करके ये उत्पाद प्रीमियम विशिष्ट बाजारों को आकर्षित कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर कारखानों में परिवर्तन करने के बजाय हस्तकौशल की मौलिकता बनाए रखना ही स्थायी निर्यात वृद्धि का मार्ग है।

54. (C) फुलकारी
राजस्थान के प्रमुख जीआई-टैग प्राप्त उत्पादों में बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, कोटा डोरिया, पॉकरी और थेवा कला शामिल हैं। इसके विपरीत, 'फुलकारी' पंजाब राज्य की एक प्रसिद्ध पारंपरिक कढ़ाई कला है, जिसे पंजाब के अंतर्गत जीआई टैग प्राप्त है। अतः फुलकारी राजस्थान का जीआई-टैग प्राप्त उत्पाद नहीं है और यह दिए गए विकल्पों में से बेमेल उत्तर है।

55. (B) केवल I, III और IV
राजस्थान के कुल निर्यात में इंजीनियरिंग वस्तुएं और वस्त्र महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जोधपुर जैसे शहरों से हस्तनिर्मित लकड़ी के फर्नीचर का भारी निर्यात होता है और राज्य सरकार निर्यात संवर्धन ब्यूरो के माध्यम से इसे सहायता प्रदान करती है। यह कथन असत्य है कि जयपुर का रत्न उद्योग केवल घरेलू बाजार पर केंद्रित है, क्योंकि जयपुर वैश्विक रत्न निर्यात का बड़ा केंद्र है। अतः द्वितीय विकल्प गलत है।

56. (A) शीशम और आम की लकड़ी
जोधपुर के प्रसिद्ध काष्ठ हस्तशिल्प और फर्नीचर उद्योग में पारंपरिक रूप से स्थानीय रूप से उपलब्ध शीशम और आम की लकड़ी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। शीशम अपनी मजबूती, स्थायित्व और सुंदर प्राकृतिक बनावट के लिए जाना जाता है, जबकि आम की लकड़ी नक्काशी और एंटीक फिनिशिंग के लिए उपयुक्त होती है। इन लकड़ियों से बने हस्तनिर्मित फर्नीचर की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारी मांग रहती है।

57. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
वैश्विक बाजार में राजस्थान के हस्तशिल्प क्षेत्र का मुख्य तुलनात्मक लाभ इसकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत, कलात्मक सौंदर्यशास्त्र और पारंपरिक कौशल में निहित है। इसके साथ ही, आधुनिक अंतरराष्ट्रीय खरीदार पर्यावरण अनुकूलता, टिकाऊ निर्माण पद्धतियों और न्यायसंगत व्यापार मानकों के पालन को अत्यधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। राजस्थानी निर्यातक इन मानकों को अपनाकर अपनी वैश्विक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। अतः दोनों कथन सत्य हैं।

58. (B) स्थानीय कारीगरों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सीधे हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्माण करना।
निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) निर्यातकों की सहायता के लिए स्थापित गैर-लाभकारी संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं बाजार की जानकारी साझा करती हैं, आरसीएमसी प्रमाणपत्र जारी करती हैं और खरीदार-विक्रेता बैठकों का आयोजन करती हैं। ईपीसी कभी भी स्वयं व्यावसायिक रूप से वस्तुओं का निर्माण नहीं करती हैं और न ही स्थानीय कारीगरों से प्रतिस्पर्धा करती हैं। अतः स्वयं निर्माण करने वाला कथन ईपीसी का कार्य नहीं है।

59. (A) ग्रामीण क्लस्टरों से विश्वसनीय फर्स्ट-माइल लॉजिस्टिक्स और पार्सल शिपिंग।
डिजिटल ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से राजस्थानी कारीगरों के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों तक पहुँचाने के लिए एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला आवश्यक है। इसमें सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स चुनौती ग्रामीण शिल्प क्लस्टरों से विश्वसनीय 'फर्स्ट-माइल' लॉजिस्टिक्स और पार्सल संग्रह की व्यवस्था करना है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों से समय पर पार्सल पिक-अप और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग हब तक परिवहन सुनिश्चित हो जाए, तो ई-कॉमर्स निर्यात अत्यधिक सफल हो सकता है।

60. (A) 2, 1, 4, 3
जयपुर में रत्न और आभूषण निर्यात की मूल्य संवर्धन श्रृंखला का सही क्रम इस प्रकार है: सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय या घरेलू स्रोतों से कच्चे अनगढ़े रंगीन रत्नों की खरीद की जाती है। इसके बाद कुशल कारीगरों द्वारा पत्थरों की कटाई, पॉलिशिंग और फेसेटिंग की जाती है। फिर तैयार पॉलिश किए गए रत्नों को सोने या चांदी के आभूषणों में जड़ा जाता है और अंत में इनका निर्यात किया जाता है।

61. (D) गहरे नील (इंडिगो) या मजीठ (मैडर) पृष्ठभूमि पर प्राकृतिक रंगों से छपाई करना।
राजस्थान का बगरू प्रिंट अपनी पर्यावरण अनुकूल पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग प्रक्रिया के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी मुख्य पहचान यह है कि इसमें गहरे प्राकृतिक रंगों, जैसे नील से प्राप्त नीले और मजीठ से प्राप्त लाल या काले रंगों का उपयोग किया जाता है। यह छपाई मुख्य रूप से मिट्टी के प्रतिरोध (दाबू) और प्राकृतिक वनस्पति रंगों का उपयोग करके की जाती है, जो इसे विशिष्ट बनाती है।

62. (C) विदेशी पर्यटकों के स्थानीय शिल्प गाँवों के भ्रमण पर प्रतिबंध लगाना।
राजस्थान सरकार हस्तशिल्प और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए परिवहन सब्सिडी प्रदान करती है, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए वित्तीय अनुदान देती है और कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करती है। सरकार कभी भी पर्यटकों के शिल्प गाँवों के भ्रमण पर प्रतिबंध नहीं लगाती, क्योंकि

Click Here to Buy book on Amazon

(C) हाडोती पठार कृषि क्षेत्र (जैसे, कोटा, बूंदी)
(D) दक्षिणी जनजातीय पट्टी (जैसे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर)

16. राजस्थान में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच निर्धनता संबंधी आंकड़े स्पष्ट असमानताएं दिखाते हैं। ऐतिहासिक रूप से, किस सामाजिक समूह ने उच्चतम निर्धनता सिरगणन अनुपात प्रदर्शित किया है?
(A) सामान्य वर्ग
(B) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
(C) अनुसूचित जनजाति (ST)
(D) अनुसूचित जाति (SC)

17. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): निर्धनता और कुपोषण के बीच एक चक्रीय, परस्पर सुदृढ़ संबंध होता है।
कारण (R): निर्धनता पर्याप्त पोषण तक पहुंच को सीमित करती है, जिसके परिणामस्वरूप खराब स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक कमियां होती हैं, जिससे भविष्य की आय की संभावना कम हो जाती है।
उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

18. 2011-12 के लिए तेंदुलकर समिति की कार्यप्रणाली पर आधारित अनुमानों के अनुसार, राजस्थान में अनुमानित निर्धनता अनुपात कितना था?
(A) 21.9 प्रतिशत
(B) 29.5 प्रतिशत
(C) 8.3 प्रतिशत
(D) 14.7 प्रतिशत

19. राष्ट्रीय औसत के साथ राजस्थान की निर्धनता प्रवृत्तियों की तुलना करने पर (2011-12 तेंदुलकर कार्यप्रणाली आंकड़ों के आधार पर), निम्नलिखित में से कौन-सा कथन ऐतिहासिक रूप से सटीक है?
(A) राजस्थान का निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम था।
(B) राजस्थान का निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक था।
(C) राजस्थान और राष्ट्रीय औसत निर्धनता अनुपात बिल्कुल बराबर थे।
(D) भारत के सभी राज्यों में राजस्थान का निर्धनता अनुपात सबसे अधिक था।

20. "निर्धनता का स्त्रीकरण" की अवधारणा यह दर्शाती है कि:
(A) महिलाओं को औपचारिक श्रम बाजारों में तेजी से एकीकृत किया जा रहा है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से घरेलू निर्धनता दरों में निरंतर कमी आ रही है।
(B) मानक राष्ट्रीय निर्धनता माप जानबूझकर महिला-प्रमुख परिवारों में कठिनाई को कम आंकने के लिए उपभोग आंकड़ों में हेरफेर करते हैं।
(C) संरचनात्मक असमानताओं के कारण महिलाएं निर्धनता की असमान रूप से उच्च दरों और गंभीरता का सामना करती हैं।
(D) जन कल्याणकारी नीतियां और निर्धनता उन्मूलन हस्तक्षेप विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जबकि पुरुषों को व्यवस्थित रूप से बाहर रखा गया है।

NODIA

21. निम्नलिखित में से कौन-सा क्षणिक या अस्थायी निर्धनता का एक उदाहरण है?
(A) सूखे के दौरान निर्धनता रेखा से नीचे आने वाला एक छोटा किसान जो अच्छे मानसून में उबर जाता है।
(B) एक भूमिहीन कृषि मजदूर जिसका परिवार तीन पीढ़ियों से स्थायी अंतर-पीढ़ीगत ऋण बंधुआ मजदूरी में फंसा हुआ है।
(C) कानूनी भूमि अधिकारों या उत्पादक पूंजी परिसंपत्तियों के बिना पहाड़ी इलाके में रहने वाले एक अलग-थलग ग्रामीण समुदाय के सदस्य।
(D) एक शहरी झुग्गी निवासी जो स्थायी शारीरिक अक्षमताओं के साथ जी रहा है जो उसे लाभदायक कार्य में भाग लेने से स्थायी रूप से रोकती हैं।

22. सूची I के पदों का सूची II में दिए गए उनके संबंधित विवरणों से मिलान कीजिए:
सूची I: (निर्धनता की अवधारणा)
P. निरपेक्ष निर्धनता
Q. सापेक्ष निर्धनता
R. दीर्घकालिक निर्धनता
S. क्षणिक/अस्थायी निर्धनता
सूची II: (विवरण)
1. किसी जनसंख्या के भीतर आय असमानताओं का आकलन करके मापी जाती है (जैसे, लॉरेंज वक्र)
2. एक निश्चित न्यूनतम उपभोग या आय सीमा के आधार पर मापी जाती है
3. अक्सर आर्थिक झटकों या मौसमी बदलावों के कारण अस्थायी रूप से निर्धनता का अनुभव करना
4. एक लंबी अवधि में निरंतर वंचना की स्थिति में बने रहना
सही कूट का चयन कीजिए:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-2, Q-1, R-3, S-4
(D) P-1, Q-2, R-4, S-3

23. निर्धनता-शिक्षा संबंध का विश्लेषण करने में, निर्धनता ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक उपलब्धि के लिए मुख्य रूप से बाधा के रूप में कैसे कार्य करती है?

73. (B) सदियों के शाही संरक्षण ने रत्न प्रसंस्करण में एक कुशल कारीगर आधार का निर्माण किया।
जयपुर के पास अनगढ़े बहुमूल्य पत्थरों की अपनी खदानें नहीं हैं, फिर भी यह रंगीन रत्नों के प्रसंस्करण का वैश्विक केंद्र है। इसका मुख्य कारण सदियों पुराना शाही संरक्षण है, जिसने जयपुर में कुशल कारीगरों और जौहरियों की पीढ़ियों को आकर्षित और विकसित किया। यह ऐतिहासिक महारत, कटाई-पॉलिशिंग का पारंपरिक ज्ञान और स्थापित वैश्विक व्यापारिक नेटवर्क जयपुर को अंतरराष्ट्रीय रत्न बाजार में अग्रणी बनाए रखता है।

74. (B) कच्ची समुद्री मछली
राजस्थान की निर्यात टोकरी में ग्वार गम, प्रसंस्कृत संगमरमर स्लैब, ग्रेनाइट, काष्ठ हस्तशिल्प और सिंथेटिक वर्स्टेड धागा जैसे प्रमुख औद्योगिक, खनिज और कृषि उत्पाद शामिल हैं। चूंकि राजस्थान एक भू-आबद्ध राज्य है और यहाँ कोई समुद्र तट नहीं है, इसलिए कच्ची समुद्री मछली राज्य से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में शामिल नहीं हो सकती। अतः कच्ची समुद्री मछली एक स्पष्ट बेमेल विकल्प है।

75. (B) केवल I, II और IV
राजस्थान में निर्यात संवर्धन ब्यूरो निर्यातक समस्याओं के समाधान हेतु नोडल एजेंसी है, एमएसएमई को आईएसओ जैसे अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन के लिए अनुदान मिलता है और राज्य जीआई-पंजीकरण को बढ़ावा देता है। तृतीय कथन असत्य है क्योंकि विपणन योजनाएं अंतरराष्ट्रीय मेलों और निर्यात संवर्धन पर विशेष ध्यान देती हैं, न कि केवल स्थानीय मेलों पर। अतः प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ कथन सही हैं।

76. (C) पेट्रोलियम और शेल गैस निष्कर्षण उद्योग
राजस्थान से निर्यात होने वाले ग्वार गम और इसके डेरिवेटिव्स की सबसे बड़ी वैश्विक मांग पेट्रोलियम और शेल गैस निष्कर्षण उद्योग से आती है। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रक्रिया में ग्वार गम का उपयोग घर्षण कम करने वाले और चिपचिपाहट बढ़ाने वाले प्रमुख एजेंट के रूप में किया जाता है। अमेरिका और कनाडा जैसे तेल उत्पादक देश शेल गैस निष्कर्षण के लिए ग्वार गम का भारी आयात करते हैं।

77. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग यह प्रमाणित करता है कि किसी उत्पाद में विशेष गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएं उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति के कारण मौजूद हैं। हालाँकि, यह धारणा गलत है कि कोई भी निर्माता इस नाम का उपयोग कर सकता है। जीआई टैग अनधिकृत निर्माताओं को उस नाम का उपयोग करने से कानूनी रूप से रोकता है, भले ही वे डिजाइन की नकल करें। अतः पहला कथन सही है।

78. (C) पारंपरिक काष्ठ (लकड़ी) हस्तशिल्प
राजस्थान का पारंपरिक काष्ठ हस्तशिल्प उद्योग व्यावसायिक लकड़ियों के साथ-साथ राज्य की देशी वृक्ष प्रजातियों, जैसे खेजड़ी और रोहिड़ा की लकड़ी का उपयोग करता है। रोहिड़ा की लकड़ी अपनी प्राकृतिक बनावट और नक्काशी के अनुकूल होने के कारण कलात्मक वस्तुओं के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। इन स्थानीय लकड़ियों से निर्मित हस्तशिल्प वस्तुएं अपनी सांस्कृतिक पहचान और टिकाऊपन के कारण अंतरराष्ट्रीय निर्यात बाजार में काफी लोकप्रिय हैं।

79. (B) कच्चे संगमरमर को पॉलिश की गई स्लैब और नक्काशीदार कलाकृतियों में प्रसंस्कृत करना।
राजस्थानी संगमरमर के संदर्भ में "मूल्य संवर्धन" का तात्पर्य खदानों से निकले कच्चे, बिना कटे संगमरमर के ब्लॉकों को काटने, तराशने, पॉलिश करने और नक्काशीदार कलाकृतियों में बदलने की प्रक्रिया से है। सीधे कच्चे पत्थर का निर्यात करने के बजाय उसे प्रसंस्कृत स्लैब या मूर्तियों में बदलने से उत्पाद का बाजार मूल्य बहुगुणित हो जाता है, जिससे निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक राजस्व मिलता है।

80. (A) 4, 2, 1, 3, 5
राजस्थान के किसी पारंपरिक शिल्प के लिए जीआई टैग सुरक्षित करने की प्रक्रिया का सही क्रम इस प्रकार है: सर्वप्रथम ऐतिहासिक प्रमाण, अनूठी विशेषताएं और भौगोलिक क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है। इसके बाद उत्पादक संघ द्वारा आवेदन दाखिल किया जाता है। फिर जीआई रजिस्ट्री द्वारा पूर्व-परीक्षण होता है। इसके बाद सार्वजनिक आपत्ति के लिए इसे प्रकाशित किया जाता है और अंत में अंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होता है।

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

पर्यटन से हस्तशिल्प की सीधी बिक्री और प्रचार होता है। अतः पर्यटकों पर प्रतिबंध लगाने वाला विकल्प असत्य है।

63. (B) जालौर
राजस्थान का जालौर जिला अपने विशाल ग्रेनाइट भंडार और अत्याधुनिक प्रसंस्करण उद्योग के लिए पूरे भारत में "ग्रेनाइट सिटी" के नाम से जाना जाता है। यहाँ विभिन्न रंगों और पैटर्न के ग्रेनाइट पत्थरों का निष्कर्षण, काटना और पॉलिशिंग की जाती है। जालौर में प्रसंस्कृत ग्रेनाइट स्लैब और टाइल्स का निर्माण और वास्तुकला क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न देशों में बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है।

64. (D) लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप के गैर-पारंपरिक बाजारों में प्रवेश करना।
राजस्थान की निर्यात रणनीति में बाजार विविधीकरण का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक पश्चिमी बाजारों (जैसे अमेरिका और पश्चिमी यूरोप) पर निर्भरता कम करना है। इसके तहत लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मध्य पूर्व और पूर्वी यूरोप जैसे नए तथा गैर-पारंपरिक उभरते बाजारों में प्रवेश करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे व्यापारिक जोखिम घटता है और राज्य के हस्तशिल्प तथा औद्योगिक उत्पादों के लिए नए खरीदार उपलब्ध होते हैं।

65. (A) P-4, Q-1, R-3, S-2
राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र अपनी विशिष्ट वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ग्वार गम का उत्पादन मुख्य रूप से पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में होता है। पन्ना पॉलिशिंग का मुख्य केंद्र जयपुर है। वर्स्टेड सूटिंग और कपड़ा उद्योग भीलवाड़ा में केंद्रित है, जबकि काष्ठ हस्तशिल्प और फर्नीचर का निर्माण जोधपुर क्लस्टर में होता है। अतः प्रथम विकल्प इन उत्पादों और उनके संबंधित भौगोलिक क्लस्टरों का सही मिलान प्रस्तुत करता है।

66. (C) यह वैश्विक खरीदारों को निरंतर गुणवत्ता और नैतिक श्रम मानकों का आश्वासन देता है।
हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल प्रमाणन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रमाणन अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को यह विश्वास दिलाता है कि उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित हैं और इनमें गुणवत्ता, एकरूपता तथा नैतिक श्रम मानकों का पालन किया गया है। प्रमाणन से उत्पादों की साख बढ़ती है, जिससे कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर दाम मिलते हैं और राज्य के हस्तशिल्प निर्यात को मजबूती प्राप्त होती है।

67. (A) यह मार्जिन को कम करता है, जिससे प्रीमियम कीमतों को सही ठहराने के लिए जीआई टैग की आवश्यकता होती है।
कम लागत वाली मशीन-निर्मित नकली वस्तुओं की उपस्थिति राजस्थानी हस्तशिल्प के बाजार मार्जिन को सीधे प्रभावित करती है। ये नकली उत्पाद कम दामों पर उपलब्ध होते हैं, जिससे असली हस्तनिर्मित सामान की मांग प्रभावित होती है। ऐसे में असली उत्पादों की प्रीमियम कीमतों को सही ठहराने के लिए जीआई टैग और प्रामाणिकता प्रमाणन अनिवार्य हो जाता है, जिससे जागरूक ग्राहक केवल असली हस्तशिल्प ही खरीदें।

68. (C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
डिजिटल ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म राजस्थानी कारीगरों के लिए वैश्विक बाजारों तक सीधे पहुँचने का एक उत्कृष्ट माध्यम प्रदान करते हैं, जिससे निर्यात बढ़ाने में मदद मिलती है। हालाँकि, यह कहना पूरी तरह गलत है कि ई-कॉमर्स में गुणवत्ता जाँच की आवश्यकता खत्म हो जाती है। वास्तव में, अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर बिक्री के लिए कड़े गुणवत्ता नियंत्रण और ग्राहक संतुष्टि मानकों का पालन करना अनिवार्य होता है।

69. (B) सफेद संगमरमर
राजस्थान के नागौर जिले में स्थित मकराना अपने सर्वोच्च गुणवत्ता वाले सफेद संगमरमर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। मकराना संगमरमर अपनी चमक, शुद्धता और दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक ताजमहल और कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल जैसी विश्व प्रसिद्ध वास्तुकला में इसी संगमरमर का उपयोग किया गया था। आज भी इसका निर्यात कई देशों में उच्च स्तरीय निर्माण और मूर्तिकला के लिए होता है।

70. (A) केवल I और II
राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद (आरईपीसी) राज्य के पारंपरिक हस्तशिल्प और आधुनिक उद्योगों दोनों के निर्यात को बढ़ावा देती है। अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को विदेशी बी2बी खरीदारों से जोड़ना है। हालाँकि, तृतीय कथन गलत है क्योंकि राजस्थान एक भू-आबद्ध राज्य है और इसके पास कोई प्रत्यक्ष समुद्री बंदरगाह नहीं है। अतः केवल प्रथम और द्वितीय कथन सही हैं।

71. (D) भारत के रेडीमेड वस्त्र निर्यात क्षेत्र में राजस्थान का कोई योगदान नहीं है।
राजस्थान का वस्त्र उद्योग राज्य के निर्यात का एक प्रमुख स्तंभ है। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, जबकि बगरू, सांगानेरी और बंधेज शिल्पों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी मांग है। राजस्थान का रेडीमेड वस्त्रों और परिधानों के भारत के कुल निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए यह कथन पूरी तरह असत्य है कि राजस्थान का रेडीमेड वस्त्र निर्यात में कोई योगदान नहीं है।

72. (A) पारंपरिक नक्काशी को आधुनिक न्यूनतम उपयोगिता डिजाइनों के साथ मिलाना।
राजस्थानी हस्तशिल्प के भावी निर्यात को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति पारंपरिक कलात्मक कौशल को आधुनिक न्यूनतम उपयोगितावादी डिजाइनों के साथ जोड़ना है। अंतरराष्ट्रीय खरीदार ऐसे उत्पाद पसंद करते हैं जो सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हों लेकिन आधुनिक घरों और उपयोगिताओं के अनुकूल हों। इस प्रकार का डिजाइन नवाचार पारंपरिक पहचान को खोए बिना राजस्थानी शिल्पों की वैश्विक अपील को काफी बढ़ा देता है।

NODIA

(B) प्रमुख प्रथम श्रेणी के शहरों में औपचारिक सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों की पूर्ण अनुपलब्धता
(C) शहरी झुग्गी-झोपड़ियों का प्रसार और अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार पर भारी निर्भरता
(D) देश भर में ग्रामीण-से-शहरी प्रवास पर प्रतिबंध लगाने वाली एक सख्त सरकारी नीति

9. प्रच्छन्न बेरोजगारी भारतीय कृषि क्षेत्र में निर्धनता का एक प्रमुख कारक है। इस पद का क्या अर्थ है?
(A) शिक्षित कार्यकर्ता जो सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करते हैं लेकिन उपयुक्त औपचारिक नौकरियां पाने में असमर्थ हैं
(B) वे व्यक्ति जो कम वेतन वाली नौकरियों में कार्यरत हैं जो उनके कौशल समूह का पूरी तरह से उपयोग करने में विफल रहते हैं
(C) रोजगार के अवसर जो विशेष रूप से वर्ष के विशिष्ट मौसमी महीनों के दौरान उपलब्ध होते हैं
(D) ऐसी स्थिति जहाँ आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हुए हैं, जिससे शून्य सीमांत उत्पादकता प्राप्त होती है

10. निम्न कृषि उत्पादकता ग्रामीण निर्धनता के बने रहने में किस प्रकार प्रत्यक्ष योगदान देती है?
(A) यह विपणन योग्य अधिशेष को घटाती है, जिससे कृषि आय कम होती है और कृषि मजदूरी में गिरावट आती है।
(B) यह छोटे ग्रामीण भूस्वामियों को लगातार महंगी भारी मशीनरी आयात करने के लिए मजबूर करती है, जिससे गंभीर ऋण संकट पैदा होता है।
(C) यह निर्मित औद्योगिक वस्तुओं के लिए ग्रामीण उपभोक्ता मांग को कृत्रिम रूप से बढ़ाती है, जिससे स्थानीय बचत तेजी से समाप्त हो जाती है।
(D) यह पूरे ग्रामीण श्रम बल के शहरी तृतीयक क्षेत्र में तत्काल और व्यापक विस्थापन का कारण बनती है।

11. शुष्कता राजस्थान में निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य में शुष्कता से उत्पन्न निर्धनता तंत्र का सटीक वर्णन करता है?
(A) अत्यधिक शुष्कता महत्वपूर्ण भूमिगत खनिज भंडारों के निष्कर्षण को स्थायी रूप से सीमित करती है, जिससे राज्य सरकार प्रमुख औद्योगिक राजस्व से वंचित हो जाती है।
(B) कम वर्षा और अत्यधिक गर्मी के कारण बार-बार फसलें खराब होती हैं और पशुधन की मृत्यु होती है, जिससे कृषि आय अस्थिर हो जाती है।
(C) तीव्र मरुस्थलीकरण कृषि भूमि के बाजार मूल्य को कृत्रिम रूप से बढ़ाता है, जिससे संसाधन-विहीन सीमांत किसानों को कृषि योग्य जोतें प्राप्त करने से रोका जा सके।
(D) कठोर शुष्क जलवायवीय परिस्थितियां पूरे पश्चिमी राजस्थान में एक सतत पर्यटन क्षेत्र के विकास और वृद्धि को पूरी तरह से रोकती हैं।

12. भारत में निर्धनता अनुमान समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. लकड़ावाला समिति ने CPI-AL और CPI-IW के आधार पर राज्य-विशिष्ट निर्धनता रेखाओं की सिफारिश की।
II. तेंदुलकर समिति ने अपने अनुमानों के लिए मिश्रित संदर्भ अवधि (MRP) का उपयोग किया।
III. रंगराजन समिति पूरी तरह से समान संदर्भ अवधि (URP) पर वापस लौट आई।
IV. अलघ कार्यदल (1979) ने केवल कैलोरी की न्यूनतम पोषण संबंधी आवश्यकता के आधार पर निर्धनता रेखाओं को परिभाषित किया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(A) I, II और III
(B) I, II और IV
(C) II, III और IV
(D) I, III और IV

13. राजस्थान में सीमित औद्योगीकरण निर्धनता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मुख्य कारण क्या है कि यह समष्टि आर्थिक विशेषता निर्धनता को बढ़ाती है?
(A) यह अधिशेष कृषि श्रम के लिए गैर-कृषि रोजगार के सृजन को सीमित करता है, जिससे उच्च कृषि निर्भरता बनी रहती है।
(B) यह मेल खाते रोजगार अवसरों के बिना अत्यधिक प्रशिक्षित तकनीकी और इंजीनियरिंग कार्यकर्ताओं का एक अभूतपूर्व संरचनात्मक अधिशेष पैदा करता है।
(C) यह क्षेत्रीय अधिकारियों और राज्य प्रशासनों को पड़ोसी कृषि राज्यों से आवश्यक खाद्य फसलों के आयात पर पूरी तरह से निर्भर होने के लिए मजबूर करता है।
(D) यह पारंपरिक ग्रामीण हस्तशिल्प और कारीगर हथकरघा क्षेत्रों के लिए वाणिज्यिक बाजार मांग और विकास की संभावनाओं को व्यवस्थित रूप से नष्ट करता है।

14. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में निर्धनता अनुमान समितियों का उनके गठन के वर्ष के आधार पर सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाता है?
(A) वाई. के. अलघ कार्यदल, लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति
(B) लकड़ावाला समिति, वाई. के. अलघ कार्यदल, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति
(C) वाई. के. अलघ कार्यदल, तेंदुलकर समिति, लकड़ावाला समिति, रंगराजन समिति
(D) तेंदुलकर समिति, वाई. के. अलघ कार्यदल, लकड़ावाला समिति, रंगराजन समिति

15. राजस्थान के भीतर निर्धनता में क्षेत्रीय विषमताएं भली-भांति प्रलेखित हैं। पहाड़ी इलाके, छोटी जोत और ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर होने के कारण आमतौर पर किस क्षेत्र में दीर्घकालिक निर्धनता की उच्च घटनाएं दिखाई देती हैं?
(A) पूर्वी मैदानी संरचनात्मक पट्टी (जैसे, जयपुर, भरतपुर)
(B) पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र (जैसे, जैसलमेर, बीकानेर)

Click Here to Buy book on Flipkart

पर प्रसिद्ध है। यह आयामी पत्थर अपनी स्थायित्व, नक्काशी की सुगमता और सौंदर्य अपील के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक इमारतों, महलों तथा आधुनिक स्मारकीय वास्तुकला, जैसे अयोध्या के श्री राम मंदिर, में इसी बंशी पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग प्रमुखता से किया गया है।

22. (C) मात्रा को सीमित करने के लिए पारंपरिक शिल्पों पर भारी राज्य निर्यात शुल्क लगाना।
राजस्थान सरकार हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई सकारात्मक नीतियां अपनाती है। इनमें नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विविधता लाना, समकालीन फैशन के अनुसार डिजाइन नवाचार को प्रोत्साहन देना और कारीगरों के लिए कौशल प्रमाणन कार्यक्रम संचालित करना शामिल है। राज्य द्वारा निर्यात मात्रा को सीमित करने या भारी शुल्क लगाने जैसी कोई नीति नहीं अपनाई जाती, क्योंकि इसका उद्देश्य निर्यात को घटाना नहीं बल्कि बढ़ाना है।

23. (D) निर्यातक मुद्दों को हल करने के लिए एकल-खिड़की (सिंगल-विंडो) नोड के रूप में कार्य करना।
राजस्थान में निर्यात संवर्धन ब्यूरो (ईपीबी) राज्य स्तर पर निर्यात को प्रोत्साहन देने वाली मुख्य एजेंसी है। इसका प्राथमिक कार्य निर्यातकों के सामने आने वाली प्रशासनिक, लॉजिस्टिक्स और नीतिगत समस्याओं को दूर करने के लिए एक एकल-खिड़की सुविधा मंच के रूप में कार्य करना है। यह ब्यूरो अंतर-विभागीय समन्वय बनाकर व्यापारिक बाधाओं को सुलझाता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों का आयोजन करके निर्यातकों को अवसर प्रदान करता है।

24. (A) कानूनी लकड़ी सोर्सिंग, टिकाऊ वानिकी और लकड़ी के उपचार का प्रमाण।
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ने के कारण राजस्थानी लकड़ी के हस्तशिल्प निर्यातकों से सख्त गुणवत्ता मानकों की मांग की जा रही है। वैश्विक खरीदार अब वैधानिक रूप से प्रमाणित टिकाऊ वानिकी, कानूनी लकड़ी की खरीद और उचित कवक-नाशक लकड़ी उपचार का प्रमाण मांगते हैं। इन नियमों का पालन करने से ही राजस्थानी फर्नीचर और काष्ठ शिल्पों को विकसित देशों के बाजारों में प्रवेश मिलता है।

25. (A) P-4, Q-3, R-1, S-2
राजस्थान के जीआई-टैग प्राप्त उत्पादों की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। सांगानेरी प्रिंट सफेद या हल्की पृष्ठभूमि पर जीवंत पुष्प पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है, जबकि बगरू प्रिंट प्राकृतिक रंगों और गहरे बैकग्राउंड का उपयोग करता है। कोटा डोरिया अपनी 'खाट' या चौकोर चेक वाली सूती-रेशम बुनाई के लिए जाना जाता है। वहीं ब्लू पॉटरी में प्राकृतिक मिट्टी के स्थान पर क्वार्ट्ज रेत और काँच का उपयोग किया जाता है।

26. (B) इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट्स फेयर (आईएचजीएफ) दिल्ली मेला
इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट्स फेयर दिल्ली मेला एशिया के सबसे बड़े बिजनेस-टू-बिजनेस सोर्सिंग सम्मेलनों में से एक है। जयपुर और जोधपुर के हस्तशिल्प तथा फर्नीचर निर्यातक इस मेले में बड़े पैमाने पर भाग लेते हैं। यह मंच राजस्थानी कारीगरों और व्यवसायियों को दुनिया भर के थोक खरीदारों, आयातकों और खुदरा श्रृंखलाओं से जोड़ता है, जिससे राज्य के हस्तशिल्प निर्यात को भारी बढ़ावा मिलता है।

27. (A) जीआई टैग जागरूक खरीदारों के लिए प्रामाणिक विरासत, उत्पत्ति और कारीगरी कौशल को सत्यापित करते हैं।
राजस्थान के भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्राप्त उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उच्च मूल्य प्राप्त होता है। जीआई प्रमाणन वैश्विक खरीदारों को यह गारंटी देता है कि उत्पाद एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पारंपरिक तकनीकों और प्रामाणिक कारीगरी द्वारा निर्मित हुआ है। यह प्रामाणिकता ग्राहकों में विश्वास पैदा करती है, जिससे वे नकली या मशीन से बने सामान की तुलना में हस्तनिर्मित विरासत उत्पादों के लिए प्रीमियम दरें देते हैं।

28. (C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
राजस्थान के हस्तशिल्प निर्यात क्लस्टरों के वैश्विक अस्तित्व के लिए उच्च गुणवत्ता और कौशल प्रमाणन बनाए रखना अनिवार्य है, जिससे उत्पादों की विश्वसनीयता बनी रहे। हालाँकि, यह धारणा पूरी तरह गलत है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों ने मानक कम कर दिए हैं। वास्तव में, अंतरराष्ट्रीय खरीदार गुणवत्ता, पर्यावरण अनुकूलता और श्रम मानकों पर अधिक सख्त नियम लागू कर रहे हैं। अतः पहला कथन सही और कारण गलत है।

29. (D) किशनगढ़
राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित किशनगढ़ को भारत और विश्व के सबसे बड़े संगमरमर प्रसंस्करण और व्यापारिक क्लस्टरों में से एक माना जाता है। यहाँ अत्याधुनिक कटाई, गढाई और पॉलिशिंग इकाइयाँ स्थापित हैं। किशनगढ़ विभिन्न प्रकार के संगमरमर स्लैब, टाइल्स और कलात्मक वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र है। यह शहर राजस्थान से प्रसंस्कृत संगमरमर के बड़े पैमाने पर होने वाले निर्यात को संचालित करता है।

30. (B) केवल II
भारत के कुल ग्वार उत्पादन में राजस्थान का योगदान 70% से अधिक है, जो इसे एक प्रमुख कृषि-निर्यात वस्तु बनाता है। अमेरिका जैसे देश शेल गैस निष्कर्षण के लिए इसका भारी मात्रा में आयात करते हैं। हालाँकि, ग्वार गम एक औद्योगिक और कृषि प्रसंस्कृत उत्पाद है, इसे सांस्कृतिक हस्तशिल्प के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसलिए केवल द्वितीय कथन असत्य है, जबकि प्रथम और तृतीय कथन सत्य हैं।

31. (B) राजस्थान में सक्रिय हीरे की खदानें हैं जो सभी औद्योगिक रत्नों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।
जयपुर विश्व में पन्ना कटाई और रंगीन रत्नों के प्रसंस्करण का अग्रणी केंद्र है। यहाँ का उद्योग मुख्य रूप से विदेशी देशों से आयातित कच्चे बहुमूल्य पत्थरों की तराशने पर आधारित है। राजस्थान में व्यावसायिक रूप से सक्रिय हीरे की खदानें नहीं हैं, अतः यह कथन असत्य है। राज्य का रत्न उद्योग कुशल

NODIA

(A) यह संवैधानिक कानूनों के तहत कम आय वाले ग्रामीण परिवारों के बच्चों को सार्वजनिक प्राथमिक स्कूलों में नामांकन प्राप्त करने से कानूनी रूप से रोकती है।
(B) यह शिक्षा की अवसर लागत को बढ़ाती है, जिससे निर्धन बच्चे बाल श्रम या घरेलू कामों में लग जाते हैं।
(C) यह निर्धन परिवारों को बुनियादी प्राथमिक स्कूली शिक्षा की उपेक्षा करते हुए महंगी तृतीयक और उच्च शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर करती है।
(D) निर्धन परिवार सार्वभौमिक रूप से निजी शुल्क-भुगतान करने वाले संस्थानों को चुनते हैं, जिससे स्वचालित रूप से राज्य कल्याण और शिक्षा अनुदान के लिए पात्रता खो जाती है।

24. भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए:
I. बिहार
II. केरल
III. राजस्थान
IV. उत्तर प्रदेश
राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर इन राज्यों को उनके बहुआयामी निर्धनता सिरगणन अनुपात के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन-सा सही अनुक्रम प्रस्तुत करता है?
(A) I, IV, III, II
(B) IV, I, III, II
(C) I, III, IV, II
(D) III, I, IV, II

25. भारत में निर्धनता मापन सुधार के आसपास चल रही बहसें अक्सर पुराने, पूरी तरह से कैलोरी-आधारित दृष्टिकोण की आलोचना करती हैं। इस दृष्टिकोण की प्राथमिक आलोचना क्या है?
(A) यह औपचारिक शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा जैसी महत्वपूर्ण गैर-खाद्य सेवाओं पर घरेलू खर्च का व्यवस्थित रूप से अतिआकलन करता है।
(B) यह शहरी महानगरीय क्षेत्रों के लिए मौद्रिक निर्धनता रेखाएं तैयार करने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण घरेलू खर्च के व्यवहार पर निर्भर करता है।
(C) यह कृत्रिम रूप से आधार रेखा सीमा को अत्यधिक उच्च निर्धारित करता है, जिससे मध्यम आय वाले परिवारों के विशाल बहुमत को गलत तरीके से निर्धन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
(D) यह आवश्यक गैर-खाद्य आवश्यकताओं और जीवन यापन की लागत में क्षेत्रीय अंतरों की उपेक्षा करता है।

26. भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में कम पूंजी निर्माण का एक नकारात्मक समष्टि आर्थिक परिणाम निम्नलिखित में से किसे माना जाता है?
(A) यह तकनीकी प्रगति को दबाता है और नए रोजगार सृजन को सीमित करता है।
(B) यह सभी सामाजिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनसांख्यिकी विकास दरों में तीव्र और स्थायी कमी का सीधा कारण बनता है।
(C) यह एक प्रमुख आर्थिक अधिशेष उत्पन्न करता है जिसके परिणामस्वरूप आधुनिक भौतिक बुनियादी ढांचे की अतिप्रचुरता होती है।
(D) यह अकुशल औद्योगिक श्रमिकों को दिए जाने वाले वास्तविक वेतन में तत्काल, पर्याप्त और निरंतर वृद्धि का कारण बनता है।

27. निर्धनता की अवधारणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वैश्विक स्तर पर किसी व्यक्ति को अत्यधिक निर्धनता में रहने वाला माना जाता है यदि वह प्रतिदिन $2.15 से कम पर जीवन यापन करता है (विश्व बैंक मानक)।
II. सापेक्ष निर्धनता केवल विकासशील देशों में प्रचलित है और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मौजूद नहीं है।
III. सिरगणन अनुपात उस जनसंख्या के अनुपात को मापता है जो निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

28. "मंथन निर्धन" की अवधारणा निर्धनता की किस व्यापक श्रेणी के अंतर्गत आती है?
(A) दीर्घकालिक निर्धनता
(B) क्षणिक/अस्थायी निर्धनता
(C) निरपेक्ष निर्धनता
(D) अत्यधिक निर्धनता

NODIA

29. तेंदुलकर समिति द्वारा अपनाई गई मिश्रित संदर्भ अवधि (MRP) की प्रमुख विशेषता क्या थी?
(A) इसने पांच गैर-खाद्य वस्तुओं के लिए 365-दिन की स्मरण अवधि और शेष के लिए 30-दिन की स्मरण अवधि का उपयोग किया।
(B) इसने सभी दैनिक खाद्य व्यय और गैर-खाद्य उपभोग्य वस्तुओं के लिए एक समान 30-दिन की स्मरण अवधि लागू की।
(C) इसने खाद्य तेलों, मांस और ताजा सब्जियों सहित खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के लिए विशेष रूप से 7-दिन की छोटी स्मरण अवधि लागू की।
(D) इसने आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लिए 365-दिन की स्मरण संरचना लागू की जबकि घरेलू टिकाऊ वस्तुओं के लिए 30-दिन की स्मरण अवधि तय की।

30. निर्धनता के अंतर-पीढ़ीगत संचरण के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा सक्रिय तंत्र को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है?
(A) माता-पिता की पीढ़ियों से संतानों को संचित निजी वित्तीय परिसंपत्तियों और अचल संपत्ति धन का कानूनी और निर्बाध हस्तांतरण।

पर निर्भर हाशिये पर स्थित अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (ST/SC) समूह।
(C) आधुनिक तकनीक-सक्षम ग्रामीण प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्थाओं में सक्रिय रूप से कार्यरत तकनीकी प्रवासी मजदूर।
(D) क्षेत्रीय ग्रामीण प्रशासनिक मुख्यालयों में स्थायी रूप से तैनात स्थायी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारी।

45. राजस्थान के कृषि क्षेत्र में निर्धनता का स्त्रीकरण आमतौर पर किस रूप में प्रकट होता है?
(A) पुरुषों के प्रवास के कारण महिलाएं अधिक कृषि कार्य करती हैं, लेकिन उनके पास भूमि अधिकारों और ऋण तक पहुंच का अभाव होता है।
(B) वैधानिक कानूनी संहिताएं स्पष्ट रूप से महिला गृह प्रमुखों को प्राथमिक कृषि भूस्वामी के रूप में नामित करती हैं।
(C) ग्रामीण महिलाएं खेती में भागीदारी से व्यवस्थित रूप से इनकार करती हैं, जिससे व्यापक कृषि श्रम की कमी होती है।
(D) सार्वजनिक रोजगार नीतियां पुरुष समकक्षों की तुलना में महिला कृषि श्रमिकों के लिए उच्च न्यूनतम मजदूरी को अनिवार्य बनाती हैं।

46. राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक ढांचे के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा संकेतक सख्ती से 'स्वास्थ्य' आयाम के तहत वर्गीकृत है?
(A) विद्यालय उपस्थिति
(B) पीने का पानी
(C) मातृ स्वास्थ्य
(D) बैंक खाता स्वामित्व

47. निर्धनता-कुपोषण संबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. निर्धनता पोषक तत्वों से भरपूर भोजन खरीदने की परिवार की क्षमता को सीमित करती है।
II. कुपोषण बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ती है और परिवार कर्ज में डूब जाते हैं।
III. कुपोषण के कारण होने वाली पुरानी बीमारी श्रम उत्पादकता को कम करती है, जिससे निर्धनता और गहरी हो जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

48. तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक समान अखिल भारतीय निर्धनता रेखा बास्केट की सिफारिश की। इसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच जीवन यापन की विभिन्न लागतों को कैसे ध्यान में रखा?
(A) क्षेत्रीय लागत भिन्नताओं की उपेक्षा करके और देश भर में एक एकल मौद्रिक सीमा लागू करके।
(B) आंकड़ा प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करने के लिए शहरी नगरपालिकाओं में ग्रामीण व्यय आधार रेखाएं लागू करके।
(C) अलग-अलग ग्रामीण और शहरी मौद्रिक रेखाएँ निर्धारित करने के लिए स्थानिक मूल्य सूचकांकों का उपयोग करके।
(D) शहरी व्यय आधार रेखा निर्धारित करने के लिए स्थिर विदेशी मुद्रा परिवर्तन अनुपातों को अपनाकर।

49. निम्नलिखित में से कौन-सा समष्टि अर्थशास्त्र नीति दृष्टिकोण सीधे पूर्ति पक्ष पर "निर्धनता के दुष्चक्र" के मूल कारण को संबोधित करता है?
(A) देश भर में घरेलू उपभोक्ता व्यय को दबाने के लिए कृत्रिम रूप से वैधानिक सीमाएं लागू करना।
(B) उत्पादक पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बचत और ऋण पहुंच को बढ़ावा देना।
(C) वाणिज्यिक व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च स्तरीय विदेशी विलासिता की वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात का विस्तार करना।
(D) वैधानिक मजदूरी और काम करने की स्थिति की आवश्यकताओं को हटाने के लिए अनौपचारिक श्रम बाजारों का विनियमन समाप्त करना।

50. भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षणों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का भारी उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है?
(A) राज्य-स्तरीय सकल घरेलू उत्पाद मेट्रिक्स के अत्यधिक सटीक सांख्यिकीय अनुमान उत्पन्न करना।
(B) जनसांख्यिकीय क्षेत्रों में कुल सकल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति व्यय को मापना।
(C) ग्रामीण जिलों में बेरोजगार तृतीयक शिक्षा स्नातकों की कुल निरपेक्ष संख्या का निर्धारण करना।
(D) राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की गणना के लिए प्रमुख संकेतकों को प्राप्त करना।

51. निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर भारत में शहरी निर्धनता के प्रमुख कारण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है?
(A) कृषि भूमि जोतों का गंभीर विखंडन
(B) अपर्याप्त आवास और स्वच्छता बुनियादी ढांचा
(C) अकुशल श्रम द्वारा ग्रामीण से शहरी प्रवास की उच्च दर
(D) शहरों में नियमित, औपचारिक रोजगार के अवसरों की कमी

52. निर्धनता और विकास संकेतकों में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित संकेतकों पर विचार कीजिए:
I. स्कूली शिक्षा के वर्ष
II. मातृ मृत्यु दर
III. पोषण
IV. परिसंपत्तियां

Downloaded from www.pdf.tube

नगरपालिका की उपयोगिता संरचना पर गंभीर ढांचागत दबाव डालता है।

37. वह परिघटना जहाँ निर्धनता व्यक्तियों को तत्काल अस्तित्व (जैसे बाल श्रम) के पक्ष में भविष्य के लाभों (जैसे औपचारिक शिक्षा पूरी करना) की उपेक्षा करने पर मजबूर करती है, किसका प्रत्यक्ष परिणाम है?
(A) वर्तमान जीवन यापन की उच्च अवसर लागत।
(B) राष्ट्रीय विनिर्माण उद्योगों में गहरी संरचनात्मक कमियां।
(C) गिनी सूचकांक द्वारा दर्शाया गया सांख्यिकीय वितरण प्रभाव।
(D) अनिवार्य सरकारी श्रम कोटा निर्धारित करने वाले लागू विधायी कानून।

38. "निर्धनता की एक ऐसी स्थिति जो अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर मौलिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरुप उत्पन्न होती है, जैसे तकनीकी बदलाव, असमान परिसंपत्ति वितरण, या पारंपरिक उद्योगों का पतन।" यह कथन किसे परिभाषित करता है?
(A) मौसमी निर्धनता
(B) घर्षणात्मक निर्धनता
(C) सापेक्ष निर्धनता
(D) संरचनात्मक निर्धनता

39. वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI) में 'जीवन स्तर' आयाम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा सूचक शामिल नहीं है?
(A) खाना पकाने का ईंधन
(B) बाल मृत्यु दर
(C) स्वच्छता
(D) बिजली

40. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में निर्धनता का एक प्रमुख संरचनात्मक कारण है?
(A) उच्च उत्पादकता वाले औपचारिक विनिर्माण क्षेत्रों में ग्रामीण कृषि श्रम का त्वरित संरचनात्मक आंदोलन।
(B) अकुशल शहरी श्रमिकों के विशाल बहुमत को सफलतापूर्वक अवशोषित करने वाला भारी-पूंजी औद्योगिक विस्तार।
(C) ऐतिहासिक भूमि संकेंद्रण जिसके कारण एक बड़ा भूमिहीन कृषि श्रम बल निर्मित हुआ।
(D) निःशुल्क, उच्च गुणवत्ता वाली तृतीयक और तकनीकी विश्वविद्यालय शिक्षा का देशव्यापी संस्थागत कार्यान्वयन।

41. निर्धनता और बेरोजगारी के संबंध के संदर्भ में, राजस्थान में "मौसमी बेरोजगारी" मुख्य रूप से किस रूप में प्रकट होती है?
(A) कुशल प्रौद्योगिकी पेशेवर सर्दियों के महीनों के दौरान व्यापक चक्रीय छंटनी का अनुभव करते हैं।
(B) आतिथ्य क्षेत्र में सेवा कर्मी विशेष रूप से प्रमुख त्योहारों की अवधि के दौरान व्यवस्थित बेरोजगारी का सामना करते हैं।
(C) औद्योगिक कारखाने के श्रमिक मानसून पावर ग्रिड विफलताओं से प्रेरित विस्तारित सुविधा तालाबंदी का अनुभव करते हैं।
(D) अपर्याप्त सिंचाई के कारण फसल के मौसम के बाहर कृषि श्रमिकों के पास रोजगार की कमी होती है।

42. सूची I में निर्धनता अनुमान समितियों का सूची II में उनकी परिभाषित विशेषताओं या सिफारिशों से मिलान कीजिए:
सूची I: (समिति)
P. वाई. के. अलघ कार्यदल
Q. लकड़ावाला विशेषज्ञ समूह
R. तेंदुलकर समिति
S. रंगराजन समिति
सूची II: (विशेषता / सिफारिश)
1. कैलोरी-आधारित मानकों से ध्यान हटाकर स्वास्थ्य और शिक्षा सहित एक व्यापक उपभोग बास्केट पर केंद्रित किया
2. शहरी क्षेत्रों में 2100 केकेएएल और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 केकेएएल के आधार पर निर्धनता रेखाओं की गणना की
3. एक संशोधित कैलोरी मानक को फिर से पेश किया और उपभोग में व्यवहार परिवर्तन को शामिल किया
4. कैलोरी मानकों को जारी रखने का सुझाव दिया लेकिन CPI-AL और CPI-IW का उपयोग करके राज्य-विशिष्ट निर्धनता रेखाओं की सिफारिश की
सही कूट का चयन कीजिए:
(A) P-2, Q-4, R-1, S-3
(B) P-4, Q-2, R-1, S-3
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-1, Q-4, R-2, S-3

NODIA

43. "निर्धनता अंतराल सूचकांक" को "सिरगणन अनुपात" की तुलना में अधिक सूक्ष्म/सटीक माप माना जाता है क्योंकि यह:
(A) क्षेत्र सर्वेक्षणों की आवश्यकता के बिना बड़े जनसांख्यिकीय डेटासेट के लिए गणनात्मक आवश्यकताओं को सरल बनाता है।
(B) यह आकलन करके निर्धनता की गहराई को मापता है कि निर्धन परिवार निर्धनता रेखा से कितना नीचे हैं।
(C) निर्धनता सीमाओं से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की सटीक कुल निरपेक्ष संख्या की गणना करता है।
(D) प्रमुख महानगरीय केंद्रों में शहरी आबादी पर अपने विश्लेषणात्मक मूल्यांकन को सख्ती से केंद्रित करता है।

44. निम्नलिखित में से कौन-सा ग्रामीण राजस्थान में दीर्घकालिक निर्धन लोगों के जनसांख्यिकीय प्रोफाइल की सबसे अच्छी विशेषता बताता है?
(A) आधुनिक निर्यात-उन्मुख वाणिज्यिक नकदी फसलों का भारी लाभ उठाने वाले धनी कृषि संपत्ति के मालिक।
(B) न्यूनतम उत्पादक परिसंपत्तियों के साथ दैनिक मजदूरी

76. सूची I में विशिष्ट निर्धनता-संबंधी अवधारणाओं का सूची II में उनके प्राथमिक आर्थिक निहितार्थों से मिलान कीजिए:

सूची I: (अवधारणा)

P. प्रच्छन्न बेरोजगारी
Q. निर्धनता का दुष्चक्र
R. बहुआयामी वंचना
S. कैलोरी एंकर

सूची II: (आर्थिक निहितार्थ)

1. एक स्व-सुदृढ़ीकरण तंत्र जो पूंजी निर्माण को रोकता है
2. शून्य सीमांत उत्पादकता के साथ कृषि में अत्यधिक रोजगार
3. भारत में निरपेक्ष निर्धनता रेखा को परिभाषित करने का ऐतिहासिक आधार
4. स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर की कमी के माध्यम से निर्धनता का मूल्यांकन करता है

सही कूट का चयन कीजिए:

(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

77. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में सीमांत किसानों के बीच निम्न कृषि उत्पादकता का प्राथमिक कारण नहीं है?

(A) पूंजी-गहन कृषि मशीनरी पर अत्यधिक निर्भरता।
(B) पारिवारिक पीढ़ियों के बीच विरासत में मिली भूमि जोतों का निरंतर उप-विभाजन और विखंडन।
(C) अस्थिर, अनिश्चित और अप्रत्याशित मौसमी मानसून वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता।
(D) नियमन वाले वित्तीय संस्थानों से समय पर और किफायती ऋण प्राप्त करने में निरंतर असमर्थता।

78. विकासशील देशों में निर्धनता के कारणों पर "संरचनावादी" दृष्टिकोण का सबसे अच्छा सारांश निम्नलिखित में से कौन-सा देता है?

(A) वंचना पूरी तरह से व्यक्तिगत श्रम की कमियों और व्यक्तिगत उद्यम की अनुपस्थिति के कारण है।
(B) निर्धनता एक क्षणिक परिघटना का प्रतिनिधित्व करती है जो मुक्त-बाजार पूंजीवादी ढाँचों को अपनाने पर स्वचालित रूप से गायब हो जाती है।
(C) निर्धनता संस्थागत संरचनाओं से उत्पन्न होती है जो असमान परिसंपत्ति और सत्ता वितरण को बढ़ावा देती हैं।
(D) कठिनाई विशेष रूप से राज्य की आर्थिक नीतियों से स्वतंत्र रूप से काम करने वाली गंभीर पर्यावरणीय परिस्थितियों के परिणामस्वरूप होती है।

79. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।

अभिकथन (A): निर्धनता में रहने वाली महिलाएं अक्सर एक ही निर्धन परिवार के पुरुषों की तुलना में अधिक पोषण संबंधी वंचना का सामना करती हैं।

कारण (R): पितृसत्तात्मक समाजों में संसाधनों का अंतर-घरेलू वितरण भोजन और स्वास्थ्य सेवा के लिए बार-बार पुरुष सदस्यों को प्राथमिकता देता है।

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

80. ग्रामीण राजस्थान में भूमि निम्नीकरण और मृदा लवणता प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे हैं। ये कारक क्षेत्रीय निर्धनता चक्र से किस प्रकार संबंधित हैं?

(A) वे जैविक कृषि उत्पादन के लिए व्यापक मांग को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कृषि क्षेत्र के राजस्व में काफी वृद्धि होती है।
(B) वे अकृषित भूमि पर स्वच्छ औद्योगिक विकास को गति देते हैं, जिससे ग्रामीण रोजगार का स्तर स्थायी रूप से बढ़ता है।
(C) वे प्रति हेक्टेयर फसल की पैदावार को घटाते हैं, जिससे कृषि आय कम होती है और ग्रामीण निर्धनता बढ़ती है।
(D) वे सूखा-प्रतिरोधी वाणिज्यिक फसलों के विशाल अधिशेष को जन्म देते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय वस्तु मूल्य निर्धारण मॉडल बाधित होते हैं।

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

उपर्युक्त में से कौन-से संकेतक स्पष्ट रुप से वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की गणना में शामिल हैं?
(A) I, III और IV
(B) I, II और III
(C) II, III और IV
(D) I, II, III और IV

53. राजस्थान जैसे विविध राज्य में क्षेत्रीय विषमताएं निर्धनता उन्मूलन प्रयासों को कैसे प्रभावित करती हैं?
(A) राजस्थान को अलग-अलग क्षेत्रीय निर्धनता चालकों को संबोधित करने के लिए लक्षित क्षेत्र योजनाओं की आवश्यकता है।
(B) समरुप सामाजिक-भौगोलिक स्थितियों के कारण विकास नीति का मानकीकरण देश भर में प्रभावी ढंग से काम करता है।
(C) सामाजिक-आर्थिक कठिनाई पूर्वी क्षेत्रों तक सीमित है, जिससे राज्य योजना पश्चिमी क्षेत्रों को बाहर करने में सक्षम है।
(D) स्थानिक आर्थिक असमानताओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, जिससे विशेष क्षेत्रीय योजनाएं अनावश्यक हो गई हैं।

54. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुक्रम मांग पक्ष पर निर्धनता के दुष्चक्र की सही तार्किक प्रगति को दर्शाता है?
(A) निम्न उत्पादकता → निम्न आय → निम्न मांग (क्रय शक्ति) → निम्न निवेश
(B) निम्न निवेश → निम्न उत्पादकता → निम्न मांग (क्रय शक्ति) → निम्न आय
(C) निम्न आय → निम्न निवेश → निम्न उत्पादकता → निम्न मांग (क्रय शक्ति)
(D) निम्न मांग (क्रय शक्ति) → निम्न उत्पादकता → निम्न निवेश → निम्न आय

55. हाल के दशकों के ऐतिहासिक रुझानों का विश्लेषण करने पर, राजस्थान में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुपात:
(A) प्रत्येक प्रशासनिक जिले में लगातार वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि प्रदर्शित की है।
(B) सामान्यतः घटा है, जबकि निर्धन लोगों की निरपेक्ष संख्या महत्वपूर्ण बनी हुई है।
(C) 1990 के दशक में समष्टि-संरचनात्मक आर्थिक सुधारों के बाद पूरी तरह से स्थिर रहा है।
(D) आधिकारिक आधार रेखा रिपोर्टों के अनुसार पूर्ण शून्य पर आ गया है।

56. निर्धनता-स्वास्थ्य संबंधों के संदर्भ में "जेब से बाहर का व्यय" शब्द का क्या अर्थ है?
(A) चिकित्सा देखभाल के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्रतिबद्ध पूंजी आवंटन।
(B) जनजातीय क्षेत्रों में निःशुल्क नैदानिक दवाएं देने के लिए गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा वितरित परिचालन निधि।
(C) सेवा स्थल पर स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को प्रत्यक्ष भुगतान, जो अक्सर परिवारों को कर्ज में धकेल देता है।
(D) सब्सिडी वाली राज्य चिकित्सा बीमा योजनाओं में भाग लेने वाले परिवारों द्वारा महसूस की गई शुद्ध वित्तीय बचत।

57. तीव्र जनसंख्या वृद्धि मुख्य रुप से भारत में निर्धनता के एक प्रमुख संरचनात्मक कारण के रुप में कार्य करती है क्योंकि:
(A) यह उपभोक्ता मुख्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार की मांग में तत्काल और तीव्र गिरावट की ओर ले जाती है।
(B) यह कृषि से उन्नत विनिर्माण क्षेत्र में एक निर्बाध आर्थिक संरचनात्मक संक्रमण का कारण बनती है।
(C) यह सक्रिय कृषि श्रम बल को घटाती है, जिससे तीव्र राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति घाटा होता है।
(D) यह निर्भरता अनुपात को बढ़ाती है और प्रति व्यक्ति पूंजी तथा संसाधन उपलब्धता को कम करती है।

58. एक व्यक्ति जो आमतौर पर निर्धनता रेखा से ऊपर है, लेकिन गंभीर सूखे या स्वास्थ्य आपातकाल जैसी विशिष्ट अवधियों के दौरान इसके नीचे चला जाता है, वह किसका सामना कर रहा है?
(A) क्षणिक/अस्थायी निर्धनता
(B) दीर्घकालिक निर्धनता
(C) अत्यधिक निर्धनता
(D) सापेक्ष निर्धनता

59. ऐतिहासिक लकड़ावाला समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य परिवर्तनों के लिए राज्य-विशिष्ट निर्धनता रेखाओं को कैसे अद्यतन किया गया था?
(A) सभी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) का उपयोग करके।
(B) कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) का उपयोग करके।
(C) राष्ट्रीय थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधार रेखा आंदोलनों का उपयोग करके।
(D) कुल सकल घरेलू उत्पाद मूल्य अपस्फीतिकारक मेट्रिक्स का उपयोग करके।

60. ग्रामीण राजस्थान में निर्धनता-शिक्षा संबंध द्वारा किस मूलभूत आर्थिक मुद्दे को उजागर किया गया है?
(A) ग्रामीण निर्धन लोगों के बीच अंग्रेजी माध्यम की निजी शिक्षा के लिए उच्च प्राथमिकता
(B) बाल श्रम से वर्तमान जीवन यापन आय और स्कूली शिक्षा से भविष्य के लाभों के बीच का संतुलन/समझौता
(C) मानव पूंजी में अत्यधिक निवेश जिसके कारण कृषि श्रम की गंभीर कमी हो रही है
(D) सांस्कृतिक कारणों से निःशुल्क सरकारी स्कूलों का उपयोग करने से हाशिये पर स्थित समुदायों का पूर्ण इनकार

NODIA

10. (A) यह विपणन योग्य अधिशेष को घटाती है, जिससे कृषि आय कम होती है और कृषि मजदूरी में गिरावट आती है।
कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता सीधे तौर पर ग्रामीण निर्धनता को बढ़ावा देती है क्योंकि यह किसानों के विपणन योग्य अधिशेष को सीमित कर देती है। फसल उत्पादन कम होने से किसानों की शुद्ध बाजार बिक्री घटती है, जिससे उनकी पारिवारिक आय में भारी गिरावट आती है। इसके साथ ही, कम उत्पादकता के कारण कृषि मजदूरों की मजदूरी भी घट जाती है।

11. (B) कम वर्षा और अत्यधिक गर्मी के कारण बार-बार फसलें खराब होती हैं और पशुधन की मृत्यु होती है, जिससे कृषि आय अस्थिर हो जाती है।
राजस्थान की जलवायुगत शुष्कता राज्य में निर्धनता के लिए एक प्राकृतिक तथा गंभीर कारक है। कम और अनिश्चित मानसून वर्षा तथा अत्यधिक गर्मी के कारण फसलों का नष्ट होना आम बात है। इसके अलावा, चारे और पानी की कमी के कारण पशुधन की हानि होती है। चूँकि ग्रामीण आबादी की आजीविका कृषि और पशुपालन पर निर्भर है, इसलिए आय अत्यंत अस्थिर हो जाती है।

12. (B) I, II और IV
भारत में निर्धनता आकलन के इतिहास में अलघ कार्यदल ने कैलोरी आवश्यकताओं के आधार पर निर्धनता रेखाएं परिभाषित की थीं। लकड़ावाला समिति ने मूल्य सूचकांकों के उपयोग से राज्य-विशिष्ट रेखाएं अनुशंसित की थीं। तेंदुलकर समिति ने मिश्रित संदर्भ अवधि को अपनाया था। रंगराजन समिति ने URP पर लौटने के बजाय संशोधित अवधि का प्रयोग किया था, इसलिए तृतीय कथन अशुद्ध है।

13. (A) यह अधिशेष कृषि श्रम के लिए गैर-कृषि रोजगार के सृजन को सीमित करता है, जिससे उच्च कृषि निर्भरता बनी रहती है।
राजस्थान में सीमित औद्योगीकरण राज्य में निर्धनता के बने रहने का एक प्रमुख समष्टि आर्थिक कारण है। द्वितीयक विनिर्माण क्षेत्र का कम विकास कृषि क्षेत्र में लगे अधिशेष श्रम बल को अवशोषित करने में विफल रहता है। इसके परिणामस्वरूप, अधिकांश जनसंख्या कम उत्पादकता और अनिश्चित आय वाले कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होती है। रोजगार अभाव कठिनाई बढ़ाता है।

14. (A) वाई. के. अलघ कार्यदल, लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति
भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु समय-समय पर विशेषज्ञों की समितियों का गठन किया गया है। इनका सही कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है: वाई. के. अलघ कार्यदल का गठन वर्ष 1979 में किया गया था, इसके पश्चात लकड़ावाला समिति का गठन 1989 में हुआ। इसके बाद सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में हुआ तथा सी. रंगराजन समिति का गठन 2012 में किया गया।

15. (D) दक्षिणी जनजातीय पट्टी (जैसे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर)
राजस्थान के दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर के हिस्से शामिल हैं, में दीर्घकालिक निर्धनता की दरें ऐतिहासिक रूप से काफी अधिक रही हैं। यह क्षेत्र उबड़-खाबड़ और पहाड़ी धरातल, कृषि योग्य भूमि के छोटे आकारों, बुनियादी अवसंरचना के सीमित प्रसार तथा आर्थिक संसाधनों की कमी से प्रभावित है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक-भौगोलिक विषमता निर्धनता को और अधिक बढ़ाती है।

16. (C) अनुसूचित जनजाति (ST)
सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में अनुसूचित जनजाति समुदाय के अंतर्गत निर्धनता सिरगणन अनुपात ऐतिहासिक रूप से उच्चतम रहा है। दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में निवास, उत्पादक परिसंपत्तियों तथा भूमि अधिकारों का सीमित स्वामित्व, उच्च निरक्षरता तथा औपचारिक अर्थव्यवस्था तक कम पहुंच इसके प्रमुख कारण हैं। यह समस्या काफी गंभीर और व्यापक रूप से बनी हुई है।

17. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
निर्धनता और कुपोषण के बीच एक गहरा और परस्पर सुदृढ़ होने वाला दुष्चक्र विद्यमान रहता है। आर्थिक निर्धनता के कारण परिवार पौष्टिक भोजन, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छता तक पहुँच प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, जिससे बच्चों में शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास बाधित होता है। इसके परिणामस्वरूप कार्यक्षमता और उत्पादकता घटती है, जो पुनः निर्धनता को बढ़ावा देती है।

18. (D) 14.7 प्रतिशत
योजना आयोग द्वारा तेंदुलकर समिति की कार्यप्रणाली के आधार पर जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011-12 में राजस्थान में कुल निर्धनता अनुपात 14.7 प्रतिशत अनुमानित किया गया था। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धनता अनुपात 16.1 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 10.7 प्रतिशत दर्ज किया गया था। वर्ष 2004-05 की तुलना में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की थी।

19. (A) राजस्थान का निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम था।
वर्ष 2011-12 के लिए तेंदुलकर कार्यप्रणाली पर आधारित आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान का कुल निर्धनता अनुपात 14.7 प्रतिशत था, जबकि इसी अवधि के लिए अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय औसत निर्धनता अनुपात 21.9 प्रतिशत दर्ज किया गया था। इस प्रकार, राजस्थान का निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी कम था। यह राज्य की सकारात्मक प्रगति को स्पष्ट दर्शाता है।

20. (C) संरचनात्मक असमानताओं के कारण महिलाएं निर्धनता की असमान रूप से उच्च दरों और गंभीरता का सामना करती हैं।
निर्धनता के स्त्रीकरण की अवधारणा इस सामाजिक-आर्थिक वास्तविकता को स्पष्ट करती है कि समाज में व्याप्त लिंग आधारित असमानताओं, संपत्ति अधिकारों के अभाव, मजदूरी में अंतर और अवैतनिक देखभाल कार्यों के कारण महिलाएं पुरुषों की तुलना में निर्धनता से अधिक प्रभावित होती हैं। इसके कारण महिला-प्रमुख परिवारों में वंचना की गंभीरता अधिक पाई जाती है और वे अत्यधिक संवेदनशील होती हैं।

Downloaded from www.pdf.tube

जनसांख्यिकी पर उच्च प्रभावी सीमांत कर बोझ डालती हैं।
(C) आधुनिक क्षेत्रों में विकास स्वास्थ्य, शिक्षा और परिसंपत्तियों की कमी वाले हाशिये पर स्थित समूहों तक पहुँचने में विफल रहता है।
(D) क्योंकि संरचनात्मक आर्थिक वंचनाएं केवल राज्य-नियोजित समाजवादी प्रणालियों में होती हैं, बाजार मॉडलों में नहीं।

69. निरपेक्ष निर्धनता को मापने में, "निर्धनता रेखा बास्केट" अनिवार्य रूप से किसका प्रतिनिधित्व करती है?
(A) बुनियादी अस्तित्व के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का एक बास्केट।
(B) राज्य कल्याणकारी लाभों की पात्रता निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत उपभोग व्यय पर वैधानिक सीमा।
(C) एक पूरे कैलेंडर वर्ष में एक औसत ग्रामीण परिवार को बनाए रखने के लिए आवश्यक कुल कृषि फसल की उपज।
(D) अल्पविकसित प्रशासनिक जिलों द्वारा निर्यात की जाने वाली निर्मित वस्तुओं का एक मानकीकृत संग्रह।

70. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): किसी देश में निरपेक्ष निर्धनता घटने पर भी सापेक्ष निर्धनता दर बढ़ सकती है।
कारण (R): आर्थिक विकास सबसे कम कमाने वालों को बुनियादी अस्तित्व सीमा से ऊपर उठा सकता है जबकि साथ ही अमीर और गरीब के बीच आय अंतर को बढ़ा सकता है।
उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

71. कौन-सा तंत्र बेरोजगारी को शहरी निर्धनता से सबसे सीधे जोड़ता है?
(A) बेरोजगार श्रम बल व्यापक आर्थिक मूल्य अपस्फीति शुरू करते हैं, जिससे निवासियों के लिए समग्र जीवन यापन की लागत कम हो जाती है।
(B) नौकरियों की कमी श्रमिकों को आकस्मिक दैनिक श्रम करने के लिए मजबूर करती है, जिससे कम और अनियमित आय प्राप्त होती है।
(C) बेरोजगारी झुग्गियों के लिए उपलब्ध शहरी भूमि को बढ़ाकर नगरपालिका के कम लागत वाले आवास स्टॉक का सीधे विस्तार करती है।
(D) बेरोजगार व्यक्ति स्वचालित रूप से सरकारी आय सहायता प्राप्त करते हैं जो आर्थिक कठिनाई को बेअसर करती है।

72. दीर्घकालिक बनाम क्षणिक/अस्थायी निर्धनता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. दीर्घकालिक निर्धनता अक्सर प्रकृति में अंतर-पीढ़ीगत होती है।
II. क्षणिक निर्धनता को समय-विशेष क्रॉस-सेक्शनल सर्वेक्षणों द्वारा आसानी से और स्थायी रूप से दर्ज किया जाता है।
III. दीर्घकालिक निर्धनता के लिए दीर्घकालिक परिसंपत्ति-निर्माण और शैक्षणिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
IV. क्षणिक निर्धनता को आर्थिक झटकों के दौरान सामाजिक सुरक्षा तंत्र और बीमा के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से संबोधित किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(A) I, II और III
(B) I, III और IV
(C) II, III और IV
(D) I, II, III और IV

73. आज राष्ट्रीय निर्धनता माप सुधार का प्राथमिक ध्यान क्या है?
(A) लकड़ावाला विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुशंसित क्षेत्रीय कैलोरी उपभोग सीमाओं को फिर से स्थापित करना।
(B) सभी भारतीय राज्यों में आधिकारिक संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय निर्धनता आधार रेखा ढांचे को लागू करना।
(C) अनुभवजन्य मात्रात्मक निर्धनता माप को व्यक्तिपरक गुणात्मक सामाजिक-आर्थिक वृत्तांतों से बदलना।
(D) आय-आधारित रेखाओं से बहुआयामी निर्धनता सूचकांकों की ओर बढ़ना।

74. राष्ट्रीय तुलनाओं के संदर्भ में, कौन-सा भारतीय राज्य लगातार अपनी जनसंख्या के उच्चतम अनुपात के बहुआयामी निर्धनता में रहने की रिपोर्ट करता है?
(A) बिहार
(B) राजस्थान
(C) उत्तर प्रदेश
(D) मध्य प्रदेश

75. रंगराजन समिति की रिपोर्ट के आधार पर, निर्धनता रेखा के खाद्य घटक की गणना के लिए कौन-सी कार्यप्रणाली अपनाई गई थी?
(A) सभी जनसांख्यिकीय समूहों में समान रूप से अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठन के पोषण मानकों को अपनाना।
(B) आयु, लिंग और गतिविधि के स्तर के आधार पर कैलोरी, प्रोटीन और वसा के लिए ICMR मानकों को लागू करना।
(C) मूल्य मुद्रास्फीति के लिए समय-समय पर समायोजित निश्चित मौद्रिक हस्तांतरण के साथ पोषण संबंधी गणनाओं को प्रतिस्थापित करना।
(D) देश भर में सभी ग्रामीण और शहरी आबादी के लिए 2400 केकेएएल की एकल पोषण सेवन आवश्यकता को अनिवार्य बनाना।

NODIA

61. तेंदुलकर समिति की कार्यप्रणाली के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए:
(A) इसने लकड़ावाला के अनुमानों की तुलना में निर्धनता सिरगणन अनुपात में तेजी से कमी की।
(B) इसने मौद्रिक निर्धनता रेखाओं को कैलोरी सेवन मानकों से जोड़ने की ऐतिहासिक प्रथा को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया।
(C) इसने आवश्यक चिकित्सा देखभाल और स्कूली शिक्षा पर निजी घरेलू खर्च को औपचारिक रुप से बास्केट में एकीकृत किया।
(D) इसने ग्रामीण कृषि और शहरी दोनों क्षेत्रों में एक एकल मानकीकृत निर्धनता रेखा बास्केट लागू की।

62. सूची I में निर्धनता से जुड़े पदों का सूची II में दिए गए उनके वास्तविक दुनिया के उदाहरणों से मिलान कीजिए:
सूची I: (निर्धनता पद)
P. शुष्कता-विशिष्ट कारण
Q. सामाजिक असमानता
R. संरचनात्मक कारण
S. क्षणिक/अस्थायी निर्धनता
सूची II: (उदाहरण)
1. राज्य में अनुसूचित जनजातियों के बीच पारंपरिक रुप से उच्च निर्धनता अनुपात देखा गया
2. गंभीर मानसून विफलता के एक ही वर्ष के कारण एक किसान का कर्ज में डूब जाना
3. बड़े पैमाने पर विनिर्माण उद्योगों की कमी जो गैर-कृषि रोजगार सृजन को सीमित करती है
4. अत्यधिक ग्रीष्मकालीन तापमान और कम वर्षा के कारण बाड़मेर में बार-बार फसल का खराब होना
सही कूट का चयन कीजिए:
(A) P-4, Q-1, R-3, S-2
(B) P-1, Q-4, R-2, S-3
(C) P-4, Q-3, R-1, S-2
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

63. अमर्त्य सेन का निर्धनता का क्षमता दृष्टिकोण इसे मुख्य रूप से किस रुप में परिभाषित करता है?
(A) मौद्रिक आय की एक सरल और सख्त कमी
(B) तेजी से बढ़ती पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का एक अपरिहार्य परिणाम
(C) 2100-कैलोरी दैनिक पोषण सीमा को पूरा करने में सांख्यिकीय विफलता
(D) कार्य करने और अपनी पसंद का जीवन जीने की बुनियादी क्षमताओं का अभाव

64. भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए:
I. बिहार
II. राजस्थान
III. केरल
IV. ओडिशा
तेंदुलकर कार्यप्रणाली (2011-12) के आधार पर इन राज्यों को निर्धनता की उच्चतम से न्यूनतम दर के क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन-सा सही क्रम दर्शाता है?
(A) I, IV, II, III
(B) I, II, IV, III
(C) IV, I, II, III
(D) I, IV, III, II

65. शहरी निर्धनता का एक प्रमुख संरचनात्मक कारण शहरी अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रकृति है। यह किसे संदर्भित करता है?
(A) महानगरीय क्षेत्रों का वाणिज्यिक और आवासीय जिलों में कठोर प्रशासनिक पृथक्करण।
(B) एक उत्पादक औपचारिक क्षेत्र और एक संवेदनशील अनौपचारिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व।
(C) नगर पालिका केंद्रों में केंद्रीय और प्रांतीय वित्तीय कर प्रशासनों का एक साथ संचालन।
(D) मूल नागरिकों और आंतरिक प्रवासियों के बीच पूरी तरह से समान परिसंपत्ति और आय वितरण पैटर्न।

66. कौन-सा भौतिक और आर्थिक कारक राजस्थान में औद्योगीकरण को गंभीर रुप से सीमित करता है, जिससे राज्य की निर्धनता में वृद्धि होती है?
(A) अंतर्निहित खनिज संपदा की पूर्ण कमी
(B) शारीरिक श्रम करने के लिए अनिच्छुक अत्यधिक कुशल आईटी पेशेवरों की अति-जनसंख्या
(C) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर अत्यधिक भौगोलिक ध्यान
(D) पानी की भारी कमी और ऐतिहासिक ढांचागत कमियां

67. "निर्धनता के स्त्रीकरण" के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह इंगित करता है कि दुनिया के निर्धन लोगों का एक बड़ा अनुपात महिलाएं हैं।
II. यह संपत्ति के अधिकारों तक असमान पहुंच और भेदभावपूर्ण उत्तराधिकार प्रथाओं से और बिगड़ता है।
III. अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्य आय सृजन गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को अत्यधिक सीमित करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

68. राजस्थान जैसे विकासशील क्षेत्रों में संरचनात्मक निर्धनता को समाप्त करने के लिए "टपकन प्रभाव" को अक्सर अपर्याप्त क्यों माना जाता है?
(A) क्योंकि राष्ट्रीय समष्टि अर्थशास्त्र विकास व्यवस्थित और तेजी से सबसे कम आय वाले वर्गों को पहले प्राथमिकता देता है।
(B) क्योंकि राजकोषीय कर संरचनाएं कम आय वाले

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) एक ऐसी स्थिति जहाँ किसी व्यक्ति के पास भोजन, आवास और वस्त्र जैसे बुनियादी जीवन स्तर को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आय का अभाव होता है।
निरपेक्ष निर्धनता एक ऐसी आर्थिक स्थिति को दर्शाती है जहाँ व्यक्ति के पास जीवन यापन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम संसाधनों का अभाव होता है। इसके अंतर्गत भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी मानवीय जरूरतें शामिल हैं। यह अवधारणा किसी समाज में आय की विषमता से परे होकर केवल न्यूनतम जीवन स्तर को आधार मानती है। यह मापन सार्वभौमिक तथा निश्चित है।

2. (D) लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक
सापेक्ष निर्धनता विभिन्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों अथवा क्षेत्रों के बीच आय और संपत्ति की विषमता को रेखांकित करती है। इसे मापने के लिए लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक सबसे प्रमुख आर्थिक उपकरण हैं। लॉरेंज वक्र जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच आय वितरण के वास्तविक आरेखीय निरूपण को प्रदर्शित करता है, जबकि गिनी गुणांक इस असमानता का गणितीय मान प्रस्तुत करता है। गिनी गुणांक का मान पूर्ण विषमता दर्शाती है।

3. (A) यह कैलोरी-आधारित मानकों से इतर उपभोग बास्केट में स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर व्यय को शामिल करने की ओर स्थानांतरित हुआ।
वर्ष 2009 में प्रस्तुत तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट ने भारत में निर्धनता आकलन की परंपरागत कैलोरी-आधारित पद्धति में महत्वपूर्ण बदलाव किया। इस समिति ने न्यूनतम कैलोरी सेवन को एकमात्र मानदंड मानने के बजाय निजी उपभोग बास्केट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले व्यय को शामिल किया। इसके अतिरिक्त, समिति ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक समान निर्धनता रेखा बास्केट का सुझाव दिया और सुधार किया।

4. (B) ग्रामीण के लिए 972 रुपये और शहरी के लिए 1407 रुपये
सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह ने वर्ष 2011-12 के लिए संशोधित निर्धनता रेखाएं निर्धारित की थीं। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये तय किया था। दैनिक आधार पर यह सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये प्रति व्यक्ति थी। रंगराजन समिति ने नया मानक अपनाया था।

5. (A) वित्तीय समावेशन
वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल द्वारा संयुक्त रुप से जारी किया जाता है। यह सूचकांक तीन मुख्य आयामों पर आधारित है, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर शामिल हैं। इन तीन आयामों के अंतर्गत कुल 10 विभिन्न संकेतकों का मूल्यांकन किया जाता है। वित्तीय समावेशन इस वैश्विक सूचकांक के प्रत्यक्ष आयामों में शामिल नहीं किया गया है।

6. (D) कृषि भूमि और उत्पादक परिसंपत्तियों का असमान वितरण
भारत में ग्रामीण निर्धनता का सबसे प्रमुख संरचनात्मक कारण कृषि भूमि और उत्पादक परिसंपत्तियों का अत्यधिक असमान वितरण है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमि केवल उत्पादन का साधन ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का प्रमुख आधार है। सीमांत औरछोटे किसानों के पास भूमि जोतों का आकार लगातार छोटा और विखंडित होता जा रहा है। इसके विपरीत, अधिकांश भूमि विषम रुप से बंटी हुई है।

7. (A) केवल I और II
निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राग्नार नर्कसे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह सिद्धांत दर्शाता है कि कम आय से कम बचत, कम निवेश और अंततः कम पूंजी निर्माण तथा निम्न उत्पादकता का निर्माण होता है। पूर्ति पक्ष पर यह चक्र लगातार घूमता रहता है। हालांकि, मांग पक्ष पर अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि क्रय शक्ति घटाकर निर्धनता जाल गहरा करती है।

8. (C) शहरी झुग्गी-झोपड़ियों का प्रसार और अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार पर भारी निर्भरता
भारत में शहरी निर्धनता का मुख्य स्वरुप अनियोजित शहरीकरण, झुग्गी-झोपड़ियों के विस्तार और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के विशाल संकेंद्रण के रुप में दिखाई देता है। ग्रामीण क्षेत्रों से बेहतर आजीविका की तलाश में आए प्रवासी अक्सर शहरों में निम्न मजदूरी, अस्थाई रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की कमी तथा अमानवीय आवास परिस्थितियों में रहते हैं। यह स्थिति अत्यंत गंभीर है।

9. (D) ऐसी स्थिति जहाँ आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हुए हैं, जिससे शून्य सीमांत उत्पादकता प्राप्त होती है
प्रच्छन्न बेरोजगारी वह आर्थिक स्थिति है जिसमें किसी कार्य या कृषि गतिविधि में आवश्यकता से अधिक श्रमिक संलग्न होते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी में यदि कुछ श्रमिकों को कार्य से हटा भी दिया जाए, तो भी कुल उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात्, अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। यह ग्रामीण निर्धनता का कारण है।

Downloaded from www.pdf.tube

(B) संस्थागत नीतिगत ढांचे जो विरासत में मिली संपत्तियों पर भारी कर लगाते हैं, जिससे बहु-पीढ़ीगत संपत्ति होल्डिंग्स व्यवस्थित रूप से घटती हैं।
(C) वह चक्र जहाँ वंचित माता-पिता मानव-पूंजी-कमी वाले बच्चों का पालन-पोषण करते हैं, जिससे निर्धनता बनी रहती है।
(D) शहरी झुग्गियों में अनौपचारिक कार्य की तलाश के लिए पैतृक कृषि व्यवसायों को छोड़ने का युवा ग्रामीण समूहों का सचेत व्यक्तिगत निर्णय।

31. निर्धनता के माप के रूप में सिरगणन अनुपात (HCR) की मुख्य सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा करता है?
(A) यह निरपेक्ष निर्धनता के मूलभूत उपायों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए विशेष रूप से सापेक्ष आर्थिक असमानताओं का मूल्यांकन करता है।
(B) इसके लिए अत्यधिक जटिल गणितीय मॉडलिंग की आवश्यकता होती है जिसकी गणना मानक राष्ट्रीय घरेलू खर्च सर्वेक्षणों का उपयोग करके नहीं की जा सकती है।
(C) यह भारतीय आर्थिक संदर्भ में केवल ग्रामीण कृषि जनसांख्यिकी पर लागू होने के लिए वैधानिक नियमों द्वारा प्रतिबंधित है।
(D) यह निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों में निर्धनता की गहराई या गंभीरता को मापने में विफल रहता है।

32. रंगराजन समिति (2014) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसने ग्रामीण क्षेत्रों में 2155 केकेएएल और शहरी क्षेत्रों में 2090 केकेएएल की पोषण संबंधी आवश्यकता के आधार पर निर्धनता रेखाओं की गणना की।
II. इसमें पर्याप्त पोषण, कपड़े, मकान का किराया और गतिशीलता के लिए मानकीकृत आवश्यकताओं को शामिल किया गया।
III. इसने 2011-12 के लिए अखिल भारतीय निर्धनता अनुपात 29.5% होने का अनुमान लगाया था।
IV. इसकी मौद्रिक निर्धनता रेखा की सिफारिशें तेंदुलकर समिति के अनुमानों से सार्वभौमिक रूप से कम थीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(A) I, II और III
(B) II, III और IV
(C) I, III और IV
(D) I, II और IV

33. शहरी निर्धनता में योगदान देने में अनौपचारिक रोजगार की क्या भूमिका है?
(A) अनौपचारिक कार्य घटिया कामकाजी माहौल के साथ असाधारण रूप से आकर्षक मौद्रिक वेतन प्रदान करता है, जो श्रम को भौगोलिक रूप से स्थिर करता है।
(B) अनौपचारिक श्रमिकों में नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी का अभाव होता है, जिससे संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
(C) अनौपचारिक अर्थव्यवस्था अत्यधिक तकनीकी और विशिष्ट कौशल सेट की मांग करती है, जो अशिक्षित कम आय वाले नौकरी चाहने वालों को व्यवस्थित रूप से बाहर करती है।
(D) अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों पर अत्यधिक कॉर्पोरेट कर लगाए जाते हैं, जिससे अनौपचारिक श्रमिकों की शुद्ध आय में भारी कमी आती है।

34. राजस्थान निर्धनता के विशिष्ट शुष्कता-संबंधी कारणों का सामना करता है। कौन-सी प्राकृतिक परिघटना पश्चिमी राजस्थान में पशुपालकों की आजीविका को अत्यधिक प्रभावित करती है?
(A) लूनी बेसिन में विनाशकारी मौसमी आकस्मिक बाढ़ सामुदायिक चरागाहों को पूरी तरह से जलमग्न कर देती है।
(B) अरावली फॉल्ट लाइनों के साथ बार-बार होने वाली भूकंपीय गतिविधियां पारंपरिक पशुधन मार्गों को स्थायी रूप से बाधित करती हैं।
(C) शुष्क मैदानों में असामान्य रूप से भारी शीतकालीन बर्फबारी जो प्राकृतिक वनस्पति और पशु चराई के मैदानों को जमा देती है।
(D) बार-बार पड़ने वाला सूखा जिसके कारण चारे और पानी की भारी कमी हो जाती है।

NODIA

35. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI) आय-आधारित निर्धनता रेखाओं की तुलना में वंचन का अधिक व्यापक चित्र प्रदान करता है।
कारण (R): MPI केवल क्रय शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में घरेलू स्तर पर अतिव्याप्त वंचनाओं का मूल्यांकन करता है।
उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

36. राजस्थान में क्षेत्रीय विषमताओं की तुलना करते समय, पश्चिमी राजस्थान के जिले अक्सर क्षणिक/अस्थायी निर्धनता के प्रति उच्च संवेदनशीलता क्यों दर्शाते हैं?
(A) पूंजी-गहन भारी विनिर्माण संयंत्रों का एक बड़ा संकेंद्रण जिसके कारण लगातार चक्रीय श्रम छंटनी होती है।
(B) सभी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रशासनिक जिलों में सार्वजनिक और निजी वित्तीय संस्थानों की पूर्ण अनुपस्थिति।
(C) अप्रत्याशित मरुस्थलीय जलवायु में वर्षा आधारित खेती और पशुधन पर भारी निर्भरता।
(D) असामान्य रूप से सघन जनसांख्यिकीय संकेंद्रण जो

21. (A) सूखे के दौरान निर्धनता रेखा से नीचे आने वाला एक छोटा किसान जो अच्छे मानसून में उबर जाता है।
क्षणिक या अस्थायी निर्धनता उस आर्थिक स्थिति को संदर्भित करती है जहाँ कोई व्यक्ति या परिवार आमतौर पर निर्धनता रेखा से ऊपर रहता है, लेकिन मौसमी बदलावों, प्राकृतिक आपदाओं, सूखे या अचानक उपजे आर्थिक झटकों के कारण अस्थायी रुप से निर्धनता रेखा से नीचे चला जाता है। परिस्थितियाँ अनुकूल होने पर वह पुनः ऊपर उठ जाता है। यह अल्पकालिक वंचना है।

22. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
निरपेक्ष निर्धनता का मापन न्यूनतम जीवन स्तर हेतु आवश्यक एक निश्चित उपभोग या आय सीमा के आधार पर किया जाता है। इसके विपरीत, सापेक्ष निर्धनता का आकलन आय विषमता के आधार पर लॉरेंज वक्र से होता है। दीर्घकालिक निर्धनता का तात्पर्य लंबी अवधि तक वंचना में बने रहने से है, जबकि क्षणिक निर्धनता मौसमी झटकों के कारण होती है। यह अंतर महत्वपूर्ण है।

23. (B) यह शिक्षा की अवसर लागत को बढ़ाती है, जिससे निर्धन बच्चे बाल श्रम या घरेलू कामों में लग जाते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक निर्धनता शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी बाधा बनकर उभरती है क्योंकि यह शिक्षा की अवसर लागत को अत्यधिक बढ़ा देती है। जब परिवार जीवन यापन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में संघर्ष करते हैं, तो बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय उन्हें दिहाड़ी मजदूरी या घरेलू कामों में लगाना पड़ता है, जिससे शिक्षा बाधित होती है।

24. (A) I, IV, III, II
नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार राज्यों में बहुआयामी निर्धनता सिरगणन अनुपात का घटता क्रम बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और केरल है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बहुआयामी निर्धनता का अनुपात सर्वाधिक दर्ज किया गया, इसके बाद उत्तर प्रदेश तथा फिर राजस्थान आता है। वहीं केरल में यह स्तर सबसे कम दर्ज किया गया है।

25. (D) यह आवश्यक गैर-खाद्य आवश्यकताओं और जीवन यापन की लागत में क्षेत्रीय अंतरों की उपेक्षा करता है।
भारत में केवल कैलोरी सेवन पर आधारित पारंपरिक निर्धनता रेखाओं की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि यह दृष्टिकोण गैर-खाद्य आवश्यक वस्तुओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, वस्त्र तथा आवास पर होने वाले अनिवार्य खर्चों की उपेक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच जीवन यापन की लागत में मौजूद अंतरों का उचित समायोजन नहीं कर पाता है। यह बड़ी कमी है।

26. (A) यह तकनीकी प्रगति को दबाता है और नए रोजगार सृजन को सीमित करता है।
किसी विकासशील अर्थव्यवस्था में कम पूंजी निर्माण का एक गंभीर समष्टि आर्थिक दुष्परिणाम यह होता है कि इससे उत्पादन क्षमता का विस्तार रुक जाता है। जब बुनियादी ढांचे, मशीनों और तकनीकों में निवेश कम होता है, तो उत्पादकता स्थिर हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप तकनीकी प्रगति बाधित होती है तथा श्रम बल के लिए नए रोजगार का सृजन सीमित हो जाता है।

27. (C) केवल I और III
अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, विश्व बैंक ने अत्यधिक निर्धनता की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2.15 डॉलर निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त, सिरगणन अनुपात निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली कुल जनसंख्या के प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। सापेक्ष निर्धनता विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी विद्यमान रहती है, अतः द्वितीय कथन पूरी तरह से अशुद्ध सिद्ध होता है।

28. (B) क्षणिक/अस्थायी निर्धनता
मंथन निर्धन उन व्यक्तिगत परिवारों को संदर्भित करता है जो निरंतर निर्धनता रेखा के ऊपर और नीचे आते-जाते रहते हैं। यह स्थिति क्षणिक या अस्थायी निर्धनता की व्यापक श्रेणी के अंतर्गत आती है। ऐसे लोगों में प्रायः छोटे किसान, मौसमी कृषि मजदूर या दिहाड़ी श्रमिक शामिल होते हैं, जिनकी आय मौसमी अनिश्चितताओं और रोजगार उपलब्धता के आधार पर बदलती रहती है।

29. (A) इसने पांच गैर-खाद्य वस्तुओं के लिए 365-दिन की स्मरण अवधि और शेष के लिए 30-दिन की स्मरण अवधि का उपयोग किया।
सुरेश तेंदुलकर समिति ने निर्धनता मापन हेतु उपभोग व्यय के संग्रहण के लिए मिश्रित संदर्भ अवधि का प्रयोग किया था। इस पद्धति के तहत कम आवृत्ति वाली पांच विशिष्ट गैर-खाद्य मदों (जैसे वस्त्र, शिक्षा तथा स्वास्थ्य व्यय) के लिए 365-दिन की स्मरण अवधि का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, अन्य सभी उपभोग्य वस्तुओं के लिए 30-दिन की अवधि तय की गई।

30. (C) वह चक्र जहाँ वंचित माता-पिता मानव-पूंजी-कमी वाले बच्चों का पालन-पोषण करते हैं, जिससे निर्धनता बनी रहती है।
निर्धनता के अंतर-पीढ़ीगत संचरण का अर्थ उस चक्र से है जिसमें कठिनाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। निर्धन माता-पिता अपने बच्चों को पर्याप्त पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ होते हैं। इसके परिणामस्वरूप, बच्चे मानव पूंजी के विकास से वंचित रह जाते हैं और वयस्क होने पर पुनः निर्धनता में ही बने रहते हैं।

31. (D) यह निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों में निर्धनता की गहराई या गंभीरता को मापने में विफल रहता है।
सिरगणन अनुपात केवल निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली आबादी के कुल प्रतिशत को मापता है। इस माप की प्राथमिक सीमा यह है कि यह निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों के बीच वंचना की गहराई या गंभीरता में कोई अंतर नहीं करता है। यह यह बताने में असमर्थ है कि वंचना कितनी गहरी और विशाल है।

Click Here to Buy book on Amazon

32. (A) I, II और III
सी. रंगराजन समिति ने निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 2155 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2090 कैलोरी की न्यूनतम आवश्यकता तय की थी। इसमें कपड़े, मकान किराया और गतिशीलता भी शामिल थे। इससे 2011-12 के लिए अखिल भारतीय निर्धनता अनुपात 29.5% अनुमानित हुआ, जो तेंदुलकर समिति के अनुमानों से अधिक था, अतः चौथा कथन गलत सिद्ध होता है।

33. (B) अनौपचारिक श्रमिकों में नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी का अभाव होता है, जिससे संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
शहरी अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक रोजगार का प्रसार शहरी निर्धनता को गहराई से प्रभावित करता है। अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के पास रोजगार अनुबंध, नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा न्यूनतम मजदूरी का अभाव होता है। इसके कारण इन श्रमिकों की आय अत्यंत अनिश्चित और कम होती है, जिससे वे किसी भी आर्थिक झटके में अत्यधिक संवेदनशील बन जाते हैं।

34. (D) बार-बार पड़ने वाला सूखा जिसके कारण चारे और पानी की भारी कमी हो जाती है।
पश्चिमी राजस्थान में बार-बार पड़ने वाला अकाल और सूखा प्राकृतिक परिघटना के रूप में पशुपालकों की आजीविका पर विनाशकारी प्रभाव डालता है। पानी की भीषण कमी और चरागाहों के सूखने से पशुओं के लिए चारे का गंभीर संकट उत्पन्न होता है। इससे पशुधन की हानि होती है और पशुपालकों को विस्थापन करना पड़ता है, जिससे उनकी आजीविका बुरी तरह प्रभावित होती है।

35. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
बहुआयामी निर्धनता सूचकांक केवल आय या उपभोग के आधार पर निर्धनता मापने की तुलना में अधिक व्यापक तथा यथार्थवादी ढांचा प्रदान करता है। केवल आय पर ध्यान देने से गैर-मौद्रिक पहलू छूट जाते हैं। यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन प्रमुख आयामों में एक साथ होने वाले वंचनों की गणना करता है, जो सत्यता उजागर करता है।

36. (C) अप्रत्याशित मरुस्थलीय जलवायु में वर्षा आधारित खेती और पशुधन पर भारी निर्भरता।
पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय जिले क्षणिक अथवा अस्थायी निर्धनता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। इसका मुख्य कारण इस क्षेत्र की अप्रत्याशित मरुस्थलीय जलवायु और कम वर्षा है, जहाँ ग्रामीण आबादी मुख्य रूप से वर्षा आधारित कृषि और पशुपालन पर निर्भर करती है। सामान्य वर्षा वाले वर्षों में ग्रामीण परिवार उबर जाते हैं, किंतु सूखे के समय वे पुनः निर्धन बन जाते हैं।

37. (A) वर्तमान जीवन यापन की उच्च अवसर लागत।
जब कोई परिवार अत्यधिक आर्थिक कठिनाई का सामना करता है, तो उसके लिए वर्तमान अस्तित्व और मूलभूत जीवन यापन की आवश्यकताएं सर्वोपरि बन जाती हैं। वर्तमान जीवन यापन की उच्च अवसर लागत के कारण निर्धन परिवार भविष्य के दीर्घकालिक लाभों, जैसे बच्चों की शिक्षा के स्थान पर उन्हें तत्काल आय हेतु बाल श्रम में लगाने को मजबूर होते हैं। यह गंभीर समस्या है।

38. (D) संरचनात्मक निर्धनता
संरचनात्मक निर्धनता उस स्थिति को संदर्भित करती है जो अर्थव्यवस्था के मूलभूत ढांचे और संस्थागत व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। इसमें तकनीकी प्रगति के कारण कौशल परिवर्तन, पारंपरिक उद्योगों का पतन, तथा संपत्ति का असमान वितरण शामिल हैं। इस प्रकार की निर्धनता दीर्घकालिक होती है और इसे मूलभूत सुधारों द्वारा ही दूर किया जा सकता है।

NODIA

39. (B) बाल मृत्यु दर
वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में जीवन स्तर आयाम के अंतर्गत छह विशिष्ट संकेतक शामिल हैं: खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास और संपत्ति। इसके विपरीत, बाल मृत्यु दर संकेतक को जीवन स्तर आयाम के तहत नहीं बल्कि स्वास्थ्य आयाम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। स्वास्थ्य आयाम में पोषण और बाल मृत्यु दर दोनों शामिल होते हैं।

40. (C) ऐतिहासिक भूमि संकेंद्रण जिसके कारण एक बड़ा भूमिहीन कृषि श्रम बल निर्मित हुआ।
भारत में निर्धनता का एक प्रमुख संरचनात्मक कारण ऐतिहासिक रूप से भूमि का अत्यधिक संकेंद्रण है, जिसके कारण एक विशाल भूमिहीन कृषि श्रमिक वर्ग का निर्माण हुआ। ऐतिहासिक प्रणालियों के कारण अधिकांश भूमि सीमित लोगों के पास रही, जबकि आबादी का बड़ा हिस्सा भूमिहीन रहा। यह भूमिहीनता ग्रामीण क्षेत्रों में आय असुरक्षा और निर्धनता को बढ़ावा देने में सहायक रही है।

41. (D) अपर्याप्त सिंचाई के कारण फसल के मौसम के बाहर कृषि श्रमिकों के पास रोजगार की कमी होती है।
राजस्थान में मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र की प्रकृति और सिंचाई सुविधाओं की भारी कमी से जुड़ी हुई है। राज्य में कृषि अधिकांशतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, जिसके कारण केवल फसल के मौसम के दौरान ही कृषि श्रमिकों को काम मिल पाता है। कटाई समाप्त होने के पश्चात वर्ष के शेष महीनों में वे पूर्णतः बेरोजगार रहने को विवश होते हैं।

42. (A) P-2, Q-4, R-1, S-3
वाई. के. अलघ कार्यदल ने शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 केकेएएल के आधार पर रेखाएं तय कीं। लकड़ावाला समिति ने राज्य-विशिष्ट रेखाएं अनुशंसित कीं। तेंदुलकर समिति ने उपभोग बास्केट में स्वास्थ्य व शिक्षा को जोड़ा। रंगराजन समिति ने संशोधित मानक और व्यवहार परिवर्तन को पुनः शामिल किया। यह वर्गीकरण सटीक एवं तार्किक रूप से उपयुक्त है।

43. (B) यह आकलन करके निर्धनता की गहराई को मापता है कि निर्धन परिवार निर्धनता रेखा से कितना नीचे हैं।
निर्धनता अंतराल सूचकांक को सिरगणन अनुपात की तुलना में अत्यधिक सटीक मापक माना जाता है क्योंकि यह निर्धनता की गहराई का आकलन करता है। सिरगणन अनुपात केवल संख्या बताता है, जबकि निर्धनता अंतराल सूचकांक यह मापता है कि निर्धन व्यक्ति निर्धनता रेखा से औसतन कितने नीचे हैं। यह सूचकांक निर्धनता निवारण हेतु आवश्यक कुल संसाधनों का सटीक संकेत प्रदान करता है।

44. (B) न्यूनतम उत्पादक परिसंपत्तियों के साथ दैनिक मजदूरी पर निर्भर हाशिये पर स्थित अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (ST/SC) समूह।
ग्रामीण राजस्थान में दीर्घकालिक निर्धनता का सामना करने वाले सामाजिक समूहों का प्रोफाइल मुख्यतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों से निर्मित होता है। ये समुदाय ऐतिहासिक रूप से उत्पादक परिसंपत्तियों, उपजाऊ भूमि और शिक्षा से वंचित रहे हैं। इनकी आजीविका मुख्य रूप से अकुशल दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर करती है, जिससे ये लगातार निर्धनता का सामना करते हैं।

45. (A) पुरुषों के प्रवास के कारण महिलाएं अधिक कृषि कार्य करती हैं, लेकिन उनके पास भूमि अधिकारों और ऋण तक पहुंच का अभाव होता है।
राजस्थान के कृषि क्षेत्र में निर्धनता का स्त्रीकरण एक प्रमुख विशेषता के रूप में उभरता है। रोजगार की तलाश में ग्रामीण पुरुषों के प्रवास करने के कारण कृषि कार्यों की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ जाती है। इसके बावजूद, कानूनी बाधाओं के कारण उनके पास भूमि स्वामित्व नहीं होता, जिससे उन्हें संस्थागत ऋण और योजनाओं तक पहुँच नहीं मिल पाती है।

46. (C) मातृ स्वास्थ्य
राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI) ढांचा तीन प्रमुख आयामों - स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर पूरी तरह आधारित है। 'स्वास्थ्य' आयाम के अंतर्गत मुख्य रूप से दो संकेतक शामिल किए जाते हैं: पोषण और मातृ स्वास्थ्य। इसके विपरीत, विद्यालय उपस्थिति शिक्षा आयाम का हिस्सा है, जबकि पीने का पानी तथा बैंक खाता स्वामित्व जीवन स्तर आयाम के अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं।

47. (D) I, II और III
निर्धनता और कुपोषण के बीच एक गहरा चक्रीय संबंध पाया जाता है। निर्धनता के कारण परिवार पोषक तत्वों से युक्त संतुलित आहार खरीदने में असमर्थ होते हैं। कुपोषण के कारण शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, जिससे बीमारियों की आवृत्ति बढ़ती है और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ता है। बीमारियाँ श्रमिकों की उत्पादकता को कम करती हैं, जिससे निर्धनता गहरी होती है।

48. (C) अलग-अलग ग्रामीण और शहरी मौद्रिक रेखाएँ निर्धारित करने के लिए स्थानिक मूल्य सूचकांकों का उपयोग करके।
तेंदुलकर समिति ने संपूर्ण देश के लिए एक समान निर्धनता रेखा बास्केट का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच जीवन यापन की लागत तथा कीमतों में अंतर को समायोजित करने के लिए समिति ने स्थानिक मूल्य सूचकांकों का प्रयोग किया। इस दृष्टिकोण के माध्यम से समिति ने दोनों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मौद्रिक रेखाएं निर्धारित कीं।

49. (B) उत्पादक पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बचत और ऋण पहुंच को बढ़ावा देना।
पूर्ति पक्ष पर निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए अर्थव्यवस्था में बचत दरों को बढ़ाने और संस्थागत ऋण तक पहुंच को सुलभ बनाने की आवश्यकता होती है। जब बचत और ऋण की सुलभता बढ़ती है, तो उत्पादक क्षेत्रों में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। अधिक निवेश से उत्पादकता और रोजगार बढ़ते हैं, जिससे आय में वृद्धि होती है।

50. (D) राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की गणना के लिए प्रमुख संकेतकों को प्राप्त करना।
भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षण (NFHS) द्वारा एकत्रित किए गए व्यापक आंकड़ों का प्रयोग मुख्य रूप से राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के निर्माण हेतु किया जाता है। नीति आयोग इस सर्वेक्षण के माध्यम से पोषण, मातृ स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के विभिन्न संकेतकों के विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करके देश में निर्धनता का अत्यंत सटीक बहुआयामी आकलन तैयार करता है।

51. (A) कृषि भूमि जोतों का गंभीर विखंडन
कृषि भूमि जोतों का अत्यधिक विखंडन और उप-विभाजन स्पष्ट रूप से ग्रामीण निर्धनता का एक मुख्य कारण है, न कि शहरी निर्धनता का। इसके विपरीत, शहरी क्षेत्रों में निर्धनता मुख्यतः अनियंत्रित ग्रामीण-शहरी प्रवास, पर्याप्त आवास सुविधाओं की कमी, बुनियादी स्वच्छता के अभाव तथा औपचारिक क्षेत्र में नियमित और सुरक्षित रोजगार के अवसरों की भारी कमी के कारण उत्पन्न होती है।

52. (A) I, III और IV
वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI) में कुल 10 संकेतक शामिल हैं। 'शिक्षा' आयाम के तहत स्कूली शिक्षा के वर्ष और उपस्थिति शामिल हैं। 'स्वास्थ्य' आयाम में पोषण तथा बाल मृत्यु दर शामिल हैं। 'जीवन स्तर' आयाम के तहत विद्युत, स्वच्छता, जल, आवास और परिसंपत्तियां शामिल हैं। मातृ मृत्यु दर इस सूचकांक के प्रत्यक्ष संकेतकों में शामिल नहीं की गई है, अतः यह स्पष्ट है।

53. (A) राजस्थान को अलग-अलग क्षेत्रीय निर्धनता चालकों को संबोधित करने के लिए लक्षित क्षेत्र योजनाओं की आवश्यकता है।
राजस्थान एक विशाल और भौगोलिक तथा सामाजिक रूप से अत्यंत विविधतापूर्ण राज्य है, जहाँ पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र और मैदानी भाग विद्यमान हैं। प्रत्येक

Downloaded from www.pdf.tube

23. राजस्थान में बेरोजगारी का एक कारण धीमी औद्योगिक वृद्धि है। इस धीमी वृद्धि का प्रत्यक्ष परिणाम निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) कारखाने के रोजगार की तलाश में पड़ोसी राज्यों से अत्यधिक कुशल औद्योगिक श्रम का व्यापक, निरंतर आगमन
(B) सभी ग्रामीण क्षेत्रों में संरचनात्मक और मौसमी बेरोजगारी का पूर्ण उन्मूलन
(C) राज्य सरकार के कर राजस्व और पूंजी भंडार में उत्पन्न तत्काल, अभूतपूर्व अधिशेष
(D) गैर-कृषि रोजगार का अपर्याप्त सृजन, जिससे कृषि पर दबाव बढ़ता है

24. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): कौशल बेमेल राजस्थान में युवाओं के बीच शिक्षित बेरोजगारी का एक महत्वपूर्ण कारण है।
कारण (R): कई डिग्री पाठ्यक्रमों का शैक्षणिक पाठ्यक्रम व्यावसायिक प्रशिक्षण और वर्तमान उद्योग की आवश्यकताओं को पर्याप्त रुप से एकीकृत नहीं करता है।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

25. भारत में वर्तमान में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) आयोजित करने के लिए कौन-सा संगठन उत्तरदायी है?
(A) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.)
(B) नीति आयोग
(C) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.)
(D) केवल श्रम और रोजगार मंत्रालय

26. ऐतिहासिक रूप से, बेरोजगारी से निपटने के लिए रोजगार कार्यालयों की स्थापना की गई थी। हाल के वर्षों में उनकी प्रासंगिकता घटने का प्राथमिक कारण क्या रहा है?
(A) उन्होंने प्रत्येक पंजीकृत उम्मीदवार को सफलतापूर्वक और लगातार स्थायी सरकारी रोजगार प्रदान किया
(B) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा सभी राज्यों में उन्हें आधिकारिक और स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था
(C) उनका संस्थागत वैधानिक जनादेश केवल भूमिहीन कृषि श्रमिकों को संगठित करने तक सीमित था
(D) डिजिटल पोर्टल और परिसर भर्ती के माध्यम से निजी भर्ती की ओर बदलाव

27. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसे पहले के पंचवार्षिक सर्वेक्षणों के स्थान पर उच्च-आवृत्ति वाले रोजगार आंकड़े प्रदान करने के लिए शुरु किया गया था।
II. यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान उत्पन्न करता है।
III. यह केवल स्नातकोत्तर डिग्री या उससे उच्च डिग्री वाले व्यक्तियों का सर्वेक्षण करता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) I और II दोनों
(D) I, II और III

28. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में "रोजगारहीन वृद्धि" शब्द का क्या अर्थ है?
(A) एक गंभीर राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी जो सीधे तौर पर सभी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर छंटनी का कारण बनती है
(B) आनुपातिक रोजगार विस्तार के बिना होने वाली आर्थिक वृद्धि
(C) सिकुड़ते राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के बावजूद लगातार हासिल की जाने वाली असामान्य रूप से उच्च रोजगार दरें
(D) सभी सार्वजनिक और निजी उद्यमों में औपचारिक क्षेत्र के कार्यबल की पूर्ण और अत्यधिक गिरावट

29. अल्प-रोजगार बेरोजगारी से मुख्य रूप से इसलिए भिन्न है क्योंकि अल्प-नियोजित व्यक्ति:
(A) प्रतिदिन सक्रिय रूप से लाभकारी रोजगार की तलाश कर रहा है लेकिन कोई भी रोजगार पाने में पूरी तरह असमर्थ रहता है
(B) अपने कौशल स्तर से नीचे की भूमिका में या अपर्याप्त घंटों के लिए काम करता है
(C) वैधानिक आयु सीमाओं के कारण कानूनी रूप से निर्दिष्ट कार्यशील-आयु समूह से पूरी तरह बाहर है
(D) किसी भी उत्पादक बाजार-आधारित आर्थिक गतिविधि में भाग न लेने या संलग्न न होने का स्वैच्छिक विकल्प चुनता है

30. संरचनात्मक बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह अर्थव्यवस्था की मूलभूत संरचना में परिवर्तनों के कारण होती है।
II. इसे हल करने के लिए अक्सर कार्यबल के दीर्घकालिक पुनः प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
III. तकनीकी बदलाव और स्वचालन इस प्रकार की बेरोजगारी के प्रमुख कारक हैं।
IV. यह केवल रोजगार में परिवर्तन के दौरान कुछ हफ्तों तक रहने वाली एक अल्पकालिक परिघटना है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) I, II और III
(B) II, III और IV

NODIA

सर्वोच्च दर्ज की गई थी, इसके बाद ओडिशा दूसरे स्थान पर था, तत्पश्चात राजस्थान तीसरे स्थान पर था, और केरल में निर्धनता दर सबसे कम दर्ज की गई थी। यह सही क्रम है।

65. (B) एक उत्पादक औपचारिक क्षेत्र और एक संवेदनशील अनौपचारिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व।
शहरी अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रकृति शहरी निर्धनता का एक प्रमुख संरचनात्मक कारण है। यह अवधारणा इस बात को रेखांकित करती है कि आधुनिक शहरों में दो क्षेत्र एक साथ विद्यमान रहते हैं: पहला, उच्च मजदूरी और सुरक्षा वाला औपचारिक क्षेत्र; तथा दूसरा, निम्न मजदूरी, असुरक्षित नौकरियों और सामाजिक सुरक्षा के अभाव वाला एक विशाल संवेदनशील अनौपचारिक क्षेत्र जो निर्धनता बढ़ाता है।

66. (D) पानी की भारी कमी और ऐतिहासिक ढांचागत कमियां
राजस्थान में औद्योगीकरण की गति को धीमा करने और परिणामस्वरूप निर्धनता को बढ़ाने में जल संसाधनों की भीषण कमी तथा अवसंरचनात्मक कमियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। राज्य में देश के कुल सतही जल का केवल 1.16 प्रतिशत उपलब्ध है। जल कमी और ढांचागत कमियों के कारण बड़े उद्योगों की स्थापना बाधित हुई है, जिससे रोजगार के अवसर सीमित हो गए हैं।

67. (D) I, II और III
'निर्धनता के स्त्रीकरण' की अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि वैश्विक स्तर पर निर्धन जनसंख्या का एक बड़ा और असमान अनुपात महिलाओं का है। यह स्थिति संपत्ति के अधिकारों तक सीमित पहुँच, भेदभावपूर्ण उत्तराधिकार कानूनों तथा आय उत्पादक कार्यों से दूरी के कारण होती है। इसके अतिरिक्त, अवैतनिक घरेलू कार्यों का बोझ उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होने देता है।

68. (C) आधुनिक क्षेत्रों में विकास स्वास्थ्य, शिक्षा और परिसंपत्तियों की कमी वाले हाशिये पर स्थित समूहों तक पहुँचने में विफल रहता है।
विकास के 'टपकन प्रभाव' का सिद्धांत यह मानता है कि उच्च आर्थिक वृद्धि का लाभ स्वतः ही समाज के निचले तबके तक पहुँच जाएगा। हालाँकि, यह सिद्धांत व्यावहारिक रूप से अपर्याप्त सिद्ध होता है क्योंकि केवल आर्थिक वृद्धि से हाशिये पर रह रहे लोगों की कमियां दूर नहीं होतीं। शिक्षा, स्वास्थ्य और संपत्ति विहीन समूह विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं।

69. (A) बुनियादी अस्तित्व के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का एक बास्केट।
निरपेक्ष निर्धनता को मापने के संदर्भ में, "निर्धनता रेखा बास्केट" वस्तुओं और सेवाओं के उस न्यूनतम समूह का प्रतिनिधित्व करती है जो किसी व्यक्ति या परिवार के न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए अनिवार्य मानी जाती हैं। इसमें न्यूनतम कैलोरी देने वाले खाद्य पदार्थ तथा वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी बुनियादी गैर-खाद्य मदें शामिल की जाती हैं।

70. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
निरपेक्ष और सापेक्ष निर्धनता के बीच का संबंध यह दर्शाता है कि निरपेक्ष निर्धनता कम होने पर भी सापेक्ष निर्धनता बढ़ सकती है। ऐसा तब होता है जब आर्थिक विकास से निचले तबके की आय बढ़कर न्यूनतम सीमा से ऊपर चली जाती है, किंतु उच्च आय वर्ग की आय में अत्यधिक वृद्धि होने से आय विषमता विस्तृत हो जाती है। यह तर्क पूर्णतः सत्य है।

71. (B) नौकरियों की कमी श्रमिकों को आकस्मिक दैनिक श्रम करने के लिए मजबूर करती है, जिससे कम और अनियमित आय प्राप्त होती है।
शहरों में नियमित और औपचारिक नौकरियों की कमी तथा बेरोजगारी सीधे तौर पर शहरी निर्धनता को बढ़ावा देती है। जब श्रमिकों को स्थायी रोजगार नहीं मिलता, तो वे आजीविका हेतु अनौपचारिक क्षेत्र में आकस्मिक दिहाड़ी मजदूरी या कम वेतन वाले कार्यों को करने को विवश होते हैं। इसके परिणामस्वरूप उनकी आय कम और अस्थिर रहती है, जो निर्धनता को बढ़ाती है।

72. (B) I, III और IV
दीर्घकालिक निर्धनता प्रायः संरचनात्मक और अंतर-पीढ़ीगत होती है, जिसके निवारण हेतु संपत्ति निर्माण तथा शिक्षा जैसे दीर्घकालिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, क्षणिक निर्धनता मौसमी झटकों के कारण होती है, जिसे सामाजिक सुरक्षा तथा बीमा द्वारा दूर किया जा सकता है। एकल सर्वेक्षण द्वारा क्षणिक निर्धनता का सटीक आकलन कठिन होने के कारण द्वितीय कथन अशुद्ध सिद्ध होता है।

73. (D) आय-आधारित रेखाओं से बहुआयामी निर्धनता सूचकांकों की ओर बढ़ना।
वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय निर्धनता मापन सुधारों का मुख्य ध्यान केवल आय या उपभोग-आधारित एकआयामी रेखाओं के स्थान पर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI) दृष्टिकोण को अपनाने पर केंद्रित है। यह दृष्टिकोण स्वीकार करता है कि निर्धनता केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य, शिक्षा और सुविधाओं से वंचित रहने की एक व्यापक स्थिति को दर्शाता है।

74. (A) बिहार
नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक रिपोर्टों के अनुसार, भारत में बिहार राज्य लगातार अपनी कुल जनसंख्या के उच्चतम अनुपात के बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन करने की रिपोर्ट करता है। यद्यपि हाल के वर्षों में बिहार ने निर्धनता घटाने में प्रगति की है, फिर भी विभिन्न संकेतकों में वंचना की उच्च दर के कारण यह शीर्ष पर है।

75. (B) आयु, लिंग और गतिविधि के स्तर के आधार पर कैलोरी, प्रोटीन और वसा के लिए ICMR मानकों को लागू करना।
सी. रंगराजन समिति ने निर्धनता रेखा के खाद्य घटक के वैज्ञानिक निर्धारण हेतु ICMR द्वारा अनुशंसित पोषण मानकों का प्रयोग किया। समिति ने व्यक्ति की आयु, लिंग और गतिविधि के स्तर

Click Here to Buy book on Flipkart

के आधार पर कैलोरी, प्रोटीन और वसा की आवश्यकताओं को शामिल किया। इसके आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 2155 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों हेतु 2090 कैलोरी तय की गई।

76. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में शून्य सीमांत उत्पादकता वाले अत्यधिक रोजगार को दर्शाती है। निर्धनता का दुष्चक्र एक स्व-सुदृढ़ीकरण चक्र है जो पूंजी निर्माण को रोकता है। बहुआयामी वंचना स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के अभाव द्वारा निर्धनता मापती है। कैलोरी एंकर भारत में निरपेक्ष निर्धनता रेखा को परिभाषित करने का ऐतिहासिक आधार रहा है, अतः यह कूट सही है।

77. (A) पूंजी-गहन कृषि मशीनरी पर अत्यधिक निर्भरता।
भारत में सीमांत और छोटे किसानों के पास वित्तीय संसाधनों की अत्यधिक कमी होती है, जिसके कारण वे पूंजी-गहन भारी कृषि मशीनरी पर निर्भर नहीं हो पाते हैं। इसके विपरीत, सीमांत किसानों में निम्न कृषि उत्पादकता के प्राथमिक कारणों में भूमि का निरंतर विखंडन, मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, तथा संस्थागत ऋण की अनुपलब्धता मुख्य रुप से शामिल हैं। यह स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है।

78. (C) निर्धनता संस्थागत संरचनाओं से उत्पन्न होती है जो असमान परिसंपत्ति और सत्ता वितरण को बढ़ावा देती हैं।
विकासशील देशों में निर्धनता के कारणों पर "संरचनावादी" दृष्टिकोण यह प्रतिपादित करता है कि निर्धनता व्यक्तिगत कमियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह समाज की मूलभूत संस्थागत, आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं की देन है। यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि संपत्ति के असमान वितरण, सत्ता संरचनाओं तथा अवसरों की असमानता के कारण लोग निर्धनता में बने रहते हैं। यह प्रमुख निष्कर्ष है।

79. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
निर्धन परिवारों के भीतर भी संसाधनों का आवंटन लैंगिक आधार पर असमान होता है। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाओं के कारण परिवारों के भीतर उपलब्ध भोजन, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के वितरण में प्रायः पुरुष सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके परिणामस्वरुप, निर्धनता में रहने वाली महिलाएं उसी परिवार के पुरुषों की तुलना में अधिक कुपोषण का सामना करती हैं।

NODIA

80. (C) वे प्रति हेक्टेयर फसल की पैदावार को घटाते हैं, जिससे कृषि आय कम होती है और ग्रामीण निर्धनता बढ़ती है।
ग्रामीण राजस्थान में भूमि निम्नीकरण, मरुस्थलीकरण और मृदा लवणता गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं हैं जो सीधे तौर पर क्षेत्रीय निर्धनता चक्र को सुदृढ़ करती हैं। मिट्टी की उर्वरता में गिरावट और लवणता वृद्धि के कारण प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता घट जाती है। कम उपज के कारण किसानों की आय में गिरावट आती है, जिससे ग्रामीण परिवार निर्धनता में जकड़े रहते हैं।

अध्याय 22

बेरोज़गारी : अवधारणा, प्रकार एवं कारण

NODIA

1. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प बेरोजगारी की मानक आर्थिक अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है?
(A) ऐसी स्थिति जहाँ पर्याप्त योग्यता होने के बावजूद व्यक्ति काम न करने का विकल्प चुनते हैं
(B) ऐसी स्थिति जहाँ कार्यशील आयु वाली आबादी पूरी तरह से असंगठित क्षेत्र में लगी हुई है
(C) ऐसी स्थिति जहाँ श्रम बल के वे सदस्य जो काम करने के इच्छुक और सक्षम हैं, लाभकारी रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं
(D) ऐसा परिदृश्य जहाँ श्रमिक नियोजित तो हैं लेकिन उन्हें कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी मिलती है

2. किसी क्षेत्र के श्रम बल की गणना निम्नलिखित में से किन समूहों को शामिल करके की जाती है?
(A) केवल वे व्यक्ति जो वर्तमान में औपचारिक क्षेत्र में नियोजित हैं
(B) नियोजित व्यक्ति तथा वे बेरोजगार व्यक्ति जो सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे हैं
(C) 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच क्षेत्र की संपूर्ण जनसंख्या
(D) केवल वे व्यक्ति जिनके पास स्नातक की डिग्री या उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण है

3. मौसमी बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में फसलों की बुआई और कटाई की चक्रीय प्रकृति के कारण होती है।
कथन II: इसका अर्थ है कि पूरे कैलेंडर वर्ष के दौरान श्रमिक की सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

4. प्रच्छन्न (अदृश्य) बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह तब होती है जब इष्टतम उत्पादन के लिए वास्तव में आवश्यक लोगों की तुलना में अधिक लोग काम में लगे होते हैं।
II. अधिशेष श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता मूलतः शून्य या ऋणात्मक होती है।
III. भारत में, यह सबसे अधिक भारी विनिर्माण और आई.टी. क्षेत्रों में देखी जाती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I
(B) I और II दोनों
(C) II और III दोनों
(D) I, II और III

5. जब कोई श्रमिक किसी अन्य अधिक उपयुक्त रोजगार की तलाश के लिए अपना वर्तमान रोजगार छोड़ देता है, तो इस संक्रमणकालीन चरण के दौरान किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है?
(A) संरचनात्मक बेरोजगारी
(B) चक्रीय बेरोजगारी
(C) घर्षणात्मक बेरोजगारी
(D) प्रच्छन्न बेरोजगारी

6. चक्रीय बेरोजगारी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समष्टि आर्थिक कारक से प्रेरित होती है?
(A) अर्थव्यवस्था में चक्रीय मंदी जिसके कारण सकल मांग में कमी आती है
(B) संरचनात्मक तकनीकी प्रगति जो कारखानों में शारीरिक श्रमिकों को प्रतिस्थापित करती है
(C) कृषि कार्यों में मौसमी बदलाव जो ग्रामीण श्रम मांग को कम करते हैं
(D) राज्य की सीमाओं के पार श्रम बल की निरंतर भौगोलिक गतिहीनता

7. सूची I में दी गई बेरोजगारी के प्रकारों को सूची II में उनकी प्रमुख विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: (बेरोजगारी का प्रकार)
P. घर्षणात्मक बेरोजगारी
Q. संरचनात्मक बेरोजगारी
R. चक्रीय बेरोजगारी
S. मौसमी बेरोजगारी
सूची II: (विशेषता)
1. उपलब्ध कौशल और बाजार की आवश्यकताओं के बीच बेमेल होना
2. एक रोजगार से दूसरे रोजगार में परिवर्तन के कारण बेरोजगारी
3. सामान्य आर्थिक मंदी के कारण रोजगार का जाना
4. कृषि चक्र के विशिष्ट महीनों के दौरान बेरोजगारी
निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित है?
(A) P-2, Q-1, R-3, S-4

क्षेत्र में निर्धनता के मुख्य कारण अलग-अलग हैं, जैसे पश्चिम में शुष्कता तथा दक्षिण में जनजातीय पिछड़ापन। इसलिए, एक समरूप नीति के स्थान पर क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु लक्षित क्षेत्रीय योजनाएं बनाना अनिवार्य होता है।

54. (A) निम्न उत्पादकता → निम्न आय → निम्न मांग (क्रय शक्ति) → निम्न निवेश
मांग पक्ष पर निर्धनता के दुष्चक्र की तार्किक श्रृंखला इस प्रकार विकसित होती है: सर्वप्रथम, किसी अर्थव्यवस्था में अकुशल तकनीकों के कारण निम्न उत्पादकता होती है, जिससे श्रमिकों की निम्न आय उत्पन्न होती है। कम आय के कारण बाजार में वस्तुओं के लिए निम्न मांग (क्रय शक्ति) निर्मित होती है। सीमित मांग के फलस्वरूप कम निवेश होता है, जो पुनः उत्पादकता घटाता है।

55. (B) सामान्यतः घटा है, जबकि निर्धन लोगों की निरपेक्ष संख्या महत्वपूर्ण बनी हुई है।
हाल के दशकों में ऐतिहासिक आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में सामान्यतः महत्वपूर्ण गिरावट आई है। हालांकि, जनसंख्या वृद्धि और धीमी गतिशीलता के कारण राज्य में निर्धन लोगों की कुल निरपेक्ष संख्या अभी भी काफी बनी हुई है। यह स्थिति चुनौती को रेखांकित करती है।

56. (C) सेवा स्थल पर स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को प्रत्यक्ष भुगतान, जो अक्सर परिवारों को कर्ज में धकेल देता है।
स्वास्थ्य अर्थशास्त्र के संदर्भ में निजी व्यय का तात्पर्य उस प्रत्यक्ष भुगतान से है जो एक परिवार को चिकित्सा सेवाओं, औषधियों तथा परीक्षणों के लिए सीधे अपनी बचत से करना पड़ता है। बीमा कवरेज के अभाव में यह अनपेक्षित और भारी स्वास्थ्य व्यय कम आय वाले परिवारों की वित्तीय स्थिति को बिगाड़ता है और उन्हें गंभीर कर्ज में धकेल देता है।

57. (D) यह निर्भरता अनुपात को बढ़ाती है और प्रति व्यक्ति पूंजी तथा संसाधन उपलब्धता को कम करती है।
तीव्र जनसंख्या वृद्धि भारत में निर्धनता के एक प्रमुख संरचनात्मक कारण के रूप में कार्य करती है क्योंकि यह परिवारों में निर्भरता अनुपात को बढ़ा देती है। जब आश्रितों की संख्या बढ़ती है, तो अर्जित आय का बड़ा हिस्सा केवल उपभोग में व्यतीत होता है, जिससे बचत घटती है। इसके अतिरिक्त, प्रति व्यक्ति पूंजी और संसाधन उपलब्धता में कमी आती है।

58. (A) क्षणिक/अस्थायी निर्धनता
एक व्यक्ति जो सामान्य परिस्थितियों में अपनी नियमित आजीविका के माध्यम से निर्धनता रेखा से ऊपर रहता है, किंतु गंभीर सूखे, प्राकृतिक आपदा या बीमारी के कारण अस्थाई रूप से निर्धनता रेखा से नीचे चला जाता है, वह क्षणिक अथवा अस्थायी निर्धनता का सामना कर रहा होता है। परिस्थितियाँ सामान्य होते ही वह पुनः ऊपर उठने में सक्षम होता है।

59. (B) कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) का उपयोग करके।
डी. टी. लकड़ावाला विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियों के अनुसार, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राज्य-विशिष्ट निर्धनता रेखाओं को समय-समय पर अद्यतन करने हेतु मूल्य परिवर्तनों का समायोजन विशेष रूप से कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) के आधार पर किया गया था। वहीं दूसरी ओर, शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों के सूचकांक का प्रयोग किया गया था।

60. (B) बाल श्रम से वर्तमान जीवन यापन आय और स्कूली शिक्षा से भविष्य के लाभों के बीच का संतुलन/समझौता
ग्रामीण राजस्थान में निर्धनता और शिक्षा का परस्पर संबंध एक गंभीर आर्थिक दुविधा को उजागर करता है। अति-निर्धन परिवारों के सामने यह बुनियादी आर्थिक समझौता होता है कि वे अपने बच्चों को बाल श्रम में लगाकर तात्कालिक जीवन यापन के लिए आय अर्जित करें या उन्हें शिक्षा भेजकर भविष्य के दीर्घकालिक लाभों का चयन करें। निर्धनता तात्कालिक मजबूरी बढ़ाती है।

61. (A) इसने लकड़ावाला के अनुमानों की तुलना में निर्धनता सिरगणन अनुपात में तेजी से कमी की।
तेंदुलकर समिति की कार्यप्रणाली के संदर्भ में यह कथन गलत है कि इसने लकड़ावाला के अनुमानों की तुलना में निर्धनता दर में कमी की। वास्तव में, तेंदुलकर समिति द्वारा अपनाई गई व्यापक उपभोग बास्केट के कारण वर्ष 2004-05 के लिए भारत का निर्धनता अनुपात लकड़ावाला समिति के 27.5% के अनुमान से बढ़कर 37.2% हो गया था। अतः यह असत्य कथन है।

62. (A) P-4, Q-1, R-3, S-2
राजस्थान में शुष्कता से उत्पन्न निर्धनता का प्रत्यक्ष उदाहरण बाड़मेर जैसे शुष्क जिलों में गर्मी और वर्षा की कमी के कारण बार-बार फसल का नष्ट होना है। सामाजिक असमानता जनजातियों में उच्च निर्धनता से दिखती है। उद्योगों की कमी एक संरचनात्मक कारण है, जबकि खराब मानसून से किसान का ऋणग्रस्त होना क्षणिक निर्धनता को दर्शाता है। यह सही सुमेलित है।

63. (D) कार्य करने और अपनी पसंद का जीवन जीने की बुनियादी क्षमताओं का अभाव
नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का निर्धनता का 'क्षमता दृष्टिकोण' निर्धनता को केवल आय की कमी के रूप में देखने के बजाय मानव जीवन की मूलभूत क्षमताओं के वंचन के रूप में परिभाषित करता है। अमर्त्य सेन के अनुसार, निर्धनता वास्तव में किसी व्यक्ति की अपनी पसंद का जीवन जीने और सक्रिय भाग लेने की मौलिक क्षमताओं की कमी की स्थिति है।

64. (A) I, IV, II, III
तेंदुलकर समिति की कार्यप्रणाली पर आधारित वर्ष 2011-12 के निर्धनता आंकड़ों के अनुसार, प्रस्तुत राज्यों में निर्धनता दर का घटता हुआ अनुक्रम इस प्रकार है: बिहार में निर्धनता दर

Downloaded from www.pdf.tube

(C) गैर-कृषि आर्थिक क्षेत्रों में श्रम बल का विस्तार रोजगार सृजन की तुलना में अधिक तेजी से होता है
(D) उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की रोजगार श्रेणियों में सीधे समय से पहले अनिवार्य सेवानिवृत्ति नीतियां लागू होती हैं

16. घर्षणात्मक बेरोजगारी का सामना करने और उसे हल करने वाले श्रमिक के तार्किक क्रम में निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित कीजिए:
1. कौशल को अद्यतन करना और पेशेवर रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण करना।
2. बेहतर भौगोलिक संभावनाओं की तलाश के लिए वर्तमान रोजगार से त्यागपत्र देना।
3. एक नए रोजगार प्रस्ताव को स्वीकार करना और सक्रिय कार्यबल में पुनः प्रवेश करना।
4. कई हफ्तों तक साक्षात्कार में भाग लेना और शर्तों पर बातचीत करना।

निम्नलिखित में से कौन-सा सही क्रम है?
(A) 2, 1, 4, 3
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 4, 1, 3
(D) 4, 1, 2, 3

17. राजस्थान में असंगठित क्षेत्र अक्सर ऐसी विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जो वास्तविक बेरोजगारी को छिपाती हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा इसका सर्वोत्तम वर्णन करता है?
(A) असंगठित क्षेत्र का रोजगार लगातार कठोर आजीवन रोजगार अनुबंध प्रदान करता है जो अचानक रोजगार की हानि को पूरी तरह से रोकता है
(B) अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम केवल औपचारिक रूप से प्रशिक्षित विश्वविद्यालय स्नातकों को काम पर रखते हैं, जिससे कौशल बेमेल समाप्त हो जाता है
(C) श्रमिकों का कम मजदूरी वाले रोजगार में समावेशन औपचारिक रोजगार के बजाय अल्प-रोजगार को दर्शाता है
(D) असंगठित क्षेत्र अपने संपूर्ण दैनिक रोजगार आंकड़ों को सीधे पी.एल.एफ.एस. को प्रेषित करता है

18. ग्रामीण राजस्थान से पड़ोसी औद्योगिक राज्यों में युवाओं के बहिर्प्रवासन को बेरोजगारी के प्रति प्राथमिक रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया के रूप में वर्गीकृत किया गया है?
(A) शहरी घनत्व को संतुलित करने के उद्देश्य से एक राज्य-अनिवार्य जनसांख्यिकीय पुनर्वितरण कार्यक्रम
(B) अपर्याप्त स्थानीय गैर-कृषि रोजगार के कारण उत्पन्न सामंजस्य की रणनीति
(C) विशेष रूप से उच्च कृषि कौशल प्राप्त करने के उद्देश्य से एक पूरी तरह से स्वैच्छिक मौसमी आवाजाही
(D) अत्यधिक स्थानीय औद्योगिक क्षमता का एक अप्रत्याशित परिणाम जिसके लिए विशेष बाहरी बाजारों की आवश्यकता होती है

19. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में रोजगार स्थिति को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली संदर्भ अवधियों का सबसे लंबी संदर्भ अवधि से सबसे छोटी संदर्भ अवधि तक का सही क्रम दर्शाता है?
(A) वर्तमान दैनिक स्थिति, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, सामान्य प्रमुख स्थिति
(B) सामान्य प्रमुख स्थिति, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, वर्तमान दैनिक स्थिति
(C) वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, सामान्य प्रमुख स्थिति, वर्तमान दैनिक स्थिति
(D) सामान्य प्रमुख स्थिति, वर्तमान दैनिक स्थिति, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति

20. आने वाले दशक में कपड़ा और विनिर्माण जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में संरचनात्मक बेरोजगारी का सबसे बड़ा जोखिम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है?
(A) स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को तेजी से अपनाना
(B) न्यूनतम कृषि समर्थन मूल्यों में वृद्धि
(C) कुल कार्यशील आयु वाली आबादी में अचानक कमी
(D) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का विस्तार

21. सूची I की रोजगार अवधारणाओं को सूची II की उनकी सटीक परिभाषाओं के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: (रोजगार अवधारणा)
P. श्रम बल
Q. कार्य बल
R. बेरोजगार
S. श्रम बल से बाहर

सूची II: (परिभाषा)
1. वर्तमान में आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए व्यक्ति
2. वे व्यक्ति जो न तो काम कर रहे हैं और न ही काम की तलाश कर रहे हैं
3. वे व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक और सक्षम हैं लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है
4. नियोजित और बेरोजगार व्यक्तियों का योग

निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित है?
(A) P-4, Q-1, R-3, S-2
(B) P-1, Q-4, R-3, S-2
(C) P-4, Q-2, R-3, S-1
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

NODIA

22. भारत में कृषि अल्प-रोजगार निम्नलिखित में से किस अवधारणा का सबसे निकटतम समानार्थी है?
(A) प्रच्छन्न बेरोजगारी
(B) घर्षणात्मक बेरोजगारी
(C) खुली बेरोजगारी
(D) चक्रीय बेरोजगारी

(B) P-1, Q-2, R-4, S-3
(C) P-2, Q-3, R-1, S-4
(D) P-3, Q-1, R-2, S-4

8. खुली बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी से मौलिक रुप से किस प्रकार भिन्न है?
(A) खुली बेरोजगारी में सभी क्षेत्रों में शून्य सीमांत उत्पादकता होती है, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी में ऋणात्मक उत्पादकता होती है
(B) खुली बेरोजगारी स्पष्ट रुप से दिखाई देती है क्योंकि व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी में व्यक्ति नियोजित प्रतीत होता है
(C) खुली बेरोजगारी केवल ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में होती है, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी केवल एक शहरी परिघटना है
(D) खुली बेरोजगारी शिक्षित युवाओं के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक है, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी राज्य के श्रम बाजार कानूनों द्वारा थोपी जाती है

9. राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारी को मुख्य रुप से निम्नलिखित में से किस परिदृश्य द्वारा अभिलक्षित किया जाता है?
(A) ग्रामीण युवाओं में बुनियादी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की व्यापक कमी, जिससे वे सीधे रोजगार के अयोग्य हो जाते हैं
(B) उच्च शिक्षित श्रम की अभूतपूर्व बाजार मांग के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक राज्य श्रम कानून जो कॉर्पोरेट भर्ती को रोकते हैं
(C) डिग्री धारक युवाओं का अधिशेष जिनकी योग्यताएं उद्योग की कौशल आवश्यकताओं से मेल नहीं खाती हैं
(D) जिलों में उच्च शिक्षण संस्थानों की पूर्ण संरचनात्मक कमी, जो उत्पादित स्नातकों की कुल संख्या को सीमित करती है

10. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): प्रच्छन्न बेरोजगारी में अधिशेष श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है।
कारण (R): प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामना कर रहे किसी कृषि खेत से कार्यबल के एक हिस्से को हटाने पर भी कुल कृषि उत्पादन कम नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

11. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) कार्यप्रणाली के तहत, किसी व्यक्ति को सामान्य प्रमुख स्थिति (यू.पी.एस.) के आधार पर तब नियोजित माना जाता है जब वह किस संदर्भ अवधि के अधिकांश समय के दौरान किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न था?
(A) पिछले 7 दिन
(B) पिछले 30 दिन
(C) पिछले 365 दिन
(D) पिछले 5 वर्ष

12. बेरोजगारी मापने में वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सी.डब्ल्यू.एस.) दृष्टिकोण द्वारा मापा जाने वाला प्राथमिक मापदंड क्या है?
(A) पिछले 365 दिनों की संदर्भ अवधि में किसी व्यक्ति की गतिविधि स्थिति
(B) पिछले 7 दिनों की संदर्भ अवधि में किसी व्यक्ति की गतिविधि स्थिति
(C) किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त रोजगार की कुल आजीवन अवधि
(D) आगामी कृषि सत्र के लिए किसी श्रमिक की अनुमानित रोजगार स्थिति

13. भारत में बेरोजगारी के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. तीव्र जनसंख्या वृद्धि श्रम बल का विस्तार उस गति से अधिक तेजी से करती है जितनी तेजी से अर्थव्यवस्था रोजगार सृजित कर सकती है।
II. धीमी औद्योगिक वृद्धि के कारण रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ती है।
III. आधुनिक शिक्षा प्रणाली वर्तमान औद्योगिक कौशल आवश्यकताओं के साथ पूरी तरह से सुसंगत है, जिससे कौशल बेमेल न्यूनतम होता है।
IV. कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी बेरोजगारी के वास्तविक स्तर को छिपाती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) I, II और IV
(B) II, III और IV
(C) I, III और IV
(D) केवल I और II

14. "युवा बेरोजगारी दर" निर्धारित करने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर किस विशिष्ट जनसांख्यिकीय समूह का विश्लेषण किया जाता है?
(A) 10 से 14 वर्ष
(B) 15 से 29 वर्ष
(C) 30 से 45 वर्ष
(D) 45 से 60 वर्ष

15. वह परिघटना जहाँ जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी के प्राथमिक कारण के रूप में कार्य करती है, निम्नलिखित में से किस गतिशीलता द्वारा सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट की जाती है?
(A) तीव्र जनसंख्या वृद्धि पूरी अर्थव्यवस्था में सकल उपभोग मांग और घरेलू बचत को लगातार कम करती है
(B) बढ़ती जनसंख्या सभी भारी विनिर्माण उद्योगों में पूंजी-श्रम अनुपात को सीधे बढ़ाती है

Click Here to Buy book on Amazon

(C) I, III और IV
(D) I, II और IV

31. राजस्थान में महिला श्रम बल भागीदारी दर (एल.एफ.पी.आर.) अक्सर मापन दृष्टिकोण के आधार पर महत्वपूर्ण भिन्नता दर्शाती है। कौन-सा कारक इस विसंगति को अत्यधिक प्रभावित करता है?
(A) अधिकांश कामकाजी महिलाएं उच्च तकनीक वाले शहरी स्टार्टअप में लगी हुई हैं जिनका सर्वेक्षण करना आधिकारिक राज्य एजेंसियों के लिए कठिन है
(B) सख्त वैधानिक प्रतिबंध जो ग्रामीण महिलाओं को किसी भी खेत-आधारित कृषि श्रम में भाग लेने से कानूनी रूप से रोकते हैं
(C) अवैतनिक कृषि पारिवारिक कार्य को अक्सर आर्थिक संकेतकों से बाहर रखा जाता है
(D) राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में महिला कार्यबल की भागीदारी की पूर्ण अनुपस्थिति

32. कौशल बेमेल के संदर्भ में, राजस्थान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारण से आलोचना का सामना करते हैं?
(A) अत्यधिक संख्या में उच्च विशिष्ट एयरोस्पेस और एयरोनॉटिकल डिजाइन इंजीनियरों का निर्माण करना
(B) सभी उत्तीर्ण छात्रों को काम के लिए केवल विदेशों में जाने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य करना
(C) केवल अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं में काम करना, जिससे स्थानीय ग्रामीण युवा पूरी तरह से अलग-थलग पड़ जाते हैं
(D) उद्योग की आवश्यकताओं के साथ असंगत अप्रचलित पाठ्यक्रमों और उपकरणों का उपयोग करना

33. सूची I में बेरोजगारी के कारणों को सूची II में बेरोजगारी के उनके संबंधित प्रकार के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: (बेरोजगारी का कारण)
P. तकनीकी प्रगति जिससे पुराने कौशल अप्रासंगिक हो जाते हैं
Q. कृषि क्षेत्र में अत्यधिक भीड़ (अधिशेष श्रम)
R. खरीफ और रबी की फसल के मौसमों के बीच का अंतर
S. विश्वविद्यालय की डिग्री से प्रथम रोजगार में संक्रमण में लगने वाला समय
सूची II: (बेरोजगारी का प्रकार)
1. मौसमी बेरोजगारी
2. घर्षणात्मक बेरोजगारी
3. संरचनात्मक बेरोजगारी
4. प्रच्छन्न बेरोजगारी
निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित है?
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-1, Q-4, R-3, S-2

34. निम्नलिखित में से कौन-सा रोजगार के संबंध में धीमी औद्योगिक वृद्धि के सामान्य कारणों का एक नकारात्मक परिणाम या अपवाद को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है?
(A) निजी पूंजी निवेश की गंभीर कमी
(B) अत्यधिक औपचारिक रोजगार सृजन
(C) अपर्याप्त और खराब बुनियादी ढांचागत विकास
(D) निरंतर और कठोर नियामक बाधाएं

NODIA

35. "जनसांख्यिकीय लाभांश" की वह निर्णायक विशेषता क्या है जो बेरोजगारी का समाधान न होने पर "जनसांख्यिकीय आपदा" में बदलने का जोखिम उठाती है?
(A) वृद्ध, आर्थिक रूप से निर्भर आबादी के अनुपात में एक तीव्र, अभूतपूर्व वृद्धि
(B) कुल प्रजनन दर में एक तेज और निरंतर गिरावट जिसके कारण सीधे तौर पर गंभीर शारीरिक श्रम की कमी होती है
(C) पूरे कुशल राष्ट्रीय कार्यबल में शुरु किए गए व्यापक, स्वैच्छिक समय-पूर्व सेवानिवृत्ति कार्यक्रम
(D) पर्याप्त रोजगार सृजन के बिना कार्यशील-आयु वाली आबादी का विस्तार

36. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): राजस्थान से गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में युवाओं का बहिर्प्रवासन मुख्य रूप से केवल उच्च शैक्षणिक अवसरों द्वारा संचालित एक आकर्षण-कारक (पुल फैक्टर) परिघटना है।
कारण (R): ग्रामीण राजस्थान में पर्याप्त गैर-कृषि रोजगार की कमी एक मजबूत प्रतिकर्ष-कारक (पुश फैक्टर) के रूप में कार्य करती है जो युवाओं को प्रवासन के लिए मजबूर करती है।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

37. किसी पारिवारिक उद्यम (जैसे खेत या छोटी दुकान) में लगे अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों को पी.एल.एफ.एस. के तहत किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है?
(A) पूर्णतः बेरोजगार खुली श्रेणी
(B) औपचारिक क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारी
(C) स्व-नियोजित श्रमिक
(D) पूरी तरह से श्रम बल से बाहर

38. संरचनात्मक और चक्रीय बेरोजगारी के बीच अंतर के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) व्यापार चक्रों में सुधार होने पर संरचनात्मक बेरोजगारी

72. अनौपचारिक (असंगठित) क्षेत्र में रोजगार की निम्नलिखित में से कौन-सी एक मूलभूत विशेषता है जो कार्यबल की सुभेद्यता को बढ़ाती है?
(A) मुद्रास्फीति से सख्ती से जुड़े सुनिश्चित न्यूनतम वेतन
(B) रोजगार की सुरक्षा में कमी और औपचारिक रोजगार अनुबंधों की अनुपस्थिति
(C) अनिवार्य भविष्य निधि और चिकित्सा बीमा योगदान
(D) अत्यधिक कठोर छंटनी नीतियां जो श्रमिकों को काम से निकालना असंभव बनाती हैं

73. भारत में श्रम बल की गणना के लिए कार्यशील-आयु आबादी के मानक को परिभाषित करते समय, पारंपरिक रूप से किस आयु वर्ग पर विचार किया जाता है?
(A) 0 से 14 वर्ष
(B) 60 वर्ष और उससे अधिक
(C) 15 से 59 वर्ष
(D) 10 से 30 वर्ष

74. निम्नलिखित में से कौन-सा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं के बहिर्प्रवासन के लिए एक प्रमुख "प्रतिकर्ष-कारक" के रूप में कार्य करता है?
(A) ग्रामीण गांवों में कई बहुराष्ट्रीय आई.टी. पार्कों की उपस्थिति
(B) युवाओं को उनके पैतृक गांवों में रहने के लिए प्रतिबंधित करने वाले सरकारी आदेश
(C) अत्यधिक उपजाऊ, गहन सिंचित कृषि भूमि की प्रचुरता
(D) स्थानीय स्तर पर गैर-कृषि आजीविका के अवसरों की गंभीर कमी

75. मानक सर्वेक्षणों के माध्यम से प्रच्छन्न बेरोजगारी को मापना मुख्य रूप से इसलिए कठिन है क्योंकि:
(A) व्यक्ति दैनिक आधार पर लाभकारी रूप से नियोजित प्रतीत होते हैं
(B) यह केवल अत्यधिक संरचित, औपचारिक कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होती है
(C) प्रभावित व्यक्ति आधिकारिक सर्वेक्षण कर्मचारियों के सामने स्पष्ट रूप से और नियमित रूप से स्वयं को बेरोजगार घोषित करते हैं
(D) यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान ठीक एक कैलेंडर दिवस के लिए सख्ती से और अनुमानित रूप से होती है

76. श्रम की बचत करने वाली मशीनों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शुरुआत के कारण उत्पन्न होने वाली तकनीकी बेरोजगारी को आमतौर पर किस व्यापक श्रेणी का उप-प्रकार माना जाता है?
(A) घर्षणात्मक बेरोजगारी
(B) संरचनात्मक बेरोजगारी
(C) मौसमी बेरोजगारी
(D) प्रच्छन्न बेरोजगारी

77. ऐसी स्थिति जहाँ राज्य सरकार की सीमित रिक्तियों के लिए बड़ी संख्या में आवेदक प्रतिस्पर्धा करते हैं, किसका सूचक है?
(A) राज्य के विभागों में नियमित रोजगार परिवर्तनों के दौरान उच्च घर्षणात्मक बेरोजगारी
(B) औपचारिक रोजगार सृजन की तुलना में अधिशेष शिक्षित श्रम
(C) अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में श्रम की गंभीर और निरंतर कमी
(D) मौजूदा निजी प्रस्तावों को अस्वीकार करने वाले शिक्षित युवाओं के बीच असामान्य रूप से उच्च स्वैच्छिक बेरोजगारी

78. कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है?
(A) अधिशेष कृषि श्रम को विनिर्माण और सेवाओं में पुनः आवंटित करना
(B) अधिक गहन शारीरिक कृषि श्रम को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर, निर्बाध राज्य सब्सिडी प्रदान करना
(C) खेती में सभी आधुनिक मशीनों के निर्माण, आयात और उपयोग पर वैधानिक रूप से प्रतिबंध लगाना
(D) मानक कानूनी कार्यशील-आयु आबादी की परिभाषा को मनमाने ढंग से घटाकर 40 वर्ष करना

79. निम्नलिखित में से कौन-सा परिदृश्य "खुली बेरोजगारी" की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है?
(A) एक निर्वाह किसान जो शून्य सीमांत अतिरिक्त उत्पादन का योगदान करते हुए परिवार के भीड़भाड़ वाले भूखंड पर काम कर रहा है
(B) एक वरिष्ठ बैंक प्रबंधक जो दो सप्ताह की संक्षिप्त अवधि में दो वित्तीय संस्थानों के बीच सुचारु रूप से बदल रहा है
(C) एक स्नातक जो सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहा है लेकिन उसे एक वर्ष से कोई रोजगार प्रस्ताव नहीं मिला है
(D) एक निर्माण मजदूर जो पूरे वार्षिक मानसूनी बारिश के मौसम में पूरी तरह से बिना काम के रहता है

80. राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारी की उच्च दर को व्यवस्थित रूप से संबोधित करने के लिए, निम्नलिखित में से कौन-सा नीतिगत संयोजन सबसे उपयुक्त है?
(A) सभी ग्रामीण-से-शहरी प्रवासन को वैधानिक रूप से प्रतिबंधित करना और पारिवारिक खेतों पर अनिवार्य आजीवन कृषि श्रम को सख्ती से लागू करना
(B) सभी तकनीकी व्यावसायिक प्रशिक्षणों को व्यवस्थित रूप से समाप्त करते हुए पारंपरिक सामान्य मानविकी डिग्री कार्यक्रमों का तेजी से विस्तार करना
(C) कोई प्रत्यक्ष आर्थिक हस्तक्षेप किए बिना केवल आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के प्रकाशन की आवृत्ति को बढ़ाना
(D) पाठ्यक्रम को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और गैर-कृषि क्षेत्रों में निवेश करना

Downloaded from www.pdf.tube

(D) घर्षणात्मक बेरोजगारी

47. शिक्षित बेरोजगारी का एक मुख्य कारण शैक्षणिक पाठ्यक्रम और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच का अंतर है। निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द इस विशिष्ट कारण को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है?
(A) भौगोलिक गतिहीनता
(B) मांग में कमी
(C) कौशल बेमेल
(D) मौसमी परिवर्तनशीलता

48. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): भारत में असंगठित क्षेत्र प्रभावी रूप से बेरोजगारी की वास्तविक गंभीरता को छिपाता है।
कारण (R): औपचारिक रोजगार पाने में असमर्थ कई व्यक्ति केवल जीवन यापन के लिए कम आय, कम उत्पादकता वाले अनौपचारिक काम में लग जाते हैं, जिससे वे सांख्यिकीय रूप से 'नियोजित' दिखाई देते हैं।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

49. सरकारी आंकड़े स्रोतों के संदर्भ में, पारंपरिक एन.एस.एस.ओ. रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षणों (ई.यू.एस.) की प्राथमिक सीमा क्या थी जिसके कारण पी.एल.एफ.एस. की शुरुआत हुई?
(A) वे मासिक अनुसूची पर बहुत अधिक बार आयोजित किए जाते थे, जिससे अत्यधिक आंकड़े ओवरलोड होते थे
(B) उन्होंने निजी उद्यमों की उपेक्षा करते हुए केवल स्थायी सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का सर्वेक्षण किया
(C) वे पंचवार्षिक आयोजित किए जाते थे, जिससे उनमें वास्तविक समय के आंकड़ों की प्रासंगिकता का अभाव था
(D) वे ग्रामीण कृषि क्षेत्रों को कवर करने में विफल रहे, केवल महानगरीय शहरों पर ध्यान केंद्रित करते थे

50. रोजगार कार्यालय में पंजीकरण किसी बेरोजगार अभ्यर्थी के लिए किस प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करता है?
(A) यह कानूनी रूप से किसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में तत्काल उच्च वेतन वाले पद की गारंटी देता है
(B) यह भावी रोजगार के लिए कार्य चाहने वाले के रूप में अभ्यर्थी की स्थिति दर्ज करता है
(C) यह राज्य पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए एक अनिवार्य वैधानिक आवश्यकता के रूप में कार्य करता है
(D) यह सीधे राज्य के खजाने से बिना शर्त स्थायी आजीवन मासिक वित्तीय भत्ता प्रदान करता है

NODIA

51. सूची I में राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशिष्ट विशेषताओं को सूची II में उनकी प्रमुख रोजगार चुनौती के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: (अर्थव्यवस्था की विशेषता)
P. वर्षा-आधारित कृषि क्षेत्र
Q. आधुनिक मशीनी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे पारंपरिक हस्तशिल्प क्षेत्र
R. सामान्य विश्वविद्यालय डिग्रियों वाले युवाओं की बढ़ती जनसांख्यिकी
S. पुराने व्यावहारिक प्रशिक्षण वाले आई.टी.आई. स्नातक
सूची II: (रोजगार चुनौती)
1. कौशल बेमेल बेरोजगारी
2. संरचनात्मक बेरोजगारी
3. मौसमी बेरोजगारी
4. शिक्षित खुली बेरोजगारी
निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित है?
(A) P-3, Q-2, R-4, S-1
(B) P-4, Q-3, R-1, S-2
(C) P-3, Q-4, R-2, S-1
(D) P-2, Q-1, R-3, S-4

52. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) अपना त्रैमासिक बुलेटिन विशेष रूप से किस जनसांख्यिकीय खंड के रोजगार संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जारी करता है?
(A) केवल शहरी क्षेत्र
(B) ग्रामीण क्षेत्रों में केवल कृषि मजदूर
(C) राष्ट्रीय स्तर पर 60 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त व्यक्ति
(D) केवल 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे

53. एक व्यक्ति जो काम करने में सक्षम है लेकिन रोजगार की तलाश करने के बजाय पूर्णकालिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प चुनता है, उसे सांख्यिकीय रूप से किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है?
(A) घर्षणात्मक रूप से बेरोजगार
(B) संरचनात्मक रूप से बेरोजगार
(C) श्रम बल से बाहर
(D) प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार

54. अनौपचारिक (असंगठित) क्षेत्र के रोजगार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसमें सामान्यतः औपचारिक अनुबंधों और सामाजिक सुरक्षा लाभों का अभाव होता है।
II. यह अल्प-रोजगार के उच्च स्तरों द्वारा अभिलक्षित होता है।
III. यह राजस्थान के कुल कार्यबल का एक नगण्य हिस्सा है।
IV. यह शहरी केंद्रों में प्रवास करने वाले अधिशेष ग्रामीण श्रम के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अवशोषित करता है।

श्रमिकों को खेत से हटा भी दिया जाए, तब भी कुल कृषि उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता तथा उत्पादन स्तर यथावत बना रहता है।

11. (C) पिछले 365 दिन
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली के अंतर्गत सामान्य प्रमुख स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए 365 दिनों की दीर्घकालिक संदर्भ अवधि को अपनाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति सर्वेक्षण की तारीख से पूर्व के 365 दिनों के बड़े हिस्से अथवा अधिकांश समय में किसी आर्थिक गतिविधि में लगा रहता है, तो उसे उस वर्ष के लिए सामान्य प्रमुख स्थिति के आधार पर नियोजित माना जाता है।

12. (B) पिछले 7 दिनों की संदर्भ अवधि में किसी व्यक्ति की गतिविधि स्थिति
वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण का उपयोग श्रम बाजार में अल्पकालिक रोजगार और बेरोजगारी की दरों को मापने के लिए किया जाता है। इस मापदंड के तहत संदर्भ अवधि सर्वेक्षण की तिथि से ठीक पहले के 7 दिन होती है। यदि कोई व्यक्ति इस सात दिवसीय अवधि में कम से कम एक घंटे के लिए भी किसी उत्पादक कार्य में लगा रहा हो, तो उसे नियोजित माना जाता है।

13. (A) I, II और IV
भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि शामिल है जो श्रम बल की आपूर्ति को बढ़ाती है। धीमी औद्योगिक वृद्धि गैर-कृषि रोजगार अवसरों को सीमित करती है, जिससे कृषि पर निर्भरता बनी रहती है और प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ती है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच व्यापक असंतुलन है, जिससे कौशल बेमेल की समस्या लगातार बनी रहती है।

14. (B) 15 से 29 वर्ष
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवा बेरोजगारी दर की गणना के लिए 15 से 29 वर्ष के जनसांख्यिकीय आयु वर्ग का विश्लेषण किया जाता है। यह विशिष्ट आयु समूह शिक्षा से श्रम बाजार में प्रवेश के संक्रमणकालीन चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस समूह की बेरोजगारी दरों का अध्ययन करने से युवा श्रम बल के समावेशन तथा उपयुक्त रोजगार नीतियों के निर्माण में मदद मिलती है।

15. (C) गैर-कृषि आर्थिक क्षेत्रों में श्रम बल का विस्तार रोजगार सृजन की तुलना में अधिक तेजी से होता है
जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण प्रतिवर्ष श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले नए कार्य चाहने वालों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। जब गैर-कृषि क्षेत्र जैसे विनिर्माण और सेवा उद्योग इस नए श्रम बल के समावेशन के लिए पर्याप्त गति से नए रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं कर पाते, तो श्रम की मांग और आपूर्ति के बीच खाई गहरा जाती है और बेरोजगारी बढ़ती है।

16. (A) 2, 1, 4, 3
घर्षणात्मक बेरोजगारी की प्रक्रिया में सबसे पहले एक श्रमिक बेहतर अवसरों की तलाश में अपनी वर्तमान नौकरी से त्यागपत्र देता है। इसके पश्चात वह अपने कौशल का अद्यतन करता है तथा जॉब पोर्टल पर पंजीकरण कराता है। तत्पश्चात वह विभिन्न साक्षात्कारों में भाग लेकर सेवा शर्तों पर वार्ता करता है और अंततः नया रोजगार प्रस्ताव स्वीकार कर कार्यबल में पुनः प्रवेश करता है।

17. (C) श्रमिकों का कम मजदूरी वाले रोजगार में समावेशन औपचारिक रोजगार के बजाय अल्प-रोजगार को दर्शाता है
राजस्थान का असंगठित क्षेत्र अक्सर वास्तविक बेरोजगारी के आंकड़ों को छिपाने का काम करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई श्रमिक आधिकारिक तौर पर किसी न किसी अनौपचारिक गतिविधि में लगे होने के कारण नियोजित दिखाई देते हैं, परंतु उन्हें बेहद कम मजदूरी प्राप्त होती है और वे अपनी क्षमता से कम कार्य करते हैं। यह स्थिति खुली बेरोजगारी के बजाय व्यापक अल्प-रोजगार को प्रदर्शित करती है।

18. (B) अपर्याप्त स्थानीय गैर-कृषि रोजगार के कारण उत्पन्न सामंजस्य की रणनीति
ग्रामीण राजस्थान से पड़ोसी औद्योगिक राज्यों में युवाओं का प्रवासन बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए अपनाई जाने वाली एक जीवनयापन रणनीति है। स्थानीय स्तर पर स्थायी तथा पर्याप्त गैर-कृषि रोजगार के अवसरों का अभाव युवाओं को अन्य क्षेत्रों में पलायन के लिए बाध्य करता है, जिससे वे अपनी आजीविका सुरक्षित कर सकें और अपने परिवारों का भरण-पोषण कर सकें।

19. (B) सामान्य प्रमुख स्थिति, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, वर्तमान दैनिक स्थिति
भारत में रोजगार मापन दृष्टिकोणों की समय अवधि के घटते क्रम में सबसे लंबी संदर्भ अवधि सामान्य प्रमुख स्थिति है, जो पूरे 365 दिनों के डेटा पर आधारित होती है। इसके पश्चात वर्तमान साप्ताहिक स्थिति आती है जिसकी संदर्भ अवधि पिछले 7 दिन होती है। अंत में वर्तमान दैनिक स्थिति आती है जो पिछले 7 दिनों के प्रत्येक दिन की गतिविधियों का आकलन करती है।

20. (A) स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को तेजी से अपनाना
कपड़ा और पारंपरिक विनिर्माण उद्योगों में आधुनिक तकनीकों, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाए जाने से श्रम की मांग में मौलिक बदलाव आ रहा है। यह प्राद्योगिकी-संचालित बदलाव पारंपरिक तथा शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों के कौशल को अप्रचलित बना रहा है, जिससे कार्यबल में व्यापक कौशल बेमेल पैदा हो रहा है और दीर्घकालिक संरचनात्मक बेरोजगारी का गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है।

21. (A) P-4, Q-1, R-3, S-2
श्रम बल का तात्पर्य नियोजित तथा बेरोजगार व्यक्तियों के कुल योग से है। कार्य बल केवल उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जो वास्तव में किसी उत्पादक आर्थिक गतिविधि में लगे हुए हैं। बेरोजगार वे व्यक्ति हैं जो काम करने के इच्छुक हैं

Click Here to Buy book on Flipkart

63. जब पारंपरिक कृषि प्रथाओं का मशीनीकरण किया जाता है (जैसे शारीरिक श्रम के स्थान पर ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का उपयोग करना), तो इसके परिणामस्वरुप शुरु में भूमिहीन मजदूरों के बीच किस प्रकार की बेरोजगारी में वृद्धि होती है?
(A) घर्षणात्मक संक्रमणकालीन बेरोजगारी
(B) शिक्षित युवा बेरोजगारी
(C) संरचनात्मक बेरोजगारी
(D) स्वैच्छिक मजदूरी बेरोजगारी

64. रोजगार के आंकड़े एकत्र करने में दसवार्षिक जनगणना, पी.एल.एफ.एस. से किस प्रकार भिन्न है?
(A) जनगणना केवल उच्च-आवृत्ति वाली त्रैमासिक कार्यबल रिपोर्ट प्रदान करती है, जबकि पी.एल.एफ.एस. केवल हर दस साल में एक बार आंकड़े जारी करता है
(B) जनगणना केवल औपचारिक सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों की गणना करती है, जबकि पी.एल. एफ.एस. केवल अनौपचारिक निजी उद्यम श्रमिकों का सर्वेक्षण करता है
(C) जनगणना केवल शहरी नगरपालिकाओं में बेरोजगारी को मापती है, जबकि पी.एल.एफ.एस. केवल ग्रामीण कृषि गांवों से आंकड़े एकत्र करता है
(D) जनगणना संपूर्ण जनसंख्या की गणना है, जबकि पी.एल. एफ.एस. विस्तृत संकेतकों के लिए एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण है

65. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: श्रम बल में वे लोग शामिल हैं जो नियोजित हैं और वे भी जो बेरोजगार हैं लेकिन काम की तलाश कर रहे हैं।
कथन II: कार्य बल में केवल वे व्यक्ति शामिल हैं जो वास्तव में नियोजित हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

66. यदि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामना कर रहे कृषि क्षेत्र से अधिशेष श्रम को नए स्थापित स्थानीय विनिर्माण उद्योग में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो कुल कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
(A) यह तुरंत अत्यधिक निचले स्तर तक गिर जाता है
(B) यह वास्तव में अपरिवर्तित रहता है
(C) यह अचानक और पूरी तरह से शून्य पर आ जाता है
(D) खेतों में भीड़ कम होने के कारण यह तुरंत दोगुना हो जाता है

67. व्यापार चक्र के किस चरण के दौरान चक्रीय बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर (चरम) पर पहुंचती है?
(A) आर्थिक तेजी
(B) विस्तार
(C) शिखर/समृद्धि
(D) गर्त/मंदी

68. भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) द्वारा आयोजित किया जाता है।
II. रोजगार कार्यालय आंकड़े सभी बेरोजगार व्यक्तियों की एक व्यापक और पूरी तरह से सटीक गणना प्रदान करते हैं।
III. दसवार्षिक जनगणना जनसंख्या को मुख्य कामगारों, सीमांत कामगारों और गैर-कामगारों में वर्गीकृत करती है।
IV. पी.एल.एफ.एस. ने उच्च-आवृत्ति वाली शहरी रिपोर्टिंग के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति की अवधारणा पेश की।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) I, II और III
(B) I, III और IV
(C) II, III और IV
(D) I, II और IV

69. बेरोजगारी मापने के लिए वर्तमान दैनिक स्थिति (सी.डी.एस.) दृष्टिकोण किस समय अवधि में किसी व्यक्ति की गतिविधि स्थिति पर विचार करता है?
(A) पिछले 365 दिन
(B) 1 महीने की अनुमानित अवधि
(C) पिछले 7 दिनों का प्रत्येक दिन
(D) व्यक्ति का संपूर्ण कार्य जीवन

70. राजस्थान में एक उच्च योग्य महिला इंजीनियर पारिवारिक बाधाओं और स्थानीय इंजीनियरिंग अवसरों की कमी के कारण प्राथमिक विद्यालय के ट्यूटर के रूप में अंशकालिक रोजगार स्वीकार करती है। इसे सर्वोत्तम रुप से किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है?
(A) दृश्य अल्प-रोजगार
(B) चक्रीय बेरोजगारी
(C) प्रच्छन्न बेरोजगारी
(D) घर्षणात्मक बेरोजगारी

71. सरकारी कौशल विकास योजनाओं का उद्देश्य बेरोजगारी के किस विशिष्ट मूल कारण का समाधान करना है?
(A) वैश्विक अर्थव्यवस्था में आवधिक चक्रीय मंदी और मांग में संकुचन
(B) वार्षिक मानसूनी वर्षा में गंभीर मौसमी भिन्नता और अनिश्चितता
(C) दो औद्योगिक शहरों के बीच आवाजाही में शामिल निरंतर भौगोलिक बाधाएं
(D) अभ्यर्थियों के कौशल और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच कौशल बेमेल

Downloaded from www.pdf.tube

का पाठ्यक्रम पुराना है और वे पुरानी मशीनों पर प्रशिक्षण देते हैं। आधुनिक उद्योग जिन नई तकनीकों और व्यावहारिक कौशलों की मांग करते हैं, उनका समावेश न होने से आईटीआई छात्र सीधे रोजगार योग्य नहीं बन पाते।

33. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
नई तकनीकों के आगमन से पुराने कौशलों का अप्रासंगिक होना संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न करता है। कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक श्रम बल का होना प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण है। बुआई और कटाई के मौसमों के बीच का अंतर मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। डिग्री प्राप्त करने के बाद पहली नौकरी खोजने में लगने वाली समय अवधि घर्षणात्मक बेरोजगारी की श्रेणी में आती है।

34. (B) अत्यधिक औपचारिक रोजगार सृजन
धीमी औद्योगिक वृद्धि सामान्यतः अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती होती है जिसके कई नकारात्मक कारण होते हैं। इन कारणों में निजी पूंजी निवेश की भारी कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और जटिल नियामक बाधाएं शामिल हैं। हालाँकि, अत्यधिक औपचारिक रोजगार का सृजन होना धीमी औद्योगिक वृद्धि का परिणाम या कारण नहीं हो सकता, बल्कि यह तो सुदृढ़ और तीव्र औद्योगिक विकास का लक्षण होता है।

35. (D) पर्याप्त रोजगार सृजन के बिना कार्यशील-आयु वाली आबादी का विस्तार
जनसांख्यिकीय लाभांश उस आर्थिक अवसर को कहा जाता है जब किसी देश की कुल जनसंख्या में कार्यशील आयु वर्ग का अनुपात आश्रित आबादी से अधिक हो जाता है। यदि अर्थव्यवस्था इस बढ़ती युवा आबादी के समावेशन के लिए पर्याप्त संख्या में गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों को पैदा करने में असमर्थ रहती है, तो यही लाभांश व्यापक बेरोजगारी और जनसांख्यिकीय आपदा में बदल जाता है।

36. (D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।
राजस्थान से युवाओं का अन्य राज्यों में प्रवासन केवल उच्च शैक्षणिक अवसरों द्वारा संचालित आकर्षण-कारक नहीं है, बल्कि यह मुख्यतः आर्थिक मजबूरियों से प्रेरित है। ग्रामीण राजस्थान में कृषि के अलावा स्थानीय गैर-कृषि आजीविका के साधनों की भारी कमी पाई जाती है। रोजगार की यह अनुपस्थिति एक मजबूत प्रतिकर्ष-कारक के रूप में काम करती है जो युवाओं को आजीविका कमाने हेतु बाहर जाने पर मजबूर करती है।

37. (C) स्व-नियोजित श्रमिक
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की सांख्यिकीय वर्गीकरण प्रणाली के तहत ऐसे व्यक्तियों को स्व-नियोजित की व्यापक श्रेणी में रखा जाता है जो अपने पारिवारिक खेतों, दुकानों या सूक्ष्म उद्यमों में अवैतनिक रूप से श्रम करते हैं। इन्हें 'पारिवारिक उद्यमों में सहायता करने वाले स्व-नियोजित श्रमिक' माना जाता है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष वेतन या मजदूरी प्राप्त किए बिना परिवार की आर्थिक गतिविधियों में योगदान करते हैं।

38. (A) व्यापार चक्रों में सुधार होने पर संरचनात्मक बेरोजगारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है
संरचनात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी की प्रकृति में मौलिक अंतर होता है। चक्रीय बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के व्यापार चक्र में सुधार आने और सकल मांग के पुनः बढ़ने पर स्वतः कम हो जाती है। इसके विपरीत, संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के स्थायी संरचनात्मक बदलावों, तकनीकी प्रगति और कौशल बेमेल के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए यह केवल आर्थिक तेजी आने से स्वतः समाप्त नहीं होती है।

39. (A) 3 → 4 → 1 → 2
बेरोजगारी दरों के व्युत्पत्ति क्रम में सबसे व्यापक जनसांख्यिकीय आधार किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या होती है। इस संपूर्ण जनसंख्या में से कार्यशील आयु वाले व्यक्तियों को अलग करके कुल श्रम बल की पहचान की जाती है। इसके पश्चात श्रम बल में से उत्पादक कार्यों में संलग्न कुल नियोजित कार्यबल को चिन्हित किया जाता है। अंत में शेष बची सक्रिय रूप से रोजगार तलाश रही जनसंख्या आती है।

NODIA

40. (B) स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में कमी के कारण राष्ट्रीय औसत से अधिक
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में बेरोजगारी दर, विशेषकर शिक्षित युवाओं में, राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक दर्ज की जाती है। राज्य में गैर-कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण रोजगार अवसरों के सीमित सृजन तथा सरकारी नौकरियों के प्रति युवाओं की अत्यधिक निर्भरता को इस उच्च दर का एक प्रमुख कारक माना जाता है।

41. (C) मौसमी छुट्टी के कारण उपभोक्ता खर्च में अस्थायी गिरावट
संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के मूलभूत ढांचे में होने वाले दीर्घकालिक परिवर्तनों से जुड़ी होती है। इसमें विनिर्माण से सेवा क्षेत्र की ओर बदलाव, उद्योगों में स्वचालित मशीनों का प्रयोग और उपभोक्ता प्राथमिकताओं के बदलने से पुराने उद्योगों का पतन शामिल है। इसके विपरीत, छुट्टियों के दौरान उपभोक्ता खर्च में आने वाली अस्थायी गिरावट एक अल्पकालिक परिघटना है, जिसका संरचनात्मक कारणों से कोई संबंध नहीं है।

42. (C) केवल III
राजस्थान में युवा बेरोजगारी की समस्या उच्च शिक्षित स्नातकों को प्राथमिक शिक्षा वालों की तुलना में अधिक प्रभावित करती है। युवा अक्सर लंबे समय तक सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जिससे यह समस्या और गहरी हो जाती है। हालांकि, राज्य के निजी क्षेत्र में कार्यबल का समावेशन इतना व्यापक या पर्याप्त नहीं है कि वह सरकारी पदों की कमी की भरपाई कर सके।

43. (A) मौसमी बेरोजगारी
कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं में फसलों के उत्पादन का एक निश्चित प्राकृतिक चक्र होता है। राजस्थान में रबी फसलों की कटाई पूरी होने के पश्चात तथा खरीफ फसलों की बुआई शुरु

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (C) ऐसी स्थिति जहाँ श्रम बल के वे सदस्य जो काम करने के इच्छुक और सक्षम हैं, लाभकारी रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं
मानक आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार बेरोजगारी अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जिसमें कार्यशील आयु वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो प्रचलित बाजार दर पर कार्य करने के लिए इच्छुक तथा पूरी तरह सक्षम होते हैं, परंतु उन्हें कोई उत्पादक कार्य नहीं मिलता। यह आर्थिक स्थिति केवल अनैच्छिक बेरोजगारी को रेखांकित करती है, जहाँ श्रम की आपूर्ति तो उपलब्ध रहती है किंतु उसकी वास्तविक मांग अपर्याप्त होती है।

2. (B) नियोजित व्यक्ति तथा वे बेरोजगार व्यक्ति जो सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे हैं
किसी क्षेत्र के श्रम बल की माप में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्यशील आयु वर्ग के उन सभी व्यक्तियों का योग शामिल किया जाता है जो वर्तमान में किसी आर्थिक गतिविधि में कार्यरत हैं अथवा जो कार्य से बाहर हैं लेकिन सक्रियता से रोजगार की खोज कर रहे हैं। इस समूह में वे व्यक्ति सम्मिलित नहीं होते जो स्वेच्छा से श्रम बाजार से बाहर हैं।

3. (C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
मौसमी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि तथा संबंधित गतिविधियों से जुड़ी होती है, जहाँ फसलों की बुआई, निराई और कटाई के समय ही श्रम की उच्च मांग उत्पन्न होती है। हालांकि, गैर-मौसम के दौरान श्रमिकों की उत्पादकता अस्थायी रूप से प्रभावित होती है, किंतु पूरे कैलेंडर वर्ष में उनकी सीमांत भौतिक उत्पादकता निरंतर शून्य नहीं रहती। इसलिए मौसमी अंतराल समाप्त होते ही उत्पादकता पुन: स्थापित होती है।

4. (B) I और II दोनों
प्रच्छन्न अथवा अदृश्य बेरोजगारी उस स्थिति को दर्शाती है जहाँ किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रमिक नियोजित होते हैं। इस परिस्थिति में अतिरिक्त श्रमिकों का निष्कासन कुल उत्पादन को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि अतिरिक्त श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक होती है। भारत में यह परिघटना भारी उद्योगों या सूचना प्रौद्योगिकी के बजाय प्राथमिक कृषि क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है।

5. (C) घर्षणात्मक बेरोजगारी
घर्षणात्मक बेरोजगारी एक अल्पकालिक तथा संक्रमणकालीन स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब कोई श्रमिक अपनी स्वेच्छा अथवा आवश्यकता से पुरानी नौकरी छोड़कर नई तथा अधिक उपयुक्त आजीविका की खोज करता है। इस परिवर्तन काल में सूचना की विषमता और भर्ती प्रक्रियाओं में लगने वाला समय इस अस्थायी बेरोजगारी का मुख्य आधार बनता है, जो एक गतिशील अर्थव्यवस्था का स्वाभाविक लक्षण है।

6. (A) अर्थव्यवस्था में चक्रीय मंदी जिसके कारण सकल मांग में कमी आती है
चक्रीय बेरोजगारी समष्टि आर्थिक व्यापार चक्रों की गतियों से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आता है, तब वस्तुओं और सेवाओं की सकल मांग में भारी गिरावट दर्ज की जाती है। इसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपना उत्पादन घटा देते हैं और कार्यबल की छंटनी करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, जिससे यह चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है।

7. (A) P-2, Q-1, R-3, S-4
घर्षणात्मक बेरोजगारी एक रोजगार से दूसरे में बदलाव के समय होने वाली अस्थायी स्थिति है। संरचनात्मक बेरोजगारी बाजार की मांगों और श्रमिकों के कौशलों के बीच अंतर के कारण उत्पन्न होती है। चक्रीय बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में मंदी और सकल मांग की कमी से संबंधित होती है, जबकि मौसमी बेरोजगारी कृषि गतिविधियों के विशिष्ट चक्रीय चक्रों और अंतराल से जुड़ी परिघटना है।

8. (B) खुली बेरोजगारी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है क्योंकि व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी में व्यक्ति नियोजित प्रतीत होता है
खुली बेरोजगारी की मुख्य पहचान यह है कि प्रभावित व्यक्ति के पास आजीविका का कोई साधन नहीं होता और वह पूरी तरह से स्पष्ट रूप से बेरोजगार दिखता है। इसके विपरीत, प्रच्छन्न बेरोजगारी में व्यक्ति किसी कार्य अथवा खेत में काम करता हुआ दिखाई देता है, परंतु वास्तव में उसकी उपस्थिति से कुल उत्पादन में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं होती और सीमांत उत्पादकता शून्य बनी रहती है।

9. (C) डिग्री धारक युवाओं का अधिशेष जिनकी योग्यताएं उद्योग की कौशल आवश्यकताओं से मेल नहीं खाती हैं
राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख आयाम यह है कि राज्य में औपचारिक डिग्री धारक युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है, किंतु उनके द्वारा अर्जित शैक्षणिक योग्यताएं आधुनिक उद्योग और बाजार की व्यावहारिक आवश्यकताओं से सुसंगत नहीं हैं। इस कौशल असंतुलन तथा व्यावसायिक दक्षता की कमी के कारण स्नातकों की विशाल संख्या के बावजूद उन्हें प्रासंगिक रोजगार पाने में कठिनाई होती है।

10. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता है जहाँ आवश्यकता से अधिक श्रमिक संलग्न होते हैं। इस स्थिति में अधिशेष श्रमिकों की सीमांत भौतिक उत्पादकता वास्तव में शून्य होती है। इसका कारण यह है कि यदि इन अतिरिक्त

Click Here to Buy book on Amazon

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) I, II और III
(B) I, II और IV
(C) II, III और IV
(D) I, III और IV

55. आर्थिक संरचनात्मक परिवर्तन का तात्पर्य आमतौर पर रोजगार निर्भरता का प्राथमिक क्षेत्र (कृषि) से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होना है। इस संक्रमण के दौरान एक सामान्य अल्प-से-मध्यम अवधि की चुनौती क्या है?
(A) सभी क्षेत्रों में पूर्ण गरीबी का तत्काल और पूर्ण उन्मूलन
(B) कुल राष्ट्रीय जनसांख्यिकीय जनसंख्या वृद्धि में अचानक और पूर्ण विराम
(C) वास्तविक राष्ट्रीय आय और सकल उत्पादन में निरंतर, स्थायी कमी
(D) कौशल संक्रमण में देरी के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी

56. यदि राजस्थान में औद्योगिक वृद्धि "श्रम-गहन" के बजाय अत्यधिक "पूंजी-गहन" होती है, तो रोजगार के संबंध में सबसे संभावित परिणाम क्या होगा?
(A) आधुनिक भारी कारखानों में अकुशल ग्रामीण कृषि श्रम का तेजी से बड़े पैमाने पर समावेशन
(B) धीमी रोजगार सृजन दर के साथ उच्च आर्थिक वृद्धि
(C) पूरे प्राथमिक कृषि क्षेत्र का पूर्ण और स्थायी रूप से गायब होना
(D) राज्य भर में सभी शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी का तत्काल और व्यापक समाधान

57. भारत/राजस्थान में महिला श्रम बल भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. महिला श्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अवैतनिक घरेलू और कृषि कार्यों में लगा हुआ है, जिसे अक्सर औपचारिक रोजगार संकेतकों से बाहर रखा जाता है।
II. सांस्कृतिक मानदंड और सुरक्षा चिंताएं महिलाओं के औपचारिक कार्यबल में प्रवेश करने में बाधा के रूप में कार्य कर सकती हैं।
III. महिला श्रम बल भागीदारी दर सभी शहरी क्षेत्रों में पुरुष भागीदारी दर से लगातार अधिक है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) I और II दोनों
(B) II और III दोनों
(C) केवल I
(D) I, II और III

58. बेरोजगारी के प्रमुख प्रकार और उसकी विशिष्ट क्षेत्रीय सांद्रता के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए।
(A) प्रच्छन्न बेरोजगारी — शहरी औपचारिक आई.टी. क्षेत्र
(B) घर्षणात्मक बेरोजगारी — पारंपरिक जीवन-निर्वाह कृषि
(C) खुली शिक्षित बेरोजगारी — अकुशल शारीरिक श्रम बल
(D) मौसमी बेरोजगारी — ग्रामीण कृषि क्षेत्र

59. निम्नलिखित में से कौन-सा आमतौर पर राजस्थान में कृषि मजदूरों के बीच मौसमी प्रवासन का कारक नहीं है?
(A) गारंटीकृत व्हाइट-कॉलर शहरी रोजगार के प्रस्ताव
(B) मौसमी मानसून की निरंतर विफलता जिसके कारण सीधे तौर पर व्यापक सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है
(C) कृषि के गैर-मौसम के दौरान व्यवहार्य स्थानीय गैर-कृषि रोजगार अवसरों का पूर्ण अभाव
(D) गैर-कटाई मौसमी महीनों के दौरान कम घरेलू कृषि आय को पूरा करने की तत्काल आवश्यकता

60. स्वैच्छिक बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जहाँ:
(A) समष्टि आर्थिक मंदी के कारण औद्योगिक श्रमिकों को अनैच्छिक रूप से बड़े पैमाने पर काम से निकाल दिया जाता है
(B) रोजगार की उपलब्धता के बावजूद लोग प्रचलित मजदूरी पर काम न करने का विकल्प चुनते हैं
(C) अधिशेष कृषि श्रमिक शून्य सीमांत भौतिक उत्पादकता वाले खेतों में काम करते हैं
(D) उच्च योग्य विश्वविद्यालय स्नातकों को उनकी सटीक योग्यताओं से मेल खाने वाले रोजगार नहीं मिल पाते हैं

61. निम्नलिखित में से कौन-सा "अनैच्छिक बेरोजगारी" को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है?
(A) योग्य श्रमिक स्वैच्छिक रूप से काम करने से इनकार करते हैं क्योंकि वे वर्तमान मजदूरी दरों को बहुत कम मानते हैं
(B) जो लोग प्रचलित मजदूरी पर काम करने के इच्छुक हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है
(C) कुशल श्रमिक कई उच्च वेतन वाले कॉर्पोरेट रोजगार प्रस्तावों के बीच स्वतंत्र रूप से और स्वैच्छिक रूप से बदलाव करते हैं
(D) सक्रिय रूप से बाजार में रोजगार की तलाश करने के बजाय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले पूर्णकालिक छात्र

NODIA

62. राजस्थान में स्नातक बेरोजगारी की मुख्य चुनौती अक्सर सामान्य डिग्रियों (जैसे बी.ए./बी.एससी.) वाले उम्मीदवारों की अत्यधिक आपूर्ति के साथ-साथ किस स्थिति के जुड़ने से उत्पन्न होती है?
(A) सॉफ्ट स्किल, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक विशेषज्ञता में गंभीर कमी
(B) ग्रामीण कृषि में अत्यधिक उन्नत रोबोटिक्स पर अत्यधिक राज्यव्यापी आर्थिक निर्भरता
(C) पूरे राज्य में अनिवार्य युवा सैन्य सेवा नीतियों का वैधानिक कार्यान्वयन
(D) सभी सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी भर्ती परीक्षाओं की पूर्ण और व्यापक संरचनात्मक अनुपस्थिति

परंतु रोजगार से वंचित हैं, जबकि श्रम बल से बाहर वे लोग हैं जो काम नहीं कर रहे और न खोज रहे हैं।

22. (A) प्रच्छन्न बेरोजगारी
कृषि अल्प-रोजगार और प्रच्छन्न बेरोजगारी एक-दूसरे के निकटतम समानार्थी अवधारणाएं हैं। इस परिस्थिति में किसी कृषि भूमि या पारिवारिक खेत पर वास्तव में आवश्यक संख्या से अधिक व्यक्ति कार्यरत होते हैं। यद्यपि वे सभी नियोजित प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें से अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, जिसका अर्थ है कि उनके हटने से कुल कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

23. (D) गैर-कृषि रोजगार का अपर्याप्त सृजन, जिससे कृषि पर दबाव बढ़ता है
राजस्थान में धीमी औद्योगिक वृद्धि का प्रत्यक्ष परिणाम यह है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में नए रोजगार का सृजन सीमित गति से होता है। इसके चलते प्रतिवर्ष श्रम बल में शामिल होने वाले नए युवाओं का गैर-कृषि क्षेत्रों में समावेशन नहीं हो पाता। परिणामस्वरुप, कार्यबल का बड़ा हिस्सा आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर रहने को मजबूर होता है, जिससे कृषि पर दबाव बढ़ता है।

24. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
राजस्थान के स्नातकों में कौशल बेमेल शिक्षित बेरोजगारी की एक प्रमुख समस्या है। उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान किए जा रहे पारंपरिक पाठ्यक्रमों का शैक्षणिक ढांचा अक्सर सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित रहता है। इनमें आधुनिक उद्योगों की व्यावहारिक जरूरतों तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव होता है, जिसके कारण उच्च डिग्रियां होने के बावजूद युवा बाजार की आवश्यकताओं के अनुरुप रोजगार पाने में असमर्थ रहते हैं।

25. (C) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.)
भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का आयोजन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। इस सर्वेक्षण की शुरुआत श्रम बल की भागीदारी, रोजगार तथा बेरोजगारी संकेतकों का समय पर और अधिक बारंबारता के साथ डेटा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी, जिससे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सटीक नीतियां बनाई जा सकें।

26. (D) डिजिटल पोर्टल और परिसर भर्ती के माध्यम से निजी भर्ती की ओर बदलाव
ऐतिहासिक रूप से रोजगार कार्यालय सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी चाहने वालों के पंजीकरण का मुख्य माध्यम थे। हाल के वर्षों में इंटरनेट तकनीक के प्रसार, डिजिटल जॉब पोर्टलों, निजी भर्ती एजेंसियों और कॉलेजों में सीधे परिसर भर्ती के उभार ने रोजगार कार्यालयों की पारंपरिक प्रासंगिकता को बहुत कम कर दिया है। अब नियोक्ता और अभ्यर्थी सीधे डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हैं।

27. (C) I और II दोनों
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की शुरुआत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा पुराने पंचवार्षिक सर्वेक्षणों के स्थान पर उच्च-आवृत्ति वाले आंकड़े प्राप्त करने हेतु की गई थी। यह सर्वेक्षण ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित प्रमुख संकेतकों का अनुमान प्रदान करता है। इसमें केवल स्नातकोत्तरों का ही नहीं बल्कि सभी शैक्षणिक स्तरों के व्यक्तियों का समावेश किया जाता है।

28. (B) आनुपातिक रोजगार विस्तार के बिना होने वाली आर्थिक वृद्धि
रोजगारहीन वृद्धि आर्थिक विकास की उस स्थिति को संदर्भित करती है जहाँ सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि दर्ज की जाती है, किंतु इस वृद्धि के अनुपात में नए रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं होता। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आर्थिक वृद्धि मुख्य रुप से पूंजी-गहन अथवा अत्यधिक स्वचालित क्षेत्रों द्वारा संचालित होती है, न कि श्रम-गहन उद्योगों द्वारा।

29. (B) अपने कौशल स्तर से नीचे की भूमिका में या अपर्याप्त घंटों के लिए काम करता है
अल्प-रोजगार की स्थिति खुली बेरोजगारी से भिन्न होती है क्योंकि अल्प-नियोजित व्यक्ति तकनीकी रुप से किसी न किसी काम में लगा होता है। हालाँकि, वह अपनी वास्तविक योग्यता और कौशल स्तर की तुलना में बहुत निचले पद पर काम कर रहा होता है या उसे अपनी इच्छानुसार पूर्णकालिक घंटे काम करने का अवसर नहीं मिलता। इससे उसकी उत्पादकता और आय दोनों क्षमता से कम रहती हैं।

30. (A) I, II और III
संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के मूलभूत ढांचे और तकनीक में आने वाले दीर्घकालिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। जब उद्योग स्वचालित और आधुनिक तकनीकों को अपनाते हैं, तो पुराने कौशल वाले श्रमिकों की मांग घट जाती है। इसे दूर करने के लिए कार्यबल के पुनः प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यह कोई अल्पकालिक स्थिति नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक और गहरी संरचनात्मक समस्या है।

31. (C) अवैतनिक कृषि पारिवारिक कार्य को अक्सर आर्थिक संकेतकों से बाहर रखा जाता है
राजस्थान में महिला श्रम बल भागीदारी दर के आंकड़ों में उतार-चढ़ाव का मुख्य कारण मापन पद्धतियों का दृष्टिकोण है। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा अपने पारिवारिक खेतों और घरेलू उपक्रमों में अवैतनिक श्रम के रुप में महत्वपूर्ण योगदान देता है। औपचारिक सांख्यिकीय सर्वेक्षणों में इस आर्थिक कार्य को अक्सर नियोजित गतिविधियों से बाहर रख दिया जाता है, जिससे दरों में विषमता दिखाई देती है।

32. (D) उद्योग की आवश्यकताओं के साथ असंगत अप्रचलित पाठ्यक्रमों और उपकरणों का उपयोग करना
राजस्थान में कौशल बेमेल की समस्या को हल करने में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका अक्सर आलोचना का विषय बनती है। इसका मुख्य कारण यह है कि कई संस्थानों

Downloaded from www.pdf.tube

स्वतः ही समाप्त हो जाती है
(B) संरचनात्मक बेरोजगारी मौलिक रूप से कार्यबल के कौशलों के दीर्घकालिक संरचनात्मक बेमेल से उत्पन्न होती है
(C) चक्रीय बेरोजगारी सीधे तौर पर समग्र समष्टि आर्थिक सकल मांग में आवधिक मंदी से जुड़ी होती है
(D) जब भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तेजी के दौर में प्रवेश करती है, तो चक्रीय बेरोजगारी में सामान्यतः काफी कमी आती है

39. खुली बेरोजगारी दर की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों को सबसे व्यापक जनसांख्यिकीय आधार से विशिष्ट लक्षित समूह तक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. कुल नियोजित कार्यबल
2. सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रही बेरोजगार जनसंख्या
3. क्षेत्र की कुल जनसंख्या
4. कुल कार्यशील-आयु जनसंख्या (श्रम बल)

व्युत्पत्ति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) $3 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 2$
(B) $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$
(C) $3 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2$
(D) $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$

40. पी.एल.एफ.एस. आंकड़ों पर आधारित हालिया राष्ट्रीय तुलनाओं के अनुसार, राजस्थान की बेरोजगारी दर, विशेष रूप से युवाओं के बीच, अक्सर कैसी पाई जाती है?
(A) तीव्र और पूर्ण औद्योगीकरण के कारण सभी राज्यों में सबसे कम
(B) स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में कमी के कारण राष्ट्रीय औसत से अधिक
(C) किसी भी राज्य-विशिष्ट भिन्नता को प्रदर्शित किए बिना परिकलित राष्ट्रीय औसत के ठीक बराबर
(D) ग्रामीण कृषि स्व-रोजगार कार्यक्रमों की पूर्ण सफलता के कारण सांख्यिकीय रूप से शून्य

41. निम्नलिखित में से कौन-सा संरचनात्मक बेरोजगारी का प्राथमिक कारण नहीं है?
(A) विनिर्माण से सेवा-उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव
(B) कारखानों में अत्यधिक उन्नत स्वचालन को लागू करना
(C) मौसमी छुट्टी के कारण उपभोक्ता खर्च में अस्थायी गिरावट
(D) उपभोक्ता प्राथमिकताओं में बदलाव जिसके कारण पारंपरिक उद्योगों का पतन होता है

42. राजस्थान में युवा बेरोजगारी की समस्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त लोगों की तुलना में स्नातकों और डिग्री धारकों को अधिक प्रभावित करती है।
II. यह सरकारी सेवाओं के प्रति प्राथमिकता और अभ्यर्थियों द्वारा तैयारी में लिए जाने वाले लंबे समय से और अधिक बढ़ जाती है।
III. निजी क्षेत्र में समावेशन अत्यधिक उच्च है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के पदों की कमी की पूरी तरह से भरपाई कर देता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) केवल III
(D) I और II दोनों

43. राजस्थान के कृषि परिदृश्य में, रबी फसलों की कटाई और खरीफ फसलों की बुआई के बीच की अवधि आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी में वृद्धि का कारण बनती है?
(A) मौसमी बेरोजगारी
(B) घर्षणात्मक बेरोजगारी
(C) शिक्षित बेरोजगारी
(D) चक्रीय बेरोजगारी

NODIA

44. एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था में घर्षणात्मक बेरोजगारी सामान्यतः किस अवधि की मानी जाती है?
(A) स्थायी और आजीवन
(B) अल्पकालिक और अस्थायी
(C) दशक भर की, जो कम से कम 10 वर्षों तक रहती है
(D) बहु-पीढ़ीगत

45. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प भारत में रोजगार पर नज़र रखने के लिए ऐतिहासिक रूप से सबसे पुरानी (पारंपरिक) से सबसे हाल ही में अपनाई गई सांख्यिकीय सर्वेक्षण पद्धतियों के सही क्रम को दर्शाता है?
(A) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) → एन.एस.एस.ओ. पंचवार्षिक सर्वेक्षण → दसवार्षिक जनगणना
(B) दसवार्षिक जनगणना → एन.एस.एस.ओ. पंचवार्षिक सर्वेक्षण → आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.)
(C) एन.एस.एस.ओ. पंचवार्षिक सर्वेक्षण → आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) → दसवार्षिक जनगणना
(D) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) → दसवार्षिक जनगणना → एन.एस.एस.ओ. पंचवार्षिक सर्वेक्षण

46. यदि राजस्थान में 2-हेक्टेयर के खेत पर परिवार के 10 सदस्य काम कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान कृषि उपज को बनाए रखने के लिए वास्तव में केवल 4 की आवश्यकता है, तो शेष 6 सदस्य किसका उदाहरण हैं?
(A) प्रच्छन्न बेरोजगारी
(B) खुली बेरोजगारी
(C) संरचनात्मक बेरोजगारी

होने से पहले के मध्यवर्ती समय में खेतों में कृषि संबंधी कार्य न्यूनतम हो जाते हैं। इस अंतराल के दौरान ग्रामीण मजदूरों और किसानों के पास काम न होने से मौसमी बेरोजगारी में वृद्धि होती है।

44. (B) अल्पकालिक और अस्थायी
एक सुदृढ़ और गतिशील अर्थव्यवस्था में घर्षणात्मक बेरोजगारी को सदैव अल्पकालिक तथा अस्थायी माना जाता है। यह स्थिति तब बनती है जब व्यक्ति अपनी योग्यता सुधारने, स्थान बदलने या बेहतर वेतन पाने की इच्छा से स्वेच्छा से पुरानी नौकरी छोड़ता है। भर्ती प्रक्रियाओं, सूचना प्राप्ति और उपयुक्त नया रोजगार मिलने में लगने वाले इस थोड़े समय को अर्थव्यवस्था की एक सामान्य विशेषता समझा जाता है।

45. (B) दसवार्षिक जनगणना → एन.एस.एस.ओ. पंचवार्षिक सर्वेक्षण → आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.)
भारत में रोजगार और श्रम बाजार के आंकड़ों के संग्रह का ऐतिहासिक विकास सबसे पहले दसवार्षिक जनगणना से शुरु हुआ। इसके पश्चात राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने विस्तृत रोजगार-बेरोजगारी संकेतकों के लिए पंचवार्षिक सर्वेक्षण प्रणाली शुरु की। अंततः, श्रम बाजार के अधिक नियमित तथा उच्च बारंबारता वाले समकालीन आंकड़े प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की शुरुआत की।

46. (A) प्रच्छन्न बेरोजगारी
जब किसी सीमित आकार के खेत पर परिवार के 10 सदस्य कार्य कर रहे हों, जबकि उतनी ही उपज प्राप्त करने के लिए केवल 4 श्रमिकों की आवश्यकता पर्याप्त हो, तो शेष 6 सदस्य प्रच्छन्न बेरोजगारी का प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यद्यपि ये 6 व्यक्ति कृषि कार्य में लगे दिखाई देते हैं, किंतु कुल उत्पादन में उनका अतिरिक्त योगदान शून्य होता है और उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य रहती है।

47. (C) कौशल बेमेल
शिक्षित बेरोजगारी का एक मुख्य और दूरगामी कारण कौशल बेमेल की समस्या है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाया जाने वाला सैद्धांतिक पाठ्यक्रम और प्रदान किए जाने वाले पारंपरिक कौशल, आधुनिक उद्योगों तथा बाजार द्वारा मांगी जाने वाली व्यावहारिक और तकनीकी दक्षताओं से मेल नहीं खाते। इसके चलते उच्च शिक्षा के बाद भी अभ्यर्थियों की रोजगार क्षमता कमजोर बनी रहती है।

48. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
भारत में असंगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था में वास्तविक बेरोजगारी के स्तर को छिपाने का काम करता है। औपचारिक क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार न मिलने पर कई व्यक्ति जीवन यापन हेतु अत्यंत कम मजदूरी और निम्न उत्पादकता वाले अनौपचारिक कार्यों को स्वीकार करने पर विवश हो जाते हैं। यद्यपि वे सांख्यिकीय सर्वेक्षणों में नियोजित के रूप में दर्ज होते हैं, किंतु वास्तव में वे अल्प-रोजगार से ग्रस्त होते हैं।

49. (C) वे पंचवार्षिक आयोजित किए जाते थे, जिससे उनमें वास्तविक समय के आंकड़ों की प्रासंगिकता का अभाव था
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा पूर्व में आयोजित किए जाने वाले रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षणों की सबसे बड़ी सीमा यह थी कि वे हर पांच साल में केवल एक बार आयोजित किए जाते थे। पांच वर्षों के लंबे अंतराल के कारण इन आंकड़ों में नीति निर्माताओं के लिए वास्तविक समय के आर्थिक परिवर्तनों और श्रम बाजार की तात्कालिक गतिशीलता का अभाव रहता था।

50. (B) यह भावी रोजगार के लिए कार्य चाहने वाले के रूप में अभ्यर्थी की स्थिति दर्ज करता है
रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराने का प्राथमिक उद्देश्य यह होता है कि सरकार के पास नौकरी चाहने वाले अभ्यर्थी की योग्यता, शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव की आधिकारिक जानकारी दर्ज हो जाए। यह पंजीकरण अभ्यर्थी को एक पंजीकृत रोजगार चाहने वाले की औपचारिक पहचान प्रदान करता है, जिससे सार्वजनिक और निजी नियोक्ताओं द्वारा अधिसूचित उपयुक्त रिक्तियों के लिए उसके नाम की सिफारिश हो सके।

51. (A) P-3, Q-2, R-4, S-1
वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र में फसलों के अंतराल के दौरान मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। मशीनीकरण का सामना कर रहे पारंपरिक हस्तशिल्प क्षेत्र में तकनीक बदलाव से संरचनात्मक बेरोजगारी आती है। सामान्य डिग्रियों वाले स्नातकों की बढ़ती संख्या शिक्षित खुली बेरोजगारी को बढ़ाती है, जबकि पुराने व्यावहारिक प्रशिक्षण वाले आईटीआई पास युवा मुख्य रूप से कौशल बेमेल बेरोजगारी का सामना करते हैं।

52. (A) केवल शहरी क्षेत्र
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रति तिमाही जारी किया जाने वाला त्रैमासिक बुलेटिन विशेष रूप से केवल शहरी क्षेत्रों के रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करता है। शहरी क्षेत्रों में वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के आधार पर श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर जैसे अल्पकालिक संकेतकों की निगरानी हेतु इन्हें प्रकाशित किया जाता है।

53. (C) श्रम बल से बाहर
सांख्यिकीय और आर्थिक मानकों के अनुसार, श्रम बल में केवल वे व्यक्ति शामिल होते हैं जो या तो काम कर रहे हैं अथवा सक्रियता से रोजगार की तलाश कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति काम करने में सक्षम होने के बावजूद श्रम बाजार में नौकरी खोजने के बजाय पूर्णकालिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लेता है, तो उसे 'श्रम बल से बाहर' माना जाता है।

54. (B) I, II और IV
असंगठित क्षेत्र का रोजगार औपचारिक अनुबंधों, सेवा सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा लाभों के अभाव के लिए जाना जाता है। इसमें लगे श्रमिक उच्च स्तर के अल्प-रोजगार से प्रभावित होते

Click Here to Buy book on Flipkart

कारण (R): DBT बायोमीट्रिक पहचान की आवश्यकता को समाप्त करता है और बिना बैंक खातों के धन वितरित करने की अनुमति देता है।

(A) दोनों कथन (A) और कारण (R) सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) दोनों कथन (A) और कारण (R) सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सत्य है लेकिन कारण (R) असत्य है।
(D) कथन (A) असत्य है लेकिन कारण (R) सत्य है।

9. आवास योजनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) के प्राथमिक गरीबी-उन्मूलन आयाम को परिभाषित करता है?

(A) यह आर्थिक प्रवासियों के लिए विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में स्थित अत्यधिक सब्सिडी वाले किराये के मकान प्रदान करती है।
(B) यह केवल व्यावसायिक शहरी अचल संपत्ति खरीदने के लिए प्रत्यक्ष नकद वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
(C) यह सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का मकान प्रदान करती है।
(D) यह अपनी आवास कल्याण वित्तीय सहायता को केवल उन परिवारों तक सीमित करती है जिनके पास राज्य सरकार की नौकरियां हैं।

10. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत, अंत्योदय अन्ना योजना (AAY) के अंतर्गत आने वाले परिवार प्रति माह प्रति परिवार कितना खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं?

(A) 15 किग्रा
(B) 25 किग्रा
(C) 35 किग्रा
(D) 50 किग्रा

11. वित्तीय समावेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: वित्तीय समावेशन का प्राथमिक उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों को वहन योग्य लागत पर बैंकिंग पहुंच और औपचारिक ऋण प्रदान करना है।

कथन II: औपचारिक बैंकिंग तक पहुंच स्वाभाविक रूप से गरीबों को असंगठित साहूकारों के ऋण जाल में फंसने से बचाती है।

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

12. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की पात्रता शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
II. आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
III. आवेदक वर्तमान में राज्य सरकार के पद पर नियोजित होना चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

13. बेरोजगार युवाओं के लिए एक आधुनिक जॉब-मैचिंग ढांचा तैयार करने हेतु देश भर के रोजगार कार्यालयों के साथ किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को एकीकृत किया गया है?

(A) ई-ग्राम स्वराज
(B) नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल
(C) प्रधानमंत्री जन-धन पोर्टल
(D) उद्यम पंजीकरण पोर्टल

14. ग्रामीण वंचना को दूर करने में मनरेगा (MGNREGA) जैसे सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण दोहरा लाभ निम्नलिखित में से कौन-सा है?

(A) ये टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के साथ-साथ गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करते हैं।
(B) ये विशेष कृषि ऋण सुविधाएं प्रदान करते हैं और निर्यात-उन्मुख फसलों पर अत्यधिक सब्सिडी देते हैं।
(C) ये ग्रामीण युवाओं को उन्नत आईटी कौशल में प्रशिक्षित करते हैं और उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों में स्थापित करते हैं।
(D) ये केवल खाद्यान्न में मजदूरी का भुगतान करके मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रतिस्थापित करते हैं।

15. स्वयं सहायता समूह (SHG)-बैंक लिंक योजना गरीबी उन्मूलन का एक प्रमुख उपाय है, क्योंकि यह मुख्य रूप से ग्रामीण गरीबों द्वारा सामना की जाने वाली किस बाधा को दूर करती है?

(A) औपचारिक उच्च शैक्षणिक और पेशेवर नौकरी की योग्यता का अभाव
(B) उपजाऊ और सिंचित कृषि योग्य भूमि की अनुपलब्धता
(C) औपचारिक बैंक ऋणों के लिए पारंपरिक संपार्श्विक (Collateral/गारंटी) प्रदान करने में असमर्थता
(D) आकर्षक शहरी वाणिज्यिक व्यापार बाजारों तक सीधी पहुंच का अभाव

16. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. यह राज्य में सभी कौशल विकास पहलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
II. यह राज्य द्वारा वित्तपोषित और केंद्र प्रायोजित दोनों कौशल योजनाओं का क्रियान्वयन करता है।
III. यह निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण भागीदारों को शामिल किए बिना कार्य करता है।
IV. इसे धारा 25 (अब धारा 8) की गैर-लाभकारी कंपनी के

NODIA

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from
PRINTED BOOKS has up to
4× HIGHER RETENTION
than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

के साथ-साथ काम की सक्रियता से तलाश कर रहे बेरोजगार व्यक्ति भी शामिल होते हैं। दूसरी ओर, कार्य बल श्रम बल का केवल वही व्यावहारिक घटक है जिसमें वास्तव में किसी न किसी उत्पादक आर्थिक गतिविधि में नियोजित और कार्यरत व्यक्तियों को शामिल किया जाता है।

66. (B) यह वास्तव में अपरिवर्तित रहता है
प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र की एक ऐसी स्थिति है जहाँ आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं और उनमें से अधिशेष श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। यदि ऐसे अतिरिक्त श्रमिकों को खेत से निकालकर किसी नए स्थानीय विनिर्माण उद्योग में स्थानांतरित कर दिया जाए, तो भी कुल कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह वास्तव में पूरी तरह अपरिवर्तित बना रहता है।

67. (D) गर्त/मंदी
चक्रीय बेरोजगारी समष्टि आर्थिक व्यापार चक्र की अवस्थाओं के साथ सीधे परिवर्तित होती है। जब अर्थव्यवस्था अपने व्यापार चक्र के सबसे निचले बिंदु यानी गर्त या गंभीर मंदी के चरण में पहुंचती है, तो सकल मांग अपने न्यूनतम स्तर पर आ जाती है। व्यावसायिक गतिविधियां ठप होने से कारखाने और उद्योग बड़े पैमाने पर छंटनी करते हैं, जिससे चक्रीय बेरोजगारी अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच जाती है।

68. (B) I, III और IV
भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का संचालन एन.एस.ओ. द्वारा किया जाता है तथा दसवार्षिक जनगणना जनसंख्या को मुख्य, सीमांत और गैर-कामगारों में वर्गीकृत करती है। पी.एल.एफ.एस. ने शहरी क्षेत्रों के लिए साप्ताहिक स्थिति की अवधारणा अपनाई है। हालांकि, रोजगार कार्यालयों के आंकड़े पूर्णतः सटीक नहीं होते क्योंकि कई नियोजित लोग भी पंजीकरण कराते हैं और कई बेरोजगार वहां पंजीकृत ही नहीं होते हैं।

69. (C) पिछले 7 दिनों का प्रत्येक दिन
वर्तमान दैनिक स्थिति दृष्टिकोण बेरोजगारी और अल्प-रोजगार को मापने के लिए सबसे सूक्ष्म सांख्यिकीय मापदंड है। इस विधि के अंतर्गत सर्वेक्षण से ठीक पहले के पिछले 7 दिनों में से प्रत्येक दिन की गतिविधि स्थिति का गहनता से आकलन किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दिन 4 घंटे या उससे अधिक काम करता है तो उसे उस दिन के लिए पूर्ण दिवस नियोजित माना जाता है।

70. (A) दृश्य अल्प-रोजगार
जब कोई उच्च योग्य महिला इंजीनियर अपनी शैक्षणिक योग्यता से काफी कम स्तर की भूमिका में काम करने के लिए मजबूर होती है और स्थानीय अवसरों के अभाव में केवल अंशकालिक ट्यूटर के रूप में कार्य करती है, तो यह स्थिति दृश्य अल्प-रोजगार को प्रदर्शित करती है। इसमें व्यक्ति नियोजित तो दिखता है लेकिन उसकी क्षमता और आय उसकी योग्यता से बहुत कम होते हैं।

71. (D) अभ्यर्थियों के कौशल और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच कौशल बेमेल
सरकारी कौशल विकास योजनाओं का मुख्य लक्ष्य श्रम बाजार में व्याप्त कौशल बेमेल की समस्या को दूर करना है। यह असंतुलन तब बनता है जब कार्य चाहने वाले युवाओं के पास उपलब्ध पारंपरिक शैक्षणिक योग्यताएं आधुनिक उद्योगों और बाजार की वर्तमान व्यावहारिक आवश्यकताओं से मेल नहीं खातीं। कौशल विकास कार्यक्रम युवाओं को प्रासंगिक व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें उद्योग के अनुकूल और सीधे रोजगार योग्य बनाते हैं।

72. (B) रोजगार की सुरक्षा में कमी और औपचारिक रोजगार अनुबंधों की अनुपस्थिति
असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार की सबसे प्रमुख और चिंताजनक विशेषता लिखित औपचारिक रोजगार अनुबंधों का न होना तथा रोजगार की सुरक्षा का पूर्ण अभाव है। इस क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को बिना किसी पूर्व सूचना के काम से निकाला जा सकता है और वे पेंशन या स्वास्थ्य बीमा जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित रहते हैं, जिससे उनकी सुभेद्यता बनी रहती है।

73. (C) 15 से 59 वर्ष
भारत में श्रम बल और रोजगार संकेतकों की गणना हेतु कार्यशील-आयु आबादी के मानक का निर्धारण करते समय पारंपरिक रूप से 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग को माना जाता है। इस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उत्पादक आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए सक्षम समझा जाता है। 15 से कम और 60 से अधिक आयु के व्यक्तियों को आश्रित माना जाता है।

74. (D) स्थानीय स्तर पर गैर-कृषि आजीविका के अवसरों की गंभीर कमी
राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं के शहरी केंद्रों में पलायन के लिए सबसे प्रमुख 'प्रतिकर्ष-कारक' स्थानीय स्तर पर पर्याप्त तथा टिकाऊ गैर-कृषि आजीविका के अवसरों की गंभीर कमी होना है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में केवल मानसूनी कृषि ही एकमात्र साधन बचती है और वह भी अनिश्चित होती है, तो युवा अपनी आजीविका चलाने के लिए बाहर जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं।

NODIA

75. (A) व्यक्ति दैनिक आधार पर लाभकारी रूप से नियोजित प्रतीत होते हैं
मानक सर्वेक्षणों के माध्यम से प्रच्छन्न बेरोजगारी का सटीक मापन करना अत्यंत कठिन होता है क्योंकि इसमें प्रभावित व्यक्ति दिन-प्रतिदिन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न और लाभकारी रूप से नियोजित प्रतीत होते हैं। वे आधिकारिक गणना के समय स्वयं को कार्यरत बताते हैं, जबकि वास्तव में उनकी उपस्थिति से कुल उत्पादन में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं होती और सीमांत उत्पादकता शून्य रहती है।

76. (B) संरचनात्मक बेरोजगारी
श्रम की बचत करने वाली अत्याधुनिक मशीनों, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अपनाने से उत्पन्न होने वाली तकनीकी

बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी का ही एक प्रमुख उप-प्रकार माना जाता है। यह बेरोजगारी तब आती है जब उत्पादन की तकनीकों में ऐसा तकनीकी बदलाव होता है जो पुराने कौशलों को पूरी तरह अप्रासंगिक बना देता है और श्रम की मांग को बदल देता है।

77. (B) औपचारिक रोजगार सृजन की तुलना में अधिशेष शिक्षित श्रम
जब राज्य सरकार की सीमित संख्या वाली प्रशासनिक और तकनीकी रिक्तियों के लिए लाखों शिक्षित अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, तो यह परिदृश्य श्रम बाजार में औपचारिक रोजगार सृजन की तुलना में शिक्षित श्रम की भारी अधिशेष आपूर्ति को दर्शाता है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि अर्थव्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण और स्थायी नौकरियों का सृजन उस गति से नहीं हो रहा जिस गति से शिक्षित स्नातक बढ़ रहे हैं।

78. (A) अधिशेष कृषि श्रम को विनिर्माण और सेवाओं में पुनः आवंटित करना
कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या का स्थायी और तर्कसंगत समाधान यही है कि खेतों पर लगे अधिशेष और कम उत्पादकता वाले श्रम बल को गैर-कृषि क्षेत्रों जैसे विनिर्माण, निर्माण और सेवा उद्योगों में पुनः आवंटित किया जाए। इससे कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम होगा और अन्य क्षेत्रों में उत्पादक कार्यबल बढ़ने से आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

79. (C) एक स्नातक जो सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहा है लेकिन उसे एक वर्ष से कोई रोजगार प्रस्ताव नहीं मिला है
खुली बेरोजगारी की अवधारणा उस स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें कोई व्यक्ति उत्पादक कार्य करने में पूरी तरह सक्षम और इच्छुक होता है तथा सक्रिय रूप से आजीविका की तलाश भी करता है, किंतु दीर्घ अवधि तक उसे कोई भी रोजगार प्राप्त नहीं होता। जैसे कि एक डिग्री धारक स्नातक का एक वर्ष तक प्रयास करने के बाद भी बेरोजगार रहना इसका उदाहरण है।

80. (D) पाठ्यक्रम को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और गैर-कृषि क्षेत्रों में निवेश करना
राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारी की गंभीर समस्या के समाधान के लिए एक बहुआयामी नीतिगत रणनीति की आवश्यकता है। इसके तहत शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को आधुनिक उद्योगों की व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्गठित करना आवश्यक है। इसके साथ ही युवाओं में स्व-रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा गैर-कृषि उद्योगों में निवेश बढ़ाकर गुणवत्तापूर्ण रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाने चाहिए।

Downloaded from www.pdf.tube

अध्याय 23

गरीबी एवं बेरोज़गारी के समाधान तथा वर्तमान प्रमुख सरकारी योजनाएँ

1. निम्नलिखित में से कौन-सा एक सामान्य गरीबी उन्मूलन रणनीति के रूप में परिसंपत्ति निर्माण (asset creation) के मूल सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
   (A) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मासिक उपभोग अनुदान प्रदान करना
   (B) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न वितरित करना
   (C) ऐसे स्थायी भौतिक या वित्तीय संसाधनों का सृजन करना जो गरीबों के लिए भविष्य में निरंतर आय सक्षम बनाते हैं
   (D) शहरी युवाओं को अस्थायी रोजगार से जोड़ने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन करना

2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) निम्नलिखित में से किस पूर्ववर्ती गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का पुनर्गठन करके शुरू किया गया था?
   (A) जवाहर रोजगार योजना
   (B) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)
   (C) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
   (D) इंदिरा आवास योजना

3. राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पात्र महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को कितना मासिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है?
   (A) ₹3,000
   (B) ₹3,500
   (C) ₹4,000
   (D) ₹4,500

4. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
   सूची I: (योजना/पहल)
   P. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना
   Q. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना
   R. प्रधानमंत्री आवास योजना
   S. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
   सूची II: (प्राथमिक उद्देश्य)
   1. भुखमरी से जुड़ी वंचना को दूर करना
   2. ग्रामीण युवा कौशल प्रशिक्षण
   3. बेरोजगारी भत्ता और इंटर्नशिप
   4. आवास संबंधी गरीबी में कमी
   (A) P-3, Q-2, R-4, S-1
   (B) P-2, Q-3, R-1, S-4
   (C) P-3, Q-4, R-2, S-1
   (D) P-4, Q-2, R-3, S-1

5. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) मूल रूप से वर्ष 2004 में निम्नलिखित में से किस नाम से स्थापित किया गया था?
   (A) राजस्थान आजीविका प्राधिकरण (RLA)
   (B) राज्य कौशल विकास परिषद
   (C) राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड्स (RMoL)
   (D) राजस्थान ग्रामीण रोजगार बोर्ड

6. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (DDU-GKY) के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य नियोजन (Placement) की क्या शर्त है?
   (A) सभी प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से 50% को वेतनभोगी रोजगार में रखा जाना अनिवार्य है।
   (B) सभी प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से 70% को वेतनभोगी रोजगार में रखा जाना अनिवार्य है।
   (C) सभी प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से 100% को स्वरोजगार में स्थापित किया जाना अनिवार्य है।
   (D) नियोजन की कोई अनिवार्य शर्त नहीं है; यह पूरी तरह से एक प्रमाणन योजना है।

NODIA

7. निम्नलिखित में से कौन-सा राजस्थान की iStart नीति का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है?
   (A) प्रारंभिक चरण के उद्यमों को परामर्श (Mentorship) और इन्क्यूबेशन सहायता प्रदान करना
   (B) सीड फंडिंग और वेंचर कैपिटल तक पहुँच को सुगम बनाना
   (C) छात्रों और ग्रामीण नवोन्मेषकों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना
   (D) असफल स्टार्टअप्स के संस्थापकों के लिए सरकारी नौकरियों की गारंटी देना

8. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है:
   कथन (A): प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) ने गरीबी उन्मूलन योजनाओं की लक्षित दक्षता में काफी सुधार किया है।

1. कौशल विकास और आजीविका सृजन
2. एकीकृत निवासी डेटा और लाभ अंतरण
3. औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा
4. स्टार्टअप और उद्यमिता संवर्धन

(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-4, R-3, S-2
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-2, S-4

25. आधार एकीकरण ने NFSA के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के कार्यान्वयन में विशेष रूप से कैसे सुधार किया है?
(A) दुकानों पर सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए वसूल की जाने वाली अधिकतम खुदरा बिक्री दर को बढ़ाकर।
(B) भौतिक खाद्यान्न को पूरी तरह से बैंक खातों में सीधे नकद जमा से प्रतिस्थापित करके।
(C) फर्जी (Ghost) लाभार्थियों और डुप्लिकेट राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण को सक्षम करके।
(D) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी लाभों को केवल शहरी निवासियों तक सीमित करके।

26. उद्यमिता संवर्धन के संदर्भ में बिजनेस इन्क्यूबेशन सेंटर की प्राथमिक भूमिका निम्नलिखित में से कौन-सी है?
(A) नई पंजीकृत कंपनियों से सीधे अनिवार्य कॉर्पोरेट आयकर का आकलन करना और उसका संग्रह करना।
(B) संघर्षरत व्यवसायों के परिचालन प्रबंधन और कार्यकारी नियंत्रण को संभालना।
(C) बड़े पैमाने के निगमों की सार्वजनिक शेयर बाजार लिस्टिंग और अनुपालन को विनियमित करना।
(D) स्टार्टअप्स को कार्यस्थल, मार्गदर्शन (Mentorship) और शुरुआती नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना।

27. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी रियायती ऋण योजनाओं का उद्देश्य मुख्य रूप से किसे ऋण प्रदान करके स्वरोजगार को बढ़ावा देना है?
(A) गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को
(B) बड़े पैमाने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को
(C) सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को
(D) कृषि भूमि खरीदने के लिए विशेष रूप से किसानों को

28. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है:
कथन (A): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) गरीबी उन्मूलन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है।
कारण (R): यह आबादी के एक बड़े हिस्से को कानूनी रूप से अत्यधिक सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिससे उनकी वास्तविक आय की रक्षा होती है और भोजन पर होने वाले जेब के खर्च में कमी आती है।
(A) दोनों कथन (A) और कारण (R) सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) दोनों कथन (A) और कारण (R) सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सत्य है लेकिन कारण (R) असत्य है।
(D) कथन (A) असत्य है लेकिन कारण (R) सत्य है।

29. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की एक केंद्रीय मान्यता यह है कि गरीबों में जन्मजात क्षमताएं होती हैं। NRLM इन क्षमताओं का उपयोग करने के लिए मुख्य रूप से किस संस्थागत तंत्र का उपयोग करता है?
(A) सरकार द्वारा संचालित शहरी रोजगार कार्यालय और जॉब पोर्टल
(B) महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) और उनके संघ (Federation)
(C) निजी वाणिज्यिक सूक्ष्मवित्त (Microfinance) और ऋण देने वाले संस्थान
(D) स्थानीय स्तर पर काम करने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

30. भारत में गरीबी को आमतौर पर निरपेक्ष गरीबी रेखा का उपयोग करके मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा निरपेक्ष गरीबी रेखा को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है?
(A) बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक आय या उपभोग व्यय की एक निश्चित न्यूनतम सीमा।
(B) शीर्ष 10% और सबसे निचले 10% नागरिकों के बीच मौजूद धन की असमानता पर आधारित एक सापेक्ष माप।
(C) संपूर्ण राष्ट्रीय जनसंख्या की औसत आय को दो से विभाजित करके गणना की गई एक सीमा।
(D) राज्य के आर्थिक औसत की तुलना में किसी परिवार के कुल वित्तीय संपत्ति मूल्यांकन की तुलना।

31. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत, कोई अभ्यर्थी अधिकतम कितनी अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर सकता है?
(A) 1 वर्ष या रोजगार मिलने तक, जो भी पहले हो
(B) 2 वर्ष या रोजगार मिलने तक, जो भी पहले हो
(C) 3 वर्ष या रोजगार मिलने तक, जो भी पहले हो
(D) रोजगार की स्थिति की परवाह किए बिना लगातार 5 वर्ष

32. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (DDU-GKY) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह विशेष रूप से 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को लक्षित करती है।
II. यह बिना किसी केंद्रीय योगदान के पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित है।
III. यह एक प्लेसमेंट-लिंक्ड (रोजगार से जुड़ा) कौशल

Click Here to Buy book on Amazon

रूप में निगमित किया गया था।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

17. युवाओं की योग्यता को उपलब्ध रोजगार के अवसरों के साथ मैपिंग करने की प्रक्रिया, जो संरचनात्मक बेरोजगारी का एक आवश्यक उपाय है, औपचारिक रूप से किस नाम से जानी जाती है?
(A) जनसांख्यिकी मैपिंग (Demographic mapping)
(B) प्रत्यक्ष लाभ मैपिंग (Direct benefit mapping)
(C) कौशल मैपिंग और करियर परामर्श (Skill mapping and career counselling)
(D) परिसंपत्ति मौद्रिकरण (Asset monetization)

18. औद्योगिक प्रोत्साहन मौलिक रूप से सामान्य बेरोजगारी को कम करने की रणनीति के रूप में कैसे कार्य करता है?
(A) विभिन्न क्षेत्रों में मानवीय श्रम को आधुनिक स्वचालित औद्योगिक प्रौद्योगिकियों से बदलकर।
(B) निवेश को आकर्षित करके जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मजदूरी रोजगार के अवसरों के सृजन को बढ़ावा देता है।
(C) प्राथमिक कृषि गतिविधियों पर कार्यशील जनसंख्या की निर्भरता को बढ़ाकर।
(D) पारंपरिक ग्रामीण हस्तशिल्प को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहरी विस्तार को सीमित करके।

19. उत्पादकता वृद्धि पर केंद्रित कृषि सुधार को मुख्य रूप से गरीबी निवारण की रणनीति माना जाता है क्योंकि:
(A) यह छोटे किसानों को कारखानों में रोजगार के लिए महानगरों की ओर पलायन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
(B) यह सभी सीमांत ग्रामीण कृषि भूमियों को पूरी तरह से समर्पित औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रों में परिवर्तित कर देता है।
(C) यह औपचारिक ग्रामीण ऋण और बैंकिंग संस्थानों की दीर्घकालिक संस्थागत आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर देता है।
(D) यह छोटे और सीमांत कृषि किसानों के विपणन योग्य अधिशेष और वास्तविक आय में सीधी वृद्धि करता है।

20. निम्नलिखित में से कौन-सा एक लक्षित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) निष्पादन प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम दर्शाता है?
(A) लाभार्थी की पहचान - आधार सीडिंग - कोष स्वीकृति - बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण
(B) आधार सीडिंग - बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण - कोष स्वीकृति - लाभार्थी की पहचान
(C) कोष स्वीकृति - लाभार्थी की पहचान - बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण - आधार सीडिंग
(D) बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण - कोष स्वीकृति - लाभार्थी की पहचान - आधार सीडिंग

NODIA

21. घर्षणजन्य बेरोजगारी (Frictional unemployment), जिसे सामान्य बेरोजगारी उन्मूलन रणनीतियों द्वारा संबोधित किया जाना आवश्यक है, को सबसे बेहतर रूप में किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है?
(A) उपलब्ध नौकरी के कौशलों और बाजार की मांगों के बीच संरचनात्मक असंतुलन के परिणामस्वरूप उत्पन्न बेरोजगारी।
(B) किसी विशिष्ट उद्योग में दीर्घकालिक संरचनात्मक गिरावट या तकनीकी बदलाव के कारण होने वाली बेरोजगारी।
(C) विभिन्न नौकरियों के बीच परिवर्तन (Transition) के दौरान व्यक्तिगत श्रमिकों द्वारा अनुभव की जाने वाली अस्थायी बेरोजगारी।
(D) कृषि और सम्बद्ध फसल कटाई के मौसम में होने वाले नियमित मौसमी उतार-चढ़ाव के कारण बेरोजगारी।

22. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच "योजना अभिसरण" (Scheme Convergence) का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या प्राप्त करना है?
(A) दोहराव वाले प्रयासों को समाप्त करना, पुनरावृत्ति से बचना और संसाधन दक्षता को अधिकतम करना।
(B) गरीबी संबंधी योजनाओं के लिए कुल बजटीय वित्तीय आवंटन और केंद्रीय व्यय को कम करना।
(C) पूरे कार्यान्वयन और परिचालन के बोझ को निजी गैर-सरकारी निकायों पर स्थानांतरित करना।
(D) यह सुनिश्चित करना कि एकीकृत केंद्रीय योजनाओं के पक्ष में राज्य की योजनाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए।

23. योजना निष्पादन के संदर्भ में, "अंतिम मील तक वितरण की चुनौतियां" (Last-mile delivery challenges) सबसे सटीक रूप से किसे संदर्भित करती हैं?
(A) केंद्र सरकार के स्तर पर उच्च स्तरीय प्रशासनिक नीतियों का रणनीतिक निर्माण।
(B) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा योजना कोष के लेखापरीक्षा की व्यापक प्रक्रिया।
(C) घरेलू गरीबी योजनाओं के लिए आयोजित औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण और ऋण वार्ता।
(D) कार्यान्वयन संबंधी कमियां जो जमीनी स्तर पर लक्षित लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने में बाधा डालती हैं।

24. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (राजस्थान संस्थागत ढांचा/पहल)
P. आईस्टार्ट राजस्थान (iStart)
Q. RSLDC
R. जन आधार प्राधिकरण
S. रीको (RIICO)
सूची II: (मुख्य फोकस क्षेत्र)

हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त कार्य और निश्चित आय नहीं मिलती। यह क्षेत्र राजस्थान के विशाल कार्यबल को समाहित करता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासन करने वाले अधिशेष श्रमिकों को अवशोषित करता है।

55. (D) कौशल संक्रमण में देरी के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी
आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जब अर्थव्यवस्था की निर्भरता कृषि से हटकर औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होती है, तो श्रम बल की मांगों में गहरा परिवर्तन आता है। कृषि क्षेत्र से निकलने वाले श्रमिकों के पास आधुनिक उद्योगों के अनुकूल प्रासंगिक कौशल नहीं होते। इस कौशल संक्रमण में देरी के कारण मध्यकालिक चरण में व्यापक संरचनात्मक बेरोजगारी पैदा होती है।

56. (B) धीमी रोजगार सृजन दर के साथ उच्च आर्थिक वृद्धि
यदि किसी राज्य में औद्योगिक विकास मुख्यतः पूंजी-गहन तकनीकों और आधुनिक स्वचालित मशीनों पर आधारित होता है, तो इससे उत्पादन और सकल घरेलू उत्पाद में तो तेज वृद्धि देखने को मिलती है, परंतु विशाल श्रम शक्ति के अनुपात में नए रोजगार का सृजन बेहद कम होता है। इसके परिणामस्वरुप उच्च आर्थिक संवृद्धि दर के बावजूद रोजगार सृजन की दर धीमी बनी रहती है।

57. (A) I और II दोनों
भारत और राजस्थान में महिला श्रम बल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पारिवारिक खेतों तथा घरेलू कार्यो में अवैतनिक रूप से योगदान देता है, जिन्हें औपचारिक आर्थिक आंकड़ों से बाहर रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड, पारिवारिक जिम्मेदारियां तथा कार्यस्थल की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी महिलाओं की औपचारिक श्रम बल भागीदारी को सीमित करती हैं। शहरी क्षेत्रों में महिला भागीदारी दर कम रहती है।

58. (D) मौसमी बेरोजगारी — ग्रामीण कृषि क्षेत्र
मौसमी बेरोजगारी की सबसे अधिक सांद्रता ग्रामीण कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि कार्य पूरी तरह से मानसून तथा फसलों की बुआई और कटाई के प्राकृतिक चक्रों पर निर्भर होता है। फसल चक्र के मध्यवर्ती महीनों में जब खेत में कोई काम नहीं होता, तब कृषि मजदूर और छोटे किसान बिना काम के बेरोजगार हो जाते हैं, जो मौसमी बेरोजगारी का उदाहरण है।

59. (A) गारंटीकृत व्हाइट-कॉलर शहरी रोजगार के प्रस्ताव
राजस्थान में कृषि मजदूरों का मौसमी प्रवासन मुख्यतः मानसून की विफलता, बार-बार पड़ने वाले सूखे और गैर-कृषि मौसम के दौरान स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसरों की अनुपस्थिति जैसे विकट कारकों से प्रेरित होता है। यह प्रवासन कम कृषि आय को पूरा करने की मजबूरी के कारण होता है। किसी गारंटीकृत व्हाइट-कॉलर शहरी रोजगार के प्रस्ताव इस प्रवासन का कारण नहीं होते हैं।

60. (B) रोजगार की उपलब्धता के बावजूद लोग प्रचलित मजदूरी पर काम न करने का विकल्प चुनते हैं
स्वैच्छिक बेरोजगारी एक ऐसी आर्थिक स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें श्रम बाजार में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं और प्रचलित मजदूरी दर पर काम मिल सकता है, परंतु व्यक्ति स्वेच्छा से उस मजदूरी दर पर काम न करने का विकल्प चुनता है। ऐसा व्यक्ति बेहतर वेतन, उच्च पद की तलाश या व्यक्तिगत कारणों से कार्य से दूर रहता है, इसलिए इसे स्वैच्छिक माना जाता है।

61. (B) जो लोग प्रचलित मजदूरी पर काम करने के इच्छुक हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है
अनैच्छिक बेरोजगारी बेरोजगारी का वह वास्तविक रूप है जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो वर्तमान में प्रचलित बाजार मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार, इच्छुक और सक्षम हैं, परंतु इसके बावजूद उन्हें बाजार में कोई उत्पादक रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता। आर्थिक विश्लेषणों और सांख्यिकीय सर्वेक्षणों में इसी स्थिति को बेरोजगारी का वास्तविक मापदंड माना जाता है।

62. (A) सॉफ्ट स्किल, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक विशेषज्ञता में गंभीर कमी
राजस्थान में कला और विज्ञान में सामान्य डिग्रियां प्राप्त करने वाले स्नातकों की संख्या बहुत अधिक है। हालाँकि, इन सामान्य स्नातकों में व्यावहारिक सॉफ्ट स्किल्स, तकनीकी दक्षता और उद्योग-उन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण का गंभीर अभाव होता है। जब बाजार की मांगों के अनुरूप व्यावसायिक विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं होती, तो डिग्रियां होने के बावजूद स्नातकों के सामने बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाती है।

63. (C) संरचनात्मक बेरोजगारी
जब कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को अपनाया जाता है और ट्रैक्टर तथा हार्वेस्टर जैसी आधुनिक मशीनें शारीरिक श्रम का स्थान ले लेती हैं, तो इससे कृषि उत्पादन की तकनीक में मूलभूत संरचनात्मक परिवर्तन आता है। इस तकनीकी बदलाव के कारण पारंपरिक शारीरिक श्रम करने वाले भूमिहीन कृषि मजदूरों की मांग घट जाती है, जिससे उनमें संरचनात्मक बेरोजगारी में वृद्धि होती है।

64. (D) जनगणना संपूर्ण जनसंख्या की गणना है, जबकि पी.एल.एफ.एस. विस्तृत संकेतकों के लिए एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण है
दसवार्षिक जनगणना देश के प्रत्येक नागरिक और परिवार को कवर करने वाली एक पूर्ण जनसांख्यिकीय गणना है, जिसमें बुनियादी रोजगार श्रेणियां दर्ज की जाती हैं। इसके विपरीत, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संचालित एक वैज्ञानिक प्रतिदर्श सर्वेक्षण है। पी.एल.एफ.एस. पूरे देश से चुने गए विशिष्ट नमूनों के आधार पर श्रम बाजार के विस्तृत और उच्च-आवृत्ति वाले आंकड़े प्रदान करता है।

65. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
श्रम बल अर्थव्यवस्था में उन सभी व्यक्तियों का योग है जो आपूर्ति पक्ष का निर्माण करते हैं, जिसमें नियोजित कामगारों

Downloaded from www.pdf.tube

विकास कार्यक्रम है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

33. स्टार्टअप्स का मूल्यांकन करने और उन्हें रेटिंग देने के लिए राजस्थान स्टार्टअप नीति के तहत शुरु किया गया प्रमुख स्टार्टअप मूल्यांकन कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है?
(A) स्टार्ट-चेक (Start-Check)
(B) राज-वैल्यू (Raj-Value)
(C) क्यू-रेट (Q-Rate)
(D) इनोवेट-स्केल (Innovate-Scale)

34. निम्नलिखित में से कौन-सा सामान्य रूप से लागू किए जाने वाले प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) तंत्र का एक अपवाद है?
(A) छात्रवृत्ति की राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में स्थानांतरित करना
(B) स्थानीय स्कूलों के माध्यम से भौतिक रूप से साइकिल और लैपटॉप वितरित करना
(C) मनरेगा (MGNREGA) श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान सीधे उनके सत्यापित बैंक खातों में करना
(D) एलपीजी सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के खाते में स्थानांतरित करना

35. कार्यान्वयन की कमियों को दूर करने के लिए, PMAY-G जैसी योजनाएं "आवाससॉफ्ट" (AwaasSoft) और "आवासऐप" (AwaasApp) का उपयोग करती हैं। इनका प्राथमिक कार्य क्या है?
(A) सब्सिडी वाले आवास गृहों के अनुकूलित स्थापत्य संरचनात्मक लेआउट तैयार करना और डिजाइन करना।
(B) मध्यम आय वाले शहरी समूहों को सीधे कम ब्याज वाले वाणिज्यिक आवास ऋण संसाधित करना और प्रदान करना।
(C) निर्धारित दरों पर ऑनलाइन भवन निर्माण सामग्री बेचने के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्थापित करना।
(D) व्यक्तिगत मकान निर्माण कार्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रैक करना।

36. प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए:
I. लाभार्थियों का चयन SECC 2011 के आंकड़ों और ग्राम सभा के सत्यापन पर आधारित है।
II. निर्माण शुरु होने से पहले धनराशि पूरी तरह से एक ही किश्त में स्थानांतरित कर दी जाती है।
III. निर्धारित न्यूनतम इकाई का आकार 25 वर्ग मीटर है, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए एक समर्पित क्षेत्र शामिल है।
IV. यह अनिवार्य करता है कि मकान का स्वामित्व अधिमानतः परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या संयुक्त रूप से हो।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, II और IV

NODIA

37. दूरदराज के क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के संदर्भ में, "बैंक मित्र" या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) की क्या भूमिका है?
(A) बड़े पैमाने के कॉर्पोरेट वाणिज्यिक ऋण सुरक्षित करने के लिए आधिकारिक वित्तीय गारंटर के रूप में कार्य करना।
(B) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग संस्थाओं की वित्तीय लेखा पुस्तकों का निरीक्षण और लेखापरीक्षा करना।
(C) गांव के स्तर पर किसी वित्तीय बैंक की ओर से शाखा-रहित Banking सुविधाएं प्रदान करना।
(D) स्थानीय किसानों को सीधे सब्सिडी वाले कृषि बीज और रासायनिक उर्वरक वितरित करना।

38. प्रमुख गरीबी योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन करते समय, "परिणाम ट्रैकिंग" (Outcome tracking) "आउटपुट ट्रैकिंग" (Output tracking) से भिन्न होती है क्योंकि परिणाम ट्रैकिंग आकलन करती है:
(A) लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और निरंतर आजीविका में वास्तविक सुधार का।
(B) एक वित्तीय वर्ष के भीतर राज्य द्वारा किया गया कुल वित्तीय व्यय और संवितरित पूंजी का।
(C) जिलों में खोले गए सरकार द्वारा वित्तपोषित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की कुल भौतिक संख्या का।
(D) आधिकारिक योजना पोर्टल पर प्राप्त और दर्ज किए गए डिजिटल लाभ आवेदनों की कुल मात्रा का।

39. उस योजना की पहचान कीजिए जो राजस्थान में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश के दौरान एक सहायक सहायता तंत्र प्रदान करने के लिए स्पष्ट रूप से तैयार की गई है।
(A) मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
(B) मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
(C) राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना
(D) मुख्यमंत्री युवा संबल योजना

40. कौशल प्रशिक्षण और रोजगार जीवनचक्र (जैसा कि RSLDC द्वारा परिकल्पित है) के निम्नलिखित चरणों को सही तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. अभ्यर्थियों का लामबंदी (Mobilization) और परामर्श
2. प्लेसमेंट के बाद ट्रैकिंग
3. कौशल मूल्यांकन और प्रमाणन
4. मुख्य कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही अनुक्रमिक क्रम दर्शाता है?
(A) 1, 4, 3, 2

(B) 4, 1, 3, 2
(C) 1, 3, 4, 2
(D) 4, 3, 1, 2

41. मनरेगा (MGNREGA) सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किसे "परिसंपत्ति निर्माण" परिणाम माना जाता है?
(A) ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण
(B) वार्षिक ग्रामीण सामुदायिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन और संचालन
(C) एक स्थायी ग्रामीण जल संरक्षण तालाब का निर्माण
(D) स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए जिला स्तरीय करियर मेलों का आयोजन

42. गरीबी योजनाओं में लक्षित दक्षता में सुधार की रीढ़ माने जाने वाले "JAM Trinty" का पूरा नाम क्या है?
(A) जस्टिस, आधार, माइक्रोफाइनेंस
(B) जॉब्स, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग
(C) जन-सुरक्षा, आवास, मुद्रा
(D) जन-धन, आधार, मोबाइल

43. निम्नलिखित में से कौन-सा कृषि क्षेत्र में ग्रामीण गरीबी का एक मुख्य कारण, "प्रच्छन्न बेरोजगारी" (Disguised unemployment) का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) इष्टतम उत्पादन के लिए वास्तव में जितने लोगों की आवश्यकता है, उससे अधिक लोग कृषि गतिविधि में लगे हुए हैं।
(B) कृषि श्रमिक पूरे वर्ष के दौरान पूरी तरह से लाभकारी मजदूरी रोजगार के बिना रहते हैं।
(C) ग्रामीण कृषि श्रमिक शहरों में पलायन करते हैं लेकिन लगातार उपयुक्त रोजगार पाने में विफल रहते हैं।
(D) पारंपरिक हस्तचलित कृषि श्रमिकों को आधुनिक स्वचालित कृषि मशीनों द्वारा स्थायी रूप से बदल दिया जाता है।

44. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (गरीबी/रोजगार रणनीति)
P. घर्षणजन्य बेरोजगारी
Q. संरचनात्मक बेरोजगारी
R. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
S. सूक्ष्मवित्त (Microfinance)
सूची II: (परिभाषा/विशेषता)
1. कम आय वाले ग्राहकों को छोटे ऋण का प्रावधान
2. उपलब्ध कौशल और बाजार की आवश्यकताओं का असंतुलन होना
3. नौकरी बदलने के बीच की समय अवधि
4. सीधे बैंक खातों में सब्सिडी का वितरण
(A) P-3, Q-2, R-4, S-1
(B) P-2, Q-3, R-1, S-4
(C) P-3, Q-4, R-2, S-1
(D) P-4, Q-1, R-3, S-2

45. राजस्थान में आईटी और गैर-आईटी स्टार्टअप्स के लिए प्लग-एंड-प्ले वातावरण, साझा बुनियादी ढांचा और नेटवर्किंग प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी राज्य नीति विशेष रुप से तैयार की गई है?
(A) राजस्थान औद्योगिक विकास नीति
(B) राजस्थान स्टार्टअप नीति
(C) राजस्थान कृषि निर्यात नीति
(D) राजस्थान पर्यटन इकाई नीति

46. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के वर्तमान दिशा-निर्देशों के तहत, बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य रूप से क्या आवश्यक है?
(A) किसी सरकारी विभाग में प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप करना।
(B) अधिकारियों के समक्ष अपने पारिवारिक राशन कार्ड जमा करना।
(C) अपने निवास को स्थायी रूप से किसी महानगरीय शहर में स्थानांतरित करना।
(D) रोजगार मिलते ही प्राप्त भत्ते को पूरी तरह से वापस चुकाना।

47. NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के संदर्भ में, "पंचसूत्र" का सिद्धांत मुख्य रुप से किसका मार्गदर्शन करता है?
(A) एक बड़े पैमाने के भारी औद्योगिक कारखाने की स्थापना के लिए आवश्यक पांच क्रमिक प्रशासनिक चरण।
(B) पांच अनिवार्य वाणिज्यिक कृषि फसलें जो सभी पंजीकृत समूह सदस्यों द्वारा उगाई जानी चाहिए।
(C) पांच मुख्य परिचालन अभ्यास: नियमित बैठकें, बचत, आंतरिक ऋण, पुनर्भुगतान और बहीखाता लेखन।
(D) समूह के पंजीकरण और निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले पांच केंद्र सरकार के डिजिटल वेब पोर्टल।

48. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है:
कथन (A): लोक प्रशासन में केंद्र-राज्य योजना अभिसरण (Convergence) की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है।
कारण (R): यह संसाधनों के एकीकरण की ओर ले जाता है, बुनियादी ढांचे के दोहराव से बचाता है, और लक्षित लाभार्थी समूह के बीच व्यापक पहुंच सुनिश्चित करता है।
(A) दोनों कथन (A) और कारण (R) सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) दोनों कथन (A) और कारण (R) सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सत्य है लेकिन कारण (R) असत्य है।
(D) कथन (A) असत्य है लेकिन कारण (R) सत्य है।

Click Here to Buy book on Flipkart

49. निम्नलिखित में से कौन-सी योजना मुख्य रूप से रोजगार या आजीविका सृजन कार्यक्रम नहीं है?
(A) मनरेगा (MGNREGA)
(B) DDU-GKY
(C) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)
(D) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

50. राजस्थान में वह संस्थागत तंत्र जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कुशल लक्ष्यीकरण और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत पारिवारिक जनसांख्यिकी डेटाबेस का उपयोग करता है, किस नाम से जाना जाता है?
(A) ई-मित्र
(B) जन आधार
(C) राजकाज
(D) संपर्क पोर्टल

51. कौशल मैपिंग मुख्य रूप से एक बेरोजगार युवा को किस प्रकार लाभ पहुंचाती है?
(A) युवाओं के व्यक्तिगत कौशल स्तर की परवाह किए बिना उन्हें सीधे मासिक नकद सहायता प्रदान करके।
(B) उम्मीदवारों द्वारा पहले लिए गए सभी बकाया उच्च शिक्षा ऋणों को पूरी तरह से माफ करके।
(C) केवल पंजीकरण कराने पर स्वचालित रूप से स्थायी राज्य सरकार के रोजगार पद प्रदान करके।
(D) उनकी विशिष्ट अभिरुचियों की पहचान करके और उन्हें संबंधित उद्योग कौशल आवश्यकताओं से मिलाकर।

52. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह ग्रामीण आबादी के 75% तक और शहरी आबादी के 50% तक को कवर करता है।
II. यह प्राथमिकता वाले परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न की गारंटी देता है।
III. गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं इसके प्रावधानों के तहत मातृत्व लाभ की हकदार हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

53. यदि कोई सरकार ग्रामीण गोदामों और शीतगृहों (Cold storage) के निर्माण की नीति लागू करती है, तो वह गरीबी कम करने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग कर रही है?
(A) विशेष कौशल विकास के माध्यम से दीर्घकालिक मानव पूंजी निर्माण
(B) कमजोर कृषि परिवारों को प्रत्यक्ष बिना शर्त नकद लाभ अंतरण
(C) फसलों की संकटग्रस्त बिक्री को रोकने के लिए कृषि बुनियादी ढांचे का निर्माण
(D) स्थानीय सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का सृजन

54. पारंपरिक रोजगार कार्यालय प्रणाली की एक बड़ी आलोचना इसकी अक्षमता थी। इस ढांचे का आधुनिकीकरण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है?
(A) डिजिटल जॉब-मैचिंग प्लेटफॉर्म जो नौकरी चाहने वालों, नियोक्ताओं और प्रशिक्षण प्रदाताओं को वास्तविक समय (Real-time) में जोड़ते हैं।
(B) परिचालन सटीकता सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक मैनुअल बहीखाता रिकॉर्ड ट्रैकिंग सिस्टम पर लौटना।
(C) रोजगार कार्यालय पंजीकरण को केवल विश्वविद्यालय स्नातक डिग्री वाले उम्मीदवारों तक सीमित करना।
(D) निजी क्षेत्र के कॉर्पोरेट नियोक्ताओं को उपलब्ध नौकरियों को ऑनलाइन सूचीबद्ध करने से रोकना।

55. 'निरपेक्ष गरीबी' और 'सापेक्ष गरीबी' के बीच मौलिक अंतर क्या है?
(A) निरपेक्ष गरीबी सामाजिक समूहों के बीच असमानता को मापती है, जबकि सापेक्ष गरीबी बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं की कमी को मापती है।
(B) निरपेक्ष गरीबी केवल शहरी केंद्रों के भीतर मौजूद है, जबकि सापेक्ष गरीबी केवल कृषि प्रधान ग्रामीण समुदायों में पाई जाती है।
(C) निरपेक्ष गरीबी केवल औपचारिक शैक्षणिक स्तरों से निर्धारित होती है, जबकि सापेक्ष गरीबी को सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतकों का उपयोग करके मापा जाता है।
(D) निरपेक्ष गरीबी तब होती है जब जीवन रक्षा की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं होतीं, जबकि सापेक्ष गरीबी का तात्पर्य औसत सामाजिक मानकों से पीछे रहने से है।

56. गरीबों के लिए सूक्ष्मवित्त (Microfinance) के लाभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह उन व्यक्तियों को छोटे पैमाने पर ऋण प्रदान करता है जिनके पास संपार्श्विक (गारंटी) का अभाव है।
II. यह पूरी तरह से बड़े पैमाने के औद्योगिक उद्यमों को वित्तपोषित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
III. यह कम आय वाले समूहों के बीच बचत की आदत को प्रोत्साहित करता है।
IV. उच्च ऋण पुनर्भुगतान दर सुनिश्चित करने के लिए यह अक्सर SHGs के भीतर सामाजिक दबाव का उपयोग करता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, II और IV

57. राजस्थान में औद्योगिक प्रोत्साहन के संदर्भ में, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (RIICO) बेरोजगारी कम करने में क्या भूमिका निभाता है?
(A) यह विशेष रूप से बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों को

Downloaded from www.pdf.tube

गया है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेरोजगार युवा और नियोक्ता वास्तविक समय में एक-दूसरे से जुड़कर अवसरों का लाभ उठाते हैं।

55. (D) निरपेक्ष गरीबी तब होती है जब जीवन रक्षा की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं होतीं, जबकि सापेक्ष गरीबी का तात्पर्य औसत सामाजिक मानकों से पीछे रहने से है।
निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी के बीच मूल अंतर उनके मापन आधार में है। निरपेक्ष गरीबी जीवन जीने के लिए आवश्यक न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं, जैसे भोजन, कपड़ा और मकान के अभाव को व्यक्त करती है। वहीं दूसरी ओर, सापेक्ष गरीबी समाज के विभिन्न आय वर्गों के बीच व्याप्त असमानता को दर्शाती है, जो जीवन स्तर की तुलना पर आधारित होती है।

56. (B) केवल I, III और IV
सूक्ष्मवित्त कम आय वाले और गरीब समूहों को बिना किसी गारंटी के छोटे ऋण प्रदान करता है। यह निर्धन परिवारों में नियमित बचत की आदत को बढ़ावा देता है तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से काम करता है, जहाँ समूह का सामाजिक दबाव ऋण का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करता है। यह केवल छोटे एवं सूक्ष्म उद्यमों पर केंद्रित रहता है।

57. (C) यह औद्योगिक क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे का विकास करता है, जिससे वाणिज्यिक उद्यम आकर्षित होते हैं जो स्थानीय स्तर पर नौकरियां पैदा करते हैं।
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम राज्य में औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य भर में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना तथा बुनियादी सुविधाओं का विकास करती है। इन सुविधाओं से आकर्षित होकर निवेशक अपने उद्योग स्थापित करते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

58. (D) समग्र आर्थिक और औद्योगिक विकास का लाभ अंततः गरीबों सहित समाज के सभी वर्गों तक पहुंचेगा।
टपकन सिद्धांत पारंपरिक विकास अर्थशास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा है। इस सिद्धांत के अनुसार, यदि देश में समग्र आर्थिक वृद्धि दर और औद्योगिक निवेश को तेज किया जाता है, तो इस विकास के लाभ धीरे-धीरे रिसकर या छनकर समाज के सबसे निचले और निर्धन वर्गों तक भी अपने आप पहुंच जाएंगे, जिससे रोजगार और आय में वृद्धि संभव होगी।

59. (B) 15 से 59 वर्ष
जनसांख्यिकी और श्रम अर्थशास्त्र के मानकों के अनुसार, किसी भी देश की कुल जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। इस आयु वर्ग के लोग देश की आर्थिक गतिविधियों और उत्पादकता में योगदान देने के लिए सक्षम होते हैं। यह वर्ग अर्थव्यवस्था के विकास का मुख्य आधार होता है।

60. (B) SHGs का गठन → ग्राम संगठन (VO) का गठन → क्लस्टर स्तरीय महासंघ (CLF) का गठन
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं के संस्थागत विकास की प्रक्रिया एक स्तरीय क्रम का पालन करती है। सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर गरीब महिलाओं को जोड़कर स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है। इसके बाद प्राथमिक समूहों को मिलाकर ग्राम संगठन बनता है। अंत में ग्राम संगठनों को मिलाकर क्लस्टर स्तरीय महासंघ का गठन होता है।

61. (B) एक गैर-मौजूद या मृत व्यक्ति जिसके नाम पर कल्याणकारी लाभों का कपटपूर्वक दावा किया जाता है।
कल्याणकारी योजनाओं में "फर्जी लाभार्थी" उन अवास्तविक या मृत व्यक्तियों को संदर्भित करता है जिनके नाम पर धोखाधड़ी करके सरकारी सब्सिडी या वित्तीय लाभ उठाया जाता है। ये फर्जी नाम बिचौलियों द्वारा सरकारी कोष का गबन करने के लिए बनाए जाते हैं। आधार सीडिंग और बायोमीट्रिक सत्यापन लागू होने से ऐसे सभी फर्जी खातों को समाप्त कर दिया गया है।

62. (A) 15 से 35 वर्ष की आयु के गरीब परिवारों के ग्रामीण युवा
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण निर्धनता को कम करना है। इस योजना का प्राथमिक लक्षित समूह 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के गरीब ग्रामीण परिवारों के युवा हैं। विशेष रूप से वंचित सामाजिक समूहों, जैसे महिलाओं और दिव्यांगों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष तक रखी गई है, ताकि उन्हें अवसर मिल सके।

63. (C) आयातित विलासिता कारों पर उच्च सीमा शुल्क लगाना
कल्याणकारी और वित्तीय समावेशन रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सुरक्षा, नकद सहायता और बैंकिंग पहुंच देना है। डीबीटी, आधार और जन-धन खाते सीधे आम नागरिकों के वित्तीय समावेशन से जुड़े हैं। इसके विपरीत, विलासिता कारों पर उच्च सीमा शुल्क लगाना एक व्यापारिक एवं कर नीति का हिस्सा है, जिसका प्रत्यक्ष निर्धनता उन्मूलन से कोई सीधा संबंध नहीं होता है।

64. (A) P-2, Q-4, R-3, S-1
गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन की विभिन्न योजनाएं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। मनरेगा ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना ग्रामीण युवाओं को कौशल एवं रोजगार प्रदान करती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सीधे खाद्य सुरक्षा देता है, जबकि आईस्टार्ट नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करता है।

65. (C) राजनीतिक सहभागिता
वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विकास ऑक्सफोर्ड पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किया गया है। यह सूचकांक केवल आय के आधार पर नहीं, बल्कि तीन मुख्य आयामों—स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर—के आधार पर गरीबी का मापन करता है। इन तीन आयामों के अंतर्गत 10

NODIA

(A) वास्तविक जरूरतमंद गरीब परिवार योजना के कल्याणकारी लाभों से छूट जाते हैं।
(B) गैर-पात्र, धनी व्यक्तियों को गरीबों के लिए तय योजना लाभ गलत तरीके से प्राप्त हो जाते हैं।
(C) आवंटित वार्षिक योजना परिचालन निधि वित्तीय वर्ष के अंत में बिना उपयोग किए व्यपगत (Lapse) हो जाती है।
(D) केंद्रीय मंत्रालय राज्य निकायों को आवंटित वित्तीय अनुदान जारी करने में विफल रहता है।

67. राजस्थान में भामाशाह योजना, जो जन आधार योजना से पहले आई थी, मुख्य रूप से एक अग्रणी योजना थी क्योंकि:
(A) यह केवल ग्रामीण वयस्क पुरुषों को सीधे बेरोजगारी भत्ता अनुदान की गारंटी देने वाली पहली कल्याणकारी योजना थी।
(B) इसने भौतिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और इसे सार्वभौमिक निजी खाद्य बाजारों से बदल दिया।
(C) इसने अपने वित्तीय आवंटन को केवल भारी शहरी बुनियादी ढांचे और बड़े पैमाने के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित किया।
(D) इसमें योजना के कल्याणकारी लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य को परिवार के मुखिया के रूप में मान्यता देना अनिवार्य किया गया था।

68. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है:
कथन (A): सूक्ष्मवित्त (Microfinance) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण का एक प्रभावी साधन है।
कारण (R): यह उन्हें स्वतंत्र वित्तीय संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है, जो अक्सर परिवार के भीतर बेहतर निर्णय लेने की शक्ति में बदल जाता है।
(A) दोनों कथन (A) और कारण (R) सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) दोनों कथन (A) और कारण (R) सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सत्य है लेकिन कारण (R) असत्य है।
(D) कथन (A) असत्य है लेकिन कारण (R) सत्य है।

69. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता पात्रता की गणना के लिए, सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा क्या है?
(A) 25 वर्ष
(B) 30 वर्ष
(C) 35 वर्ष
(D) 40 वर्ष

70. भारी उद्योगों की तुलना में 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों' (MSMEs) को बढ़ावा देना विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी से निपटने के लिए एक श्रेष्ठ रणनीति के रूप में कैसे कार्य करता है?
(A) MSME आमतौर पर अत्यधिक श्रम-गहन होते हैं और निवेशित पूंजी की प्रति इकाई अधिक नौकरियां पैदा करते हैं।
(B) MSMEs को भारी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है जबकि वे लगभग शून्य स्थानीय श्रम का उपयोग करते हैं।
(C) MSMEs पूरी तरह से वैधानिक नियंत्रणों से बाहर काम करते हैं और सभी पर्यावरण नियमों को दरकिनार करते हैं।
(D) MSMEs बिना किसी मूलभूत बुनियादी ढांचे या बैंकिंग सहायता की आवश्यकता के स्वतंत्र रूप से काम करते हैं।

71. "रिवॉल्विंग फंड" (घूर्णी कोष) और "कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड" (CIF) वित्तीय सहायता तंत्र विशेष रूप से किसे प्रदान किए जाते हैं?
(A) महानगरीय शहरों में स्टार्टअप इन्क्यूबेशन केंद्रों को
(B) बड़े कॉर्पोरेट कृषि उद्यमों को
(C) राज्य कौशल विकास निगमों को
(D) NRLM ढांचे के तहत स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को

72. राजस्थान की योजना वितरण में तकनीकी एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. जन आधार कार्ड राज्य द्वारा संचालित सभी योजनाओं के लिए परिवार और व्यक्ति के लिए एक एकल पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है।
II. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) जन आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।
III. जन आधार पंजीकरण पूरी तरह से ऑफलाइन है और इसके लिए किसी जनसांख्यिकी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

73. निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय कृषि क्षेत्र में एक संरचनात्मक चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है जिसे योजनाएं गरीबी कम करने के लिए दूर करना चाहती हैं?
(A) खेती में अत्यधिक यांत्रिकीकरण जिससे अधिक पूंजी संचय होता है
(B) बुनियादी खाद्यान्नों के लिए कुल घरेलू उपभोक्ता मांग की कमी
(C) छोटी और विखंडित जोतें जो परिचालन संबंधी पैमाने की किफ़ायत को कम करती हैं
(D) राज्य सरकारों द्वारा सभी कृषि उत्पाद निर्यातों पर पूर्ण प्रतिबंध

74. राजस्थान में विशिष्ट क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए डिज़ाइन किए गए "राज्य पूरक कार्यक्रम" (State

Click Here to Buy book on Amazon

के गरीब ग्रामीण युवाओं को लक्षित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को उद्योग की मांग के अनुसार कौशल प्रदान करके रोजगार दिलाना है।

33. (C) क्यू-रेट (Q-Rate)
राजस्थान सरकार ने स्टार्टअप्स की क्षमता, व्यावसायिक विचार और विकास की संभावनाओं का पारदर्शी मूल्यांकन करने के लिए क्यू-रेट कार्यक्रम शुरू किया है। इस रेटिंग तंत्र के तहत विशेषज्ञों द्वारा स्टार्टअप्स का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है। इस रेटिंग के आधार पर योग्य और उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप्स को सरकारी प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता और इन्क्यूबेशन तक पहुंच दी जाती है।

34. (B) स्थानीय स्कूलों के माध्यम से भौतिक रूप से साइकिल और लैपटॉप वितरित करना
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का मुख्य सिद्धांत कल्याणकारी सब्सिडी या वित्तीय सहायता को बिना बिचौलियों के सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित करना है। जब सरकार द्वारा छात्रों को साइकिल या लैपटॉप जैसी भौतिक वस्तुएं सीधे वितरित की जाती हैं, तो यह वस्तु आधारित वितरण का उदाहरण है, जो प्रत्यक्ष नकद अंतरण का एक अपवाद माना जाता है।

35. (D) व्यक्तिगत मकान निर्माण कार्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रैक करना।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पारदर्शिता लाने के लिए आवाससॉफ्ट और आवासऐप जैसी डिजिटल प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। इन अनुप्रयोगों का प्राथमिक कार्य लाभार्थियों द्वारा निर्मित किए जा रहे मकानों की भौतिक प्रगति की तस्वीरों द्वारा वास्तविक समय में ट्रैकिंग करना है। निर्माण चरणों के सत्यापन के पश्चात ही अगली वित्तीय किश्त खाते में हस्तांतरित की जाती है।

36. (B) केवल I, III और IV
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों का चयन सामाजिक-आर्थिक जनगणना आंकड़ों एवं ग्राम सभा के सत्यापन द्वारा होता है। मकान का आकार न्यूनतम 25 वर्ग मीटर तय है और स्वामित्व महिला के नाम रहता है। निर्माण की कुल धनराशि एकमुश्त न देकर कार्य की भौतिक प्रगति के आधार पर किश्तों में सीधे खाते में हस्तांतरित की जाती है।

37. (C) गांव के स्तर पर किसी वित्तीय बैंक की ओर से शाखा-रहित Banking सुविधाएं प्रदान करना।
बैंक मित्र अथवा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम मील तक वित्तीय समावेशन पहुंचाने वाले अधिकृत एजेंट होते हैं। ये प्रतिनिधि व्यावसायिक बैंकों की ओर से गांवों के स्तर पर डिजिटल उपकरणों के माध्यम से खाता खोलने, नकद जमा करने, निकासी करने और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बांटने जैसी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे ग्रामीणों को आसानी होती है।

38. (A) लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और निरंतर आजीविका में वास्तविक सुधार का।
योजना निगरानी में आउटपुट ट्रैकिंग केवल भौतिक या वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति को मापती है, जैसे खर्च किया गया बजट या प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या। इसके विपरीत, परिणाम ट्रैकिंग योजना के दीर्घकालिक और वास्तविक प्रभावों का मूल्यांकन करती है। यह इस बात का आकलन करती है कि योजना के लागू होने के बाद लाभार्थियों के जीवन स्तर में कितना सुधार आया।

39. (D) मुख्यमंत्री युवा संबल योजना
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा संबल योजना विशेष रूप से राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। इस योजना के अंतर्गत स्नातक डिग्री धारक पात्र युवाओं को रोजगार की तलाश के दौरान निश्चित मासिक बेरोजगारी भत्ता और कौशल विकास हेतु इंटर्नशिप प्रदान की जाती है। इससे युवाओं को आर्थिक संबल मिलता है।

40. (A) 1, 4, 3, 2
कौशल प्रशिक्षण और आजीविका विकास की प्रक्रिया एक तार्किक अनुक्रम का पालन करती है। सबसे पहले संभावित अभ्यर्थियों की लामबंदी और परामर्श करके उनकी रुचि की पहचान की जाती है। इसके पश्चात उम्मीदवारों को मुख्य कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने पर उनका कौशल मूल्यांकन और प्रमाणन होता है। अंत में प्लेसमेंट के बाद उनकी ट्रैकिंग की जाती है।

41. (C) एक स्थायी ग्रामीण जल संरक्षण तालाब का निर्माण
मनरेगा योजना केवल अकुशल श्रमिकों को मजदूरी रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना भी है। जब मनरेगा के तहत जल संरक्षण तालाबों, चेक डैमों या ग्रामीण सड़कों का निर्माण होता है, तो ये स्थायी भौतिक परिसंपत्ति बनती हैं। इनसे कृषि और पर्यावरण को लाभ मिलता है।

42. (D) जन-धन, आधार, मोबाइल
जेएएम ट्रिनिटी का पूर्ण रूप जन-धन, आधार और मोबाइल है, जो भारत में पारदर्शी सामाजिक कल्याण वितरण प्रणाली का मुख्य आधार है। जन-धन योजना के तहत गरीबों के बैंक खाते खोले गए, आधार ने बायोमीट्रिक पहचान प्रदान की, तथा मोबाइल नेटवर्क ने त्वरित सूचना साझा की। इन तीनों के एकीकरण से सब्सिडी सीधे बैंक खाते में पहुंचना संभव हो सका है।

43. (A) इष्टतम उत्पादन के लिए वास्तव में जितने लोगों की आवश्यकता है, उससे अधिक लोग कृषि गतिविधि में लगे हुए हैं।
प्रच्छन्न बेरोजगारी भारतीय कृषि क्षेत्र की एक प्रमुख संरचनात्मक समस्या है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी कार्य को करने के लिए वास्तव में जितने श्रमिकों की

NODIA

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (C) ऐसे स्थायी भौतिक या वित्तीय संसाधनों का सृजन करना जो गरीबों के लिए भविष्य में निरंतर आय सक्षम बनाते हैं
गरीबी उन्मूलन में परिसंपत्ति निर्माण का मुख्य उद्देश्य निर्धन वर्ग को केवल तत्काल नकद या अल्पकालिक राहत देने के बजाय दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा देना है। जब गरीबों को टिकाऊ भौतिक या वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं, तब वे अपनी आजीविका के साधन स्वयं विकसित कर सकते हैं। इससे उन्हें निरंतर आय अर्जित करने का अवसर मिलता है और वे स्वावलंबी बनकर गरीबी से बाहर निकल पाते हैं।

2. (B) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जून 2011 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरु किया गया था। यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम वर्ष 1999 में प्रारंभ की गई स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का एक पुनर्गठित और उन्नत रुप है। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करके उनकी सूक्ष्म ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि स्थायी आजीविका का सृजन हो।

3. (D) ₹4,500
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को संबल प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को ₹4,500 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है, जबकि सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों को ₹4,000 प्रति माह दिए जाते हैं। इस सहायता का उद्देश्य रोजगार की खोज में युवाओं को आर्थिक सहारा देना है।

4. (A) P-3, Q-2, R-4, S-1
विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं के अपने विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और इंटर्नशिप प्रदान करना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना का ध्यान ग्रामीण युवाओं के कौशल प्रशिक्षण पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री आवास योजना बेघर परिवारों को मकान देकर आवास सम्बन्धी गरीबी दूर करती है, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भुखमरी से सुरक्षा देता है।

5. (C) राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड्स (RMoL)
राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की नींव वर्ष 2004 में रखी गई थी। प्रारंभिक चरण में इसे राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड्स के रूप में स्थापित किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य में निर्धन और कमजोर वर्गों के आजीविका अवसरों का विस्तार करना था। बाद में वर्ष 2010 में इसे एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया और वर्तमान स्वरूप दिया गया।

6. (B) सभी प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से 70% को वेतनभोगी रोजगार में रखा जाना अनिवार्य है।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कौशल विकास कार्यक्रम है। इस योजना का एक अनिवार्य दिशानिर्देश यह है कि प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षित और प्रमाणित ग्रामीण युवाओं में से कम से कम 70% उम्मीदवारों को न्यूनतम निर्धारित वेतन पर संगठित क्षेत्र में वेतनभोगी रोजगार में नियोजित करना अनिवार्य होता है। इससे स्थायी आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

7. (D) असफल स्टार्टअप्स के संस्थापकों के लिए सरकारी नौकरियों की गारंटी देना
राजस्थान सरकार की आईस्टार्ट पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में नवाचार को बढ़ावा देना और एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसके तहत नए उद्यमियों को इन्क्यूबेशन, सीड फंडिंग, मार्गदर्शन और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान किए जाते हैं। हालांकि, यह नीति किसी भी असफल स्टार्टअप के संस्थापकों के लिए सरकारी नौकरियों की कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं करती है।

8. (C) कथन (A) सत्य है लेकिन कारण (R) असत्य है।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने बिचौलियों को हटाकर और सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि भेजकर कल्याणकारी योजनाओं की दक्षता को काफी बढ़ाया है। हालांकि, यह प्रणाली बायोमीट्रिक पहचान और आधार सत्यापन पर अत्यधिक निर्भर करती है तथा इसके लिए लाभार्थियों का सक्रिय बैंक खाता होना अनिवार्य है। इसलिए बायोमीट्रिक सत्यापन को समाप्त करने का दवा पूरी तरह असत्य एवं निराधार है।

9. (C) यह सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का मकान प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त आवास संबंधी गरीबी को समाप्त करना है। इसके तहत कच्चे, जर्जर मकानों में रहने वाले या बेघर परिवारों को स्वच्छ रसोई घर एवं बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान बनाने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना निर्धन परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाती है।

10. (C) 35 किग्रा
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत निर्धनतम परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले अत्यधिक गरीब परिवारों को प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न अत्यधिक सब्सिडी वाली दरों पर प्रदान

Downloaded from www.pdf.tube

किया जाता है। इसके विपरीत, प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति अनाज मिलता है।

11. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
वित्तीय समावेशन का मुख्य लक्ष्य समाज के वंचित और कम आय वाले वर्गों को किफायती लागत पर औपचारिक बैंकिंग, बचत और ऋण सुविधाएं प्रदान करना है। जब निर्धन लोगों की पहुंच औपचारिक बैंकों तक हो जाती है, तो वे अपनी बचत को सुरक्षित रख पाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर कम ब्याज पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन्हें साहूकारों के शोषण से मुक्ति मिलती है।

12. (A) केवल I और II
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री धारक होना अनिवार्य है। यह योजना केवल बेरोजगारों के लिए है, इसलिए सरकारी कर्मचारी इसके पात्र नहीं होते।

13. (B) नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल
नेशनल करियर सर्विस पोर्टल केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल पहल है। देश भर के पारंपरिक रोजगार कार्यालयों को इस आधुनिक पोर्टल से एकीकृत किया गया है। यह मंच नौकरी चाहने वाले बेरोजगार युवाओं, विभिन्न नियोक्ताओं और कौशल प्रशिक्षण संस्थानों को एक ही स्थान पर जोड़ता है। इससे रोजगार प्राप्ति की प्रक्रिया सुगम होती है।

14. (A) ये टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के साथ-साथ गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करते हैं।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा जैसे सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम दोहरा लाभ प्रदान करते हैं। एक तरफ, ये कार्यक्रम ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में कानूनी रूप से गारंटीकृत मजदूरी रोजगार देकर आजीविका सुरक्षा देते हैं। दूसरी तरफ, इनके माध्यम से जल संरक्षण और ग्रामीण सड़कों जैसे स्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण भी होता है, जो अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करता है।

15. (C) औपचारिक बैंक ऋणों के लिए पारंपरिक संपार्श्विक (Collateral/गारंटी) प्रदान करने में असमर्थता
ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को औपचारिक बैंक ऋण प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा किसी भी प्रकार की भौतिक संपत्ति या गारंटी का न होना है। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंक योजना इस समस्या का समाधान करती है। इसमें समूह की सामूहिक बचत और अनुशासन को ही मुख्य आधार माना जाता है। इससे गरीबों को बिना संपार्श्विक के ऋण आसानी से मिल जाता है।

16. (B) केवल I, II और IV
राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम राज्य में कौशल प्रशिक्षण की नोडल संस्था है। यह राज्य तथा केंद्र सरकार की विभिन्न कौशल विकास योजनाओं को निष्पादित करता है। इसे धारा 8 के अंतर्गत एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह निगम निजी क्षेत्रों के प्रशिक्षण साझेदारों का व्यापक सहयोग लेता है, जिससे कौशल प्रशिक्षण का व्यापक प्रसार संभव होता है।

17. (C) कौशल मैपिंग और करियर परामर्श (Skill mapping and career counselling)
संरचनात्मक बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब नौकरी चाहने वाले युवाओं के कौशल और बाजार की आवश्यकताओं के बीच अंतर होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए कौशल मैपिंग और परामर्श प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत युवाओं की योग्यता का मूल्यांकन करके उन्हें उद्योग की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण एवं सही करियर चुनने का मार्गदर्शन दिया जाता है।

18. (B) निवेश को आकर्षित करके जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मजदूरी रोजगार के अवसरों के सृजन को बढ़ावा देता है।
सरकार जब उद्योगों को कर छूट, रियायती भूमि और सस्ती बिजली जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है, तो इससे पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलता है। नए उद्योग स्थापित होने से विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होती हैं। इसके साथ ही आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार जैसे क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रोजगार का व्यापक सृजन संभव हो पाता है।

NODIA

19. (D) यह छोटे और सीमांत कृषि किसानों के विपणन योग्य अधिशेष और वास्तविक आय में सीधी वृद्धि करता है।
भारत की अधिकांश निर्धन ग्रामीण जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। जब सिंचाई, उन्नत बीज और आधुनिक तकनीक के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाई जाती है, तब छोटे किसानों की कुल पैदावार में वृद्धि होती है। इससे किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अतिरिक्त अधिशेष बचता है। इसे बेचकर उनकी आय बढ़ती है और गरीबी कम होती है।

20. (A) लाभार्थी की पहचान - आधार सीडिंग - कोष स्वीकृति - बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की प्रक्रिया एक सुनियोजित और तार्किक क्रम में काम करती है। सर्वप्रथम मापदंडों के आधार पर पात्र लाभार्थी की पहचान की जाती है। इसके बाद फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बैंक खाते को आधार से जोड़ा जाता है। तत्पश्चात संबंधित विभाग द्वारा कोष स्वीकृत किया जाता है और अंत में राशि बैंक खाते में स्थानांतरित होती है।

21. (C) विभिन्न नौकरियों के बीच परिवर्तन (Transition) के दौरान व्यक्तिगत श्रमिकों द्वारा अनुभव की जाने वाली अस्थायी बेरोजगारी।
घर्षणजन्य बेरोजगारी एक अल्पकालिक और प्राकृतिक बेरोजगारी का रूप है जो अर्थव्यवस्था में तब उत्पन्न होती है जब श्रमिक एक नौकरी छोड़कर दूसरी नई नौकरी की तलाश कर रहे होते हैं। इस परिवर्तन काल के दौरान व्यक्ति को कुछ समय के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है। यह स्थिति बाजार में सूचना के अभाव एवं नए अवसर की खोज के कारण बनती है।

22. (A) दोहराव वाले प्रयासों को समाप्त करना, पुनरावृत्ति से बचना और संसाधन दक्षता को अधिकतम करना।
योजना अभिसरण से तात्पर्य केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न समरूप योजनाओं तथा संसाधनों को एक साथ जोड़ना है। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही प्रकार के कार्यों में संसाधनों और प्रयासों के दोहराव को रोकना है। जब विभिन्न प्रशासनिक विभाग मिलकर कार्य करते हैं, तो वित्तीय पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग संभव होता है। इससे योजना का लाभ सीधे जरुरतमंदों तक पहुंचता है।

23. (D) कार्यान्वयन संबंधी कमियां जो जमीनी स्तर पर लक्षित लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने में बाधा डालती हैं।
अंतिम मील तक वितरण की चुनौतियां उन व्यावहारिक और प्रशासनिक बाधाओं को दर्शाती हैं जो किसी नीति के अंतिम निष्पादन चरण में सामने आती हैं। उच्च स्तर पर नीतियां बनाई जाती हैं, लेकिन दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे तथा जागरूकता के अभाव के कारण वास्तविक लाभ गरीब तक नहीं पहुंच पाता। इन कमियों को दूर करना अत्यंत आवश्यक होता है।

24. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
राजस्थान का संस्थागत ढांचा विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए समर्पित है। आईस्टार्ट राजस्थान का मुख्य उद्देश्य राज्य में नए स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देना है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम युवाओं के कौशल प्रशिक्षण का कार्य करता है। जन आधार प्राधिकरण डेटाबेस द्वारा पारदर्शी लाभ अंतरण सुनिश्चित करता है, जबकि रीको औद्योगिक बुनियादी ढांचे को विकसित करता है।

25. (C) फर्जी (Ghost) लाभार्थियों और डुप्लिकेट राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण को सक्षम करके।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार के एकीकरण ने पारदर्शिता और लक्षित दक्षता में क्रांतिकारी सुधार किया है। राशन कार्डों को आधार से जोड़ने और बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली लागू करने से फर्जी और दोहरे कार्ड समाप्त हो गए हैं। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि सरकारी खाद्यान्न सब्सिडी केवल वास्तविक एवं पात्र गरीबों तक ही पहुंचे तथा कालाबाजारी पर अंकुश लग सके।

26. (D) स्टार्टअप्स को कार्यस्थल, मार्गदर्शन (Mentorship) और शुरुआती नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना।
बिजनेस इन्क्यूबेशन केंद्र नए और उभरते उद्यमों को उनके शुरुआती चरण में पोषित करने का काम करते हैं। ये केंद्र नवोदित उद्यमियों को किफायती कार्यस्थल, तकनीकी सुविधाएं, व्यावसायिक मार्गदर्शन और निवेशकों से जुड़ने के अवसर प्रदान करते हैं। इससे नए व्यावसायिक विचारों को सफल कंपनियों में बदलना आसान होता है, जिससे अर्थव्यवस्था में रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं।

27. (A) गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को संस्थागत वित्तीय प्रणाली से जोड़ने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि क्षेत्र के छोटे कारोबारियों, जैसे दुकानदारों, छोटे कारीगरों तथा सेवा प्रदाताओं को बिना किसी गारंटी के रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देना तथा वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना है।

28. (A) दोनों कथन (A) और कारण (R) सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में गरीबी और भुखमरी उन्मूलन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह कानून देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या को अत्यधिक सब्सिडी वाली दरों पर अनाज प्राप्त करने का अधिकार देता है। गरीबों के भोजन पर होने वाले खर्च में कमी आने से उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे उनकी वास्तविक आय की सुरक्षा होती है।

29. (B) महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) और उनके संघ (Federation)
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है कि गरीबों में निर्धनता से बाहर निकलने की स्वाभाविक क्षमता होती है। इस क्षमता का उपयोग करने के लिए यह मिशन मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों में संगठित करता है। ये संस्थाएं सदस्यों में बचत, परस्पर सहयोग और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देती हैं।

30. (A) बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक आय या उपभोग व्यय की एक निश्चित न्यूनतम सीमा।
निरपेक्ष गरीबी रेखा एक ऐसे मौद्रिक मानक या उपभोग व्यय सीमा को व्यक्त करती है जो किसी व्यक्ति के जीवित रहने के लिए आवश्यक बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को तय करती है। इन बुनियादी आवश्यकताओं में न्यूनतम पोषण आहार, वस्त्र, स्वच्छ जल, आवास और प्राथमिक स्वास्थ्य शामिल हैं। जो इस न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, वे गरीब कहलाते हैं।

31. (B) 2 वर्ष या रोजगार मिलने तक, जो भी पहले हो
राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पात्र लाभार्थी युवाओं को अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। हालांकि, यदि लाभार्थी को इन दो वर्षों की अवधि समाप्त होने से पहले ही कोई रोजगार प्राप्त हो जाता है, तो भत्ते का भुगतान उसी समय तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाता है।

32. (C) केवल I और III
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय लागत साझा की जाती है। यह योजना विशेष रुप से 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग

Click Here to Buy book on Flipkart

सीधे मासिक नकद बेरोजगारी भत्ता प्रदान करता है।
(B) यह ग्रामीण औद्योगिक विकास क्षेत्रों में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण और प्रत्यक्ष संचालन करता है।
(C) यह औद्योगिक क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे का विकास करता है, जिससे वाणिज्यिक उद्यम आकर्षित होते हैं जो स्थानीय स्तर पर नौकरियां पैदा करते हैं।
(D) यह एक राज्य व्यापार एजेंसी के रूप में कार्य करता है जो केवल विदेशी बाजारों को कृषि कच्चे माल का निर्यात करता है।

58. "ट्रिकल-डाउन इफेक्ट" (टपकन सिद्धांत) की अवधारणा, जिस पर अक्सर गरीबी उन्मूलन में चर्चा की जाती है, यह सिद्धांत देती है कि:
(A) कल्याणकारी गरीबी योजनाओं को सीधे सबसे गरीब परिवारों को बिना शर्त नकद अनुदान स्थानांतरित करना चाहिए।
(B) वित्तीय सरकारी सब्सिडी आवश्यक कृषि फसल उत्पादों के लिए प्रदान की जानी चाहिए।
(C) राष्ट्रीय आर्थिक धन को धनी व्यक्तियों से गरीब आबादी में पुनर्वितरित किया जाना चाहिए।
(D) समग्र आर्थिक और औद्योगिक विकास का लाभ अंततः गरीबों सहित समाज के सभी वर्गों तक पहुंचेगा।

59. भारत में मानक जनसांख्यिकी और रोजगार मैपिंग में "कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या" (Working Age Population) की सबसे उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से कौन-सी है?
(A) 10 से 50 वर्ष
(B) 15 से 59 वर्ष
(C) 21 से 65 वर्ष
(D) 18 से 70 वर्ष

60. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत ग्रामीण महिलाओं को संस्थागत रुप देने की सही अनुक्रमिक प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन-सी है?
(A) ग्राम संगठन (VO) का गठन → SHGs का गठन → क्लस्टर स्तरीय महासंघ (CLF) का गठन
(B) SHGs का गठन → ग्राम संगठन (VO) का गठन → क्लस्टर स्तरीय महासंघ (CLF) का गठन
(C) क्लस्टर स्तरीय महासंघ (CLF) का गठन → SHGs का गठन → ग्राम संगठन (VO) का गठन
(D) SHGs का गठन → क्लस्टर स्तरीय महासंघ (CLF) का गठन → ग्राम संगठन (VO) का गठन

61. कल्याणकारी योजनाओं में आधार सीडिंग का उद्देश्य "फर्जी (Ghost) लाभार्थियों" को समाप्त करना है। "फर्जी लाभार्थी" का सटीक तात्पर्य क्या है?
(A) एक वास्तविक योजना लाभार्थी जो दूसरे प्रशासनिक राज्य में रहने के लिए स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया है।
(B) एक गैर-मौजूद या मृत व्यक्ति जिसके नाम पर कल्याणकारी लाभों का कपटपूर्वक दावा किया जाता है।
(C) एक वास्तविक पात्र लाभार्थी जिसका योजना नामांकन आवेदन सत्यापन के लिए लंबित है।
(D) एक सक्रिय लाभार्थी जो अपने व्यक्तिगत बैंक खाते को योजना Portals से जोड़ने से इनकार करता है।

62. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (DDU-GKY) के लिए प्राथमिक लक्षित लाभार्थी समूह निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) 15 से 35 वर्ष की आयु के गरीब परिवारों के ग्रामीण युवा
(B) 18 से 45 वर्ष की आयु के शहरी युवा
(C) सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी
(D) आईटी प्रशिक्षण चाहने वाले वर्तमान में नियोजित सरकारी शिक्षक

63. प्राथमिक उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित रणनीतियों में से विषम का चयन कीजिए:
(A) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजनाओं का कार्यान्वयन
(B) आधार बायोमीट्रिक पहचान प्रणालियों का एकीकरण
(C) आयातित विलासिता कारों पर उच्च सीमा शुल्क लगाना
(D) सार्वभौमिक जन-धन शून्य-बैलेंस बैंक खाते खोलना

64. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (गरीबी/रोजगार रणनीति)
P. ग्रामीण मजदूरी रोजगार गारंटी
Q. कौशल और प्लेसमेंट
R. प्रत्यक्ष खाद्य सुरक्षा
S. स्टार्टअप सहायता
सूची II: (उदाहरण योजना)
1. iStart
2. MGNREGA
3. NFSA
4. DDU-GKY
(A) P-2, Q-4, R-3, S-1
(B) P-4, Q-2, R-1, S-3
(C) P-2, Q-3, R-4, S-1
(D) P-3, Q-4, R-2, S-1

65. बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) तीन व्यापक आयामों पर गरीबी का आकलन करता है। निम्नलिखित में से कौन-सा इनमें से एक आयाम नहीं है?
(A) स्वास्थ्य
(B) शिक्षा
(C) राजनीतिक सहभागिता
(D) जीवन स्तर

66. अंतिम मील तक वितरण की चुनौतियों का मूल्यांकन करते समय, गरीबी उन्मूलन योजनाओं में "समावेशी त्रुटियां" (Inclusion Errors) तब होती हैं जब:

NODIA

आवश्यकता होती है, उससे अधिक लोग उसमें संलग्न होते हैं। ऐसे में अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। यदि उन्हें हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन नहीं घटता है।

44. (A) P-3, Q-2, R-4, S-1
रोजगार और गरीबी उन्मूलन की विभिन्न अवधारणाएं स्पष्ट उद्देश्यों को दर्शाती हैं। घर्षणजन्य बेरोजगारी नई नौकरी की खोज के दौरान लगने वाले समय से संबंधित है। संरचनात्मक बेरोजगारी कौशल और बाजार मांग के असंतुलन से उत्पन्न होती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सब्सिडी को सीधे खाते में भेजता है, जबकि सूक्ष्मवित्त कम आय वाले समूहों को छोटे ऋण प्रदान करता है।

45. (B) राजस्थान स्टार्टअप नीति
राजस्थान स्टार्टअप नीति राज्य में नवाचार, उद्यमिता और नई कंपनियों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई है। यह नीति आईटी और गैर-आईटी दोनों प्रकार के स्टार्टअप्स को प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं, साझा बुनियादी ढांचा, इन्क्यूबेशन सहायता, वित्तीय सब्सिडी और नेटवर्किंग मंच प्रदान करती है। इसका मुख्य लक्ष्य युवाओं को सफल उद्यमी बनने हेतु प्रोत्साहित करना और सशक्त बनाना है।

46. (A) किसी सरकारी विभाग में प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप करना।
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संशोधित नियमों के अनुसार, बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए केवल पंजीकृत रहना ही पर्याप्त नहीं है। इस योजना के तहत वित्तीय भत्ता प्राप्त करने की एक अनिवार्य शर्त यह है कि अभ्यर्थियों को किसी राजकीय विभाग या उपक्रम में प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी होती है। इससे व्यावहारिक अनुभव भी मिलता है।

47. (C) पांच मुख्य परिचालन अभ्यास: नियमित बैठकें, बचत, आंतरिक ऋण, पुनर्भुगतान और बहीखाता लेखन।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के सुचारु, अनुशासित और पारदर्शी संचालन के लिए 'पंचसूत्र' के सिद्धांत का अनिवार्य रूप से पालन किया जाता है। इन पांच मूलभूत नियमों में नियमित बैठक करना, नियमित बचत करना, सदस्यों में आंतरिक ऋण बांटना, समय पर पुनर्भुगतान और बहीखाता लेखन शामिल हैं। यह अनुशासन समूह को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है।

48. (A) दोनों कथन (A) और कारण (R) सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
लोक प्रशासन में केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के अभिसरण पर विशेष बल दिया जाता है क्योंकि यह प्रशासनिक व्यवस्था की दक्षता को बढ़ाता है। जब दोनों स्तरों की योजनाएं और संसाधन आपस में तालमेल बिठाकर काम करती हैं, तो वित्तीय पूंजी का दोहराव बंद होता है और बुनियादी ढांचे का कुशल उपयोग संभव हो पाता है और लाभ बढ़ता है।

49. (C) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्राथमिक रूप से देश में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को घटाने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए संचालित कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार या आजीविका सृजन करना नहीं है। इसके विपरीत, मनरेगा और अन्य वर्णित कार्यक्रम सीधे रोजगार एवं आजीविका सुरक्षा से जुड़े हुए प्रमुख कार्यक्रम हैं।

50. (B) जन आधार
राजस्थान में जन आधार योजना 'एक कार्ड, एक नंबर, एक पहचान' के सिद्धांत पर आधारित एक एकीकृत शासन व्यवस्था है। यह मंच राज्य के प्रत्येक परिवार का एक एकल जनसांख्यिकी डेटाबेस तैयार करता है। इस एकीकृत डेटाबेस के माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी रूप से पहुंचाए जाते हैं और सुशासन आता है।

51. (D) उनकी विशिष्ट अभिरुचियों की पहचान करके और उन्हें संबंधित उद्योग कौशल आवश्यकताओं से मिलाकर।
कौशल मैपिंग बेरोजगार युवाओं की क्षमताओं, शैक्षणिक पृष्ठभूमि और अभिरुचियों का व्यवस्थित मूल्यांकन करने की तकनीक है। इस प्रक्रिया के माध्यम से युवाओं की विशिष्ट दक्षताओं की पहचान की जाती है और उन्हें बाजार तथा उद्योग की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप सही प्रशिक्षण से जोड़ा जाता है। इससे युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होती है और अवसर मिलते हैं।

NODIA

52. (D) I, II और III
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला एक ऐतिहासिक कानून है। यह देश की 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को कवर करता है। इसके तहत पात्र परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाली दरों पर अनाज दिया जाता है। साथ ही, गर्भवती महिलाओं और माताओं को पोषण संबंधी वित्तीय एवं खाद्य सहायता भी प्रदान की जाती है।

53. (C) फसलों की संकटग्रस्त बिक्री को रोकने के लिए कृषि बुनियादी ढांचे का निर्माण
ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों और शीतगृहों का निर्माण कृषि बुनियादी ढांचे के विकास की श्रेणी में आता है। जब किसानों के पास अपनी फसल सुरक्षित रखने के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो वे कटाई के तुरंत बाद कम कीमतों पर फसल बेचने को मजबूर नहीं होते। वे उचित दाम मिलने पर फसल बेचकर अधिक आय अर्जित कर पाते हैं।

54. (A) डिजिटल जॉब-मैचिंग प्लेटफॉर्म जो नौकरी चाहने वालों, नियोक्ताओं और प्रशिक्षण प्रदाताओं को वास्तविक समय (Real-time) में जोड़ते हैं।
पारंपरिक रोजगार कार्यालयों की सबसे बड़ी कमी यह थी कि वे मैनुअल पंजीकरण पर आधारित थे, जिससे युवाओं और नियोक्ताओं के बीच संपर्क नहीं हो पाता था। आधुनिक आधुनिकीकरण के तहत इस ढांचे का डिजिटलीकरण किया

Supplementary Programme) का सबसे अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
(B) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
(C) प्रधानमंत्री आवास योजना
(D) इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

75. गरीबी उन्मूलन योजनाओं की शब्दावली में, "क्षमता निर्माण" (Capacity Building) का सबसे सटीक अर्थ है:
(A) व्यक्तिगत और सामुदायिक आजीविका में सुधार के लिए उनके कौशल, क्षमताओं और ज्ञान को बढ़ाना।
(B) अतिरिक्त सरकारी आरक्षित खाद्यान्न रखने के लिए बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय भंडारण गोदामों का निर्माण करना।
(C) राज्य सरकार की कुल संस्थागत वित्तीय उधार सीमा में वृद्धि करना।
(D) नए निर्मित ग्रामीण आवास गृहों के भौतिक संरचनात्मक आयामों और रहने के क्षेत्रों का विस्तार करना।

76. राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. पात्र परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाली दरों पर गेहूं प्रदान किया जाता है।
II. पात्र परिवारों की पहचान करना केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।
III. इसमें गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी सहायता के प्रावधान शामिल हैं।
IV. उचित मूल्य दुकानें (FPS) पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीनों का उपयोग करके सब्सिडी वाला खाद्यान्न वितरित करती हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, II और IV

77. "जनसांख्यिकी लाभांश" (Demographic Dividend) शब्द, जिसे रोजगार योजनाओं का उद्देश्य भुनाना है, किसे संदर्भित करता है?
(A) आधारभूत गरीबी को कम करने के लिए राज्य के खजाने द्वारा पंजीकृत ग्रामीण नागरिकों को सीधे भुगतान किया जाने वाला वार्षिक नकद लाभांश।
(B) जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास में वृद्धि, विशेष रूप से एक बड़ी कार्यशील आयु वाली आबादी का होना।
(C) वरिष्ठ नागरिकों की आबादी का तीव्र संरचनात्मक जनसांख्यिकी विस्तार जिसके लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहायता की आवश्यकता होती है।
(D) कृषि ग्रामीण और औद्योगिक शहरी क्षेत्रों में समान रूप से फैली कार्यशील आबादी का संतुलित भौगोलिक वितरण।

78. प्रमुख योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण घटक "सामाजिक अंकेक्षण" (Social Audit) है। इसमें मुख्य रूप से क्या शामिल है?
(A) स्थानीय समुदाय या ग्राम सभा द्वारा सामूहिक रूप से योजना के निष्पादन और वित्तीय रिकॉर्ड का मूल्यांकन।
(B) विशेष रूप से प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा आयोजित योजना व्यय रिकॉर्ड का एक औपचारिक संस्थागत लेखापरीक्षा।
(C) सार्वजनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भौतिक योजना प्रगति की तस्वीरें लेने और अपलोड करने की प्रक्रिया।
(D) केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पंजीकृत योजना लाभार्थियों से सीधे उनके मोबाइल नंबरों पर संपर्क करना।

79. जब कोई व्यक्ति सिलाई का व्यवसाय शुरू करने के लिए सिलाई मशीन खरीदने हेतु स्वरोजगार योजना के तहत रियायती ऋण लेता है, तो सिलाई मशीन किसका प्रतिनिधित्व करती है?
(A) तरल कार्यशील पूंजी
(B) उपभोग्य परिचालन परिसंपत्ति
(C) उत्पादक भौतिक परिसंपत्ति
(D) सामाजिक उपरिपूंजी (Social Overhead) परिसंपत्ति

80. एक विशिष्ट व्यापक गरीबी उन्मूलन ढांचे के निम्नलिखित हस्तक्षेपों को सही तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. सतत आय सृजन क्षमता को बढ़ाना
2. तत्काल राहत प्रदान करना (जैसे, सब्सिडी वाला भोजन)
3. परिसंपत्ति निर्माण और सूक्ष्मवित्त सहायता
4. कौशल प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही अनुक्रमिक क्रम दर्शाता है?
(A) 2, 4, 3, 1
(B) 4, 2, 1, 3
(C) 1, 3, 2, 4
(D) 3, 1, 4, 2

Downloaded from www.pdf.tube

संकेतक शामिल होते हैं। इसमें राजनीतिक सहभागिता शामिल नहीं की जाती है।

66. (B) गैर-पात्र, धनी व्यक्तियों को गरीबों के लिए तय योजना लाभ गलत तरीके से प्राप्त हो जाते हैं।
कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में दो मुख्य त्रुटियां देखी जाती हैं: समावेशी त्रुटि और बहिष्करण त्रुटि। समावेशी त्रुटि तब होती है जब पहचान प्रणाली की कमियों के कारण गैर-पात्र अथवा संपन्न व्यक्ति गलत तरीके से योजना सूची में शामिल होकर गरीबों के लिए निर्धारित लाभ प्राप्त कर लेते हैं। इससे योजना के संसाधनों का अनुचित प्रयोग देखने को मिलता है।

67. (D) इसमें योजना के कल्याणकारी लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य को परिवार के मुखिया के रूप में मान्यता देना अनिवार्य किया गया था।
राजस्थान में शुरू की गई भामाशाह योजना एक अग्रणी महिला सशक्तिकरण और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना थी। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसने परिवार में वित्तीय निर्णय लेने का अधिकार महिलाओं को देने के उद्देश्य से परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला को मुखिया घोषित करना अनिवार्य किया था। सभी लाभ महिला के खाते में ही हस्तांतरित होते थे।

68. (A) दोनों कथन (A) और कारण (R) सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
सूक्ष्मवित्त विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब महिलाओं को आसानी से छोटे ऋण और वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं, तो वे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने से निर्णय लेने में उनकी भूमिका एवं स्थिति मजबूत हो जाती है।

69. (B) 30 वर्ष
राजस्थान की मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पात्र अभ्यर्थियों की आयु सीमा से संबंधित स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, आरक्षित वर्गों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए यह अधिकतम सीमा 35 वर्ष तक निर्धारित है।

70. (A) MSME आमतौर पर अत्यधिक श्रम-गहन होते हैं और निवेशित पूंजी की प्रति इकाई अधिक नौकरियां पैदा करते हैं।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारी उद्योगों की तुलना में रोजगार सृजन के लिए अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह क्षेत्र अत्यधिक श्रम-गहन होता है और इसमें निवेशित पूंजी की प्रति इकाई अधिक नौकरियों का सृजन होता है। कम पूंजी में स्थानीय स्तर पर अधिक लोगों को काम मिलना संभव हो पाता है।

71. (D) NRLM ढांचे के तहत स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के मुख्य घटक हैं। रिवॉल्विंग फंड समूहों की संस्थागत क्षमता और बचत प्रणाली को मजबूत करने के लिए मिलता है, जबकि कम्युनिटी फंड सदस्यों की आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु प्रदान किया जाता है।

72. (A) केवल I और II
राजस्थान में जन आधार योजना राज्य की सभी कल्याणकारी पहलों के लिए एक एकल पहचानकर्ता के रूप में कार्य करती है। जन आधार डेटाबेस के माध्यम से राज्य सरकार की डीबीटी राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। यह प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल जनसांख्यिकी डेटाबेस पर आधारित है, इसलिए ऑफलाइन होने का कथन पूरी तरह गलत है।

NODIA

73. (C) छोटी और विखंडित जोतें जो परिचालन संबंधी पैमाने की किफ़ायत को कम करती हैं।
भारतीय कृषि क्षेत्र में निर्धनता का एक बड़ा कारण भूमि जोतों का अत्यधिक विखंडन और छोटा आकार है। जब किसान के पास बहुत छोटे खेत होते हैं, तो आधुनिक कृषि प्रणालियों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना संभव नहीं हो पाता। इससे कृषि की लागत बढ़ जाती है और उत्पादकता कम रहती है, जिससे किसानों की आय सीमित बनी रहती है।

74. (D) इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना एक राज्य पूरक पहल का उत्कृष्ट उदाहरण है। जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्य करता है, उसी तर्ज पर राजस्थान ने शहरी निर्धनों के लिए इसे लागू किया है। इसके तहत शहरी परिवारों को प्रतिवर्ष गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है।

75. (A) व्यक्तिगत और सामुदायिक आजीविका में सुधार के लिए उनके कौशल, क्षमताओं और ज्ञान को बढ़ाना।
गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में क्षमता निर्माण से तात्पर्य व्यक्तियों, समुदायों और स्थानीय संस्थाओं की आंतरिक दक्षताओं को बढ़ाना है। इसके अंतर्गत निर्धन वर्गों को कौशल प्रशिक्षण, व्यावसायिक ज्ञान, वित्तीय साक्षरता और प्रबंधन क्षमताएं प्रदान की जाती हैं। इसका उद्देश्य गरीबों को इस योग्य बनाना है कि वे स्वयं आजीविका चला सकें और आत्मनिर्भर बन सकें तथा आय बढ़ा सकें।

76. (B) केवल I, III और IV
राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को सब्सिडी वाला गेहूं दिया जाता है। इसमें उचित मूल्य दुकानों पर बायोमीट्रिक मशीनों का प्रयोग होता है तथा गर्भवती माताओं हेतु पोषण प्रावधान शामिल हैं। योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान करने का दायित्व राज्य सरकार

का होता है, इसलिए इसे केवल केंद्र का काम बताना पूरी तरह गलत है।

77. (B) जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरुप आर्थिक विकास में वृद्धि, विशेष रूप से एक बड़ी कार्यशील आयु वाली आबादी का होना।
जनसांख्यिकी लाभांश उस आर्थिक लाभ को दर्शाता है जो किसी देश की जनसंख्या संरचना में परिवर्तन से प्राप्त होता है। जब किसी देश में आश्रितों की तुलना में कार्यशील आयु वर्ग के लोगों का अनुपात अधिक होता है, तो श्रम शक्ति बढ़ती है। यदि इस आबादी को कौशल और रोजगार दिया जाए, तो आर्थिक विकास की गति काफी तेज होती है।

78. (A) स्थानीय समुदाय या ग्राम सभा द्वारा सामूहिक रूप से योजना के निष्पादन और वित्तीय रिकॉर्ड का मूल्यांकन।
सामाजिक अंकेक्षण पारदर्शी शासन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें योजना के निष्पादन और वित्तीय खर्चों का मूल्यांकन सीधे स्थानीय समुदाय और ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। मनरेगा जैसी योजनाओं में यह प्रक्रिया अनिवार्य है, जहाँ ग्रामीण एकत्र होकर काम की गुणवत्ता, मस्टर रोल और किए गए भुगतान का पारदर्शी रूप से भौतिक सत्यापन पूरा करते हैं।

79. (C) उत्पादक भौतिक परिसंपत्ति
जब कोई व्यक्ति आय अर्जित करने या स्वरोजगार शुरु करने के उद्देश्य से कोई उपकरण या मशीन खरीदता है, तो वह वस्तु एक उत्पादक भौतिक परिसंपत्ति कहलाती है। सिलाई व्यवसाय के संदर्भ में सिलाई मशीन एक ऐसी टिकाऊ संपत्ति है जो सीधे उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देती है और निरंतर आय का साधन बनती है, जिससे आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है।

80. (A) 2, 4, 3, 1
व्यापक गरीबी उन्मूलन का ढांचा एक चरणबद्ध और तार्किक प्रक्रिया का अनुसरण करता है। प्रथम चरण में निर्धन परिवारों को राहत देने के लिए सब्सिडी युक्त भोजन जैसी तत्काल सहायता दी जाती है। द्वितीय चरण में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। तृतीय चरण में सूक्ष्मवित्त और परिसंपत्ति सृजन किया जाता है, जिससे अंततः स्थायी आय सृजन क्षमता का विकास संभव होता है।

Click Here to Buy book on Amazon

अध्याय 24
सामाजिक न्याय एवं कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण

1. भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद राज्य को जनता के दुर्बल वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करने का निर्देश देता है?
   (A) अनुच्छेद 15(4)
   (B) अनुच्छेद 46
   (C) अनुच्छेद 16(4)
   (D) अनुच्छेद 335

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के बीच अंतर पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
   (A) दोनों अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों में सीटों के आरक्षण का स्पष्ट उल्लेख करते हैं।
   (B) अनुच्छेद 16(4) को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, जबकि अनुच्छेद 15(4) मूल संविधान का भाग था।
   (C) किसी भी अनुच्छेद में लक्षित समूह का सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना आवश्यक नहीं है।
   (D) अनुच्छेद 15(4) शैक्षणिक प्रगति सहित विशेष प्रावधानों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 16(4) विशेष रूप से राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण से संबंधित है।

3. दुर्बल वर्गों के सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक ढाँचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   I. अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है।
   II. अनुच्छेद 23 सार्वजनिक नियोजन में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का स्पष्ट रूप से निषेध करता है।
   III. अनुच्छेद 38 राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने और आय की असमानताओं को कम करने का जनादेश देता है।
   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (A) केवल I और II
   (B) केवल II और III
   (C) केवल I और III
   (D) I, II और III

4. 103वें संविधान संशोधन अधिनियम ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की। निम्नलिखित में से किस समूह को इस नए ईडब्ल्यूएस आरक्षण ढाँचे के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है?
   (A) वर्तमान में किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्ति
   (B) अनारक्षित श्रेणियों के वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है
   (C) अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए मौजूदा आरक्षण योजनाओं के तहत पहले से शामिल व्यक्ति
   (D) पाँच एकड़ से कम कृषि भूमि के स्वामी व्यक्ति

NODIA

5. सार्वजनिक नियोजन में आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
   अभिकथन (A): भारत के उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले (1992) में सार्वजनिक नियोजन में कुल आरक्षण पर 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित की।
   कारण (R): न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 16(4) पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात करता है और समानता के नियम का एक अपवाद है, इसलिए आरक्षण ऐसा सामान्य नियम नहीं बनना चाहिए जो योग्यता को दरकिनार कर दे।
   (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
   (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
   (C) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
   (D) अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

6. 'क्रीमी लेयर' (उन्नत वर्ग) की अवधारणा, जो पिछड़े वर्गों के समृद्ध हिस्से को आरक्षण के लाभों से बाहर करती है, वर्तमान संवैधानिक ढाँचे में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस श्रेणी पर लागू होती है?
   (A) अनुसूचित जाति
   (B) अनुसूचित जनजाति
   (C) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
   (D) अन्य पिछड़ा वर्ग

7. राजस्थान में ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोटे के मानक कार्यान्वयन के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के तहत शामिल न होने के अलावा लाभार्थी परिवार की पहचान करने का मुख्य मानदंड क्या है?
   (A) परिवार के मुखिया की शैक्षणिक योग्यता और रोजगार की स्थिति
   (B) कुल वार्षिक पारिवारिक आय और विशिष्ट संपत्ति स्वामित्व की सीमाएँ

(C) केवल कृषि स्रोतों से प्राप्त कुल वार्षिक पारिवारिक आय
(D) परिवार का स्थायी भौगोलिक स्थान और मूल निवास की स्थिति

8. दुर्बल वर्गों के लिए संस्थागत ढाँचे से संबंधित निम्नलिखित मील के पत्थरों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर आयोग) की नियुक्ति।
II. ईडब्ल्यूएस आरक्षण शुरू करने वाला संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम।
III. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को विभाजित करने वाला संविधान (नवासीवाँ संशोधन) अधिनियम।
IV. द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) की नियुक्ति।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम का चयन कीजिए:
(A) I, IV, III, II
(B) I, III, IV, II
(C) IV, I, III, II
(D) I, IV, II, III

9. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 यह निर्धारित करता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों पर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की संगति के साथ विचार किया जाएगा?
(A) जनसंख्या का निरपेक्ष संख्यात्मक बल
(B) राज्य के खजाने की वित्तीय क्षमता
(C) इन समुदायों द्वारा झेली गई ऐतिहासिक प्रतिकूलता
(D) प्रशासन की कार्यकुशलता बनाए रखना

10. सूची I के संवैधानिक अनुच्छेदों को सूची II में दिए गए संस्थागत जनादेशों से संबंधित प्रावधानों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अनुच्छेद)
P. अनुच्छेद 338
Q. अनुच्छेद 338A
R. अनुच्छेद 338B
S. अनुच्छेद 340
सूची II: (प्रावधान)
1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. पिछड़े वर्गों की परिस्थितियों की जाँच के लिए आयोग की नियुक्ति
3. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
4. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

11. राजस्थान सरकार का कौन-सा नोडल विभाग अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए लक्षित नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है?
(A) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(B) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(C) महिला एवं बाल विकास विभाग
(D) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

12. राजस्थान में अल्पसंख्यक कल्याण के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और असत्य कथन की पहचान कीजिए।
(A) राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम स्वरोजगार के लिए रियायती ऋण प्रदान करता है।
(B) राजस्थान में राज्य सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षण संवैधानिक रूप से 12 प्रतिशत तय किया गया है।
(C) राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी।
(D) राजस्थान में अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक विकास कार्यक्रमों में मान्यता प्राप्त मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण शामिल है।

13. राजस्थान में संचालित 'पालनहार योजना' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह अनाथ और वंचित बच्चों की देखभाल, पालन-पोषण और शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
II. योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त के रूप में बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्र या विद्यालय भेजना आवश्यक है।
III. विधवा माताओं के बच्चे और सिलिकोसिस या एचआईवी/एड्स से पीड़ित माता-पिता के बच्चे भी इस योजना के तहत पात्र हैं।
IV. योजना के तहत बच्चे के 18 वर्ष के होने पर केवल एकमुश्त अनुदान दिया जाता है और उस आयु से पहले कोई मासिक भत्ता नहीं दिया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, III और IV
(D) I, II, III और IV

14. राजस्थान में 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' (पूर्व में हथलेवा योजना) का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अवसर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है?
(A) गरीबी रेखा से नीचे के परिवार में बालिका का जन्म
(B) बालिका का उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश
(C) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और बीपीएल परिवारों की बालिकाओं का विवाह
(D) एक वयस्क महिला द्वारा सूक्ष्म उद्यम इकाई की स्थापना

15. राजस्थान में 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' निम्नलिखित में से किस विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी?

Downloaded from www.pdf.tube

(A) जनजातीय युवाओं को अनुदानित विशेष खेल प्रशिक्षण और कोचिंग प्रदान करना
(B) वंचित ग्रामीण महिलाओं को मूलभूत आईटी और डिजिटल कंप्यूटर कौशल में प्रशिक्षित करना
(C) ग्रामीण विद्यालय छोड़ने वाले युवाओं को प्रमाणित व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना
(D) कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता करना

16. राजस्थान में जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) क्षेत्र के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: राजस्थान के अधिसूचित टीएसपी क्षेत्रों के भीतर सरकारी रोजगार में विशेष आरक्षण कोटा विशेष रूप से स्थानीय अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है।
कथन II: राजस्थान में टीएसपी क्षेत्र बिना किसी विशिष्ट जिला सीमाओं के राज्य के संपूर्ण भौगोलिक विस्तार को कवर करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

17. राजस्थान में वंचित महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों के संबंध में निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): 'मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना' राजस्थान में विशेष रूप से विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।
कारण (R): इन श्रेणियों की महिलाएं अक्सर गंभीर आर्थिक संवेदनशीलता और सामाजिक बहिष्कार का सामना करती हैं, जिससे उनकी आजीविका सहायता के लिए लक्षित राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

18. नीचे चार संस्थागत निकाय दिए गए हैं। उनकी संवैधानिक या वैधानिक स्थिति के आधार पर बेमेल की पहचान कीजिए।
(A) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
(B) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(C) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
(D) राष्ट्रीय महिला आयोग

19. राजस्थान राज्य सेवाओं में आरक्षण व्यवस्था के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण कोटा वर्तमान में 21 प्रतिशत निर्धारित है।
II. अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण कोटा वर्तमान में 16 प्रतिशत निर्धारित है।
III. अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के लिए 5 प्रतिशत के अलग आरक्षण का प्रावधान है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से गलत है/हैं?
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) केवल III
(D) केवल I और III

NODIA

20. राजस्थान राज्य अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं में वर्तमान आरक्षण नीति के तहत, अनुसूचित जाति (एससी) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सीटों का सटीक प्रतिशत क्या है?
(A) 12 प्रतिशत
(B) 14 प्रतिशत
(C) 16 प्रतिशत
(D) 21 प्रतिशत

21. राजस्थान में 'मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना' के तहत, वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए महिला आवेदक की न्यूनतम पात्र आयु क्या है?
(A) 50 वर्ष
(B) 55 वर्ष
(C) 58 वर्ष
(D) 60 वर्ष

22. सूची I की राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को सूची II में दिए गए उनके प्राथमिक लक्षित लाभार्थियों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (पेंशन योजनाएँ)
P. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
Q. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
R. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
S. मुख्यमंत्री कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
सूची II: (लक्षित लाभार्थी)
1. छोटे और सीमांत वृद्ध किसान
2. विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं
3. एक निर्दिष्ट आयु से अधिक के बुजुर्ग पुरुष और महिला नागरिक
4. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति
(A) P-3, Q-4, R-2, S-1
(B) P-1, Q-2, R-4, S-3
(C) P-2, Q-3, R-1, S-4
(D) P-3, Q-2, R-4, S-1

23. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, जो राजस्थान की राज्य सेवाओं पर सीधे लागू होता है, सरकारी प्रतिष्ठानों में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य न्यूनतम आरक्षण प्रतिशत क्या है?

(A) 2 प्रतिशत
(B) 3 प्रतिशत
(C) 4 प्रतिशत
(D) 5 प्रतिशत

24. राजस्थान का एक निवासी जो बीपीएल श्रेणी से संबंधित है, राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहता है। इस योजना के वितरण के लिए मानक प्रक्रियात्मक चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए।
(A) कोषालय में भौतिक फॉर्म जमा करना → जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृति → बायोमेट्रिक सत्यापन → डीबीटी अंतरण
(B) स्वीकृति और डीबीटी अंतरण → जन आधार के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन → उपखंड अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन → ई-मित्र के माध्यम से आवेदन जमा करना
(C) जन आधार के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन → ई-मित्र के माध्यम से आवेदन जमा करना → उपखंड अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन → स्वीकृति और डीबीटी अंतरण
(D) उपखंड अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन → स्वीकृति और डीबीटी अंतरण → ई-मित्र के माध्यम से आवेदन जमा करना → बायोमेट्रिक सत्यापन

25. राजस्थान सरकार की सिलिकोसिस नीति प्रभावित व्यक्तियों के वित्तीय, चिकित्सा और सामाजिक पुनर्वास पर केंद्रित है। कौन-सा विशिष्ट व्यावसायिक समूह इस नीति का मुख्य लक्ष्य है?
(A) खतरनाक रासायनिक कीटनाशकों के संपर्क में लगातार रहने वाले कृषि मजदूर
(B) आधुनिक हथकरघा और पावरलूम बुनाई में लगे कपड़ा उद्योग के श्रमिक
(C) ठोस शहरी कचरा एकत्र करने में शामिल नगर निगम के सफाई कर्मचारी
(D) खदान श्रमिक और पत्थर पीसने (क्रशिंग) तथा पत्थर तराशने की इकाइयों के मजदूर

26. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह अधिनियम इन श्रेणियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध किए गए विशिष्ट आपराधिक अपराधों को "अत्याचार" के रूप में परिभाषित करता है।
II. यह ऐसे अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए जिला स्तर पर विशेष न्यायालयों की स्थापना का जनादेश देता है।
III. यह इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों को चलाने के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
IV. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत इस अधिनियम के तहत आरोपी के लिए एक मानक अधिकार के रूप में आसानी से उपलब्ध है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

27. राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित 'नवजीवन योजना' किस विशिष्ट समूह के पुनर्वास के लिए लक्षित है?
(A) पूर्व में हाथ से मैला ढोने के काम में लगे व्यक्ति
(B) अवैध शराब निर्माण और व्यापार में शामिल परिवार
(C) गंभीर मादक द्रव्यों के सेवन और नशीली दवाओं की लत से पीड़ित युवा
(D) बेघर बच्चे और खतरनाक व्यवसायों से मुक्त कराए गए बाल मजदूर

28. दुर्बल समूहों के लिए भूमि वितरण नीतियों के संबंध में निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): भूमिहीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को अधिशेष कृषि भूमि का वितरण उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य नीति रही है।
कारण (R): कृषि भूमि का स्वामित्व न केवल आजीविका का एक स्थायी स्रोत प्रदान करता है, बल्कि ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्थायों में दुर्बल समूहों की सामाजिक स्थिति को भी बढ़ाता है।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

29. राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की स्थापना 1992 में निम्नलिखित में से किस ढांचे के तहत की गई थी?
(A) संसद का राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990
(B) केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा औपचारिक रूप से पारित एक कार्यपालक प्रस्ताव
(C) संविधान के भाग IV के तहत एक समर्पित संवैधानिक अनुच्छेद
(D) जनहित याचिका में उच्चतम न्यायालय का एक बाध्यकारी सीधा आदेश

30. दुर्बल युवाओं के लिए पीएम-दक्ष योजना जैसी विशेष कौशल विकास योजनाओं को लागू करने का सबसे उपयुक्त प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) सरकारी रोजगार में आरक्षण की संवैधानिक प्रणाली को समाप्त करना
(B) ग्रामीण युवाओं का शहरी केंद्रों की ओर संरचनात्मक

Click Here to Buy book on Flipkart

आर्थिक प्रवास सुनिश्चित करना
(C) उनकी रोजगार क्षमता और उद्यमशीलता की क्षमताओं को बढ़ाना
(D) स्थायी नियोजन होने तक अस्थायी बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना

31. राजस्थान में 'देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना' मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस श्रेणी की बालिकाओं के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है?
(A) अनुसूचित जाति श्रेणी (एससी)
(B) अनुसूचित जनजाति श्रेणी (एसटी)
(C) मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय
(D) अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी)

32. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक संरक्षणों से संबंधित सभी मामलों की जाँच और निगरानी करता है।
II. अधिकारों से वंचित करने की किसी विशिष्ट शिकायत की जाँच करते समय इसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं।
III. यह अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूची में स्वतंत्र रूप से संशोधन करने के लिए अधिकृत है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

33. राजस्थान में महिला सशक्तिकरण योजनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा 'आईएम शक्ति उड़ान योजना' का उद्देश्य नहीं है?
(A) महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन का वितरण
(B) ब्यूटी पार्लर स्थापित करने के लिए सीधी वित्तीय सहायता प्रदान करना
(C) मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में जागरूकता पैदा करना
(D) मासिक धर्म स्वास्थ्य समस्याओं के कारण विद्यालयों से किशोरी बालिकाओं की ड्रॉपआउट दर को कम करना

34. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराधों की जाँच और सुनवाई में शामिल मानक चरणों को सही प्रक्रियात्मक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
I. पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करना।
II. विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल करना।
III. पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा जाँच पूरी करना।
IV. विशेष न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया जाना।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम का चयन कीजिए:
(A) I, III, II, IV
(B) I, II, III, IV
(C) III, I, II, IV
(D) I, III, IV, II

35. राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष पारित राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम के तहत किया गया था?
(A) 1993
(B) 2001
(C) 2005
(D) 2011

36. सूची I की शैक्षणिक सशक्तिकरण योजनाओं को सूची II में उनके प्रमुख प्रावधानों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (योजनाएं)
P. पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति
Q. उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति
R. डॉ. अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना
S. कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना
सूची II: (प्रावधान)
1. कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली मेधावी छात्राओं को आवागमन/गतिशीलता सहायता
2. कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता
3. उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर रहने वाले छात्रों के लिए आवासीय भत्ता
4. कक्षा 11, 12 और कॉलेज में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता
(A) P-4, Q-2, R-1, S-3
(B) P-2, Q-3, R-4, S-1
(C) P-2, Q-4, R-3, S-1
(D) P-3, Q-4, R-2, S-1

37. निम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जनादेश या कार्य नहीं है?
(A) अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार करने के दोषी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से दंडित करना
(B) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना
(C) संघ और किसी राज्य के तहत अनुसूचित जनजातियों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना
(D) अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक संरक्षणों के कामकाज पर राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Downloaded from www.pdf.tube

छात्रों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना है।
(D) यह प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक एससी या एसटी उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख से 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है।

55. राजस्थान में अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणियों के साथ-साथ अल्पसंख्यक छात्रों को भी कवर करती है।
II. राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम अपने ऋणों को केवल कृषि गतिविधियों तक ही सीमित रखता है।
III. राज्य की योजनाओं के लिए मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन शामिल हैं।
IV. राज्य ने इन विशेष पहलों की देखरेख के लिए एक अलग अल्पसंख्यक मामलात विभाग की स्थापना की है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

56. 'कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना' मेधावी छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए कई पूर्व योजनाओं को एकीकृत करती है। इस योजना के तहत स्कूटी का आवंटन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मानदंड पर निर्भर करता है?
(A) राज्य शारीरिक दक्षता मूल्यांकन परीक्षा में प्रदर्शन
(B) परिवार द्वारा किसी भी चौपहिया वाहन का पूर्व स्वामित्व
(C) कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंक
(D) मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री का सफलतापूर्वक समापन

57. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) दुर्बल युवाओं के लिए लक्षित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। राज्य-प्रायोजित इन कौशल विकास पहलों का मूलभूत दृष्टिकोण क्या है?
(A) पूरी तरह से निःशुल्क चार वर्षीय तकनीकी इंजीनियरिंग डिग्री अनिवार्य रूप से प्रदान करना
(B) शारीरिक श्रम के काम के लिए युवा नौकरी चाहने वालों को विदेशों में यात्रा करने के लिए प्रायोजित करना
(C) अनिवार्य प्रशिक्षण के बिना सीधे स्थायी बेरोजगारी भत्ते का वितरण करना
(D) प्लेसमेंट या स्वरोजगार सुनिश्चित करने वाला उद्योग-संबद्ध अल्पकालिक प्रशिक्षण

58. भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 कमजोर वर्गों के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए मूलभूत हैं। वे विशेष रूप से क्या अनिवार्य करते हैं?
(A) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण
(B) सभी सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजन और राज्य की सेवाओं में अनिवार्य आरक्षण
(C) अस्पृश्यता और बंधुआ मजदूरी के रूपों का पूर्ण निषेध और उन्मूलन
(D) मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए वैधानिक राष्ट्रीय निकायों की स्थापना

NODIA

59. पूर्व में संयुक्त 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग' का दो अलग-अलग संवैधानिक निकायों में विभाजन किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था?
(A) 73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992
(B) 86वाँ संशोधन अधिनियम, 2002
(C) 89वाँ संशोधन अधिनियम, 2003
(D) 102वाँ संशोधन अधिनियम, 2018

60. राजस्थान में जन आधार कार्ड सामाजिक न्याय के ढाँचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में इसका सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक कार्य निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) नागरिकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए आवश्यक आधिकारिक पासपोर्ट के रूप में कार्य करता है
(B) दोहरे (फ़र्ज़ी) लाभार्थियों को रोकने के लिए एकीकृत निवासी आईडी और डीबीटी प्लेटफॉर्म
(C) सभी कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति को ट्रैक करने के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है
(D) राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान आधिकारिक मतदाता पहचान पत्रों का स्थान लेता है

61. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत भारत में विशिष्ट समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। निम्नलिखित में से किस समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है?
(A) बहाई
(B) बौद्ध
(C) पारसी
(D) जैन

62. राजस्थान में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की प्राथमिक भूमिका क्या है?
(A) राज्य के निवासियों को सीधे आधिकारिक जाति और समुदाय प्रमाण पत्र जारी करना
(B) लोक सेवा भर्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करना
(C) पिछड़े वर्ग में शामिल करने के अनुरोधों की जाँच करना और सूची संबंधी शिकायतों की सुनवाई करना
(D) दुर्बल किसानों को सरकारी कृषि भूमि के भूखंड आवंटित करना

46. राजस्थान में 'मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना' के लिए पात्र होने के लिए, बौनेपन से पीड़ित आवेदक की ऊँचाई सामान्यतः किससे कम होनी चाहिए?
(A) 3 फीट 6 इंच
(B) 4 फीट 0 इंच
(C) 4 फीट 6 इंच
(D) 5 फीट 0 इंच

47. राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक ढाँचे के सही पदानुक्रमित क्रम का उच्चतम राज्य स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक चयन कीजिए।
(A) निदेशालय (राज्य) → जिला कार्यालय → ब्लॉक कार्यालय → पंचायत/शहरी वार्ड स्तर के कार्यकर्ता
(B) ब्लॉक कार्यालय → जिला कार्यालय → निदेशालय (राज्य) → पंचायत स्तर के कार्यकर्ता
(C) निदेशालय (राज्य) → पंचायत स्तर के कार्यकर्ता → ब्लॉक कार्यालय → जिला कार्यालय
(D) जिला कार्यालय → निदेशालय (राज्य) → ब्लॉक कार्यालय → पंचायत/शहरी वार्ड स्तर के कार्यकर्ता

48. 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना' (पीएमएजीवाई) का कार्यान्वयन उन गाँवों के एकीकृत विकास के उद्देश्य से किया जाता है जहाँ किस विशिष्ट समुदाय की जनसंख्या 50% से अधिक है?
(A) अनुसूचित जनजाति (एसटी)
(B) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)
(C) अनुसूचित जाति (एससी)
(D) अल्पसंख्यक

49. राजस्थान के संदर्भ में सूची I के नोडल विभागों को सूची II में दिए गए उनके प्राथमिक लक्षित समूहों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (नोडल विभाग)
P. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
Q. अल्पसंख्यक मामलात विभाग
R. विशेष योग्यजन निदेशालय
S. राजस्थान राज्य महिला आयोग
सूची II: (लक्षित समूह)
1. दृष्टि और श्रवण बाधा वाले व्यक्ति
2. नामित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति
3. मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन
4. घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर उत्पीड़न की पीड़ित महिलाएं
(A) P-3, Q-2, R-4, S-1
(B) P-2, Q-3, R-1, S-4
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

50. सामाजिक न्याय योजनाओं के वितरण में नौकरशाही की देरी अक्सर प्रणालीगत अक्षमताओं से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से किसे सार्वभौमिक रूप से दुर्बल वर्गों को पेंशन स्वीकृत करने में देरी का मुख्य प्रशासनिक कारण माना जाता है?
(A) वार्षिक बजट में केंद्र सरकार के धन का अपर्याप्त आवंटन
(B) आवेदकों के बीच अपर्याप्त डिजिटल साक्षरता और तकनीकी पहुँच
(C) स्थानीय आबादी के जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल में तीव्र और लगातार बदलाव
(D) जटिल बहुस्तरीय सत्यापन और अनुमोदन प्रक्रियाएं

51. राजस्थान में सहरिया विकास परियोजना विशेष रूप से सहरिया जनजाति पर केंद्रित एक लक्षित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है। यह परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में लागू की गई है?
(A) बारां
(B) डूंगरपुर
(C) बांसवाड़ा
(D) उदयपुर

52. महिलाओं के अधिकारों के लिए संस्थागत तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: राष्ट्रीय महिला आयोग संविधान के तहत महिलाओं के लिए प्रदान किए गए संरक्षणों से संबंधित मामलों की जाँच करता है।
कथन II: राज्य महिला आयोग कड़ाई से राष्ट्रीय महिला आयोग की अधीनस्थ शाखाओं के रूप में कार्य करते हैं और मामलों का स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

53. राजस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र होने के लिए, सभी स्रोतों से छात्र के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सामान्यतः किस सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए (हाल के मानक मानदंडों के अनुसार)?
(A) 1.00 लाख रुपये
(B) 1.50 लाख रुपये
(C) 2.50 लाख रुपये
(D) 8.00 लाख रुपये

54. 'स्टैंड अप इंडिया' योजना के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए, जो आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के चौराहे पर कार्य करती है।
(A) यह रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडरों) को कड़ाई से 10,000 से 50,000 रुपये के बीच बैंक ऋण प्रदान करती है।
(B) यह बीज खरीदने के लिए भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण प्रदान करती है।
(C) यह प्रबंधन की डिग्री हासिल करने वाले अल्पसंख्यक

Click Here to Buy book on Amazon

38. 'मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. यह बिना किसी राज्य के योगदान के केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित है।
II. जब लाभार्थी 75 वर्ष की आयु पार कर लेता है तो पेंशन की राशि स्वतः बढ़ जाती है।
III. केंद्र या राज्य सरकार से नियमित पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति सामान्यतः पात्र नहीं होता है।
IV. यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, III और IV
(D) I, II, III और IV

39. राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई 'डॉ. अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना' का उद्देश्य आरक्षित श्रेणियों के महाविद्यालयीन छात्रों के किस विशिष्ट व्यय को पूरा करना है?

(A) निजी इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों के लिए पूरा शिक्षण शुल्क माफ करना
(B) पात्र छात्रों के लिए आवासीय सुविधा और मासिक कमरा किराया भत्ता
(C) व्यक्तिगत लैपटॉप और आवश्यक डिजिटल अध्ययन सामग्री की सीधी खरीद
(D) घर से कॉलेज आने-जाने के लिए दैनिक सार्वजनिक परिवहन व्यय

40. राजस्थान में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:

अभिकथन (A): राजस्थान में जन आधार ढाँचे का उपयोग करके प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के कार्यान्वयन से छात्रवृत्ति और पेंशन योजनाओं में रिसाव (लीकेज) में काफी कमी आई है।

कारण (R): डीबीटी सत्यापित लाभार्थियों के आधार-लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि स्थानांतरित करके नौकरशाही बिचौलियों को हटाता है।

(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

41. अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों सहित दुर्बल व्यक्तियों के कौशल विकास को लक्षित 'पीएम-दक्ष' (प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही) योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है?

(A) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
(B) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
(C) ग्रामीण विकास मंत्रालय
(D) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

NODIA

42. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुसूचित जातियों की प्रारंभिक सूची को अधिसूचित करने की शक्ति किसमें निहित है?

(A) राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद भारत के राष्ट्रपति
(B) एक वैधानिक विधायी अधिनियम के माध्यम से भारत की संसद
(C) केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
(D) संबंधित विशिष्ट राज्य की विधानसभा

43. राजस्थान में राज्य महिला आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?

(A) इसका गठन राज्य में महिलाओं के अधिकारों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जाँच के लिए किया गया है।
(B) इसके पास घरेलू हिंसा के मामलों में अपराधियों को कारावास की सजा देने की कानूनी शक्ति है।
(C) आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
(D) यह संविधान और महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों के मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करता है और संशोधनों की सिफारिश करता है।

44. अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक मानकों में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारें एसपीक्यूईएम (SPQEM) योजना लागू करती हैं। इस संदर्भ में SPQEM का पूर्ण रूप क्या है?

(A) स्पेशल प्रोग्राम फॉर क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसाज़
(B) स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसाज़
(C) स्टेट प्लान फॉर क्वांटिटेटिव एजुकेशनल मेजरमेंट
(D) स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर क्वालिफाइंग एजुकेटेड माइनॉरिटीज़

45. एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत विशेष न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करती है।
II. इन विशेष न्यायालयों का अनन्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के नागरिक संपत्ति विवादों को निपटाना है।
III. यह अधिनियम आदेश देता है कि इन विशेष न्यायालयों द्वारा सुनवाई अधिमानतः आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से दो महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से गलत है/हैं?

(A) केवल I
(B) केवल II
(C) केवल I और III
(D) केवल II और III

63. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 कमजोर वर्गों के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है।इसे मुख्य रूप से किसके लिए दंड का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था?
(A) घरेलू परिवारों में दहेज की मांग और घरेलू हिंसा का आचरण
(B) नामित वन भूमियों का अवैध अतिक्रमण और कब्जा
(C) औद्योगिक कार्यस्थलों में कम उम्र के बच्चों का खतरनाक नियोजन
(D) अस्पृश्यता का आचरण और उससे संबंधित निर्योग्यताओं को लागू करना

64. सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू करने के संदर्भ में, 'रोस्टर प्रणाली' का उद्देश्य क्या है?
(A) सभी नए नियुक्त रंगरूटों के बीच यादृच्छिक रूप से भौगोलिक कार्य पदस्थापन आवंटित करना
(B) सार्वजनिक कर्मचारियों के लिए वार्षिक वित्तीय वेतन वृद्धि को विनियमित करना
(C) आरक्षित समूहों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए रिक्तियों को ट्रैक करना
(D) राज्य सरकार के कर्मचारियों के परिचालन कार्य सारणियों को तय और प्रबंधित करना

65. संवैधानिक प्रावधान जो स्पष्ट रूप से राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति के मामलों में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है, कहाँ स्थित है?
(A) अनुच्छेद 15(5) में
(B) अनुच्छेद 16(4A) में
(C) अनुच्छेद 335 में
(D) अनुच्छेद 342 में

66. राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम (आरएससीएसटीएफडीसीसी) इन समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करता है। यह मुख्य रूप से इस जनादेश को कैसे निष्पादित करता है?
(A) ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे सरकारी प्राथमिक स्कूलों की स्थापना और संचालन करके
(B) सार्वजनिक आवास कॉलोनियों के निर्माण के लिए विशाल निजी भूमि के टुकड़ों का अधिग्रहण करके
(C) सभी जिला न्यायिक न्यायालयों में मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र खोलकर
(D) आय सृजन गतिविधियों के लिए ऋण, मार्जिन मनी और माइक्रोफाइनेंस प्रदान करके

67. दुर्बल ग्रामीण आबादी के बीच सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरुकता के अंतर को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त और टिकाऊ तरीका माना जाता है?
(A) प्रचार-प्रसार के लिए ग्राम पंचायतों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वयं सहायता समूहों को लामबंद करना
(B) आधिकारिक अंग्रेजी में ऑनलाइन विस्तृत कल्याण नीति दस्तावेज प्रकाशित करना
(C) केवल जिला सूचना पट्टों पर सार्वजनिक योजना की सूचनाएं प्रदर्शित करना
(D) दिशानिर्देश प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को राज्य मुख्यालय का दौरा करने की आवश्यकता होना

68. 'हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना' सामाजिक न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। निम्नलिखित में से कौन-सा इस योजना का एक मुख्य घटक है?
(A) स्वच्छता श्रम छोड़ने वाले परिवारों को मुफ्त कृषि भूमि के भूखंड आवंटित करना
(B) केंद्र सरकार के रेलवे में गारंटीकृत स्थायी रोजगार पदों की पेशकश करना
(C) यांत्रिक स्वच्छता उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी और ऋण प्रदान करना
(D) अकुशल श्रम के रूप में निजी कॉर्पोरेट फर्मों में अनिवार्य प्लेसमेंट की सुविधा प्रदान करना

69. कुछ क्षेत्र-विशिष्ट अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रमों (जैसे बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम / पीएमजेवीके) के लिए, किसी क्षेत्र को हस्तक्षेप के लिए आमतौर पर तब चिह्नित किया जाता है जब उस ब्लॉक या नगर में अल्पसंख्यक आबादी कुल आबादी का कम से कम कितना प्रतिशत हो?
(A) 10 प्रतिशत
(B) 15 प्रतिशत
(C) 25 प्रतिशत
(D) 50 प्रतिशत

70. राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अनेक 'आश्रम छात्रावास' संचालित करता है। इन संस्थानों का विशिष्ट उद्देश्य क्या है?
(A) बेसहारा बुजुर्ग नागरिकों के लिए पूर्णकालिक आवासीय वृद्धाश्रम स्थापित करना
(B) जनस्वास्थ्य के लिए विशेष चिकित्सा पृथकवास (क्वारंटीन) सुविधाओं के रूप में कार्य करना
(C) विशेष रूप से विरासत क्षेत्रीय हस्तशिल्प में गहन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना
(D) आरक्षित श्रेणी के छात्रों को मुफ्त आवास, भोजन और शैक्षणिक सहायता प्रदान करना

71. आरक्षण के कार्यान्वयन की समय-सीमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण 1990 में लागू किया गया था।
कथन II: ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान करने वाला 103वाँ

Downloaded from www.pdf.tube

20. (C) 16 प्रतिशत
राजस्थान की राज्य स्तरीय, अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं तथा सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण की स्थापित नीति के अनुसार विभिन्न सामाजिक समूहों का कोटा तय किया गया है। इस व्यवस्था में अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कुल पदों का सटीक 16 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही अन्य वर्गों का भी कोटा नियमानुसार लागू किया गया है।

21. (B) 55 वर्ष
राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना' के तहत वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने हेतु लिंग आधारित न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत महिला आवेदकों के लिए न्यूनतम पात्र आयु 55 वर्ष तय की गई है, जबकि पुरुष आवेदकों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित की गई है।

22. (D) P-3, Q-2, R-4, S-1
राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में 'मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना' बुजुर्गों के लिए है। 'मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना' विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता महिलाओं को लक्षित करती है। 'मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना' दिव्यांग व्यक्तियों हेतु संचालित है, जबकि 'मुख्यमंत्री कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना' छोटे व सीमांत वृद्ध किसानों को वित्तीय सुरक्षा देने के उद्देश्य से लागू की गई है।

23. (C) 4 प्रतिशत
केंद्र सरकार द्वारा पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य न्यूनतम आरक्षण कोटा बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे पूर्व के 1995 के कानून में यह सीमा 3 प्रतिशत निर्धारित थी। राजस्थान सरकार ने भी इस 4 प्रतिशत आरक्षण नियम को पूर्णतः लागू किया है।

24. (C) जन आधार के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन → ई-मित्र के माध्यम से आवेदन जमा करना → उपखंड अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन → स्वीकृति और डीबीटी अंतरण
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने हेतु सबसे पहले जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदक का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाता है। इसके पश्चात ई-मित्र केंद्र से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात उपखंड अधिकारी या विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन होता है। अंतिम चरण में स्वीकृति के बाद पेंशन राशि सीधे डीबीटी द्वारा आवेदक के खाते में स्थानांतरित की जाती है।

25. (D) खदान श्रमिक और पत्थर पीसने (क्रशिंग) तथा पत्थर तराशने की इकाइयों के मजदूर
राजस्थान सरकार की सिलिकोसिस नीति मुख्य रूप से उन खदान श्रमिकों, पत्थर पीसने वाली इकाइयों और पत्थर तराशने के काम में लगे मजदूरों को लक्षित करती है जो लगातार धूल तथा सिलिका कणों के संपर्क में आते हैं। यह एक घातक बीमारी है जो खनन उद्योग के श्रमिकों को प्रभावित करती है। यह नीति पीड़ितों को वित्तीय सहायता तथा पुनर्वास प्रदान करती है।

NODIA

26. (A) केवल I, II और III
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 गैर-एससी/एसटी वर्ग द्वारा इन वर्गों पर किए जाने वाले अपराधों को रोकता है। यह अधिनियम त्वरित सुनवाई हेतु विशेष न्यायालयों के गठन और विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति का निर्देश देता है। हालाँकि इस कानून के तहत आरोपी को अग्रिम जमानत एक मानक अधिकार के रूप में आसानी से नहीं मिलती।

27. (B) अवैध शराब निर्माण और व्यापार में शामिल परिवार
राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित 'नवजीवन योजना' का प्राथमिक उद्देश्य अवैध शराब के निर्माण और व्यापार में शामिल परिवारों तथा व्यक्तियों का सर्वांगीण पुनर्वास करना है। इस योजना के माध्यम से ऐसे परिवारों को मुख्यधारा में लाने के लिए कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और रोजगार के वैकल्पिक अवसर सुलभ कराए जाते हैं।

28. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
भूमिहीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को कृषि योग्य भूमि का आवंटन करना कल्याणकारी राज्य का एक प्रमुख नीतिगत उद्देश्य रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि न केवल आजीविका और खाद्य सुरक्षा का एक स्थाई स्रोत प्रदान करती है, बल्कि यह ग्रामीण सामाजिक संरचना में कमजोर वर्गों की सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा को भी मजबूत करती है।

29. (A) संसद का राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990
राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में भारतीय संसद द्वारा पारित एक विशेष वैधानिक कानून 'राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990' के तहत की गई थी। यह एक सांविधिक निकाय है जो महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, शिकायतों की जाँच करने और नीतिगत सुधारों की सिफारिश करने हेतु गठित किया गया था ताकि महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सके।

30. (C) उनकी रोजगार क्षमता और उद्यमशीलता की क्षमताओं को बढ़ाना
दुर्बल एवं वंचित वर्गों के युवाओं के लिए लागू की जाने वाली 'पीएम-दक्ष' जैसी विशेष कौशल विकास पहलों का मुख्य प्राथमिक उद्देश्य उन्हें बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप

संरचनात्मक वित्तीय निर्भरता पैदा करना

(C) वास्तविक समानता प्राप्त करना और कमजोर वर्गों को विकास की मुख्यधारा में एकीकृत करना

(D) गैर-आरक्षित उन्नत वर्गों के मौलिक संवैधानिक अधिकारों को सीमित करना

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Flipkart

संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2019 में पारित और लागू किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

72. संवैधानिक आयोग और उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों के कार्यकाल की मानक अवधि के बीच सही युग्म की पहचान कीजिए, जैसा कि पारंपरिक रूप से उनके संबंधित नियमों में तैयार किया गया है।
(A) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग — 5 वर्ष
(B) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग — 6 वर्ष
(C) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग — 3 वर्ष
(D) राष्ट्रीय महिला आयोग — 2 वर्ष

73. नीचे राज्य की चार कल्याणकारी योजनाएं सूचीबद्ध हैं। प्रदान किए गए लाभ की मूलभूत प्रकृति (नियमित निर्वाह भत्ता बनाम शैक्षणिक/योग्यता अनुदान) के आधार पर बेमेल की पहचान कीजिए।
(A) मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
(B) मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
(C) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
(D) मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना

74. जब राजस्थान में भूमिहीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को कृषि भूमि वितरित की जाती है, तो शोषण को रोकने के लिए ऐसे भूमि आवंटन के साथ अक्सर कौन-सी मानक कानूनी शर्त जुड़ी होती है?
(A) आवंटी की सुरक्षा के लिए भूमि गैर-एससी/एसटी व्यक्तियों को अहस्तांतरणीय है
(B) आवंटन के पांच वर्षों के भीतर भूमि को गैर-एससी/एसटी खरीदारों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए
(C) आवंटित कृषि भूमि को व्यावसायिक औद्योगिक उपयोग के लिए परिवर्तित किया जाना चाहिए
(D) भूमि को केवल आधिकारिक राज्य सरकार के कार्यकर्ताओं द्वारा ही प्रबंधित और खेती किया जा सकता है

75. कमजोर वर्गों के लिए बजटीय आवंटन के संदर्भ में, अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में धन निर्धारित करने की रणनीति को ऐतिहासिक रूप से विशेष घटक योजना (एससीपी) के रूप में जाना जाता था। नियोजन शब्दावली में इसका वर्तमान मानक नाम क्या है?
(A) मार्जिनलाइज़्ड रिसोर्स एलोकेशन
(B) अनुसूचित जाति उप-योजना
(C) डायरेक्ट बेनिफिट ट्राइबल प्लान
(D) कंसोलिडेटेड वेलफेयर फंड

76. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ने मान्यता प्राप्त दिव्यांगता श्रेणियों की संख्या को 7 (1995 के अधिनियम के तहत) से बढ़ाकर कितना करके भारत में दिव्यांगता अधिकारों के क्षितजन का विस्तार किया?
(A) 14
(B) 21
(C) 28
(D) 32

NODIA

77. 'पीएम-यशस्वी' योजना विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस श्रेणी के छात्रों के लिए तैयार की गई एक व्यापक छात्रवृत्ति योजना है?
(A) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी श्रेणियों से संबंधित छात्र
(B) उग्रवाद प्रभावित ग्रामीण जिलों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्र
(C) पेशेवर मेडिकल डिग्री कार्यक्रमों में नामांकित अनुसूचित जाति के छात्र
(D) विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र

78. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 4 के तहत, ऐसे लोक सेवक (जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो) के लिए क्या परिणाम निर्धारित है जो इस अधिनियम के तहत किए जाने के लिए आवश्यक कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करता है?
(A) बिना किसी विभागीय जाँच के लोक सेवा से तत्काल बर्खास्तगी
(B) बिना किसी कारावास के एक लाख रुपये तक का मौद्रिक अर्थदंड लगाना
(C) छह महीने से लेकर एक वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास
(D) दूरस्थ गैर-संवेदनशील जिले में अनिवार्य प्रशासनिक स्थानांतरण

79. दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक और उच्च-स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वावधान में संचालित होते हैं?
(A) शिक्षा मंत्रालय
(B) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
(C) अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय
(D) जनजातीय कार्य मंत्रालय

80. लोकतांत्रिक व्यवस्था में लक्षित सामाजिक न्याय योजनाओं (जैसे आरक्षण, सब्सिडी और सुरक्षात्मक कानून) को लागू करने के अंतिम उद्देश्य को सबसे उपयुक्त रूप से किस प्रकार वर्णित किया गया है?
(A) सभी निजी कॉर्पोरेट कार्यकारी बोर्डों में कठोर संख्यात्मक प्रतिनिधित्व हासिल करना
(B) राज्य की सहायता पर पिछड़े समूहों की आजीवन

कार्यकुशलता बनाए रखने के सिद्धांत का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा।

10. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। 102वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जाँच हेतु आयोग नियुक्ति की शक्ति देता है।

11. (B) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज्य का मुख्य नोडल विभाग है जो अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के उत्थान के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, छात्रवृत्ति पहलों, आवासीय विद्यालयों और पुनर्वास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी निभाता है ताकि वंचितों को सशक्त बनाया जा सके।

12. (B) राजस्थान में राज्य सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षण संवैधानिक रूप से 12 प्रतिशत तय किया गया है।
राजस्थान में राज्य सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए पृथक से 12 प्रतिशत का कोई संवैधानिक अथवा वैधानिक धर्म-आधारित आरक्षण प्रावधान नहीं है। भारत में धार्मिक आधार पर पृथक आरक्षण व्यवस्था असंवैधानिक मानी गई है। इसके स्थान पर राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक और सामाजिक विकास हेतु स्व-रोजगार ऋण, मदरसा आधुनिकरण तथा विभिन्न विशेष कल्याणकारी योजनाएं संचालित करती है।

13. (A) केवल I, II और III
राजस्थान की 'पालनहार योजना' अनाथ, वंचित और संवेदनशील श्रेणी के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शुरु की गई है। इसके अंतर्गत बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा हेतु प्रतिमाह नियमित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, न कि केवल 18 वर्ष पर एकमुश्त राशि। इस योजना में बच्चे को नियमित रूप से विद्यालय या आंगनवाड़ी भेजना अनिवार्य शर्त है ताकि उनकी शिक्षा बाधित न हो।

14. (C) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और बीपीएल परिवारों की बालिकाओं का विवाह
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' (पूर्व में हथलेवा योजना) का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय राहत पहुँचाना है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और बीपीएल परिवारों की बालिकाओं के विवाह के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बालिका की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जाती है।

15. (D) कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता करना
राजस्थान की 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रशासनिक व व्यावसायिक प्रवेश परीक्षाओं हेतु पात्र छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

16. (A) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
राजस्थान में जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) क्षेत्र राज्य के सभी जिलों में फैले होने के बजाय दक्षिण राजस्थान के विशिष्ट अनुसूचित जिलों और ब्लॉकों तक ही सीमित हैं। इन अधिसूचित टीएसपी क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास और रोजगार सुरक्षा हेतु सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जाता है। इसलिए टीएसपी का दायरा संपूर्ण राज्य में न होकर सीमित है।

17. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
'मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना' राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पहल है। समाज में ऐसी महिलाओं को अक्सर आर्थिक निर्भरता, सामाजिक उपेक्षा और तीव्र आजीविका संकट का सामना करना पड़ता है। अतः राज्य सरकार का यह हस्तक्षेप उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करता है।

18. (D) राष्ट्रीय महिला आयोग
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A) तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अनुच्छेद 338B) भारतीय संविधान के तहत सीधे स्थापित संवैधानिक निकाय हैं। इसके विपरीत राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत वर्ष 1992 में की गई थी। अतः इसकी प्रकृति अन्य तीनों निकायों से भिन्न है।

19. (B) केवल II
राजस्थान में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के तहत राज्य की लोक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 16 प्रतिशत तथा अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के लिए 5 प्रतिशत का कोटा निर्धारित है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का आरक्षण कोटा 12 प्रतिशत है, न कि 16 प्रतिशत। अतः यह कथन असत्य है।

NODIA

प्रावधान 77वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1995 द्वारा जोड़ा गया था ताकि सरकारी सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त बनाया जा सके।

66. (D) आय सृजन गतिविधियों के लिए ऋण, मार्जिन मनी और माइक्रोफाइनेंस प्रदान करके
राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम इन वर्गों के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने हेतु कार्य करता है। यह निगम मुख्य रूप से विभिन्न आय सृजन और स्वरोजगार गतिविधियों के लिए रियायती दरों पर ऋण, मार्जिन मनी सहायता तथा माइक्रोफाइनेंस उपलब्ध कराकर इस जनादेश को सफलता पूर्वक पूरा करता है।

67. (A) प्रचार-प्रसार के लिए ग्राम पंचायतों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वयं सहायता समूहों को लामबंद करना
दुर्बल ग्रामीण आबादी तक सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका स्थानीय संस्थागत ढाँचों का उपयोग करना है। इसके लिए ग्राम पंचायतों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं तथा स्वयं सहायता समूहों को लामबंद किया जाता है, क्योंकि ये ग्रामीण समाज से सीधे जुड़े होते हैं और योजनाओं की जानकारी सहजता से दे सकते हैं।

68. (C) यांत्रिक स्वच्छता उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी और ऋण प्रदान करना
'हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना' पूर्व में इस काम में लगे व्यक्तियों को गरिमापूर्ण आजीविका में पुनर्वासित करने हेतु संचालित है। इस योजना का एक मुख्य घटक स्वच्छता के काम के मशीनीकरण हेतु यांत्रिक स्वच्छता उपकरण व वाहन खरीदने के लिए पूंजीगत सब्सिडी और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है।

69. (C) 25 प्रतिशत
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जैसी योजना के अंतर्गत उन विशिष्ट ब्लॉकों या कस्बों को 'अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र' के रूप में चिन्हित किया जाता है जहाँ अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी कुल स्थानीय जनसंख्या का कम से कम 25 प्रतिशत या उससे अधिक होती है। इन क्षेत्रों में सामाजिक तथा शैक्षणिक बुनियादी ढाँचे का विकास सघनता से किया जाता है।

70. (D) आरक्षित श्रेणी के छात्रों को मुफ्त आवास, भोजन और शैक्षणिक सहायता प्रदान करना
राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित 'आश्रम छात्रावास' विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य आरक्षित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए स्थापित आवासीय संस्थान हैं। इन छात्रावासों का मुख्य उद्देश्य आरक्षित श्रेणियों के विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने हेतु पूर्णतः निःशुल्क आवास, भोजन तथा अनुकूल शैक्षणिक वातावरण एवं सहायता उपलब्ध कराना है।

71. (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1980 में सौंपी थी, जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने वर्ष 1990 में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 27% आरक्षण लागू किया। वहीं दूसरी ओर, अनारक्षित वर्ग के निर्धनों हेतु 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने वाला 103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2019 में लागू किया गया था। अतः दिए गए दोनों कथन पूरी तरह सही हैं।

72. (C) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग — 3 वर्ष
भारत के संविधान और संबंधित नियमों के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए तय किया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्यकाल भी 3 वर्ष ही होता है। अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का 3 वर्ष वाला युग्म सत्य है।

73. (D) मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना
दी गई कल्याणकारी योजनाओं में वृद्धजन पेंशन योजना, एकल नारी पेंशन योजना तथा विशेष योग्यजन पेंशन योजना तीनों सामाजिक सुरक्षा की नियमित पेंशन योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को मासिक निर्वाह भत्ता देना है। इसके विपरीत 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' एक शैक्षणिक योजना है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बनी है।

74. (A) आवंटी की सुरक्षा के लिए भूमि गैर-एससी/एसटी व्यक्तियों को अहस्तांतरणीय है
राजस्थान में जब भूमिहीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को कृषि भूमि आवंटित की जाती है, तो उनके शोषण और भूमि बेदखली को रोकने के लिए विशेष शर्त लागू होती है। इसके तहत ऐसी भूमि को किसी भी गैर-एससी/एसटी व्यक्ति को बेचना या हस्तांतरित करना कानूनन प्रतिबंधित और गैर-हस्तांतरणीय रखा गया है ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे।

75. (B) अनुसूचित जाति उप-योजना
अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु उनकी जनसंख्या के अनुपात में बजटीय संसाधनों का आवंटन सुनिश्चित करने की रणनीति को ऐतिहासिक रूप से 'विशेष घटक योजना' कहा जाता था। वर्तमान नियोजन शब्दावली में इस वित्तीय रणनीति का नया मानक नाम 'अनुसूचित जाति उप-योजना' कर दिया गया है ताकि विकास निधि का सीधा लाभ केवल इन वर्गों को मिल सके।

76. (B) 21
भारत सरकार द्वारा पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ने 1995 के पुराने कानून को प्रतिस्थापित किया। 1995 के अधिनियम में केवल 7 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया था, जिसे 2016 के नए कानून में बढ़ाकर 21 कर दिया गया। इसमें एसिड हमला पीड़ित, बौनापन और थैलेसीमिया जैसी अनेक नई स्थितियों को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई है।

Downloaded from www.pdf.tube

प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने से युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होती है और वे स्वरोजगार अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाते हैं।

31. (D) अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी)
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित 'देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना' मुख्य रूप से अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) की छात्राओं के शैक्षणिक विकास हेतु बनाई गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर निःशुल्क स्कूटी प्रदान कर उच्च शिक्षा हेतु निरंतर प्रोत्साहित करना है।

32. (A) केवल I और II
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित मामलों की जाँच करता है। किसी शिकायत की जाँच करते समय इसे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। हालाँकि, अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन का अधिकार केवल संसद के पास निहित है।

33. (B) ब्यूटी पार्लर स्थापित करने के लिए सीधी वित्तीय सहायता प्रदान करना
राजस्थान की 'आईएम शक्ति उड़ान योजना' राज्य की महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य तथा मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़ी एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसके तहत निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं तथा जागरुकता बढ़ाई जाती है ताकि विद्यालयों में बालिकाओं की ड्रॉपआउट दर कम हो सके। ब्यूटी पार्लर स्थापना हेतु आर्थिक सहायता देना इसका उद्देश्य नहीं है।

34. (A) I, III, II, IV
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के मामलों में मानक प्रक्रियात्मक क्रम सबसे पहले पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने से प्रारंभ होता है। इसके बाद डीएसपी स्तर के अधिकारी द्वारा जाँच पूरी की जाती है। तत्पश्चात विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाता है और अंत में न्यायालय अंतिम निर्णय एवं सजा सुनाता है।

35. (B) 2001
राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों, सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग को वैधानिक दर्जा देने हेतु राज्य विधानमंडल द्वारा 'राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001' पारित किया गया। यह निकाय अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण हेतु निरंतर कार्य करता है।

36. (C) P-2, Q-4, R-3, S-1
राजस्थान की शैक्षणिक योजनाओं के तहत पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 और 10 के आरक्षित वर्ग के छात्रों को सहायता प्रदान करती है। उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों हेतु है। 'डॉ. अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना' घर से दूर रहने वाले छात्रों को आवासीय भत्ता देती है। 'कालीबाई भील स्कूटी योजना' मेधावी छात्राओं को आवागमन सुविधा प्रदान करती है।

37. (A) अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार करने के दोषी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से दंडित करना
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना करता है, जो एक जाँच और परामर्शदात्री निकाय है। इस आयोग के पास जनजातीय अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की जाँच करने तथा सलाह देने की शक्ति है। हालाँकि, यह निकाय किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध हेतु न्यायिक सजा या दंड देने के लिए अधिकृत नहीं है।

NODIA

38. (B) केवल II, III और IV
राजस्थान की 'मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना' राज्य सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके तहत पात्र वृद्धजनों को नियमित पेंशन दी जाती है और 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पेंशन राशि में स्वतः वृद्धि होती है। सरकारी पेंशनभोगियों को यह लाभ नहीं मिलता तथा भुगतान सीधे डीबीटी माध्यम से बैंक खाते में ही किया जाता है।

39. (B) पात्र छात्रों के लिए आवासीय सुविधा और मासिक कमरा किराया भत्ता
राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई 'डॉ. अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना' का मुख्य उद्देश्य आरक्षित श्रेणियों के उन महाविद्यालयीन छात्रों को सहायता देना है जो शिक्षा हेतु घर से दूर शहरी क्षेत्रों में किराए पर रहते हैं। यह योजना ऐसे छात्रों को उनके आवास, भोजन और कमरा किराए के व्यय हेतु प्रतिमाह निश्चित वित्तीय भत्ता प्रदान करती है।

40. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
राजस्थान में जन आधार पहचान प्रणाली के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को लागू करने से छात्रवृत्ति और पेंशन लाभों में वित्तीय रिसाव में काफी कमी आई है। डीबीटी प्रणाली बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करके धनराशि को पात्र लाभार्थियों के आधार-लिंक बैंक खातों में सीधे और पारदर्शी तरीके से सुरक्षित रूप से हस्तांतरित करना सुनिश्चित करती है।

41. (D) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
'पीएम-दक्ष' योजना केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रमुख कौशल विकास योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जनजातियों तथा सफाई कर्मचारियों के पात्र युवाओं को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनकी रोजगार क्षमता एवं उद्यमशीलता में निरंतर वृद्धि करना है ताकि देश में सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके।

42. (A) राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद भारत के राष्ट्रपति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341(1) के अनुसार, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संबंधित राज्य के राज्यपाल से

परामर्श करने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति को अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जातियों की प्रारंभिक सूची जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसके बाद इस सूची में संशोधन का अधिकार केवल भारतीय संसद में ही निहित होता है।

43. (B) इसके पास घरेलू हिंसा के मामलों में अपराधियों को कारावास की सजा देने की कानूनी शक्ति है।
राजस्थान राज्य महिला आयोग एक वैधानिक संस्था है जिसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं, जिससे यह महिलाओं के अधिकारों के हनन और उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच कर सकती है। हालाँकि, इस आयोग के पास अपराधियों को सजा या जेल भेजने की कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। यह केवल अपनी सिफारिशें सक्षम अधिकारियों या सरकार को भेजता है।

44. (B) Scheme for Providing Quality Education in Madrasas
SPQEM का पूरा नाम 'स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसाज़' (मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना) है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य परंपरागत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में विज्ञान, गणित, भाषा और कंप्यूटर जैसे विषयों की पढ़ाई को बढ़ावा देना है ताकि छात्र औपचारिक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से सहजता से जुड़ सकें।

45. (B) केवल II
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालयों का प्राथमिक उद्देश्य इसके तहत दर्ज आपराधिक अत्याचार के मामलों की त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई करना है, न कि नागरिक संपत्ति विवादों का निपटारा करना। राज्य सरकार मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट करती है और सुनवाई शीघ्रता से पूरी की जाती है।

46. (A) 3 फीट 6 इंच
राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना' के तहत बौनेपन से ग्रस्त व्यक्तियों को विशेष योग्यजन श्रेणी में शामिल कर पेंशन दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु बौनेपन से पीड़ित वयस्क आवेदक की ऊँचाई सामान्यतः 3 फीट 6 इंच या उससे कम होना अनिवार्य मानदंड निर्धारित किया गया है।

47. (A) निदेशालय (राज्य) → जिला कार्यालय → ब्लॉक कार्यालय → पंचायत/शहरी वार्ड स्तर के कार्यकर्ता
राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की प्रशासनिक संरचना सर्वोच्च राज्य स्तर से धरातलीय स्तर तक सुव्यवस्थित पदानुक्रम का पालन करती है। इसमें शीर्ष स्तर पर राज्य स्तरीय निदेशालय कार्य करता है, जो नीतियों का निर्माण करता है। इसके नीचे जिला कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय और अंत में पंचायत तथा वार्ड स्तर के कार्यकर्ता योजनाओं के क्षेत्रीय कार्यान्वयन का दायित्व संभालते हैं।

48. (C) अनुसूचित जाति (एससी)
'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना' केंद्र प्रायोजित एक विशेष योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य उन गाँवों का सर्वांगीण विकास करना है जहाँ अनुसूचित जाति की आबादी कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक है। इस योजना के माध्यम से इन गाँवों में बुनियादी ढाँचे, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों जैसी आवश्यक सुविधाओं में व्यापक स्तर पर सुधार किया जाता है।

49. (B) P-2, Q-3, R-1, S-4
राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का विकास करता है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण की देखरेख करता है। विशेष योग्यजन निदेशालय दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायी है, जबकि राज्य महिला आयोग हिंसा और उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा तथा कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है।

50. (D) जटिल बहुस्तरीय सत्यापन और अनुमोदन प्रक्रियाएं
दुर्बल और संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति में होने वाले प्रशासनिक विलंब का मुख्य कारण बहुस्तरीय, जटिल और समय लेने वाली सत्यापन एवं अनुमोदन प्रक्रियाएं हैं। स्थानीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक अनेक स्तरों पर कागजी जाँच और प्रशासनिक अनुमतियों से होकर गुजरना पड़ता है। इस वजह से स्वीकृति मिलने में अत्यधिक विलंब हो जाता है।

51. (A) बारां
राजस्थान में सहरिया विकास परियोजना विशेष रूप से राज्य की भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह, सहरिया जनजाति के उत्थान हेतु संचालित केंद्रित कार्यक्रम है। यह परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में लागू की गई है जहाँ इस जनजाति की सघन आबादी स्थाई रूप से निवास करती है।

52. (A) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के संवैधानिक संरक्षण से जुड़े मामलों की निगरानी करता है। दूसरी तरफ राज्य महिला आयोग राष्ट्रीय आयोग के सीधे अधीनस्थ नहीं हैं, बल्कि वे राज्य के कानूनों द्वारा गठित स्वायत्त संस्थाएं हैं। राज्य आयोगों को महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों और उत्पीड़न के मामलों में स्वतः संज्ञान लेने की पूर्ण कानूनी शक्ति प्राप्त होती है।

53. (C) 2.50 लाख रुपये
राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्रता प्राप्त करने हेतु एक निर्धारित आय सीमा तय की गई है। इस योजना का लाभ लेने हेतु छात्र के माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका उद्देश्य गरीब छात्रों को संबल देना है।

Click Here to Buy book on Amazon

54. (D) प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक एससी या एसटी उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख से 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है।
'स्टैंड अप इंडिया' योजना का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना है। इसके तहत प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक एससी या एसटी तथा एक महिला उधारकर्ता को नया उद्यम लगाने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया जाता है।

55. (B) केवल I, III और IV
राजस्थान में अल्पसंख्यक कल्याण हेतु राज्य सरकार ने एक पृथक अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया है। राज्य में छह समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। अनुप्रति कोचिंग योजना में ये छात्र भी पात्र हैं। हालाँकि, अल्पसंख्यक वित्त निगम केवल कृषि तक सीमित न रहकर विभिन्न व्यावसायिक व स्वरोजगार गतिविधियों के लिए भी रियायती ऋण उपलब्ध कराता रहता है।

56. (C) कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंक
राजस्थान की 'कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना' राज्य की छात्राओं के शैक्षणिक उत्थान हेतु क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी का आवंटन मुख्य रूप से उनकी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत और मेरिट पर निर्भर करता है। इसके लिए कटऑफ अंक निर्धारित किए जाते हैं।

57. (D) प्लेसमेंट या स्वरोजगार सुनिश्चित करने वाला उद्योग-संबद्ध अल्पकालिक प्रशिक्षण
राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम राज्य के वंचित और दुर्बल वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल प्रशिक्षण चलाता है। इस पहल का मुख्य दृष्टिकोण युवाओं को उद्योग-संबद्ध, बाजार की मांग पर आधारित अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसका मुख्य ध्येय युवाओं को प्रत्यक्ष प्लेसमेंट दिलाना या स्वरोजगार हेतु पूरी तरह सक्षम बनाना है।

58. (A) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। इसी प्रकार, अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों हेतु सीटों के आरक्षण का जनादेश देता है। ये दोनों अनुच्छेद इन श्रेणियों का संसदीय व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं।

59. (C) 89वाँ संशोधन अधिनियम, 2003
पूर्व में संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक संयुक्त आयोग गठित था। भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2003 में पारित 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त आयोग को दो पृथक निकायों में विभाजित किया गया। इसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुच्छेद 338A द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पृथक रूप से अस्तित्व में आया।

60. (B) दोहरे (फ़र्ज़ी) लाभार्थियों को रोकने के लिए एकीकृत निवासी आईडी और डीबीटी प्लेटफॉर्म
राजस्थान में जन आधार कार्ड योजना राज्य सरकार के सामाजिक सुरक्षा ढांचे की रीढ़ है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य राज्य के प्रत्येक परिवार को एक एकीकृत निवासी पहचान संख्या प्रदान करना तथा डीबीटी मंच उपलब्ध कराना है। इससे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति तथा अन्य लाभों में फर्जी लाभार्थियों और मध्यस्थों को रोकने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

61. (A) बहाई
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर छह धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया है। इनमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय शामिल हैं। बहाई समुदाय को भारत में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है।

62. (C) पिछड़े वर्ग में शामिल करने के अनुरोधों की जाँच करना और सूची संबंधी शिकायतों की सुनवाई करना
राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एक सलाहकार निकाय है जिसकी प्राथमिक भूमिका राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची में नई जातियों को शामिल करने या हटाने के दावों की जाँच करना है। इसके साथ ही यह आयोग पिछड़े वर्गों की सूची से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करता है और अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को प्रेषित करता है।

63. (D) अस्पृश्यता का आचरण और उससे संबंधित निर्योग्यताओं को लागू करना
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए बनाया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य समाज में अस्पृश्यता का आचरण करने, किसी व्यक्ति को धार्मिक या सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश से रोकने और अस्पृश्यता जन्य अयोग्यताओं को लागू करने पर कठोर दंडात्मक प्रावधान सुनिश्चित करना है।

NODIA

64. (C) आरक्षित समूहों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए रिक्तियों को ट्रैक करना
सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीतियों को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए 'रोस्टर प्रणाली' एक आवश्यक प्रशासनिक तंत्र है। रोस्टर एक क्रमिक बिंदु रजिस्टर होता है जिसके माध्यम से किसी संवर्ग में आने वाली सीधी भर्ती या पदोन्नति की रिक्तियों में विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की निगरानी और सटीक रूप से ट्रैकिंग की जाती है।

65. (B) अनुच्छेद 16(4A) में
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4A) स्पष्ट रूप से राज्य को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण का प्रावधान कर सके। यह

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) अनुच्छेद 46
भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 46 राज्य को स्पष्ट निर्देश देता है कि वह जनता के दुर्बल वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करे। इसके अतिरिक्त यह प्रावधान राज्य को इन वर्गों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित करने का भी संवैधानिक दायित्व सौंपता है ताकि समाज में वास्तविक समानता और कल्याण स्थापित हो सके।

2. (D) अनुच्छेद 15(4) शैक्षणिक प्रगति सहित विशेष प्रावधानों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 16(4) विशेष रूप से राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण से संबंधित है।
संविधान का अनुच्छेद 15(4) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश सहित विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है। दूसरी ओर, अनुच्छेद 16(4) केवल राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न पाने वाले पिछड़े नागरिकों के लिए नौकरियों और पदों में आरक्षण से संबंधित है। पहला सामाजिक व शैक्षणिक विकास पर केंद्रित है, जबकि दूसरा लोक नियोजन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।

3. (C) केवल I और III
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का पूर्ण उन्मूलन करता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 38 राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने तथा आय की असमानताओं को कम करने का जनादेश देता है। दूसरी ओर, सार्वजनिक नियोजन में भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 16(2) के अंतर्गत आता है, जबकि अनुच्छेद 23 मानव व्यापार को रोकता है।

4. (C) अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए मौजूदा आरक्षण योजनाओं के तहत पहले से शामिल व्यक्ति
103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस कानून के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण का लाभ केवल उन नागरिकों को प्राप्त होता है जो पहले से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण प्रणालियों में शामिल नहीं हैं। इसका उद्देश्य अनारक्षित श्रेणी के गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करना है।

5. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
वर्ष 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ जजों की पीठ ने निर्णय दिया था कि सार्वजनिक रोजगार में कुल आरक्षण का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 16(4) केवल पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु एक विशिष्ट अपवाद प्रावधान है। अतः प्रशासनिक दक्षता और समता का संतुलन बनाए रखने हेतु यह सीमा तय की गई।

6. (D) अन्य पिछड़ा वर्ग
क्रीमी लेयर यानी उन्नत वर्ग का सिद्धांत मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण तंत्र पर लागू किया जाता है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों में से उन व्यक्तियों अथवा परिवारों को बाहर करना है जिन्होंने पर्याप्त सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्रगति हासिल कर ली है। इंदिरा साहनी निर्णय के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण में समानता और सामाजिक न्याय बनाए रखने के लिए आय और पद के आधार पर यह सीमा लागू की गई।

7. (B) कुल वार्षिक पारिवारिक आय और विशिष्ट संपत्ति स्वामित्व की सीमाएँ
राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का आरक्षित वर्गों में न होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त मुख्य पात्रता मानदंड परिवार की सभी स्रोतों से प्राप्त कुल वार्षिक आय और विशिष्ट परिसंपत्ति सीमाओं पर आधारित होता है। इसमें 8 लाख रुपये की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा के साथ कृषि भूमि तथा मकान संबंधी शर्तों का पालन आवश्यक है।

8. (A) I, IV, III, II
दुर्बल वर्गों हेतु संस्थागत सुधारों का कालानुक्रमिक क्रम काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन (1953) से शुरू होता है। इसके बाद मंडल आयोग (1979) नियुक्त हुआ। तत्पश्चात 89वें संविधान संशोधन अधिनियम (2003) द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोगों को पृथक किया गया। अंत में 103वें संशोधन (2019) द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण लागू किया गया।

9. (D) प्रशासन की कार्यकुशलता बनाए रखना
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि संघ या किसी राज्य के मामलों से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों पर विचार किया जाएगा। हालाँकि इस संवैधानिक प्रावधान में यह शर्त भी शामिल है कि ऐसे दावों पर विचार करते समय प्रशासन की

Downloaded from www.pdf.tube

77. (A) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी श्रेणियों से संबंधित छात्र
'पीएम-यशस्वी' योजना केंद्र सरकार की एक व्यापक छात्रवृत्ति योजना है। यह योजना मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) तथा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (डीएनटी) श्रेणियों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। इसके तहत पात्र छात्रों को उत्कृष्ट विद्यालयों में अध्ययन हेतु वित्तीय छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

78. (C) छह महीने से लेकर एक वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 4 में लोक सेवकों द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड का स्पष्ट कानूनी प्रावधान है। यदि कोई लोक सेवक (जो एससी या एसटी का न हो) अपने निर्धारित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करता है, तो उसे छह महीने से एक वर्ष तक की सजा दी जा सकती है।

79. (D) जनजातीय कार्य मंत्रालय
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। इन विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक व उच्च शिक्षा प्रदान करना है ताकि वे विकास की मुख्यधारा से जुड़कर सफलता प्राप्त कर सकें।

80. (C) वास्तविक समानता प्राप्त करना और कमजोर वर्गों को विकास की मुख्यधारा में एकीकृत करना
एक कल्याणकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरक्षण, सब्सिडी और सुरक्षात्मक कानूनों जैसे लक्षित उपायों का अंतिम ध्येय समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को सामाजिक व आर्थिक संबल प्रदान करना है। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य समाज में वास्तविक समानता प्राप्त करना तथा दुर्बल वर्गों को विकास की मुख्यधारा में एकीकृत कर उनका सर्वांगीण सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।

NODIA

अध्याय 25

कल्याणकारी योजनाएँ एवं विकास संस्थान

1. राजस्थान सरकार का कौन-सा विभाग मुख्य रूप से वृद्धजन एवं विधवा पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है?
   (A) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
   (B) महिला एवं बाल विकास विभाग
   (C) आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग
   (D) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

2. राजस्थान में एक प्रमुख कल्याणकारी पहल के रूप में शुरू की गई 'भामाशाह योजना' का मूल उद्देश्य क्या था?
   (A) ग्रामीण जिलों में लघु एवं सीमांत किसानों को रियायती कृषि बिजली और सौर पंप प्रदान करना
   (B) सभी ग्रामीण भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना और भूमि विवादों के समाधान के लिए एक स्वचालित ऑनलाइन तंत्र स्थापित करना
   (C) महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देते हुए वित्तीय समावेशन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सुनिश्चित करना
   (D) भारी औद्योगिक इकाइयों को विशेष रूप से जमानत-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण और कर छूट प्रदान करना

3. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   कथन I: इस योजना का उद्देश्य संबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में नकद-रहित (कैशलेस) इलाज की सुविधा प्रदान करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है।
   कथन II: राजस्थान के सभी निवासियों के लिए प्रीमियम पूरी तरह से निःशुल्क है, चाहे उनकी आर्थिक या व्यावसायिक श्रेणी कुछ भी हो।
   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (A) केवल कथन I सही है
   (B) केवल कथन II सही है
   (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
   (D) न तो कथन I और न ही कथन II सही है

4. सूची I की संस्थाओं को सूची II में दिए गए उनके प्राथमिक कार्यों से सुमेलित कीजिए।
   सूची I: (संस्था)
   P. राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी)
   Q. राजस्थान सहकारी डेयरी संघ (आरसीडीएफ)
   R. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका)
   S. रीको
   सूची II: (प्राथमिक कार्य)
   1. ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना
   2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना
   3. औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना और संबंधित अवसंरचना प्रदान करना
   4. ग्रामीण समितियों से दूध एकत्र करना और डेयरी उत्पादों का विपणन करना
   (A) P-2, Q-4, R-1, S-3
   (B) P-3, Q-1, R-4, S-2
   (C) P-2, Q-1, R-4, S-3
   (D) P-4, Q-2, R-1, S-3

5. ग्रामीण राजस्थान में सहकारिता आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?
   (A) राजस्थान में सहकारी बैंकिंग संरचना पूरी तरह से निजी व्यावसायिक बैंकों द्वारा नियंत्रित और वित्त पोषित है।
   (B) प्राथमिक कृषि साख समितियां (पैक्स) अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के लिए ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं।
   (C) सहकारी समितियां ऋण वितरित करने और बीज तथा उर्वरक जैसे कृषि आदानों की आपूर्ति करने की दोहरी भूमिका निभाती हैं।
   (D) सहकारिता आंदोलन का विस्तार कृषि से आगे बढ़कर डेयरी, आवास और उपभोक्ता वस्तुओं तक हो गया है।

6. औद्योगिक इकाइयों को संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के तहत राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
   (A) 1951
   (B) 1955
   (C) 1969
   (D) 1980

7. राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसीको) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   I. यह राज्य में कारीगरों और बुनकरों को विपणन सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
   II. यह अपने 'राजस्थली' एम्पोरियम के माध्यम से वैश्विक स्तर पर राजस्थानी हस्तशिल्प का विपणन करता है।
   III. यह राज्य में सभी बड़े पैमाने के भारी उद्योगों के पंजीकरण के लिए शीर्ष नियामक निकाय के रूप में कार्य करता है।
   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Click Here to Buy book on Flipkart

(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

8. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) आंदोलन ने ग्रामीण राजस्थान में गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
कारण (R): एसएचजी ग्रामीण महिलाओं के बीच औपचारिक साख तक आसान पहुँच प्रदान करते हैं तथा सामूहिक बचत एवं सूक्ष्म-उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

9. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यरत किसी स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का मूल कार्य सिद्धांत क्या है?
(A) निरंतर अनुदान वित्तपोषण और विदेशी गैर-सरकारी संगठनों से प्रत्यक्ष परिचालन प्रबंधन पर निर्भरता
(B) स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच सामूहिक बचत और आंतरिक ऋण लेनदेन
(C) निर्वाचित ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से सीधे केंद्र सरकार की सब्सिडी का अनिवार्य वितरण
(D) प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य के लिए स्वतंत्र रूप से एक बड़े पैमाने की वाणिज्यिक कंपनी को पंजीकृत करना और चलाना अनिवार्य होना

10. राजस्थान में संचालित कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण पैटर्न के संदर्भ में असंगत की पहचान कीजिए।
(A) पीएम-किसान सम्मान निधि
(B) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
(C) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
(D) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

11. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के चरम परिचालन चरण के दौरान, प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रदान किया जाने वाला बढ़ा हुआ अधिकतम स्वास्थ्य बीमा कवर कितना था?
(A) 5 लाख रुपये
(B) 10 लाख रुपये
(C) 15 लाख रुपये
(D) 25 लाख रुपये

12. राजस्थान में निम्नलिखित डिजिटल शासन और कल्याणकारी मंचों के प्रारंभिक शुभारंभ को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. भामाशाह योजना
2. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
3. जन आधार योजना
4. राजस्थान संपर्क पोर्टल
(A) 1, 4, 3, 2
(B) 1, 3, 4, 2
(C) 4, 1, 3, 2
(D) 3, 1, 4, 2

13. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह निराश्रित विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को नियमित मासिक पेंशन प्रदान करती है।
II. इस योजना के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है।
III. लाभार्थियों का बिना किसी अपवाद के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी से संबंधित होना अनिवार्य है।
IV. जैसे-जैसे लाभार्थी निर्दिष्ट आयु सीमाओं को पार करता है, पेंशन की राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

14. खंड स्तर (पंचायत समिति) पर राज्य की ग्रामीण कल्याण योजनाओं के मैदानी कार्यान्वयन की देखरेख के लिए उत्तरदायी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है?
(A) उप-खंड अधिकारी (एसडीओ)
(B) खंड विकास अधिकारी (बीडीओ)
(C) तहसीलदार
(D) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

15. निम्नलिखित में से कौन-सा डिजिटल पोर्टल मुख्य रूप से राजस्थान में नागरिकों की शिकायतों के निवारण या प्रत्यक्ष सार्वजनिक कल्याण वितरण के लिए अभिकल्पित नहीं किया गया है?
(A) राजकाज पोर्टल
(B) राजस्थान संपर्क
(C) जन सूचना पोर्टल
(D) ई-मित्र

16. राजस्थान सहकारी डेयरी संघ (आरसीडीएफ) ग्रामीण आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान देता है। साधारण दुग्ध संग्रह से इतर, इसके प्रभाव तंत्र का सबसे उपयुक्त वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा करता है?
(A) यह बड़े पैमाने पर निजी वाणिज्यिक डेयरी फार्म स्थापित करता है और संचालित करता है जो ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को सीधे रोजगार देते हैं।
(B) यह विदेशी मुद्रा भंडार उत्पन्न करने के लिए एकत्र

Downloaded from www.pdf.tube

बिना किसी समान राज्य वित्तीय योगदान के भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है?
(A) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
(B) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)
(C) पीएम-किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
(D) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)

67. मनरेगा या जलसम्भर (वॉटरशेड) विकास जैसी ग्रामीण कल्याणकारी योजनाओं के तहत निर्मित भौतिक बुनियादी ढाँचे की मजबूत निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा आमतौर पर कौन-सा तकनीकी हस्तक्षेप लागू किया जाता है?
(A) यादृच्छिक रूप से चुने गए शहरी निवासी पैनलों का मासिक टेलीफोनिक फीडबैक सर्वेक्षण आयोजित करना
(B) वेब डैशबोर्ड से जुड़े मोबाइल ऐप के माध्यम से निर्मित संपत्तियों की जियो-टैगिंग करना
(C) प्रत्येक पांच वित्तीय वर्षों में एक बार ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा कागजी साइट मानचित्रों का हस्तलिखित जमा कराया जाना
(D) ग्राम की भौतिक श्रम गतिविधियों की लगातार निगरानी के लिए निजी वाणिज्यिक ड्रोन ऑपरेटरों को काम पर रखना

68. "पालनहार योजना" राजस्थान सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है जो मुख्य रूप से किसको वित्तीय सहायता और सामाजिक-आर्थिक सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है:
(A) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निराश्रित वरिष्ठ नागरिक जो अस्सी वर्ष से अधिक आयु के हैं और जिनका कोई पारिवारिक सहारा नहीं है
(B) वाणिज्यिक बागवानी के लिए जलवायु-नियंत्रित पॉलीहाउस का निर्माण करने का इरादा रखने वाले लघु एवं सीमांत किसान
(C) जिलों में हथकरघा वस्त्रों और स्थानीय हस्तशिल्प के निर्माण में लगे पंजीकृत पारंपरिक कारीगर
(D) अनाथ और संवेदनशील बच्चों का पालन-पोषण करने वाले पालनहार (संरक्षक) या संस्थान

69. कल्याणकारी योजना के कार्यान्वयन में ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. अधिकारी ग्राम पंचायत के प्रशासनिक सचिव के रूप में कार्य करता है।
II. अधिकारी अभिलेखों के रखरखाव और ग्राम सभा की बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों को निष्पादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
III. अधिकारी के पास ग्राम के मानदंडों का उल्लंघन करने पर व्यक्तियों को सजा सुनाने का न्यायिक अधिकार होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

70. राजस्थान में गर्भवती महिलाओं को व्यापक रुप से ट्रैक करने, मातृ स्वास्थ्य की निगरानी करने और बच्चों के लिए अनुसूचित टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए किस विशिष्ट डिजिटल एप्लिकेशन/पोर्टल का उपयोग किया जाता है?
(A) राज-किसान साथी पोर्टल
(B) ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन नेटवर्क
(C) पीसीटीएस पोर्टल
(D) शाला दर्पण पोर्टल

71. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (आरजीएवीपी) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?
(A) यह भारी इंजीनियरिंग में कौशल विकास के लिए विशेष रूप से शहरी पुरुष युवाओं को लक्षित करता है।
(B) यह राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत है।
(C) राजस्थान के मुख्यमंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
(D) यह ग्रामीण राजस्थान में आजीविका परियोजनाओं को लागू करने के लिए छाता (अम्ब्रेला) संगठन के रूप में कार्य करता है।

72. प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के औपचारिक प्रभाव मूल्यांकन और परिणाम मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?
(A) वे वितरण तंत्र में बाधाओं और रिसाव की पहचान करने में मदद करते हैं।
(B) वे नीति संशोधन या बजट पुनरावंटन को सही ठहराने के लिए साक्ष्य-आधारित डेटा प्रदान करते हैं।
(C) वे मापते हैं कि क्या इच्छित सामाजिक-आर्थिक लाभ वास्तव में लक्षित जनसांख्यिकी तक पहुँचे हैं।
(D) वे केवल कनिष्ठ स्तर के क्षेत्रीय कर्मचारियों को दंडित करने और बर्खास्त करने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं।

73. राजस्थान राज्य महिला आयोग राज्य के कल्याणकारी ढाँचे में एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में कार्य करता है। इसका प्राथमिक समग्र कार्य क्या है?
(A) विशेष रूप से महिला उद्यमियों को रियायती व्यावसायिक ऋण प्रदान करने वाले एक वाणिज्यिक विकास बैंक के रूप में कार्य करना
(B) नीति पर सरकार को सलाह देना और महिलाओं के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की जाँच करना
(C) सरकारी अस्पतालों में ग्रामीण महिलाओं के लिए अनिवार्य नैदानिक स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा जांच का संचालन करना
(D) जनजातीय पट्टियों में विशेष रूप से बालिकाओं के लिए

NODIA

सभी संविदात्मक और अस्थायी कर्मचारी

24. राजस्थान में प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: पैक्स आमतौर पर किसानों को सीधे सेवा प्रदान करने के लिए ग्राम या ग्राम पंचायत स्तर पर काम करती हैं।
कथन II: इनका प्राथमिक जनादेश भारी कृषि मशीनरी और भूमि विकास की खरीद के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल कथन I सही है
(B) केवल कथन II सही है
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(D) न तो कथन I और न ही कथन II सही है

25. राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. शिल्पी योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
II. फ्लेक्सी लोन योजना कार्यरत उद्योगों के लिए कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण प्रदान करती है।
III. युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना विशेष रूप से युवा उद्यमियों को नई इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
IV. आरएफसी विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को गैर-पुनर्भुगतान योग्य धनराशि पूरी तरह से अनुदान में देता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, III और IV
(D) I, II, III और IV

26. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का ग्राम स्तर से जिला स्तर की ओर सही पदानुक्रमित क्रम दर्शाता है?
(A) जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत
(B) ग्राम सभा, जिला परिषद, पंचायत समिति
(C) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद
(D) पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद

27. मुख्यमंत्री राजश्री योजना का उद्देश्य बालिका के प्रति सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत लाभार्थी को ₹50,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह कुल राशि कितनी अलग-अलग किस्तों में वितरित की जाती है?
(A) 3 किस्तें
(B) 4 किस्तें
(C) 6 किस्तें
(D) 8 किस्तें

28. केंद्र और राज्य के विभिन्न प्रत्यक्ष नकद अंतरण कार्यक्रमों के बीच योजना के दोहराव (लाभार्थियों के ओवरलैप) की चुनौती को रोकने के लिए, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्य रूप से किस मास्टर जनसांख्यिकीय डेटाबेस का उपयोग किया जाता है?
(A) जन आधार डेटाबेस
(B) ई-मित्र रजिस्ट्री
(C) राज-नेट डायरेक्टरी
(D) राजस्थान संपर्क लॉग्स

29. कल्याणकारी योजना शासन के संदर्भ में, "योजना संतृप्ति" (स्कीम सैचुरेशन) की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है?
(A) किसी राज्य कल्याणकारी योजना के लिए निर्धारित सभी बजटीय वित्तीय आवंटन का पूरी तरह से समाप्त हो जाना
(B) लक्षित योजना जनसंख्या के भीतर सभी पात्र लाभार्थियों का पूर्ण कवरेज
(C) खराब प्रदर्शन करने वाली सरकारी योजना का औपचारिक विधायी समापन और प्रशासनिक बंद होना
(D) क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं पर अत्यधिक प्रशासनिक बोझ जिसके कारण पंचायतों में प्रणालीगत परिचालन में देरी होती है

30. राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) को लागू करने और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कौन-सी राज्य स्तरीय परिषद नोडल एजेंसी है?
(A) राजस्थान फाउंडेशन
(B) राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका)
(C) राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड
(D) राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी)

31. आजीविका संवर्धन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन की एक प्रमुख पहल 'राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना' (आरआरएलपी) को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था से प्रमुख वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी?
(A) विश्व बैंक
(B) एशियाई विकास बैंक (एडीबी)
(C) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)
(D) विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ)

32. राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत महिलाओं के लिए वृद्धजन पेंशन के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु क्या है?
(A) 50 वर्ष
(B) 55 वर्ष
(C) 58 वर्ष
(D) 60 वर्ष

Click Here to Buy book on Amazon

49. केंद्रीय और राज्य कल्याणकारी संरचनाओं के बीच समन्वय के संदर्भ में, "अभिसरण" (कनवर्जेंस) शब्द का सबसे सटीक अर्थ क्या है?
(A) राज्य-प्रायोजित सभी सामाजिक योजनाओं का केंद्रीय मंत्रालयों को पूर्ण प्रशासनिक हस्तांतरण और संरचनात्मक सुपुर्दगी
(B) प्रमाणित निजी अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा फर्मों के माध्यम से राज्य की सभी विकासात्मक योजनाओं का अनिवार्य वित्तीय लेखा परीक्षण
(C) लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य कल्याण विभागों को बंद करने की औपचारिक वैधानिक प्रक्रिया
(D) एकीकृत विकास लक्ष्यों के लिए योजनाओं में धन और अवसंरचना का संयोजन

50. राजस्थान जन आधार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह पूरे परिवार के लिए "एक संख्या, एक कार्ड, एक पहचान" की अवधारणा को अपनाती है।
II. यह एक एकीकृत नेटवर्क के माध्यम से नकद और गैर-नकद दोनों लाभों के वितरण की सुविधा प्रदान करती है।
III. यह सख्ती से अनिवार्य करती है कि परिवार के सबसे बुजुर्ग पुरुष सदस्य को ही परिवार का मुखिया नामित किया जाना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से गलत है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

51. राजस्थान मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 75 वर्ष और उससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं को प्रदान की जाने वाली मानक मासिक पेंशन राशि कितनी है (2024 के संशोधनों से पूर्व के मानक ऐतिहासिक स्लैब के अनुसार)?
(A) ₹500
(B) ₹750
(C) ₹1000
(D) ₹1500

52. जिला योजना समिति (डीपीसी) जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं को समेकित करती है। राजस्थान में पारंपरिक रूप से डीपीसी के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है?
(A) जिले के सांसद
(B) जिला कलेक्टर
(C) जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)
(D) जिला प्रमुख

53. राजस्थान में आरसीडीएफ के तहत डेयरी सहकारिता की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं।
कथन II: जिला-स्तरीय स्तर में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ शामिल होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल कथन I सही है
(B) केवल कथन II सही है
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(D) न तो कथन I और न ही कथन II सही है

54. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (आरजीएवीपी - राजीविका) का मुख्य रणनीतिक ध्यान केंद्रित है:
(A) दूरस्थ ग्रामीण इलाकों को शहरी केंद्रों से जोड़ने वाले बड़े मल्टी-लेन राजमार्गों और वाणिज्यिक परिवहन गलियारों का निर्माण करने पर
(B) सभी वयस्क ग्रामीण नागरिकों को मुफ्त स्मार्टफोन, उच्च गति वाले ब्रॉडबैंड कनेक्शन और डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करने पर
(C) गरीबी उन्मूलन और सतत आजीविका के लिए ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में लामबंद करने पर
(D) बड़े किसानों द्वारा उत्पादित अत्यधिक रियायती कच्चे कृषि जिंसों के सीधे अंतर्राष्ट्रीय निर्यात की सुविधा प्रदान करने पर

NODIA

55. निम्नलिखित में से कौन-सा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर मानक शिकायत निवारण तंत्र में घटनाओं के क्रम को सही ढंग से दर्शाता है?
(A) अधिकारी द्वारा समाधान → नागरिक प्रतिक्रिया → पंजीकरण → विभाग को आवंटन
(B) विभाग को आवंटन → पंजीकरण → अधिकारी द्वारा समाधान → नागरिक प्रतिक्रिया
(C) पंजीकरण → विभाग को आवंटन → अधिकारी द्वारा समाधान → नागरिक प्रतिक्रिया
(D) नागरिक प्रतिक्रिया → पंजीकरण → विभाग को आवंटन → अधिकारी द्वारा समाधान

56. केंद्रीय मौद्रिक नियामक के रूप में कार्य करने के बजाय सीधे दीर्घकालिक संरचनात्मक वित्त और कल्याण का समर्थन करने के उनके प्राथमिक कार्य के आधार पर निम्नलिखित वित्तीय संस्थानों में से असंगत की पहचान कीजिए।
(A) नाबार्ड
(B) सिडबी
(C) राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी)
(D) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

57. "सामाजिक अंकेक्षण" (सोशल ऑडिट) जनभागीदारी और पारदर्शिता पर बल देने वाला एक महत्वपूर्ण निगरानी तंत्र है। यह मुख्य रूप से किस प्रमुख रोजगार कल्याण योजना से जुड़ी एक कानूनी रूप से अनिवार्य आवश्यकता है?
(A) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)
(B) महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा)
(C) स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी)

पहचान करना
(B) राज्य के कोष से अंतिम प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृतियां जारी करना
(C) स्वास्थ्य और स्वच्छता योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना
(D) फॉरवर्ड और बैकवर्ड मार्केट लिंकेज स्थापित करने में स्वयं सहायता समूहों की सहायता करना

42. मानक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बैंक लिंकेज जीवनचक्र के निम्नलिखित चरणों को सही क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. आंतरिक ऋण देना और कोष का निर्माण
2. प्रारंभिक गठन और समूह गतिशीलता की स्थापना
3. बाह्य ऋण के लिए बैंक के साथ औपचारिक जुड़ाव (लिंकेज)
4. बाहरी/बैंक मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा एसएचजी की ग्रेडिंग

(A) 2, 1, 4, 3
(B) 2, 4, 1, 3
(C) 1, 2, 3, 4
(D) 4, 2, 1, 3

43. भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत 29 कार्यात्मक विषयों को, जिनमें कई ग्रामीण कल्याण योजनाएं और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शामिल हैं, पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है?
(A) नौवीं अनुसूची
(B) दसवीं अनुसूची
(C) बारहवीं अनुसूची
(D) ग्यारहवीं अनुसूची

44. ग्रामीण राजस्थान के एक बीपीएल परिवार को हृदय रोग के लिए तत्काल उन्नत शल्य चिकित्सा (सर्जरी) की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य तंत्र उन्हें इस विशेष चिकित्सा उपचार के लिए नकद-रहित कवरेज प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है?
(A) चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
(B) मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा सहायता योजना
(C) मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
(D) मुख्यमंत्री पालनहार सामाजिक सुरक्षा योजना

45. सूची I के ई-गवर्नेंस पोर्टलों को सूची II में दिए गए उनके विशिष्ट कार्यों से सुमेलित कीजिए।
सूची I: (ई-गवर्नेंस पोर्टल)
P. जन आधार
Q. जन सूचना
R. राज कौशल
S. शाला दर्पण
सूची II: (कार्य)
1. सरकारी विद्यालयों का वास्तविक समय का डेटा और निगरानी
2. श्रमिकों और नियोक्ताओं को जोड़ने वाला रोजगार विनिमय मंच
3. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहचान के लिए मास्टर डेटाबेस
4. सरकारी योजना की जानकारी का स्वतः प्रकटीकरण

(A) P-3, Q-4, R-2, S-1
(B) P-4, Q-3, R-1, S-2
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

46. राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?
(A) ये योजनाएं विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, जिनमें राज्य के कोष पर शून्य वित्तीय बोझ है।
(B) पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवेदन प्रक्रियाओं का अत्यधिक डिजिटलीकरण किया गया है।
(C) लाभार्थियों को प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन से गुजरना पड़ता है, जो अब बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से डिजिटल रूप से किया जा सकता है।
(D) बुजुर्गों, विधवाओं और विशेष योग्यजनों जैसे विभिन्न संवेदनशील समूहों के लिए विशेष पेंशन मौजूद हैं।

47. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) विशेष रूप से बड़े पैमाने के, भारी इंजीनियरिंग बहुराष्ट्रीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
कारण (R): आरएफसी की स्थापना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत की गई थी।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

48. राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करती है?
(A) सरकारी रियायती दरों पर उच्च उपज वाले बीज और रासायनिक उर्वरक खरीदने वाले लघु एवं सीमांत किसानों को
(B) अभिनव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्थापित करने के लिए बिना जमानत के सीड कैपिटल फंडिंग चाहने वाले शिक्षित ग्रामीण युवाओं को
(C) कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता का शिकार होने वाले कृषि श्रमिकों को
(D) गंभीर परिचालन ऋण चूक और वित्तीय संकट का सामना कर रही प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों को

Downloaded from www.pdf.tube

किए गए सभी दूध और दुग्ध उत्पादों का विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात करता है।
(C) यह ग्रामीण उत्पादकों को सीधी बाजार पहुँच, उचित मूल्य और पशु चिकित्सा सहायता प्रदान करके बिचौलियों को समाप्त करता है।
(D) यह दूध एकत्र किए बिना केवल संकर नस्ल के मवेशियों के लिए वाणिज्यिक ऋण वितरित करने तक ही अपने कार्यात्मक क्षेत्र को सीमित रखता है।

17. सूची I की कल्याणकारी योजनाओं को सूची II में दिए गए उनके प्राथमिक लक्षित जनसांख्यिकीय समूहों से सुमेलित कीजिए।
सूची I: (कल्याणकारी योजना)
P. पालनहार योजना
Q. मुख्यमंत्री राजश्री योजना
R. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
S. नवजीवन योजना
सूची II: (लक्षित जनसांख्यिकी)
1. अवैध शराब के कारोबार में लिप्त व्यक्ति जो वैकल्पिक आजीविका की तलाश में हैं
2. अनाथ बच्चे और विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चे
3. सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता वाले बुजुर्ग नागरिक
4. बालिकाएं, जिनके जन्म, स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देना है
(A) P-2, Q-4, R-3, S-1
(B) P-4, Q-2, R-1, S-3
(C) P-2, Q-1, R-3, S-4
(D) P-3, Q-4, R-2, S-1

18. राजस्थान संपर्क पोर्टल से संबंधित केंद्रीकृत टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है, जिस पर नागरिक सरकारी योजनाओं से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं?
(A) 104
(B) 108
(C) 181
(D) 1098

19. अंतिम छोर तक कल्याणकारी सेवाओं के वितरण में राज्य के साथ भागीदारी करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की सबसे सटीक भूमिका निम्नलिखित में से कौन-सी है?
(A) राज्य सरकार के विभागों को कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रशासनिक कार्यकारी आदेश और नीतिगत निर्देश सीधे जारी करना
(B) स्थानीय समुदायों को लामबंद करना, योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना और लक्षित लाभार्थियों की क्षमता का निर्माण करना
(C) सभी राज्य और केंद्रीय कोष वितरण गतिविधियों में निर्वाचित ग्राम पंचायत प्रशासन को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करना
(D) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की आधिकारिक रिपोर्टों का स्वतंत्र, कानूनी रूप से बाध्यकारी सांविधिक लेखा परीक्षा करना

20. कल्याणकारी योजनाओं और उनके प्राथमिक क्षेत्रों के निम्नलिखित संयोजनों पर विचार कीजिए:
I. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना - शिक्षा और युवा विकास
II. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना - शहरी रोजगार
III. मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना - एमएसएमई औद्योगिक सहायता
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से गलत है/हैं?
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) केवल III
(D) केवल I और III

21. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): ग्रामीण सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए वैध लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन करने में ग्राम सभाएं अत्यधिक सहायक होती हैं।
कारण (R): ग्राम सभाएं सांविधिक निकाय हैं जिनमें ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

22. राजस्थान सरकार द्वारा जनता को योजनाओं से संबंधित जानकारी स्वतः प्रदान करने के लिए 'जन सूचना पोर्टल' शुरु किया गया था। यह किस कानून की धारा 4(2) के जनादेश को पूरा करता है?
(A) राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011
(B) राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम, 2022
(C) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
(D) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

23. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, निम्नलिखित में से कौन-सी श्रेणी का परिवार 100% निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का हकदार नहीं है?
(A) किसी निर्दिष्ट संवेदनशील श्रेणी में न आने वाले करदाता परिवार
(B) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के प्रावधानों के तहत आधिकारिक रूप से चिह्नित और कवर किए गए परिवार
(C) ऐसे कृषि परिवार जिनकी भूमि भू-अभिलेखों में लघु एवं सीमांत किसान श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत है
(D) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में वर्तमान में कार्यरत

NODIA

(D) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)

58. राजस्थान के डिजिटल सेवा वितरण बुनियादी ढाँचे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. 'राजनेट' एक एकीकृत नेटवर्क है जो राज्य मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

II. ई-मित्र कियोस्क विशेष रूप से शहरी महानगरीय क्षेत्रों में संचालित होते हैं।

III. ई-मित्र प्लस मशीनें स्वयं-सेवा कियोस्क हैं जो स्वचालित नकद जमा और प्रमाण पत्रों की छपाई की अनुमति देती हैं।

IV. डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तंत्र का पुरजोर समर्थन करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, II और IV

59. सूची I की एमएसएमई/औद्योगिक योजनाओं को सूची II में दिए गए उनके प्रमुख उद्देश्यों से सुमेलित कीजिए।

सूची I: (योजना)

P. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
Q. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)
R. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना
S. पीएम विश्वकर्मा योजना

सूची II: (उद्देश्य)

1. पात्र शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना
2. एमएसएमई की स्थापना या विस्तार के लिए ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान करना
3. प्रशिक्षण और ऋण के साथ पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करना
4. बड़े पैमाने पर और क्षेत्र-विशिष्ट निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर छूट और सब्सिडी प्रदान करना

(A) P-2, Q-4, R-1, S-3
(B) P-4, Q-2, R-3, S-1
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

60. राजफेड (राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(A) यह पंचायत चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी प्राथमिक संवैधानिक निकाय है।
(B) यह राजस्थान में कृषि उपज के विपणन के लिए शीर्ष सहकारी संगठन के रूप में कार्य करता है।
(C) यह नोडल केंद्रीय एजेंसियों की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद की सुविधा प्रदान करता है।
(D) यह किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे कृषि आदानों की आपूर्ति करके सहायता करता है।

61. भामाशाह योजना संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: योजना के तहत, पारिवारिक बैंक खाता परिवार की महिला मुखिया के नाम पर खोलना अनिवार्य किया गया था।

कथन II: इस आवश्यकता के पीछे मूल तर्क महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना और घर के भीतर उनकी निर्णय लेने की भूमिका को बढ़ाना था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल कथन I सही है
(B) केवल कथन II सही है
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(D) न तो कथन I और न ही कथन II सही है

62. राजस्थान में जन स्वास्थ्य कल्याण के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करने वाली 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' आधिकारिक तौर पर किस तिथि को शुरु की गई थी?

(A) 26 जनवरी, 2020
(B) 1 मई, 2021
(C) 15 अगस्त, 2022
(D) 2 अक्टूबर, 2023

63. एमएसएमई इकाइयों की स्थापना या विस्तार के लिए राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) द्वारा आमतौर पर प्रदान की जाने वाली दीर्घकालिक वित्तीय ऋण सहायता की मानक ऊपरी सीमा क्या है?

(A) ₹1 करोड़ तक
(B) ₹5 करोड़ तक
(C) ₹20 करोड़ तक
(D) ₹100 करोड़ तक

64. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) राजस्थान में ग्रामीण विकास के पुनर्वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाबार्ड की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई थी?

(A) 1969
(B) 1975
(C) 1982
(D) 1991

65. सरकारी कल्याणकारी आंदोलनों की शब्दावली में, "अंत्योदय" की अवधारणा क्या दर्शाती है?

(A) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन को अधिकतम करना
(B) केवल शहरी आईटी पेशेवरों के कौशल को बढ़ाने पर केंद्रित नीति
(C) भूमि अभिलेखों का प्रशासनिक डिजिटलीकरण
(D) समाज के अंतिम व्यक्ति (सबसे गरीब) का उत्थान और विकास

66. निम्नलिखित कृषि कल्याणकारी योजनाओं में से कौन-सी पूरी तरह से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका अर्थ है कि यह

Click Here to Buy book on Flipkart

33. जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास तंत्र में उनके प्राथमिक परिचालन स्तर के आधार पर निम्नलिखित पदाधिकारियों में से असंगत की पहचान कीजिए।
(A) पटवारी
(B) ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ)
(C) सरपंच
(D) जिला कलेक्टर

34. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): जन आधार जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के कार्यान्वयन ने कल्याणकारी योजना वितरण में रिसाव को काफी हद तक कम कर दिया है।
कारण (R): डीबीटी तंत्र सीधे लाभार्थी के प्रमाणित बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित करके प्रशासनिक बिचौलियों को समाप्त करता है।
(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) अभिकथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

35. राजस्थान के डिजिटल कल्याण वितरण में व्यापक रूप से प्रयुक्त 'ई-मित्र' शब्द को सबसे सटीक रूप से किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है:
(A) एक राज्य-प्रायोजित डिजिटल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं को सामुदायिक खेलों के लिए जोड़ने के लिए अभिकल्पित किया गया है
(B) कियोस्क और ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से नागरिक सेवाएं प्रदान करने वाला एक एकीकृत ई-गवर्नेंस नेटवर्क
(C) वास्तविक समय में वर्षा के पैटर्न पर नज़र रखने के लिए समर्पित एक उपग्रह-आधारित मौसम संचार नेटवर्क
(D) दीर्घकालिक औद्योगिक ऋण वितरित करने के लिए अधिकृत राज्य के स्वामित्व वाली एक विशेष गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था

36. भामाशाह योजना से जन आधार योजना में हुए परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: जन आधार कार्ड परिवार को 10-अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करता है।
कथन II: भामाशाह के विपरीत, जन आधार लिंग-निरपेक्ष दस्तावेज़ीकरण को बढ़ावा देने के लिए परिवार के मुखिया के रूप में महिला की स्थिति को हटा देता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल कथन I सही है
(B) केवल कथन II सही है
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(D) न तो कथन I और न ही कथन II सही है

NODIA

37. राजस्थान में अल्पकालिक सहकारी साख संरचना के निम्नलिखित स्तरों पर विचार कीजिए:
I. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (शीर्ष बैंक)
II. केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी)
III. प्राथमिक कृषि साख समितियां (पैक्स)
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प क्रमशः राज्य स्तर से जिला स्तर और ग्राम स्तर तक इन संस्थाओं के क्रम का सही प्रतिनिधित्व करता है?
(A) I, II, III
(B) III, II, I
(C) II, I, III
(D) I, III, II

38. उत्कृष्ट पारंपरिक हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने और मान्यता देने के लिए राजस्थान में कौन-सी संस्था 'बुनकर पुरस्कार योजना' को लागू करने के लिए उत्तरदायी है?
(A) राजस्थान राज्य कृषि विपणन एवं विकास बोर्ड
(B) राजस्थान वित्त निगम (औद्योगिक अवसंरचना प्रभाग)
(C) उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय
(D) राजस्थान पर्यटन विकास निगम (हस्तशिल्प एवं विरासत विंग)

39. राजस्थान सहकारी डेयरी संघ (आरसीडीएफ) राज्य भर में किस लोकप्रिय ब्रांड नाम से अपने दूध और दुग्ध उत्पादों का प्रसंस्करण एवं विपणन करता है?
(A) सरस
(B) अमूल
(C) मदर डेयरी
(D) राज-दुग्ध

40. राजस्थान संपर्क पोर्टल की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह नागरिक शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है।
II. यह वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा शिकायतों के निवारण की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।
III. यह दीवानी विवादों के लिए न्यायिक अदालत प्रणाली को पूरी तरह से निरस्त और प्रतिस्थापित करता है।
IV. इसमें नागरिकों के लिए अपनी प्रस्तुत शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने का प्रावधान शामिल है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

41. गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में राजस्थान सरकार के साथ भागीदारी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा उनकी सामान्य अधिकृत भूमिकाओं का अपवाद है?
(A) बेसलाइन सर्वेक्षण करना और संवेदनशील समूहों की

प्राथमिक आवासीय विद्यालयों की सीधे स्थापना और प्रशासन करना

74. जिला परिषद स्तर पर, ग्रामीण विकास योजनाओं के व्यापक जिला-स्तरीय कार्यान्वयन का समन्वय करने वाले पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कौन कार्य करता है?
(A) जिला पंचायती राज संस्थाओं की अध्यक्षता करने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित जिला प्रमुख
(B) लोकसभा में जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थानीय सांसद
(C) राज्य द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (आईएएस/आरएएस)
(D) जिला जन स्वास्थ्य प्रशासन का निर्देशन करने वाले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ)

75. नोडल विभाग और उसकी संबंधित कल्याणकारी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित है?
(A) कृषि विभाग – मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
(B) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग – मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
(C) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग – मुख्यमंत्री राजश्री योजना
(D) महिला एवं बाल विकास विभाग – इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना

76. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य राजस्थान सहकारी डेयरी संघ (आरसीडीएफ) का मानक कार्यात्मक क्षेत्र नहीं है?
(A) विदेशी आयातित डेयरी मशीनों की सीधी खुदरा बिक्री
(B) संतुलित पशु आहार की आपूर्ति
(C) डेयरी किसानों को कृत्रिम गर्भाधान और पशु चिकित्सा सेवाओं का प्रावधान
(D) पाश्चुरीकृत दूध और दुग्ध उत्पादों का विपणन

77. किसी सहकारी समिति के मूलभूत सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: सहकारी समितियाँ "एक अंश, एक मत" के सिद्धांत पर काम करती हैं, जिससे वे सबसे अमीर सदस्यों के वर्चस्व में आ जाती हैं।
कथन II: वे योगदान की गई पूंजी की परवाह किए बिना "एक सदस्य, एक मत" के लोकतांत्रिक सिद्धांत पर काम करती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल कथन I सही है
(B) केवल कथन II सही है
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(D) न तो कथन I और न ही कथन II सही है

78. कौन-सा राज्य-स्तरीय संस्थागत निकाय राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश की सुविधा के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है?
(A) राजफेड (शीर्ष विपणन संघ)
(B) रीको
(C) राजसीको (लघु उद्योग निगम)
(D) आरएसएलडीसी (आजीविका विकास निगम)

79. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (पूर्व में सहयोग एवं उपहार योजना) मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जीवन घटना के लिए संरचित वित्तीय सहायता प्रदान करती है?
(A) बीपीएल, अंत्योदय और वंचित परिवारों की लड़कियों का विवाह
(B) उच्च तकनीकी या स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय डिग्री कार्यक्रमों में बालिका का नामांकन
(C) महिला उद्यमी द्वारा एक नए एमएसएमई सूक्ष्म-उद्यम स्टार्टअप की शुरुआत के लिए इक्विटी फंडिंग
(D) जटिल प्रसव प्रसूति से संबंधित चिकित्सा और शल्य चिकित्सा खर्चों के लिए पूर्ण वित्तीय प्रतिपूर्ति

80. शासन और कल्याण वितरण में जवाबदेही लागू करने के उद्देश्य से 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम' किस वर्ष अधिनियमित किया गया था?
(A) 2005
(B) 2011
(C) 2014
(D) 2019

www.nodia.in

NODIA

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (D) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण की मुख्य जिम्मेदारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की है। यह विभाग राज्य के वृद्धजनों, विधवाओं, परित्यक्ताओं और विशेष योग्यजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले कार्यक्रमों का प्रबंधन करता है। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों का सशक्तिकरण करना तथा उन्हें जीवन यापन के लिए नियमित आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

2. (C) महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देते हुए वित्तीय समावेशन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सुनिश्चित करना
भामाशाह योजना राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2014 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल थी। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और सरकारी योजनाओं के लाभों को सीधे पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों तक पहुँचाना था। इस योजना की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें परिवार की महिला को मुखिया मानकर बैंक खाता खोला जाता था, जिससे महिला सशक्तिकरण को अभूतपूर्व प्रोत्साहन प्राप्त हुआ।

3. (A) केवल कथन I सही है
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जिसके तहत संबद्ध अस्पतालों में नकद-रहित इलाज की सुविधा मिलती है। हालांकि, यह योजना सभी निवासियों के लिए निःशुल्क नहीं है। केवल संवेदनशील श्रेणियों के परिवारों का प्रीमियम सरकार वहन करती है, जबकि करदाता या गैर-पात्र श्रेणियों को योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना अनिवार्य होता है।

4. (A) P-2, Q-4, R-1, S-3
राजस्थान में विभिन्न संस्थाएं अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करती हैं। राजस्थान वित्त निगम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ ग्रामीण समितियों से दूध एकत्र कर डेयरी उत्पादों का विपणन करता है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देती है, तथा रीको औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं अवसंरचना निर्माण का कार्य करता है।

5. (A) राजस्थान में सहकारी बैंकिंग संरचना पूरी तरह से निजी व्यावसायिक बैंकों द्वारा नियंत्रित और वित्त पोषित है।
ग्रामीण राजस्थान में सहकारिता आंदोलन लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है और यह निजी व्यावसायिक बैंकों द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। राज्य में सहकारी बैंकिंग संरचना एक त्रिस्तरीय प्रणाली के तहत काम करती है, जिसमें शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियां शामिल हैं। ये संस्थाएं राज्य सरकार तथा नाबार्ड के सहयोग एवं दिशा-निर्देशों के तहत संचालित होती हैं।

6. (B) 1955
राजस्थान वित्त निगम की स्थापना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत 17 जनवरी 1955 को की गई थी। इस संस्था का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण हेतु दीर्घकालिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह निगम विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विभिन्न ऋण योजनाओं के माध्यम से वित्तीय संबल प्रदान करता है।

7. (A) केवल I और II
राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसीको) की स्थापना राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा पारंपरिक कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह निगम कारीगरों और बुनकरों को विपणन सहायता प्रदान करता है और 'राजस्थली' एम्पोरियम के माध्यम से हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री एवं प्रचार-प्रसार करता है। हालांकि, यह बड़े पैमाने के भारी उद्योगों के पंजीकरण या नियंत्रण के लिए नियामक निकाय के रूप में कार्य नहीं करता है।

8. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
स्वयं सहायता समूह आंदोलन ने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये समूह ग्रामीण महिलाओं को एक मंच प्रदान करते हैं जहाँ वे छोटी-छोटी बचत करके आपस में कम ब्याज पर ऋण का लेन-देन कर सकती हैं। इससे बैंक साख तक उनकी पहुँच आसान होती है तथा सूक्ष्म-उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है, जिससे उनकी आय और सामाजिक स्थिति में सुधार होता है।

9. (B) स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच सामूहिक बचत और आंतरिक ऋण लेनदेन
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों का मूलभूत कार्य सिद्धांत स्वावलंबन और पारस्परिक सहयोग पर आधारित है। ये समूह अपनी सदस्यों के बीच नियमित सामूहिक बचत को बढ़ावा देते हैं और एकत्रित कोष से सदस्यों की आकस्मिक या व्यावसायिक जरूरतों के लिए आंतरिक ऋण लेनदेन करते हैं। यह प्रक्रिया सदस्यों को

Downloaded from www.pdf.tube

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs, you are wasting valuable time.

Research shows that learning from **PRINTED BOOKS** has up to **4× HIGHER RETENTION** than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS** move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND** in competition.

In competitive exams, being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

साहूकारों के जाल से बचाती है तथा उनमें वित्तीय अनुशासन और सूक्ष्म-उद्यमिता की भावना विकसित करती है।

10. (C) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पूरी तरह से राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित राज्य क्षेत्र की एक कल्याणकारी योजना है। इसके विपरीत, पीएम-किसान सम्मान निधि पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना केंद्र और राज्य सरकार के साझा वित्तीय योगदान से संचालित होने वाली केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। इस प्रकार वित्तपोषण पैटर्न में भिन्नता पाई जाती है।

11. (D) 25 लाख रुपये
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना थी। इसके क्रियान्वयन के प्रारंभिक चरण में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाता था, जिसे बाद में बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया। योजना के चरम परिचालन चरण में राज्य सरकार द्वारा इस कवरेज राशि को और अधिक बढ़ाते हुए प्रति परिवार प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपये तक कर दिया गया था।

12. (A) 1, 4, 3, 2
राजस्थान में डिजिटल शासन एवं कल्याणकारी पहल योजनाओं के शुभारंभ कालानुक्रमिक क्रम पर आधारित हैं। भामाशाह योजना को वर्ष 2014 में वित्तीय समावेशन हेतु शुरु किया गया था। नागरिकों की शिकायतों के ऑनलाइन निवारण के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल का विकास किया गया। इसके पश्चात् वर्ष 2019 में जन आधार योजना लागू की गई, और अंत में मई 2021 में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ हुआ।

13. (B) केवल I, II और IV
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना राजस्थान की निराश्रित विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें आवेदन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और आयु बढ़ने के साथ पेंशन राशि में वृद्धि होती है। हालांकि, इस योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए केवल बीपीएल श्रेणी का होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि निर्धारित वार्षिक आय सीमा के भीतर आने वाली महिलाएं भी पात्र होती हैं।

14. (B) खंड विकास अधिकारी (बीडीओ)
पंचायत समिति या खंड स्तर पर ग्रामीण विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रशासनिक निष्पादन एवं पर्यवेक्षण की मुख्य जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी की होती है। यह अधिकारी ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। खंड विकास अधिकारी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित ग्रामीण योजनाओं का मैदानी स्तर पर समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है तथा ग्राम पंचायतों की गतिविधियों का समन्वय करता है।

15. (A) राजकाज पोर्टल
राजकाज पोर्टल मुख्य रूप से राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के आंतरिक प्रशासनिक कार्यों, अवकाश प्रबंधन, कार्य-मूल्यांकन रिपोर्ट और कार्यालयी पत्राचार का प्रबंधन करने के लिए विकसित किया गया एक ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म है। यह पोर्टल प्रत्यक्ष रूप से आम नागरिकों की शिकायतों के निवारण या जन-कल्याणकारी सेवाओं के वितरण के लिए अभिकल्पित नहीं किया गया है। नागरिकों के लिए राजस्थान संपर्क, जन सूचना पोर्टल और ई-मित्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

16. (C) यह ग्रामीण उत्पादकों को सीधी बाजार पहुँच, उचित मूल्य और पशु चिकित्सा सहायता प्रदान करके बिचौलियों को समाप्त करता है।
राजस्थान सहकारी डेयरी संघ ग्रामीण आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह त्रिस्तरीय सहकारी ढांचे के माध्यम से गांव स्तर पर दुग्ध उत्पादकों को संगठित करता है। यह ढांचा बिचौलियों के शोषण को समाप्त कर पशुपालकों को उनके दूध का पारदर्शी एवं उचित मूल्य दिलाता है। इसके अतिरिक्त, संघ ग्रामीण क्षेत्रों में नस्ल सुधार, पशु आहार आपूर्ति और समय पर पशु चिकित्सा सहायता जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं भी निरंतर प्रदान करता है।

17. (A) P-2, Q-4, R-3, S-1
पालनहार योजना अनाथ और विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना बालिकाओं के जन्म, स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देती है। नवजीवन योजना का उद्देश्य हथकढ़ शराब के निर्माण व व्यापार में लिप्त व्यक्तियों का पुनर्वास कर उन्हें आजीविका के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराना है।

NODIA

18. (C) 181
राजस्थान में नागरिकों की सरकारी सेवाओं और योजनाओं से संबंधित शिकायतों के त्वरित एवं पारदर्शी निवारण के लिए 'राजस्थान संपर्क' नामक केंद्रीकृत पोर्टल संचालित है। इस प्रणाली के तहत एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 181 कार्यरत है। नागरिक इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्याएं पंजीकृत करा सकते हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा दर्ज की गई शिकायत के समाधान की स्थिति को आसानी से ट्रैक भी कर सकते हैं।

19. (B) स्थानीय समुदायों को लामबंद करना, योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना और लक्षित लाभार्थियों की क्षमता का निर्माण करना
कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में गैर-सरकारी संगठन सरकार और समाज के बीच एक सेतु का काम करते हैं। इनका मुख्य कार्य ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को लामबंद करना, विभिन्न योजनाओं के लाभों के

60. (A) यह पंचायत चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी प्राथमिक संवैधानिक निकाय है।
राजफेड (राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ) राज्य में कृषि उपज के विपणन की शीर्ष सहकारी संस्था है। इसका मुख्य कार्य किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज की सरकारी खरीद करना और किसानों को खाद, बीज तथा कीटनाशक उपलब्ध कराना है। पंचायत चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का संवैधानिक कार्य है, इसमें राजफेड की कोई भूमिका नहीं होती है।

61. (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
भामाशाह योजना राजस्थान सरकार की एक ऐतिहासिक पहल थी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए पारिवारिक बैंक खाता परिवार की महिला मुखिया के नाम पर खोलना अनिवार्य किया गया था। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय रुप से आत्मनिर्भर बनाना, उनके नाम से बैंक खाते खोलकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना तथा पारिवारिक निर्णयों में उनकी भूमिका और सामाजिक स्थिति को अधिक मजबूत करना था।

62. (B) 1 मई, 2021
राजस्थान में आम जनता को बीमारियों के महंगे इलाज से सुरक्षा देने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' शुरु की गई थी। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 1 मई, 2021 को किया गया था। योजना के तहत पात्र परिवारों को संबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में नकद-रहित (कैशलेस) इलाज की सुविधा प्रदान की गई, जो राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम था।

63. (C) ₹20 करोड़ तक
राजस्थान वित्त निगम राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सावधि ऋण सहायता प्रदान करता है। निगम द्वारा नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण, विस्तार और विविधीकरण हेतु ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। पात्र एमएसएमई इकाइयों को आरएफसी द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय साख की मानक ऊपरी सीमा वर्तमान में ₹20 करोड़ तक निर्धारित की गई है।

64. (C) 1982
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए साख व्यवस्था को विनियमित और पुनर्वित्तपोषित करने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड की औपचारिक स्थापना बी. शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। यह बैंक राजस्थान सहित पूरे देश में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण, सहकारी बैंकों के सुदृढ़ीकरण और ग्रामीण आजीविका पहलों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

65. (D) समाज के अंतिम व्यक्ति (सबसे गरीब) का उत्थान और विकास
कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं के संदर्भ में "अंत्योदय" का शाब्दिक एवं वैचारिक अर्थ "पंत के अंतिम व्यक्ति का उदय" है। यह अवधारणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे निचले पायदान पर स्थित निर्धन, वंचित और असहाय व्यक्ति तक सरकारी विकास योजनाओं के लाभ पहुँचाना है। अंत्योदय का मूल लक्ष्य सबसे गरीब व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना है।

66. (C) पीएम-किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
पीएम-किसान सम्मान निधि पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता 100% केंद्रीय वित्तपोषण के साथ प्रदान की जाती है, जिसमें राज्यों का कोई वित्तीय अंशदान नहीं होता। इसके विपरीत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों वित्तीय योगदान देते हैं।

67. (B) वेब डैशबोर्ड से जुड़े मोबाइल ऐप के माध्यम से निर्मित संपत्तियों की जियो-टैगिंग करना
मनरेगा और जलसम्भर विकास जैसी ग्रामीण योजनाओं में निर्मित परिसंपत्तियों की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसके तहत भुवन ऐप या मोबाइल अनुप्रयोगों के माध्यम से निर्मित भौतिक बुनियादी ढांचे की जियो-टैगिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में जीपीएस निर्देशांकों और तस्वीरों को केंद्रीय वेब डैशबोर्ड से जोड़ दिया जाता है, जिससे परिसंपत्तियों की वास्तविक स्थिति की निगरानी पारदर्शी तरीके से की जा सके।

68. (D) अनाथ और संवेदनशील बच्चों का पालन-पोषण करने वाले पालनहार (संरक्षक) या संस्थान
पालनहार योजना राजस्थान सरकार की एक अत्यंत संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों, विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चों या जेल भुगत रहे माता-पिता के बच्चों को संस्थागत देखरेख के बजाय पारिवारिक माहौल में पालने की सुविधा देना है। इसमें बच्चों का पालन-पोषण करने वाले रिश्तेदारों या संरक्षकों (पालनहार) को बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल हेतु प्रति माह नियमित वित्तीय सहायता दी जाती है।

69. (A) केवल I और II
ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक सचिव के रुप में कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य पंचायत के रिकॉर्ड बनाए रखना, ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन करना और पंचायती राज प्रस्तावों तथा विकास योजनाओं को निष्पादित करना है। हालांकि, ग्राम विकास अधिकारी के पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं होती है और वह किसी नागरिक को किसी उल्लंघन या अपराध के लिए सजा सुनाने का अधिकार नहीं रखता है।

Click Here to Buy book on Amazon

अवधारणा शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने और सामाजिक न्याय को अंतिम छोर तक पहुँचाने के प्रशासनिक लक्ष्य को दर्शाती है।

30. (B) राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका)
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के अधीन स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। यह परिषद राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। राजीविका का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना, उनकी क्षमताओं का विकास करना और उन्हें स्थायी आजीविका के अवसरों से जोड़कर गरीबी उन्मूलन सुनिश्चित करना है।

31. (A) विश्व बैंक
'राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना' राज्य में गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण परिवारों के आजीविका संवर्धन हेतु शुरु की गई एक महत्वपूर्ण पहल थी। इस व्यापक परियोजना को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने में 'विश्व बैंक' ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित कर उन्हें विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और सूक्ष्म उद्यमों से जोड़ा गया।

32. (B) 55 वर्ष
राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना राज्य के बुजुर्ग निवासियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जाती है। इस योजना के तहत महिलाओं और पुरुषों के लिए न्यूनतम पात्र आयु सीमा अलग-अलग निर्धारित की गई है। योजना के नियमों के अनुसार, वृद्धजन पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए, जबकि पुरुषों के लिए यह न्यूनतम आयु सीमा 58 वर्ष रखी गई है।

33. (D) जिला कलेक्टर
जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास की संरचना में प्राथमिक परिचालन स्तर का अंतर पाया जाता है। पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच सीधे ग्राम स्तर या पंचायत स्तर पर कार्य करते हैं और ग्रामीण आबादी से सीधा संपर्क बनाए रखते हैं। इसके विपरीत, जिला कलेक्टर संपूर्ण जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख होता है, जिसका कार्यक्षेत्र जिला स्तर पर वृहद नीतिगत समन्वय, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण तक विस्तृत होता है।

34. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
जन आधार जैसे आधुनिक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के क्रियान्वयन ने कल्याणकारी योजनाओं की वितरण प्रणाली को अत्यधिक पारदर्शी और कुशल बनाया है। डीबीटी प्रणाली बिचौलियों और प्रशासनिक मध्यस्थों को पूरी तरह समाप्त कर देती है। इसमें सरकारी सब्सिडी और वित्तीय लाभ सीधे लाभार्थी के आधार-संबद्ध प्रमाणित बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं, जिससे रिसाव, देरी और फर्जीवाड़े की संभावना न्यूनतम हो जाती है।

35. (B) कियोस्क और ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से नागरिक सेवाएं प्रदान करने वाला एक एकीकृत ई-गवर्नेंस नेटवर्क
'ई-मित्र' राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी ई-गवर्नेंस पहल है जो पीपीपी मॉडल पर आधारित है। इसे राज्य के नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभागों और निजी संस्थाओं की सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है। ई-मित्र कियोस्क और ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से बिल भुगतान, प्रमाण पत्र जारी करने, और कल्याणकारी योजनाओं में आवेदन करने जैसी सैकड़ों नागरिक-केंद्रित सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराई जाती हैं।

36. (A) केवल कथन I सही है
भामाशाह योजना के स्थान पर शुरु की गई जन आधार योजना के तहत प्रत्येक नामांकित परिवार को एक 10-अंकीय पहचान संख्या तथा परिवार के सदस्यों को 11-अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या दी जाती है। भामाशाह योजना की ही भांति, जन आधार योजना में भी महिला सशक्तिकरण के सिद्धांत को बनाए रखा गया है, जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को ही परिवार का मुखिया माना जाता है।

37. (A) I, II, III
राजस्थान में किसानों की कृषि आवश्यकताओं के लिए अल्पकालिक सहकारी साख संरचना का ढांचा त्रिस्तरीय है। राज्य स्तर पर शीर्ष संस्था के रूप में 'राजस्थान राज्य सहकारी बैंक' कार्य करता है। मध्यवर्ती यानी जिला स्तर पर 'केंद्रीय सहकारी बैंक' अपनी शाखाओं के माध्यम से सेवाएं देते हैं। सबसे निचले यानी ग्राम स्तर पर 'प्राथमिक कृषि साख समितियां' सीधे किसानों को अल्पकालिक ऋण और कृषि आदान उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं।

38. (C) उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय
राजस्थान में पारंपरिक हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने तथा उत्कृष्ट कारीगरों की कला को मान्यता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'बुनकर पुरस्कार योजना' चलाई जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन और प्रशासनिक संचालन उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के माध्यम से राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर श्रेष्ठ बुनकरों को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित किया जाता है।

39. (A) सरस
राजस्थान सहकारी डेयरी संघ (आरसीडीएफ) राज्य में डेयरी विकास और दुग्ध उत्पादकों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली शीर्ष संस्था है। यह संघ राज्य भर में फैले अपने जिला दुग्ध संघों के माध्यम से दूध का एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और वितरण करता है। आरसीडीएफ अपने पाश्चुरीकृत दूध, घी, छाछ, पनीर और अन्य दुग्ध उत्पादों का प्रसंस्करण एवं विपणन 'सरस' नामक सुप्रसिद्ध ब्रांड नाम से करता है।

NODIA

40. (B) केवल I, II और IV
राजस्थान संपर्क पोर्टल राज्य का एक एकीकृत नागरिक शिकायत निवारण मंच है। यह नागरिकों को विभिन्न विभागों से संबंधित अपनी शिकायतें ऑनलाइन या 181 नंबर पर दर्ज करने, उनकी स्थिति ट्रैक करने और समाधान पर प्रतिक्रिया देने की सुविधा देता है। उच्च प्रशासनिक अधिकारी भी इस पोर्टल से निवारण की निगरानी करते हैं। हालांकि, यह पोर्टल किसी भी प्रकार से न्यायिक अदालत प्रणाली या दीवानी न्यायालयों का विकल्प नहीं है।

41. (B) राज्य के कोष से अंतिम प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृतियां जारी करना
राजस्थान में गैर-सरकारी संगठन विभिन्न सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं में सरकार के रणनीतिक भागीदार के रूप में कार्य करते हैं। वे जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण करने, योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने, जागरूकता बढ़ाने और स्वयं सहायता समूहों की सहायता करने का कार्य करते हैं। हालांकि, राज्य के सार्वजनिक कोष से वित्तीय स्वीकृतियां जारी करना या बजट आवंटित करना केवल सक्षम सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों का सांविधिक अधिकार है, जिसमें एनजीओ की कोई भूमिका नहीं होती।

42. (A) 2, 1, 4, 3
स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बैंक लिंकेज प्रक्रिया एक व्यवस्थित क्रमिक जीवनचक्र का पालन करती है। सबसे पहले ग्रामीण महिलाओं को एकत्र करके समूह का गठन और प्रारंभिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके बाद सदस्य नियमित रुप से बचत करके आंतरिक ऋण देना शुरु करते हैं। कुछ समय बाद बैंकों या बाहरी एजेंसियों द्वारा समूह के कामकाज और वित्तीय अनुशासन की ग्रेडिंग की जाती है, और अंततः बैंक लिंकेज के तहत ऋण स्वीकृत किया जाता है।

43. (D) ग्यारहवीं अनुसूची
भारतीय संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इस अनुसूची में कुल 29 कार्यात्मक विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। इन विषयों में कृषि, ग्रामीण विकास, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और गरीबी उन्मूलन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं, जिन्हें प्रशासनिक और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकारों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है।

44. (A) चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
राजस्थान में ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों के निवासियों को गंभीर बीमारियों के लिए नकद-रहित (कैशलेस) चिकित्सा उपचार प्रदान करने हेतु चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई थी। यदि किसी निर्धन या बीपीएल परिवार के सदस्य को हृदय रोग जैसी गंभीर स्थिति के लिए उन्नत शल्य चिकित्सा (सर्जरी) की आवश्यकता होती है, तो यह योजना संबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की नकद-रहित स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है।

45. (A) P-3, Q-4, R-2, S-1
राजस्थान के ई-गवर्नेंस पोर्टल विशिष्ट कार्य करते हैं। जन आधार योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हेतु परिवारों का मास्टर डेटाबेस प्रदान करती है। जन सूचना पोर्टल सरकारी योजनाओं की जानकारी का स्वतः प्रकटीकरण सुनिश्चित करता है। राज कौशल पोर्टल बेरोजगार श्रमिकों और नियोक्ताओं को मिलाने वाले रोजगार मंच के रूप में कार्य करता है, जबकि शाला दर्पण पोर्टल राज्य के सरकारी विद्यालयों के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक डेटा की वास्तविक समय में निगरानी करता है।

46. (A) ये योजनाएं विशेष रुप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, जिनमें राज्य के कोष पर शून्य वित्तीय बोझ है।
राजस्थान में संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित नहीं हैं। यद्यपि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत कुछ पेंशन योजनाओं में आंशिक केंद्रीय सहायता मिलती है, लेकिन राज्य में वृद्धजनों, विधवाओं और विशेष योग्यजनों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन का एक बड़ा वित्तीय हिस्सा राजस्थान सरकार अपने स्वयं के राज्य कोष से वहन करती है, जिससे राज्य पर महत्वपूर्ण वित्तीय जिम्मेदारी होती है।

47. (D) अभिकथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।
राजस्थान वित्त निगम की स्थापना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के तहत 1955 में की गई थी। इस निगम का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करना है। यह निगम केवल बड़े पैमाने के या बहुराष्ट्रीय उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य ध्यान राज्य के छोटे एवं मध्यम स्तर के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

48. (C) कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता का शिकार होने वाले कृषि श्रमिकों को
राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना राजस्थान सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य, मंडी गतिविधियों या कृषि यंत्रों के उपयोग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने वाले किसानों और कृषि श्रमिकों को वित्तीय संबल प्रदान करना है। कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने अथवा शारीरिक विकलांगता की स्थिति में पीड़ित या उसके परिवार को निर्धारित वित्तीय सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।

49. (D) एकीकृत विकास लक्ष्यों के लिए योजनाओं में धन और अवसंरचना का संयोजन
लोक कल्याण और प्रशासनिक शब्दावली में "अभिसरण" (कनवर्जेंस) का तात्पर्य विभिन्न सरकारी विभागों, योजनाओं और निधियों के संसाधनों का एकीकरण करना है। इसका मुख्य उद्देश्य दोहराव को रोकना तथा धन और अवसंरचना का प्रभावी संयोजन करके समन्वित विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। उदाहरण के लिए, मनरेगा, जलसम्भर विकास और स्वच्छ भारत मिशन के संसाधनों को एक साथ मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में

Downloaded from www.pdf.tube

टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण करना अभिसरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

50. (B) केवल III
राजस्थान जन आधार योजना 'एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान' के सिद्धांत पर काम करती है और यह नकद तथा गैर-नकद दोनों प्रकार के लाभों के वितरण की सुविधा देती है। योजना का एक प्रमुख उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है, इसलिए इसमें यह नियम है कि परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को ही परिवार का मुखिया नामांकित किया जाता है, न कि सबसे बुज़ुर्ग पुरुष सदस्य को।

51. (D) ₹1500
राजस्थान में मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत निराश्रित विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को आयु वर्ग के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती थी। ऐतिहासिक स्लैब के अनुसार, 18 से 55 वर्ष की आयु पर ₹500, 55 से 60 वर्ष पर ₹750, 60 से 75 वर्ष पर ₹1000, तथा 75 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं को ₹1500 प्रति माह की पेंशन राशि प्रदान की जाती थी।

52. (D) जिला प्रमुख
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-जेडडी के तहत प्रत्येक जिले में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की विकास योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला योजना समिति (डीपीसी) के गठन का प्रावधान है। राजस्थान में स्थापित व्यवस्था और लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार, जिला परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष यानी 'जिला प्रमुख' को जिला योजना समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, जबकि जिला कलेक्टर इसके सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

53. (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
राजस्थान सहकारी डेयरी संघ (आरसीडीएफ) के अंतर्गत राज्य में आनंद मॉडल पर आधारित त्रिस्तरीय सहकारी ढांचा कार्यरत है। इसमें सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायतों में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां कार्य करती हैं, जो दुग्ध उत्पादकों से दूध एकत्र करती हैं। मध्यवर्ती यानी जिला स्तर पर 'जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ' कार्यरत हैं, जो दूध के प्रसंस्करण, शीतलन और परिवहन का दायित्व संभालते हैं।

54. (C) गरीबी उन्मूलन और सतत आजीविका के लिए ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में लामबंद करने पर
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) का मुख्य रणनीतिक ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों से निर्धनता मिटाने पर केंद्रित है। इसके लिए यह परिषद ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों और क्लस्टर स्तरीय संघों में लामबंद करती है। राजीविका का उद्देश्य इन समूहों को वित्तीय साख, कौशल प्रशिक्षण, और बाजार से जोड़कर महिलाओं को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना तथा उनका सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।

55. (C) पंजीकरण → विभाग को आवंटन → अधिकारी द्वारा समाधान → नागरिक प्रतिक्रिया
राजस्थान संपर्क पोर्टल पर नागरिक शिकायत निवारण की प्रक्रिया एक सुव्यवस्थित क्रम का पालन करती है। सबसे पहले नागरिक पोर्टल या 181 हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी शिकायत पंजीकृत कराता है। इसके बाद शिकायत को संबंधित विभाग और अधिकारी को आवंटित किया जाता है। अधिकारी शिकायत की जांच करके उसका समाधान प्रस्तुत करता है, और अंत में शिकायतकर्ता नागरिक से समाधान के संबंध में उसकी प्रतिक्रिया या संतुष्टि का स्तर लिया जाता है।

56. (D) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
नाबार्ड, सिडबी और राजस्थान वित्त निगम जैसी संस्थाएं विकास वित्तीय संस्थानों के रूप में कार्य करती हैं, जिनका मुख्य कार्य कृषि, सूक्ष्म-लघु उद्योगों और क्षेत्रीय विकास के लिए दीर्घकालिक साख तथा ढांचागत सहायता प्रदान करना है। इसके विपरीत, भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, जिसका प्राथमिक कार्य देश की मौद्रिक नीति का संचालन करना, मुद्रा जारी करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और पूरी बैंकिंग प्रणाली का नियमन एवं पर्यवेक्षण करना है।

57. (B) महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा)
सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी योजना के क्रियान्वयन की जांच स्वयं स्थानीय समुदाय और लाभार्थियों द्वारा की जाती है। यह प्रणाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत कानूनी रूप से अनिवार्य की गई है। इसके माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता, श्रमिकों के मस्टर रोल, मजदूरी के भुगतान और व्यय की पारदर्शिता की नियमित रूप से ग्राम सभा द्वारा निष्पक्ष समीक्षा की जाती है।

58. (B) केवल I, III और IV
राजस्थान का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अत्यधिक सुदृढ़ है। राजनेट के जरिए ग्राम पंचायत तक कनेक्टिविटी उपलब्ध है, ई-मित्र प्लस मशीनें स्वयं-सेवा और दस्तावेज छपाई की सुविधा देती हैं, और यह पूरा ढांचा डीबीटी तंत्र को मजबूत बनाता है। हालांकि, यह कहना गलत है कि ई-मित्र केवल शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं; वास्तव में ई-मित्र कियोस्क राज्य के सुदूर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से सेवाएं दे रहे हैं।

59. (A) P-2, Q-4, R-1, S-3
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना नए उद्यमों हेतु ऋण पर ब्याज अनुदान देती है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना व्यापक निवेश के लिए कर छूट प्रदान करती है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देती है। वहीं पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, औजार और रियायती ऋण सहायता प्रदान करके उनके पारंपरिक कौशल और आजीविका को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संचालित की जाती है।

NODIA

प्रति जन-जागरूकता फैलाना और वंचित वर्गों की क्षमता का निर्माण करना है। ये संस्थाएं अंतिम छोर के पात्र व्यक्तियों को पहचानकर उन्हें योजनाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

20. (C) केवल III
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता प्रदान करती है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों में परिवारों को आजीविका सुरक्षा देने हेतु रोजगार प्रदान करती है। वहीं मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना कृषि कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने वाले किसानों और कृषि श्रमिकों को वित्तीय सहायता देने के लिए है, न कि सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक सहायता के लिए।

21. (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
ग्राम सभा ग्रामीण विकास एवं सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्राम पंचायत के अंतर्गत पंजीकृत सभी वयस्क मतदाताओं की एक सांविधिक संस्था है। स्थानीय निवासी होने के कारण ग्राम सभा के सदस्य गांव की वास्तविक परिस्थितियों और परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति से भली-भांति परिचित होते हैं। इसी कारण ग्राम सभाएं सामाजिक कल्याण योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन निष्पक्षता से करने में अत्यधिक सक्षम होती हैं।

22. (C) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
राजस्थान सरकार द्वारा शुरु किया गया 'जन सूचना पोर्टल' सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में एक अनूठी पहल है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) में यह प्रावधान है कि सरकारी प्राधिकरण स्वयं ही सूचनाओं को सार्वजनिक करेंगे। इसी कानूनी जनादेश को पूरा करते हुए जन सूचना पोर्टल विभिन्न विभागों और योजनाओं से संबंधित जानकारी को बिना आवेदन किए आम जनता के लिए स्वतः उपलब्ध कराता है।

23. (A) किसी निर्दिष्ट संवेदनशील श्रेणी में न आने वाले करदाता परिवार
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र परिवारों, लघु एवं सीमांत किसानों, संविदाकर्मियों तथा बीपीएल परिवारों का संपूर्ण प्रीमियम राज्य सरकार वहन करती है। हालांकि, जो परिवार आयकरदाता हैं और किसी भी निर्दिष्ट संवेदनशील या प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें योजना में शामिल होने के लिए निर्धारित वार्षिक प्रीमियम राशि का भुगतान करना अनिवार्य होता है, वे निःशुल्क लाभ के हकदार नहीं हैं।

24. (A) केवल कथन I सही है
प्राथमिक कृषि साख समितियां (पैक्स) राजस्थान में त्रिस्तरीय अल्पकालिक सहकारी साख संरचना का आधार हैं, जो सीधे ग्राम या ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों के साथ जुड़कर कार्य करती हैं। पैक्स का मुख्य जनादेश किसानों को फसल उत्पादन, बीज, उर्वरक खरीदने के लिए अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराना है। भारी मशीनरी या भूमि विकास हेतु दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों का मुख्य कार्य होता है।

25. (A) केवल I, II और III
राजस्थान वित्त निगम उद्योगों को ऋण सहायता प्रदान करता है। इसकी शिल्पी योजना कारीगरों को, फ्लेक्सी लोन योजना कार्यशील पूंजी को, और युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना नए युवाओं को वित्तीय संबल देती है। हालांकि, यह निगम किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी को विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए पूर्णतः गैर-पुनर्भुगतान योग्य अनुदान राशि प्रदान नहीं करता है, बल्कि व्यावसायिक शर्तों पर ऋण वितरित करने का कार्य करता है।

26. (C) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद
भारत में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। राजस्थान में पंचायती राज संरचना का पदानुक्रम ग्रामीण स्तर से जिला स्तर की ओर क्रमशः तीन स्तरों में विभाजित है। इसमें सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती या खंड स्तर पर पंचायत समिति और शीर्ष अथवा जिला स्तर पर जिला परिषद कार्य करती है, जो स्थानीय स्वशासन का संचालन करती हैं।

27. (C) 6 किस्तें
मुख्यमंत्री राजश्री योजना का उद्देश्य राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और उनके स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र बालिका के जन्म से लेकर बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने तक कुल 50,000 रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह पूरी राशि बालिका के विभिन्न विकास चरणों पर कुल 6 अलग-अलग किस्तों में सीधे हस्तांतरित की जाती है।

28. (A) जन आधार डेटाबेस
राजस्थान सरकार द्वारा जन आधार योजना को राज्य के निवासियों का एक एकीकृत मास्टर जनसांख्यिकीय डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। यह डेटाबेस प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रमों में लाभार्थियों के दोहराव, फर्जीवाड़े और अयोग्य लोगों के शामिल होने की समस्या को रोकने के लिए इसी डेटाबेस का प्राथमिक रूप से उपयोग किया जाता है।

29. (B) लक्षित योजना जनसंख्या के भीतर सभी पात्र लाभार्थियों का पूर्ण कवरेज
लोक कल्याणकारी शासन के संदर्भ में "योजना संतृप्ति" का तात्पर्य उस स्थिति से है जब किसी विशिष्ट जनकल्याणकारी योजना का लाभ उसके लक्षित समूह के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँच जाता है। इसका अर्थ यह है कि योजना के अंतर्गत कोई भी वंचित या छूटा हुआ पात्र लाभार्थी नहीं रहता है। यह

Click Here to Buy book on Flipkart

70. (C) पीसीटीएस पोर्टल
राजस्थान में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए 'पीसीटीएस' (प्रेग्नेंसी, चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल का उपयोग किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर/पोर्टल के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण, प्रसव पूर्व जांचों, संस्थागत प्रसवों और बच्चों के टीकाकरण का वास्तविक समय में डिजिटलीकरण किया जाता है। यह प्रणाली शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने में एक महत्वपूर्ण साधन साबित हुई है।

71. (A) यह भारी इंजीनियरिंग में कौशल विकास के लिए विशेष रूप से शहरी पुरुष युवाओं को लक्षित करता है।
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन करना है। यह परिषद राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत है और मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। राजीविका का मुख्य ध्यान विशेष रूप से ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उन्हें स्थायी आजीविका से जोड़ने पर केंद्रित है, न कि शहरी पुरुष युवाओं को भारी इंजीनियरिंग प्रशिक्षण देने पर।

72. (D) वे केवल कनिष्ठ स्तर के क्षेत्रीय कर्मचारियों को दंडित करने और बर्खास्त करने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं।
कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का उद्देश्य योजना की प्रभावशीलता, पारदर्शिता और कमियों को समझना होता है। यह मूल्यांकन साक्ष्य-आधारित डेटा प्रदान करता है ताकि नीतिगत सुधार किए जा सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुँच रहे हैं या नहीं। इन अध्ययनों का उद्देश्य कनिष्ठ कर्मचारियों को दंडित या बर्खास्त करना कतई नहीं होता, बल्कि प्रणालीगत सुधार और योजना के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना होता है।

73. (B) नीति पर सरकार को सलाह देना और महिलाओं के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की जाँच करना
राजस्थान राज्य महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए की गई है। आयोग का मुख्य कार्य महिलाओं से संबंधित नीतिगत मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना, महिलाओं को प्राप्त संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की जांच करना, उत्पीड़न के मामलों की जांच करना तथा महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न सिफारिशें प्रस्तुत करना है।

74. (C) राज्य द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (आईएएस/आरएएस)
जिला परिषद स्तर पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज योजनाओं का कुशल समन्वय एवं प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति की जाती है। यह पद राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (भारतीय प्रशासनिक सेवा या राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी) द्वारा धारण किया जाता है। यह अधिकारी जिला परिषद के प्रस्तावों को लागू करने और विकास कार्यक्रमों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होता है।

75. (D) महिला एवं बाल विकास विभाग – इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, जो दूसरी संतान के जन्म पर माताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसके विपरीत, वृद्धजन पेंशन योजना सामाजिक न्याय विभाग द्वारा, चिरंजीवी योजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, और राजश्री योजना भी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित होती है। इस प्रकार नोडल विभाग और योजना का सही युग्म उपलब्ध है।

76. (A) विदेशी आयातित डेयरी मशीनों की सीधी खुदरा बिक्री
राजस्थान सहकारी डेयरी संघ (आरसीडीएफ) का मुख्य ध्यान दुग्ध उत्पादकों के कल्याण और डेयरी विकास पर केंद्रित है। यह संघ पाश्चुरीकृत दूध और सरस ब्रांड के उत्पादों का विपणन करता है, किसानों को संतुलित पशु आहार आपूर्ति करता है तथा कृत्रिम गर्भाधान और पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। हालांकि, विदेशी आयातित डेयरी मशीनों की सीधी खुदरा बिक्री करना आरसीडीएफ के मानक कार्यात्मक क्षेत्र या उद्देश्यों में शामिल नहीं है।

77. (B) केवल कथन II सही है
सहकारिता का मूल दर्शन लोकतांत्रिक मूल्यों और समानता पर आधारित है। सहकारी समितियां "एक सदस्य, एक मत" के सिद्धांत पर काम करती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि किसी सदस्य द्वारा समिति में लगाई गई शेयर पूंजी चाहे कितनी भी हो, प्रत्येक सदस्य को चुनाव और निर्णय प्रक्रिया में केवल एक वोट देने का अधिकार होता है। यह व्यवस्था अमीर सदस्यों के वर्चस्व को रोकती है और सभी को समान अधिकार देती है।

78. (B) रीको
राजस्थान में औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश संवर्धन के लिए 'रीको' (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम) शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है। रीको राज्य भर में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करता है, उद्योगों को भूमि आवंटित करता है, और मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली तथा पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराता है। यह संस्था राज्य में बड़े और मध्यम पैमाने के उद्योगों को आकर्षित करने हेतु नोडल एजेंसी है।

79. (A) बीपीएल, अंत्योदय और वंचित परिवारों की लड़कियों का विवाह
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' (पूर्व में सहयोग एवं उपहार योजना) का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों, अंत्योदय परिवारों, तथा आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों की कन्याओं के विवाह के अवसर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बालिका

Downloaded from www.pdf.tube

की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर इस योजना में अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।

80. (B) 2011
राजस्थान में प्रशासनिक जवाबदेही तय करने तथा नागरिकों को समयबद्ध सीमा के भीतर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम' वर्ष 2011 में लागू किया गया था। इस कानून का मुख्य लक्ष्य ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, लालफीताशाही पर अंकुश लगाना और विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है।

www.nodia.in

NODIA

अध्याय 26

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

1. मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था?
(A) 2001
(B) 2003
(C) 2005
(D) 2008

2. राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए कौन-सा केंद्रीय मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है?
(A) पंचायती राज मंत्रालय
(B) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(C) ग्रामीण विकास मंत्रालय
(D) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

3. मनरेगा के तहत किसी ग्रामीण परिवार को प्रदान किया जाने वाला मौलिक कानूनी अधिकार क्या है?
(A) प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों का गारंटीकृत कुशल शारीरिक मजदूरी रोजगार
(B) प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों का अकुशल शारीरिक मजदूरी रोजगार
(C) प्रति कैलेंडर वर्ष 150 दिनों का गारंटीकृत अर्ध-कुशल मजदूरी रोजगार
(D) प्रति कैलेंडर वर्ष 200 दिनों का गारंटीकृत अकुशल शारीरिक मजदूरी रोजगार

4. मनरेगा द्वारा दी गई परिभाषाओं के अनुसार, जॉब कार्ड आवंटन के उद्देश्य से "परिवार" का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है?
(A) एक ही उपनाम और पैतृक संपत्ति साझा करने वाले परिवार के सदस्य
(B) एक ही गाँव के वार्ड में रहने वाले वयस्कों का कोई भी समूह
(C) एक ही छत के नीचे रहने वाले केवल रक्त संबंधी
(D) एक साथ रहने वाले और एक ही रसोई का भोजन साझा करने वाले परिवार के सदस्य

5. मनरेगा के तहत काम की कानूनी गारंटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: यह योजना वैध मांग के 15 दिनों के भीतर काम प्रदान करने के लिए सरकार को कानूनी रूप से बाध्य करती है।
कथन II: यदि सरकार 15 दिनों के भीतर काम प्रदान करने में विफल रहती है, तो आवेदक दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होता है।
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II, कथन I का परिणाम है
(B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं परंतु एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं
(C) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है परंतु कथन II सही है

6. श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान के लिए मनरेगा द्वारा निर्धारित प्राथमिक तंत्र क्या है?
(A) ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा दैनिक नकद वितरण
(B) मजदूरी के बराबर कृषि जिंसों और खाद्यान्न के माध्यम से भुगतान
(C) श्रमिकों के बैंक या डाकघर खातों में प्रत्यक्ष अंतरण
(D) गाँव के वार्ड सदस्य और श्रमिक के संयुक्त खाते में प्रत्यक्ष अंतरण

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): मनरेगा यह अनिवार्य करता है कि मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक या डाकघर खातों में जमा किया जाना चाहिए।
कारण (R): बिचौलियों को खत्म करने तथा मजदूरी के रिसाव और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।

Click Here to Buy book on Amazon

(C) 1999
(D) 2004

28. SGRY जैसी पूर्ववर्ती रोजगार योजनाओं और वर्तमान मनरेगा ढांचे के बीच मौलिक वैचारिक अंतर क्या है?
(A) SGRY आवंटन-आधारित थी, जबकि मनरेगा एक अधिकार-आधारित गारंटी है
(B) SGRY सख्ती से मांग-संचालित योजना थी, जबकि मनरेगा आवंटन-आधारित ढांचे पर कार्य करती है
(C) SGRY ने विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि मनरेगा पूरी तरह से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है
(D) SGRY केवल नकद भुगतान प्रदान करती थी, जबकि मनरेगा खाद्यान्न के साथ प्रत्यक्ष अंतरण प्रदान करती है

29. निम्नलिखित में से कौन-सी एक अग्रणी राज्य-स्तरीय रोजगार गारंटी योजना थी जिसने ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय मनरेगा के निर्माण को प्रेरित किया?
(A) राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
(B) महाराष्ट्र रोजगार गारंटी योजना
(C) केरल राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन
(D) गुजरात राज्य ग्रामीण मजदूरी रोजगार कार्यक्रम

30. ग्रामीण रोजगार/गरीबी उन्मूलन योजनाओं (सूची I) का उनके संबंधित प्रारंभ वर्षों (सूची II) के साथ मिलान कीजिए।
सूची I: (योजनाएं)
P. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
Q. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
R. रोजगार आश्वासन योजना
S. काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम
सूची II: (प्रारंभ वर्ष)
1. 1993
2. 2001
3. 2004
4. 2005
(A) P-4, Q-2, R-1, S-3
(B) P-4, Q-1, R-2, S-3
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

31. कृषि के मंदी वाले मौसम में, मनरेगा मुख्य रूप से किस प्रकार ग्रामीण गरीबी में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है?
(A) कम कृषि मांग के दौरान वैकल्पिक आय सहायता प्रदान करके
(B) सभी पंजीकृत छोटे और सीमांत किसानों को अत्यधिक कुशल स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान करके
(C) सभी काटी गई कृषि उपज के लिए व्यापक न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देकर
(D) छोटे किसानों को सीधे मुफ्त आधुनिक कृषि मशीनरी और उपकरण की आपूर्ति करके

32. ग्रामीण रोजगार अधिनियम के नाम परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. मूल कानून 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) के रूप में पारित किया गया था।
II. 2 अक्टूबर 2009 को "महात्मा गांधी" (MGNREGA) को शामिल करने के लिए इसका नाम बदला गया था।
III. नाम बदलने की प्रक्रिया ने देश भर में आधारभूत कानूनी गारंटी को 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

33. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्यक्रम मनरेगा के ग्रामीण रोजगार गारंटी ढांचे का पूर्ववर्ती या उसमें विलय किया गया कार्यक्रम नहीं था?
(A) काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम
(B) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
(C) रोजगार आश्वासन योजना
(D) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

NODIA

34. मनरेगा में श्रमिकों के विश्वास को प्रभावित करने वाली एक बड़ी कार्यान्वयन बाधा "विलंबित भुगतान" का मुद्दा है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, मस्टर रोल बंद होने के कितने दिनों के भीतर भुगतान प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए और राशि श्रमिक के खाते में जमा की जानी चाहिए?
(A) 7 दिन
(B) 15 दिन
(C) 30 दिन
(D) 45 दिन

35. मनरेगा से जुड़ी आम आलोचनाओं और भ्रष्टाचार की चिंताओं के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) सरकारी धन का गबन करने के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा आधिकारिक मस्टर रोल में नियमित रूप से काल्पनिक और गैर-मौजूद श्रमिकों के नाम जोड़े जाते हैं
(B) यह योजना पूरी तरह से भारी मशीनों पर निर्भर है, जिससे सभी अकुशल शारीरिक मजदूरी रोजगार समाप्त हो गए हैं
(C) इस योजना के तहत बनाई गई ग्रामीण सामुदायिक संपत्तियों की संरचनात्मक गुणवत्ता और दीर्घकालिक उपयोगिता पर टिकाऊपन की कमी के लिए अक्सर सवाल उठाए जाते हैं
(D) विभिन्न राज्यों में पंजीकृत शारीरिक श्रमिकों को अक्सर अपने वैधानिक मजदूरी मुआवजे को प्राप्त करने में गंभीर प्रशासनिक देरी का सामना करना पड़ता है

36. मनरेगा भ्रष्टाचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प "फर्जी श्रमिकों" (Ghost Workers) का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

(D) जल संरक्षण संरचनाएं

18. मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. चेक डैम और रिसाव पोखरों का निर्माण।
II. जोहड़ जैसे पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार।
III. ग्रामीण सड़क संपर्क के बुनियादी ढांचे का निर्माण।
IV. गाँव में खनन के लिए भारी मशीनीकृत उत्खनकों की खरीद।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, III और IV
(D) I, II, III और IV

19. राजस्थान में मनरेगा कोष का उपयोग करके व्यापक रुप से पुनर्जीवित की गई पारंपरिक जल संरक्षण संरचना की पहचान कीजिए।
(A) केवल सीमेंट से बनी बावड़ियां
(B) जोहड़ और मिट्टी के चेक डैम
(C) भूमिगत कंक्रीट जलसेतु
(D) अलवणीकरण तालाब

20. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प किसी अवधारणा का उसके मनरेगा तंत्र के साथ गलत युग्म दर्शाता है?
(A) प्राथमिक पारदर्शिता तंत्र - सामाजिक अंकेक्षण ढांचा
(B) वैधानिक पहचान दस्तावेज - पारिवारिक जॉब कार्ड
(C) दैनिक उपस्थिति रिकॉर्ड - कार्यस्थल मस्टर रोल
(D) शिकायत निवारण - उच्चतम न्यायालय

21. मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना और निष्पादन संबंधी विसंगतियों का पता लगाना
(B) निर्मित सभी संपत्तियों की दीर्घकालिक वाणिज्यिक लाभप्रदता और राजस्व सृजन का मूल्यांकन करना
(C) पंजीकृत श्रमिकों के चुनावी मतदान पैटर्न और राजनीतिक संबद्धता का निर्धारण करना
(D) राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद और समष्टि आर्थिक वृद्धि योगदान की गणना करना

22. निम्नलिखित में से कौन-सा मनरेगा के तहत रोजगार चाहने वाले ग्रामीण परिवार के लिए शुरुआती प्रक्रियाओं का सही क्रमिक क्रम दर्शाता है?
(A) काम की मांग, पंजीकरण, जॉब कार्ड जारी करना, काम का आवंटन
(B) पंजीकरण, जॉब कार्ड जारी करना, काम की मांग, काम का आवंटन
(C) जॉब कार्ड जारी करना, पंजीकरण, काम का आवंटन, काम की मांग
(D) पंजीकरण, काम की मांग, काम का आवंटन, जॉब कार्ड जारी करना

23. राजस्थान में, ग्रामीण रोजगार गारंटी के साथ एकीकृत विशेष राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत, सहरिया, खैरवा और काथोड़ी जनजातियों से संबंधित परिवारों को कितने अतिरिक्त दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है?
(A) 25 अतिरिक्त दिन
(B) 50 अतिरिक्त दिन
(C) 100 अतिरिक्त दिन
(D) 150 अतिरिक्त दिन

24. काम के पहले 100 दिनों के लिए मनरेगा के तहत केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय बोझ साझा करने के तंत्र के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) राज्य सरकार अकुशल शारीरिक श्रम की 100% लागत वहन करती है
(B) केंद्र सरकार सामग्री और कुशल श्रम दोनों की 100% लागत वहन करती है
(C) राज्य सरकार अकुशल शारीरिक श्रम की 50% लागत वहन करती है
(D) केंद्र सरकार अकुशल शारीरिक श्रम की 100% लागत वहन करती है

25. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण सख्ती से निजी बाहरी वाणिज्यिक लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा आयोजित किए जाते हैं।
कारण (R): ग्राम सभा के पास सभी स्थानीय कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करने का वैधानिक अधिकार और जिम्मेदारी है।
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।

26. पूरक मजदूरी रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2001 में शुरु की गई किस पूर्ववर्ती ग्रामीण रोजगार योजना का अंततः नरेगा (NREGA) में विलय कर दिया गया था?
(A) जवाहर रोजगार योजना (JRY)
(B) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)
(C) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)
(D) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)

27. कृषि के मंदी वाले मौसम के दौरान रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से मनरेगा के प्रमुख अग्रदूत कार्यक्रमों में से एक 'रोजगार आश्वासन योजना' (EAS) किस वर्ष शुरू की गई थी?
(A) 1989
(B) 1993

Downloaded from www.pdf.tube

(C) खंड विकास अधिकारी
(D) जिला कलेक्टर

62. निम्नलिखित में से कौन-सा मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया का सही क्रमिक क्रम दर्शाता है?
(A) सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा सत्यापन, ग्राम पंचायत द्वारा रिकॉर्ड तैयार करना, ग्राम सभा में प्रस्तुति, सुधारात्मक कार्रवाई
(B) ग्राम पंचायत द्वारा रिकॉर्ड तैयार करना, सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा सत्यापन, ग्राम सभा में प्रस्तुति, सुधारात्मक कार्रवाई
(C) ग्राम सभा में प्रस्तुति, सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा सत्यापन, ग्राम पंचायत द्वारा रिकॉर्ड तैयार करना, सुधारात्मक कार्रवाई
(D) सुधारात्मक कार्रवाई, ग्राम पंचायत द्वारा रिकॉर्ड तैयार करना, सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा सत्यापन, ग्राम सभा में प्रस्तुति

63. निम्नलिखित में से कौन-सा एक स्वीकृत मनरेगा गतिविधि और उसकी श्रेणी का सही युग्म है?
(A) वनीकरण - सूखा रोधन
(B) पंचायत भवन का निर्माण - व्यक्तिगत लाभार्थी संपत्ति
(C) एक बड़े कॉरपोरेट फार्म के लिए भूमि समतल करना - ग्रामीण बुनियादी ढांचा
(D) गाँव के तालाब की खुदाई - शहरी स्वच्छता

64. निम्नलिखित में से कौन-सी सड़क और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी कार्य सामान्यतः मनरेगा के तहत अनुमत नहीं है?
(A) असंपर्क बसावटों को जोड़ने वाली बारहमासी ग्रामीण सड़कों का निर्माण
(B) गाँव के भीतर सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का निर्माण
(C) यांत्रिक पेवर का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन
(D) ग्रामीण सड़कों पर पुलिया और क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाओं का निर्माण

65. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): मनरेगा ने ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
कारण (R): यह अधिनियम पुरुषों और महिलाओं के लिए समान मजदूरी का आदेश देता है और यह आवश्यक बनाता है कि कुल कार्यबल का कम से कम एक-तिहाई हिस्सा महिलाएं होनी चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।

66. श्रम-गहन कार्यों को प्राथमिकता देना सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा के तहत 60:40 का निर्धारित मजदूरी-सामग्री अनुपात किस प्रशासनिक स्तर पर आकलित किया जाता है?
(A) संपूर्ण जिला स्तरीय प्रशासनिक इकाई
(B) मध्यवर्ती ब्लॉक स्तरीय प्रशासनिक इकाई
(C) ग्राम पंचायत स्तर
(D) राज्य सरकार स्तरीय प्रशासनिक इकाई

67. अनुसूचित जाति समुदाय से संबंध रखने वाला एक सीमांत किसान अपनी कृषि भूमि को समतल करने और सिंचाई का कुआं खोदने के लिए मनरेगा श्रम का उपयोग करना चाहता है। क्या अधिनियम के तहत इसकी अनुमति है?
(A) नहीं, मनरेगा मजदूरी और सामग्री कोष का उपयोग केवल और केवल सार्वजनिक सरकारी भूमि पर सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण के लिए किया जा सकता है
(B) हां, पात्र सीमांत किसानों की निजी भूमि पर भूमि विकास कार्यों की अनुमति है
(C) हां, लेकिन केवल इस वैधानिक शर्त के तहत कि लाभार्थी किसान 5 वर्षों के भीतर सरकार को कुल मजदूरी लागत पूरी तरह से लौटा देगा
(D) नहीं, सभी व्यक्तिगत कृषि और भूमि विकास गतिविधियों को मनरेगा के वैधानिक दायरे से सख्ती से बाहर रखा गया है

68. मनरेगा के तहत काम के आवंटन के प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: कार्यान्वयन एजेंसी को आवेदक के गाँव के 5 किमी के दायरे में काम प्रदान करना होगा।
कथन II: यदि 5 किमी के दायरे से बाहर काम प्रदान किया जाता है, तो श्रमिक किसी अतिरिक्त मुआवजे का हकदार नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II, कथन I का परिणाम है
(B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं परंतु एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं
(C) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है परंतु कथन II सही है

69. मनरेगा के तहत ग्राम सभा की वैधानिक भूमिकाओं की पहचान करते समय निम्नलिखित में से कौन-सा असंगत (Odd one out) है?
(A) करेंसी नोटों की छपाई और ढलाई करना
(B) स्थानीय ग्राम विकास कार्यों को तैयार करना और उनकी सिफारिश करना
(C) निष्पादित सभी परियोजनाओं का वैधानिक सामाजिक अंकेक्षण करना
(D) वार्षिक ग्राम विकास योजना को औपचारिक रूप से मंजूरी देना

NODIA

(A) पंजीकृत ग्रामीण श्रमिक जो विशेष रुप से रात की पाली में शारीरिक श्रम करते हैं
(B) मौसमी प्रवासी मजदूर जो रोजगार के लिए अक्सर विभिन्न प्रशासनिक जिलों के बीच आवाजाही करते हैं
(C) वरिष्ठ प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारी जो उपग्रह के माध्यम से ग्रामीण कार्यस्थलों की दूरस्थ निगरानी करते हैं
(D) मजदूरी चुराने के लिए मस्टर रोल में दर्ज फर्जी या मृतक व्यक्ति

37. निम्नलिखित में से किसे मनरेगा के मुख्य निष्पादन दिशानिर्देशों का "अपवाद" या उल्लंघन माना जाता है?
(A) गाँव के कार्यों को निष्पादित करने के लिए निजी ठेकेदारों को किराए पर लेना
(B) रिसाव पोखरों और जल संरक्षण संरचनाओं की खुदाई के लिए शारीरिक श्रम का उपयोग करना
(C) आधिकारिक कार्यस्थल मेट और पर्यवेक्षकों के रूप में सेवा करने के लिए प्रशिक्षित स्थानीय महिलाओं को नियुक्त करना
(D) समान कार्य करने वाले पुरुष और महिला श्रमिकों दोनों को सख्ती से समान मजदूरी प्रदान करना

38. मनरेगा कार्यस्थलों पर कार्यान्वयन संबंधी कमियों का विवरण देने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. अनिवार्य पेयजल सुविधाओं का अभाव।
II. भीषण गर्मी के दौरान विश्राम के लिए छाया की कमी।
III. एक कार्यात्मक प्राथमिक चिकित्सा किट की अनुपलब्धता।
IV. छोटे बच्चों की आवश्यक संख्या मौजूद होने पर भी अनिवार्य शिशुगृह सुविधाओं का न होना।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कार्यस्थल ऑडिट में अक्सर उजागर होने वाली सुविधाओं की कमी का प्रतिनिधित्व करता है/करते हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I, III और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) I, II, III और IV

39. मनरेगा का प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के साथ अभिसरण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस परिणाम को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है?
(A) जलसंभर विकास और सिंचाई क्षमता को बढ़ाना
(B) उच्च गति वाली ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार करना
(C) जनजातीय पट्टियों में आधुनिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों और चिकित्सा इकाइयों का निर्माण करना
(D) सीमांत किसानों को रियायती रासायनिक उर्वरक और उच्च उपज वाले बीज वितरित करना

40. निम्नलिखित में से कौन-सा एक ग्रामीण योजना और मनरेगा के साथ इसकी विशिष्ट अभिसरण गतिविधि का सही युग्म है?
(A) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) - मुफ्त खाद्यान्न और आपातकालीन राशन का सीधा वितरण
(B) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन - बहु-लेन राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का निर्माण
(C) जल जीवन मिशन - व्यापक कृषि फसल बीमा और वित्तीय ऋण प्रदान करना
(D) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) - व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (IHHL)

41. पूरे भारत में मनरेगा कार्यान्वयन के पूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) को किस नाम से जाना जाता है?
(A) नरेगा-दर्पण (NREGA-Darpan)
(B) नरेगासॉफ्ट (NREGASoft)
(C) ई-पंचायत (e-Panchayat)
(D) मनरेगा-ट्रैक (MGNREGA-Track)

42. मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को उनके घटित होने के सही क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. मजदूरी सूची का निर्माण
2. मस्टर रोल पर दैनिक उपस्थिति दर्ज करना
3. फंड ट्रांसफर ऑर्डर (FTO) का निर्माण
4. तकनीकी सहायक द्वारा कार्य आउटपुट का मापन
सही क्रम का चयन कीजिए:
(A) 2, 4, 1, 3
(B) 2, 1, 4, 3
(C) 4, 2, 1, 3
(D) 1, 2, 4, 3

43. मनरेगा के तहत बनाई गई संपत्तियों की जियो-टैगिंग मुख्य रूप से किसलिए लागू की जाती है?
(A) व्यक्तिगत श्रमिकों की दैनिक शारीरिक गतिविधियों और जीपीएस निर्देशांकों को ट्रैक करने के लिए
(B) वास्तविक समय में गाँव के सटीक भूजल स्तर और जलवैज्ञानिक परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए
(C) प्रत्येक श्रमिक के घर और निर्दिष्ट कार्यस्थल के बीच की सटीक यात्रा दूरी की गणना करने के लिए
(D) संपत्तियों को डिजिटली सत्यापित करने और दोहरे बिलिंग को रोकने के लिए

44. कोविड-19 महामारी जैसे गंभीर आर्थिक संकट के समय मनरेगा ने क्या भूमिका निभाई?
(A) इसने विपरीत प्रवास (reverse migration) के दौरान एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल के रूप में कार्य किया
(B) चिकित्सा अनुसंधान की ओर सभी वित्तीय संसाधनों को पुनरआवंटित करने के लिए इसे देश भर में अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था
(C) इसे संरचनात्मक रूप से विशेष रूप से शहरी स्वच्छता

Click Here to Buy book on Flipkart

श्रमिकों के लिए एक रोजगार योजना में परिवर्तित कर दिया गया था
(D) उसने काम के आवंटन को सख्ती से निजी खेतों पर मौसमी कृषि कटाई गतिविधियों तक सीमित कर दिया

45. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): कृषि संकट या सूखे के वर्षों के दौरान, मनरेगा कार्य की मांग में आमतौर पर कमी आती है।
कारण (R): सूखे के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से छोड़कर श्रमिक पूरी तरह से शहरी केंद्रों की ओर पलायन कर जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं परंतु कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है परंतु कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।

46. मनरेगा ढांचे के तहत, इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (e-FMS) का प्राथमिक कार्य क्या है?
(A) स्थानीय ग्रामीण संपत्ति कर और नगर पालिका विकास शुल्क इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्र करना
(B) श्रमिक खातों में सीधे इलेक्ट्रॉनिक मजदूरी अंतरण सुनिश्चित करना
(C) ग्राम पंचायत अधिकारियों की दैनिक उपस्थिति और प्रदर्शन मानकों को ट्रैक करना
(D) निजी वाणिज्यिक बोलीदाताओं को सार्वजनिक ग्रामीण सामुदायिक संपत्तियों और बुनियादी ढांचे की नीलामी करना

47. मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दरों में प्रतिवर्ष संशोधन किया जाता है। ये संशोधन वर्तमान में निम्नलिखित में से किस आर्थिक सूचकांक से जुड़े हुए हैं?
(A) कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL)
(B) शहरी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW)
(C) सभी वस्तुओं का राष्ट्रीय थोक मूल्य सूचकांक (WPI)
(D) वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद अंतर्निहित मूल्य अवस्फीतिकारक (GDP Deflator)

48. मनरेगा मजदूरी दरों की अधिसूचना के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) पूरे भारत के सभी राज्यों में मजदूरी दरें एक समान हैं
(B) स्थानीय मुद्रास्फीति के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा स्वतंत्र रूप से मजदूरी दरें निर्धारित की जाती हैं
(C) केंद्र सरकार द्वारा राज्यवार मजदूरी दरें अधिसूचित की जाती हैं
(D) शेयर बाजार के प्रदर्शन के आधार पर मजदूरी दरें प्रतिदिन बदलती हैं

NODIA

49. मनरेगा के तहत पंजीकरण कराने और रोजगार मांगने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम वैधानिक आयु आवश्यकता क्या है?
(A) 16 वर्ष
(B) 18 वर्ष
(C) 21 वर्ष
(D) 25 वर्ष

50. मनरेगा कार्यान्वयन प्राधिकरणों (सूची I) का उनकी संबंधित भूमिकाओं/स्तरों (सूची II) के साथ मिलान कीजिए।
सूची I: (कार्यान्वयन प्राधिकरण)
P. ग्राम पंचायत
Q. कार्यक्रम अधिकारी
R. जिला कार्यक्रम समन्वयक
S. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
सूची II: (भूमिकाएं/स्तर)
1. मनरेगा कार्यान्वयन पर राज्य सरकार को सलाह देती है
2. जिला स्तर पर योजना का समन्वय और निगरानी करता है
3. ब्लॉक/पंचायत समिति स्तर पर योजनाओं को समेकित करता है और निष्पादन का समन्वय करता है
4. गाँव के स्तर पर आवेदन प्राप्त करती है और जॉब कार्ड जारी करती है
(A) P-4, Q-3, R-2, S-1
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-4, Q-2, R-3, S-1
(D) P-1, Q-3, R-2, S-4

51. मनरेगा की मुख्य विशेषताओं का आकलन करते समय निम्नलिखित में से कौन-सा असंगत (Odd one out) है?
(A) स्थानीय ग्राम सभाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत योजना और निर्णय प्रक्रिया
(B) मिट्टी के कार्यों के लिए भारी मशीनों का अनिवार्य उपयोग
(C) प्रति परिवार 100 दिनों के अकुशल रोजगार का कानूनी रूप से लागू करने योग्य वैधानिक अधिकार
(D) विलंबित काम आवंटन के लिए दैनिक बेरोजगारी भत्ते की अनिवार्य पात्रता

52. मनरेगा के तहत कार्य निष्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. कार्यों के निष्पादन के लिए निजी ठेकेदारों को शामिल करना सख्ती से प्रतिबंधित है।
II. श्रम-विस्थापित करने वाली मशीनों का उपयोग सामान्यत: प्रतिबंधित है।
III. यह योजना विशेष रूप से कुशल ग्रामीण कारीगरों को 100 दिनों के काम की गारंटी देती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

53. यदि किसी पंजीकृत मनरेगा श्रमिक को उसके गाँव से 5 किमी की त्रिज्या से बाहर काम आवंटित किया जाता है, तो वह श्रमिक किस अतिरिक्त लाभ का हकदार है?
(A) मजदूरी दर का अतिरिक्त 10%
(B) स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा सीधे प्रदान की जाने वाली एक मुफ्त साइकिल
(C) आवश्यक दैनिक शारीरिक कार्य आउटपुट लक्ष्य में अनिवार्य 20% की कटौती
(D) वार्षिक रोजगार के अतिरिक्त 25 दिनों की तत्काल वैधानिक गारंटी

54. कार्यस्थल पर्यवेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: ग्राम रोजगार सहायक कार्यस्थल के रिकॉर्ड बनाए रखने और ग्राम पंचायत की सहायता करने के लिए जिम्मेदार है।
कथन II: "मेट" एक स्थानीय कार्यस्थल पर्यवेक्षक है जो दैनिक उपस्थिति दर्ज करता है और कार्य आउटपुट की देखरेख करता है।
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II, कथन I का परिणाम है
(B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं परंतु एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं
(C) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है परंतु कथन II सही है

55. मनरेगा के तहत कार्यस्थल पर्यवेक्षण के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसे कार्यस्थल "मेट" के रूप में नियुक्त करने के लिए अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है?
(A) स्थानीय महिला श्रमिकों को
(B) सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को
(C) शहरी क्षेत्रों के स्नातक युवाओं को
(D) जिला मुख्यालय के तकनीकी इंजीनियरों को

56. राजस्थान राज्य द्वारा मनरेगा के तहत जल संरक्षण कार्यों (जैसे जोहड़ और चेक डैम) को प्राथमिकता देने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है?
(A) शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में राज्य के बढ़ते अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग को सक्रिय रूप से समर्थन देना और उसका विस्तार करना
(B) प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पर्यटन विकास अनुदान प्राप्त करने के लिए वैधानिक आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करना
(C) वाणिज्यिक सौर ऊर्जा पार्क बनाने के लिए ग्रामीण सामुदायिक भूमि के विशाल क्षेत्रों को साफ करना
(D) शुष्क जलवायु, भूजल क्षरण और सूखे के प्रभावों को कम करना

57. राजस्थान मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत, राज्य सरकार 100 दिन पूरे करने वाले सामान्य परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करती है। इन अतिरिक्त 25 दिनों का वित्तीय खर्च कौन वहन करता है?
(A) पूरी तरह से केंद्र सरकार
(B) पूरी तरह से राज्य सरकार अपने स्वयं के बजट से
(C) केंद्र और राज्य के बीच समान रूप से (50:50) साझा
(D) विश्व बैंक के अनुदानों द्वारा वित्तपोषित

58. राजस्थान में मनरेगा के विशिष्ट कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. 100 दिन पूरे करने वाले सामान्य परिवार राज्य द्वारा वित्तपोषित 25 दिनों के अतिरिक्त काम के लिए पात्र हैं।
II. सहरिया और काथोड़ी जैसी विशेष जनजातियां कुल 200 दिनों के काम की हकदार हैं।
III. जल संरक्षण कार्य राज्य में निर्मित संपत्तियों का अत्यधिक अधिकांश हिस्सा हैं।
IV. स्वयं सहायता समूहों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राज्य ने महिलाओं को मनरेगा स्थलों पर काम करने से पूरी तरह से छूट दी है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, III और IV
(D) I, II, III और IV

59. राजस्थान में मनरेगा के प्रावधानों के लागू होने के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) राज्य सभी स्थानीय कार्यों की निगरानी के लिए स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण के एक व्यापक नेटवर्क को अनिवार्य करता है
(B) राज्य बड़े पैमाने पर जलसंभर विकास और मृदा संरक्षण कार्यक्रमों के साथ मनरेगा शारीरिक श्रम का सक्रिय रूप से अभिसरण करता है
(C) मजदूरी भुगतान मुख्य रूप से और अनिवार्य रूप से केंद्रीकृत आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं
(D) किसानों के लिए निजी स्विमिंग पूल का निर्माण

60. मनरेगा के राष्ट्रव्यापी अधिनियम बनने से पहले, किस राज्य की रोजगार गारंटी योजना ने अधिकार-आधारित दृष्टिकोण पर बल देने वाले प्राथमिक परिचालन खाके के रूप में कार्य किया?
(A) महाराष्ट्र
(B) तमिलनाडु
(C) पंजाब
(D) पश्चिम बंगाल

61. किसी गाँव के भीतर निष्पादित सभी मनरेगा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए वैधानिक रूप से किसे अधिकृत किया गया है?
(A) राज्य महालेखाकार
(B) ग्राम सभा

NODIA

8. ऐसे मामलों में जहाँ मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों से अधिक विलंबित होता है, श्रमिक कानूनी रूप से किस मुआवजे का हकदार है?
(A) देरी के प्रति दिन बकाया मजदूरी का 0.05 प्रतिशत
(B) देरी के प्रति दिन बकाया मजदूरी का 0.50 प्रतिशत
(C) देरी के प्रत्येक सप्ताह के लिए 100 रुपये की एकमुश्त दर
(D) देरी के प्रति दिन बकाया मजदूरी का 1.5 प्रतिशत

9. निम्नलिखित में से कौन-सी कार्यस्थल सुविधा मनरेगा के तहत कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रदान किए जाने के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है?
(A) स्थल पर सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल
(B) कार्यस्थल के लिए निःशुल्क दैनिक परिवहन
(C) आपातकालीन चिकित्सा उपचार के लिए सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स
(D) विश्राम की अनिवार्य अवधि के लिए पर्याप्त छाया की सुविधा

10. मनरेगा के तहत कार्यस्थल की सुविधाओं (सूची I) का उनके संबंधित वैधानिक प्रावधानों (सूची II) के साथ मिलान कीजिए।
सूची I: (कार्यस्थल की सुविधाएं)
P. पीने का पानी
Q. शिशुगृह सुविधा
R. प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स
S. छाया
सूची II: (वैधानिक प्रावधान)
1. काम के घंटों के दौरान विश्राम की अवधि के लिए अनिवार्य
2. यदि छह वर्ष से कम आयु के पांच से अधिक बच्चे उपस्थित हों तो अनिवार्य
3. कार्यस्थल पर मामूली चोटों और आपात स्थितियों के इलाज के लिए अनिवार्य
4. स्थल पर सभी श्रमिकों के लिए पर्याप्त आपूर्ति अनिवार्य
(A) P-4, Q-2, R-3, S-1
(B) P-2, Q-4, R-1, S-3
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

11. मनरेगा के कार्यान्वयन में ग्राम सभा की भूमिका के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) यह गाँव में शुरु किए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करती है
(B) यह ग्राम पंचायत के भीतर कार्यों के निष्पादन की निगरानी करती है
(C) यह अपने अधिकार क्षेत्र में निष्पादित सभी मनरेगा परियोजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण करती है
(D) यह श्रमिकों को मजदूरी वितरित करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक प्राधिकारी है

12. मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत की जिम्मेदारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त करना और उनका सत्यापन करना।
II. पात्र पंजीकृत परिवारों को जॉब कार्ड जारी करना।
III. काम के लिए आवेदन प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार आवंटित करना।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

13. मनरेगा के संस्थागत ढांचे के अनुसार, वार्षिक ग्राम विकास योजना और परियोजनाओं की सूची को कौन मंजूरी देता है?
(A) खंड विकास अधिकारी
(B) ग्राम सभा
(C) जिला कलेक्टर
(D) राज्य रोजगार गारंटी परिषद

14. मनरेगा के तहत कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के लिए वैधानिक न्यूनतम आवश्यकता क्या है?
(A) कुल श्रमिकों में से एक-चौथाई महिलाएं होनी चाहिए
(B) कुल श्रमिकों में से एक-तिहाई महिलाएं होनी चाहिए
(C) कुल श्रमिकों में से आधी महिलाएं होनी चाहिए
(D) कुल श्रमिकों में से दो-तिहाई महिलाएं होनी चाहिए

15. यदि मनरेगा के तहत किसी कार्यस्थल पर किसी निश्चित दिन 120 श्रमिक कार्यरत हैं, तो महिला श्रमिकों की कानूनी रूप से अनिवार्य न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए?
(A) 30
(B) 40
(C) 50
(D) 60

16. सभी मनरेगा कार्यों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर बनाए रखा जाने वाला मजदूरी लागत और सामग्री लागत का मानक निर्धारित अनुपात क्या है?
(A) 50:50
(B) 60:40
(C) 40:60
(D) 75:25

17. मनरेगा के तहत संपत्ति निर्माण के लिए पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, विशेष रूप से राजस्थान जैसे राज्यों में?
(A) बड़े पैमाने पर शहरी आवास परिसर और वाणिज्यिक क्षेत्र
(B) बहु-लेन राज्य राजमार्ग और एक्सप्रेसवे
(C) औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक बुनियादी ढांचा

Downloaded from www.pdf.tube

70. मनरेगा से जुड़े तकनीकी शब्दों (सूची I) का उनकी विशिष्ट परिभाषाओं/कार्यों (सूची II) के साथ मिलान कीजिए।
सूची I: (तकनीकी शब्द)
P. जॉब कार्ड
Q. मस्टर रोल
R. मापन पुस्तिका
S. नरेगासॉफ्ट
सूची II: (परिभाषाएं/कार्य)
1. योजना के समग्र आंकड़े बनाए रखने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म
2. श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य के भौतिक आउटपुट को दर्ज करने वाला दस्तावेज
3. कार्यस्थल पर दैनिक श्रमिक उपस्थिति दर्ज करने वाला प्राथमिक दस्तावेज
4. पंजीकृत परिवारों को जारी किया गया मूल पहचान पत्र
(A) P-4, Q-3, R-2, S-1
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-4, Q-2, R-3, S-1
(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

71. मनरेगा के लिए प्रस्तावित भावी सुधार, जैसे कि "प्रोजेक्ट उन्नति" (Project LIFE-MGNREGA), निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर बल देते हैं?
(A) श्रमिकों का कौशल विकास करना और टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण करना
(B) अगले दशक के भीतर वैधानिक रोजगार गारंटी योजना को पूरी तरह से समाप्त करना
(C) स्वायत्त रोबोटिक उत्खनन तकनीक के साथ सभी शारीरिक मजदूरी श्रम को व्यवस्थित रुप से प्रतिस्थापित करना
(D) सभी मजदूरी भुगतानों को राष्ट्रीय मुद्रा से अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा अंतरण में परिवर्तित करना

72. मनरेगा में लागू तकनीकी और भावी सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. लक्षित वितरण सुनिश्चित करने और मजदूरी के रिसाव को कम करने के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) को अनिवार्य किया गया है।
II. पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता बढ़ाने के लिए निर्मित संपत्तियों की जियो-टैगिंग का उपयोग किया जा रहा है।
III. ग्राम पंचायत को दरकिनार करने के लिए योजना निष्पादन का पूर्ण निजीकरण शुरू किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

NODIA

73. मनरेगा श्रमिकों के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी पूर्व-आवश्यकता आवश्यक है?
(A) श्रमिक के आधार नंबर को वैध अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट और आव्रजन डेटाबेस के साथ जोड़ना
(B) आधार को बैंक खाते से जोड़ना और इसे NPCI के साथ मैप करना
(C) स्थानीय डाकघर बचत खाते में एक अनिवार्य वापसी योग्य नकद सुरक्षा शुल्क जमा करना
(D) मूल भौतिक जॉब कार्ड को निर्दिष्ट वाणिज्यिक बैंक प्रबंधक को स्थायी रुप से सौंपना

74. मनरेगा में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS) एप्लिकेशन को हाल ही में मुख्य रुप से किस उद्देश्य के लिए पेश किया गया था?
(A) पंजीकृत ग्रामीण श्रमिकों को अनिवार्य विश्राम अवधि के दौरान इंटरैक्टिव शैक्षिक गेम खेलने की अनुमति देने के लिए
(B) श्रमिकों के फोन पर राज्य प्रायोजित कृषि विज्ञापनों और मौसम के अपडेट को सीधे प्रसारित करने के लिए
(C) वास्तविक समय में उपस्थिति और जियो-टैग की गई कार्यस्थल की तस्वीरें कैप्चर करने के लिए
(D) छोटे और सीमांत ग्रामीण किसानों को तत्काल कम ब्याज वाले डिजिटल सूक्ष्म ऋण संसाधित करने और जारी करने के लिए

75. शिकायतों को संभालने, भ्रष्टाचार की जांच करने और मनरेगा के तहत एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करने के लिए, "लोकपाल" (Ombudsman) के रुप में जाना जाने वाला एक स्वतंत्र प्राधिकारी किस प्रशासनिक स्तर पर स्थापित किया गया है?
(A) ग्राम पंचायत स्तर
(B) ब्लॉक/तहसील स्तर
(C) जिला स्तर
(D) राष्ट्रीय स्तर

76. निम्नलिखित में से किस संस्थान की मनरेगा कार्यों के प्रत्यक्ष नियोजन, निष्पादन या लेखापरीक्षा में कोई निर्दिष्ट वैधानिक भूमिका नहीं है?
(A) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
(B) ग्राम सभा
(C) राज्य रोजगार गारंटी परिषद
(D) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG)

77. यदि किसी ग्रामीण परिवार में पति, पत्नी और दो वयस्क बेटे शामिल हैं जो सभी अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, तो मनरेगा के तहत उनके जॉब कार्ड पंजीकरण पर कैसे कार्रवाई की जाएगी?
(A) प्रत्येक वयस्क व्यक्ति के लिए एक-एक करके चार अलग और स्वतंत्र जॉब कार्ड जारी किए जाएंगे
(B) परिवार के लिए एक जॉब कार्ड जारी किया जाएगा

जिसमें सभी वयस्क सदस्यों को सूचीबद्ध किया जाएगा
(C) दो अलग-अलग जॉब कार्ड जारी किए जाएंगे, एक माता-पिता के लिए और एक वयस्क बेटों के लिए
(D) केवल परिवार के नामांकित मुखिया का आधिकारिक रूप से पंजीकरण किया जाएगा और उसे काम करने की अनुमति दी जाएगी

78. मनरेगा के तहत मुख्य समयबद्ध अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वैध आवेदन के 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी किया जाना चाहिए।
II. काम की मांग करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए।
III. मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए।
IV. 15 दिनों के भीतर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, III और IV
(D) I, II, III और IV

79. 100 दिवसीय रोजगार गारंटी सीमा के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) अप्रयुक्त अधिकार के दिन स्वचालित रूप से अगले वित्तीय वर्ष में स्थानांतरित हो जाते हैं
(B) वार्षिक रोजगार के गारंटीकृत 100 दिनों की गणना प्रत्येक वयस्क सदस्य के बजाय प्रति पंजीकृत परिवार के अनुसार सख्ती से की जाती है
(C) एक ही पंजीकृत परिवार से संबंधित कई वयस्क सदस्यों को आपस में 100 दिनों का काम साझा करने की कानूनी रूप से अनुमति है
(D) संबंधित राज्य सरकार को पूरी तरह से अपने राज्य के बजट से वित्तपोषित 100 दिनों से अधिक का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने का पूरा अधिकार है

80. निम्नलिखित ऐतिहासिक ग्रामीण रोजगार योजनाओं को सबसे पहले से सबसे नवीनतम के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)
2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
3. रोजगार आश्वासन योजना (EAS)
4. जवाहर रोजगार योजना (JRY)
सही क्रम का चयन कीजिए:
(A) 4, 3, 1, 2
(B) 3, 4, 1, 2
(C) 4, 1, 3, 2
(D) 1, 3, 4, 2

Click Here to Buy book on Amazon

उत्तर (व्याख्या सहित)

NODIA

1. (C) 2005
भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को वर्ष 2005 में संसद द्वारा कानूनी रूप से पारित किया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक उस परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत अकुशल शारीरिक रोजगार देना है जिसके वयस्क सदस्य ऐसा कार्य करने के इच्छुक हैं। बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया।

2. (C) ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा के समग्र कार्यान्वयन, नीति निर्माण और निगरानी के लिए जिम्मेदार प्रमुख नोडल निकाय है। यह मंत्रालय केंद्रीय स्तर पर धनराशि के आवंटन, राज्यों के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी करने और कार्यक्रम के निष्पादन का मूल्यांकन करने का कार्य करता है। राज्य सरकारें तथा स्थानीय निकाय इस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा निर्धारित कानूनी दिशानिर्देशों के आधार पर ही संचालन सुनिश्चित करते हैं।

3. (B) प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों का अकुशल शारीरिक मजदूरी रोजगार
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक पात्र परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अकुशल शारीरिक मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाती है। यह अधिकार उन ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्राप्त होता है जो स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार होते हैं। यह कानून ग्रामीण आजीविका को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करता है।

4. (D) एक साथ रहने वाले और एक ही रसोई का भोजन साझा करने वाले परिवार के सदस्य
मनरेगा के दिशानिर्देशों के अनुसार जॉब कार्ड आवंटन हेतु "परिवार" की परिभाषा एक साथ रहने वाले और एक ही रसोई से पका हुआ भोजन साझा करने वाले व्यक्तियों के समूह से संबंधित है। इसमें वे सभी रिश्तेदार या व्यक्ति शामिल होते हैं जो एक ही आवास स्थान में निवास करते हैं। एक परिवार के रूप में इस कानूनी पहचान का उद्देश्य वार्षिक सीमा का निर्धारण प्रशासनिक रूप से करना है।

5. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II, कथन I का परिणाम है
मनरेगा कानून के तहत यदि कोई पंजीकृत श्रमिक रोजगार के लिए औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करता है तो सरकार उसे 15 दिनों के भीतर कार्य आवंटित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। यदि प्रशासन निर्धारित 15 दिनों की अवधि के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो आवेदक को दैनिक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार होता है। यह सीधा वैधानिक परिणाम माना जाता है।

6. (C) श्रमिकों के बैंक या डाकघर खातों में प्रत्यक्ष अंतरण
मनरेगा में मजदूरी भुगतान की पारदर्शिता बनाए रखने और रिसाव रोकने के लिए श्रमिकों के बैंक खातों या डाकघर खातों में प्रत्यक्ष बैंक अंतरण को प्राथमिक तंत्र बनाया गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से मजदूरी की राशि सीधे श्रमिक के व्यक्तिगत या संयुक्त खाते में स्थानांतरित की जाती है। नकद भुगतान को समाप्त करके यह प्रणाली बिचौलियों की भूमिका खत्म करती है जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।

7. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक अथवा डाकघर खातों में जमा करना अनिवार्य किया गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू करने का मुख्य उद्देश्य मजदूरी वितरण प्रणाली से बिचौलियों को पूरी तरह समाप्त करना और धन के रिसाव तथा भ्रष्टाचार को रोकना है। खाते में सीधे धन हस्तांतरित होने से पारदर्शिता सुनिश्चित होती है तथा श्रमिकों को पूरी मजदूरी प्राप्त होती है।

8. (A) देरी के प्रति दिन बकाया मजदूरी का 0.05 प्रतिशत
मनरेगा प्रावधानों के अनुसार मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान होना अनिवार्य है। यदि भुगतान में 15 दिनों से अधिक का विलंब होता है तो संबंधित श्रमिक देरी की अवधि के लिए प्रति दिन बकाया मजदूरी का 0.05% के हिसाब से विलंब मुआवजा प्राप्त करने का वैधानिक हकदार बन जाता है। यह प्रावधान प्रशासनिक निकायों को समयबद्ध कार्य हेतु जवाबदेह बनाता है।

9. (B) कार्यस्थल के लिए निःशुल्क दैनिक परिवहन
मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत कार्यस्थल पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए पेयजल, विश्राम के लिए छाया, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तथा बच्चों के लिए शिशुगृह की व्यवस्था करना अनिवार्य वैधानिक कार्यस्थल सुविधाएं हैं। हालांकि, कार्यस्थल तक आने-जाने के लिए निःशुल्क दैनिक परिवहन सुविधा प्रदान करना कानूनन अनिवार्य नहीं है। दूरी अधिक होने पर अतिरिक्त मजदूरी भत्ता दिए जाने का कानूनी प्रावधान रखा गया है।

10. (A) P-4, Q-2, R-3, S-1
मनरेगा के तहत कार्यस्थल पर विभिन्न सुविधाएं अनिवार्य रूप से प्रदान की जाती हैं। पीने के पानी की पर्याप्त आपूर्ति सभी श्रमिकों के लिए अनिवार्य है। यदि कार्यस्थल पर छह वर्ष से कम आयु के पांच से अधिक बच्चे मौजूद हैं तो शिशुगृह सुविधा

अधिनियम' कर दिया गया। हालांकि, इस प्रक्रिया से कानूनी गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या स्वतः बढ़कर 150 दिन नहीं हुई, बल्कि मूल सीमा 100 दिन रही।

33. (D) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
मनरेगा के वैधानिक निर्माण के समय कई पूर्ववर्ती ग्रामीण रोजगार और आजीविका योजनाओं का इसमें विलय किया गया था, जिनमें काम के बदले अनाज कार्यक्रम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन योजना शामिल थीं। इसके विपरीत, 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' एक प्रत्यक्ष आय सहायता योजना है जिसे वर्ष 2019 में शुरु किया गया था। इसका इसमें विलय नहीं हुआ है।

34. (B) 15 दिन
मनरेगा के वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार श्रमिकों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मस्टर रोल बंद होने की तिथि के 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान की पूरी प्रक्रिया संपन्न की जानी चाहिए। इसमें कार्य का भौतिक मापन, मजदूरी सूची बनाना और राशि सीधे बैंक खाते में जमा कराना शामिल है। 15 दिनों के बाद विलंब पर मुआवजा देय होता है।

35. (B) यह योजना पूरी तरह से भारी मशीनों पर निर्भर है, जिससे सभी अकुशल शारीरिक मजदूरी रोजगार समाप्त हो गए हैं
मनरेगा की प्रमुख चुनौतियों में मस्टर रोल में फर्जी नाम दर्ज होना, परिसंपत्तियों के टिकाऊपन पर सवाल उठना और मजदूरी भुगतान में होने वाली प्रशासनिक देरी शामिल हैं। हालांकि, यह कहना गलत है कि यह योजना भारी मशीनों पर निर्भर है। मनरेगा के नियमों के तहत मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध है, क्योंकि यह कानून अकुशल मानव श्रम को रोजगार देता है।

36. (D) मजदूरी चुराने के लिए मस्टर रोल में दर्ज फर्जी या मृतक व्यक्ति
मनरेगा के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के संदर्भ में "फर्जी श्रमिक" उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो वास्तविकता में अस्तित्व में नहीं हैं, अथवा मृत हो चुके हैं या कार्यस्थल पर कभी उपस्थित नहीं हुए। बिचौलियों द्वारा मस्टर रोल में ऐसे नाम दर्ज करके धन का गबन किया जाता है। इसे रोकने हेतु बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू की गई है।

37. (A) गाँव के कार्यों को निष्पादित करने के लिए निजी ठेकेदारों को किराए पर लेना
मनरेगा के वैधानिक कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के तहत गाँव के विकास कार्यों के निष्पादन हेतु निजी ठेकेदारों को शामिल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ठेकेदारी प्रथा को प्रतिबंधित करने का मुख्य कारण मध्यस्थों द्वारा अकुशल मजदूरों का शोषण रोकना तथा पूरी मजदूरी राशि का सीधा भुगतान श्रमिकों को सुनिश्चित करना है। स्थानीय कार्यों का निष्पादन ग्राम पंचायतों तथा पंजीकृत अकुशल श्रमिकों द्वारा ही किया जाता है।

38. (D) I, II, III और IV
मनरेगा के तहत कार्यस्थल पर अनिवार्य मानवीय सुविधाएं प्रदान करने के वैधानिक प्रावधान हैं। हालांकि प्रशासनिक उपेक्षा के कारण कार्यस्थल लेखापरीक्षा में अक्सर पेयजल की कमी, भीषण गर्मी में विश्राम हेतु छाया का अभाव, प्राथमिक चिकित्सा किट की अनुपलब्धता तथा पांच से अधिक बच्चे होने पर भी शिशुगृह सुविधाओं का न होना जैसी गंभीर कमियां उजागर होती हैं। यह उल्लंघन माना जाता है।

39. (A) जलसंभर विकास और सिंचाई क्षमता को बढ़ाना
मनरेगा का प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ अभिसरण मुख्य रुप से ग्रामीण क्षेत्रों में जलसंभर विकास और सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लक्ष्य पर केंद्रित है। इस तालमेल के माध्यम से मनरेगा के अकुशल श्रम का उपयोग चेक डैमों, तालाबों, वर्षा जल संचयन संरचनाओं और नहरों के निर्माण में किया जाता है। इससे कृषि भूमि को टिकाऊ जल संसाधन प्राप्त होते हैं।

40. (D) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) - व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (IHHL)
मनरेगा का विभिन्न केंद्रीय ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ अभिसरण परिसंपत्तियों के प्रभावी निर्माण में मदद करता है। स्वच्छ भारत मिशन के साथ मनरेगा का अभिसरण व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के निर्माण से संबंधित है। इसमें शौचालय निर्माण के लिए अकुशल शारीरिक श्रम घटकों का वित्तपोषण मनरेगा निधि द्वारा किया जाता है, जिससे ग्रामीण स्वच्छता स्तर में व्यापक सुधार लाया जा सका है।

41. (B) नरेगासॉफ्ट (NREGASoft)
मनरेगा के अंतर्गत देश भर में निष्पादित सभी गतिविधियों का पारदर्शी और केंद्रीकृत रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए 'नरेगासॉफ्ट' नामक प्रबंधन सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह वेब-आधारित सॉफ्टवेयर पंजीकृत श्रमिकों के विवरण, जॉब कार्ड, कार्य आवंटन, मस्टर रोल, परिसंपत्ति निर्माण और मजदूरी भुगतान तक के आंकड़ों को डिजिटल रुप से ट्रैक करता है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है।

42. (A) 2, 4, 1, 3
मनरेगा में मजदूरी भुगतान का एक तार्किक प्रशासनिक क्रम होता है। सबसे पहले कार्यस्थल पर मस्टर रोल पर दैनिक उपस्थिति दर्ज की जाती है। कार्य समाप्त होने पर तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य का भौतिक मापन किया जाता है। भौतिक मापन के आधार पर मजदूरी सूची का निर्माण होता है। अंत में, फंड ट्रांसफर ऑर्डर डिजिटल रूप से तैयार किया जाता है।

43. (D) संपत्तियों को डिजिटली सत्यापित करने और दोहरे बिलिंग को रोकने के लिए
मनरेगा के तहत निर्मित सभी ग्रामीण परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग मुख्य रूप से संपत्तियों को डिजिटली सत्यापित करने और दोहरे बिलिंग या कागजी परिसंपत्तियों के निर्माण जैसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लागू की गई है। इस प्रक्रिया में

Downloaded from www.pdf.tube

सत्यापन करते हैं। यह प्रक्रिया निष्पादन संबंधी वित्तीय विसंगतियों, फर्जी प्रविष्टियों और भ्रष्टाचार को उजागर करने का कार्य करती है ताकि लाभ सीधे वास्तविक लाभार्थियों को मिल सके।

22. (B) पंजीकरण, जॉब कार्ड जारी करना, काम की मांग, काम का आवंटन
मनरेगा के तहत आजीविका प्राप्त करने की प्रक्रिया का एक निश्चित प्रशासनिक क्रम है। सबसे पहले ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराना होता है। इसके बाद पात्र परिवार को आधिकारिक जॉब कार्ड जारी किया जाता है। जॉब कार्ड मिलने के बाद श्रमिक काम की लिखित मांग प्रस्तुत करते हैं। मांग जमा होने के 15 दिनों के भीतर काम का आवंटन किया जाता है।

23. (C) 100 अतिरिक्त दिन
राजस्थान सरकार ने राज्य की विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों जैसे सहरिया, खैरवा और काथोड़ी जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए मनरेगा के तहत विशेष प्रावधान किए हैं। इन विशिष्ट जनजातीय परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त 100 दिनों के रोजगार के अतिरिक्त 100 दिनों का पूरक रोजगार राज्य बजट से दिया जाता है, जिससे उन्हें कुल 200 दिनों की सुरक्षा मिलती है।

24. (D) केंद्र सरकार अकुशल शारीरिक श्रम की 100% लागत वहन करती है
मनरेगा के वित्तीय ढांचे के अंतर्गत प्रथम 100 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम के लिए दी जाने वाली पूरी मजदूरी लागत (100%) केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। हालांकि सामग्री लागत और कुशल श्रमिकों के वेतन का व्यय केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के अनुपात में साझा किया जाता है। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी भत्ते का भुगतान राज्य सरकार करती है।

25. (D) कथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।
मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण कराने की कानूनी जिम्मेदारी किसी निजी व्यावसायिक लेखापरीक्षा फर्म की नहीं होती, बल्कि यह मुख्य रूप से ग्राम सभा द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक समुदाय-आधारित पारदर्शी तंत्र है। ग्राम सभा के पास अपने अधिकार क्षेत्र में निष्पादित सभी स्थानीय कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करने का वैधानिक अधिकार और दायित्व है। राज्य इकाइयां केवल सहायता प्रदान करती हैं।

26. (C) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)
ग्रामीण क्षेत्रों में पूरक मजदूरी रोजगार तथा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की गई थी। इस योजना में नकद मजदूरी के साथ खाद्यान्न वितरण शामिल था। जब वर्ष 2005 में अधिनियम लाया गया, तब इस योजना का पूर्ण विलय नरेगा में कर दिया गया ताकि रोजगार का एकीकृत वैधानिक ढांचा बनाया जा सके।

27. (B) 1993
कृषि के मंदी वाले मौसम के दौरान ग्रामीण निर्धन परिवारों को अतिरिक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1993 में 'रोजगार आश्वासन योजना' का शुभारंभ किया गया था। यह योजना मनरेगा की एक महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती व्यवस्था थी। इसके तहत देश के पिछड़े ग्रामीण ब्लॉकों में रोजगार प्रदान किया जाता था जो बाद में कानून हेतु उपयोगी सिद्ध हुआ।

28. (A) SGRY आवंटन-आधारित थी, जबकि मनरेगा एक अधिकार-आधारित गारंटी है
पूर्ववर्ती योजनाओं जैसे SGRY और मनरेगा के बीच सबसे मौलिक अंतर उनके कानूनी दृष्टिकोण का है। SGRY एक बजटीय आवंटन-आधारित योजना थी, जिसमें रोजगार देना वित्तीय उपलब्धता पर निर्भर करता था। इसके विपरीत, मनरेगा एक मांग-संचालित कानूनी अधिकार-आधारित गारंटी है। इसमें सरकार पात्र ग्रामीणों द्वारा काम मांगे जाने पर 15 दिनों में रोजगार प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होती है।

29. (B) महाराष्ट्र रोजगार गारंटी योजना
1970 के दशक में शुरू की गई महाराष्ट्र रोजगार गारंटी योजना भारत में पहली ऐसी अग्रणी राज्य-स्तरीय पहल थी जिसने ग्रामीण मजदूरों को काम मांगने पर रोजगार का वैधानिक अधिकार प्रदान किया था। इस ऐतिहासिक योजना की सफलता और इसके अधिकार-आधारित मॉडल ने प्रभाव डाला। अंततः इसी मॉडल के अनुभवों को अपनाकर पूरे देश के लिए राष्ट्रीय कानून पारित किया गया।

NODIA

30. (A) P-4, Q-2, R-1, S-3
भारत में विभिन्न कालखंडों में ग्रामीण रोजगार योजनाएं शुरू की गईं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को संसद द्वारा 2005 में पारित किया गया। इससे पूर्व संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ 2001 में हुआ था। ग्रामीण निर्धनों के लिए रोजगार आश्वासन योजना 1993 में शुरू की गई थी, जबकि काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम 2004 में प्रारंभ हुआ था।

31. (A) कम कृषि मांग के दौरान वैकल्पिक आय सहायता प्रदान करके
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य मौसमी प्रकृति के होते हैं, जिससे बुवाई और कटाई के बीच के मंदी वाले समय में अकुशल मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाता है। मनरेगा इस मंदी की अवधि में ग्रामीण निर्धनों को अकुशल शारीरिक कार्य के माध्यम से वैकल्पिक आय सहायता और आजीविका सुरक्षा प्रदान करती है। इससे संकटग्रस्त पलायन पर रोक लगती है।

32. (A) केवल I और II
ग्रामीण रोजगार कानून मूल रूप से 2005 में 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' के नाम से पारित किया गया था। महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी

77. (B) परिवार के लिए एक जॉब कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें सभी वयस्क सदस्यों को सूचीबद्ध किया जाएगा
मनरेगा दिशानिर्देशों के अंतर्गत जॉब कार्ड व्यक्तिगत रूप से जारी नहीं किया जाता, बल्कि संपूर्ण "परिवार" को एक इकाई मानकर एक ही संयुक्त जॉब कार्ड जारी किया जाता है। यदि किसी परिवार में पति, पत्नी और दो वयस्क बेटे हैं, तो उन सभी चार वयस्क सदस्यों के नाम उसी एक पारिवारिक जॉब कार्ड में सूचीबद्ध किए जाएंगे। वे 100 दिनों का काम साझा कर सकते हैं।

78. (D) I, II, III और IV
मनरेगा कानून में पारदर्शी कार्यान्वयन के लिए 15 दिनों की समयबद्ध कानूनी समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इसके तहत आवेदन करने पर 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी होना चाहिए। मांग प्रस्तुत करने के 15 दिनों में काम मिलना अनिवार्य है। 15 दिनों में मजदूरी का भुगतान होना चाहिए तथा 15 दिनों में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देय होता है।

79. (A) अप्रयुक्त अधिकार के दिन स्वचालित रूप से अगले वित्तीय वर्ष में स्थानांतरित हो जाते हैं
मनरेगा के तहत प्रत्येक पंजीकृत परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अकुशल रोजगार का अधिकार प्राप्त होता है। यह अधिकार प्रति परिवार के आधार पर होता है जिसे वयस्क सदस्य आपस में बांट सकते हैं। हालांकि, यदि कोई परिवार वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का उपयोग नहीं करता है, तो वे अप्रयुक्त दिन अगले वित्तीय वर्ष में स्थानांतरित नहीं होते हैं।

80. (A) 4, 3, 1, 2
भारत में समय-समय पर ग्रामीण आजीविका और रोजगार की दिशा में विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए। इनका सही कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है: जवाहर रोजगार योजना वर्ष 1989 में, रोजगार आश्वासन योजना वर्ष 1993 में, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में, और अंततः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जो ऐतिहासिक कदम रहा।

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Flipkart

संपत्ति के जीपीएस निर्देशांक और तस्वीरें अपलोड की जाती हैं। इससे निर्मित संरचनाओं का सटीक स्थान पता चलता है तथा पारदर्शिता बढ़ती है।

44. (A) इसने विपरीत प्रवास (reverse migration) के दौरान एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल के रूप में कार्य किया
कोविड-19 महामारी के दौरान जब देशव्यापी तालाबंदी लागू हुई, तो शहरों से लाखों असंगठित श्रमिक ग्रामीण इलाकों की ओर वापस लौटे। इस अभूतपूर्व विपरीत प्रवास के समय मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य किया। इस योजना ने संकट में पड़े प्रवासी मजदूरों को गांव में तत्काल रोजगार देकर मदद की।

45. (D) कथन (A) गलत है परंतु कारण (R) सही है।
कृषि संकट या सूखे के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक कृषि रोजगार घट जाता है, जिसके कारण मनरेगा के तहत काम की मांग में गिरावट के बजाय भारी वृद्धि होती है। सूखाग्रस्त परिस्थितियों में कृषि आय समाप्त होने पर ग्रामीण मजदूर आजीविका हेतु मनरेगा पर निर्भर हो जाते हैं। हालांकि, सूखे के समय मजबूरी में ग्रामीण आबादी का शहरों की ओर पलायन भी होता है।

46. (B) श्रमिक खातों में सीधे इलेक्ट्रॉनिक मजदूरी अंतरण सुनिश्चित करना
मनरेगा ढांचे के तहत लागू इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम का प्राथमिक कार्य केंद्रीय और राज्य निधियों से सीधे पंजीकृत श्रमिकों के बैंक अथवा डाकघर खातों में पारदर्शी रूप से इलेक्ट्रॉनिक मजदूरी अंतरण सुनिश्चित करना है। इस प्रणाली के माध्यम से मध्यवर्ती खातों में धन के अटकने और नकद वितरण की धांधली समाप्त हो जाती है। यह पारदर्शी अंतरण सुनिश्चित करता है।

47. (A) कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL)
मनरेगा के तहत अकुशल शारीरिक श्रमिकों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी दरों में प्रतिवर्ष संशोधन किया जाता है। ये संशोधन मुख्य रूप से कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) से जुड़े होते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की लागत को समायोजित करने के लिए मजदूरी बढ़ाई जाती है।

48. (C) केंद्र सरकार द्वारा राज्यवार मजदूरी दरें अधिसूचित की जाती हैं
मनरेगा अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार अकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण और आधिकारिक अधिसूचना प्रतिवर्ष केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। यह मजदूरी दर प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग-अलग अधिसूचित की जाती है जो स्थानीय जीवन यापन लागत पर आधारित होती है। पंचायतें इसे बदल नहीं सकतीं।

49. (B) 18 वर्ष
मनरेगा के तहत पंजीकृत होने और अकुशल शारीरिक मजदूरी रोजगार मांगने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष होनी अनिवार्य है। भारत में बाल श्रम निषेध कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केवल वयस्क ग्रामीण नागरिकों (18 वर्ष या उससे अधिक आयु) को ही इस योजना में जॉब कार्ड में नामांकित कर काम दिया जाता है।

50. (A) P-4, Q-3, R-2, S-1
मनरेगा का कार्यान्वयन विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर फैला हुआ है। ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर पंजीकरण आवेदन प्राप्त करती है और जॉब कार्ड जारी करती है। ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी योजनाओं को समेकित करता है। जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक योजना की निगरानी करता है, जबकि राज्य परिषद राज्य स्तर पर सरकार को सलाह प्रदान करने का कार्य करती है।

51. (B) मिट्टी के कार्यों के लिए भारी मशीनों का अनिवार्य उपयोग
मनरेगा की मुख्य विशेषताओं में स्थानीय ग्राम सभाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत योजना बनाना, प्रति परिवार 100 दिनों के अकुशल रोजगार का कानूनी अधिकार देना और काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का वैधानिक प्रावधान शामिल है। हालांकि, मिट्टी के कार्यों के लिए भारी मशीनों का उपयोग इसके सिद्धांतों के विपरीत है। यह योजना अकुशल मानव श्रम को ही प्राथमिकता देती है।

52. (A) केवल I और II
मनरेगा के तहत कार्यों के निष्पादन के लिए निजी ठेकेदारों को शामिल करना सख्त रूप से प्रतिबंधित है तथा श्रम-विस्थापित करने वाली भारी मशीनों का उपयोग मना है। हालांकि, यह योजना विशेष रूप से केवल कुशल कारीगरों के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के काम की कानूनी गारंटी प्रदान करना है।

53. (A) मजदूरी दर का अतिरिक्त 10%
मनरेगा प्रावधानों के अनुसार श्रमिकों को सामान्यतः उनके निवास स्थान से 5 किलोमीटर की त्रिज्या के भीतर ही रोजगार आवंटित किया जाता है। यदि प्रशासन 5 किलोमीटर की इस सीमा से बाहर कार्य प्रदान करता है, तो यात्रा व्यय की भरपाई के लिए संबंधित श्रमिक निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर का अतिरिक्त 10% भत्ते के रूप में प्राप्त करने का कानूनी हकदार होता है।

54. (B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं परंतु एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं
ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के प्रशासनिक रिकॉर्ड, आवेदन पंजीकरण और मस्टर रोल प्रबंधन में सहायता करने के लिए जिम्मेदार कर्मचारी होता है। दूसरी ओर, "मेट" कार्यस्थल पर तैनात एक स्थानीय पर्यवेक्षक होता है जो श्रमिकों की दैनिक उपस्थिति दर्ज करता है और कार्यस्थल

Downloaded from www.pdf.tube

निरीक्षण करता है। दोनों पद अपनी अलग-अलग और स्वतंत्र भूमिकाएं निष्पादित करते हैं।

55. (A) स्थानीय महिला श्रमिकों को
मनरेगा के अंतर्गत कार्यस्थल पर्यवेक्षण को पारदर्शी बनाने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशिक्षित महिला श्रमिकों को कार्यस्थल 'मेट' के रूप में नियुक्त करने हेतु अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है। महिला मेटों की नियुक्ति से कार्यस्थल पर महिलाओं की उपस्थिति में वृद्धि होती है तथा महिलाओं में नेतृत्व क्षमता एवं प्रशासनिक कौशल विकसित होता है। इससे सशक्तिकरण बढ़ता है।

56. (D) शुष्क जलवायु, भूजल क्षरण और सूखे के प्रभावों को कम करना
राजस्थान एक मुख्य रूप से शुष्क और अर्ध-शुष्क भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है जहाँ अनियमित वर्षा, जल संकट और सूखा पड़ने की समस्या बनी रहती है। इसलिए राज्य में मनरेगा के तहत जोहड़ और चेक डैम जैसे जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। इन संरचनाओं के निर्माण से भूजल स्तर रीचार्ज होता है तथा सूखे के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है।

57. (B) पूरी तरह से राज्य सरकार अपने स्वयं के बजट से
राजस्थान में 'मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' के अंतर्गत, केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त 100 दिनों का मनरेगा रोजगार पूरा करने वाले सामान्य ग्रामीण परिवारों को 25 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाता है। केंद्र का दायित्व केवल 100 दिनों तक सीमित है, इसलिए इन अतिरिक्त 25 दिनों के रोजगार का पूरा वित्तीय खर्च राजस्थान राज्य सरकार अपने बजट से वहन करती है।

58. (A) केवल I, II और III
राजस्थान में मनरेगा के विशिष्ट कार्यान्वयन के तहत 100 दिन पूरे करने वाले सामान्य परिवारों को राज्य सरकार द्वारा 25 अतिरिक्त दिन का काम दिया जाता है, जबकि सहरिया और काथोड़ी जैसी विशेष जनजातियों को कुल 200 दिनों के काम की पात्रता हासिल है। राज्य में जल संरक्षण कार्य प्रमुख हिस्सा हैं। महिलाओं को छूट नहीं दी गई है, बल्कि प्रोत्साहन दिया जाता है।

59. (D) किसानों के लिए निजी स्विमिंग पूल का निर्माण
राजस्थान में मनरेगा के तहत कार्यों की निगरानी सामाजिक अंकेक्षण द्वारा की जाती है, जलसंभर विकास के साथ श्रम का अभिसरण होता है तथा भुगतान आधार प्रणाली से होते हैं। हालांकि, किसानों के लिए निजी स्विमिंग पूल का निर्माण करना मनरेगा में अनुमत नहीं है। मनरेगा केवल जल संचयन और बुनियादी ढांचा जैसी सार्वजनिक तथा पात्र व्यक्तिगत संपत्तियों की अनुमति देता है।

60. (A) महाराष्ट्र
1970 के दशक में शुरु की गई 'महाराष्ट्र रोजगार गारंटी योजना' भारत में अधिकार-आधारित रोजगार मॉडल की जनक मानी जाती है। इस योजना ने सर्वप्रथम ग्रामीण नागरिकों को काम मांगने पर रोजगार पाने का विधिक अधिकार दिया था। इसके सफल संचालन और प्रभावों का अध्ययन करके ही केंद्र सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर कानून का वैधानिक खाका तैयार किया।

61. (B) ग्राम सभा
मनरेगा कानून के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी भी ग्राम पंचायत के भीतर निष्पादित किए गए सभी विकास कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए केवल 'ग्राम सभा' को ही अधिकृत किया गया है। ग्राम सभा स्थानीय ग्रामीणों और श्रमिकों की बैठक आयोजित करके मस्टर रोल तथा खर्च का सार्वजनिक सत्यापन करती है ताकि योजना में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे।

62. (B) ग्राम पंचायत द्वारा रिकॉर्ड तैयार करना, सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा सत्यापन, ग्राम सभा में प्रस्तुति, सुधारात्मक कार्रवाई
मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण की एक स्पष्ट चरणबद्ध वैधानिक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले ग्राम पंचायत द्वारा सभी भौतिक और वित्तीय रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं। इसके बाद स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई इन रिकॉर्डों और संपत्तियों का सत्यापन करती है। तीसरे चरण में निष्कर्षों को ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। अंत में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

63. (A) वनीकरण - सूखा रोधन
मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सूखा रोधन गतिविधि के रुप में व्यापक पैमाने पर वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यों को स्वीकृत किया गया है। पेड़ों का रोपण करने से पर्यावरण संतुलन बेहतर होता है, मृदा अपरदन रुकता है और जल संचयन बढ़ता है, जिससे सूखे के प्रभावों को रोकने में मदद मिलती है। यह पर्यावरण सुधार का प्रमुख स्वीकृत कार्य माना जाता है।

64. (C) यांत्रिक पेवर का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन
मनरेगा कानून का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और अकुशल मानव श्रम को रोजगार प्रदान करना है। इसके तहत ग्रामीण संपर्क सड़कों, कच्ची सड़कों और पुलियों का निर्माण अनुमत है। हालांकि, यांत्रिक पेवर का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन करना मनरेगा में अनुमत नहीं है, क्योंकि यह अत्यधिक मशीनीकृत कार्य है जो श्रम सिद्धांतों के विरुद्ध है।

65. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
मनरेगा ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। इस कानून में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान मजदूरी का वैधानिक प्रावधान किया गया है तथा कार्यबल में कम से कम एक-तिहाई हिस्सा महिलाओं का होना अनिवार्य बनाया गया है। इससे महिलाओं को सीधे स्वतंत्र आय प्राप्त होती है।

NODIA

66. (C) ग्राम पंचायत स्तर
मनरेगा के तहत योजनाओं के श्रम-प्रधान स्वरुप को बनाए रखने के लिए मजदूरी और सामग्री लागत का 60:40 अनुपात आकलित किया जाता है। अधिनियम के अनुसार इस निर्धारित 60:40 के वित्तीय अनुपात को संपूर्ण ग्राम पंचायत स्तर पर बनाए रखना वैधानिक रूप से अनिवार्य है। यद्यपि किसी एकल कार्य में सामग्री अधिक हो सकती है, परंतु पंचायत का औसत 60:40 होना चाहिए।

67. (B) हां, पात्र सीमांत किसानों की निजी भूमि पर भूमि विकास कार्यों की अनुमति है
यद्यपि मनरेगा का ध्यान मुख्य रुप से सार्वजनिक सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर रहता है, लेकिन कानून में विशिष्ट श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पात्र छोटे या सीमांत किसानों की निजी भूमि पर परिसंपत्तियों निर्माण की स्पष्ट अनुमति दी गई है। ये किसान अपनी भूमि विकास और कुओं की खुदाई हेतु मनरेगा सहायता प्राप्त कर सकते हैं जिससे सुधार होता है।

68. (C) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है
मनरेगा दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों को आवेदक श्रमिक के गाँव के 5 किलोमीटर के दायरे में ही काम प्रदान करना अनिवार्य होता है। हालांकि, यह सोचना गलत है कि 5 किमी से बाहर काम मिलने पर अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलता। वास्तव में, यदि कार्यस्थल 5 किमी से बाहर दिया जाता है तो श्रमिक 10% अतिरिक्त भत्ता पाने का हकदार होता है।

69. (A) करेंसी नोटों की छपाई और ढलाई करना
मनरेगा के तहत ग्राम सभा के पास स्थानीय स्तर पर व्यापक वैधानिक अधिकार हैं। इनमें स्थानीय ग्राम विकास योजनाओं को तैयार करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करना, योजनाओं को मंजूरी देना तथा सामाजिक अंकेक्षण करना शामिल है। इसके विपरीत, करेंसी नोटों की छपाई करना भारतीय रिजर्व बैंक का संप्रभु कार्य है जिसका ग्राम सभा की वैधानिक भूमिका से कोई संबंध नहीं है।

70. (A) P-4, Q-3, R-2, S-1
मनरेगा में विभिन्न तकनीकी शब्दों का विशिष्ट प्रयोग होता है। जॉब कार्ड पंजीकृत ग्रामीण परिवारों को जारी किया जाने वाला मूल पहचान पत्र है। मस्टर रोल कार्यस्थल पर दैनिक श्रमिक उपस्थिति दर्ज करने का प्राथमिक दस्तावेज है। मापन पुस्तिका भौतिक कार्य के आउटपुट को दर्ज करने वाला दस्तावेज है, जबकि नरेगासॉफ्ट योजना के समग्र आंकड़ों को डिजिटल रुप से बनाए रखने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

71. (A) श्रमिकों का कौशल विकास करना और टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण करना
मनरेगा के तहत 'प्रोजेक्ट उन्नति' जैसे भावी सुधार पहलों का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत अकुशल श्रमिकों के कौशल स्तर का उन्नयन करना है ताकि वे आजीविका के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, इन पहलों का जोर परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करके टिकाऊ ग्रामीण संपत्तियों का निर्माण करना है। श्रमिकों को प्रशिक्षित बनाकर सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है।

72. (A) केवल I और II
मनरेगा में हाल के तकनीकी सुधारों के तहत लक्षित वित्तीय वितरण सुनिश्चित करने और मजदूरी के रिसाव को पूरी तरह समाप्त करने के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली को अनिवार्य किया गया है। साथ ही, निर्मित परिसंपत्तियों की पारदर्शिता हेतु जियो-टैगिंग का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। हालांकि, पंचायतों को दरकिनार करके निष्पादन का पूर्ण निजीकरण नहीं किया गया है।

73. (B) आधार को बैंक खाते से जोड़ना और इसे NPCI के साथ मैप करना
मनरेगा श्रमिकों के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली के सफल कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक शर्त यह है कि श्रमिक का आधार नंबर उनके संबंधित बैंक खाते से अनिवार्य रूप से लिंक होना चाहिए। इसके साथ ही, उस बैंक खाते का NPCI मैपर के साथ सफलतापूर्वक मैप होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया से मजदूरी का हस्तांतरण सीधे सही खाते में होता है।

74. (C) वास्तविक समय में उपस्थिति और जियो-टैग की गई कार्यस्थल की तस्वीरें कैप्चर करने के लिए
मनरेगा में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एप्लिकेशन का उपयोग मुख्य रूप से कार्यस्थल पर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से कार्यस्थल पर श्रमिकों की वास्तविक समय की उपस्थिति और जियो-टैग तस्वीरें सीधे अपलोड की जाती हैं। इससे फर्जी उपस्थिति और मस्टर रोल धांधली पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलती है।

75. (C) जिला स्तर
मनरेगा के तहत शिकायतों का त्वरित समाधान करने, भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच करने तथा पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला स्तर पर 'लोकपाल' की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। जिला स्तरीय लोकपाल एक स्वतंत्र प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है जो शिकायतों की निष्पक्ष जांच करता है और आवश्यक आदेश पारित करने का कार्य करता है।

76. (A) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
मनरेगा के योजना संचालन में विभिन्न संस्थानों की विशिष्ट वैधानिक भूमिकाएं हैं। ग्राम सभा नियोजन करती है, राज्य परिषद सलाह देती है, और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा करते हैं। इसके विपरीत, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी मनरेगा के नियोजन, निष्पादन या प्रत्यक्ष अंकेक्षण में कोई विशिष्ट वैधानिक भूमिका या प्रत्यक्ष दायित्व निर्धारित नहीं किया गया है।

Click Here to Buy book on Amazon

P. ग्राम पंचायत
Q. पंचायत समिति
R. जिला परिषद
S. ग्राम सभा

सूची II: (प्रशासनिक अधिकारी)
1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)
2. ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ)
3. खंड विकास अधिकारी (बीडीओ)
4. कोई विशिष्ट समर्पित प्रशासनिक प्रमुख नहीं

(A) P-3, Q-2, R-1, S-4
(B) P-2, Q-3, R-1, S-4
(C) P-2, Q-1, R-3, S-4
(D) P-1, Q-3, R-2, S-4

10. राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और कर राजस्व के वितरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। इसका गठन किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत किया जाता है?
(A) अनुच्छेद 243G
(B) अनुच्छेद 243H
(C) अनुच्छेद 243I
(D) अनुच्छेद 243K

11. पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए 'ई-ग्राम स्वराज' पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या प्रदान करना है?
(A) पंचायत गतिविधियों की योजना, लेखांकन और निगरानी के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच
(B) ग्रामीण किसानों को कृषि वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण तंत्र
(C) ग्रामीण स्थानीय चुनावों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और अभ्यर्थी सत्यापन पोर्टल
(D) ग्रामीण स्कूली बच्चों के लिए डिज़ाइन किए गए डिजिटल ई-लर्निंग और शैक्षिक मॉड्यूल

12. पंचायती राज शासन के संदर्भ में, संरचनात्मक चुनौती जिसे अक्सर "3एफ (3F) की समस्या" कहा जाता है, मुख्य रुप से किसके अपर्याप्त हस्तांतरण को दर्शाती है?
(A) खाद्य, चारा और ईंधन संसाधन
(B) वन, मत्स्य पालन और कृषि संपत्ति
(C) धन, कार्य और कार्यकर्ता (Funds, Functions, Functionaries)
(D) वित्त, प्रारुप और प्रतिपुष्टि उपकरण

13. ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) निर्माण प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. ग्राम सभा में जीपीडीपी का अनुमोदन
2. आवश्यकताओं का आकलन और स्थितिजन्य विश्लेषण
3. विकास योजना का परियोजनाकरण और अंतिम रुप देना
4. ग्राम पंचायत योजना सुविधा दल का गठन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए:
(A) 4, 2, 3, 1
(B) 2, 4, 3, 1
(C) 4, 3, 2, 1
(D) 2, 3, 4, 1

14. पंचायती राज संस्थाएं निम्नलिखित में से किस प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना के लिए प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी के रुप में कार्य करती हैं?
(A) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
(B) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
(C) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
(D) आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना

15. जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) को पारंपरिक रुप से किसके लिए स्थापित किया गया था?
(A) जिला परिषद के लिए जिला स्तरीय स्थानीय चुनाव कराना
(B) गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रबंधन करना
(C) ग्रामीण क्षेत्रों में जटिल भूमि विवादों के लिए मध्यस्थता प्रदान करना
(D) ग्रामों में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और ऋण सहकारिताओं को विनियमित करना

16. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह प्रत्येक स्तर पर पंचायत के लिए पांच वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान करता है।
II. यह प्रत्येक पांच वर्ष में राज्य वित्त आयोग की स्थापना को अनिवार्य बनाता है।
III. यह संसद सदस्यों (सांसदों) को ग्राम सभा की बैठकों में मतदान करने की अनुमति देता है।
IV. यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और IV
(B) केवल I, II और III
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

17. पंचायत समिति की संरचना में आम तौर पर किसे छोड़कर निम्नलिखित सभी शामिल होते हैं?
(A) पदेन अध्यक्ष के रुप में कार्य करने वाला जिला कलेक्टर
(B) खंड के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य
(C) खंड के भीतर ग्राम पंचायतों के सभी सरपंच
(D) विधान सभा के सदस्य (विधायक) जिनके निर्वाचन क्षेत्र खंड के अंतर्गत आते हैं

NODIA

अध्याय 27
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास

1. भारत में आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक उद्घाटन राजस्थान में किया गया था। यह ऐतिहासिक आयोजन किस जिले में और किस तिथि को हुआ था?
(A) नागौर, 2 अक्टूबर 1959
(B) जयपुर, 15 अगस्त 1959
(C) जोधपुर, 26 जनवरी 1959
(D) उदयपुर, 2 अक्टूबर 1960

2. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, निम्नलिखित में से कौन 'ग्राम सभा' को सही ढंग से परिभाषित करता है?
(A) किसी ग्राम के सभी वयस्क निवासियों से मिलकर बनी एक संस्था
(B) ग्राम पंचायत की निर्वाचित कार्यकारी समिति
(C) ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था
(D) सरपंच द्वारा मनोनीत ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों की परिषद

3. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व को संवैधानिक गारंटी प्रदान करता है।
कारण (R): यह अधिनियम राज्य सरकारों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में प्रत्येक पांच वर्ष में पंचायतों के नियमित चुनाव कराना अनिवार्य बनाता है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

4. निम्नलिखित में से कौन-सा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का एक अनिवार्य प्रावधान नहीं है?
(A) सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की स्थापना
(B) ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव
(C) सभी स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण
(D) पंचायतों को कर, शुल्क और पथकर (टोल) लगाने तथा एकत्र करने की वित्तीय शक्तियां प्रदान करना

5. अनुच्छेद 243K के तहत, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) संबंधित राज्य के राज्यपाल
(C) भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
(D) राज्य के मुख्यमंत्री

6. भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसमें पंचायतों को सौंपे गए 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।
II. इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था।
III. इसमें कृषि, ग्रामीण आवास और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे विषय शामिल हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

7. राजस्थान में, पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का अनिवार्य प्रतिशत क्या है?
(A) 33 प्रतिशत
(B) 50 प्रतिशत
(C) 25 प्रतिशत
(D) 60 प्रतिशत

8. पंचायती राज व्यवस्था का कौन-सा स्तर ग्राम स्तर और जिला स्तर के बीच मध्यवर्ती कड़ी के रूप में कार्य करता है?
(A) पंचायत समिति
(B) ग्राम सभा
(C) जिला परिषद
(D) जिला योजना समिति

9. सूची I में दिए गए पंचायती राज स्तरों को सूची II में राजस्थान में उनके संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (पंचायती राज स्तर)

Downloaded from www.pdf.tube

दी जाती है। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तथा विश्राम के लिए छाया की व्यवस्था कानूनी रूप से अनिवार्य मानी जाती है।

11. (D) यह श्रमिकों को मजदूरी वितरित करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक प्राधिकारी है
मनरेगा के अंतर्गत ग्राम सभा योजना निर्माण, कार्यों की प्राथमिकता तय करने, परियोजनाओं की निगरानी करने तथा सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करने का अधिकार रखती है। हालांकि, ग्राम सभा प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों को मजदूरी वितरित करने वाला प्राधिकारी नहीं है। मजदूरी का भुगतान सीधे बैंकों या डाकघरों में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। ग्राम सभा केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करने का कार्य करती है।

12. (D) I, II और III
मनरेगा अधिनियम के सुचारु संचालन में ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। ग्राम पंचायत ग्रामीण परिवारों से पंजीकरण आवेदन प्राप्त करती है और उनका सत्यापन करती है। इसके बाद पात्र पंजीकृत परिवारों को औपचारिक जॉब कार्ड जारी किए जाते हैं। इसके साथ ही, जब भी कोई पंजीकृत श्रमिक काम मांगता है, तो 15 दिनों के भीतर रोजगार आवंटित करना अनिवार्य होता है।

13. (B) ग्राम सभा
मनरेगा के विकेंद्रीकृत नियोजन ढांचे में ग्राम सभा सबसे शक्तिशाली निर्णय लेने वाला निकाय है। गाँव के विकास की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वार्षिक ग्राम विकास योजना तैयार करना और निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं की अंतिम सूची को मंजूरी देना ग्राम सभा का वैधानिक अधिकार है। स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी से बनी योजना ही स्वीकृति हेतु आगे भेजी जाती है।

14. (B) कुल श्रमिकों में से एक-तिहाई महिलाएं होनी चाहिए
मनरेगा कानून में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वैधानिक प्रावधान शामिल किए गए हैं। अधिनियम के अनुसार योजना के तहत कार्यरत कुल कार्यबल में कम से कम एक-तिहाई महिलाएं होनी चाहिए। यह प्रावधान ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करता है और उन्हें निर्णय लेने तथा श्रम बाजार में पुरुषों के समान मजदूरी प्राप्त करने में मदद करता है।

15. (B) 40
मनरेगा अधिनियम की धारा के अनुसार किसी भी कार्यस्थल पर काम कर रहे कुल श्रमिकों में कम से कम एक-तिहाई संख्या महिला श्रमिकों की होनी चाहिए। यदि किसी कार्यस्थल पर कुल 120 श्रमिक कार्यरत हैं, तो 120 का एक-तिहाई हिस्सा 40 होता है। अतः कानूनी रूप से अनिवार्य न्यूनतम महिला श्रमिकों की संख्या 40 होनी अनिवार्य है। यह नियम भागीदारी को मजबूत करता है।

16. (B) 60:40
मनरेगा योजना के अंतर्गत श्रम-गहन स्वरूप को बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी और सामग्री लागत का मानक अनुपात 60:40 निर्धारित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि कुल व्यय का कम से कम 60% भाग अकुशल शारीरिक श्रम मजदूरी पर और अधिकतम 40% भाग सामग्री तथा कुशल श्रम पर खर्च किया जा सकता है। यह संतुलन रोजगार बढ़ाता है।

17. (D) जल संरक्षण संरचनाएं
राजस्थान जैसे शुष्क और अर्ध-शुष्क राज्यों में मनरेगा के तहत टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति निर्माण के अंतर्गत जल संरक्षण संरचनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। जल संकट से निपटने, भूजल स्तर को सुधारने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जोहड़, चेक डैम और तालाबों के जीर्णोद्धार जैसे कार्यों को लागू किया जाता है। इससे जल सुरक्षा सुदृढ़ होती है।

18. (A) केवल I, II और III
मनरेगा के अंतर्गत पर्यावरण अनुकूल और श्रम-प्रधान सामुदायिक कार्यों को प्राथमिकता से स्वीकृति दी जाती है। इसके तहत चेक डैम तथा रिसाव पोखरों का निर्माण, पारंपरिक जल निकायों जैसे जोहड़ों का जीर्णोद्धार तथा ग्रामीण संपर्क सड़कों के बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। हालांकि, भारी मशीनीकृत उत्खनकों की खरीद अथवा उपयोग सख्त रूप से प्रतिबंधित है, क्योंकि योजना का मूल उद्देश्य अकुशल शारीरिक श्रम द्वारा आजीविका देना है।

19. (B) जोहड़ और मिट्टी के चेक डैम
राजस्थान में मनरेगा कोष का प्रभावी उपयोग करके पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं जैसे जोहड़ और मिट्टी के चेक डैमों का व्यापक जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण किया गया है। ये पारंपरिक मिट्टी के बांध और संरचनाएं वर्षा जल को रोकने, भूजल स्तर को पुनः रिचार्ज करने तथा स्थानीय स्तर पर पेयजल एवं सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई हैं। इससे सुधार हुआ है।

20. (D) शिकायत निवारण - उच्चतम न्यायालय
मनरेगा के प्रशासनिक ढांचे में प्राथमिक पारदर्शिता सामाजिक अंकेक्षण द्वारा सुनिश्चित होती है, वैधानिक पहचान पत्र पारिवारिक जॉब कार्ड है, और दैनिक उपस्थिति कार्यस्थल मस्टर रोल में दर्ज की जाती है। हालांकि, योजना के भीतर प्राथमिक शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर लोकपाल तथा कार्यक्रम अधिकारी कार्यरत हैं। उच्चतम न्यायालय योजना का प्रशासनिक शिकायत निवारण तंत्र नहीं है, बल्कि यह सर्वोच्च न्यायिक संस्थान है।

21. (A) सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना और निष्पादन संबंधी विसंगतियों का पता लगाना
मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाना है। इसके तहत स्थानीय समुदाय और ग्राम सभा मिलकर सरकारी रिकॉर्ड, मस्टर रोल तथा किए गए भौतिक कार्यों का प्रत्यक्ष

NODIA

18. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण ने जमीनी स्तर पर महिला राजनीतिक नेतृत्व के उभराव को सक्षम बनाया है।
कारण (R): "सरपंच पति" की अवधारणा, जहां पुरुष रिश्तेदार वास्तविक नेताओं के रूप में कार्य करते हैं, ने सभी राज्यों में महिला आरक्षण के प्रशासनिक प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

19. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद विशेष रूप से पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है?
(A) अनुच्छेद 243A
(B) अनुच्छेद 243B
(C) अनुच्छेद 243C
(D) अनुच्छेद 243D

20. ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास जनादेश के तहत, ग्राम पंचायतें मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी हैं?
(A) प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, चौड़ीकरण और संरचनात्मक रखरखाव
(B) बड़े पैमाने पर बहु-राज्यीय सिंचाई बांधों का संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण
(C) बहु-विशेषज्ञता तृतीयक देखरेख क्षेत्रीय अस्पतालों की स्थापना और प्रबंधन
(D) ग्रामीण सड़कों, जल निकासी और पेयजल सुविधाओं का रखरखाव

21. ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) "नीचे से ऊपर की ओर नियोजन" पर बल देती है। ग्रामीण विकास के संदर्भ में इसका क्या तात्पर्य है?
(A) योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जाती हैं और ग्रामों में सीधे लागू की जाती हैं
(B) योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर ग्राम सभा में निवासियों द्वारा तैयार की जाती हैं
(C) नियोजन जिला परिषद स्तर पर प्रारंभ होता है और खंडों में लागू किया जाता है
(D) जिला योजना समिति स्थानीय निकायों से परामर्श किए बिना योजनाओं को अंतिम रूप देती है

22. सूची I में पंचायती राज संबंधी समितियों को सूची II में उनकी प्रमुख सिफारिशों या विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (समितियां)
P. बलवंत राय मेहता समिति
Q. अशोक मेहता समिति
R. एल.एम. सिंघवी समिति
S. जी.वी.के. राव समिति
सूची II: (सिफारिशें / विशेषताएं)
1. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता
2. पंचायती राज की द्विस्तरीय प्रणाली
3. पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली
4. ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं
(A) P-2, Q-3, R-4, S-1
(B) P-3, Q-1, R-2, S-4
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-4, Q-2, R-1, S-3

23. राजस्थान में, ग्राम सभा की वैध बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) कानूनी रूप से कितनी निर्धारित की गई है?
(A) कुल सदस्यों का एक-तिहाई
(B) कुल सदस्यों का एक-पांचवां
(C) कुल सदस्यों का दसवां भाग
(D) कुल सदस्यों का बीसवां भाग

24. राजस्थान में निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का समन्वय मुख्य रूप से किस शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जाता है?
(A) इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (आईजीपीआरएंडजीवीएस)
(B) राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी)
(C) हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा)
(D) राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

25. ग्राम स्तर से जिला स्तर तक पंचायती राज संस्थाओं के सही पदानुक्रमित क्रम की पहचान कीजिए:
(A) ग्राम सभा → जिला परिषद → पंचायत समिति → ग्राम पंचायत
(B) ग्राम पंचायत → पंचायत समिति → जिला परिषद
(C) पंचायत समिति → ग्राम पंचायत → जिला परिषद
(D) ग्राम पंचायत → जिला परिषद → पंचायत समिति

26. जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह ऐतिहासिक रूप से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पृथक पंजीकृत समिति के रूप में स्थापित की गई थी।
II. केंद्र सरकार ने बेहतर कार्यात्मक तालमेल सुनिश्चित करने के लिए जिला परिषद के साथ इसके पूर्ण एकीकरण की पहल की है।
III. यह बिना किसी केंद्रीय वित्तीय सहायता के पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II

Click Here to Buy book on Flipkart

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (A) नागौर, 2 अक्टूबर 1959
भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु ने इस ऐतिहासिक व्यवस्था का उद्घाटन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय लोगों को शासन में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनाना था।

2. (C) ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था
भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के तहत ग्राम सभा किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी नागरिकों का समूह है। यह संस्था पंचायती राज व्यवस्था की मूल नींव मानी जाती है। ग्राम सभा ग्रामीण शासन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसके माध्यम से स्थानीय नागरिक विकास योजनाओं की स्वीकृति तथा पंचायत के वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों की नियमित समीक्षा में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं।

3. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
वर्ष 1992 में पारित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस अधिनियम ने भाग 9 तथा ग्यारहवीं अनुसूची जोड़कर स्थानीय निकायों को सुरक्षा दी। इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण में प्रत्येक पांच वर्ष में पंचायतों के चुनाव आयोजित करना अनिवार्य बना दिया गया। नियमित चुनाव की यह संवैधानिक बाध्यता ही पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व की गारंटी सुनिश्चित करती है।

4. (D) पंचायतों को कर, शुल्क और पथकर (टोल) लगाने तथा एकत्र करने की वित्तीय शक्तियां प्रदान करना
73वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनिवार्य और स्वेच्छिक दो प्रकार के प्रावधान शामिल किए गए हैं। सभी राज्यों में त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना, सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। वहीं दूसरी ओर पंचायतों को कर, शुल्क अथवा पथकर लगाने, एकत्र करने तथा उपयोग करने का अधिकार देना राज्य विधानमंडलों की इच्छा पर निर्भर करता है।

5. (B) संबंधित राज्य के राज्यपाल
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (के) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, जो पंचायतों के सभी चुनावों के संचालन और मतदाता सूची तैयार करने का कार्य करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। हालांकि, उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया अत्यंत विशिष्ट और कठिन है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया के समान है।

6. (B) केवल I और III
भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची को वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, न कि 74वें संशोधन द्वारा। यह अनुसूची पंचायतों के प्रशासनिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित है और इसमें कुल 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। इन विषयों में मुख्य रूप से कृषि, ग्रामीण आवास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीने का पानी, सड़कें तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण ग्रामीण कार्य सम्मिलित किए गए हैं।

NODIA

7. (B) 50 प्रतिशत
यद्यपि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन राजस्थान सरकार ने राज्य पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके इस सीमा को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। इसके तहत राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीनों स्तरों पर साधारण सदस्यों के पदों और अध्यक्षों के पदों में महिलाओं के लिए आधा हिस्सा आरक्षित किया गया है।

8. (A) पंचायत समिति
भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना के अंतर्गत तीन प्रमुख स्तर होते हैं, जिनमें सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत और सबसे शीर्ष स्तर पर जिला परिषद होती है। इन दोनों स्तरों के बीच खंड या ब्लॉक स्तर पर कार्य करने वाली संस्था को पंचायत समिति कहा जाता है। पंचायत समिति ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समन्वय करती है तथा उन्हें समेकित कर जिला परिषद के समक्ष भेजती है।

9. (B) P-2, Q-3, R-1, S-4
राजस्थान में पंचायती राज के विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए विशिष्ट अधिकारी तैनात किए गए हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख के रूप में ग्राम विकास अधिकारी कार्य करता है। खंड स्तर पर पंचायत समिति का प्रशासनिक प्रमुख खंड विकास अधिकारी होता है। जिला स्तर पर जिला परिषद के प्रशासनिक कार्यों का संचालन

4. पंचायतों का गठन

(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

36. पंचायती राज के मौलिक विचार-विमर्श निकाय के रूप में ग्राम सभा की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

(A) ग्राम स्तर पर पूर्ण कार्यकारी और निर्णय लेने की शक्तियों का केंद्रीकरण करना
(B) राज्य विधान सभा के प्रत्यक्ष कार्यात्मक विकल्प के रुप में कार्य करना
(C) गंभीर आपराधिक अपराधों के मुकदमे के लिए एक औपचारिक न्यायिक अदालत के रूप में कार्य करना
(D) सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करना

37. राजस्थान में, एक कैलेंडर वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठकें आयोजित करना वैधानिक रूप से अनिवार्य है?

(A) दो
(B) तीन
(C) चार
(D) छह

38. भारत में ग्रामीण विकास और स्थानीय शासन के विकास में निम्नलिखित चरणों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए:

1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अधिनियमन
2. सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) का शुभारंभ
3. बलवंत राय मेहता समिति का गठन
4. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा) का अधिनियमन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए:

(A) 2, 3, 1, 4
(B) 3, 2, 1, 4
(C) 2, 1, 3, 4
(D) 1, 2, 4, 3

39. राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रत्येक कितने वर्षों की समाप्ति पर किया जाना चाहिए?

(A) तीन वर्ष
(B) चार वर्ष
(C) पांच वर्ष
(D) दस वर्ष

40. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:

कथन (A): ग्राम सभा मनरेगा के तहत निष्पादित कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) करने के लिए वैधानिक तंत्र के रूप में कार्य करती है।

कारण (R): सामाजिक अंकेक्षण समुदाय को ग्रामीण योजनाओं के व्यय और कार्यान्वयन की प्रत्यक्ष जांच करने की अनुमति देकर जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

NODIA

41. निम्नलिखित में से कौन-सा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध 29 विषयों में शामिल नहीं है?

(A) बिजली के वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण
(B) लोक व्यवस्था का अनुरक्षण
(C) सार्वजनिक वितरण प्रणाली
(D) परिवार कल्याण

42. निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए कानूनी रूप से पात्र है?

(A) वर्तमान सरपंच के साथ केवल आधिकारिक रूप से निर्वाचित वार्ड पंच
(B) ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति
(C) ग्राम की प्रादेशिक सीमा के भीतर रहने वाला कोई भी वयस्क निवासी
(D) ग्राम में संपत्ति के मालिक, चाहे उनका स्थायी प्राथमिक निवास कुछ भी हो

43. मनरेगा में पंचायतों की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. ग्राम पंचायतें मुख्य रूप से ग्राम में निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
II. पंचायती राज संस्थाओं को लागत के संदर्भ में कम से कम 50% कार्यों को निष्पादित करना अनिवार्य है।
III. केवल राज्य सरकार, न कि पंचायत, ग्रामीण परिवारों को कानूनी रूप से जॉब कार्ड जारी कर सकती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

44. राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है?

(A) अंचल समिति
(B) मंडल परिषद
(C) पंचायत समिति
(D) जनपद पंचायत

45. सूची I में ग्रामीण शासन की चुनौतियों को सूची II में उनके उपयुक्त विवरणों के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची I: (चुनौतियां)

P. धन का हस्तांतरण

और अभिलेखों के रख-रखाव में सरपंच की सहायता करता है, किस नाम से जाना जाता है?
(A) पटवारी (ग्राम राजस्व लेखाकार)
(B) कानूनगो (राजस्व सर्किल निरीक्षक)
(C) ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ)
(D) तहसीलदार (उप-जिला राजस्व अधिकारी)

63. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के लागू अयोग्यता नियमों के अनुसार, पंचायत के लिए निर्वाचित व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि वह:
(A) चुनाव लड़ने के समय 25 वर्ष से कम आयु का है
(B) निर्धारित तिथि के पश्चात दो से अधिक संतान रखता है
(C) औपचारिक विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं रखता है
(D) ग्राम क्षेत्र में कृषि भूमि का स्वामी नहीं है

64. पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण का संवैधानिक जनादेश किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है?
(A) सभी राज्यों में एक समान निश्चित 15% आरक्षण कोटा
(B) राज्य मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री का पूर्ण विवेक
(C) जिले में ऐतिहासिक साक्षरता दर और शैक्षणिक स्तर
(D) पंचायत क्षेत्र में कुल जनसंख्या से उनकी जनसंख्या का अनुपात

65. निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय जमीनी स्तर के शासन के संदर्भ में "सरपंच पति" अवधारणा का सही वर्णन करता है?
(A) निर्वाचित महिला सरपंच के पति द्वारा सत्ता का अनौपचारिक प्रयोग
(B) सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सरपंच को प्रदान किया जाने वाला राज्य पुरस्कार
(C) उप-सरपंच का औपचारिक वैधानिक पदनाम
(D) स्थानीय ग्रामों में एक पारंपरिक विवाद निवारण परिषद

66. 'ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट' जैसी पहलों के माध्यम से पंचायत अभिलेखों और प्रशासन के डिजिटलीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) जमीनी स्तर की राजनीति में स्थानीय निवासियों की प्रत्यक्ष भागीदारी को कम करना
(B) निर्वाचित ग्रामीण प्रतिनिधियों को स्वचालित प्रणाली से बदलना
(C) स्थानीय शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल बनाना
(D) पंचायतों की कराधान शक्तियों को केंद्र सरकार को स्थानांतरित करना

67. संविधान की 'ग्यारहवीं अनुसूची' में 29 हस्तांतरित विषय शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र इसमें सम्मिलित है?
(A) कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है
(B) विदेशी मामले और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति
(C) प्रमुख समुद्री बंदरगाहों और नागरिक उड्डयन का विनियमन
(D) उच्च न्यायालयों की स्थापना और क्षेत्राधिकार

68. ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) अभिसरण की अवधारणा का समर्थन किस प्रकार करती है?
(A) यह प्रत्येक केंद्रीय योजना के लिए स्वतंत्र, पृथक योजना को प्रोत्साहित करती है
(B) यह कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक बड़ी शहरी निकाय बनाती है
(C) यह ग्राम सभा से राज्य स्तरीय अधिकारियों को नियोजन शक्ति स्थानांतरित करती है
(D) यह समग्र ग्राम विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के संसाधनों को एक ही योजना में एकीकृत करती है

69. मनरेगा के दिशा-निर्देशों के तहत, कौन-सा निकाय कार्य की मांग का विवरण देते हुए वार्षिक "श्रम बजट" तैयार करने के लिए वैधानिक रूप से उत्तरदायी है?
(A) जिला कलेक्टर
(B) ग्राम पंचायत
(C) राज्य रोजगार गारंटी परिषद
(D) ग्रामीण विकास मंत्रालय

70. पंचायती राज के संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग की प्राथमिक और स्पष्ट भूमिका क्या है?
(A) राज्य और केंद्र के बीच सीमा विवादों को सुलझाना
(B) ग्राम पंचायतों के दैनिक वित्तीय खातों का अंकेक्षण करना
(C) स्थानीय स्वशासन निकायों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और नियमित चुनाव सुनिश्चित करना
(D) जिला परिषद कार्यालयों के लिए स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करना

71. पंचायतों को "निधियों के हस्तांतरण" के संबंध में प्रमुख चुनौतियों में से एक उनकी अत्यधिक निर्भरता किस पर है?
(A) स्वयं के आय के स्रोतों (ओएसआर) पर
(B) अंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसियों से सीधे वित्तपोषण पर
(C) कृषि आय कर से एकत्र राजस्व पर
(D) उच्चतर सरकारों से प्राप्त सशर्त/सबद्ध अनुदानों पर

72. पंचायती राज व्यवस्था के किस स्तर को पंचायत समितियों द्वारा तैयार की गई खंड-स्तरीय योजनाओं की समीक्षा और समेकन का कार्य सौंपा गया है?
(A) जिला परिषद
(B) ग्राम सभा
(C) जिला योजना समिति
(D) राज्य योजना बोर्ड

73. पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 243D के तहत) किस पर लागू होता है?
(A) अध्यक्षों को छोड़कर, केवल साधारण सदस्यों के पदों पर

Downloaded from www.pdf.tube

(D) राज्यपाल और मुख्यमंत्री पंचायत चुनावों पर सीधा प्रशासनिक नियंत्रण साझा करते हैं

54. पंचायत का सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। हालांकि, यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है, तो नई पंचायत के गठन के लिए चुनाव कितनी अवधि के भीतर पूरे हो जाने चाहिए?
(A) इसके विघटन की तिथि से 3 माह
(B) इसके विघटन की तिथि से 6 माह
(C) इसके विघटन की तिथि से 1 वर्ष
(D) इसके मूल कार्यकाल की शेष अवधि

55. निधियों के संरचनात्मक हस्तांतरण के लिए राज्य वित्त आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस मानक की सिफारिश की जाती है?
(A) महत्वपूर्ण कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद कोटा तय करना
(B) स्थानीय कारीगर समूहों द्वारा किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए वाणिज्यिक ऋण स्वीकृत करना
(C) ग्रामीण क्षेत्रों से सैन्य भर्ती के लिए अनिवार्य कोटा और मानदंड स्थापित करना
(D) राज्य और पंचायतों के बीच शुद्ध राज्य कर राजस्व और शुल्कों का वितरण

56. पंचायती राज निकायों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसने जमीनी स्तर पर ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए एक औपचारिक तंत्र प्रदान किया है।
II. यह आदेश देता है कि सभी स्तरों पर अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित हों।
III. यह वंचित समूहों के लिए अलग विकासात्मक योजनाओं की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर देता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

57. ग्रामीण शासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, ग्राम पंचायतों को स्वयं के आय के स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत के लिए स्वयं के आय के स्रोतों का सही उदाहरण है?
(A) केंद्रीय वित्त आयोग से सीधे प्राप्त अनावद्ध सहायता अनुदान
(B) पंचायत द्वारा गृह कर, जल कर और स्थानीय मेलों पर एकत्र किए गए कर
(C) मनरेगा योजना के तहत जारी प्रत्यक्ष मजदूरी और सामग्री निधि
(D) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत प्राप्त निधि

58. जिला योजना समिति (डीपीसी) पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों द्वारा तैयार की गई स्थानीय योजनाओं को समेकित करने के लिए बनाई गई एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। डीपीसी का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?
(A) अनुच्छेद 243ZD
(B) अनुच्छेद 243ZE
(C) अनुच्छेद 243ZF
(D) अनुच्छेद 243ZG

59. यदि राजस्थान में कोई निर्वाचित सरपंच अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है, तो उसे अपना लिखित त्यागपत्र किसे सौंपना होगा?
(A) विकास अधिकारी (खंड विकास अधिकारी)
(B) जिला कलेक्टर
(C) जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)
(D) राज्य निर्वाचन आयुक्त

60. पंचायत स्तर पर केंद्रीय योजनाओं के अभिसरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसका व्यवस्थित उद्देश्य विकासात्मक प्रयासों के दोहराव और निधियों के अतिव्यापन को रोकना है।
II. यह पंचायतों को स्वच्छता परियोजनाओं के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के धन के साथ-साथ अकुशल श्रम के लिए मनरेगा धन का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।
III. इसके लिए ग्राम पंचायतों को समाप्त करना और निजी ठेकेदारों को कार्यान्वयन सौंपना आवश्यक है।
IV. यह आंगनवाड़ी केंद्रों जैसी टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण के लिए संसाधन उपयोग को अनुकूलित करता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल I, II और IV
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

NODIA

61. संवैधानिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में, जिला परिषद मुख्य रूप से किस रूप में कार्य करती है?
(A) सभी छोटे स्थानीय नागरिक कार्यों के लिए जिम्मेदार एक कार्यकारी कार्यान्वयन एजेंसी
(B) अंतर-ग्राम भूमि विवादों को सुलझाने वाली एक औपचारिक न्यायिक अदालत
(C) राज्य स्तरीय वाणिज्यिक करों के लिए प्राथमिक राजस्व-संग्रह एजेंसी
(D) जिला स्तर पर एक पर्यवेक्षी और समन्वयकारी सलाहकारी निकाय

62. राजस्थान में ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख और कार्यकारी अधिकारी, जो सरकारी कार्यों, वित्तीय संचालन

Q. कार्यों का हस्तांतरण
R. कार्यकर्ताओं का हस्तांतरण
S. क्षमता निर्माण

सूची II: (विवरण)
1. पंचायत स्तर पर पर्याप्त trained तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी
2. नए निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए नियमित, संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता
3. राज्य के विभागों की वास्तविक प्रशासनिक विषयों को स्थानीय निकायों को स्थानांतरित करने में अनिच्छा
4. अपर्याप्त अनावद्ध वित्तीय संसाधन और कम आंतरिक राजस्व सृजन क्षमता

(A) P-3, Q-4, R-2, S-1
(B) P-4, Q-1, R-3, S-2
(C) P-1, Q-3, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

46. जिला परिषदें विभिन्न कार्यात्मक स्थायी समितियों के माध्यम से कार्य करती हैं। राजस्थान में, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आमतौर पर किस सेवा का अधिकारी होता है?
(A) राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) का वरिष्ठ अधिकारी
(B) भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) का वरिष्ठ अधिकारी
(C) आईएएस या राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) का अधिकारी
(D) राज्य न्यायिक सेवा का वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी

47. राजस्थान में मानक पंचायती राज मानदंडों के अनुसार, निम्नलिखित में से किस तिथि को छोड़कर अन्य सभी तिथियों पर ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है?
(A) 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस)
(B) 1 मई (मजदूर दिवस)
(C) 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस)
(D) 10 दिसंबर

48. ग्रामीण शासन के लिए संस्थागत निधि हस्तांतरण तंत्र के सही तार्किक क्रम की पहचान कीजिए:
(A) राज्य वित्त आयोग का गठन → पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा → राज्यपाल को सिद्धांतों की सिफारिश → राज्य विधानमंडल द्वारा कार्यान्वयन
(B) राज्य विधानमंडल द्वारा कार्यान्वयन → राज्य वित्त आयोग का गठन → राज्यपाल द्वारा सिफारिश
(C) राज्यपाल द्वारा सिफारिश → राज्य विधानमंडल द्वारा कार्यान्वयन → राज्य वित्त आयोग का गठन
(D) राज्य वित्त आयोग का गठन → राज्य विधानमंडल द्वारा कार्यान्वयन → वित्तीय स्थिति की समीक्षा

49. पंचायती राज संस्था में सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है?
(A) 18 वर्ष
(B) 21 वर्ष
(C) 25 वर्ष
(D) 30 वर्ष

50. निम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) का प्राथमिक उद्देश्य है?
(A) संवेदनशील ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित संक्रामक रोगों का उन्मूलन करना
(B) भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण प्रदान करना
(C) पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करना
(D) प्रमुख शहरी स्मार्ट शहरों के लिए बुनियादी ढांचा विकास को वित्तपोषित करना

51. पंचायतों द्वारा ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. ग्राम पंचायतें बुनियादी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं।
II. प्राथमिक विद्यालय के भवनों का निर्माण और रखरखाव कई राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के दायरे में आता है।
III. जिला परिषदें आम तौर पर प्रमुख अंतर-खंड ग्रामीण सड़कों की देखरेख करती हैं।
IV. पंचायती राज संस्थाएं भारी विनिर्माण उद्योगों की स्थापना के लिए संवैधानिक रूप से उत्तरदायी हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और III
(B) केवल II, III और IV
(C) केवल I, III और IV
(D) I, II, III और IV

52. राजस्थान के पंचायती राज ढांचे के संदर्भ में, 'वार्ड सभा' शब्द औपचारिक रूप से किसे दर्शाता है?
(A) एक ही पंचायत समिति के भीतर सभी निर्वाचित सरपंचों की एक औपचारिक बैठक
(B) जिला परिषद की मुख्य वित्तीय देखरेख और लेखापरीक्षा समिति
(C) खंड स्तर पर स्थित एक जमीनी स्तर का विवाद निवारण निकाय
(D) ग्राम पंचायत के एक विशिष्ट वार्ड के सभी वयस्क मतदाताओं की सभा

53. पंचायती राज संस्थाओं को "कर्मचारियों के हस्तांतरण" से संबंधित एक मुख्य चुनौती "दोहरे नियंत्रण" का मुद्दा है। इस संदर्भ में दोहरे नियंत्रण का अर्थ है:
(A) राज्य और केंद्र सरकारें संयुक्त रूप से स्थानीय ग्रामीण बाजारों और कर संग्रह का प्रबंधन करती हैं
(B) मैदानी अधिकारी प्रशासनिक रूप से पंचायतों को लेकिन तकनीकी रूप से राज्य के विभागों को रिपोर्ट करते हैं
(C) ग्राम पंचायतें और जिला परिषदें अपने अतिव्यापी कार्यात्मक क्षेत्राधिकारों पर विवाद करती हैं

Click Here to Buy book on Amazon

(B) तीनों स्तरों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की सीटों और अध्यक्षों के पदों दोनों पर
(C) केवल ग्राम पंचायत स्तर पर
(D) केवल उन क्षेत्रों में जहां महिला जनसंख्या पुरुषों से अधिक है

74. स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) निम्नलिखित में से किस स्थिति को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है?
(A) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) दर्जा
(B) खुले में शौच मुक्त प्लस (ओडीएफ प्लस) दर्जा
(C) राष्ट्रीय विरासत ग्राम का दर्जा
(D) स्मार्ट सिटी का दर्जा

75. ग्राम सभा की वैधानिक भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?
(A) यह निर्वाचित विधायक को पदमुक्त करने की शक्ति रखती है।
(B) यह सहभागी नियोजन, सामुदायिक निर्णय लेने और नियमित सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक लोकतांत्रिक मंच प्रदान करती है।
(C) यह कार्यान्वयन से पहले सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए स्थानीय योजनाओं और कार्यक्रमों का अनुमोदन करती है।
(D) यह कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान और चयन के लिए उत्तरदायी है।

76. जिला स्तर पर केंद्रीय गरीबी उन्मूलन योजनाओं का समन्वय पारंपरिक रूप से किस संस्था द्वारा किया जाता था, जिसका बाद में जिला परिषद में विलय कर दिया गया?
(A) नीति आयोग
(B) राज्य वित्त आयोग
(C) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए)
(D) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

77. राजस्थान में पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण मुख्य रूप से क्यों आवश्यक माना जाता है?
(A) यह स्थानीय प्रतिनिधियों को राज्य के वित्तीय निर्देशों को दरकिनार करने में सक्षम बनाता है
(B) यह स्थानीय नेताओं को प्रतिस्पर्धी भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयार करता है
(C) यह अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से निधि प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शर्त है
(D) निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास हस्तांतरित विषयों के कुशल प्रबंधन हेतु प्रायः प्रशासनिक और तकनीकी अनुभव की कमी होती है

78. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्यात्मक विषय पंचायती राज संस्थाओं के ग्रामीण विकास जनादेश से सबसे निकटता से जुड़ा हुआ है?
(A) उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों का नियमन
(B) शेयर बाजारों का नियमन
(C) ग्रामीण आवास और गौण वन उपज
(D) पासपोर्ट और वीजा जारी करना

79. कौन-सा संवैधानिक प्रावधान विशेष रूप से पंचायतों की संरचना से संबंधित है?
(A) अनुच्छेद 243A
(B) अनुच्छेद 243B
(C) अनुच्छेद 243C
(D) अनुच्छेद 243E

80. पंचायतों के कामकाज में सुधार हेतु 'ऑडिटऑनलाइन' एप्लिकेशन का कार्यान्वयन किया गया है। इस एप्लिकेशन का मुख्य उद्देश्य किसे सुगम बनाना है?
(A) स्थानीय पंचायत चुनावों के दौरान ऑनलाइन मतदान
(B) ग्राम सभा बैठकों की लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग
(C) ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु शिकायत निवारण
(D) वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पंचायत खातों का ऑनलाइन अंकेक्षण

www.nodia.in

NODIA

20. (D) ग्रामीण सड़कों, जल निकासी और पेयजल सुविधाओं का रखरखाव
पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्तर पर बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने का मुख्य उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण आंतरिक सड़कों का निर्माण व रखरखाव, नालियों की सफाई, जल निकासी प्रणाली का प्रबंधन, तथा पेयजल सुविधा सुनिश्चित करना शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग या बड़े बांध राज्य अथवा केंद्र सरकार के अनन्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।

21. (B) योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर ग्राम सभा में निवासियों द्वारा तैयार की जाती हैं
ग्राम पंचायत विकास योजना में "नीचे से ऊपर की ओर नियोजन" की अवधारणा का अर्थ यह है कि विकास की योजनाएं किसी उच्च स्तरीय नौकरशाही द्वारा थोपने के बजाय स्थानीय निवासियों द्वारा तैयार की जाएं। इस प्रक्रिया में ग्राम सभा की बैठकों में गाँव के नागरिक अपनी वास्तविक समस्याओं और प्राथमिकताओं पर खुली चर्चा करते हैं तथा स्वयं अपनी वार्षिक विकास योजनाओं का अनुमोदन करते हैं।

22. (C) P-3, Q-2, R-1, S-4
भारत में पंचायती राज के विकास में विभिन्न समितियों ने महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थीं। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की। एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने का सुझाव दिया, जबकि जी.वी.के. राव समिति ने ग्रामीण विकास हेतु प्रशासनिक सुधारों की विस्तृत सिफारिश की थी।

23. (C) कुल सदस्यों का दसवां भाग
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम सभा की किसी भी वैध बैठक को आयोजित करने के लिए नियमानुसार गणपूर्ति होना अनिवार्य है। राजस्थान में ग्राम सभा की बैठक हेतु गणपूर्ति कुल सदस्यों का दसवां भाग निर्धारित की गई है। यदि निर्धारित समय पर आवश्यक सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं, तो बैठक को स्थगित कर दिया जाता है तथा पुनः तिथि अनुसूचित की जाती है।

24. (A) इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (आईजीपीआरएंडजीवीएस)
राजस्थान में स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान एक स्वायत्त शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है। यह संस्थान राज्य में पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्रामीण विकास विभागों के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान का संचालन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशासनिक, वित्तीय और व्यावहारिक रूप से कुशल तथा दक्ष बनाना है।

25. (B) ग्राम पंचायत → पंचायत समिति → जिला परिषद
73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर से जिला स्तर तक एक स्पष्ट पदानुक्रमित संरचना का प्रावधान किया गया है। इसमें सबसे निचला अथवा प्राथमिक स्तर ग्राम पंचायत होता है, जो गाँव के स्तर पर कार्य करता है। इसके ऊपर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति होती है, जो खंड स्तर पर स्थित होती है, जबकि सबसे शीर्ष स्तर पर जिला परिषद कार्यरत होती है।

26. (A) केवल I और II
जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को ऐतिहासिक रूप से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पृथक समिति के रूप में पंजीकृत किया गया था। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने तथा दोहराव रोकने हेतु केंद्र सरकार ने इसके जिला परिषद में विलय की पहल की है। यह एजेंसी केवल राज्य द्वारा वित्तपोषित नहीं थी, बल्कि इसमें केंद्र और राज्य का वित्तीय अंशदान शामिल होता था।

27. (C) 29
वर्ष 1992 में पारित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस अनुसूची के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक रूप से कुल 29 कार्यात्मक विषय सौंपे गए हैं। इन विषयों में मुख्य रूप से कृषि, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़कें, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण कार्य स्पष्ट रूप से शामिल किए गए हैं।

28. (C) राज्य के राज्यपाल को
अनुच्छेद 243 (आई) के तहत गठित राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की गहन समीक्षा करता है और राज्य के शुद्ध कर राजस्व के वितरण तथा वित्तीय अनुदानों के सिद्धांतों से संबंधित अपनी सिफारिशें सीधे राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। इसके पश्चात राज्यपाल इन सिफारिशों को, उन पर की गई आवश्यक कार्रवाई के ज्ञापन के साथ, राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाने की समुचित व्यवस्था करते हैं।

29. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
यद्यपि ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों हेतु 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है, किंतु व्यावहारिक रूप से कई राज्यों में इन कार्यों का हस्तांतरण अधूरा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अधिकारों के हस्तांतरण की सीमा को राज्य विधानमंडलों के विवेक पर छोड़ता है। इसी कारण से कई राज्यों ने पूर्ण शक्तियां हस्तांतरित नहीं की हैं।

30. (C) ग्राम सभा
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र बेघर तथा कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक जनगणना से प्राप्त लाभार्थियों की प्राथमिक सूची का पारदर्शी सत्यापन करने, अपात्र व्यक्तियों को हटाने तथा अंतिम पात्र सूची को स्वीकृति देने में ग्राम सभा अत्यंत महत्वपूर्ण वैधानिक भूमिका निभाती है।

Downloaded from www.pdf.tube

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है, जबकि ग्राम सभा सभी नागरिकों का निकाय है।

10. (C) अनुच्छेद 243I
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 (आई) राज्य वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। राज्यपाल द्वारा प्रति पांच वर्ष में गठित यह स्वायत्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। यह आयोग राज्य द्वारा वसूले जाने वाले करों और शुल्कों के शुद्ध राजस्व को राज्य सरकार तथा पंचायती राज संस्थाओं के बीच बांटने के सिद्धांतों की सिफारिश राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, जिससे स्थानीय निकायों को सुदृढ़ता मिलती है।

11. (A) पंचायत गतिविधियों की योजना, लेखांकन और निगरानी के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया 'ई-ग्राम स्वराज' पोर्टल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्राम पंचायतों में विकेंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग, वास्तविक समय की निगरानी और पारदर्शी लेखांकन के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करना है। इस पोर्टल के माध्यम से पंचायत की विकास परियोजनाओं और वित्तीय लेन-देन की जानकारी आम जनता हेतु सुलभता से उपलब्ध होती है।

12. (C) धन, कार्य और कार्यकर्ता (Funds, Functions, Functionaries)
पंचायती राज संस्थाओं की कार्यात्मक दक्षता के संदर्भ में "3एफ की समस्या" एक प्रमुख संरचनात्मक प्रशासनिक चुनौती मानी जाती है। इसमें 3एफ का अर्थ धन, कार्य और कार्यकर्ता से होता है। इस समस्या का मुख्य तात्पर्य यह है कि अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन, स्पष्ट प्रशासनिक अधिकार तथा पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी हस्तांतरित नहीं किए गए हैं, जिससे स्थानीय स्वशासन प्रभावित होता है।

13. (A) 4, 2, 3, 1
ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में पूरी होती है। सबसे पहले ग्राम पंचायत योजना सुविधा दल का गठन किया जाता है। इसके पश्चात गाँव की प्राथमिक आवश्यकताओं का सटीक आकलन तथा स्थितिजन्य विश्लेषण किया जाता है। तीसरे चरण में चिन्हित आवश्यकताओं के आधार पर विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाता है। अंत में योजना को स्वीकृत करने हेतु ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

14. (C) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं को योजना निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी का मुख्य दायित्व सौंपा गया है। कानून के अनुसार मनरेगा के तहत कुल निष्पादित कार्यों में से कम से कम पचास प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा पूरे किए जाने अनिवार्य हैं। ग्राम पंचायतें ही ग्रामीण परिवारों के जॉब कार्ड बनाती हैं तथा सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया आयोजित करने में सहायक बनती हैं।

15. (B) गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रबंधन करना
जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की स्थापना ऐतिहासिक रूप से जिला स्तर पर गरीबी उन्मूलन, स्वरोजगार तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन, प्रबंधन और वित्तीय अनुप्रमाणन के लिए की गई थी। यह एजेंसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निधियों का प्रबंधन करती थी। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने तथा दोहराव को समाप्त करने हेतु वर्तमान में इस संस्था का विलय पूर्णतः जिला परिषद के भीतर कर दिया गया है।

16. (A) केवल I, II और IV
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रत्येक स्तर पर पंचायतों का सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित है। यह अधिनियम प्रत्येक पांच वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों हेतु जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान करता है। हालांकि, संसद सदस्य ग्राम सभा के मतदाता नहीं होते, क्योंकि ग्राम सभा केवल संबंधित गाँव की मतदाता सूची के पंजीकृत निवासियों से मिलकर बनती है।

17. (A) पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला जिला कलेक्टर
पंचायत समिति की संरचना में संबंधित खंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने गए सदस्य शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त उस खंड की ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा उस क्षेत्र के राज्य विधान सभा सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। हालांकि, जिला कलेक्टर पंचायत समिति का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है। इसका अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने मध्य में से ही अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।

18. (C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने से लाखों महिलाएं निर्वाचित होकर निर्णय प्रक्रिया में शामिल हुई हैं, जिससे जमीनी स्तर पर महिला राजनीतिक नेतृत्व का उदय हुआ है। यद्यपि कुछ स्थानों पर पुरुष रिश्तेदारों द्वारा शक्तियों के प्रयोग की 'सरपंच पति' प्रवृत्ति दिखी है, किंतु इसने महिला आरक्षण के वास्तविक प्रभाव को सभी राज्यों में पूरी तरह समाप्त नहीं किया है।

NODIA

19. (D) अनुच्छेद 243D
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 (डी) पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटें आरक्षित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, इसी अनुच्छेद के तहत महिलाओं के लिए भी न्यूनतम एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

27. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, ग्यारहवीं अनुसूची के तहत पंचायतों को संवैधानिक रूप से कितने कार्यात्मक विषय सौंपे गए हैं?
(A) 18
(B) 22
(C) 29
(D) 35

28. पंचायतों को निधियों के हस्तांतरण के संबंध में राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें किसे सौंपी जाती हैं?
(A) सीधे राज्य विधानमंडल को
(B) मुख्यमंत्री को
(C) राज्य के राज्यपाल को
(D) पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को

29. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): ग्यारहवीं अनुसूची के अस्तित्व के बावजूद कई राज्यों में पंचायतों को कार्यों का व्यावहारिक हस्तांतरण अधूरा बना हुआ है।
कारण (R): 73वां संविधान संशोधन अधिनियम शक्तियों और अधिकारों के हस्तांतरण की सटीक सीमा को राज्य विधानमंडलों के विवेक पर छोड़ता है।
(A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(B) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है लेकिन कारण (R) सही है।

30. प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत, लाभार्थियों की सूची के सत्यापन और उसे अंतिम रूप देने में कौन-सा ग्रामीण निकाय महत्वपूर्ण वैधानिक भूमिका निभाता है?
(A) जिला परिषद
(B) राज्य मानव अधिकार आयोग
(C) ग्राम सभा
(D) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी

31. पंचायत स्तर पर "केंद्रीय योजनाओं के अभिसरण" की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) दूरस्थ ग्रामों में प्रशासनिक नौकरशाही और निर्णय लेने के पदानुक्रम का विस्तार करना
(B) टिकाऊ परिसंपत्तियां बनाने और दोहराव को रोकने के लिए बहु-योजना संसाधनों को एकत्र करना
(C) स्थानीय सरपंच की आंतरिक वित्तीय स्वायत्तता को सीमित और कड़ाई से नियंत्रित करना
(D) संप्रभु राज्य के विधायी विषयों को पूरी तरह से समवर्ती सूची में स्थानांतरित करना

32. हस्तांतरित निधियों के ऑनलाइन भुगतान और पारदर्शी लेखांकन के लिए पंचायतों द्वारा निम्नलिखित में से किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है?
(A) राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)
(B) शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू-डीआईएसई+)
(C) स्वयं (SWAYAM)
(D) सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

33. राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
II. राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही पद से हटाया जा सकता है।
III. राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
IV. राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों के साथ-साथ राज्य विधान सभा के चुनाव भी कराता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल I, II और IV
(B) केवल I, II और III
(C) केवल II, III और IV
(D) केवल I, III और IV

34. जिला परिषद के अध्यक्ष (जिला प्रमुख) का चुनाव निम्नलिखित में से किस प्रकार किया जाता है?
(A) सभी पंजीकृत वयस्क मतदाताओं द्वारा जिला स्तरीय प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से
(B) मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य सरकार द्वारा सीधे मनोनीत
(C) अप्रत्यक्ष रूप से, जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने मध्य में से
(D) प्रशासनिक वरिष्ठता के आधार पर सीधे राज्यपाल द्वारा नियुक्त

35. सूची I में दिए गए संवैधानिक अनुच्छेदों को सूची II में उनके संबंधित विषयों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (संवैधानिक अनुच्छेद)
P. अनुच्छेद 243A
Q. अनुच्छेद 243B
R. अनुच्छेद 243E
S. अनुच्छेद 243G
सूची II: (विषय)
1. पंचायतों की अवधि
2. पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और उत्तरदायित्व
3. ग्राम सभा

Click Here to Buy book on Flipkart

31. (B) टिकाऊ परिसंपत्तियां बनाने और दोहराव को रोकने के लिए बहु-योजना संसाधनों को एकत्र करना
पंचायत स्तर पर "केंद्रीय योजनाओं के अभिसरण" का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी विकास योजनाओं के वित्तीय, तकनीकी और मानव संसाधनों को एकीकृत करना है। इस प्रक्रिया से निधियों के दोहराव को रोका जा सकता है तथा उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होता है। उदाहरण के लिए मनरेगा के श्रम को अन्य योजनाओं से जोड़कर टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण किया जाता है।

32. (D) सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)
सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) वित्त मंत्रालय द्वारा विकसित एक वेब-आधारित ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन मंच है। पंचायतों द्वारा हस्तांतरित सरकारी निधियों का सीधा, पारदर्शी और त्वरित लेन-देन करने के लिए पीएफएमएस का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से योजनाओं के तहत सीधे लाभार्थियों और विक्रेताओं के बैंक खातों में डिजिटल रूप से भुगतान हस्तांतरित किया जाता है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।

33. (B) केवल I, II और III
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (के) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता तथा उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही हटाया जा सकता है। यह आयोग केवल पंचायतों व नगरपालिकाओं के चुनाव कराता है, जबकि विधान सभा चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है।

34. (C) अप्रत्यक्ष रूप से, जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने मध्य में से
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, जिला परिषद के अध्यक्ष (जिला प्रमुख) का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से जनता द्वारा सीधे निर्वाचित सदस्य अपनी पहली बैठक में अपने मध्य में से किसी एक सदस्य को जिला परिषद का अध्यक्ष चुनते हैं। उपाध्यक्ष का चुनाव भी इसी अप्रत्यक्ष प्रक्रिया से होता है।

35. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित विभिन्न अनुच्छेदों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 (ए) ग्राम सभा से संबंधित है। अनुच्छेद 243 (बी) पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243 (ई) पंचायतों की पांच वर्ष की अवधि निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 243 (जी) में पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों का वर्णन दिया गया है।

36. (D) सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करना
ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का मूल निकाय है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण भारत में सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करना है। यह संस्था गाँव के प्रत्येक पंजीकृत नागरिक को शासन और विकास योजनाओं की चर्चा में सीधे भाग लेने का अवसर देती है। ग्राम सभा पंचायत के प्रतिनिधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखती है तथा जमीनी स्तर पर पारदर्शिता एवं जवाबदेही स्थापित करती है।

37. (C) चार
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एक कैलेंडर वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम चार बैठकें आयोजित करना कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया गया है। ये चार बैठकें सामान्यतः चार विशिष्ट अवसरों पर आयोजित की जाती हैं, जिनमें 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त तथा 2 अक्टूबर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विषम परिस्थितियों में अथवा आवश्यकता पड़ने पर ग्राम सभा की विशेष बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं।

38. (A) 2, 3, 1, 4
भारत में ग्रामीण विकास तथा स्थानीय शासन का कालानुक्रमिक विकास इस प्रकार है: सर्वप्रथम वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। वर्ष 1992 में संसद द्वारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ तथा अंततः वर्ष 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों हेतु पेसा अधिनियम को संवैधानिक रूप से अधिनियमित किया गया।

39. (C) पांच वर्ष
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (आई) के प्रावधानों के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना अनिवार्य है। यह आयोग राज्य सरकार तथा पंचायती राज संस्थाओं के मध्य राजस्व वितरण, करों के आवंटन और पंचायतों को दिए जाने वाले वित्तीय सहायता अनुदानों के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है, ताकि स्थानीय स्वशासन सुदृढ़ बन सके।

40. (A) कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत निष्पादित सभी विकास कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए ग्राम सभा को वैधानिक तंत्र के रूप में अधिकृत किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, जो स्थानीय ग्रामीण समुदाय को योजनाओं के व्यय और कार्यान्वयन की प्रत्यक्ष जांच करने की शक्ति देकर शासन में पूर्ण जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

41. (B) लोक व्यवस्था का अनुरक्षण
संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों को हस्तांतरित 29 विषयों की सूची में ग्रामीण विद्युतीकरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा परिवार कल्याण जैसे विषय शामिल हैं। इसके विपरीत लोक व्यवस्था का अनुरक्षण (कानून-व्यवस्था)

Downloaded from www.pdf.tube

अयोग्य माना जाता है। यह प्रावधान जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने हेतु बनाया गया था।

64. (D) पंचायत क्षेत्र में कुल जनसंख्या से उनकी जनसंख्या का अनुपात
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (डी) के अनुसार, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का निर्धारण उस संबंधित पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है। कुल आबादी में उनका जो अनुपात होता है, उसी अनुपात में उनके लिए सीटों का संवैधानिक आरक्षण सुनिश्चित किया जाता है।

65. (A) निर्वाचित महिला सरपंच के पति द्वारा सत्ता का अनौपचारिक प्रयोग
भारतीय ग्रामीण शासन में "सरपंच पति" एक अनौपचारिक सामाजिक-प्रशासनिक प्रवृत्ति को निरूपित करता है। इसके अंतर्गत यद्यपि कोई महिला संवैधानिक रूप से सरपंच के पद पर चुनी जाती है, परंतु उसके पद की वास्तविक प्रशासनिक शक्तियों, दायित्वों और निर्णयों का संचालन अनौपचारिक रूप से उसके पति या किसी पुरुष संबंधी द्वारा किया जाता है। यह प्रथा महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक सहभागिता के मूल उद्देश्यों को बाधित करती है।

66. (C) स्थानीय शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल बनाना
'ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट' का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के सभी कार्यों, वित्तीय लेन-देन, परियोजना नियोजन तथा अभिलेखों को पूरी तरह से डिजिटल बनाना है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पंचायत अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने से ग्रामीण स्थानीय शासन अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल बनता है। इससे आम नागरिकों के लिए सरकारी योजनाओं और पंचायत की वित्तीय जानकारी आसानी से सुलभ हो जाती है।

67. (A) कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है
भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों को हस्तांतरित किए गए कुल 29 कार्यात्मक विषयों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में शामिल प्राथमिक विषयों में 'कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है' स्पष्ट रूप से सम्मिलित है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु कृषि पद्धतियों का सुधार तथा कृषि विस्तार गतिविधियों का प्रबंधन पंचायतों के संवैधानिक दायित्वों और अधिकारों के अंतर्गत आता है।

68. (D) यह समग्र ग्राम विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के संसाधनों को एक ही योजना में एकीकृत करती है
ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में अभिसरण की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य गाँव के समग्र विकास हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा वित्तीय संसाधनों को एक ही एकीकृत योजना में समाहित करना है। जीपीडीपी अलग-अलग योजनाएं चलाने के बजाय मनरेगा, स्वच्छता मिशन तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संसाधनों को जोड़कर गाँव की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने में मदद करती है।

69. (B) ग्राम पंचायत
मनरेगा अधिनियम के वैधानिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, आगामी वित्तीय वर्ष में गाँव में अकुशल रोजगार की कुल संभावित मांग का आकलन करते हुए वार्षिक श्रम बजट तैयार करने का प्राथमिक दायित्व सीधे ग्राम पंचायत का होता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की बैठकों में ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत मांग और स्थानीय विकास कार्यों के आधार पर यह श्रम बजट बनाकर स्वीकृति हेतु आगे भेजती है।

70. (C) स्थानीय स्वशासन निकायों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और नियमित चुनाव सुनिश्चित करना
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (के) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था के रूप में किया गया है। इसका प्राथमिक और स्पष्ट दायित्व पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और नियमित चुनाव संपन्न कराना है। यह आयोग पंचायत चुनावों की मतदाता सूचियों को तैयार करने के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण हेतु संवैधानिक रूप से उत्तरदायी होता है।

71. (D) उच्चतर सरकारों से प्राप्त सशर्त/सबद्ध अनुदानों पर
पंचायती राज संस्थाओं को निधियों के हस्तांतरण के क्षेत्र में एक प्रमुख चुनौती उनकी अत्यधिक वित्तीय निर्भरता है। पंचायतों के अपने स्वयं के आंतरिक राजस्व स्रोत अत्यंत सीमित हैं। इसके परिणामस्वरूप पंचायतें अपनी अधिकांश विकासात्मक और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए उच्चतर सरकारों से प्राप्त होने वाले सशर्त अथवा सबद्ध अनुदानों पर ही निर्भर रहती हैं, जिससे उनकी स्थानीय वित्तीय स्वायत्तता सीमित हो जाती है।

72. (A) जिला परिषद
त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना में जिला परिषद शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करती है। जिला परिषद का एक प्रमुख दायित्व अपने क्षेत्राधिकार की विभिन्न पंचायत समितियों द्वारा तैयार की गई खंड-स्तरीय विकास योजनाओं की समीक्षा करना, उनका परीक्षण करना तथा उन्हें समेकित करना है। इस प्रक्रिया के माध्यम से जिले के विभिन्न खंडों के मध्य संतुलित विकास तथा उचित प्रशासनिक समन्वय सुनिश्चित किया जाता है।

73. (B) तीनों स्तरों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की सीटों और अध्यक्षों के पदों दोनों पर
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (डी) के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान है। यह संवैधानिक नियम पंचायती राज के तीनों स्तरों पर समान रूप से लागू होता है। यह आरक्षण प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाने वाले सदस्यों के साथ-साथ तीनों स्तरों के अध्यक्षों के पदों पर भी अनिवार्य रूप से लागू किया गया है।

NODIA

नामांकित हैं। वार्ड सभा अपने विशिष्ट वार्ड के विकास कार्यों, प्राथमिकताओं और स्थानीय समस्याओं पर गहन विचार-विमर्श करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है।

53. (B) मैदानी अधिकारी प्रशासनिक रूप से पंचायतों को लेकिन तकनीकी रूप से राज्य के विभागों को रिपोर्ट करते हैं
पंचायती राज संस्थाओं में कर्मचारियों के हस्तांतरण के संदर्भ में "दोहरे नियंत्रण" का तात्पर्य उस स्थिति से है, जहाँ मैदानी कर्मचारी प्रशासनिक रूप से पंचायतों को रिपोर्ट करते हैं, किंतु तकनीकी, वित्तीय एवं सेवा मामलों में अपने राज्य स्तरीय विभागों के अधीन रहते हैं। इस दोहरे नियंत्रण के कारण पंचायतों का अपने प्रशासनिक कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाता।

54. (B) इसके विघटन की तिथि से 6 माह
संविधान के अनुच्छेद 243 (ई) के तहत पंचायतों का सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष होता है। हालांकि, यदि कोई पंचायत पांच वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले भंग या विघटित कर दी जाती है, तो इसके विघटन की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। नई पंचायत केवल शेष बची अवधि हेतु ही कार्य करती है।

55. (D) राज्य और पंचायतों के बीच शुद्ध राज्य कर राजस्व और शुल्कों का वितरण
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (आई) के अंतर्गत गठित राज्य वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाओं के बीच वित्तीय संबंधों का नियमन करना है। यह आयोग राज्य के शुद्ध कर राजस्व तथा शुल्कों को राज्य और पंचायतों के मध्य बांटने के सिद्धांतों की सिफारिश करता है। इससे स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ता प्राप्त होती है।

56. (A) केवल I और II
73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण निर्धारित है। इसने ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया है। यह नियम सभी स्तरों पर अध्यक्ष पदों पर भी लागू होता है। परंतु, यह उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान हेतु पृथक विकास योजनाओं की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है।

57. (B) पंचायत द्वारा गृह कर, जल कर और स्थानीय मेलों पर एकत्र किए गए कर
पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता के लिए स्वयं के आय के स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में लगाए और वसूले जाने वाले कर, जैसे गृह कर, जल कर, स्थानीय मेलों तथा बाजारों पर एकत्र शुल्क, स्वयं के राजस्व के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। बाह्य अनुदान अथवा केंद्रीय योजना निधियां पंचायत के अपने आंतरिक आय स्रोतों में शामिल नहीं होती हैं।

58. (A) अनुच्छेद 243ZD
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 (जेडडी) जिला योजना समिति के गठन का स्पष्ट प्रावधान करता है। जिला स्तर पर गठित यह संवैधानिक संस्था जिले की ग्रामीण पंचायतों तथा शहरी नगरपालिकाओं द्वारा पृथक रूप से तैयार की गई योजनाओं को समेकित करती है। यह समिति पूरे जिले के लिए एक समग्र एवं एकीकृत विकास योजना का प्रारूप तैयार करके स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करती है।

59. (A) विकास अधिकारी (खंड विकास अधिकारी)
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई निर्वाचित सरपंच समय से पूर्व स्वेच्छा से त्यागपत्र देना चाहता है, तो उसे अपना लिखित त्यागपत्र संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी (खंड विकास अधिकारी) को प्रेषित करना होता है। विकास अधिकारी द्वारा नियमानुसार त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के उपरांत सरपंच का पद कानूनी रूप से रिक्त मान लिया जाता है।

60. (B) केवल I, II और IV
पंचायत स्तर पर योजनाओं के अभिसरण का प्राथमिक उद्देश्य विकास कार्यों में दोहराव और निधियों के अपव्यय को रोकना है। यह व्यवस्था स्वच्छ भारत मिशन के धन के साथ मनरेगा के श्रम बजट का उपयोग करके आंगनवाड़ी केंद्रों जैसी टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण में मदद करती है। इसके लिए पंचायतों को समाप्त करने या निजी ठेकेदारों को लाने की आवश्यकता नहीं है।

61. (D) जिला स्तर पर एक पर्यवेक्षी और समन्वयकारी सलाहकारी निकाय
संवैधानिक त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचे में जिला परिषद शीर्ष संस्था होती है। इसका प्राथमिक कार्य जिले की पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना एवं उनमें समन्वय स्थापित करना है। जिला परिषद कोई प्राथमिक निष्पादन एजेंसी नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण जिला स्तर पर एक पर्यवेक्षी, समन्वयकारी तथा सलाहकारी निकाय के रूप में दायित्वों का निर्वहन करती है।

62. (C) ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ)
राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) कहा जाता है। पूर्व में इस पद को ग्राम सेवक के नाम से जाना जाता था। ग्राम विकास अधिकारी पंचायत के सभी वित्तीय व प्रशासनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखता है, ग्राम सभा की कार्यवाही दर्ज करता है तथा शासकीय योजनाओं के संचालन में सरपंच की सहायता करता है।

63. (B) निर्धारित तिथि के पश्चात दो से अधिक संतान रखता है
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट अयोग्यता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के निर्धारित कट-ऑफ तिथि के पश्चात दो से अधिक संतानें हैं, तो वह पंचायत प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ने के लिए कानूनन

Click Here to Buy book on Amazon

Visit :

www.pdf.tube

Download PDFs For :

- ✓ MPPSC Chapterwise Question Bank
- ✓ KVS/NVS Chapterwise Question Bank
- ✓ KVS/NVS 30 Sample Papers for Tier-II
- ✓ DSSSB TGT Chapterwise Question Bank
- ✓ DSSSB Sample Papers
- ✓ Chapterwise Question Bank
- ✓ JEE NEET Foundation
- ✓ Primary Classes Worksheets
- ✓ Olympiad Guide
- ✓ Sample Papers
- ✓ Previous Year CBSE Papers
- ✓ Previous JEE, NEET and CUET Papers

NODIA

Nodia Editions LLP

125, Sector 6, Vidhyadhar Nagar, Jaipur 302039

MRP ₹ 500.00

74. (B) खुले में शौच मुक्त प्लस (ओडीएफ प्लस) दर्जा
स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण का मुख्य लक्ष्य गांवों में स्वच्छता के स्तर को सुदृढ़ करना है। इसके तहत ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने के साथ-साथ ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन लागू करके 'ओडीएफ प्लस' दर्जा प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। ग्राम पंचायतें गाँव में कचरा निस्तारण, स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण तथा जन-जागरूकता अभियानों का सक्रिय प्रबंधन करती हैं।

75. (A) यह निर्वाचित विधायक को पदमुक्त करने की शक्ति रखती है।
ग्राम सभा स्थानीय शासन में सहभागी लोकतंत्र, योजना निर्माण और सामाजिक अंकेक्षण की एक संवैधानिक संस्था है। यह विकास योजनाओं के अनुमोदन तथा लाभार्थियों के चयन का कार्य करती है। हालांकि, ग्राम सभा के पास राज्य विधान सभा के निर्वाचित विधायक को पदमुक्त करने की कोई कानूनी शक्ति नहीं होती है। विधायक को पद से हटाने की प्रक्रिया राज्य विधान सभा तथा संवैधानिक नियमों के अधीन आती है।

76. (C) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए)
जिला स्तर पर केंद्र प्रायोजित गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्रबंधन पारंपरिक रूप से जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) द्वारा किया जाता था। प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने, दोहरे नियंत्रण को समाप्त करने तथा स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा डीआरडीए का पूर्ण विलय जिला परिषद में कर दिया गया है, जिससे विकास कार्य एकीकृत रूप से संचालित हो सकें।

77. (D) निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास हस्तांतरित विषयों के कुशल प्रबंधन हेतु प्रायः प्रशासनिक और तकनीकी अनुभव की कमी होती है
राजस्थान में पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि नए निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास हस्तांतरित विषयों के कुशल प्रबंधन, वित्तीय नियमों तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पर्याप्त अनुभव नहीं होता है। प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें योजनाओं के संचालन, बजट प्रबंधन तथा ग्रामीण विकास को लागू करने हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी रूप से पूरी तरह दक्ष बनाया जाता है।

78. (C) ग्रामीण आवास और गौण वन उपज
भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के तहत पंचायतों को सौंपे गए 29 कार्यात्मक विषयों में 'ग्रामीण आवास' तथा 'गौण वन उपज' स्पष्ट रूप से सम्मिलित हैं। ये विषय सीधे तौर पर ग्रामीण विकास, आजीविका और आवास से जुड़े हैं। इसके विपरीत उच्च शिक्षा, शेयर बाजार तथा पासपोर्ट जारी करने जैसे विषय केंद्र अथवा राज्य सरकारों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।

79. (C) अनुच्छेद 243C
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 (सी) विशेष रूप से 'पंचायतों की संरचना' से संबंधित है। यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडल को कानून बनाकर पंचायतों की संरचना के संबंध में आवश्यक उपबंध करने का संवैधानिक अधिकार देता है। इसके तहत पंचायतों के सभी स्तरों पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा सीटें भरने तथा अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है।

80. (D) वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पंचायत खातों का ऑनलाइन अंकेक्षण
'ऑडिटऑनलाइन' एप्लीकेशन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है, जो ई-पंचायत का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायतों के वित्तीय खातों और व्यय का ऑनलाइन अंकेक्षण सुगम बनाना है। यह प्रणाली पंचायत खातों की लेखापरीक्षा प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करके वित्तीय गड़बड़ियों को रोकती है तथा स्थानीय स्वशासन निकायों में पूर्ण पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का एक प्रमुख विषय है। यह विषय राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि पंचायती राज संस्थाओं के दायरे में।

42. (B) ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति
ग्राम सभा किसी ग्राम पंचायत की प्राथमिक और स्थायी संस्था होती है। कानूनन, उस संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति ग्राम सभा का वैधानिक सदस्य होता है। उसे ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने, विचार-विमर्श करने तथा मतदान करने का पूरा अधिकार होता है। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, सदस्य नहीं हो सकता।

43. (A) केवल I और II
मनरेगा के कार्यान्वयन में पंचायतों की केंद्रीय भूमिका होती है। ग्राम पंचायतें गाँव में कराई जाने वाली विकास परियोजनाओं की पहचान करने हेतु जिम्मेदार होती हैं। अधिनियम के अनुसार कम से कम पचास प्रतिशत कार्य पंचायतों द्वारा निष्पादित किए जाने अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को जॉब कार्ड जारी करने का अधिकार भी सीधे ग्राम पंचायत को ही प्राप्त होता है।

44. (C) पंचायत समिति
राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित है। इस ढांचे में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद कार्य करती है। इन दोनों के मध्य स्थित खंड स्तर को राजस्थान में आधिकारिक रूप से 'पंचायत समिति' के नाम से जाना जाता है। पंचायत समिति ग्राम पंचायतों और जिला परिषद के बीच प्रशासनिक एवं विकासात्मक समन्वय स्थापित करने वाली महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है।

45. (D) P-4, Q-3, R-1, S-2
पंचायती राज में धन का हस्तांतरण अपर्याप्त अनावद्ध वित्तीय संसाधनों और कम राजस्व सृजन से संबंधित है। कार्यों का हस्तांतरण राज्य विभागों द्वारा स्थानीय निकायों को अधिकार देने में अनिच्छा को दर्शाता है। कार्यकर्ताओं का हस्तांतरण प्रशासनिक एवं तकनीकी कर्मचारियों की कमी से जुड़ा है। क्षमता निर्माण नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता को निरूपित करता है, जिससे वे विकास कार्यों को कुशलतापूर्वक संभाल सकें।

46. (C) आईएएस या राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) का अधिकारी
राजस्थान में पंचायती राज की शीर्ष संस्था जिला परिषद में प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन हेतु एक वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अथवा वरिष्ठ राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) का अधिकारी होता है। यह अधिकारी जिला परिषद के निर्णयों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होता है।

47. (D) 10 दिसंबर
राजस्थान में पंचायती राज नियमों के अनुसार वर्ष में चार निश्चित तिथियों पर ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है। ये निर्धारित तिथियां 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 1 मई (मजदूर दिवस), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) तथा 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) हैं। इन चार विशिष्ट तिथियों में 10 दिसंबर शामिल नहीं है, अतः इस तिथि पर बैठक अनिवार्य नहीं होती है।

48. (A) राज्य वित्त आयोग का गठन → पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा → राज्यपाल को सिद्धांतों की सिफारिश → राज्य विधानमंडल द्वारा कार्यान्वयन
पंचायती राज संस्थाओं को निधियों के हस्तांतरण की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। सर्वप्रथम राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसके बाद आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। तत्पश्चात आयोग करों के वितरण हेतु सिद्धांतों की सिफारिशें राज्यपाल को सौंपता है। अंत में राज्य विधानमंडल द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकृत कर लागू किया जाता है।

49. (B) 21 वर्ष
भारत में पंचायती राज संस्थाओं के किसी भी स्तर पर चुनाव लड़ने अथवा प्रतिनिधि बनने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। यद्यपि भारत में मतदान करने का अधिकार नागरिक को 18 वर्ष की आयु में ही मिल जाता है, किंतु पंचायती राज का चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवार को न्यूनतम 21 वर्ष का होना चाहिए।

50. (C) पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करना
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पंचायती राज मंत्रालय की एक प्रमुख केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं, प्रशासनिक दक्षता और संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करना है। इसके तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा पंचायत कर्मियों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे वे सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने तथा स्थानीय स्तर पर सुशासन स्थापित करने में पूर्ण सक्षम हो सकें।

NODIA

51. (A) केवल I, II और III
पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का उचित रखरखाव करने, प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण तथा अंतर-खंड ग्रामीण सड़कों की देखरेख हेतु उत्तरदायी हैं। ये विषय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल हैं। हालांकि, भारी विनिर्माण उद्योगों की स्थापना तथा संचालन का कार्य केंद्र एवं राज्य सरकारों के औद्योगिक क्षेत्राधिकार में आता है, न कि पंचायती राज संस्थाओं के अधीन।

52. (D) ग्राम पंचायत के एक विशिष्ट वार्ड के सभी वयस्क मतदाताओं की सभा
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत 'वार्ड सभा' स्थानीय लोकतंत्र की सबसे छोटी और प्राथमिक इकाई है। यह किसी ग्राम पंचायत के एक विशिष्ट वार्ड में रहने वाले उन सभी वयस्क नागरिकों की सभा है, जो उस वार्ड की मतदाता सूची में